

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

અન્તર્રાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર

(International Economics)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र

(INTERNATIONAL ECONOMICS)

भारत के विशेष सदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं,
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय एवं प्रशुल्क नीति
का एक सारपूर्ण एवं आलोचनात्मक अध्ययन]

लेखक

डा० पी० सी० धीवास्तव, एम० ए०, पी-एच० डी०,
प्रधानाचार्य एवं अध्यक्ष, व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग,
जी० एस० कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकॉनॉमिक्स, जयलपुर ।



नवयुग साहित्य सदन,
लोहामण्डी, भागरा-२

प्रथम संस्करण—सन् १९६७
द्वितीय संस्करण—सन् १९६९
तृतीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण—१९७०

मूल्य : १७ रुपये मात्र

तृतीय सस्करण का भूमिका

एस्तुन पुस्तक का द्वितीय सस्करण एक वर्ष की अल्प अवधि में ही समाप्त हो गया, जो इस बात का प्रतीक कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों ने इसे उपयोगी पाया। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापक बन्धुओं ने पुस्तक का जो स्वागत किया उससे प्रेरणा लेकर लेखक ने तृतीय सस्करण को उपयोगी बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किया है। इस कार्य में छात्रों, प्राध्यापकों और अपने कतिपय शिष्यों से प्राप्त हुए विभिन्न सुझावों से बड़ी सहायता मिली है।

इस नये सस्करण को भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने के प्रतिरिक्त, यव-तन्त्र नवीनतम् तथा और चीकों को सम्मिलित किया गया है। 'परिचय खण्ड' में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्णनास की समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ समझाये गये हैं और यह बताया गया है कि इसका प्रादुर्भाव एवं विकास कैसे हुआ। दूसरे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त का विवेचन किया गया है और समय-समय पर जो सिद्धान्त प्रस्तुत किये जाते रहें उनकी विषय-चर्चा की गई है। इसके प्रतिरिक्त, आर्थिक विकास पर पड़ने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभावों को भी स्पष्ट किया गया है। तीसरे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलुओं—विदेशी भुगतान, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, अवमूल्यन, विनिमय नियन्त्रण, प्रत्यक्ष प्रवर्धन अन्तरण समस्या इत्यादि का विवेचन किया गया है। चौथे खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति—स्वतन्त्र व्यापार, संरक्षण, द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ, व्यापारिक संधियाँ, कार्टेल्स, एकाधिकार, शोषण, वस्तु व्यापार समझौते आदि को समझाया गया है। पाँचवें खण्ड में भारत के विदेशी व्यापार का विकास दिखाया गया है और निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात-साख विषयक अध्याय बढ़ाये गये हैं। विदेशी मुद्रा विदेशी पूँजी की समस्याओं पर पृथक् पृथक् विचार किया गया है। रुपये के १९६६ के अवमूल्यन तथा पौण्ड के १९६७ के अवमूल्यन से भारत के विदेशी व्यापार पर गम्भीर प्रभाव हुए। इनके प्रवर्धन के लिए पृथक् पृथक् अध्याय रचे गये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग वाले अन्तिम छठे खण्ड में भी नवीनतम् सामग्री दी गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग शीघ्र अध्याय में कोलम्बो योजना, अफ्रीकी सागर बाजार आदि के विषय में विस्तृत सामग्री बढ़ाई गई है। एशियाई

विकास बैंक एवं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की उप-लक्ष्यो तथा विश्व मन्दो, स्वर्ण संकट जैसी घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है। अतः आशा है कि विद्यार्थियों के लिए यह सस्वरण अथ अधिक उपयोगी होगा।

लेखक ने विभिन्न पत्र, पत्रिकाओं एवं इनमें प्रकाशित प्राध्यापकों एवं विद्वानों के लेखों से समुचित सहायता ली है, जिसके लिये वह इनका आभारी है।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु सुभाव सदैव की भांति सादर निमन्त्रित हैं।

—लेखक

अनुक्रमिका

अध्याय

पृष्ठ-क्रम

[प्रथम खण्ड] विषय-प्रवेश (Introduction)

१. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र ।	३—८
२. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व	९—१५
३. अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार	१६—२५
४. आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन	२६—४२

[द्वितीय खण्ड]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विद्युद्ध सिद्धान्त (The Pure Theory of International Trade)

५. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास	४५—४९
६. व्यापारवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व सिद्धान्त	५०—५५
७. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उद्भव (एडम स्मिथ के विचार)	५६—६५
८. (क) सुलनायक लागत सिद्धान्त (रिकार्डों का दृष्टिकोण)	६६—६९
(ख) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य एवं पूति	६९—१०७
९. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य साम्य सिद्धान्त ।	१०८—११६
१०. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त	१२०—१२८
११. व्यापार-शक्ते ।	१२९—१४१
१२. उत्पत्ति के विशिष्ट साधन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	१४२—१५१
१३. परिवर्तनशील लागते एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार	१५२—१६४
१४. राष्ट्रीय आय के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव	१६५—१७३
१५. अन्तर्देशीय साधन और वस्तु-आवागमन	१७४—१८२

[तृतीय खण्ड]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू (The Monetary Aspects of International Trade)

१६. विदेशी मुद्रा के साधन एवं ढंग	१८५—१९५
१७. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रातान सन्तुलन	१९६—२३९
१८. विनिमय दरों का सिद्धान्त	२३३—२४५
१९. स्वर्णमान एवं मुद्रा प्रक्रिया (टुकसाती समता सिद्धान्त)	२४६—२६५
२०. अपरिवर्तनशील पत्र-चलन (अर्थ शक्ति समता सिद्धान्त)	२६६—२८३
२१. मुद्रा प्रसार के युग में विनिमय	२८४—२९७
२२. अवमूल्यन एवं अविमूल्यन	२९८—३०७
२३. विनिमय नियन्त्रण	३०८—३२७
२४. अन्तरण समस्या	३२८—३४८

[चतुर्थ खण्ड]
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति
 (International Commercial Policy)

२५ विदेशी व्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या	३५१-३५४
२६ स्वतन्त्र व्यापार	३५६-३६६
२७ सारक्षणा	३६७-३८८
२८ द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ	३८९-३९९
२९ साम्राज्यीय अधिमान	४००-४०३
३० राशिपानन, क्वॉटल्स एवं एकाधिकार	४०४-४२६
३१ व्यापारिक सन्धियाँ	४२७-४४६

[पाँचवाँ खण्ड]
भारत का विदेशी व्यापार
 (India's Foreign Trade)

३२ भारत का विदेशी व्यापार	४४९-४६८
३३ भारत की विदेशी व्यापार नीति	४६९-४८३
३४ भारत की प्रमुख नीति	४८४-४८५
३५ निर्यात संवर्धन	४८६-४८८
३६ निर्यात बाधा	४८९-४९३
३७ आयात प्रतिस्थापन	४९४-४९६
३८ राजकीय व्यापार	४९७-४९८
३९ भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार समझौते	४९९-५०३
४० १९६६ से रुपाय वी अवमूल्यन और विदेशी व्यापार	५०४-५४६
४१ पौड वी अवमूल्यन और भारत	५४७-५५५
४२ भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या	५५६-५६५
४३ विदेशी पूँजी एवं विदेशी विनिमय	५६६-५८०

[छठा खण्ड]
अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग
 (International Economic and Monetary Co-operation)

४४ प्रत्येक विकसित देशों की समस्याएँ	५८३-५८६
४५ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग	५८७-६२६
४६ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	६२७-६४६
४७ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक	६४७-६६२
४८ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम	६६३-६७०
४९ अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्	६७१-६७५
५० एशियाई विकास बैंक	६७६-६८२
५१ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता	६८३-६८५
५२ मदी—एन निषेध समस्या	६८६-६८९
परिशिष्ट—विदेशी व्यापार मुख	७००-७०४

प्रथम सर्ग

विषय - प्रवे

[INTRODUCTION]

रक्षकों के विचार—

- १) जी० एल० मेहता (G. L. Mehta)—“हम पर्याप्त सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं और यह भी चाहते हैं कि स्वयं भी विभिन्न असमानताओं को समाप्त करने में भरसक सहयोग दें। हर्य की बात है कि अनेक एशियाई और अफ्रीकी देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है किन्तु यह राजनैतिक स्वतन्त्रता तब तक निरर्थक है जब तक कि इसके साथ ही उनके आर्थिक विकास में भी प्रगति न हो।”

[“We would like to receive adequate aid and we would also like to exert our own efforts to eliminate various disparities and inequalities. Many Asian and African countries have won independence but this political independence has no meaning unless it is accompanied by economic development and growth.”]

- (२) सैमुअलसन (Samuelson)—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सहत्वपूर्ण होने का एक मौलिक कारण यह है कि विदेशी व्यापार एक ऐसी ‘उपभोग-सम्भावना अनुसूची’ प्रस्तुत करता है, जो हमें सभी वस्तुओं की अधिक मात्रा, उस मात्रा से भी अधिक, जो कि हमारे निजी ‘आन्तरिक उत्पादन-सम्भावना अनुसूची’ द्वारा उपलब्ध थी जाती है, प्रदान करता है।”

[“International trade is important for the following basic reason. Foreign trade offers a ‘Consumption-possibility schedule’ that can give us more of all goods than can our own domestic production-possibility schedule.”]

- (३) हैरोड (Harrod)—“अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक विस्तृत और जटिल विषय है, इस पर एक ऐतिहासिक अथवा भौतिक दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत पाठकगण वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति के कारणों और प्रभावों का विश्लेषण पाने की भी आशा कर सकते हैं। इसके द्वारा उन्हें उचित समाधान खोजने तथा भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने में सहायता मिलेगी।”

[“International Economics is a large and complex subject; it might be surveyed from a historical or a geographical point of view, a brief description of the principal constituent items of international trade might be attempted, above all the reader might hope to find an analysis of the causes and phases of the present crisis, with a view to forming opinions about the probable course of events and the appropriate remedies for the situation.”]

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र

(The Scope of International Economics)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र वह है जिसमें राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रों के इन पारस्परिक सम्बन्धों से कुछ विशेष समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन विशेष सम्बन्धों और समस्याओं पर माने गये निम्नलिखित प्रकाश डाला गया है।

व्यापार की भूमिका

जिस प्रकार व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं रह सकता उसी प्रकार राष्ट्र भी पूर्णतः स्व-निर्भर नहीं हो सकते। यदि वे इसका प्रयास करेंगे, तो उनका जीवन-स्तर पर्याप्त ऊँचा नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक राष्ट्र कुछ विशेष वस्तुओं का ही उत्पादन करता है और अपने उत्पादन का एक भाग निर्रिक्त उपभोग के लिए रखकर शेष को अन्य राष्ट्रों से अपनी अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करने में प्रयोग करता है। इस प्रकार, विशिष्टीकरण का अर्थ है व्यापार और व्यापार के अभाव में विशिष्टीकरण नहीं हो सकता। मदेह नहीं कि विदेशों से होने वाला व्यापार आन्तरिक व्यापार की तुलना में प्रायः श्रम होता है, किन्तु कुछ देशों (जैसे—इङ्ग्लैण्ड) के लिए वह जीवन-मरण का प्रश्न बना हुआ है। यथार्थ में विदेशी व्यापार के परम महत्त्व के दो बुनियादी कारण हैं—एक तो यह कि विदेशों से वे वस्तुएँ मँगाई जा सकती हैं, जिन्हें देश में ही उत्पन्न करना सम्भव नहीं है और दूसरे, जो वस्तुएँ स्वदेश में उत्पन्न की जा सकती हैं वे भी विदेशों से कम लागत पर ही प्राप्त हो जाती हैं।

प्रसाधनों एवं तकनीकों का आवागमन

केवल वस्तुएँ ही नहीं बल्कि इन्हें बनाने वाले कुछ प्रसाधन भी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जाते-जाते हैं। ऐसे आवागमन भी विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। पूँजी, श्रम और तकनीकी कौशल ऐसे ही प्रसाधन हैं। इस प्रकार के आवागमन प्रथम महायुद्ध से पूर्व एक बहुत विस्तृत पैमाने पर हुआ था। पश्चात्कालीन युद्धों (जैसे—प्रादेशिक युद्धों के) सम्बद्ध राष्ट्रों (जैसे—यूनाइटेड स्टेट्स) की कायपालत कर दी थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध के समय से इन आवागमनों में कुछ

की आई। विशेषतः श्रम का प्रवाह तो बहुत ही घट गया है। अब द्वितीय महायुद्ध बाद विकास। मुख्य देशों व विकास के लिए विकसित देशों से पूँजी और तकनीकी ज्ञान का आवागमन विशाल पैमाने पर पुनः होना लगा है।

प्रतिबन्धों का विकास

१९वीं शताब्दी में राष्ट्रात्मक वस्तुओं और साधनों के आवागमन का स्वागत नहीं था तथा इन पर सामूहिक प्रतिबन्ध ही लगाये थे। उस काल में क्रेताओं को सस्ते सस्ते बाजार में खरीदने तथा बिक्रीनामा हो मँहों से मँहों बाजार में बेचने की पूरी इच्छा थी। गतिविधि व आनन्द जान पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। विनिर्मुक्तताओं को अपने नाम बिना भी दण्ड में लगाने और इच्छानुसार वापस लेने की अनुमति थी। व. सु. म. १९१६ के बाद स्थिति बहुत बदल गई। विभिन्न राष्ट्रात्मक तत्त्वों की दीवारें खड़ा कर दी, प्रत्यक्ष परिमाणान्तर प्रतिबन्ध भी लगाये गये, विशेष (वस्तुओं व साधनों व लिए लाइसेन्स व्यवस्था प्रचलित की गई और कुछ वस्तुओं का आयात ना विस्तृत ही राख दिया गया। औद्योगिक वस्तुओं की मुद्रा कोष के प्रयत्न व फलस्वरूप अब इन प्रतिबन्धों को हटाया जा रहा है, यद्यपि इसकी गति धीमी है।

राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

उत्तमोत्तम शताब्दी में ब्रिटिशों का विश्व का प्रभुत्व राष्ट्र कहलाने का योग्य प्राप्त हुआ। उनकी औद्योगिक विरासतों और औद्योगिक प्रगति ने उसे विश्व का प्रधान औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। उनकी प्रभुत्व व्यापार और वित्त व धन में भी विस्तृत था। ब्रिटिश जहाज ब्रिटिश मान की विश्व के कोने-कोने में ल जाते और वहाँ से खाद्यान्न व वस्त्र आन भरकर लौटते थे। नन्दन विश्व का प्रमुख वित्त केन्द्र बना हुआ था।

विन्तु प्रथम महायुद्ध में बाद ब्रिटन की प्रभुता को सम्पूर्ण चुनौती प्रस्तुत हुई। पहल तो युनाइटेड स्टेट्स और फिर जर्मनी ने उस औद्योगिक क्षेत्र में पछाड़ दिया। आज तो औद्योगिक, व्यापारिक एवं विज्ञान क्षेत्र में अमेरिका ही प्रभुत्व प्राप्त हुआ है। विन्तु जिन परिस्थितियों में ब्रिटन ने नतीजा की भूमिका निभाई थी वह उनमें विस्तृत है जिनमें कि अमेरिका को आन्तरिक नतीजा की भूमिका निभानी पड़ रहा है। ब्रिटन की प्रभुता वाल युग में सर्वत्र पूँजीवाद ही छाया हुआ था विन्तु आज के विश्व का परस्पर विरोधी विचारधाराओं (पूँजीवाद एवं साम्यवाद) में बँटा हुआ है। यही नहीं, पहल विश्व—अर्थव्यवस्था अप्रसन्न स्वतन्त्र व्यापार व आधार पर एकाग्र हो गई था विन्तु आजकल इसका स्थान प्रतिबन्धों और क्षेत्रीय गुटों में ले लिया है। आर्थिक गुटों व अतिरिक्त विश्व में साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के गुट भी हैं, जिनमें मध्य सामूहिक व्यापार होना है। पहल नन्दन विश्व अब व्यवस्था का एक अलग केन्द्र था विन्तु अब कई केन्द्र (जैसे, न्यूपाक) बन गये हैं, जिनमें इनके मध्य बहुकारी उपायों द्वारा अनुत्पन्न रखा जा रही हो गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याय

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के प्रकाश में हम उस अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं की गम्भीरता को महज हो समझ सकते हैं जो आज विश्व के सामने उपस्थित हैं। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ निम्न प्रकार हैं —

(१) क्षेत्रीय गुटों के निर्माण से उत्पन्न समस्याएँ— द्वितीय विश्व युद्ध बाद अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में कई क्षेत्रीय गुट बन गये हैं, जिनमें यूरोपि साम्राज्य (European Common Market, ECM) प्रमुख है। इस संधि फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्सेम्बर्ग यह छह राष्ट्रों में तैयार हुये और यह तय किया कि सदस्यों के मध्य व्यापार पर कोई तटकर नही लगाया समुदाय के भीतर श्रम और पूँजी के आवागमन पर नये हुए प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया जायेगा और बाहरी विश्व के विरुद्ध समान तटकर रले जायेंगे। इस समुदाय के लक्ष्य पर्याप्त सीमा तक पूरे हुये हैं। इससे प्रेरणा लेकर कुछ अन्य क्षेत्रीय गुट भी बने, जैसे—यूरोपीयन स्वतन्त्र व्यापार संधि (European Free Trade Association, E F T A)। इसमें ये यूरोपीय देश सम्मिलित हुये, जहाँ साम्राज्य में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं थे। इनका लक्ष्य सदस्यों के मध्य केवल औद्योगिक उत्पादों के आवागमन पर नये हुए तटकरों को समाप्त करना था। दक्षिणी अमेरिका के छह राष्ट्रों में भी, जो एच ईस्टम यूनियन में पहले ही सम्मिलित हो चुके थे, एक दूसरे के उत्पादों के विरुद्ध लगाये हुए तटकरों को घटाने की विधा में कदम उठाया। विन्तु विचारणीय बात यह है कि इन क्षेत्रीय गुटों के निर्माण का शेष विश्व पर क्या प्रभाव होगा या हुआ है। सदेह नहीं कि ऐसे किसी भी गुट के तटकर गुट बनने से पहले के श्रोगत राष्ट्रीय तटकरों से ऊँचे नहीं हैं, किन्तु गुट बन जाने मात्र से ही कुछ मददस्व-राष्ट्र, गुट के अन्य सदस्य-देशों से तटकर न देने या रियायती दर से तटकर देने की मुविधा के कारण वहाँ तैर सदस्य राष्ट्रों के तटकर बाह्य आयातों को प्रतिस्थापित (Replace) करने में समर्थ हो गये हैं और जिस सीमा तक ऐसा हुआ है उस सीमा तक शेष विश्व को कुप्रभावित हुआ माना जायेगा। अब यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व-स्थायित्व के हित में है कि इसका उचित समाधान तलाश किया जाय।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याएँ—द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की समस्या उत्पन्न हुमा। इसके सदस्य देशों ने अपनी मुद्रा का सम-मूल्य डालर और स्वर्ण में घोषित किया हुआ है। डालर और स्टैबिलि को विश्व के अनेक देशों द्वारा रिजर्व करेंसियों के स्वरूप में प्रयोग किया जा रहा है। किन्तु सन् १९५८ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भुगतान संतुलन में भारी 'घाटा' (Deficit) रहने लगा और उसके स्थलोंको भी भारी गिरावट आ गई है। डालर के विरुद्ध अल्पकालीन विदेशी दावे (Foreign claims) कई गुने हो गये हैं। यद्यपि यदि जल्दी ही उचित उपाय न किये गये, तो इस रिजर्व करेंसी में विश्व का विश्वास नष्ट हो जायेगा।

पचा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की सवट का सामना करना पड़ेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था। सुधार के लिए समय समय पर जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे हैं, वह कोई विशेष फलदायक नहीं हुए हैं।

(३) आर्थिक विकास की समस्याएँ—द्वितीय विश्व युद्ध ने वाद अफ्रीका और एशिया के अनेक देश स्वतन्त्र हुए और अब वह अपने शीघ्र आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। किन्तु विकास-कार्य उनके लिए सहज नहीं है। इसमें उन्हें विकसित देशों की सहायता आवश्यक है। किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे—क्या यह सहायता शर्त रहित (Unconditional) होनी चाहिये? क्या सहायता देने वाले देश सहायता पाने वाले देश को ऋण के सदुपयोग के सम्बन्ध में कुछ इशतहान पूरा करने को कहें? सहायक देश को सहायता प्राप्त देश के विकास-कार्यक्रमों में कहीं तक भाग लेना चाहिये और क्या जिम्मेदारी सहायता देने वाले देशों पर है, जैसे जैसे पर्यटन-विकसित देशों का विकास होता, उनकी प्रत्यक्ष-व्यवस्था में परिवर्तन होगा और वह अधिकाधिक औद्योगिक (Industrialise) होते जायेंगे।

यह हमें पर उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों को अपने यहाँ कुछ समायोजन करने आवश्यक होगा। ये समायोजन क्या हैं और किस तरह किये जायें? एक अन्य विचार-समस्या और है। विकासोन्मुख देशों की भुगतान संतुलन में भारी घाटे उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि उनके आयात निर्यातों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गयी है। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिये पूर्णतः सामान बड़े पैमाने पर मँगाना पड़ रहा है। इस घाटे की पूर्ति प्रायः विदेशी ऋण लेकर की गयी है, किन्तु उसे एक न एक दिन तो लौटाना ही पड़ेगा। अतः आवश्यक आयातों के भुगतान के लिये पर्याप्त मात्रा में निर्यात बढ़ाने की बुनियादी समस्या अभी उत्पन्न हुई है, जिसका स्थायी समाधान खोजना आवश्यक है।

साम्यवाद द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती के मदर्भ में यह परम आवश्यक है कि उपर्युक्त समस्याओं का समाधान अविलम्ब खोजा जाय। विकसित देशों को चाहिए कि विकासोन्मुख देशों की समस्याओं के प्रति एक अधिक उदार दृष्टिकोण अपनायें, क्योंकि इनका विकास होना विश्व शांति की गारन्टी है।

समस्याओं के समाधान के लिए बुनियादी बात

हमारे प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इन समस्याओं के समाधान हेतु पाठकों को कुछ बुनियादी बातें बताना मात्र है, कोई रेडीमेड नुस्खे प्रस्तुत करना नहीं। बुनियादी बातों की जानकारी होने से समस्याओं का समाधान खोजने में सुविधा होगी। ये बुनियादी बातें निम्नांकित हैं—

(१) विदेशी व्यापार का सिद्धान्त—सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि राष्ट्रीय के मध्य व्यापार क्यों होता है, कौन-कौन से घटक यह नियंत्रण करते हैं कि प्रमुख देश विन-विन वस्तुओं में विशिष्टीकरण करें, कि वस्तुओं का निर्यात करें और कि वस्तुओं को मँगायें। जब तक हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बुनियादी

सिद्धान्त की नहीं समझ लेगे, तब तब उन नीतियों का मुत्तावाज करने में रहेंगे जो कि आन्तरिक बस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर प्रभाव डाल रही साथ ही, व्यापार विषयक नियमों को दृष्टिगत रखकर ही विवासोन्मुख देश अन्तर्गत प्रसाधनों के समुचित विदोहन के लिए समुचित रीति बना सकते हैं।

(२) भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी शिरोधार्य—किसी देश के आयातों की निर्यातों में होने वाले परिवर्तन उसके भुगतान सन्तुलन पर तात्कालिक प्रभाव डालते हैं और घाटे या आधिक्य के रूप में प्रतिबिम्बित होते हैं। उक्त परिवर्तनों को देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था (रोजगार-स्तर, व्यावसायिक क्रिया, कीमती वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ता है तथा अन्ततः विदेशी बाजारों में स्वदेश की स्पर्धा शक्ति प्रभावित हो जाती है। जब तक हमें ऐसे प्रभावों की जानकारी न होगी, हम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में कदापि सफल नहीं होयेंगे। क्योंकि प्रभाव विनिमय दरों की स्थिरता या परिवर्तनशीलता के अनुसार चलता चलता होता है, इसलिये भुगतान सन्तुलन का दोना प्रकार की दरा के सम्बन्ध में अध्ययन करना होगा। तब ही हम यह भी जान सकेगे कि भूतकाल में स्वर्णमान का सङ्कट क्यों किया गया और हमारी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का आधार क्या है।

(३) सत्वाधो का ज्ञान—किसी देश की आर्थिक प्रगति पर तात्कालिक और सत्वाधो भिन्नतायें भी प्रभाव डालती हैं, अतः इन सत्वाधो का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उदाहरणार्थ, अंग्रेजी शताब्दी के प्रारम्भ में जब अमेरिका लैटिन अमेरिकन देश आजाद हुए, तो उनकी स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स से कोई बहुत भिन्न नहीं थी। किन्तु १४० वर्ष के मध्यान्तर में यूनाइटेड स्टेट्स तो धन और उत्पादकता में अग्रणी प्रगति कर गया जबकि लैटिन अमेरिकी देश लगभग वैसे ही बन रहे जैसे कि वह सदा से थे सर्वात् कृषि प्रधान, निर्धन और स्थैतिक। इस विपत्ति के लिए उनके कवल प्रसाधन सम्बन्धी अन्तरो को ही बिम्बेदार नहीं उद्घाटन करना, बल्कि दोनों क्षेत्रों की तात्कालिक विशेषताओं का अन्तर भी विमर्श करना है।

उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए धीमे धीमे प्रारम्भिक लोग निम्न मध्यम वर्ग में से थे। यह बहुत महत्वाकांक्षी न थे। उन्होंने केवल छोटे छोटे काम ही स्थापित किये, जो प्रायः पारिवारिक स्तर से संचालित किये जा सकते थे। किन्तु स्पेनिश प्रवासी प्रायः सागन्तवादी वर्ग के थे। उनकी महत्वाकांक्षायें अमित थीं। उन्होंने विशाल भू-सम्पत्तियाँ खरीदीं और खोद लीं प्रभुताशाली बन गये। प्रताप निर्वाणवाद की नीति ने आर्थिक विकास की गति को यूनाइटेड स्टेट्स में तो तेज कर दिया, किन्तु लैटिन अमेरिकी देशों में धीमा, क्योंकि वहाँ आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण घटक—'स्फूर्तवान महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग', जो कि व्यावसायिक नेता प्रदान करता है—अनुपस्थित रहा। या तो इस एजेंसी का सृजन करना चाहिये या अथवा इसका विकल्प खोजना था, जो नहीं किया गया। फलतः लैटिन

अमेरिकन देशों का आर्थिक विकास कुण्ठित हो गया। स्पष्ट है कि समस्याओं को समझने और हल करने हेतु सैद्धान्तिक विश्लेषण के साथ-साथ ऐतिहासिक विश्लेषण करना भी जरूरी है। यही कारण है कि अगले अध्याय में हमने वस्तुनिष्ठवादियों के विचारों का विवेचन किया है, क्योंकि इन्हीं के सुधार या प्रतिक्रिया के रूप में बाद के अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। कुछ पुराने विचार तो आज भी हमारे निर्णयों पर प्रभाव डाल रहे हैं।

परीक्षा प्रश्न *

(१ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन कीजिये।

[Discuss the scope of International Economics]

२ अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याएँ क्या हैं? इनके समाधान के लिए किन दुनियादी बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है?

[What are the current international economic problems requiring immediate attention? What are the basic points which have to be considered in order to solve these successfully?]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्त्व

(Importance of International Trade)

परिचय—

देशों के मध्य होने वाले व्यापार को 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' कहा जाता है। एक देश विशेष के दृष्टिकोण से, उसके निवासी अन्य देशों के लोगों से जो व्यापार करते हैं वह इसका विदेशी व्यापार है। ऐसा व्यापार 'मान्तरिक' (Inter-national) या 'घरेलू' (Domestic) व्यापार की तुलना में कहीं अधिक जटिल हुआ करता है, क्योंकि वह कई प्रकार की मुद्राओं पर आधारित होता है किसी एक प्रकार की मुद्रा पर नहीं। जब हम अन्य देशों को माल बेचते हैं, तो उनसे रुपये में भुगतान लेना चाहते हैं क्योंकि इसी मुद्रा को हम अपने देश में प्रयोग कर सकते हैं। किन्तु अन्य देश सब ही 'रुपया' प्राप्त कर सकते हैं जब कि वह हमें माल दें। यदि वह हमें अपना माल नहीं बेच सकते, तो हमसे खरीद भी नहीं सकते। इस प्रकार, विदेशी व्यापार किसी भी देश के लिए केवल 'एक ओर का रास्ता' (One way street) नहीं होता, जिसके द्वारा ट्रेडिक बेचन जावे ही जावे यावे नहीं। वास्तव में वह 'दोनों ओर का रास्ता' (Two way street) है, अर्थात् ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा ट्रेडिक जाता भी है और जाता भी।

विदेशी व्यापार की आवश्यकता (The Need for Foreign Trade)

संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी व्यापार 'मात्रा' (Quantity) की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा ही है। वहाँ उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का केवल पाँच प्रतिशत ही विदेशों में बेचा जाता है। किन्तु अन्य देश, जैसे कि ब्रिटिश और बेल्जियम, अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी व्यापार पर बहुत अधिक सीमा तक निर्भर हैं। सच तो यह है कि किसी भी देश के निवासियों के लिए विदेशी व्यापार के बिना निर्वाह करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। उदाहरणार्थ, हम विदेशों से औद्योगिक मशीनों और साज-सामान खरीदते हैं, जोकि हमारे देश के औद्योगिकरण के लिए नितांत आवश्यक हैं। यही नहीं, अन्य अनेक वस्तुओं के लिए भी, जोकि हमारे जीवन को सुखपूर्ण बनाती हैं, हम विदेशी व्यापार पर ही निर्भर हैं। हमें विदेशों से रक्षा सामग्री और कई औद्योगिक

गिव बच्चे मालो का भी आयात करना पड़ना है। दूसरी ओर, हमारे निर्यात यद्यपि हमारे कुल उत्पादन का एक बड़ा अंग नहीं है, तथापि कई उद्योगों में यह कुल बिक्री का एक महत्वपूर्ण अंग है। यही कारण है कि अब कभी विदेशों में बिक्री कम हो जानी है, तो विदेशी विनियम की समस्या' (Problem of Foreign Exchange) सम्भीर रूप धारण कर लेती है।

विदेशी व्यापार को बाधनीय बनाने वाले कारण—

विदेशी व्यापार के उपरोक्त उदाहरणों से उन बुनियादी कारणों का पता चलता है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधनीय एवं आवश्यक बनाते हैं। नीचे इन कारणों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।¹

(१) उपभोग व्यापक रूप से—कुछ देश भौगोलिक अवस्था जलवायु सम्बन्धी कारणों से कुछ वस्तुओं उत्पन्न नहीं कर सकते, किन्तु अन्य देश इन्हें आवश्यकता से अधिक मात्रा (Surplus quantity) में उत्पन्न कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कहना उत्पन्न करना अमेरिका में सम्भव है यद्यपि बहुत लचीले निपिड तरीकों से भले ही सम्भव हो, किन्तु लैटिन अमेरिका में कहना प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, अतः अमेरिका वासी इसे लैटिन अमेरिका से आयात करते हैं। दूसरी ओर, वे अपनी कपास उन देशों को निर्यात करते हैं, जहाँ जलवायु और मिट्टी कपास की पैदावार के लिए अनुपयुक्त है। स्पष्टतः ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक है, क्योंकि इसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व के लोग उन वस्तुओं का, जो कि विश्व के केवल कुछ ही भागों में उत्पन्न की जा सकती हैं, आनन्द उठा लेते हैं।

(२) जीवन स्तर ऊँचा—विभिन्न देशों में आन्तरिक व्यापार के अध्ययन से हमें यह पता चल जायेगा कि विशिष्टीकरण (Specialization) वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में (और इसलिए जीवन-स्तर में भी) वृद्धि करता है। यही सिद्धान्त वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी लागू होता है। उदाहरणार्थ, स्विट्जरलैंड और अमेरिका उच्च कोटि की घड़ियाँ बनाते हैं, किन्तु स्विट्जरलैंड के निर्माताओं को घड़ियों के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करते हुए अनेक वर्ष बीत गये हैं, जिससे वे इन्हें बढिया और कम लागत पर ही बना लेते हैं। ऐसी दशा में दोनों देशों के लिये यह लाभदायक होगा कि वे उस वस्तु के बनाने में, जिसमें उन्हें एक विशेष लाभ (Special advantage) है, विशिष्टता प्राप्त करें, और फिर

1 "Much popular writing on the subject of foreign trade shows considerable knowledge about the mechanism of foreign payments, the foreign exchanges, the balance of trade and circumstances likely to affect it but no understanding whatever of what it is all for"—R F Harrod *International Economics*, p 10.

अपनी-अपनी विशेष वस्तुओं का परस्पर विनिमय करते। यही कारण है कि वास्तविक व्यवहार में स्वयं उद्योगपति अमेरिकियों को उच्च कीट की धड़ियाँ बेचते हैं जबकि अमेरिका वाले उन्हें मशीनें एवं मोटरें। इस तरीके से दोनों ही देश कम व्यय पर अधिक और उत्तम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं और अधिक एवं उत्तम वस्तुओं के उपयोग का अर्थ है दोनों ही देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठना।

(३) आर्थिक विपदाओं के समय सहायक—विश्वी भी देश की अर्थ-व्यवस्था अचानक ही उत्तरावहाय के अँवर में फँस सकती है। उदाहरणार्थ, भारत में मानसूनी (Monsoons) के अतफल रहने पर इसके कृषि-उत्पादन को बड़ी ठेस पहुँचती है और ऐसे समय में देश की जनता के भूखों मरने की नीयत आ जाती है। लेकिन ऐसी विपदाएँ विश्व के सब देशों पर एक ही साथ नहीं आती। परिणामतः हम अपने यहाँ खाद्यान्न के अभाव (Food scarcity) को विदेशों से खाद्यान्न का आयात करके दूर कर सकते हैं। वास्तव में, भारत अपने खाद्य संकट को, जिससे अंगुल में करोड़ों लोग जब तक फँस जाया करते हैं, अन्न के आयात द्वारा हल करता रहता है।

(४) सारे विश्व में कीमत की समानता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समस्त विश्व-बाजार (World market) में समान होने की प्रवृत्ति रखती हैं तथा इससे विभिन्न देशों के उपयोग सम्बन्धी ढाँचो (Consumption patterns) और जीवन स्तरों में भी समानता आती है। समानता, प्राकृतिक और जनसंख्या के वर्तमान युग में ऐसा समानीकरण (Equalisation) आर्थिक एवं राजनैतिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही लाभप्रद है।

(५) राष्ट्र की कुशलता में वृद्धि—वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की (और इसविषय प्रतियोगिता की) उपस्थिति में स्वदेशी उद्योगों को अपने निदेशी प्रतिस्पर्धियों का भय रहता है, जिससे कि सर्वे के अन्ती कुशलता बढ़ाने के लिये प्रयत्न करते रहते हैं। इससे राष्ट्र की कुशलता में व्यापक वृद्धि होना स्वाभाविक है।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय शानति और एकता की स्थापना—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा विभिन्न राष्ट्र पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं तथा परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो तानाकान्द सम्झौता जनवरी १९६६ में सम्पन्न हुआ उसके अन्तर्गत राजनैतिक सहमति की सफलता के लिए प्रथम नदम के रूप में सामान्य सम्बन्धों की, और इस हेतु विदेशी व्यापार की दशाओं को, सद्भावपूर्ण बनाने पर बल दिया गया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियाँ

(Disadvantages of International Trade)

निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उल्लेख्य लाभ बहुत ही सन्तोषप्रद हैं। साथ

ही, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के विरुद्ध कोई आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती है। किन्तु, वास्तविक व्यवहार ॥ हम एक चित्र ही चीज देखते हैं जो यह कि विभिन्न राष्ट्र विदेशी व्यापार में उतनी स्वतन्त्रता से प्रविष्ट नहीं होते, जितनी स्वतन्त्रता से होना चाहिए अथवा हो सकते हैं। यहाँ तक कि वे अपने कुछ प्राथमिक सामान (जैसे—घटोई हुई लागतों और नीची कीमतों) को भी छोड़ देते हैं। प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन की प्रत्येक बारीक से बारीक बात के बारे में सदा सजग रहता है। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा सकोच किस लिए? यह सकोच सम्भवतः विदेशी व्यापार से उदय होने वाली हानियों के कारण है। तुलनात्मक सामान का सिद्धान्त (Law of Comparative Advantage) ठीक ही यह संकेत करता है कि देशों के बीच व्यापार लाभदायक है, किन्तु राष्ट्र केवल इस लाभ की इच्छा से ही अपने विदेशी व्यापार के मामले में नियन्त्रित नहीं होने, बरन् उन्हें अन्य बातों पर भी, विशेषतः विदेशी व्यापार की हानियों पर, ध्यान देना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाली हानियाँ प्रायः निम्नलिखित हैं—

(१) आवश्यक सामग्री और खनिजों के भण्डार खाली होना—कुछ सामग्रियों और खनिजों के भण्डार देश में केवल निम्नी उपभोग के लिए ही एक दीर्घ-समय तक पर्याप्त होते हैं। लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत जब उन्हें विदेशों को भेजा जाता है तो उनके भण्डार शीघ्र ही समाप्त होने लगते हैं तथा इनका प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता। उदाहरण के लिए, कुछ समय पूर्व तक भारत से अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ (जैसे—मैंगनीज खनिज) मूल रक्षा (Raw state) में ही निर्यात की जाती रही थी। इससे देश को बहुत ही मामूली लाभ हुआ जब कि आयातक देशों ने उन्हें पहले माल में बदल कर और विक्रय करके बहुत लाभ कमाया। यदि इन प्रसाधनों को सुरक्षित रखा गया होता, तो वे देश के लिए अब अधिक लाभप्रद हो सकते थे, क्योंकि आजकल यहाँ गये गये उद्योग धंधों की स्थापना की जा रही है।

(२) कठु अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेश के उद्योगों को बाह्य प्रतियोगिता के समक्ष असहाय अवस्था में छोड़ देता है। विदेशी वस्तुओं के राजिपातन (Dumping) का भी भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे देश के विकासोन्मुख उद्योग खतरे में पड़ जाते हैं। यही बात भारत में सचमुच घटित भी हुई। स्वेज नहर के निर्माण तथा यातायात एवं सम्वादवाहन के साधनों की अभूतपूर्व सज्जि के फलस्वरूप, मशीनों का बना हुआ सत्ता माल देश में अजगड़गड़ाते लगे। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में कृटीर उद्योग टिक न सके और बन्द हो गये। कृटीर उद्योगों का पतन होने से इथि पर जनसंख्या का भार बढ़ गया और हमारी अर्थव्यवस्था असन्तुलित बन गई।

(३) एराणी विशास—तुलनात्मक सामान सिद्धान्त के आचरण के फलस्वरूप एक देश केवल निम्नी चीनी वस्तुओं का उत्पादन करता है। इससे

युद्धकाल में जबवा अन्य आपदाओं के समय आत्म-निर्भरता (Self-sufficiency) की विषय समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा लोगों को मिलने वाले रोजगारों की संख्या भी घट जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्धों द्वारा उत्पन्न हुई सम्पूर्ण विश्व की आर्थिक परावलम्बता के कारण ही १९२९-३२ की मन्दी ने विश्व-व्यापी आकार ग्रहण कर लिया था और कुछ देशों की मन्दी अन्य देशों पर भी फैल गई थी।

(४) अजोषित प्रसाधन—एक देश में कुछ प्रसाधन केवल इसलिए ही अजोषित (Unexploited) पड़े रह जाते हैं कि इनके प्रयोग द्वारा जो वस्तुएँ उत्पन्न की जा सकती थी उन्हें श्वेक्षतः कम लागत पर ही निदेशों से प्राप्त किया जा सकता है।

(५) उपभोग सम्बन्धी आदतों में विषमता—कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश की उपभोग सम्बन्धी आदतों को भी, हानिप्रद वस्तुओं के आयात द्वारा (जैसे—पिछले ज़मानों में चीन की रक्षा में अफीम का आयात) कुप्रभावित कर देता है।

कुल पर, हम यह कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का पलड़ा इसके हानियों वाले पलड़े से कहीं अधिक भारी है, और यदि एक उपयुक्त नीति अपनाई जाय, तो इसके अनेक दोषों से मुक्ति मिल सकती है। किन्तु यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के बीच वस्तुओं का विनिमय अधिकतम सीमा तक 'स्वतन्त्र' (Free) हो।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और हितों का संघर्ष (International Trade and Conflict of Interests)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से लाभदायक है। यदि उस पर प्रतिबंध न लगाये जायें तो विश्व का उत्पादन अधिकतम सीमा तक बढ़ सकता है। किन्तु यह समझा जाता है कि समस्त विश्व के लिए लाभदायक होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक राष्ट्र विशेष के लिए, कुछ दशाओं में, हानिप्रद हो सकता है। फलतः, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया जाता है। विश्व-हित और राष्ट्रीय-हित में संघर्ष होने को निम्न-लिखित दशाएँ बताई जाती हैं :—

(१) रोजगार—कहा जाता है कि एक देश आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि करके अपने यहाँ रोजगार के स्तर को ऊँचा कर सकता है। जिस प्रकार नया विनियोग करने से आय और रोजगार में वृद्धि होती है उसी प्रकार शुद्ध निर्यात में वृद्धि होने से उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ जाते हैं। विनियोग-गुणक की ही भाँति 'विदेशी व्यापार गुणक' (Foreign Trade Multiplier) भी अपना प्रभाव दिखाता है, अर्थात्, निर्यात में जितनी वृद्धि होती है, उत्पादन, आय और रोजगार में उससे कई गुणा वृद्धि हो जाती है।

[यदि उक्त तर्क का समुचित विश्लेषण करें, तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि शुद्ध निर्यात में वृद्धि करके कोई राष्ट्र केवल अस्थायी रूप से ही लाभान्वित

हो सकता है। कारण, यदि प्रत्येक राष्ट्र निर्यात करना ही पसन्द करे, तो फिर आयात कौन करेगा ? यही नहीं, जब एक राष्ट्र अपने यहाँ आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है, तो अन्य राष्ट्र भी वैसा ही कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो रोजगार में वृद्धि न हो सकेगी।]

(२) श्रमिकों का आवागमन—जब एक देश में वास्तविक मजदूरियाँ अन्य देशों की अपेक्षा कम हों, तब सम्पूर्ण विश्व के आर्थिक बलबाग की दृष्टि से यह बाधनीय होता है कि श्रमिकों का आवागमन प्रवास निर्बाध होने दिया जाये। किन्तु ऊँची मजदूरी वाले देश (जैसे कि अमेरिका) के श्रमिकों के लिए वहाँ कम मजदूरी वाले देश (जैसे कि भारत) से श्रमिकों का आगमन विस्तृत रूप में हाजिर हो सकता है, क्योंकि जबकि संसार भर के मजदूरों की औसत वास्तविक मजदूरियाँ बढ़ जायेंगी, तब अमेरिकी मजदूरों की आय कम हो जायगी। इस प्रकार, यह एक ऐसी दशा है जिसमें (कहा जाता है कि) राष्ट्रीय हित विश्व हित से टकराते हैं और तर्क दिया गया है कि तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त को लागू करते समय इस परिस्थिति को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

[ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि पहली परिस्थिति की भाँति ही यह दूसरी परिस्थिति भी भ्रमपूर्ण है। वास्तव में, तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त केवल इतना ही बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय वितरण की एक दी हुई दशा में लाभप्रद होता है किन्तु वह ऐसा बदायि नहीं कहना कि साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय स्थानान्तरण में प्रत्येक देश को तभी लाभ पहुँचेगा जबकि इन स्थानान्तर से विश्व का औसत जीवन-स्तर ऊँचा हो जाय।]

(३) एकाधिकार—आन्तरिक व्यापार की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एकाधिकार (Monopolies) बन जाते हैं। चरम एकाधिकारी की भाँति एक देश भी अपने व्यापार को सीमित करके अधिकतम लाभ उठाने की चेष्टा कर सकता है।

[इस तर्क के सदर्थ में हमारा निवेदन इतना ही है कि यह प्रयास सफल हो हो ऐसा जल्द ही नहीं है, क्योंकि प्रथमतः, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारी को अन्य देशों की सम्भावित प्रतिযোগिता का भय रहता है, और दूसरे, अन्य देश भी उसकी देखा-देखी अपने यहाँ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में कमी आ जावेगी और सम्बद्ध सभी पक्ष हानि उठावेंगे। इस प्रकार, कोई देश शेष विश्व की उपेक्षा करके केवल अस्थायी रूप से ही लाभान्वित हो सकता है। अन्ततः उसे भी, शेष विश्व के साथ ही साथ, हानि उठानी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, कुछ समय पूर्व तक कम्प्यूनिस्ट देश (विशेषतः सोवियत रूस) एकाधिकारी की भाँति चताने का माल करते रहे थे। किन्तु नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इस प्रयास की निरर्थकता का अनुभव कर लिया है और अब वे गैर-कम्प्यूनिस्ट देशों से भी व्यापार बढ़ाने के लिए उत्तर हो गये हैं।]

(४) अविकसित देश—जब एक घनी राष्ट्र (जैसे कि अमेरिका) अविकसित देशों (जैसे कि भारत) को सहायता देता है, तो ये देश अपने वहाँ प्रतिस्पर्धी उद्योग विकसित कर लेते हैं, जिससे घनी राष्ट्र की स्थिति कमजोर हो जाती है। घत यह भी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रीय-हित और विश्व-हित परस्पर टकराते हैं।

[किन्तु व्यावहारिक तथ्यों से यह तर्क भी सच्चा प्रमाणित नहीं होता। नि सन्देह भारत ने अमेरिकी सहायता के फलस्वरूप नये नये उद्योग कायम कर लिए हैं किन्तु ये सब के सब उद्योग अमेरिकी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने वाले नहीं हैं, और फिर, जहाँ भारत अधिक निर्यात करने लगा है वहाँ वह अधिक आयात भी तो कर रहा है। इसी का परिणाम है कि उसके समक्ष भुगतान-सन्तुलन-माम्नाधी विषम कठिनाइयाँ उपस्थित हैं।]

(५) युद्ध—हितों के संघर्ष की सबसे प्रमुख परिस्थिति आर्थिक क्षेत्र से बाहर की है और इसका सम्बन्ध युद्ध एवं तत्सम्बन्धी दशाओं से है। कोई भी राष्ट्र यह पसन्द नहीं करेगा कि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने सम्भावित शत्रुओं पर निर्भर रहे। साथ ही, वह उनकी शक्ति बढ़ाने में भी अपना सहयोग नहीं देना चाहेगा।

निष्कर्ष—

यह अन्तिम परिस्थिति ही राष्ट्रीय एवं विश्व-हित के संघर्ष की वास्तविक रूपा है। इस एक परिस्थिति को छोड़कर अन्य सब परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय, आर्थिक एवं राजनैतिक दोनों ही दृष्टियों से, विश्व कल्याण का एक ठोस माध्यम प्रतीत होता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ-हानियों का विवेचन करिये। क्या आप, कुल पर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करेंगे ?

[Discuss the advantages and disadvantages of international trade. Would you, on the whole, favour international trade ?]

२. अन्तरक्षेत्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक आधार क्या है ? विवेचन कीजिये।

[What is the economic basis of inter regional and international trade ? Discuss.]

(बिक्रम, एम० ए०, १९९६)

अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार

(International and Inter-regional Trade)

प्रारम्भिक—अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र 'सामान्य अर्थशास्त्र' की एक शाखा

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन समस्त आर्थिक व्यवहारों (Economic transactions) से है जिनमें किसी राष्ट्रीय सीमान्त की समस्या उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण हैं—प्रवास (Emigration), एक देश के व्यक्तियों द्वारा दूसरे देश के व्यक्तियों को श्रृण दना प्रचवा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना।¹ सीमान्त अधिकारियों के लिए यह सम्भव है कि वे भारत में आने वाले प्रचवा यहाँ से जाने वाले समस्त व्यक्तियों, सामानों और डाक-बैलों की विस्तृत जाँच द्वारा, उन समस्त अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारों की, जिनमें कि भारत सम्मिलित हुआ था, एक सूची बना ले। यह सूची इङ्गलैंड, अमेरिका, रूस जापान, चीन, पाकिस्तान आदि के सीमान्त-अधिकारियों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय सूचियों से बहुत भिन्न न होगी। किन्तु हमें देशों में उदाहरण तक ही सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी देश के अन्दर ही उसके किसी क्षेत्र (Area) विशेष को भी उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली प्रदेश को लेते हैं। दिल्ली राज्य के सीमा अधिकारियों द्वारा प्रवास श्रृण, वस्तुओं के क्रय-विक्रय आदि की जो सूची तैयार की जायेगी वह भी बहुत सभों में भारत के या अन्य देशों के सीमा-त-अधिकारियों की सूची से मिलती जुलती होगी।

स्पष्टतः, यदि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को एक पृथक् अध्ययन का स्थान देना है, तो यह दिखाना आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय सूची में प्रविष्ट किये गये व्यवहारों की कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो कि राष्ट्रीय सीमाओं से भिन्न किन्हीं अन्य सीमाओं पर

1 "International Economics is concerned with all economic transactions involving passage across a national frontier. Examples are emigration, the loan of capital by the nationals of one country to those of another, the purchase of goods by the nationals of one country from those of another"—R F Harrod *International Economics*, pp 4-5

बनाई गई सूची के व्यवहारे में नहीं पाई जाती हैं।¹ अन्य शब्दों में हमें यह देखा होगा कि विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के आधीन निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य के आर्थिक व्यवहार एवं ही राष्ट्रीय सरकार के आधीन विन्तु अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य होने वाले आर्थिक व्यवहारों से किन बातों में भिन्न है।

किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि इन अन्तरो पर आवश्यकता से अधिक वन न दिया जाय। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय (International) और अन्तर्प्रदेशीय (Inter-state) दोनों ही प्रकार के व्यवहारों में यह समानता देखी जाती है कि समाप्त व्यवहार जिन भुगतानों को जन्म देते हैं उनमें से 'आवक भुगतानों' (Inward payments) का जोड़ 'जावक भुगतानों' (Outward payments) के जोड़ के बराबर होता है और यदि कोई अन्तर है तो उसे मुद्रा के वास्तविक स्थानान्तरण द्वारा पूरा लिया जाता है। वास्तव में किसी देश के विदेशी भुगतानों को जिस 'मिष्ट-निष्पन्न' (व्यवस्था) द्वारा संतुलित रखा जाता है उससे सम्बन्धित सिद्धान्त उस देश के अन्दर ही किन्हीं-की-सेवा के मध्य भुगतानों को संतुलित रखने में भी लागू किये जा सकते हैं। संक्षेप में अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्प्रदेशीय भुगतान समतुल्य के सिद्धान्त समान होते हैं।

साथ ही यह भी सम्भवता आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्प्रदेशीय (या आन्तरिक) व्यवहारों के मध्य एक प्रतिष्ठ सम्बन्ध पाया जाना है जिस कारण इन दोनों प्रकार के व्यवहारों को विलुक्त ही पृथक् पृथक् भेदिए जा सकते हैं। वास्तव में, राष्ट्र विषय की परिस्थितियाँ व केवल हमारे प्रायानों और नियतों के परिमाण को वरन् ऐसे आन्तरिक विषयों, जैसे कि आयकर से प्राप्तियाँ नये घरों की निर्माण की दर आदिको भी प्रभावित कर सकती हैं और करती भी हैं। हमें इसी सम्बन्ध पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार) और आन्तरिक व्यवहार (आन्तरिक व्यापार) में तुलना

प्रतिष्ठित सत्यवास्तवों ने अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों को व्यापार की दो भिन्न भिन्न अतिर्या माना था। उनकी परिभाषा के अनुसार, 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार' वह व्यापार है जो विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच होता है किन्तु

1 "Clearly if international economics is to be justified as a proper subject of study, it is necessary to show that the transactions entered on the British inventory have attributes which make them differ substantially from transactions recorded in any of the similar inventories which might be drawn up on boundaries not coincident with national frontiers — *Ibid*, p. 5.

‘आन्तरिक व्यापार’ वह है जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है। स्पष्टतः यह भेद राजनैतिक सीमाओं पर आधारित है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश के सीमांत की पार कर जाता है, आन्तरिक व्यापार ऐसा नहीं करता। ऐसी भिन्नता के मन्दर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विद्यमानता और दिशा को स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने एक पृथक् सिद्धान्त (तुलनात्मक सागत सिद्धान्त) प्रस्तुत किया। किन्तु एक नये या पृथक् सिद्धान्त की रचना का प्रयास तब ही उचित ठहराया जा सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आन्तरिक व्यापार से कुछ ‘मौलिक भिन्नता’ (Fundamental difference) रखता हो। भ्रत क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करने हेतु एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता है, इस विषय में अपनी सम्मति देने के पूर्व हमें इन दोनों की समानताओं और भिन्नताओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये।

आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों के मध्य समानतायें—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित बातों में आन्तरिक व्यापार से मिलता जुलता है —

(१) वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय—दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। मुद्रा तो केवल मध्यस्थ का कार्य करती है क्योंकि सब ही सीधे भ्रगत वस्तुओं का वस्तुओं से, सेवाओं या सेवाओं से प्रथम वस्तुओं का सेवाओं से विनिमय मान है।

(२) सम्बन्धित पक्ष ‘व्यक्ति’ होते हैं—जिन प्रकार आन्तरिक व्यापार में है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी सम्बन्धित पक्ष ‘व्यक्ति’ ही होते हैं। नि सदैव प्रत्येक सरकार अपनी विभागीय आवश्यकताओं का सामान आयात करती है, किन्तु इस स्थिति में वह एक व्यापारी के समान ही कार्य करती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कुछ भाग सरकारों के मध्य होता है परन्तु अधिकतर भाग व्यक्तियों के बीच ही सम्पन्न किया जाता है।

(३) ऐच्छिक सीमा—सरकारें कुछ वस्तुओं के व्यापार का नियंत्रण कर सकती हैं अथवा उस पर परिमाणात्मक प्रतिबंध (Quantitative restrictions) लगा सकती हैं। किन्तु वे व्यापारियों को किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिये विवश नहीं कर सकती हैं। लोग विदेशी वस्तुओं तब ही खरीदते हैं जबकि उनमें इससे लिये इच्छा हो। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में, आन्तरिक व्यापार की भाँति, ऐच्छिक सीमा से ही उत्पन्न होता है।

आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानतायें—

अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन और आन्तरिक लेन देन में प्रायः निम्नलिखित असमानतायें बताई जाती हैं —

(१) दूरी—अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों में कभी-कभी दूरी के आधार पर भी भेद किया जाता है। लेकिन विद्वानों ने इस भेद को (कि अन्तर्राष्ट्रीय

भाषार दूरी का व्यापार है और आन्तरिक व्यापार (बाइट वा) महत्व नहीं दिया है। उदाहरणार्थ, समुत्तर और लाहौर के मध्य दूरी अपेक्षित कम है किन्तु इन स्थानों के मध्य वा व्यापार 'विदेशी व्यापार' की श्रेणी में आता है, जबकि समुत्तर और बम्बई के मध्य दूरी अपेक्षित अधिक है किन्तु इनके बीच का व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' की श्रेणी में गिना जाता है। स्पष्टतः दूरी की अधिकता या कमी को अन्तराष्ट्रीय और आन्तरिक व्यापारों के मध्य भेद का आधार बनाना ठीक नहीं है।

(२) करेन्सी—आन्तरिक व्यापार में केवल एक ही करेंसी—आन्तरिक चलन—का प्रश्न उदय होता है। इसके विपरीत, अन्तराष्ट्रीय व्यापार में दो करेंसियों का प्रश्न है—आन्तरिक चलन और बाह्य चलन। इस विनिष्ठता के कारण ही अन्तराष्ट्रीय लेन देन में एक अतिरिक्त कार्य (करेन्सियों के परिवर्तन का कार्य) करना आवश्यक हो जाता है। किन्तु यह कोई मौलिक भेद नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि व्यापार की प्रक्रिया कुछ अधिक जटिल बन जाती है।

(३) व्यापारिक सम्बन्ध—कहा जाता है कि, क्योंकि एक देश के लोग अन्य देशों में अपने व्यापारिक सम्बन्धों के बारे में, अपने ही देश के अन्य भागों की अपेक्षा, वही अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए अन्तराष्ट्रीय व्यापार को आन्तरिक व्यापार से पृथक् समझना चाहिए। जगत में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पछत्ती विदेशी व्यापार सम्बन्धी सूचना का सङ्ग्रह पृथक् से करना वांछनीय प्रतीत होता है तथापि इस प्रकार के व्यापार को स्पष्ट करने हेतु एक पृथक् सिद्धान्त का निर्माण करना उचित प्रतीत नहीं होता। एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता जैसा कि हम पहले ही सकेत कर चुके हैं, तब ही पड़ेगी जबकि व्यापार की स्वभाव मौलिक रूप से भिन्न हो।

(४) साधनों की गतिशीलता—भिवता का अन्य साधन उत्पत्ति-साधनों की गतिशीलता से सम्बन्धित है और प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रियों की सम्मति में वह एक मौलिक भिन्नता है। उन्होंने कहा था कि उत्पत्ति-साधन एक देश से दूसरे देश को जाने की प्रवृत्ति एक देश में ही एक भाग से दूसरे भाग को अधिक सुगमता से आ जा पड़े है। तबनी ही भाषा में, उत्पत्ति-साधनों की अन्तराष्ट्रीय गतिशीलता (International mobility) बहुत ही कम है जबकि उनकी आन्तरिक गतिशीलता (Internal mobility) ऊँची होती है। यम और पूँजी की अन्तराष्ट्रीय गतिशीलता में ऐसा ठालने वाले प्रायः निम्न घटक गिनाये जाते हैं—(क) यम की गतिशीलता के सम्बन्ध में—भाषा और प्रथाओं में अन्तर, विदेशियों के प्रति सामान्य विद्वान्त-भावना, सम्पत्ति नियम, जाति भेद आदि और (ख) पूँजी की गतिशीलता सम्बन्ध में—संपत्तियों की देशभाल सम्बन्धी कठिनाइयाँ, विनियम सम्बन्धी कठिनाइयाँ, मुद्रा, अवरुद्ध खाते (Blocked accounts), जन्त सम्पत्तियाँ आदि। वास्तव प्रविष्टि धर्मशास्त्रियों ने भी यह अनुभव किया था कि उत्पत्ति-साधनों की

अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक गतिशीलता के मध्य केवल अन्तर का अन्तर है। किन्तु उन्होंने यह युक्त किया कि अग्रो (Degrees) का यह अन्तर इतना अधिक है कि वह लगभग भूगोल (Kind) का ही अन्तर बन गया है। इस आधार पर उन्होंने यह मान लिया कि उत्पत्ति साधन देश के अन्दर तो पूर्णरूप से गतिशील (Perfectly mobile) है किन्तु सीमान्त के पार पूर्णतः गतिरहित (Perfectly immobile)। इस भेद के कारण ही उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् सिद्धान्त के लिये विचित्र न्यायोचित आधार मिलता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों में अम का समावेश—

स्पष्ट है कि व्यापार को आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों में विभाजित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दोनों प्रकार के व्यापारों की परिभाषा करने में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राजनैतिक सीमाओं के आधार पर भेद किया, किन्तु जब वे दोनों के मध्य मौलिक भेद को बताने का यत्न करते हैं, तो ऐसा भेद साधनों की गतिशीलता या गतिहीनता से पामा जाता है। इस प्रकार, भेद का एक आधार तो 'आर्थिक' (Economic) है किन्तु दूसरा 'राजनैतिक' (Political)। इन दोनों के निष्कर्ष सदा ही समान नहीं होते। यदि साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता 'शून्य' नहीं है तो आन्तरिक साधनों की गतिशीलता भी पूर्ण नहीं। भारत में, 'अप्रतिस्पर्धा समूह' (non-competing groups) की समस्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही पाई जाती ही ऐसा नहीं वरन् वह एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य भी पाई जाती है। उदाहरणार्थ पत्राकी परिवारों के मद्रास जाने में और मद्रासी परिवारों के पत्राज जाने में अतक भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाएँ हैं। दूसरी ओर, हम यह भी बोलते हैं कि जहाँ लड़का, अधीन और आस्ट्रेलिया में अनेक श्रमिकों ने प्रवास किया।

भिन्नता का आर्थिक आधार—

इस प्रकार, साधनों की गतिशीलता राजनैतिक सीमाओं के साथ यह विस्तृत (Co extensive) नहीं है। अन्य शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को साधनों की गतिशीलता के आधार पर ही समस्त आन्तरिक व्यापार से भिन्न नहीं किया जा सकता। अतः हमें यह निर्णय करना है कि व्यापार का वर्गीकरण राजनैतिक आधार पर करें या आर्थिक आधार पर। स्पष्टतः, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमें आर्थिक भिन्नता में, अर्थात् साधनों की गतिशीलता और गतिहीनता के आधार पर भिन्नता में अधिक रुचि लेनी चाहिए।

उपरोक्त कारणों से, मोहीसन (Vahin) और डकन (Duncan) जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यापार को आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वर्गित करना अनुचित बताया और उस 'क्षेत्रीय' (Regional) एवं 'अन्तर्क्षेत्रीय' (Inter-regional) व्यापारों में वर्गित करने का सुझाव दिया।

अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा क्षेत्रीय एवं आन्तरिक व्यापार—

अब हम एक ओर 'अन्तर्देशीय' व्यापार और 'अन्तर्राष्ट्रीय' व्यापार में और दूसरी ओर, 'क्षेत्रीय' और 'आन्तरिक' व्यापार में भेद करते हैं। जबकि क्षेत्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार आर्थिक सीमाओं (Economic boundaries) से सम्बन्धित हैं, तथा राष्ट्रीय (आन्तरिक या गृह) और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राजनैतिक सीमाओं से। आधुनिक धर्मशास्त्र का दृष्टिकोण यह है कि दो विभिन्न राजनैतिक क्षेत्रों के मध्य व्यापार-सिद्धान्त की रचना करने के बजाय दो आर्थिक क्षेत्रों के मध्य, जो कि एक दूसरे से प्रिकुम-भिन्न होते हैं, व्यापार-सिद्धान्त की रचना करनी चाहिए।

दोनों प्रकार के व्यापारों को शासित करने वाला सिद्धान्त—

आर्थिक एवं वास्तव दोनों ही प्रकार के व्यापारों की दशा में एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वस्तुओं का संचरण है ताकि वह अपनी उन आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने में समर्थ हो जाय जिन्हें वह केवल अपनी उत्पादित वस्तुओं के उपयोग द्वारा ही संतुष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार, दोनों ही दशाओं में व्यापार का आधार 'यम विभाजन' है, जो लोगों को ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है जिसमें उन्हें विशेष लाभ है। इस प्रकार, 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' (Doctrine of Comparative Cost) केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है, बल्कि वह एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों के मध्य होने वाले व्यापार में भी समान रूप से लागू होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए 'पृथक् सिद्धान्त' की आवश्यकता भन्न हो न हो, किन्तु इसके 'पृथक् अध्ययन' की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की भिन्नात्मक विशेषताएँ—

मोहलिन का यह कथन सत्य है कि मूल्य सिद्धान्त में जो नियम निर्धारित किये गये हैं वे सैद्धांतिक अध्ययन में सर्वव्यापी हैं। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता न होने के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् अध्ययन की भी आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् से अध्ययन करना निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक है।—

(१) देशों के मध्य साधनों की गतिहीनता और एक ही देश के भीतर साधनों की गतिशीलता—साधनों की गतिहीनता (Immobility of factors) के कारण ही तुलनात्मक लागत सम्बन्धी भिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं। एक देश के भीतर उत्पादन लागत विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों को निर्धारित करती हैं। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सापेक्षिक कीमतों का तात्पर्य एक ही वस्तु की किन्हीं दो देशों में प्रचलित कीमतों से है। इससे परिस्थिति में बहुत हेर-फेर हो जाता है।

(२) विभिन्न देशीय बैंकों के प्रभाव क्षेत्र—जब व्यापार एक देश के भीतर किया जाता है तो एक माय मुद्रा के सभ्य में नैसर्गिक सम्बन्धों के समानता विनिमय व्यवहारों को सुविधापूर्ण बना देती है। लेकिन जब विभिन्न मुद्रा मान प्रचलित होते हैं (जैसे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में) तब कुछ जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि हमारा सामना विभिन्न चलन पद्धतियों और व्यापारिक तत्वों से होता है। यही नहीं प्रत्येक राष्ट्रीय चलन पर इसकी राष्ट्रीय सरकार (प्रत्यक्ष कन्द्रीय बैंक) का नियंत्रण होता है। मुद्रा मान के सुचारु रूप से संचालित होने के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्रीय बैंक एक विनियम नीति अपनायें। किन्तु यह जरूरी नहीं है कि यह नीति एक ही समय पर सभी देशों में एक समान हो। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार (International transactions) जो कि विभिन्न मुद्रा अधिकारियों के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के मध्य अधिक व्यवहारों की प्रणाली में होते हैं या अन्तरिक व्यापार (Internal trade) को सुलभता में एक विशिष्ट स्थिति रखते हैं। इसी से उनका पृथक् अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है।

(३) विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था—प्रत्येक देश के उत्पादकों को वहाँ की सरकार द्वारा कुछ समान सुविधायें प्रदान की जाती हैं लेकिन विभिन्न देशों में उत्पादकों को मिली हुई सुविधायें समान नहीं होती हैं। अतः आन्तरिक एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भेद इस प्रकार बिगाड़ जा सकता है कि आन्तरिक व्यापार को सरकार से समान सुविधा प्राप्त उत्पादकों के मध्य होने वाला विनिमय है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न सरकारों से विभिन्न सुविधाएँ प्राप्त उत्पादकों के मध्य होने वाला विनिमय है।¹ इस भेद के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् से अध्ययन करना उपयोगी है।

(४) सरकार का हस्तक्षेप—विशुद्ध मूल्य सिद्धांत (Pure value theory) सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के विरुद्ध है वह उत्पादकों और साधन स्वामियों के मध्य पूर्ण प्रतियोगिता की विद्यमानता को आवश्यक मानता है तथा यह कल्पना करता है कि स्वतंत्र बाजार समान (Free market mechanism) द्वारा प्रत्येक प्रमाणित अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। किन्तु आधुनिक समय में स्वतंत्र बाजार सिद्धान्त की अपूर्णताओं के कारण राज्य आर्थिक क्षेत्र में अधिक हस्तक्षेप करता है। स्वतंत्र बाजार व्यवस्था नामों को उन्हीं लोगों के पक्ष में अधिक अनुकूल

¹ It would still be possible to distinguish between internal trade as interchange between producers provided by government with similar amenities for production and international trade as interchange between producers provided by the government with dissimilar amenities —Harrod *International Economics* p 9

वितरण करती है जो कि पहले से ही लाभ-मध्यम थे। इन परिस्थितियों में, शारीरिक दृष्टि से योग्य समस्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का सामाजिक दायित्व राज्य के कंधों पर आ गया है। फलतः आजकल 'सामान्य कीमत सिद्धान्त' के नियमों को बिना संशोधन किये, लागू करना सम्भव नहीं रहा है। इस प्रकार, यहां आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य भिन्नता का एक स्पष्ट साधारण रूप होता है, क्योंकि घरेलू या आन्तरिक बाजारों हेतु राजकीय नीति को संचालित करने वाले उद्देश्य उन उद्देश्यों से सर्वथा भिन्न होंगे जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु राजकीय-नीति वा संचालन करते हैं। आन्तरिक नीति प्रायः राष्ट्रीय भावना पर आधारित होती है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-नीति में राष्ट्रीय भावनाओं के साथ ही साथ विश्व-भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ना है।

(५) बाजारों का विभाजन—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक एवं राजनैतिक घटक बाजारों के विभाजन को प्रभावित करने हेतु या एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रसाधनों के आवागमन का नियमन करते हैं। जब, प्रसाधनों के वृद्धि वस्तु में स्थानान्तरित की जा सकती है। लेकिन, चूंकि स्वयं वस्तुओं पर भी निपट्रण लागू हुये हैं, इसलिए वस्तुओं का स्थानान्तरण भी सुगम नहीं रह गया है। फलतः कीमत सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू नहीं रहने, बाजार विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक बाजार का आचरण भिन्न होता है। निस्सन्देह, परस्परगत कीमत-विभेद सिद्धान्त दो या अधिक विषयों वा और एक वस्तु वा विवेचन करता है, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह विषय अधिक जटिल होती हैं, जिस कारण अन्य घटकों को भी मॉडल (Model) में सम्मिलित करना पड़ता है। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

(६) विदेशी व्यापार में परिवर्तन—हमारा विश्व परिवर्तनशील अर्थ-व्यवस्थाओं वाला विश्व है। राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ ही साथ राष्ट्र आर्थिक आत्म-निर्भरता और स्वाभिमान में भी बढ़ गये हैं। इसका प्रमाण हमें अधिकतम देशों में आर्थिक विकास के लिए बनाई जा रही योजनाओं से मिलता है। ऐसी परिवर्तनशील परिस्थितियों के अन्तर्गत यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का पृथक् अध्ययन करें, तो इससे परिवर्तनशील घटकों और प्रवृत्तियों को समझना अधिक सुगम हो जायेगा। कारण, संरचनात्मक परिवर्तन (Structural changes) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सबसे पहले दिखाई दे जाते हैं।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विशिष्ट समस्याएँ—अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक विशिष्ट (Special) समस्याएँ भी हैं। यदि हम उक्त समस्याओं का अध्ययन आन्तरिक प्रवृत्तियों के अन्तर्गत विश्व-विकास-प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में करें, तो उन्हें अधिक सुगमता से हल कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता (International liquidity) की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विशिष्ट

समस्याओं का एक ज्वलन्त उदाहरण है। हम सब यह जानते हैं कि द्रवता के लिए माँग विनिमय कार्यों हेतु की जाती है। सट्टा और दूरदर्शिता अन्य दो उद्देश्य हैं। इनसे भी द्रवता के लिए माँग उदय होती है। आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सिद्धान्त लागू करते समय यद्यपि उद्देश्य समान होते हैं तथापि उनके परिणाम (Consequences) अलग-प्रलग होते हैं। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता सम्बन्धी माँग दो राजनैतिक घटक आर्थिक घटकों की अपेक्षा अधिक प्रभावित करते हैं, किन्तु यह बात एक आन्तरिक अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में उतनी सही नहीं है।

(८) वर्ग सम्बन्धी भेद (Difference as to group)—एक देश अपने आपको एक राजनैतिक इकाई के रूप में इस आधार पर संगठित करता है कि उसमें निवास करने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय एकता की भावना रखते हैं। इस विशाल राष्ट्रीय एकता या समूह के भीतर 'प्रादेशिक स्वाभिमान' के लिए भी सदैव स्थान रहता है किन्तु राष्ट्र पहले और प्रान्त या क्षेत्र पीछे होते हैं। निस्सन्देह जहाँ अनेक क्षेत्र होते हैं वहाँ भिन्नतायें भी अनेक होती हैं तथा ये राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखती हैं। किन्तु क्षेत्रीय भिन्नतायें अधिक से अधिक 'स्वरूप सम्बन्धी' होती हैं 'मूल सम्बन्धी' नहीं। इस दृष्टि से अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता यह है कि जबकि क्षेत्रों के मध्य व्यापार एक ही वर्ग के व्यक्तियों के मध्य का व्यापार होता है तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के मध्य, अथवा यों कहें कि विभिन्न प्रकार की एकता वाले वर्गों के मध्य का व्यापार है। फ्रीडरिक लिस्ट (Frederick List) के शब्दों में आन्तरिक व्यापार 'हम लोगों' के बीच में, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 'हमारे और 'उनके' बीच में होता है।¹

परीक्षा प्रश्न .

- 1 किन आवश्यक बातें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रीय और अन्तर्देशीय व्यापार से भिन्न हैं? क्या अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्-विभाजन पर आधारित विशिष्टीकरण विश्व व्यापार को अधिबल देने में सदा सहायक होगा? कारण सहित उत्तर दीजिये।

[In what essential way is the international trade different from the regional and inter-regional trade? Would specialisation on the basis of international division of labour

1 'Domestic trade = among us international trade = between us and them —Frederick List, quoted in C Kindleberger *International Economics*, p 10.

always lead to the maximisation of world trade ? Give reasons for your answer]

घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच जिन आधारों पर भेद किया जाता है उनका विवेचन करें। ऐसे भेद के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों को समीक्षा कीजिये।

[Discuss the grounds for the distinction that has been made between Home Trade and International Trade Examine the criticism that has been advanced against such a distinction]

अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य भेद कीजिये। क्या ये समान सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं ? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये।

[Distinguish clearly between Inter-regional and International Trade Are they governed by the same principles ? Illustrate your answer with examples]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार से कैसे भिन्न है ? स्पष्ट रूप से समझाइये।

[How is international trade different from inter-regional trade ? Explain clearly] (विक्रम, एम० ए०, १९६६)

‘अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा मात्र है।’ विवेचन कीजिए।

[‘The theory of international trade is nothing more than a special case of inter-regional trade ’ Discuss]

(इताहा०, एम० ए०, १९६६)

आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विभाजन

(Economic Self-sufficiency & International Division of Labour)

आर्थिक आत्म-निर्भरता एवं विदेशी व्यापार

सामान्यतः यह देखने में आता है कि एक देश कुछ वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है और बदले में कुछ अन्य वस्तुएँ एवं सेवाएँ आयात करता है। कोई देश निर्यात प्राय ऐसी ही वस्तुएँ करेगा, जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से अधिक हो, और आयात ऐसी वस्तुओं का, जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से कम हो। साधारणतः यह कह सकते हैं कि एक देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) होता है और ये प्रायः ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से अधिक है। इसी प्रकार, कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके उत्पादन में देश को तुलनात्मक हानि (Comparative disadvantage) होती है और वे प्रायः ऐसी वस्तुएँ हैं जिनमें आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की माँग से कम होता है। कुल पर, यह कहा जा सकता है कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि सभी वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भर हो।

विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में आत्म-निर्भरता का अंश—

कोई देश किस अंश तक आत्म-निर्भर है इसका अनुमान उस सीमा से लगाया जा सकता है जिस तक कि वहाँ उत्पन्न की जाने वाली वस्तुएँ और सेवाएँ आन्तरिक माँग को सन्तुष्ट करने में प्रयोग की जाती हैं। किन्तु आत्म-निर्भरता की यह परिभाषा बहुत सन्तोषजनक नहीं है। सच तो यह है कि यही आत्म-निर्भरता की एक-मात्र परिभाषा नहीं है, अन्य परिभाषाएँ भी हैं। किन्तु इस परिभाषा का महत्त्व इस तथ्य में निहित है कि अने ही अग्रगण्य एक अलग मात्रा में किये जाते हैं, किन्तु, अर्थ-व्यवस्था के लिए यदि वह आवश्यक हैं, तो देश को आत्म-निर्भर नहीं कहा जा सकता।

यदि उपरोक्त दृष्टिकोण से विचार किया जाय, तो यह कह सकते हैं कि विश्व में कोई भी अर्थ-व्यवस्था पूर्णतः आत्म-निर्भर नहीं है। सोवियत रूस में कुल वस्तुओं

और मेघाघो के २ या ३% भाग को छोड़कर कर शेष सबके उत्पादन की व्यवस्था देश के अन्दर ही की जाती है। इसी प्रकार से, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल उत्पादन का ४ से ५% तक का ही आयात किया जाता है। सविन इङ्ग्लैंड अन्य देशों पर एक बड़े अंश में निर्भर है। वह अपनी केवल ७५% आवश्यकताएँ ही आन्तरिक उत्पादन द्वारा सन्तुष्ट कर सकता है। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली में आन्तरिक उत्पादन कुल आन्तरिक माँग का ८०% है। बेल्जियम, डेन्मार्क और न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय उत्पादन का दो-तिहाई भाग स्वदेश में ही उपभोग किया जाता है। भारत अपने राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग ८ या १०% विदेश के अन्य देशों से आयात करता है। अन्य शब्दों में, उसका आन्तरिक उत्पादन स्वदेश की ९० से ९२% माँग को पूरा कर पाता है।

अर्थ-व्यवस्थाओं की आंशिक आत्म-निर्भरता का कारण—

यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रत्येक अर्थ-व्यवस्था अन्य देशों पर कुछ न कुछ सीमा तक निर्भर क्यों होती है? अन्य शब्दों में प्रश्न यह है कि वे कौन-कौन से घटक हैं जो किसी अर्थ व्यवस्था के पूर्ण आत्म-निर्भर बनने में बाधा डालते हैं? इन घटकों का मौलिक आधार (Fundamental basis) यह है कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन में एक देश तुलनात्मक लाभ रखता है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं में उसे तुलनात्मक हानि होती है। फलतः यह उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ प्राप्त है। यह तुलनात्मक लाभ कई घटकों के प्रभाव-स्वरूप उभरता है, जैसे—प्रौद्योगिक, राजनैतिक सीमाएँ, भौगोलिक विकास का स्तर आदि

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन (International Division of Labour)

विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण की प्रोत्साहित करने वाले मौलिक घटक—

जहाँ विभिन्न साधारणतः श्रम-विभाजन के कारण आवश्यक हो जाता है इसलिए विदेशी व्यापार तब प्रगट होता है जबकि श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का एक अनिवार्य परिणाम है।¹

श्रम-विभाजन के दो बहुत—यहाँ श्रम विभाजन के दो बहुतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है—प्रथमतः, उत्पादक निया को छोटे-छोटे भागों में बाँटा जाता है, जिससे कि प्रत्येक अधिक को जो कार्य करता है वह सुगमतापूर्वक और प्रभाव-

¹ "As exchange in general is necessitated by the division of labour, so foreign trade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers. It is the necessary consequence of an international division of labour"—R. F. Harrod: *International Economics*, p. 11

३. १। से सम्पन्न किया जा सके। दूसरे, उत्पादन व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाय कि जिन लोगों में कुछ प्रकार के कार्य करने की विशिष्ट क्षमताएँ हैं उन्हें अधिकतम सुयोग मिले।

यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि प्रत्येक देश में प्रायः लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, जब क्या वहाँ सम्पूर्ण उत्पादन-क्रिया को अनेक सुगम हिस्सों में बाँटते हुए उसे पृथक् पृथक् व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न कराने के लिए व्यक्तियों की इतनी कमी पड़ सकती है कि अन्य देशों के व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ जाय? एडम स्मिथ (Adam Smith) ने पिनी के निर्माण की क्रिया को १८ छोटी छोटी प्रक्रियाओं में बाँटा था। वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में हम इस समस्या को कई गुना कर सकते हैं। यदि विभिन्न वस्तुओं को इनकी विभिन्न किस्मों की सम्मिश्रता से, जिनका उपयोग आजकल समाज में किया जाता है, और प्रत्येक किस्म को इसके उत्पादन के लिए आवश्यक उप क्रियाओं की समस्याओं से मुक्त करें, तो यह देखेंगे कि मुश्किल (अर्थात् रोज़गारों की कुल समस्या) देश के व्यक्तियों की संख्या से कहीं अधिक है।

उपरोक्त प्रश्न पर एक अधिक थोड़ा दृष्टि से भी विचार किया जा सकता है—हमारी माँग सभी वस्तुओं के लिए समान नहीं है। यदि कार्यशील जनसंख्या को विभिन्न वस्तुओं के लिए हमारी माँगों के अनुपात में बाँटा जाय, तो यह सम्भव है कि किसी वस्तु के निर्माण के लिए, जिसके लिए माँग कुछ माँग का एक प्र-प्रति-शत ही है, सुरक्षित की गई श्रम-संख्या उस वस्तु के उत्पादन में सबसे मितव्ययिता पूर्ण श्रमविभाजन करने के लिए अपर्याप्त रहे। यदि किसी राष्ट्र की आत्म निर्भर होना है, तो उसके व्यक्तियों का एक बड़ा भाग प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में ही लगना चाहिए तत्पश्चात् जो श्रम-संख्या बचे वह अन्य उत्पादों के लिए अपर्याप्त हो सकती है। इसीलिए कुछ न कुछ अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन आवश्यक जाता है।¹

¹ 'Our demand for all commodities is not equal, if the working population were divided in proportions corresponding to our demand for various products, it is possible that the number earmarked for making some product the demand for which is a minute proportion of the whole, would not be sufficient to give the most economical division of labour in the making of that product. If a nation is to be self-sufficing, a large proportion of its workers must be engaged in making the main staple commodities, and the surplus left over for each of the various specialities might be inadequate, and so some international division of labour would be desirable'—R. F. Harrod - *International Economics*, pp 11-12

किन्तु यह एक बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का कारण नहीं हो सकता। इस हेतु हमें विभाजन के एक अन्य पहलू पर ध्यान देना होगा। यह पहलू उपयुक्त क्षमतायें रखने वालों को उपयुक्त कार्य पर नियुक्त करने की सुविधा से सम्बन्धित है। प्रत्येक राष्ट्र को केवल उसी वस्तु या वस्तुओं का उत्पादन करने दिया जाय जिन्हें वह सबसे सस्ता उत्पाद कर सकता हो।¹

“अर्थ-व्यवस्थाओं की पारस्परिक निर्भरता” के कारण—

अब हम उग कारखाने या घटकों पर प्रवाण डालेंगे जो कि उपरोक्त विशेष सुविधा के प्रादुर्भाव के लिए दायी हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं —

(१) प्राकृतिक साधनों का प्रभाव—प्राकृतिक प्रसाधन विशेष सुविधाएँ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जहाँ खाने पाई जाती हैं वही पर खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। इसका अर्थ है विदेशी व्यापार होना। कारण जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में खनिज स्थित हैं उन्हें उस खनिज के विनिमय में जिसका वे निर्यात करते हैं, किसी न किसी प्रकार की वस्तुएँ मिलनी चाहिए।

भूमियों की प्राकृतिक उष्णता भी देश देण में भिन्न भिन्न होती है। यह मिट्टी स्वयं में तो विदेशी व्यापार को जन्म देने की सामर्थ्य नहीं रखती, क्योंकि विश्व की जन सत्ता भूमि की उर्वरता के अनुपात में बँगी हो सकती है, जिससे उर्वर भूमियों को घनी जनसंख्या और कम उर्वर भूमियों को अल्प जन संख्या पोषण के लिए मिले। किन्तु वास्तविक जगत में जन सत्ता का वितरण इस प्रकार है नहीं हुआ है। अतः विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलना है।

जलवायु का सभी कृषि वस्तुओं और अनेक निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव के कारण अर्थशास्त्रियों ने जलवायु को भौगोलिक श्रम विभाजन में केन्द्रीय स्थान दिया है। जलवायु के दो प्रमुख ऋतु हैं—वर्षा और तापक्रम। उदाहरणार्थ, गेहूँ को सींचिए। इसके लिए वर्षा पर्याप्त हल्की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है किन्तु फल के जल्दी पकने के लिये घुट्ट जलवायु आवश्यक है। इसके विपरीत, नाबल सब ही पैदा किया जा सकता है जबकि वर्षा प्रचुरता से हो और पौधे की जड़ों से कुछ समय तक पानी बना रहे। इसी प्रकार वन उषज वर्षा के बाहुल्य वाले प्रदेशों में ही मिलती है। अनेक प्रकार की फसलों और वनस्पतियों के लिए ठण्डे और कम जलवायु की आवश्यकता पड़ती

1 'By hypothesis, however, this cannot be the cause of international division of labour on a big scale. And so it is necessary to look to the other aspect of the division namely, the convenience of setting those with special facilities to do the tasks for which they are most fitted. Let each nation produce that which it can produce most cheaply'—*Ibid*, p. 12

जलवायु के कारण ही बहुत ठण्डे प्रदेशों में केवल एक फसल प्रति वर्ष पैदा हो जा सकती है। इन जलवायु सम्बन्धी दशाएँ यह निर्धारित करती हैं कि कृषि-क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुएँ उत्पन्न की जायेंगी। उदाहरणार्थ, चाय केवल एशिया में ही उत्पन्न हो जाती है। चाय के कुल विश्व उत्पादन में भारत और लद्दा का पट भाग प्रमज्ज ४६% और ४१% है। लद्दा की ग्रन्थव्यवस्था से चाय का इतना (आत्महृत्स्वपूर्ण) स्थान है कि यह इसके कुल निर्यातों का ४८% भाग है।

बाँटा निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर भी जलवायु का प्रभाव देखा गया है। उदाहरणार्थ सूत कटाई उद्योग के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है, क्योंकि नम प्राञ्जलवायु सूत को बार-बार टूटने से बचाती है। उन उद्योग के लिए भी नम जलवायु आवश्यक है। जलवायु की उपयुक्तता के कारण ही इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग लकाशापर रोजगार में विकसित हो गया। उसेखनीय है कि बहुत गर्म या बहुत ठण्डा जलवायु

के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाती है क्योंकि बहुत ठण्डे जलवायु के प्रसंगत बार-बार लोगों को गरम रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है जबकि बहुत गर्म जलवायु के प्रसंगत कुलर लगाने पड़ते हैं ताकि वहाँ थर्मिको के लिए काम करने का वातावरण ठीक बना रहे। इन समस्याओं जलवायु वाले देशों में, जहाँ कि गरम या ठण्डा रखने की व्यवस्थाओं पर अधिक व्यय नहीं करवा पड़ता, उत्पादन लागत कम होती है, जिससे कि वे एक लाभप्रद स्थिति में आ जाते हैं।

वातावरण से जलवायु सम्बन्धी भिन्नताओं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालने वाला एक महत्वपूर्ण घटक समझी जाती रही है। उदाहरणार्थ, मसाले पूर्वी देशों से पश्चिमी देशों को भेजे जाते हैं, क्योंकि यूरोप की जलवायु मसालों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। नि सदेह आज भी जलवायु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालने वाला एक शक्तिशाली घटक है, किन्तु इसका प्रभाव कुछ वस्तुओं के उत्पादन में पहले की अपेक्षा कम हो गया है। उदाहरण के लिए, गेहूँ की एक विशेष किस्म का विकास कर लिया गया है जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसके पकने में कम समय लगता है। इसी प्रकार, जिन क्षेत्रों में सर्पा कम होती थी, वहाँ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था द्वारा खेती की पूर्ति करती गई है। यही कारण है कि पंजाब और राजस्थान के अनेक जिलों में, जहाँ पहले घटिया फसलें उत्पन्न हो जाती थी भासवा जल परियोजना के निर्माण के बाद, अच्छे फसलें उत्पन्न हो जाने लगी हैं। इसी प्रकार, वातानुबन्धन तकनीक (Air-conditioning technique) की सहायता से कुछ देशों में भी वस्त्र उद्योग प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

निष्कर्ष के रूप में, खाद्य पदार्थों की दशा में जलवायु का ही मुख्य प्रभाव पड़ता है, किन्तु निर्मित उत्पादों की दशा में उसका महत्त्व कम है। उत्पादन कार्य यही स्थापित (Locate) होने की प्रवृत्ति रखता है जहाँ जलवायु अनुकूल हो, क्योंकि जलवायु की अनुकूलता वस्तु की उत्पादन-लागत में कमी कर देती है। परि-

निष्कर्ष के रूप में, खाद्य पदार्थों की दशा में जलवायु का ही मुख्य प्रभाव पड़ता है, किन्तु निर्मित उत्पादों की दशा में उसका महत्त्व कम है। उत्पादन कार्य यही स्थापित (Locate) होने की प्रवृत्ति रखता है जहाँ जलवायु अनुकूल हो, क्योंकि जलवायु की अनुकूलता वस्तु की उत्पादन-लागत में कमी कर देती है। परि-

एक देश (यहवा क्षेत्र) अन्य देशों (या क्षेत्रों) की वही वस्तुएँ निर्यात करेंगे जिनमें उन्हें एक तुलनात्मक लाभ है। इस प्रकार, असमान क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का एक आधारभूत कारण है।

(२) विभिन्न देशों में साधन-सज्जाओं से सम्बन्धित भिन्नता—प्रकृति माता ने उत्पादक साधनों की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप में सम्पन्न नहीं बनाया है। यदि कुछ देशों में कुछ साधनों की पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो अन्य देशों में किन्हीं दूसरे साधनों का बाहुल्य है। यदि प्राकृतिक प्रसाधनों का वितरण समान रूप से हुआ होता, तो क्षेत्रीय या राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के लिए बहुत ही छोड़ा प्रसरण बचता। किन्तु प्रकृति ने जिस प्रकार से विश्व की रचना की है उसके अन्तर्गत यह देखा जाता है कि जिन देशों के पास प्राथमिक साधनों की पूर्ति अच्छी मात्रा में है वह उन प्रसाधनों के उपयोग से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन में एक तुलनात्मक लाभ रखते हैं। उदाहरणार्थ, प्रति व्यक्ति कृषि-भूमि आस्ट्रेलिया में २५८ एकड़ है, विन्तु भारत और जापान में क्रमशः ३२ एकड़ और ०४ एकड़ है। इसका अर्थ यह हुआ कि आस्ट्रेलिया में जन-संख्या कम और भूमि अधिक है किन्तु भारत और जापान में जन-संख्या अधिक और भूमि कम है। यद्यपि संपदा के वितरण में तो बहुत ही अधिक असमानता पाई जाती है। उदाहरणार्थ विश्व के तांबा भंडार का ८०% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उपलब्ध है। तेल प्रसार मध्य पूर्व के देश विशाल तेल क्षेत्रों के स्वामी बने हुए हैं। सम्भव है कि भविष्य में प्राकृतिक प्रसाधनों की तीव्र के प्रयत्नों के फलस्वरूप नये-नये भण्डार पता चें और देशों के मध्य साधन-सज्जा (Factor endowment) सम्बन्धी जो असमानता आज विद्यमान है वह और अधिक बढ़ जाय। यदि ऐसा हुआ, तो एक देश अन्य देशों पर निर्भर बना रहेगा।

(३) जन-संख्या का असमान वितरण—यदि प्रकृति माता ने पृथ्वी के सभी भागों में सभी चीजें समान प्रचुरता से प्रदान की होती तो भी जन-संख्या का वितरण जिस असमान रूप से हुआ है उससे विदेशी व्यापार बाधनीय बन गया है। कुछ उत्पादक-कार्य (जैसे—निष्कर्षण उद्योग extractive industries) प्राकृतिक प्रसाधनों के निष्पत्ति ही सम्पन्न किये जाने आवश्यक है। अन्य कार्य (जैसे—कच्चे मालों की निमित्त वस्तुओं में बदलना) इनसे दूर के स्थानों में भी संचालित किये जा सकते हैं। भूमि की तुलना में घनी जन-संख्या वाले देश स्वभाविक रूप से उन उत्पादन कार्यों पर अपने प्रचुरता वाले साधनों का प्रयोग करेंगे जिनमें भूमि के निकट संचालित करना आवश्यक नहीं है, और अपने द्वारा निमित्त उत्पादों का विनिमय किसी हुई जनसंख्या वाले देशों के कच्चे पदार्थों से कर लेंगे।^१

^१ 'Countries with a population dense in proportion to the capi-
(Contd on next page)

(४) मानवीय क्षमता में भिन्नता—जिस प्रकार भूमि की उर्वरता सर्वत्र समान नहीं होती है उसी प्रकार मानवीय क्षमता भी देश-देश में भिन्न-भिन्न होती है। यह भिन्नता हस्त-कौशल, वैज्ञानिक योग्यता, स्फूर्ति और साहस सम्बन्धी स्वाभाविक आनीय गुणों के कारण हो सकती है अथवा राजनैतिक एवं सामाजिक संरचना (Political and social structure) के कारण भी, जो कि स्वयं जातीय क्षमता का या ऐतिहासिक घटनाओं की सम्पूर्ण शृङ्खला का परिणाम होती है, मानवीय क्षमता में भिन्नता ला सकती है। अतः वे प्रक्रियाएँ, जिनमें वैज्ञानिक निपुणता या सङ्गठन क्षमता का, कुशलता-वृद्धि की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है, स्वभावतः ऐसे ही लोगों द्वारा अपनाई जानी चाहिए जिनमें कि उक्त गुण प्रचुरता से हों।¹

(५) बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता—विशिष्टीकरण के लिए यह कारण भी दायी है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन सघु पैमाने पर निपुणतापूर्वक सम्पन्न नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, यदि एक धमन-भट्टी (blast furnace) का पूर्ण उपयोग उठाना है, तो हमें १० लाख व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिये लोहा उत्पन्न करना चाहिए। एक कारखाने में साधारणतः दो या तीन भट्टियाँ लगाई जाती हैं। अतः एक लोहा एवं स्पात कारखाना २० से ३० लाख व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त स्पात का उत्पादन कर सकता है। ऐसी बड़ी फैक्ट्री की स्थापना के लिए विशिष्टीकरण अपनाना आवश्यक हो जाता है। अतः सम्भव है कि कुछ बहुत छोटे देश (जैसे—केन्या, जर्मैका या पाराग्वे) इतने विशाल कारखाने स्थापित न करे और अपने सघु कारखाना के उत्पादन वाले अन्य देशों से लोहे का सामान आयात करना अधिक उचित समझे।

(६) जनसंख्या का पेशेवर वितरण—विभिन्न देशों में जनसंख्या के पेशेवर (Occupational distribution) से सम्बन्धित प्राँवड़े यह कहते हैं कि कुछ देशों में जनसंख्या का एक बहुत ऊँचा अनुपात प्राथमिक उद्योगों में सलग्न है। उदाहरणार्थ, भारत में लगभग ७०% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। ऐसी दशा में वहाँ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि का पेशीकरण नहीं किया जा

city of the soil would naturally employ their surplus on the processes which do not have to be undertaken in conjunction with the soil and exchange manufactured goods for the raw products of more sparsely peopled regions"—Harrod *International Economics*, p 13

- 1 "Process in which scientific skill or the capacity for conducting great collaborative enterprises—production on a large scale—count for more in increasing efficiency should naturally be undertaken by the peoples more highly endowed with these qualities"—Harrod *International Economics*, p 13.

सकता। यदि ऐसा किया जाय, तो बड़े पैमाने पर बेकारी फैलने का भय है, जिससे अपने व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरा में पड़ सकता है। घन श्रमिक श्रमिका प्रयोग वाली विधियाँ (Labour intensive methods) ही काम में लाना भारत के लिए एक उचित नीति होगी। इसी चटक के कारण विशिष्टीकरण को अपनाना भी सामाजिक दृष्टिकोण से वांछनीय न होया, क्योंकि रोजगार की य-श्रीकरण पर प्राथमिकता (Priority) मिलनी ही चाहिए। दूसरी ओर ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँ जन शक्ति का प्रभाव अनुभव किया जा रहा है। इन देशों में विशिष्टीकरण बढ़ाया जा सकता है और ऐसी बस्तुओं के उत्पादन में, जिनमें देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, विस्तृत श्रम विभाजन प्रवर्धित किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, इंग्लैंड केरी पदार्थों (Dairy products) का उत्पादन रेन्गाक की अपेक्षा कम लागत पर कर सकता है किन्तु फिर भी वह इन्हें डेन्मार्क से आयात करता है। इसका कारण यह है कि इंग्लैंड में जलमत्तया घोंडी है और इसलिए श्रम-साधन का प्रयोग अधिक उष्ण देश-समूहों में सामुदायिकता के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण कुछ सीमा तक जनसंख्या के पैकेज वितरण से निर्धारित होता है।

(७) भूतकालीन सचय—यह सम्भव है कि भूतकाल में हुये विकास कार्य के फलस्वरूप किसी राष्ट्र को वर्तमान समय में साज-सामान (जैसे—रेल्वे, कारखाने, कुशल सफ़ाई, विशिष्ट ज्ञान, उपयोगी आदतें आदि के रूप में) का महत्त्व सचय प्राप्त हो, जिससे कुछ प्रकार के उत्पादन कार्यों के लिए उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में भी देश को विशेष सुविधाओं प्राप्त होने लगती हैं और वह विशिष्टीकरण कर लेता है।

(८) प्रसाधनों का उपयोग—निम्नलिखित प्रकृति ने प्रत्येक देश को उत्पत्ति के समस्त प्राथमिक साधनों का समान बोट (Quota) प्रदान नहीं किया है, जिस कारण (अर्थात् साधन-संख्या की भिन्नता के कारण) विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। किन्तु, इस असमान वितरण के प्रभाव की, प्रचुर साधनों के अधिकधिक प्रयोग और शून्य साधनों के मितव्ययितापूर्ण प्रयोग द्वारा कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन देशों में, जहाँ भूमि-साधन प्रचुर मात्रा में और श्रम साधन न्यून मात्रा में हैं, वहाँ श्रम की कमी को कुछ सीमा तक भूमि पर पूँजी के अधिक प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है, और जहाँ श्रम साधन प्रचुर मात्रा में तथा भूमि साधन न्यून मात्रा में हैं, वहाँ श्रम-साधन के अधिक प्रयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक देश को अपने उत्पादक-साधनों का पूर्णतम उपयोग करने हेतु अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट तकनीकों (Specialized techniques) का विकास करना पड़ेगा।

उत्पत्ति के लिए विभिन्न साधनों के राशिय (Combination) की आवश्यकता पड़ती है। किसी उद्योग में जो संयोग अपनाया गया हो उसमें विभिन्न साधनों के

उद्योगों को बदलना सम्भव है। किन्तु ऐसा प्रतिस्थापन (Substitution) एक सीमा तक ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मिट्टी में पेट्रोल निकालने के लिये एक निपट देश में प्रापिक धन का उपयोग किया जा सकता है किन्तु इतने पर भी पूर्ण और साज-सामान का कार्य पूर्ति के लिये दक्षेष्ट मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा। धन को एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इस सीमा के आगे धन की वृद्धि अक्षय्यपूर्ण होती है। इस प्रकार की सीमाओं (Limitations) से भी भौगोलिक विशिष्टीकरण के लिए प्रेरणा मिलती है और कमस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ हो जाता है।

(१) वातायाम व्यवस्था—जहाँ तक उद्योगों विशेषण निर्माण उद्योगों के स्थिति चयन (Location) का सम्बन्ध है भौगोलिक विशिष्टीकरण के लिए वातायाम व्यवस्था का बहुत महत्त्व है। इस वातायाम को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—जहाँ में वृक्ष गिराये जाते हैं। उत्पत्त्यात् वातायामें और वस्ते काटे और तोड़े जाते हैं। विभाजन घट मन्त्रों और रत्नीपरी में परिवर्तित किये जाते हैं और लकड़ी स्लीपरी और तानों के रूप में ही वातायाम की जाती है, ताकि उनसे पर्नीयर, बसों के छाने, रेलों के छाने आदि बनाये जा सकें। वृक्षों से स्लीपरी के बनाने की प्रवृत्ति में बहुत सा भार (Weight) कम हो जाता है। इससे स्लीपरी के वातायाम में मितव्ययिता हो जाती है। नियम यह है कि उत्पादन की प्रारम्भिक दशाओं में भार की हानि अधिक होती है किन्तु बाद की प्रत्येक अवस्था में ऐसी हानि कम होती है। उत्पत्ति का एक प्रमुख नियम यह है कि उत्पादन की अनिम अवस्था बाजार के अधिक से अधिक निकट स्थापित होनी चाहिए। इस प्रकार, भौगोलिक इकाइयों का स्थान निश्चित करते समय वातायाम व्यवस्था को उचित महत्त्व देना आवश्यक है। उद्योग का स्थिति-चयन ही तब आवश्यक बह जायेगा जबकि वातायाम व्यवस्था कम से कम हो जाय। भौगोलिक विशिष्टीकरण साधन सम्मानों की भिन्नताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह स्वयं भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति के 'कारण' का कार्य करता है।

विशिष्टीकरण को बढ़ावा देने वाले उपर्युक्त घटकों का मिला-जुला प्रभाव ही किसी देश में वस्तु विशेष की उत्पादन-लागत को निर्धारित करता है। चूँकि ये घटक देश-देश में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वस्तु की लागत भी विभिन्न देशों में विभिन्न होती है और यह लागत-भिन्नताये (Differences in Comparative Costs) ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है।

“अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन के आधार पर एक विशिष्टीकरण के द्वारा विश्व व्यापार का अधिकतम हो जाना आवश्यक नहीं है”

(“Specialization on the Basis of International Division of Labour may not necessarily lead to Maximisation of World Trade”)

जसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कच्ची सामग्रियों, शक्ति और धन के

रूप में प्राकृतिक साधन इस प्रकार विखरे हुए हैं कि कुछ देशों में कुछ वस्तुओं के अतिरिक्त सभी वस्तुएँ लगभग सब देशों में उत्पन्न की जा सकती हैं। किन्तु वास्तविक जीवन में हम प्रत्येक देश की अपनी आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएँ बनाते हुए नहीं देखते। एवं देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में जिन्हें उत्पन्न करने के लिये उसके पास आवश्यक प्रसाधन सस्ती कीमतों पर और प्रचुरता से उपलब्ध हैं, विशिष्टता प्राप्त करता है। इसी से उसका उत्पादन अन्य अन्य देशों में वैसी ही वस्तु के उत्पादन व्ययों से कम रहता है। यह लागत भिन्नता (Cost Difference) ही विशेषीकरण का साधारण है। यही देश वही वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं जिनमें उनको एक तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) होता है और बदले में विदेशों से उन वस्तुओं को जिन्हें वे अपने यहाँ अधिक लागत पर ही उत्पन्न कर सकें, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित होते हैं और जिस-जैसे धर्म विभाजन की प्रगति होती है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ने लगता है।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी धनाभा में लाभ होना आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, जैसा कि मार्शल (Marshall) ने सकेन किया है, यदि निर्यात-वस्तुएँ उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जा रही हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार लाभदायक न होगा। कारण, जब निर्यात वस्तुएँ उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पन्न की जाती हैं तो उत्पादन व्यय बढ़ने लगते हैं, जिससे व्यापार से मिलने वाले लाभ घटने लगता है, निर्यात में भी कमी होने लगती है और अन्ततः वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है।

उत्पत्ति साधनों की गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय के लिये मुख्य रूप से दायीं

("International Trade arises primarily due to a Lack of Mobility in the Factors of Production")

हम यहाँ पूर्व ही बता चुके हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रायः एक राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र जन-समुदाय को सूचित करने हेतु किया जाता है। लेकिन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में, इस शब्द से आशय एक स्वतन्त्र आर्थिक इकाई (Independent economic unit) का है। [आधुनिक अर्थशास्त्रियों, जैसे ओहलिन और टर्कन ने यह सुझाव दिया है कि 'राष्ट्र' शब्द के दोहरे अर्थ से उदय होने वाले किसी भ्रम की समाधान से बचने के लिए 'राष्ट्र' शब्द के स्थान में 'क्षेत्र' (Region) शब्द का प्रयोग करना चाहिये। अतः हम "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार" के बजाय "अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार" की चर्चा करते हैं।]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देने वाले कारण के बारे में प्रतिष्ठित मत—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का

बुनियादी कारण उत्पत्ति-साधनों में विभिन्न देशों में बीच गतिशीलता का अभाव होना है। उनका यह दृष्टिकोण या बिश्व और पूँजी एक ही देश में एक जिले से दूसरे जिले को तो स्वतन्त्रतापूर्वक आते-जाते हैं किन्तु विभिन्न देशों के मध्य नहीं आते-जाते। विभिन्न देशों में मध्य साधनों की गतिहीनता के अनेक कारण हैं। सच तो यह है कि विदेशों में ऊँची मजदूरी मिलने पर भी अधिक अपने देश से बाहर जाने को तैयार नहीं होते। उनकी यह हिचकिचाहट भाषा, रुढ़ियों, धर्म, प्रशासी नामाशिक एवं राजनैतिक जीवन आदि में भिन्नताओं के कारण है। पूँजी के आवागमन के बारे में भी वही बात सच है। लोगों की अविश्वास, अनभिज्ञता, पूँजी के आवागमन में निहित जोखिम और कानूनी प्रतिबन्ध राष्ट्रीय इकाइयों के मध्य पूँजी के प्रवाह को रोकते हैं।

देशों के मध्य उत्पत्ति-साधनों की अपेक्षा अधिक गतिहीनता (Immobility) प्रतियोगिता के महत्त्व को कम कर देती है। अन्य शब्दों में, साधनों की एक देश से दूसरे देश को गतिहीनता का कारण प्रतिस्पर्धा का अभाव रहना है। प्रतियोगिता के फलस्वरूप समान वस्तुओं की उत्पादन-लागतें देश भर में समान रहने की प्रकृति रखती हैं। किन्तु इसके अभाव में समान वस्तुओं की उत्पादन लागतें देश-देश में भिन्न हो जाती हैं और यह लागत-भिन्नताएँ ही स्वतन्त्र देशों के मध्य व्यापार को जन्म देती हैं। इस प्रकार, विभिन्न देशों के मध्य साधनों की गतिहीनता प्रतियोगिता पर अपने प्रभाव के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय व्यापार के उदय में सहायक बनती है।

प्रतिष्ठित दृष्टिकोण का समर्थन और विरोध—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के उपरोक्त दृष्टिकोण की बहुत आलोचना हुई है। प्रमुख आलोचनाएँ, जो बि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने की हैं, नीचे दी जाती हैं —

(१) अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिये प्रसाधनों का असमान वितरण बुराई है, साधनों की गतिहीनता नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण की प्रथम आलोचना यह है कि अन्तराष्ट्रीय व्यापार के उदय का कारण साधनों की गतिहीनता नहीं है, बरन् यह है कि विश्व में प्राकृतिक साधनों का वितरण असमान रूप से हुआ है।

यदि हम इस आलोचना का सावधानी से विश्लेषण करें, तो पता चलेगा कि यह प्रतिष्ठित मत का समर्थन करता है विरोध नहीं। प्राकृतिक प्रसाधनों के असमान वितरण की समस्या आज हमारे सामने इसीलिये तो है कि वे प्रचुरता के स्तरों में अभाव के स्तरों में नहीं जा सकते। यदि उनमें गतिशीलता होती, तो प्राकृतिक साधनों के असमान वितरण की समस्या उदय नहीं हो सकती थी। वितरण की असमानता इस दृष्टिकोण की पुष्टि करती है कि गतिशीलता का अभाव ही अन्तराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख स्रोत है।

(२) एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य और विभिन्न देशों के मध्य गतिशीलता सम्बन्धी भेद अंतरों का है गुण का नहीं। अ-प्रतिस्पर्धी समूहों (Non-

competing groups) की स्थिति केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही पाई जाता हो, ऐसा नहीं है। एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा-रहित समूह विद्यमान होते हैं। एक ही देश के अन्दर विभिन्न व्यापारों और विभिन्न भागों में मजदूरियों के विशाल अन्तर देखने में आते हैं। इन अन्तरों के लिये साधनों की गतिहीनता बायी है। क्या हम नहीं देखते कि मद्रासी परिवारों को पञ्जाब जाने में और पञ्जाबी परिवारों को मद्रास जाने में सकोच होता है? स्पष्टतः, साधनों की प्राकृतिक गतिशीलता "पूर्ण" नहीं है। माघ ही, माघनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिहीनता भी 'शून्य' (Zero) नहीं होती है। उदाहरण के लिये, क्या लोग बेजिम्पन प्रोर स्पेन से, भीमार्म पार करके, फ्रांस में नहीं आने रहते हैं? क्या पूँजी विशाल मात्रा में अमेरिका से तर्ष-विकसित एशियाई देशों की नहीं गई है? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Industry and Trade में मार्शल (Marshall) ने उद्योगों द्वारा कच्चे माल प्राकषित करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार, एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य और विभिन्न देशों के बीच साधनों की गतिशीलता में केवल 'अंश' (Degree) का ही भेद है 'गुण' (Kind) का नहीं।

उपर्युक्त आलोचना के उत्तर में प्रतिष्ठित सिद्धान्त के समर्थकों का कहना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को भी उक्त तथ्य का ज्ञान था। उदाहरणार्थ, एडम स्मिथ (Adam Smith) ने प्रवास (Emigration) के महत्त्व पर बल दिया था और मिल (Mill) ने भी यह स्वीकार किया था कि पूँजी अधिक गतिशील हो गई है और इसका स्वभाव अन्तर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। इन पर भी आलोचना में कुछ तथ्य की कमी है, जिससे हटकर नहीं किया जा सकता, विशेषतः वर्तमान युग में, जबकि विश्व के देशों के मध्य राजनैतिक सम्बन्ध विघटे हुए हैं। प्राञ्जल हम देखते हैं कि लगभग सभी देशों ने प्रवास सम्बन्धी नियम (Immigrations regulation) बना दिये हैं, जो बाह्य श्रम के प्रवेश को रोकते हैं। पूँजी के सम्बन्ध में भी ऐसा जाना है कि किन्हीं देशों में व्याज दर ऊँची है तो किन्हीं देशों में नीची। विश्व के विभिन्न देशों में व्याज-दरों की प्रसमानता इस बात का ठोस साक्ष्य है कि पूँजी ग्लोबल व्याज दर वाले देशों से ऊँची व्याज दर वाले देशों में जाने के लिए प्रवृत्त है। यह अनिच्छा भौतिक श्रमाग्री की अस्थिरता, पूँजी के निर्माण पर नैतिक-मार्ग के प्रतिबन्ध, राष्ट्रीयकरण की वृद्धि में क्षतिपूर्ति न मिलने का सत्य और विदेशियों के प्रति अनिश्वास की भावना आदि के कारण है। संक्षेप में, साधनों की गतिहीनता सम्बन्धी प्रतिष्ठित धारणा आज जितना अधिक सत्य है उतनी पक्ष कमो नहीं थी।

(३) उत्पत्ति-साधनों में गतिशीलता का अभाव होना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय होने का एक बर्थात स्पष्टीकरण नहीं है। सच तो यह है कि अन्य घटक भी (जैसे—करवियों की मिसला, भौतिक नीति का स्वतन्त्र रूप से निर्धारण आदि) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। किन्तु न्याय की दृष्टि से यह स्वीकार

करना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य घटकों की भूमिका को भुलावा नहीं था ।

इस प्रकार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की त्रुटि यह स्वीकार करने में निहित थी कि केवल साधनों की गतिहीनता मात्र ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का कारण है । इस मान्यता के ही कारण उनकी उचित और अनुचित आलोचनाएँ हुई हैं । सत्य यह है कि उत्पत्ति साधनों में विभिन्न देशों के मध्य गतिशीलता का अभाव होना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय का 'एक' (न कि एकमात्र) कारण है ।

वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का औचित्य (Rationale for International Exchange of Goods and Services)

अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का औचित्य सम्बन्धित पक्षों द्वारा व्यापार से पारस्परिक लाभ उठाने में निहित है । एक निश्चित साम के अभाव में, कोई भी दो पक्ष (चाहे वे दो व्यक्ति हो या दो देश) विनिमय सम्बन्धी किसी भी समझौते में सम्मिलित होना पसन्द नहीं करेंगे । दोनों पक्षों को पारस्परिक लाभ (Mutuality of advantage) होना यह स्पष्ट करता है कि कयो देश अपनी कुछ उत्पादित वस्तुओं का अन्य देशों की उत्पादित वस्तुओं के साथ विनिमय करने के लिए तैयार हो जाते हैं । 'लाभ' शब्द में अनाधिक और अधिक दोनों ही प्रकार के लाभ सम्मिलित हो सकते हैं । अतः यहाँ हम केवल आर्थिक लाभ के स्पष्टीकरण पर ही ध्यान देंगे ।
आर्थिक लाभ का स्वभाव—

लाभ की पारस्परिकता का प्राणिक कारण यह है कि देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ऐसी वस्तुएँ भी प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें अपने यहाँ उत्पन्न करना उनके लिए या तो सम्भव नहीं था अथवा लाभप्रद नहीं था । सभी देश सभी वस्तुएँ, जो कि उनकी जनसंख्याएँ उपभोग करती हैं, उत्पन्न करने के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं होते हैं, और इसलिए ऐसी वस्तुएँ, जो या तो निकटतम भी उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं अथवा केवल बहुत ऊँची लागत पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं, निर्दानों के बर्तन में प्राप्त करनी पड़ती हैं । राष्ट्रों के सम्पूर्ण इतिहास में, कुछ सक्षिप्त समयावधियों को छोड़ कर वह भी राजनैतिक व्यापार पर, अन्य दशाओं में पूर्ण आत्म-निर्भरता पर कभी भी अमल नहीं किया गया है ।

तुलनात्मक उत्पादन लागत—

प्रत्येक देश प्रायः उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने का योग करता है जिन्हें कि वह अपने निज के माध्यम-माध्यार और तत्सम्बन्धी लागत मरचना को ध्यान में रखते हुए न्योत्तम क्षमता रखना हो । विभिन्न देशों के पास विभिन्न मात्राओं और गुण वाले उत्पादन साधन (भूमि, श्रम, पूँजी, सज्जन और साहस) होते हैं । अतः विशिष्टीकरण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि वीज भी वस्तुएँ न्यूनतम तुलनात्मक लागत पर बनाई जा सकती हैं । प्रायः उन वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम तुलनात्मक

लागत पर किया जा सकता है जिनकी उत्पादन लागत का एक बड़ा अनुपात वहाँ प्रचुरता से पाये जाने वाले साधन के प्रयोग से सम्बन्धित हो।

उदाहरणार्थ, भारत को ही लीजिए। हमने छूट, जाग, मिलहन और अन्य कृषि-पदार्थों के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया है। क्यों ? हमका कारण बिल्कुल सीधा-सादा है। उसकी प्राकृतिक साज-सज्जा (जलवायु, भूमि आदि) इन फसलों के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार, ब्रिटेन में औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण किया है, क्योंकि उसके साधन-सम्पदा (जमीन, निपुणता, मजदूर एवं जनिज प्रसाधन) इन वस्तुओं का उत्पादन करने में बहुत ही सुविधाजनक है। इन परिस्थितियों में, भारत और ब्रिटेन वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक विनिमय द्वारा लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि भारत ब्रिटेन से औद्योगिक वस्तुओं और ब्रिटेन भारत से कृषि-उत्पाद मगाता है।

सर्वाधिक लाभ कौन प्राप्त करता है ?

निम्नलिखित दोनो ही देश अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय से लाभ उठाने हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि कौन देश सबसे अधिक लाभ उठाता है अथवा कितनी मात्रा में विनिमय किया जाता है ? तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त हमें केवल इतना ही बताता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय क्यों किया जाता है। वह इस बात को बताने में असमर्थ है कि कितनी मात्राओं में तथा किस कीमत पर विनिमय होगा। उत्पादन-लागत कीमत की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है, किन्तु व्यापार की वास्तविक शर्तें (Actual terms of trade) एक दूसरे की वस्तुओं के लिए माँग और पूर्ति की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है। अन्य शब्दों में, कितनी मात्रा में विनिमय किया जायेगा यह इस बात पर निर्भर होगा कि कितना शुद्ध लाभ अर्जित होता है और शुद्ध लाभ की मात्रा व्यापार की शर्तों पर निर्भर होती है।

‘लागत’ शब्द के विभिन्न अर्थ—

भीचे हम उन विभिन्न अर्थों पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें कि ‘उत्पादन-लागत’ वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है :—

(१) **मौद्रिक लागत (Money Cost)**—सभी मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में लागत की गणना मुद्रा के सम्बन्ध में की जाती है, क्योंकि यह किसी वस्तु की उत्पादन लागत की गणना करने का सबसे सुगम ढंग है। तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त बताता है कि प्रत्येक देश वही वस्तुएँ उत्पन्न करेगा, जिनमें उसकी मौद्रिक लागत न्यूनतम आवे। चूंकि विभिन्न देशों में विभिन्न करदियॉ चलती हैं, इसलिए भोसत लागतों की एक साम्य विनिमय-दर के आधार पर ही तुलना करना सम्भव है। लेकिन, जब तक दोनो अर्थव्यवस्थाएँ एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन न करे, तब तक भोसत लागतों की तुलना का प्रश्न ही नहीं उठता एवं दो विभिन्न वस्तुओं की भोसत लागतों की तुलना करना व्यर्थ है। अतः मौद्रिक लागतें तुलनात्मक उत्पादन-लागत का एक भ्रूरा सूचक (Rough index) हैं।

(२) साधन-लागत (Factor Cost)—स्वयं भौतिक लागत का निर्धारण उत्पात्ति के विभिन्न साधनों (भूमि, श्रम, पूँजी, संगठन और साहम) को दिये जाने प्रमाणित पुरस्कार द्वारा होता है। उत्पात्ति के साधनों के पुरस्कार किसी साधन की पूर्ति की तुलना में उसकी माँग पर निर्भर होने हैं। अतः लागत-संरचना (Cost structure) यह पता चल सकता है कि कौन-सा साधन अधिक प्रयोग किया जा रहा है। यदि (A) किसी वस्तु के उत्पादन में एक ऐसे साधन का, जो कि बहुत दुर्लभ (Scarce) है, अतिरिक्त अधिक प्रयोग किया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि लागत बहुत बढ़ जायेगी। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि इंग्लैंड जूट का उत्पादन करने लगा है। इसके लिये उसे अतिरिक्त लागत, यजवूरी और अन्य प्रासंगिक व्यय (Incidental costs) चुकाने पड़ते हैं। चूँकि जूट को उत्पादन-लागत का अधिकतम भाग भूमि और श्रम के सम्बन्ध में किया जाता है, इसलिए इंग्लैंड के लिए मौसम लागत उससे कहीं अधिक होगी जो कि वास्तविक व्यय के रूप में है। देश में पूँजी की अधिकता होने के कारण ब्रिटेन को विनियोग-पूँजी नीची व्याज दरों पर मिला जायेगी। किन्तु वहाँ कृषि योग्य भूमि और श्रम का अभाव है, अतः वह भूमि या श्रम साधन विधियों का प्रयोग नहीं कर सकता। स्पष्टतः, उसे अपने को ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में, जिनके लिए प्रचुर भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है, नहीं फँसाना चाहिये। यही तर्क भारत को भी, यदि वह ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करे जिनके लिये देश में दुर्लभ साधनों की प्रचुर पूर्ति चाहिए, लागू होता है।

(३) अवसर-लागत (Opportunity Costs)—अवसर-लागतों का अभिप्राय उन विकल्पों का है जिनमें उत्पात्ति-साधनों के एक विशेष क्षेत्र में ही प्रयोग करने के कारण छोड़ देना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में इन्हें प्रयोग करना अन्य क्षेत्रों में प्रयोग न करना है। इन्हीं को छोड़े हुए विकल्प (Alternatives foregone) कहते हैं। यदि ब्रिटेन जूट के उत्पादन का प्रयास करे, तो छोड़े हुये विकल्पों के रूप में उसकी अवसर-लागत इतनी अधिक होगी कि जूट का उत्पादन उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकेगा। यदि वे ही साधन किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करने में प्रयोग किये जायें, तो उसकी उत्पादन-लागत बहुत ही न्यून हो सकती है तथा उस वस्तु के बदले वह भारत से जूट को मुक्ततापूर्वक माँगा सकता है।

स्पष्टतः तुलनात्मक लागत के आधार पर उत्पात्ति-साधनों को सर्वोत्तम प्रयोग में लाया जा सकता है और फिर कुछ नियतों के बदले में आयात करके परस्पर लाभ उठाया जा सकता है। अगले खण्ड में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है।

परीक्षा प्रश्न :

१. विश्व-व्याप्यवस्थायें अपनी आर्थिक क्रियाओं के सम्बन्ध में एक दूसरे पर निर्भर क्यों होती हैं ? कारण बताइये ।
२. "चूँकि विनिमय साधारणतः श्रम-विभाजन के कारण आवश्यक हो जाता है, इसलिए विदेशी व्यापार तब प्रगट होता है जबकि श्रम-विभाजन, राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है ।" विवेचन कीजिये ।
३. "उत्पत्ति साधनों की अतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय के लिए मुख्यतः दायी है ।" विवेचन करिये ।

[International Trade arises primarily because of the lack of mobility in the factors of production " Discuss]

(आगरा, एम० कॉम०, १९६९)

४. आपकी सम्मति में वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का प्रीविल्य क्या है ?
५. अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आर्थिक आधार क्या है ? विवेचन कीजिये ।

[What is the economic basis of international and inter-regional trade ? Discuss]

(विक्रम, एम० ए०, १९६९)

द्वितीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धा-

THE PURE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE

।धानों के विचार—

१) नर्कसे (Nurkse) — 'निम्नदेह व्यापार के खुल जाने से एक आदिम धन-व्यवस्था को विशाल लाभ हो सकते हैं, किन्तु क्या इस बात की कोई गारण्टी है कि तत्पश्चात् केवल व्यापार द्वारा ही एक ऐसा विकास दर मुलभ हो जायेगी जिसे देश में (उदाहरणार्थ) जन गस्या की वृद्धि या विदेशों में प्रचलित जीवन स्तरों के सम्पर्क में सन्तोषजनक ममका जा सके ? स्पष्टतः ऐसी कोई गारण्टी नहीं है विशेषतः ऐसी दशा में जबकि निर्यात-उत्पादों के लिये, जिन्हे देश में ही उत्पन्न करने पर तुलनात्मक लाभ मिदान्त होर देता है बाह्य माग (अ) कीमत की दृष्टि से सामान्यतः लोचनीय हो और "ससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि (ब) "सबे (बाह्य माग के) कुल परिमाण में मन्व गति से वृद्धि हानी हो। अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के समस्त लाभ ठीक होते हुए भी वहाँ गतिरोध और तुलनात्मक स्थिरता या निश्चेष्टता की सम्भावना है।"

[There is no doubt that the opening up of trade can bring very sizable gains to a primitive economy but is there any guarantee that trade alone will thereafter cause a rate of growth that can be regarded as satisfactory in the light, for instance of population increase at home or the living levels prevailing abroad ? There is no such guarantee especially if the export products—which the comparative-advantage principle forces a country to produce—face an external demand which (a) is generally inelastic with respect to price, and (b) what may be more important shows only a sluggish rate of increase in total volume. Granted all the advantages of international specialization, there remains a possibility of deadlock and comparative stagnation "]

क्लेरमोंटे (Clairmonte)— 'अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन ने ऐतिहासिक प्रतिद्वन्द्वित विकास व्यवस्था में कुछ देशों की आर्थिक सम्पत्तियों को उपयोग के अनुपयुक्त बना दिया है। कम विकसित भागों में एक गतिवान शक्ति बनना तो दूर रहा। उसने प्रायः मुस्थापित राष्ट्रीय रूप से सङ्गठित वर्रे औद्योगिक देशों के हित में ही कार्य किया है। '

['International specialization has brought in its train a free-
zing of the economic endowments of a given country at a
certain historically conditioned stage of development. Far
from constituting a dynamic force in the less developed areas
it has operated in the interests of the larger, nationally integ-
rated and better established industrial communities "]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास

(Development of the Theory of International Trade)

परिचय—एडमस्मिथ द्वारा स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन

जैसा कि हम अध्याय २ में बता आये हैं यह एडम स्मिथ ने जिन्होंने स्वतन्त्र व्यापार (Free Trade) का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। वास्तव में उनके समय में परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि स्वतन्त्र व्यापार पर बल देना आवश्यक हो गया। जैसे—व्यापारबादी नीतियों (Mercantilist policies) के दुष्परिणामों में विश्व तड़प आ गया था और लॉक (Locke) ह्यूम (Hume) एवं निर्वाचावादियों (Physiocrats) ने एक स्वतन्त्र प्रणाली के लिए उचित दार्शनिक आधार बना दिया था। किन्तु स्मिथ का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने अर्थिक प्रसाधनों के सर्वोत्तम वितरण के लिए स्वतन्त्र व्यापार को उपयुक्त बताया। उन्होंने यह दिखाने का भारी प्रयत्न किया कि यदि व्यक्ति को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने दिया जाय, तो वह अपने प्रसाधनों की अधिक प्रभावपूर्ण ढङ्ग से उपयोग में ला सकता है किन्तु सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने की दशा में इतना प्रभावपूर्ण प्रयोग सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राष्ट्रों के मध्य प्रसाधनों के वितरण से सम्बन्धित लाभ कम हो जाते हैं।

(1) लागतों की भूमिका (Role of Costs)

रिकाडों का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त—

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रिकाडों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में एक सर्वमान्य आधुनिक सिद्धान्त प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। कुछ लेखकों ने, जैसे कि शुम्पीटर (Schumpeter) ने, रिकाडों के योगदान के महत्त्व को घटाने और उसके पूर्ववर्तियों के महत्त्व को बढ़ाने का यत्न किया है। निःसन्देह रिकाडों के पूर्व टीरेन्स (Torrens) ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त प्रचलित किया था, किन्तु इस सिद्धान्त को, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का आधार है, सबसे अधिक स्वीकृति दिलाने में सफलता रिकाडों ने ही पाई। अत्यन्त दुर्गम किन्तु अवास्तविक मान्यताओं के अन्तर्गत रिकाडों ने यह दिखाया कि दो देश, जिनमें से प्रत्येक दो वस्तुओं उत्पन्न करता है, व्यापार से, यदि वस्तुएं पैदा करने की सापेक्षिक

जागने दोनो देशो में भिन्न-भिन्न हैं तो लाभ उठा सकते हैं। वे तब भी लाभ उठावेंगे जबकि दोनो में से किसी एक देश में निरपेक्ष उत्पादन लागतें (Absolute cost of production) दोनो ही वस्तुओं के लिए कम हों।

१। डॉ. की अवास्तविक मान्यतायें—

रिकाडों के सिद्धान्त की अवास्तविक मान्यताओं को हटाने के लिए प्रगते १२५ वर्षों में जितने प्रयत्न किये गये वे उन प्रयत्नों से अधिक थे जो कि उस सिद्धान्त को छोड़ने हेतु किये गये। प्रायः शब्दों में, रिकाडों के सिद्धान्त को रद्द करने के बजाय इसे सुधारने के प्रयत्न ही अधिक किये गये। रिकाडों ने मुद्रा, वित्तिय-दरों और मजदूरी दरों को अपने असाम्यता सम्बन्धी विवेचन (Discussion of disequilibrium) में सम्मिलित तो किया किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त को एक भाग में और मौद्रिक विवेचन को दूसरे भाग में रखा। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का यह द्विवर्गीय विभाजन—(१) विशुद्ध सिद्धान्त (The Pure Theory) जो कि सामान्य स्थैतिक मूल्य सिद्धान्त (General static theory of value) का भाग है और (२) प्रावैगिक कीमत एवं मुद्रा सिद्धान्त (The Dynamic Price and Monetary Theory)—आजकल भी चला आ रहा है। वास्तव में जैसा कि मिरडल (Myrdal) ने अपनी नई पुस्तक The International Economy में लिखा है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त एतन्त्र बाजार व्यवस्था के सिद्धान्त का पूरक है।

उत्पादकता सम्बन्धी भिन्नताओं पर बल—

वर्ष १८३० में सीनियर (Nassau Senior) ने यह समझाया कि कुछ देशों में मजदूरी की दरें प्रायः देशों की अपेक्षा अधिक ऊँची क्यों गयीं। उनका स्पष्टीकरण मुख्यतः श्रम-उत्पादकता सम्बन्धी भिन्नताओं के आधार पर था, चाहे इस अधिक उत्पादकता का कारण अधिक परिश्रम करना अधिक बुद्धि होना या अधिक पूँजी का विनियोग करना कुछ भी रहा हो। यह स्पष्टीकरण तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के सम्बन्ध में मजदूरी-दरों से सम्बन्धित अन्तरों का महत्त्व समझाने का एक सराहनीय प्रयास था क्योंकि रिकाडों (Ricardo) ने केवल 'श्रम समय' (Labour Time) का ही विवेचन किया था मजदूरी-दरों (Wage rates) का नहीं। जान स्टुमट मिल (J S Mill) और केर्नेस (Carne) ने भी यह मत व्यक्त किया था कि एक विनिर्दिष्ट उद्योग में किसी देश की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर मजदूरी की दरों का प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु मजदूरी की दरों के प्रभाव को सविस्तार समझाने तथा पूँजी-लागतों (Capital costs) के सम्बन्ध पर विचार करने का श्रेय बीसवीं शताब्दी के एक अग्रजानी को ही मिला।

पूँजी-लागतों को विचार में लेना—

टाशिंग ने यह स्वीकार किया कि मजदूरियों से नस्यागत विघ्नो (Institu-

(usual obstacles) की भलक मिल सकती है और इसलिए जब कुछ देशों में मजदूरों के विशिष्ट वर्गों को अन्य देशों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तो उनके द्वारा उत्पन्न वस्तुएं भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित सस्ती होती हैं। किन्तु टॉजिंग का कहना था कि मजदूरी कमाने वालों के विशिष्ट वर्गों के लिए मजदूरी की सापेक्षिक दरें विभिन्न देशों में एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हूँगी करती हैं।

टॉजिंग ने यह भी माना कि पूँजी-लागतों को विचार में लेना चाहिए, क्योंकि वह देश, जिसके पास बहुत पूँजी है और जहाँ व्याज की दरें नीची हैं, ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न करेगा, जिनके लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, लाभदायक स्थिति में रहना है। प्रो० वाइनर (Viner) भी, जो कि टॉजिंग के एक प्रतिमाधाली शिष्य है, टॉजिंग के इस विचार से सामान्य सहमति रखते हैं कि पूँजी लागतों को विचार में लेने में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कोई भारी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु हमारी सम्मति में टॉजिंग और वाइनर दोनों ही ने अन्य सब लागतों की उपेक्षा और लागतों पर आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है और पूँजी सम्बन्धी लागतों में वे केवल व्याज-दर को ही गिनते हैं जबकि पूँजी की उपलब्धता, प्रतिस्थापन व्यय और पूँजी के प्रत्यक्ष से सम्बन्धित व्यय भी विचारणीय हैं।

सम्भवतः टॉजिंग और वाइनर ही ऐसे विख्यात अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तज्ञ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के 'वास्तविक लागत सिद्धान्त' (Real Cost Theory) से चिपके हुए हैं। यह लोग श्रम सम्बन्धी अवयवों और बिरनि रहने की लागतों (Cost of abstinence) पर जोर देते हैं। जैसा कि प्रो० हैबरलर (Haberler) ने कहा है, 'ये विद्वान यह मान कर चलते हैं कि सभी साधनों के प्रयोग में अनुपयोगिता अवश्य होती है और इनका पुरस्कार उम अनुपयोगिता (Disutility) के अनुपात में होता है प्रत्येक सभी उद्योगों में विभिन्न प्रकार के श्रमों और अन्य साधनों (Inputs) का प्रयोग एक जैसे अनुपात में ही किया जाता है। ऐसी मान्यताएँ वास्तविक सत्ता के तथ्यों से मेल नहीं रखती हैं।'¹

अन्य लागतों को भी विचार में लेना—

प्राद के विवेचनों में ऐसे धटकों पर भी, [जैसे—प्रति श्रमिक अवश शक्ति की मात्रा, उत्पादकता एवं पूँजी, प्रत्यक्ष-कीमत, श्रमिक मूल्य का आचरण, कर प्रणालि-

¹ "They assume that all inputs involve disutility and that their remuneration is proportionate to the disutility involved or that the different types of labour and other inputs are employed in approximately the same proportion by all industries. These assumptions are far removed from the facts of the real world."
—G. Haberler : *A Survey of International Trade Theory*, p. 13.

जियाँ, व्यावसायिक संस्था का आकार और बाह्य मितव्ययितायें], जो कि देशों और इनके पृथक्-पृथक् उद्योगों की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं, बल दिया गया। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों के मजदूरी सम्बन्धी दरों के ढाँचों में बड़ी गिनतायें देखी जाती हैं और यह भी देखा जाता है कि अमेरिका में बढ़ाये गये मूल्य (Value added) में मजदूरियों का भाग केवल ४०% के लगभग है। इसके अतिरिक्त मजदूरियों से वेतनों का अनुपात बहुत विभिन्न देखा जाता है, जिसका यह अर्थ है कि प्रबन्ध, अनुसन्धान आदि बातों पर विभिन्न देशों में समान महत्त्व नहीं दिया जाता। यह भी देखा गया है कि निर्माणी मजदूरियाँ निमित्त वस्तु के मूल्य का एक छोटा-सा भाग होती हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने हेतु बिक्रय-लागतों (Selling costs) पर भी ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

(II) माँग का प्रभाव (Influence of Demand)

प्रन्तर्राष्ट्रीय माँग का समीकरण (मिल) —

अभी तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में केवल लागतों की भूमिका का विचार किया था। अब हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह पर माँग के प्रभाव का विवेचन करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर माँग के प्रभाव का विस्तार सहित विश्लेषण किया। मिल ने व्यापार से होने वाले लाभ की माप और उस अनुपात का, जिस पर विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं का व्यापार किया जायेगा, पता लगाने का यत्न किया। रिकार्डों के विश्लेषण में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया था। उन्होंने तो केवल उन सीमाओं को ही बताया था जिनके भीतर व्यापार की शर्तें तय होनी चाहिए। अर्थशास्त्र के प्रति मिल का एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उन्होंने यह स्पष्टता के साथ दिखाया कि व्यापार की शर्तें कैसे निर्धारित होती हैं। इस हेतु उन्होंने 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का समीकरण' (Equation of International Trade) प्रस्तुत किया। किन्तु व्यापार से होने वाले लाभ का माप करने के लिए मिल ने 'व्यापार की शर्तों' के विचार का जिस तरह उपयोग किया उसकी कड़ी आलोचना हुई।

(III) एक व्यापक आधार का निर्माण

[माँग एवं पूर्ति दोनों पर एक साथ विचार करना]

सीनियर, टॉजिय और वाइजर ने दो रिकार्डों के विश्लेषण में संशोधन करने के प्रयास किये थे किन्तु बाद के अर्थशास्त्रियों ने तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त के लिये एक व्यापक आधार बनाने का यत्न किया। उन्होंने तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त को मिल के माँग सम्बन्धी विश्लेषण से जोड़ दिया। इस दिशा में सबसे नया विवेचन मार्शल का था, जिन्होंने एक मिश्रित वस्तु (Composite Commodity) की, जिसे उन्होंने 'गॉठ' (Bale) कहा, चारणा प्रचलित की। मार्शल का अनु-

सरण करने हुए एवम्बन्ध ने व्यापार से होने वाले लाभ के वितरण को और भागे बढ़ाया तथा सरक्षण और व्यापार की शर्तों के बारे में बहुत कुछ बताया। लेकिन सबसे श्रान्तिकारी विवेचन ग्रीहत्सिन ने प्रस्तुत किया।

(IV) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या को सामान्य साम्य सिद्धान्त लागू करना

ग्रीहत्सिन ने सभी सम्बन्ध घटकों को विचार में लेने का यत्न किया और ऐसा करते हुए उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर सात सम्बन्धी भिन्नताएँ (Differences in factor-endowments) के जो प्रभाव पड़ते हैं उन पर बत दिया। उनका तर्क यह था कि प्रत्येक देश ऐसे ही उद्योगों पर अपना प्रयत्न केन्द्रित करता है जो अपेक्षित प्रचुर साधनों (Plentiful factors) को प्रयोग में लाते हैं। उन्होंने माँग की भूमिका पर भी विचार किया और बताया कि उत्पत्ति-साधनों के मूल्य (या घुसकार) माँग सम्बन्धी दशाओं पर निर्भर होते हैं। उदाहरणार्थ, यह देश, जहाँ प्रचुर और सस्ता श्रम उपलब्ध है, उन उद्योगों को चलावेगा, जो कि प्रचुर सस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं। किन्तु साधन की कोमलता होने से इसकी माँग में जो भारी वृद्धि होती है वह प्रचुरता वाले साधन (श्रम) को और ऐसे साधनों की कीमतों में, जो कि इसके पूरक हैं वृद्धि कर देगी। संक्षेप में, ग्रीहत्सिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या को सामान्य साम्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory) लागू किया है। हैबरलर ने सुझाया कि यह माना कि प्रत्येक देश में साधनों की एक निश्चित किन्तु विभिन्न मात्राओं में प्राप्ति होती है। तत्पश्चात् ग्रीहत्सिन के सपान उन्होंने उस ढंग को दिखाया, जिसमें साम्य सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय भेद देशों के बीच व्यापार को सम्भव बनाते हैं। हैबरलर ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के वास्तविक लागत सिद्धान्त की मीट्रिक लागतों के सिद्धान्त से प्रतिस्थापित (Replace) कर दिया है। प्रस्तुत खण्ड के पहले भागों में इन विभिन्न सिद्धान्तों का सविस्तार वर्णन किया गया है।

परीक्षा प्रश्न :

1. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास किस तरह हुआ है ? संक्षेप में समझाइये।
[Write a note on the development of the theory of international trade]
2. दुसनात्मक लागत सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए और इसके सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये नवीनतम विचारों को बताइये।

व्यापारवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व सिद्धान्त

(Mercantilists and Earlier Theories of International Trade)

प्राचीन आर्थिक विचारधारा और व्यापार

प्रादिकानीन समाज में आवश्यकताओं और सन्तुष्टि के मध्य सम्बन्धित था। सभ्यता अपनी शिशु-व्यवस्था में थी। आर्थिक कलापों के प्रति प्रभावपूर्ण प्रेरणाओं का अभाव था। यह तो केवल कबीली अर्थव्यवस्था (Tribal economy) के विकास की उच्चतम व्यवस्था में ही था कि जनसंख्या और उत्पादक योग्यता में वृद्धि के फल-स्वरूप अम विभाजन प्रगट हुआ और वस्तुएँ 'विनिमय' के लिए उत्पादित की जाने लगी। स्पष्टतः जब आन्तरिक विनिमय ही अविच्छिन्न हो, तब अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन समयता जैसे-जैसे अधिक विकसित होती गई और आर्थिक प्रगति हुई आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ़ता गया।

(I) प्राचीन भारत और व्यापार—

भारतीय सभ्यता और सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीन है। वेद और उपनिषद्, ब्राह्मण ग्रन्थ, मनु और याज्ञवल्क्य संहिता, पाणिनी सूत्र, रामायण, महाभारत आदि में भारतीय समाज की आर्थिक प्रगति की झलकें प्राप्त होती हैं। कहा जाता है कि जबकि विश्व के आधुनिक और प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों में शताब्दियों पूर्व जंगली जातियों का निवास था तब भारत में सुसभ्य, प्रगतिशील एवं धनी जातियाँ निवास करती थीं। न केवल आन्तरिक व्यापार बल्कि विदेशी व्यापार भी पर्याप्त विकसित व्यवस्था में था। देश विदेश के व्यापारी भारत में आते थे। भारतीय आर्थिक विचारकों ने अम विभाजन के महत्त्व को समझ कर ही वर्ण व्यवस्था बनाई थी। उनकी दृष्टि में आन्तरिक और विदेशी व्यापार राष्ट्र की सम्पत्ति और भाग का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत था। किन्तु उनके आर्थिक विचारों पर आध्यात्मिक विचार छाये रहे।

(II) हिन्दू (यहूदी) आर्थिक विचारक एवं व्यापार—

आध्यात्मिक दृष्टि से प्राचीन यहूदी समाज सबसे सगठित समाज था, जिसका विवरण प्राचीन बाइबिल के आदेश तथा अन्य धर्मोपदेशों से प्राप्त होता है। मोल्ड-

टेस्टामेंट के अनुसार प्रचुरता की दशा में व्यापार और वाणिज्य वास्तवीय था । बाइबलह सोलोमन के शासन काल में व्यापार की बहुत उन्नति हुई । उसका जहाजों घेडा दूर-दूर के देशों तक यात्रायें करता था । व्यापार को सुगम और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उसने व्यापार-मागों पर मण्डार-नगरी (Store cities) का निर्माण कराया ।

प्राचीन हिब्रू समाज में व्यापारिक नियम स्वाय भावना से आन प्रीति में । सदाहरणार्थ, कानून द्वारा मिलावट और बेईमानों का निषेध था । मट्टा और एकाधिकार को अप्रोत्सहित किया जाता था । मध्यस्थों को बुरा समझा जाता था । लालच पदायों के संबन्ध की अनुमति नहीं थी । इनके निर्माण का भी निषेध था । विक्रताग्री के लाभ को भी सीमित कर दिया गया था ।

(II) यूनानी आर्थिक विचारक और व्यापार—

यूनानी समाज में श्रम विभाजन की प्रथा थी । प्लेटो के अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वयं में पूर्ण नहीं है और इस हेतु उसे दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है । मनुष्य की तीन प्राथमिक आवश्यकतायें—भोजन, वस्त्र और मत्तन—हैं, जिनकी पूर्ति के लिये कृषक, युनकर और कारीगर का कार्य अनिवार्य है तथा उनके बीच विनिमय की गति बनाये रखने के लिये व्यापारियों की श्रेणी भी आवश्यक है । प्लेटो (Plato) का विचार था कि सभी वस्तुयें अधिक मात्रा में अधिक सदनता और सुन्दर कल में तैयार होती हैं जबकि व्यक्ति उनी काम को करते हैं जो उनकी रुचि, स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल हो । किन्तु उसने श्रम विभाजन के सामाजिक पहलु पर विचार नहीं किया था और इसे अपने युग की एक तर्क-सङ्गत आर्थिक आवश्यकता मान समझा था । उत्तरी श्रम विभाजन सम्बन्धी विचारधारामों ने एडम स्मिथ के श्रम विभाजन सम्बन्धी विचारों के लिये आधार-गिना का काम रिया । जीनफन (Xenophon) ने भी श्रम विभाजन पर बहुत बल दिया । उन्होंने अपनी पुस्तक 'The Ways and Means to Increase the Revenue of Athens' में निर्वनता को दूर करने के उपायों में वाणिज्य व्यापार का विस्तार, विदेशियों के लिये सुविधायें, गिराँत के लिये सरकार द्वारा जहाज निर्माण आदि का उल्लेख किया है । उनके विचारों का भी व्यापारवाधियों और प्रकृतिवाधियों पर बहुत प्रभाव पड़ा ।

(IV) रोमन आर्थिक विचारक और व्यापार—

रोमन विचारकों में सिसरो (Cicero) अग्रणी है । उसने भी श्रम विभाजन के लाभ की दृष्टिगत समते हुये श्रम विभाजन पर बल दिया । रोमन राज्य सङ्घट के समय व्यापारिक और आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करता था । बहुमूल्य धातुओं के निर्माण पर प्रतिबन्ध था ।

मध्यकालीन आर्थिक विचार और व्यापार

मध्य युग के समाजों में आर्थिक कार्यकलाप की प्रगति में अधिक गति प्राप्त

करली। पूँजीवाद का जन्म इसी युग में हुआ। अदत्त व्यवस्था मज्ज हो चुकी थी तथा मुद्रा व्यवस्था ने जड़े मजबूत कर ली थी। इस युग के विचारकों ने श्रम विभाजन, विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में विसृत विचार प्रस्तुत किये। सेण्ट टॉमस एक्विनास (St. Thomas Aquinas) ने श्रम विभाजन को तो स्वीकार किया, किन्तु अनिवार्य वस्तुओं के व्यापार को छोड़ कर शेष व्यापार को अप्राकृतिक बताया। अन्य लेखकों (जैसे Oresme) ने व्यापार के विकास पर बहुत बल दिया।

व्यापारवादों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में व्यापारवादियों के विचार सबसे स्पष्ट थे। प्राधुनिक सिद्धान्त पर उनका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। स्वतन्त्र व्यापार के प्रबल समर्थक एडम स्मिथ की धारणाएँ अनेक बातों में व्यापारवादियों की धारणाओं की प्रतिपूरक और विरोधी हैं। मध्ययुगीय विचारधारा के बाद जो प्राथमिक विचार और नीतियाँ प्रचलित हुईं उनको व्यापारवाद की सजा दी गई, क्योंकि इसमें राष्ट्र की प्राथमिक शक्ति को बढ़ाने के लिए वाणिज्य तथा विदेशी व्यापार जैसे साधनों पर बल दिया गया था। यह विचारधारा १६वीं शताब्दी से लेकर १८वीं शताब्दी के दूसरे भाग तक प्रचलित रही।

थॉमस मॉ (Thomas Munn) को इङ्ग्लैंड के व्यापारवादियों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। वे अपने समय और देश में व्यापार का अनुकूल सम्मेलन और व्यापाराधिक्य प्राप्त करने हेतु अपने देश के विदेशी व्यापार का नियमन करना चाहते थे। इङ्ग्लैंड की सम्पन्न बनाने के लिए उनके व्यापारवादी विचारों की सक्षिप्त सूची निम्न प्रकार है —

- (१) सभी देश, जिनके यहाँ सोने चाँदी की खान नहीं हैं, एक ही उपाय से धनी बनते हैं और वह उपाय है विदेशी व्यापार का अनुकूल व्यापाराधिनय। उसने 'सामारण' और 'विशेष' व्यापाराधिनयों में भी भेद किया।
 - (२) इङ्ग्लैंड को चाहिए कि व्यापार के लिए एक मण्डी स्थापित करे, जिसमें इङ्ग्लैंड स्वयं वितरण का केन्द्र बने तथा जहाजरानी और व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करे।
 - (३) विदेशों से आयात को कम करने के लिए परती भूमि पर कृषि की जाय और पंशन की वस्तुओं के आयात को विशेष रूप से कम किया जाय।
 - (४) देश के जहाजों में ही माल का निर्यात किया जाय, जिनसे विदेशी व्यापार के सभी लाभ प्राप्त हो सकें।
 - (५) कच्चे माल पर अत्यधिक कर न लगाये जायें, अन्यथा मूल्य-वृद्धि होने से विदेशों में उसकी विप्री बहुत कम हो जायेगी।
- जैसा कि ऐरिक रॉल (Eric Roll) ने बताया है मॉ ने विदेशी व्यापार

की तुलना आधिक्य उत्पन्न करने के एक प्राचीन ढङ्ग से की है। विलियम पेटी (इङ्ग्लैंड) के अनुसार व्यापार का अन्तिम परिणाम साधारण सम्पत्ति का बहुल्य होना नहीं वरन् सोना, चाँदी और जवाहरान का बहुल्य होना है। एक प्रत्यक्ष अंग्रेज विचारक जोशिया चाइल्ड ने भी, जिनकी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का अनुभव था, व्यापाराधिक्य के महत्त्व का संकेत दिया। किन्तु विशेष-व्यापाराधिक्य के स्थान पर उन्होंने साधारण व्यापाराधिक्य की ओर ही अधिक ध्यान दिया। फ्रान्स के व्यापारवादी विचारक कोलबर्ट (Colbert) ने सभी आर्थिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिपादन किया। उनकी धारणा थी कि व्यापार का एकमात्र उद्देश्य विदेशी मुद्रा का सर्जन और राज्य की शक्ति को बढ़ाना है। जीम बोडीन ने व्यापार की स्वतन्त्रता के पक्ष में विचार प्रगट किये। रिचर्ड कैथिलीन प्रनुकुल व्यापाराधिक्य के पक्ष में थे। उनकी धारणा थी कि यह राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। उनका यह भी विश्वास था कि देश को कच्चे माल का आयात और निमित्त माल का निर्यात करना चाहिए। इटली के एंथोनिमो सोरा राष्ट्र में ऐसी कुशल और परिधर्मी जन सख्या के पक्ष में थे, जो देशों और विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सके। मैकियावेली ने यह मत प्रगट किया कि आर्थिक नियामों पर राज्य का पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

आस्ट्रिया के वॉन हॉर्निक (Von Hornick) ने यह मत प्रगट किया कि किसी देश की शक्ति और प्रभुत्व उस देश में उपलब्ध सोने और चाँदी तथा जीवन-निर्वाह के लिये आवश्यक या सुविधाजनक उस सब साधनों और वस्तुओं पर निर्भर है जिन्हें उस देश ने दूसरे देशों पर निर्भर न रहते हुये अपने ही साधनों से प्राप्त किया है। उसने बताया कि देश के सोने-चाँदी को बाहर न जाने दिया जाय, देश की वस्तुओं से ही निर्यात किया जाय यथासम्भव विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचा जाय, अनिवार्य आयातों को वस्तुओं के बदले में ही भेगाया जाय, सोने-चाँदी के बदले में नहीं। विदेशों से आयात करने पर कच्चा माल ही भेगाया जाय। यदि कोई वस्तु देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है (चाहे वह चटिया अथवा की हो), तो उसका आयात नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सभी देशों के व्यापारवादी यह विश्वास करते थे कि सोना और चाँदी ही देश की शक्ति का आधार है। जिन देशों के पास सोना चाँदी की खानें नहीं हैं उन्हें ये बहुमूल्य वस्तुएँ विदेशी व्यापार द्वारा प्राप्त करनी चाहिये। इस हेतु उन्हें अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात करने (अर्थात् प्रनुकुल व्यापाराधिक्य) पर बल दिया। जहाजरानी और सड़की बनाने की, जो विदेशी व्यापार में सहायक थे, उच्च महत्त्व प्राप्त था। किन्तु निर्यात के लिए वही वस्तुएँ उपयुक्त समझी जाती थी, जिनसे आयातों की ऊँची लागत उन्मूल हो जाय। अतः विदेशों को रोकने के लिए एक मास-तयार करने पर बल दिया गया। आयात को रोकने का समर्थन किया गया। राज्य को ऐसे नियम एवं नियंत्रण

स्थापित करने का अधिकार था, जिनसे कि देश के उद्योग और व्यापार को उत्पत्ति हो तथा राष्ट्र के लिये अधिक से अधिक अनुमूल व्यापाराधिक्य सुलभ हो जाय। उपनिवेशों का विकास भी इस आधार पर करना था कि वे मुख्य राष्ट्र के उद्योगों के लिये कच्चे माल को पूर्ति करते रहे। वृत्ति के लिए सरक्षण देने का समर्थन किया गया, क्योंकि इससे साधारणों का आयात कम होता था।

व्यापारवादियों के विदेशी व्यापार सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन—

स्वीडन के प्रर्थशास्त्री हेक्शर (Heckscher) ने वस्तुवाद की विदेशी वस्तुओं का भ्रम बताया है। उनकी यह धारणा कि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में बहुत सही है। व्यापारवाद की तत्कालीन परिस्थितियों में सोने-चाँदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों को महत्त्व देने का कुछ सीमा तक ही उचित ठहराया जा सकता है। अन्य मन्थों में, अल्पकालीन दृष्टि से सोने-चाँदी की प्राप्ति उचित नहीं जा सकती है। मत व्यापारवादियों की त्रुटि यह थी कि उन्होंने इसे राष्ट्रीय नीति का स्थायी आधार बनाने का प्रयत्न किया। वास्तव में सोने-चाँदी के ऐसे सग्रह से क्या लाभ, जो देश की आर्थिक प्रगति में कोई ठोस सहायता न दे सके? आधुनिक प्रर्थशास्त्री सोने चाँदी के निजी अस्तित्व को इतना महत्त्व नहीं देते जितना कि उस उत्पादक आर्थिक व्यवस्था का, जिसमें कि सोने-चाँदी के प्रयोग में देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़े और राष्ट्र की रक्षा-व्यवस्था सुदृढ़ हो जाय।

विदेशी व्यापार द्वारा सोना-चाँदी प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ दूषित है। विदेशी व्यापार का वास्तविक लाभ तो उपयोगिता को बढ़ाने और राष्ट्र के लिये विभिन्न वस्तुओं प्राप्त करने में है। यदि विश्व के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुमूल व्यापाराधिक्य और सोने-चाँदी की प्राप्ति को अपनी लक्ष्य बनायें, तो विश्व-प्रत्येक व्यवस्था का मञ्चालन कठिन हो जाय। वास्तव में, व्यापारवादियों के विचार राष्ट्रीय प्रत्येक-व्यवस्था तक ही सीमित थे, उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्येक-व्यवस्था का विचार नहीं रखा था।

व्यापारवादी विचारधारा और तत्सम्बन्धी नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में ही प्रभुत्ववाद (Phy-iocracy) का जन्म हुआ, जिसने स्वतन्त्र व्यापार पर बल दिया और देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्येक विभाजन को उपयोगी बताया।

उपसंहार—आधुनिक युग में व्यापारवादी प्रभाव

वर्ष आधुनिक प्रगतिशील देशों में व्यापारवादी नीतियों का सक्रिय अनुसरण किया गया है। उदाहरणार्थ, विश्व मन्थों के युग में देशों ने स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को छोड़कर सरक्षण की नीति अपनाई। आज जब हम यह देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में (विशेषतः विदेशी व्यापार में) सरकारों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। प्रत्येक देश अपने स्वयं कोष सुरक्षित रखने के लिये प्रयत्नशील है, और इस हेतु वह अनुमूल व्यापाराधिक्य पर बल देता है। अतः निर्धन-उत्पादकों को विशेष प्रोत्सा-

रन दिये जा रहे हैं। हाँ, यह अक्षय है कि आन इन राष्ट्रीय नानि की शेष विशय मे पृथक् रूप मे मचानिन न करके अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों हितों के अपूर्व समा योहन के साथ मचानिन करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तराष्ट्रीय व्यापार के व्यापारवादी एवं अन्य पूर्व सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।

[Give an account of mercantilists and earlier theories of international trade]

- २ वर्तमान भारतीय अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में एक अग्रनिबधित आयातों वाली नीति के परिणामों की समीक्षा कीजिए।

[Examine the consequences of a policy of unrestricted imports in context of the present day Indian economy]

- ३ विदेशी व्यापार के व्यापारवादी सिद्धान्त व प्रमुख तर्कों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसकी परिमोषाया के बावजूद क्या यह वर्तमान युग में अन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का पुनर्गठन करने में लिए एक उपयुक्त ढांचा प्रदान करता है ?

[Critically examine the main elements of the mercantilist theory of foreign trade. Despite their limitations do they provide a framework for restating the theory of international trade today?]

(इलाहाबाद, एम० १९६९)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उद्गम (एडम स्मिथ के विचार)

(The Origins of Classical theory of International Trade .
The Views of Adam Smith)

परिचय—

प्रतिष्ठित अधेशास्त्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त स्वतन्त्र व्यापार और सरकारवाद के वाद-विवाद से सम्बन्धित रहा है और सब तो यह है कि इसका विकास स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में ही किया गया था।

एडम स्मिथ द्वारा सरकार के हस्तक्षेप का विरोध
(Smith's Assault upon Government Interference)

आर्थिक प्रणालियों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप की नीति पर प्रबल आशयन करके एडम स्मिथ ने व्यापारवाद की आगे वाली मृत्यु की पूर्व-घोषणा कर दी। 'वैश्व धन-स' (Wealth of Nations) में उन्होंने लिखा था कि किस उद्योग में पूँजी लगाई जाय और किस में नहीं, इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति अपनी 'स्थानीय परिस्थिति' के सन्दर्भ में जितना अच्छी तरह से कर सकता है उतना एक राजनीतिज्ञ या शासक के लिये कदापि सम्भव नहीं है, चाहे वह राजनीतिज्ञ या शासक एक कोनिस या सीनेट ही क्यों न हो। यदि वह निर्णय के अधिकार को अपने हाथ में ले लेता है, तो न केवल उस पर अनावश्यक व्यस्तता का भार बढ़ जायेगा वरन् अधिकार का दुरुपयोग भी किया जा सकता है।¹

इसके बाद उन्होंने यह बताया कि आन्तरिक बाजार में यह उद्योग की

1 "The statesman, who should attempt to direct private people in what manner they ought to employ their capitals, would not only load himself with a most unnecessary attention, but assume an authority which could safely be trusted, not only to no single person, but to no council or senate whatever, and which would no where be so dangerous as in the hands of a man who had folly and presumption enough to fancy himself fit to exercise it."—Adam Smith : *Wealth of Nations*, p 423.

उत्पत्ति को एकाधिकार देने का अर्थ कुछ सीमा तक प्राइवेट व्यक्तियों को यह निर्देश देना है कि वे अपनी पूँजियाँ किस तरीके से प्रयोग में लायें। किन्तु ऐसे निर्देश या नियम देकार हैं और हानिकारक भी प्रमाणित हो सकते हैं। जब विदेश में कोई वस्तु उत्तनी ही सस्ती खरीदी जा सकती है जितनी कि स्वदेश से, तब प्रतिवन्ध लगाने वाला नियम स्पष्टतः व्यर्थ है और जब वस्तु विदेश से उत्तनी सस्ती नहीं खरीदी जा सकती है, तब नियम सामान्यतः हानिप्रद होता है। प्रत्येक विवेकशील परिवार स्वामी का यह निश्चित सिद्धान्त होता है कि वह अपने घर पर ऐसी वस्तु बनाने का प्रयास कभी न करे, जिस पर बाहर से कम करने की अपेक्षा अधिक व्यय भाये। अतः एक दर्जी अपने लिए जूते स्वयं कभी नहीं बनाता किन्तु मोची से खरीदता है। मोची भी अपने लिए कपड़े स्वयं नहीं बनाता बल्कि दर्जों की सेवामें सेता है। एक कृषक न तो कपड़े बनाता है और न जूते, बल्कि वह दर्जी और मोची की सेवासों का उपयोग करता है। ये सब व्यक्ति अपने-अपने साधनों का ऐसे तरीके से प्रयोग करने में अपना हित अद्भुतप्रकार करते हैं जिसमें उन्हें अपने बड़ोसियों की तुलना में कुछ विशेष लाभ हो और फिर अपनी उत्पत्ति के एक भाग के बदले में दूसरों से अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की महत्ता पर जोर

(Stress on the Significance of International Division of Labour)

एडम स्मिथ ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की महत्ता पर निम्न शब्दों में प्रकाश डाला है—“प्रत्येक प्राइवेट परिवार के आनन्द में जो बात बुद्धिमत्तापूर्ण है वह एक विशाल देश के आचरण में कठिनाता से ही मूर्खतापूर्ण हो सकती है। यदि एक विदेशी देश हमें कोई वस्तु उससे सस्ती दे सकता है जो कि हम स्वयं बनाते हैं, तो उससे ऐसी वस्तु को हमें अपने निजी उद्योग की, जिसमें हमें कुछ विशेष लाभ है, उपज के कुछ भाग के बदले में खरीद लेना चाहिए। विशेष वस्तुओं के उत्पादन में एक देश की अपेक्षा दूसरे देश की जो प्राकृतिक लाभ प्राप्त होते हैं वे कभी कभी इतने अधिक होते हैं कि समस्त विश्व यह स्वीकार करता है कि इनसे लड़ना व्यर्थ है।”¹ उदाहरणार्थ, व्यवसायिक तकनीकी द्वारा स्कॉटलैंड में बहुत बढ़िया भूगर्भ उत्पन्न

¹ “What is prudence in the conduct of every private family, can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some knowledge. The natural advantages which one country has over another in producing particular commodities are sometimes so great that it is acknowledged by all the world to be in vain to struggle with them.”—*Ibid*, p 426.

किये जा सकते हैं और इनसे बहुत बढ़िया शराब भी तैयार की जा सकती है किन्तु इसमें विदेशों से उतनी ही अच्छी शराब मगान की अपेक्षा नीम मुना व्यय होगा। तब क्या केवल इसलिए कि स्काटलैण्ड में वॉरेंट और वाण्डो के निर्यात को प्रोत्साहन मिले समस्त विदेशी शराबों के आयात पर प्रतिशत नगाने वाला कानून उचित कहलायगा ?

श्रम विभाजन के विस्तार के लिए स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन

(Smith's Support of Free Trade as Promoting
the Division of Labour)

हमारे का श्रम विभाजन सम्बन्धी दृष्टिकोण प्रगतिशील है क्योंकि श्रम विभाजन की महत्ता पर हम डेने हुए उगने यह विश्वास कि इसमें आय में भी वृद्धि हो जाती है। चूंकि स्वतन्त्र व्यापार प्रत्येक देश को केवल उन वं मुद्रा के उत्पादन पर ही, जिनमें वह बहुत सस्ती बना सकता है स्थान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह श्रम विभाजन के विस्तार में (और इसके द्वारा आय की वृद्धि) में सहायक होता है। अतः उसने स्वतन्त्र व्यापार का भरपूर समर्थन किया। हम सम्भव में उसके अपने शब्द उल्लेखनीय हैं और इस प्रकार है— जब निपाहिया और नौ सैनिकों को सम्राट की सेवा से पृथक् कर दिया जाता है, तो व किसी भी स्थान में कोई भी धंधा करने के लिए स्वतन्त्र होते हैं। इसी प्रकार की प्राकृतिक स्वतन्त्रता यह निर्णय करने के सम्बन्ध में कि कौन गा उद्योग करें, सम्राट की समस्त प्रजा को लौटा देनी चाहिए। सर्वोत् कारपोरेशनों के एकाधिकारों को भंग कर दिया जाय एवं निष्पक्ष सम्बन्धी विधान को भी रद्द कर दिया जाय क्योंकि ये दोनों नियम प्राकृतिक स्वतन्त्रता पर राक्षस होते हैं। क्या धंधा तलाश करने के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्धक कानून बने हुए हैं उन्हें भी रद्द कर देना चाहिए, जिसमें कि एक निधन कारीगर किसी एक रोजगार या स्थान में बंधा होने पर किसी अन्य रोजगार या स्थान में निधन होकर काम कर सकें।”

1 “Soldiers and seamen indeed when discharged from the king's service, are at liberty to exercise any trade, within any town or place of Great Britain or Ireland. Let the same natural liberty of exercising what species of industry they please, be restored to all His Majesty's subjects, in the same manner as to soldiers and seamen, that ■ break down the exclusive privileges of corporations and repeal the statute of apprenticeship, both of which are real encroachments upon natural liberty, and add to these the repeal of the law of settlements so that a poor workman, when thrown out of employment either in one trade or in one place, may seek for it in another trade or in another place without the fear either of a prosecution or of removal, and neither the public nor the individuals will suffer much more than those who defend it with their blood, nor deserve to be treated with more delicacy”—*Ibid*, p 437.

स्वतन्त्र व्यापार के अपवाद (Exceptions to Free Trade)

कई प्रश्नों पर विषय के विचार बहुत सामुहिक जाँचते हैं। उदाहरणार्थ सरक्षण के पक्ष में सुरक्षा के तर्कों की स्वीकार करता है।¹ इसके अतिरिक्त विषय न यह भी स्वीकार किया है कि विदेशों को व्यापार विषय उदार नीति पर चलाने हेतु प्रतिशोधात्मक द्यूटी (Retaliatory duties) का प्रयोग किया जा सकता है।²

प्रतिबन्धों को शनैः शनैः हटाना (Gradual Removal of Restrictions)

जब किसी देश में (जैसा कि इङ्ग्लैंड में था) विदेशी वस्तुओं के स्वतन्त्र आयात पर एक दीर्घ अवधि से प्रतिबन्ध लगे हुए हों, तब यह विचार करने की बात है कि स्वतन्त्र व्यापार की पुनः स्थापना किस सीमा तक अवधि किस तरीके से की जाय। सरक्षित उद्योगों का हटना विनाश हो जाता है कि उनमें हजारी-लासी

- 1 "There seem, however, to be two cases in which it will generally be advantageous to lay some burden upon foreign, for the encouragement of domestic industry. The first is, when, some particular sort of industry is necessary for the defence of the country. The defence of Great Britain, for example, depends very much upon the number of its sailors and shipping. The act of navigation, therefore, very properly endeavours to give the sailors and shipping of Great Britain the monopoly of the trade of their own country, in some cases, by absolute prohibitions, and in others by heavy burdens upon the shipping of foreign countries."—*Ibid*, p. 429.
- 2 "The second case, in which it will generally be advantageous to lay some burden upon foreign for the encouragement of domestic industry, is, when some tax is imposed at home upon the produce of the latter. In this case, it seems reasonable that an equal tax should be imposed upon the like produce of the former. The case in which it may sometimes be a matter of deliberation how far it is proper to continue the free importation of certain foreign goods, is, when some foreign nation, restrains by high duties or prohibitions the importation of some of our manufactures into their country. Revenge in this case naturally dictates retaliation. There may be a good policy in retaliations of this kind, when there is a probability that they will procure the repeal of the high duties or prohibitions complained of"—*Ibid*, pp. 432-34.

प्रमिक काम पर लग जाते हैं। ऐसी दशा में मानवता का तकाजा है कि व्यापार ही स्वतन्त्रता शनैः शनैः स्थापित की जाय। यदि ऊँचे कर और कठोर निषेधादेश प्रचलन ही समाप्त कर दिये गये, तो सस्ती विदेशी वस्तु गृह बाजार में इतनी तेजी से दूरी जायेगी कि सम्बन्धित देशी उद्योग सकट में पड़ जाये और लाखों मजदूरों की जीविका ख़िन जाये। इस प्रकार, एडम स्मिथ ने एक स्वतन्त्र व्यवस्था में समा-शोधन की आवश्यकता पर पर्याप्त बल दिया। किन्तु वे समायोजन की जटिलता को पूर्णरूप से नहीं देख सके।¹

निहित स्वार्थ एवं सुरक्षण (Vested Interests and Protection)

समाचार सुरक्षण मिलते रहने से उद्योग धन्यों में निहित स्वार्थ स्थापित हो जाते हैं, और भविष्य में जब कभी सुरक्षण को समाप्त करने की चर्चा चलती है तो वे इसके विरोध में सगठित हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे अपनी धन सम्पत्ति और राजनैतिक शक्ति के प्रयोग द्वारा विधायकों को डराने की चेष्टा करते हैं, जिससे कि सुरक्षण विरोधी कानून पास न हो सके। इस सम्बन्ध में स्मिथ का कहना है कि

“The case in which it may sometimes be a matter of deliberation, how far, or in what manner, it is proper to restore the free importation of foreign goods, after it has been for some time interrupted, is, when particular manufactures, by means of high duties or prohibition upon all foreign goods which can come into competition with them, have been so far extended as to employ a great multitudes of hands. Humanity may in this case require that the freedom of trade should be restored only by slow gradations, and with a good deal of reserve and circumspection. Were those high duties and prohibition taken away all at once, cheaper foreign goods of the same kind might be poured so fast into the home market as to deprive all at once many thousands of our people, of their ordinary employment and means of subsistence. The disorder which this would occasion might no doubt be very considerable. It would in all probability however, be much less than is commonly imagined for the following two reasons: First all those manufactures, of which any part is commonly exported to other European countries without a bounty could be every little affected by the freest importation of foreign goods . . . Secondly, though a great number of people should, by thus restoring the freedom of trade, be thrown all at once out of their ordinary employment and common method of subsistence, it would by no means follow that they would thereby be deprived either of employment or subsistence.”—*Ibid*, pp 435-36.

विधान सभा को सामान्य हित (General good) सम्बन्धी विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कम से कम इतना तो आवश्यक ही है कि वह नये एकाधिकार स्थापित न करे तथा पुराने एकाधिकारों को मजबूत न बनावे अन्यथा मवित्य में इन पर अकुल सशाना बठिन ही जायगा ।¹

यातायात व्यय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (Transportation Cost and International Trade)

स्मिथ ने यह माना है कि यातायात व्यय व्यापार को बढ़ाते हैं। पत वुड्सवि-
यन तर्क दिया कि सरक्षण से निर्यातार्थों को कृषकों की तुलना में अधिक लाभ होता
है। कृषि पदार्थों भारी होने के कारण अधिक व्यय पर ही स्थानांतरित किये जा
सकते हैं। चूंकि कृषि पदार्थों के यातायात व्यय ऊंचे होने हैं, इसलिए वे
व्यापारियों के मार्ग में प्राकृतिक बाधाओं का कार्य करते हैं, जिससे फिर कृषि की रक्षा
के लिए टैरिफ लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है।²

1 This monopoly has so much increased the number of some particular tribes of them that, like an over-grown standing army, they have become formidable to the government, and upon many occasions intimidate the legislature. The legislature, were it possible that its deliberations could be always directed not by the clamorous importunity of partial interests, but by an extensive view of the general good, ought upon this very account, perhaps, to be particularly careful neither to establish any new monopolies of this kind nor to extend further those which are already established. Every such regulation introduces some degree of real disorder into the constitution of the state, which it will be difficult afterwards to cure without occasioning another disorder."—*Ibid* p 436

2 "Manufactures, those of the finer kind especially, are more easily transported from one country to another than corn or cattle. It is in the fetching and carrying manufactures, accordingly, that foreign trade is chiefly employed. In manufactures, a very small advantage will enable foreigners to undersell our own workmen, even in the home market. It will require a very great one to enable them to do so in the rude produce of the soil. If the free importation of foreign manufactures were permitted, several of the home manufactures would probably suffer and some of them perhaps go to ruin altogether. But the freest importation of the rude produce of the soil could have no such effect upon the agriculture of the country."

—*Ibid*, p 426.

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में निरपेक्ष नागतो पर बल देता

विषय प्रवेश' सम्बन्धी खण्ड में हमने यह स्थापित किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक पृथक अध्ययन की आवश्यकता है। अब हम इस प्रश्न पर विचार करने हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है? विभिन्न समयों पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके भिन्न-भिन्न उत्तर प्रस्तुत किये। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में सामान्य भिन्नताओं का सिद्धान्त (Doctrine of Cost Differences) बताया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में यह सिद्धान्त एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों के नाम से बहुत सम्बन्धित रहा है। एक अलग अध्याय में हमने डेविड रिकार्डों के योगदान की विवेक चर्चा की है। यहां पर हम केवल एडम स्मिथ के दृष्टिकोण पर विचार करेंगे।

एडम स्मिथ के दृष्टिकोण को विशेषतायें—

एडम स्मिथ के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण की समझने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है —

(१) भ्रम मूल्य सिद्धान्त का प्रयोग—एडम स्मिथ ने मूल्य के भ्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को अपनाते हुए वस्तु की एक इकाई के उत्पादन करने में लगे हुए भ्रम की मात्रा पर बल दिया है। इस सिद्धान्त के अनुसार वस्तुएँ एक दूसरे में, अपने में निहित भ्रम की सापेक्षिक मात्राओं के अनुसार, विनिमय की जाती हैं। अर्थात् समान मूल्य वाली वस्तुओं में भ्रम की समान मात्रा होती है। उन्होंने यह मान लिया था कि यद्यपि भाग्यो की विभिन्न प्रकार के षटक प्रभावित करते हैं तथापि उत्पादन सुविधा (Production advantage) मुख्यतः भ्रम पक्ष से ही उदय होती है। एडम स्मिथ ने निम्न विस्मय उत्पन्न किया—“यदि शिकारिया के किसी देश में समान मात्रा में भ्रम व्यय करके वस्ति या तो एक ऊदबिलाव मार सकता है या दो हिरन तो यह स्वाभाविक है कि एक ऊदबिलाव का विनिमय दो हिरनों से किया जायगा।”¹ यदि उक्त अनुपात बदल जाय (मान लीजिये कि एक ऊदबिलाव तीन हिरनों से विनिमय किया जाय लगे), तो इस परिवर्तित अनुपात का लाभ उठाने की इच्छा से अधिक लोग अधिक सस्या में ऊदबिलावों को मारने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे, जिससे ऊदबिलावों की पूर्ति तो बढ़ जायेगी किन्तु हिरनों की पूर्ति घट जायेगी और फलस्वरूप विनिमय अनुपात हिरनों के पक्ष में और ऊदबिलावों के विपक्ष में बदलने लगेगा तथा अन्ततः मूल अनुपात (Original ratio) पुनः प्रचलित हो जायगा।

¹ “If among a nation of hunters for example, it usually costs twice the labour to kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange for or be worth two deer.” —Adam Smith - *Wealth of Nations*, p. 37.

इस प्रकार विनिमय अनुपात या मूल्य केवल मार्पेक्षिक श्रम लागतों से ही माँग और पूर्ति पर उनके प्रभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे, श्रम मूल्य सिद्धान्त वास्तविकता से कहीं दूर है। यह केवल निम्न मान्यताओं के आशीन ही सत्य हो सकता है — (i) कि समस्त श्रम एक ही गुण वाला है, (ii) कि प्रत्येक घन्टा सभी के लिए तुल्य है, (iii) कि श्रम ही उत्पात्ति का एक मात्र गतिशील साधन है, एवं (iv) श्रमिकों में स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धिता होगी है। वास्तविक जगत् में इनमें से कुछ मान्यताएँ तो कभी भी सत्य नहीं होती हैं और कुछ मान्यताएँ सदा सत्य नहीं होती हैं, जिस कारण श्रम मूल्य सिद्धान्त वैध नहीं रहता।

(२) देशों के मध्य श्रम को-अवनिर्माण और एक ही देश के अन्दर श्रम की गतिशील सम्बन्धता—स्मिय ने श्रम को, जो कि उत्पादन लागतों को निर्धारित करने वाला एक मात्र घटक है, एक ही देश के अन्दर जो गतिशील किन्तु देशों के मध्य गतिशील मान लिया। उस प्रकार, एक देश विशेष के अन्दर श्रम-साधन विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों के मध्य सम सीमान्त रूप में (Equi-marginally) वितरित हो जाता है, जिससे कि प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में उसकी सीमान्त उत्पात्ति ज्येष्ठ क्रिये पर श्रम-घण्टी की संख्या के बराबर होती है। किन्तु चूँकि देशों के मध्य श्रम पूर्णतः गतिशील (Immobile) होता है, इसलिए वह एक उद्योग में दूसरे उद्योग की (यदि दोनों उद्योग विभिन्न देशों में स्थापित हों) आ-जा नहीं सक्ता। इन प्रकार बंद अर्थ-व्यवस्थाओं (Closed economies) में अर्थात्, उन देशों में जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचलित नहीं है, इस अद्वितीय प्रस्तावना (अर्थात् श्रम) के विन्यय में कुलमाधोजन (Mal adjustment) उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें वास्तुकों के दर में प्राप्ति होने वाली संतुष्टि कम हो जायगी, क्योंकि श्रम की गतिहीनता वास्तुओं के मध्य अधिकतम श्रम विभाजन सम्भव नहीं करने देती है। स्पष्टतः श्रम के विन्यय में अनुराता का धर्म है अधिकतम से कम मात्रा में उत्पत्ति होना। सोचाव से श्रम की गतिहीनता विन्यय-संतुष्टि के अधिकतम होने में बाधक बननी आवश्यक नहीं है, बल्कि कि वस्तुएँ जिनमें श्रम निहित होता है, रजन्यतापूर्वक विनिमय की जायें। अतः अर्थों में, वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

(३) समस्त भिन्नताओं का सिद्धान्त—उपरोक्त मान्यता की दशा में उन वस्तुओं का जिनका अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय किया जा सकता है, चुनाव करने की समस्या उत्पन्न होती है। स्मिय ने इसका उत्तर लागत भिन्नताओं के सिद्धान्त (Doctrine of Cost Differences) द्वारा दिया।

(४) केवल दो देशों और दो वस्तुओं पर विचार—एडम स्मिथ ने (और आगे चल कर रिकार्डों ने भी) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के स्पष्टीकरण की सुगमता के लिए एक ऐसा मॉडल (Model) चुना, जिसमें केवल दो ही देश और दो ही वस्तुएँ हैं। क्या एक देश एक की हुई वस्तु के उत्पादन में अन्य देश

की अपेक्षा कोई विशेष लाभ (Special advantage) रखता है और यदि रखता है, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय उस वस्तु की एक इकाई का उत्पादन करने में दोनो देशों की लागतों के मध्य भिन्नता द्वारा होता है। ऐसी परिस्थिति में, यदि दोनो देशों में से प्रत्येक एक वस्तु की, घन्य देश की अपेक्षा, निरपेक्ष रूप से कम उत्पादन-अभ-लागत' (Absolutely lower labour cost of production) पर उत्पन्न कर सकता है, तो वस्तुओं का विनिमय किया जायेगा।

उदाहरण के लिए, मान लें कि 'अ' देश 'क' वस्तु की एक इकाई १० और 'ल' वस्तु की एक इकाई २० श्रम-इकाइयों की सहायता से उत्पन्न कर सकता है जबकि 'ब' देश को 'क' और 'ल' वस्तुओं की एक-एक इकाई उत्पन्न करने में क्रमशः २० और १० श्रम इकाइयाँ प्रयोग करनी पड़ती हैं।

अभ-लागत संरचना की तुलना

वस्तु	अ देश में उत्पादन लागत (श्रम इकाइयाँ)	ब देश में उत्पादन-लागत (श्रम इकाइयाँ)
'क' वस्तु की एक इकाई	१०	२०
'ल' वस्तु की एक इकाई	२०	१०

उपरोक्त परिस्थिति में, अ देश 'क' वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, क्योंकि इसमें ही उसे निरपेक्ष लागत लाभ (Absolute cost advantage) प्राप्त है, किन्तु ब देश 'ल' वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, क्योंकि उसे इसी वस्तु में निरपेक्ष लागत लाभ है। बाद में वे इन्हे परस्पर विनिमय कर लेंगे और इस क्रिया के फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के विस्तार द्वारा लाभ उठावेंगे। अन्य शब्दों में कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो जायेगी। [उपरोक्त तालिका में जिस परिस्थिति को प्रस्तुत किया गया है उसे 'लागतों की निरपेक्ष भिन्नता' (Absolute Difference in Costs) कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश एक वस्तु दूसरे देश की अपेक्षा निरपेक्ष रूप से कम लागत पर बना सकता है।]

वास्तविक जगत में हम यह देखते हैं कि विश्व व्यापार का एक बड़ा भाग सागत सम्बन्धी निरपेक्ष भिन्नता पर ही आधारित है। इस विषय में हमारा ध्यान तुरन्त ही उत्पन्न और समशीतोष्ण देशों के मध्य होने वाले व्यापार पर जाता है। हम 'वास्तविक लागत' सम्बन्धी धारणा की कुछ भी व्याख्या क्यों न करें, यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उत्पन्न कटिमान्द्योय उत्पन्न समशीतोष्ण देशों में प्रथम तो उत्पन्न ही नहीं की जा सकती और यदि किसी प्रकार उन्हें वहाँ उत्पन्न करना सम्भव हो भी, तो बहुत अधिक लागत पर ही उत्पन्न की जा सकेंगी। यही बात उर्वरा भूमियों वाले कुछ देशों और कोयला एवं लोहे की खानों वाले औद्योगिक देशों के

दारे में देखी जाती है। इन परिस्थितियों में, सरसता में यह देखा जा सकता है कि विनिष्ठीकरण और व्यापार के कलस्वरूप विश्व-उत्पादन तथा विश्व माय यथेष्ट मात्रा से बढ़ जाती है। अगूरो और शराब के उत्पादन के उदाहरण द्वारा एडम स्मिथ ने यह दर्शाया कि अपेक्षित कम पूँजी और कम श्रम के प्रयोग की आवश्यकता वाली वस्तुओं के बदले में अगूरो का आयात न करते हुए यदि स्काटलैण्ड में ही अगूर उत्पन्न किया गया तो इस देश को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी।

परीक्षा प्रश्न :

- १ एडमस्मिथ द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का विवेचन कीजिये।

[Discuss the classical theory of international trade with particular reference to Adam Smith]

- २ 'श्रम-विभाजन' और 'स्वतन्त्र व्यापार' के समर्थन में तर्क दीजिये।

[Give arguments to support "division of labour" and "freedom of trade"]

- ३ 'आधुनिक विश्व में देशों के मध्य व्यापार के उदय का एक मात्र कारण लागतों का निरपेक्ष अन्तर है।' इस कथन की सावधानी से समीक्षा कीजिये।

["Absolute Difference in Costs alone give rise to the phenomenon of trade between countries of the present day world. Examine this statement carefully"]

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त

(रिकाडों का दृष्टिकोण)

(The Theory of Comparative Costs)

परिचय—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त क्या है ?

जबकि एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ (Absolute advantage) को अधिक महत्व दिया, तब डेविड रिकाडों (David Ricardo) ने तुलनात्मक लाभ (Comparative advantage) पर अधिक बल दिया। यद्यपि विश्व के व्यापार का एक बड़ा भाग लाभतो में निरक्षेप अन्तर पर आधारित है, जिससे एडम स्मिथ ने ठीक ही इसे एक सामान्य प्रचलित दशा माना, तथापि रिकाडों इसे एक सामान्य प्रचलित दशा स्वीकार नहीं करते। वे इस स्थिति को कम प्रचलित मानते हुये अपने सिद्धान्त का विवेचन एक अन्य स्थिति से, जो उनकी सम्मति में बहुत प्रचलित है, प्रारम्भ करते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम अनुकूल परिस्थितियों में भी लाभ सहित किया जा सकता है। उनकी यह मान्यता थी कि उस दशा में भी, जिसमें कि एक देश को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में अन्य देश की अपेक्षा एक निरपेक्ष लागत लाभ प्राप्त है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों ही देशों के लिये लाभप्रद हो सकता है, बशर्ते कि प्रथम देश सबसे अधिक लाभदायक वस्तु के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करे और दूसरी वस्तु के उत्पादन का कार्य अन्य देश पर छोड़ दे। यह नियम ही 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' कहलाता है।

यद्यपि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पर रॉबर्ट टोरेन्स (Robert Torrens) ने भी, किन्तु कम प्रभावपूर्ण दृष्टि से, विचार किया था, तथापि रिकाडों को ही इस सिद्धान्त का वास्तविक प्रणेता माना जाता है। प्रो० हैबरलर (Haberler) ने यह दिखा दिया है कि रिकाडों के सिद्धान्त के लगभग प्रत्येक भाग पर इनके पूर्ववर्तियों ने कुछ न कुछ विचार किया था, किन्तु एडम स्मिथ के सहस्र रिकाडों की प्रतुलनीय प्रतिभा विभाजित सत्यो को एक समन्वित और व्यापक सत्य में परिचित करने के

महाश्र कार्य में समान हुई ।¹ हैरिस के अनुसार, निरपेक्ष लाभ के बजाय सापेक्षिक लाभ पर बल देना ही, एडम स्मिथ की तुलना मेरिकाडों की महानता का सूचक है ।²

रिकाडों के सिद्धान्त की मान्यताये

सुगमता की दृष्टि से रिकाडों ने भी दो देशों और दो वस्तुओं वाला मॉडल बना । उन्होंने पुर्तगाल और इङ्ग्लैंड को लिया तथा कपड़ा और गन्नाय यह दो वस्तुएँ लीं । सरलता की दृष्टि से ही उन्होंने समस्त लागतों को श्रम-घण्टों (Hours of labour) में मापा । एडम स्मिथ की भाँति-उन्होंने यह माना कि श्रम एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य तो पूर्ण गतिशील है किन्तु देशों के मध्य पूर्ण गतिहीन । उन्होंने यातायात व्ययों का विचार में नहीं लिया । उन्होंने यह माना कि प्रत्येक वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत प्रत्येक देश में स्थिर (Constant) रहती है । हाँ, मिट्टी, जलवायु, कृषि एवं खनिज-प्रसाधनों की भिन्नताएँ दोनों देशों में विभिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक लागत में अनेक भिन्नताएँ उत्पन्न कर सकती हैं । विभिन्न धन्यों से सम्बन्धित कौशल और पूँजी की मात्राओं में, जिनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के श्रम को सकल बनाने के लिये होती है, अन्तरों की अपेक्षा कर दी गई है अथवा यो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के श्रमों या पूँजी स्टाँकों के मूल्य एक प्रमाण कुशलता वाले श्रम के मूल्य के स्वर्भ में व्यक्त किये गये हैं । अतः किसी भी देश में वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत उस देश के एक प्रमाण कुशलता वाले श्रम की मात्रा के समानुपात में होती है । चूँकि यातायात निशुल्क किया जाता है, इसलिए दोनों देशों में विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्य (Relative values) सामान्यतः एक ही रहेंगे । अर्थात् यदि दो इकाई कपड़े का मूल्य इङ्ग्लैंड में १ इकाई गन्नाय के मूल्य के बराबर है, तो पुर्तगाल में भी २ इकाई कपड़े का मूल्य १ इकाई गन्नाय के बराबर ही होगा ।³

¹ "Prof. Haberler, has shown that nearly every part of Ricardo's doctrine was anticipated by some of his predecessors, but his matterly genius like that of Adam Smith, was largely occupied with the supreme task of building up a number of fragmentary truths into coherent doctrine."—A. Marshall *Credit and Commerce*, 1923 edn, p. 41.

² "This emphasis on comparative advantage as opposed to absolute advantage marks Ricardo's great advance over Adam Smith."—S. E. Harris : *International and Inter-regional Economics*, p. 15

³ "Marshall put Ricardo's assumptions as follows :—'We may proceed on Ricardo's lines, and suppose that E and G are neighbouring islands which trade with one another, the goods (See page 68)

रिकाडों के सिद्धान्त की व्याख्या

रिकाडों ने गुंतगात और इङ्गलैंड के मध्य निम्नलिखित परिस्थिति को उदाहरणस्वरूप चुना —

श्रम लागत संरचना की तुलना

उत्पाद	गुंतगात में श्रम-लागत	इङ्गलैंड में श्रम लागत
१ इकाई शराब	२० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम	१२० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम
१ इकाई कपड़ा	६० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम	१०० व्यक्तियों का १ वर्ष का श्रम

निरपेक्ष लाभ की परिस्थिति में (देखिये पिछला अध्याय) की एक साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी यह मान जायेगा कि दो देशों (मान लीजिए कि अ और ब) के मध्य जबकि अ देश को 'क' वस्तु में और ब देश को 'ख' वस्तु में श्रेष्ठता प्राप्त है व्यापार पारस्परिक रूप में लाभदायक है क्योंकि 'क' वस्तु की १ इकाई उत्पन्न करने में अ देश को ब देश की अपेक्षा कम श्रम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु 'ख' वस्तु की १ इकाई उत्पन्न करने में ब देश को अ देश की अपेक्षा कम श्रम-इकाइयों की जरूरत होती है। यह बताने के लिए कि ऐसी दशा में अ देश 'क'

(From page 67)

being carried at public expense to the extent of one half by either island, and thus the cost of transport is eliminated from the trading account, the peoples, however, are supposed to be intolerant of one another's customs, and to refuse to migrate from one island to the other. The real cost of production of each commodity in each island is taken to be constant, though differences of soil, climate, agricultural and mineral resources cause many differences in the relative cost of various commodities in the two islands. Differences in the relative cost of various commodities and in the amount of capital by which each man's labour needs to be assisted, are neglected (or else the values of the several classes of labour and stocks of capital are expressed in terms of the value of 1 hour of a standard efficiency), so that the real cost of production of any commodity in either island can be regarded as proportional to the amount of the standard labour of that island. Also transport being gratuitous, the relative values of different things would of course remain generally the same in the two islands, if a quarter of oats and a hundred weight of sugar were of equal value in one island, they would be of equal value also in the other"—*Money, Credit and Commerce*, pp 322-323.

वस्तु में और व देश का' वस्तु में विनिष्ठीकरण करेगा, साधारण व्यक्ति को किसी रिकार्डों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

किन्तु रिकार्डों ने तो इसमें बड़ी अधिकृतता दी। उनमें दिखाया कि यदि प्र देश दोनों ही वस्तुओं व देश की तुलना में कम द्रव्यमानों द्वारा बना होता हो, तो भी उनके मध्य व्यापार लाभदायक हो सकता है। ऐसी ही परिस्थिति ऊपर की तालिका में दिखाई गई है। रिकार्डों ने यह प्रमाणित किया है कि यदि पुर्तगाल शराब के उत्पादन में और इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विनिष्ठीकरण करते हुये इन उत्पादकों का परस्पर विनिमय करने, तो इंग्लैंड और पुर्तगाल दोनों ही लाभान्वित होंगे। रिकार्डों के शब्दों में —

“इंग्लैंड की स्थिति इस प्रकार की हो सकती है कि उसे कपड़ा उत्पन्न करने के लिए प्रति वर्ष १०० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़े और यदि उसने शराब बनाने का फैसला किया, तो उसे उसकी आवश्यकता के लिये १२० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यह इंग्लैंड के हित में होगा कि वह कपड़े का निर्यात करके पुर्तगाल से शराब का आयात करे।”

“पुर्तगाल में शराब के उत्पादन के लिये केवल ८० व्यक्तियों के एक वर्ष के श्रम की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वह कपड़ा उत्पन्न करे, तो उसे उसी अवधि के लिये ६० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। अतः उनके लिए यह लाभदायक होगा कि वह कपड़े के बदले में शराब का निर्यात करे। यह विनिमय इस तथ्य के बलपूर्वक होगा कि पुर्तगाल जिस वस्तु का आयात करता है वह वहाँ इंग्लैंड की भविष्य कम श्रम से बनाई जा सकती है। यद्यपि वह कपड़े का उत्पादन ६० व्यक्तियों के श्रम द्वारा कर सकता है तथापि वह इसे उस देश से आयात करेगा जहाँ कि इसका उत्पादन करने के लिये १० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता पड़ती है, कारण, शराब के उत्पादन करने में पूँजी लगाने में उसे ‘विशेष’ लाभ है। वह इसका निर्यात करके इंग्लैंड के उनसे कपड़े से, जो कि वह शराब के उत्पादन में लगी हुई पूँजी का कुछ भाग कपड़े के निर्माण में मोड़कर उत्पन्न करता, अधिक मात्रा में कपड़ा आयात कर सकता है।”

‘इस प्रकार, इंग्लैंड ८० व्यक्तियों के श्रम की उपज के बदले में १०० व्यक्तियों के श्रम की उपज देगा। ऐसा विनिमय उसी देश के व्यक्तियों के मध्य नहीं हो सकता था। १०० अंग्रेजों के श्रम की उपज ८० अंग्रेजों की उपज के बदले में नहीं दी जा सकती, किन्तु १०० अंग्रेजों के श्रम की उपज ८० पुर्तगालियों ६० रुसियों अथवा १२० आरतियों के श्रम की उपज के बदले में दी जा सकती है इस सम्बन्ध में अन्तर का कारण यह है कि अधिक उपयोगी रोजगार दूँदने के लिए

¹ *The Works and Correspondence of David Ricardo* (Stallia, ed 1952, vol. I, pp 135-136.

पूँजी एक देश-से दूसरे देश की बड़ी कठिनाई से जाती है किन्तु एक ही देश में एक प्रांत में दूसरे प्रांत की बड़ी सुगमता से चली जाती है।¹

देश के भीतर साधनों की गतिशीलता और देशों के मध्य गतिहीनता

ऐसे विनियम एक ही देश के भीतर क्यों सम्भव नहीं होंगे, इसका कारण रिकार्डों ने यह बताया कि पूँजी और धन उन भागों में चले जायेंगे जहाँ कि उनकी उत्पादकता अधिक थी। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय अर्थव्यवस्थाओं में विरोध इस मान्यता पर आधारित है कि पूँजी और जनसंख्या एक देश के भीतर तो गतिशील है लेकिन देश के मध्य यह गतिहीन है। 'मिसन्देश इङ्ग्लैंड के पूँजीपतियों और दोनों देशों के उपभोक्ताओं के लिए यह सामंजस्य होगा कि इन परिस्थितियों के अन्तर्गत बाराब और कपड़ा दोनों ही पुर्तगाल में उत्पन्न किये जायें और इसलिये कपड़ा बनाने में इङ्ग्लैंड का जो धन और पूँजी लगी हुई है उसे इस कार्य के लिए पुर्तगाल भेज दिया जाय। उस देश में इन वस्तुओं के तापेक्षिक मूल्य का नियमन उसी नियम के अनुसार होगा जो कि सब लागू होता जब कि इनमें से एक माकशामर की ओर बूतरी सन्तान की उपज होती, और अन्य प्रत्येक वस्त्र में, यदि पूँजी उन देशों की, जहाँ उसका सबसे सामंजस्य तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, स्वतन्त्रतापूर्वक जा सकती है तो लाभ की दर में कोई अंतर नहीं होगा एवं वस्तुओं की वार्षिक (या श्रम) लागत में, बिक्री के लिए विभिन्न बाजारों में वस्तु की स्थानान्तरित करने के धन की मात्रा के अतिरिक्त अन्य कोई भिन्नता न होगी।'²

किन्तु अनुभव से पता चलता है कि पूँजी की सुरक्षा (काल्पनिक या वास्तविक), जबकि यह इसके स्वामी के तात्कालिक नियन्त्रण में रहते, साथ में प्रत्येक व्यक्ति की, अपने पितृ देश और पुराने सम्बन्धों की छोड़ने तथा अपनी पुरानी भावनाओं को एक नये देश की परम्पराओं, नई सरकार, नये कानून या वि के अनुरूप आसने के सम्म प में स्वाभाविक प्रवृत्ति पूँजी के प्रवास को रोकती है। ये भावनाएँ, जिन्हें दुर्घट हात छुये देखकर मुझे खेद होगा, अनेक पनी व्यक्तियों को विदेशी राष्ट्रों में अपनी सम्पत्ति के लिए अधिक लाभदायक रोजगार या उपयोग खोजने के बजाय अपने ही देश में कम दर के लाभ से ही संतुष्ट रहने को प्रेरित करती हैं।³

किन्तु यह समझ लेना चाहिये कि रिकार्डों ने इस बात पर बल नहीं दिया था कि जनसंख्या और पूँजी कभी भी राष्ट्र की सीमाओं से बाहर नहीं जाती। मिसन्देश यह इस बात को जानता था कि ऐसे आवागमन होते हैं, किन्तु एक देश के भीतर होने वाले आवागमनों की अपेक्षा कम सत्ता में। इसी प्रकार, यद्यपि उसने अपने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विकास दो वस्तुओं की मान्यता के आधार पर किया था, तथापि उसने सिद्धान्त का सन्दर्भ दो से अधिक वस्तुओं के

¹ *Ibid*, pp. 136-137

प्रति जोड़ने की अपेक्षा नहीं की थी। “सुखमता के लिये मैं यह मानता रहा हूँ कि दो देशों के मध्य व्यापार दो वस्तुओं तक सीमित है—कपड़ा और शराब, किन्तु यह सब जानते हैं कि आयात और निर्यात की सूचियों में अनेक ऐसे विभिन्न वस्तुयें प्रवेश करती हैं।”¹

८-रिकार्डों के योगदान की आलोचना

जॉन स्टुअर्ट मिल ने रिकार्डों के योगदान का जो सविस्तर विवरण दिया है वह इसके महत्त्व का एक श्रेष्ठ सूचकांक है। मिल (Mill) ने लिखा है कि—“राजनैतिक प्रत्यक्षानुभव को रिकार्डों ने जितने सच्यों (Truths) से सम्पन्न बनाया है उसमें से किसी ने भी ज्ञान की इस शाखा को वह सही और वैज्ञानिक स्वभाव, जो कि इसे प्राप्त है, दिलाने में इतनी सहायता नहीं की, जितनी कि उसके द्वारा दिये गये वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से राष्ट्रों को होने वाले लाभ के स्वभाव के सहो विस्लेषण ने की है।”²

रिकार्डों ने यह दिखाया कि राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय से होने वाले लाभ एक मात्र इस बात में निहित है कि यह प्रत्येक को, श्रम और पूँजी की एक ही हुई मात्रा के बदले में, कुल पर सब वस्तुओं की अधिक मात्रा प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

‘चूँकि प्राम, एक देश के पास दो वस्तुयें होती हैं जिनमें से वह एक को विदेशी देश की तुलना में, कम श्रम-लागत पर बना सकता है, इसलिए वह उस देश के हित में होगा कि वह प्रथम उत्प्रेक्षित वस्तु का निर्यात और दूसरी वस्तु का आयात करे, भले ही वह दोनों वस्तुओं को अपने यहाँ विदेशी देश की प्रवेक्षा श्रम के कम व्यय पर (किन्तु समान मात्रा में कम श्रम-व्यय पर नहीं) अथवा दोनों ही वस्तुयें अधिक व्यय पर (किन्तु समान मात्रा में अधिक व्यय पर नहीं) बना सकता हो। इसके विपरीत, यदि यह दोनों ही वस्तुयें अधिक सुविधा से अथवा अधिक

1 “To simplify question, I have been supposing the trade between two countries to be confined to two commodities—to wine and cloth; but it is well known that many and various articles enter into the list of exports and imports.”—*Ibid.*, p. 141.

2 “Of the truths with which political economy has been enriched by Mr. Ricardo, none has contributed more to give to that branch of knowledge the comparatively precise and scientific character which it at present bears, than the more accurate analysis which he performed of the nature of the advantage which nations derive from a mutual interchange of their productions.....”—J. S. Mill: *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*, pp. 1-3.

कठिनाई में उत्पन्न कर सकता है और यह अधिकता समान अंशों में है, तो पारस्परिक विनिमय के लिये कोई प्रसौभन नहीं रहेगा।”¹

स्मिथ रिकार्डों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का मूल्यांकन

सम्पूर्ण १९वीं शताब्दी में और बीसवीं शताब्दी के भी पहले २०-२० वर्षों में एडम स्मिथ रिकार्डों द्वारा प्रतिपादित (एव तदुपरान्त मिल द्वारा सुधारा हुआ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक सामान्यन स्वीकृत स्पष्टीकरण था। किन्तु यह सिद्धान्त बहुत दुर्बल था, क्योंकि इसकी मान्यतायें बहुत ही कार्त्तिक थीं। आधुनिक वर्षों में कई प्रसिद्ध लेखकों ने, जिनमें मोगूलन और ब्राह्म उल्लेखनीय हैं, इसकी बहुत आलोचना की है। प्रमुख आलोचनायें सक्षम में नीचे दी गई हैं।

(१) केवल धन लागत ही तुलना का सर्वश्रेष्ठ आधार नहीं—स्मिथ-रिकार्डों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त धन लागतों (labour costs) पर आधारित है। अन्य तथ्य (जैसे भूमि, पूँजी और साहस) जोकि लागत का अंग होते हैं और समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, सिद्धान्त में विस्फुल ही स्थान प्राप्त करते हैं। यह धारणा की बात है कि जबकि लागतों और मूल्य का धन-सिद्धान्त (labour theory of costs and prices) १९वीं शताब्दी में ही, धन के अति-स्पर्धी समूहों की विद्यमानता तथा उत्पत्ति के अन्य साधनों के साथ साथ धन की विभिन्न गुण-सम्पन्न धारणियों को सम्मिलित करने की आवश्यकता के कारण, स्थापित किया गया था, तब इस अप्रशंसित सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बनाये रखा गया। आलोचकों ने इस मान पर ठीक ही बल दिया है कि धन-लागत दृष्टि कोण को अब छोड़ देना चाहिए। यथार्थ में यह कीमतें ही हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि किन वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार किया जायेगा और किन देश उन्हें उरररर

1 "As often as a country possesses two commodities one of which it can produce with less labour, comparatively to what it would cost in a foreign country, than the other, so often it is the interest of the country to export the first mentioned commodity and to import the second, even though it might be able to produce both the one and the other at a less expense of labour than the foreign country can produce them but not less than in the same degree or might be unable to produce either except at a greater expense, but not greater in the same degree. On the contrary, if it produces both commodities with greater facility, or both with greater difficulty and greater in exactly the same degree, there will be no motive to inter-change"—*Ibid* pp 13

करेगा। अतः यह उचित होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का कीमतों के सम्बन्ध में विश्लेषण किया जाय।

[किन्तु प्रो० टॉजिंग ने चतुर्दशपूर्वक यह समझाते हुये कि उत्पादन के अन्य सब तत्त्व (पूँजी आदि) अन्तिम विश्लेषण में मजदूरियों से कुछ भिन्न प्रमाणित नहीं होते, अतः लागत सिद्धान्त का समर्थन किया था।]

(२) स्थिर लागतों की माध्यता वास्तविक संसार में उपपन्न नहीं—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की यह मान्यता है कि लागतें स्थिर रहती हैं। किन्तु वास्तविक संसार में अधिकांश वस्तुएँ या तो बढ़ती हुई लागती (उपज-ह्रास) के अन्तर्गत या फिर घटती हुई लागतों (उपज-वृद्धि) के अन्तर्गत ही उत्पन्न की जाती हैं। इस दोष को दूर करने के लिये ही बेस्टेबिल (Bastible) ने सिद्धान्त में परिवर्तनीय लागतों (Variable costs) की धारणा को सम्मिलित किया।]

(३) यातायात व्ययों की भी विचार में लेना आवश्यक—प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने यातायात व्ययों (transport costs) की उपेक्षा कर दी है। निर्यात वस्तुओं का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि उनमें यातायात व्यय लग सकें और आयात वस्तुओं का मूल्य ऊँचा होना चाहिए। मान लीजिए कि दो देशों के मध्य व्यापार नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में, यदि यातायात-व्यय कीमत भिन्नताओं (Price differentials) में अधिक है, तो व्यापार आरम्भ न हो सकेगा। वास्तव में इसी कारण से अनेक वस्तुओं और सेवाओं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश नहीं करती हैं। विवेचन जहाँ दूरियाँ और यातायात साधन प्रलग-प्रलग हैं, वहाँ यातायात-व्यय लागत-अनुपातों (cost ratios) में भिन्नता का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जर्मनी के वन्दरगाह, द्वितीय महायुद्ध के पहले, इससे से कोयला मँगाते थे, यद्यपि जर्मनी स्वयं कोयले का एक विख्यात उत्पादक और निर्यात करने वाला था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार एक देश का एक भाग किसी वस्तु का आयात कर सकता है जबकि उसी देश का दूसरा भाग उसे उत्पन्न करता है और निर्यात भी कर सकता है। इससे यातायात व्ययों की विचार में लेने का महत्व स्पष्ट है।

[कुछ भर्षणास्त्रियों ने इस समस्या के समाधान के लिए यह मान लिया है कि जो देश किसी वस्तु का निर्यात करता है वही इसके यातायात व्यय को भी वहन करता है तथा यातायात व्यय उत्पादन-लागत में शामिल रहते हैं।]

(४) यह मान लेना ठीक नहीं कि उत्पात के साधन आन्तरिक रूप से पूर्ण गतिशील हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय रूप से पूर्ण गति रहित—वास्तविक जगत में, उत्पात के विभिन्न साधन एक ही देश के एक भाग से दूसरे भागों की भाँति एक उद्योग से दूसरे उद्योग या उद्योगों में पूर्ण गतिशील नहीं होते। इसका प्रमाण यह है कि विभिन्न पदों और विभिन्न धनो मजदूरी की विभिन्न दरें प्रचलित होती हैं। निःसन्देह, एक सीमा तक समायोजन होना सम्भव है लेकिन इसकी गति बहुत

धीमी होती है। परिणामतः मध्यांतर (Interval) से, साधनों की गतिहीनता कीमतों को प्रभावित कर देती है और कीमतों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के प्रवाह पर भी असर पड़ता है। स्मरणयोग्य है कि साधनों की आन्तरिक गतिहीनता अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण का, जिसके साधन एक देश को एक विशेष वस्तु या वस्तुयें ही उत्पन्न करनी पड़ती हैं परिणाम है।

(५) जब व्यापार करने वाले दोनो देश असमान आर्थिक धाकार वाले हों या जब व्यापार की वस्तुओं का असमान आर्थिक मूल्य हो, तब यह सिद्धान्त लागू नहीं होता—प्रो० ग्राहम (Graham) ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निम्न दो निष्कर्षों की कटु आलोचना की है—(i) कि सुननासक लागतों के अन्तर्गत प्रत्येक देश किसी एक वस्तु में ही विशिष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, और (ii) कि व्यापार का लाभ दोनों देशों के मध्य समान रूप से विभाजित होता है। उनका कहना है कि “प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह निष्कर्ष तब ही सच हो सकता है जबकि वह मानकर दोनों पक्षों को समान कर दिया जाय कि व्यापार से सम्बद्ध दोनों वस्तुओं का कुल उपभोग मूल्य समान है तथा व्यापार समान आर्थिक महत्त्व रखने वाले दो देशों के मध्य होता है।”¹ किन्तु जब हम एक बड़े देश (जैसे कि अमेरिका) और एक छोटे देश (जैसे कि जर्मनी) का उदाहरण लेते हैं, तो हम यह देखेंगे कि छोटा देश पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण करने की स्थिति में होगा, क्योंकि उसकी अतिरिक्त उपज बड़े देश में सुगमतापूर्वक विक्रयार्थ, किन्तु बड़ा देश पूर्ण रूप से विशिष्टीकरण नहीं कर सकेगा, क्योंकि (i) दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा उसे अपने उपभोग के लिए आवश्यक है उसे वह विदेशी देश से प्राप्त नहीं कर पावेगा, और (ii) उसका अपनी विशिष्टीकृत वस्तु का समस्त उत्पादन उस छोटे देश में विक्रय सकेगा। स्पष्टतः बड़े देश की दोनों ही वस्तुयें उत्पन्न करनी पड़ेंगी तथा ऐसी दशा में समस्त लाभ दोनों देशों द्वारा समान रूप से, जैसा कि मिल एव प्रतिष्ठित वर्ग के अर्थ-सदस्यों की कल्पना थी, प्राप्त नहीं किया जा सकेगा बल्कि सबका सब लाभ छोटे देश द्वारा ही उठाया जावेगा।

इसी प्रकार, उस दशा में भी अपूर्ण विशिष्टीकरण होगा जबकि व्यापार से सम्बन्धित दोनों वस्तुयें असमान मूल्य की हों। उदाहरण के लिए कपड़े और दियानसाई की ही लीजिए। यहाँ दियानसाई के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने वाला देश अपूर्ण विशिष्टीकरण करेगा क्योंकि उसके निर्यातों का मूल्य उसकी कपड़ा सम्बन्धी समस्त आवश्यकता के प्रत्यक्ष की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त होगा। अतः उसे

1 “This conclusion of classical economists can hold ground only if the dice are loaded by assuming trade in two commodities of approximately equal consumption value and between two countries of approximately equal economic importance”

कपड़ा और दियामसार्ड दोनों ही चीज उत्पन्न करनी पड़ेगी। फिर ऐसी दशा में लाभ का समान रूप से तो नया असमान रूप से भी विभाजन नहीं होता, वरन् कुछ लाभ बण्डा निर्गता करने वाले देश द्वारा ही हृष्य कर लिया जाता है।

(६) श्रम की गतिहीनता स्वतन्त्र प्रतिযোগिता की मान्यता से असङ्गत है—श्रम-सूत्र सिद्धान्त, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का आधार है, इस मान्यता पर निर्भर है कि श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। किन्तु हमारे वास्तविक संसार में एकाधिकारिक मजदूरी-एकाधिकारिक परिस्थितियाँ ही हमारी मध्य व्यवस्थाओं का सक्षण बनी हुई हैं। उदाहरणार्थ, श्रम संघों (labour unions) और मास्तिन-संघों (employers' unions) की विघ्नमयता श्रम और पूँजी को एक बड़ी सीमा तक अगतिशील (immobile) बना देती है जिससे वह सर्वोत्तम बाजार को धारणों और शीघ्रता से नहीं सामने जाने पाते जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत ऐसा ही होना चाहिए था।

(७) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में केवल पूँति पक्ष का ही विचार किया गया है—यह सिद्धान्त इस बात को तो बतलाता है कि एक देश कौन-सी वस्तु बेचेगा या खरीदेगा, किन्तु यह नहीं बताता कि इन वस्तुओं में व्यापार किन कीमतों पर किया जावेगा। इस प्रश्न के लिए यह जरूरी था कि माँग पक्ष का भ्रमर्यन किया जाय। रिकार्डों ने तो केवल इतना ही कहा था कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस बात का निश्चय करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कौन-सी वस्तुएँ खरीदी-देची जाएंगी और मिल ने यह स्पष्ट किया था कि प्रतिपूरक माँग (reciprocal demand) उन कीमतों को निर्धारित करती है जिन पर वस्तुएँ विनिमय की जाएंगी। किन्तु इस ढङ्ग से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माँग और पूँति पक्षों (demand and supply sides) को पृथक्-पृथक् करना प्रुटिपूर्ण था। सच तो यह है कि माँग एवं पूँति दोनों ही समुक्त रूप से खरीदी और देची जाने वाली वस्तुओं की मात्राएँ और कीमतें निर्धारित करती हैं।

(८) समान साधन-सम्पत्ति वाले देशों के मध्य भी व्यापार बन सकता है—विषय के गर्म और शीतोष्ण कटिबंधों के मध्य अथवा घनों जन-संख्या वाले औद्योगिक देशों और कम जन-संख्या वाले कृषि देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का कारण स्पष्टतः इन देशों की साधन-सम्पत्तियों में भिन्नता होता है। किन्तु समान साधन सम्पत्ति (factor endowment) वाले देशों (उदाहरणार्थ औद्योगिक देशों) ने मध्य भी व्यापार बन सकता है, क्योंकि उपज वृद्धि नियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप उनकी तुलनात्मक लागतों में भिन्नता आ जाती है।

(९) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त स्थैतिक मान्यताओं पर आधारित है—इस सिद्धान्त में इस प्रकार की मान्यताएँ की गई हैं कि रुचियाँ, भूमि, श्रम और पूँजी भाँति उत्पत्ति साधनों की पूर्तियाँ स्थिर (constant) रहती हैं। चूंकि ये मान्यताएँ स्वभाव से स्थैतिक (static) हैं इसलिए वे सिद्धान्त को वास्तविक जगत

के लिए, जो कि प्रारंभिक या गतिमान (dynamic) है, अनुपयुक्त बना देती है। उदाहरणार्थ प्रदर्शन प्रभाव (demonstration effect) के कारण रूढ़ियाँ परिवर्तन होता रहना है, नतीजतन विचारों के माय-माय टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन होते रहते हैं और साधन भी परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील टेक्नोलॉजी एवं साधन सम्पत्ति वाली परिस्थिति में तुलनात्मक लागतों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

(१०) कार्यान्वयन की दृष्टि से मॉडल प्रतिबन्धात्मक है— स्थायी रिवाजों 'माडल' (Model) कार्यान्वयन की दृष्टि से प्रतिबन्धात्मक (restrictive) है क्योंकि यह केवल दो देशों और दो वस्तुओं से ही सम्बद्ध है। अन्य शब्दों में यह एक प्रति-सुगम (over simplified) माडल है। लेकिन जब हम शून्य दशों और अनन्त वस्तुओं की परिस्थिति पर विचार करते हैं तो सिद्धान्त की गुणगना जानी रहती है। [यह उल्लेखनीय है कि बेस्टेबिल (C F Bastable) ने इस सिद्धान्त को दो से अधिक देशों और दो से अधिक वस्तुओं पर विस्तृत करने का प्रयत्न किया है।]

(११) प्रतिष्ठित सिद्धान्त दो देशों के मध्य उन वस्तुओं के व्यापार की उपेक्षा करता है जोकि उनमें से केवल एक देश द्वारा ही उत्पादन की जाती है। इस तरह उसने आयात निर्यात सूची के सबसे महत्वपूर्ण अंग को छाड़ दिया है।

(१२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वास्तविक या भौतिक लागतों की भिन्नता पर निर्भर नहीं है—तुलनात्मक लागत भिन्नता की एक अन्य दुर्बलता यह है कि देशों के मध्य व्यापार लागत भिन्नताओं पर (चाहे ये भौतिक हों या वास्तविक) निर्भर नहीं करता, जैसा कि यह सिद्धान्त सुझाता है। आयातकर्ता लाभों के कारण चिन्ता नहीं करते। उन्हें तो उन कीमतों से मतलब है जो कि वे चुकायेंगे। इस प्रकार वस्तुओं की कीमतों का अनुपात (ratio of prices) ही वस्तुओं और भवाया के समस्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का आधारभूत कारण है।

(१३) एक देश जान बूझकर एक विशेष वस्तु उत्पन्न करने का यत्न कर सकता है—ताम्र एवं बुनियादी महत्व के कारण एक देश एक विशेष वस्तु के बनाने के लिए जानबूझकर यत्न करता है चाहे इसके उत्पादन में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं हो और विदेशों से उसका सस्ती कीमतों पर आयात किया जा सकता हो। उदाहरणार्थ, भारत ऊँची लागत सहन करके भी उद्योगों और दक्षिण के कुछ राज्यों में पटसन उत्पन्न करता है मने ही वह इसे पारिस्तायिक से कम क्षमता पर बना सकता था।

(१४) जब कोई देश वस्तु की एक किस्म का तो आयात करे किन्तु दूसरी किस्म का निर्यात, तो ऐसी परिस्थिति में प्रतीक्षित सिद्धान्त लागू नहीं होता। उदाहरणार्थ, भारत बपड़े की महँगी एवं थोड़ी किस्म का आयात करता है किन्तु सस्ता एवं मोटी किस्मों का निर्यात। [हथारी सम्पत्ति में इसे सिद्धान्त की सीमा कहा जाता है क्योंकि आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत वस्तु की विभिन्न किस्मों को पृथक् पृथक् वस्तुओं माना जाता है।]

(१२) विश्वेषण का एक भीषण और खतरनाक साधन— ओहलिन (Ohlin) ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त की कटु आलोचना करते हुए इसे विश्वेषण या एब बेड्या (chummy) और खतरनाक साधन (dangerous tool) बताया है। उक्त निदोघन वेदना इसलिये है कि यह इस बात की परीक्षा नहीं करता कि एब देश में उत्पादन का संस्थापन किस सीमा तक नीची मजदूरियों, नीचे व्याज, न्यून मातावात व्यय आदि के कारण है और खतरनाक इसलिये है कि यह केवल दो देशों और दो वस्तुओं मानी परिस्थितियों का विश्लेषण करता है किन्तु इसके निष्कर्षों को सामाजिक परिस्थितियों पर, जिनमें अनेक देशों और अनेक वस्तुओं का प्रश्न उत्पन्न है, लागू करने का यत्न किया जाता है।

तुलनात्मक लाभ सिद्धान्तों की अवास्तविक मान्यताओं का परित्याग

संक्षेप में तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त यह है कि विदेशी व्यापार का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों को चाहिए कि उनमें से प्रत्येक उस वस्तु में विशेषीकरण कर जिसमें वह सबसे मज्जत उत्पन्न कर सकता हो। 'सहमे सत्ता उत्पादन' कहा है, इसे 'विदेशी व्यापार विषय के लेखकों ने प्रायः आरम्भ में दो वस्तुओं और दो राष्ट्रों का उदाहरण देकर समझाना सुविधाजनक समझा है। इसके बावजूद एक-एक बरके जटिल तर्कों को सम्मिलित करके विचार किया जाता है।'¹

(1) मौद्रिक लागत—

उत्पादन में तुलनात्मक सस्तेपन (या लाभ) की देखने व लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन मापन के माप की एक इकाई हो। किन्तु विभिन्न देशों में एक ही इकाई माप के लिए प्रयोग की जाय ऐसा न हो आवश्यक है और न सम्भव ही है। लागतों की परेशानी (trouble), प्रयत्न (effort) अथवा इसके लिये दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में मापा जा सकता है। यह पुरस्कार एक निश्चित मात्रा में उपभोग वस्तुओं अथवा द्रव्य ही सत्यता है। हैबर्स्टर के मतानुसार लागत को अपसर-लागत के रूप में प्रगट किया जा सकता है। यहाँ पर हम मौद्रिक लागत श्रवणति हुए यह देखेंगे कि क्या मौद्रिक अवस्थितियों में भी तुलनात्मक लाभ का सिद्धान्त वैध है। उस प्रकार का प्रयत्न सर्वप्रथम टॉसिग (Tausig) ने किया था। उन्होंने श्रम लागत के तुलनात्मक अंतरों की बीमती के निरपेक्ष अंतरों में यशस्वी दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसे हम नीचे प्रस्तुत करते हैं—

वस्तुओं की श्रम लागतें

देश	श्रम लागत	यहाँ की उत्पादित इकाइयों	कपड़े की उत्पादित इकाइयों
अमेरिका	१० दिन का श्रम	२०	२०
जर्मनी	१० दिन का श्रम	१०	१५

¹ Habeslet : *The Theory of International Trade*, pp. 132-144.

यहाँ अमेरिका की उत्पादन की दोनो ही शाखाओ में जर्मनी की अपेक्षा निरपेक्ष (absolute) ग्रेष्ता प्राप्त है और गेहूँ में तुलनात्मक लाभ (comparative advantage) है। आ अमेरिका गेहूँ में और जर्मनी कपडे में विनिम्बोकरण करेगा। मुद्रा के रूप में स्थिति इस प्रकार होगी —

वस्तुओ की मौद्रिक लागतें

देश	दैनिक मजदूरी (डालर)	कुल मजदूरी (डालर)	१० दिन के श्रम की उपज	मौद्रिक लागत = (पूति) प्रति इकाई लागत (डालर)
अमेरिका —				
(१) गेहूँ	१५	१५	गेहूँ की २० इकाइयाँ	०.७५
(२) कपडा	१५	१५	कपडे की २० इकाइयाँ	०.७५
जर्मनी —				
(१) गेहूँ	१०	१०	गेहूँ की १० इकाइयाँ	१.००
(२) कपडा	१०	१०	कपडे की १५ इकाइयाँ	०.६६ $\frac{2}{3}$

जर्मनी की अपेक्षा अमेरिका में गेहूँ का मूल्य कम है। अतः अमेरिका से गेहूँ का निर्यात किया जायेगा। किन्तु जर्मनी में अमेरिका की अपेक्षा कपडे का मूल्य कम है। अतः वहाँ से अमेरिका को कपडे का निर्यात किया जायेगा। यह निष्कर्ष तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के ही अनुरूप है। निःसन्देह यहाँ मौद्रिक मजदूरियों मन-मानी चुनी गई है। किन्तु इसके बिना आपत्ति उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह दिखाया जा सकता है कि, हमारी पूर्व धारणाओ (assumptions) के अन्तर्गत, दोनो देशों में मौद्रिक मजदूरियों का अनुपात एक अधिकतम और एक न्यूनतम सीमा के अन्दर रहना चाहिये। हाँ, इन सीमाओ के भीतर एक या दोनरे अथवा तीसरे किसी भी अनुपात का चुनाव अवश्य मनमाना (arbitrary) है किन्तु इससे बिचारा-धीन समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

यदि यह मानने कि जर्मनी में दैनिक मजदूरी १ डालर है, तो अमेरिका में दैनिक मजदूरी २ डालर से अधिक नहीं हो सकती है। वह जर्मन-मजदूरी के दूने से अधिक कदापि नहीं हो सकती है। यह अधिकतम सीमा गेहूँ में अमेरिका के लागत लाभ (अर्थात् २०:१०) द्वारा निर्धारित हुई है। यदि अमेरिकन मजदूरी २ डालर तक बढ़ जाय, तो अमेरिका में गेहूँ और कपडे दोनो की ही प्रति इकाई लागत १-१ डालर होगी। ऐसी दशा में गेहूँ का निर्यात अलाभदायक हो जायेगा किन्तु कपडे का आयात पहने की ही भाँति होना रहेगा। इसके फलस्वरूप अमेरिका का भुगतान सतुलन निष्क्रिय (Passive) बन जायेगा, स्वर्ण बाहर जाने लगेगा तथा कीमते और मजदूरियों पुनः घटने के लिए विवश हो जायेगी।

इसी प्रकार, यह भी दिखाया जा सकता है कि दैनिक मजदूरी अमेरिका में १३३ डॉलर से कम नहीं हो सकती है। वह जर्मन-मजदूरी के चार तिहाई (four-thirds) से कम नहीं हो सकती है। यह न्यूनतम सीमा अमेरिका के कपड़े सम्बन्धी लागत लाभ (अर्थात् २० १५) द्वारा निर्धारित हुई है। यदि अमेरिकन मजदूरी १३३ डॉलर से कम हो जाये (जबकि जर्मनी में मजदूरी मास्यतानुसार १ डॉलर हो रहे), तो जर्मनी का व्यापार सन्तुलन निष्क्रिय हो जायेगा, जर्मनी से स्वर्ण बाहर जाने लगेगा और अमेरिका में (स्वर्ण के आते रहने से) कीमतेँ और मजदूरियाँ बढ जायेंगी (किन्तु जर्मनी में कम हो जायेंगी)। इस प्रकार, मजदूरियों का अनुपात इन न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के भीतर ही रहने पर निर्धारित होगा।

किन्तु, केवल लागत-आंकड़ों (cost data) के आधार पर ही यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरियों का अनुपात (और इसलिए अमेरिकन गेहूँ एवं जर्मन कपड़े का प्रतिमय-अनुपात) इन सीमाओं के भीतर ठीक-ठीक (exactly) कहाँ निश्चित होगा। इस सम्बन्ध में टॉजिंग ने पारस्परिक माँग (reciprocal demand) की भूमिका पर बल दिया है।¹

जैसा कि हैबरलर ने लिखा है, उपरोक्त उदाहरण से यह सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस देश में उत्पत्ति की दृष्टि से अधिक प्रशुद्ध हैं वहाँ मजदूरियाँ या, अधिक सामान्य शब्दों में, माय द्वारा देश की अपेक्षा ऊँची होगी चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि टॉजिंग की मौद्रिक-लागत सम्बन्धी व्याख्या पारस्परिक लाभ के सिद्धान्त का अनुमान लगाने में असमर्थ है। इसे प्रो० हैबरलर ने अपने अनन्तर लागत विश्लेषण के प्रयोग द्वारा सम्भव बनाया है।²

(II) दो से अधिक वस्तुयें—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त दो से अधिक वस्तुओं की दशा में भी वैध है। इसे दिखाने के लिए हैबरलर ने यह युक्ति अपनाई है कि वे दो वस्तुओं को अनेक वस्तुओं का प्रतिनिधि और लागत-अंकों को समान लागत-अनुपातों वाली वस्तुओं की एक सम्पूर्ण शृङ्खला से निकाले गये श्रेष्ठत मान लेते हैं। ऐसी दशा में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—य को धरनी समस्त निर्यात वस्तुओं में व की अपेक्षा तुलनात्मक लाभ और समस्त आयात वस्तुओं में तुलनात्मक हानि होगी। इसी प्रकार, व देश को होगा।

मान लीजिए कि A, B, C, D एवं E ५ वस्तुयें हैं जिनमें से प्रत्येक की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए थ्रम लागनी की प्रावश्यक इकाइयाँ प देश में a_1, b_1, c_1, d_1 और e_1 और व देश में a_2, b_2, c_2, d_2 एवं e_2 हैं। यह भी मान

¹ See Chapter 8.

² See Chapter 10.

नीजिए कि A, B, C, D , और E की (गोद्विच) भूमि कीमतें (अर्थात्, प्रति इकाई गोद्विच लागत) अ देश में pa_1, pb_1, pc_1, pd_1 एवं p_1 और व देश में pa_2, pb_2, pc_2, pd_2 एवं p_2 हैं। मान लीजिए कि गोद्विच मजदूरी (प्रति इकाई धन) अ देश में W_1 और व देश में W_2 है। इन कल्पनाओं के सन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि —

प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य (जैसे pa_1)
 = प्रत्येक वस्तु एक इकाई उत्पन्न करने की श्रम-इकाइयाँ (a_1) \times मजदूरी
 प्रति श्रम-इकाई (W_1), अर्थात् —

$$\begin{array}{l|l} pa_1 = a_1 W_1 & pa_2 = a_2 W_2 \\ pb_1 = b_1 W_1 & pb_2 = b_2 W_2 \\ pc_1 = c_1 W_1 & pc_2 = c_2 W_2 \\ pd_1 = d_1 W_1 & pd_2 = d_2 W_2 \\ p_1 = e_1 W_1 & p_2 = e_2 W_2 \end{array}$$

हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देश में सापेक्षिक कीमतें श्रम लागतों द्वारा निर्धारित होती हैं¹, जिससे

$$\begin{array}{l} pa_1 \quad pb_1 \quad pc_1 \quad pd_1 \quad p_1 = a_1 \quad b_1 \quad c_1 \quad d_1 \quad e_1 \\ \text{एवं} \quad pa_2 \quad pb_2 \quad pc_2 \quad pd_2 \quad p_2 = a_2 \quad b_2 \quad c_2 \quad d_2 \quad e_2 \end{array}$$

अब हम यह कल्पना करते हैं कि विनिमय की दर (अर्थात् अ देश की एक करेंसी-इकाई के बदल में बी जाने वाली व देश की करेंसी इकाइयों की संख्या) R है। फलतः प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य दोनों देशों में व देश की करेंसी में इस प्रकार है —

$$\begin{array}{l|l} \text{अ देश में कीमतें} & \dagger \quad \text{अ देश में कीमतें} \\ a_1 \times W_1 & a_1 \times W_1 \times R \\ b_1 \times W_1 & b_1 \times W_1 \times R \\ c_1 \times W_1 & c_1 \times W_1 \times R \\ d_1 \times W_1 & d_1 \times W_1 \times R \\ e_1 \times W_1 & e_1 \times W_1 \times R \end{array}$$

इस दशा में यह कह सकते हैं कि अ देश जिन वस्तुओं को (जैसा कि A को) निर्यात करे, उसमें से प्रत्येक के लिये $a_1 \times W_1 \times R < a_2 \times W_2$ का सम्बन्ध

¹ "In order to determine the absolute strength of the money wages we must include in our data the quantity of money. This is done by making assumptions as to the absolute rates of money wages which prevail. It is important to recognise that the sole function of the Labour Theory of Value is to determine the relative prices" — Haberler *International Trade*, pp 136-37

लागू होना चाहिये, क्योंकि किसी वस्तु का निर्यात तब ही निगा जायेगा जबकि इसकी पूर्ति कीमत (अर्थात् मौद्रिक लागत) विदेशी देश की अपेक्षा कम हो। इसी प्रकार, अ देश जिन वस्तुओं का (जैसा कि B को) आयात करे, उनमें से प्रत्येक के लिये $b_1 \times W_1 \times R > b_2 \times W_2$ का सम्बन्ध लागू होना चाहिये।

$$\text{अथ, चूँकि } a_1 \times W_1 \times R < a_2 \times W_2, \text{ अर्थात् } \frac{a_1}{a_2} < \frac{W_2 \times R}{W_1}$$

$$\text{और } b_1 \times W_1 \times R > b_2 \times W_2, \text{ अर्थात् } \frac{b_1}{b_2} > \frac{W_2 \times R}{W}$$

इसलिये $\frac{a_1}{b} < \frac{b_1}{b_2}$ होना चाहिये।

उपरोक्त सम्बन्ध भी इसी तथ्य को (जो कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त द्वारा बताया गया है) प्रगट करना है कि अ देश को ब देश पर A वस्तु के उत्पादन में, अर्थात् अपनी मरम्मत आयात वस्तुओं की अपेक्षा अपनी समस्त निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होनी चाहिए। मार्शल का अनुसरण करते हुए हम विभिन्न वस्तुओं को इनमें ब देश पर अ देश की तुलनात्मक श्रेष्ठता के अनुसार कमवढ कर सकते हैं। मान लीजिये कि यह कम इस प्रकार है—A, B, C, D और E, ऐसी दशा में $\frac{a_1}{a_2} < \frac{b_1}{b_2} < \frac{c_1}{c} < \frac{d_1}{d_2} < \frac{e_1}{e_2}$ होगा। यदि अ देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को आयात की जाने वाली वस्तुओं से पृथक करने वाली रेखा खींच दें, तो हम यह देखेंगे कि समस्त निर्यात रेखा के एक ओर और समस्त आयात रेखा के दूसरी ओर पड़ते हैं। अर्थात्, यह मही होगा कि अ देश A और C वस्तुओं का ही निर्यात किन्तु B वस्तु का आयात करे।

विभाजन रेखा की वास्तविक स्थिति क्या होगी अर्थात् A के नीचे हाथी या II के नीचे या C के नीचे अथवा D के नीचे इस बारे में अब तक कुछ कहना कठिन है जब तक कि हम केवल लागत आँकड़ों (Cost data) पर ही विचार करते रहते हैं। सम्भवत इसीनिय मोह्विन ने यह घोषित किया था कि जब दो में अधिक वस्तुएँ होती हैं, तब तुलनात्मक लागत सिद्धान्त टूट जाता है। हैबरलर का कहना है कि विभाजन रेखा की सही स्थिति धार्य करने के लिये हम एक शर्त और प्रचलित करनी पड़ेगी वह इस प्रकार कि भुगतानों के मन्तुलन के डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर होने चाहिये¹ मान लीजिए कि लागत आँकड़े निम्नलिखित हैं —

¹ Habesler *The Theory of International Trade*, pp 137-139.

Kinds of Goods→	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Real Cost per Unit In terms of labour-hours) ↓										
In country I (a_1, b_1, c_1, \dots)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
In country II (a_2, b_2, c_2, \dots)	40	36	32	30	25	20	18	16	14	12

नोट—उपरोक्त तालिका में Country I में विभिन्न वस्तुओं की इकाईयों इस प्रकार चुनी गई है कि प्रत्येक वस्तु की प्रति इकाई लागत एक ही समान (अर्थात् २०) प्राप्ती है।

भागफल $\frac{W_2}{W_1 \times R}$ देश I द्वारा निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं के मध्य विभाजक रेखा की स्थिति को निर्धारित करता है। यदि दोनों देशों में मौद्रिक मजदूरियाँ समान हों $\left(\frac{W_1}{W_1 \times R} = 1 \right)$, तो Country I जिन वस्तुओं को अपेक्षा कम निरपेक्ष लागत पर उत्पन्न कर सकता है उन सबकी मौद्रिक लागतें (अर्थात् A से E तक वस्तुओं की मौद्रिक लागतें) country I में country II की अपेक्षा कम होगी। अतः वह इन वस्तुओं का निर्यात और G, H, I तथा J वस्तुओं का आयात करेगा। F वस्तु सीमा पर पड़ती है, अतः यह साथ ही साथ दोनों देशों में उत्पन्न की जायेगी।

यदि मौद्रिक मजदूरियाँ (Money Wages) country II की अपेक्षा country I में १०% नीची हों, तो मौद्रिक लागत (Money cost) भी country II की अपेक्षा country I में नीची होगी, भले ही इसकी वास्तविक लागत १०% ऊँची हो। प्रत्यक्ष शब्दों में, नीची मजदूरियाँ उत्पादन सम्बन्धी दबावों की प्रतिफलता को निम्नमात्रित कर देती है।

मान लीजिये कि मौद्रिक मजदूरियाँ दोनों देशों में समान हैं। जब ऐसा है, तो हम यह ठीक-ठीक जान सकते हैं कि कौन-सी वस्तुएँ निर्यात और कौन-सी वस्तुएँ आयात की जायेंगी तथा यह निश्चित कि मौद्रिक कीमतों पर सम्पन्न होगा। Country I २० प्रति इकाई कीमत पर A से E तक वस्तुओं को निर्यात करेगा और Country II १८ प्रति इकाई कीमत पर G को, १६ प्रति इकाई कीमत पर

H को, १४ प्रति इकाई कीमत पर I को और १२ प्रति इकाई कीमत पर J को निर्यात करेगा। यह परिस्थिति भुगतान के संतुलन में साम्यावस्था बनाये रखेगी या नहीं यह दोनों देशों की प्रतिकूल मांग (Reciprocal demand) पर निर्भर है।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि यह साम्यावस्था बनाये रखने में भ्रमभय है और Country I का भुगतान संतुलन निम्नलिखित हो गया है, अथवा युद्ध मुद्राविज्ञा होने रहने से विद्यमान साम्यावस्था भङ्ग हो गई है जिसमें कि Country I का भुगतान संतुलन निम्नलिखित हो गया है। ऐसी दशा में मौद्रिक यंत्र (Monetary mechanism) क्रियाशील हो जाता है, स्वर्ण Country I में Country II को प्रवाहित होने लगता है, Country II में कीमते घीन मजदूरियाँ बढ़ने लगती हैं, किन्तु Country I में गिरने लगती है, W_1 छोटा और W_2 बड़ा होने लगता है, भागफल $\frac{W_2}{W_1} \times R$ बढ़ जाता है, विभाजक रेखा का स्थान बदल जाता है, और F

का समावेस Country I द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की श्रेणी में हो जाता है। भुगतान-संतुलन में साम्य निम्नलिखित कारणों से स्थापित हो जाता है — (i) जब F का निर्यात किया जा रहा है, (ii) Country I की अन्य निर्यात वस्तुएँ (A से E तक) पहले से मस्ती हो जाती हैं, और (iii) Country II की निर्यात वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं। यदि ये बातें साम्य की स्थापना के लिये पर्याप्त न हों, तो Country I में स्वर्ण का निर्यात जारी रहेगा, विभाजक रेखा और भी घाने निकल जायेगी Country I वस्तु G का प्रापत करने के बजाय निर्यात करने लगेगी, जिससे अतत साम्य की स्थापना हो जायेगी।

अब तब यह स्पष्ट हो गया होगा कि दो वस्तुओं के उदाहरण की दशा में जिस भाँति दोनों देश उस वस्तु में विशेषता द्वारा, जिसमें प्रत्येक की तुलनात्मक लाभ है, अपने कुल उत्पादन को बढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं उसी भाँति प्रत्येक वस्तुओं की दशा में भी है। दोनों देशों में लाभ का विभाजन आयात और निर्यात वस्तुओं के मध्य विभाजक रेखा की सही स्थिति पर निर्भर है।¹

1 "It is clear that the complications we have just introduced do not disturb our presumption that unrestricted exchange of goods between countries is economically advantageous. The examples we gave upon the assumption of only two goods showed plainly that both countries could increase their total output by each specialising upon the good in which it had a comparative advantage. We can reach the same conclusion upon the assumption of numerous export and import commodities. We can 'pair off' any export commodity with any
(Contd. Next Page)

(III) यातायात व्यय—

हमारा यह निष्कर्ष कि एक दी हुई वस्तु मर्यादित ही एक निर्यात वस्तु से एक आयात वस्तु में अथवा एक आयात वस्तु से एक निर्यात वस्तु में बदल जाती है, सवास्तविक प्रतीत हो सकता है। कारण, यह निष्कर्ष इन कल्पनाओं (Assumptions) से उदय होता है कि यातायात लागतें शून्य हैं तथा स्थिर लागतें नियाशील हैं। जब हम यातायात व्ययों को विचार में लेते हैं, तो वस्तुओं की एक तीसरी श्रेणी, जो कि केवल अन्तरिक्ष व्यापार में प्रवेश करेगी, प्रगट होती है। कोई भी वस्तु निर्यात से आयात श्रेणी की सीमा नहीं गुजरती, बरन् उसे पहले इस तीसरी श्रेणी में प्रवेश करना पड़ता है और दोनों ही देशों में, अपने अपने ग्रह बाजार के लिये उत्पन्न की जाती है। इसे हैयरस्टर ने निम्नलिखित ढङ्ग से समझाया है—

मान लीजिए कि country I से country II को A वस्तु का यातायात करने की वास्तविक लागत (जब इकाइयों में या उत्पादक प्रसाधनों की इकाइयों में, जिनमें भी a_1, b_1, c_1 आदि व्यक्त की गई हों) a'_{12} है और विपरीत दिशा में यातायात की लागत a'_{21} है। सुबसता हेतु यह भी मान लीजिये कि पूर्ति करने वाला देश ही यातायात व्यय का भुगतान करता है। ऐसी दशा में हम यह कह सकते हैं कि country I द्वारा वस्तु का निर्यात तब किया जायेगा जबकि $\frac{a_1 + a'_{12}}{a_2 + a'_{12}} <$

$\frac{W_2}{W_1 \times R}$ और आयात तब किया जायेगा जबकि $\frac{W_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1}{a_2 + a'_{12}}$ हो।

किन्तु $\frac{a_1}{a_2 + a'_{12}} < \frac{a_1 + a'_{12}}{a_2}$ है। अतः, यदि $\frac{W_2}{W_1 \times R}$ का मूल्य उक्त दोनों मूल्यों

के मध्य हो, जिससे कि $\frac{a_2}{a_2 + a'_{12}} < \frac{W_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1 + a'_{12}}{a_2}$ हो, तो वस्तु न तो

आयात की जावेगी और न निर्यात की जावेगी। इस प्रकार किसी भी वस्तु के सम्बन्ध में हमारे पास दो मूल्य होते हैं $\frac{a_1}{a_2 + a'_{12}}$ और $\frac{a_1 + a'_{12}}{a_2}$

अन्य शब्दों में, जब तक दो देशों के मध्य वस्तु की लागत में अन्तर एक देश से दूसरे देश को यातायात करने के व्यय से अधिक न होया, तब तक उस वस्तु का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। वह कम, जिसमें कि निम्नलिखित वस्तुओं की

import commodity It is clear that whichever of these pairs we consider, each country has an advantage in the commodity it exports relatively to the commodity it imports. Thus, the division of labour between the two countries depends upon the exact position of the dividing line between export and import commodities"—Haberler *International Trade*. p. 139

यह दिखाने हेतु रखा जायेगा कि यदि country I ने निर्यात बढ़ाये तो कौन-सी वस्तु अगनी बार निर्यात वस्तु बन जायेगी, यातायात व्ययों को विचार में लेने पर बदल जागा है। किसी देश की निर्यात-क्षमता केवल इसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत पर ही नहीं, जैसा कि हमने पहले मान लिया था, बल्कि यातायात व्ययों पर भी निर्भर होती है।

इसे पिछली तालिका की सहायता से समझा सकते हैं। यदि country II से I की स्वर्ण जाने से प्रचका R में वृद्धि होने से भागफल $\frac{W_2}{W_1 + R}$ छोटा हो जाता है, जिससे कि विभाजक रेखा A की विज्ञा में विमर जाये, तो वस्तु D निर्यात-वस्तु नहीं रहती, क्योंकि यह भागफल $\frac{d_1 + d_{12}}{d_2}$ में नीचे गिर जाता है। किन्तु D अचानक ही आयात वस्तु में परिणत नहीं हो जायेगी। यह आयात वस्तु तब ही बनेगी जबकि इस भागफल के मुख्य में कुछ कमी और हो जाय तब वह $\frac{d_1}{d_1 + d_{12}}$ से कम हो जाय।

किन्तु यातायात व्यय के प्रवेश के फलस्वरूप उत्पन्न हुई जटिलता के कारण हमारे इस अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन प्रत्येक देश को लाभ पहुँचाता है। हाँ, यह अवश्य है कि 'बिना व्यय यातायात की रक्षा' की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-विभाजन यातायात व्यय वाली रक्षा में कम सीमा तक ही सम्भव हो सकेगा। यातायात व्ययों के भुगतान की आवश्यकता विश्व की तब की प्रवेष्टा, जबकि वस्तुएँ अपेक्षित सबसे उपयुक्त स्थानों में उत्पन्न की जाये और वहाँ से उन्हे बिना व्यय ही यातायात किया जा सके, अधिक गरीब बना देती है। लेकिन विश्व में यातायात व्ययों के विद्यमान होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह राष्ट्रो को लाभप्रद है, क्योंकि वे इसमें तब ही भाग लेंगे जबकि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ विभाजन का लाभ यातायात व्यय की प्रोक्षा अधिक होगा।¹

1 "The necessity of paying transport charges makes the world poorer than it would be if all goods could be produced in the relatively most suitable places and thence transported without any cost. But in so far as international trade takes place despite the existence of transport costs, it must be advantageous, since it will be undertaken only if the gain from division of labour exceeds the costs of transport"—Haberlar *International Trade*, p. 142

(IV) उत्पादन की परिवर्ती लागतें—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का विवेचन करते हुए यह कल्पना भी की गई थी कि उत्पत्ति की प्रत्येक शाखा में (दोनों देशों में) स्थिर लागतों का नियम क्रियाशील है, जिससे किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्राएँ पहले के बराबर प्रति इकाई श्रम व्यय से ही उत्पन्न की जा सकती हैं। हमारा पूर्व-परिचित उदाहरण यह था,—

वस्तुओं की श्रम लागतें

देश	श्रम लागत	गेहूँ की उत्पादित इकाइयाँ	कपड़े की उत्पादित इकाइयाँ
अमेरिका	१० दिन का काम	२०	२०
जर्मनी	१० दिन का श्रम	१०	१५

यदि जर्मनी गेहूँ की खेती जहाँ जहाँ कम कर देता है और इसके स्थान में कपड़ा उत्पन्न करता है, तो प्रत्येक १० इकाई गेहूँ के लिए, जिन्हें वह उत्पन्न करना मना कर देता है, वह अतिरिक्त १५ इकाई कपड़ा उत्पन्न करने सकेगा। इसी प्रकार, अमेरिका में दोनों वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन अनुपात १ : १ पर स्थिर रहा आएगा।

अब हम स्थिर लागत की मान्यता को छोड़ देते हैं, क्योंकि यह एक अत्यन्त मूलक दशा है। अधिक प्रचलित दशा बढ़ती हुई लागतों (या उपन द्वारा नियम) की है। एक विशेष विन्दु के बाद, जो व्यवहार में प्रतियोगिता के आधीन सदा ही पार कर लिया जाता है, अतिरिक्त मात्राएँ केवल प्रति इकाई बढ़ती हुई लागत पर ही उत्पन्न की जा सकती हैं। इस नियम की विचार में लेने का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की वैधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

यदि यह मानले कि जर्मनी और अमेरिका दोनों ही देशों में उत्पत्ति बढ़ती हुई लागतों के आधीन की जा रही है, तो उपरोक्त उदाहरण में हमने जो एक लिये हैं वे गोमान् उत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हुए समझने चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होने के पूर्व स्थिति यह होगी कि जर्मनी में उत्पन्न की गई गेहूँ की मात्रा में जो पिछरी वृद्धि की गई थी उसका व्यय प्रत्येक १० इकाई गेहूँ के लिए १० इकाई श्रम है और इसी प्रकार, कपड़े की सीमान्त लागत १५ इकाई कपड़े के लिये १० इकाई श्रम।

अब जर्मनी पर विदेशी प्रतियोगिता का दबाव पड़ता है और इसके परीभूत होकर वह बचड़ा अधिक विन्दु गेहूँ कम उत्पन्न करने लगता है, तो कपड़ा उत्पन्न करने की सीमान्त लागत बढ़ेगी, क्योंकि कम उपयुक्त भूमियाँ पर सी मैन (Fix) उत्पादन किया जाएगा तथा विद्यमान प्रयोग वाली भूमियों पर अधिक श्रम और पूँजी लगाई जायेगी। दूसरी ओर, गेहूँ उत्पन्न करने की सीमान्त लागत घटेगी, क्योंकि कम उपयुक्त भूमि का सेती से हटा लिया जाएगा तथा अन्य भूमियों पर पहले की अपेक्षा कम श्रम और पूँजी व्यय की जायेगी।

परिणामतः सीमान्त लागती का अनुपात जर्मनी के गेहूँ के पक्ष में परिवर्तित होगा। किन्तु अमेरिका में वह कपड़े के पक्ष में परिवर्तित हो जायेगा, क्योंकि वह पहले की अपेक्षा अधिक गेहूँ और कम कपड़ा उत्पन्न करता है। इस प्रकार, जैसे-जैसे जर्मनी गेहूँ उत्पादन के स्थान में वस्त्र-उत्पादन और अमेरिका वस्त्र उत्पादन के स्थान में गेहूँ-उत्पादन बढ़ाता जायेगा, दोनों देशों के मध्य तुलनात्मक लागत अनुपात में प्रत्येक चार दिशाओं से कम होने जायेगा और इसके फलस्वरूप प्रतिस्थापन प्रक्रिया बेर-मबेरा में समाप्त हो जायेगी। श्रम-विभाजन इस कार्य में सम्पूर्ण रहेगा कि जर्मनी अपने गेहूँ के उत्पादन को पूर्ण रूप से गहरी छोड़ेगा, किन्तु अपनी भूमि तथा सीमित कर देगा जोकि अमरीकी प्रतियोगिता से संभ्रान्त पूर्वक प्रतिपादित कर सके। इसी प्रकार, अमेरिका अपने कपड़ा उत्पादन को पूर्णतः नहीं छोड़ेगा किन्तु सीमित कर देगा। श्रम-विभाजन कहा तक किया जायेगा अबका अन्य शब्दों में, गेहूँ में अमेरिका और कपड़े में जर्मनी का तुलनात्मक लाभ सीमान्तों पर कम तक, जबकि अमेरिका और जर्मनी में चल रहे प्रतिस्थापन के प्रभावस्वरूप सीमान्त बढ़त रहें हों, जारी रहेगा। यह कुछ अंश में उस तेजी पर निर्भर है जिससे लागत उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और उत्पादन घटने पर घटती है।¹

बढ़ती हुई लागतों के नश्य को हम पूर्व उदाहरण में सम्मिलित कर सकते हैं। अभी तक हमने प्रत्येक वस्तु के लिये एक उत्पादन लागत निर्दिष्ट की थी—जैसे वस्तु A के लिए देखें I में a_1 और देखें II में a_2 , किन्तु अब हम प्रत्येक वस्तु के लिये लागतों की एक सम्पूर्ण शृङ्खला निर्दिष्ट कर देंगे, जैसे वस्तु A के लिए देखें I में $a'_1, a''_1, a'''_1, \dots$ और देखें II में $a'_2, a''_2, a'''_2, \dots$ और इसी प्रकार B, C, D के लिए भी \dots ये अनेक वस्तु की विभिन्न मात्राएँ उत्पन्न करने की विभिन्न सीमान्त लागतें सूचित करते हैं।

अन्य जटिलताओं की भाँति बढ़ती हुई लागतों से सम्बन्धित जटिलता को विचार में लेने से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। निम्नदेह श्रम विभाजन द्विचर लागती की दशा की अपेक्षा अब कम दूरी तक बढ़ाया जायेगा, क्योंकि जैसे-जैसे इसे बढ़ाया जाता है एक देश (जो कि सीमान्त पर है) की तुलनात्मक क्षमता कम होती जाती है तथा अन्ततः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार, यदि हम (बढ़ती हुई) सीमान्त लागतों से (न कि स्थिर लागतों से) सम्बन्धित लागत-अंकुशों पर विचार करें तो देश की तुलनात्मक क्षमता कम होती है; और उस बिन्दु से प्राये, जिस पर बढ़ती हुई लागतें दो देशों के मध्य लागत अन्तरों को खत्म कर देती हैं, श्रम-विभाजन को बढ़ाना लाभदायक नहीं होता। किन्तु उस बिन्दु तक बढ़ाना तो लाभदायक

¹ *Ibid.*, p 143

हे हो। अतः यह धारणा कि स्वतन्त्र व्यापार सर्वश्रेष्ठ आर्थिक नीति है, ठीक प्रमाणित होती है।¹

पढ़ती हुई लागते एक जटिल समस्या प्रस्तुत करती है। इन पर १३ वें अध्याय में विचार किया जायेगा।

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और अर्थ विकास देश
अर्थ विकास देशों पर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त लागू करने की कई बाधाएँ पर आलोचना की गई है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नांकित हैं —

(१) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त स्थैतिक स्वभाव का है—यह एक विशेष समय पर कुल उत्पत्ति को अधिकतम करने पर बल देता है चाहे विकास की दर कुछ भी हो। किन्तु चामू उत्पत्ति के अधिकतम होने से विकास-दर भी अधिकतम हो जाये ऐसा जल्दगी नहीं है। एक अर्थ विवर्धित देश के लिए विकास दर बढ़ना चाहे उत्पत्ति के अधिकतम होने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके प्रसाधन का वितरण तथा साहसिया की वृद्धि, यम शक्ति के गुण में सुधार और परिमाण में वृद्धि, कौशल में वृद्धि, वचन सम्बन्धी घादती, उपभोग के स्वरूप, जनसंख्या की वृद्धि दर आदि पर प्रभाव डालते हुए अर्थव्यवस्था की विकास की दर को प्रभावित करता है। एक अर्थ विवर्धित देश के निम्ने यह लाभप्रद होता है कि वह अपने प्रसाधन की विकास प्रोत्साहन उद्योगों में लगाए, नतु वही प्रसाधन कुछ अन्य उद्योगों में चानू उत्पात्ति में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर सकने है, क्योंकि विकास दर में वृद्धि नहीं होती है।

(२) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त अल्पदृष्टिकोण है—किस वस्तु का बीनसे देश में उत्पादन किया जाना चाहिये इसका निर्णय करने में तुलनात्मक लागत विविध देशों में केवल चामू उत्पादन लागत को ही विचार में लेता है।

उत्पादन की दीर्घकालीन उत्पादन लागतों को उचित महत्त्व नहीं देता। प्रारम्भ में कुछ प्रौद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागत अर्थ विकास देशों में विवर्धित देशों की अपेक्षा ऊँची हो सकती है। किन्तु दीर्घकाल में ऐसे उद्योगों को यदि प्रारम्भिक अनुसंधान में तरक्षण प्रदान किया जाय तो इन वस्तुओं की उत्पादन लागत अर्थ विकास देशों में अपेक्षाकृत नीची हो सकती है, क्योंकि वहाँ इन वस्तुओं के उत्पादन

1 "Thus, the comparative disadvantage of a country is less if we regard the cost data as relating to (increasing) marginal cost and not to constant costs, and it is not profitable to carry the division of labour beyond the point at which increasing cost wipe out the cost differences between the two countries. But it is profitable to carry it up to that point. Our presumption that Free Trade is the best economic policy, therefore, remains intact."—Haberler *The Theory of International Trade*, p. 143

के निम्ने प्रपेक्षाकृत अधिक अनुकूल प्राकृतिक प्रसाधन उपलब्ध होते हैं। प्राज विकसित देशों में अनेक औद्योगिक वस्तुओं की उत्पादन लागतें इगर्नि ए नीची हैं कि उन्होंने कृत्रिम धनुष्य सुविधायें (जैसे—विद्युत पूंजी, बेहतर टेक्नालजी, दक्ष श्रम) विकसित कर ली हैं। यदि यह सुविधायें अर्द्ध विकसित देश भी विकसित कर लें, तो वह अनेक औद्योगिक वस्तुओं विकसित देशों की प्रपेक्षा सस्ती बना सकते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक सुविधायें प्राण्य हैं जो विकसित देशों की नहीं हैं। कोई कारण नहीं है जो अर्द्ध विकसित देश कृत्रिम सुविधायें विकसित न कर सकें बशर्ते सच्चाई से प्रयत्न करें। किन्तु तुलनात्मक सागन सिद्धान्त तो यह मान कर चलता है कि साधन-मंदार स्थिर और अरिवर्तनीय है।

किन्तु वर्तमान तुलनात्मक लाभ के अनुरूप विजिप्टीकरण के लाभों की उपेक्षा करना एक तेजी से बदलते हुए विश्व में हानिप्रद भी हो सकता है, क्योंकि सम्भव है कि जब तक विश्व दीर्घकालीन उत्पत्ति-धनुष्यतम की व्यवस्था में पहुँचें, विभिन्न देशों के तुलनात्मक लाभों में कुछ देशों में नये प्रसाधनों की खोज या टेक्नालजी के परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवर्तन हो जायें। अतः दीर्घकालीन उत्पत्ति धनुष्यतम प्राप्त करने के लोभ में देश सकांतिकालीन धन्य उठाते रह सकते हैं और बालू तुलनात्मक लाभ के आधार पर विजिप्टीकरण के लाभों की खोजें रह सकती हैं। किन्तु यह बात कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में सही हो सकती है। कुल पर, दीर्घकालीन तुलनात्मक लाभों के आधार पर विजिप्टीकरण के लाभ सञ्जातिकालीन लागतों की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि ऐसे मौलिक परिवर्तन जो कि तुलनात्मक लाभों को बढ़ा दें, बार-बार और कीमनापूर्वक घटित नहीं होते।

(३) विश्व धन्य के वितरण की उपेक्षा की गई है—तुलनात्मक लागत सिद्धान्त केवल उत्पादन पक्ष को ही दृष्टिगत रखता है। कुल विश्व उत्पादन मौल्य अधिकतम किया सकता है इसे तो वह बताता है किन्तु वितरण की उपेक्षा कर देता है। किसी नीति का विश्व धन्य के आवधिक कल्याण पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भूतयासन करने में नीति का विश्व धन्य के वितरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम महत्वपूर्ण नहीं होता। विश्व धन्य को अधिकतम करने वाली नीतियाँ, जो इसके वितरण को महत्व न देती हों, अर्द्ध विकसित देशों को कदापि स्वीकार्य न होगी जब तक कि विश्व धन्य के वितरण का नियमन करने के लिये कोई प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था न बनी हो, क्योंकि ऐसी नीतियाँ प्रायः अर्द्ध विकसित देशों के हिस्से को कुप्रभावित करती हैं। साधारणतः, प्रति व्यक्ति धन्य कृषि की अपेक्षा उद्योग में ऊँची होती है। यदि कम विकसित देश विश्व धन्य में एक स्वागोचित हिस्सा पाना चाहें, तो उन्हें अपने उद्योग का विकास करना होगा चाहे उनके ऐसा करने में विश्व धन्य में कुछ कमी आ जाय। किन्तु उन्हें यह सावधानी रखनी चाहिये कि उनके व्यापारिक प्रतिवन्ध विश्व धन्य को कहीं इतना कम न कर दें कि इसमें उनका निरपेक्ष हिस्सा घट जाय।

हाल के अनुभव से पता चला है कि प्राथमिक उत्पादन वाले देशों को बहुत अनुकूल व्यापार-शर्तें नहीं मिलने वाली हैं। कुछ धर्मशास्त्रियों को यह विश्वास था कि इन देशों की भविष्य में अनुकूल व्यापार शर्तें मिल सकेंगी, क्योंकि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन पर बढ़ती हुई लागतें कार्यशील होनी हैं जबकि औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन पर घटती हुई लागतें। किन्तु इतिहास ने इस विश्वास को गला प्रमा-
खित कर दिया है। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि व्यापार शर्तें जल्द ही प्राथमिक उत्पादक देशों के पक्ष में हो जायेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने औद्योगीकरण के लिये नियोजित प्रयास आरम्भ कर दिये हैं। एक और ती औद्योगीकरण औद्यो-
गिक वस्तुओं की पूर्ति में भारी वृद्धि कर देगा तथा दूसरी ओर वह प्राथमिक उपजों के लिये माँग बढ़ा देगा। किन्तु विभिन्न अर्थ विकसित देशों के विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण करने में यह साफ पता चलता है कि इन्होंने उद्योग के माध्यम-
द्वारा विकास को भी महत्व दिया है। यह अनुभव करने लगे हैं कि विकसित
हूँ औद्योगिक विकास की पूर्व शर्तें हैं। अतः कच्चे मालों का प्रसारण करने की कोई
सम्भावना नहीं है और इसलिए व्यापार-शर्तें प्राथमिक देशों के पक्ष में परिवर्तित
होने की सम्भावना भी कम है। सच तो यह है कि कई बारलों से व्यापार शर्तें
उनके अधिक प्रतिकूल हो जाने की आशंका है, जैसे—प्रारम्भिक कच्चे मालों के
स्थानांतरण का पता चलना, औद्योगिक देश में भी कृषि का तेजी से विकास होना, वैज्ञा-
निक अनुसंधानों के फलस्वरूप प्रति निमित्त इकाई कच्चे माल के प्रयोग में कमी होना,
विकसित देशों द्वारा संरक्षण की नीति अपनाना, विकसित देशों में जनसंख्या घटने
की दर घटना आदि।

(४) सुलभतायुक्त साधन सिद्धान्त सभी देशों में पूर्ण रोजगार और उपस्थि-
तायुक्त में पूर्ण प्रतिशीलता की कल्पना करता है। किन्तु अर्थ विकसित देशों में
व्यापक बेकारी अर्थ रोजगार देखते हैं। वहाँ कृषि में मानव शक्ति की सीमांत
उत्पादकता लगभग शून्य (और कुछ मामलों में तो ऋणात्मक) है। यदि बेकार रहने
वाली मानव शक्ति को आयात-स्थानांतरणों का उत्पादन में लगाया जाय, तो बेकार
रहने की अपेक्षा वह राष्ट्रीय साधन में कुछ न कुछ वृद्धि तो कर ही सकेगी।

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है, जो यह कि एक अर्थ विकसित देश में बेकारी
मुक्त, पूँजी, भूमि आदि प्रसाधनों की कमी से उदय होती है। अतः वहाँ केवल
निर्धन आधिक्य होना मान पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत, रोजगार में आयात
आधिक्य के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। उदाहरणार्थ, पूँजीयत इन्विजमेन्ट के
प्रतिरिक्त आयात प्रतिरिक्त श्रम को काम दे सकते हैं। अब आयातों पर प्रतिबन्ध
केवल उन्हीं वस्तुओं के सम्बन्ध में रोजगार की मात्रा को बढ़ा सकता है जिनके
लिये स्थानांतरण देश के अन्दर ही मुख्यतः बेकार धर्मिकों की सहायता से (अधिक
पूरक माधनों की आवश्यकता के बिना) उत्पन्न किये जा सकते हों।

(५) सुलभतायुक्त साधन सिद्धान्त सामाजिक साधनों की अपेक्षा करता है—

यह सिद्धान्त प्राइवेट लागतों को तो दृष्टिगत रखता है लेकिन सामाजिक लागतों को विचार में नहीं लेता। जहाँ प्राइवेट और सामाजिक लागतों में भारी अंतर रहता हो, तुलनात्मक लागतों के आधार पर विशिष्टीकरण करने से विश्व का अधिकतम उत्पाद अधिकतम नहीं हो सकेगा।

(६) तुलनात्मक लागत सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था करता है। किन्तु अर्द्धविकसित देशों में हाल के वर्षों में शीघ्र विकास के लिये नियोजन पर बल दिया जाने लगा है, जिस कारण कीमन मिनेजिज्म के स्वतन्त्र क्रियाकलाप को धक्का लगा है। अपूर्ण प्रतियोगिता वाले विश्व में कीमत सीमान्त लागतों के (जिनकी धर्म तुलनात्मक लागत सिद्धान्त करता है) बराबर नहीं होते हैं।

(७) अर्द्धविकसित देशों की विविध स्थिति—अर्द्धविकसित देशों को कृषि में, जो कि बढ़ती हुई लागतों के अधीन है, तुलनात्मक लागत है। अतः यदि वे कृषि में विशिष्टीकरण कर, तो कृषि उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन लागत बढ़ेगी। उन्हें उद्योग में, जिस पर घटती हुई लागतें क्रियाशील हैं, तुलनात्मक हानि होगी है। अब जब वह औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावेंगे, तो इसकी उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। इस प्रकार, विशिष्टीकरण का विस्तार कृषि व उद्योग दोनों में उत्पादन लागतों को बढ़ावेगा, जिससे विश्व बाजार में अर्द्धविकसित देशों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और ज्यादा बिगड़ जायेगी तथा वह अपनी विकास क्षमताओं का बिंदोहन करने में बाधामें अनुभव करेंगे। अब जब किसी देश की बढ़ती हुई लागतों वाले व्यवसाय में तुलनात्मक लाभ किन्तु घटती हुई लागतों वाले उद्योग में तुलनात्मक हानि हो, तो उस देश के लिये तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के निर्देशानुसार विशिष्टीकरण करना लाभदायक नहीं भी हो सकता है।

परीक्षा प्रश्न :

- तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की समीक्षा करिये और इस सिद्धान्त की प्राथमिक व्याख्या पर प्रकाश डालिये। (आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

[Examine the theory of Comparative Costs Throw light on the modern Concept of the theory]

प्राथमिक तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की परीक्षायें बताइयें।

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

[Indicate the limitations of the classical theory of Comparative costs]

- परिवर्ती लागतों और मातायात व्ययों को विचार में लेने पर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के निष्कर्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(विजय, एम० ए०, १९६६)

[How is the theory of comparative costs affected by the introduction of (a) varying costs and (b) transport costs ?]

- ४ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को समझाइये जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नाग्न होता है । इस विषय पर आधुनिकतम विचार प्रस्तुत करिये ।

(आयरा, एम० ए०, १९६८)

[Explain the theory of Comparative costs as applied to inter national trade Give the latest views on the subject]

- ५ 'लागत अनुपातों में अन्तर होना ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है ।' स्पष्ट कीजिये ।

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

['A difference in the cost ratios is then the basis of inter national trade ' Explain]

- ६ तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को जिस तरह यह विनासोन्मुख देशों को लागू होता है समझाइये ।

(गोरमपुर, एम० ए०, १९६६)

[Explain the theory of comparative costs Is it applicable to developing countries ?]

- ७ मिर्डल के इस कथन के सम्बन्ध में तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की परीक्षामार्ग इंगित करिये कि 'जिस तरह आर्थिक सिद्धान्त विकसित हुआ वह लाख करोड़ों लोगों की रुचियों और महत्वाकांक्षाओं का एक अंश तक विवेकीकरण था ।

(इसाहू, एम० ए०, १९६८)

[Indicate the limitations of the theory of comparative costs in the light of Myrdal's observation that economic theory, as it was developed, was to some extent a rationalisation of the interests and aspirations of the millions where it grew]

- ८ इस तक का विवेचन करिये कि जब तक तुलनात्मक लागतों में अन्तर नहीं होगा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु तुलनात्मक लागतों में यदि समानता स्थापित होने की सम्भावना नहीं रहती तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई अन्त नहीं होता ।

(इलाहाबाद, एम० कॉम०, १९६७)

[Discuss the argument that there would be no motive for international trade unless there was initially a difference between comparative costs, but there would be no limit to international trade unless there was finally an equality between comparative costs]

- ९ बढ़ती हुई लागतों का नियम दो देशों के मध्य व्यापार को कैसे प्रभावित करता है ? विवेचन कीजिये ।

(विक्रम, एम० ए०, १९६६)

[How does the law of increasing cost affect trade between two countries ? Discuss]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माँग एवं पूर्ति

(Supply and Demand in International Trade)

परिचय—

रिकार्डों और उनके तात्कालिक अनुवर्तियों ने केवल व्यापार को जन्म देने वाली परिस्थितियों का ही वर्णन किया था और उनका विश्लेषण केवल इतना ही बताने के लिये पर्याप्त था कि 'व्यापार-शर्तें' (Terms of Trade) किन सीमाओं के अन्दर रहेगी। यथा वस्तुओं का विनिमय व्यापारिक देशों के व्यापार पूर्व लागत अनुपातों (Pre trade cost ratios) के मध्य किया जायगा। किन्तु इन सीमाओं के भीतर किस विशेष बिन्दु पर व्यापार शर्तें तय होंगी, इसका उत्तर वह नहीं दे पाये थे। मंच तो यह है कि व्यापार शर्तों की वास्तविक स्थिति प्रत्येक देश की (दूसरे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तु के लिये) माँग पर निर्भर होती है। यदि कोई देश अनेक वस्तुओं उत्पन्न करता है, तो केवल लागत प्रमाण (Cost data) को देख कर ही यह नहीं बताया जा सकता कि वह कौन सी वस्तु निर्यात और कौन सी वस्तु आयात करेगा। आयात और निर्यात की वस्तुओं के मध्य विभाजक रेखा माँग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। सर्व प्रथम जॉन स्टुअर्ट मिल ने और बाद में मार्शल ने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में आवश्यक समोधन और विस्तार करके उसे उक्त प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाया। प्रस्तुत अध्याय में इन्हीं महत्वपूर्ण प्रयासों की चर्चा की गई है।

मिल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सिद्धान्त (Mill's Theory of International Values)

मिल द्वारा 'माँग' के महत्त्व पर बल दिया जाना—

किसी देश में एक विदेशी वस्तु का मूल्य गृह उत्पत्ति की मात्रा पर, जो कि उसके बदले में विदेशी को देनी पड़ेगी, निर्भर करता है। सत्य शब्दों में, विदेशी वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की शर्तों पर निर्भर होते हैं। किन्तु ये शर्तें स्वयं किन पर निर्भर हैं? वह क्या है जो एक निश्चित मात्रा में कपड़े के बदले में इङ्गलैंड से स्पेन को एक पाइप विनिमय करने हेतु प्रेरित करता है? मिल ने

¹ *Principles of Political Economy*, Book 3, Chapter XVIII

सम्मति है कि उनकी उत्पादन लागतें बराबर नहीं हैं। 'यदि नपडा और शराब दाना ही स्पेन में बनाये जाते, तो ये स्पेन में अपनी उत्पादन लागतों पर विनिमय किये जाते, यदि य दोनों इङ्ग्लैंड में बनाये जाते, तो भी उनका विनिमय उत्पादन लागतों पर ही किया जाता, किन्तु जब समस्त नपडा इङ्ग्लैंड में और समस्त शराब स्पेन में उत्पन्न की जाती है, तो ये ऐसी परिस्थितियों में हैं जिनको उत्पादन-लागत का नियम लागू नहीं होता है। उदनुसार, जैसा कि हमने ऐसी ही दुविधापूर्ण स्थिति में एक बार पहले भी किया था, हमें एक प्राचीन नियम—माग और पूर्ति के नियम का सहारा लेना चाहिये और इसमें ही हम पुन अपनी कठिनाई का समाधान पायेंगे।'¹ इस प्रकार मिल के अनुसार व्यापार की दोनों वस्तुओं का विनिमय मुख्य दोनों देशों में, माग के प्रभाव द्वारा, इस प्रकार से समायोजित (Adjust) होता है कि प्रत्येक देश में आयात उसके निर्यातों से प्रिस्कुल चुक जायेंगे।

उदाहरण—

जब दो देशों के मध्य व्यापार होने लगता है तब दोनों वस्तुय एक-दूसरे से, दोनों देशों में एक समान विनिमय दर पर (यातायात व्यय को छोड़ते हुए) ही विनिमय की जायेंगी। तक के लिये मानिये कि एक बराबर वस्तुय दूसरे देश की बिना श्रम या स्वयं के यातायात की जा सकती है। जैसे ही व्यापार आरम्भ होगा, दोनों वस्तुओं का मुख्य (एक दूसरे में अनुमानित) दोनों देशों में समान स्तर पर आ जायगा।²

मान लीजिये कि श्रम के रूप में १० गज कपड़े की लागत उतनी ही है जितनी कि इङ्ग्लैंड में १५ गज लिनिन (Linen) और जर्मनी में २० गज लिनिन

1 "If the cloth and the wine were both made in Spain they would exchange at their cost of production in the Spain, if they were both made in England they would exchange at their cost of production in England but all the cloth being made in England, all the wine in Spain they are in such circumstances to which the law of cost of production is not applicable We must accordingly, as we have done before in a similar embarrassment, fall back upon an antecedent law, that of supply and demand, and in this we shall again find the solution of our difficulty"—J. B. Mill *Principles of Political Economy*, Chapt 18.

2 "Supposing for the sake of argument that the carriage of the commodities from one country to the other could be effected without labour and without cost, no sooner would the trade be opened than the value of the two commodities, estimated in each other, would come to a level in both countries"—*Ibid*

की। इस मांग्यता के अन्तर्गत, यह इङ्ग्लैंड के हित में होगा कि वह जर्मनी से लिनन भेगा। और जर्मनी के हित में होगा कि वह इङ्ग्लैंड से कपड़ा भेगा। जब प्रत्येक देश दोनों ही वस्तुओं अपने निर्यात करता है, तब १० गज कपड़ा इङ्ग्लैंड में १५ गज लिनन से और जर्मनी में २० गज लिनन से विनिमय होता था। अब दोनों देशों में कपड़ा लिनन से समान मूल्य में गजों में बदला जायेगा। यह समान रहना क्या होगी ?

	कपड़ा	लिनन
इङ्ग्लैंड में १० दिन के श्रम का उत्पादन	१० गज	१५ गज
जर्मनी में १० दिन के श्रम का उत्पादन	१० गज	२० गज
इङ्ग्लैंड में व्यापार पूर्व लागत अनुपात	१०	१५
जर्मनी में व्यापार पूर्व लागत अनुपात	१०	२०

यदि १५ गज लिनन के बदले में १० गज कपड़ा बदला गया, तो इङ्ग्लैंड की स्थिति पूर्ववत् ही रहती है और जर्मनी ही समस्त लाभ ले लेगा। यदि २० गज लिनन के बदले में १० गज कपड़ा विनिमय हुआ तो जर्मनी की स्थिति पूर्ववत् रहेगी और समस्त लाभ इङ्ग्लैंड वहाँ लया। यदि १५ और २० के बीच में किसी भी संध्या के बदले में विनिमय किया गया, तो व्यापार न लाभ दोनों देशों में बँट जायेगा। मान लीजिये कि १० गज कपड़े का विनिमय १८ गज लिनन से होता है, तो इङ्ग्लैंड को प्रत्येक १५ पर ३ गज कपड़े का लाभ होगा और जर्मनी प्रत्येक २० में से २ की वचत कर लेगा। अब समस्या यह है कि क्या कौन से कारण हैं, जो उस अनुपात को, जिसमें कि इङ्ग्लैंड का कपड़ा जर्मनी में लिनन से विनिमय किया जायेगा, निर्धारित करते हैं।

चूँकि विनिमय मुख्य घटता बढ़ता रहता है, इसलिये हम कोई भी विनिमय मूल्य मान कर चल सकते हैं। मान लीजिये कि बाजार की तीव्रबाजी के कालस्वरूप १० गज कपड़ा दोनों देशों में १७ गज लिनन से विनिमय होता है किसी वस्तु के लिये भाँग (अर्थात् वह मात्रा जिसके लिये केता मिल जायेगा) कीमत के अनुसार घटती-बढ़ती है। जर्मनी में १० गज कपड़े की कीमत अब १७ गज लिनन है (अथवा १७ गज लिनन के तुल्य जो भी जर्मन मुद्रा हो उसके बराबर है) जब इस कीमत पर गजों में कपड़े की कोई विशेष मात्रा ऐसी है जिसकी माँग की जायेगी, अर्थात् जिसके लिये केता मिल जायेगा। कपड़े की एक दो हुई मात्रा ऐसी है, जिससे अधिक कपड़ा उस कीमत पर नहीं बेचा जा सकता, और इससे कम मात्रा में का उस कीमत पर माँग की पूरी अनुपूर्ति न कर सकेगा। मान लीजिये कि यह मात्रा १० गज की १००० मुनी है।

अब इङ्ग्लैंड में, १७ गज लिनन की कीमत १० गज कपड़ा (या इसके बराबर इङ्ग्लैंड की मुद्रा) है। लिनन की मात्रा में एक विशेष मात्रा ऐसी है जो

उस कीमत पर केवल माँग की सन्तुष्टि भर कर सकेगी, अधिक नहीं। मान लीजिये कि यह सस्या १७ गज की १००० गुने है।

१७ गज लिनिय का १० गज कपड़े से जो अनुपात है वही १७ गज के १००० गुने वा १० गज के १००० गुने से है। विद्यमान विनिमय मूल्य पर, इङ्गलैंड की जितनी मात्रा से लिनिय की आवश्यकता है वह कपड़े की उस मात्रा के लिये जो कि उन्हीं विविध-वस्तुओं पर जर्मनी को चाहिए, पूरा पूरा भुगतान कर सकेगी। प्रत्येक पक्ष में माँग इसकी पर्याप्त है कि वह दूसरे पक्ष की पूर्ति को ग्रहण (कप) कर सकेगी है। चूँकि यहाँ माँग और पूर्ति के नियम की शर्त पूरी हो गई है, इसलिए दोनों वस्तुओं १० गज कपड़े के बदले में १७ गज लिनिय की दर पर विनिमय की जाते रहेंगे।

किन्तु हमारी कल्पनाएँ कुछ और भी हो सकती थीं। मान लीजिये, पारस्परिक विनिमय की कल्पित दर पर, इङ्गलैंड १७ गज के ८०० गुने से अधिक लिनिय का उपयोग करने की इच्छा नहीं रखता है। स्पष्टतः, लिनिय की यह मात्रा मानी हुई विनिमय दर पर, १० गज के १००० गुने कपड़े का, जिसकी हमारी कल्पना के अनुसार जर्मनी की आवश्यकता है, मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त न होगी। इस कीमत पर तो जर्मनी को केवल १० गज वा ८०० गुना कपड़ा ही मिल सकेगा। शेष २०० की प्राप्ति के लिए, अन्य साधन के अभाव में वह अधिक कीमत (११ गज से भी अधिक लिनिय) १० गज कपड़े के बदले में देने की विवश हो जायेगा मान लीजिये कि वह १८ गज का प्रस्ताव रखता है। सम्भवतः इस कीमत पर इङ्गलैंड लिनिय की अधिक मात्रा लेने को तैयार हो जायेगा। मान लीजिए कि वह १८ गज वा ६०० गुना उपयोग करने को तैयार है। दूसरी ओर, कपड़े की कीमत बढ़ जाने के कारण इसकी माँग जर्मनी में घटेगी। यदि जर्मनी १० गज के १००० गुने के बजाय अब केवल १० गज का ६०० गुना कपड़ा लेकर ही सन्तुष्ट हो जाय, तो वह १८ गज के ६०० गुने लिनिय के, जिसे इङ्गलैंड बदली हुई कीमत पर खरीदने को तैयार है, मूल्य का भुगतान कर सकेगा। इस प्रकार, माँग दोनों पक्षों की ओर पुनः पूर्ति की ग्रहण करने के योग्य हो जायेगी और १८ के बदले १० गज वह दर होगी जिस पर कि दोनों पक्षों में कपड़ा लिनिय से विनिमय किया जायेगा।

स्पष्टतः जब दो देश परस्पर दो वस्तुओं में व्यापार करते हैं, तो इन वस्तुओं का विनिमय मूल्य, एक दूसरे से सापेक्षिक रूप में दोनों पक्षों के उपभोक्ताओं की रुचियों और परिस्थितियों के अनुसार, समायोजित हो जायेगा। यह समायोजन इस तरीके से होगा कि एक देश द्वारा अपने पड़ोसी देश से वस्तुओं की जो माग्यें, आपात की जायेंगी वे दूसरे को भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी। चूँकि उपभोक्ताओं की रुचियों और परिस्थितियों को किसी विशेष नियम में बाँधा नहीं जा सकता, इसलिए उन अनुपातों को भी निर्धारित करना बर्तन है जिनमें कि दोनों

वस्तुओं का विनिमय होगा। हम यह जानते हैं कि ये सीमाएँ, जिनके अन्दर ही अन्दर घटा-बढ़ी हो सकती है, एक देश में उनकी उत्पादन लागतों के मध्य अनुपात और दूसरे देश में उनकी उत्पादन लागतों के मध्य अनुपात है। १० गज वस्त्रों का विनिमय २० गज तिनिन से अधिक और १५ गज तिनिन से कम नहीं हो सकेगा। किन्तु इनके बीच की किसी भी संख्या से विनिमय हो सकता है। अतः यह अनुपात जिसमें व्यापार का लाभ दोनों देशों में बँट सकता है बँट हो सकते हैं। प्रत्येक देश का प्रामुखात्मक भाग जिन परिस्थितियों पर निर्भर रहता है उनकी एक मोटी कदरेखा मात्र ही दी जा सकती है।

यातायात व्यय—

यातायात व्यय द्वारा जो परिवर्तन ला दिया जाता है उसके बारे में मिल हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—“यातायात व्यय किस प्रकार विभाजित होगे इसका तो कोई ठीक नहीं है किन्तु इतना निश्चित है कि एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम लाभ है और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे अधिकतम अनुविधा होती है। इसके मध्य अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका व्यापार इसलिए नहीं हो सकेगा कि सम्मानित लाभ यातायात व्ययों द्वारा ही लपा लिया जाता है।”

दो से अधिक वस्तुयें—

दो से अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में व्यापार का विवेचन करते हुए मिल ने प्रतिपूरक माँग की भूमिका पर विशेष रूप से बल दिया। “यदि हम इङ्ग्लैण्ड की ओर से कोयला या कपास और जर्मनी की ओर से शराब, अनाज अथवा लकड़ी बढ़ाने, तो इससे सिद्धान्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्येक देश के निर्यात आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त (Exactly equal) होने चाहिए। यहाँ हमारा अभिप्राय अब ‘कुल आयात’ और ‘कुल निर्यात’ से है, एक विशेष वस्तु के आयात निर्यात से नहीं। अंग्रेज थम के ५० दिनों का उत्पादन चाहे वह कपड़ा, कोयला, लोहा या अन्य किसी वस्तु के रूप में हो जर्मन थम के ४० या ५० या ६० दिन के लिये, शराब, अनाज या लकड़ी किसी भी रूप में उत्पादन के बदले, अन्तर्राष्ट्रीय माँग के अनुसार विनिमय होगा। एक न एक अनुपात ऐसा होता है जिस पर दोनों की एक दूसरे के उत्पादों के लिए माँग समुत्तुलित हो जाती है, अर्थात् इङ्ग्लैण्ड द्वारा जर्मनी की दो गई वस्तुओं का पूरा-पूरा (अधिक नहीं) भुगतान उन वस्तुओं द्वारा हो जायेगा, जो कि जर्मनी इङ्ग्लैण्ड को देगा। अब इसी अनुपात में अंग्रेज थम की उपज और जर्मन-थम की उपज जो एक दूसरे से विनिमय की जायेगी।”

1 “If we now super-add coals or cottons on the side of England,
(Contd on next page)

व्यापार के लाभ का माप और इसका विज्ञान—

मिल के अनुसार व्यापार का लाभ उस अन्तर के बराबर होता है जो कि 'घरेलू लागत अनुपात' (Domestic cost ratio) और 'साम्य व्यापार शर्तों' (Equilibrium terms of trade) में पाया जाय। यदि घरेलू लागत अनुपात और साम्य व्यापार शर्तों के मध्य अन्तर बढ़ जाय, तो व्यापार से लाभ की मात्रा बढ़ जायेगी, और यदि अन्तर घट जाय, तो लाभ की मात्रा में कमी हो जायेगी। चूंकि १९वीं शताब्दी के प्रथमाध में निर्देशाव बनाने की टेक्नीक का अधिक विश्वास नहीं हो पाया था, इसलिए मिल और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने व्यापार से लाभ का माप करने के लिए समस्त निर्यातों और आयातों की कीमतों की तुलना नहीं की थी। किन्तु विनिमय की जाने वाली मात्राओं पर ध्यान देकर वे वास्तव में उन्हीं परिवर्तनीय घटकों (Variables) पर विचार कर रहे थे, जिनका हम आयात और निर्यात-कीमतों की तुलना के द्वारा अध्ययन करते हैं।

इस प्रश्न का जि भीन सा देख व्यापार से होने वाले लाभ का सबसे अधिक भाग प्राप्त करेगा, मिल ने यह उत्तर दिया कि वही देश सबसे अधिक लाभ पावेगा, जिनके उत्पादकों के लिए अन्य देशों में सबसे अधिक माँग है, ऐसी माँग जोकि अतिरिक्त सस्तेपन से (Additional cheapness) बढ़ने की प्रवृत्ति रखती हो। 'जिस सीमा तक किसी देश के उत्पादन यह विशेषता रखते हैं उस सीमा तक वह देश समस्त विदेशी वस्तुओं को कम लागत पर प्राप्त कर लेगा। विदेशी बाजारों में उसके निर्यातों के लिए माँग की तीव्रता जितनी अधिक होगी, उतना ही सस्ते आयात वह प्राप्त कर सकेगा। उसे अपने आयात तक भी सस्ते प्राप्त होते हैं जबकि उनके लिए उसकी अपनी माँग की तीव्रता (Intensity) और विस्तार (Extent) कम हो। बाजार उन देशों के लिए सबसे सस्ता होता है जिसकी माँग कम हो। एक देश, जिसे कुछ ही विदेशी वस्तुओं की और वह भी सीमित मात्रा में आवश्यकता है

and wine or corn or timber on the side of Germany, it will make no difference in the principle. The exports of each country must exactly pay for the imports, meaning now the aggregate exports and imports not those of particular commodities taken singly. There is some proportion at which the demand of the two countries for each other's products will exactly correspond, so that the things supplied by England to Germany will be completely paid for, and no more, by those supplied by Germany to England. This accordingly will be the ratio in which the produce of English and produce of German labour will exchange for one another."—*Mill Principles of Political Economy*, p. 590.

जबकि स्वयं उसकी वस्तुओं की विदेशी देशों में बहुत माँग है, अपन सीमित मात्रात बहुत ही मामूली लागत पर अर्थात् अपनी थम और पूँजी की बहुत ही थोड़ी मात्रा के उत्पादन के बदले में प्राप्त कर सकेगा ।¹

दो से अधिक देश—

मिल उन पहले अर्थशास्त्रियों में से थे, जिन्होंने अन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को दो से अधिक देशों पर विस्तृत किया, यद्यपि अनेक अर्थशास्त्रियों ने भी तब से ऐसा ही किया है। मिल ने यह दिखनाया कि ब्रिटिश निर्यातों के त्रय में जिन लेने वाले एवं तीसरे देश को विचार में लेने पर व्यापार की शर्तें ब्रिटेन के अधिक अनुकूल हो जाती है चाहे वह तीसरा देश ब्रिटेन की आवश्यकता की कोई भी वस्तु उत्पन्न न करता हो। वह लिखते हैं कि —

‘अन्त में, अब हम दो से अधिक मूल देशों पर विचार करेंगे। जर्मनी के लिनिय के लिए इङ्ग्लैण्ड की माँग के कारण विनिमय दर ‘१० गज कपड़ा १६ गज लिनिन के बदले तब वह जाने केगश्चात मान लीजिए कि इङ्ग्लैण्ड और किसी अन्य देश (जो लिनिय का ही निर्यात करता है) के मध्य व्यापार खुल जाता है। यह भी मान लीजिए कि (यदि इस तीसरे देश के अतिरिक्त किसी अन्य देश से इङ्ग्लैण्ड का व्यापार नहीं है) अन्तराष्ट्रीय माँग के प्रभाव द्वारा वह उससे १० गज कपड़े के विनिमय में १७ गज लिनिन प्राप्त कर सकता है। हायट्रय अब वह जर्मनी से पूर्व-दर पर लिनिय अधिक नहीं खरीदता। इससे जर्मनी का साल कम बिकेगा और विषयगत वह अन्य देश की भाँति ही १७ गज देने हेतु तैयार हो जायेगा। प्रस्तुत दशा में यह मान कर चला गया है कि तीसरे देश में उत्पादन और माँग सम्बन्धी परिस्थितियाँ इङ्ग्लैण्ड के लिए जर्मनी की परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। किन्तु यह मान्यता आवश्यक नहीं थी। हम यह भी मान सकते थे कि यदि जर्मनी से व्यापार नहीं होता है तो इङ्ग्लैण्ड अन्य देश की बेसी ही लाभदायक शर्तें देने के लिए विवश हो जाता, जोकि वह जर्मनी को देता है—अर्थात् १६ गज अथवा इससे भी कम मात्रा में लिनिय के बदले में १० गज कपड़ा। “इतने पर भी, तीसरे देश के साथ व्यापार खुल जाने से इङ्ग्लैण्ड के पक्ष में अन्तर पड़ ही जायेगा। कारण, इङ्ग्लैण्ड के निर्यातों के लिए अब बोहरे बाजार हो गये है जबकि लिनिय के लिए इङ्ग्लैण्ड की माँग पूर्ववत् है। इससे यह अनिवार्य है कि इङ्ग्लैण्ड लाभ

1 ‘In so far as the production of any country possess this property, the country obtains all foreign commodities at less cost. It gets its imports cheaper, the greater the intensity of the demand in foreign countries for its exports. It also gets its imports cheaper, the less the extent and intensity of its own demand for them. The market is cheapest to those whose demand is small’—*Ibid*, p 591.

शायक शर्तें प्राप्त कर ले। दोनों देशों को अब इङ्गलैंड के उत्पादन की इतनी मात्रा में आवश्यकता है, जिसकी पहले उनमें किसी एक को नहीं थी। अतः इसे प्राप्त करने के लिए वे अपने निर्यातों की माँग में वृद्धि करने का यत्न करेंगे। यहाँ तक कि इन्हें प्रेषित कम मूल्य पर ही देने को तैयार हो जायेंगे।”¹

“यह उत्प्रेक्षनीय है कि इङ्गलैंड में पक्ष में यह प्रभाव, जो कि उसके निर्यातों के लिए एक अन्य बाजार खुल जाने से उदय होता है, तब भी इसी प्रकार से उदय होगा जबकि वह देश, जिससे माँग आती है, इङ्गलैंड को इसकी आवश्यकता की कोई वस्तु भी बेचने में समर्थ नहीं है। मान लीजिये कि तीसरे देश की इङ्गलैंड से लोह का कपड़े की आवश्यकता है किन्तु वह स्वयं लिनिय या ऐसी कोई अन्य वस्तु, जिसके लिए इङ्गलैंड में माँग है, उत्पन्न नहीं करता। किन्तु वह निर्यात योग्य कुछ वस्तुएँ उत्पन्न करता है जिनका वह अपने आयातों का भुगतान न कर सकेगा। उसके नियति यद्यपि वे इङ्गलैंड के उपयुक्त नहीं हैं तथापि किसी अन्य देश में तो बाजार प्राप्त कर ही सकते हैं। चूँकि यहाँ तीन देशों की वस्त्रों की गरी है, इसलिए यह मानना चाहिए कि उसे अपनी वस्तुओं के लिए जर्मनी में बाजार मिलता है तथा इङ्गलैंड से वह जो आयात करता है उसका भुगतान वह अपने जर्मन आहूतों पर आदेशों द्वारा करता है। इस प्रकार, जर्मनी को, अपने आयातों का भुगतान करने के प्रतिरिक्त, एक तीसरे देश के कारण भी इङ्गलैंड का ऋणी बनना पड़ता है और दोनों भुगतानों के लिए साधन उसे अपनी वस्तु की निर्यात-माय में से जुटाने पड़ते हैं। अतः उसे अपना उत्पादन इङ्गलैंड की पर्याप्त अनुकूल शर्तों पर देना पड़ता है जिससे कि वहाँ माँग इतनी बढ़ सके कि जो दोनों ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त हो।”²

1 “the opening of the third country makes a great difference in favour of England. There is now a double market for English export, while the demand of England for linen is only what it was before. This necessarily obtains for England more advantageous terms of interchange. The two countries, requiring much more of her produce than was required by either alone, must, in order to obtain it, force an increased demand for their exports, by offering them at a lower value.”—*Ibid*, p. 591

2 “This effect in favour of England from the opening of another market for her exports, will equally be produced even though the country from which the demand comes should have nothing to sell which England is willing to take. Germany besides having to pay for her own imports, now owes a debt to England on account of the third country and the means for both purposes must be derived from her exportable produce. She must therefore tender that produce to England on terms sufficiently favourable to force a demand equivalent to this double debt.”—*Ibid*

यह बातें विस्तृत इसी प्रकार से होती हैं कि मानो तीसरे देश ने जर्मनी का उत्पादन अपनी निजी वस्तुओं के बदले में खरीदा है और फिर उसे इंग्लैंड को उसके उत्पादन के बदले में दिया है। अंग्रेजी माल के लिए मांग बढ़ गई है, जिसका भुगतान जर्मनी के माल को देना पड़ता है और ऐसा तब ही किया जा सकता है जबकि इंग्लैंड में मांग को बढ़ावा (अर्थात् उनका मूल्य कम करके) बढ़ाया जाय। "इस प्रकार, किसी विदेश में देश के निर्यातों के लिए मांग बढ़ने से देश के ऐसे आयात भी, जिन्हें वह अन्य देशों से प्राप्त करता है, अधिक मस्ता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है और विपरीत क्रम से, किसी विदेशी वस्तु के लिए उसकी अपनी मांग में वृद्धि होने से, अन्य बातें समान रहने पर, वह सभी विदेशी वस्तुओं के लिए महंगा भुगतान करने को विवश हो जाता है।"¹

अन्तर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण—

जिस नियम को सभी समझाया गया है उसे मिला न "अन्तर्राष्ट्रीय मांग का समीकरण" (Equation of International Demand) कहा है। इसे हमें तुल्य शब्दों में निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है, "एक देश का उत्पादन अन्य देशों के उत्पादन से ऐसे मूल्यों पर, जो कि उसके कुल निर्यातों द्वारा उसके कुल आयातों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो, बिनागय किया जावेगा। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का यह सिद्धान्त वास्तव में एक अधिक सामान्य सिद्धान्त—मूल्य सिद्धान्त का, जिसे मांग-पूर्ति का समीकरण (Equation of Supply and Demand) कहते हैं, विस्तार मान है।" यह पहले ही देख चुके हैं कि एक वस्तु का मूल्य सदा ही अपने आपकी इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि जिसमें वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति में ठीक समान स्तर तक आ जाय। किन्तु समस्त व्यापार, चाहे वह राष्ट्रों के मध्य हो या व्यक्तियों के मध्य, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय मान ही है, जिसमें कि वह चीजें जो कि वे क्रमिक रूप से बेचते हैं, उनके खरीदने का 'साधन' भी होती हैं। एक देश द्वारा जो आपूर्ति (supply) करीदी जाती है वह अन्य देश द्वारा भी गई खरीद के लिए उसकी मांग के समान है। इस प्रकार, मिला न बताया है कि मांग और पूर्ति प्रतियुक्त मांग (Reciprocal demand) का ही दूसरा नाम है, और यह कहता कि मूल्य अपने आपकी इस प्रकार से समायोजित कर लेगा, जिससे कि मांग और पूर्ति बराबर हो जाय, वास्तव में यह कहने के तुल्य है कि वह

¹ "Thus, an increase of demand for a country's exports in any foreign country enables her to obtain more cheaply even those imports which she procures from other quarters. And conversely an increase of her own demand for any foreign commodity compels her, ceteris paribus, to pay dearer for all foreign commodities"—*Ibid*, p. 593.

अपने व्यापको इस प्रकार से समायोजित करेगा कि एक पक्ष की मांग दूसरे पक्ष की मांग से बराबर हो जाय ।

मिल के सिद्धान्त की आलोचना—

व्यापार से लाभ की गणना करने के सम्बन्ध में ही मिल ने मांग की भूमिका पर प्रथम ध्यान दिया । उन्होंने यह दिखाने का यत्न किया कि व्यापार करने वाले देशों के मध्य व्यापार का लाभ, व्यापार शर्तों पर मांग सम्बन्धी दशाओं के प्रभाव द्वारा, निम्न प्रकार विनष्ट हो जाता है । किन्तु व्यापार की शर्तों के निर्धारण एवं व्यापार के लाभ के सम्बन्ध में मिल ने जो विश्लेषण किया उसकी कटु आलोचना हुई है । प्रमुख आलोचनायें निम्नांकित हैं —

(१) पूर्ति सम्बन्धी दशाओं की अपेक्षा—मार्शल (Marshall) ने यह बताया कि मिल के विश्लेषण में पूर्ति की अपेक्षा की गई है । वास्तव में पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करती हैं । उनके निम्न के शब्दों में—
-“विदेशी वस्तुओं के लिए देश की प्रभावपूर्ण मांग की लोच न केवल इसी सम्पत्ति और उनके लिए इसकी जनसंख्या की इच्छाओं की लोच द्वारा, बल्कि इनकी अपनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आपूर्तियों को विदेशी बाजारों की मांग के माध्यम समायोजित करने की सामर्थ्य द्वारा भी प्रभावित होती है ।”¹

(२) व्यापार से बड़े देशों को छोटे देशों की अपेक्षा लाभ कम होना प्राक्-शक नहीं—मार्शल ने इस धारणा के सम्बन्ध में भी मिल की आलोचना की है कि व्यापार से बड़े देश छोटे देशों की अपेक्षा कम लाभ उठाते हैं, क्योंकि प्रदत्त देशों की मांग विदेशी वस्तुओं के लिये अधिक होती है जिस कारण विविधता की शर्तों में उनमें निपट स परिवर्तन हो जाता है । नि सदेह यह ठीक है कि छोटे देश विदेशी व्यापार पर अधिक निर्भर होने के कारण अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु मार्शल का कहना है कि एक धनी देश भी (i) नई वस्तुओं का प्रचलन कर सकता है, (ii) विस्तृत एवं सुसंगठित व्यापारिक सम्बन्धों से लाभ उठा सकता है, (iii) एक विशेष वस्तु से भरे हुये बाजार में उस वस्तु की बिना करने के बजाय नये बाजार खोल सकता है, और (iv) निर्धन देशों की अपेक्षा यह विभिन्न बाजारों की मांग के अनुसार अपने उत्पादक को समायोजित करने की अधिक शक्ति स्थिति में होता है । यही नहीं, आयातों पर प्रतिबन्ध लगा के भी एक देश प्रायः अपनी व्यापार शर्तों को,

1 “ ..the elasticity of her effective demand for foreign goods is governed not only by her wealth and the elasticity of the desires of her population for them, but also by her ability to adjust the supplies of her own goods of various kinds to the demands of foreign markets ”—Marshall *Money, credit and Commerce* pp 167 69

सुधार करता है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह कठिनाई भी है कि घटे हुए व्यापार और उत्पात साधनों के कुक्षितरण के पक्षस्वरूप हानि भी होने सकती है ।

मार्शल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त का सामान्यीकरण
(Marshall's Generalisation of The Theory of International Values)

जबकि टॉजिंग (Taussig) और वाद में वाइनर (Viner) रिकार्डियन विश्लेषण में सुधार करने के प्रयत्न कर रहे थे तब अन्य अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को एक नये माग पर लाना प्रारम्भ कर दिया । इन अर्थशास्त्रियों में सबसे प्रथम स्थान मार्शल (Marshall) का है, जिन्होंने एक तो लागतों में मापक के रूप में प्रतिष्ठित अथ समय के प्रयोग में सुधार करने का प्रयत्न किया और दूसरे, मूल्य के मापक सम्बन्धी विश्लेषण को पुराने पूर्ण-विश्लेषण से जोड़ने का प्रयास किया ।

प्रतिनिधि गाँठों की धारणा —

रिकार्डों के ही सामान्य मार्शल भी उत्पादन-लागतों और व्यापार के लाभों को वास्तविक तर्कों (Real terms) में अर्थात् प्रयत्न और विरति के रूप में (As effort and abstinence) व्यक्त करने के पक्ष में थे । रिकार्डों ने वस्तुओं के मूल्य को 'धन समय' (Labour time) के तर्कों में मापा था । किन्तु मार्शल के मतानुसार—'यह बख्शना करना अधिकांश श्रेष्ठ प्रतीत होता है कि प्रत्येक देश अपने निर्यातों को प्रतिनिधि गाँठों (Representative bales) में बनावेगा है अर्थात् ऐसी गाँठें, जिनमें से प्रत्येक उनके विभिन्न प्रकार के श्रमों के समान कुल विनियोगों का प्रतिनिधित्व करे ।'¹ चूँकि गाँठ एक निश्चित मात्रा में निविष्ट श्रम और पूँजी (Fixed input of labour and capital) को सूचित करती है, इसलिये इनमें से किसी भी साधन की प्रभावपूर्णता में वृद्धि या लागतों में सामान्य बढ़ती गाँठ के प्रकार को, जिसे निर्यात योग्य वस्तुओं में गिना जाता है, बढा देगी ।

दो देशों (C और G) के मध्य विनियम के विवेचन के लिए मार्शल ने यह माना कि वे गाँठों में विनियम करते हैं । उन्होंने यह भी माना कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं को, जिनकी माँग उत्पादन-लागत के तर्कों में विदेशों में सबसे अधिकृत है, निर्यात करेगा और इस प्रकार अधिकतम लाभ उठावेगा । किन्तु एक सीमा के पार, उसे कोई दूसरी वस्तु बेचना लाभदायक हो जायेगा और यही कम लाभ भी लेगा । हैबर्लर का कहना है कि—'स्पष्टतः, गाँठ सम्बन्धी धारणा ने दो वस्तु-विश्लेषण

¹ "But, it seems better to suppose either country to make up her exports into representative bales, that is, bales each of which represents uniform aggregate investments of her labour (of various qualities) and of her Capital"—Marshall *Money, Credit and Commerce*, p. 17.

की कई कठिनाइयों में से एक को समाप्त कर दिया है कि (मान लीजिये) E देश प्रारम्भिक व्यापार वाली (Originally traded) निर्यात-वस्तु को किसी अन्य वस्तु (या वस्तुओं के मिश्रण) से प्रतिस्थापित करके अच्छी शर्तें प्राप्त कर सकता है। पृथक्-पृथक् वस्तुओं के निर्यात श्रेणी से गैर निर्यात (अथवा आयात) श्रेणी में (एक विपरीत) परिवर्तित होने के साथ साथ, वस्तु सरचना को भी, टेक्नाॅलॉजिकल एवं सन्तुलनकारी समायोजनों के प्रभाव स्वरूप बदलने की अनुमति देकर, मार्शल एक जटिल बदला को साधारण रूप से समझाने में समर्थ हो गये हैं।¹

माँग एवं पूर्ति के संयुक्त कार्यवाहन पर बहुत बल देना—

मार्शल ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के ढाँचे के निर्धारकों के रूप में माँग एवं पूर्ति दोनों के संयुक्त कार्यवाहन पर बहुत बल दिया है। वह लिखते हैं कि—“दो देशों के मध्य सामान्य व्यापार में किसी को भी केवल माँग या केवल पूर्ति से ही विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। प्रत्येक की माँग उसके निवासियों की विदेशी से कुछ वस्तुएँ प्राप्त करने की इच्छा से उदय होती है और उसकी पूर्ति का मूल उन वस्तुओं को, जो कि अन्य देशों के लोग लेना चाहते हैं, उत्पन्न करने की सुविधाओं में छिपा है। किन्तु उसकी माँग व्यापार को उकसाया देने में सामान्यतः केवल उस सीमा तक ही प्रभावशाली है जहाँ तक उसके पीछे उपयुक्त वस्तुओं की पूर्ति की मात्रा है और उसकी पूर्ति उस सीमा तक सक्रिय होती है जहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं के लिए उसकी माँग विस्तृत है।”²

1 “To treat the exchange between two countries (E and G) Marshall had them exchange bales. He assumed that each country in turn would press the commodities in strongest demand abroad relative to its cost of production, thus marketing to the best advantage. Beyond a certain point, it would become profitable to market a second commodity and so on. Obviously the concept of the bale avoids one of the difficulties involved in two-commodity examples, that country E, say, could achieve better terms by substituting for the export good initially traded some other good or a combination of goods. By permitting the commodity composition to vary, as a result both of technological and of equilibrating adjustments, with individual goods shifting from export to non-export or import and vice versa, Marshall was able to treat complex phenomena quite simply.”—G. Haberler : *The Theory of International Trade*, pp 10-11.

“In the general trade between two countries neither can be specially associated either with demand or with supply. The

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य का उदाहरण—मांगों ने निम्नलिखित तालिका की सहायता से व्यापार-समावनाओं को दिखाया है :—

उन शर्तों की अनुसूची जिन पर E व्यापार करने का इच्छुक है			उन शर्तों की सूची जिन पर G व्यापार करने का इच्छुक है	
E गाँठों की संख्या	(दर) प्रति १०० E गाँठों G गाँठों की संख्या, जिस पर E कालम १ में दो हुई गाँठें देगा।	(मात्रा) G गाँठों की कुल संख्या, जिनके बदले में E कालम १ में दो गई संख्या में E गाँठें देने की तैयार है।	(दर) प्रति १०० G गाँठें E गाँठों की संख्या जिस पर G कालम १ में दो गई संख्या में E गाँठें लीरने की तैयार है	(मात्रा) G गाँठों की कुल संख्या, जिन्हें G कालम २ में दो गई E गाँठों के बदले में देने की तैयार है
१	२	३	४	५
१०,०००	१०	१,०००	२३०	२३,०००
२०,०००	२०	४,०००	१७५	३५,०००
३०,०००	३०	९,०००	१४३	४९,१००
४०,०००	३५	१४,०००	१२२	४८,८००
५०,०००	४०	२०,०००	१०८	५४,०००
६०,०००	४६	२७,६००	९५	५७,०००
७०,०००	५५	३८,५००	८६	६०,२००
८०,०००	६८	५४,४००	८२½	६६,०००
९०,०००	७८	७०,२००	७८	७०,२००
१,००,०००	८३	८३,०००	७६	७६,०००
१,१०,०००	८६	९४,६००	७४½	८१,६५०
१,२०,०००	८८½	१०६,२००	७३½	८६,५००

तालिका में प्रथम पंक्ति यह दिखाती है कि E देश १००० G गाँठों के बदले में १०,००० E गाँठें देने की तैयार है किन्तु G देश १०,००० E गाँठों के बदले में २३,००० G गाँठें देने की प्रस्तुत हो बायेगा। यतः G गाँठों की पूर्ति इसकी माँग की तुलना में बहुत अधिक है। प्रथम तालिका की अन्तिम पंक्ति यह दिखाती है कि

demand of each has its origin in the desires of her people to obtain certain goods from abroad, and her supply has its origin in her facilities for producing things which the people of other countries desire. But her demand is, in general, effective in causing trade, only in so far as it is backed by her supply of appropriate goods, and her supply is active, only in so far as she has a demand for foreign goods"—Marshall : *Money, Credit and Commerce*, p. 137.

१,०६,२०० G गाँठों के बदले में E देश १,२०,००० E गाँठ देने को तैयार है किन्तु G देश १,२०,००० E गाँठों के बदले में केवल ८८,१०० G गाँठ ही देना चाहता है। यहाँ G गाँठों के लिए माँग इनकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक है। लेकिन, जब E देश ६०,००० E गाँठ देने के लिए और बदले में ७०,२०० G गाँठ लेने हेतु तैयार है तब साम्यावस्था प्राप्त हो जायेगी क्योंकि G देश ६०,००० E गाँठों के विवे पूर्ण (सन्तुष्टि न पम) ७०,२०० G गाँठ देने को तैयार है। ऐसी अवस्था में E और G दोनों प्रकार की गाँठों के बाजार साफ हो जायेंगे। विनिमय अनुपात १०० E गाँठ = ७८ G गाँठ निर्धारित होगा। E के लिए व्यापार की अर्थ तालिका के शीर्ष भाग की ओर अधिक लाभदायक और नीचे के भागों की ओर कम लाभदायक होगी।

प्रतिपूरक माँग और पूर्ति वक्रों की सीमायें—

हैबरलर का मत है कि मार्शल द्वारा दी गई अनुसूचियाँ साधारण माँग और पूर्ति अनुसूचियों (Ordinary supply and demand schedules) के समान हैं। जैसे जैसे E गाँठों में G गाँठों की कीमत घिरता जाती है, G गाँठों के लिए E की माँग G गाँठों की पूर्ति की तुलना में अधिक बढ़ती जाती है और घट में पूर्ति की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है। इस प्रकार, य वास्तव में प्रतिपूरक माँग अनुसूचियाँ ही हैं और इन्हें प्रायः ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। प्रतिपूरक माँग वक्रों की प्रस्ताव वक्र (Offer curves) भी कहते हैं। साधारण माँग एवं पूर्ति वक्रों के समान ही इन अनुसूचियों पर भी प्रत्येक बिन्दु एक सम्भावित साम्य का बिन्दु होता है। किन्तु इनमें से किसी भी वक्र पर कोई भी गति (Movement) इस मायना के प्राधीन होती है कि सम्बद्ध देश की प्रथम व्यवस्था न अपने आन्तरिक व्यापार को नई माध्य परिस्थितियों के अनुसार समायोजित कर लिया है।¹

बाद के अर्थशास्त्रियों ने मार्शल से प्रस्ताव वक्रों का विस्तृत उपयोग किया है। इन अर्थशास्त्रियों में एजवर्थ (Edgeworth) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने इनका प्रयोग व्यापारित कीति सम्बन्धी समस्याओं की परीक्षा करने हेतु किया। लेकिन ये वक्र, सभी वक्रों, जितना बताते हैं उससे कहीं अधिक धिया भी लेते हैं। उदाहरणार्थ, प्रतिनिधि गाँठ की वस्तु रचना के परिवर्तनों की तह में व्यापार के दम से सम्बद्ध जटिल परिवर्तन दृष्टे हैं। इन परिवर्तनों का स्पष्ट विवेचन करने के उद्देश्य से ही एजवर्थ ने लागतों का एक नया माप विकसला। यह

1 'Like ordinary supply and demand curves, each point on these schedules is a point of potential equilibrium. But a movement along one of these curves presupposes that the economy of the relevant country has rearranged its internal trade to conform to the new equilibrium conditions'—Haberler *loc. cit.*

माप है—‘उत्पादक साधनों की इकाई’ (Unit of Productive Forces), जो किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले श्रम, पूँजी एवं अन्य साधनों का योग (Combination) है। तत्पश्चात् उन्होंने किसी देश के निर्यातों की रचना पर लागू होने के प्रभाव का विचार किया। उन्होंने यह सकेत करने की सावधानी रखी कि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जोकि देश में ही उत्पन्न की जा सकती हैं और विदेश से आयात भी। उन्होंने यह भी बताया कि कौनसी वस्तु निर्यात की जावेगी इसका पता लगाने हेतु विभिन्न वस्तुओं के लिये प्रत्येक देश की माँग पर भी विचार करना चाहिये।¹

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विकास करने में मिल ने जो योग दिया उसका विश्लेषण कीजिये।

[Analyse the contribution of Mill of the development of the theory of international trade]

- २ मार्शल के प्रतिपूरक माँग और पूर्ति वक्रों की सहायता से यह विस्तारित कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साम्य कैसे प्राप्त होता है। क्या ये वक्र एक सामान्य साम्य को दिखाते हैं ?

[Illustrate equilibrium in international trade with the aid of Marshall's reciprocal demand and supply curves. Do these curves represent a general equilibrium ?]

¹ J. Y. Edgeworth : *Paper Relating to Political Economy*, 1925, Volume II, pp 52-53

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य साम्य सिद्धान्त

(General Equilibrium Theory of International Trade)

परिचय—

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा बीसवीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में सामान्य साम्य सिद्धान्त के प्रति खोज की रचि बहुत बढ गई। प्रायः इस सिद्धान्त को एक जटिल यथार्थीय रूप प्रदान किया गया है, यथात् अर्थ-व्यवस्था की कई समीकरणों द्वारा व्याख्या की गई है। किन्तु सामान्य साम्य सिद्धान्त का मौलिक मूल्य (Fundamental truth) बहुत ही सीधा-साधा है और यह है कि अर्थव्यवस्था का प्रत्येक परिवर्ती घटक (Variable), चाहे वह कीमत हो या परिणाम, अर्थव्यवस्था के अन्य सब परिवर्ती घटकों (Other variables) पर निर्भर होता है और वस्तुओं की कीमतें एवं मांग तथा उत्पादक संचालन के पुष्टिकार और उनकी आपूर्तियाँ (Supplies) सब साथ ही साथ निर्धारित होती हैं। यह सिद्धान्त, जो कि एक अकेले बाजार में मूल्य या कीमत-सम्बन्धों को स्पष्ट करने हेतु बनाया गया था, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भी लागू किया गया है। किन्तु ऐसा विस्तार बाधापूर्ण तरीके से हुआ। सन् १९३३ में दो रचनाएँ, एक ओट्टलिन द्वारा और दूसरी हेबरसर द्वारा, प्रकाशित हुई। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त सामान्य साम्य प्रणालियों के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत किए गये थे।

सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त

(General Equilibrium Theory of Value)

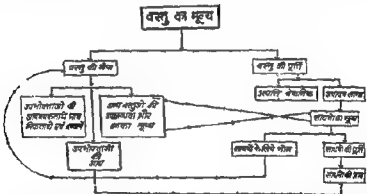
मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त की विशेषताएँ—

ओट्टलिन के अनुसार, 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त का विस्तार मान है'। अतः उसने लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त का विवेचन करने से पूर्व हम मूल्य के सामान्य साम्य सिद्धान्त के विषय में जान लेना चाहिए।

(१) वस्तु के मूल्य का निर्धारण माँग और पूर्ति के साध्य द्वारा—किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है। जबकि वस्तु के लिए माँग उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, अभिरुचियाँ (Preferences), इच्छाओं और आमदनियाँ पर तथा अन्य वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर निर्भर

होती है, वस्तु की पूर्ति इसे उत्पन्न करने की सम्भावना पर (यर्थात् उत्पत्ति-साधनों की उपलब्धता) ऐसे उत्पादन की भौतिक तथा टेक्निकल दशाओं पर निर्भर है। माध्य बिन्दु पर माँग और पूर्ति बराबर होती है और इसी पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। यह मूल्य वस्तु की उत्पादन लागत (जिसमें सामान्य भी सम्मिलित है) के बराबर होगा और वस्तु की उत्पादन लागत उन सब साधनों के मूल्य का योग होनी है जो कि वस्तु के उत्पादन में सहयोग देते हैं।

उत्पत्ति-साधनों के मूल्य भी इनकी माँग-पूर्ति के द्वारा तय होते हैं। साधनों के लिए माँग घट्नाच निर्मित वस्तु के लिए माँग पर ही निर्भर है, क्योंकि साधनों का प्रयोग निर्माण हेतु ही तो किया जाना है। घन-निर्मित वस्तु के लिए माँग जितनी अधिक होगी, साधनों के लिए माँग भी उतनी ही अधिक होगी। किसी साधन के लिए कुल माँग समस्त उद्योगों के लिए आवश्यक उस साधन की विभिन्न मात्राओं का जोड़ है। दूसरी ओर, साधनों की पूर्ति इन्हें मिलन वाली कीमती के साथ घटती बढ़ती है।



(२) मूल्य निर्धारण पर प्रभाव डालने वाले घटकों की परस्पर निर्भरता—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि एक वस्तु विशेष के मूल्य को प्रभावित करने वाले अनेक घटक हैं जो स्वयं भी परस्पर प्रभावित होते हैं। यदि प्रत्येक बाजार में साधनों की पूर्ण रूप से गतिशील और पूर्णतः विभाज्य मान ले तथा यह भी मान लें कि साधनों की पूर्ति स्थिर (Constant) एवं ज्ञात (Known) है, तो यह देखने के प्रत्येक बाजार की मुख्य समस्या में कार्यकारी सम्बन्धों (Functional relations) में ५ सैट विद्यमान होते हैं—

— (१) वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है।

(२) वस्तु की माँग सभी वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ताओं की शक्तों पर निर्भर करती है।

- (iii) एक व्यक्ति की आय उसकी साधन सम्बन्धी मात्रा और इसके मूल्य पर निर्भर करती है ।
 (iv) किसी उत्पत्ति-साधन के लिए माँग उस साधन की पूर्ति के बराबर होनी है, जिसे दिया गया और स्थिर मान लिया है ।
 (v) वस्तु के उत्पादन के लिए किसी साधन की कितनी मात्रा आवश्यक होगी यह उत्पादन सम्बन्धी भौतिक दशाओं और उत्पत्ति-साधनों की कीमत पर निर्भर है ।

(३) उक्त सम्बन्धों से साधनों और वस्तुओं की कीमतें निकालना—इस प्रकार, प्रोह्लिन ने वस्तुओं के मूल्यों, उत्पत्ति साधनों के मूल्यों, वस्तु की माँग, उत्पत्ति-साधनों की माँग एवं पूर्ति आदि की परस्पर-निर्भरता दिखाई है । प्रत्येक बाजार या क्षेत्र में एक समय विशेष पर, सभी वस्तुओं और उत्पत्ति-साधनों की कीमतें अन्तिम रूप से चार भौतिक घटकों द्वारा निर्धारित होती है । इसमें से दो घटक माँग से और दो घटक पूर्ति से सम्बन्ध रखते हैं तथा निम्न प्रकार हैं—(अ) उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें व इच्छायें, (ब) उत्पत्ति साधनों की स्वामित्व सम्बन्धी दशायें, जोकि व्यक्तियों की आय को और आय द्वारा वस्तुओं की माँग को प्रभावित करती हैं, (ग) उत्पत्ति-साधनों की पूर्ति, एवं (द) उत्पत्ति की भौतिक दशायें । यदि ये चार बातें दी गई हों तो उपरोक्त पाँच सम्बन्धों के आधार पर साधन और वस्तु दोनों ही के मूल्यों को निकाला जा सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त का प्रयोग (General Equilibrium Theory of value applied to International Trade)

उपरोक्त सामान्य साम्य मूल्य सिद्धान्त की प्रोह्लिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में लागू किया है । इसके स्पष्टीकरण हेतु उमने निम्न बातें मान ली हैं :—(i) केवल दो क्षेत्रों पर ही विचार किया जाना है, (ii) उत्पत्ति साधनों की गुणात्मक भिन्नता पर ध्यान नहीं देना है, (iii) एक ही क्षेत्र के भीतर साधन पूर्ण गतिशील हैं किन्तु दो या अधिक क्षेत्रों के बीच में नहीं है, (iv) अन्य सब चीजें पूर्णतः गतिशील हैं, (v) केवल वस्तु व्यवहारों पर ही विचार करना है, एवं (vi) प्रत्येक क्षेत्र में रकतन्त्र पत्र मुद्रा प्रणाली प्रचलित है ।

प्रोह्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषतायें—

प्रोह्लिन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त की निम्नलिखित विशेषतायें हैं —

(१) व्यक्तियों की ही भाँति राष्ट्रों या क्षेत्रों के बीच विशिष्टीकरण सम्भव है—प्रोह्लिन का कहना है कि व्यक्ति निम्न कारणों से विशिष्टता प्राप्त करते और व्यापार करते हैं ऊँची कारणों से प्रदेश और राष्ट्र भी विशिष्टता प्राप्त करते और व्यापार करते हैं । कुछ व्यक्ति अपने स्वभाव से ही किसी कार्य की अन्य व्यक्तियों की

तुनमा मे अधिक योग्यता से कर सकते हैं। जैसे—एक व्यक्ति अच्छा बागवान होता है जबकि दूसरा अच्छा प्रोबेसर और तीसरा कुशल डाक्टर। एक बागवान प्रकुशल निवृत्तक, एक निवृत्तक अनुमान ख्यापक तथा एक ख्यापक प्रकुशल बागवान ही प्रमाणित होगा। अतः अपने अपने अनुबून कामों में निष्पटता प्राप्त करना सब पक्षों के लिए लाभप्रद है। यदि सभी व्यक्ति एक ही क्षमता के होने लगे तो भी वे निष्पटिकरण के द्वारा सामान्यित हो सकते हैं।

व्यक्तियों की ही भाँति राष्ट्र और क्षेत्र भी एक दूसरे से विभिन्न उत्पादक-सुविधाएँ रखते हैं, जैसे—यदि कुछ देशों में उपजाऊ भूमियाँ हैं, तो अन्य देशों में सन्पद क्षमिज भण्डार होने हैं या पूँजी की प्रचुरता होती है। [स्मरण रहे कि 'प्रचुरता' और 'न्यूनता' सापेक्षिक शब्द हैं, अर्थात् एक देश में किसी साधन विशेष की विशाल मात्रा उपलब्ध हो सकती है किन्तु इसकी संभावना के लिए माँग यदि इस मात्रा से भी अधिक हो तो उक्त साधन 'न्यूनता' माना कहलायेगा।] अतः राष्ट्र और क्षेत्र भी उत्पादन में निष्पटिकरण करते देखे जाते हैं।

(२) उत्पादक सुविधाओं की भिन्नता के कारण वस्तु कीमत भिन्नताएँ उदय होती हैं—प्रोह्लिन ने बताया है कि उत्पादक-सुविधाएँ विभिन्न देशों में विभिन्न होती हैं, जिस कारण कीमत भिन्नताएँ उदय हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। इस बात को गीबे सम्झाया गया है।

एक अकेले बाजार के सम्बन्ध में जिस सामान्य साम्य भूषण सिद्धांत का विश्लेषण हमने ऊपर किया था उससे यह स्पष्ट है कि एक वस्तु विशेष का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति पर तथा माँग उन्मोक्तकों की आवश्यकताओं और दानकी माँग पर, उन्मोक्तकों की माँग साधनों की कीमत पर एवं वस्तु की पूर्ति उत्पात्ति-साधनों की पूर्ति और उत्पात्ति की भौतिक दशाओं पर निर्भर होती है। प्रोह्लिन का कहना है कि उत्पात्ति की भौतिक दशाएँ सर्वत्र समान हैं जिससे इन्हे विचार से पृथक् रखा जा सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य इसकी माँग सम्बन्धी दशाओं और साधन सेवाओं की पूर्ति पर निर्भर है।

उपरोक्त सन्दर्भ में हम यह देख सकते हैं कि जिन्हीं दो क्षेत्रों में सभी वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें निम्न शर्तें पूर्ण होने पर ही समान होंगी—(प्र) वस्तुओं के लिए माँग सम्बन्धी दशाएँ दोनों क्षेत्रों में समान होनी चाहिए, (व) उत्पात्ति साधन दोनों ही क्षेत्रों में समानुपात में उपलब्ध होने चाहिए, एवं (म) साधनों की पूर्ति में यदि कोई अन्तर हो, तो उनका संतुलन माँग सम्बन्धी दशाओं से ठीक करने ही अन्तर द्वारा हो जाना चाहिए। चूँकि ये शर्तें प्रायः अपूर्ण रहती हैं, इसलिए वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता देखी जाती है। प्रोह्लिन ने बताया है कि (प्र) और (स) शर्तों की पूर्ति होना तो कभी भी सम्भव नहीं है। अतः 'माँग की तुलना में उत्पात्ति साधनों की पूर्ति' (Supply of factors of production in relation to demand), अर्थात् 'उत्पात्ति-साधनों की सापेक्षिक न्यूनताओं' (Relative scarcities

of productive factors) में भिन्नताये होने के फलस्वरूप वस्तु कीमतों में भिन्नता उदय हो जाती है।

उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में भूमि की प्रचुरता है जबकि वहाँ धम धम पूँजी का अभाव है, अर्थात् वहाँ भूमि सन्ती और अन्य साधन महँगे हैं। दूसरी ओर, इङ्ग्लैंड में पूँजी की प्रचुरता और भूमि का अभाव है, अर्थात् वहाँ पूँजी-साधन सस्ते और भूमि-साधन महँगे हैं। परिणामतः जिन वस्तुओं (जैसे—गेहूँ, ऊन, मांस आदि) के उत्पादन के लिए बड़ी मात्राओं में भूमि की आवश्यकता पड़ती है किन्तु, धम और पूँजी की अधिक आवश्यकता नहीं है, वे आस्ट्रेलिया में सस्ती होगी। दूसरी ओर, इङ्ग्लैंड में, जहाँ पूँजी की प्रचुरता और भूमि की कमी है, वे वस्तुएँ (जैसे कपड़ा) सस्ती होगी, जिनके उत्पादन में भूमि की अपेक्षा पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार, स्पष्ट है कि सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता वस्तु की माँग सम्बन्धी वशाओं और साधन-सेवाओं की पूर्ति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं।

(३) दोनों क्षेत्रों में वस्तु कीमतों में भिन्नतायें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण हैं—प्रचुर साधनों के प्रयोग से सम्बद्ध वस्तु देश में सस्ती उत्पन्न की जा सकती है, जिससे उसे अन्य देशों की अपेक्षा इस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है और इसके फलस्वरूप निरिष्टोत्करण और व्यापार की वृद्धि होती है। ओहलिन के शब्दों में, 'अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का तात्कालिक कारण सदा यह है कि वस्तुएँ स्वदेश में उत्पन्न करने की अपेक्षा, विदेशों से कम श्रौतिक कीमतों पर ही मँगाई जा सकती हैं।'¹ इस प्रकार, साधनों तो साधनों की पूर्ति तथा इनके प्रयोग की प्रभावपूर्णता से सम्बन्धित ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त को एक अधिक व्यापक आधार प्रदान किया। उसने सब घटकों को विचार में लिया तथा तलनात्मक लागतों की कीमन प्रणाली से, साधनों की माँग और साधनों की पूर्ति से सम्बन्धित किया। ओहलिन के लिए अग्रतिस्पर्धा समूहों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह गुरुओं की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के धम को उत्पादन के पृथक्-पृथक् साधन मान लेता है।²

1 Ohlin : *Inter-regional and International Trade*, p. 12

2 "By thus relating costs to the supply of the factors and the effectiveness with which they are used Ohlin provides a broader base for the theory of international trade than did the classical and neo-classical theories. He introduced all the factors and relates comparative costs to the price system, to factor supply and factor demand. Ohlin has no trouble in dealing with non-competing groups, he simply treats qualitatively different types of say, labour as separate factors of production"—S E Harris *International and Inter-regional Trade*, p. 52.

(४) विदेशी व्यापार की वस्तुओं का निर्यात—सापेक्षिक पूर्ति में भिन्नताओं से तो केवल यह पता चलता है कि कुछ वस्तुयें अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती होंगी। लेकिन यह पता नहीं चलता कि किन किन वस्तुओं में विदेशी व्यापार होगा। इस हेतु प्रत्येक क्षेत्र के नेताओं को चाहिए कि स्वदेश निर्यात वस्तुओं की कीमते विदेश निर्यात वस्तुओं से मिलावे। इसके लिए एक सामान्य (Common) करेंसी के प्रयोग की आवश्यकता है और यदि दो करेंसियाँ प्रयोग में आ रही हैं तो उनके मध्य विनिमय दर (Rate of exchange) मान्य होनी चाहिए।

(५) सामान्य करेंसी—मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में समान करेंसी प्रणाली है। इन देशों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं हैं। ऐसी वृत्ति में प्रत्येक देश में विभिन्न वस्तुओं की कीमते उनकी क्रमिक आन्तरिक माँगों (Respective internal demands) के अनुसार निर्धारित होती। जब दोनों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध शुरू होते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र की माँग दूसरे क्षेत्र की सूर्य प्रणाली के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आती है और अशाकृत सस्ते साधनों वाली वस्तुओं की स्वदेशी माँग के साथ उन्हीं वस्तुओं की विदेशी माँग भी कुछ बढ़ेगी। किन्तु साथ ही अशाकृत महँगे साधनों वाली वस्तुओं की स्वदेशी माँग विदेश की बली जावेगी। पारस्परिक माँगों (Reciprocal demands) के प्रभाव स्वरूप सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता उत्पन्न हो जायेगी और समानता की स्थापना तब ही होगी जबकि वस्तुओं का एक समान मूल्य (Equal value of goods) दोनों देशों के मध्य माना करेगा।

(६) भिन्न करेंसियाँ—यदि दोनों देशों में भिन्न करेंसी प्रणालियाँ हैं तो विनिमय दर पर भी ध्यान देना आवश्यक है। कारण, सापेक्षिक साधन कीमतों का अन्तर स्वयं को केवल विदेशी विनिमय दर के द्वारा ही वस्तु कीमतों के निरपेक्ष अन्तर के रूप में, जो कि व्यापार का तात्कालिक कारण है, प्रदर्शित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, उनकी पारस्परिक माँग कीमतों पर विनिमय-दर के माध्यम से प्रतिक्रिया दिलावेगे।

भिन्न-भिन्न करेंसियों वाले क्षेत्रों के मध्य साधन कीमतों की तुलना

उत्पत्ति-साधन	साधन-कीमत पाकिस्तान में (पा० १५५)	साधन-कीमत भारत में (पा० २०)	साधन कीमत भारत में (१ भा० १० = १५ पा० १०) (पा० २०)	साधन-कीमत भारत में (१ भा० १० = २ पा० २०) (पा० ४०)
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
O	I	0 20	0 30	0 40
P	I	0 30	0 45	0 60
Q	I	0 40	0 60	0 80
R	I	0 50	0 75	1 00
S	I	0 60	0 90	1 20
T	I	0 70	1 05	1 40

उपरोक्त नालिका से यह प्रगट है कि पाकिस्तान में साधनों की कीमतें समान हैं जबकि भारत में T याम महंगा और O सबसे सस्ता साधन है। व्यापार के दृष्टिकोण से निरपेक्ष सस्तापन (Absolute cheapness) महत्वपूर्ण है, सापेक्षिक सस्तापन (Relative cheapness) नहीं। निरपेक्ष सस्तापन विनिमय की दर पर निर्भर होता है। जब विनिमय दर १ भारतीय रुपया = १ ५ पाक रुपये है, तब पहले पांच साधन भारत में सस्ते और छठा साधन महंगा है। विन्तु जब विनिमय दर १ भारतीय रुपया = २ पाकिस्तानी रुपये है, तब केवल प्रथम तीन साधन सस्ते हैं, चौथे साधन का मूल्य समान है और पाँचवें व छठे साधन महंगे हैं। इस दशा में भारत O P Q साधनों की अधिक आवश्यकता वाली वस्तुयें बनायेगा किन्तु पाकिस्तान R एवं T साधनों की अधिक आवश्यकता वाली वस्तुयें बनाने पर ध्यान देगा। R साधन वाली वस्तु दोनो देशों में पैदा की जायेगी। सस्ते साधनों वाली वस्तुयें (Cheap factor products) निर्यात की जायेंगी और महंगे साधनों वाली वस्तुयें (Dear factor products) आयात होंगी।

(५) विनिमय की दर एवं अन्तर्देशीय वस्तु व्यापार का मूल्य दोनों ही पारस्परिक माँग द्वारा निर्धारित होते हैं—स्मरण रहे कि विनिमय दर यह तो दिखाती है कि प्रत्येक क्षेत्र में कौन से साधन सस्ते और कौन से साधन महंगे हैं किन्तु इनके संस्तेपन प्रत्यक्ष महंगेपन से निर्धारित नहीं करनी है। जिस प्रकार साधन-कीमतें पारस्परिक माँग (Reciprocal demand) द्वारा निर्धारित होती हैं उसी प्रकार विनिमय दर भी पारस्परिक माँग की बुनियादी शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर ऐसी होनी चाहिए कि दोनों क्षेत्रों में तात्पर्य-पूर्ति, आन्तरिक माँग (Internal demand) और एक दूसरे की वस्तुओं के लिये पारस्परिक माँग की सी हुई दशाओं के अन्तर्गत आयात और निर्यात बराबर हो जायें।

(६) विदेशी व्यापार द्वारा साधन-कीमतों में साध्य की बड़ाया—जब एक क्षेत्र व्यापार एक देश (या क्षेत्र) तथा बाह्य विश्व के मध्य खुल जाता है तो आन्तरिक कीमतों की प्रारम्भिक प्रणाली में समायोजन हो जाते हैं। औद्योगिक ने बताया है कि विदेशी व्यापार अपेक्षित प्रचुर साधनों की कीमतों में वृद्धि तथा दुर्लभ साधनों की कीमतों में कमी लाने की प्रवृत्ति रखता है। 'हम एक बहुत ही सरल और समूलतः उदाहरण लेते हैं, जिसमें केवल दो देश और दो साधनों (धम और भूमि) पर ही विचार किया जायेगा। भूमि की प्रचुर पूर्ति किन्तु धम की खूब पूर्ति वाला देश ऐसी वस्तुओं का आयात करे, जिनके उत्पादन के लिए अधिक धम की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसी वस्तुओं के निर्यात करे, जिनके उत्पादन के लिए भूमि की बहुत मात्रा आवश्यक होती है, लाभ उठायेगा। अतः औद्योगिक एजेंडस पहली प्रकार की वस्तुयें उत्पन्न करने में वजाय दूसरी वस्तु के उत्पादन के उद्योगों में सतर्क हो जायेंगे। अन्तः अधिक धम प्रयोग करने वाले उद्योग कम हो जायेंगे प्रथम श्रेणी हो जायेंगे, जिससे देश में धम के लिए माँग कम हो जायेगी। अधिक मात्राओं

में भूमि का प्रयोग करने वाले उद्योग बढ़ गे, जिससे भूमि का लिए मांग बढ़ जायगी। इस प्रकार, श्रम की कुलभत्ता कम हो जाना है किन्तु भूमि की कुलभत्ता बढ़न लगती है। दूसरे देश (या क्षेत्रों) में, जहाँ श्रम की प्रचुर पूर्ति उपलब्ध है किन्तु भूमि की पूर्ति कम है, अधिक मात्राओं में श्रम के प्रयोग का प्रयोग उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित होने से श्रम की दुर्लभता बढ़ कर भूमि की सापेक्षिक दुर्लभता में बढ़ो हो जायेगी। इस प्रकार दोनों ही देशों में सापेक्षिक प्रचुरता का प्रमाण बन लिए मांग बढ़ जाती है और उसे ऊँची कीमत प्राप्त होती है जबकि कम पूर्ति वाले साधन के लिए मांग कम हो जाती है जिससे उस पदार्थ की अग्रेष्ठा कम कीमत मिलती है। इस प्रकार, दोनों की कीमत दोनों देशों में समानता की ओर बढ़न लगती है।

(७) साधन कीमतों में केवल आर्थिक समानता—किन्तु यह केवल आर्थिक प्रभाव है। यद्यपि हुई साधन कीमतों के प्रति साधन पूर्तियों का क्या रश्च होना पड़ेगी विचार में, मूल्य समतल है, यदि उद्योगों के लिए जापानी बलों के निर्वात में, जो कि सस्ते श्रम की विशाल पूर्तियाँ पर आधारित है, वृद्धि होन से जापान में कम-श्रम की कीमत बढ़ जाय, तो श्रम की पूर्ति में काफी वृद्धि हो सकती है, जिससे अग्रणी सापेक्षिक माध्यम पुनर्कार का मूल्य कम आयेगा। इससे प्रति व्यक्ति बलों के उत्पादन का प्रमाण जो साधन श्रम के पूरक है व भी अधिक माना में आगे जायेगा, जिससे उनकी कीमत भी बढ़ सकती है। घन ओहलिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न माध्यमों की सापेक्षिक कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय भिन्नताओं का घटाता है तथापि साधन कीमत सभी भी पूर्णतः समान नहीं हो सकती। अन्तर्राष्ट्रीय समानता की दिशा में प्रवृत्ति होने की प्रवृत्ति साधन कीमतों की प्रवृत्ति अन्तु कीमतों में अधिक पाई जाती है।

[कुछ अपवादों पर परिस्थितियों में साधन-कीमत (निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों ही) पूर्ण समानता की स्थिति में हो सकती है। प्रो० शुम्पेटर ने इसका प्रमाण भी दिया है किन्तु उन्हें कई कल्पनायें करनी पड़ी हैं यथा—स्वतन्त्र बाजार, यातायात लागतें न होना सभी बाजारों में शुद्ध प्रतियोगिता, उत्पादन द्वारा म समरूपता (Homogeneous production function) (वैमाने समान्य मित-प्रतिपादा का प्रभाव), दोनों देशों में सभी वस्तुएं उत्पन्न होना। यदि कल्पनायें वास्तव में बहुत प्रतिबन्धनात्मक हैं।]

वास्तविक जीवन के सदर्भ में ओहलिन का सिद्धान्त

श्रम श्रम के विवेचन में यह स्पष्ट हो गया होगा कि (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का तात्त्विक कारण दोनों देशों की सापेक्षिक वस्तु-कीमतों में असमानताएँ होना

¹ P A Samuelson "International Trade and the Equalization of Factor Prices" *Economic Journal*, June, 1948

है, (ii) सापेक्षिक वस्तु-कीमतों में सममानता उत्पत्ति साधनों की सापेक्षिक दुर्लभताओं में भिन्नताओं के कारण उदय होती है, (iii) विनिमय दर की स्थापना पर 'सापेक्षिक कीमत भिन्नताओं' निरोधन कीमत-भिन्नताओं में परिणत हो जाती है। इससे यह मान्य होता है कि प्रत्येक देश किन वस्तुओं में विशिष्टीकरण करेगा, एवं (iv) विनिमय दर और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तु का मूल्य पारस्परिक मांग द्वारा निर्धारित होता है।

ग्रोहलिन ने बताया है कि यदि उत्तरी ग्रहण की हुई पूर्व धारणाओं को त्याग दिया जाय, तो भी उत्तका सिद्धान्त वास्तविक जीवन में अडिग रहता है। यथा—(i) वह कई देशों पर लागू किया जा सकता है। ऐसा करने से इसके निष्कर्षों में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं किन्तु जटिलता बढ जावेगी, (ii) एक ही समान साधन-सम्पत्ति वाले देशों के मध्य भी विशिष्टीकरण और व्यापार होना उचित है, क्योंकि एक विशाल (स्वदेशी + विदेशी) बाजार उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रेरणा देते हुए श्रेष्ठता (Superiority) या मितव्ययितायें (Economies) प्राप्त करावेगा। इस प्रकार, उत्पादन के बड़े पैमाने की मितव्ययितायें अन्तर्देशीय विनिमय के लिए एक अतिशय व्यापार प्रस्तुत करती हैं, (iii) भूमि, श्रम और पूँजी की, अन्तर्देशीय तुलना की दृष्टि से, विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है, क्योंकि इनमें गुणात्मक भिन्नतायें हानी हैं, (iv) यातायात व्यय व्यापार को घटाते हैं तथा कीमतों पर व्यापार के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें दुर्बल बनाते हैं, (v) ग्रोहलिन ने साधनों के अन्तर्देशीय गतिशीलता के बाधक घटकों को भी समझाया है कि किन प्रकार साधनों के अन्तर्देशीय वस्तु-आवगमनों का स्थान से सकते हैं, एवं (vi) चूँकि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर केवल परिमाण (Volume) का है इसलिए ग्रोहलिन का अन्तर्देशीय व्यापार सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी लागू होता है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त पर ग्रोहलिन के सिद्धान्त की श्रेष्ठता

अनेक बातों में ग्रोहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित (रिकार्डों के) सिद्धान्त की अपेक्षा एक सुधार है, क्योंकि वह लागतों और कीमतों पर बल देता है तथा साथ ही वास्तविक तथ्यों में अधिक निकट है। किन्तु जेमा कि प्रो० वाइनर (Viner) ने कहा है, ग्रोहलिन का यह कहना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के प्रति अनुचित है कि उन्होंने सापेक्ष साधन-पूर्तियों के प्रभाव पर विचार नहीं किया था। वाइनर ने स्पष्ट दिखा दिया है कि प्रतिष्ठित विद्वान इस समस्या से अपरिचित न थे।¹ उदाहरणार्थ, माल्थस ने निम्न था—“यूरोप ने अनेक देशों में मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा इंग्लैंड में मुद्रा का नीचा मूल्य मुरात हमारी निर्यात वस्तुओं के सम्प्रेषण से, जो स्वयं हमारी श्रेष्ठ मशीनों, निपुणता और पूँजी ने कारण है, उदय हुआ है। अमेरिका

¹ J. Viner *Study in the Theory of International Trade*, p. 305

में मुद्रा का मूल्य और भी नीचा है और इसलिए है कि वहाँ कच्चे मासों की प्रचुरता है और वे सस्ते हैं। यह प्रचुरता और सस्तापन उसकी भूमि, जलवायु और स्थिति सम्बन्धी भाषा के कारण है। भाषा में या श्रम की कीमत में अन्तर इतने अधिक नहीं है कि वे उत्पादन सम्बन्धी इन सुविधाओं की सन्तुलित कर सकें और इस प्रकार निर्यातों की बाहुल्यता को रोक सकें।¹

अधिकांश अर्थशास्त्री यह स्वीकार करने लगे हैं कि ओहलिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त की अपेक्षा श्रेष्ठ है। किन्तु हैबरतर ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त को जिस तरह से पुनः प्रस्तुत किया है उसके सन्दर्भ में यह देखा जा सकता है कि ओहलिन और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्तों में बहुत सादृश्य है। हैबरतर के अनुसार प्रत्येक व्यापारी देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है, जिन्हें वह कम अवसर लागत पर बना सकता है और उन वस्तुओं का आयात करता है जिन्हें वह अधिक अवसर लागत पर ही बना सकता है। कम अवसर लागत वाली वस्तु वास्तव में वे हैं जिनके लिए प्रचुरता बाल साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है और अधिक अवसर लागत वाली वस्तु वे हैं जिनके लिए दुर्लभता वाले साधनों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ओहलिन के सिद्धान्त को प्रतिष्ठित सिद्धान्त के पुनः कथन (Restatement) में मिलाया जा सकता है।²

1 "The lower value of money in England compared with the value of money in most of the states of Europe has appeared to arise principally from the cheapness of our superior machinery, skill and capital. The still lower value of money in the United States is occasioned by the cheapness and abundance of her raw products derived from the advantages of her soil, climate and situation, neither the difference in profits, nor the difference in the price of labour, is such as to counterbalance this facility of production and prevent the abundance of exports"—Malthus: *Principles of Political Economy*, 2nd Ed. pp 106-107.

2 "The Ricardian example of trade between England and Portugal can be interpreted in terms of the theory of opportunity cost without breaching Ricardo's reasoning and objectives. The explanatory function of the labour theory of value is to determine the price ratio, or, put in reciprocal terms, the exchange ratio between the two commodities. It has also the purpose of showing that the two commodities can be substituted

विन्तु हैरिस (Harris) को यह विश्वास है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने साधन अनुपात पर बल नहीं दिया था और ओह्रनिन को ही इस बात का श्रेय है कि उसने साधन-सम्पत्तियों और स्थान-चयन सिद्धान्त (Theory of location) को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में मिला दिया।¹

दुर्गके अतिरिक्त ओह्रनिन ने सबके (जिनमें नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री भी सम्मिलित हैं) द्वारा मान्य मूल्य-सिद्धान्त को ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया है। उसने यह सकारण रूप में दिखा दिया है कि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मध्य कोई बुनियादी भेद नहीं है, केवल परिमाण मात्र-धी भेद (Quantitative difference) है और कि एक अकेले बाजार के मूल्य सिद्धान्त को ही विस्तृत करके अनेक बाजारों में प्रचलित मूल्य के स्पष्टीकरण हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

विन्तु यह स्वीकार करना होगा कि ओह्रनिन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित सुगम श्रम लागत स्पष्टीकरण की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल है और यह जटिलता स्वाभाविक भी है क्योंकि जिन मूल्य सिद्धान्त (सामान्य साम्य सिद्धान्त) पर वह आधारित है वह स्वयं भी जटिल है और जिन मथ्यों को वह स्पष्ट करता है वे भी जटिल हैं। विना जटिल होते हुए भी ओह्रनिन का सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक यथार्थवादी विश्लेषण करता है। लेकिन ऐसी यथार्थवादिता सुगम प्रतिष्ठित सिद्धान्त के सम्बन्ध में नहीं पाई जाती है।

led for each other in proportion to their costs by means of a shift in production, that is, by a transfer of the means of production (Labour) If it were possible to show, without making the unacceptable assumptions of the labour theory of value, that the exchange ratio (price ratio) in the market and the rate of substitution coincide the national trade would remain intact. And it can indeed be proved that, under certain ideal conditions even if we assume the existence of a large number of more or less immobile and specific factors of production, the exchange ratio will be equal to the marginal rate of substitution. These required conditions are identical to those which usually underline general equilibrium theory—free competition in the commodity and product markets as well as the absence of so called external economics"—Haberler : *A Survey of International Trade Theory*, 1955, pp 14-15

¹ Harris : *International and Inter-regional Economics*, p 55

परीक्षा प्रश्न :

१. मूल्य का सामान्य साम्य सिद्धान्त क्या है ? यह किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पर्याप्त स्पष्टीकरण देता है ?

[What is the General Equilibrium Theory of Value ? How far does it afford a satisfactory explanation of inter-regional trade ?]

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित एवं आधुनिक सिद्धान्तों की तुलना कीजिये ।

[Compare the classical and modern theories of international trade]

- ओहलिन के सामान्य साम्य सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये । इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करिये ।

(गोरख०, एम० ए०, १९६६)

[Explain Ohlin's general equilibrium theory. Examine it critically]

- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में ओहलिन के योगदान की समीक्षा कीजिये ।

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

[Explain the contribution of Ohlin to the theory of international Trade.]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त (Opportunity Cost Doctrine of International Trade)

प्रारम्भिक—

सामान्य साम्य विश्लेषण के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त का एक अन्य दृष्टिकोण भी है, जिसे प्रो० हेबरलर ने विवक्षित किया है और वह 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धान्त' कहलाता है। हेबरलर ने भी विभिन्न साधन-सम्पत्तियों (Factor-endowments) की भूमिका पर बल दिया है, किन्तु सुगमता के लिये वे यह मान लेते हैं कि देश विशेष में उपलब्ध साधनों की पूर्ति स्थिर (Fixed) है यद्यपि उनका प्रयोग कई ढंगों में किया जा सकता है—जैसे, एक वस्तु के उत्पादन में कुछ नमी करके दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक देश के पास उत्पादन सम्भावनाओं (Production-possibilities) के कई सेट होने हैं। प्रो० हेबरलर के विमर्शण में श्रम लागतों का स्थान एक वस्तु की दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित करने की लागतों न ले लिया है और इन्हें 'क्षाने हुए विकल्प' (Alternative forgone) के रूप में व्यक्त किया जाता है।

✓ अवसर लागत सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताय

(1) साधनों की अनेकता, विविधता और विशिष्टता पर बल देना—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त श्रम मूल्य सिद्धान्त (Labour theory of Value) पर आधारित है। श्रम मूल्य सिद्धान्त की अनेक त्रुटियाँ हैं। हा, यदि उत्पत्ति का एक ही साधन (समान गुण युक्त श्रम) होना, तो वह सामान्य मूल्य सिद्धान्त की एक विशिष्ट दशा के रूप में वैध (Valid) ठहराया जा सकता था। किन्तु वास्तविक विश्व में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक देश में अनेक प्रकार के अनेक उत्पत्ति साधन (जैसे विभिन्न गुणों वाले श्रम, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक तथा मनुष्य निर्मित साधन) पाये जाते हैं। इन सब साधनों की किसी एक सामान्य मात्रा इकाई के रूप में नहीं पाया जा सकता।

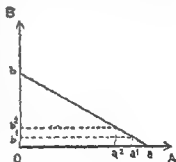
इसके अतिरिक्त, अनेक उत्पत्ति-साधन विशिष्ट (Specific) होते हैं। अर्थात् या तो वे केवल एक विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग किये जा सकते हैं अथवा अन्य कार्य में स्थानान्तरित करने पर उनकी उपज इतनी घटती होगी कि स्थानान्तरण

करना व्यर्थ रहता है। साधनों की इस विनिष्ठता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे— प्रवास पर कानूनी नियन्त्रण, अत्यधिक यातायात-व्यय, तकनीकी अनुपयुक्तता। साथ ही, साधनों की विनिष्ठता स्थायी हो सकती है अथवा 'अस्थायी'।

(II) प्रतिस्थापन-वक्र से सापेक्षिक कीमतों का पता लगाना—

अम मूल्य सिद्धान्त के प्रयोग का एवमान उद्देश्य दोनी देशों में स प्रत्येक में सापेक्षिक कीमते (Relative prices) पता लगाना था। रिकार्डों ने कहा था कि 'अम लागत पूर्ति को प्रभावित करके कीमतों को निर्धारित करती है। हेबरस्टर ने बताया है कि सापेक्षिक कीमत, अम-मूल्य सिद्धान्त की श्रवांस्तविक मांगता को प्रभावित बिना ही पता लगाई जा सकती है। यह जिससे है —

'मान लीजिए कि स्थिर लागत प्रचलित है। वस्तु A की प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिए अम की एक और वस्तु B की प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिये अम की दो इकाइयों के व्यय की आवश्यकता पड़ती है। निकट के बिन्दु १ में X axis पर A की मात्रा में और Y axis पर B की मात्रा में भाषी गई है, जिससे कि दोनों axis के मध्य कोई भी भाग A और B के एक विक्षेप समीप को सूचित करता है। यदि अम की कुल उपलब्ध पूर्ति को केवल A वस्तु के उत्पादन में ही लगावे, तो उससे A वस्तु की Oa मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है और यदि केवल B वस्तु के उत्पादन में ही लगावे, तो उससे B वस्तु की Ob मात्रा का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार



चित्र १

उपलब्ध अम द्वारा दोनी वस्तुओं के अनेक संयोग (Combinations) उत्पन्न किए जा सकते हैं। इन विभिन्न संयोगों की सूची निम्न प्रकार हो सकती है —

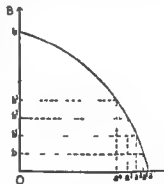
उत्पादन-संयोग तालिका

संयोग क्रमिक	A वस्तु	+	B वस्तु
1.	Oa	+	शून्य
2.	Oa^1	+	Ob^1
3.	Oa^2	+	Ob^2
4.	...	+	...
5.	...	+	...
n	शून्य	+	Ob

A और B वस्तुओं के जो विभिन्न संयोग कुल उपलब्ध श्रम के प्रयोग द्वारा उत्पन्न किये जा सकते हैं वे सब a b रेखा पर ही पड़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि II दस्तु की एक प्रतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए A वस्तु की २ इकाईयाँ कम करनी पड़ती है। अन्य शब्दों में, A और B के मध्य प्रतिस्थापन की दर (Rate of Substitution) 1:2 है। यही वस्तुओं का विनिमय अनुमान भी है।”

अब यदि हम यह मानें कि अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई लागतें प्रचलित हैं, तो उक्त परिस्थिति में क्या अन्तर पड़ेगा? हैबर्सर ने बताया है कि ऐसी दशा में प्रतिस्थापन वक्र (Substitution curve) मूल बिन्दु अवतल (Concave to the origin O) होगा। पहले की भाँति इस दिशा में भी A की Oa मात्रा और B की शून्य मात्रा उत्पन्न की जा सकती है।

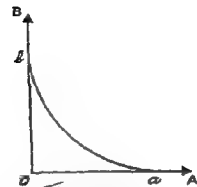
यदि B की Ob^1 मात्रा उत्पन्न करना चाहे, तो A की aa^1 मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि B की एक और प्रतिरिक्त मात्रा $b^1 b^2$ उत्पन्न करना चाहें, तो ऐसा केवल तब ही किया जा सकता है जबकि हम A की पहले से अधिक मात्रा ($a^1 a^2 > aa^1$) का त्याग करने को तैयार हो जायें। आगे भी यही तम चलेंगा। जैसे-जैसे B का उत्पादन बढ़ाने और A का उत्पादन घटाने जायेंगे, B की उत्पादन-लागत बढ़ती जायेगी, बिन्दु A की उत्पादन लागत कम होनी जायेगी, जिससे B की एक प्रतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु A की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि हम b बिन्दु से चलते, तो भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई देगी, अर्थात् A की एक प्रतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु B की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता। यही कारण है कि प्रतिस्थापन वक्र मूल बिन्दु से अवतल होता है।



चित्र २—बढ़ती हुई लागतों के आधीन प्रतिस्थापन वक्र

बिन्दु A की उत्पादन लागत कम होनी जायेगी, जिससे B की एक प्रतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु A की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यदि हम b बिन्दु से चलते, तो भी ऐसी ही प्रवृत्ति दिखाई देगी, अर्थात् A की एक प्रतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने हेतु B की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा का त्याग करना पड़ता। यही कारण है कि प्रतिस्थापन वक्र मूल बिन्दु से अवतल होता है।

यदि दोनों वस्तुओं का उत्पादन घटती हुई लागतों के आधीन होता है, तो प्रतिस्थापन वक्र मूल बिन्दु से उत्तरोत्तर (Convex) होगा। जैसे-जैसे B (या A) के उत्पादन में $A_1(P, M)$, $A_2(P, M)$, उत्पादन, प्रतिस्थापन, $A_1(P, M)$, $A_2(P, M)$, की अवसर लागत B (या A) के रूप में घटती जायेगी।



चित्र ३—बढ़ती हुई लागतों के
आधीन प्रतिस्थापन वक्र

प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में विविध अनुपात कैसे निर्धारित होगा ? स्थिर लागतों के आधीन तो वह केवल लागतों (Costs) से ही निर्धारित होता है, माँग की भूमिका केवल इतनी है कि यह उत्पत्ति की दोनो आख्याओं में उपभोग साधनों के वितरण को (और इस तरह से A और B की उत्पत्ति की जाने वाली सापेक्षिक मात्राओं को) निश्चित करती है। लेकिन बढ़ती हुई लागतों की दशा में वह (माँग) विविध के अनुपात पर भी प्रभाव डालने लगती है, क्योंकि सापेक्षिक लागतें—प्रतिस्थापन अनुपात—A और B के लिए सापेक्षिक माँग की घटा-बढ़ी के अनुसार परिवर्तित हो जाया करती हैं। एक दिये हुए माँग सम्बन्धी समूह की दशा में, A और B जिस अनुपात पर बाजार में एक दूसरे से विनिमय की जायेगी वह उस बिन्दु पर इनके प्रतिस्थापन अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि वस्तुओं के मध्य विविध अनुपात इनकी सीमान्त लागतों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि यदि वह इससे कम या अधिक है, तो समायोजन की प्रवृत्ति (Process of adjustment) प्रारम्भ हो जायेगी, जिससे अन्ततः विविध अनुपात सीमान्त लागतों के अनुपात के समान हो जायेगा। अतः हैबरलर ने कहा है कि —

“अब यह स्पष्ट है कि हमें मुख्य के अर्थ सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं रही है। हम वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दशा में आसूँ कर सकते हैं तथा उन्हें एक प्रतिस्थापन वक्र की अवस्था में प्रगट कर सकते हैं चाहे उत्पत्ति के अनेक साधन उपलब्ध हो या केवल एक समान (Homogeneous) श्रम-साधन ही उपलब्ध हो। जबकि माँग दो हुई है, तब चाहे जितने साधन हो सो वस्तुओं को सापेक्षिक कीमतें इनकी लागतों द्वारा निर्धारित होगी। किन्तु अब हमें लागतों का माप करने में भास्त्रियन सम्प्रदाय का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात् लागतों का माप त्यागे गये विवर्तों द्वारा करें। वि. यम की भाँसा द्वारा। इस प्रकार, वस्तु A की एक

दो हुई मात्रा x की लागत B वस्तु की वह मात्रा है जिसे A वस्तु की $x + 1$ इकाइयों के बजाय x इकाइयाँ उत्पन्न करने हेतु छोड़ना पड़ता है। बाजार में A और B के मध्य विनिमय अनुपात इसी अर्थ में इनकी लागतों के बराबर (अर्थात् अवसर लागतों के बराबर) होना चाहिए।¹

चूँकि विभिन्न देशों की साधन सम्पत्तियाँ (Factor endowments) भिन्न-भिन्न होती हैं इसलिए उनके प्रतिस्थापन वक्र विभिन्न स्वरूपों (Forms) के होंगे। मांग सम्बन्धी दृष्टांत भी इसी प्रकार विभिन्न हो सकती हैं। यद्यपि ऐसी दशा में, जहाँ कारणों से जिन्हें ओह्लिन ने बताया था व्यापार दोनों देशों के लिए लाभदायक होगा।

(III) आधुनिक मोंट्रिक अर्थ-व्यवस्था में भी विनिमय अनुपात उनकी प्रतिस्थापन लागतों से निर्धारित होना—

हेबरलर ने बताया है कि एक आधुनिक मोंट्रिक अर्थ-व्यवस्था में भी विनिमय अनुपात (वस्तुओं की सापेक्ष कीमतें) वस्तुओं की प्रतिस्थापन लागतों से ही निर्धारित होते हैं। हाँ यह सत्य है कि वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन-सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं रहते बल्कि अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, क्योंकि मुद्रा एक मध्यस्थ का कार्य करती है।²

1 "It is now obvious that we have no further need of the labour theory of value. We can derive the conditions of substitution between the commodities, and express them in the form of a substitution curve, when many different factors of production are available just as well as when there is only homogeneous labour. However many factors there may be, the relative prices of two commodities will be determined (given the demand) by their costs—but we must now follow the Austrian School in measuring costs not by the absolute amount of labour required but by the alternatives forgone. Thus, the marginal cost of a given quantity x of the commodity A must be regarded as that quantity of B which must be forgone in order that x , instead of $x + 1$ units of A can be produced. The exchange ratio on the market between A and B must equal their costs in this sense of the term.—*Haberler The Theory of International Trade*, p. 177

2 "We must now show the application of this reasoning to a modern money economy. Of course we cannot state, for example, that a certain change in the relative prices of wheat and motor cars will cause one additional motor car to be produced in the place of so many bushels of wheat. Nevertheless our doctrine can be applied in its essentials, given certain condition to a modern economy.....The substitution relations between the conditions are no longer direct, but are indirect, operating through the medium of money cost."—*Ibid*

भ्रम लागती या भ्रमसर लागती के स्थान में हम 'भौदिक लागत' शब्द का प्रयोग उचित रूप से कर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिस्थापन लागतें भौदिक व्यय-व्यवस्था में निम्न दशायें विद्यमान होने पर ही विनिमय अनुपात को निर्धारित कर सकती हैं —

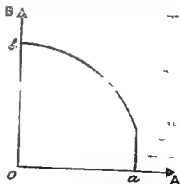
(१) प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त (मुद्रा) लागत के बराबर होती है। सीमान्त लागत से तात्पर्य $x-1$ इकाइयों के वक़ाय x इकाइयों उत्पन्न करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त साधनों की कीमतों के जोड़ का है,

(२) प्रत्येक उत्पत्ति-साधन की विभिन्न इकाइयों का मूल्य (जहाँ ये साधन गतिशील और एक दूसरे के स्थानापन्न (Substitute) हों) सभी प्रयोगों में समान होता है, एवं

(३) उत्पत्ति के प्रत्येक साधन (गतिहीन और विशिष्ट साधनों की सम्मिलित न करते हुए) की इकाइयों का मूल्य इसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है। (यह सीमान्त उत्पादकता से आशय उत्पत्ति के साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग द्वारा भौतिक उत्पन्न में होने वाली मूल्य-वृद्धि का है।) किन्तु यह आवश्यक है कि साधन इकाइयाँ एक समान और एक दूसरे की स्थानापन्न हों और य वग़ाय जैसा कि सब जानते हैं प्रतियोगिता द्वारा स्थापित होनी है।

(IV) विशिष्ट घटकों पर विशेष बल—

प्रो० हैबरलर न उस अंश पर, जहाँ तक उत्पत्ति साधन किसी एक उद्योग की दृष्टि से विशिष्ट (Specific) होते हैं (प्रयत्न यों कहें कि अग्रे उद्योगों के लिए बेकार होते हैं) विशेष रूप से बल दिया है। विशिष्ट साधन वह हैं जो केवल किसी वस्तु विशेष के उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं किन्तु अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये अनुपयुक्त प्रयत्न बहुत ही अल्प साध्य होने हैं। विशिष्ट साधनों की उपस्थिति सिद्धान्त की वैधता पर प्रभाव नहीं डालती है। हाँ इनकी वजह से प्रतिस्थापन वक्र का रूप अवश्य बदल जाता है। अविशिष्ट साधनों का अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र उतना ही अधिक चपटा (Flatter) होगा और जिस अनुपात में दोनों वस्तुयें मांगी जाती हैं उसमें होने वाले परिवर्तन सापेक्षित लागतों में उतने ही छोटे परिवर्तन लायेंगे। इसके विपरीत, विशिष्ट साधनों का अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र में उतनी ही अधिक फुलावट (Bulge) होगी और दोनों वस्तुयें जिस अनुपात में मांगी जाती हैं उसमें होने वाले परिवर्तन सापेक्षित लागतों में उतने ही बड़े परिवर्तन लायेंगे।



चित्र—विशिष्ट साधनों का अधिक अनुपात होने पर प्रतिस्थापन वक्र

(V) उत्पत्ति ह्रास नियम पर विस्तारपूर्वक विचार—

उन्होंने बढती हुई लागतों की समस्या पर विस्तार विचार किया और बताया कि "जिन शुभमता से एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु द्वारा किया जा सकता है, यह दूसरी वस्तु का उत्पादन बढाये जाने के साथ ही साथ कम होती जाती है।" ¹ बढती हुई लागत की दशाओं के अन्तर्गत जो उत्पादन होता है वह इस बात को समझने में सहाय्य है कि क्यों कोई देश अपनी पूँति के एक भाग के लिए अपने जरेखू स्रोतों पर और शेष भाग के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहता है।

स्थिर लागत सम्बन्धी मान्यता का त्याग करने पर विशिष्टीकरण के लाभों से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उदय होते हैं :—

(१) ग्राह्य और अन्य विद्वानों ने बताया है कि एक ऐसे देश को जो बढती हुई लागतों वाले उद्योग में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है और घटती हुई लागतों के अन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्तुयें आयात करता है, व्यापार ने फलस्वरूप हानि ही सकती है।

(२) किन्तु बढती हुई लागतें ही अपूर्ण विशिष्टीकरण का एक मात्र कारण नहीं है। इसका दूसरा कारण है एथियों में अन्तर होना। यद्यपि अधिकतर अमेरिकन अमेरिका में बनी हुई कारों ही पसन्द करते हैं और चाहे वह देश एक ही हुई बिस्म की कार का उत्पादन सबसे सस्ती लागत पर कर सकता है, तथापि कुछ अमेरिकन ब्रिटिश कारों को उसी प्रकार से पसन्द करते हैं, जिस प्रकार से कि कुछ लोग फ्रेंच गराब और स्विस् घड़ियों को अमरीकी गराब और घड़ियों की अपेक्षा अधिक पसन्द करते हैं। ऐसे उत्पादन और विक्रय सम्बन्धी दोनों उत्पाद-भेद (Product differentiation) के रूप के समझे जाने चाहिए (ब्रिटिश कार एक वस्तु है, अमेरिकन कार दूसरी), बाजारों के विभाजन के रूप नहीं।

अवसर लागत दृष्टिकोण की समीक्षा

अवसर लागत दृष्टिकोण लागत पक्ष की कठिनाइयों से तो बचता है लेकिन माँग पक्ष पर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देता है। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) व्यक्ति के लिए उदासीनता वह इस मान्यता के आधार पर खींचा जाता है कि उसकी माँग स्थिर रहती है। लेकिन समाज के लिए एक अकेला उदासीनता वह खींचना सम्भव नहीं है भले ही इसकी कुल माँग को स्थिर मान ले। कारण, कुल माँग के स्थिर रहते हुए यदि इसमें वितरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो वह व्यक्तिगत सदस्यों का अनुराग कम को और इस प्रकार समाज के उदा-

1 For a full discussion, see Viner *Studies in the Theory of International Trade*, pp. 470-482

सीनना वक्र को बदल देगा। उदासीनता वक्रों का प्रयोग इस मान्यता पर निर्भर है कि यह एक दूसरे को काटते नहीं हैं। किन्तु धाय के विभिन्न वितरणों को व्यक्त करने वाले कुछ उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उनमें से कौन बेहतर स्थिति में है। एक अकेला समाज उदासीनता वक्र तब ही खींचा जा सकता है जब हम यह मान लें कि समाज की स्थिर कुल धाय के वितरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु ऐसा करने पर अवसर लागत दृष्टिकोण की व्यावहारिक उपयोगिता कम हो जायेगी :

(२) उपभोग उदासीनता वक्र यह कल्पना करता है कि उपभोक्ताओं की हवियाँ बिचाराधीन अवधि पर्यन्त अपरिवर्तित रहती हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा होना जरूरी नहीं है।

(३) उत्पादन-उदासीनता वक्र यह कल्पना करते हुए बनाये जाते हैं कि (i) उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर है, (ii) बाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रकार की मितव्ययिताये अनुपस्थित हैं, तथा (iii) उत्पाद एवं साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि उत्पत्ति साधनों की पूर्ति इनकी कीमतों के परिवर्तनों से प्रभावित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में स्थान में अपूर्ण प्रतियोगिता ही अधिक प्रचलित दशा है तथा बाह्य एवं आन्तरिक मितव्ययिताये प्राप्त हो सकती हैं।

अवसर लागत सिद्धान्त और तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कौन बेहतर है ?

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के दो कार्य हैं—विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक कार्य तथा कल्याण या नीति सम्बन्धी कार्य। पहिले कार्य का तात्पर्य व्यापार को जन्म देने वाले कारणों से और दूसरे का तात्पर्य व्यापार के मोचित्व से है। विश्लेषण के कार्य के लिए तो अवसर लागत दृष्टिकोण को बेहतर समझा जाता है किन्तु नीति सम्बन्धी कार्य के लिए तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को। हैबरलर को इस बात का समदेह है कि वास्तविक लागत दृष्टिकोण जो विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, नीति के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है। सच्चाई यह है कि दोनों प्रकार के दृष्टिकोण अपनी-अपनी दुर्बलताये रखते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

1. हैबरलर द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।

(सागरा, एम० कॉम०, १९६६)

[Briefly-explain the opportunity-cost doctrine of International trade as propounded by Haberler.]

- २ - "अवसर लागत विश्लेषण 'प्रतिष्ठित तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' और पूर्ण विकसित 'सामान्य विश्लेषण सिद्धान्त' के मध्य एक सम्बन्ध बढी है।" स्पष्ट कीजिए।

["Opportunity cost analysis is a link between the classical theory of comparative costs and the full-blown general equilibrium analysis involving variations in the amount of factors of production" Discuss.]

- ३ क्या यह कहना सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत दृष्टिकोण प्रतिष्ठित दृष्टिकोण का पूरक अधिक है स्थानापन्न कम ? कारण सहित उत्तर दीजिए। (इलाहा०, एम० ए०, १९६६)

[Is it correct to say that the opportunity cost approach to the theory of international trade is more a complement to rather than a substitute for, the classical approach ? Give reasons.]

- ४ शिशु उद्योगों को रक्षण देने की औचित्य की अवसर लागत सिद्धान्त के सन्दर्भ में समीक्षा कीजिये। इसे अर्द्ध-विकसित देशों में लागू करने की दृष्टि से आप उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक समझते हैं ?

(इलाहा०, एम० कॉम०, १९६६)

[Examine in terms of the opportunity cost theory the plea for protection of infant industries ? What changes would be needed in your view to make it applicable to under developed countries ?]

व्यापार शर्तें

(Terms of Trade)

प्रारम्भिक—‘व्यापार-शर्तों’ से आशय

विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुएँ होनी हैं जिनका कानूनी चलन इनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होता है। परिणामतः देशों को अपने आपातों के लिए नियंत्रण के रूप में भुगतान करना पड़ता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक ‘बदल-बदल’ (Barter) या ‘वस्तुओं के प्रत्यक्ष विनिमय’ का रूप धारण कर लेता है। जिन दर पर नियंत्रण आपातों के सबसे दिये जाते हैं उसे ‘व्यापार की शर्तें’ (Terms of Trade) कहते हैं।¹ उदाहरण के लिए, यदि भारत को अमेरिका से १००० टन गेहूँ के बदले में १०० टन मारियन भेजना पड़ता है, तो व्यापार की शर्तें १००० : १०० होगी। यह अनुपात हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि १ टन मारियन के बदले में भारत को कितने टन गेहूँ प्राप्त होता है। ‘व्यापार-शर्तों’ के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएँ प्रचलित हैं, जिन्हें आगे समझाया गया है।

‘शुद्ध’ एवं ‘कुल’ व्यापार शर्तें

प्रो० टॉजिंग (Tausig) ने दो प्रकार की व्यापार-शर्तों का उल्लेख किया है—‘शुद्ध’ एवं ‘कुल’।

(१) ‘शुद्ध’ बदल बदल वाली व्यापार शर्तें (अथवा वस्तुगत व्यापार शर्तें)—
जिन्हें दो क्रम से आने वाली अवधियों में आयात कीमतों से निर्यात कीमतों की तुलना के अनुपात को शुद्ध अदम बदल वाली व्यापार शर्तें (Net Barter Terms of Trade) अथवा ‘वस्तुगत व्यापार शर्तें’ (Commodity Terms of Trade) कहते हैं।² योज रूप से इसे निम्नांकित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है —

¹ When the trade between two countries involves only two goods, one on either side, we speak of an ‘exchange ratio’ or ‘exchange rate,’ but when it involves more than two goods, we speak of the ‘terms of trade’

² The ratio of comparison between export prices to import prices in any two consecutive periods is called the Net Barter Terms of Trade or the Commodity Terms of Trade.

$$\frac{px_1}{pm_1} = \frac{px_0}{pm_0}$$

जिसमें, p = कीमत

x = नियमित

m = आयात और अधोलिखित (Subscripts) का आशय समयावधि से है।

यदि निर्यात कीमत सूचकांक t_0 और t_1 अवधि में १०० से बढ़ कर २०० हो गया है और इसी अवधि में आयात कीमत सूचकांक केवल १०० से बढ़कर १५० हो गया है, तो व्यापार की शर्तें निम्नांकित होंगी —

$$\frac{200}{150} = \frac{100}{100} = 1.33 : 1.00$$

इसका आशय यह है कि t_1 समय पर व्यापार की शर्तों में उक्त समयावधि के भीतर ३३% सुधार हो गया है। अन्य शब्दों में, आयात कीमतों की तुलना में निर्यात कीमतों में हुई अधिक वृद्धि व्यापार की शर्तों में अनुकूल परिवर्तन होने का सूचक है। विपरीत क्रम से, यदि निर्यात कीमतें आयात कीमतों की अपेक्षा कम बढ़ें, तो यह व्यापार की शर्तों में प्रतिवृत्त परिवर्तन होने का सूचक है।

(२) 'कुल वस्तु विनिमय वाली व्यापार शर्तें'—व्यापार शर्तों से सम्बन्धित शुद्ध बदल बदल धारणा का प्रयोग अब ही वास्तविक होता है जबकि सम्बन्धित देश के भुगतान सन्तुलन में वस्तुओं और सेवाओं के आयात सम्बन्धी भुगतानों (Payments) और निर्यात सम्बन्धी प्राप्तियों (Receipts) के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सम्मिलित न हो। लेकिन, जब भुगतान सन्तुलन में आयातों एवं निर्यातों (द्वय प्रथवा प्रद्वय) के अतिरिक्त अन्य मदों से सम्बन्धित भुगतान भी (जैसे इकरारों द्वारा स्थानांतर (Unilateral transfers) सम्मिलित हो, तो कुल बदल बदल वाली व्यापार शर्तों (Gross Barter Terms of Trade) को ही विचार में लेना चाहिए। हम धारणा के अनुसार हम कीमतों से सम्बन्ध स्थापित करने के बजाय अब मात्राओं या परिमाणों (Quantities) से सम्बन्ध रखते हैं। यद्यत् 'कुल बदल बदल वाली व्यापार शर्तों' का आशय वास्तविक निर्यात मात्राओं और वास्तविक आयात मात्राओं के मध्य तुलना के अनुपात से है। इसे बीज रूप में निम्न प्रकार से प्रगट किया जा सकता है —

$$\frac{q_{x_1}/p_{x_1}}{q_{m_1}/p_{m_1}} = \frac{q_{x_0}/p_{x_0}}{q_{m_0}/p_{m_0}}, \text{ or } \frac{q_{x_1}}{q_{m_1}} \cdot \frac{p_{m_0}}{p_{x_1}} = \frac{q_{x_0}}{q_{m_0}} \cdot \frac{p_{m_0}}{p_{x_0}}$$

जिसमें p = सामान्य कीमत स्तर

q = मात्रा

x = निर्यात

m = आयात और Subscripts समयावधियों के सूचक हैं

‘एकल’ एवं ‘द्वि-साधनात्मक’ व्यापार-शर्तें
(Single and Double Factorial Terms of Trade)

वाइनर ने व्यापार शर्तों को एकल एवं द्वि साधनात्मक व्यापार-शर्तों के रूप में स्पष्ट किया है ।

(१) एक साधनात्मक व्यापार-शर्तें—सूची ‘कुन’ बदल बदल व्यापार-शर्तों की धारणा में सीमन तत्त्व, जो कि एक प्रकार का सीमन है, सम्मिलित है, इसलिए यह भी ‘शुद्ध बदल-बदल व्यापार शर्तों’ की धारणा की भांति समूची, शुद्धपूर्ण है तथा भुगतान-मन्तुवन की वास्तविक दशा को दिखाने में प्रमत्त है । यही नहीं शुद्ध और ‘कुन’ अवल वचन व्यापार-शर्तों का अर्थ केवल तब ही स्पष्ट हो पाता है जबकि भुगतान-मन्तुवन दोनों अवधियों में साम्यावस्था में बना रह । यह भी आवश्यक है कि तुलना के लिए चुनी गई अवधिया इतनी निश्चिततम (Proximate) हो कि उन पर उत्पादकता सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े । वाइनर (Viner) के अनुसार, ‘यदि निर्यात वस्तुओं के उत्पादन के सीमित तत्वों की गुणों (Coefficients) के रूप में उत्पादन लागत का एक सूचकांक बनाना सम्भव हो और यदि ‘वस्तुगत-व्यापार शर्त सूचकांक’ को उक्त तत्वों की गुणों के व्युत्क्रम (Reciprocal) से गुणा किया जाय, तो इसके फलस्वरूप जो सूचकांक प्राप्त होगा वह व्यापार के लाभ की प्रवृत्ति के बारे में वस्तु व्यापार-शर्त सूचकांक की स्पष्टा प्रतिक प्रवृत्ति मार्ग दर्शन प्रदान कर सकता है ।’ उक्त ऐसी व्यापार शर्तों को ‘एकल साधनात्मक व्यापार शर्तें’ (Single Factorial Terms of Trade) कहा है ।¹

(२) द्वि साधनात्मक व्यापार शर्तें—विन्तु उत्पादकता दो मुद्दी होती है, अर्थात् यह न केवल निर्यात का वस्तु आयातों को भी प्रभावित करती है । यदि हम इस बात को विचार में लें, तो इन्हें ‘द्वि साधनात्मक व्यापार-शर्तें’ (Double Factorial Terms of Trade) कहा है । वाइनर के अनुसार, ‘द्वि-साधनात्मक व्यापार शर्तों का अर्थ निदेशी देश की, जिसके उत्पाद हमारे स्वदेश की उत्पादक-सेवाओं की एक इकाई के उत्पाद से विनिमय होते हैं, उत्पादक सेवाओं की इकाइयों की संख्या में है ।’²

‘आय-गत’ और ‘बाजार-गत’ व्यापार शर्तें
(Income and Market Terms of Trade)

(१) आय गत व्यापार शर्तें—रोबर्टसन (Robertson) की सम्मति में ‘साधनात्मक व्यापार शर्तें’ (इकहरी या दोहरी) एक वास्तविक माप है । उन ती यह धारणा सैद्धांतिक रूप में सही हो सकती है किन्तु व्यावहारिक रूप से नहीं । व्यवहार में, उत्पादकता तत्त्व को मापना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि जब हम

¹ *Studies in the Theory of International Trade*, p 559.

² *Ibid* p 561

उत्पादकता को मापने का प्रयत्न करते हैं तब कई समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं, जैसे— उत्पादकता में अन्तर लाने वाले घटक कौन कौन से हैं ? निर्यात, आगमन अथवा सम्पूर्ण औद्योगिक इनमें से किस क्षेत्र की उत्पादकता को जाँचे ? क्या समय एवं मूल्य अग्रयन पर्याप्त सूचना प्रदान कर सकेगे ? बाह्य घटकों (जैसे जलवायु, कार-वार्ने का स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? ऐसी ही समस्याओं ने विद्वानों को उक्त धारणाओं में संशोधनों पर विचार करने हेतु विवश कर दिया है। इन संशोधनों में से ही एक 'आयात वदस वाली व्यापारी शर्तों' का एक रूपान्तर है और इसे 'आयात करने की क्षमता' (Capacity to import) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीज रूप में इसे निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$qm = \frac{px \cdot qx}{pm}$$

जहाँ, qm = आयात करने की क्षमता

p = कीमत

x = निर्यात

m = आयात

आयात करने की क्षमता उस दशा में अधिक होगी जबकि (i) निर्यातों की कीमत ऊँची हो जाय, (ii) निर्यातों की मात्रा बढ़ जाय और/अथवा (iii) आयातों की कीमत घट जाय। चूँकि इस दृष्टिकोण से तुलना के आधार का अभाव है, इसलिये हम आयात-गत व्यापार शर्तों को निम्न ढंग से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$qm_0 \quad qm = \frac{px \cdot qx}{pm} \quad \frac{px_0 \cdot qx_0}{pm_0}$$

(२) 'बाजार शर्त' व्यापार शर्तें—उपरोक्त मापक की कठिनाई यह है कि वह शुद्ध व्यापार शर्तों में केवल निर्यात-मानाओं की गणना करता है। अतः इसे 'व्यापार से निर्यात-लाभ' (Export gain from trade) कहना ठीक होगा। किन्तु हमारी रुचि इससे कहीं अधिक गहरी है, जिस कारण 'शुद्ध' और 'कुल' व्यापार शर्तों का मिश्रण लेना अधिक उपयुक्त ज्ञेयता है। "इस मिश्रण को 'बाजार-गत व्यापार शर्तें' (Market Terms of Trade) कह सकते हैं और इसे किन्हीं दो अवधियों में निर्यात मूल्य और मात्रा तथा आयात मूल्य और मात्रा के मध्य

तुलना के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।^१ बीच रूप में इसे निम्न प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं —

$$T_t = \frac{p_x q_x}{p_m q_m} - \frac{p_{x_0} q_{x_0}}{p_{m_0} q_{m_0}}$$

व्यापार शर्त सम्बन्धी धारणा का व्यावहारिक महत्त्व

व्यापार शर्त सम्बन्धी धारणा का व्यावहारिक महत्त्व बहुत अधिक है। इसे निम्नांकित ढङ्ग में बताया जा सकता है —

(१) व्यापार के लाभ में से मिलने वाले हिस्से का निर्धारण—किसी देश को वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय से उदय होने वाले लाभ में से कितना हिस्सा प्राप्त होगा, इसका निर्धारण 'व्यापार-शर्त' द्वारा ही होना है। 'व्यापार शर्त' जिनकी अनुसूच ङगी देश को उनका ही अधिक लाभ मिलेगा। हमें यह स्मरण रहे कि व्यापार-शर्त कुल लाभ (Total gain) में केंद्रित देश के हिस्से की ही निर्धारित करती है, किन्तु 'कुल लाभ' स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होता है।

(२) लाभों के पुनर्रूप और रोजगार पर प्रभाव—व्यापार-शर्त देश में साधनों के रोजगार और उनके पुनर्रूप को भी प्रभावित करती है। जब व्यापार-शर्तों में सुधार होता है, तो निर्यात वस्तु उद्योगों में काम करने वाले साधनों के पुनर्रूप (मजदूर आदि) में वृद्धि हो जाती है। अन्य उद्योगों में भी वैसे ही साधनों के पुनर्रूप बढ़ जाते हैं। जहाँ जहाँ आय, रोजगार और मजदूरी कई अन्य उद्योगों में बढ़ जायेंगे। विपरीत क्रम से, जब व्यापार-शर्त बिगड़ती है, तो आय, रोजगार और मजदूरियों में गिरावट आ जाती है।

(३) आर्थिक विकास में सहायता—व्यापार-शर्त आर्थिक विकास में भी बाधक या सहायक हो सकती है। कहा जाता है कि अन्य बातों के साथ-साथ यदि व्यापार-शर्त भी लाभदायक हो, तो ग़रीब आर्थिक देश भी अधिक तेजी से विकास कर सकते हैं। कारण, अनुसूच व्यापार शर्त उन्हें अधिक मात्रा में आयात करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिससे प्रसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है और इसलिए तेजी से विकास होन लगता है। इसी आधार पर मोन्ट्रियल के कामनवेल्थ सम्मेलन तथा दिल्ली में आयोजित मुद्रा वोग की वापिस बैठक (१९५८) में प्रति-निधियों ने यह मत प्रकट किया था कि प्राथमिक वस्तुओं (Primary products) की विश्व-बीमारी में सुधार होना चाहिए।

(४) विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता—व्यापार-शर्त सम्बन्धी धारणा हमें उस मूल्य का ज्ञान कराती है जो आयातों के लिए चुकाये गये मूल्य की तुलना में, हमारे निर्यातों के मूल्य से प्राप्त होता है।^१ यह जानकारी हमें विनिमय की सापेक्षिक मात्राओं (Relative volumes of exchange) पर सापेक्षिक कीमतों (Relative prices) के प्रभाव को समझने में सहा-

^१ "Market Terms of Trade may be defined as the ratio of comparison between export volume and value to import volume and value in any two consecutive periods"—Kersi D Doodha, *Economic Relations in International Trade*, p. 44-48.

यता देती है। इससे हम अपनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति का और इसमें होने वाले सामयिक परिवर्तनों का अनुमान सुगमतापूर्वक लगा सकते हैं।

(५) विदेशी व्यापार से शुद्ध लाभ और हानि का अनुमान लगाने में सहायता—व्यापार-शर्तों से इस बात पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है कि एक देश की अपने विदेशी व्यापार से कितना शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि) हो रहा है। सामान्यतः हम देखते हैं कि व्यापार-शर्तों के प्रतिकूल रहने से कृषक देशों की हानि होती है।

व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली बात

दिल्ली दश के लिए व्यापार की शर्तें मरदा एक ही समान नहीं रहती हैं। वास्तव में वे समय-समय पर बदलती रहती हैं। शत प्रकार, जिस देश के लिए व्यापार की शर्तें बदलने अनुकूल थी, अब प्रतिकूल हो सकती हैं। व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली बातें निम्नलिखित हैं—

(१) माँग की लोच—अन्य बातें समान रहते हुए यदि देश के निर्यात-मान के लिए विदेशी माँग की लोच कम है, तो देश अनुकूल व्यापार शर्तें प्राप्त करने की स्थिति में होगा और यदि माँग अधिक है, तो व्यापार शर्तें अनुकूल न हो सकती हैं।

(२) स्थानापन्न की उपलब्धता—यदि अन्य देशों द्वारा उपलब्ध स्थानापन्न (Substitutes) निर्माण विधे जाते हैं, तो निर्यातक देश के लिए व्यापार की शर्तें कम अनुकूल (या प्रतिकूल) होगी। यदि स्थानापन्न नहीं है तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी।

(३) पूर्ति की लोच—यदि सम्यक् देश में आपूर्ति की लोच (Elasticity of supply) ऊँची है तो वह अपनी वस्तुओं की पूर्ति को विदेशी माँग में होने वाली घट-बढ़ के साथ सुगमतापूर्वक समायोजित कर लेगा जिससे व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी। विपरीत परिस्थिति में, व्यापार की शर्तें कम अनुकूल (या प्रतिकूल भी) हो सकती हैं।

(४) माँग का आकार—आयातक देश की माँग का आकार भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करता है। एक बड़ा आयातक देश (जैसे कि भारत या अमेरिका) की माँग प्रायः विशाल होती है। एक बड़ा आयातक देश के कारण, वह अपने लिए लाभप्रद रूप में मॉडे बानी कर सकता है, विशेषतः जबकि निर्यातक देश छोटा है। और अपने अनिश्चित उत्पादन के लिए अन्तराष्ट्रीय बाजार में दूसरा आयातक दुर्लभ में असमर्थ हो।

(५) विनिमय-दर—एक देश जानबूझकर व्यापार की शर्तों को, अपनी करिष्मी व बल्लु मूल्य का बड़ा कर, अपने पक्ष में कर सकता है।

(६) राजनैतिक शर्तें—व्यापार की शर्तें राजनैतिक दशाभा से भी प्रभावित होती हैं। यदि विदेशी व्यापार में आयातक देश आग में मिन राष्ट्र

है, तो व्यापार की शर्तें अनुकूल और सरल होगी और यदि विभिन्न राष्ट्र नहीं हैं तो शर्तें कड़ी हो सकती हैं ।

इस प्रकार, व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाले अनेक घटक हैं । ऐसे घटकों की उपयुक्त सूची पूर्ण नहीं है । उनमें कुछ अन्य घटक भी सम्मिलित किये जा सकते हैं ।

अनुकूल एवं प्रतिकूल व्यापार शर्तें

यदि कोई देश एक ही हुई निर्वाण-मात्रा के बदले पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में आयात करने में समर्थ हो जाय या उसे पहले जितनी आयात मात्रा के बदले में कम मात्रा में निर्वाण करना पड़े, तो कहेंगे कि व्यापार की शर्तें उसके 'अनुकूल' (Favourable) हो गई हैं । इसके विपरीत, जब कोई देश एक ही हुई निर्वाण मात्रा के विनिमय में पहले से कम मात्रा में आयात कर सकता हो या पहले जितनी मात्रा के आयात के बदले में उसे अधिक मात्रा में निर्यात करना पड़ता हो, तो कहेंगे कि व्यापार की शर्तें उस देश के 'प्रतिकूल' (Unfavourable) हो गई हैं । चूंकि एक देश का लाभ दूसरे देश की हानि होती है, इसलिये जो व्यापार शर्तें एक देश के 'अनुकूल' हैं वही दूसरे देश के 'प्रतिकूल' होती हैं ।

व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होने का महत्त्व

व्यापार की शर्तों में होने वाले परिवर्तन व्यापार के लाभों को तथा देश की उदय होने वाली वास्तविक आय को भी प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं । व्यापार-शर्तें जितनी अधिक अनुकूल होंगी, सम्बन्धित देश को लाभ में से उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा । जब व्यापार की शर्तों में सुधार होता है तो निर्यात-वस्तुओं के बिक्री के बड़े उद्योगों में लाभों का पुष्कार बढ़ जाता है और प्रायः व्यवस्था में घाव, रोजगार एवं मजदूरियों में सामान्य वृद्धि होती है । किन्तु कुछ दशाओं में, व्यापार-शर्तों में अनुकूल परिवर्तन होने पर भी लाभ न होना सम्भव है । उदाहरणतः प्राणिक मन्दों के युग में, कृषि वस्तुओं की कीमतें निम्न वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मिल जाती हैं, जिससे व्यापार-शर्तें निम्न वस्तुओं का निर्यात करने वाले देश के पक्ष में सुधार जाती हैं । निम्न मन्दों, व्यापारियों का सस्ता आयात निर्माणी देशों में जीवन-स्तर को उठाता है किन्तु कुछ देशों में लोगों की बड़ी हुई ऋण-शक्ति उनकी निर्माणी देशों से आयात करने की क्षमता को घटा देती है, जिससे इन देशों में भी प्रायः और रोजगार को ठेक पहुँचती है ।

इसी प्रकार, कुछ दशाओं में यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार की शर्तों में प्रतिभूत परिवर्तन होने का प्रभाव उस देश के लिए कुल पर लाभदायक ही हो । उदाहरणार्थ उत्पादन-सम्पत्तियों में सुधार होने से निर्यातों की कीमतें घट सकती हैं । यदि ऐसा हुआ, तो सम्बन्धित देश के लिए व्यापार शर्तें अधिक विपरीत जाती हैं । किन्तु कुछ पर यह किमति देश के लिए लाभदायक ही रहेगा, क्योंकि जागतिक में कमी और उत्पादन की वृद्धि के कारण लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है ।

स्पष्टतः अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समझने के लिए व्यापार शर्तों का ही नहीं, बरन् अन्य घटकों की भी जानकारी होनी चाहिए।

शुद्ध और कुल व्यापार शर्तों पर पुन विचार

‘शुद्ध’ और ‘कुल’ वस्तुगत व्यापार शर्तों में सम्बन्ध तथा इनकी गणना—

अग्रलिखित तालिका से यह पता चलता है कि शुद्ध और कुल वस्तुगत शर्तों में क्या सम्बन्ध है तथा इनकी गणना करने का दृष्टि क्या है।

व्यापारिक मासिकी में दर्ज किए गए वास्तविक मूल्य (उदाहरणार्थ) आयात के लिए सन् १८९० में ३५६ मिलियन पीट या किन्सु वालम A यह दिखाता है कि आयात वर्ष १९०० की तुलना में आयात-कीमते ७% ऊंची थी। तदनुसार इन ३५६ के अपरिष्कृत या कच्चे अंक (Crude figure) को १.०७ से भाग देते हैं, जिससे भागफल ३३३ (वालम F) आता है। तालिका के अन्य अंक तो स्वतः स्पष्ट हैं।

इंग्लैण्ड की ‘शुद्ध’ और ‘कुल’ व्यापार-शर्तें

	Index of		Net Terms of Trade A/B	Value in £ Millions		Value after correcting for Price changes		Corrected Values ex- pressed as Relatives (1900=100)		Gross Terms of Trade ($\frac{I}{H}$)
	Im- port prices	Ex- port prices		Im- ports	Ex ports	Im- ports D	Ex- ports E	Im- ports	Ex- ports	
	1900	100				A	B			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1890	107	95	1.13	356	263	333	278	72.4	98.6	1.36
1900	100	100	1.00	460	291	460	291	100	100	1.00
1910	110	98	1.12	575	430	525	438	114.1	150.3	1.32

१८९० में १९०० की अवधि में ‘शुद्ध’ (Net) व्यापार शर्तों में सुधार हुआ है, क्योंकि आयात-कीमते निर्यात-कीमतों की तुलना में गिर गई हैं। १९०० से १९१० की अवधि में यदि विपरीत दिशा में हुई है। शुद्ध व्यापार शर्तों की अपेक्षा ‘कुल’ व्यापार शर्तें, पिछड़ी अवधि में अधिक सुधार दर्शाती हैं। इसका कारण है आयात-आधिक्य में वृद्धि होता, जो स्वयं इस कारण है कि यू.के. का निर्यात १८९०

की अपेक्षा १६०० में कम था। १६१० में पुँजी का निर्यात कहीं अधिक था जिससे आयातों का आधिपत्य अपेक्षात छोटा था तथा कुल व्यापार शर्तों अधिक 'प्रतिकूल' थी। [इंग्लैंड ने बताया है कि व्यवहार में सही चित्र पाने के लिये एक सम्बन्धी प्रवृत्ति के आंकड़ों का अध्ययन करना चाहिये।]

‘शुद्ध व्यापार शर्तों’ की अपेक्षा ‘कुल व्यापार शर्तों’ की श्रेष्ठता—

टॉजिंग ने सुझाव दिया था कि जब हम किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाले लाभ की गणना करना चाहते हैं, तो हमें ‘कुल व्यापार शर्तों’ की धारणा का प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् हमें एक देश जो वस्तुमें भेजता है उनके कुल (समायोजित) मूल्य की तुलना उसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के कुल (समायोजित) मूल्य से करनी चाहिये। शुद्ध व्यापार शर्तों की तुलना में कुल व्यापार शर्तों की श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें इकांतरका भुगतानों की भी सम्मिलित किया जाता है। परिक्रामत शुद्ध व्यापार शर्तें, किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ का सही अनुमान प्रदान करने में असमर्थ रहती हैं। प्रो० टॉजिंग के शब्दों में—“जब किसी देश को निर्यात-आधिक्य है (बोझिये वह दूसरे देश को ऋण दे रहा है या अपने पुराने ऋणों को चुका रहा है या व्याज सम्बन्धी व्ययों का भुगतान कर रहा है), तो ‘शुद्ध व्यापार शर्तों’ में उसके केवल ऐसे निर्यात ही सम्मिलित होते हैं जोकि उसके धान्य आयातों का भुगतान करें, और इसलिये उसकी स्थिति की प्रादक्ष्यकता से वही अधिक अनुकूल प्रगट करती है। विपरीत क्रम से, जब किसी देश को आयात-आधिक्य है, तो शुद्ध व्यापार शर्तें उसकी स्थिति को उचित से वही अधिक प्रतिबुद्ध दिखाती हैं।”¹

एक सांख्यिकीय धारणा के रूप में ‘कुल व्यापार शर्तों’ की सीमायें—

हैबरलर ने बताया है कि कुल व्यापार शर्तों की व्याख्या करने में वही ही सावधानी से काम लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें स्मरणीय बताई गई हैं —

(१) विभिन्न कारणों की एक ही श्रेणी में सम्मिलित करना अनुचित है— यद्यपि वास्तविक आयात और निर्यात मूल्यों का विद्वान बनाना बहुत रोचक और उपयोगी है तथापि आयातों या निर्यातों के आधिक्य का कारण जानना भी बहुत

¹ “When a country has an export surplus (for she may be granting a loan or repaying her old loans or making payments on account of interest charges to another country), the ‘net terms of trade’ cover only her those exports which pay for her current imports and hence give too favourable a picture of her position. Conversely, when a country has an import surplus, the ‘net terms of trade’ give the unfavourable a picture.”

जबूरी है। जैसे—यह बान जानना महत्वपूर्ण है कि नियति आधिक्य सति पूर्ति के कारण उत्पन्न हुआ है (जैसा कि जर्मनी की दशा में १९३० से १९३१ तक था) अथवा विदेशों को ऋण देने से हुआ (जैसा कि अमेरिका के साथ युद्धोत्तर अवधि में था) अथवा विदेशी ऋणों पर व्याज देने और ऋणों की अदायगी के कारण हुआ (जैसा कि १९३२ में जर्मनी के साथ था)। अन्य शब्दों में विभिन्न प्रकार के भुगतानों को एक ही धोखे में सम्मिलित करना ठीक नहीं है।

(२) विचाराधीन अवधि इतनी बड़ी होनी चाहिये कि उसमें विदेशी ऋणों से सम्बन्धित सभी भुगतान एवं वापसियाँ सम्मिलित हो जायें। कभी-कभी एक शोधकम ऋणों को मात्र की स्वीकृति से उदय होन बाल नियति आधिक्य और व्याज अथवा भट (Tribute) के इन से उदय होन बान नियति आधिक्य के मध्य तुलना की जाती है और ऐसी तुलना के आधार पर यह निष्कर्ष निरास लिया जाता है कि पहला नियति आधिक्य उतना ही प्रतिबुद्ध तत्त्व है जितना कि बाप का नियति आधिक्य, किन्तु ऐसा निष्कर्ष गलत है। इस भुटि से यत्न का उपाय यह है कि अवधि इतनी लम्बी रखी जाय कि उसमें ऋण की स्वीकृति और इसकी वापसी दोनों हो आ जाय।^१ किन्तु जैसा कि हेबरलर ने बताया है, यदि पूँजी का नियति देमी अवधि के ताबाध में जारी रहे तो यह उपाय (बीच अवधि देने का) भी असफल हो जायेगा।

(३) इकतर्फा व्याज सम्बन्धी भुगतान संतुलित करने चाहिये। यदि हम किसी प्रकार से इतनी लम्बी अवधि चुनने में सफल भी हो जायें, जिसमें कि उस अवधि के भीतर दिये गये समस्त विदेशी ऋणों के भुगतान एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित रहे और कोई अन्य पूँजी प्रवाह (Capital flow) न भी हो तो भी व्यापार शर्तें वही धिन प्रस्तुत करने में असफल रहती हैं, क्योंकि खनदार देश को पूरी अवधि पर्यन्त आबात-आधिक्य रहता है जिससे हम यह निष्कर्ष निरास करते हैं कि तनदार देश में इकतर्फा लाभ उठाया है। किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो पूँजी उसने उधार दी थी वह स्वदेश में उनिन रूप से प्रयोग में नहीं आ रही थी। यही कारण है कि प्रो० वाइनर (Viner) ने कहा है कि— उस मूल्यों का अनुमान लगावे समय जो कि एक देश देता है और प्राप्त करता है, उस पूँजी की सेवाओं के लिये, जोकि वह निर्यात करता है, प्राप्त होने वाले व्याज के भुगतान को संतुलित करने हेतु विपरीत पक्ष में कुछ न कुछ सम्मिलित किया जाना चाहिए।^२

1 "It is true that one could try to correct this by taking a period of time long enough to include the repayment of such credits, as well as the granting of them"—*Haaberler Theory of international Trade*, p 164

2 (Footnote see on next page)

वाशर ने यह भी बताया कि 'सेवासो' (जैसे—जहाजी सेवासो) और 'पूँजी की सेवासो' में अधिक तीव्र भेद करना सतर्जनाक है, क्योंकि पहली मद में पूँजी पर कुछ व्याज मंदा ही सम्मिलित होता है। उदाहरणार्थ, एक अमेरिकन तेल कम्पनी एक सेलवाहक जहाजों के ब्रिटिश वेडे का, जिसके निर्माण में १०,००,००० पाँड व्यय हुए हैं प्रयोग करती है और इस जहाजों सेवा के लिये वह २,००,००० पाँड बापित देती है, जिसमें से १०,००० पाँड जहाजों में विनियोजित ब्रिटिश पूँजी पर व्यय है, ५०,००० पाँड जहाजों के ह्रास की पूर्ति के लिये भुगतान है (जो कि जहाजों के वार्षिक निर्यात के बराबर है) और १,००,००० पाँड विपुल जहाजी सेवासो के लिये है। मान लीजिये कि एक अन्य मामले में, तेलवाहकों का एक ब्रिटिश जहाजों वेडा अमेरिकी कम्पनी को १०,००,००० पाँड में बेचा जाता है, जिसका भुगतान २० वर्षों में १% व्याज दर सहित होता है। मान लीजिये कि इस वेडे के संचालन का भार एक ब्रिटिश जहाजी कम्पनी को सौंपा जाता है, जो अपनी सेवासो के लिये १,००,००० पाँड लेती है। पहले की भाँति अब भी इङ्ग्लैंड के निर्यातों में २,००,००० पाँड वार्षिक है, जिसमें १०,००० पाँड तो जहाजों के निर्यात, ५०,००० पाँड ब्रिटिश पूँजी के प्रयोग के लिये व्यय और १,००,००० पाँड जहाजी सेवासो के भुगतान के लिये है। यद्यपि इन दोनों वशामों में कोई मौलिक भेद नहीं है, तथापि टॉजिंग पहली दशा में, जहाजी सेवा के निर्यात मीपंक के अन्तर्गत १०-१५ हजार पाँड की दोनों मदें सम्मिलित करेंगे, किन्तु दूसरी दशा में, उनके अनुसार, पहली मद जहाजों के निर्यात के रूप में दिखाई जायेगी और दूसरी मद बिल्कुल ही नहीं दिखाई जायेगी।^१

(४) कुल व्यापार शर्तों से केवल प्रतिकूल या अनुकूल परिवर्तनों की जानकारी मिलती है—हैबरर ने बताया है कि इस प्रकार के चिह्नों को (अर्थात् कुल व्यापार शर्तों को), जो किसी देश के आयातों और निर्यातों के वास्तविक मूल्यों (Real values) की तुलना से बनाया जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश को उन्नत होत बाने निरुपेक्ष लाभ (या हानि) के मापक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में लाभ की गणना करने में व्यापार-शर्तों की जो भूमिका (Part) थी, वह मूलतः भिन्न थी। इस धारणा का प्रयोग यह दिखाने हेतु किया गया था कि कुल लाभ (अर्थात् उत्पादन में वृद्धि) दो देशों के मध्य कैसे वितरित होता है। लाभ का अधिकांश भाग उस देश या इस देश को व्यापार-शर्तों इनकी दो सम्भव

"In evaluating the values which a particular country parts with and receives, something must be included for the services of the capital it exports as contra to the interest payment she receives"—Viner

^१ Quoted from Haberler's theory of International Trade, p. 165.

सीमाओं में एक या दूसरी के निकट होने के अनुसार मिलेगा। कुल व्यापार शर्तों से यह पता लगाना कि एक देश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन से कितना निरपेक्ष लाभ प्राप्त करेगा असम्भव है। हम उनसे भाग सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हुये अनुकूल या प्रतिकूल परिवर्तनों का ही पता लगा सकते हैं। शायद एक पक्षीय भुगतानों से उदय होने वाले द्वितीयस्तरमय भार का भी पता लगा सकें। किन्तु इस सम्बन्ध में कटिनाई यह है कि मास्थिकी श्रान्तियों की विभिन्न व्याख्याओं की जा सकती है। कारण, तकनीकी प्रगति आदि से आंकड़ों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं।

(५) किसी देश को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ (या हानि) होता है उसके मापक के रूप में कुल व्यापार शर्तों का प्रयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिये। उदाहरणार्थ, क्षति पूर्ति सम्पन्धी भुगतानों (Reparation payments) को हानि नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 'फल' नहीं कहा जा सकता।

(६) जैसा कि प्रो० टाजिंग ने स्वयं भी स्वीकार किया है, जब व्यापार शर्तें विदेशी वस्तुओं के लिये किसी देश की माँग में वृद्धि होने के कारण उससे विवक्षित हो जाती हैं, तो हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उस देश को हानि है। कारण, अधिक माँग करना एक स्वेच्छिक कार्य (Voluntary act) है। यदि कोई व्यक्ति जी वस्तुय पहनें खरीदता आया था उनसे भिन्न और अधिक कीमती पर खरीदता है, तो स्पष्टतः वह ऐसा इस कारण करता है कि उसे अपनी आदतें बदलने में लाभ प्रतीत होता है।

(७) सांख्यिकीय आंकड़े ग्राम के वितरण में होने वाले परिवर्तनों की पूर्ण उपेक्षा कर देते हैं। जैसा कि प्रो० हेबरलर ने बताया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और देश की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति से उदय होने वाले लाभ के बारे में किये गये उपरोक्त विवेचन यह भुला देते हैं कि वृद्धि या संकुचन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने, विघ्न पड़ने, रुकने या तीव्र होने के कारण वितरण और लाभ या हानि में भी परिवर्तन हो सकते हैं। चूंकि ये विवेचन ऐसे महत्वपूर्ण घटकों को भुला देते हैं, इसलिये वे अयार्थता से दूर होते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१ 'व्यापार शर्तों' से आप क्या समझते हैं ? किसी देश की व्यापार-शर्तों को प्रभावित करने वाले घटकों की पूर्ण रूप में व्याख्या कीजिये।

[What do you understand by 'Terms of Trade' ? Discuss fully the factors governing the terms of trade of any country.]

- २ टॉजिग ने शुद्ध और कुल व्यापार शर्तों की जो धारणा प्रस्तुत की है उसका विवेचन कीजिये और कुल व्यापार शर्तों के महत्त्व को समझाइये ।

[Discuss Taussig's concept of Net and Gross Terms of Trade and estimate the significance of the latter]

- ३ व्यापार शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाइये । व्यापार शर्तों पर तुल्यताओं के प्रभावों का विवेचन भी कीजिये ।

[Explain clearly the different concepts of Terms of Trade Also analyse the effects of the parties on terms of trade]

- ४ वस्तुगत और आयगत व्यापार शर्तों से क्या क्या समझते हैं ? इन धारणाओं के व्यावहारिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये ।

[Explain fully what do you understand by 'Commodity Terms of Trade' and 'Income Terms of Trade' What is the practical significance of these concepts ?]

- ५ व्यापार-शर्तों की विभिन्न धारणाओं की परिभाषा कीजिये । किस सीमा तक यह व्यापार से होने वाले लाभ का माप है ?

(इनाह०, एम० कॉम०, १९६९)

[Define various concepts of terms of trade used in the international trade theory How far are they indicative of gains from trade ?]

उत्पत्ति के विशिष्ट साधन सवम् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (Specific Factors of Production and International Trade)

परिचय—

तुलनात्मक लागत सिद्धान्त यह मानकर चला था कि देश के भीतर उत्पत्ति के सभी साधन पूर्णतः गतिशील हैं और ऐसी दशा में, कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप जो समायोजन (Adjustment) आवश्यक हों उन्हें देश कुछ हानि उठाये बिना ही सम्पन्न कर सकता है। अतः अब हमें यह देखना है कि यदि गतिरहित एवं विशिष्ट साधनों की उपस्थिति को विचार में लिया जाय, तो इससे तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के निष्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

गति-रहित एवं विशिष्ट साधनों की उपस्थिति

एक पूर्वे विश्लेषण में हम यह देख चुके हैं कि वस्तुओं के विनिमय अनुपात, स्थिर लागतों (Constant costs) के अन्तर्गत, प्रतिस्थापन अनुपात (Substitution ratio) के बराबर होते हैं तथा माँग केवल उत्पत्ति की विभिन्न शाखाओं के मध्य उपलब्ध साधनों के वितरण की, और इसके द्वारा, वस्तुओं की उत्पन्न की जाने वाली सापेक्षिक मात्राओं को ही प्रभावित करती है। किन्तु वकती हुई लागतों के प्राचीन (स्मरण रहे कि घटी हुई लागतें प्रगल्भदभूत हैं) माँग विनिमय-अनुपात को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि सापेक्षिक लागतें (= प्रतिस्थापन अनुपात) वस्तुओं के लिये सापेक्षिक माँग (Relative demand) के साथ ही साथ परिवर्तित होती हैं। वस्तुओं के एक दिये हुए संयोग की दशा में, जिनके लिये माँग की जाती है, इनके मध्य विनिमय-अनुपात उस संयोग वाले बिन्दु पर इनके प्रतिस्थापन अनुपात के बराबर होगा। अर्थात् जिस अनुपात पर वस्तुय बाजार में परस्पर विनिमय की जायेगी वह इनकी सीमान्त लागतों (Marginal costs) के बराबर होगा। यदि अनुपात इससे भिन्न है, तो यह एक असाधारण्य (Disequilibrium) होगी, जिसमें एक वस्तु को अधिक और दूसरी वस्तु को कम मात्रा में उत्पन्न करने के लिये प्रेरणा उत्पन्न होकर समायोजन की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी।

चाहे एक समान साधन श्रम (Homogeneous factor labour) हो या विभिन्न साधन, दोनों ही दशाओं में वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतें (जबकि माँग

सम्बन्धी दशाथ दी हुई है) सीमान्त लागतों द्वारा (अथवा प्रतिस्थापन अनुपात द्वारा) निर्धारित होती है। 'सीमान्त लागत' विरामी वस्तु की वह मात्रा है, जिसे एक अन्त्य दी हुई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने हेतु त्यागना पड़ता है। विभिन्न साधन जिस अनुपात में मिलाने जायेंगे वह उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं की सापेक्षिक मात्राओं के साथ बदलते रहेंगे। यदि III वस्तु की अधिक और A वस्तु की कम मात्रा उत्पन्न की जानी है तो उन उत्पत्ति साधनों का, जिन्हें केवल III के ही उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है अथवा जो B के उत्पादन के लिये A के उत्पादन की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है अधिक प्रयोग किया जायेगा। यदि कोई साधन एक दस्तके के उत्पादन के लिए पूर्णरूप से विशिष्ट है, तो इसका तब राश कुछ भी मूल्य न होगा जब तक कि उस वस्तु की उत्पादित-मात्रा इसकी समस्त उपलब्ध इकाइयों को काम देने हेतु पर्याप्त न हो।

उपलब्ध साधनों का, जिन्हें एव या अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है, अनुपात जितना बड़ा होगा, प्रतिस्थापन वक्र जितना ही चपटा (Flat) होगा तथा इनके उत्पादन-संयोग में किसी परिवर्तन से सम्बद्ध वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन भी उतना ही अल्प होगा। यदि प्रघटिका साधन किसी एक वस्तु के लिये विशिष्ट हैं, तो वक्र में फुलाहट (Bulge) अधिक होगी तथा यदि माँग में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में कोई घटा बढी होता है III सापेक्षिक कीमतों में बड़ा परिवर्तन हो जायेगा। प्राँय और औद्योगिक वस्तुओं के मध्य 'अन' एक सामान्य साधन है, जिसकी गतिशीलता अल्पकाल में बहुत हो खोड़ी होती है। अतः प्रतिस्थापन वक्र में एक खींच माड़ (Kink) होता है, जो यह सूचित करता है कि यदि औद्योगिक वस्तु का उत्पादन बहुत घटा दिया जाय, तो भी कृषि वस्तु का उत्पादन अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। कारण, उपलब्ध साधनों का एक मामूली भाग ही उत्पत्ति की एक शाखा से दूसरी शाखा को ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि यह ट्रांसफर धिक्कुल भी सम्भव नहीं है, तो प्रतिस्थापन वक्र L-shaped होगा। यही कारण है कि जब माँग में परिवर्तन होता है, तो सापेक्षिक कीमतों में अन्त्य दशाओं की अपेक्षा अधिक परिवर्तन हो जाते हैं। अन्त्य शब्दा में, उत्पत्ति-प्रणाली अपने आपकी नई माँग परिस्थिति के अनुसार समायोजन नहीं करके पाती है।

हैबरसर ने यह बताया है कि प्रतिस्थापन वक्र का आकार पुरानी स्थिति और नई स्थिति में अल्प अन्तीत होत वाली समयावधि की लम्बाई के अनुसार परिवर्तित होता है। दीर्घकाल में वक्र अधिक चपटा (Flatter) होता है, क्योंकि इस अवधि में साज-सामान प्राप्त जाते हैं अथवा अश्वचित्त हो जात है तथा अन्त्य को नये कार्य के लिये दीक्षित किया जा सकता है, किन्तु अल्पकाल में अश्विकाश साधन (जैसे कि साज-सामान, प्लान्ट यहाँ तक कि अन्त्य भी) विशिष्ट होते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि अल्पकाल में भी उत्पत्ति-साधन कुछ सीमा तक गतिशील और अश्विशिष्ट ही होते हैं। जैसे, प्लान्ट में नगी हुई पूँजी इसके धितने पर, यदि पहले से ही ह्रास पर

खोचा गया था, 'मुक्त' (Free) हो जाती है और यह आवश्यक नहीं है कि इसे पहले वाले प्रयोग में ही लगाया जाय, उसे अन्य प्रयोगों में भी सँभाल कर सकते हैं। इन दीर्घनाल में मध्यनाल की प्रवेष्टा बर अधिक चपटा होता है।

इसका अर्थ है कि यदि माँग में परिवर्तन होना है, तो प्रारम्भ में सापेक्षिक कीमतों में विशेष परिवर्तन होना स्वाभाविक है। कारण, जिस उद्योग में माँग मुझी है उसका उत्पादन एक दम ही नहीं बढ़ेगा, बरन् उद्योग को अनुपूततम क्षमता प्राप्त करने में समय लग जायेगा, क्योंकि प्रतिरिक्त धमिकों को नवीन कार्य के लिये प्रशिक्षित होने में समय लगना है। दूसरी ओर, जिस उद्योग से माँग कम हुई है वहाँ उत्पादन एक दम ही कम नहीं हो जायेगा, क्योंकि उत्पत्ति के अनेक साधन या तो पूर्णतः निशिष्ट होते हैं या गम्भीर हानि सहकर ही अन्य प्रायोगों में जा सकते हैं। मन् जब तक प्राथमिक लागों (Prime Costs) वसूल होती रहें, उत्पादन में उनका प्रयोग जारी रहेगा। हाँ, उनके मूल्य को अपनिग्न (Write off) कर दिया जायेगा। चूँकि माँग की अपेक्षा उत्पत्ति अधिक रहेगी (बचाव भण्ड भई है), इसलिए उत्पाद के मूल्य में भारी गिरावट घा जायेगी। कुछ समय व्यतीत होने पर ही तदुचित होने वाले उद्योग में उत्पादन कम हो सकेगा, क्योंकि तब तक मशीनें चित्त चुकी होगी और उन्हें प्रनिरवापित नहीं किया जायगा। इस प्रकार, सापेक्षिक वस्तुओं की कीमतों में अन्तर बाद की उनका नहीं रहेगा जितना कि प्रारम्भ में था।

एक मीट्रिक अर्थ व्यवस्था में प्रतिस्थापन-अनुपात श्रवस न होकर अप्राप्य होते हैं, क्योंकि मुद्रा मध्यस्थ का काम करती है। मन् 'वायते' वास्तव में 'मीट्रिक लागते' ही होती है। प्रत्येक उत्पाद की कीमत दूसरी सीमान्त मीट्रिक लागत के बराबर होती है, और सीमान्त मीट्रिक लागत किसी वस्तु की एक अनिरिक्त इकाई उत्पन्न करने में प्रयोग किये जाने वाली सभी अनिरिक्त साधनों की कीमतों का योग होती है। यदि जीवन एवं स्थानापन्न साधनों की एक इकाई की कीमत सभी प्रयोगों में समान होती है तथा अनिरिक्त और निशिष्ट साधनों की एक इकाई की कीमत इसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होती है।

उपरिक्त परिस्थितियाँ प्रतियोगिता द्वारा सम्भन बनाई जाती हैं। अधिक और भूस्वामियों तथा सामान्य उत्पत्ति के सभी साधन अपनी अपनी सेवाओं के लिये अधिकतम पुरष्कार पाना चाहते हैं। साह्यी, जो इनकी सेवाओं को किराये पर लेने हैं, इन्हे इस प्रकार से मज्जठिन करन और प्रयोग में लाते हैं कि उनकी अपनी आमदनी अधिकतम हो जाय। इस प्रतियोगिता के कारण यदि किसी कारखाने में एक साधन की सीमान्त उत्पादकता उसकी सामान्य सीमान्त उत्पादकता (= साधन-कीमत) से कम है, तो साह्यी उस साधन की कुछ इकाइयाँ तो हटाकर प्राप्ति की प्रवेष्टा अपनी लाभते अधिक घटा सकेगा। य इकाइयाँ अन्य सखानों या प्रयोगों में, जिनमें उनकी सीमान्त उत्पादकता अधिक है, भरी जायेगी। यदि किसी उद्योग में

साधन विशेष की सीमान्त उत्पादकता उतकी मापान्य सीमान्त उत्पादकता (=कीमत) में अधिक है, तो सम्बद्ध साहसो उस साधन की अधिक इकाइयाँ फिराये पर लेगा, क्योंकि ऐसा करके वह व्ययों की प्रवेक्षा अपनी प्राप्तियाँ अधिक बढ़ा लेगा। इस प्रकार, प्रतिप्रोशिता के प्रभावस्वरूप, सीमान्त-उत्पादकता और कीमत उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा में समान हो जाती है।

“राष्ट्रीय आय के आकार में नहीं, किन्तु इसके वितरण में परिवर्तन होते हैं”

प्रायः तर्क किया जाता है कि जब गतिरहित और विशिष्ट साधन विद्यमान होते हैं तब प्रत्येक समायोजन, भले ही यह तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त द्वारा संकेत की गई दिशा में हो, भारी हानि उठा कर ही सम्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब किसी आयात-कर को हटाया जाता है, तो उत्पत्ति में हेर फेर करना प्रावश्यक हो जाता है। ऐसा करने में उत्पत्ति के उन साधनों (जैसे-भूमि, भवन, मशीनरी, मध्य उत्पाद आदि) का, जो कि सरलण से वंचित किए गये उद्योग में काम आते रहे हैं और जिन्हें अन्य प्रयोगों में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, मूल्य कम हो जायेगा तथा इन विशिष्ट साधनों के स्वामियों को अपनी प्राय में कटौती सहनी पड़ेगी।

उपरोक्त तर्क कन्टम यूनिशन बनाने प्रपचा टैरिफ के हटाने या घटाने के प्रत्येक प्रस्ताव के विरुद्ध दिया जाता था। उदाहरणार्थ, कहा जाता था कि आस्ट्रिया व जर्मनी के मध्य कन्टम यूनिशन बनाने से उत्पत्ति की सभी शाखाओं में भारी समायोजन करने पड़ेंगे, जिनमें पूँजी का इतना भारी विनाश होगा कि यह पूछा जा सकता है कि क्या उत्पत्ति में एक सम्भावित किन्तु दूरस्थ (Probable but remote) वृद्धि बहुत महँगी नहीं खरीदी गई है? वर्तमान पीढ़ी उन लोगों से, जो कि समायोजन सम्पन्न होने पर ही उदय होते हैं कैसे लाभान्वित होगी? जैसा कि क्रोस ने एक बार कहा था, “दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।”

किन्तु इस तर्क में, जो विविध रूपों में सदा प्रस्तुत किया जाता रहा है, एक गम्भीर त्रुटि है—“पूँजी की हानि” का अर्थ “राष्ट्रीय आय में हानि” होता नहीं है। इससे तो केवल “राष्ट्रीय आय के वितरण” में ही परिवर्तन होता है। समायोजन के मधुपों के फलस्वरूप जो हानि वास्तव में होती है और जिसे मलती से पूँजी की हानि समझ लिया जाता है वह ‘पूँजी की हानि’ की प्रवेक्षा कहीं कम है। इसे प्रमाणित करने के लिए हेंबरलर ने एक गणितीय उदाहरण प्रयोग किया है जिसे हम नीचे प्रस्तुत करते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

मान लीजिए कि देश में लीह-स्मिज के भण्डार हैं, जिस पर एक लोह-स्पात उद्योग पाधारित है। मान लीजिए कि उद्योग को विदेशों से बढ़ी हुई प्रतिप्रोशिता

का सामना करना पड़ता है जिस कारण जोह एव स्यात की कीमतें गिरने लगती हैं और अन्य में कुछ या सब कारखाने बन्द होने के लिए विवश हो जाते हैं। विदेशी बाह्य एव स्यात की कीमतों में गिरावट किसी भी निम्न कारण से हो सकती है—

(i) सम्बद्ध देश में घपना आयात घटा दिये हो, या (ii) पातायात व्ययों में कमी आ गई हो, या (iii) विदेशी उद्योग को उसकी सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी हो, अथवा (iv) उसने अपनी उत्पादन तकनीक में कोई ऐसी सुधार कर लिए हों जिनका ज्ञान गृह उद्योग को नहीं है, अथवा (v) मौद्रिक-व्यवस्था (Monetary mechanism) की कार्यक्षमता से प्रभावस्वरूप भी विदेशी मागतों में सामान्य रूप से कमी (General reduction) आ सकती है (ऐसा तब हो सकता है जबकि विदेशी देश एक-पक्षीय मुद्रादान कर रहा हो)। विदेशी लागतों में घटौती का कारण कुछ भी रहा हो, हम सुगमता की दृष्टि से यह मान लेते हैं कि कीमतों में जो गिरावट आई है वह स्थायी (Permanent) है। गृह बाह्य एव स्यात उद्योग में एक सत्यान की प्राप्ति का और व्यय निम्न प्रकार हो सकते हैं —

प्राप्तियाँ (Receipts)

उत्पादों के विक्रय से कुल प्राप्ति (Gross Receipts) १००

व्यय (Expenditure)—

(१) बाह्य व्यय—मजदूरियों व घेतनी, सामग्रियों आदि

तथा इस सब पूँजी पर व्याज १०

(२) स्थिर पूँजी सम्बन्धी व्यय—भवन, मशीनरी आदि

में विनियोजित स्थिर पूँजी पर व्याज और ह्रास २०

(३) विशिष्ट साधन सम्बन्धी व्यय—संस्था के लोह

खनिज के भण्डारों वाली भूमि का लगान ३० १००

उपरोक्त उदाहरण में बाह्य व्यय (Current expenses) उत्पात के तत्कालीन और विशिष्ट साधनों के लिए व्ययमान है, जो किसी भी क्षण अन्यत्र अथवा अन्य प्रयोगों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर स्थिर पूँजी की लागतों (Costs of fixed capital) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यय उद्योग के लिए “विशिष्ट” हैं। प्रायः अपेक्षित एक सन्वत्सरी अवधि के बाद ही पूँजी, जबकि वह बिक जाय और बेची जाय, “मुक्त” (Free) हो सकती है। इसी मर की मर्यादा में ‘प्राभास-लगान’ (Quasi rent) कहा है। तीसरी ओर स्थिर पूँजी के विशिष्ट साधनों का प्रायः का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें ही हम यहाँ के ‘विशुद्ध संसाधन’ अर्थ में लगान कह सकते हैं।

[किन्तु स्मरण रहे कि व्यय की विशेष मर्यादा का उपरोक्त तीन श्रेणियों में वितरण बदल भी सकता है। उदाहरणार्थ, यदि सम्बद्ध संस्था अपने लिए लोह खनिज किसी अन्य मर्यादा से खरीदती है, तो इसके मूल्य को गहली थोड़ी से दिखाया जायगा और ऐसी दशा में खनिज भण्डार का लगान तीसरी श्रेणी में सम्मिलित न

होगा । किन्तु यह एक ऐसा ही अन्य परिवर्तन भी, जो समस्या हमारे सामने उपस्थित है उस पर प्रभाव नहीं डालते है ।]

अब मान लीजिए कि लोह एवं स्पात की कीमत गिरती है तथा प्राप्तिशो में ३० की कमी हो जाती है । नि सन्देह यह हमारे साहसी के लिए एक भारी हानि है, किन्तु इसके कारण वह अपने उत्पादन में तनिक भी कमी नहीं दियेगा । हाँ उसे अपने विनिष्ट साधनों के मूल्य की विवशता अपलिप्तिन (Write off) कर देना पड़ेगा, तथा समस्त लगान समाप्त हो जायेगी । किन्तु जब तक वन और मत्तल पूँजी पर ब्याज अर्जित होता रहे तब तक वह उत्पादन की जारी रखेगा । स्पष्टतः लोह एवं स्पात उत्पादकों ने यहाँ जो हानि उठाई है उसकी क्षतिपूर्ति उपभोक्ताओं के मूल्य में कमी के कलस्वरूप हुए इतन ही लाभ द्वारा हो जाती है । यहाँ राष्ट्रीय आय में कमी नहीं हुई है, बल्कि उत्पत्ति की मात्रा ब्यावहार्य रहती है ।¹

मान लीजिए कि कुछ समय बाद लोहे व स्पात की कीमत अपिब गिर जाती है, जिससे प्राप्तिशो में १० या १५ की प्रतिशत घटोती होती है । इससे उत्पादन की हानि बढ जाती है, किन्तु जब तक वन पूँजी, जिसकी आवश्यकता प्रथम श्रेणी के बाग्न व्यवसाय के भुगतान के लिए पड़ती है पुनरुत्पादित (Reproduce) होती रहे तब तक उत्पादन भी जारी रहेगा । इस बार विनिष्ट साधनों (स्विर पूँजी) के मूल्य की टूट-फूट (Scrap value) तक अपलिप्तिन कर दिया जायेगा । यदि ऐसे साधन पूर्णतः विनिष्ट नहीं ह किन्तु अन्यत्र प्रयोग किया जा सकते हैं, तो उनके मूल्य का उस प्रयोग मूल्य तक अपलिप्तिन किया जायेगा । यह एक 'पूँजी हानि' (Capital loss) है, और इसे भी सहन कर लिया जायेगा । कारण, उपक्रमी यह तो पसन्द करेगा कि इस हानि की हिमाय की पुनर्बा में दियाये तथा उत्पादन जारी रखे किन्तु वह उपक्रम की छोड़ना और इस प्रकार सब कुछ खो देना पसन्द नहीं करेगा । पसल आभाव नमान भी सुप्त हो जाता है । किन्तु प्रथम श्रेणी की लागतों में कोई कमी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें अवशिष्ट साधनों के लिए भुगतान

1 "If the consumers live outside the territory of the national or other community under consideration, this community may of course suffer a loss. But there will be no loss from a cosmopolitan standpoint. This does not mean, however, that Free Trade is to be advocated in such a case, only from an altruistic cosmopolitan standpoint. For, if the industry of one country is displaced by the industry of another from some third market, the country which is injured is powerless to alter the situation by imposing or increasing import duties."

सम्मिलित हैं। यदि उन्हें इनकी पूर्ण बाजार कीमत न चुवाई गई, तो ये सत्ता को छोड़ कर अन्य प्रयोगों में चले जायेंगे।

अब तक हमने विशेष व्यक्तियों के लिए हानि पर विचार किया है, सम्पूर्ण समाज (Community as a whole) की दृष्टि से नहीं, क्योंकि सोहे व स्वात के उपभोक्ताओं को ठीक उतना ही लाभ होता है जितना कि उत्पादकों को खोना पड़ता है। अब एक बंदम आगे बढ़ते हैं—मान लीजिए कि सोहे एव स्वात की कीमते और अधिक गिर जाती हैं अथवा स्थिर पूँजी का एक भाग इतना घिस गया है कि यदि सत्ता को चानू रखना है तो उसे तुरन्त ही बदल देना चाहिए। अब (अंत में) सत्ता बन्द होने के लिए विवश है, क्योंकि वह अपने अविच्छिन्न साधन को बाजार कीमत का भुक्तान नहीं कर सकती है। चूंकि वे अन्य प्रयोगों में इतना पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं कि उन्हें अपनी बाजार कीमते मिल जायें, इसलिए सत्ता के बन्द होने से समाज को कोई हानि नहीं होती है। इसके विपरीत, यदि उस साधन को वृत्तिम उपयोग (वैसे सरकारी सहायता या कर) द्वारा खर्च उद्योग में ही, जहाँ कि उनकी उपयोगिता अब कम है, रोक रखा गया, तो अक्षय समाज को हानि पहुँचेगी।

सामान्यत एक उद्योग के अन्तर्गत अनगिनती सत्तायें होती हैं। इनमें से सीमान्त सत्तायें भी सम्मिलित हैं जिन्हें (उपयुक्त उदाहरण वाली सत्ता के प्रसंग में) लगान भी, जो कि हानि के भट्ठकों की सहाय में उनके रक्षक का कार्य करता, मिलती नहीं होता है। यही नहीं, इसमें से एक या दूसरी सत्ता यदि वह उत्पादन जारी रखना चाहे तो किसी भी क्षण अपनी कुछ सत्ताओं पूँजी बदलन के लिए विवश हो सकती है। इन दशाया में उत्पाद के मूल्य में प्रत्येक कमी के साथ उद्योग में, सीमान्त सत्ताएँ एक एक करके बन्द होती जायगी क्योंकि उत्पादन जारी रखने के लिए प्रेरणा का प्रभाव है। हमने कृतस्वरूप उद्योग में संकुचन अवश्य हो जायेगा। किन्तु सिद्धान्त रूप में इसकी प्रक्रिया पहले के समान ही रहती है।

कीमते जितना अधिक गिर सकती हैं अथवा यों कहें। कि विदेशी देश जितना सत्ता खर्च सकते हैं, युद्ध-दश को धर्म के अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन से लाभ भी उतना ही अधिक होगा। किन्तु स्मरण रहे कि कीमन में गिरावट को रोकने हेतु कर का आरोपण (Imposition) उन अपवादभूत दशाओं में, जिनमें कि सीमान्त सत्ता को लगान मिलता है तथा इसलिए कुछ समय तक वह अपना उत्पादन कार्य कीमत में कमी होने पर भी जारी रख सकती है, राष्ट्रीय माध्य में कमी कर ही दे ऐसा आवश्यक नहीं है। कारण, ऐसी दशाओं में कर के आरोपण से साधनों के वितरण में कोई बुराई नहीं आती है, जिससे उत्पादन उतना ही होगा जितना कि कर न लगने पर होता रहा था। अब यदि अप्रत्यक्ष प्रभावों की छोड़ दें, तो बरो का प्रभाव बचल इतना ही होगा कि राष्ट्रीय माध्य के वितरण में परिवर्तन हो जायेगा।

उपर्युक्त समस्त विवेचन इस मान्यता पर आधारित है कि प्रतियोगिता के कारण कीमतों में लोच है तथा यदि आवश्यक हुआ तो विभिन्न साधनों की कीमतें, संस्था द्वारा इनका प्रयोग बन्द होने से पूर्व भी, शून्य तक गिर सकती हैं। यह बात भौतिक उत्पत्ति साधनों के बारे में लागू अधिक सही है। एक भूषण या भवन का स्वामी इसे खाली या निष्क्रिय पड़ा रहने देने की अपेक्षा यह तय करेगा कि इसे अपने ही काम में लाना रहे प्रकृति दुर्गति की किराये पर उठा कर कुछ लाभ कमा ले। क्या हम नहीं देखते कि कुछ संस्थाएँ 'बन्द' होने की अपेक्षा 'हानि' पर श्रवती रहती हैं? विशेषतः, जब उपक्रमियों की भविष्य उद्गम प्रतीत हो, तो वह मध्यमतर में भारी हानि सह कर भी उत्पादन कार्य जारी रखते हैं, भले ही प्राथमिक लागने (Prime costs) भी बमूक न हो सकें। कारण, चलती हुई संस्था को बन्द करने और कुछ समय के बाद उसे पुनः खोलने की अपेक्षा मध्यमतर में उसे खुले रखना कम महंगा (Less costly) प्रतीत होता है।

किन्तु हमारी मान्यता (कि प्रतियोगिता कीमतों में लोच उत्पन्न करती है) एक सबसे महत्वपूर्ण साधन (भ्रम) को लागू नहीं होती है। यहाँ कीमती-मपन्न प्राथमिक रूप से मूल्य की मानि साचरण करने लगता है, क्योंकि श्रमिक मजदूरियों में सामूहिक कठोरता होने पर ही प्रायः अपना श्रम देने से रोक लेता है। इससे हड़तालों और बेकारी के प्रसार के रूप में जो 'गतिरोध' हमें हैं उनसे वास्तविक हानि उदय होती है। किन्तु स्पष्टतः ऐसी हानि, जो एक मध्यमतर अवधि में होती है, स्थिर पूँजी के मूल्य में हुए हानि से भिन्न स्वभाव रखती है, क्योंकि प्रतिम प्रकार की हानि अवश्यभावी है चाहे कीमत सम्यक् पूर्ण सहजता से ही क्यों न काम करे। हैबरलर की सम्मति है कि "ये सघर्षात्मक हानियाँ (Frictional losses), जो कि मजदूरों की दूरी की अपूर्ण संचय के कारण उदय होती हैं, जगती गम्भीर नहीं हैं जितनी कि प्रथम दृष्टि में इन्हें समझा जाता है। कारण, सभी साधन न श्रम, कुछ अपवादभूत दशाओं को छोड़ कर, सबसे कम निष्पत्ति हैं।"¹

उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, विपरीत सम्मति का प्रगट करने पर भी, उत्पत्ति के असोपित साधनों की विद्यमानता देखिके के पक्ष में कोई तर्क नहीं है। शुलर (Schuller) ने अपना स्पष्टीकरण एक विवाद-रहित तथ्य से प्रारम्भ किया और कहा कि "किसी भी देश में प्राकृतिक साधन-सर्वेरा भूमि, जन-शक्ति, कोयला, लोहा एवं अन्य खनिजों के भण्डार पूर्णतः सोपित नहीं किये जा रहे हैं और वे उत्पादन की किसी भी सामा के लिये, जिसे इनकी आवश्यकता पड़े, उपलब्ध हो सकते हैं।" किन्तु हम तथ्य से उन्हीने यह निष्कर्ष

¹ "We may perhaps add that these frictional losses due to the imperfect flexibility of wage rates are less serious than one might at first suppose, since of all factors labour, apart from a few exceptional cases, is the least specific."—*Ibid*, p. 187.

जि ज्ञाना कि ऐसे निष्पन्न साधनो को टेरिफ की प्रेरणा के द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है और इससे, कुछ दशासो मे, अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। किन्तु हैबरखर के अनुसार यह तर्क, जहा तक वह उत्पत्ति के भौतिक साधनो से सम्बन्धित है, एक असत्यता (Fallacy) पर आधारित है। यह कोई आश्चर्यप्रद या असाधारण बात नहीं है कि उत्पत्ति के समस्त साधन प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसा कि रोपके (Ropke) ने कहा है, आर्थिक शक्तियाँ 'अधिकतम' (Maximum) को नहीं बरन् 'अनुकूलतम उपयोग' (Optimum utilisation) को सम्भव बनाती हैं। हम जायद ही कोई ऐसी दशा सोच सकें जिसमें भूमि का प्रत्येक टुकड़ा, समस्त प्लान्ट और साज-सामान जो चाहे कितना ही पुराना हो, प्रयोग में आने लगे और बोयले वा प्रत्येक भण्डार चाहे वह कितना ही सराब हो, खनन क्रिया के अन्तर्गत आ जाय। नि सन्देह कहा जा सकता है कि लगभग ऐसी ही स्थिति चीन या भारत में पाई जाती है। यदि ऐसा है, तो साधनो की निष्क्रियता महान् गरीबी की निशानी है, सम्पत्ति की प्रचुरता की नहीं जैसा कि शुलर का सिद्धान्त दर्शाता है।

[सम्भवतः शुलर के मस्तिष्क में अल-जक्ति सम्बन्धी प्रस्तावना थे, जो प्रायः पूँजी के प्रभाव के कारण पूर्ण शोषित नहीं हो पाये हैं। यदि ऐसा है तो निष्पन्न प्रमाणन गरीबी की निशानी हो सकते हैं। किन्तु इससे भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि टेरिफ शुद्ध पूँजी के आयात में सहायक हो सके।]

इस बात में भी कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उत्पत्ति के अशोषित साधन प्राकृतिक हैं (जैसे—भूमि और खनिज भण्डार) अथवा मनुष्य निर्मित (जैसे—कारखाने व मशीनें) यद्यपि एक साधारण व्यक्ति को मनुष्य निर्मित उत्पत्ति साधनो के अशोषित रहने की ही चिन्ता अधिक होती है। वास्तव में, उत्पत्ति के अशोषित साधन (बशर्ते इनके उत्पादों का मुख्य अर्थ साधनो की, जिनका सहयोग उत्पादन कार्य में आवश्यक है, लायती के लिए पुरा न हो, क्योंकि अन्य साधन अल्प अथवा अधिक उत्पादन कर सकते हैं) न हो पूँजी के बिना अर्थव्यवस्था की हानि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे तो प्राथमिक उत्पत्ति की अश्विनी मजिद तक पहुँचाने वाली मजदूर के मील के पत्थर सदृश हैं, जिस पर अर्थव्यवस्था तबनीकी प्रगति के अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ विभाजन के प्रभाव के अन्तर्गत चलती चली जा रही है।¹ [स्मरण रहे कि प्रयोग में न आई हुई अर्थ शक्ति—वेकारी—एक अलग श्रेणी में गिनी जाती है।]

1 "In reality, the non-utilised means of production (provided the value of their products would not cover the costs of the other factors which must be combined with them, since the latter can produce more elsewhere) represent neither a des-

उपसंहार—

जि सन्देह है हानिया जो इतनी स्पष्ट और प्रभावोत्पादक हैं, निष्क्रिय साधनों के स्वाधियों की दृष्टि से वास्तविक हानिया हो सकती हैं किन्तु अन्य व्यक्तियों को होने वाले अधिक लाभों से इनकी क्षति पूर्ण हो जाती है। सम्पूर्ण समाज को कुल पर लाभ होता है हानि नहीं। उदाहरणार्थ जब कोई कारखाना उपर्युक्त कारणों से बन्द किया जाता है और इसमें लगी हुई पूँजी का परिचोषन नहीं होने पाता तो यह मरन रूप से कहा जा सकता है कि मूल विनियोग (चाह तो भूटिपूर्ण गणना के कारण या याद में हुए अस्थिर परिवर्तनों के कारण) ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। किन्तु धार्मिक क्षेत्र में “जो हो वग मो हो मग” वाली बात चरितार्थ होती है। जिन परिस्थितियों की हमने कल्पना की है उनमें समाज के प्रसाधनों का भविष्य में उन्नतिय उपयोग सब ही हो सकता है जब कि कारखाना बन्द हो जाय।^१

परीक्षा प्रश्न :

- १ “यह सदा कहा जाता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धान्त देश के भीतर सभी साधनों को पूर्णतः गतिशील मानकर चलता है और इस शर्त के पूरा होने पर ही देश के निम्न यह सम्भव है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा आवश्यक कच्चे माल समायोजनों को हानि उठाये बिना ही सम्पन्न कर सके।” विवेचन कीजिये।

[“It is constantly urged that the Theory of International Trade, as we have presented it assumes the complete mobility of all factors, or means of production, within a country, and that a country can carry out the adaptations required by international trade without loss only if this conditions is fulfilled” Discuss]

- २ विविष्ट साधनों की उपस्थिति को विचार में लेते हुये तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का पुनः कथन कीजिये।
[Restate the Theory of Comparative Costs with special reference to specific factors]

truction of capital nor a loss to the economy as a whole. They are milestones upon the road of economic progress along which the economy is moving under the influence of technical progress or of the international division of labour.”

—*Ibid*, 188.

^१ Haberler *The Theory of International Trade*, p. 189.

परिवर्तनशील लागतें सवम् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Variable Costs and International Trade)

परिचय—

हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त का विवेचन सर्वप्रथम इस माय्यता के साथ प्रारम्भ किया था कि उत्पत्ति की विभिन्न शाखाओं में स्थिर लागतें (Constant costs) विद्यमान हैं। तत्पश्चात् हमने यह दिखाया कि यदि इस माय्यता को छोड़ दें और यह मान कि उत्पत्ति की प्रत्येक शाखा में बढ़ती हुई लागतें (Increasing costs) विद्यमान होती हैं, तो भी तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के इस निष्कर्ष को कोई क्षति नहीं आयेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन (और व्यापार) सम्बन्ध पक्ष। वे लिए लाभदायक है अर्थात् वह इनके कुल उत्पादन को बढ़ाता है। हा इतना आवश्यक है कि बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत धर्म विभाजन का क्षेत्र स्थिर लागतों की अपेक्षा कुछ संकुचित हो जाता है। कारण, जैसे जैसे धर्म विभाजन बढ़ाया जाता है देश की (सीमांत पर) तुलनात्मक हानि घटने लगती है और अन्त में लुप्त हो जाती है। तुलनात्मक हानि में कमी होने के फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य 'लागत-अन्तर' भी घटने लगता है और अन्ततः बिल्कुल ही समाप्त हो सकता है। स्पष्टतः इस बिन्दु से आगे धर्म-विभाजन (अतएव व्यापार) करना लाभदायक नहीं होगा, किन्तु इस बिन्दु तक तो वह लाभदायक है ही। प्रस्तुत अध्याय में हम यह श्रम कि घटती हुई लागत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के निष्कर्षों को कहाँ तक प्रभावित करती हैं।

घटती हुई लागतें (Decreasing Costs)

बढ़ती हुई लागतों की परिस्थिति का अध्ययन करना जितना सरल है, घटती हुई लागतों का अध्ययन करना उतना ही कठिन। प्रो० शुम्पीटर (Schumpeter), नाइट (Knight) आदि विद्वान तो घटती हुई लागतें विद्यमान होने की सम्भावना से ही इनकार करते हैं। किन्तु प्रो० हैबरलर का मत है कि 'वे लागतें अपवादमूलक दृष्टांश (Exceptional cases) में विद्यमान हो सकती हैं और ये दृष्टांश महत्वपूर्ण हैं। किन्तु नतीज और सङ्कटन में प्रगति के परस्पर विरोध प्राणनाम नहीं होता, जिसकी

सभावना को उक्त विधान भी स्वीकार करते हैं, घटती हुई लागतों की वास्तविक दशा नहीं है भले ही ऐसी कमी उत्पादन में वृद्धि के साथ ऐतिहासिक रूप में सम्बद्ध हो। कारण, ऐसी प्रगति तो आर्थिक सामग्री (Economic data) में ही परिवर्तन होने के समान है और उसे प्रदर्शित करने हेतु सम्पूर्ण लागत वक्र को नीचे की ओर खिसकाना (Shift) पड़ता है। उसे ऐसे लागत वक्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता जो कि वाहिनी ओर अधोगुली ढाल रखे। जब लोग घटती हुई लागतों के नियम की चर्चा करते हैं, तो उनके अस्तित्व में प्रायः लागत सम्बन्धी ऐसी ऐतिहासिक घटीतिपा ही होती है, किन्तु हमारे मिथ्यात्व की संघटा पर ऐसी दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।¹

घटती हुई लागतें, उचित अर्थ में, उत्पत्ति के विस्तार का परिणाम है। वे कारखाना के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप उदय होती हैं। घटती हुई लागतों का कारण बुनियादी रूप से यह है कि उत्पत्ति के अनेक साधन पूर्ण रूप से विभाज्य (Divisible) नहीं हैं, जिनसे एक विशेष तकनीकी अनुकूलतम आकार वाले प्लांट के उपयोग के लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पत्ति करना आवश्यक है तथा उसके पूर्णरूप प्रयोग कर सके हेतु तो इससे भी बड़ी अधिक मात्रा में उत्पत्ति की जानी चाहिए। यदि बाजार इतना विनाल है कि वह अनुकूलतम आकार वाले कई कारखानों को कुल उत्पत्ति को ग्रहण कर सकता है, तो घटती हुई लागतों का नियम त्रियाशील नहीं रहता और हम घटती हुई लागतों के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।²

यदि किसी प्लांट का अनुकूलतम आकार, बाजार के विस्तार की तुलना में, इतना विनाल है कि उगकी मात्रा को केवल कुछ ही प्लांटों अथवा केवल एक ही

1 "I believe they can exist in exceptional cases and that these exceptional cases are of importance. Let me hasten to add that a reduction in costs due to progress in technique and organisation (the possibility of which is of course not disputed by the writers in question) does not constitute a true case of decreasing costs even if it is associated historically with an increase in production. Such progress is a change in the economic data and is to be represented graphically by a downward shifting of the whole cost curve and not by a cost curve which slopes downwards to the right. When people speak of the Law of Decreasing Costs they frequently have in mind mainly these 'historical' reductions in costs; but our theory is not invalidated by such cases"—Haberler: *The Theory of International Trade*, p. 144.

2 (Footnote see on next page)

प्लांट के उत्पादन द्वारा पूरा करना सम्भव है, तो घटती हुई लागतें एकाधिकारिक परिस्थिति (Monopolistic situation) को जन्म देती हैं। अतः यदि हम किसी उत्पादन शाखा में स्वतन्त्र प्रतियोगिता से मिलती-जुलती कोई चीज देखें, तो यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह बढ़ती हुई लागतों के आधीन है।

फ्रैंक डी० ग्राहम का दृष्टिकोण—

प्रो० फ्रैंक डी० ग्राहम (Frank D. Graham) ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त की विस्तृत आलोचना करते हुए घटती हुई लागतों की क्रियाशीलता पर विचार किया है। उन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के विरुद्ध इतनी आपत्ति नहीं उठाई है जितनी इसके इस निष्कर्ष के विरुद्ध कि तुलनात्मक लागतों के अनुरूप ही यदि देश वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे और आयात-निर्यात करे, तो उन्हें लाभ होगा। अर्थात् प्रत्येक देश में उत्पादन की भाषा बड़ जायेगी। वे अपना तर्क एक ऐसी स्थिति से आरम्भ करते हैं, जिसमें तुलनात्मक लागत परिस्थिति के कारण देश उन उद्योगों में, जिनमें कि लागतें बड़ रही हैं, विशिष्टता प्राप्त करने, तथा उन उद्योगों में जिनमें कि लागतें घट रही हैं, छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। उनका कहना है कि कृषक देशों की स्थिति सामान्यतः ऐसी ही है। पिछली शताब्दी के अन्त तक अमेरिका की और उसी शताब्दी के प्रथमार्ध में यूरोपीय महाद्वीप की (इंग्लैंड से सम्बन्धों के सबसे गे) स्थिति भी वही ही थी। दूसरी ओर, औद्योगिक देश ऐसी सुलभ स्थिति में होते हैं कि वे उत्पत्ति की उन शाखाओं में, जिनमें कि घटती हुई लागतें प्रचलित हैं, काम आरम्भ कर सकते हैं या बड़ा सकते हैं।¹

ग्राहम ने अपने मत में समर्थन में निम्नलिखित उदाहरण दिया है—मान लीजिए कि मैं कृषि उपजों का तथा यदि मैं औद्योगिक उत्पादों की प्रतिनिधि (Representative) हूँ। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आरम्भ के पूर्व

“Decreasing costs in the proper sense are the consequence of an expansion of production and not merely phenomena which happen to take place at the same time as such an expansion. They come about through an increase in the size of the works. They are due, fundamentally, to the fact that many factors of production are not completely divisible, so that a large output is needed for a plant to be of the technical optimum size and yet to utilise fully all its factors. When a market is large enough to absorb the total output of a number of works of optimum size, the law of decreasing costs no longer applies and we are again in the region of increasing costs.”—*Ibid.*, p. 144

1 Graham: “Some Aspects of Protection Further Considered,” *Quarterly Journal of Economy*, Vol. 37 (Feb 1923), pp. 199

इङ्ग्लैंड में विनिमय-अनुपात ४० इकाई गेहूँ = ४० घड़ियाँ हैं, और, अमेरिका में ४० इकाई गेहूँ = ३७ घड़ियाँ हैं। स्पष्टतः अमेरिका को गेहूँ के और इङ्ग्लैंड को घड़ियों के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है। सुविधा हेतु ब्राह्म ने यह भी मान लिया है कि अमेरिका में वृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई लागत तथा निर्माणी क्षेत्र में घटती हुई लागत क्रियाशील है किन्तु इङ्ग्लैंड में औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक या सीमान्त लागतों में किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के बिना ही, बढ़ाया जा सकता है तथा उसके कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में भी यही बात है अर्थात् इङ्ग्लैंड में कृषि एक औद्योगिक क्षेत्रों पर स्थिर लागतें कायम रखता है। इन साम्यताओं के प्रथम अमेरिकी उद्योगपतियों के लिए यह लाभदायक है कि वे श्रम और पूँजी को उद्योग से कृषि में आकर्षित करें। ३७ घड़ियाँ उत्पन्न करने में पहले जितना श्रम और पूँजी लागता था उसकी सहायता से जब तक गेहूँ की ३७ से अधिक इकाइयाँ उत्पन्न की जाती रहेंगी तब तक गेहूँ उद्योग घड़ी उद्योग की अपेक्षा अधिक मजदूरी और अधिक व्याज दे सकता है।

मान लीजिए कि घड़ियों के उत्पादन की ३७,००० इकाइयों में काम किया जाता है और इससे जो साधन मुक्त हुए वे गेहूँ की ३७,५०० इकाइयाँ अतिरिक्त (Additional) उत्पादन करते हैं। अतिरिक्त उत्पादन का यह अंश ४०,००० से कम लिया गया है, क्योंकि कृषि में बढ़ती हुई लागतें क्रियाशील हैं। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात ४० घड़ियाँ = ४० इकाई गेहूँ है। अतः ३७,५०० इकाई गेहूँ ३७,५०० आंग्ल घड़ियों में बदला जा सकता है। "किन्तु अमेरिका में घड़ियों के उत्पादन में घटौती होने से घड़ियों की लागत इकाई बढ़ जाती है....." जिससे अब केवल ३६ घड़ियाँ ही उनकी लागत पर उपलब्ध हैं जिसके लिए ट्रान्सफर से पूर्व ३७ घड़ियाँ उपलब्ध थीं। गेहूँ के उत्पादन में परिवर्तन तब तक होता रहेगा जब तक कि उसमें श्रम और पूँजी स, जोकि ३६ घड़ियाँ उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है, ०.६ इकाई गेहूँ उत्पन्न करना सम्भव रहे। मान लीजिए कि श्रम और पूँजी के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, जिससे कि घड़ियों के कुल उत्पादन में ३६,००० इकाइयों की कमी हो जाती है, कुल गेहूँ-पूर्ति में ३६,२०० इकाइयों की वृद्धि होती है। ये ३६,२०० इकाइयाँ गेहूँ ३६,२०० आंग्ल घड़ियों से बदली जावेंगी। इस प्रकार कुल व्यापार का फल यह है कि जितना प्रयत्न से पहले $(३७,००० + ३७,००० =)$ ७४,००० घड़ियों का उत्पादन होना था, उससे अब $(३७,५०० + ३६,२०० =)$ ७३,७०० घड़ियाँ ही प्राप्त होती हैं—अर्थात् ३०० घड़ियों की हानि हुई.....। यह प्रक्रिया थाने चालू रहेंगी और हानि उस समय तक बढ़ती जायेगी जब तक कि अमेरिकन घड़ी उद्योग पूर्णतः ब्रिटिश घड़ी उद्योग से प्रतिस्थापित (Replace) न हो जाय।

[लेबरर ने लिखा है कि इङ्ग्लैंड की गणतन्त्र-स्थिति के बारे में हम क्या कहना करते हैं, यह उद्देश्य का विषय नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह

कल्पना करते कि इङ्ग्लैण्ड में कृषि उत्पादन में स्थिर या बढ़ती हुई लागतें त्रियाशील हैं किन्तु निर्माणियों में घटती हुई लागतें (अथवा, उसके घटियों के उत्पादन व्यय, उत्पादन में विस्तार होने पर, गेहूँ के उत्पादन-व्यय की अपेक्षा, जबकि गेहूँ के उत्पादन में बमी की जाय, अधिक तेजी से घिरते हैं), तो अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात अमेरिका के अधिक अनुकूल हो जायेगा तथा उसकी 'हानि' लाभ में परिवर्तित हो सकती है ।¹]

उपरोक्त उदाहरण द्वारा ब्राह्म ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि किसी भी देश के लिए, जो कि हम उदाहरण में अमेरिका के संक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है, अन्तर्राष्ट्रीय धन विभाजन का परिणाम लागतों में सामान्य वृद्धि होना है । लागतें विकासोन्मुख उद्योग में तो इसलिए बढ़ती हैं कि वह बढ़ती हुई लागतों के क्षेत्र में हैं किन्तु पतनोन्मुख उद्योग में इसलिए कि वह घटती हुई लागतों के प्रभाव में है । [ऐसी परिस्थितियों में यह सम्भव है कि गेहूँ और घटियों का आन्तरिक विनिमय अनुपात स्थिर (Constant) बना रहे । इसका कारण यह है कि दोनों प्रकार के उद्योगों में लागने समान दिशा में बदलती हैं । अब दोनों उद्योगों में सीमान्त लागतों में प्रतिगत वृद्धि समान होना सम्भव है । यदि ऐसा हुआ, तो उनके मध्य पुराना लागत अनुपात ही बच्यम रहेगा ।]

किन्तु ब्राह्म का उपरोक्त निष्कर्ष सब ही सत्य या वैश हो सकता है जबकि उनकी मायनाओं को स्वीकार कर लिया जाय, विशेषतः यह स्वीकार कर दिया जाय कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा लागतों में बमी धायेगी और जैसे-जैसे उत्पादन घटेगा, लागतों में वृद्धि होगी । किन्तु वास्तविकता यह है कि उनकी मायनायें पतनोन्मुख (Proccarions) है । केवल उपर्युक्त धर्म में ही घटती हुई लागतों की कल्पना करना पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें यह भी देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उनकी ही हुई कल्पनायें सम्भव या असम्भव हैं । इन हेतु हम प्राथमिक लागत विज्ञान के मदर्भ में ब्राह्म के तर्क की परीक्षा करेंगे ।

- 1 "At this point, it becomes clear that the assumption we make about cost conditions in England is not a matter of indifference. Were we to assume, for example, constant or increasing costs in her agriculture and decreasing costs in her manufacturing (or that her cost of producing watches falls faster with an expansion in their output than her cost of producing wheat falls with a contraction in its output), the international exchange ratio must become more favourable to the United States, and her loss may be transformed into a gain."—*Ibid*, p 200.

लागतों में 'ऐतिहासिक' ह्रास (Historical Reduction in Costs)—

किसी उद्योग में घटती हुई लागतों का नियम उस दशा में क्रियाशील कहा जाता है जबकि इसके उत्पादन में बिस्तार होने के फलस्वरूप सीमान्त लागतों में अपवा सीमान्त एवं औसत दोनों ही प्रकार की लागतों में कमी हो जाय। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, कुछ लेखकों का मत है कि इस अर्थ में घटती हुई लागतें अतन्त्र हैं तथा स्थैतिक सिद्धान्त (Static theory) में इनके लिये कोई स्थान नहीं है। कारण, उनका कहना है कि, लागतें केवल तब ही कम हो सकती हैं जबकि कोई नई तकनीकी विधियाँ प्रयोग की जायें और नई तकनीकी विधियों के प्रयोग का अर्थ है आर्थिक सामग्री (Economic data) में परिवर्तन होना। उत्पत्ति का विद्याल पैमाना साधनों में केवल एक ढंग से कमी ला सकता है जो यह कि विभिन्न तकनीकी विधियों के प्रयोग की अनुमति दी जाय। [यह तर्क इतनी ही दृढ़ता से बढ़ती हुई लगतों के नियम के भी विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब एक नेत को भविष्यात्मिक पूँजी और श्रम का प्रयोग करते हुए गहन विधि से जीता जाता है, और प्रति इकाई श्रम व पूँजी उत्पत्ति घटती जाती है अथवा जब खराब से खराब भूमि भी जंगली जंगल लगती है तथा लागतें बढ़ने लगती हैं, तो प्रायः इन दशाओं में भी विभिन्न तकनीकी विधियाँ ही प्रयोग की जाती हैं। ऐसी दशा में क्या हम यह तर्क करेंगे कि यदि नई विधि प्रयोग न की जाती, तो लागतें बढ़ने का नियम क्रियाशील न हो सकता था ?]

हैबरलर की सम्मति में यह तर्क [कि केवल नई तकनीकी विधियाँ प्रयोग करने से ही लागतें कम हो सकती हैं और चूँकि इससे प्राथमिक सामग्री में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे घटती हुई लागतों की दशा नहीं मानना चाहिये] वैध नहीं है। कारण, स्थैतिक सिद्धान्त (Static theory) में हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि 'प्रयोग की जाने वाली तकनीकी विधियाँ (Technical methods) स्थिर रहती हैं वरन् केवल यह मानते हैं कि तकनीकी ज्ञान (Technical knowledge) और तकनीकी योग्यता (Technical ability) स्थिर रहती हैं। हमें 'प्रयोग की जाने वाली तकनीकी विधियों में मात्र की वृद्धि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन' तथा 'तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन' में भेद करना चाहिये। प्रथम दशा में नवीन प्रयोग वाली तकनीकी विधियाँ पहले से 'ज्ञात' और 'परीक्षा की हुई' थीं, इनके प्रत्येक प्रयोग में जाने वा कारण यह था कि उत्पादन की मात्रा क्षीय, यो कि उनका लाभ सहित प्रयोग नहीं किया जा सकता था। दूसरी दशा में, नई विधियाँ पहले से 'ज्ञात' नहीं थी अथवा 'व्यवहार में अजगर्ज' नहीं गई थी, ये ज्ञान में हुई वास्तविक वृद्धि का सूचक हैं। यह दूसरी दशा नि सन्देह एक ऐतिहासिक एवं प्राच्यिक विषय (Historical and dynamic phenomenon) है और इसके फल-स्वरूप आर्थिक सामग्री में परिवर्तन होता है, तथा, जैसा कि पहले ही देख चुके हैं, जब इसके कारण लागतों में कमी आती है, तो यह सैद्धान्तिक अर्थ में, घटती हुई

लागतों के नियम का विषय नहीं है। यद्यपि घटती हुई लागतों के साथ ही साथ, एक ऐतिहासिक संध्य के रूप में उत्पत्ति का भी विस्तार होता है तथापि इसे उस नियम का उदाहरण नहीं समझना चाहिए। "इस प्राथमिक और ऐतिहासिक स्वभाव के लागत-ह्रास को हमारे विश्लेषण में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह भारतो में परिवर्तन लाना है जिसे आर्थिक सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। नि सदेह वह कुछ परिस्थितियों में, तुलनात्मक लागतों में और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दूरगामी परिवर्तन ला सकता है किन्तु ऐसे लागत-ह्रास स्वयं वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की विद्यमानता या विस्तार पर निर्भर नहीं होते।"¹ (उदाहरणार्थ उत्पादन वृद्धि के द्वारा आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है किन्तु इसका कोई निश्चित समय नहीं है इसलिए इन्हें एक नियम के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।) आहम ने भी अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करते समय लागतों में होने वाले ऐसे ऐतिहासिक ह्रासों को अपने दिमाग में नहीं रखा है।

विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में घटती हुई लागतों का नियम—

हमने यह देखा कि विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में घटती हुई लागतें उत्पादन के विस्तार वा, जो कि मांग में हुई वृद्धि का परिणाम है, कल होनी है। लागतों में ह्रास दो प्रकार से सम्भव होता है—(I) अन्तरिक या अन्तर्गतताये (Internal economies), एवं (II) बाह्य अन्तर्गतताये (External economies)।

आन्तरिक अन्तर्गततायी वा सम्बंध एक व्यक्तिगत कर्म या प्लांट के आकार में होने वाली वृद्धि में है किन्तु बाह्य अन्तर्गतताये सम्पूर्ण उद्योग (Industry as a whole) से, जिसके आकार में सम्भवतः कुछ नई कर्मों के प्रवेश द्वारा वृद्धि हो सकती है, सम्बंधित है। प्रत्येक कर्म चाहे वह अपना आकार न बढ़ावे उत्पादन की दशा में सुधरने से लाभान्वित होती है। शुष्कीकरण की भाँति जो 'परम्परागत' यह समझते हैं कि तकनीकी ज्ञान के स्थिर रहते हुये लागत ह्रास की सम्भावना नहीं है, उनके मस्तिष्क में 'स्थिर तकनीकी ज्ञान' और 'स्थिर तकनीकी विधियों' के सम्बन्ध का भ्रम (जिसकी आलोचना हमने ऊपर की है) तो है ही, साथ में यह धारणा भी है कि उत्पादन के लिए मांग बढ़ने के परिणामस्वरूप उद्योग का जो विस्तार होता है वह विकासशील उद्योग में अधिक मात्रा में प्रयोग किये जा रहे

1 "A reduction in costs of this dynamic and historical nature has no place in our analysis, since it represents a change of data not to be explained by economic theory. It may indeed cause far reaching alterations, under certain conditions, in comparative costs and in international trade, but such reductions in costs are not themselves dependent of the existence or extent of the international exchange of goods."

साधनों की कीमतों को अवश्य ही बढ़ा देगा। उदाहरणार्थ, यदि कृषि उपजों के लिए माँग बढ़ जाय तो भूमि और कृषि श्रम [जो कि बहुत सीमा तक एक निश्चित साधन है क्योंकि अन्य चीजों से श्रमिक कृषि में आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं] की कीमतें बढ़ जायेंगी। प्रयोग किये जा रहे कुछ साधनों की कीमतों में ऐसी वृद्धि होने से, जैसे-जैसे किमी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, उसती (वस्तु की) मौद्रिक लागत बढ़ती जाती है।¹ यह तर्क कुछ सीमा तक ही ठीक है। किन्तु यह भी समझिए कि 'बढ़ती हुई लागत' की दिशा में जो प्रकृति दृष्टिगोचर होती है उसे स्थायी या अस्थायी रूप से आन्तरिक और बाह्य मितव्ययिताओं द्वारा विजय किया जा सकता है। जब ये मितव्ययिताये लागत वृद्धि की अपेक्षा बढ़ जाती हैं तो घटती हुई लागतें क्रियाशील होने लगती हैं।²

(१) आन्तरिक मितव्ययितायें और कमालत लागत द्वारा नियम—उत्पादन क्षेत्र के अधिकांश भाग में, विशेषतः उद्योगों में, एक फर्म के आकार में वृद्धि होने पर लागत कम होने लगती है। इसका कारण यह है कि अनेक उत्पत्ति साधन पूर्ण विभाजन योग्य नहीं होते। कुछ साधनों (उदाहरणार्थ मोटर कारों के निर्माण के लिए "कन्वेयर सिस्टम" (Conveyor system) का एक शून्यतम आकार होता है। इससे कम आकार में उनका प्रयोग साम्प्रदायिक नहीं रहता। अतः फर्म की उत्पत्ति एक निश्चित शून्यतम मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए तब ही इन्हे लाभ सहित स्थापित (Install) किया जा सकता है। किन्तु एक बार स्थापित हो जाने पर वह अत्यन्त सहयोगी घटकों में अधिक निष्पटीबद्ध होगा गुणवत्ता बना देते हैं, क्योंकि उत्पादन विधियाँ अब पहले से मिला हाथी। अन्य मापन भी विभिन्न आकारों में उपलब्ध होते हैं और एक सीमा तक इनके बारे में भी यह देखा जाता है कि ये जितने बड़े होंगे उतनी ही कम उनकी लागत प्रति इकाई होगी। उदाहरणार्थ एक इलेक्ट्रिक मोटर की लागत इसकी आधी क्षमता के मोटर की लागत से कम होती है किन्तु ३०% कम होगी है। एक विज्ञान मात्रा में उत्पत्ति करने से विद्यमान साधनों (उदाहरणार्थ, कार्यालय स्टाफ एक सत्र सामान) का पूर्णतम प्रयोग सम्भव हो जाता है। अतः कुछ प्रकार के व्ययों में उत्पत्ति की अपेक्षा कम आनुपातिक वृद्धि होती है, जिससे जब उत्पत्ति बढ़ती है तो उनकी प्रति इकाई लागत घटने लगती है। कुछ उद्योगों में तो अप्रत्यक्ष विस्तार संस्थानों के लाभ स्वतः स्पष्ट है।

अन्य विषय के निम्न पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है—यदि एक

1 Haberler *The Theory of International Trade*, p. 203

2 " it is beyond question that the tendency towards increasing costs can be temporarily or permanently offset or more than offset by the internal and external economies. When it is more than offset, we have the phenomenon of decreasing costs"—*Ibid.*, p. 203

दिये हुए समय पर किसी उद्योग में संस्थानों के आकार को बढ़ा कर उत्पादन लागते घटाना सम्भव है, तो यह स्थिति स्वतन्त्र प्रतियोगिता द्वारा प्राप्त हो जायेगी। कारण प्रतियोगिता पर विजय पाने की इच्छा से प्रत्येक साहसी यह कोशिश करता है कि वह अपनी निजी लागतों को अपनी संस्था का आकार बढ़ा कर घटा ले। संस्थानों के आकार में वृद्धि होने की प्रक्रिया तब ही स्वेयी जबकि या तो (अ) वह सीमा पहुँच जाये, जिससे अधिक आकार में वृद्धि होना लागता को घटाने के बजाय बढ़ाये (यह सीमा कृषि उद्योग में जल्दी ही आ जाती है), अथवा (ब) बाजार को देखते हुए सम्बद्ध संस्थान का आकार इतना बढ चुका हो कि इन्ही गिनी फर्में ही पृथक् बच रहे जिससे कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाय। ऐसी दशा में, ये फर्में परस्पर समझौता कर गयी और एकाधिकार उत्पन्न हो जायगा।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटती हुई लागतों, जो कि आन्तरिक मितव्ययिताओं से उदय होती है, दीर्घकाल में, स्वतन्त्र प्रतियोगिता के साथ प्रसंगत होती हैं। इस प्रकार ग्राह्य का लक्ष्य वृद्धिपूर्ण है क्योंकि वह स्वतन्त्र प्रतियोगिता की मांगता पर आधारित है। वे यह मान कर चलते हैं कि अमेरिकन घड़ी उद्योग, जो कि घटती हुई लागतों के आधीन अधालित हो रहा है, आगम्य प्रतिस्पर्धा के दबाव में गमन गमन संकुचित होने लगता है और यह मान्यता अमेरिकी उद्योग में स्वतन्त्र प्रतियोगिता की निश्चयात्मकता सम्बन्धी कल्पना पर आधारित है। लेकिन यह कल्पना असम्भव है, यदि उद्योग वास्तव में ही घटती हुई लागतों के आधीन है, तो उसमें बहुत पहले ही एकाधिकार स्थापित हो चुका होगा।

अब यह देखना शेष है कि यदि घटती हुई लागतों के अभावस्वरूप कोई उद्योग पहले से ही एक एकाधिकारी (जैसे ट्रस्ट या कार्टेल) के आधीन है, तो क्या ग्राह्य के अथवा इनके जन्म तर्कों में कुछ सत्य है। एक एकाधिकारी अपनी उत्पत्ति को, जब भी उसकी सीमान्त लागत घट सके, बढ़ाने के लिए विवश नहीं होता। वह अपने उत्पादन में तब ही वृद्धि करता जबकि माग अपनी साक्ष्य हो कि उसकी कुल प्राप्तियों में उसकी कुल लागतों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाय। अब मान लीजिये कि इस उद्योग की बढ़ती हुई विदेशी प्रतियोगिता का सामना करता पड़ता है। क्या इसके बम प्रतिकूल परिणाम हमें जा ग्राह्य में बताया है?

नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हैबररर न बताया है, विदेशी प्रतियोगिता के कारण कीमतों में आई हुई किसी एकाधिकारी के लाभ का कम कर दगी। किन्तु यह एक ऐसा परिवर्तन है, जो कि केवल राष्ट्रीय आय के वितरण में होता है और शायद इसे अवांछनीय भी नहीं कहा जायगा। वास्तव में हमें देखना तो यह चाहिये कि इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

एक एकाधिकारी, अनगिनत प्रतिस्पर्धी माहमिया (जिनकी कल्पना ग्राह्य न की है) के अनुमान, परिस्थिति पर सम्पूर्णता के साथ विचार कर सकेगा तथा वह भी निर्णय कर सकेगा कि बढ़ती हुई परिस्थितिया में कितनी मात्रा में उत्पत्ति

करना सबसे लाभदायक है। यह हो सकता है कि, यदि घटती हुई लागने अब भी प्रचलित रहे, उत्पत्ति में वृद्धि करना उसके लिए लाभदायक प्रमाणित हो (इसमें उसकी सीमान्त लागतें कम हो जायेंगी) और देश विदेश में यह मूल्य को और भी घटा कर अपनी बिक्री बढ़ा ले। इससे सम्पूर्ण समाज को तो कोई हानि नहीं है, हाँ, विदेशी बिक्री पर एकाधिकारी के लाभों में कुछ प्रतिवार्य कमी आती है। यदि वह ऐसा समझे कि विदेशी सम्पादकों की तुलना में उसे अपनी कीमत को घटाने से कोई लाभ नहीं है, तो फिर उसे ऊँची कीमत ही स्वीकार करनी चाहिए। इस दशा में यदि उद्योग की कुल मुद्रा-प्राप्ति का कुल मुद्रा लागतों से कम है, तो यह 'विशिष्ट घटक' (Specific factors) की समस्या के तुल्य है। उद्योग के विशिष्ट साधनों के लगान और आभात लगान (Quasi rents) गिरेंगे, और इतने पर भी यदि उद्योग की प्राप्ति का इसके अविशिष्ट सहयोगी साधनों के भुगतानों के लिए प्राप्ति न हो सके तो उद्योग ही बन्द कर दिया जायेगा। इससे राष्ट्रीय आय के आकार पर वैसे ही प्रभाव होवे जैसे विशिष्ट घटकों की दशा में होते हैं। किन्तु किसी भी दशा में उत्पादन शक्ति-शक्ति संकुचित (साथ में लागतों में निरन्तर वृद्धि) न होगा, जिसकी ग्राह्य में कल्पना की है।

उल्लेखनीय है कि संस्थानों के आकार में वृद्धि के फलस्वरूप घटती हुई लागतों की व्यापकता वस्तुधा के अप्रतिबन्धित अन्तराष्ट्रीय विनिमय के विरुद्ध कोई तर्क नहीं है, वरन् इसे पक्ष का ही एक तर्क कहा जा सकता है। कारण, अन्तराष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके फलस्वरूप बाजार का विस्तार बढ़ जाता है, जिसमें वही पैमाने के संस्थानों का अधिक प्रचलन उपयोग होना लगता है। इसके साथ ही साथ, बाजार के आकार का विस्तार एकाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को बढ़ावा देता है। यह लाभ आधुनिक युग में वही पैमाने के संस्थानों, बड़ी मात्रा की उत्पत्ति और एकाधिकार के प्रति जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके अन्दर्भ में छोटे देशों के लिये बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

(२) बाह्य मितव्ययितायें और घटती हुई लागतें—मार्शल (Marshall) ने दिखाया है कि वस्तु की उत्पादन लागत और उत्पादित-मात्रा के मध्य दुहरा सम्बन्ध होता है—एक ओर तो लागतें उद्योग के विभिन्न संस्थानों के आकार के साथ परिवर्तित होती हैं (जैसे—एक दिए हुए संस्थान की उत्पत्ति में वृद्धि होने पर उसे आन्तरिक मितव्ययितायें सम्भव हो जाती हैं जिस कारण लागतों में कमी आती है) तथा दूसरी ओर, सम्पूर्ण उद्योग के विस्तार द्वारा भी उद्योग में अलग-प्रत्येक संस्थान की लागतों में कमी आ सकती है। इस प्रकार, एक व्यक्तिगत संस्थान की लागतें न केवल अपनी उत्पादित मात्रा का परन्तु सम्पूर्ण उद्योग की उत्पादित मात्रा का भी फल होती हैं। यह सम्भव है कि अलग-अलग रूप से प्लान्ट (या फर्म) बढ़ती हुई लागतों के आधीन प्रियाशील हो, जिससे कि यदि इसकी उत्पत्ति अधिक (larger)

होती है वा औद्योगिक साधने की शक्ति, किन्तु सम्पूर्ण उद्योग का विकास प्रत्येक व्यक्तिगत मस्तिष्क के ऊपर की ओर बढ़त हुए सम्पूर्ण साधन तक को नीचा कर सकता है ।

बाह्य मितव्ययिताओं व अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैसे—निपुण श्रम की पूर्ण विवर्धन होना, यातायात एवं मदेनवाहन के साधनों में सुधार, उद्योग में काम आने वाली मशीनों के शुष्क एवं मूल्य में सुधार आदि । संश्लेषित रूप से यह धारणा की जा सकती है कि यदि उद्योग बढ़ी हुई मात्रा के प्रत्युत्तर में, नई पधों व प्रवेश द्वारा, अपना विस्तार करे, तो दीर्घकाल में (क्योंकि निरन्तर रूप से ऐसा विस्तार एवं दीर्घकालीन घटना है) वस्तु की लागत एवं मूल्य दोनों ही कम हो सकते हैं यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिगत मस्तिष्क की नागरता से, यदि उसमें अपनी उत्पत्ति बढ़ाई, वृद्धि हो जायेगी ।

प्रागर्थात्मिक एवं बाह्य बचतो में भेद—प्रागर्थात्मिक एवं बाह्य बचत में एक महत्त्वपूर्ण भेद है—प्रागर्थात्मिक बचत को, जो कि एक व्यक्तिगत मस्तिष्क के प्रकार में वृद्धि होने का परिणाम है, माहसीयण बचत सामंजस्य-शील अनुमानों में पूर्ण सम्मिलित कर लेते हैं । अतः ऐसी मितव्ययिताओं को प्राप्त करना व्यक्तिगत उपक्रम और पहल (private enterprise and initiative) पर निर्भर होता है । किन्तु, इसके विपरीत, बाह्य मितव्ययिताय उद्योग में सब उपक्रमियों को (कबल उन्हीं उप-विभागों को नहीं जो कि नये कारखाने स्थापित करते हैं या पुराने कारखानों का विस्तार करते हैं), भागान्वित करती है । ये स्वभावतः प्रविष्टिचन एवं प्रसृष्ट होती हैं, निम्नतः इनकी नीचा या मूल्य का पूरा अनुमान लगाया कठिन है । यही नहीं, इनका कुछ ऐसी घटका से भी सम्बन्ध है, जिनमें साहसी व तब नहीं होती, जैसे—एक निपुण श्रमिक जनसंख्या की क्षमताय । प्रायः माहसी ऐसे घाणियों पर ध्यान करने में हिचकता है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसने विनियोग का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, उसके प्रतियोगियों को नहीं । इससे यह स्पष्ट है कि बाह्य मितव्ययिताओं को प्राप्त करने का भार (जैसे—श्रमिकों की शिक्षा बोधा का कार्य) व्यक्तिगत मस्तिष्क पर नहीं छोड़ा जा सकता ।

उपयुक्त में निम्न निष्कर्ष निकलता है—संभव है कि कोई उद्योग पहले से ही बाह्य मितव्ययिताओं का लाभ उठा रहा हो और अधिक विस्तार द्वारा अधिक लाभ उठा सकता हो । किन्तु इसमें प्रतियोगिता बाधक है, जिससे अब अधिक विस्तार नहीं किया जायेगा । कारण, प्रत्येक व्यक्तिगत साहसी बढ़ती हुई लागतों के अधीन कार्य कर रहा है, जिनमें वह अपनी उत्पत्ति का विस्तार करने में कोई प्रेरणा नहीं पाता । उस प्रकार उद्योग का विस्तार तो होगा ही नहीं, लाभ ही, बढ़ती हुई विदेशी प्रतियोगिता के कारण उसकी उत्पत्ति में अनुचलन हो सकता है । यदि ऐसा अनुचलन हुआ तो इसमें उद्योग का अब तक जो बाह्य मितव्ययिताओं मिली हुई थी वे भी क्षीन जायगी और अनुचलन व पतनस्वरूप दण्ड हमारे सामने बच रहे

वाले सस्थानों की लागतों में वृद्धि हो जायेगी। ऐसे समय पर ही ग्राहम द्वारा उल्लेखित कुचक्र प्रयुक्त होता है। किन्तु यदि तट करो का सरकाय अस्थायी रूप से मिल जाय, तो उद्योग अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है तथा विस्तृत होकर बाह्य मितव्ययिताओं वा अधिक लाभ उठा सकता है।

किन्तु जैसा कि हैबरलर ने बताया है बाह्य मितव्ययिताओं की निम्न योग्य है — (अ) उद्योग का विस्तार कुछ बाह्य अमितव्ययिताओं (External Irreconomies) को जन्म दे सकता है, जिनमें प्रत्येक मस्थान की लागतें बढ़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, यातायात एवं संचार सम्बन्धी साधन अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। या, यदि उत्पत्ति साधन बढती हुई लागतों के अधीन उत्पन्न किए जा रहे हैं तो इनके लिए उद्योग की बड़ी हुई भाग उनकी कीमतें बढ़ा देती है। (ब) ऐसी प्रत्येक मितव्ययिता जोकि एक उद्योग के लिए बाह्य और दूसरे उद्योग के लिए आन्तरिक है, हमारे प्रस्तुत तर्क के क्षेत्र के बाहर है। उदाहरणार्थ, 'घ' उद्योग द्वारा प्रयोग की गई मशीनें यदि उन्हे वृद्ध सस्थानों में बनाया जाय तो वे अधिक सस्ती स्वयं की जा सकती हैं। मशीन निर्माता उद्योग के साहसरी इस सम्भावना से परिचित होने चाहिए। उन्हें अ उद्योग के विस्तार से ही प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी ओर से भी ऐसा कर सकते हैं। (ग) यदि उपरोक्त बातें ध्यान में रखते हुए भी हम यह जोर देकर कहें कि अतिसंस्पर्धा आन्तरिक और सम्भावित बाह्य मितव्ययिताये विद्यमान है, तो यह याद रखना चाहिए कि (१) उनमें से अधिकांश, (श्रम बाजार के उन्नत सञ्चयन के समान) एक उद्योग को ही नहीं बरन् अनेक उद्योगों को साथ ही साथ, अथवा, कुपि की अपेक्षा सम्पूर्ण उद्योग को लाभान्वित करती है।

उपसंहार—

यदि उपरोक्त बातों पर उचित ध्यान दिया जाय, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवार्य है कि घटती हुई लागतें अपने वास्तविक सैद्धान्तिक अर्थ में शायद ही क्रियाशील हो। यह बहुत ही असाधारण बात होगी कि बाह्य मितव्ययिताये कितनी भी लम्बी अवधि में बढती हुई लागतों की स्थायी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ले। मत यदि हम बढती हुई लागतों को ही क्रियाशील मानते हुए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का विवेचन करते हैं, तो कोई गम्भीर गलती नहीं करते।

परीक्षा प्रश्न :

१. उत्पत्ति ह्रास (या लागत वृद्धि) नियम की निष्पत्तीलता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव दिगताइये। (विश्वम, एम० ए०, १९६६)

[Show the effect of the operation of the Law of Diminishing Returns (Increasing Costs) on international trade]

- २ क्या यह उचित होगा कि उत्पत्ति वृद्धि (या लागत ह्रास) नियम के अधीन उत्पन्न की जाने वाली वस्तु के आयात की स्वतन्त्रता दी जाय ?

[Is it advisable to permit free imports of a commodity subject to increasing returns (decreasing costs) ?]

- ३ "स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत विशिष्टीकरण कुछ दशाग्रो में देश की उत्पादक सम्पत्ति को हानि पहुँचा सकता है।" इस कथन की आधुनिक लागत सिद्धान्त के प्रकाश में समीक्षा कीजिए।

['Specialisation under free trade might in some cases lead to the weakening of a country's productive conditions' (Ohlin) Examine this statement in the light of modern cost doctrine]

- ४ "यदि इन सब बातों को उचित महत्त्व दिया जाय, तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि घटती हुई लागतें, विशुद्ध सैद्धान्तिक अर्थ में, बन्धो-कभार और अपवाद भूत दशाग्रो में ही दिखाई देती हैं.... अतः हम यह मान कर कोई भारी वृद्धि नहीं करेगे कि सामान्यतः लागतें वृद्धिशील होती हैं।" (हैबरलर) आलोचना कीजिए।

["If due weight is given to all these considerations, one will be constrained to the conclusion that decreasing costs, in the true theoretical sense, are phenomena which occur only seldom and in exceptional cases... Hence we shall commit no grave error by continuing to assume, in general, that costs are increasing" (Haberler) Comment]

- ५ "यह दिखाया जा सकता है कि बढ़ती हुई लागतों का नियम अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के क्षेत्र को सीमित करता है, किन्तु घटती हुई लागतों का नियम उसे बढ़ाता है।" स्पष्ट कीजिए। (आमरा, पृष्ठ ९०, १९६८)

['It is demonstrable that the law of diminishing returns tends to limit the area of international exchange while that of the law of increasing returns is calculated to increase it' Explain]

राष्ट्रीय आय क वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव

(Effect of International Trade upon Distribution of National Income)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय आय क व्यक्तिगत (Personal) एवं कार्यात्मक (Functional) वितरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कारण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन का जनस्वरूप उपरि के विभिन्न साधनों की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाता है। प्रतिष्ठित एवं नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त में इस महत्वपूर्ण विषय पर दो जीपका के आधीन विचार किया गया है—(I) लगान (या लाभ) और मजदूरी पर प्रभाव¹ एवं (II) भूमिकों के प्रतिस्पर्धी वर्गों की आय पर प्रभाव²

(I) लगान, मजदूरी और व्याज (अथवा लाभ) पर प्रभाव

प्रतिष्ठित अधशास्त्रियों ने सर्वत्र यह माना कि विदेशी व्यापार एक ओर दृष्टक दशों और दूसरी ओर निमाणी दशों के मध्य हानि वाला व्यापार है। मत उन दिनों काय के कार्यात्मक वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव से आशय यह था कि मजदूरी लगान और व्याज (या लाभ) किस प्रकार निरपेक्ष रूप में (absolutely) और एक दूसरे के साथ सापेक्ष रूप में (relatively) परिवर्तित होते हैं।

(१) लगान (Rents)—जब एक देश और एक औद्योगिक देश के मध्य व्यापार प्रारम्भ होता है तो कृषक देश में कृषि वस्तुओं औद्योगिक देश को निर्यात की जायगी। निर्यात के लिए कृषि वस्तुओं की माग बढ़ने में कृषि का सीमांत विस्तृत होता है तथा इसलिए लगान बढ़ने लगते हैं। आधुनिक भाषा में भूमि आदनी माग की तुलना में अधिक दुर्लभ हो जाती है जिससे लगान बढ़ जाते हैं। कच्चे आकड़ों का निर्माण होने में मजदूरी और वात सम्पदा के स्वामिना की आय भी बढ़ जाती है।

¹ Bastable *Theory of International Trade* Chap 6

² Cairnes *Some Leading Principles of Political Economy*

किन्तु औद्योगिक देश में कृषि या सीमान्त सक्रिय होने लगता है तथा भूमि की दुर्लभता पहले से कम हो जाती है। इस प्रकार, उस देश में लगान (और खनिज तथा वन सम्पदा के स्वामियों की आय भी) घटने लगते हैं।

(२) मजदूरी (Wages)—निर्माण देश में खाद्यान्न सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि कृषि वस्तुओं का आयात हो रहा है और इस प्रकार, वास्तविक मजदूरियों (Real wages) में वृद्धि हो जाती है। साथ ही यह है कि औद्योगिक देश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की, जिसके बजट में आयातित वस्तुओं का समावेश हो, वास्तविक आय बढ़ जायेगी। किन्तु, सभी व्यक्ति एवं वर्ष एक समान लाभ नहीं उठाते। उदाहरणार्थ, आयातित वस्तुओं का उपभोग अधिक मात्रा में करने वाले व्यक्ति बड़ी हुई वास्तविक आय के रूप में अधिक लाभान्वित होते हैं दूसरी ओर, कृषक देश में, कृषि वस्तुओं के निर्यात के कारण, भोजन सामग्री महंगी हो जायेगी, जिससे अधिको एवं अन्य व्यक्तियों पर प्रतिशूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात् उनकी वास्तविक मजदूरियाँ कम हो जाती हैं। विदेशों से आयात के फलस्वरूप निमित्त वस्तुएं मनी हो जायेगी, जिस कारण अधिको की वास्तविक मजदूरी में हुई घटौती कुछ सीमा तक पूरी हो सकती है। किन्तु चूंकि उनकी आय का एक बड़ा अनुपात खाद्यान्न पर व्यय होता है। इसलिए उन्हें विदेशी व्यापार से कुल पर हानि ही रहेगी।

(३) व्याज (Interest)—यदि किसी देश के विदेशी व्यापार में साम्य की अवस्था है अर्थात् यदि उसके निर्यात उसके आयातों पर भुगतान कर देते हैं, तो स्वर्ण के आवागमन की समस्या खड़ी न होगी। सामान्यतः दीर्घ काल में तो साम्यवस्था ही पाई जाती है, किन्तु, अल्पकाल में वह शायद ही देखने में आवे। वास्तव में, अल्पकालीन की साधारणतः प्रचलित अवस्था "असाम्यता" ही है। यदि देश को निर्यात-आधिव्यय (Export surplus) है, तो स्वर्ण अर्थ-व्यवस्था में घायिका, जिससे मुद्रा की पूर्ति (Money-supply) बढ़ेगी और इसलिये व्याज दर घट जायेगी। इसके विपरीत, यदि देश का "आयात आधिव्यय" (Import surplus) है, तो अर्थ-व्यवस्था से स्वर्ण बाहर जायेगा, जिससे मुद्रा की पूर्ति घट जायेगी और इसलिये व्याज-दर बढ़ जायेगी।

(४) लाभ (Profits)—कृषक और औद्योगिक दोनों ही देशों में लाभ बढ़ने है, क्योंकि निजिस्टीकरण के द्वारा लागत कम हो जाती है तथा बड़े हुए बाजार ऊंची कीमतें दिलाते हैं।

कभी-कभी कहा जाता है कि जब एक ऊंची मजदूरी वाला देश (High wages' country) (जैसे अमेरिका) एक न्यून मजदूरी वाले देश (Low wages'-country) (जैसे कि चीन या जापान) से व्यापार करे, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मजदूरी पर प्रतिशूल प्रभाव डालता है। किन्तु यह बयान भ्रमपूर्ण है। प्रो० टॉलिन (Tausig) ने ठीक ही कहा है कि "सामान्यतः सबसे अधिक परिचित और सबसे अधिक निगाहार विश्वास यह है कि व्यापार में पूर्ण स्वतन्त्रता होने पर विश्व भर

की मीट्रिक मजदूरियों में समानता प्राप्त जायेगी— "यद्यपि ये समानीकरण (Equalisation) की ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है" मजदूरों की समस्या गगन में उत्प्लावकता की समस्या है। उद्योग की उत्पादकता जितनी अधिक होगी, मजदूरियों का सामान्य स्तर भी उतना ही ऊँचा होगा।¹

सम्पत्ति के वितरण पर विदेशी व्यापार के प्रभावों का अध्ययन करने के उपरोक्त प्रतिष्ठित दृष्टिकोण में दो दोष उल्लेखनीय हैं—प्रथमतः, यह स्थिर आय प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों की प्रेरणा करता है। दूसरे, यह सामान्य भी वास्तविकता के विपरीत है कि कुछ देशों के आयात पूरण 'प्रामाणिक वस्तुओं' के और कुछ देशों के निर्यात पूरण 'निमित्त वस्तुओं' के होते हैं। दृष्टान्त की सामग्री में उक्त विवेचन महत्वपूर्ण होते हुए भी अप्रामाण्य और भ्राम्यता से दूर है।²

(11) प्रतिस्पर्धा रहित समूहों की आय पर प्रभाव

श्रमिकों के 'अप्रतिस्पर्धी' या 'बन्द' समूहों का विद्यमान इस तथ्य पर आधारित है कि श्रम अनेक प्रकार का होता है। इस पर 'बन्द समूह' से दूसरे 'बन्द समूह' की अधिक कितनी न किसी बाधा के कारण प्राप्त जा सकती, किन्तु एक ही समूह के भीतर उनमें स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे मजदूरियों की समान दर प्रचलित हो जाती है। चूंकि श्रम एक विविधतामय साधन है, समांग साधन (Homogenous factor) नहीं, इसलिए सभी श्रमिकों के लिए समान मजदूरी दर प्रचलित होने की कल्पना लुप्त हो जाती है।

अप्रतिस्पर्धी समूहों की विद्यमानता का कीमत मयत्र पर जो प्रभाव पड़ता है उसका विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से विवेचन किया है। कैर्नेस (Cairnes) ने, जो कि इस धारणा के जन्मदाता है, विभिन्न बन्द समूहों की संख्या एवं इनका स्वभाव नियत और दिया हुआ माना है। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अंतर्गत, जो कि यह कल्पना करता है कि देशों के मध्य साधन गतहीन है, प्रत्येक देश की समग्र आय-प्राप्ति एक तरह से एक भिन्न

¹ "Perhaps the most familiar and most unfounded of all is the belief that complete freedom of trade would bring about an equalisation of money wages the world over.....There is no such tendency to equalisation " "the question of wages is at the bottom one of productivity The greater the productivity of industry at large the higher will be the general level of prices"—Toussig

² "This analysis is undoubtedly pertinent. At the same time, it is inadequate in that the three fold division of factors into land, labour and capital, and the corresponding three fold classification of incomes, is too great an over simplification of reality"—Haberer : *The Theory of International Trade*, p. 190.

अप्रतिस्पर्धी समूह हैं। उनका निष्कर्ष है कि यदि किसी देश विशेष के अन्दर अप्रतिस्पर्धी समूह विद्यमान है, तो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का सिद्धान्त (Theory of International Value) नाम्बू करने समझाया जा सकता है। एक ही देश के भीतर इन समूहों की एक दूसरे की वस्तुओं के लिए वारस्परिक मांग हो प्रत्येक समूह में मजदूरियों का स्तर निर्धारित करेगी।

वेर्नेम की तुलना में टॉर्जिय का विश्लेषण अधिक सहज है। वे समूहों की मर्यादा और स्वभाव को तदा के लिए निश्चित एवं दिया हुआ नहीं मानते। उनका मन है कि कम से कम दोषकाष्ठ में एक विशेष प्रकार के धर्म की मांग की, जो इसके उत्पादों के लिए मांग से उत्पन्न होगी है, उस विशेष समूह में मजदूरियों का स्तर निर्धारित करने वालों नहीं मान सकते। कारण धर्म की पूर्ति सम्बन्धी दशाओं को भी विचार में लेना आवश्यक है। वास्तव में, सम्भव तो यह भी है कि विभिन्न समूहों के मध्य मजदूरियों के सापेक्षिक स्तरों पर मांग का कोई प्रभाव न पड़े।

दोसरे समझाने। हेनरी मार्शल (Marshall) ने निम्न उदाहरण दिया है —
 “मान लीजिये कि समाज कई समतल भौगोलिक (Horizontal grades) में विभाजित है और प्रत्येक में इसके अपने ही सदस्यों के बच्चों में भरती की जाती है तथा प्रत्येक का अपने एक निजी जीवन-स्तर है। धन जब धारा बह जाती है तब मर्यादा में तेजी में वृद्धि होन लगती है तथा जब वह स्तर से गिर जाती है, तब तेजी से कमी होने लगती है। ऐसी दशा में माना पिना धारने नामकी को अपनी ही श्रेणी के किसी व्यवसाय के लिए तैयार कर सकते हैं किन्तु इससे ऊपर मुगमनापूर्वक नहीं उठा सकते और नीचे भी नहीं गिरने दे सकते।” इन साधनताओं के प्रथम किसी भी आधार में सामान्य मजदूरी (Normal Wage) वह होती जो कि नियमित रूप में रोजगार पलभ व्यक्ति को अपने और अपने सामान्य धारार वाले परिवार के लिए, अपनी श्रेणी के स्तर के अनुसार, भरल-पोषण का समुचित प्रवसर दे। वह माप पर निर्भर नहीं होती है। माप से तो उसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि यदि उन श्रेणी के धर्म के लिए मांग न हो, तो इससे सम्भव व्यवसाय भी बन्द हो जायेगा। अन्य शब्दों में, सामान्य मजदूरी धर्म के उत्पादन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है।”

मैक्रानिक अर्थशास्त्र की भाषा में यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्मों की पूर्ति स्थिर बावत पर की जाती है और उनका पूर्ति मज समतल (Horizontal) होती है। जब ऐसा है, तो फिर धर्म के परिवर्तन दीर्घकाल प्रत्यक्ष कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, केवल पूर्ति की मात्रा को ही प्रभावित करेगा। इस प्रकार, हमारे सामने दो परस्पर विरोधी धारणाएँ हैं—वेर्नेम के अनुसार इन बन्द समूहों का भौतिक धर्म की पूर्ति पूर्णतः वेर्नेम के अनुसार है किन्तु मार्शल के अनुसार (तुल्य धारणाओं के

अधीन) वह पूर्णतः लोचदार है अर्थात् केर्नेस के अनुसार वृत्ति वर्क नम्ब के रूप में (Vertical) होता है जबकि मार्शल के अनुसार वह समतल (Horizontal) होता है। मार्ग के परिवर्तन प्रथम दशा में केवल कीमत को प्रभावित करते हैं किन्तु बाद की दशा में केवल थम की प्रस्तुत मान को स्पष्टतः, विशिष्ट समूहों की तुलनात्मक स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रभाव पड़ेगा उसका विवेचन दोनों दशाओं में भिन्न-भिन्न होगा।

केर्नेस की कहपना में 'बन्द समूह' की समस्या—

मान लीजिए कि एक देश में 'बन्द समूह' विद्यमान है। विदेशों में कोई ऐसा परिवर्तन होता है, जिससे फलस्वरूप उस देश को इस समूह के उत्पादों में पहुँच की अपेक्षा अधिक तुलनात्मक हानि होने लगती है और इसीसे उन्हें अब विदेशों आयातों से अधिक कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से यूरोपीय कृषि में विदेशों से अनाज के बड़े हुए आयातों के दबाव के कारण कृषि-मजदूरों की मजदूरियाँ घट गई थी, उसी प्रकार, उपर्युक्त उदाहरण वाले देश में उस बन्द समूह के सदस्यों की मजदूरियों में भी पिरावट आ जाती है। किन्तु यदि उनकी मजदूरियाँ तेजी में गिरती हैं, तो अधिक इस समूह को कुछ समय के मरदर छोड़ते जायेंगे तथा इनका स्थान भरा न जायेगा। इस प्रकार केर्नेस का बन्द समूह एक पल्पकालीन उदाहरण है जबकि मार्शल का दीर्घकालीन।

टॉजिंग और मार्शल के 'बन्द समूह' की समस्या—

दूसरी ओर, यदि देश की बन्द समूह के उत्पादों में तुलनात्मक लाभ है और इसलिए वह इन्हें निर्यात करता है, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप मजदूरियों में वृद्धि हो जायेगी। यह बिल्कुल सम्भव है कि इस घुप के थम-सथ इतने पर्याप्त शक्तिशाली हो कि नये प्रवेसकों को रोक सके और इस प्रकार, समूह को 'बन्द' रख सके चाहे इसकी मजदूरियाँ अन्य समूहों से बहुत ही ऊँची हों। यदि यह सोचें कि लोचदार वृत्ति की मान्यता विश्व की वास्तविक परिस्थितियों से बहुत सङ्गत (Consistent) है, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि दीर्घकाल में विभिन्न समूहों की सापेक्षिक मजदूरियों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।¹

1 "The lines of social and industrial stratification in a country are determined chiefly by the conditions that prevail within its own limits—by the numbers in the several groups and their demands for each other's services, and in some uncertain degree by their different standards of living. An added impact of demands from a foreign country will rarely change the relative rates of wages which have come about from the domestic factors. The social stratification that results from the domestic

यदि उक्त परिस्थिति को मांशेन के उदाहरण का समोपित रूप समझा जाय, तो टाजिग के यह कहने पर भी कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या विभिन्न अर्थिक-समूहों की सापेक्षित स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है उनकी यह स्वीकारोक्ति कोई विरोधाभास नहीं कि विभिन्न प्रकार की अर्थभूतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वभाव पर प्रभाव डालती हैं। नि सन्देह यह एक देश में विद्यमान उन सामाजिक स्तरों और बन्ध समूहों से बहुत प्रभावित होता है जो कि अन्य देशों में विद्यमान नहीं हैं, वगैरें इससे कुछ प्रकार के अर्थ की पूर्तियाँ प्रचुर और मरनी हो जायें, इस सम्बन्ध में टाजिग ने जर्मनी का उदाहरण दिया है, जहाँ मुद्रा की प्रचुरता में योगदान समान-विशेषता और दूसरे गणायका की विद्यमानता के कारण यह देश रसायना और कोयला उपाद्यों का निर्यात करता है। जैसा कि हैबरलर (Haberler) ने कहा है, एक विशेष प्रकार के अर्थ की प्रचुर पूर्ति के विद्यमान होने का वही प्रभाव होता है, जो कि किसी अन्य साधन की प्रचुर पूर्ति का होता है—जैसे द्विप भूमि की प्रचुरता वाले देश कृषि के लिए विशेष उपयुक्त होने हैं। किन्तु साधनों की प्रचुरता है या नहीं इसका निर्णय माँग के सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है।

टाजिग की व्याख्या बुद्धिमत्तापूर्ण होते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में अ प्रतिस्पर्धी समूहों की समस्या, उस रूप में भी, जिसमें नि डो टाजिग ने प्रस्तुत किया है, सैद्धांतिक रूप से पूर्ण और व्यवस्थित नहीं है। अतः उसे हैबरलर ने अपने साम्य सिद्धान्त द्वारा अधिक स्पष्ट करने का यत्न किया है।¹ हैबरलर द्वारा प्रतिस्पर्धी समूहों की समस्या पर विचार—

“अर्थिकों के बन्द समूह न्यूनाधिक विशिष्ट साधनों की विशेष दशाएँ हैं, जो कि तकनीकी या अन्य कारणों से कुछ धनो तक ही सीमित हो गये हैं।”²

conditions is well established and seems to be deeply rooted, and it is non likely that international trade will impinge on it with such special effect on a particular grade as to warp it noticeably.”—*Tauszig International Trade*, pp 56-57

- 1 “... the treatment of non competing groups in the classical theory, even as he (Tauszig) presents it, cannot be termed theoretically complete and systematic It is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that we substitute our general theory for the simplifying assumptions of the Labour Theory of Value”—*Haberler: The Theory of International Trade*, p 193

- 2 “Closed groups of workers are obviously only special cases, in our terminology, of more or less specific factors, limited for technical or other reasons to certain employment”—*Ibid*, p 193.

उत्पत्ति के विभिन्न विशिष्ट और अविशिष्ट साधनों की सापेक्षिक दुर्लभता, सीमान्त उत्पादकता और इसलिए सापेक्षिक कीमतों पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन प्रस्तुत किये जा सकते हैं —

(१) उत्पत्ति के माध्यम अल्पकाल में विशिष्ट और गतिहीन होते हैं। जब वस्तुओं का आयात किया जाने लगता है, तो वे साधन, जो अभी तक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम थे, अब कम मूल्य जायेंगे, जिससे उनकी कीमतें गिरेगी।

(२) दूसरी ओर, “निर्यात उद्योगों” (Export industries) के लिए जिन विशिष्ट और गतिहीन साधनों की प्रापश्यकता पड़ती है उनकी माँग विदेशी व्यापार के फलस्वरूप बढ़ जायेगी। चूँकि उनकी सापेक्षिक दुर्लभता में वृद्धि हो गई है, इसलिए उनकी कीमतों में वृद्धि हो जायेगी।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो जाने से अनेक विभिन्न प्रयोगों में आ सकने वाले अ-विशिष्ट साधनों की कीमतें बढ़ जायेगी किन्तु यह वृद्धि प्रथम (२) के अन्तर्गत हुई वृद्धि से कम होगी। अन्य शब्दों में, प्रथम प्रकार के साधनों के स्वामियों की आय (वास्तविक आय), विदेशी, द्वितीय प्रकार के साधन स्वामियों की आय बढ़ेगी और तृतीय श्रेणी के साधन स्वामियों की आय बढ़ेगी किन्तु कम सीमा तक।

भूमि और उत्पत्ति के भौतिक साधनों में भेद—

हैबरलर में उत्पत्ति के भौतिक साधनों (Material means of production) एवं श्रम (Labour) में, विशेषतः दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, भेद किया है। उन्होंने बताया है कि, दीर्घकाल में, उत्पत्ति के भौतिक साधन जो कि अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, प्रमुखतः कृषि में पाये जाते हैं। ऐसे भौतिक साधनों में हम विभिन्न गुणों वाली भूमि तथा सब प्रकार के प्राकृतिक साधन सम्मिलित करते हैं यद्यपि सभी प्रकार के प्राकृतिक उपहार विशिष्ट नहीं होते। अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि निर्माण, वाणिज्य एवं यातायात में, अत्यधिक विशिष्ट भौतिक साधन दीर्घकाल में एक स्वरूप भूमिका रखते हैं किन्तु अल्पकाल में उनका बहुत महत्त्व होता है। कारण, अधिकाल भवन, प्लांट और मशीन-सामान, यातायात-साधन और अन्तरिम उत्पाद, जो कि एक विशेष समय पर विद्यमान होते हैं, विशिष्ट ही होते हैं। अतः विदेशी प्रति-योगिता की तीव्रता में वृद्धि होने से, या टैरिफों में घटा-बढ़ी होने प्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में परिवर्तन होने से सम्बन्धित उत्पत्ति साधनों की विशाल साम-हानियाँ हो सकती हैं।

अब श्रम को लीजिए। दीर्घकाल में और कुछ अपवादभूत दशाओं के अति-रिक्त श्रम सब दशाओं में श्रम सबसे कम विशिष्ट और सबसे अधिक समायोजनीय (Adaptable) साधन होता है। अल्पकाल में वह बहुत विशिष्ट और कम गतिशील होगा है। अतः जब आर्थिक पट-परिवर्तन के कारण एक उद्योग या एक फर्म में तो श्रम की माँग अधिक होती है किन्तु दूसरे उद्योगों या दूसरी फर्मों में कम, तो मजदूरियों

मे स्पाई या अस्पाई कमी आ जाती है। कुछ श्रमिकों का दुख बहुत बढ़ जाता है जो फिर विरोध-भाव को जन्म देता है। यह भी निर्विवाद है कि आधुनिक प्रगतिशयो में श्रम की गतिशीलता और समायोजनोपता को घटाने की प्रवृत्ति है। एक प्रोर सङ्घ ट्रिट श्रम की शक्ति आजकल बहुत बढ़ गई है, दूसरी ओर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का, जिसने कि भूतकाल में उद्योगों के मध्य श्रम का भागी पुनर्वितरण सम्भव बना दिया था (क्योंकि इसके कारण नये प्रवेशक विकासोन्मुख उद्योगों के मुटने सम्भव हो गये थे), स्थान स्थैतिक (Stationary) जनसंख्या ने से लिया है, जिससे अब पुनर्वितरण के अन्तर्गत पतनोन्मुख उद्योगों से श्रमिकों का विकासोन्मुख उद्योगों में वास्तविक आवागमन होने लगा है।

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दीर्घकाल में सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि दीर्घकाल में समस्त साधनों में श्रमिक सबसे कम विशिष्ट हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के फल-स्वरूप उत्पादकता में हुई सामान्य वृद्धि से श्रमिकों को लाभ होता है तथा उस पर राष्ट्रीय आय के कार्यात्मक वितरण में परिवर्तन होने का कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।¹ यही कारण है कि श्रमिक सच स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करते हैं। किन्तु अल्पकाल में विशिष्ट एवं गतिहीन श्रमिक समूहों को, विशिष्ट भौतिक साधनों के स्वामियों की भाँति ही, जबकि उन्हें एक न एक कारणवश अधिक तीव्र विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, आय में गम्भीर ह्रास सहना पड़ता है। विशेषतः जब अन्य वीमत्तों की अपेक्षा मजदूरिया कम लोचदार हो, ताँ हानि की गम्भीरता बढ़ जाती है। एक भौतिक साधन की वीमत्त इससे पहले कि उसका प्रयोग रोक जाय शून्य तक गिर सकती है किन्तु श्रमिक, जिन्हें सरकार के हस्तक्षेप और शक्तिशाली श्रम मण्डलों का सहारा प्राप्त है, मजदूरिया एक सीमा से अधिक गिरने की दशा में अपना श्रम नहीं बेचेंगे। फलतः बदली हुई परिस्थितियाँ से प्रभावित उद्योगों में भीषण बेकारी फैल सकती है।

1 "In the long run the working class as a whole has nothing to fear from international trade since, in the long run, labour is the least specific of all factors. It will gain by the general increase in productivity due to the international division of labour and is not likely to lose at all seriously by a change in the functional distribution of the national income."

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 195

परीक्षा प्रश्न :

१. आय के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या प्रभाव होते हैं ?
[What is the effect of international trade on income distribution ?]
२. देश में सम्पत्ति के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें पूर्णरूप से समझाइये । (आगरा, एम० कॉम०, १९६८)
[Explain fully the effects of international trade on the distribution of wealth in the country]
३. “टाउसिग द्वारा दी गई व्याख्या श्रम के अग्रतिस्पर्धी समूहों की बहुत सन्तोषजनक नहीं है और इसे एक अधिक पूर्ण एवं स्पष्ट व्याख्या द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जहाँ श्रम मूल्य सिद्धान्त की सुगम मान्यताओं के बजाय हम अपने सामान्य सिद्धान्त का ही उपयोग करें।” विवेचन करिये ।
[‘It (Tausig’s exposition of noncompeting groups of labour) is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that we substitute our general theory for the simplifying assumptions of the labour theory of value’ Discuss]

अन्तर्क्षेत्रीय साधन और वस्तु-आवागमन

(Interregional Factor and commodity Movements)

प्रारम्भिक—साधन-आवागमन से आशय एवं इसकी बाधाएँ

भूमि और प्राकृतिक साधन प्रायः अगतिशील (Immobile) होते हैं और इसलिए साधन-आवागमन की समस्या केवल श्रम और पूँजी में ही सम्बन्ध रखती है। श्रम के आवागमन में मुख्य बाधा व्यवसाय, स्थान और वातावरण के परिवर्तन तथा 'ज्ञान और निश्चित' दशा से अज्ञात और अनिश्चित' दशा में परिवर्तन के प्रति मनोवैज्ञानिक प्ररुचि होना है। इस प्ररुचि को दूर करने वाली प्रत्येक बाधा प्रयास, प्रथा और सामाजिक संस्थाओं सम्बन्धी भिन्नताएँ हैं। जहाँ मनोवैज्ञानिक घटक आवागमन या गतिशीलता के लिए अनुकूल होते हैं वहाँ वित्तीय साधनों का अभाव श्रम की गतिशीलता में बाधा डाल सकता है। अन्य शब्दों में, आवागमन के व्यय भी साधनों की गतिशीलता में बाधा प्रस्तुत करते हैं। पूँजी की गतिशीलता में भी प्रमुख बाधा मनोवैज्ञानिक ही है। पूँजी के स्वामी अपनी सम्पत्ति एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को भेजने में मकोच करते हैं, क्योंकि उन्हें यह आशंका रहती है कि एक विदेशी राष्ट्र में वे अपनी पूँजी के प्रयोग पर प्रत्यक्ष नियन्त्रण न रख सकेंगे अथवा उनकी पूँजी का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त बाधाओं के होते हुए भी श्रम और पूँजी-साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को घाते जाते हैं। ऐसे आवागमन का कारण ऊँची मजदूरियाँ अथवा ऊँची व्याज-दरें हैं। जिस क्षेत्र में श्रम और पूँजी साधन जायें, वहाँ मजदूरी और व्याज दरें इतनी ऊँची होनी चाहिए कि साधनों की मनोवैज्ञानिक एवं अन्य बाधाओं पर विजय पाने की प्रेरणा मिले। अतः साधन नीचे पुरस्कार वाले क्षेत्र से ऊँचे पुरस्कार वाले क्षेत्र को जाते हैं। अन्य शब्दों में, वे उस क्षेत्र से, जहाँ उनकी पूर्ति प्रचुर मात्रा में है, उस क्षेत्र को जहाँ उनकी न्यूनता होती है, जाते हैं।

साधनों के आवागमन के परिणामस्वरूप प्रचुरता वाले क्षेत्र में उनकी पूर्ति घटने लगती है और इसलिए वहाँ उनके पुरस्कार में वृद्धि होती है, किन्तु न्यूनता वाले क्षेत्र में पूर्ति बढ़ने से पुरस्कार कम होने लगते हैं। इस प्रकार, साधनों की अन्तर्क्षेत्रीय गतिशीलता साधन-कीमती में समानता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती

है। यथार्थ में हमारे सामने दो बयान हैं — (प्र) वस्तुओं का अन्तर्देशीय विनिमय न केवल वस्तु कीमतों में बरन् साधन-कीमतों में भी साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति रखता है, और (व) उत्पत्ति साधनों की अन्तर्देशीय यत्कीलता भी साधन-कीमतों में साम्य स्थापित करने की प्रवृत्ति रखती है। नीचे हमने साधन-आवागमनों और वस्तु-आवागमनों के मध्य सम्बन्ध दिखाया है।

साधन-आवागमनों और वस्तु-आवागमनों के मध्य सम्बन्ध

(१) साधन-आवागमन का स्थान वस्तु आवागमन द्वारा लिया जाना—

एक और यह सम्भव है कि क्षेत्रों के मध्य व्यापार खुलने से साधनों के आवागमन की कौड़ी आवश्यकता ही न रहे। अन्य शब्दों में, साधन-आवागमन का स्थान वस्तु-आवागमन द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। यदि दो क्षेत्रों के मध्य कोई व्यापार नहीं होता है, तो दोनों वस्तुओं और उत्पत्ति साधनों की कीमतों में विचाल भिन्नताएँ होंगी। किन्तु जब दो क्षेत्रों के मध्य अन्तर्देशीय व्यापार स्थापित हो जाता है, तो वस्तुओं की दौरे सामान्य की भी कीमतों में समानता (Equality) आ जायेगी। वस्तुओं के आवागमन (अर्थात् व्यापार) की मात्रा जितनी अधिक (और व्यापार में बाधों जितनी कम) होगी वस्तुओं की साधनों की कीमतों का साम्य भी उतना ही पूर्ण होगा। यदि सामान्य कीमतों में साम्य का क्षेत्र के मध्य साधनों का आवागमन नहीं हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि व्यापार पूर्ण और कम के अन्तर्देशीय आवागमन को अनावश्यक बनाता है और वस्तु आवागमन साधनों के आवागमन का स्थान ले लेता है।

(२) वस्तु आवागमन का स्थान साधन-आवागमन द्वारा लिया जाना—
क्षेत्रों के बीच का दूसरा पहलू भी है। साधनों का आवागमन वस्तु आवागमनों के स्थानापन्न का कार्य कर सकता है। यदि साधन-उत्पत्ति में अन्तर्देशीय भिन्नताएँ हैं, तो साधनों का आवागमन होने लगेगा जबतक इन क्षेत्रों की साधन-कीमतों का अन्तर इतना विशाल हो कि ऐसा आवागमन आर्थिक (Profitable) हो जाय। साधनों के आवागमन के फलस्वरूप साधन कीमतों में साम्य की स्थापना की प्रवृत्ति होती है और अन्ततः वस्तु-कीमतों के समानोन्मुख द्वारा (क्योंकि, यदि साधन-कीमतें समान हैं तो वस्तु कीमतें भी समान हानी चाहिए) वह अन्तर्देशीय व्यापार की आवश्यकता और इसके परिमाण (Volume) को घटाता है। इस प्रकार, साधन-आवागमन वस्तुओं के आवागमन का स्थानापन्न बन सकता है।

(३) अन्तर्देशीय कीमत तुल्यता पर प्रभाव—दोनों 'अन्तर्देशीय व्यापार' और 'अन्तर्देशीय साधन आवागमन' अन्तर्देशीय कीमत तुल्यता पर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। किन्तु एक की वृद्धि सदा ही दूसरे में कमरे जाती है। यदि मान लीजिए कि यातायात के साधनों में सुधारों के फलस्वरूप व्यापार में वृद्धि होती है, तो वस्तुओं और साधनों दोनों की कीमतों में पहले की अपेक्षा अधिक समानता आ जायेगी, जिस कारण साधन-आवागमन घट जायेगा। उसके विपरीत, यदि

साधनों की गतिशीलता में वृद्धि हो जाती है, तो दोनों क्षेत्रों में उनकी कीमतों के मध्य अधिक समानता आ जायेगी और ऐसा होने पर वस्तुओं के विनिमय में भी वमी हो जायेगी। ओहलिन (Ohlin) के शब्दों में—“सब कुछ जबकि व्यापार में घट बढ़ होनी है, तब इस बात पर निर्भर है कि साधनों की कीमतें और इसलिये उनका आवागमन कितनी गहन प्रतिक्रिया दिखाता है, और जबकि साधनों के आवागमन में घट बढ़ होती है, तब इस बात पर कि वस्तु-कीमतें और इसलिये व्यापार की कितनी गहन प्रतिक्रिया होती है।”¹

(४) विभिन्न क्षेत्रों के मध्य केवल वस्तुओं का आवागमन या वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आवागमन—ओहलिन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ देशों में क्षेत्रों के मध्य केवल वस्तुओं का आवागमन देखने में आता है। वस्तुओं का आवागमन दोनों क्षेत्रों में कीमतों की एक ऐसी समरूपता (Uniformity) स्थापित कर सकता है कि पूँजी और श्रम के अन्तर्देशीय आवागमन के लिये कोई आवश्यकता न रहे। यदि वस्तु और साधन कीमतों में पूर्ण तुल्यता न भी हो, तो माफ़न कीमतों में अन्तर इतना मूल्य हो सकता है कि साधनों की गतिशीलता स्व. जाय। ऐसी परिस्थितियों में साधनों की गतिशीलता कीमतों पर या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। दूसरी ओर, एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना (कम से कम सिद्धान्ततः) की जा सकती है, जिसमें केवल साधनों का ही आवागमन होता है, वस्तुओं का आवागमन नहीं। किन्तु यह परिस्थिति व्यवहार में देखने में नहीं आती है और इसलिए (ओहलिन के अनुसार) विभिन्न क्षेत्रों के मध्य या तो केवल वस्तुओं का अथवा वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आवागमन होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों के अध्ययन में साधन-एवं वस्तु-आवागमनों की भूमिका

यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार के परिवर्तनों का अध्ययन करते समय कीमतों में समानता लाने वाली उपर्युक्त दोनों प्रवृत्तियों को उचित महत्त्व दिया जाय। जैसा कि ओहलिन ने कहा है, “जब परिवर्तन, जो कीमत भिन्नताओं को बढ़ाने वाले हैं, निम्न दो प्रकार से संतुलित (Counter-balanced) हो जायेंगे—
(I) व्यापार में परिवर्तन के द्वारा, जो वस्तु कीमतों को प्रत्यक्ष और साधन कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, एवं (II) साधन-आवागमन के परिवर्तन

1 “Everything depends upon the intensity of the reaction of factor prices and, therefore, movements when trade varies; and upon the intensity of the reaction of commodity prices and, therefore, trade when factor movements vary.”—Bertin Ohlin. *Interregional and International Trade*, p. 169.

द्वारा, जो द्वितीय श्रेणी की कीमतों को प्रत्यक्ष और प्रथम श्रेणी की कीमतों को अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है। इस प्रकार, कीमत-समानिकरण की प्रवृत्ति दोनों में कार्य करती है।¹

(I) साधन-आवागमन में वृद्धि का व्यापार पर प्रभाव—

अब हम यह देखेंगे कि साधन-आवागमन में वृद्धि का व्यापार के स्वभाव और आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। उपर्युक्त विवेचन के सदर्भ में यह कह सकते हैं कि साधन-आवागमन में वृद्धि होने पर व्यापार का आकार सकुचित हो जायेगा। किन्तु, व्यवहार में, अन्ध घटकों पर भी विचार करना पड़ेगा। व्यापार का आकार (Volume) निम्न तीन घटकों पर निर्भर होता है —(१) साधनों की पूर्ति में अन्त-मानता, (२) विभिन्न क्षेत्रों में माँग का आकार, जो प्रत्येक क्षेत्र में वहाँ की राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर होती है, और (३) माँग की दिशा (Direction) इन तीनों ही घटकों पर साधन-आवागमन का प्रभाव पड़ता है।

(१) साधनों की बड़ी हुई गतिशीलता के फलस्वरूप उत्पादक साधनों की पूर्ति एक क्षेत्र में घट कर दूसरे क्षेत्र में बढ़ जाती है तथा प्रथम क्षेत्र में कुल आय दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा बहुत घट जायेगी।

(२) व्यापार का साधन-आवागमन की मात्रा पर भी निर्भर है और माँग की मात्रा सामर्थ्यनिष्ठों पर। साधन सम्बन्धी आवागमन माँग को दो तरह से प्रभावित कर सकते हैं (i) वे विभिन्न क्षेत्रों में कुल आयों के अन्ध सम्बन्धों को बदल सकते हैं। सामान्यतः, साधन प्रचुर पूर्ति वाले क्षेत्रों से स्थूल पूर्ति वाले क्षेत्रों को जाते हैं। वे दूसरे देश में राष्ट्रीय आय को बढ़ा देते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार में वृद्धि करते हैं। (ii) वे साधनों के उपयोग की कुशलता को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार सर्वत्र आय के सृजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के आकार में भी वृद्धि हो जाती है।

(३) साधनों के आवागमन माँग के स्वभाव की भी ओर इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा को प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से इस बारे में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है कि बड़ी हुई साधन-गतिशीलता का व्यापार की मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है

¹ "Variations which would increase price discrepancies will be counteracted both by a change in trade, which directly affects commodity prices and indirectly factor prices, and by a change of factor movements, which affects the latter prices directly and former indirectly. The tendency towards price equalisation thus operates in two ways"—*Ibid*, p. 170

उसका स्वभाव क्या होगा। सिद्धांततः वह साधन कीमतों और वस्तु कीमतों को समान बनावेगी और इस प्रकार व्यापार को समाप्त करने का कार्य करेगी। किन्तु व्यवहार में वह व्यापार की मात्रा को बढ़ा सकती है वशतः उसका उपर्युक्त तीनों घटकों पर प्रभाव सकारात्मक (Positive) हो।

(II) व्यापार के परिवर्तनों का साधन-आवागमन पर प्रभाव—

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि व्यापार में परिवर्तन हानि का साधन सम्बंधी आवागमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिद्धान्ततः, वस्तुओं के आवागमन में (अर्थात् व्यापार की मात्रा) में वृद्धि वस्तु कीमतों और साधन कीमतों को भी समान बनावेगी तथा ऐसी साम्यता स्थापित होने पर साधन-आवागमन रुक जायेगा। दूसरी ओर, यह भी सम्भव है कि अनुपयुक्त क्षेत्र यातायात के साधनों में सुधार के फल-स्वरूप उपयुक्त क्षेत्र बन जायें और अधिक भ्रम व पूँजी को आकर्षित करने लगे। यदि ऐसा हुआ, तो साधनों के आवागमन रुक जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उत्पत्ति-साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता परस्पर पूरक है, स्थानापन्न नहीं।

ग्रुं-विकसित देशों की विशेषताएँ एवं समस्याएँ—

आधुनिक विश्व को मोटे रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—विकसित, एवं अर्द्ध विकसित। यह विभाजन प्रायः प्रति व्यक्ति मोतव आय पर आधारित होता है। चूँकि प्रति व्यक्ति आय का कोई निश्चित माकार नहीं होता, इसलिये विभाजन देखा भी निश्चित और स्पष्ट नहीं होती। सामान्यतः सम्पूर्ण पश्चिमी संसार (कृष्य पूर्वी यूरोपीय देशों को छोड़ते हुए), सम्पूर्ण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और रूस आदि विकसित क्षेत्र हैं किन्तु शेष विश्व, जिसमें सभी एशियाई देश (जापान को छोड़ते हुए), सम्पूर्ण अफ्रीका (दो अफ्रीकी देशों को छोड़ते हुए) और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश सम्मिलित हैं, अर्द्ध-विकसित कहलाता है। स्वयं अर्द्ध विकसित देशों में भी प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में परस्पर महत्वपूर्ण भिन्नताएँ पायी जाती हैं। किन्तु इनकी निम्नलिखित सामान्य विशेषताएँ (Common features) भी हैं—

(१) इन देशों में अधिकांश लोग बहुत दरिद्र हैं और वह जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं कर सकते।

(२) उनकी आय बहुत ही न्यून है और अधिकांश के पास कोई बचत नहीं होती।

(३) राष्ट्रीय आय का एक माथूली अनुपात (लगभग १% से ७% तक) ही विनियोजन में स्वेगल किया जाता है।

(४) अधिकांश श्रमिक, प्रायः हाथ पैरों से ही, निष्कर्षण उद्योग (Extractive industries) में कार्य करते हैं। उनके अंगार, यदि कोई हैं, प्राचीन

और अर्पण्य होते हैं। वे जीवन निर्वाह के लिए प्रायः अनाज ही उत्पन्न करते हैं।

(५) उनके प्रसारण प्रायः अज्ञात होते हैं और जो प्रसारण ज्ञात (Known) है भी उनका अंश नही होने पाता है।

(६) चीन के अतिरिक्त सभी अर्द्ध-विकसित देश कुछ वर्ष पूर्व तक पश्चिम के प्रगतिशील देशों के उपनिवेशवादी प्रभाव के अन्तर्गत थे।

अर्द्ध-विकसित देशों की सहायता के दो रूप—

प्रत्येक अर्द्ध-विकसित देशों ने अपनी हानि में ही स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अब वे अपनी प्रत्यक्ष-उत्पादों का बाजार से सीधे विकास करना चाहते हैं, जिससे उनकी सर्ववृद्धिशील जनसंख्या के लिए पर्याप्त जीवन-निर्वाह सामग्री उपलब्ध हो सके और उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सके। किन्तु उन्होंने अपने उत्पादन साधनों के भण्डार में एक बात का घोर अभाव अनुभव किया है। यह अभाव है पूँजी का और तकनीकी ज्ञान का। वे अपना भौतिकीकरण करना चाहते हैं और इन सम्बन्ध में प्रगतिशील पश्चिमी देशों से सहायता की अपेक्षा रखते हैं।

इस सहायता के दो स्वरूप हो सकते हैं—(i) उत्पादक-साधनों का आवास-प्रवास (Factor Movements) इस स्वरूप के अन्तर्गत कुछ उत्पादक साधनों का, जो कि अर्द्ध-विकसित देशों में अर्पण्य है अथवा बिल्कुल ही अनुपस्थित है (जैसे—पूँजी, श्रम, बुनियादी कच्चे माल आदि) आवास-प्रवास होता है, एवं (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade or Commodity Movements) दुगके द्वारा अर्द्ध-विकसित देश ऐसे साधन, जो कि उनके यहाँ उपलब्ध नहीं हैं या अर्पण्य है, अपने निर्यातों के द्वारा भुगतान करके, प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमारे सामने समस्या यह निश्चय करने की है कि किम सीमा तक द्वितीय विकल्प अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वस्तु आवागमन पहले विकल्प अर्थात् साधन-आवागमन का स्थापनापन (Substitue) हो सकता है।

यह सीमा जहाँ तक 'व्यापार' साधनों की गतिशीलता का स्थापनापन है—

वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उत्पत्ति-साधनों की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता का स्थापनापन माना जा सकता है। किन्तु इसकी दो सीमाएँ हैं—प्रथम, व्यापार की मात्रा इतनी पर्याप्त और अर्द्ध-विकसित देशों के लिए इतनी लाभदायक होनी चाहिए कि वे भौतिकीकरण के लिए आवश्यक आपूर्तियाँ (Essential supplies) प्राप्त कर सकें, और द्वितीय, व्यापार द्वारा वह परिणाम सम्भव होना चाहिए जो कि अमेरिका, कनाडा आदि में विस्तृत फ़ालनू मूल्यवर्धों को घेरने के लिए, अर्द्ध-विकसित देशों से अनिश्चित श्रम (Surplus labour) के बड़े पैमाने पर होने वाले आवास प्रवास द्वारा सम्भव है। स्पष्टतः द्वितीय अर्थ एक राजनैतिक अवलोकन है, जिसका पूरा होना अनेकों राष्ट्रवाद के वर्तमान युग में कठिन है। यही नहीं, यह भी संदेहस्पद है

कि क्या देशों के दो वर्गों के बीच विदेशी व्यापार कभी भी वही परिणाम दिखा सकेंगा, जोकि एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त श्रम के आवास-प्रवास द्वारा दिखाया जा सकता है।

उत्पत्ति साधनों का प्रवास कहाँ तक सम्भव है ?

घट्ट-विकसित देशों की औद्योगिक देश बनने और इस प्रकार कम से कम समय के भीतर अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने की इच्छा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त एक अन्य ढङ्ग से अर्थात्, उत्पत्ति-साधनों के आवास-प्रवास द्वारा भी पूरी हो सकती है। सर्वप्रथम, निपुण श्रम और साज-सामान को सीजिए। निपुण श्रम (Skilled labour) विकसित देशों से घट्ट-विकसित देशों में जा सकता है और वहाँ बहुत ही सहायक प्रमाणित हो सकता है, क्योंकि इसके बल पर पिछड़े हुए देश औद्योगीकरण की लहर प्रारम्भ करने में समर्थ हो जायेंगे तथा कालान्तर में स्थानीय श्रम को इस योग्य बना सकेंगे कि जब विदेशों से आये हुए तकनीकी श्रमिक अपने देशों को लौटकर जायें तब वे उनका स्थान ग्रहण कर लें। किन्तु विदेशों से आने वाली पूँजी घट्ट-विकसित देशों में बनी रह सकती है यद्यपि उसे भी आयातक देश के निपुणों के अनुसार कार्य करना होगा। हाँ, लाभ को अक्षरम ही विदेशियों द्वारा अपने देश को प्रेषित किया जा सकेगा। यह भी सम्भव है कि प्रगतिशील देशों की सरकारें पिछड़े हुए देशों को औजार या बुनियादी उपभोग-वस्तुओं के रूप में पूँजी की भाण्ड दे और उनके श्रमिकों की तकनीकी प्रशिक्षण दें। पिछड़े हुए देशों को प्रगतिशील देशों एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद आदि) द्वारा भी ऋण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार, भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी माधन विश्व के प्रायः प्रत्येक भाग में जा सकते हैं।

किन्तु उत्पत्ति-साधनों का एक प्रवास होते रहने की भी एक सीमा है। कारण, व्यावहारिक कठिनाइयाँ साधनों का एक सीमित मात्रा से अधिक प्रवास नहीं होने देती हैं। फलतः पिछड़े हुए देशों के लिए यह भविष्यवाणी हो जाता है कि वे आयात का आश्रय लें। आयातों का मूल्य घुमाने के लिए वे अपने निर्यात वस्तुओं का बर्तन करते हैं। विदेशी मुद्रा के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए वे आयातों की न्यूनतम और निर्यातों की अधिकतम रचना चाहते हैं किन्तु उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होने पाती है। कारण, विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का दबाव आयातों को कम नहीं होने देता। यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति साधनों के प्रवास का एक अच्छा स्थानापन्न होता, तो उक्त सङ्कट उत्पन्न ही नहीं हो सकता था। अब, सङ्कट उत्पन्न होना इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति-साधनों के अन्तर्राष्ट्रीय आवास प्रवास का एक अच्छा स्थानापन्न नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। विकसित एवं घट्ट-विकसित देशों के मध्य विदेशी व्यापार का परिमाण (Volume) इतना पर्याप्त

नहीं होता कि पिछड़े हुए देश आयातों का भुगतान करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकें। निर्यात-आधिव्यय (Exportable surplus) के छोटे होने के दो कारण हैं—(i) उनकी राष्ट्रीय आय कम है, और, (ii) उनकी उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताएँ उनकी सदा बढ़ती हुई जनसंख्याओं के सदृश में निरन्तर बढ़ रही हैं। चूँकि राष्ट्रीय आय का आकार 'निर्यात-आधिव्यय' की वृद्धि के लिए एक पूर्व-शर्त है और यह (निर्यात-आधिव्यय का आकार) स्वयं भी राष्ट्रीय आकार की वृद्धि के लिए एक पूर्व-शर्त होता है, इसलिए अनेक कुचक्र (Vicious circles) बन जाते हैं। निम्नलिखित पिछड़े हुए देशों की सरकारें निर्यातों की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक सम्भव प्रयत्न करती हैं किन्तु इतना होते हुये भी निर्यात धीमे-धीमे बढ़ते हैं।

पूर्ति-पक्ष की कठिनाइयों के लिए तो क्या कहे, माँग पक्ष से भी कठिनाइयाँ उदय होती हैं। पिछड़े हुए देशों में परस्पर इस बात की प्रतियोगिता होती है कि वे अपने लिए अधिक से अधिक निर्यात बाजार प्राप्त करें। इस प्रतियोगिता के फल-स्वरूप व्यापार सम्बन्धी शर्तें (Terms of trade) उनके प्रतिकूल होने लगती हैं। कुछ पिछड़े हुये देश तो प्रतियोगिता को सहन नहीं कर पाते और प्रलय रहने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरी ओर, प्रगतिशील देश प्रायः लाभदायक शर्तें प्राप्त कर लेते हैं। कुछ प्रगतिशील देश अनेक वस्तुओं में, जो कि पिछड़े हुए देश उन्हे दे सकते हैं, आन्वेषण लगभग आरम्भ-निर्भर बने हुये हैं।

इस प्रकार, चूँकि माँग दुर्बल और आपूर्ति बेलाव है,¹ इसलिए व्यापार की शर्तें अनिवार्यतः प्रगतिशील देशों के पक्ष में रहती हैं। अनेक बलाओं में बला गया है कि विकसित देश पिछड़े हुए देशों को जो सहायता देते हैं उसका अधिकांश भाग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इनकी हानि के द्वारा निरूपभावि हो जाता है। अतः यदि प्रगतिशील देश उदार बन कर अर्द्ध-विकसित देशों के साथ सुव्यव शर्तों पर व्यापार करने को तत्पर हो जायें, तो यह आशा कर सकते हैं कि इन देशों को जिस विदेशी विनिमय-तकट का सामना करना पड़ता है उसमें कुछ कमी हो जायेगी।

उपसंहार—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दो देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पत्ति सामग्री के आवास-प्रवास का स्थानापन्न नहीं है। यह तो एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही आवश्यक है और ध्यान देने योग्य है।

परीक्षा प्रश्न :

- 1 'साधन आवागमन' से क्या आशय है ? वस्तु आवागमन से इनका सम्बन्ध दर्शाइये।

[What do you understand by the phrase 'Factor Movements' ?]

Demonstrate the relation between factor movements and commodity movements]

- २ “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों का अध्ययन करते समय कीमत-सुलभता स्थापित करने वाली प्रवृत्तियों को उचित महत्व देना चाहिए’—इस महत्व को स्पष्ट कीजिए ।

[‘The tendencies towards price equalisation should be given proper emphasis in any study of variations of international trade ?’ Explain what should be the proper emphasis]

तृतीय खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू

[THE MONETARY ASPECTS OF
INTERNATIONAL TRADE]

विद्वानों के विचार—

(१) सैमुअलसन (Samuelson)—' उन्नीसवीं शताब्दी का विदेशी ऋण लेन-देन दोनों प्रकार से कल्याणप्रद था—इससे उसे लाभ हुआ जिसे ऋण मिला और उसको भी लाभ हुआ जिसने ऋण दिया । निःसन्देह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त प्रबन्ध सदा ही इतनी सहज गति से नहीं चला क्योंकि कुछ विनि-योग अविवेकपूर्ण प्रमाणित हुए । उपनिवेशों की राजनैतिक समस्याओं तथा राष्ट्रवाद ने स्थिति को जटिल बना दिया, तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रथम महायुद्ध के बाद मन्द होती हुई अन्ततः टूट गई । ”

[Nineteenth-century foreign lending was twice blessed : it blessed him who gave and him who received. Of course international trade and finance did not always operate quite so smoothly, some investments proved unwise. Political problems of colonies and nationalism complicated the situation. And the whole process went away and broke down after World War I ”]

(२) नर्कसी (Nurkse)—'हमारा सामान्य विष्कर्ष यह है कि विनिमय दरों में कोई परिवर्तन करना उचित है या नहीं, इसका निर्णय मुख्यतः भुगतान सन्तुलन के सन्दर्भ में ही करना चाहिए । एक अधिक्य भुगतान सन्तुलन वाले देश को कभी भी अवमूल्यन नहीं करना चाहिए, उसे तो करेंसी के मूल्य में वृद्धि (Appreciation) करनी चाहिए । किन्तु जब भुगतान सन्तुलन निरन्तर घाटा दिखाये केवल तब ही अवमूल्यन के लिये राय दी जानी चाहिए । हाँ, कुछ विशेष दशाओं में, भुगतान सन्तुलन में साम्यता होने पर भी, अवमूल्यन को उचित ठहराया जा सकता है । ”

[“Our general conclusion is that the balance of payments must be the chief criterion for any changes in exchange rates. A country with a surplus in its balance of payments should never resort to devaluation, on the contrary, it might be asked to appreciate its currency. Only when a country's balance shows a persistent deficit can devaluation be approved, though in special cases, as we have seen it may be desirable to permit devaluation even if the balance of payments is apparently in equilibrium ”]

विदेशी भुगतान के साधन एवं ढङ्ग

(Means and Methods of Foreign Payments)

परिचय —

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रस्तुता (अर्थात् एक देश की अन्य देशों के प्रति देयता) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा एक देश से दूसरे देश को विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों के निरन्तर प्रवाहित होने के कारण उदय होती है और यह कार्य मौद्रिक प्रणाली (Monetary Mechanism) का है कि इसे दोनों (लेनदार एवं देनदार) देशों के लिए सबसे सुविधाजनक तरीके में निपटवाय। इस कार्य में प्रमुख कठिनाई स्पष्ट यह है कि प्रत्येक राष्ट्रजन स्वदेश की करेंसी को प्राथमिकता देता है। ऐसी प्राथमिकता के कई कारण होते हैं—प्रथम, वे स्वदेशी मुद्रा में भली-भाँति परिचित होते हैं और इसमें खरे-खोटे की पहचान कर सकते हैं। दूसरे, स्वदेशी करेंसी का मूल्य स्थायी (stable) रहता है, एक तीसरे विधिप्राप्त सम्बन्धी नियमों (legal tender laws) के कारण, जो कि देश के निवासियों को ऋणों के भुगतान में उनसे स्वदेशी करेंसी लेने पर विवश करने है, उन्हें स्वदेशी मुद्रा में अधिक विश्वास होता है। प्राथमिकता की इस भावना के फलस्वरूप ही विदेशी विनिमय की समस्या उत्पन्न होती है। प्रस्तुत खण्ड के विभिन्न अध्यायों में हम यह देखेंगे कि मौद्रिक प्रणाली इस समस्या को कैसे हल करती है।

विदेशी भुगतान की आवश्यकता

विदेशी भुगतान की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का परिणाम है। इन व्यवहारों के कारण ही एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों को भुगतान करते हैं। देश के राष्ट्रजनों और सरकार पर विभिन्न सातों में द्रव्य देने का भार पड़ता है और इसके निवटारे के लिए उन्हें द्रव्य भेजना (remit) पड़ता है। ऐसे विप्रेषणों के लिये यह आवश्यक है कि एक देश के द्रव्य को दूसरे देशों के द्रव्य से बदलन की व्यवस्था की जाय।

विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार—

देशों के मध्य द्रव्य के विप्रेषण की आवश्यकता जिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों से उदय होती है, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) वस्तुगत व्यवहार (Merchandise Transactions)—देशों के मध्य होने वाले सबसे स्पष्ट और सामान्य प्रकार के व्यवहार वस्तुओं के आवागमन से सम्बन्धित है। आयातों के लिये विदेशों को भुगतान करने का दायित्व आता है किन्तु निर्यातों के बदले में विदेशों से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार मिलता है। वस्तुओं के अतिरिक्त, बहुमूल्य धातुओं का भी आयात और निर्यात किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ के पश्चात् अनेक देशों ने मुद्रा अधिकारियों ने सोने और चांदी के आयात और निर्यात को बहुत ही सीमित कर दिया है। लेकिन, जब कभी इन धातुओं का आयात किया जाता है तो इनके लिए आयातक देश पर भुगतान करने की जिम्मेदारी आती है और जब इनका निर्यात किया जाता है, तो उन भुगतान पाने का अधिकार मिलता है। [उल्लेखनीय है कि जब सोने का आवागमन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के एक अङ्ग के रूप में होता है, तो उसे इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं करते।]

(२) पूँजीगत व्यवहार (Capital Transactions)—पूँजी के आवागमनों से भी देशों के मध्य विप्रेष उदय होते हैं। ऐसे आवागमन दीर्घकालीन हो सकते हैं या अल्पकालीन। (अ) दीर्घकालीन आवागमन—एक देश में रहने वाले व्यक्ति तथा वहाँ की स्थायें विदेशी नाइस, मिथोरिटीज सेयर्स एवं अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियाँ बरीदती हैं। एक सरकार भी दूसरी सरकार को ऋण देती है। एक देश के निवासी अन्य देशों में भूमि, भवन एवं अन्य संपत्तियों का क्रय करते हैं। भूतकाल में त्रिय गये ऋणों को लौटाया जाता है। विदेशियों से स्वदेश की सहायों के शोषण आदि पुनर्क्रय किये जाते हैं। इन सब कार्रक्तानों के कारण एक देश में दूसरे देश की भुगतान भेजने (अथवा विप्रेष) की आवश्यकता उदय होती है। (ब) अल्पकालीन आवागमन—पूँजी के अल्पकालीन आवागमनों में एक देश के निवा-
 १. द्वारा दूसरे देश में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय करना सम्मिलित है। एक के राष्ट्रजन विदेशी बैंकों में द्रव्य जमा करते हैं। इस प्रकार के पूँजी-आवागमन विभिन्न देशों में विभिन्न व्याज-दरों प्रचलित होने के फलस्वरूप उदय होते हैं और इनके कारण भी द्रव्य भेजने-भगाने की अर्थात् विप्रेषों की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

(३) सेवायें एवं अन्य व्यवहार (Services and other transaction)—एक देश के लोग विदेशी एजेन्सियों की विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे, एक देश की वैज्ञानिक-शिक्षण, इन्दोरेन्स एवं अन्य कम्पनियाँ दूसरे देशों के राष्ट्रजनों को सेवायें प्रदान करती हैं और इन सेवाओं के लिए पुरस्कार पाने की अधिकारी बनती हैं। पर्यटक एवं विद्यार्थी विदेशों की जाते हैं और वहाँ द्रव्य खर्च करते हैं। एक देश में रहने वाले विदेशी अपनी जाय या कुछ भाग अपने देशों को भेजते हैं। एक देश के राष्ट्रजन (एवं सस्यायें) विदेशों की दान एवं उपहार देते हैं। इन सब व्यवहारों के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान या विप्रेषों की आवश्यकता उदय

होती है। [इस धर्मो के व्यवहारो म किये गये विशेष प्राय अहस्य स्वभाव (invisible nature) के होते है, क्योंकि उनका पुरा रिकार्ड नही रखा जाता तथा इनके बारे मे सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नही होती है।]

विदेशी विनिमय की समस्या

जब कोई व्यक्ति एक ही देश म रहने वाले अन्य व्यक्ति को भुगतान करता है, तो वह इसके लिए देश मे ही प्रचलित विभिन्न प्रकार की मुद्राओ मे से किसी का भी प्रयोग कर सकता है। उदाहरणार्थ, जबलपुर म रहने वाला व्यक्ति अगरे मे रहने वाले व्यक्ति को रुपया छिपको म, कर्न्सी नाटो मे या एक भारतीय बैंक पर लिये गये धंका के रूप म भुगतान कर सकता है। ऐसे भुगतानो म कोई समस्या पैदा नही होती केवल द्रव्य को एक स्थान मे दूसरे स्थान पर भेजने की समस्या ही उठती है।

लेकिन, जब ऋणी और लेनदार अलग अलग देशो मे निवास करने लगे तब स्थिति कुछ भिन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ जब जबलपुर का व्यापारी लन्दन के व्यापारी से वस्तुये आयात करता है, तो वह रुपयो मे भुगतान कर सकता है लेकिन रुपया लन्दन के व्यापारी के लिए कोई उपयोग नही रखते, क्योंकि यह इंग्लैंड म विधि प्राप्ता नही है। अत दोनो पक्षो के लिए सन्तोषप्रद भुगतान तब ही सम्भव है जबकि रुपयो को पीछे मे बदलने की कोई व्यवस्था हो। या तो जबलपुर का व्यापारी पहले अपने रुपयो को पीछे मे बदले और फिर लेनदार का भेजे अथवा लन्दन का व्यापारी रुपयो मे भुगतान स्वीकार कर ले और फिर अपने देश की मुद्रा मे परिवर्तन कराने। अन्य शब्दो मे एक सुनियोजित विदेशी विनिमय व्यवस्था (foreign exchange mechanism) होना आवश्यक है। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों मे द्रव्य के स्थानान्तरण की समस्या के साथ ही साथ द्रव्य परिवर्तन की समस्या भी निहित है।

विदेशों को भुगतान भेजने के ढंग

विदेशो को भुगतान भेजने के निम्नलिखित ढंग है —

(१) धातुओं के स्थानान्तरण द्वारा—जैसा कि इस खण्ड के एक अगले अध्याय मे बताया है, स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशो को भुगतान करने मे स्वर्ण विण्ड या सिक्का प्रयोग किया जा सकता था। किन्तु स्वर्ण भेजने की लागत और अनुविधा इतनी अधिक थी कि इस ढंग का व्यापक रूप से प्रयोग नही हो सका। प्राय बैंक ही अपनी अभाव परत शाखाओ की सहायता के लिए, एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त कोष भेजते समय, स्वर्ण का प्रयोग करते थे। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के एन सामान्य साधन के रूप मे स्वर्ण का प्रयोग कभी नही हुआ।

(२) नगदी के स्थानान्तरण द्वारा—जबो-कभी ऋणी अपने देश की मुद्रा मे ही भुगतान कर सकता है और लेनदार उसे किसी बैंक से अपने देश की मुद्रा मे बदलवा सकता है अथवा ऋणी स्वय ही किसी बैंक को अपने देश की मुद्रा देकर विदेशी लेनदार के देश की मुद्रा प्राप्त कर सकता है और फिर लेनदार को भेज

सकता है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान जो अपार राशि में होते हैं इस ढंग से निबटारे जाने सम्भव नहीं है।¹

(३) साख पत्रों के स्थानान्तरण द्वारा—विदेशी भुगतान का सबसे प्रचलित ढंग साख पत्रों के प्रयोग का है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से एक विदेशी करेंसी खरीदता है तो उसे स्वदेशी मुद्रा के बदले में एक साख-पत्र प्राप्त होता है। यह साख-पत्र उसे अन्य देश की मुद्रा पाने का अधिकार देता है। साख-पत्र का वचान कर विदेशी तानदार को भेज दिया जाता है। इस प्रकार, बैंक में उपलब्ध होने वाले साखपत्रों का कि विदेशों में देय (payable) होते हैं, विदेशों करेंसी की पूर्ति का प्रतीक है और विदेशी भुगतानों के हेतु इनका नया 'विदेशी करेंसी के लिए माँग' का प्रतीक है।

विदेशी भुगतान के साधन

साख-पत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। विदेशी भुगतान के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों का विवरण नीचे दिया जाता है।

(१) बिल्ल ऑफ एक्सचेंज (Bills of Exchange)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में भुगतान का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय साधन बिल्ल ऑफ एक्सचेंज है। बैंकदार इसे निकाल कर ख़ुशी का देता है और ख़ुशी इस पर स्वीकृति देकर वापस भेज देता है। सम्प्रदाय लेखक (बैंकदार) यह बिल अपने ही देश में किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे उसनी ही रकम ख़ुशी के देश के किसी व्यक्ति को चुकानी हो, भेज देता है। फ़ौता उसे (बिल को) अपने बैंकदार के पास भेज देता है जो फिर इसका रुपया ख़ुशी (द्रायी) से परिपक्वता (due date) पर संग्रह कर लेता है।

प्रायः बिना को इनके बैंकदार (Drawee) की ओर से सत्याभूति (जैसे बैंकम ४. नि. गृह) द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर विदेशी बैंकों को कम परिचित व्यक्तियों के हस्ताक्षरों की तुलना में, । १ भुगतानपूर्वक स्वीकार्य होते हैं। जब बिल पर स्वीकृति हो जाए और वह लेखक के पास लौटकर आ जाय, तब लेखक उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के बजाय किसी बैंक में भुना सकता है और बैंक इसे या तो अन्य देश में अपनी शाखा को संग्रह के लिए भेज देता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे अन्य देश में भुगतान करने के लिए इसकी आवश्यकता हो, दे सकता है।

उल्लेखनीय है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा विदेशी भुगतान सम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय में एक दिशा में प्रत्येक भुगतान दूसरी दिशा में उतनी ही रकम के किसी अन्य भुगतान के साथ समुचित हो जाय।

¹ Haberler : *The Theory of International Trade*, p 15

(२) बैंक ड्राफ्ट्स और टेलीग्राफिक ट्रान्सफर्स (Bank Drafts and Telegraphic Transfers)—बैंक ड्राफ्ट बिल' के सदस्य होता है और इसे एक बैंकर द्वारा दूसरे बैंकर पर लिखा जाता है। ऋणी अपने बैंक से यह अनुरोध कर साता है कि वह उसे ऋण की रकम के लिए एक ड्राफ्ट बेच दे। ड्राफ्ट लेकर वह फिर इसे अपने विदेशी लेनदार को भेज देता है, जो इसकी रकम अपने देश में इस बैंक की शाखा में अथवा अन्य बैंक से जिसके साथ निर्गमित करने वाले बैंक (issuing bank) के व्यापारिक सम्बन्ध हो, संग्रह कर लेता है। भुगतान करने वाला बैंक निर्गमक बैंक (issuing bank) से रकम पाने का अधिकारी हो जाता है और यह रकम उसे एक विपरीत दिखाई ड्राफ्ट या अन्य साधन द्वारा मिल सकती है।

चूँकि बैंक ड्राफ्ट साधारण ढाक से मँगाया-भेजा जाता है, जिसमें बहुत समय लग जाता है और इस बीच कोष अटके पड़े रहते हैं, इसलिए टेलीग्राफिक या कैबिल ट्रांसफर द्वारा भुगतान करना अधिक अच्छा साधन समझा जाता है, क्योंकि इसमें समय कम लगता है। ट्रांसफर बेचने वाला बैंक अन्य देश में अपनी शाखा को तार द्वारा यह आदेश देता है कि एक विशेष व्यक्ति को अमुक रकम चुका दी जाय। इस प्रकार प्रायः तीन दिन के भीतर ही लेनदार को रकम मिल जाती है।

(३) चेक (Cheque)—अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में बैंकों का महत्त्व और प्रयोग बहुत बढ़ गया है। विदेशों में अच्छी ख्याति रखन वाली एक मुपरीचित फर्म अपने विदेशी लेनदार को बैंक भेजकर भुगतान कर सकती है। वह बैंक फर्म द्वारा अपने ही बैंक पर लिखा जाता है किन्तु प्राप्तकर्ता (payee) इसका अपने देश की किसी बैंक से अपनी कहींसी में ही भुगतान प्राप्त कर लेता है। क्यन्कर्ता बैंक इस रकम को (ऋणी के देश के) ड्राफ्टी बैंक से पाने का अधिकारी हो जाता है और प्रायः एक विपरीत दिखाई प्रेषण द्वारा उनका आपस का खाता चुक जाता है। एक देश के बैंकों पर लिखे गये बैंक अन्य देश के बैंकों द्वारा जबकि दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्ध हो (जैसे भारत और नेपाल अथवा नयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा) प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक प्रतिष्ठित (honour) किये जाते हैं।

(४) साक्ष-पत्र (Letter of Credit)—साक्ष पत्र वह प्रमेत है जो एक व्यक्ति को निर्गमक बैंक पर एक निश्चित रकम का बिल या बैंक निखाने का अधिकार देता है। समुचित प्रमाणित देकर आयातकर्ता किसी भी बैंक से अपने पक्ष में साक्ष खुला सकता है। जब ऐसा किया जाता है तब बैंक अपने ग्राहक (आयातकर्ता) को एक साक्ष-पत्र जारी कर देता है और इसके आधार पर आयातकर्ता उस बैंक पर बैंक निखकर (अथवा निर्यातकर्ता बिल लिखकर) भुगतान ले-दे सकते हैं। चूँकि भुगतान को जिम्मेदारों वहाँ बैंक ने स्वीकार की हुई है, इसलिए साक्ष का लक्ष्य कराने में निर्यातकर्ता को तनिक भी संकोच नहीं होता।

विदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए भी सेंटर ऑफ क्रेडिट बहुत उपयोगी होते हैं। पूरा मूल्य और कमिशन मिलने पर बैंक पर्यटक के पक्ष में एक साक्ष-पत्र

जारी कर देता है जिसके आधार पर वह उस बैंक की विदेश स्थित शाखा (या एजेंट) पर चंफ निकालकर स्वयं प्राप्त कर सकता है।

(५) यात्री चैक (Travellers' Cheque)—विदेश जाने व्यक्तियों को वैयक्तिक यात्री चैक भी निर्गमित करते हैं। यात्री चैक एक बैंक द्वारा अपने को ही दिया हुआ यह आदेश है कि चैक में उल्लिखित व्यक्ति को एक निर्धारित रकम का भुगतान कर दिया जाय। जब व्यक्ति पूरा मूल्य और कमीशन बैंक में जमा करा देता है, तो बैंक द्वारा उसे यात्री चैक हस्त्य कर दिया जाता है जिसे वह अपने विदेश भ्रमण के दौरान उस बैंक की विदेश स्थित शाखा या कारम्पा-डेंट बैंक (correspondent bank) में भुना सकता है। पहचान के लिए निर्गमन के समय ही बैंक पर कृता को हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं और भुनाते समय वह जा हस्ताक्षर करें उसमें इनका मिलान कर लिया जाता है। पश्चिमो देशों में यात्री चैक बहुत प्रचलित है।

विदेशी विनिमय बाजार (Foreign Exchange Market)

विदेशी विनिमय बाजार का अर्थ—

जिम व्यक्ति के पास खर्चने के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो वह इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं बेचता, बल्कि इस कार्य में एक बिल ओकर (जो बिल को उससे खराद लेता है) अथवा एक बैंक (जो बिल को भुना लेता है) की सहायता लेता है। इसी प्रकार जिम व्यक्ति को बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदना है वह स्वयं ही ऐसे व्यक्ति को गलास नहीं करता जिसके पास बिल विक्रय हो बल्कि वह किसी बैंक या बिल श्रानर के पास जाता है जो उसे बिल या बैंक ड्राफ्ट बेच देता है। इस प्रकार मध्यस्थों के कारण बिलों या ड्राफ्टों के त्रय विक्रय का कार्य बहुत सुगम हो जाता।

। ध्यान रहे कि बिल या ड्राफ्ट स्वयं में विदेशी मुद्रा नहीं होते बल्कि विदेशी मुद्रा अधिकार दिलाने वाले प्रपत्र होते हैं। विदेशी मुद्रा पर अधिकार दिलाने वाले प्रपत्रों का काम करने वालों, बेचने वालों एवं इसके मध्य मध्यस्थता करने वालों को सामूहिक रूप से 'विदेशी विनिमय बाजार' कहते हैं। विदेशी विनिमय बाजार कोई विशेष स्थान (अर्थात्—स्टॉक एक्सचेंज) नहीं होता जहाँ कि क्रैता बिक्रेता एक दूसरे के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आते हैं और त्रय विक्रय करते हैं बल्कि यह एक ऐसा सम्पूर्ण क्षेत्र है जिसमें क्रैता और बिक्रेता फैले हुए हैं कारण यातायात एवं संचार साधनों की प्रगति के फलस्वरूप अब उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क आवश्यक नहीं रह गया है।

स्वतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धित विदेशी विनिमय बाजार—

आजकल विदेशी विनिमय बाजार स्वतन्त्र (free) नहीं है क्योंकि प्रायः सभी देशों में इसके कार्यक्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे—मुद्रा अधिकारियों द्वारा विदेशी विनिमय की दरों पर नियन्त्रण रखा जाता है वे ही आयातकों में विदेशी करेंसी या आपूर्तियाँ (Supplies) का वितरण करते हैं और यह आदेश जारी करने वाले ही विदेशी करेंसी निर्यातक प्राप्त करें उस केवल निश्चित व्यवहारियों (dealers)

को ही बेचा जाय। विदेशी देशों में ऋण लेने या ऋण देने पर भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। हाँ, प्रथम महायुद्ध के पूर्व एवं दो महायुद्धों के बीच के कुछ वर्षों में विदेशी विनिमय बाजार स्वतन्त्ररूप से निर्यातीय थे। [सुगमता के लिए विदेशी विनिमय दलों के सिद्धान्त का अध्ययन एक स्वतन्त्र विनिमय बाजार के गन्दर्भ में ही किया जायगा।]

विदेशी विनिमय के व्यापारी—

विदेशी विनिमय बाजार में व्यवहार करने वाले (dealers) को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—(अ) सहायक व्यापार के रूप में विदेशी करेंसी का क्रय और निर्यात करने वाले व्यापारी एवं (ब) मुख्य व्यापार के रूप में विदेशी करेंसी का क्रय निर्यात करने वाले व्यापारी। प्रथम वर्ग में वस्तुओं के या विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रेता सम्मिलित होते हैं किन्तु दूसरे वर्ग में बैंक डिस्काउन्ट गृह, विल ब्रोकर आदि आते हैं।

(१) बैंक—विदेशी विनिमय बाजार के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी बैंक (Banks) होते हैं। विदेशी विनिमय में व्यवहार करने वाले बैंक विदेशी देशों में अपनी शाखाएँ रखते हैं। प्रत्येक शाखा पर पर्याप्त कोष रखा जाता है। यदि किसी देश में बैंक की शाखा नहीं है तो वहाँ कोष किसी अन्य बैंक के पास, जो उसके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिये उत्तर हो, रखा जाता है। ऐसे बैंकों को 'कोरस्पोंडेन्ट बैंक' (correspondent banks) कहा जाता है। इस प्रकार विनिमय व्यवहार करने वाले बैंकों की मध्या में अनेक शाखाओं और कोरस्पोंडेन्ट के द्वारा सारे संसार में उपलब्ध हो जाती है। ये बैंक विला को बेचने भुगतान तथा इन किसी की रकमें संग्रह करते हैं एवं बैंक ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर तथा अन्य साधन-पनों का निर्वाहन करते हैं। एक देश में वहाँ किसी विनिमय बैंक के पास द्रव्य जमा कराके तथा विदेशी तैन्धार को इसकी शाखा या कोरस्पोंडेन्ट के द्वारा भुगतान करने से एक देश में दूसरे देश की द्रव्य का विप्रेषण सम्भव हो जाता है। स्मरण रहे कि विदेशी विप्रेषण के फलस्वरूप यदि एक केन्द्र (देश) में बैंक के कोष बढ़ते हैं, तो दूसरे केन्द्र (देश) में घटते हैं।

(२) विलों के दलाल—यह लोग विलों के नेताओं और विक्रेताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करते हैं। सम्भव है कि किसी व्यक्ति के पास कोई विदेशी विल हो और उसे विदेशी-विनिमय-बाजार के विषय में अधिक जानकारी न हो। ऐसी दशा में वह अनुभवी एवं कुशल विल ब्रोकरों की सेवाओं का लाभ महित प्रयोग कर सकता है। एक अनुभवी विल-ब्रोकर उसे अधिक अनुकूल शर्तें मिलाने में सहायक होता है। वह या तो स्वयं ही विल का क्रय करता है। या उसे किसी बैंक से भुगतान देता है; और बाद में अन्य व्यापारियों को या बैंकों को, जिन्हें विदेशों में भुगतान भेजना हो, बेच देता है। स्मरण रहे कि विल-ब्रोकर एक मध्यस्थ मान है जो बर्गीकरण पर प्रयत्नित करते रहते हैं, वह बैंकों की भाँति, जोकि खुद ही ड्राफ्ट और विल खिना करते हैं, व्यापारी नहीं होते।

(३) स्वीकृति गृह—विदेशी विप्रेषण कार्य में स्वीकृति गृह (Acceptance House) भी सहायता करते हैं। एक विप्रेषककर्त्ता, जिसे विदेशी देशों में कोई नहीं जानता या कम जानता है, किसी स्वीकृति-गृह से साक्ष प्राप्त कर सकता है। जब ऐसा करता है, तो सम्बन्धित स्वीकृति गृह उस पर लिखे गये बिल को उसकी ओर से स्वीकृत कर लेता है। स्वाभाविक ऐसा बिल सुगमतापूर्वक विपणन-योग्य (readily marketable) होता है।

विदेशी विनिमय बाजार में ग्राहक—

जो लोग अपना व्यापार (विदेशी करेंसी के क्रय अथवा विक्रय का व्यापार) बाजार में लाते हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बाँट सकते हैं :—

(अ) सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक-वर्ग वस्तुओं का आयात और निर्यात करने वाले व्यापारियों का है। एक देश में निर्यात कर्त्ता (exporters) के पास बेचने या भुगतान के लिये बिस्स होते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने विदेशी देनदारों से प्राप्त किया है। इस प्रकार वे विदेशी करेंसी के विक्रेता हैं। दूसरी ओर आयातकर्त्ता (importers) बिलों या ड्राफ्टों का क्रय करते हैं क्योंकि उन्हें विदेशी देनदारों को भुगतान करना है। इस तरह यह लोग विदेशी करेंसी के क्रेता हैं।

(ब) देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले यात्री भी विदेशी करेंसी में क्रेता-विक्रेता होते हैं। विदेशी पर्यटक अपने साथ यात्री-बैंक, साल-बन एव अन्य प्रत्येक लाते हैं और इन्हें देश में बैंकों को बेचते हैं। किन्तु देश में बाहर जाने वाले पर्यटक विदेशी करेंसी सम्बन्धी ऐसे अधिकार पत्रों को खरीदते हैं।

(स) विदेशी देशों में ऋण लेने और देने वाले व्यक्ति ग्राहकों के तीसरे वर्ग में सम्मिलित किये जाते हैं। जो व्यक्ति विदेशी स्टॉक एव प्रतिभूतियाँ खरीदने में इच्छुक हैं या जिनके पास अन्य देशों की बैंकों में जमा करने हेतु अल्पकालीन शोध होते हैं वह विनिमय बाजार में विदेशी करेंसी सम्बन्धी अधिकारों (claims on foreign currency) का क्रय करते हैं और जो व्यक्ति विदेशी देशों से उधार लेते हैं, उनके पास बेचने के लिये विदेशी करेंसी होती है। व्यक्ति एव संस्थाएँ (जैसे-बैंक, इन्स्यूरेंस कंपनियाँ), जो विदेशी पूँजी बाजारों में ऋण प्राप्त करना चाहती हैं, अपने एजेण्टों के द्वारा वहाँ डॉल्म और रोयर्स बेच कर ऋण प्राप्त करती हैं। इसमें उन्हें विदेशी करेंसी पर अधिकार मिल जाता है जिसे बाद में वह अपने देश के विनिमय बाजार में बेच देती हैं।

(द) सरकारें भी विनिमय बाजार में व्यापार करती हैं। प्रायः एक सरकार अपने निजी प्रयोग के लिये वस्तुओं का आयात करती है और इन वस्तुओं का भुगतान करने के हेतु विदेशी करेंसी खरीदना आवश्यक हो जाता है। यही नहीं, एक सरकार दूसरी सरकार को ऋण भी देती है। इसमें उधार लेने वाली सरकार को उधार देने वाले देश की करेंसी प्राप्त हो जाती है जिसे बाद में उधार लेने वाले देश के विनिमय बाजार में बेचने के लिए प्रस्तावित (offer) किया जाता है।

(य) स्वतन्त्र विनिमय बाजार में सटोरिये (speculators) भी उपस्थित होते हैं और विदेशी करेंसी का क्रय-विक्रय करते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य विदेशी करेंसी का मूल्य घटने-बढ़ने की सम्भावनाओं से लाभ कमाना है, सामान्य ग्राहकों की भाँति, वास्तविक भुगतान लेना-देना नहीं है। जब विनिमय-दरों में तेज उतार-चढ़ाव होने है, तो उनके कार्यकलापों में बहुत तेजी आ जाती है।

विदेशी भुगतान की काय विधि

अब हम यह देखेंगे कि विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में वास्तव में क्या कार्य-विधि अपनाई जाती है। तथा बैंकों और अन्य मध्यस्थों की क्या भूमिका होती है।

आयातकर्ता की दृष्टि से—

आयातकर्ता निम्नलिखित किसी भी तरीके द्वारा अपने निर्यातकर्ता को भुगतान कर सकता है —

(१) डाक द्वारा करेंसी भेजना—(अ) वह डाक द्वारा अपने देश की करेंसी भेज सकता है, जिसे निर्यातकर्ता अपने बैंक में डिपोजिट कर देता है और बदले में बैंक उसके खाते में रकम उसके देश की मुद्रा में क्रेडिट कर देता है। अथवा (ब) वह किसी बैंक या विनिमय-दलाल से निर्यातकर्ता के देश की करेंसी प्राप्त करके इसे डाक द्वारा निर्यातकर्ता को भेज सकता है। किन्तु इस तरीके द्वारा निपटायें जाने वाले विदेशी भुगतानों की मात्रा बहुत ही थोड़ी होती है।

(२) बैंक भेजना—वह अपने देश में किसी बैंक पर लिखे गये बैंक को भेज सकता है, जिसे निर्यातकर्ता अपने देश में अपनी बैंक में जमा करा देता है। यह बैंक भेजने वाले के देश में अपने कोरस्पोंडेंट बैंक को उस बैंक को संप्रत्यक्ष प्रेषित कर देता है तथा इस प्रकार आयातकर्ता के देश में 'क्रेडिट बलेंस' प्राप्त कर लेता है।

(३) बैंक ड्राफ्ट या टेलीग्राफिक ट्रान्सफर भेजना—वह अपने बैंक से एक बैंक ड्राफ्ट बन करके डाक द्वारा लेनदार को भेज सकता है। लेनदार इसे अपने देश में अपने बैंक में जमा करा देता है और वह बैंक ड्राफ्ट बैंक के कोरस्पोंडेंट बैंक से उस ड्राफ्ट का भुगतान मगह कर लेता है। [यदि तुरन्त भुगतान करना हो, तो बैंक ड्राफ्ट के बजाय टेलीग्राफिक ट्रान्सफर तरीका आ सकता है।]

(४) बिल क्रय करके भेजना—निर्यातकर्ता के देश में किसी अन्य व्यक्ति पर लिखा गया एक बिल जो उतनी ही रकम का हो जितनी कि उसे चुकानी है, किसी बैंक या बिल बाँकर से खरीद कर वह निर्यातकर्ता को भेज सकता है और फिर निर्यातकर्ता उस बिल का भुगतान बिल के स्वीकर्ता से अपने बैंक के द्वारा प्राप्त कर सकता है।

(५) बिल पर स्वीकृति देना—आयातकर्ता निर्यातकर्ता से स्वयं पर एक बिल लिखने का अनुरोध कर सकता है। स्वीकृति के पश्चात् निर्यातकर्ता उस बिल को अपने बैंक से भुना सकता है। भुनाने वाला बैंक इसे आयातकर्ता के देश में स्थित अपने कोरस्पोंडेंट को भेज देता है जो परिपक्वता पर इसका रकमा आयातकर्ता से

सम्रह कर लेता है। अथवा भुनाने वाला बैंक यह भी कर सकता है कि सम्बन्धित बिल उस देश में किसी आयातकर्ता को बेच दे। यह आयातकर्ता इसे अपने लेनदार को भेज देता है और लेनदार अपने बैंक से, बिल बेच कर रपया प्राप्त कर लेता है। परिपक्वता पर यह बैंक अपना रपया स्वीकर्ता से वसूल कर लेता है। इस कार्य विधि से सम्बन्धित विचोतिये बैंक अपना साधारण कमीशन अर्जित कर लेते हैं और बिल भुनाने समय म्याज वाटकर बिल को रकम चुका देते हैं।

निर्यातकर्ता की दृष्टि से—

(१) साधारण दस्तावेज से बिल लिखना—यदि निर्यातकर्ता आयातकर्ता से भरोसा-भरित परिचित है, और उसे इसकी ईमानदारी और शोचनमता में विश्वास है, तो वह वस्तु जहाज द्वारा भेज सकता है और साधारण रूप से उस पर बिल लिख सकता है। पाय में वह इसे (बिल को) अपने बैंक से भुना लेता है या स्वीजरण एव सम्रहण हेतु सीप देता है।

(२) दस्तावेजी बिल लिखना—यदि निर्यातकर्ता को आयातकर्ता पर पूर्ण विश्वास नहीं हो, तो वह आयातकर्ता पर एक विशेष प्रकार का बिल लिख सकता है, जिसे 'स्वीकृति पर प्रलेखों की सुपुर्दगी वाला बिल' (Documents against Acceptance or D/A Bill) कहते हैं। इस दशा में माल के अधिकार-पत्रों को, जिनके आधार पर आयातकर्ता जहाजी कम्पनी से माल छुड़ा सकेगा सीधे आयातकर्ता को न भेजकर बिल के साथ गयी करके किसी बैंक के द्वारा भेजा जाता है। यह बैंक बिल स्वीकार करने पर ही माल के अधिकार पत्र आयातकर्ता को देगा अन्यथा नहीं।

(३) यदि आयातकर्ता पर और भी कम विश्वास हो, तो निर्यातकर्ता उस पर 'भुगतान करने पर प्रलेखों की सुपुर्दगी वाला बिल' (Documents Against Payment or D/P Bill) लिखता है। ऐसी दशा में आयातकर्ता को बैंक द्वारा माल के अधिकार पत्र तब ही सीपे जायेंगे जब वह उक्त बिल का भुगतान कर दे।

(४) बैंक में साल खुलवाना—यदि आयातकर्ता पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति है, तो निर्यातकर्ता उससे किसी बैंक में साल खोलने का आग्रह कर सकता है। यदि ऐसा कर दिया गया है, तो वह साल देने वाले बैंक पर बिल लिखेगा। तत्पश्चात् यह बिल साधारण रूप से भुनाया जाता है और भुनाने वाले बैंक के कोरस्पोंडेंट बैंक द्वारा साल देने वाले बैंक से सम्रह कर लिया जाता है।

स्पष्टतः विदेशी भुगतानों की व्यवस्था में बैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में देनदारों और लेनदारों के बीच एक सम्पर्क कड़ी (connecting link) या मध्यस्थ (intermediary) का काम करते हैं। उनकी भूमिका (role) को निम्न प्रकार से सन्निध किया जा सकता है—(अ) वे विदेशी विनिमय बिलों एव विदेशी करों में भुगतान होने वाले अन्य अधिकार पत्रों का कथ-विकथ

करते हैं (द) डाफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रान्स्फर यानी चैक आदि के प्रयोग द्वारा एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र को कोषों के स्थानान्तरण में सहायता करते हैं, एवं (स) विश्व के विदेशी विनिमय बाजारों में निकट सम्पर्क रखते हैं तथा अपने विविध ज्ञान और अनुभव से व्यापारियों के प्रेषण-कार्य को मितव्ययितापूर्वक सम्पन्न करा देने हैं। कभी-कभी ब्रोकरों और अन्य मध्यस्थों को मेवाओं का भी बिलों का रूप विक्रय करने में प्रयोग किया जाता है।

सरकारों तथा संस्थाओं के ऋण सम्बन्धी लेन-देन —

यदि कोई सरकार या संस्था किसी विदेशी देश में ऋण लेना चाहती है, तो वह उस देश में अपने एजेन्ट द्वारा बाण्ड्स या सिक्कारिटीज बेच सकती है। इनका विक्रय धन विनिमय व्यवहार कराने वाले बैंक में जमा हो जाता है। जब और जैसे आवश्यकता हो तब और वैसे ही यह धन बिलों या डाफ्टों द्वारा ऋणों के देश को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। ऋणों चाहे तो उक्त धन को ऋण देने वाले देश से अयात करने में स्वर्च कर सकता है। उधार देने वाले देश (lending country) में किसी बैंक पर निम्ने गये डाफ्ट प्राप्त अन्य देशों से व्यापारियों को भी स्वीकार्य होने है।

परीक्षा प्रश्न :

1. 'विदेशी विनिमय बाजार' से आप क्या समझते हैं? एक विदेशी विनिमय बाजार में कौन-कौन ब्यौहारी और ग्राहक होते हैं?

[What do you mean by the term 'Foreign Exchange Market'? Who are the dealers and customers in a foreign exchange market?]

2. वह विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार कौन कौन से हैं जिनमें विदेशी भुगतानों की आवश्यकता उत्पन्न होती है? ऐसे भुगतान करने के ढंगों एवं साधनों का वर्णन कीजिए।

[What are the different kinds of international transactions which necessitate foreign payments? Describe the means and methods adopted for making such payments]

अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन

(Balance of International Payments)

परिचय—

एक देश के अनगिनती विदनी ध्यद्वार जा उस देश से अन्य देशों को और अन्य देशों से उस देश को भुगतान की आवश्यकता उत्पन्न करते हैं, प्रायः एक तालिका या खाते के रूप में, जो कि 'अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन' कहलाता है, प्रस्तुत किये जाते हैं।

भुगतान-संतुलन का अर्थ

किसी देश का भुगतान संतुलन एक दो हुई अवधि के भीतर उसके समस्त आर्थिक व्यवहारों का जो कि देश और भेष विश्व के मध्य हुये हो, एक समबद्ध विवरण है जिसमें इनके मोक्षिक मूल्य दिखाये जाते हैं। इसमें न केवल द्वि-पक्षी व्यवहार (two sided transactions) बरन एक पक्षी व्यवहार (one sided transactions) भी, जैसे उपहार युद्ध से हुई क्षति की पूर्ति का भुगतान, ऋण, व्याज सम्बन्धी भुगतान आदि, सम्मिलित होने हैं।¹ प्रो० हैबरलर (Haberler) ने बताया है कि भुगतान संतुलन शब्द कई विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिनसे भ्रम होने का भय है। अतः इन विभिन्न अर्थों को समझ लेना चाहिए, ताकि कोई भ्रमस्पष्टता न रहे।²

¹ "By 'balance of international payments' we mean the statement that takes into account the values of all goods all gifts and foreign aid, all capital loans (or IOU's) and all gold coming in and going out and the inter-relations among all these items"

—Samuelson - *Economics*, p 645-46

'The term balance of payments' is used in a number of different senses, which are apt to be confused with one another. It is very important to distinguish between them as the failure to do so has led to serious misconceptions"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 18

(१) एक अवधि विवेचन में विदेशी मुद्रा की खरीदी एवं बेची गई मात्राये (Amounts of foreign currency bought and sold)—भुगतान सन्तुलन शब्द का प्रयोग कभी कभी एक ही हुई समयावधि (प्रायः एक वर्ष) के भीतर विदेशी मुद्रा की खरीदी और बेची गई मात्राओं के लिये किया जाता है। इस अर्थ में भुगतान सन्तुलन नि सन्देह सदा साम्यावस्था में रहेगा, क्योंकि खरीदी गई मात्रा आवश्यक रूप से बेची गई मात्रा के बराबर होती है।

(२) एक विशेष समयावधि में विदेशों को किये गये और विदेशों से प्राप्त भुगतान (Payments made, within the period to and from foreign countries)—भुगतान सन्तुलन से अभिप्राय उन भुगतानों का भी लिया जा सकता है जो कि एक विशेष समयावधि के भीतर देश को विदेशों से प्राप्त हो या विदेशों को करने गये। यह दूसरा अर्थ पहले अर्थ के समान नहीं है क्योंकि भुगतान न केवल विदेशी मुद्रा के भ्रम द्वारा चरित्र संचित विदेशी मुद्रा (इसमें यदि प्राप्तकर्ता दश स्वर्ण-मान पर है तो स्वर्ण को भी सम्मिलित करते हुए) के हस्तांतरण द्वारा भी किये जा सकते हैं। वास्तव में जब किये जाने वाले भुगतान प्राप्त-भुगतानों से अधिक होते हैं, तो ऐसी अधिकता को केवल इसी प्रकार से अर्थान् संचित विदेशी मुद्रा के तदर्थ में ही स्पष्ट किया जा सकता है। प्रस्तुत अर्थ में भुगतान सन्तुलन निष्क्रिय (passive) हो सकता है। किन्तु यह निष्क्रियता तब तक ही रहती है जब तक कि मुद्रा का स्टॉक समाप्त न हो जाय। यही नहीं, यदि भुगतान सन्तुलन किसी एक समय पर निष्क्रिय रहे, तो इसमें यह प्रमाणित होता है कि वह अवश्य ही किसी अन्य समय पर सक्रिय (active) रहा होगा, अन्यथा मुद्रा का स्टॉक मौजूद न होता। अतः इस अर्थ में भी भुगतान सन्तुलन दीर्घ काल में साम्यावस्था में ही रहेगा। [किन्तु एक स्वर्ण-उत्पादक देश का भुगतान सन्तुलन स्थायी रूप से निष्क्रिय रह सकता है।]

(३) 'आय खाते' पर भुगतान सन्तुलन (Balance of payments 'on income account'—कभी कभी भुगतान सन्तुलन का प्रयोग एक संकुचित अर्थ—'आय खाते पर भुगतान सन्तुलन'—में किया जाता है। इसमें व्याज-सन्तुलन (interest balance) और व्यापार एवं सेवाओं का सन्तुलन (balance of trade and services) सम्मिलित होता है। यदि यह निष्क्रिय है, तो या तो पूँजी-सन्तुलन (capital balance) सक्रिय होता है या फिर स्वर्ण या विदेशी करेंसी का म्बागान्तरण होता है। अन्य राष्ट्रीय, प्रतिरूपा सन्तुलन 'ऋणता' (indebtedness) में हुई वृद्धि अथवा स्वर्ण में बहिर्गमन के बराबर होता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय ऋणश्रतता का सन्तुलन (Balance of indebtedness)—भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी धारणा का प्रयोग कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय ऋणश्रतता के सन्तुलन के अर्थ में भी किया जाता है। इस अर्थ में भुगतान सन्तुलन एक विशेष समय पर बनाया पावनी (Claims) और दायित्वों (Liabilities) की कुल राशि को दिखलगा है।

(५) विदेशी करेंसी को माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी सम्पूर्ण परिस्थिति (The whole demand and supply situation of foreign currency)—भुगतान सन्तुलन का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ उन प्रभावों में सम्बन्धित है जो वह विनिमय दरों पर डालता है।

विनिमय दर (अर्थात् विदेशी करेंसी या करेंसिया में स्वदेशी करेंसी का मूल्य) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर महत्वपूर्ण असर डालती है। इसके स्पष्टीकरण के लिए केवल एक दिय हुए समय पर बकाया (outstanding) दायित्वा की कुल राशि को लयवा एक दी हुई समयावधि में देय हान वाले (falling due) दायित्वा की कुल राशि को मापना ही पर्याप्त नहीं है। दी हुई समयावधि में वास्तव में किय गये समस्त भुगतानों का लेखा करने से भी विनिमय दर को स्पष्ट करने में सहायता नहीं मिलेगी। कारण आर्थिक विश्लेषण कि-ही विद्यमान दायित्वा की रकम से ही प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। रिकार्डो (Ricardo) ने भी मातृयस को लिखे गये पत्र में इसी बात पर जोर दिया था।¹ वास्तव में आर्थिक विश्लेषण में यह भी विचार किया जाना चाहिये कि ये दायित्वा माग और पूर्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया के प्रारम्भ में किस प्रकार उदय हुए थे। जब हम इस तरह से विश्लेषण करने लगते हैं तो विनिमय दर अपने दोनों निर्धारकों—विदेशी करेंसी के लिये माग एवं इसकी पूर्ति—को स्वयं भी निर्धारित करती हुई दिखाई देती है। अतः भुगतान सन्तुलन शब्द का प्रयोग सम्पूर्ण 'माग एवं पूर्ति परिस्थिति' के अर्थ में किया जाता है और यह अर्थ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी विवेचनों में सर्वाधिक प्रचलित है।²

भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित मर्दें

भुगतान सन्तुलन के गुणात्मक विश्लेषण (qualitative analysis) में पूर्व इसका परिमाणात्मक विश्लेषण (quantitative analysis) करना आवश्यक है। अर्थ शब्दों में हम यह देसना चाहिए कि एक देश के भुगतान सन्तुलन में प्रायः कौन कौन सी मर्दें सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार का सबसे व्यापक विश्लेषण जर्मनी की Enquete Ausschuss द्वारा किया गया था और पेरिस सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद् (International Chamber of Commerce) द्वारा बनाई गई

¹ 'You (Malthus) appear to me not sufficiently to consider the circumstances {which} induce one country to contract a debt to another (In) all cases you bring forward you always suppose the (debt) already contracted'—*Letters of Ricardo to Malthus* ed by J. Bonar P 11

² 'The term "balance of payments" is then used in the sense of the whole demand and supply situation and in this sense it will be used in the following pages'—*Haberler The Theory of International Trade* P 19

योजना पर आधारित था। प्रो० हेबरनर ने मुगलान सन्तुलन में सम्मिलित होने वाली मदों को निम्नलिखित ढङ्ग से वर्णित किया है —

(१) वस्तुओं में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International trade in commodities)—मुगलान सन्तुलन में सबसे प्रमुख मद वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। आयातों और निर्यातों के मूल्य की तुलना द्वारा 'व्यापार सन्तुलन' (balance of trade) प्राप्त होता है। उपरोक्त जर्मन वर्गीकरण के अनुसार निर्यात पक्ष में निम्न मदों की गृहक-गृहक गणना की जाती है — (i) साधारण रूप से निर्यात की गई वस्तुएँ, (ii) विदेशियों को बेचे गये जहाज, (iii) विदेशी बन्दरगाहों पर बेची गई मछलियाँ, (iv) विदेश स्थित जहाजों में से बेची गई विदेशी वस्तुएँ, (v) से जाई गई अन्तर्राष्ट्रीय टाक, (vi) विदेशों को दी गई बिजली एवं (vii) चोरी छिपे बाहर भेजी गई वस्तुएँ। इनमें से कई मदें विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी आकड़ों में नहीं दिखाई जाती हैं। केवल वही मदें दिखाई जाती हैं जो कि वस्टर विभाग में लिंकन।

(२) सेवाओं के लिये भुगतान (Payments for services)—वस्तुओं की भांति सेवाओं के लिये भी भुगतान होते हैं। इन्हें 'अदृश्य आयात और निर्यात' भी कहा जाता है, क्योंकि करस्टम विभाग में इनका पूरा ध्योरा नहीं होता (जबकि वस्तुओं के आयात-निर्यात का होता है)। अदृश्य आयात-निर्यात में निम्न सेवाओं का समावेश किया जाता है—जहाजी सेवाएँ, यानी भाटे, बन्दरगाह एवं नहर व्यव, डाक, टेलीफोन और तार शुल्क, व्यापारिक सेवाएँ (फीम एवं कमीशन), वित्तीय सेवाएँ (बैंकों आदि) एवं पर्यटन कार्यालय की सेवाएँ। प्रायः इस बात का भय रहता है कि कुछ मदें नहीं दो बार ग गिन ली जायें। उदाहरणार्थ, यदि कोई आयात की हुई वस्तु एक ऊँची कीमत पर पुनः निर्यात (re-export) की जाती है, तो यह अन्तर (मने ही वह उन सेवाओं के कारण हो जो कि अदृश्य निर्यात में सम्मिलित की जा चुकी है) आयातों और निर्यातों के कीमत सम्बन्धी आकड़ों में भी भ्रमकेगा। अतः ऐसी दशा में उसे गृहक-गृहक नहीं गिनना चाहिये।

कमी-कमी 'व्यापार के सन्तुलन' (balance of trade) एवं 'सेवाओं के सन्तुलन' (balance of services) को एक ही शीर्षक के अन्तर्गत समूहबद्ध किया जा सकता है और फिर इसकी तुलना 'सात्व सन्तुलन' (Balance of credit) से की जाती है।

(३) सात्व सन्तुलन (Credit Balance)—'सात्व-सन्तुलन' में एक ओर तो 'व्याज सन्तुलन' (interest balance) अथवा 'पूँजी विपयक भुगतानों का सन्तुलन' (balance of payments on capital), और दूसरी ओर, 'पूँजी सन्तुलन' (capital balance) अथवा पूँजी के भुगतानों एवं पुनर्भुगतानों का सन्तुलन (balance of payments and repayments of capital) सम्मिलित होता है।

'रग्गज सन्तुलन' या 'पूँजी विपयक भुगतानों के सन्तुलन' में सरकार, स्वायत्त

सम्भाव्य और प्राद्वैत व्यक्तियों के ऋणों पर व्याज, परिवर्तनीय लाभ एव लाभान, किराने आदि तथा सम्भवतः पेटेंट कार्पाइराइट की आय भी सम्मिलित होती है।

'पूँजी सन्तुलन' या 'पूँजी विषयक भुगतानों एवं पुनर्भुगतानों के संतुलन' में विनियोगों को सम्मिलित किया जाता है और ये विनियोग अल्पकालीन और दीर्घकालीन विनियोगों में विभक्त किये जा सकते हैं। दीर्घकालीन पूँजी के निर्यात ॥ विदेशी उपक्रमों के क्षेत्रों का स्वयं, स्वदेशी प्रतिभूतियों का पुनर्ग्रहण या विदेशों से लिये गये ऋण की वापिसी, स्वदेश-स्थित सम्पत्ति में विदेशों हिस्से का द्रव्य करना आदि सम्मिलित है। अल्पकालीन पूँजी के निर्यातों में विदेशों में रक्के हुये बैंक बैलेंसेज में हुई वृद्धि विदेशी ऋणों के चारणा में वृद्धि तथा विदेशी देशों के प्रति व्यापारिक ऋणग्रस्तता के परिमाण में हुई कमी सम्मिलित है।

किन्तु स्मरण रहे कि दीर्घकालीन पूँजी का प्रवाह अल्पकालीन पूँजी के प्रवाह में प्रतिष्ठ रूप में सम्बन्धित होता है और एक में हुये परिवर्तन अभी-कभी दूसरे में हुये विपरीत परिवर्तन में निष्प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कि दोनों प्रकार के परिवर्तन विदेशों करेन्सी के लिये मांग या इसकी पूर्ति पर सामूहिक और प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालने हैं।^१ उदाहरणार्थ, यदि एक जर्मन फर्म न्यूयार्क में १० मि० खानर का ऋण जारी करती है, तो शका यह अर्थ नहीं है कि विदेशी विनियम बाजार में डालने की पूर्ति और मांग की मांग तुरन्त ही क्रमशः १० मि० और २५ मि० में बढ़ जायेगी। वास्तव में होता यह है कि न्यूयार्क बैंक जर्मन फर्म के पत्र में एक क्षाता खोल देता है, जिस पर वह अपने अपने अपनी आवश्यकतानुसार बैंक लिक्विटी रहेगी। अतः ऐसी दशा में, दीर्घकालीन ऋण एक अल्पकालीन सम्पत्ति के सृजन द्वारा निष्प्रभावित हो जाता है और करेन्सी के लिये प्रभावपूर्ण मांग तब ही उदय हो सकेगी जबकि इस सम्पत्ति का प्रयोग किया जाय।

(४) सरकारी व्यवहार (Government transactions)—भुगतान सन्तुलन में सम्मिलित अन्य मदें निम्न हैं—सरकारी व्यवहार (जैसे—कूटनीतिक प्रतिनिधियों के वेतन, क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता, आदि) एवं द्रव्य के उपहार (जैसे प्रवासियों द्वारा स्वदेश को भेजे गये विषय)।

(५) विविध मदें (Miscellaneous items)—कुछ मदें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें भुगतान सन्तुलन में 'अस्पष्ट या विविध' शीर्षक के अधीन दिखाया जाता है। भुगतान सन्तुलन की मदों का डेबिट्स और क्रेडिट्स में विभाजन—

जिस प्रकार एक व्यापारी के लिए उसके समस्त व्यवहारों का केवल

^१ The flow of long term capital is closely connected with the flow of short term capital, and changes in the one tend sometimes to be compensated by opposite changes in the other, so that only fluctuations in both combined affect directly the demand or the supply of foreign currency"—*Ibid.*, p. 17

गकलन (collection) मात्र ही पर्याप्त नहीं है (क्योंकि इससे उसे अपने व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता), उसी प्रकार एक देश के लिए उसकी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही-सही ज्ञान प्राप्त हेतु समस्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों की एकत्रित सूचना ही पर्याप्त नहीं होती। उसे एक व्यवसायी की भांति ही अपने व्यवहारों को 'देने' और 'पानों' में अथवा 'डेबिट्स' और 'क्रेडिट्स' में बांटना आवश्यक है। यही कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में, चाहे इसे खाने के रूप में जनावे या तालिका के रूप में दोनों ही दशाओं में, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को डेबिट्स और क्रेडिट्स शीर्षकों में विभक्त करके दिखाया जाता है। अतः यहाँ प्रश्न उठता है कि किन व्यवहारों (या मदों) को डेबिट शीर्षक में दिखाने और किन को क्रेडिट शीर्षक में।

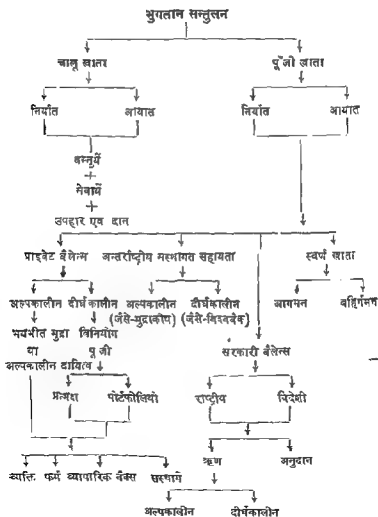
एक देश के राष्ट्रजनों द्वारा विदेशियों को भुगतान आवश्यक बनाने वाले व्यवहार 'आयात' या 'डेबिट' कहलाते हैं। किन्तु जो व्यवहार विदेशियों द्वारा राष्ट्रजनों के प्रति भुगतान करना आवश्यक बनते हैं उन्हें 'निर्यात' या 'क्रेडिट' कहा जाता है।¹ वस्तुओं के आयातमय के सम्बन्ध में तो आयात निर्यात या डेबिट-क्रेडिट शब्द सुसम्मतपूर्वक समझ लिए जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं के सभी निर्यात विदेशियों में उस देश को भुगतान दिलवाने हैं और वस्तुओं के सभी आयात उस देश से विदेशियों को भुगतान करवाते हैं। किन्तु पूँजी और सेवा सम्बन्धी व्यवहारों के सम्बन्ध में डेबिट-क्रेडिट शब्दों का प्रयोग करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऋण लेने वाले राष्ट्र की दृष्टि में दूसरे देश में भिया गया ऋण एक 'निर्यात' या 'क्रेडिट' है, क्योंकि उसे ऋण देने वाले देश से भुगतान मिलता है और ऋणदाता देश की दृष्टि से एक 'आयात' डेबिट है, क्योंकि उसे भुगतान करना पड़ता है। जब ऋणी देश व्याज चुकाता है या मूलधन लौटाता है, तो यह व्यवहार उसके लिए 'आयात' और देने वाले देश के लिए 'निर्यात' के सदृश होते हैं। इसी प्रकार, जब एक देश के राष्ट्रजनों को विदेशियों ने सेवाओं का पुरस्कार मिलता है, तो यह उनके लिए निर्यात या क्रेडिट मद है किन्तु देने वाले देश के लिए 'आयात' या डेबिट' मद। संक्षेप में जब देश भुग-

1 "A good way to decide how any item should be treated is to ask the following question: Is the item like one of our merchandise exports, providing us with more foreign currencies? Such an export-type item is called a 'credit item' and gives us a supply of foreign money. Or, is the item like one of our merchandise imports, causing us to use up stock of foreign currencies and making it necessary to get more foreign currency? Such an import-type item is called a 'debit-item' and gives us a demand for foreign money."—Samuelson : *Economics*, p. 647.

तान पा रहा हो, तो उसकी स्थिति 'लेनदार' (Creditor) और जब भुगतान दे रहा रहा हो, तो उसकी स्थिति 'देनदार' (Debtor) के सदृश्य होती है।

भुगतान सन्तुलन के दो भाग—चानू खाता एवं पूँजी खाता

भुगतान सन्तुलन को दो भागों में बाँटा जाता है—(अ) चानू खाता और (ब) पूँजी खाता।



‘चालू खाता’ (Current Account) भुगतान-सन्तुलन का वह भाग है जिसमें ‘वर्तमान’ में स्थानान्तरित की गई वस्तु और सेवाओं के लिए भुगतान सम्मिलित होते हैं। यहाँ ‘वर्तमान’ से आशय भुगतान सन्तुलन की विचारणीय अवधि का है। चालू खाते की सबसे बड़ी मद वस्तुओं का आयात-निर्यात है। किन्तु अ-मौद्रिक स्वर्ण (non-monetary gold) का आवागमन राजकीय प्रतिवन्धों के कारण कम ही होता है। चालू खाते की एक अन्य प्रमुख मद ‘सेवाएँ’ है। पूँजी के सम्बन्ध में भुगतान (व्याज-लाभांश) भी चालू खाते में आते हैं। सरकारों व्यवहार, दान (charities) उपहार (gifts) एवं विविध मदें (जैसे फ़िल्मों का किराया, तकनीकशिल्पों और गैज-मै सेवाएँ आदि) भी चालू खाते का ही अंग हैं।

‘पूँजी खाता’ (Capital Account) में विदेशों से एवं विदेशों को सरकारी रूप से या व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग खातों के ऋणों के लेन-देन सम्मिलित होते हैं। दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों ही प्रकार के पूँजी-आवागमन पूँजी खाते में आते हैं। पुराने ऋणों का वार्षिकी (amortisation), सरकार और केन्द्रीय बैंक की विदेशी बिलिमय सम्पत्तियों में हुये परिवर्तन तथा केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण कोष में हुये परिवर्तन भी पूँजी खाते के अन्तर्गत ही सम्मिलित किये जाते हैं। स्मरण रहे कि भारत जैसे देश में भुगतान सन्तुलन में प्राइवेट पूँजी के आवागमन ‘पूँजी सन्तुलन’ का एक छोटा भाग ही होते हैं और प्राइवेट व्यक्तियों व मस्थानों द्वारा दीर्घकाल बिलियमों की तथा व्यापार के अवप्रबन्धन हेतु की गई अल्पकालीन साख की सूचित करते हैं। बैंकिंग खाते के पूँजी सम्बन्धी आवागमन अवेभाकृत विज्ञापन (large) होते हैं। इनमें केन्द्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों के बैलेन्स में हुये परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। सरकारी खाने के ऋणों में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं विभिन्न विदेशी सरकारों में प्राप्त ऋण सम्मिलित होते हैं। यदि सरकार ने किन्हीं पड़ोसी देशों को कुछ ऋण दिये हों, तो ये भी इसी दीर्घक के अन्तर्गत दिखाये जाते हैं।

“भुगतान सन्तुलन सदा समतुलित होता है” (Balance of Payments Always Balances)

इस अर्थ में कि सभी भुगतान और प्राप्तियाँ समान रहें, भुगतान सन्तुलन में साम्यता सदा ही विद्यमान होती है। एक देश के सब क्रेडिट्स मिलकर उसके समस्त डेबिट्स के बराबर होने चाहिए। अन्य शब्दों में भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी विवरण के समस्त घनात्मक (+) एवं ऋणात्मक (—) पिट्ट एक साथ विचार में लिये जाने पर एक दूसरे को नाट देते हैं तथा (इसलिये) उनका शुद्ध सामूहिक शेष शून्य (Zero) होता है। यदि चालू खाते के सन्तुलन में कोई अन्तर है, तो अनिवार्य रूप से उसकी पूर्ति पूँजी खाते में विपरीत दिशा के अन्तर द्वारा हो जायेगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश को अपने चालू खाने में ‘प्राप्तियों’ (receipts) की अपेक्षा ‘देना’ (payments) अधिक है, तो यह न्यूनता (deficiency) स्वर्ण के निर्यात द्वारा या विदेशों से पहिले से संचित कोष पर आहरण (drawing) द्वारा या अन्य देशों से दीर्घ-

कान्सीन या अल्पकालीन ऋण लेकर पूरा की जा सकती है। अभी हाल में न्यूनता की पूर्ति का एक नया उपाय प्रपट हुआ है—कुछ देशों ने भिन्न देशों के अनुदान (grants) एवं उपहार (gifts) के आश्रय पर विदेशों में अपना ऊँचा व्यय कायम रखा है। उदाहरणार्थ भारत के चालू आयात 'चालू निर्यातों' से बहुत अधिक रहते हुए भी वह विभिन्न ठहरावों के आधेन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी और रूस आदि देशों द्वारा प्रदत्त साख के आधार पर, विशाल मात्राओं में पूँजीगत वस्तुओं और मशीन खरीदने में समर्थ हुआ है। इस प्रकार, उसके चालू खाते की न्यूनता (deficit) पूँजी खाने के उतने ही आधिनय (surplus) द्वारा सन्तुलित (balanced) हो गई है तथा इसमें 'और देशों' कुल भुगतान एक दूसरे को सन्तुलित अर्थात् बराबर कर देते हैं।

यदि उपरोक्त उपाय (स्वयं का आवागमन) गिछली अवधियों में मचित एवं निमित्त की हुई विदेश स्थित सम्पत्ति पर आहरण और पूँजी या सहायता की प्राप्ति में ना फल्य आयें तो भी भुगतान सन्तुलन के डेबिट और क्रेडिट पक्षों का समतुलन हो जायगा क्योंकि बिना रकम का भुगतान नहीं किया जाता, उसे अल्पकालीन विदेशी ऋण शीर्षक के अन्तर्गत सम्बन्धित विदेशों के प्रति राष्ट्र के दायित्व के रूप में दिखाया जाता है, जिससे भुगतान (credit) पक्ष की 'कमी' पूरी हो जाती है।

प्रायः कहा जाता है कि निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं (exports pay for imports)। स्पष्टतः यह कथन भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में है न कि 'व्यापार सन्तुलन' या व्यापार एवं सेवाओं के सन्तुलन' (अर्थात् चालू खाते) के सम्बन्ध में, क्योंकि शायद ही किसी देश के इश्य (वस्तुगत) निर्यात उसके इश्य (वस्तुगत) आयातों के बराबर रहते हों। और यदि अह्वय मदों (सेवाओं) को विचार में ले लें तो भी केवल यह आशा मात्र रहती है कि देश के निर्यात उससे आयातों का भुगतान कर सकेंगे। किन्तु सम्पूर्ण भुगतान सन्तुलन के बारे में यह निश्चितता के साथ कहा जा सकती है कि देश के निर्यात आयातों का भुगतान करते हैं।

भुगतान सन्तुलन में असाम्यता

(Dis-equilibrium in the Balance of Payments)

'समतुलन' होते हुए भी 'असाम्यता' विद्यमान हो सकती है—

उपरोक्त उद्योगों में कुल क्रेडिट्स और कुल डेबिट्स के मध्य अनिवार्य रूप से समतुलन होने की बात का कोई विषयोणात्मक महत्त्व (analytical significance) नहीं है। यदि महत्त्व है तो इस बात का कि यह समतुलन कैसे सम्भव हुआ। यदि क्रेडिट्स और डेबिट्स के मध्य समतुलन बनाये रखने के लिये विशाल मात्रा में स्वयं का आवागमन हो विदेशों में देश के मचित कोषों पर विशाल मात्राओं में आहरण करना पड़े या अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण लेने पड़े तो समतुलन धोखे में डालने वाला है और भुगतान सन्तुलन में जो साम्यावस्था दिखाई पड़ती है वह भ्रामक

है, कारण, ये उपाय सदा स्तैमास नहीं किये जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति तो यह बनानी है कि देश की अव्यवस्था में कोई गहरा कुसमायोजन (maladjustment) विद्यमान है जिसके उपचार के लिए आयातों के घटाने तथा निर्यातों के बढ़ाने जैसे सक्रिय कदम (active steps) उठाने की आवश्यकता है। यद्यपि साम्यवस्था यह है जो कि स्वर्ण या पूँजी के आवागमन बिना ही प्राप्त हो जाय। किन्तु ऐसी साम्यता एक पर्याप्त लम्बी अवधि में ही सम्भव है। इसका वारण यह है कि पर्याप्त लम्बी अवधि में मौसमी न्यूनतायें समाप्त हो जाया करती हैं और स्वर्ण के असाधारण आवागमन, विदेशों कोषों में भारी घटा-बढ़ी और विदेशों से निरन्तर विशाल ऋण लिय-दिय बिना ही देश के भुगतान उसकी प्राप्तियों के बराबर हो जाने है। साधारणतः धनार्थ अल्पकाल में देशों के भुगतान सन्तुलन में असाध्यता (disequilibrium) हो होती है।

प्रतिकूल एवं अनुकूल भुगतान संतुलन—

जब किसी देश के डेबिट्स उसके क्रेडिट्स की तुलना में इस सीमा तक अधिक हो कि विशाल मात्राओं में स्वर्ण भेजना पड़े या विदेशों में रखे हुए कोषों में से विशाल मात्राओं में आहरण करना पड़े या विदेशों में ऋण लेने पड़े, तो कहा जाता है कि भुगतान सन्तुलन देश के प्रतिकूल (unfavourable) है, भुगतान सन्तुलन निष्क्रिय (Passive) हो गया है अथवा भुगतान सन्तुलन में 'घाटा' (deficit) है। इनकी विपरीत दशा में भुगतान को 'अनुकूल' (favourable) 'सक्रिय' (active) या 'आधिन्य' (surplus) कहा जाता है।

उदाहरणार्थ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशों से भारी मात्रा में पूँजीगत वस्तुयें पैगानी पड़ती हैं। एक लाख करोड़ की हल करने के लिए विदेशों में व्यापारों का आयात करना पड़ता है। किन्तु उसके चाखू निर्यात इन विशाल आयामों की तुलना में बहुत ही कम है। फलतः उसे षास्त्र बाने में भारी घाटा रहता है, जिसकी पूर्ति उसके पूँजी धाने में, पूँजी के आवागमन द्वारा उत्पन्न हुए, 'आधिन्य' में होनी है। उसे अनेक देशों में सरकारी स्तर पर तथा प्राइवेट नागरिकों में ऋण, सहायता और अनुदान के रूप में विशाल साख मिल रही है और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएँ भी मदद दे रही हैं। यद्यपि इन परिस्थितियों में, उसके 'देन-देन' तो बराबर हो जाते हैं किन्तु इस समतुलन को ओट में 'असाम्यता' द्विधी हुई है उसमें मुक्त नहीं मोड़ना चाहिए। यत्र असाम्यता स्पष्ट ही भारत के प्रतिकूल है तथा अस्वस्थता में कुसमायोजनों के विद्यमान होने की सूचक है। अतः इसके उपचार के लिए प्रयत्न करने जरूरी है।

भुगतान सन्तुलन का एक उदाहरण—

भुगतान सन्तुलन में प्रगट की जाने वाली विभिन्न मदों को बनी प्रकार में समझने के लिए नीचे हम अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन का एक उदाहरण प्रस्तुत करने हैं।

अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन, १९६२

(मि० डालरों में)

क्रम संख्या	मदें (अ)	क्रेडिट्स (ब)	डेबिट्स (ग)	शुद्ध क्रेडिट्स (+) अथवा डेबिट्स (-) (द)
(I)	धान खाता			
१	ग्राइनेट			
१	वस्तुएं	२०,४७६	१६,१४२	+४,३३४
	वट्टाए			
२	यातायात	१७४६	२,०४५	- ३०९
३	साधन-व्यय	६२१	१,८०५	- १८४
४	विनियोगों पर आय (ब्याज आदि)	३,८२०	६५६	+३,१६४
५	ग्राइनेट भेक्षण		४६१	- ४६१
६	विविध भेक्षाएँ	१,४७५	४३६	+१,०३९
७	धान ग्राइनेट संतुलन			+६,७८६
८	अमेरिकी सरकार			
८	फौजी सामान और भेक्षाओं का निर्यात (+)	१,५३६		
	मित्र राष्ट्रों को फौजी सहायता सम्बन्धी भुगतान (-)		१,५३६	०
९	अन्य फौजी व्यवहार	६६०	३,०२८	- २,३६८
१०	अन्य अनुदान एवं भुगतान		२,१४८	- २,१४८
११	विविध सरकारी व्यवहार	६५६	७३६	- ८०
१२	धान सरकारी व्यवहार			-४,५६६
१३	धान दाते पर शुद्ध संतुलन			+२,१८७
(II)	डॉलर खाता ऋण-पत्रों (IOU's) का शुद्ध निर्यात (+) या आयात (-)			
	दीर्घकालीन ऋण (-) या दायित्व (+)			
१४	ग्राइनेट			-२,४६५
१५	सरकारी			-१,७६१
१६	शुद्ध दीर्घकालीन विदेशी विनियोग			-४,२२६
१७	धान खाते पर शुद्ध संतुलन + दीर्घकालीन ऋण (अमेरिका) के भुगतानों में मुनिवासी घाटा अल्पकालीन ऋण (-) या दायित्व (+)			-२,०६६
१८	ग्राइनेट			+ ३०
१९	सरकार			+२,१५७

२०। अल्पकालीन ऋण में शुद्ध विनियोग	+ २.१८७
(III) शुद्ध स्वण निर्यात (+) या आयात (-)	+ ६०७
२१ ऋणिया एवं भूतों	- १.०२४
२२ बुनियादी घाटे की पूर्ति	+ २.०६६
२३ कुल पर अन्तर्राष्ट्रीय समतान सन्तुलन का शुद्ध योग	०

उपरोक्त तालिका में अमेरिका के १९६२ के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी सरकारी आंकड़े दिये हुये हैं। इसके तीन प्रमुख खण्ड हैं—(I) बाह्य खाता, (II) पूँजी खाता और (III) स्वर्ण आवागमन। इसके अतिरिक्त सांख्यिकीय त्रुटियों एवं भूलों (statistical errors and omissions) के लिए भी एक मध्य पृष्ठा से दी हुई है।

१९६२ में अमेरिका का वस्तु निर्यात २० ४७६ मि० डालर और वस्तु-आयात १६ १४४ मि० डालर था जिससे शुद्ध अन्तर ४,३३४ मि० डालर आया। (देखिये पहली पंक्ति)। चूंकि क्रेडिट्स (+) अधिक हैं, इसलिये कालम (द) में राशि के पूर्व (-) चिन्ह लगाया गया है। कुछ लोग ऐसे व्यापार सन्तुलन को अनुकूल बताते हैं। किन्तु केवल वस्तुआ के आयात निर्यात सन्तुलन को ही अनुकूल या प्रतिकूल मान लेना ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम इसी अध्याय में आगे बतायेंगे, कभी-कभी व्यापार सन्तुलन में घाटा भी देश के लिए एक बहुत अनुकूल बात हो सकती है।^१

जब अमेरिकी नागरिक विदेशों को यात्रा पर जाते हैं अथवा निजी रूप से उपहार भेजते हैं तो वह विदेशी करेंसियों का प्रयोग करते हैं। अतः इन्हे कालम (घ) में डेबिट सीपर्स के अन्तर्गत रखा गया है। [विदेशी देशों के भुगतान सन्तुलन में वे 'क्रेडिट' सीपर्स के अन्तर्गत दिखाये जायेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि से डालर अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं।] अहम्य बदो (पंक्ति २ से ६ तक) का अन्तिम प्रभाव यह है कि

^१ 'Centuries ago when merchandise items predominated, writers concentrated on this narrow category alone. If merchandise exports were greater in value than merchandise imports, they spoke of 'favourable balance of trade', if imports exceeded exports they spoke of an 'unfavourable balance of trade'. This is not a good choice of terms, since we shall see that a so called 'unfavourable' balance of trade may be a very good thing for a country'—Samuelson : *Economics*, p. 647.

चासू प्रॉइवेट खाते में अमेरिका के क्रेडिट्स डेबिट्स की अपेक्षा पहले से भी अधिक बढ़ गये देखिए पक्ति ७)।

आगे (पक्ति ८ में १२ तक) सरकारी मदें दिखाई गई हैं। इनमें से आठवीं पक्ति स्वयं में धातिपूर्क (self-cancelling) है, क्योंकि सरकार द्वारा जा फौजी वस्तुओं और सेवाओं निर्यात की गई (गान ताजिये कि जर्मनी को) उनका मूल्य आयातक देश (जर्मनी) के पास ही उपहार के रूप में ही छाड़ दिया गया। अतः इन पाँच एक निर्यात क्रेडिट दिने, वा आयात-डेबिट में भी दिखाना चाहिये। अन्य फौजी व्यवहारों में जर्मनी को अमेरिकी फौजों के लिये पेट्रोल आदि की व्यवस्था क सम्पन्न में किये गए भुगतान सम्मिलित है। अमेरिकी सरकार के अन्य विदेशी कार्यक्रम ११वीं पक्ति में सम्मिलित है। सरकारी खाते पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात-निर्यात का अन्तिम परिणाम १२ वीं पक्ति में दिखाया गया है। अन्तिम परिणाम यह है कि चासू सरकारी खाते पर क्रेडिट्स की अपेक्षा डेबिट्स अधिक हैं (= ४,५६६ मि० डालर)। चूँकि चासू सरकारी खाते पर ऋणात्मक योग की अपेक्षा चासू प्रॉइवेट खाते पर वित्तीय योग अधिक है, इसलिए चासू खाते में शुद्ध योग (= + २,१८७ मि० डालर) निकलता है।

अमेरिका अपने चासू खाते के शुद्ध योग (Net difference) की पूर्ति कैसे कर सकता है? जैसा कि उक्त तालिका में दिखाया गया है, उनकी पूर्ति या तो स्वर्ण के आवागमन (III) द्वारा अथवा शुद्ध विनियोजन (II) द्वारा की जा सकती है। कारण, जो कुछ एक राष्ट्र प्राप्त करता है उसके लिए या तो उसे भुगतान करना चाहिए अथवा ऋणों बनाना चाहिए। दोहरे लेखों की बुद्ध-धीमि के इस तथ्य का अर्थ यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के समुलन की सम्पूर्ण तालिका जो अन्तिम योग (overall-balance) दिखाये वह धूम्य होना चाहिए।¹

१६ वीं पक्ति यह प्रकट करती है कि अमेरिका एक शुद्ध दीर्घकालीन लेनदार है, अर्थात् वह विदेशों में, अमेरिका में, विदेशियों की अपेक्षा अधिक राशि में विनियोजन कर रहा है या ऋण दे रहा है। अन्य शब्दों में, उसे IOU's (ऋण स्वीकृतियों) अधिक प्राप्त हुई है। चूँकि IOU's देना 'निर्यात-क्रेडिट' मद है और IOU's पाना 'आयात-डेबिट' मद है, इसलिए अमेरिका के अतिरिक्त विनियोजन (surplus investments) ऋणात्मक योग (= -४,२५६ मि० डालर) रखते हैं।

१७वीं पक्ति में अमेरिका के समस्त चासू व्यवहारों और दीर्घकालीन पूँजी के

¹ "How must a nation offset its net balance on current account? Either by gold, or by net borrowing. For it is a tautology that what you get you must either pay for or owe for. And this fact of double entry book-keeping means that the whole table of the balance of international payments must show a final perfect balance"—*Ibid.*, p. 649

आवागमनो का योंन दिक्षाया गया है। चानू सरकारी डेविटस और दीर्घकालीन वित्त-योग डेविटस इतने अधिक थे कि भुगतान सन्तुलन में यहाँ तक अमेरिका को एक भुद्र बुनियादी घाटे (net basic deficit) (= २,०६६ मि० डावर) का सामना करना पड रहा है। ध्यान रहे कि 'भुगतान सन्तुलन में घाटा' कथन भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम देश बुरे हैं, सम्पूर्ण भुगतान सन्तुलन साम्यावस्था में होता है। अतः जब कभी समाचार पत्र भुगतान सन्तुलन में घाटे की खर्षा करत है, तो प्रायः उनका आशय १७ बी पक्ति से होता है।

'बुनियादी घाटे' की पूर्ति दो तरह से की जा सकती है—या तो स्वर्ण का निर्यात किया जाय अथवा विदेशियों से यह अनुरोध किया जाय कि वे अमेरिका में अल्पकालीन पूँजी खाते पर तरल सम्पत्तियाँ रखना स्वीकार कर लें। विष्णु प्रधान रहे कि विदेशी जन चाहे तब ही इन तरल सम्पत्तियों के बजाय स्वर्ण माँग सकते ह। उदाहरण के लिए, जब वे देखें कि अन्य वित्तीय केन्द्र न्यूयार्क केन्द्र की अपेक्षा अल्पकालीन शोषो पर अधिक व्याज दे रहे ह, तो वे अपने अल्पकालीन कोषो को स्वर्ण में बदलने पर जोर दें। अमेरिका के बुनियादी घाटे की पूर्ति कुछ अंश में सोने के निर्यात द्वारा हुई है। [विशेषज्ञ का कहना है कि सार्विकी भूज-भूत के क्षोर्पक में जो डेविड दिवाया गया है वह अल्पकालीन पूँजी के बहिर्गमन के कारण है जिसका रिफार्म नहीं हो सका। यही कारण है कि विदेशियों द्वारा अमेरिका में २,१८७ मि० की अल्पकालीन सम्पत्तियाँ रखने पर भी ६०७ मि० डावर का स्वर्ण निर्यात करना पडा।]

उपरोक्त विवेचन में अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में दोहरे लेते की डेविड और क्रेडिट मदे सम्मिलित होती है, जिसमें वह सदा सन्तुलित रहता है। सन् १९८६ और १९४६ के मध्य जबकि अमेरिका स्वर्ण और तरल सम्पत्तियाँ प्राप्त कर रहा था, तब भी भुगतान सन्तुलन में साम्यता विद्यमान थी और प्राण थी, जबकि 'डालर अभाव' का स्थान टालर-प्रचुरता में ले लिया है साम्यता विद्यमान है, क्योंकि अमेरिका के बाज़ू और दीर्घकालीन पूँजी के सन्तुलन में बुनियादी घाटे की पूर्ति स्वर्ण के बहिर्गमन तथा विदेशियों द्वारा देश में अल्पकालीन सम्पत्तियाँ रखने में हो रही है।

भुगतान सन्तुलन की विभिन्न अवस्थाएँ

किसी देश के भुगतान सन्तुलन में, उसके आर्थिक विधास के स्तर के ही अनु-रूप, विभिन्न अवस्थाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। उदाहरणार्थ, समुक्त राज्य अमेरिका को एक युवा कृषक राष्ट्र से एक मुक्तिसित औद्योगिक राष्ट्र बनने में चार ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरना पडा। ये अवस्थाएँ निम्नलिखित हैं —

(१) युवा एवं वृद्धिशील अरणी राष्ट्र—क्रान्तिकारी मुद्र युग से लेकर गृह-युद्ध के तत्काल बाद तक अमेरिका ने कंस्ट्रैक्टेड अकाउन्ट में अत्यन्त अधिक विधा और निर्यात कम। उसे अन्तर की राशि दक्षिण और यूरोप से उधार मिली, जिससे वह

अपना पूँजी-बाँचा (capital base) बनाने में समर्थ हुआ। इस प्रकार, इन दिनों अमेरिका एक युवा और वृद्धिशील-ऋणी राष्ट्र (a typical young and growing debtor nation) था।

(२) परिपक्व ऋणी राष्ट्र—सन् १८७३ से सन् १९१४ तक अमेरिका के व्यापार मनुस्त्र में अनुकूलता प्रगट हुई। किन्तु उमें भूतकालीन ऋणों पर लाभांश और ध्याज की जो विशाल रकमें चुकानी पड़ी उन्होंने अमेरिका के बाह्य खाते के दौलत को न्यूनतम पर मनुस्त्रित कर दिया। पूँजी के सावागमन भी प्रायः मनुस्त्रित में दे क्योंकि नये ऋण पुराने ऋणों का निपटारा (cover) कर रहे थे। यह एक परिपक्व ऋणी राष्ट्र (mature debtor nation) की अवस्था थी।

(३) नव ऋण-दाता-राष्ट्र—प्रथम महायुद्ध की अवधि में अमेरिका ने अपने निर्यात बहुत अधिक बढ़ा लिये। प्रारम्भ में तो अमेरिकी नागरिकों ने मित्र राष्ट्रों को ऋण दिये, बाद में जब अमेरिका भी युद्ध में प्रविष्ट हो गया, तब अमेरिकी सरकार ने भी युद्ध सम्बन्धी साज-सामान और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिये डल्लरेंड और प्रांस को ऋण दिये। इस प्रकार युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका भाषिक गमारा में एक लेनदार राष्ट्र के रूप में प्रगट हुआ। किन्तु अभी अमेरिकी जनता की मनोवैज्ञानिक स्थिति इस नई परिस्थिति के अनुरूप समायोजित नहीं हुई थी। अतः १९२० और १९२६ के मध्य ऊँचे प्रशुल्क (high tariffs) लगाये गये। पूँजी अमेरिकावासी आयात करने को तैयार न थे, इसलिये विदेशियों के लिये मूलधन तो बचा ब्याज और लाभांश तक चुकाने के लिये पर्याप्त साधन जुटाना कठिन हो गया। जब तक अमेरिकी नागरिक आयात न करने हुए विदेशियों को नये ऋण देते रहे, तब तक प्रत्येक चीज सतह पर सही प्रतीत हुई। अन्य गवदी में, अमेरिका जितना आयात करता था उतने कहीं अधिक निर्यात करता था और शेष बखार उसके निर्यात-अतिरिक्त की पूर्ति के लिए उसे साना और ऋण-म्बीकृतिदा (IOU's) भेजता था। जब तक वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स में स्ट्रीट के विनियोजकों की रुचि को विदेशी बाँझों में कामन रख सके, तब तक उत मार्ग निष्कटक प्रतीत हुआ। किन्तु १९२६ में और इसके बाद, जब अमेरिकन विनियोजकों ने विदेशों में श्रमा लगाना बन्द कर दिया, सकट सहसा ही टूट पड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोध हुआ गया तथा ऋणों के भुगतान में कृति होने लगी। इस दुर्व्यवस्था के लिए शेष बिस्व के साथ-साथ अमेरिका, खुद भी दोषी था।

(४) परिपक्व लेनदार राष्ट्र—आजकल अमेरिका अपने विकास की चौथी अवस्था में है, जिसमें यह अपनी चानु आवश्यकतायें पूरी करने हेतु पिछले विनियोजकों पर विदेशों से मिलने वाली आय का प्रयोग कर रहा है।

डल्लरेंड इस अवस्था में अमेरिका में भी पहले ही प्रवेश कर चुका था। जैसा कि ऐसी अवस्था में गढ़ा होगा जाया है, उसके आवाज उसके निर्दानों को अपना अधिक हुए। इसमें उसका व्यापार सतुलन 'अतिरूप' हो गया। लेकिन यह

प्रतिकूलता उसके लिए कोई दुःख की बात नहीं थी। अथवा उसके व्यापार मण्डल में प्रतिकूलता उसकी गिराई हुई थक्का का सूचक नहीं था, बरन् उसकी उन्नत अवस्था का प्रतीक थी। कारण उसके नागरिक एक ऊँचा जीवन-स्तर कायम रखने में समर्थ थे, क्योंकि वे बहुत सस्ता खाद्यान्न आयात कर लेने थे और बदले में कीमती निर्यात वस्तुओं के रूप में कुछ अधिक नहीं देने थे। अन्य शब्दों में श्रेष्ठ अपने आयात आधिक्य का भुगतान कम व्याज और लाभालाभ में से करते थे जो कि भूतकालीन विदेशी पिनियोगो पर उन्हें मिल रहा था।

किन्तु यद्यपि स्थिति भी खराब नहीं थी। कारण इंग्लैण्ड में जो पूँजीगत वस्तुएँ उन्हें पहले उधार दी थीं उनके प्रयोग द्वारा वे सामान्यतः उससे अधिक मूल्य वृद्धि कर रहे थे जो कि वे व्याज व लाभालाभ के रूप में इंग्लैण्ड को चुकाते थे। इस प्रकार दोनों ही पक्ष पसन्द थे। वास्तव में “१९वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय ऋण ऋणों और ऋणदाता दोनों के लिए लाभदायक थे। हाँ, कुछ दशाओं में अवश्य ही वह हानिग्रय प्रमाणित हुए। विनोद राजनैतिक भावनाओं से दिए गये ऋणों में जो कि उपनिवेशवाद पर आधारित थे स्थिति को कठनपूर्ण बना दिया तथा इन्हीं के कारण पथम महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का प्रवाह दृढ़ गया।”¹

भुगतान सन्तुलन एवं व्यापार सन्तुलन

आप लोगों में ‘भुगतान सन्तुलन’ और ‘व्यापार सन्तुलन’ सम्बन्धी धारणाओं के अर्थ में भ्रान्ति पाई जाती है। कभी-कभी लोग यह कहते सुने गये हैं कि भुगतान सन्तुलन में तो ‘व्यापार सन्तुलन’ का भाव सम्मिलित है किन्तु ‘व्यापार सन्तुलन’ में भुगतान-सन्तुलन का भाव सम्मिलित नहीं है। ऐसे कथनों से प्रचलित भ्रान्ति में और भी वृद्धि हो गई। अब हमें इन धारणाओं का सही-सही अर्थ जान लेना चाहिए।

व्यापार सन्तुलन—

जैसा कि हमने पहले भी मकेत किया था कि यदि एक ऐसा विवरण तैयार किया जाय जिसमें एक ओर निर्यात की गई विभिन्न वस्तुओं की ‘मात्राएँ’ एवं ‘मूल्य’ तथा दूसरी ओर, आयात की गई विभिन्न वस्तुओं की ‘मात्राएँ’ एवं ‘मूल्य’ दिखाये गए हों तो इसे ‘व्यापार सन्तुलन’ (Balance of Trade) कहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि निर्यात के जो मूल्य गणना में लिए जाते हैं वे $C + I + F$ (Cost and Insurance and Freight) होते हैं। अन्य शब्दों में आयात मूल्य में हमारे बन्दरगाहों तक याता-यात व्यय सम्मिलित होते हैं, किन्तु निर्यात मूल्य में विदेशी बन्दरगाहों तक का याता-यात व्यय सम्मिलित नहीं होता। यही कारण है कि व्यापार सन्तुलन में जो खाने बनाए जाते हैं एक निर्यात $F + O + B$ दिवाने हुए और इनका आयात $C + I + F$ दिवाने हुए।

¹ Samuelson : Economics p 625

स्पष्टतः व्यापार-सन्तुलन एक समयावधि से, जो प्रायः एक वर्ष होता है, सम्बन्धित होता है। किन्तु ये विवरण तिमाही या मासिक आधार पर भी बनाये जा सकते हैं। यदि निर्यातों का कुल मूल्य एक वर्ष में आयातों के कुल मूल्य के बराबर हो जाय, तो व्यापार सन्तुलन 'सम (even)' कहा जाता है। यदि आयातों का कुल मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य से अधिक हो, तो उसे 'ऋणात्मक' (Negative) या 'निष्क्रिय' (Passive) और यदि निर्यातों का कुल मूल्य आयातों के कुल मूल्य से अधिक हो, तो उसे 'धनात्मक' (Positive) या 'सक्रिय' (Active) कहते हैं। कुछ लोग इन्हें क्रमशः 'प्रतिकूल' (Unfavourable) और 'अनुकूल' (favourable) विशेषण दे देते हैं, जो कि ठीक नहीं है।

भुगतान सन्तुलन—

जबकि व्यापार सन्तुलन से आशय केवल वस्तुओं के आयातों और निर्यातों के मूल्य से है, तब भुगतान सन्तुलन वही अधिक व्यापक है और इसका आशय द्रव्य एवं अद्रव्य (वस्तुओं और सेवाओं) दोनों ही प्रकार की आयात-निर्यात मदों के कारण उत्पन्न हुए कुल डेबिट्स और कुल क्रेडिट्स से है। इस प्रकार, व्यापार सन्तुलन भुगतान सन्तुलन का एक भाग है। वह केवल द्रव्य आयातों और द्रव्य निर्यातों के मूल्य के अन्तर को सूचित करता है, जब इसका कोई विश्लेषणात्मक महत्त्व नहीं है। किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि व्यापार सन्तुलन भुगतान सन्तुलन का प्रायः एक बड़ा भाग होता है। इसके अतिरिक्त भुगतान सन्तुलन के अन्य प्रमुख भाग निम्न हैं— सेवाओं का सन्तुलन (Balance of Services or Balance on Income Account) पूँजी खाते पर सन्तुलन (Balance on Capital Account) तथा स्वर्ण का आवागमन।

स्पष्टतः व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा भुगतान सन्तुलन का महत्त्व अधिक है, क्योंकि यह 'व्यापार सन्तुलन' से वही अधिक व्यापक विचार है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, व्यापार सन्तुलन के सम्बन्ध में 'प्रतिकूल' और 'अनुकूल' शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। य शब्द भुगतान सन्तुलन के बारे में उचित रूप से प्रयोग किये जा सकते हैं। किन्तु भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता या अनुकूलता तत्काल ही नहीं जानी जा सकती है। इस हेतु हमें भुगतान-सन्तुलन की मदों का गहरा विश्लेषण करना पड़ता है।

भुगतान सन्तुलन का महत्त्व

भुगतान सन्तुलन किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवहारों का जो कि दी हुई अवधि में हुए हैं, एक परिमाणान्तरक सारांश (quantitative summary) होता है और देश की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है।

(१) विदेशी सहायता पर निर्भरता की सीमा का सूचक—अर्थव्यवस्था

देशों का भुगतान सन्तुलन यह दिखाएगा कि उनका आर्थिक विकास किस सीमा तक पूँजी सन्निधि करने वाले देशों की वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

(२) पिछले निर्यातों के प्रभाव का दिग्दर्शक—एक प्राचीन देश, जो कि वित्तीय दृष्टि से अच्छी हालत में है और जिसने विदेशों से भारी निनिमोग है त्रित पर उसे व्याज, लाभांश आदि के रूप में घटेष्ट आय हो जाती है, उसका भुगतान सन्तुलन यह दिखाएगा कि उसके नागरिक किस सीमा तक भूतकालीन निर्यातों के सहारे निर्वाह कर रहे हैं।

(३) बदलती हुई आर्थिक परिस्थिति का सूचक—विन्तु भुगतान सन्तुलन के अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इस बात में है कि वह सम्बन्धित देश की बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति का सूचक है। जिस प्रकार एक बैरोमीटर वायुमंडल के प्रति क्षण बदलते हुए दबाव का मापता है, उसी प्रकार भुगतान सन्तुलन देश की बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का मापक है। यदि इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाय, तो इसके द्वारा राष्ट्र की अलाकालीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्भावनाओं की अमूल्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है और फिर ऐसी जानकारी के आधार पर यह कह सकते हैं कि देश अन्तर्राष्ट्रीय शोधक्षमता रखता है या नहीं तथा उसकी विनिमय दर (या मौद्रिक इकाई का मूल्य) उपयुक्त है या नहीं।

वास्तव में, "एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के लिये भुगतान सन्तुलन का बड़ी महत्व है जोकि एक रसायन शास्त्री के लिये आधुनिक तत्त्व-तालिका का होता है।"¹

एक दीर्घकालिक असाम्यता की अवस्थानोयता
(Undersatability of a Chronic Imbalance)

भुगतान सन्तुलन की लगातार सक्रियता की हानियाँ

यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन लगातार 'सक्रिय' (active) बना रहे तो सामान्यतः इसे उस देश के लिए कोई खतरा नहीं समझा जाता। केवल स्वीडन के मामले में ही भुगतान सन्तुलन की अनुवृत्ता की अव्यवस्था के हित के विरुद्ध माना गया था और इस सम्बन्ध में निम्न तर्क दिये गए थे—(i) सक्रिय सन्तुलन के फलस्वरूप स्वर्ण का आयात होता है, जिससे देश के प्रसाधन एक ऐसे विनियोग में अटक जाते हैं जिन पर उसे कोई आय नहीं होती। (ii) सक्रिय सन्तुलन देश में मुद्रा प्रसार उत्पन्न कर सकता है। यदि स्वर्ण का आयात होता है तथा देश स्वर्णमान पर है, तो इससे कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यदि स्वर्ण का आयात न किया जाय और विदेशों से ही वेंचस्सेज रख लिये जाएँ तो फिर देश के निर्यातकों की भुगतान करण के लिए करेंसी निर्गमन करनी पड़ती है। दोनों ही दशाओं में,

¹ "What the Periodic Table of Elements is to the chemist, the Balance of Payments is to the International Economist"

अदि सक्रिय सन्तुलन एवं दीर्घकालीन विक्षेपता बन जाय तो, मुद्रा प्रसार हृद में बाहर हा सक्ता है। अतः यह कहा गया कि भुगतान सन्तुलन को निरन्तर सक्रियता को गुधारने की आवश्यकता है।

भुगतान संतुलन की दीर्घकालीन निष्क्रियता की हानियाँ—

भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को विदेशों से ऋण लेकर या अपने विदेश स्थित बैंलेन्स पर आहरण करके पूरा किया जा सकता है। अब स्पष्टतः किसी भी देश के बैंलेन्स या उसकी मातृ विदेशी देशों में अमीमित नहीं होती है। तीसरा उपाय है स्वर्ण का निर्यात करना, किन्तु देश के स्वर्ण-स्टॉक भी सीमित हो जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भुगतान सन्तुलन की दीर्घकालीन प्रतिकूलता का सुधार किया जाना चाहिए। यह उपचार इसमें पहले ही कि देश के स्वर्ण कोष बहुत ही न्यून रह जायें, कर देना आवश्यक है। आखिरकार स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों का माध्यम है और कुछ देशों में तो वह करेंसी के प्रति विश्वास का स्रोत है, अतः स्वर्ण का स्टॉक एक स्थूलतम सीमा से कदापि कम नहीं होने देना चाहिए।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों ही, यदि वे दीर्घकालिक हो, विदेशी व्यापार के लिए हानिप्रद हैं। अतः इनके उपचार के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। उदाहरणार्थ अमेरिका का भुगतान-सन्तुलन दीर्घकाल से अमेरिका के लिए अनुकूल बना आ रहा है, जिससे दोष विदेश के लिए तो डालर सकट का शिरदर्द पैदा हुआ ही, अमेरिका के लिए भी वह एक समस्या बन गया। अतः उसे नॉर्वे-डालर देशों के साथ मिलकर इस समस्या के हल करने पर ध्यान देना पड़ा।

असाम्यता का उपचार

भुगतान सन्तुलन की लगातार सक्रियता या निष्क्रियता किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अन्य शब्दों में, जब सन्तुलन की असाम्यता के दीर्घकालिक बन जाने का खतरा प्रतीत हो, तब उसका अविलम्ब उपचार करना चाहिये।

असाम्यता के उपचार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की धारणा थी कि यदि भुगतान सन्तुलन में कोई असाम्यता उदय हो जाय, तो उसका उपचार स्वचालित रूप से (automatically) हो जाता है। सर्वप्रथम, ह्यूम ने व्यापार सन्तुलन के स्वकीय नियमन का सिद्धान्त (Theory of Automatic Regulation of Balance of Trade) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मान लीजिये ग्रेट ब्रिटेन की समस्त मुद्रा एक ही रात में पाँच गुनी कर दी जाती है। 'तब नवा समस्त धन एवं वस्तुओं की कीमतें इतनी ऊँची तक न पहुँच जायेंगी कि कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हमसे खरीदने में समर्थ न रहे और विदेशी वस्तुएँ इतनी महती न हो जायेंगी कि हम उन्हें खरीदने ही चले जायें' ऐसी दशा में हमें बड़ी हानि उठानी पड़ेगी तथा हमारे स्वर्ण कोष रिक होने लगेंगे। अन्ततः हमारी नीयतें पट कर विदेशियों के स्तर पर आ जायेंगी। इस

प्रकार, हम अपनी उस महान् खेद्यता को खो देते हैं जिसने हमें उपरोक्त अलाभ-
दायक स्थिति में पहुँचाया था।”¹

रिकाडों का दृष्टिकोण—

लेकिन यह रिकाडों ही थे, जिन्होंने एक सिद्धान्त की बुनियाद डाली। उन्होंने एक देश से दूसरे देश को वस्तुओं के आवागमन तथा, इनकी विपरीत दिशा में, द्रव्य के आवागमन को जामित करने वाले सिद्धान्तों का पता लगाया और बताया कि “व्यास्तिक करेंसी वाले देश की धातु की वह राशि स्वतः ही प्राप्त हो जायेगी जिसकी उसे, अपनी कीमतों की, विदेशों में प्रचलित कीमतों की तुलना में एक ऐसे स्तर पर जिससे कि उसके आयातों और निर्यातों के मध्य साम्य बना रहे, कायम रखने के हेतु आवश्यकता है।”²

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने यह मत प्रकट किया कि जब एक विशेष देश के भुगतान समुलन में चले आ रहे साम्य (equilibrium) में कोई बिघ्न पड़ता है, तो स्वचालित शक्तियाँ (automatic forces) सक्रिय हो जाती हैं तथा साम्य को पुनः स्थापित कर देती हैं। एक प्रकार से इन अर्थशास्त्रियों ने व्यापारवादी युग की प्रचलित उम बहुर धारणा में (कि देश को एक अनुकूल व्यापार समुलन द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में स्वर्ण का आयात करने की चेष्टा करनी चाहिये) परिवर्तन ला दिया।

साम्य की पुनः स्थापना की चार दशावस्थाएँ—

मान लीजिये कि एक नियत वार्षिक दर से सतिपूरक भुगतान करते रहने में किसी देश के भुगतानों के समुलन में बिघ्न पड़ जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार, चार स्पष्ट अवस्थाओं के द्वारा, जिनमें से कि प्रत्येक में जाने वाले और देने वाले देशों में विपरीत दिशाई गतियाँ होती हैं, समाधान सम्भव हो जाता है। ये अवस्थाएँ (steps) निम्नलिखित हैं—

¹ "Suppose that all the money of Great Britain were multiplied five fold in a night ... Must not the price of all labour and capital rise to such an exorbitant height that no neighbouring nation could afford to buy from us, while their commodities, on the other hand, become comparatively cheap that inspite of all the loss which would be run in upon us and money flow out, till we fall to the level with foreigners and lose that great superiority of riches which layed us under such disadvantages?"

—Hume

² "A country with a metallic currency will automatically get the amount of bullion it needs to maintain its prices at such a level relative to the prices prevailing abroad as to maintain an even balance between its exports and imports"—Ricardo

(१) देने वाले देश की करंसी का विनिमय मूल्य (exchange value) स्वर्ण निर्यात बिन्दु तक गिर जावेगा ।

(२) देने वाले देश से स्वर्ण पाने वाले देश में आयेगा । 'द देने वाले' देश के धातु कोष में घटौती के परिणामस्वरूप उसकी 'मुद्रा-पूर्ति' में कमी होने लगेगी ।

(३) मुद्रा पूर्ति (money supply) में कमी के फलस्वरूप निर्यात वस्तुओं और स्वदेशी बाजार में विक्रय वाली वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आयेगी ।

(४) स्वदेशी बाजार और निर्यात की वस्तुओं की कीमतें (आयात वस्तुओं की कीमतों की तुलना में) घटने के फलस्वरूप आयातों में कमी हो जावेगी तथा निर्यात बढ जायेगे ।

स्वर्ण का प्रवाह, त्रिदशी कीमती की तुलना में गृह कीमतों में कमी होने और राष्ट्रीय आय में गिरावट की श्रित्यावे तक जारी रहेगी जब तक कि वार्षिक निर्यात का आधिव्यय क्षतिपूर्क भुगताना की वार्षिक दर के बराबर न हो जाय । सम्पत्तान्, धैष अवधि में, अन्य बातें समान रहते हुवे स्वर्ण प्रवाह 'शून्य' रहेगा तथा कीमतों व आय में और अधिक परिवर्तन नहीं होंगे । अन्य प्रकार के असाम्य (जैसे निर्यातों की तुलना में अधिक आयात करने से उत्पन्न हुआ असाम्य) की इसी उद्गम में सुधार जायेगे ।

नव-परम्परावादियों द्वारा किये गये सशोधन—

नव परम्परावादियों (neo-classicists) ने स्वर्ण प्रवाहों द्वारा भुगतानों के समुत्पन्न की असाम्यता के स्वकीय मुधार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त में कुछ सशोधन किये । सर्व प्रथम, उन्होंने यह बताया कि साम्य केवल स्वर्ण के आवागमन के फलस्वरूप ही नहीं, वरन् पूँजी के आवागमनों के फलस्वरूप भी बना रह सकता है । कारण, स्वर्ण प्रसाधन देश के बाह्य प्रसाधनों (external resources) का एक अङ्ग मात्र है । अतः असाम्य की दशा में यदि देश बाह्य-कोष एवं सम्पत्तियों जोता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने स्वर्ण लोपा । दूसरे नव-परम्परावादियों ने परिमाण सिद्धान्त की अपरिष्कृत व्याख्या (crude version) के बजाय, जो कि रिकार्डों के सिद्धान्त का आधार थी, इसके परिष्कृत रूप (refined version) को अपने सिद्धान्त का आधार बनाया । आवश्यक वेद्यों में मुद्रा-पूर्ति पर आनुपातिक कोष प्रणाली द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है अर्थात् वहाँ केन्द्रीय बैंकों के निये यह आवश्यक है कि वे चलन में करंसी के कुल मूल्य का एक आनुपातिक भाग (जैसे १०%) स्वर्ण में या स्वर्ण में परिवर्तनशील विन्ही अन्य चीजों में रखे । ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक द्वारा सुरक्षित कोष में रखी गई प्रत्येक एक स्वर्ण इकाई के बदले मुद्रा के परिमाण में दो इनाइया की वृद्धि होगी न कि केवल एक इकाई की, जिसकी कलना अपरिष्कृत व्याख्या में की गई थी ।

अनाग्यता के सुधार संबंधी प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निष्कर्ष—

स्वयंमान देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति में उदय होत वाली असाम्यता के सुधार का जो सिद्धान्त प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था उसमें कुछ रोचक निष्कर्ष निकाले गये। ये निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

(१) विनिमय दर एक निश्चित टकसाली समता पर स्थिर हो जाने की प्रवृत्ति रखती है—यह कल्पना की गई है कि स्वर्ण के आवागमन के फलस्वरूप विनिमय दर एक नियत टकसाली समता (mint par) पर स्थिर हो जाने की प्रवृत्ति रखेगी। अतः किसी देश के भुगतान समतुलन में साम्यावस्था बनी हुई है या एक धार हट कर पुनः स्थापित हो गई है इसका पता व्यापार करने वाले देशों के मध्य एक नियत स्वर्ण समता पर विनिमय दर के स्थिर हो जाने से ज्ञात किया जा सकता है। रिकार्डों में तो एक 'आदर्श' विनिमय दर की धारणा करती थी। आन्तरिक कीमती, उत्पादन, मजदूरियों और आय के स्तर यह सभी इस 'आदर्श' (norm) (अर्थात् वह स्वर्ण समता जो कि दयदासिता समता भी है) के निकटतम आने का यत्न करते हैं। समायोजन प्रक्रिया के लिये यह आवश्यक है कि कीमती, मजदूरियाँ और आय तीनों ही त्रय शक्ति मानक (norm) की अनुसारता में समायोजित हो जायें। [इस हेतु आर्थिक प्रणाली में पूर्ण लोच होने की उत्पत्ति करनी पड़ती है।]

(२) विश्व का स्वर्ण भण्डार देशों में समान रूप से वितरित हो जाता है—रिकार्डों की दृष्टि में स्वर्ण एक वस्तु मात्र है जो समस्त संसार में तुरन्त ही विनिमय की जा सकती है। मध्यस्थी मांग होने के कारण इसकी कीमत सर्वत्र समानता की प्रवृत्ति रखती है। अतः रिकार्डों ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक देश में न तो अति-अधिक स्वर्ण रह सकता है और न अति कम। कारण, जब किसी देश की मौद्रिक प्रणाली में बहुत अधिक स्वर्ण होता है, तो वहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं जिससे निर्यात हतोत्साहित और आयात प्रोत्साहित होने हैं भुगतान-समतुलन निश्चित बन जाता है तथा आयात-अतिरिक्त (import surplus) के भुगतान हेतु स्वर्ण का निर्यात करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ण की मात्रा कोष में उचित स्तर तक घटने लगती है। दूसरी ओर जब किसी देश में स्वर्ण की बहुत ही कमी हो, तो विपरीत दिशाई घटनाएँ होती हैं। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के मध्य स्वर्ण का व्यापारित वितरण कराने में एक माध्यम का कार्य करता है।

(३) स्वर्णमान का सधर्म रहित कार्यवाह्य—रिकार्डों ने एक सरल अ-प्रवर्धित मौद्रिक प्रणाली की धारणा की हुई थी, जो आन्तरिक और बाह्य दयाशील तथा आ-आने वाले स्वर्ण की मात्रा पर निर्भर है। जब किसी देश को स्वर्ण प्राप्त होता है, तो वह केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश कर लेता है, जिसमें कि चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। [यह मान लिया गया था कि जब कभी स्वर्ण कोष में वृद्धि होती, तब ही केन्द्रीय बैंक मुद्रा की शक्ति बढ़ा देगा।]

अति कल्पनात्मक दशाओ में ही सिद्धान्त बंध होना—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असाम्यता के सुधार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त केवल बहुत ही कल्पनात्मक (hypothetical) दशाओ के अन्तर्गत, जोकि हमारे आधुनिक जगत में कठिनाता से ही विद्यमान है बंध होना है।

(१) १९वें शताब्दी के अन्तर्मान, आधुनिक विश्व में बाह्य स्थायित्व की अपेक्षा आन्तरिक स्थायित्व को अधिक महत्त्व दिया जाता है—उन्नीसवीं शताब्दी में यह विचार फैला जाता था कि यदि केवल बाह्य स्थायित्व (external stability) का ध्यान रखा जाय, तो आन्तरिक स्थायित्व (internal stability) अपना ध्यान खुद कर लेगा, लेकिन, प्रोफेसर कीन्स (Keynes) के प्रभाव के अन्तर्गत आधुनिक जगत में आन्तरिक स्थायित्व को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा है। अब यह कहा जाता है कि लागत कोमल स्थायित्व या आन्तरिक स्थायित्व को बिगड़ने नहीं देना चाहिये अन्यथा अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के संघर्ष तथा दबाव उत्पन्न हो जायेंगे। इस बात की आवश्यकता रखने चाहिए कि स्फुरित (inflationary) एवं विस्फीतिक (deflationary) दोनों ही प्रकार के दबाव से बचा जाय, क्योंकि दोनों के पुरे प्रभाव पड़ने हैं। [स्मरण रह कि उन्नीसवीं शताब्दी में विनिमय समता को टकसासी समता के बराबर स्थिर रखा जाता था। यदि किसी तरह से इनमें भिन्नता हो भी जाती थी तो उसे स्वर्ण पाने वाले देश में मुद्रा प्रसारिक परिस्थिति द्वारा एवं स्वर्ण खोने वाले देश में मुद्रा विस्फीति परिस्थिति द्वारा सुधार लिया जाता था।]

(२) आधुनिक अर्थ-व्यवस्थाओ की विशेषता उनकी बेतोकता है—देश में पूर्ण प्रतियोगिता और उपत्ति के साधनों को पूर्ण यतिशील मानते हुये प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने अर्थ-व्यवस्थाओ को पूर्णतः लोचदार (flexible) समझ लिया। लेकिन, हमारे आधुनिक विश्व में, अपूर्ण एवं एकपक्षिकारिक प्रतियोगितायें विभिन्न अंशों में विद्यमान हैं। अतः इस सीमा तक वर्तमान अर्थ-व्यवस्थायें बेतोक हैं और स्वयं को शीघ्रतापूर्वक तथा स्वचालित रूप से समायोजित करने में असमर्थ हैं। उदाहरणार्थ, श्रम संघों के उदय के कारण मजदूरी-ढाँचे कठोर और बेतोक हो गये हैं।

(३) स्वर्ण के एक व्यापारुद्ध वितरण की कल्पना सब नहीं है?—प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने यह मान लिया था कि विभिन्न देशों में स्वर्ण व्यापक रूप से वितरित हो जाना है। लेकिन यह मान्यता आज सही नहीं है। यदि रिकार्डों की कल्पना के अनुसार चला जाय तो व्यापारिक देशों द्वारा स्वर्ण की अत्यधिक प्राप्ति या अत्यधिक भुगतान स्वचालित रूप से समाप्त हो जाने चाहिये, किन्तु १९३० में ऐसा नहीं हुआ था। कारण, अमेरिका ने स्वयंभूत का सेल ठीक तरह से नहीं खोला। उसने देश में आने वाले स्वर्ण को मौद्रिक चलन में प्रवेश नहीं करने दिया। परिणामतः समायोजन की दिशा रुक गई तथा अमेरिका में स्वर्ण के अन्वेषण लग गये।

(४) राजकीय हस्तक्षेप आज का एक फंजन बन गया है—रिकाबों ने यह सोचा कि यदि हमारे पास एक ऐसी नलन प्रणाली हो जो स्वचालित रूप से साम्य' म आने की सामर्थ्य रहे तो सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु आजकल हम यह देखते हैं कि न केवल मौद्रिक प्रणाली के क्षेत्र में बरत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी सरकार का हस्तक्षेप बढ़ गया है । पूँजीवादी यता तब न नियोजित विकास की योजनाएँ बनाई हुई हैं । इस प्रकार आज असाम्यता गर्मी चीज नहीं रह गई है जो कि अर्थव्यवस्था द्वारा स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाय परन्तु ऐसी चीज है जिसके लिए योजनाबद्ध प्रयास करने पड़ते हैं ।

चूँकि प्रतिष्ठित सिद्धान्त द्वारा मानी गई द्वायमे वास्तविक जगत में मिलान नहीं है इसलिए व्यापारिक देशों के भुगतान सन्तुलनों में असाम्यता का स्वचालित सुधार वा प्रतिष्ठित सिद्धान्त लागू नहीं होता ।

असाम्यता के सुधार के लिए आधुनिक युग में अपनाये गये उपाय—

आजकल भुगतान सन्तुलन की साम्यता को कायम रखने के लिए (और यदि वह टूट गई है तो उसकी पुन स्थापना के लिए) मनेन एव पूर्व नियोजित प्रयत्न किए जाते हैं । इन उपायों का अध्ययन हम प्रतिकूल असाम्यता के सन्दर्भ में करेंगे । कारण, प्रतिकूल असाम्यता 'अनुकूल असाम्यता' की अपेक्षा अधिक हानिप्रद है । इसके अतिरिक्त एक मत्रिय सन्तुलन को सही करने के उपाय उन उपायों के ठीक विपरीत हैं जो कि भुगतान सन्तुलन की निष्पक्षता के उपचार के लिए अपनाये जाते हैं । विभिन्न उपायों की दो बर्गों में विभक्त किया जा सकता है —(I) मौद्रिक उपाय (monetary Methods) एव (II) अ मौद्रिक उपाय (Non Monetary Methods) ।

(I) मौद्रिक उपाय

मौद्रिक उपायों में निम्नाविध उपाय सम्मिलित हैं —

(१) स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य का ह्रास—मूल्य ह्रास में सरकार या कानून के हस्तक्षेप के बिना ही, देश की आर्थिक परिस्थिति के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप, स्वदेशी मुद्रा का बाह्य मूल्य (external value) कम हो जाता है । यह बात तब ही सम्भव है जबकि विनिमय दर को स्वतन्त्र (free) छोड़ दिया जाय । जब भुगतान सन्तुलन में प्रतिकूल असाम्यता होती है, तो स्वदेशी करेंसी के लिए माँग इसकी पूर्ति की तुलना में कम होगी, अर्थात् वेकों में विदेशी करेंसी विनिमय खरीदने वाले लोग बेचने वालों की अपेक्षा अधिक आयेंगे । फलतः वेकस अपना विदेशी मुद्रा का माग ऊँचा बनाने लगेंगे । इससे विदेशी करेंसिया में स्वदेशी करेंसी का मूल्य गिर जाता है । यही स्थिति मूल्य ह्रास (depreciation) कहलाती है । इसके कारण स्वदेशी मुद्रा विदेशियों के लिए खर्ची हो जाती है और (यदि स्वदेशी बाजार में नीमत स्तर पूर्ववत् रहे तो) स्वदेशी वस्तुयें विदेशियों की खर्ची मिलने लगती हैं । इससे निर्यात प्रोत्साहित होते हैं ।

दुगरी ओर चूँकि स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में गिरावट आती है जबकि विदेशी वरर-सी के मूल्य में वृद्धि होती है, इसलिए, विदेशी वस्तुओं देशवासियों का मर्चो पडने लगती है। इससे आयात निरुत्साहित होते हैं। निर्यात-प्रोत्साहन और आयात हताश्याहन दोनों के सामूहिक प्रभाव स्वरूप भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता का मुधार हो जाता है।

(२) मुद्रा का अवमूल्यन करना—प्रायः सभी देशों में विनिमय-दरों पर नियन्त्रण रखा जाता है। ऐसी दशा में जब भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को दूर करने हेतु स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी होना आवश्यक समझा जाय तो सरकार जानबूझकर विनिमय दर को एक दृष्टे हुए स्तर पर निश्चित कर देती है। स्वदेशी मुद्रा के बाह्य मूल्य को सरकार द्वारा जानबूझकर घटाना ही मुद्रा का 'अव-मूल्यन' (Devaluation) कहलाता है। यदि देश स्वर्णमान पर हो और अन्य देश भी स्वर्णमान अपनाय हुए हों, तो अवमूल्यन के लिये स्वदेशी करन्सी की धातु-मात्रा (metallic contents) को कम कर दिया जाता है। अन्य दशाओं में जिस दर पर मुद्रा अविभाजी द्वारा विदेशी वरर-सी खरीदी और बेची जाती है उसे ऊँचा करके अव-मूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन का प्रभाव भी मूल्य ह्रास के सदृश होता है क्योंकि धना में ही विनिमय दर में गिरावट आती है। फलतः निर्यात प्रोत्साहित और आयात हताश्याहित होते हैं जिनमें भुगतान सन्तुलन के रेडिट और क्रेडिट खानों के मध्य बालि पडने लगती है।

किन्तु स्मरण रहे कि मूल्य ह्रास और मुद्रा अवमूल्यन दोनों ही उपायों की सफलता विदेशियों की अनुकूल प्रतिक्रिया (favourable reaction) और उनकी माँग सम्बन्धी लोच पर निर्भर होती है। यदि विदेशी सरकारें किसी देश निरोध की विनिमय दर में गिरावट को सहन न करें और प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी विनिमय-दरों में भी कमी कर दें, तो उक्त देश को मूल्य ह्रास या अवमूल्यन से आशा किया गया लाभ प्राप्त न हो सकेगा। सन् १९३० की मन्दी के समय में ऐसा हो देखा गया था। इसी तरह अवमूल्यन की नीति ग्रहण करते समय अन्य देशों की स्वदेशी वस्तुओं के लिए माँग की लोच पर भी ध्यान देना आवश्यक है। यदि निर्यात वस्तुओं के प्रति विदेशियों की माँग लोचदार है तो अवमूल्यन के फलस्वरूप मूल्य में कमी होने से आप की हानि इतनी न होगी जितनी कि निर्यातों के बढ़ने से लाभ। अर्थात् कुल पर, देश की अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकेगा। दूसरी ओर, यदि देश की निर्यात वस्तुओं के प्रति विदेशियों की माँग वेलोच है तो अवमूल्यन करने में देश को कोई विशेष लाभ न होगा।

(३) मुद्रा का संकुचन करना—उपरोक्त दोनों उपाय (मूल्य ह्रास एवं अवमूल्यन) स्वदेश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करने से सम्बन्धित हैं। किन्तु तीसरा उपाय स्वदेशी मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को ऊँचा उठाने से सम्बन्ध रखता है। जिस प्रकार में स्वदेशी वरर-सी का बाह्य मूल्य गिरने से भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता

से सुधार की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार स्वदेशी करों का आन्तरिक मूल्य बढ़ने से भी असाम्यता का सुधार सम्भव हो जाता है। करों का आन्तरिक मूल्य ज़ोपा करने हेतु चलन माध्यम का संकुचन करने सामान्य कीमत् स्तर को गिराया जाता है। इसे मुद्रा-संकुचन (currency deflation) कहते हैं। जब देश में वस्तुओं की कीमते घट जाती है, तो वह वस्तु के लिये अच्छा और विदेश के लिये 'बुरा' बाज़ार बना जाता है। अर्थात्, विदेशी हम से अधिक खरीदते हैं और देशवासी भी, विदेशों में वस्तु खरीद करके, स्वदेशी वस्तुओं पर ध्यान देते हैं। इससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात घटते हैं तथा अन्ततः दोनों ही एक-दूसरे के साथ समायोजित हो जाते हैं।

किन्तु मुद्रा के संकुचन द्वारा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का उपचार बार्ड अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि देश में कीमतों का जम्बूझकर गिराने से आर्थिक संकट उत्पन्न होने का भय रहता है। कारण, जब कीमते घट जाती हैं, तो उत्पादकों को हानि होने लगती है, वे उत्पादन घटाने लगते हैं, जिससे बेकारी एक मंदी फैलती है यह यदि कभी यह उपाय अपनाया ही जाय, तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी।

(II) अ-मौद्रिक उपाय—

मौद्रिक उपायों के अन्तर्गत आयात-निर्यात को प्रत्यक्ष रूप से (मुद्रा के द्वारा) प्रभावित करके भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का यत्न किया जाता है, किन्तु अ-मौद्रिक उपायों के अन्तर्गत आयात-निर्यात को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है। ये उपाय आयातों को प्रतिबंधित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने में सम्बन्धित हैं। निर्यात प्रोत्साहन की अपेक्षा आयात-प्रतिबंधों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है।

(१) आयातों में कटौती—प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के हेतु सर्वप्रथम देश की आयात सूची की सावधानी से परीक्षा करके यह पता लगाना चाहिए कि किन अनावश्यक आयातों को, देश को अर्थ-क्षयकता को हानि पहुँचाय बिना, घटाया या समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान में रखना चाहिए—

(१) अनेक वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनका आयात प्रायः भर्ना वर्गों की इच्छाओं को सन्तुष्ट करने हेतु किया जाता है और यह सोच उन वस्तुओं को इसलिए प्रयोग में लाते हैं कि एक विलासपूर्ण जीवन धनीत कर सकें। उन इनके आयात को सहज ही कम किया जा सकता है।

(२) ऐसे आयात-स्थानापन्नो को, जिनका उत्पादन स्थानीय रूप में उपलब्ध उत्पाद साधनों की सहायता से तुरन्त ही अरम्भ किया जा सकता है, देश में ही उपज करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

- (iii) ऐसी वस्तुयें आयात करनी चाहिए जो कि भविष्य में आयातों को घटाने में सहायक हों। उदाहरणार्थ, आयात स्थानापन्नो (Import substitutes) के उत्पादन का संगठन करने हेतु विदेशों से आयात किये जाने वाले उत्पत्ति साधन निम्न प्रकार सहायक हो सकते हैं—
 (अ) कालान्तर में आयातों में कटौती को सुविधाजनक बनाना, (ब) बुद्धि आवश्यक आयात स्थानापन्नो का देशी उत्पादन सम्भव बनाना, एवं (स) आयात रचना में इस प्रकार संशोधन करना कि जिसमें अंतिम उपयोग के लिए निमित्त वस्तुओं के बजाय दुर्लभ उत्पत्ति-साधनों के आयात को बढ़ावा मिले।

अवांछनीय आयात को घटाने या समाप्त करने के हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

(अ) आयात निषेध (Import prohibition)—जिन वस्तुओं को अनावश्यक या कम महत्त्वपूर्ण समझा जाय, उनके आयात का निषेध दिया जा सकता है। इनके बच्चे मालों के निर्यात का भी देश में इनकी कीमते गिराने के लिए, निषेध किया जा सकता है।

(ब) आयात कर (Import duties)—आयातों को कम करने का एक अन्य उपाय यह है कि आयात वस्तुओं पर कर लगाये जायें या जब यह पहले से ही लगे हुये हों तो उनमें वृद्धि कर दी जाय। यह कर वस्तु की प्रति इकाई के अनुसार या कीमत के एक प्रतिशत के रूप में लगाये जा सकते हैं। इकाई की परिभाषा विभिन्न प्रकार से (जैसे—टौल, लम्बाई, आयतन या अन्य विविध विवरण के रूप में) की जा सकती है। वस्तु की कीमत के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाये गये करों को 'गुन्या-नुसार चुगी' (advalorem duties) कहते हैं। आयात कर लगने या बढ़ने से कंसाओं को ऊँची कीमत देनी पड़ती है और विक्रेताओं को कम कीमत मिलती है तथा अन्तर की राजस्व सरकार के खजाने में पहुँच जाती है। इस प्रकार, विदेशों से पूर्ति और स्वदेश में माँग दोनों में ही कमी हो जाती है। अतः यह कहा जाता है कि आयात-कर भुगतान-सन्तुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का एक प्रभावशाली उपाय है।

किन्तु, अनेक दशाओं में प्रभावशाली होने लगे भी, आयात कर सभी दशाओं में और सर्वदा प्रभावशाली होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, आयातों पर खर्च करने से जो लाभ देने वाले निर्माण की जाने वाली वस्तुओं पर व्यय करने में प्रयोग किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो निर्यात भी घट जायेंगे जिससे आयातों को घटाने में हुआ लाभ बेकार हो जायेगा। अथवा यह भी हो सकता है कि बचाई हुई आय को कर-मुक्त या कम कर लगी हुई विदेशी वस्तुओं पर व्यय किया जाय। ऐसी दशा में भी 'कुल आयात' में कोई कमी न हो सकती।

(स) प्रशासनिक उपाय—इन उपायों का सम्बन्ध वस्तु सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करने से है । नियमों की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है जोकि आयातको को परेशानी में डालने वाली तथा निरुत्साहित करने वाली हो उदाहरणार्थ, यदि कोई आयात कर मूल्यानुसार लगाया गया है तो चुन्नी अधिकारी बीजक की संपत्ता को अस्वीकार करते हुए वास्तविक में अधिक कोमत नियत करके अधिक कर वसूल कर सकते हैं । लेकिन इस उपचार में अनैतिकता की पुट होने के कारण इसका व्यापक समर्थन नहीं किया गया है ।

(इ) कोटा प्रणाली—आयातों को सीमित करने का एक अन्य उपाय कोटा प्रणाली (Quota System) है । कोटा प्रणाली के रूप कई हैं जैसे —

(१) लाइसेंस कोटा प्रणाली, जिसके अन्तर्गत सरकार कुछ विनियुक्त व्यापारियों को ही वस्तुओं के आयात करने की अनुज्ञा (licence) देती है । ये व्यापारी भी केवल निश्चित वस्तुओं और निश्चित मात्राओं में ही मंगा सकते हैं । किन्तु वस्तुओं का और कितनी मात्राओं में आयात किया जाय इसका निर्णय समय-समय पर देश की परिस्थितियों में सदर्थ में सरकार करती है ।

(२) एक पक्षीय कोटा प्रणाली, जिसमें देश अपने ही आयातों पर प्रतिबन्ध लगाता है । इसके आधीन या तो प्रत्येक वस्तु की अधिकतम आयात-मात्रा निश्चित कर दी जाती है और इसे बिना के किसी भी देश से मंगाया जा सकता है, जिस देश में इसे 'सार्वजनिक कोटा' (Global Quota) कहते हैं, अथवा, सरकार द्वारा वस्तु के आयात के लिये निश्चित की गई अधिकतम मात्रा उन्हीं देशों से एवं उतनी ही मात्राओं में मंगाई जा सकती हैं, जिन्हें सरकार ने नियत कर दिया हो, जिस देश में इसे 'विभाजित कोटा' (Allocated Quota) कहते हैं ।

(३) द्विपक्षीय कोटा प्रणाली, जिसमें सरकार किसी देश से केवल एक निश्चित मात्रा तक आयात करने की अनुमति देती है और इस मात्रा तक आयातकों से केवल रियायती आयात कर ही वसूल किये जाते हैं किन्तु अधिक आयात करने पर वे दण्डस्वरूप ऊँची दर से वसूल किये जायेंगे ।

कोटा वस्तु की मात्रा (Quantity) के सदर्थ में निश्चित किया जा सकता है अथवा मूल्य (Value) के सदर्थ में । अधिकारीगण यह निश्चित कर सकते हैं कि अमुक वस्तु का आयात अमुक मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये । मात्रा के बजाय मूल्य-सीमा को कोटा प्रणाली का आधार बनाना अधिक उचित प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुल आयात मूल्य में कमी करना है न कि आयात-मात्रा में कमी करना ।

स्मरण रहे कि आयातों में कटौती करने भी एक सीमा होती है। देश की प्रगति और सम्पन्नता के हित में कुछ आयात करने अति आवश्यक हैं। इसके अनि-रिक्त विदेशी देशों द्वारा बदले की कार्रवाही (retaliation) की भी आशङ्का है, क्योंकि वे भी अपने यहाँ हमारे देश में जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमारे द्वारा आयातों में कटौती के प्रयत्न भुगतान सम्बन्धन की प्रतिकूलता को मुखारने की दृष्टि से, प्रभावशाली न होयें, इस प्रकार, एक दूसरे पर सीमा तब आयात किये ही जायेंगे।

(२) निर्यात वृद्धि—निर्यात वृद्धि (Enlargement of Exports) सम्बन्धी उपाय भी भुगतान सम्बन्धन की प्रतिकूलता का एक अच्छा उपचार हो सकते हैं, क्योंकि आयात अतिरेक का भुगतान निर्यात वृद्धि द्वारा किया जा सकता है। निर्यातों में वृद्धि करने हेतु निम्न कदम उठाये जा सकते हैं—(अ) कुछ मर्चे केवल निर्यात के लिए ही सुरक्षित रखकर निर्यात वस्तुओं के लिए स्थानीय माँग का काम किया जा सकता है। (ब) देश के बाहर नये बाजारों की खोज की जाय और विभिन्न वस्तुओं की निर्यात सम्भावनाओं का पता लगाया जाय। (स) समुचित वार्ता द्वारा व्यापार की अधिक अनुकूल शर्तें प्राप्त की जायें। इसका प्रभाव उसना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि निर्यात के भौतिक आकार में वृद्धि होने का। (द) बहु-पक्षीय व्यापार समझौते किये जायें। (इ) निर्यात-कर घटाये जायें। (२) उतारान लागत घटाई जायें। (ल) एक सीमा से अधिक निर्यात करने वाले व्यापारियों को विशेष सुविधाएँ दी जायें। (म) निर्यात वस्तुओं के प्रयोग में जाने वाले कच्चे मालों पर बमूल की गई छुट्टी लौटाई जाय। (ह) कुछ वस्तुओं के निर्यात को आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाय।

(३) विविध नियन्त्रण—इस उपाय का आशय निर्यात-आय पर कड़ी निगाह रखने तथा जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हो उसके व्यय पर कड़ा नियन्त्रण रखने में है। सब व्यापारियों को, जिन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यह आदेश दिया जा सकता है कि वे उसे एक केन्द्रीय कोष में जमा करा दें। बाद में अधिकारीगण इसे विभिन्न मदों पर, सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता रूप के अनुसार, वितरित कर सकते हैं।

ऊपर वर्णित भौतिक एवं अमौद्रिक उपाय विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न समयों पर अपनाये गये हैं। ये उपाय एक दूसरे के पूरक हैं विरोधी नहीं। इनमें परस्पर उचित सम्बन्ध होना चाहिए। जैसे आपसद कर लगाना खदके प्रचलित ढङ्ग है। आर्थिक सहायता या ऋण कभी-कभी ही प्रयोग किया जाता है। जबमूल्यन, मूल्य ह्रास, कोटा और विविध-नियन्त्रण असाधारण उपाय हैं, जो तब ही अपनाये जाते हैं जबकि साधारण उपाय सफल न हों।

आधुनिक वर्षों में असाध्यता के गुधार में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी सहायता मिलने लगी है। इस गस्था ने भुगतान सम्बन्धन की असाध्यताओं को दो वर्गों

मे दाँटा है—मौलिक असाम्यता (Fundamental disequilibrium) एवं अस्थायी असाम्यता (Temporary disequilibrium) । प्रत्येक देश में उपचार के अलग अलग उपाय किये जाने चाहिए । इस विषय में कोप के विशेषज्ञों का बहुमूल्य परामर्श सदा उपलब्ध रहता है तथा कोप में अस्थायी ऋण भी मिल सकते हैं ।

उल्लेखनीय है कि भुगतान सन्तुलन की अल्पकालिक असाम्यता अधिक चिन्ता की बात नहीं है किन्तु दीर्घकालिक असाम्यता नि सन्देह चिन्ता का विषय होती है । देखा जाय तो कोई देश अपने भुषण सन्तुलन को निरन्तर और दीर्घकाल तक अनुकूल बनाये नहीं रह सकता है । भुषण सन्तुलन को अनुकूल रखने के लिए निर्माता को प्रोत्साहन देना और व्यापारों पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है किन्तु जब एक देश ऐसी स्वायत्त नीति अपनाता है तो अन्य देश भी अपने हितों की रक्षा के निम्न, वैसी ही नीति अपनाने लगते हैं । इससे विश्व व्यापार में कमी आ जाती है । भुगतान सन्तुलन को निरन्तर अनुकूल बनाये रखना केवल ऐसी असाधारण दशाओं में ही सम्भव है जिनमें कि देश अधिकार वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो और उसके निर्यातों के प्रति विदेशियों की माँग बेनीच हो । लेकिन ऐसे देश भी जल्दी ही राजनैतिक झगड़ों में फँस जाते हैं और उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ती है । उदाहरणार्थ मध्य पूर्व के देशों में जनसंख्या कम है और वहाँ अधिक तादाद में तेल मिलता है, जिसमें वहाँ उद्योग-धंधे विकसित न होने हुए भी उनका भुगतान सन्तुलन निरन्तर अनुकूल रहता है । किन्तु इसी में विश्व के शक्तिशाली देश वहाँ अपने राजनैतिक दाँव-पेच दिखाते रहते हैं । कुल पर, यह कह सकते हैं कि विश्व व्यापार सब देशों के सहयोग पर निर्भर है । सामूहिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन की प्रवृत्ति यथाम्भव मन्तवित और स्थिर ही रहनी चाहिए ।

आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन का परस्पर समायोजन (Reconciliation of Internal and External Balance)

जब किसी देश का भुगतान सन्तुलन उसके प्रतिस्पर्धियों से हो गया है तो अधिकारियों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के सन्तुलनों पर एक ही हुई नीति के प्रभावों को समझना पड़ता है । उदाहरणार्थ देश A की विदेशों में बाई हुई मन्दी के फलस्वरूप अपनी विदेशी विदेशी न कमी आने से भुगतान सन्तुलन में प्रतिस्पर्धिता का सामना करना पड़ सकता है । प्रतिस्पर्धियों भुगतान सन्तुलन के उपचार का प्रतिष्ठित उपाय तो यह था कि मजदूरों में मजदूरी (wage deflation) या (बाद में) क्रिन्डम हॉम द्वारा माँग को कम किया जाय । किन्तु अभी हाल में आय नीति (Income policy) पर अधिक बल दिया गया है ।

आय नीति (Income policy)—

‘आय नीति’ के आधीन अनुत्क उद्योगों (जैसे-करो में वृद्धि या सांख्यिकिक दृष्टि से नवीन) के द्वारा माँग में शक्ति नीति मुद्रा पुष्टि में वृद्धि एवं ऊँची व्याज दर) की महत्ता तेज़ी हुई, आय पर नियन्त्रण किया जाता है । एक प्रतिस्पर्धी-भुगतान-
अ० पृ०, १५

सन्तुलन वाली अवधि में बाय की बिरावट के साथ सम्बन्धित बाधाओं में कभी हो जाती है। किन्तु वित्तीय नीति (प्रचुल्क नीति+मौद्रिक नीति) का सहारा लेते समय, अधिकारियों को चाहिए कि इसके आन्तरिक सन्तुलन पर जो प्रभाव पड़ेगे उनको भी विचार में रखें। उदाहरणार्थ, सन्तुलन की नीति A देने के लिए बाह्य-सन्तुलन की समस्या का तो सुलझा देती है किन्तु आन्तरिक सन्तुलन की समस्या को बनभा देती है। जैसे—A देश में बेरोजगारी पहले से ही थी, किन्तु अब वह अधिक उग्र हो जाती है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

जब दो देशों के समक्ष अपने आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलनों के मध्य सामंजस्य रखने की समस्याएँ हो तो उनके सम्बन्धित समाधान का तरीका मोर्सेसर मीड (Meade) ने अपनी पुस्तक Balance Payments में सुझाया है। यह तरीका निम्न-लिखित तालिका के रूप में सक्षिप्त किया जा सकता है—

**Conflicts of Criteria for Inflationary and Deflationary
Financial Policies¹**

National Income in the Surplus Country	National Income in the Deficit Country	In the interests of		
		external balance	internal balance in the Surplus Country	internal balance in the Deficit Country
<p>is too low (L) Or too high (H)</p>		<p>there should be an inflation (S+) or deflation (S—) of domestic expendi- ture in the surplus country and an inflation (D+) or deflation (D—), of domestic expenditure in the deficit country</p>		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
L	L	S+ D—	S+ D+	S+ D+ (1)
	H	S+ D—	S+ D+	S— D— (2)
H	L	S+ D—	S— D—	S+ D+ (3)
	H	S+ D—	S— D—	S— D— (4)

¹ Reproduced from *International and Interregional Economics*

—Harris, p. 77.

उपरोक्त तालिका में चार पंक्तियाँ हैं जिन से प्रथम उन बैकल्पिक नीतियों का मकन करती है जो कि दोनों देशों में राष्ट्रीय आय बहुत ही नीची (1.) होने की दशा में आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन प्राप्त करने हेतु अपनाई जानी चाहिए। सन्तुलन बाह्य सन्तुलन प्राप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय खाते में अतिरेक (surplus) रखने वाले देश को अपनी आय में घाट की वित्त व्यवस्था (deficit financing) द्वारा, धृष्टि करन (inflate) का यत्न करना चाहिए। आधिक्य वाले देश की यह नीति भुगतान सन्तुलन में इसके आधिक्य की छटा दूनी या गगापत कर देगी, जिससे आधिक्य वाला देश एवं घाटे वाला देश दोनों ही अपना-अपने अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में साम्य के अधिच निकट पहुँच जायेंगे। आधिक्य देश (S) के लिए इसका प्रभाव आन्तरिक आवश्यकता के अनुरूप ही होता है—आय में वृद्धि होना, रोजगार में वृद्धि होना और बेकारी में कमी आना। अतः न केवल S+ (अर्थात्, आधिक्य वाले देश में आन्तरिक व्यय को बढ़ाने की नीति) आन्तरिक एवं बाह्य दोनों सन्तुलन के लिए एक सही नीति है (इसीलिए S+), 1c, 1d और 1e में है), वरन् आधिक्य (S) देश के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सन्तुलन की प्राप्ति के लिए आवश्यक नीतियाँ में सञ्जति (consistency) भी पाई जाती है।

किन्तु अब घाटे वाले देश (D) की दृष्टि से विचार कीजिए। बाह्य सन्तुलन की ओर बढ़ने के लिए D को अपनी आय का मकुचन करना चाहिए जिससे कि आय में और इसलिए आयातों में कमी होकर सन्तुलन की प्रतिकूलता सुधरने लगे। किन्तु दुभाग्यवश बाह्य सन्तुलन के लिए प्रस्तावित नीति आन्तरिक सन्तुलन की दृष्टि में गलत नीति है। चूँकि D मन्दी के शक्कर में पड़ा हुआ है, इसलिए मकुचन उसके लिए लाभप्रद दवा नहीं है। अतः D के मामले में एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसलिए उसे बहुत सीमा तक S की सही नीतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि S की सही नीतियों के द्वारा बाह्य और आन्तरिक सन्तुलन प्राप्त हो सके, तो फिर D को अपनी आन्तरिक स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार चलना होगा, अर्थात् विस्तारमूलक नीति चलाने हेतु विदेशी ऋणों और निर्यातों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे कि यह नीति उसके अन्तर्राष्ट्रीय खाते में सङ्कट की स्थिति पैदा न कर सके, क्योंकि आयात अत्यधिक बढ़ जायेंगे।

तीन अन्य दशाओं (अर्थात् S में निम्न राष्ट्रीय आय + D में ऊँची राष्ट्रीय आय, S में ऊँची राष्ट्रीय आय + D में नीची राष्ट्रीय आय, एवं S में ऊँची राष्ट्रीय आय + D में ऊँची राष्ट्रीय आय) भी गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। ये समस्याएँ दो दशाओं में यथोचित रूप से हल हो जाती हैं किन्तु तीसरी दशा (S में ऊँची राष्ट्रीय आय + D में नीची राष्ट्रीय आय) में नहीं। बाह्य सन्तुलन की प्राप्ति के लिए आन्तरिक व्यय की S में घटाना और D में घटाना चाहिए (जैसा कि प्रथम पंक्ति में है)। किन्तु S में आन्तरिक सन्तुलन स्थापित करने के लिए S और D दोनों की ही आन्तरिक व्यय घटाने चाहिए, अतः यहाँ देश में, जोकि गम्भीर-नियोजित अर्थ-

व्यवस्था (under employed economy) है। आन्तरिक समुलन की प्राप्ति के लिए, दोनों देशों को व्यय बढ़ाने चाहिए। अतः S की बाह्य आवश्यकताओं के लिए जो नीति महो है वह उभरी आन्तरिक स्थिति के लिए समान नीति है, कारण, आन्तरिक व्यय की वृद्धि, जो मजदूरी समुलन को सुधारेगी, आन्तरिक स्थिति को और भी स्थानिक बना देगा तथा D भी यह पायेगा कि बाह्य नीति के लिए आन्तरिक व्यय में जिस घटोती की आवश्यकता है उसे कार्योन्वित करने में उसकी पहले से ही अर्द्धनियोजन व्यवस्था और भी समुचित हो जायेगी। प्रोफेसर भीड ने अपनी पुस्तक के एक अंग में अध्याय में इन्हीं चार दशाओं के लिए, जबकि अधिकारियों को प्रसुक्त एवं मौखिक नीतियों के द्वारा आन्तरिक व्यय में घटाव करने के आधुनिक हथियारों के साथ कीमत सम्बन्धी हथियार (जैसे—मजदूरी में घटोती, मूल्य ह्रास) भी उपलब्ध हों, वैकल्पिक नीतियों पर विचार किया है। घाटे वाले देश के लिए बाह्य समुलन की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम उपाय मजदूरियों में कमी करना या विनिमय ह्रास करना है, किन्तु यहाँ भी बाह्य एवं आन्तरिक उद्देश्यों में संघर्ष पर गिरावू रखनी चाहिए। यह सम्भव है कि आन्तरिक समुलन बढ़ने हेतु वित्तीय नीति और बाह्य समुलन के लिए कीमत नीति अपनाई जाय अथवा विपरीत क्रम में बाह्य समुलन के लिए वित्तीय नीति तथा आन्तरिक समुलन के लिए कीमत नीति अपनाई जाय।

डालर-संकट

'डालर संकट' का अर्थ डालर की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम हो जाना है। डालर की पूर्ति का स्रोत अमेरिका द्वारा विश्व के अन्य देशों में खरीद करना या उन्हें ऋण देना है और डालर की मांग तब उदय होती है जबकि अन्य देश उसमें आयात करते हैं या उसे मूलधन, व्याज अथवा लान्सेस चुकाते हैं। नीचे हम जिस 'डालर संकट' की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस तथ्य का फल मान है कि विश्व-बाजार में डालर की पूर्ति विभिन्न देशों में इनकी मांग में कम है। अन्य शब्दों में आधुनिक वर्षों में अमेरिका देश विश्व में जितना क्रय कर रहा है या उसे उधार दे रहा है उससे कहीं अधिक मात्रा में देश विश्व अमेरिका से खरीद रहा है।

डालर संकट के कारण—

डालर के अभाव की समस्या का अध्ययन स्टैलिन्स एरिया की वृद्धिशील में सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व स्टैलिन्स क्षेत्र के देशों की डालर की कोई कमी अनुभव नहीं हुई थी। दुर्भाग्यवश (डालर) में उन्हें जितना भुगतान करना पड़ता था उतना उन्हें उपलब्ध था। चामू याने गे, डालर देशों के साथ स्टैलिन्स देशों को जो घाटा (deficit) या उनकी पूर्ति नहीं खानों से निरर्थक रूप स्वर्ण के निर्यात से हो जाती थी। किन्तु युद्ध के बाद स्थिति विपरीत हो बदल गई। स्टैलिन्स देशों की दुर्लभ करेंसी की प्राप्ति और भुगतानों के मध्य अन्तर रहने लगा, जो १९४७ में ४,१०० मिलियन डॉलर पर था पहुँचा। इस खूनी (gap) के निम्न-लिखित कारण थे —

(१) **प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन**—डालर सकट के लिए दायी सबसे प्रमुख घटक स्टलिङ्ग देशों के व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता थी। डालर क्षेत्र के साथ स्टलिङ्ग देशों का व्यापारिक घाटा सन् १९४७ में २७०० मि० तक पहुँच गया था।

(२) **कीमतों में वृद्धि**—युद्ध काल में कीमतें बहुत बढ़ गई थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें दूनी से भी अधिक हो गई थी। किन्तु अमेरिका से आयातों की कीमतें निर्यात-कीमतों की अपेक्षा अधिक (लगभग १०% अधिक) बढ़ गई।

(३) **पुनर्निर्यात पर ब्रिटेन को आय में कमी**—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ब्रिटेन से अमेरिका को जो वादी जाया करती थी उस पर उसे प्रति वर्ष १०० मि० डालर की आय होती थी। किन्तु सन् १९४७ में यह प्रवाह बहुत ही घट गया। इसी प्रकार, अन्य वस्तुएँ जो कि इंग्लैंड से होकर अमेरिका और कनाडा जाया करती थी अब उनका जाना बन्द हो गया। जबकि पहले ब्रिटेन के निर्यात और पुनर्निर्यात उत्तरी और मध्य अमेरिका में देश के आयातों का लगभग आधा (५०%) भुगतान कर दिया करते थे, १९४७ में वह केवल एक चौथाई (२५%) या इससे भी कम कर सका।

(४) **डालर देशों से आयातों में वृद्धि**—स्टलिङ्ग एरिया के सभी सदस्य (केवल यू० के० के अतिरिक्त) डालर क्षेत्र को युद्ध-पूर्व वर्षों की तुलना में डोड़ा निर्यात कर रहे थे, किन्तु वे आयात भी तीन गुना कर रहे थे। युद्ध-पूर्व अवधि में डालर-आयातों का भुगतान करने के लिये ब्रितानी राशि बाह्यिषे ही उससे निर्यातों का मूल्य १५% अधिक ही बैठता था, किन्तु १९४७ में वह आयातों के मूल्य का केवल आधा ही था। बड़े हुए आयातों के कारण स्पष्ट है—अन्य देशों ने युद्ध काल में अपने प्रयोगत सामान के सम्बन्ध में बहुत हानि उठाई तथा अपन विदेश स्थित विनियोग एवं सम्पत्तियाँ बेचन के लिये भी विपक्ष हो गये। किन्तु दूसरी ओर, अमेरिका ने युद्धकाल में अपनी उत्पादक शक्ति इतनी बढ़ा ली थी कि अब युद्ध समाप्त हुआ तो उसने अपने को गैर विश्व से आगे पाया। अतः वह विश्व को अपने बच की अपेक्षा करी अधिक बचन में समर्थ था।

(५) **स्वर्ण एवं रजत निर्यातों का महत्व कम होना**—स्वर्ण और रजत की कीमतों का स्तर पहले की अपेक्षा नीचा होने से स्टलिङ्ग-डालर-सन्तुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये दो वस्तुएँ सबसे महत्वपूर्ण डालर-निर्यात थीं। यदि इनकी कीमतों की अन्य कीमतों की माति बढ़ जाती, तो उनके निर्यात से स्टलिङ्ग एरिया को ३,१०० मि० डालर की अतिरिक्त आय हो सकती थी।

(६) **अदृश्य मंडों पर घाटा**—डालर सकट को बढ़ाने वाला एक अन्य घटक यह था कि अदृश्य मंडों में शुद्ध आय की अपेक्षा घाटा रहने लगा। इस हेर-फेर के प्रमुख कारण निम्न थे ब्रिटिश आयत कमनियों के मचालन से डालर-खाने अधिक होना और ब्रिटेन को तिथिन में डालर-आय में कमी होना।

उपराक्त समस्त परिस्थितियाँ का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका विश्व में जितना खरीद रहा था उससे अधिक उसे बेच रहा था । चिन्तु यह बेचल अन्त-व्ययि के लिए ही सम्भव था । अतः जैसा ही डालर अभाव अधिक कष्टदायक बना, इसे दूर करने के उपाय निम्न तीन दशाजा में आरम्भ किये गये — (i) अमेरिका में विश्व के अन्य भागों को उदारतापूर्वक ऋण देना आरम्भ किया । इस कदम का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि डालरों की सप्लाई में वृद्धि हुई (मार्शल गहायता एवं पुनर्वास कार्यक्रम इसी श्रेणी में आते हैं), (ii) विश्व के अन्य देशों में अमेरिकी वस्तुओं का आयात में कटौती का आदेश दिया, एवं (iii) नॉन-डालर देशों में अपने डालर-बायियों के भुगतान के लिये अपने अधिकतम डालर और स्वर्ण कोषों में विशाल राशिओं का आहरण किया ।

दुर्भाग्यवश परिस्थिति अधिकधिक बिगड़ती चली गई, क्योंकि अमेरिकन अन्त-व्ययस्था में मंदी ने अपना दुष्प्रभाव उठाना आरम्भ कर दिया था । फलतः वहाँ व्यापारिक दशागें तेजी से बिगड़ने लगीं, औद्योगिक उत्पादन घीसा पड़ गया तथा अन्य देशों की वस्तुओं के लिये अमेरिकी मांग कम हो गई । दूसरी ओर, दोष विश्व में, एहाँ मुद्रा उर्जित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण तेजी में किया जा रहा था, अमेरिकी माल की मांग पूर्ववत् बनी रही । फलतः 'डालर-अभाव' बड़ गया और इसमें डालर और नॉन-डालर देशों के व्यापारिक सम्बन्धों के टूटने तक का अवसर आ गया । कारण, नॉन-डालर देश अमेरिका में वस्तुओं नहीं खरीद पा रहे थे और वे आपस में ही व्यापार करने लगे थे । इस प्रकार, विश्व पृथक् पृथक् व्यापारिक गुटों में तेजी में बंटने लगा जो आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि में अवांछनीय था ।

परिस्थिति के सुधार-हेतु किये गये प्रयत्न—

अतः इजलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन में द्वय विचार विमर्शों के फलस्वरूप अमेरिका यह अनुमति करने लगा कि डालर-सफूट केवल नॉन-डालर देशों के लिये ही नहीं, बरन् डालर देशों के लिये भी सिर-बंद है अतः अमेरिका को इनके निवारण में सक्षम योग देना पारिसे ।

डालरों की पूर्ति बढ़ाने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि अमेरिका अपने आयात प्रयुक्तों में मंदी परहे तथा कस्टम प्रशासन को सुगम बनाकर अधिक विदेशी वस्तुओं खरीदे और विदेशी विनियोजन का एवं स्वाधीन कार्यक्रम बनाये । तब में अमेरिका एक पक्षीय दस्तावेज, उपहारों और सहायता-अनुदानों के द्वारा डालर के अभाव को कम करने के लिए प्रयत्न करता रहता है । चिन्तु याद रह कि बेकारी-अनुदान (doles) स्वभावतः अर्थात्काल लगे हैं । यही नहीं, अन्य अवधियों वाले ऋण भी प्राप्तकता देशों के दीर्घकालीन आर्थिक विकास का स्वार्थ आधार नहीं बन सकते ।

१९४७ के अंत तक अमेरिका ने ८,००० मि० डालर से भी अधिक का ऋण

दिये और ६ ००० मि० डालर से भी अधिक के अनुदान स्वीकार किये। मादाग-सहायता-पार्यक्रम ने यूरोपीय देशों को पुनर्जीवन प्राप्त करने में बड़ी सहायता पहुँचाई। इस पर १९४० और १९५२ के मध्य १७,००० मि० डालर व्यय हुए। इन सब उपायों के फलस्वरूप अब डालर अभाव बहुत सीमा तक मुलभूत गया।

परीक्षा प्रश्न :

- १ 'भुगतान सन्तुलन' वाक्यांश से सम्बन्धित विभिन्न व्याख्याएँ क्या हैं ? इन धारणा के आर्थिक महत्त्व का विवेचन कीजिए।
- २ 'भुगतान सन्तुलन' से आप क्या समझते हैं ? जब यह देश के प्रतिकूल होता है तो इसे सुधारने हेतु जो उपाय प्राप्त अपनाये जाते हैं उनका संक्षिप्त विवेचन करिये। (आगरा एम० कॉम० १९६६)
- ३ अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सन्तुलन में साम्यावस्था बनी रहने के प्रतिष्ठित सिद्धांत का विवेचन कीजिये।

[Discuss the classical theory of mechanism whereby international balances of payments are maintained in or restored to equilibrium]

- ४ किसी देश के आयात एवं निर्यात अतत रवय को सन्तुलित कर लेते हैं।" इस कथन की समीक्षा करिये और यह समझाइय कि क्या इसके कोई अपवाद हैं।
५. भुगतानों के सन्तुलन में डालर-घाटे को पाटने की समस्या आज भी विश्व की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं में से एक है।" समीक्षा कीजिये।
- ६ उन मंडों की जोकि अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के सन्तुलन के क्रेडिट पक्ष में प्रगट की जाती हैं एवं सूची तैयार कीजिये। डेबिट पक्ष की मंडों के निचे भी सूची बनाइये। अनुकूल व्यापार सन्तुलन से क्या आशय है ? बाह्य खाते के सन्तुलन से एवं बुनियादी घाटे से आप क्या समझते हैं ? अहर्दय मंड से क्या आशय है ? अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूँजी आवागमनी में भेद बताइये।
- ७ एक नव ऋणी देश एक परिपक्व ऋणी देश, एक नव ऋण-दाता देश एवं एक परिपक्व ऋणदाता देश के लिए कार्पनिक भुगतान सन्तुलन बनाइय।

[Construct hypothetical balance sheets of a young debtor country, a mature debtor country, a new creditor country and a mature creditor country]

- ८ अनुकूल भुगतान सन्तुलन की प्राप्ति में एक विकासोन्मुख देश को जिन कठिनाइयाँ को मुहत्तना पड़ता है उनका वर्णन कीजिये।

[Describe the difficulties which an economically underdeveloped country experiences in achieving a favourable balance of payments]
(आगरा, एम० ए० १९६६)

‘किसी देश का भुगतान सन्तुलन सदा सन्तुलित रहता है।’ यदि ऐसा है, तो फिर भुगतान सन्तुलन में असाम्यता का क्या अर्थ है ?

[The balance of payment of a country is always in balance ”
What then is the precise meaning of disequilibrium in balance of payments ?]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)

किसी देश के भुगतान सन्तुलन में असाम्यता के क्या कारण हैं ? अर्द्ध-विकसित देशों के विशेष सदर्भ सहित यह बताइय कि ऐसी असाम्यता को कैसे सुधारा जा सकता है ?

[What are the causes of disequilibrium in the balance of payments of a country ? Discuss the correctives of such disequilibrium with special reference to under-developed countries]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

विनिमय दरों का सिद्धान्त

(Theory of Exchange Rates)

परिचय

आन्तरिक व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलताएँ अधिक होने का एक प्रमुख कारण इसमें विदेशी विनिमय की समस्या उपस्थित होना है। एक देश के व्यापारी विदेशियों में अपनी मुद्रा में ही भुगतान लेना चाहते हैं क्योंकि उनके देश में वही विधि प्रायः होती है। इसी के फलस्वरूप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में परिवर्तन कराने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य विदेशी-विनिमय बाजारों द्वारा सम्पन्न होता है, जहाँ की विदेशी मुद्रा के बिल खरीदे और बेचे जाते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि विनिमय दरें, जिन पर एक करेंसी के बदले अन्य करेंसियों का त्रय विनय होता है कैसे निर्धारित होती है तथा समय-समय पर इनमें परिवर्तन क्यों होते रहते हैं। सुगमता की दृष्टि से यह विवेचन स्वतन्त्र विनिमय बाजार के सम्बन्ध में किया गया है। किन्तु वास्तव में आजकल किसी भी देश में विनिमय बाजार स्वतन्त्र नहीं हैं।

‘विदेशी विनिमय’ से आशय

मौलिक विशेषज्ञों ने विदेशी विनिमय वाक्यांश का प्रयोग निम्न अर्थों में किया है — (i) संकुचित अर्थ में कुछ लेखकों व विद्वानों ‘विनिमय’ वाक्यांश का प्रयोग उस दर के लिये किया है जिस पर एक देश की मुद्रा-इकाई दूसरे देश की मुद्रा इकाई में बदल जाती है और, कुछ अन्य लेखकों ने इसका प्रयोग उन सुविधाओं के लिए किया है जो कि विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध में उपलब्ध हो। ऐसे भी लेखक हैं जिन्होंने इसका आशय विदेशी विनिमय दलों से लगाया है। (ii) विस्तृत अर्थ में विदेशी विनिमय वाक्यांश का प्रयोग उस प्रणाली (mechanism) के हेतु किया गया है जिसके अनुसार विदेशी दायित्वों को निपटाया जाता है। डा० टामस के शब्दों में — विदेशी विनिमय अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम उन सिद्धान्तों का, जिनके अनुसार विदेश के विभिन्न देशों में निवास करने वाले लोग एक दूसरे के प्रति

अपने ऋणों को चुकाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं।¹ हाटेंते विदत्त के अनुसार—
“विदेशी विनिमय वह प्रणाली है जिसके द्वारा दो देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का निपटारा किया जाता है।”²

स्पष्टतः, विदेशी विनिमय शब्दों के अर्थ के बारे में लेखकों में बहुत मतभेद है। वास्तव में इसका तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यापार करने वाले राष्ट्र अपने अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान करते हैं। इसमें भुगतान के साधन नियम, नियन्त्रण एवं ऐसे भुगतानों में सहायता देने वाली समस्याएँ भी सम्मिलित होती हैं।

‘विनिमय-दर’ का अर्थ

प्रत्यक्ष दत्त की अपनी विशेष मुद्रा होती है, जो कि उसकी सीमा (frontiers) के अन्दर ही विधि ब्राह्म है। उदाहरणार्थ, भारतीय रुपया किसी विदेशी देश में प्रयोज्य रूप में वस्तुओं नहीं खरीद सकता, वह एक विदेशी मुद्रा के माध्यम से ही ऐसा करता है। इस हेतु एक करंसी को दूसरी करंसी में बदलना आवश्यक है। जिस दर पर एक करंसी दूसरी करंसी या वय करती है उस विनिमय दर कहते हैं। इस प्रकार, किसी करंसी की विनिमय दर केवल इसकी बाह्य कीमत या बाह्य क्रय-शक्ति का सूचक होती है। मान लीजिये कि एक रुपया अंग्रेजी करंसी में १८ पैसे खरीद सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि भारत में एक रुपया जितनी वस्तुओं खरीदता है उतनी वस्तुमें दक्षिण अफ्रीका में १८ पैसे व्यय करके खरीदी जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी साहित्य में विनिमय दर को परिभाषित करने का सर्वाधिक प्रचलित आदर्श ठीक यह है— जिस दर पर करंसियों का एक दूसरे में परिवर्तन होता है उसे ‘विदेशी विनिमय दर’ कहते हैं। यह दर वह कीमत है जो कि विदेशी करंसी की एक इकाई के लिए स्थानीय करंसी में चुकाई जाती है।³

‘प्रत्यक्ष’ एवं ‘अप्रत्यक्ष’ दरें

विनिमय दर किो प्रकार सूचित की जाय यह एक सुविधा का विषय है।

1 “Foreign exchange is that branch of the science of economics in which we seek to determine the principles on which the peoples of the world settle their debts one to the other”

—Thomas.

2 “Foreign exchange are a mechanism by which international indebtedness is settled between one country and another”

—Hartley Withers

3 “The rate at which this exchange (between national and foreign currencies) is performed is called the foreign exchange rate, which may hence be defined as the price that must be paid in local currency for a unit of foreign currency” —Kesari D. Doodha : *Economic Relations in International Trade* p 116

सामान्यतः गणना की सुविधा के लिए राष्ट्रीय करेंसी का मूल्य किसी बहुलपूर्ण (Key) करेंसी की एक इकाई के रूप में प्रगट किया जाता है। उदाहरणार्थ, हम यह कह सकते हैं कि विनिमय दर £ 1 = Rs. 13 33 or \$ 1 = Rs. 4 76 किन्तु, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आन्तरिक करेंसी की इकाई को ही अन्तःराष्ट्रीय-विनिमय-गुणना का आधार बनाया जा सकता है। ऐसी दशा में हम विनिमय दर इस प्रकार बताने हैं—Rs. 1 = 1 sh 6 d जधवा Rs. 1 = U S 21 cents। प्रथम प्रकार में सूचित की गई दरों को 'अप्रत्यक्ष दरें' (Indirect Rates) और द्वितीय प्रकार से सूचित की गई दरों को 'प्रत्यक्ष दरें' (Direct Rates) कहा जाता है। विनिमय दर सूचित करने का कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है क्योंकि दोनों का भाव एक ही है। किन्तु विनिमय दर के अनुबल या प्रतिबल तान का विचार करते समय सावधानी रक्ता आवश्यक होगा।

‘हाजिर दर’, ‘मुद्दी दर’ एवं ‘बागदा दर’

यह सोचना अप्रसूत है कि विदेशी विनिमय बाजार में एक दिए हुए समय-दिष्ट पर कोई एक अन्त्य दर प्रचलित होती है। वास्तव में वहाँ अनेक विनिमय दरे उद्धृत (quote) की जाती हैं, जिनमें से तीन दरें मुख्य हैं—हाजिर दर, मुद्दी दर एवं बागदा-दर।

(१) हाजिर दर (Spot rate)—हाजिर दर वह है जो बाजार में इसी समय उद्धृत (currently quoted) की जा रही है। अन्य शब्दों में, यह दर विदेशी मुद्रा की तत्काल खरीद-बिक्री के लिए है। कंता और बिकता के लिए, यह मानने हुए कि कोपों का स्थानान्तरण नहीं करना है, अलग-अलग विनिमय दरें उद्धृत की जाती हैं। उदाहरणार्थ \$ 2 78 = £ 1 sellers एवं \$ 2 82 = £ 1 buyers, इस दोनों दरों में जो अन्तर विद्यमान है वह स्वर्ण की अमेरिका में इंग्लैण्ड या इङ्ग्लैंड में अमेरिका भेजने के यातायात व्ययों का सूचक है। किन्तु यातायात व्यय ही एक मात्र व्यय नहीं है जो कि कोपों के स्थानान्तरण में होते हैं वरन् अन्य व्यय भी हो सकते हैं। अतः इन्हें भी दर उद्धृत करते समय विचार में लिया जाता है। उदाहरण, मुद्रा-परिवर्तक (money changer) अपना कमीशन लेगा। इसके अतिरिक्त धीमे का व्यय आदि भी है।

कंताओं अथवा बिक्रेताओं के प्रतिनिधि के रूप में धेवन ग्राहकों के निर्देश सम्बन्धित विदेशी केन्द्र में अपने प्रधानों (या प्रतिनिधियों) को केविल द्वारा भेजते हैं। इनके परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय शीघ्र ही कंता से विदेश को अन्तराणित (transfer) हो जाता है। यह बैंक जिस दर पर व्यवहार करता है उसे ‘केबल-दर’ (cable rate) कहते हैं। इसे ‘टेलि. ट्रां. दर’ (T T Rate) भी कह सकते हैं, क्योंकि केविल का टेलीग्राफिक ट्रांसफर प्रेषित किया जाता है।

प्रयानुसार एक टे. ट्रा. व्यवहार तत्त दिन से जिस दिन कि व्यवहार में प्रविष्ट किया गया था, दो या तीन दिन के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिए। इस अवधि

के अन्त में विक्रेता के लिए यह आवश्यक है कि वह क्रेता को विदेशी विनिमय की सुविधा दे दे तथा इसका भुगतान क्रेता के बैंक को करना पड़ता है ।

मुद्रा-पूर्व कुछ अन्य दरें भी प्रचलित थीं, जैसे—'चैक दर' (Cheque rate) वह दर थी जिस पर एक भारतीय बैंक अपने किसी ग्राहक से किसी विदेशी केंद्र में अपने एजेंट पर एक चैक या ड्राफ्ट खरीदेगा (या उसे बेचेगा) । 'मेल-ट्रान्सफर' (Mail Transfer or M T) या 'मेल दर' (Mail Rates or M R) के अधीन विदेशी विनिमय किसी ग्राहक को इस धारणा के साथ देता (या खरीदता) जाता था कि विदेशी बैंक या एजेंट को आवश्यक निर्देश डाक द्वारा भेजे जाएंगे, तार द्वारा नहीं यद्यपि 'डाक-दर' सस्ती होती है । तथापि इसे कम पसन्द किया जाता है, क्योंकि मध्यांतर (interval) में व्याज की हानि होती है तथा सीधा रद्द (cancel) होने का भय भी रहता है ।

(२) मुद्रती दर (Long Rate)—जैसा कि हमने पहले भी बताया था, विदेशी धारित नगदी (cash) में नहीं निपटाये जाते, वरन् आन्तरिक बाजार की भाँति विदेशी विनिमय बाजार में भी प्रायः लेख्य-साक्ष्य (documentary evidences) का ही प्रयोग किया जाता है । सबसे लोकप्रिय लेख्य-साक्ष्य 'सिग्न ऑफ एक्सचेंज' है जो कि आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता पर लिखा गया होता है । ये सिग्न 'सिग्नो' (sigil) हो सकते हैं और मियादी (tenure) भी । मत इनके लिए विनिमय दरें भी इसी प्रकार से पृथक्-पृथक् बताई जा सकती हैं । गया—'दर्शनी विनिमय दर' (sight rate of exchange) वह है, जिस पर बैंक विदेशी करेंसी के दिला को, जो कि प्रस्तुति पर (on presentation) ही देय होते हैं, खरीदता है । 'दर्शनी दर' और 'दी० टी० दर' में बहुत ही मामूली अन्तर होता है ।

'मियादी विनिमय-दर' (usance rate of exchange), जिसे मुद्रती विनिमय दर (long exchange rate) भी कहते हैं, वह दर है जिस पर एक बक एक निश्चित अवधि वाले विदेशी करेंसी के दिला को खरीदता-बेचता है । मियादी दर और दी० टी० दर में व्याज की हानि के बराबर अन्तर रखा जाता है ।^१ जिस अवधि के लिए व्याज की गणना की जाती है वह ३० दिन से १८० दिन (+३ दिन अनुग्रह सम्बन्धी) तक होनी है । यही नहीं कोपो के विनियोजन की अवसर लागत (opportunity cost) और स्टाम्प ड्यूटी भी विचार में ली जाती है । इस प्रकार, जब दिनी की मज्या 'शून्य' (zero) से आगे बढ़ाई जाती है, तो 'दर्शनी-दर' एक 'मुद्रती दर' में परिणत हो जाती है । मुद्रती व्यवहारों की बुनियादी धारणा यह है कि क्रेता एक करेंसी अन्ती, दूसरी करेंसी को एक निश्चित भावी तिथि पर प्राप्त करने के अधिकार के बदले में, चुकाता है ।

१ "The basis of the long rate of exchange is the rate of interest.
—Norman Crump • *The ABC of the Foreign Exchange.*

(३) **बायदा दर (Forward Rate)**—मुदती दरो का प्रयोग समय-मूल्य (Time worth) के माप-हेतु लिया जाता है। इस प्रकार, यह दर एक विनियोजन प्रक्रिया (process of investment) की सूचक है क्योंकि बिल का श्रेता एक दो हुई अवधि के लिये अपने द्रव्य को बटका रहा है। केबिल और मुदती दरो में अन्तर सामान्यतः 'विनियोग की आय' अर्थात् व्याज-दर के बराबर होता है।

यदि बिल न करीयते हुए, कोई व्यक्ति कुछ अवधि बाद के लिये विदेशी करें-सी खरीदे तो उसे उस करें-सी के लिए तब ही भुगतान करना पड़ेगा जबकि वह उसे नियत अवधि के बाद प्राप्त हो जाय। इसे एक 'बायदा विनिमय व्यवहार' (Forward exchange transaction), और जिस दर पर भविष्य में मुपुर्तगी दी जाती है उसे 'बायदा विनिमय दर' (Forward exchange rate) कहते हैं। टट्ट-राय की बातें ठीक-ठीक एक 'बायदा अनुबंध' (futures of forward contract) में सम्मिलित होती हैं। विदेशी विनिमय की भावी मुपुर्तगी के लिये जब अनेक व्यापारी नियमित रूप से अनुबंध करने लगते हैं तो करें-सियों के सम्बंध में एक मण्डित बायदा बाजार विकसित हो जाता है।

जिन विनी विनिमय बाजार स्वतन्त्र थे उन विनी बायदा विनिमय व्यवहार बहुत लोकप्रिय थे। वारण स्वतन्त्र करें-सी प्रणालियों के अधीन, विदेशी अर्थव्यवस्था पत्र-मुद्रा का चलन होने पर विनिमय दरो में विभिन्न देशों की वैकिंग और मुद्रा सम्बन्धी दशाओं के अनुसार बहुत घटा-बढ़ी हो जाया करती थी, जिससे वे बड़ी अनिश्चित रहती थी। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बाधा पड़ने लगी, क्योंकि व्यापारियों के लिये किसी समय विदेश पर यह निर्णय करना कठिन होता था कि एक निश्चित मास में विदेशी करें-सी के लिये कितनी स्वदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी अथवा जो विदेशी मुद्रा उसे प्राप्त होगी वाणी है उसका स्थानीय करें-सी में कितना मूल्य रहे जायेगा। किन्तु यह अनिश्चितता एक उपयुक्त बायदा विनिमय व्यवहार में प्रविष्ट होकर दूर की जा सकती है।

उदाहरणार्थ मान लीजिये कि किसी निर्यातकर्ता को भविष्य में, निर्यात करने गये मास के मूल्य स्वल्प एक निर्धारित राशि मिलने वाली है। उसने अपने मास (या हानि) का अनुमान इस राशि के आधार पर और इस राशि का अनुमान प्रचलित विनिमय दर के आधार पर लगाया है। चूंकि विनिमय दर में कुछ भी और किसी भी समय परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए यह बहना कठिन है कि वास्तव में भुगतान की प्राप्ति के समय विदेशी करें-सी का मूल्य स्वदेशी करें-सी में कितना होगा। अतः यह सम्भव है कि विनिमय दर के परिवर्तन के फलस्वरूप उसका लाभ सम्बन्धी अनुमान बट बड़ जाय। यदि वह विनिमय उधार-बढ़ाव की इस जोखिम को अपने ऊपर न लेना चाहे तो अपनी आशा की गई विदेशी मुद्रा की बमाई (expected foreign earnings) का, पहले से ही ज्ञात नीमत पर, बायदा-विक्रय (forward sale) करके अनिश्चितता को दूर कर सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि 'बायदा दर' सदा 'हाजिर दर' के मूल्य उद्धृत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पहली प्रकार की दरें दूसरी प्रकार की दरों की तुलना में 'प्रध्याजि पर' (at a premium) अथवा 'डिस्काउन्ट पर' (at a discount) हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, मन्दन बाजार में १ माह बाद टावरी के लिये बायदा दर हाजिर से $\frac{1}{2}$ cent नीचे उद्धृत की जाती है। ऐसी दशा में यदि हाजिर दर ४ ८६ डालर है तो एक माह बाद की बायदा दर ४ ८५ $\frac{1}{2}$ डालर प्रति पौंड होगी, और यदि बायदा दर हाजिर से $\frac{1}{2}$ cent ऊँचे पर उद्धृत की जाय, तो बायदा दर ४ ८६ $\frac{1}{2}$ डालर प्रति पौंड होगी। अब तब बायदा दर हाजिर दर में नीचे रहे तब तब यह कहेंगे कि बायदा दर प्रध्याजि पर है। इसका अर्थ हुआ कि बायदा-हाजिर हाजिर डालरों की अपेक्षा महँगे हैं। और जब यह हाजिर दर से ऊपर हो जाय तो कहेंगे कि बायदा दर डिस्काउन्ट पर है। अर्थात् बायदा डालर हाजिर डालरों की अपेक्षा सस्ते हैं।

व्योहारों का रक्षावरण (Dealer's Cover)

प्रायः साधन-सम्पन्न बैंक्स ही बायदा व्यापार करते हैं। एक व्यापारी तो अपनी जातिन को बायदा अनुबन्ध के द्वारा बैंक पर टाव देता है। किन्तु प्रश्न यह है कि बैंक अपनी रक्षा किन प्रकार करेगा? इसका एक सुगम उपाय यह है कि वह अपनी लचील और विनी का सन्तुलन कर ले। किन्तु पूरा पूरा सन्तुलन होता एक दुर्लभ समय की बात है। इसके अतिरिक्त जब व्योहार अल्प राशिओं में होते हैं, तो यह स्पष्टतः मितव्ययितापूर्ण होगा कि कोई कार्यवाही करने से पूर्व 'इन्हे इस्टीमेट' होने दिया जाय। वह इस प्रकार किया जाना है कि व्योहारी (बैंक अपनी 'स्थिति' (position) का दिन भर 'खुला' open) रखता है और फिर उन्हें 'खरा' (square-up) कर लेता है।

मान लीजिये कि एक बैंक ३ माह के बायदा डालर प्रति पौंड ४ ८५ $\frac{1}{2}$ डालर की दर से देवता है और इस दर पर वह एक लाख डालर देने का आश्वासन देता है। अब, यदि बैंक यह निर्णय करे कि उपरोक्त अवधि बीतने पर ही वह हाजिर दर में, जो भी उस समय प्रचलित हो, डालर त्रय करके अपना एक लाख डालर देने का आश्वासन पूरा कर देगा, तो वह अपने को एक जोखिम में डाल रहा है, जिससे उसे हानि सहन करनी पड़ सकती है। कारण, यदि तीन महीने बाद हाजिर-दर प्रति पौंड ४ ८५ डालर हुई, तो उसे एक लाख डालर के त्रय के लिये २०,९१८ पौंड १६ शि० ५ पं० देने पड़ेंगे, जबकि बायदा-विक्रय द्वारा केवल २०,५६७ पौंड ६ शि० ५ पं० मिलेंगे, जिससे उसे २१ पौंड १३ शि० की हानि उठानी पड़ेगी। हाँ, यदि हाजिर दर प्रति पौंड ४ ८६ डालर होगी, तो उसे इतने का ही लाभ हो जाता।

किन्तु बैंक्स सटोरिया के समान जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि वे दूसरों के धन की सुरक्षित रखने के जिम्मेदार होते हैं। अब वे एक अनिश्चित मार्ग नहीं

अपनायेगे, वरन् अपनी रक्षा के लिये उपाय अवश्य करन है। उपाय यह है कि बैंक अपनी 'सिद्धि' को मुरज्त ही 'खर' बना लेता है। यदि एक ओर विनिमय बाजार में कुछ लोग बायदा क्रय के सोदे करते हैं तो दूसरी ओर कुछ लोग बायदा-बिक्री के सोदे करते हैं। अतः, जैसा हो बैंक ने उक्त बायदा-बिक्री का सोदा किया, वह उतनी ही रकम के लिए डालरों के बायदा क्रय का मोदा भी, जो ३ महीने का हो हो, लेता है। इससे उसकी आंखिम समाप्त हो जायगी अर्थात् वह न तो लाभ उठायेगा न हानि किन्तु सामान्य बगीचन जो कि वह खेता और बिकेना दोनों हो चाहते थे चार्ज करता है, अवश्य अजित कर लगर। तीन महीने के बाद वह अपने बायदा क्रय सम्बन्धी सोदे के अन्तर्गत एक लाख डालर प्राप्त करके अपने बायदा क्रय सम्बन्धी सोदे के अन्तर्गत सुपुर्दगी में दे देगा।

किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उपर्युक्त प्रकार के सोद (बायदा बिक्री और बायदा क्रय) परस्पर मिलाप (match) कर हो जायें। उदाहरणार्थ जिस दिन बैंक न ३ माह के एक लाख बायदा-डालर बचे हैं उसी दिन वह ठीक उतनी ही रकम का और ठीक उतनी ही अवधि के बायदा डालर खरीदने में असमर्थ रह सकता है। मान लीजिए कि वह ४-५ दिन के बाद उतनी रकम और उतनी अवधि के बायदा-डालर खरीदने में समर्थ होता है। अतः तब बायदा दर उस दर से कुछ भिन्न हो सकती है जिस पर कि पहला सोदा हुआ था तथा इस भिन्नता के फलस्वरूप बैंक को हानि हो सकती है। इस हानि से बचने के लिए जो तरीका व्यापारी प्रायः अपनाया करते हैं वह इस प्रकार है कि वे उतनी ही रकम का एक हाजिर सोदा खरीदे और फिर हाजिर बिक्री के द्वारा एक बायदा सोदा खरीवें। उदाहरणार्थ यदि बैंक ने ३ माह बाद एक लाख डालर की बायदा-बिक्री की है, तो वह तुरन्त ही प्रचलित स्टॉक-डालर हाजिर-दर पर एक लाख डालर का हाजिर क्रय कर लेता है। तीन महीने के बाद, जब बैंक द्वारा अपने शाहक की एक लाख डालर देने होंगे तब यह राशि उसे हाजिर-सोदे से प्राप्त हो जायेगी।

बायदा-दर को प्रभावित करने वाले घटक

अन्य सभी चीजों की भाँति बायदा-दर (अर्थात् बायदा-विनिमय की कीमत) भी मांग-भूति की सामेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। जब किसी चरम्बी के बायदा विनिमय के लिये मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक हो जाय, तो इसकी कीमत स्थानीय चरम्बी में बढ़ जाती है, अर्थात् बायदा-चरम्बी प्रव्याप्ति पर उपलब्ध होती है। इसके विपरीत, यदि बायदा विनिमय के लिये मांग इसकी पूर्ति से कम है तो उसकी कीमत स्थानीय चरम्बी में घट जायेगी, अर्थात् बायदा-चरम्बी डिस्काउन्ट पर उपलब्ध हो सकेगी। चूँकि बायदा-विनिमय सामान्यन आपानको द्वारा खरीदा और निर्माणों द्वारा बेचा जाता है इसलिए यों भी कह सकते हैं कि जब देश के आपान निजानों की अपेक्षा अधिक होते हैं, तो बायदा विनिमय के लिए मांग इसकी

आपूर्तियों से अधिक होती है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है तथा बायदा विनिमय प्रव्याजि पर उपलब्ध होती है, और, जब निर्यात आयातों की अपेक्षा अधिक होती है, तो वह डिस्काउन्ट पर उपलब्ध होती है।

बायदा-दर और हाजिर-दर में सम्बन्ध—

सामान्यतः, बायदा दर में हाजिर दर में बराबर रहने की प्रवृत्ति होती है। यदि इन दोनों में कोई अन्तर है, तो वह दो मुद्रा बाजारों में प्रचलित व्याज दरों में भिन्नता रहने का परिणाम होता है। अतः बायदा-दर और हाजिर दर में मध्यमितना अन्तर होगा, इसकी गणना प्रचलित व्याज-दरों को विचार में लेकर की जा सकती है।

जब कोई बैंक लन्दन में एक बायदा विनियम के लिए रक्षावरण (cover) के रूप में फ्रांसिसी फ्रैंक्स (F Francs) का, हाजिर क्य करता है, तो उसके कोष लंदन में घट जाते हैं किन्तु पेरिस में बढ़ जाते हैं। अब, यदि पेरिस में अल्पकालीन विनियोग पर व्याज दर लंदन की अपेक्षा ऊँची है, तो हाजिर फ्रैंक्स के जय द्वारा उसे लाभ होता है। अतः वह बायदा फ्रैंक्स डिस्काउन्ट पर भी बेच सकता है, किन्तु यह डिस्काउन्ट (हानि) उसके व्याज सम्बन्धी लाभ से अधिक नहीं होना चाहिए। मन्त्र तो यह कि प्रतिभोगिता बैंक को अपने व्याज सम्बन्धी लाभ की सम्पूर्ण सीमा तक डिस्काउन्ट देने के लिए विवश कर देती है। किन्तु जब अधिक डिस्काउन्ट माँगा जाय, तो बैंक बायदा विक्री करना बंद करके बायदा खरीद करना पसंद करेगा।

यदि पेरिस में अल्पकालीन विनियोग पर व्याज दर लंदन की अपेक्षा कम हो, तो उक्त तर्कों की विपरीत रूप में लागू करते हुए यह दिखाया जा सकता है कि बैंक अपने बायदा फ्रैंक्स प्रव्याजि पर बेचेगा और यह प्रव्याजि उसकी व्याज सम्बन्धी हानि में अधिक नहीं हो सकती है। यदि सर्वाधिक मुद्रा बाजारों में प्रचलित व्याज-दरों में अन्तर बढ जाय तो हाजिर और बायदा-दरों के मध्य अन्तर में भी वृद्धि हो जायगी।

बायदा दरों को प्रभावित करने वाली व्याज-दरों के अतिरिक्त अन्य दशाये निम्नलिखित हैं —(i) प्रचलित राजनैतिक दशायें, (ii) मोद्रिक मान का स्थानित्व, एवं (iii) बाजार मगटन एवं प्रतिभोगिता सम्बन्धी दशायें।

विनिमय दरों का महत्त्व

अन्तराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दरें कई प्रकार से महत्त्वपूर्ण हैं —(i) वे स्वदेशी और विदेशी बाजारों में वस्तुओं और उत्पात-साधनों की प्रचलित कीमतों के मध्य प्रत्यक्ष सम्बन्ध (direct link) स्थापित करती हैं, (ii) इनके उतार-चढ़ाव द्वारा भुगतान सन्तुलन में असाम्यतायें उत्पन्न हो जाती हैं। नीची विनिमय दर (देशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा का नीचा मूल्य) आयातों को प्रोत्साहित और निर्यातों को अ-प्रोत्साहित करके भुगतान सन्तुलन में घाटा (deficit) उत्पन्न कर देती है, जबकि ऊँची विनिमय दर (वर्षान् स्वदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा का ऊँचा मूल्य)

आयातों को उत्तेजित और निर्यातों को प्रोत्साहित करके भुगतान संतुलन में 'आधिन्य' (surplus) उत्पन्न करती है, (iii) विनिमय दरें ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सम्बन्धी व्यवहारों को सहज या कठिन बनाती हैं। संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक सम्बन्ध विनिमय दरों से बहुत प्रभावित होते हैं।¹

विनिमय दर का निर्धारण

'स्वाभाविक' एवं 'वास्तविक' विनिमय दरें—

सिद्ध प्रकार से एक वस्तु की दशा में हम 'सामान्य मूल्य' (Normal price) और 'बाजार-मूल्य' की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बाजार-मूल्य सामान्य-मूल्य के दुर्ब-निर्ब मंडराता है, उन्ही प्रकार विदेशी विनिमय बाजार में भी 'सामान्य', 'स्वाभाविक' या 'साम्य' विनिमय दर और 'बाजार' या 'वास्तविक' विनिमय दर होती है तथा 'बाजार' या 'वास्तविक' विनिमय दर 'सामान्य' विनिमय दर के दुर्ब-निर्ब मंडराती रहती है।

स्वाभाविक विनिमय दर का निर्धारण—

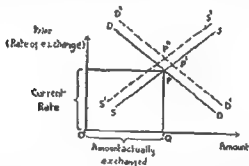
एक साधारण वस्तु की भाँति विदेशी-विनिमय-दर भी माँग एवं पूर्ति की शक्तियों के संतुलन द्वारा निर्दिष्ट होती है।² विदेशी विनिमय की माँग उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशी से प्राप्त वस्तुओं में सेवाओं का भुगतान करना चाहते हैं जबकि हमकी पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जिन्होंने वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात द्वारा अथवा विदेशी पूँजी के आयात द्वारा विदेशी मुद्रा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। जब विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा की माँग इसकी पूर्ति के बराबर हो जाय, तो विनिमय-दर में समता होती है। इस दर को ही विनिमय समता (Parity of Exchange) कहा जाता है। यदि विदेशी मुद्रा (या इसके बिलों) की माँग इसकी पूर्ति से अधिक हो जाय (अथवा देशी मुद्रा या इसके बिलों की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जाय), तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से ऊँचा हो जायगा; अतः विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए हम पहले से अधिक देशी मुद्रा देनी पड़ेगी। यदि विदेशी मुद्रा (या इसके बिलों) की माँग इसकी पूर्ति से कम हो जाय, तो विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से कम हो जायेगा। अतएव, जब विदेशी मुद्रा या इसके बिलों की खरीदने के लिए हम पहले की अपेक्षा कम देशी मुद्रा देनी पड़ेंगे।

चूँकि एक कर-सी की पूर्ति दूसरी कर-सी के लिए माँग होती है, इसलिए हम इनमें से किसी एक को भी 'वस्तु' और दूसरी को 'मुद्रा' मान सकते हैं। उदा-

¹ P. T. Ellsworth : *The International Economy*, pp. 262-263

² 'The exchange rate between the means of payment of two countries is determined, like all other prices, by supply and demand'—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 19.
अ. व्या, १९

हरणार्थ, यदि विदेशी करेंसी को एक वस्तु मानें, जिसके लिए मौद्रिक माँग है, तो इसकी कीमत स्वदेश करेंसी में प्रगट की जा सकती है। नीचे के चित्र में कीमते (अर्थात्, विनिमय-दरों जो कि स्वदेशी करेंसी को इकाइया की मर्यादा में विदेशी करेंसी की एक इकाई की कीमतें हैं) Y-axis पर, एवं विदेशी मुद्रा की खरीदी और बेची हुई मात्राएँ X-axis पर दिखाई गई हैं। माँग वक्र DD बाई से बाई और



चित्र—विनिमय दरों के निर्धारण का माँग-पूरत सिद्धान्त

अधोमुखी (downwards) ढालू है। इससे यह सूचित होता है कि लोग कम कीमतों पर अधिक मात्राओं में विदेशी करेंसी खरीदने के लिए तैयार हैं। इसी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि विदेशी करेंसी सस्ती होने के परिणामस्वरूप विदेशी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं तथा अधिक मात्राओं में आयात की जाने लगती हैं।

पूरत वक्र (SS) बाई में दायी ओर उर्ध्वमुखी (upwards) ढालू है, जो इस तथ्य का सूचक है कि लोग उच्च कीमत पर अधिक मात्राएँ बेचने को तैयार हैं। कारण विदेशी करेंसी में स्वदेश वस्तुओं की कीमतें मारने के कारण निर्यात प्रोत्साहित होते हैं।

दोनों वक्र एक-दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। इसका अर्थ यह है कि सम्बन्धित विनिमय दर ऐसी है, जिस पर विदेशी करेंसी के लिए माँग इसकी पूरत के बराबर है। यदि यही कीमत प्रचलित हो जाय, तो बाजार में साम्यावस्था होती है।

अब मान लीजिए कि भुगतान-सन्तुलन (सम्पत्ति-सामित्व के अर्थ में) के प्रति-कूल परिवर्तन के कारण माँग बढ़ जाती है। अर्थात्, विद्यमान माँग में उन लोगों की माँग भी जुड़ जाती है, जो कि विदेशियों को अतिरिक्त ऋण चुकाना चाहते हैं। इसे माँग वक्र के DD से D'D' की स्थिति में 'शिफ्ट' (Shift) द्वारा दर्शाया गया है। नया माँग वक्र पूरत वक्र को P' पर काटता है। इससे प्रकट होता है कि अब विनिमय दर बढ़ गई है और बेची गई विदेशी मुद्रा मात्रा से भी वृद्धि हो गई है। स्मरण रहे कि विनिमय दर में वृद्धि पूरत में कमी आने के कारण (उदाहरणार्थ निर्यातों में निरावट के कारण) भी हो सकती है। यदि पूरत वक्र SS से S'S' तक खिसक जाय,

तो कीमत P से बढ़ कर P' हो जायेगी तथा वही गई विदेशी मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जायेगी।

यहाँ भुगतान सन्तुलन के अन्वय १७ न दिखे गये अर्थ १ और ५ में भेद को स्मरण कीजिए। अर्थ १ का आशय OQ (वास्तव में खरीदी और वही गई विदेशी मुद्रा की मात्रा) से है किन्तु अर्थ ५ का आशय इन दोनों द्वारा प्रदर्शित सम्पूर्ण मांग पूर्ति सम्बन्धी परिस्थिति से है। प्रथम अर्थ में भुगतान सन्तुलन के दोनों पक्ष, परिभाषा-अनुसार ही, बराबर होते हैं और यह कथन कि 'दे बराबर है' शब्दों का प्रयोग करना अनावश्यक है, यदि ऐसा न कर, तो कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। किन्तु, जब हम यह कह सकते हैं एक दिए हुए समय पर भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल है, तो हमारा आशय यह है कि तत्कालीन प्रचलित-दर पर (अथवा उस दर पर जो नि सामान्य (normal) समझी जाती है) पूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक है, क्योंकि मांग अथवा पूर्ति वह अथवा दोनों ही 'क्षिप्त' हो गये हैं। किन्तु विनिमय-दर में परिवर्तन करके साम्य की स्थापना की जाती है।

इस तथ्य के सन्दर्भ में, कि भुगतान सन्तुलन की अनिश्चितता गंदों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, यह कल्पना की जा सकती है कि विनिमय-दर, वस्तुओं की (जिनके मांग व पूर्ति दोनों में क्षिप्त हो सकता है) कीमतों की मांग, क्षिप्त होती रहती है। किन्तु अनुभव से पता चला है कि सामान्य दशाओं (normal conditions) में अन्तर्गत विनिमय दर लगभग स्थायी रहती है। अतः कोई ऐसा मिकेनिज्म होना चाहिए जो कि मांग-पूर्ति का नियमन करता है। मांग और पूर्ति सम्बन्धी उक्त दोनों के सन्दर्भ में मिकेनिज्म की त्रियाशीलता इस तरह समझी जानी चाहिए—पूर्ति की समान करने वाला (equalising) स्रोत केन्द्रीय बैंक का स्वर्ण कोष या विनिमय गमानीकरण कोष है। अतः कुछ सीमा तक कुल पूर्ति का वक्र समतल होता है। स्वर्ण कोष की समाप्त होने से बचाने के लिए, ऐसी प्रवृत्तियाँ सन्तुल्य हो जाती हैं, जो मांग और पूर्ति दोनों को एक उचित तरीके से 'क्षिप्त' करने का यत्न करती हैं, कीमतें परिवर्तित हो जाती हैं और पूर्ण की वृद्धि भी व्यापार-दर के परिवर्तनों द्वारा प्रभावित होता है। इस मिकेनिज्म की वर्षा अगले अध्यायों में की गई है। अध्याय १६ में स्वर्णमान के अधीन और अध्याय २० में अपरिवर्तनशील चलन के अधीन त्रियाशील होने वाले मिकेनिज्म पर प्रकाश डाला गया है।

दो से अधिक देशों के सम्बन्ध में विचार—

अभी तक हमने यह कल्पना की थी कि विनिमय केवल दो ही देशों के मध्य की समस्या है। किन्तु एक आधुनिक देश का सम्बन्ध उनके विभिन्न देशों से होता है। प्रत्येक देश अन्य अनेक देशों से व्यापार करता है। अतः यह आशा नहीं करनी चाहिये कि देश का भुगतान सन्तुलन अलग-अलग प्रत्येक देश के साथ साम्यावस्था में होगा। वास्तव में उपरोक्त विस्मरण अन्य सब देशों को मिलाकर इसके (समूह के) साथ देश के भुगतान सन्तुलन पर लागू होना है। किन्तु सामाजिक-मन्य निरन्तरीय

व्यापार (triangular trade) के द्वारा क्रियाशील होता है। साम्यावस्था में स्थिति कुछ इस तरह से होती है—उदाहरणार्थ, जर्मनी अमेरिका से किये गये आयात का मूल्य अक्षत दक्षिणी अमेरिका को मन्त्र वेन कर भुकाता है जबकि दक्षिणी अमेरिका देश अमेरिका को कच्चा मान निर्यात करते हैं। मौद्रिक पक्ष पर, हम यह कल्पना कर सकते हैं कि अमेरिकन निर्यातकर्ता को इसके जर्मन ग्राहक से एक दिन राजित पर प्राप्त होता है जिसे वह ब्राजील में बहवा भेजाने वाले व्यापारकर्ता को बेच देता है। वास्तव में ये सभी व्यवहार-शृङ्खलाएँ बँकों द्वारा लन्दन बाजार के माध्यम से फाइनेन्स की जाती हैं। किन्तु इससे कोई विरोध अन्तर नहीं पड़ता है। कारण, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अक्षत एक विकेन्द्रित निकासी गृह का कार्य करती है।

जब दो से अधिक देश हैं, तो इनके मध्य एक से अधिक विनिमय-दरें प्रचलित होती। उदाहरणार्थ, तीन देशों के मध्य तीन अनुपात (जैसे १ : २, १ : ३ और २ : ३) होने, चार देशों के मध्य ६ अनुपात (जैसे १ : २; १ : ३, १ : ४, २ : ३; २ : ४; ३ : ४) और n देशों के मध्य $\frac{n(n-1)}{2}$ अनुपात होंगे। चूँकि तार और टेली-

फोन द्वारा विभिन्न विदेशी बाजार मापस में सम्बन्धित होने हैं, इसलिये विभिन्न अनुपातों का आपस में एक न एक निर्धारण योग्य सम्बन्ध होना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि मापस के लिये डालर दर में स्थिति होती है, जबकि पौण्ड के लिये डालर दर और मार्क के लिये स्टलिंग-दर-स्थायी (stable) बनी रहे, तो मार्क को डालरों में, डालरों को पौण्ड में और पौण्ड को मार्क में परिणित करना तब तक लाभदायक रहेगा जब तक—यह मानने हुए कि डालर-पौण्ड दर साम्यावस्था में है—मार्क के लिये स्टलिंग-दर अनुपाततः न बढ़ जाय। निस्सन्देह यदि सम्पर्क साधन नष्ट करके (जैसे कि युद्धकाल में होता है) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार को टुकड़ों में बाँट दिया जाय, तो उगमे भिन्नताये अस्थायी रूप से उदय हो सकती हैं [यही बात एक विनिमय अनुपात के बारे में, जबकि दो देश प्रत्यक्ष सम्पर्क में होते हैं, लागू होती है] किन्तु अनुभव में यह पता चलता है कि अत्यधिक उत्तार-चढ़ाव होते हुये भी ये भिन्नताये (discrepancies) शीघ्र ही समाप्त हो जाया करती हैं। हाँ, विभिन्न भूगतान मापनों के लिये एक ही करंसी में विभिन्न दरें विद्यमान हो सकती हैं।

उपसंहार—

विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों में विनिमय-समता विभिन्न प्रकार से लागू होती है। जब दो देश घातुमान पर नहीं हैं तथा वहाँ की सरकारें विनिमय दर का नियमन भी नहीं करती हैं, तब बाजार-दर का निर्धारण 'भुगतान-मनुचल सिद्धान्त' द्वारा और समता-दर (अथवा स्वाभाविक विनिमय दर) का निर्धारण 'क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त' द्वारा होता है। लेकिन जब दो देश घातुमान पर हों, तो स्वाभाविक विनिमय दर का निर्धारण 'टंकाली समता सिद्धान्त' द्वारा होता है। इन विभिन्न सिद्धान्तों पर अगले अध्यायों में प्रकाश डाला गया है।

परीक्षा प्रश्न

- १ विनिमय दर क्या है ? यह किसी विनिमय बाजार में किस प्रकार उद्धृत (quote) की जाती है ?

[What is Rate of Exchange ? How is it quoted in an exchange market ?]

- २ हाजिर मुदती एवं वायदा विनिमय दरों में भेद कीजिये और प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये ।

[Distinguish between spot, long and forward rates of exchange giving examples of each ?]

- ३ वायदा विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है ? इसका हाजिर दर से क्या सम्बन्ध है ।

[How is the forward rate of exchange determined ? What relation does it bear to spot rate ?]

- ४ साम्य विनिमय दर कैसे निर्धारित की जाती है ।

[How is the equilibrium rate of exchange determined ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

स्वर्णमान एवं सुधार प्रक्रिया

(टकसाली समता सिद्धान्त)

(The Gold Standard and Process of Adjustment)

परिचय—

एक पिछले अध्याय में हमने यह देखा था कि देश के भुगतान सन्तुलन में असाम्यता, विशेषतः जबकि वह दीर्घकालिक हो, अच्छी नहीं होती है। इसका उपचार विनिमय-दर के परिवर्तन द्वारा सम्भव है। विनिमय-दरों में परिवर्तन विभिन्न मौद्रिक मानों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार से और विभिन्न सीमाओं तक होते हैं। कुछ समय पूर्व तक स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में बहुत प्रचलित रहा और आज भी कुछ (जैसे फ्रांस) इसकी पुनः स्थापना के इच्छुक हैं। अतः प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि स्वर्णमान की क्या विशेषताएँ हैं, इसके अन्तर्गत विनिमय-दरों का क्या आचरण रहता है तथा भुगतान-सन्तुलन में समायोजन किस प्रकार सम्भव होते हैं।

स्वर्णमान का अर्थ

स्वर्णमान कोई जानबूझकर बनाई गई व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन विकास का फल है। इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सन्दर्भ में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वर्णमान की विभिन्न परिभाषायें दी गई हैं। प्रमुख परिभाषायें निम्नांकित हैं —

- (१) राबर्टसन (Robertson)—“स्वर्णमान वह मौद्रिक परिस्थिति है जिसमें एक देश अपनी मुद्रा-इकाई का मूल्य और एक निश्चित तौल वाले स्वर्ण का मूल्य समान-स्तर पर रखता है।”¹
- (२) कैमरर (Kemmerer)—“स्वर्णमान वह मुद्रा प्रणाली है, जिसके अन्तर्गत कीमतें और मजदूरियाँ और ऋण उस मुद्रा में व्यक्त किये

1 “Gold standard is a state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a defined weight of gold at an equality with one another”—Robertson : *Money*, p 7

जाते हैं जिसका मूल्य स्वर्ण की एक नियत मात्रा के बराबर रखा जाता है।¹

(३) क्रॉउथर (Crowther)—“स्वर्णमान विनिमय दरों के स्थायित्व को बनाये रखने की युक्ति है।”²

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण मूल्य मान (standard of value) का काम करता है। वरन्हीं की इकाई या तो स्वर्ण की होती है अथवा उसका सूत्र एक विशेष सोल और शुद्धता वाले स्वर्ण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष (किन्तु स्पष्ट) रूप में परिभाषित होती है। इसके अतिरिक्त स्वर्ण का आदान निर्यात स्वतन्त्रतापूर्वक रिया जाता है और स्वर्ण मान देन में मुद्रा अधिकारी नियम कीमतों पर किसी भी सोमा तक स्वर्ण का नया या निरम करने के लिये बाधों हान हैं। हैबलर के शब्दों में— स्वर्णमान शब्द का प्रयोग एक संकुचित अर्थ में किया जा सकता है या व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में इसका आशय उस मौद्रिक प्रणाली से है जिसमें एक आदेश विवरण के स्वर्ण सिक्के या स्वर्ण सर्टिफिकेट्स (१००% धातु धनिष्ठ) चलन माध्यम होते हैं। व्यापक अर्थ में, इसके अन्तर्गत एक ऐसी दशा भी सम्मिलित है जिसमें नोट अथवा बाँदों के सिक्के भी विधि बाह्य होते हैं किन्तु ये स्वर्ण में एक निश्चित दर में परिवर्तित कराय जा सकते हैं। निःसन्देह यह भी आवश्यक है कि स्वर्ण के सिक्कों के गनाने पर क. प्रतिबन्ध न हो।³

स्वर्णमान के विभिन्न रूप

विभिन्न समयों पर विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार स्वर्णमान के विभिन्न रूपान्तर आनाये गये हैं —

¹ A gold standard is a monetary system where the unit of value in which prices and wages are customarily expressed and in which the debts are usually contracted, consists of the value of a fixed quantity of gold in essentially free gold market.”

— Kemmerer *The Gold Standard—Its Nature and Future*, p. 5

² The gold standard is “a device for maintaining the stability of exchange rates”—Crowther *An Outline of Money*, p. 277

³ “The term ‘gold standard’ may be used in a narrower or in a wider sense. In the narrower sense, it signifies a monetary system under which gold coins of standard specification, or gold certificates with 100% gold backing form the circulating medium. In the wider sense, it covers also the case where notes or silver coins are legal tender, provided they are convertible into gold at a fixed rate. There must, of course, be no prohibition of the melting down of gold coins.”—Haberer *The Theory of International Trade*, p. 23

(१) स्वर्णचलन मान (Gold Currency Standard)—यह प्रथम महा-युद्ध के पहले अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया था । इस मान में स्वर्ण-सिक्के चलन का प्रमुख रूप होते हैं, पूर्ण-काय (full bodied) होते हैं तथा जबकी टलाई स्वतन्त्र होती है, अन्य प्रकार की करेंसी स्वर्ण-मुद्रा में परिवर्तनीय होती है, स्वर्ण के आयात-निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होते एवं देश में चलन की मात्रा स्वर्ण कोष पर आधारित होती है ।

(२) स्वर्ण धातु मान (Gold Bullion Standard)—इसे प्रथम महा-युद्ध के पश्चात् अमेरिका को छोड़कर अन्य सब स्वर्णमान देशों ने अपनाया था, क्योंकि उनके पास समस्त चलन को १००% आठ देने के हेतु पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं था । इस मान में सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं होता, किन्तु स्वर्ण मूल्यमान का कार्य करता है, सांकेतिक मुद्राओं की कीमत स्वर्ण में मूचित की जाती है, कागजी नोटों के पीछे ३५-४०% स्वर्ण की आठ होती है । किन्तु ये एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं, सरकार द्वारा नियत दरो पर असोमित माना में स्वर्ण के क्रय-विक्रय की व्यवस्था होती है, विदेशी भुगतानों के हेतु स्वर्ण देने के लिए सरकार पर्याप्त स्वर्ण कोष रखती है और स्वर्ण की टलाई स्वतन्त्र नहीं होती ।

(३) स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange Standard)—इसका प्रचलन भी प्रथम महायुद्ध के बाद ही अधिक रहा । यह स्वर्ण धातुमान की तुलना में अधिक मितव्ययी होता है । इस मान की विशेषतायें निम्नलिखित हैं—इसमें स्वर्ण सिक्के या परिवर्तनशील कागजी द्रव्य का चलन नहीं होता, केवल सांकेतिक सिक्के एवं अपरिवर्तनशील कागजी द्रव्य ही चलन में होता है, देश की प्रामाणिक मुद्रा का सम्बन्ध सोने से अप्रत्यक्ष (किसी स्वर्ण चलन मान या स्वर्ण पाटमान वाले देश की करेंसी के द्वारा) होता है । संज्ञातिव दृष्टि से मुद्रा अधिकारी देश की मुद्रा के बदले में स्वर्ण या विदेशी मुद्रा देने के लिए बांधी होता है किन्तु व्यवहार में यह सुविधा केवल विदेशी भुगतानों के लिये ही दी जाती है । विदेशी भुगतान स्वर्ण से या स्वीकृत विदेशी मुद्रा में लिए जाते हैं । स्वर्ण प्रत्यक्ष रूप से न ही मूल्यमान का कार्य करता है, न विनिमय-माध्यम का, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से सभी कीमतें स्वर्ण कीमतों द्वारा ही निश्चित होती हैं । देशी मुद्रा के पीछे सबसे बड़ी आठ विदेशी मुद्रा की होती है । विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय के द्वारा करेंसी की मात्रा का प्रसार और संकुचन होता रहता है ।

स्वर्णमान के आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहलू

स्वर्णमान का कोई भी रूप अपनाया जाय वह दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने में अवश्य ही समर्थ होना चाहिये । प्रथमतः वह देश में करेंसी के परिमाण का नियन्त्रण (regulation of the volume of currency) करे, और दूसरे, विनिमय दरो में स्थायित्व (exchange stability) बनाये रखे । जबकि गहला कर्तव्य स्वर्णमान देश में करेंसी के आन्तरिक मूल्य को स्थायी रखने से सम्बन्धित

है, दूसरा कर्त्तव्य करेंसी के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने से सम्बन्ध रखता है। पहले कर्त्तव्य को हम 'स्वर्णमान का आन्तरिक पहलू' (Domestic Aspect of the Gold Standard) और दूसरे को 'स्वर्णमान का अन्तर्राष्ट्रीय पहलू' (International Aspect of the Gold Standard) कहते हैं। स्वर्णमान के इन दोनों पहलुओं में भेद बतलाने हुए काउथर ने लिखा है कि "आन्तरिक स्वर्णमान में मुख्य तत्त्व स्पष्ट यह है कि स्वर्ण कोष और चलन के मध्य कानून द्वारा मात्रा-अनुपात (proportion of volume) कायम रखा जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की मुख्य बात यह है कि स्वर्ण में करेंसी की परिवर्तनशीलता कायम रखी जाती है, अर्थात्, एक स्वर्ण इकाई और चलन इकाई के मध्य मूल्य-अनुपात (proportion of value) को बनाम रखा जाता है।"¹

सामान्यतः ये दोनों पहलू स्वर्णमान के प्रत्येक रूप में सह रूप से विद्यमान रहते हैं किन्तु असाधारण परिस्थितियों में स्वर्णमान में केवल एक ही पहलू ही प्रभावी है। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ में इङ्ग्लैंड स्वर्णमान से हट गया और बैंक ऑफ इङ्ग्लैंड ने सरकारी नियत दर पर करेंसी को स्वर्ण में बदलना या स्वर्ण का विक्रय करना बन्द कर दिया। किन्तु वह करेंसी की मात्रा (Volume) का स्वर्ण कोष के आधार पर नियमन करता रहा। इसका अर्थ यह है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान को तो छोड़ दिया किन्तु आन्तरिक स्वर्णमान को बनाये रखा।

आन्तरिक स्वर्णमान के गुण-घोष—

गुण—आन्तरिक स्वर्णमान के कई गुण हैं—

(१) चूँकि करेंसी की मात्रा का नियमन स्वर्ण कोष के आधार पर किया जाता है, इसलिए करेंसी के अत्यधिक निर्यसन का भय नहीं है।

(२) जनता को भी इसमें अधिक विश्वास होता है क्योंकि करेंसी का स्वर्ण से, जोकि विश्व मान्य है, प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

(३) इसका सञ्चालन सरकार के न्यूनतम हस्तक्षेप द्वारा ही, स्वचालित रूप से, होता है। स्वर्ण का आवागमन करेंसी की मात्रा में वृद्धि और सन्तुलन उत्पन्न करके स्वर्ण के मूल्य और करेंसी की मात्रा में एक पूर्ण निश्चित अनुपात को बनाये रखता है।

(४) स्वर्णमान में मूल्य स्तर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर रहता है। कारण, करेंसी का आधार स्वर्ण है, जिसका अधिक उत्पादन विद्यमान मॉडिक स्वर्ण के कुल

¹ "The cardinal point in the Domestic Gold Standard is clearly the proportion of volume enforced by the law between the gold reserve and the currency. The essence of the International Gold Standard is the convertibility of the currency into gold, i.e., the fixed proportion of value between a unit of gold and a unit of currency"—Crowther *An Outline of Money* p. 284,

स्टॉक का एक बहुत ही अल्प भाग होता है। जत स्वर्ण-मात्रा में और, इसलिये चलन की मात्रा में, अस्थिरता का अभाव होता है। चूंकि, मूल्य प्रणाली अपेक्षित एक स्थायी स्वर्ण-वृत्तियाद (gold base) पर टिकी होती है, इसलिये वह स्वयं भी किसी अन्य मान की अपेक्षा अपेक्षित स्थायी रहती है।

दोष—जहां आन्तरिक स्वर्णमान में उतार साध है वहां इसके कुछ दोष भी हैं, जिन्हें निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है —

(१) आन्तरिक स्वर्णमान के अन्तर्गत चलन व्यवस्था लोच रहित हो जाती है। राष्ट्रीय सङ्घट (जैसे कि युट अथवा आर्थिक सङ्घट) के समय में अथवा नियोजित आर्थिक विकास में अपाध में सरकार स्वर्ण कोषों में वृद्धि रुक बिना, चलन में वृद्धि नहीं कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विपन्नता में बाधा पड़ने लगती है। भारत में आन्तरिक स्वर्णमान तो सामान्य समय में ही साथ देता है और असाधारण समय में जबकि उसके महत्वाग की गिनत आवश्यकता पड़ती है वह साथ छोड़ देता है। इसी कारण हम एक अच्छे मौसम का मान (a fair weather standard) कहा गया है।

(२) आन्तरिक स्वर्णमान कीमत स्थायित्व की कठिन समस्या उत्पन्न करता है। देश की करैसी इकाई के मूल्य की स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा सम्बन्धित करके इसने कीमत स्तर की स्वर्ण मात्रा में नई खानों का पता लगाने, पुरानी खानों के खत्म होना, स्वयं खनन की टेक्नीक सुधरने, विभिन्न देशों में विश्व के स्वर्ण-स्टॉक का वितरण बदलना आदि के फलस्वरूप भी उतार-चढ़ाव होने रहते हैं उन पर नियंत्रण या परिवर्तनीय बना दिया है। यह सच है कि विश्व का मौद्रिक स्वर्ण सम्बन्धी स्टॉक अपेक्षा स्थायी है, क्योंकि स्वर्ण का वार्षिक उत्पादन विद्यमान स्टॉक का एक बहुत ही अल्प भाग है किन्तु इसका भाव यह तो नहीं है कि व्यक्तिगत देशों के मौद्रिक स्वर्ण सम्बन्धी स्टॉक सदा स्थिर ही बने रहेंगे। यदि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक स्वर्ण की कुल मात्रा के वितरण में कुलमापोजन (maladjustment) उत्पन्न हो जाय, तो उन देशों में कीमतें बहुत घट-बढ़ सकती हैं। विश्व का मौद्रिक इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि आन्तरिक स्वर्णमान करैसी की मात्रा और कीमत स्तर को स्थायी नहीं बनाता बल्कि निरन्तर परिवर्तित होत रहने के लिये विवश कर देता है। वास्तव में वह करैसी की मात्रा और स्वर्ण की मात्रा के पारस्परिक सम्बन्ध को ही स्थायी करता है।¹

(३) यदि आन्तरिक स्वर्णमान का स्थायित्व आवश्यक है, सम्भव भी हो, तो वह देश की वार्षिक समृद्धि के लिए खतरा है। कारण, इसके अन्तर्गत, स्वर्ण कोष की

1 The domestic gold standard does not stabilise the volume of currency, but forces it to fluctuate. It merely stabilises the volume of gold and the volume of currency.

मात्रा में घटा-बढ़ी होने पर बरैमी की मात्रा में घट वृद्ध हो जाती है चाहे देश को बरैसी की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की आवश्यकता हो या नहीं। फलतः अर्थ-व्यवस्था में जन-तन्त्र मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन की हतचलें उत्पन्न होकर नुकसान पहुँचानी रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण-दोष—

‘अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान’ में आशय ऐसी मौद्रिक व्यवस्था का है जिसमें विश्व के अनेक देश अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में धोषित कर देने हैं, वहाँ स्थानीय बरैसी का स्वर्ण में और स्वर्ण को स्थानीय बरैसी में परिणित कराया जा सकता है। तथा उनमें परस्पर स्वर्ण का आवागमन निर्बाध रूप में होता है।¹

गुण—जब स्वर्णमान एक ही माप अनेक देशों द्वारा अपनाया जाता है, तो हमने निम्न लाभ होने हैं —

(१) यह स्वर्णमान देशों को एक अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम और मूल्य प्रमाण उपलब्ध करता है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों में द्रुत सुविधा हो जाती है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की कार्यशीलता के अन्तर्गत विनिमय-देशों में स्थायित्व रहता है। कारण, विभिन्न देशों की मौद्रिक इच्छाया वांछित स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है एवं सरकारें एक पूर्व निश्चित दर पर स्वर्ण के अमीमित मात्राओं में नय-विक्रय का आन्वागमन देती हैं। इन परिस्थितियों में विभिन्न स्वर्णमान देशों की बरैमियों की इकाइयों के मध्य स्थायी सम्बन्ध चित्रित हो जाते हैं। विनिमय-स्थायित्व के कारण ही विभिन्न देशों के लोग अन्तर्राष्ट्रीय लूण लेने-देने में कोई मकोब का भय नहीं करते।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के अन्तर्गत विभिन्न देशों की कीमतें परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हो जाती हैं। यदि किसी समय पर कीमतें एक देश में तीव्री और अन्य देशों में ऊँची हों तो यह भिन्नता स्वर्ण-आवागमन के निकटिन्म द्वारा सुधर जाती है।

(४) स्वर्णमान अविवेकी सरकारों की वृद्धियों में देश की रक्षा करता है। स्वर्णमान के नियम सरकार को स्वर्ण-वैष के उचित अनुपात से अधिक बरैमी और

¹ “The only intelligible meaning to be assigned, to the phrase the International Gold Standard is the simultaneous presence, in a group of countries, of arrangements by which, in each of them, gold is convertible at a fixed rate into the local currency and the local currency into gold, and by which gold movements from any one of these to any of the others are freely permitted by all of them.”—Gregory.

साध का विस्तार करने से रोकने है। हल्का विस्तार या संकुचन तो सम्भव है लेकिन अन्यथा मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-संकुचन नहीं किया जा सकता है।

बोप—जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के इतने लाभ हैं वहाँ इसके कुछ बोप भी हैं —

(१) स्वर्णमान का कार्य सम्पादन मुद्रा-संकुचन में प्रभावित तथा एक पक्षीय होता है। जबकि स्वर्ण खोने वाले देश के लिये यह अनिवार्य है कि अपने यहाँ साध को संकुचित करे और संकुचन के दुष्परिणामों को भोगे, तब स्वर्ण खाने वाला देश अपने यहाँ साध को बढ़ाने और मुद्रा प्रसार का अनुभव करने के लिए विवश नहीं है। उदाहरणार्थ, इङ्ग्लैंड में स्वर्ण के निर्यात के कारण वहाँ आम कम हो गई और सफ़ाई बंद गई किन्तु अमेरिका में स्वर्ण का आयात करंसी का विस्तार नहीं करा गया जिससे वहाँ मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न न हुई। स्वर्णमान के इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार के दो कारण हैं —(i) इङ्ग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका एक विशाल देश है जिससे कि एक विशाल निर्यात आधिक्य या पुराने ऋण की वापसी के कलस्वरूप वहाँ विशाल मात्रा में प्रवाहित होने वाले स्वर्ण का अर्थव्यवस्था पर विस्तारारामक प्रभाव अन्य ही पड़ता है, और (ii) विदेशी व्यापार की मात्रा देशी व्यापार की अपेक्षा अमेरिका में बहुत ही कम किन्तु इङ्ग्लैंड से बहुत अधिक है।¹

(२) अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन का प्रायः एक कुशल साधन पिक नहीं हुआ है। इसके विपरीत, वह सख्ती और कभी-कभी किसी के एक देश में दूसरे देश में खनने का साधन रहा है।² इसका अर्थ यह है कि एक देश की

1 Among the causes responsible for the deflationary bias of the gold standard, 'one is the unequal importance of the balance of payments as between countries whose foreign trade and other payments are large relative to the home economy and countries for which foreign trade is less important. The other is the unequal size of countries. Gold standard theory was based on the principle of interaction between homogeneous countries of approximately equal size'—John H. Williams. 'The Adequacy of Existing Currency Mechanism under Varying Circumstances,'—*American Economic Review*, March, 1937, p. 154.

2 'The gold standard has frequently not been efficient instrument of two sided compensatory international adjustment it was meant to be. It has been a means of spreading depressions and sometimes booms from one country to another,'—John H. Williams : 'The Post War Monetary Plan,'—*American Economic Review*, March, 1944, p. 373

कठिनाइयों में अन्य देशों की भी मागी होना पड़ता था भले ही वे इसके विधे तैयार न हों।

(३) स्वर्णमान का स्वचालित स्वभाव कई अर्थों पर निर्भर होता है। प्रथम, तो स्वर्ण-आवागमन गिकेनिज्म (Gold flow-mechanism) के स्वचालित कार्यवाहन के फलस्वरूप साख के जो संकुचन और फँसाव होते हैं वे देशों की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरनाक हैं। दूसरे स्वर्णमान देशों में केन्द्रीय बैंक इच्छा रखते हुए भी लागतों और कीमतों को साख संकुचन की दशा में नीचे की ओर तथा मात-प्रसार की दशा में ऊपर की ओर समायोजित करने में असमर्थ हो सकते हैं।¹

(४) युद्धोत्तरकाल के मौद्रिक इतिहास के पृष्ठ पतन से यह पता चलता है कि स्वर्णमान देशों के विनिमय स्थायित्व के लिए कीमत स्थायित्व का परित्याग करने की विवश करता है। वास्तव में स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय स्थायित्व और कीमत स्थायित्व दोनों एक ही साथ सम्भव नहीं हैं। एक वर्णमान देश अपने आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं करने पाता है।

स्वर्णमान व्यवहार में

स्वर्णमान के इतिहास का शुभारम्भ सन् १८१९ में होता है जबकि यह इंग्लैंड में कानून द्वारा स्थापित किया गया था। जर्मनी ने इसे सन् १८७३ में अप-नाया। फ्रांस ने सन् १८७८ में और अमेरिका ने सन् १९०० में स्वर्णमान की ग्रहण किया। रूस, जापान, हावैड, डेन्मार्क, आस्ट्रिया आदि (जिनके पास स्वर्ण का स्टॉक बहुत कम था) ने अपने यहां स्वर्ण विनिमय मान प्रचलित किया। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध शुरू होने के पहले ही स्वर्णमान व्यापक रूप से प्रचलित हो चुका था। अधिकांशतः यह एक महत्वपूर्ण स्वर्णमान (Full gold standard) था। न केवल मुद्रा-व्यवस्था (Monetary system) में से बल्कि देश में भी स्वर्ण का स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन होता था। यह इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि उन दिनों स्वर्ण की असीमित व स्वतन्त्र सिकन बलाई प्रचलित थी, सरकारों द्वारा स्वर्ण का निर्यात दलों पर कय विनय किया जाता था तथा अन्य प्रकार की मुद्राओं में स्वर्ण में स्वतन्त्र और असीमित रूप में परिवर्तनशील थी।

स्वर्ण चलन मान (Gold Coin Standard) सन् १९१४ में पहला विश्व

1 "In the modern world where on the one hand, inflows of gold are liable to be sterilised and prevented from causing an expansion of credit, whilst on the other hand the deflation of credit set up elsewhere is prevented by social causes from transmitting its full effect to money-wages and other costs it may be that the whole machine will crack before the reaction back to the equilibrium has been brought about" — *Committee on Finance and Industry Report, 1931, p 108*

युद्ध प्रारम्भ होने तक सहजतापूर्वक (smoothly) कार्य करता रहा। किन्तु युद्ध-काल में, स्वर्ण के स्वतन्त्र आयात-निर्यात को रोक दिया गया। परिणामतः अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान टूट गया तथा अपरिवर्तनशील पत्र चलन (Inconvertible paper currencies) ही सर्वत्र प्रचलित हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद, विश्व के अग्रणी राष्ट्रों का ध्यान पुनः स्वर्णमान की स्थापना पर गया।

लेकिन स्वर्णमान के पुनर्स्थापन की समस्या कुछ सरल नहीं थी, क्योंकि युद्ध ने अपने पीछे अनुराधिकार के रूप में अनेक जटिल समस्याएँ छोड़ी थीं। ये समस्याएँ निम्न थीं—(i) युद्धकाल में तथा युद्धोत्तर वर्षों में विभिन्न देशों में मुद्रा-प्रसार विभिन्न मात्राओं में बढ़ाया हुआ था। मुद्रा प्रसार की असमानता के कारण ही आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-स्तर-सम्बन्ध अस्त-व्यस्त हो गये। (ii) युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व शक्ति पर एक लेनदार राष्ट्र के रूप में प्रगट हुआ, जबकि अभी तक वह एक देनदार देश था। यूरोपीय और इंग्लैंड की स्थिति बहुत कुबल हो गई। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त प्रबन्ध का केन्द्र मन्दन से हट कर म्यूचुअलिटी में आ गया। (iii) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में, विशेषतः मुद्रा एवं अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में, सरकार व्यापक रूप से हस्तक्षेप करने लगी थी। और (iv) विश्व के मौद्रिक स्वर्ण कोष केन्द्रीय बैंकों व सरकारी खजानों में केन्द्रित हो गये तथा सिक्का ढलाई (Coinage) के लिए उपलब्ध नहीं रहे।

इस प्रकार, युद्धोत्तर विश्व की रचना युद्ध-पूर्व के विश्व से बिल्कुल भिन्न हो गई थी तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्त टकराने लगे थे। यह अनुभव निभा गया कि यदि वास्तविक चलन-इकाई सोने की न बनाई जाए, तो स्वर्ण के प्रयोग में निष्प्रभावता (economy) हो सकती है। इधर जनता भी पत्र मुद्रा का प्रयोग करने की भावी हो चुकी थी। यहाँ तक कि कई देशों में स्वर्ण सिक्के पुनः प्रचलित करने का प्रयत्न असफल हो गया था। इससे स्पष्ट है कि इन बलवती हुई परिस्थितियों में युद्ध पूर्व मूल्यों का स्वर्णमान स्थापित करना सम्भव न था। अतः सन् १९२० में जेनेवा कांफ्रेंस हुई, जिसमें स्वर्णपाटमान (Gold Bullion Standard) अथवा स्वर्ण विनिमयमान (Gold Exchange Standard) अपनाने का निर्णय हुआ। सर्वप्रथम अमेरिका स्वर्णमान पर सीटा। तत्पश्चात्, तीन देशों ने उसका अनुसरण किया। सन् १९२८ में, जबकि फ्रान्स ने भी स्वर्णमान अपना लिया, स्वर्णमान की पुनः स्थापना का कार्य सम्पूर्ण हो गया।

युद्धोत्तर स्वर्णमान का खण्डन—

यद्यपि स्वर्णमान सन् १९२८ में पूर्णतः पुनः स्थापित हो गया था तथापि व्यवहार में वह सहज गति से कार्य नहीं कराने पाया। वह कठिनाई से तीन वर्ष ही चला और इन तीनों वर्षों में भी उसका कार्य नम्मादन काटो से परिपूर्ण रहा। इसके अन्तिम रूप में खण्डन के लिए निम्नलिखित कारण दायीं थे—

(१) स्वर्ण-स्टैंडार्डों का असमान रूप से वितरण होना (Unequal distri-

bution of gold stocks)—युद्ध में भाग लेने वाले देशों ने अमेरिका व फ्रांस से अपार मात्रा में युद्ध सामग्री को खर्च किया था। किन्तु वेनिसदा राष्ट्रा में उनमें वस्तुओं में भुगतान लेता स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वर्ण मही मुद्रा खान करने की माँग की जिससे इन दोनों देशों में स्वर्ण संचित होने लगा। 'शून्य' अन्य देशों के स्वर्ण कोष बहुत घट गये थे इसलिए उनके लिये स्वर्णमान पर डटे रहना कठिन हो गया।

(२) स्वर्णमान खेल के नियमों का उल्लंघन (Defiance of the rules of the gold standard game)—स्वर्णमान की असफलता का कारण यह भी था कि इसके खेल के नियमों का पूर्ण रूप में पालन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए जब किसी देश में स्वर्ण आया, तो बड़ा साख का प्रसार न होने दिया गया और स्वर्ण आयागमन के प्रभावों को व्यर्थ करने में खुले बाजार के कार्य-कलापों (open market operations) का प्रयोग किया गया। इस प्रकार, सामान्य सीमा स्तर स्वर्ण के आवागमन से अप्रभावित ही रहा। फल यह हुआ कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी कर्तव्य (regulatory function) को पूरा करने में असमर्थ हो गया।

(३) दोषपूर्ण साख संरचना (Defective credit structure)—स्वर्ण प्रवाहों (Gold flows) के वांछित गुणगान प्राप्त करने हेतु यह बहुत ही वांछनीय था कि साख मुद्रा का नियन्त्रण किया जाय। लेकिन अनेक देशों की साख संरचना दोषपूर्ण होने के कारण बैंक दरों में बीच-बीच में घटा-बढ़ा करने का परिणाम यह हुआ कि द्रव्य-कोष एक देश से दूसरे देश की, सुरक्षाश्रय विनियोग के लिए, जल्दी-जल्दी आने-जाने लगे।

(४) क्षति भुगतान एवं युद्ध ऋण (Reparations and war debts)—जर्मनी द्वारा युद्ध सम्बन्धी क्षति के भुगतानों तथा युद्ध जनित ऋणों ने स्वर्णमान की कार्य-प्रणाली पर भारी बोझ (Strain) डाला। क्षति व ऋणों के भुगतान में अमेरिका और फ्रांस की स्वर्ण की विशाल मात्राएँ प्राप्त हुई, जिससे वहाँ स्वर्ण-भण्डार भरपूर हो गये किन्तु अन्य देशों में इसकी कमी हो गई।

(५) अर्थ-व्यवस्थाओं की बेलाचता में वृद्धि (Growing inelasticity in economic system)—विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं की बढ़ती हुई बेलाचता के कारण स्वर्णमान के सहज रूप में कार्य-सम्पादन में, बड़ी बाधा पड़ने लगी थी। स्वर्ण खोने वाले देश में नीमतेँ मिलनी चाहिए थी जबकि स्वर्ण प्राप्त करने वाले देश में नीमतेँ बढ़नी चाहिए थी। किन्तु यह सब नहीं हो सका, क्योंकि देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ पहले के समान लोचदार नहीं थी। उदाहरण के लिए, सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कोई कमी नहीं की जा सकती थी। सुदृढ यम-संधि के बहुत विरोध के कारण मजदूरियों में कटौती करना भी सम्भव नहीं था। एकधिकारों व कर्तव्यों की शक्ति के कारण कच्चे मालों व निर्मित मालों की कीमतें भी नहीं घटाई जा सकती थी।

(६) राजनैतिक अस्थिरता एवं मन्दो (Political instability and depression)—कुछ देशों में प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद जो राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी उसके कारण फ्रांस ने वहाँ से अपने विनियोजित कोष लौटाने प्रारम्भ किये । यही नहीं, अमेरिका में औद्योगिक सम्पन्नता (prosperity) और स्टॉक विनिमय प्रतिभूतियाँ (stock exchange securities) की ऊँची कीमतों के कारण कुम्भ्यात 'वाल स्ट्रीट स्रक' (Wall Street Crash) टूट पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण विश्व में रोजगार, कीमत व उत्पाति स्तर गिरने लगे । इस तरह महान् मंदी का सूत्रपात हुआ, जिसने स्वर्णमान को भी अपनी जेबेट में से लिया ।

(७) त्रुटिपूर्ण समता-स्तर (Incorrect parity levels)—ब्रिटिश पाउण्ड १०% से अधिमूल्यवान् (over-valued) था । इसके विपरीत, फेंच फ्रांक इतना ही अधमूल्यवान् (under-valued) था । इस दोषपूर्ण समता के कारण भी इङ्गलैंड से सोने का लगातार बहिर्गमन होता रहा ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद आर्थिक दशाएँ बीरे-बीरे इतनी प्रतिफल हाँ गईं कि स्वर्णमान सन् १९३१ में अन्ततः टूट ही गया । स्वर्णमान के जखन के पश्चात् इङ्गलैंड, अमेरिका और फ्रांस ने विनिमय-दरों के उतार चढ़ावों का नियन्त्रण करने हेतु 'विनिमय समानीकरण कोष' (Exchange Equalisation Funds) स्थापित किये । सन् १९३६ में जब द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ तब सभी देशों ने विनिमय नियन्त्रण कठोरतापूर्वक लागू किये और स्वर्णमान पर लोपाने का विचार राहा के लिए त्याग दिया । सन् १९४५ में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई । इसकी योजना के अनुसार विनिमय दरों के निर्धारणों में स्वर्ण की भूमिका अब पहले जितनी महत्त्वपूर्ण नहीं रही है ।

स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त (Theory of Gold Movements)

भुगतान समतुलन में साम्यता लाने वाली सुधार प्रक्रिया—

स्वर्णमान देशों के भुगतान समतुलन में असाम्यता का सुधार या साम्य की स्थापना स्वर्ण के आवागमन के द्वारा, अर्थात्, स्वर्णमान देशों के मध्य स्वर्ण के आगमन (inflow) और बहिर्गमन (outflow) द्वारा होती है । 'स्वर्ण के आवागमन के सिद्धान्त' के अनुसार, नीची लागत-शीलत मरचना वाले देश में स्वर्ण का आगमन होता है किन्तु अपेक्षित ऊँची लागत-शीलत मरचना वाले देश से स्वर्ण का बहिर्गमन ।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—सुधार प्रक्रिया को समझाने के लिये हम दो देशों का उदाहरण लेते हैं । मान लीजिये कि A और B दो स्वर्णमान देश हैं । यह भी मान लीजिये कि A देश का भुगतान समतुलन B देश के भुगतान समतुलन के सदृश में 'निष्क्रिय' (passive) हो गया है, अर्थात्, A जितना माल B को निर्यात करता है उससे कहीं अधिक माल का आयात कर रहा है । ऐसी परिस्थिति में A को

II के प्रति कुछ शुद्ध रकम का (जो कि भुगतान-सतुलन में घाटे के बराबर है) भुगतान करना है जो स्वर्ण के निर्यात द्वारा किया जायेगा। स्वर्ण के इस बहिर्गमन का तात्कालिक प्रभाव यह होगा कि A में करन्सी का संकुचन और B में करन्सी का प्रसार होगा। मुद्रा परिणाम सिद्धान्त की परिष्कृत व्याख्या (refined version) के अनुसार A में करन्सी का संकुचन होने से वस्तुओं की कीमतें गिर जाएंगी आय और रोजगार में भी कमी हो जायेगी और चूँकि समस्त वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं इसलिए A देश विदेशियों द्वारा प्रय के लिये एक अच्छा किन्तु विषय के लिए बुरा बाजार बन जाता है, जिससे A देश से B देश को निर्यात प्रोत्साहित होने है।

दूसरी ओर, स्वर्ण के आगमन के फलस्वरूप जब B देश में करन्सी का प्रसार होता है, तो वहाँ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं एवं आय और रोजगार में भी वृद्धि होती है। चूँकि सब कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिये वह बिच के लिये एक अच्छा किन्तु नय के लिये खराब बाजार हो जाता है, जिससे वहाँ आयात प्रोत्साहित और निर्यात अ-प्रोत्साहित होते हैं।

उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि दोनों देशों में कीमत सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रभाव इस प्रकार होता है कि A के आयात घट जाते हैं किन्तु निर्यात बढ़ जाते हैं, B के आयात बढ़ जाते हैं किन्तु निर्यात घट जाते हैं और इन प्रवृत्तियों के सम्मिलित प्रभाव इस प्रकार है कि दोनों देशों के भुगतान सतुलन में साम्य बाने स्थापित होने लगता है।

A देश के आयात (अथवा III देश के निर्यात) एक अय कारण में भी घटते हैं। चूँकि A देश में रोजगार और आय घट गई हैं, इसलिए वहाँ सभी प्रकार की (देशी + विदेशी) वस्तुओं के उपभोग में कमी हो जायेगी और देश के आयातों में घटौती के रूप में प्रतिबिम्बित होगी। दूसरी ओर, B देश में आयात (अथवा A देश के निर्यात) बढ़ जायेंगे, क्योंकि B देश में आय व रोजगार में वृद्धि हो गई है जिसके फलस्वरूप वहाँ देशी विदेशी सभी वस्तुओं का उपभोग बढ़ जायेगा। यह उपभोग-वृद्धि A में B को बटे हुये आयातों के रूप में प्रतिबिम्बित होगी।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि स्वर्ण के आवागमन एक देश में मुद्रा-प्रसारित प्रक्रिया को और दूसरे देश में मुद्रा-सिंफीतिव प्रक्रिया को जन्य देकर स्वर्णमान देशों के भुगतान सतुलन में साम्य की स्थापना में सहायक होते हैं। यह सुधार प्रक्रिया स्वयंचालित रूप में (automatically) चलती रहती है और स्वर्ण के आवागमनों में किसी का भी हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकती है। किन्तु सुधार प्रक्रिया के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समायोजन दोनों देशों में सापेक्षिक कीमता और आयों के परिवर्तनों द्वारा, जो कि स्वयं सम्बद्ध देशों की आर्थिक क्रिया के स्तर में परिवर्तन का परिणाम है, सम्भव होता है। इस स्वचालित प्रक्रिया को केन्द्रीय

बैंकों की नीति से बहुत बल मिलता है। उदाहरणार्थ, यदि वे स्वर्ण खोने वाले देश में बैंक-दर बढ़ा दें, तो वहाँ समस्त व्यापारिक बैंकों द्वारा भी व्याज दरें बढ़ा दी जायेंगी, जिससे विनियोग, रोजगार और आय में और भी अधिक कमी हो जायेगी तथा विदेशों से कोष विनियोग के लिए आने लगेगे, जिससे स्वर्ण जाना रुक जायगा। किन्तु स्वर्ण पाने वाले देश में, बैंक दर में कमी होने पर, व्यापारिक बैंक भी व्याज दर घटा देने इससे विनियोजन प्रायः व रोजगार बढ़ेगा। ये प्रवृत्तियाँ मुद्यार प्रतियाँ की गति प्रदान कर देती हैं, जिससे वह जल्दी ही पूर्ण हो जाते हैं। स्वर्ण के आवागमन को सम्भव बनाने वाली दशायें—

स्वर्ण के आवागमन और इसके द्वारा मुद्यार की प्रतियाँ सम्भव होना ये गति यह आवश्यक है कि विभिन्नलिखित बातों का पालन किया जाय —

(१) सभी स्वर्णमान देश स्वर्णमान के नियमों का सन्चार्य से पालन करें। इसका अभिप्राय यह है कि स्वर्णमान देशों के मुद्रा अधिकारी स्वर्ण-प्रवाह-मिकेनिज्म को स्तम्भितपूर्वक कार्य करने दें। प्रत्येक देश स्वर्ण-मुद्रा के औचित्य व्यवहार को ही अपनी बैंकिंग नीति का लक्ष्य बनाय स्वयं उनका स्वतन्त्र एवं ऐच्छिक योगदान बहुत ही उत्प हो। अतः करैन्सी और साख का स्वर्ण खोने वाले देश में सकुचन तथा स्वर्ण पाने वाले देश में विस्तार होना चाहिये।

(२) स्वर्णमान देशों की धन-व्यवस्था सततद्वार होनी चाहिये। तब ही स्वर्ण कोषों में हुई तनिक भी घटा-बढ़ी सम्बद्ध देशों की लागत-कीमत संरचना में प्रतिबिम्बित हो सकेगी और तब ही स्वर्ण खाने वाले देश में सकुचन और स्वर्ण पाने वाले देश में मुद्रा प्रसार आत्मिक रूप से सम्भव होगा। इस हेतु स्वर्णमान देशों में एक विशेष प्रकार का आगत वातावरण होना चाहिये। उदाहरणार्थ, मजदूरी गन्त-भी नीलि लचीली होनी चाहिये। जब स्वर्ण के बाहर जाने पर आय का सकुचन होने लगे तथा मजदूरी में कटौती करनी पड़े, तब इसमें धमकाई की बाधक नहीं बनना चाहिए।

(३) निम्नकारक पूँजी-आवागमन नहीं होने चाहिये। जब पूँजी बड़े पैमाने पर सहसा ही एक देश में दूसरे देश की प्रयाण करती है, तो भुगतान सतत सम्बन्धी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, स्वर्ण के विशाल आवागमन होने लगते हैं और इससे स्वर्ण-प्रवाह-मिकेनिज्म काम करने में असमर्थ हो जाता है।

(४) माँग की कीमत सम्बन्धी लोच ऊँची होनी चाहिये। यदि देशों और विदेशी माँग की कीमत लोच (price elasticities) ऊँची होये, तो कीमत में जो असत एक उत्प परिवर्तन हो सम्बद्ध देशों में निर्यात और आयात के लिये माँग में

1 The main criterion of the banking policy of each country should be the average behaviour of all the other members, its own voluntary and independent contribution being a modest one".—Keynes : *A Treatise on Money*, Vol II, p 303.

बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर सकेगा और इन तरह समाशोधन-क्रिया सहज हो सम्पन्न हो सकेगी ।

(५) स्वर्ण समताओं में स्थापित होना भी आवश्यक है । यदि लोगों को यह शक्य रहती है कि स्वर्णमान देश अपनी विनिमय दर में स्थिरता वायम् न रख सकेगा, तो सट्टा ध्वजहारों का जोर बढ़ जाता है ।

(६) राजनैतिक स्थापित भी स्वर्णमान के सहज रूप से काय करने रहने के लिए आवश्यक है ।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर का निर्धारण
(टकरात-समता सिद्धान्त)

‘टकराती समता’ क्या है ?

स्वर्णमान विश्व में सबसे प्रचलित एक धातुमान रहा है । अब हम दो स्वर्णमान देशों के बीच स्वाभाविक विनिमय दर के निर्धारण पर प्रकाश डालेंगे । प्रायः देशों के विधान द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि उसकी मुद्रा में अनुकूल माना में विद्युत् स्वर्ण रहेगा । दो मुद्राओं के स्वर्ण मूल्यों की समानता स्थापित करते समय विधान द्वारा उल्लिखित विद्युत् स्वर्ण-मूल्य को ही ध्यान में रखा जाता है न कि मुद्रा के अतिरिक्त मूल्य का क्योंकि उसमें मुद्रा स्वर्ण के साथ मिलावट भी हो सकती है ।¹ विधान द्वारा निर्धारित विद्युत् स्वर्ण के आधार पर दो देशों के बीच जो समानता स्थापित होती है उन विनिमय की टकराती समता’ (Mint Par of Exchange) या विनिमय की स्वर्ण-मूल्य समता’ (Gold Par of Exchange) कहते हैं ।² हैदराल के शब्दों में — यदि दो या अधिक व्यापारी देशों में स्वर्णमान हो और यदि स्वर्ण के आयात-निर्यातों पर कोई प्रतिबन्ध न हो, तो विभिन्न करमियों का गठबन्धन बहुत हट जाता है । टकराहरण के लिए, यदि एक ओर स्वर्ण से एक निश्चित माना में पौंड के टिकके या इसमें बीस गुन मात्रा बनाया जा सकते हैं, तो (यदि यह मान दिया जाय कि मुद्रा टालने का कोई व्यय नहीं है) कोई भी व्यक्ति २० मात्रा के बदले एक पौंड या एक पौंड के बदले २० मात्रा प्राप्त कर सकता है ।³

¹ ‘The Mint Par depends, in short not on the coin itself but on the legal definition of it, not on the sovereign de facto but on the sovereign de jure unless and until the law is altered the Mint Par can not alter’ — Clare and Crump

² ‘Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same monetary standards’ — Thomas

³ ‘If two or more trading countries are on the gold standard, and if there are no obstacles to the import and export of gold, (Contd. on next page)

टकसाली समता पर आधारित विनिमय दर—

प्रथम विश्व युद्ध के पहले और इसके बाद युद्धोत्तरकाल में भी कई वर्षों तक अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही पूर्णरूपेण स्वर्णमान पर थे। स्वर्ण-सावरेन में ११३ ००१६ ग्रेन और स्वर्ण डालर में २३ २२०० ग्रेन स्वर्ण (स्टैण्डर्ड विबुडता) था। चूँकि टकसाली समता दोनों करैसियों में निहित स्वर्ण के अनुपात में होती है, इसलिए डालर और पाँड में विनिमय दर, टकसाली समता के आधार पर, ११३ ००१६ २३ २२०० अर्थात् १ : ४ ८६६५ थी, जिसका आशय है कि ४ ८६६५ अमेरिकी स्वर्ण डालर १ पाँड के बराबर थे।

उपरोक्त सङ्ग से जो विनिमय दर निकाली गई है वह एक 'आदर्श' (norm) है, जो कि शीर्षकाल में प्रचलित होगी। 'दैनिक' अथवा 'बाजार विनिमय दर' इस आदर्श से कुछ निश्चित योगाओं के भीतर भिन्न हो सकती है और होती है। ये सीमायें एक देश से दूसरे देश की स्वर्ण के यातायात में हुए वास्तविक व्यय (जिसमें बीमा, पैकिंग व्यय आदि सम्मिलित हैं) द्वारा नियत होती हैं।

स्वर्ण धिन्बुओं का महत्त्व—

स्वर्णमान देशों में लोगों की यह विकल्प होता है कि वे अन्य देशों की या तो टेलीग्राफिक ट्रांसफर और विनिमय बिलों द्वारा अथवा स्वर्ण भेजकर भुगतान करें। जब स्वर्ण भेजकर भुगतान किया जाता है, तो सरकारी कीमत के अतिरिक्त भाड़ा बीमा, पैकिंग और स्थानान्तरण की अवधि के लिए व्याज की हानि के रूप में अन्य व्यय भी करने पड़ते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय माध्यम हेतु जब स्वर्ण का प्रयोग किया जाय, तो इन व्ययों की भी ध्यान में रखना चाहिए।

मान लीजिए कि पाँड और फ्रैंक के मध्य टकसाली समता दर १ पाँड = १२४ २१ फ्रैंक है और अन्य व्यय दोनों दिशाओं में ५० फ्रैंक है। फ्रांसिसियों द्वारा अँग्रेजों को स्वर्ण में भुगतान करने के लिए प्रत्येक पाँड ऋण के सम्बन्ध में कुल व्यय १२४ २१ + ५० अर्थात् १७४ ७१ फ्रैंक करना पड़ेगा। इसी तरह, जब इंग्लैंड से भाड़ा की भुगतान स्वर्ण में किये जाते हैं, जो अँग्रेज ऋणी द्वारा चुकाये गये प्रत्येक पाँड के लिए उसके फ्रांसीसी ऋणदाता का (१२४ २१ + ५० =) १२९ ७१ फ्रैंक प्राप्त होत है।

जब तक दोनों करैसियों के मध्य विनिमय दर १ पाँड = १२४ ७१ फ्रैंक से

then the different currencies are rigidly linked together. For instance, if an ounce of gold can be coined into a definite number of pounds sterling and into twenty times as many marks then—still under the provisional assumption that no costs are involved—one can convert at will twenty marks into one pound and vice versa"—Haberler : *The Theory of International Trade*

रहा रहे तब तक फासीसी ऋणियों के लिए सामान्य ढङ्ग से (अर्थात् सात पत्रों के प्रयोग द्वारा) भुगतान करना ठीक होगा, लेकिन जब विनिमय दर १२४७१ फ्रैंक से अधिक हो जाय, तो स्वर्ण भेजकर भुगतान करना ही लाभदायक होगा। फलतः स्वर्ण फ्रांस से इङ्ग्लैंड को निर्यात होने लगेगा। अब इसे फ्रांस के लिए 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' (Gold Export Point) या 'उच्चतम स्वर्ण बिन्दु' (Upper gold point) कहेंगे। इङ्ग्लैंड की दृष्टि से इसे 'स्वर्ण आयात बिन्दु' या 'निम्नतम स्वर्ण बिन्दु' कहते हैं।

इसी प्रकार, जब तक विनिमय दर १२३७१ फ्रैंक से अधिक रहे, तब तक अंग्रेज ऋणियों द्वारा भुगतान सामान्य ढङ्ग से (सात पत्रों के प्रयोग द्वारा) किये जायेंगे। लेकिन, यदि विनिमय दर १२३७१ फ्रैंक से नीचे गिर जाय, तो इङ्ग्लैंड से फ्रांस का भुगतान स्वर्ण भेज कर किया जायेगा क्योंकि अब ऐसा करना ही लाभ-प्रद है। चूँकि इस बिन्दु पर स्वर्ण इङ्ग्लैंड में फ्रांस को निर्यात होने लगता है, इसलिए इसे इङ्ग्लैंड की दृष्टि से, 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' या 'उच्चतम स्वर्ण बिन्दु' और, फ्रांस की दृष्टि से, 'स्वर्ण आयात बिन्दु' या 'निम्नतम स्वर्ण बिन्दु' कहेंगे।

दो देशों के मध्य विनिमय-दर उक्त 'उच्चतम' एवं 'निम्नतम' स्वर्ण बिन्दुओं की सीमा में अधिक परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि, जैसे ही विनिमय दर इनमें से किसी भी बिन्दु को पार करती है, वैसे ही स्वर्ण का आवागमन होने लगता है। स्वर्ण आने वाले देश में करेसी का सकुचन और स्वर्ण जाने वाले देश में करेसी का प्रसार होकर विनिमय दर पुनः स्वर्ण-बिन्दुओं की परिधि में लौट आती है।

इस प्रकार, स्वर्ण (या रजत) मान के अधीन विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सम्पूर्ण विवेचन में स्वर्ण-बिन्दुओं का बहुत महत्व है, क्योंकि इनसे यह पता चलता है कि विदेशी विनिमय बाजार में दैनिक विनिमय दर में कितना अधिकतम उतार-चढ़ाव हो सकता है। ये बिन्दु हमें यह भी बताते हैं कि विनिमय दर एकसाली विनिमय दर में जो विदेशी विनिमय दर के एकसाली सिद्धान्त पर आधारित है, क्यों भिन्न होती है।

सुधार प्रक्रिया—

मान लीजिए कि लगातार फलसें खराब रहने से या एक दीर्घ अवधि तक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी भुगतान करने की आवश्यकता के कारण व्यापार मनुजान प्रुष्ट स्वामी रूप से निजिम् हो जाता है और विदेशी मुद्रा की दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊँची हो जाती है। ऐसी दशा में स्वर्ण का वहिर्गमन अब तक जारी रह सकता है? क्या कोई ऐसी सीमा है जिसमें अधिक स्वर्ण को चलाने में जो न तिराला जायेगा? क्या करेसी पर अमुविधाबन्धन दबाव को रोकने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? अथवा, क्या विभिन्न देशों में स्वर्ण का वितरण स्वतः ही हो जायेगा?

व्यापारवादियों का दृष्टिकोण—इस पुस्तक के प्रारम्भ में ही हम यह बता चुके हैं कि व्यापारवादियों ने सक्रिय सन्तुलन और स्वर्ण के आगमन को बढ़ाने

की दृष्टि से आयातों पर प्रतिबन्ध तथा निर्यातों को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया था। व्यापारवादियों की यह आलोचना की जाती है कि उन्होंने कुल भुगतान सन्तुलन के बजाय केवल व्यापार सन्तुलन पर ही ध्यान दिया। किन्तु यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि अनेक व्यापारवादियों ने व्यापार सन्तुलन के अतिरिक्त भुगतान सन्तुलन की गंदी की भी स्पष्ट रूप से चर्चा की है। कुछ गदों जो जात्र महत्वपूर्ण समझे जाती हैं उन दिनों नगण्य थी या बिद्यमान नहीं थी। अतः इन्हे विचार में न लेना कोई भ्रुति नहीं थी।

व्यापारवादियों की नीति इस विचार पर आधारित थी कि स्वर्ण का संचय होना देश की वास्तविक सम्पत्ति में वृद्धि होना है। किन्तु उनका यह विचार वृद्धिपूर्ण था और यदि वह ठीक भी होता, तो जो कट्टर (सरकारों हस्तक्षेप) उन्होंने सुझाया वह लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता था। यह डर भी निराधार था कि यदि सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो स्वर्ण का असीमित बहिर्गमन हो सकता है। उनका सम्पूर्ण सिद्धान्त भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी अपरिष्कृत विचारों पर आधारित था। अन्त में, स्लूम ने १७५२ में प्रकाशित अपनी पुस्तक Political Discourses में व्यापारवादियों के सिद्धान्त के स्थान पर एक नवीन सिद्धान्त प्रस्तुत किया। यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त का प्रारम्भिक रूप था, जिसे बाद में एडम स्मिथ, थॉमस, रिकार्डो, सोनियर, गिल, कर्नेंग, बेरटेबल, टॉबिन आदि ने सुधारा और विस्तृत किया।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त—हमारी समस्या यह समझना है कि व्यापार सन्तुलन के निष्पन्न होने तथा स्वर्ण के बाहर जाने लपने के बाद साम्य की पुनः स्थापना कैसे होगा? प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के अनुसार इच्छा सम्पन्न यह है स्वर्ण का बहिर्गमन चलन में मुद्रा के परिमाण को घटा देता है, जिसके फलस्वरूप कीमतें गिरती हैं, निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं। किन्तु विदेशी देश में, जहाँ कि भुगतान सन्तुलन सक्रिय हो गया है, विपरीत घटवाये होती है—स्वर्ण अन्दर आने लगता है, चलन में करेन्सी की मात्रा बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ती हैं, आयात प्रोत्साहित और निर्यात हतोत्साहित होते हैं। स्वर्ण का आवागमन, जो कि व्यापार सन्तुलन की निष्क्रियता के कारण आवश्यक नगदी का भुगतान करने के सहस्य है, दोनों देशों के कीमत स्तरों में एक भिन्नता पैदा कर देने है। इससे वस्तुओं का प्रवाह उस दिशा में होने लगता है, जिसमें कि स्वर्ण का प्रवाह मूलतः हो रहा था और वस्तुओं का प्रवाह स्वर्ण के प्रभाव को विपरीत दिशा में घटाता है। परिणामतः ये दोनों स्वर्ण आवागमन आपस में चुक (cancel) जाते हैं तथा वस्तुओं के आवागमन द्वारा भुगतान सन्तुलन में साम्य स्थापित हो जाता है।

इस प्रकार, भुगतान अस्थायी रूप से तो स्वर्ण में किन्तु अंतिम रूप में वस्तुओं में किया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि किसी देश पर अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व महान् हो जा पड़े, तो उसके निर्यातों की मात्रा एवं इसके परिणामस्वरूप

विदेशी बिलों की पूर्ति बढ जायेगी। साथ ही इन बिलों के लिये माँग कम हो जायेगी, क्योंकि आयात मकुचित होन लगते हैं। अतः बिज बाजार पुन साम्यावस्था में आ जाता है तथा विनिमय दर पुन स्वर्ण-बिन्दु से नीचे गिर जाती है।

यही मिकेनिज्म है जो कि भुगतान समुलन में साम्य बनाये रखता है और किसी भी देश के स्वर्ण स्टॉक को पूर्णतः खत्म नहीं होने देता है तथा विश्व-व्यापार में भाग लेन वाले स्वर्णमान देशों में स्वर्ण के उचित वितरण को प्रोत्साहित करता है। यह मिकेनिज्म स्वर्ण के आवागमन को स्वचालित रूप में नियमित करता रहता है। अतः इसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचनाएँ-

प्रतिष्ठित सिद्धान्त यूरोपीय महाद्वीप में कभी लोकप्रिय नहीं हो सका।

(१) होवपूर्ण आधार—इसके सम्बन्ध में आलोचना का लक्ष्य मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त रहा जिस पर कि यह आधारित है। निम्न दर्शा हमें मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के दो रूपों में भेद करना चाहिये। अपरिष्कृत व्याख्या से अनुसार, मुद्रा के परिमाण में एक बिन्दु होने प्रतिजन से घटा-बढी, उसी अनुपात में कीमतों में भी घटा-बढी उत्पन्न कर देती है। निम्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त इतनी कठोर कल्पना नहीं करता। वह तो केवल इतनी कल्पना करता है कि मुद्रा-मात्रा की वृद्धि कीमतों में वृद्धि और मुद्रा-मात्रा की कमी कीमतों में कमी कर देती है। कीमतों में यह घटा-बढी वितरित हो जायेगी इस बारे में वह कुछ नहीं कह सकता। निःसन्देह परिष्कृत मुद्रा परिमाण सिद्धान्त की सघटा में इन्कार करना सम्भव नहीं है। स्वाभाविक है कि मुद्रा मात्रा कीमतों पर हम ही प्रभाव डालेगी जबकि वह वास्तव में लक्ष की जायेगी और इस प्रकार यह यन्त्रों के लिये प्रभावपूर्ण माँग का प्रतीक है। यह कहने के बजाय कि मुद्रा मात्रा में कमी होती है या स्वर्ण बाहर आ रहा है, हम प्रतिष्ठित सिद्धान्त का अर्थ बदले बिना, यह भी कह सकते हैं कि कुल मौद्रिक आय गिरती है, मुद्रा की पूर्ति घटती है वस्तुओं के लिये माँग कम हो जाती है, प्रथम (प्र० ओहलिन का अनुसरण करते हुये) नय शक्ति में बदलाव (shift) हुआ है।

(२) विशाल बिन्दु का सुधार-सम्भव नहीं—यह आपत्ति भी उठाई गई है कि व्यवहार में जो स्वर्ण-आवागमन होने है उनकी मात्रा भुगतान-समुलन में प्रायः उदय होने वाले विशाल बिन्दुओं को जीतने के लिये नगण्य है। किन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं भुलाना चाहिये कि आधुनिक देशों के अन्तर्गत प्रत्यक्ष मौद्रिक प्रणाली केन्द्रीय बैंक की मचेत नीति (deliberate policy) और अन्तर्राष्ट्रीय साख के मिकेनिज्म द्वारा प्रभावित होती है। दूसरे, स्वर्ण के आवागमन, नय शक्ति के परिमाण में, अपनी अपेक्षा, जनेब मुद्रा परिवर्तन कर देने है। हाँ, विमुद्रा स्वर्णमान के अधीन, जबकि चल माध्यम केवल स्वर्ण का ही होता है, ऐसे आवागमन अधिक बड़े पैमाने पर होने आवश्यक है।

(३) कीमतों में भिन्नता पर्याप्त समय के लिये नहीं—प्रो० लास्किन (Laughlin) ने यह आपत्ति उठाई है कि आधुनिक बाजारों में रेत, तार, टेलीफोन आदि से इतना घनिष्ठ सम्पर्क बन गया है कि कीमत-भिन्नताएं इतने समय तक नहीं बनी रहती हैं कि वस्तुओं के पर्याप्त विशाल आवागमन हो सके। किन्तु इस आलोचना को यह कह कर रद्द किया जा सकता है कि इससे तो यह प्रमाणित होता है कि गिकेनिंग कितनी शीघ्रता से कार्य आरम्भ कर देता है।

(४) स्वर्णमान युग की समाप्ति—आजकल स्वर्णमान प्रचलित नहीं है। अतः विदेशी विनिमय दर के टक्काली सिद्धान्त के लागू होने के लिए कोई स्कोप (scope) नहीं है।

(५) आन्तरिक कीमत-स्थापित्व का बलिवान—प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अन्तर्गत विनिमय-स्थापित्व आन्तरिक कीमता के स्तर में अस्थिरता उत्पन्न होकर ही सम्भव है, जोकि जनता पर बहुत बलिवान डालती है।

(६) सुधार का कम असम्बन्ध—निःसन्देह यह सच है कि मुग्तान सन्तुलन की असम्बन्धता विनिमय दर पर प्रतिक्रिया दिखलाती है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि सुधार उसी तरीके से होता है जिसमें कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने बताया था। कारण — (i) अब वस्तुएँ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मात्र महत्वपूर्ण वस्तु नहीं हैं, वरन् पूर्वी-आवागमन और रोनाये भी कुछ व्यवहारों में एक महत्वपूर्ण भाग रखने लगी हैं; (ii) स्वर्ण ही सर्वप्रथम 'गति' (movement) नहीं बिलखाता वरन् इससे भी पहले अपकालीन कोपी, प्रतिभूतियों आदि का आवागमन होने लगता है, जिससे यदि इससे ही साम्य स्थापित हो जाय, तो फिर कीमतें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती हैं। पुनः जो स्वर्ण देश में आता भी है, वह केन्द्रीय बैंक के ही पास आता है और यह बैंक इसे चलन में प्रवेश करने से रोक सकता है।

(७) लागत कीमत सरचनाओं में आवश्यक लोच का अभाव—स्वर्ण के आवागमन के सिद्धान्त की कार्यशीलता स्वर्णमान देशों में लागत-कीमत सरचनाओं की लोच पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि आजकल के बदले हुए सत्यागत वातावरण में यह लोच कहीं नहीं रह गई है। उदाहरणार्थ, जब इङ्ग्लैण्ड ने स्वर्णमान १९२५ में पुनः काम किया गया, तो वहाँ पुरानी समता (parity) की ही अपेक्षा की गई थी, क्योंकि अधिवासियों को यह विश्वास था कि ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था लोचदार है तथा इसलिये मजदूरियाँ गिरेंगी। किन्तु श्रम संधी ने मजदूरियों में कटौती का, जो कि मुग्तान सन्तुलन की असम्बन्धता के सुधार के लिए आवश्यक थी, घोर विरोध किया। इस प्रकार, आजकल, 'नूँ' अर्थ-व्यवस्था में लोच का अभाव हो गया है, इसलिये स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त कार्यशील नहीं हो सकता है।

(८) देशों पर सुधार का भार असमान रूप से पड़ता—यही नहीं, स्वर्ण के आवागमन का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि सुधार का भार दोनों देशों पर बराबर-बराबर पड़ता है। लेकिन ऐसा तब ही होता है जबकि व्यापार

करने वाले दोनों देश आर्थिक दृष्टि से समान आकार वाले हों। यदि एक छोटे देश (जैसे कि हेन्गाको) से स्वर्ण जाय, तो वहाँ कीमतें बहुत अधिक गिर सकती हैं जबकि उतना ही स्वर्ण जब एक बड़े देश (जैसे अमेरिका) में जाय, तो वहाँ कीमतों में एक अल्प वृद्धि ही होगी, कारण, जाने वाला स्वर्ण अमेरिका के कुल स्वर्ण कोष का एक छोटा-सा ही भाग है।

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के सफल कार्यवाहान के लिये आवश्यक शर्तें बताइए। स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर क्यों परिवर्तित हो जाती है? ऐसे परिवर्तनों की सीमाये समझाइए।

[State the conditions necessary for the working of international gold standard. Why does the rate of exchange fluctuate under gold standard? State the limits to its fluctuations.] (विक्रम, एम० ए० १९६६)

- २ द्वितीय महायुद्ध से पहले की अवधि में स्वर्णमान की असफलता इन तथ्यों के कारण थी कि राष्ट्रों ने स्वर्णमान के खेल के नियमों का पालन नहीं किया था।" इस कथन का विवेचन कीजिये। यह भी बताइये कि स्वर्ण मान से उदय होने वाले प्रभाव किस सीमा तक स्वर्णमान की असफलता के लिये दायी रहे।

["The failure of the Gold Standard in the period before World War II was due to the fact that the nations concerned did not observe the rules of the Gold Standard Game." Discuss this statement. Also indicate how far the influences emanating from the side of gold as such were responsible for the failure of the Gold Standard"]

- ३ जब दोनों देश स्वर्णमान पर हों, तो उनके मध्य विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है? विनिमय दर किस सीमाओं के भीतर परिवर्तित हो सकती है उनको समझाइए।

[How is the rate of exchange determined when both the countries are on Gold Standard? Also explain the limits within which the rate of exchange fluctuates]

अपरिवर्तनशील पत्र-चलन

[क्रय शक्ति समता सिद्धान्त]

(Inconvertible Paper Currencies)

परिचय—

पिछले अध्याय में उन करेंसियों का विवेचन किया गया था जों कि स्वर्ण की परिवर्तनशीलता के द्वारा एक दूसरे से जोड़तापूर्वक सम्बन्धित थीं। प्रस्तुत अध्याय अपरिवर्तनशील पत्र-करैंसियों से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह बताया गया है कि जब देशों में अपरिवर्तनशील पत्र-करैंसियाँ प्रचलित हैं (अर्थात् आजकल की भाँति प्रबन्धित पत्र चलन है), तो विनिमय-दरें किस प्रकार निर्धारित होती हैं।

प्रबन्धित चलन
(Managed Currency)

प्रबन्धित चलन के आशय—

‘प्रबन्धित चलन’ का आशय उस मुद्रा मान से है जिसके आधीन मुद्रा मूल्य का नियमन केन्द्रीय बैंक द्वारा एक विशेष योजना के अनुसार किया जाता है। अर्थात्, जब सरकार देश की मौद्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में किसी निश्चित उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए एक निश्चित मौद्रिक नीति अपनाती है, तो ऐसी करैंसी ‘प्रबन्धित’ कहलाती है। इस प्रकार, एक प्रबन्धित चलन की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं —(i) करैंसी-यूनिट किसी धातु या अन्य करैंसी में परिवर्तनीय (convertible) नहीं होती है, (ii) करैंसी नोट किन मानों में जारी किये जायें यह देश की क्रय शक्ति सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में सरकार के अनुमान पर निर्भर है। अन्य शब्दों में, करैंसी की इशू करने की कोई न्यूनतम या अधिकतम राशिवाँ निर्धारित नहीं होती है बरन् यह पूर्णतः सरकार के निर्णय पर छोड़ दी जाती है।

प्रबन्धित चलन के गुण—

प्रबन्धित चलन के विम्बलितसित गुणों का संकेत किया जाता है —

(१) इसका प्रयोग देश में आर्थिक दशाओं पर प्रभाव डालने हेतु एक साधन के रूप में किया जा सकता है। यदि सरकार एक विशेष नीति (जैम—पूर्ण

रोजगार की नीति) का पालन करना चाहे तो वह उक्त नीति का इस बात की चिन्ता किये बिना कि अन्य देशों पर अथवा स्वदेश में ही करंसी के परिमाण और मूल्य पर इसके क्या प्रभाव होंगे पालन कर सकती है। वास्तव में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए सरकारें आवश्यक अन्य नीतियों के साथ ही साथ मौद्रिक नीति का भी प्रयोग करने लगी हैं।

(२) इसमें मौद्रिक स्वतन्त्रता रहती है—अर्थात् राष्ट्रवाद (Extreme nationalism) के वर्तमान युग में मौद्रिक स्वतन्त्रता का बहुत महत्त्व है और इसके कई आर्थिक लाभ भी हैं।

प्रबन्धित चलन के दोष—

प्रबन्धित चलन का सबसे बम्भोर दोष यह है कि इस पर शानक दल के राजनैतिक दृष्टिदोष का बहुरा असर पड़ता है। यद्यपि समस्त प्रबन्धित चलन की नीति के जिन नरवार के प्रभाव से स्वतन्त्र माना जाता है हाथ में होता है तथापि यह आशा नदी की आसनी कि मौद्रिक नीति राजनैतिक प्रभावों में मुक्त रह सकेगी। उदाहरण के लिए युद्धकाल में करंसी का विस्तार करने के लिए सरकारें प्रायः प्रलाभित हो जाया करती हैं। ऐसे करंसी विस्तारों के कारण ही बुदकने वाले मुद्रा प्रसार' (Galloping inflations) उभर ही गये थे, और इन्होंने समाज के सभी वर्गों को तबाह (ruin) कर दिया था। सभी प्रबन्धित चलन (managed currencies) में मुद्रा प्रसार का बीज छिपा होता है।

स्वयंमान की तुलना में श्रेष्ठता -

इस दोष के होने पर भी प्रबन्धित चलन स्वयंमान की तुलना में अधिक स्वीकार्य है क्योंकि (i) प्रबन्धित चलन अपेक्षित अधिक तीनपूर्ण होता है, जिसमें वह एक आधुनिक गतिशील देश की आवश्यकताओं का पूरा करने में अधिक समर्थ है (ii) नागरिकों के कल्याण की भावना से ओत-प्रोत एक आधुनिक सरकार प्रबन्धित चलन प्रणाली का पूरा रोजगार की प्राप्ति तथा निर्यन्त्रता के उन्मूलन के लिए प्रयोग कर सकती है, एवं (iii) एक बहु उल्लेखित दोष इतना खराब मुद्रा प्रसारिक (inflationary) होता है, किन्तु यह दोष वास्तविक सतरे का ओत तब ही बन पाता है जबकि इसका प्रयोग अविनेकी सरकार के हाथों में हो और अदिनकी सरकार के अन्तर्गत तो स्वयंमान भी सही उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह इसे कठिना-मौ, कठिनाई, उत्पन्न होने की स्थिति पर खड़ी है।

अतः हम एक प्रबन्धित चलन के पक्ष में हैं। साथ ही हमारा यह भी सुझाव है कि मौद्रिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बोप के तत्त्वानुधान में अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए।

प्रबन्धित चलन के अन्तर्गत विविधय दरो का निर्धारण

परिवर्तनशील पन चलनो के सपेक्षिक मूल्य खुले बाजार में माँग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होने हैं। "एक का दूसरे में मूल्य उसी प्रकार घटता बढ़ता रहता

है, जिस प्रकार कि साधारण वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती हैं। इनमें कोई नियत समताये (fixed parities) या स्वर्ण बिंदु (gold point) नहीं होते, और यदि भुगतान गतुल्य निष्क्रिय है, तो स्वर्ण का बहिर्गमन नहीं होगा, किन्तु करंसी का मूल्य ह्रास (depreciation) हो जायेगा। इनमें ऐसी कोई सीमा या निश्चित बिंदु नहीं है जहाँ कि मूल्य ह्रास रुक सकता हो जैसा कि स्वर्णमान करंसीयों के अन्तर्गत होता था। दूसरी ओर, यह भी सही है कि मूल्य ह्रास एक अनिश्चित समय तक नहीं चल सकता। हाँ, जब मुद्रा-प्रसार निरन्तर बढ़ रहा हो, तो बात दूसरी है। कारण, सापेक्षिक कीमत-परिवर्तन, जो आयातों को घटाने, निर्यातों को बढ़ाने तथा इस प्रकार साम्य की पुनर्स्थापना करने के लिए आवश्यक हैं तथा जो स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण के बहिर्गमन द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं, यहाँ विभिन्न दर के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं।¹ अब समस्या यह मान्य करना है कि कौन से सामान्य सिद्धान्त यह निश्चित करेंगे कि मूल्य में ह्रास किस सीमा तक हो सकता है।

भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त बनाम मुद्रा प्रसार सिद्धान्त—पुत्र-काल में, जबकि स्वर्णमान की देशों द्वारा एक-एक करके स्थिति किया गया करंसीयों के मूल्य ह्रास का प्रश्न व्यावहारिक राजनीति का प्रश्न बन गया और सम्पूर्ण जर्मनी में इस पर उग्र विवाद चढ़ने लगा। विदेशी करंसीयों में मार्क का तेजी से मूल्य ह्रास होने के दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये—(i) सरकारी दृष्टिकोण जिसकी भावना व्यापारवादी थी। यह भुगतान सन्तुलन की निष्क्रियता को दोषी ठहराता था एवं (ii) आलोचकों का दृष्टिकोण, जिसके अनुसार सब दोष मुद्रा प्रसार का ही था।

भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त (Balance of Payments Theory)

अपने सरल रूप में (in naive form) भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त यह कहता

- 1 "The value of one in terms of the other is subject to variations like the price of ordinary commodities. There are no fixed parities or gold points and a passive balance of payments will cause, not an outflow of gold, but a depreciation of the exchange. There is no fixed point at which depreciation will cease, corresponding to the gold export point—on the other hand, depreciation cannot go on indefinitely, except under a progressive inflation. For the relative price changes which are necessary to reduce imports, stimulate exports and restore equilibrium—and which under the gold standard are induced by the outflow of gold—are here produced by variations in the rate of exchange"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 30

है वि विनिमय दर भुगतान सन्तुलन (माँग एवं पूर्ति के अर्थ में) के द्वारा निर्धारित होती है। नि सन्देह इस सिद्धान्त के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है किन्तु प्रश्न तो यह है कि वे क्या चीजे हैं जो माँग और पूर्ति को निर्धारित करती हैं ?

परिष्कृत (refined) भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त इस अतिरिक्त प्रश्न का भी उत्तर देने का यत्न करता है। इसके अनुसार भुगतान सन्तुलन मुख्यतः उन घटकों द्वारा निर्धारित होता है जो कि विनिमय दर के परिवर्तनों से स्वतन्त्र हैं। निश्चित एवं नियत भुगतानों (जैसे वसति-पूर्ति एवं विदेशी ऋणों पर व्याज) के अतिरिक्त, अनेक आयातिक कच्चे माल के लिए माँग बेजोच होती है क्योंकि वे केवल विदेशों से ही प्राप्त हो सकते हैं।

मास्कोवना—उक्त सिद्धान्तों की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि इसमें भुगतान सन्तुलन का एक निश्चित मात्रा (fixed quantity) सुझा लिया है। कीन्स (Keynes) ने एक बहुत उपयुक्त उपाय देते हुए बताया है कि यह सिद्धान्त ठीक वस्तुओं के नियम को नहीं लागू करता है जहाँ कि इष्टियों का नियम अधिक उपयुक्त है। व्यापार सन्तुलन (एक कुछ अहम्य आयात निर्यात भी) देश और विदेशों के कीमत-स्तरों के सांख्यिक सम्बन्धों पर निर्भर है। आयातित खर्च पदार्थों के लिये माँग भी कुछ माँगा तक सीमबद्ध होती है। कारण, वही मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ या तो सस्ती वस्तुएँ (जैसे—रोटी और आलू) द्वारा अथवा महँगी वस्तुएँ (जैसे—मसि और फल) द्वारा सन्तुष्ट की जा सकती है। गश्प में, भुगतान सन्तुलन कुछ सीमा तक ही विनिमयी पर निर्भर है। अतः इसका प्रयोग इन्हे स्पष्ट करने हेतु नहीं किया जा सकता।

यह आपत्ति मुद्रा-प्रसार सम्प्रदाय (Inflation School) के विद्वानों द्वारा उठाई गई थी। उन्होंने बताया कि यदि करेंसी का परिमाण लगातार न बढ़ाया गया होता, तो मार्क के मूल्य में ह्रास कभी नहीं हो सकता था। यह तो आन्तरिक कीमतों की वृद्धि ही थी, जिसने आयातों के संकुचन और निर्यातों के विस्तार में बाधा डाली। अन्यथा, सापेक्षिक कीमती में परिवर्तन होकर साम्य की पुनः स्थापना हो सकती थी। यही बात सौ से अधिक वर्षों पूर्व रिकार्डों ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि—“जर्मनी में हुए ह्रास का सही माप विनिमय है।”¹ सन् १९१४ से १९२० तक जर्मनी में जैसी दया हुई वैसी ही इङ्ग्लैंड में नैपनिक्न-पुडों के समम में थी। बीसवीं शताब्दी ने इन घटनाओं के बारे में हमारा ज्ञान कुछ अधिक नहीं बढ़ाया है।

¹ “The exchange accurately measures the depreciation of the currency”

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त (The Purchasing Power Parity Theory)

यह दृष्टिकोण नि निम्निय म गिरावट के त्रिमे मुद्रा प्रसार दायो है, त्रय-
सन्निभमता सिद्धान्त पर आधारित है ।

त्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का प्रतिपादन जॉन व्हीटले ने मन् १८०२ में किया था । सन् १८१० म विनियम ब्लेक न इस स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया । रेविड रिफार्डों ने इसका पुनरुद्घन किया और स न म स्वीडन के अध्यक्षानी प्रो० कंसल की इसके विकास का श्रव मिला । इन्ग्लैंड ही इस सिद्धान्त को काय प्रणाली को सम्मान क निय 'त्रय शक्ति समता' वाक्यांश का प्रयोग किया था । इस सिद्धान्त क दो रूप हैं—पहला रूप, धनात्मक पक्ष (Positive aspect) जिसके अन्तर्गत दा अपरिवर्तन शील करैरिया के मध्य विनियम दर का निराकरण किया जाता है और, दूसरा रूप निम्निय दरा म होने का न उचार बनावा के कारणों य इनकी सीमाभा म मन्वधित है ।

क्रय शक्ति समता सिद्धान्त क्या है ?

प्रो० कंसल ने सिद्धान्त को व्याख्या निम्न प्रकार में की है—“जो देश आरिक्वनशीन पत्र मुद्रा मान अपनाय हू है उनके मध्य विनियम की वृत्तिपदी दर त्रय शक्ति समता द्वारा जो कि दा करैरियो के अपने अपन गृह बाजारों में क्रय शक्तिया के मध्य अनुपात का रूप म निघाारित होती है । किसी समय विशप पर विनियम की वास्तविक दर विरता करैरिया के लिय मीग और पून क प्रभावा के कारण, त्रय शक्ति समता म भिन्न हो सकती है किन्तु इसमें त्रय शक्ति समता बिहु क हद गिद महरान की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ समय तक महरान क बाध श्रन्तन यह इस समता पर ही स्थिर होत लगती है ।”

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

उक्त सिद्धान्त को एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिए कि मा दिव हूँ समय पर इङ्ग्लैंड म एक पीड द्वारा एक दी हुई वस्तु मूची म म प्रगक वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीदी जा सकती है और इही वस्तुओं की

- 1 In the case of countries on inconvertible paper currency standard the basic rate of exchange between them is determined by the purchasing power—the ratio between the purchasing powers of two currencies in their respective home markets. The actual rate of exchange at any time may move from the purchasing power parity due to influences of demand and supply for foreign currency but the purchasing power par is the point towards which the rate will constantly tend to move, and at which it must ultimately come to rest”—Cassel.

इतनी ही मात्रा में अमेरिका में ५ डालरों से खरीदी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में 'पीड र्टर्नित' और 'डालर' की त्रय-शक्ति इंग्लैंड में अमेरिका में एक समान होगी और इस समानता के अनुरूप ही विनिमय दर भी १ पाउंड = ५ डालर होगी। यदि किसी कारणवश विनिमय-बाजार में १ पाउंड का मूल्य ५.१० डालर हो जाय किन्तु दोनों करेंसियों की त्रय-शक्ति पूर्ववत् रहे तो इंग्लैंड-निवासी जो अमेरिका में वस्तुएं खरीदना वही वस्तुओं अपने देश में खरीदने की अपेक्षा लाभदायक हो जायगा क्योंकि १ पाउंड के बदले में ५.१० डालर प्राप्त करके और फिर इनमें से केवल ५ डालर व्यय करके उतनी ही वस्तुएं खरीदी जा सकती है जितनी कि इंग्लैंड में १ पाउंड से। इस प्रकार उन्ने लाभ के रूप में ०.१० डालर बच रहेंगे।¹ दूसरी ओर, अमेरिकावासी इंग्लैंड की अपेक्षा अपने ही देश में वस्तुएं खरीदना लाभदायक पायेंगे। इस प्रकार, 'अमेरिका में इंग्लैंड को' वस्तुओं का प्रवाह 'इंग्लैंड में अमेरिका को' वस्तुओं के प्रवाह की अपेक्षा बढ़ जायेगा। एतल डालरों की मांग बढ़ जायगी और पीड की मांग घट जायेगी और इस तरह विनिमय दर घटकर पुनः १ पाउंड = ५ डालर स्तर पर आ जाती है।

इसके विपरीत, यदि किसी कारण १ पाउंड का विनिमय मूल्य घटकर ४.६९ डालर रह जाय, (किन्तु करेंसियों की आन्तरिक त्रय-शक्ति पूर्ववत् बनी रहे) तो अमेरिकन को अपने देश की अपेक्षा इंग्लैंड में तथा इंग्लैंडवासियों को अमेरिका की अपेक्षा अपने ही देश में वस्तुओं खरीदना लाभदायक होगा। फलतः इंग्लैंड के आयात घट जायेंगे किन्तु निर्यात बढ़ जायेंगे। इसका प्रभाव पीड की मांग-पूर्ति पर पड़ेगा अर्थात् पीड की मांग बढ़ जायेगी और पूर्ति घट जायगी, अर्थात्, जो वही कि डालरों की पूर्ति बढ़ जायगी और मांग घट जायेगी। 'डालरों की मांग' की अपेक्षा 'पीड की मांग' बढ़ने से पीड का मूल्य बढ़ने लगेगा और अन्ततः विनिमय दर पुनः १ पाउंड = ५ डालर पर ही स्थिर हो जायगी। इस प्रकार दोनों करेंसियों के मध्य १ पाउंड = ५ डालर की दर का 'स्वाभाविक विनिमय दर' कहा जा सकता है।

हम यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। किसी देश (मान लीजिए A) के विनिमय बाजार में एक विदेशी करेंसी (b) की मांग इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि वह करेंसी (b) अपने कुछ बाजार (दिश B) में त्रय-शक्ति है। A देश के निवासी उस करेंसी (b) को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें B देश में खरीदी जाने वाली वस्तुओं का भुगतान उक्त करेंसी (b) में करना है। दूसरी ओर, जब एक निश्चित राशि में विदेशी करेंसी (b) के लिए स्वदेशी करेंसी (a) की निश्चित राशि देनी पड़ती है, तब दोगला मतलब यह है कि स्वदेशी (A) में इतनी त्रय-शक्ति B देश को दे दी गई है। स्पष्टतः वह विदेशी करेंसी (b) के त्रय का अर्थ

¹ Transport costs have been ignored.

है ॥ देश की क्रय-शक्ति के बदले A देश में क्रय-शक्ति देना । साम्य की स्थिति में विनिमय दर इन क्रय शक्तियों के अनुपात में हो होनी चाहिये ।

मान लीजिये, A देश की करेंसी (a) की वार्षिक क्रय-शक्ति X है जबकि B देश की करेंसी (b) की वार्षिक क्रय-शक्ति Y है । यदि A देश की करेंसी (a) की एक इकाई के बदले में B देश की करेंसी (b) की $\frac{1}{r}$ इकाईयाँ उपलब्ध हैं, अर्थात् यदि विनिमय दर $a=rY$ (b), तो B देश में A देश की करेंसी (a) की क्रय शक्ति rY होगी ।

चूँकि साम्य की अवस्था में A देश की करेंसी (a) की वार्षिक एय बाह्य क्रय-शक्ति एक समान होती है, इसलिये $X=rY$, अतः $r=X/Y$ इसने भी यह प्रगट होता है कि विनिमय दर दो करेंसियों की क्रय-शक्तियों का अनुपात होती है ।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त हमें दो देशों के मध्य, जो कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Inconvertible paper currency) अपनाये हुये हैं, विनिमय-दरों में होने वाले परिवर्तनों का स्वयंस्वरूप प्रदान करता है । किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार की सामान्य वृद्धियों के अनुरूप ही एक उपयुक्त विनिमय-दर प्रचलित हो जाती है और 'क्रय शक्ति समता' के बराबर रहती है । कुछ छोटे-मोटे उतार-चढ़ावों को छोड़ कर, वह प्रायः अपरिवर्तित ही रहती है तथा सब बदलती है जबकि दोनों करेंसियों की क्रय शक्तियों में परिवर्तन हो जाय । यदि किसी भी करेंसी की क्रय शक्ति में परिवर्तन हो जाय तो इसका अन्तर सम्बद्ध देशों के मध्य विनिमय-दर पर भी पड़ता है, अर्थात्, अन्य करेंसियों के सम्बन्ध में स्वदेशी करेंसी का बाह्य मूल्य उसी अनुपात में बदल जायगा ।

क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनाएँ तथा सीमाएँ—

वास्तविक विनिमय दरें क्रय शक्ति समताओं के आधार पर गणना की गई विनिमय दरों में प्रायः भिन्न हुआ करती हैं । कुछ विद्वान इन भिन्नताओं के आधार पर ही क्रय शक्ति समता सिद्धान्त की अस्वीकार करते हैं । ऐसी भिन्नताएँ निम्न कारणों से हो सकती हैं —

(१) सूचक अंकों की गूँठियाँ एवं विभिन्न देशों में इनका विभिन्न होना— विनिमय दर दो देशों में इनके कीमत सूचकांकों की तुलना पर आधारित होती है । किन्तु विभिन्न देशों में निर्देशांक तुलना के योग्य नहीं होते । कारण, इनकी रचना भिन्न भिन्न साधारण वर्गों के सम्बन्ध में की जाती है । प्रतिनिधि वस्तुएँ, इन्हें दिये गये भार (weights) तथा औसत निकालने के ढंग भी देश में भिन्न-भिन्न होते हैं । अतः ऐसे निर्देशांकों की पारस्परिक तुलना करने से वास्तविक क्रय शक्ति समता का पता नहीं चल पाता ।

(२) निर्देशांकों में घास्तविक व्यापार की वस्तुएँ सम्मिलित करना— आन्तरिक कीमतों के सूचकांक उन वस्तुओं की कीमतें लेकर बनाये जाते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश नहीं करती । ऐसी वस्तुएँ (domestically

traded goods) विदेशी विनिमय सौदो को जन्म नहीं देती है। अतः सम्भव है कि एक देश के कीमत सूचकांक में परिवर्तन पूर्णतः उन परिवर्तनों के कारण हो जाय जो कि आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं की कीमतों में हुये हैं, भले ही ऐसे परिवर्तन में विनिमय बाजार में करैसियों की माँग और पूर्ति अप्रभावित रहें। निःसन्देह किसी देश को ऐसे असम्बद्ध क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनमें एक क्षेत्र का कीमत स्तर दूसरे क्षेत्रों के कीमत-स्तरों पर कोई प्रभाव न डाले। अन्य शब्दों में आन्तरिक व्यापार वाली वस्तुओं की कीमतों में, होने वाला परिवर्तन सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर फैल सकता है और इस प्रकार वह अन्तर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसा सब ही सम्भव है जबकि उपस्ति-साधन विभिन्न स्रोतों के मध्य गतिशील (mobile) हों। पूर्ण व्यावहारिक जीवन में ऐसी गतिशीलता अनुपस्थित होती है इसलिए किसी देश में आन्तरिक व्यापार की वस्तुओं की कीमतों में हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप जो परिवर्तन कीमतों—निर्देशांक में होता है वह गणना की गई क्रय शक्ति समता से, वास्तविक विनिमय दर को बहुत प्रभावित किये बिना ही, परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इससे वास्तविक विनिमय दर गणना की हुई क्रय-शक्ति समता में भिन्न हो जाती है।

(३) विदेशी विनिमय सम्बन्धी माँग और पूर्ति पर घटबूट का प्रभाव—विनिमय बाजार में करैसिया की दीर्घकालीन माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ केवल कीमत परिवर्तनों में ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि अन्य घटकों से भी प्रभावित होती है, जैसे—एक देश में दूसरे देश को जाँपो का आयापन, सरकारों की परस्पर सृष्टि प्रवृत्ति, एवं सद्भाव व्यवहार। ये सभी घटक विनिमय बाजार में माँग-पूर्ति सम्बन्धी दशाओं को बदल देते हैं चाहे भंग्यत्व में परिवर्तन हुये हों या नहीं। इन प्रकार यद्यपि क्रय शक्ति समता पूर्ववत् रहती है तथापि दीर्घकालीन माँग के मध्य वास्तविक विनिमय दर उक्त एक या अधिक घटकों में हुए परिवर्तनों के कारण, भिन्न हो सकती है।

(४) सरक्षण करो, कोटा और अन्य प्रतिबंधों द्वारा व्यापार में हस्तक्षेप—वस्तुओं के व्यापार में एक दिशा की अपेक्षा दूसरी दिशा में अधिक हस्तक्षेप हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश अपने आयातों पर सरक्षण कर (Tariff duties) लगा दे, जहाँ अन्य देश ऐसा न करें, तो इसकी अपनी करैसी के लिए माँग अपरिवर्तित रहेगी किन्तु विदेशी करैसी के लिए माँग घट जायगी। सरक्षण-कर लगाने वाला देश की करैसी के मुख्य का पता बड़े नग पायेगा।

(५) यह कहना असत्य है कि विनिमय दर सम्बन्धी परिवर्तन कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं डालते—क्रय शक्ति सिद्धान्त इस बात पर बल देता है कि कीमत स्तर सम्बन्धी परिवर्तन विनिमय-दरों में तो परिवर्तन ला देते हैं किन्तु विनिमय दर के परिवर्तनों का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्तु यह बल सदा ही सत्य नहीं है। ऐसी अनेक परिस्थितियाँ का उल्लेख किया जा सकता है, जिनमें

विनिमय दर पहले कुछ कारणा से परिवर्तित हो गई और फिर इसने कीमन स्तरा में भी परिवर्तन ला दिया। मान लीजिए, रुपये की विनिमय दर २० सेंट है अथवा ५ रुपये एक डालर के बराबर है। मान लीजिए कि अमेरिका से भारत को पूँजा के आगमन के फलस्वरूप रुपयों की माँग बढ़ जाती है, जिससे विनिमय दर रुपये के पक्ष में ऊँची उठ जाती है अथवा वह प्रति रुपया २५ सेंट हो जाती है। ऐसी दशा में अमेरिकियों के लिए भारतीय करेंसी और (इसलिए) भारतीय वस्तुएँ भी महँगी पड़ेंगी। अतः भारतीय निर्यात कम हो जायेंगे। चूँकि निर्यात कम हो गये हैं, इसलिए देश में वस्तुओं की माँग घटने और (इसलिए) सप्लाई होने के कारण (प्रति रुपया २० सेंट के बजाय २५ सेंट), भारतीयों के लिये अमेरिकन मान सरता पड़ने लगता है। परिणामतः अमेरिकन वस्तुओं के लिये भारतीय माँग अमेरिकन कीमतों का बढ़ाती हुई चलेगी। इस तरह, हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कीमत स्तर विनिमय दर सम्बन्धों पर परिवर्तनों का अनुसरण करता है।

(६) एक उपयुक्त सूचना के चुनाव में कठिनाई—पूर्विक सामान्य कीमतों के निर्देशांक काम में लाने जाने हैं इसलिए यह समस्या उत्पत्ती है कि कौन सा निर्देशांक लिया जाय। क्या यह थोक बिक्रय कीमत सूचनाक हो या कृषि एवं कच्चे मालों का सूचनाक या रहन महन लागत का सूचनाक हो। यदि हम थोक सूचनाक को चुनें, तो अनेक अल्प वस्तुएँ तथा प्रायः सभी सेवाएँ विचार में नहीं आ सकेंगी। यदि हम रहन सहन लागत के सूचनाक का चयन करें, तो इसमें अनेक ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हो जायेंगी जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

(७) फंडान एवं आग तरों में परिवर्तन—ऐसे परिवर्तनों के कारण विनिमय दर अस्त-व्यस्त हो जाती है। किन्तु अल्प-शक्ति समष्टि सिद्धान्त इन परिवर्तनों पर कोई ध्यान नहीं देता है।

(८) एक गतिशील संचार के सम्बन्ध में सिद्धान्त की अनुपयुक्तता—यह सिद्धान्त सब ही बंध हो सकता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की दशाएँ अपरिवर्तित रहें। लेकिन प्राथमिक संचार में यह दशाएँ (अर्थात् विदेशी वस्तुओं के लिए माँग अथवा आन्तरिक वस्तुओं की पूर्ति) प्रायः बदलती रहती है और इनके साथ ही साथ व्यापार की शर्तों में परिवर्तन होता रहता है।

(९) वह सिद्धान्त निरपेक्ष कीमत-स्तरों की लागू नहीं होता—यह सिद्धान्त कीमत स्तरों के परिवर्तनों को ही लागू होता है निरपेक्ष कीमत-स्तरों को नहीं। प्रो० वैनन के शब्दों में 'इसका कारण यह है कि दोनों देशों की आर्थिक परिस्थिति में, निर्यात निर्यात यातायात और कस्टम के बारे में भेद होता है। यह

भित्तियाँ सामान्य विनिमय-दर में करेंसियों की निहित क्रय-शक्तियों के अनुपात की तुलना में कुछ विचलन (deviations) ला देती है।¹

(१०) **यातायात-व्ययों की उपेक्षा**—क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त यातायात व्ययों की उपेक्षा करता है। लेकिन प्रो० जेकब वाइनर ने बताया है कि यदि यातायात व्यय एक दिशा में बढ़ जायें और दूसरी दिशा में कम हो जायें, तो वस्तुओं की कीमतें भी एक देश में बढ़ जायेंगी और दूसरे में घट जायेंगी। किन्तु केवल एक दिशा में ऐसी बाधाएँ पड़ने से क्या शक्ति समता अस्त-व्यस्त हो जाती है।

(११) **दो देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों के परिवर्तनों की उपेक्षा**—क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त दो देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों में समय-समय पर होते रहने वाले आर्थिक परिवर्तनों को विचार में नहीं लेता, यद्यपि ऐसे परिवर्तनों के कारण उनकी साम्य दर (Equilibrium rate) में परिवर्तन हो जाता करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई तीसरा देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतियोगी बनकर प्रकट होता है, तो दोनों मूल देशों के मध्य व्यापार के प्रवाह पर असर पड़ता है तथा इनके मध्य विनिमय-दर भी बदल जाती है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त—एक तुलना

प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने विनिमय-दरों का विश्लेषण तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (Comparative Cost Principle) के आधार पर किया। इसने एक समय पर दो देशों और दो वस्तुओं पर ही विचार किया और यह माना कि लागत के जितने तत्व पर विचार करना चाहिए वह केवल थम लागत ही है। इसने यह भी कल्पना की थी कि सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्र में 'उत्पत्ति स्थिर निम्न' (Law of Constant Returns) ही लागू हो रहा है। इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने एक अति सरल (simplified) परिस्थिति चुन ली थी जो कि व्यावहारिक विश्व में अनुपलब्ध है। वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक देश और अनेक वस्तुएँ एक ही साथ व एक ही समय में प्रविष्ट होती हैं तथा कई प्रकार की करेंसियों में सामना करना पड़ता है। यही नहीं, विभिन्न देशों के उत्पत्ति साधन सम्बन्धी भन्धार भी भिन्न-भिन्न होते हैं। और उनके आर्थिक विकास के स्तरों (stages of economic development) में बहुत भिन्नता पाई जाती है।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त ऐसी व्ययें कल्पनाएँ नहीं करता, और यही कारण है कि इसे प्रतिष्ठित विद्वानों के स्पष्टीकरण पर एक मुधार माना गया है। इसने एक देश की करेंसी में दूसरे देश की करेंसी के मूल्य निर्धारण की समस्या को

¹ "Differences in the two countries' economic situation, particularly in regard to export, transport and customs, cause the normal exchange rate to deviate to a certain extent from the quotient of the currencies intrinsic purchasing powers"

सामान्य किंमत सिद्धान्त (General Theory of Pricing) का ही एक अङ्ग बना दिया है।

विनिमय-दरों के निर्धारण में क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का व्यावहारिक मार्ग दर्शन

दीप हमें हृथ भी त्रय शक्ति समता सिद्धान्त समी मौद्रिक दगाओं के अनन्त विनिमय दरों में होने वाले दीर्घकालीन (Long term) परिवर्तनों का एक माध विषय पुक्त स्पष्टीकरण है। सम्मद्ध देशों में कीमतों के परिवर्तन हो जाने पर करैन्सियों का मूल्य भी घटता बढ़ता है। यह कहना केवल अपूर्ण (superficial) है कि प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तन ऋणता मन्तुलन (Balance of Indebtedness) में परिवर्तन होने के कारण होने है। त्रय शक्ति समता इसत भी आगे बढ़कर यह स्पष्ट करती है कि स्वयं भुगतान मन्तुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है। यह दिसलाती है कि देशों के मध्य व्यापार और भुगतान मुख्यत उनके सापेक्षिक कीमत-स्तरी के परिवर्तनों के कारण घटो-बढ़ते हैं। अतः दीर्घकालीन में विनिमय दर कीमतों और कीमत परिवर्तनों पर निर्भर होती है।

त्रय-शक्ति सिद्धान्त की वैधता (validity) का अनुमान निम्नलिखित वास्तविक उदाहरणों से लगाया जा सकता है —

(१) वर्ष १९२५ में इङ्गलैण्ड ने स्वर्णमान (Gold Standard) पुन अपनाया और अपने पीछ की स्वर्ण समता स्वाभाविक दर से काफी ऊँची निमत की जिससे कि पीछ अधिक मूल्यित (over valued) हो गया। इसका फल यह हुआ कि इङ्गलैण्ड में कीमतें और लागनें निम्न स्तर की अपक्षा वही अधिक बढ़ गई। परिणामतः भुगतान तुला उसके बरत प्रतिकूल हो गई। यहाँ से स्वर्ण का निर्यात होने लगा। इस प्रवृत्ति को निप्रभावित ((counteract) करने के लिए अधिकारियों ने विदेशों में भारी ऋण लेन गुरु किये। लेकिन ऐसा करना भी उक्त ज्वार (tide) को न रोक सका। आन्तरिक स्वर्ण के निर्यात पर रोक लगाई गई। ऐसा करने से चूँकि स्वर्ण निर्यात बिन्दु (gold export point) निष्क्रिय (unoperative) हो गया इसलिए पीछ का मूल्य फिरने लगा और शीघ्र ही यह अपने स्वाभाविक स्तर पर जो कि सामाजिक कीमत-स्तरी के अनुदण हुआ करता है पहुँच गया।

(२) द्वितीय महायुद्ध की अवधि में डालर स्टैबिलि और रुपया-डालर दरें त्रय शक्ति समता में बहुत स्थिर हो गई थी और इन दरों को विनिमय निप-रण के द्वारा कृत्रिम स्तरों (artificial levels) पर स्थिर रखा गया था। चूँकि डालर की तुलना में स्टैबिलि, रुपया व अन्य करैन्सी सय। अधिकमूल्यित थी, इसलिए सम्मद्ध देशों को अपने भुगतान मन्तुलन में बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही थी। इन कठिनाइयों के निवारण के निम्ने, यह आवश्यक था कि या तो सम्मद्ध देशों में कीमतें और लागनें घटाने पर त्रय शक्ति समता (policies) को बढ़ाया जाय, अथवा, नियन्त्रित दरों (court called rates) को तो फलने हूय उक्त वास्तविक समताओं के स्तर पर ल

थाया जाय। व्यवहार में दूसरा तरीका ही अपनाया गया था, अर्थात् दूजलैण्ड, भारत व अन्य देशों ने अपनी करेंसियों का बाहर-मूल्य घटाकर नियन्त्रित दरो व स्वाभाविक दरो में समानता स्थापित की।

त्रय शक्ति समता सिद्धान्त अस्थिर और परिवर्तनशील विनिमय-दरों के युग में मोटे रूप में उस सीमा का मापक (measure) है, जिसके भीतर वास्तविक दरें माप्य दर में भिन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, विनिमय दरों में स्थायित्व लाने के हेतु त्रय शक्ति समता की गणना करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अपनाई जान वाली दरों के औचित्य का निर्णय त्रय शक्ति समता के सदर्थ में ही किया जा सकता है।

त्रय-शक्ति समता और टकसाली समता

त्रय शक्ति समता का प्रयोग प्रायः अपरिवर्तनशील करेंसियों के मध्य विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु किया जाता है। लेकिन वैसे यह किसी भी मोद्रिक परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। अर्थात्, यदि दो देश स्वर्णमान पर हैं, अथवा रणतमान या पत्र मान पर, तो भी यह सिद्धान्त हम बात को, कि विनिमय दर किसी विशेष स्तर पर ही क्यों निर्धारित होती है, स्पष्ट करते में समर्थ है। तब तो यह है कि 'विनिमय की टकसाली समता' (parity of exchange) भी स्वर्ण में व्यक्त की गई एक विशेष प्रकार की त्रय शक्ति समता ही है। स्वर्णमान के अधीन, दो देशों में कीमतें स्वर्ण में निर्धारित की जाती हैं और कदमी की स्वर्ण-समता हमकी त्रय-शक्ति का सूचक होती है। अतः, टकसाली समता ही दो करेंसियों के मध्य त्रय शक्ति समता भी होती है।

जिग दिनों विश्व में स्वर्णमान प्रचलित था, घटना कम त्रय-शक्ति समता की तरह में ही चला। अर्थात्, स्वर्णमान के अधीन भी कीमतें विभिन्न देशों के मध्य समानता की प्रवृत्ति दिखलक्षी है। यदि किसी देश की स्वर्ण का अभाव अनुभव हुआ और इससे उसके मुद्रा चलन की अपर्याप्तता के कारण कीमतों में गिरावट आई, तो सम्बद्ध कदमी की त्रय शक्ति अपने मूल स्तर पर लौटने की प्रवृत्ति दिखलाती थी। कारण विचाराधीन देश में कीमतें गिरने से इसके निर्यातों की प्रोत्साहन मिलता है तथा अन्य करेंसियों का सापेक्षिक अति मूल्यांकन (relative over valuation) इसके आयातों को हतोत्साहित करता है। ऐसा होने से धीरे-धीरे एक 'अनुकूल ध्यानार सन्तुलन' ((favourable balance of trade) का उदय होने लगता है। आयातों की अपेक्षा निर्यातों का यह आधिक्य प्रायः स्वर्ण में चुम्बित किया जाता है। अतः अनुकूल ध्यानार सन्तुलन वाला देश स्वर्ण प्राप्त करेगा। इस प्रकार, उसके स्वत्वे (possession) में स्वर्ण की मात्रा बढ़ जायेगी, और, चूंकि स्वर्ण की कीमतें बढ़ने में गुप्त-परिमाण बढ़ जाता है इसलिए वहाँ कीमतों में पुनः वृद्धि होने लगेगी। दूसरी ओर, उस देश में, जिसमें स्वर्ण खोया है, मुद्रा-परिमाण घटने से कीमतें गिरने लगेगी। इस प्रकार कीमत समता पुनः स्थापित हो जाती है।

दो स्वर्णमान देशों के मध्य 'टकसाली समता' और दो अपरिवर्तनीय पत्र करेंसियों वाले देशों के मध्य 'त्रय शक्ति समता' में एक स्पष्ट भेद यह है कि जबकि टकसाली समता एक 'स्थिर समता' (Fixed par) है तब त्रय शक्ति समता 'चल समता' (Moving par) है। दूसरे, स्वर्णमान के अधीन वास्तविक दर स्वर्ण-विन्दुओं के मध्य ही परिवर्तित होती रहती है, किन्तु जब देश अपरिवर्तनीय पत्र मान पर है, तो विनिमय दरों के घटने-बढ़ने की कोई सीमाएँ नहीं होती हैं। कारण, इस परिस्थिति में स्वर्ण के आनागमन तो होने नहीं जो कि उत्सार-मटावों की सीमा त कर दें।

अब टकसाली समता एक भ्रमनाय की चीज बन गई है, क्योंकि सम्पूर्ण विश्व में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया है। फिर, 'टकसाली समता' तब ही लागू होती है जबकि स्वर्ण का आयात और निर्यात स्वतन्त्रता पूर्वक हो, लेकिन न केवल स्वर्णमान आज प्रचलित नहीं है, वरन् स्वर्ण के आयात-निर्यात पर भी प्रतिबन्ध लागू हुये हैं। अतः विदेशी विनिमय का टकसाली समता निश्चिन्त अब पहले जितना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है।

फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह पुर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि यह विनिमय दरों की स्थिरता पर अधिक ध्यान देता है, जबकि त्रय-शक्ति समता के अधीन विनिमय दरों के स्थायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने विनिमय दरों के स्थायित्व पर समुचित ध्यान दिया है और हम हेतु यह सब सदस्य देशों ने यह आशा करता है कि वे अपनी-अपनी करेंसिया का मूल्य स्वर्ण के रूप में घोषित कर देंगे। प्रायः सभी सदस्यों ने ऐसा कर भी दिया है। अब घोषित स्वर्ण मूल्यों के आधार पर किसी भी करेंसियों की विनिमय दर ताल करना बहुत सरल है। इस निश्चित दर से विनिमय दर के परिवर्तन के लिये वह विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति देता है।

लोचदार एवं स्थिर विनिमय दरों के गुण-दोष

विनिमय दरों में स्थायित्व (stability) रखना सभी समयों में सभी देशों का एक वाछनीय उद्देश्य रहा है। सन् १९२०—३० की अवधि में विनिमय दरों में जब सब परिवर्तन होते रहे थे, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन (competitive devaluation) का बड़ाका मिला और विदेश व्यापार के लिये इसके परिणाम बुरे हुये। विश्व व्यापार की मात्रा, रचना और दिशा (direction) सभी पर प्रतिबुद्ध प्रभाव हुआ। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के चरण में भी राष्ट्रों को यह भय रहने लगा था कि ऐसी ही स्थिति युद्ध के बाद फिर उत्पन्न हो जायेगी। अतः पुनरावृत्ति रोकने के लिये उनके हृदय में जो उत्कट इच्छा थी उसने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के तत्त्वावधान में मगठित होने के लिए प्रेरित किया। जब से यह स्थापित हुआ है, वह विनिमय स्थायित्व के लिये तथा सभी विनिमय नियन्त्रणों को हटवाने के लिये यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा है।

लेकिन अनेक सदस्य देशों के लिये कुछ कारणों से जैसा विनिमय-स्थायित्व बनाये रखना सम्भव नहीं हुआ जैसा कि मुद्रा कोष के मविधान में आवश्यक बताया गया है और उन्हें अपनी विनिमय दरों में समय-समय पर परिवर्तन करने पड़े हैं। किन्तु ऐसा परिवर्तन प्रायः कोष के परामर्श से और इसकी पूर्वं अनुमति से ही किया गया है। सन् १९४६ में २२ देशों ने सहसा ही एक साथ अवमूल्यन का जो कदम उठाया, उससे प्रभावित होकर प्रेक्षकों (observers) ने यह मत प्रगट करना आरम्भ किया कि नरन्मियों के मध्य नियत विनिमय दरें कायम रखना अवम्भव है। आधुनिक वर्षों में भी ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि 'समायोजनीय विनिमय दरों' (adjustable exchange rates) अथवा स्थायी दरों (stable rates) की प्रणाली को वांछनीय नहीं समझते तथा 'स्वतन्त्र' (free) अथवा 'उत्सार-बन्धन' वाली (fluctuating) विनिमय दरों को अधिक उपयोगी बनाते हैं। हमें इस वाद-विवाद में कोई मत प्रकट करने से पूर्व दोनों प्रकार की विनिमय दरों के गुण-दोषों का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये।

स्थायी दर रखने के पक्ष में—

स्थायी विनिमय दरों के पक्ष में निम्नलिखित सात बातें बताये जाते हैं —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा—यदि विनिमय दरें स्थायी रहें, तो विदेशियों को और जो लोग उन्हें सात बेचा करते हैं उन्हें भी यह माहूम करने में, कि अपनी देशी नरन्मियों के हितों से उन्हें कितना भिन्नता या कितना ठेका पड़ेगा, कोई बड़बुदाई न होगी। प्रान्ति या भुगतान की राशि निश्चित होने से विश्व व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। यह तेजी से तथा अधिक परिमाण से होने लगता है।

(२) विकास योजनाओं की श्रुति में सह्यता—विकास योजनाओं की प्रगति में विनिमय दरों की स्थिरता से बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विदेशों से विकास पूँजी मिलना सुगम हो जाता है।

(३) विदेशी व्यापार पर निर्भरता वाली अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयुक्त—विनिमय दरों का स्थायीकरण उन देशों के लिये, जिनकी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है (जैसे कि इंग्लैंड या डेन्मार्क), एकमात्र विवेक संगत नीति कही जाती है। जितना कम वे इस नीति से हटेंगे उतना ही उनके लिये अच्छा होगा, क्योंकि यदि वे नीति में बारम्बार हटते हैं तो उनका विदेशी व्यापार अस्त-व्यस्त होने लगेगा तथा ऐसा देखे में देख कर, अन्तर्राष्ट्रिय समृद्धि भी कुदभावित हो जायेगी।

(४) पूँजी की 'बौड़' के विरुद्ध सुरक्षा—विदेशी पूँजी पर निर्भरता वाले देशों को तो निश्चय ही नीमत पर विनिमय दर के स्थायित्व में विघ्न नहीं पड़ने देना चाहिये, क्योंकि विश्व के प्रमुख दलों के मॉड्रिक मान जब तक उचित रूप में स्थिर रहने हैं, वे अपनी करीबी का मूल्य उनकी करीबी के सन्दर्भ में अपरिवर्तित रख कर 'पूँजी दो दाँड़' के विरुद्ध सुरक्षित हो जाते हैं।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए श्राव-
दस्त्र—जब विदेशी विनिमय दरें साक्षात्कार रूप में घटती-बढ़ती हैं, तो विनिर्मातागण
विनिमय दरों के प्रतिबल परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली हानियों के भय में
विदेशी देशों को उधार देने में संवदते हैं। मौद्रिक उचितता को देखते से पता चलता
है कि जब तक स्वर्णमान के अधीन स्थायी विनिमय दर प्रणाली विद्यमान रही, अन्-
तर्राष्ट्रीय-मूल लेन-देन सहज गति में सम्पन्न होते रहे, लेकिन स्वर्णमान का खण्डन
होने ही, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय ह्रास (exchange depreciation) प्रारम्भ हो
गया और मूलों के लेन-देन में बाधा पड़ने लगी।

(६) मौद्रिक पुटों वाले विश्व के लिए उपयुक्त—एक स्थायी विनिमय दर
एक करेंसी-क्षेत्र (जैसे कि ग्रेट ब्रिटिश एरिया) वाले विश्व के लिये बहुत ही उपयुक्त
होती है। यदि एक महत्वपूर्ण देश (जैसे कि इंग्लैंड) जिसको करेंसी उस क्षेत्र की
एक प्रमुख (major) करेंसी है, अपनी विनिमय दर को घटने बढ़ने के लिए, छोड़
देता है, तो इसका न केवल उसकी करेंसी पर बल्कि अन्य सम्बद्ध करेंसियों पर भी
प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार सभी देशों के लिए अनेक अहित समस्याएँ उत्पन्न हो
जायँगी।

(७) लड़ा जलित कुप्रभावों में कमी होगा—पिछला अनुभव यह बताता है
कि विनिमय दरें पूँजी के विशाल (large) हस्तांतरों से बहुत प्रभावित होती हैं।
अन सम्बद्ध देश यह पसन्द करते हैं कि अपनी विनिमय दरों में इस प्रकार में
समायोजन कर लें कि लड़ा व्यवहारों के द्वारा उन्हें कम से कम हानि हो।

नि सन्देह, कोई भी देश वही विनिमय दर अनेक वर्षों तक कायम नहीं रख
सकता। यदि किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में कोई मौद्रिक परिवर्तन (Funda-
mental change) हो जाय (क्याकि आन्तरिक अथवा बाह्य परिस्थितियाँ बहुत
बदल गई हैं), तो परम्परागत विनिमय दर अनुपयुक्त हो जाती है और वह देश इसे
बदलने के लिए विवश हो जाता है। ऐसे अनिवार्य परिवर्तनों की सम्भावना की भुल
कोप में भी स्वीकार किया है तथा उसके विधान में इसके बिना छूट भी दी गई है।

स्वतन्त्र विनिमय दर के पक्ष में (The case for a free Exchange Rate)—
लोचदार या स्वतन्त्र विनिमय दरों के पक्ष वात तर्क प्रायः उन तर्कों के
समूह के रूप में हैं जो कि स्थिर विनिमय दर के पक्ष में दिए गए हैं।

(१) लोचदार विनिमय दरों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना विकास
नहीं जितना कि स्थिर विनिमय दर से—महापुञ्जों के बीच की अवधिओं अथवा
युद्धोत्तर अवधिओं के इतिहास से हम बात का प्रमाण नहीं मिलता कि स्थिर विनिमय
दरों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ पहुँचाया हो। जब तक व्यापारियों की प्रवृत्ति
विनिमय दरों में तथा इन्हें कायम रखने में सरकारों की क्षमताओं में विश्वास है, उन्हें
कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन सम्भव है कि व्यापारियों की महीनो तक अनिश्चित
दशा में रहना पड़े तथा पुनर्मूल्यन (Revaluation) की, जो किया भी जा सकता है

और नहीं भी, प्रतीक्षा करनी पड़े। इसके अतिरिक्त, यदि पुनर्मूल्यन के समय का अनुमान लगाना सम्भव ही, तो भी यह परिवर्तन जिनका होगा उसका अनुमान लगाना पदापि सम्भव नहीं है। अतः परिवर्तन के बारे में अनिश्चितता के कारण व्यापार और भुगतान अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। इसके विपरीत, स्वतन्त्र विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत, विनिमय दर की भावी प्रवृत्ति (future trend) का अनुमान लगाना प्रायः सम्भव होता है। जैसे, जबकि सम्बद्ध देश का भुगतान समुलन साम्यावस्था (equilibrium) में है, तो विनिमय दर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, और, जब वह असाम्य की अवस्था में है, तब बाजार के हल का अनुमान लगाया जा सकेगा। यही नहीं, अग्रिम विनिमय बाजार (forward exchange markets) भी जायातकों और निर्यातकों की संरक्षण दे सकते हैं। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोकदार विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इतनी हानिप्रद नहीं हैं जितनी कि स्थिर विनिमय दरें।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहारों पर लाभदायक प्रभाव—स्थायी विनिमय दरों के समर्थक प्रायः इस बात पर बल देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थायित्व बाध्यकारी है। किन्तु, यह एक प्रगट रहस्य (open secret) है कि ऋणदाता या ऋणी कोई भी यह धावा नहीं करता कि प्रचलित दर ही दशावधियों तक चलेगी अतः यह अस्म्भावित (not probable) है कि ऋण लेने देने के निर्णयों पर स्थिर विनिमय दर का तो अनुकूल प्रभाव पड़े किन्तु लोचदार विनिमय दर का प्रतिकूल। यही नहीं, बल्कि समुलन को समायोजित करने तथा भुगतान समुलन सम्बन्धी सक्लों की रोकने में लोचदार दरें स्थिर दरों की अपेक्षा अधिक उपयोगी हो सकती हैं। अतः यह कह सकते हैं कि लोचयुक्त विनिमय दरें अन्तर्राष्ट्रीय ऋण व्यवहारों पर अच्छा प्रभाव डालती हैं।

(३) करेंसी गुटों में दुर्बलता नहीं—जिसी करेंसी शक्ति का अस्तित्व स्थिर विनिमय दरों पर ही निर्भर हो ऐसा नहीं है। जहाँ तक स्टलिण गुट का सम्बन्ध है, वह एक विशेष प्रकार का क्षेत्रीय भुगतान समूह (Regional Payment Group) है, जिसका डींचा सन् १९२०-३० की अवधि में, जबकि स्टलिण बाजार परिस्थितियों के अनुसार घटने-बढ़ने के लिए स्वतन्त्र था तैयार किया गया था। यथार्थ में, विभिन्न देशों की किसी विशेष वर्गीय ब्लॉक से बंधने वाले कारण राजनैतिक व सामाजिक होते हैं। अतः गुट के प्रमुख देश को, अन्य सदस्य देशों से पूर्ण परामर्श करने के पश्चात् करेंसी के मूल्य में परिवर्तन करने दिया जाय, तो इससे गुट कमजोर नहीं पड़ेगा।

इस प्रकार स्थिर विनिमय के पक्ष में ज्ञात योग्य कि स्वतन्त्र विनिमय प्रणाली के विरोध में दिए जाने वाले कुछ प्रचलित तर्क (stock arguments) वास्तव में उतने महत्वपूर्ण नहीं जितने कि ऊपर से दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थिर विनिमय दरों के विरोध में कुछ ऐसे तर्क हैं जिनसे लोचदार विनिमय दरों का पक्ष अधिक सुदृढ़ बनता है। ये तर्क निम्नलिखित हैं—

(i) स्थिर विनिमय दरें सट्टे को प्रोत्साहित करती हैं। यदि जनता को यह आशंका हो जाये कि करेंसी का अवमूल्यन (devaluation) किया जाने वाला है, तो सरकार के लिए किसी भी दर को बनाये रखना कठिन हो जाता है क्योंकि यह गिरती ही चली जाती है। परिणामतः विनिमय-नियन्त्रण होने पर भी करेंसी का स्थायित्व खतरे में पड़ जाता है।

(ii) स्थिर दर देशों के मध्य प्रचलित वारतविक लागत-कीमत सम्बन्ध को नहीं दिखाती है वरन् वह सम्बन्ध को दिखाती है जो कि पहले कभी विद्यमान रह चुका है। वास्तव में लागत-कीमत सम्बन्ध प्रायः परिवर्तित होते रहते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों द्वारा विभिन्न आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया जाता है।

(iii) स्थिर दरें एक देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूसरे देश पर विस्तृत कर देती हैं। उदाहरणार्थ, डानर के साथ स्टर्लिंग का कठोर गजबन्धन होने के कारण ही मन् १९५५ के बाद पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ अधिक हो गई थीं।

निरूपण— किसी न किसी प्रकार का स्थायित्व अति आवश्यक है।

उपरोक्त मंडान्तिक तर्क, पिछली दो शताब्दियों का अनुभव और मुद्रा कोष को विभिन्न दरों के स्वाई रखने में अपर्याप्त सफलता मिलना ये सब बातें होने इन निष्कर्ष पर पहुँचाती हैं कि स्थिर दरों के स्थान में स्वतन्त्रतापूर्वक घटने बढ़ने वाली विनिमय दरें अपनाजी चाहिए। किन्तु, केवल अल्पकालीन समयांतरों (short intervals) को छोड़ कर कोई भी देश अपनी विनिमय दर को, बाह्य एवं आन्तरिक आर्थिक दबावों में होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर बदलते रहने के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकता। सच तो यह है कि अल्पधिक स्वतन्त्रता देने के सम्मिल परिणाम हो सकते हैं, जैसे —(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सहज प्रवाह में बाधा पड़ना, (ii) अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के मध्य उत्पत्ति-साधनों के समुचित विभाजन में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न होना, (iii) पूँजी का विदेशों को भागना, (iv) विदेशी विनिमय में सट्टे को प्रोत्साहित मिलना, (v) असाधारण रूप से अधिक द्रवता पसन्दगी उत्पन्न होकर संचय (hoarding) की वृद्धि होना, (vi) व्याज दरों में वृद्धि होना तथा इससे विनियोग, रोजगार और आय में गिरावट आना, (vii) दीर्घकालीन विदेशी विनियोजन के प्रवाह में बाधा पड़ना। इस प्रकार, कुछ न कुछ प्रकार, का स्थायित्व होना नितान्त आवश्यक है। हमारी सम्पत्ति में सर्वोत्तम स्थिति न तो यह है कि विनिमय दरें निरन्तर बदलती रहे, और न यह है कि वे परोक्षतापूर्वक निरन्तर ही स्थायी रहे, वरन् ऐसी स्थिति सर्वोत्तम है जिसमें प्रत्येक देश विनिमय दर को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित या परिवर्तित कर सके।

परीक्षा प्रश्न :

१. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करिये ?

[Critically examine the purchasing power parity theory]

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७, गोरख०, एम० ए०, १९६८)

२. विदेशी विनिमय के त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना करिये। अनेक विकासोन्मुख देशों में जो मुद्रा प्रसारित दशाएँ आजकल देखने में आती हैं उसमें उसका क्या विशेष महत्त्व है ?

[Explain critically the purchasing power parity theory of foreign exchanges. What special significance does it have in the inflationary conditions that characterise many developing countries today ?]

(इनाहा० एम० ए०, १९७२)

३. समतादारी को गणना के लिए घरेलू व्यापार की वस्तुओं की कीमतों को विचार में लेना अमम्बद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वाली वस्तुओं की कीमतों को विचार में लेना अनावश्यक है।" समीक्षा कीजिये।

["For calculation of parity rate prices of domestically traded goods are irrelevant and prices of internationally traded goods are unnecessary." Comment]

(इलाहा०, एम० कॉम० १९६९)

४. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त का विवेचन कीजिये और विनिमय दर के निर्धारण में इसके महत्त्व को समझाइये।

[Discuss the Purchasing power parity theory and explain its importance in determining the rate of exchange]

(विन्नम, एम० ए० १९६६)

५. त्रय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना करिये। यह आधुनिक दशाओं में कहाँ तक लागू होता है ?

[Critically examine the purchasing power parity theory. How far is it applicable under modern conditions ?]

(आमरा एम० कॉम०, १९६८)

६. विदेशी विनिमय के त्रय शक्ति समता सिद्धान्त को मूल्य में समझाइयें। यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है ?

[Explain briefly the purchasing power parity theory of foreign exchange. How does it differ from the classical theory ?]

(आमरा, एम० ए०, १९६८)

मुद्रा प्रसार के युग में विनिमय

(Exchange During Inflation)

परिचय—

पिछले अध्यायो में हमने विनिमय दरो के स्थैतिक सिद्धान्त (static theory of foreign exchanges) का विवेचन किया था। देशों के मध्य कीमत विनिमय (price exchange relationships) सम्बन्ध इसी साम्य की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब हम प्रारंभिक (dynamic) या अस्थिर (unstable) विनिमय दरो का विवेचन करेंगे जो साम्य में अस्थायी विचलनों (temporary divergences) का प्रतिनिधित्व करती है तथा जिनमें और अधिक विचलन के बीज मौजूद होते हैं। किन्तु यह समझना भूल है कि स्थैतिक सिद्धान्त ने परिवर्तनों की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी थी। यद्यपि यह है कि हमने भी 'साम्य में विचलन पड़ने के पूर्व की दशाओं' और 'नये साम्य की स्थापना के बाद की दशाओं' के मध्य तुलना करके परिवर्तनों को विचार में लिया है। यदि इन दोनों प्रकार की दशाओं में कोई भिन्नताये हैं, तो उन्हें एक 'कारण' के 'प्रभाव' के रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है। इस विश्लेषण विधि को तुलनात्मक स्थैतिकी (Comparative Static) कहते हैं।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि एक अपरिवर्तनशील पत्र चलन के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा को २०% बढ़ा दिया जाता है। ऐसी दशा में साम्य विश्लेषण (equilibrium analysis) यह दिखलाता है कि जब अतिरिक्त द्रव्य जो सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में परिभ्रमण (circulate) करने का अवसर मिल जाय, तो वहाँ कीमतें पहले की अपेक्षा ऊँची हो जायेंगी। यह कल्पना करते हुये कि इस साम्यो-परिवर्तन (change of data) में कीमत-समायोजनों के अनिर्दिष्ट कोई अन्य स्थायी परिवर्तन नहीं होते हैं, तो नवीन साम्यावस्था में कीमतें २०% ऊँची हो जायेंगी और विनिमय दर २०% नीची। किन्तु मुद्रा प्रसार की प्रक्रिया वास्तविक जगत में, व्यापार की मात्रा तथा उद्योग की मरचना पर सदा ही कुछ स्थायी या दीर्घकालीन प्रभाव डालती है, जिस कारण माँग की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। उस बिन्दु पर, जहाँ अनिर्दिष्ट मुद्रा चपन में पहली बार प्रवेश करती है, नया शक्ति बढ़ती है, अन्यथा वह कुछ समय तक अपरिवर्तित (unchanged) रहती है। किन्तु जब वृद्धि अन्य

बिन्दुओं पर भी फेल जाते हैं तो, पूर्ति, जिसने कि स्वयं को मूल परिवर्तन के साथ समायोजित करना आरम्भ कर दिया था सदा ही पुन समायोजित नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस जाया में कि कथ शक्ति में स्थाई ज़िपट (परिपतन) हुआ है, पूर्णों का विनियोग किया जा चुकता है। यही नहीं मुद्रा प्रसार के आरम्भ के समय जिन पर शून्य था वे, जेसदारों की हानि पर स्थायी रूप में साभावित हो जाते हैं। अब यह बहुत ही दुर्लभ सम्भावना (rare possibility) है कि सभी कीमते समान रूप से झट जायेंगी अथवा बीसत कीमत स्तर ठीक २०% ही ऊँचा हो जायगा और विद्वानों विनिमय दर पहले की अपेक्षा ठीक २०% ही नीची हो जायगी।

इस उदाहरण से जहाँ यह स्पष्ट है कि किन्तु मात्र सिद्धान्त (pure quantity theory) कीमत परिवर्तनों को स्पष्ट करने में अपयाप्त है वहाँ यह इस बात को भी दिखाता है कि उक्त जटिल चटको (स्थायी परिवर्तनों) को बिचार में लेने पर भी स्थैतिक विश्लेषण लागू किया जा सकता है।

एक साम्य से दूसरे साम्य में संक्रमण

(Transition from One Equilibrium to Another)

स्थैतिक विश्लेषण की कमी की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि दो साम्याओं में मध्यस्थ अवस्थाओं (intermediate stages) की परीक्षा की जाय। स्थैतिक दशाओं में भी समायोजन-यन्त्र (mechanism of adjustment, एक ऐसी कीमत विपमता (price discrepancy) प्रस्तुत करता है जो कि स्थैतिक दशाओं में मरणात् नहीं रहती। उदाहरणार्थ, जब किसी दश का नृणन सतुलन निम्निय हो जाता है, तो वहाँ कीमते गिरती हैं किन्तु अन्त में बर्तते हैं, जिससे निर्यात प्रोत्साहित होने हैं आयात निरस्तार्थित और इस प्रकार साम्य पुन स्थापित हो जाता है। किन्तु प्राथमिक दशा में कुछ कम अस्थायी कीमत विपमताओं से सम्बन्धित होती हैं, और ये विपमताएँ मुद्रा प्रसार के समय में समायोजन-यन्त्र द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं।

मुद्रा प्रसार की अवधि में कीमत स्तर एवं विनिमय दरें—

य कीमत विपमताएँ मुद्रा प्रसार के समय में उत्पन्न होती हैं। यदि विस्तार की उत्तोरत्तर लहर इतनी तजी से एक दूसरे का अनुसरण करे कि अर्धं चवस्था को एक के समान होने का अवसर नहीं मिलता कि दूसरी उत पर आ धमकती है, तो कीमते और विनिमय दर कुछ समय तक एक दूसरे में साम्य के बाहर (out of equilibrium) रह सकती हैं।

मुद्रा प्रसार जिस बिन्दु पर अनिश्चित मुद्रा प्रवेश कराई जाती है उस बिन्दु के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिये, स्वर्ण मुद्रा प्रसार (gold inflation) में स्वर्ण के उपादका को ही सर्वप्रथम इसके फल भोगने पड़ते हैं किन्तु माध्य प्रसार (credit inflation) में साहसिया की। यहाँ पर हंग बजट मुद्रा प्रसार (budget inflation) की स्थिति चले, क्योंकि अन्य प्रकार के मुद्रा प्रसारों में

कीमतें इतनी परिवर्तित नहीं होती है कि वे विनिमय की तुलना में कोई विशेष भिन्नता प्रदर्शित कर सकें ।

बजट-मुद्रा प्रसार में अतिरिक्त मुद्रा सर्व प्रथम सरकारी अधिकारियों और सरकारी ठेकेदारों द्वारा व्यय की जाती है । ये लोग जो वस्तुओं खरीदते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्म अपना व्यय बढ़ाती हैं और इस प्रकार कीमतों की वृद्धि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के अग्र हिस्से में भी फैल जाती है । देर-सबेर में विनिमय का भी ह्रास होना चाहिये । यदि अतिरिक्त मुद्रा की उत्तरोत्तर बाधाये प्रारम्भ में स्वदेशी वस्तुओं पर ही व्यय को जाती है तो विनिमय में ह्रास होने की अपेक्षा औसत कीमतों के बढ़ने की गति अधिक होती है । इसके विपरीत यदि वे आयात पर व्यय को जायें तो विनिमय में ह्रास की गति औसत कीमतों में वृद्धि की गति से अधिक होगी ।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण —

जर्मनी का १९१४-२३ की अवधि का मुद्रा प्रसार बुनियादी मिष्ठान्तों को स्पष्ट करने में बहुत ही सहायक है । इसे हम चार अवस्थाओं में बाँट सकते हैं —

(१) युद्ध काल—युद्ध के दिनों में घेराबन्दी के कारण जर्मनी का विदेशी व्यापार लगभग रुक सा गया था । अतः निर्यात (और विशेषतः आयात) का परिमाण (volume) कीमतों में परिवर्तनों के प्रति सामान्य गति में प्रतिक्रिया नहीं दिखा सका, जिससे मार्क का बाह्य मूल्य इसके आन्तरिक मूल्य की अपेक्षा कम होती गया । अन्य शब्दों में, मुद्रा का मूल्य ह्रास उतनी गति से नहीं हुआ, जितनी गति कि देश में कीमतें बढ़ गई थी ।

(२) युद्ध के तत्काल बाद—मार्च १९१९ में, जबकि घेराबन्दी उठा ली गई थी आयातों का परिमाण बढ़ गया और भुगतान सन्तुलन निष्क्रिय बन गया तथा कीमतों में वृद्धि की अपेक्षा विनिमय में अनुपात से अधिक ह्रास हुआ । यदि मुद्रा मात्रा को उत्तरोत्तर न बढ़ाया जाता, तो निर्यातों के विस्तार और आयातों के संकुचन द्वारा साम्य की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती । किन्तु, हुआ यह कि युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिये कुछ अतिरिक्त मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कराई गई ।

उल्लेखनीय है कि कीमतों की वृद्धि की तुलना में विनिमय के अधिक ह्रास (depreciate) होने का कारण मनोवैज्ञानिक था । जब मुद्रा प्रसार एक सीमा को पार कर जाता है, तो लोग यह आशा करने लगते हैं कि देर-सबेर में कीमतें बढ़ती ही जाएंगी । इससे सटोरियों विदेशी विनिमय बाजार पर प्रभुत्व जमा लेते हैं और विनिमय-ह्रास की गति बढ़ जाती है । सटोरियों के प्रभाव को बाद में जनता द्वारा भी बल मिलने लगता है, क्योंकि वह भी विदेशी मुद्रा का मूल्य करने लगती है ।

किन्तु बढ़ती हुई गति में होने वाला विदेशी विनिमय ह्रास (exchange depreciation) तो एक व्यापक प्रक्रिया (wider process) का अङ्ग मानें ।

जिम तरह विदेशी विनिमय दर में कीमत वृद्धि की अपेक्षा तेज गति में हुआ होता है उसी प्रकार में कीमत वृद्धि एवं विनिमय-द्वान् दोना ही प्रक्रियाओं की गति मुद्रा-माना में वृद्धि की गति से तेज होती है। कारण जब लोगों की कीमतों में नई वृद्धि की आसना होती है तो वे अपनी मुद्रा को जीर्णोद्धारोन्नत व्यय करने की इच्छा में प्रवृत्त हो कुछ ऊँची कीमतें देने को तैयार हो जाते हैं मजदूरियों एवं नौकरों के भुगतान की बारम्बारता (frequency) बढ़ जाती है और अन्त में लोभ अदान-बदान अपना लेते हैं या विदेशी मुद्रा को विनिमय साम्य के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे समय में वस्तुओं की कीमतें तेज गति में बढ़ जाती हैं और उस कार्य का परिमाण भी अधिक मुद्रा को करना पड़ जाता है। मुद्रा-परिमाण के परिवर्तनों और इसके मूल्य के परिवर्तनों में भिन्नता जिसे माँपा तक वह सकती है उसका अनुमान जर्मन मार्क के उदाहरण से लगाया जा सकता है। वर्ष १९२२ में मुद्रा का कुल चलन-परिमाण चाँदू दर पर स्वर्ण में वर्ष १९१६ की अपेक्षा ३८ वां भाग था।

(३) १९२३ के लगभग—जर्मन मुद्रा प्रसार की अन्तिम अवस्थाओं में परिस्थिति में एक बार पुनः परिवर्तन हुआ। वस्तु के प्रति दौड़ सामान्य बन गई और कीमतों की वृद्धि में विनिमय द्वारा के स्तर को स्पष्ट कर दिया। १९२३ तक, जबकि मुद्रा प्रसार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया था, भिन्नता (discrepancy) बहुत अधिक नहीं रह गई थी, क्योंकि दोनों हस्तगत (movements) समान विद्युत् सहाय्य तीव्र गति से हो रही थी। मुद्रा-परिमाण सम्बन्धी वृद्धि तो इस बीच इनसे बहुत पीछे छूट गई थी।

(४) करँसी का स्थायीकरण—इस अन्तिम तथ्य ने करँसी के स्थायीकरण की समस्या को अति भुग्न बना दिया। एक बार विश्वास लौटा कि चलन गति अपनी सामान्य दर पर सौट आती है तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। इसका यह अर्थ है कि यदि केन्द्रीय बैंक स्थायीकरण के लक्ष्य पर पहले चलन में मुद्रा की मात्रा के साथ साम्यता की अनुसंधान में एक स्वर्ण समता स्थापित कर दे, तो विनिमय में उतारान ही वृद्धि हो जाएगी और कीमतों में गिराव पड़ेगा। किन्तु ऐसी दशा में वैश्व स्वस्थ-कोय एकत्र न कर सके।¹

अतः युद्धोत्तर काल में अधिकांश स्थायीकरण एक ऐसी समता (parity) पर सम्पन्न किये गये, जो विनिमय की वास्तविक दर में कुछ ऊँची किन्तु उस विनि-

1 "Once confidence has been restored the velocity of circulation falls to its normal rate, and the supply of foreign currency increases. This means that if the central bank were to establish a gold parity corresponding in equilibrium to the amount of money in circulation just before stabilisation then the exchange would immediately appreciate and prices would have to fall."—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 57.

मय दर से जो कि प्रचलित कीमत स्तर की साम्यता में होती चाहिये, कुछ नीची भी। इससे केन्द्रीय बैंक स्वर्ण कोप एक्ज करने में तथा साथ ही चलन में मुद्रा-मात्रा को बढ़ाने में समर्थ हो गये। किन्तु यह स्मरणीय है कि मुद्रा मात्रा में वृद्धि करने और कीमतों को बढ़ाने की सम्भावना या आवश्यकता जहाँ एक ओर स्थायीकरण का गुण बनाने का प्रभाव रखती है, वहाँ दूसरी ओर मुद्रा प्रसारित तंत्री (और इसके परिणामस्वरूप बाद में मंदी) भी उत्पन्न कर सकती है।

हान की व्याख्या भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त एवं

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार

भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त की व्याख्याओं में तुलना—

उपराक्त विश्लेषण प्रतिष्ठित सिद्धान्त का पुरव है, विरोधी नहीं। यहाँ प्रतिष्ठित सिद्धान्त और भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त की तुलना साध सहित की जा सकती है। हेस्केरिख (Helfferich) ने भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त के दृष्टिकोण से प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना की है।¹ उन्होंने विनिमय दर कीमत स्तर और मुद्रा मात्रा के बीच में पड़ने वाले समय विन्मय (time-lag) का विशेष उल्लेख किया और लिखा है कि "जर्मनी की मौद्रिक दशाओं पर विचार करने में प्रचलित दृष्टिकोण (अर्थात् प्रतिष्ठित सिद्धान्त) विमुद्र मुद्रा परिमाण सिद्धान्त पर आधारित है और तदनुसार यह पत्र चलन में हुई वृद्धि को जर्मन कीमतों की वृद्धि और करेसी के हान का कारण मानता है। किन्तु निष्कर्ष से परीक्षा करने पर हम यह देखेंगे कि यहाँ 'कारण' और परिणाम' का स्थान आपस में बदल गया है और जर्मनी के पत्र-चलन में वृद्धि जर्मन विनिमय की गिरावट का तथा इसके परिणामस्वरूप मज दूरिपो और कीमतों में हुई वृद्धि का वस्तु प्रभाव' है, 'कारण' नहीं।

यदि मुद्रा प्रसार 'कारण' और जर्मन विनिमय का हान इसका 'प्रभाव' होता तो अंग्रेज शर्वाशास्त्रियों के प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार, घटता त्रम निम्न प्रकार चलता—पत्र चलन में वृद्धि स्वदेश कीमतों के स्तर में 'अनुपातिक' वृद्धि उत्पन्न कर देती, ये ऊँची कीमतें आयातों को प्रोत्साहित करती तथा निर्यात को कठिन बना देती जिससे व्यापार सन्तुलन और इसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रृंखला का सन्तुलन प्रतिफल हो जाता। जब श्रृंखला-सन्तुलन निष्क्रिय होता है, तो विदेशी मुद्रा के निम्ने माग बढ़ जाती है और विनिमय दरें ऊँची हो जाती हैं। किन्तु सार्विकी आयातों (जर्मनी के केन्द्रीय बैंक द्वारा पत्र-निर्यात २३ गुना और स्वदेशी वस्तुओं का शोक-शीमत-सूचनांक २२६ गुना हो गया था तथा बाजार दर ३४६ गुनी हो गई थी) पर दृष्टि डालने में पता चलता है कि उक्त तर्क-क्रम लागू नहीं होता है। स्पष्ट है कि जर्मनी की दशा में मोट चलन में वृद्धि कीमतों में वृद्धि से पूर्व की घटना नहीं है और यह भी कि वर्रेन्गी के हान ने इसका अनुसरण तो किया किन्तु

¹ Helfferich : *Money*, pp 598-601.

कुछ वित्तम्व के साथ तथा धीरे-धीरे १ नोट चलन की २३ गुनी वृद्धि, स्वदेशी कीमतों में १० गुनी और डालर-दर में १५ गुनी अधिक वृद्धि का कारण नहीं हो सकती है। इन घटनाओं के वास्तविक कारणों की विशद् और सामान्य व्याख्या तब ही सम्भव है जबकि हम केवल विदेशी विनिमय को ही प्रारम्भ विन्दु बनायें।^१

इसका कारण यह है कि जर्मनी के विनिमय का पतन किसी भी तरह नोट चलन में वृद्धि से सम्बन्धित नहीं है। २५ जनवरी १९२३ को उल्लेखित डालर दर (= २१,५८६) पर एक स्वर्ण-मार्क लगभग ५,००० कागजी मार्क के बराबर था। रोस बैंक के नोटों का पतन उस समय १,६५४ मिलियार्ड था, जिसका मूल्य केवल १३० मिलियन स्वर्णों के बराबर होता है। यह घुट छिड़ने के पूर्व जर्मनी की प्रचलित करेंसी के स्वर्ण मूल्य के सबसे माग से ज्यादा अधिक नहीं है।

वह सिद्धान्त, जिम्मे जर्मन करेंसी के पतन के लिए मुद्रा प्रसार को कारण बताया था, इस सिद्ध-साधन पर आधारित है कि मुद्रा का विदेशी मूल्य, जिसे विनिमय दरो के रूप में व्यक्त किया जाता है, केवल पत्र चलन से परिमाणात्मक घटक द्वारा ही निर्धारित हो सकता है। किन्तु उपरोक्त दशा में, जिसमें अभी-अभी यह विपदा जा चुका है कि पत्र चलन में वृद्धि करती ह्रास की अपेक्षा बहुत पिछड़ गई थी, विदेशी विनिमय के पतन के कारण, जोकि पत्र चलन की वृद्धि से स्वतन्त्र है, पूर्णरूपेण स्पष्ट है। हम एक ऐसे देश के बारे में विचार कर रहे हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय श्रृणता, वार्सेलीज की सधि के अन्तर्गत वेय भुगतानी और सुपूर्वी से पृथक्, ३ मिलियार्ड स्वर्णों भावम की सीमा तक निष्क्रिय थी तथा लन्दन के अन्टीमेटल के देश की श्रृणवस्तुता में ३३ मिलियार्ड स्वर्णों पाश्चिम के बराबर वार्षिक क्षतिपूर्ति भुगतान की वृद्धि कर दी थी। दसने वह भुगतान भी जुड़ गये जोकि जर्मनी पर युद्ध पूर्व के श्रृणों के निपटारे के लिए थे। इस प्रकार, जर्मनी के अन्तर्राष्ट्रीय श्रृणता सम्बन्धन की वार्षिक निष्क्रियता ७ मिलियार्ड स्वर्णों भावम से भी अधिक बढ़ गई, अतः 'कारण-परिणाम क्रम' इस प्रकार है —

- (१) सर्वप्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय श्रृणवस्तुता के अत्यधिक भार तथा कास की हिसाबमक नीति के कारण जर्मनी की करेंसी का ह्रास हुआ
- (२) तत्पश्चात् समस्त आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई,
- (३) जिसमें फिर कीमतों और मात्रादूरियों में सामान्य वृद्धि हो गई

^१ "A conception of the general and comprehensive outline of the interplay of causes in these developments can, in fact, be obtained only if the foreign exchange is made the starting point" — *Heimrich*

- (४) जिसने करैसी के लिए जनता की ओर रीश बैंक के वित्तीय अधिकारियों की माँग को बढ़ा दिया
 (५) अन्ततः रीश बैंक पर जनता द्वारा अधिक माँग की गई, तथा
 (६) इससे विवश होकर रीश के वित्तीय अधिकारियों को नोटों के निर्गमन में वृद्धि करनी पड़ी ।

इस प्रकार हैन्फेरिच लिखते हैं 'सामान्यतः प्रचलित दृष्टिकोण के विपरीत, यह करैसी का ह्रास है जो कि कारण परिणाम षण को प्रारम्भ करता है, मुद्रा प्रसार नहीं । मुद्रा प्रसार कीमतों में वृद्धि का और करैसी के ह्रास का कारण नहीं है वरन् करैसी का ह्रास ही ऊँची कीमतों का तथा नोट चलन की मात्रा में अधिक वृद्धि का कारण है ।'

प्रो० हैबरलर की सम्मति में 'हैन्फेरिच का उपरोक्त विश्लेषण प्रतिष्ठित सिद्धान्त की पूर्ण जानकारी पर आधारित नहीं है । कारण, प्रतिष्ठित सिद्धान्त नैतिक है जबकि हैन्फेरिच ने जित घटना का उदाहरण दिया है वह साम्म वशाओं के विपुल विपरीत (opposite) है । वास्तव में प्रतिष्ठित सिद्धान्त की व्याख्या साम्म के सिद्धान्त के रूप में करना चाहिए । अतः मुद्रा प्रसार विषयक घटनाओं स्पष्टतः सक्रमण कास की अनियमितताये हैं जिन्हें इस सिद्धान्त की आलोचना के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता''¹

प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने इस बात पर बल दिया है कि दीर्घकाल में (जो बहुत दीर्घ न हो) कीमतों और विनिमय दरों के मध्य फलनात्मक सम्बन्ध (functional relations) होते हैं और मुद्रा परिमाण की वृद्धि कीमतों में वृद्धि और विनिमय में ह्रास दोनों को ही बढ़ावा देगी । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पहली घटना दूसरी घटना से पहले ही हो, वह बाद भी हो सकती है । यदि कीमतें पिछड़ जायें, तो निर्यातों पर प्रीमियम उत्पन्न हो जाता है तथा विनिमय राशिपतन (exchange dumping) होने लगता है । किन्तु इसी कारण साम्म की पुनः स्थिति भी हो जायेगी, बशर्ते नई मुद्रा के ईर्ष्यान्वितों से समातार बाधा न डाली जाय । अतः यह नहीं कहना चाहिये (किन्तु श्रम शक्ति समता सिद्धान्त के समर्थक ऐसा कहते हैं) कि कीमतों में वृद्धि होना 'मूल कारण' तथा विनिमय में ह्रास होना इसका 'प्रभाव' है । प्रत्यर्थ में ये दोनों परिवर्तन आपस में फलनात्मक सम्बन्ध (functional relations) रखते हैं तथा एक ही कारण के प्रभाव हैं और यह कारण है मुद्रा मात्रा में वृद्धि होना, जो स्वयं बजट-घाटे का प्रभाव होती है ।

संदेह नहीं कि ह्रास और कीमत-वृद्धि बजट के संतुलन को कठिन बना देती है और इसलिए मुद्रा का अधिक प्रसार, कीमतों में नई वृद्धि तथा नया ह्रास होता है । (यह बात आजकल भारत में घटित हो रही है) किन्तु, जैसा कि अनुभवों से

पता चला है इस कुचक्र को तोड़ा जा सकता है, और, यदि वज्र के घाटे को पूरा करना असम्भव हो, क्योंकि एक ठोस वित्त नीति कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है, अथवा, क्योंकि बाहर से राष्ट्रीय खजाने पर जो भार जैमे—(क्षति पूति का भुगतान) टाले गये है वह अर्थव्यवस्था की करदान क्षमता से कहीं अधिक है, तो भी इसका इग प्रस्ताव ना विरोध नहीं होता कि यदि मुद्रा के परिमाण को स्थिर रखा जाय, तो ऐसी शक्तियाँ त्रिआशील हो जाती है जोकि कीमतों तथा विनिमय के परिवर्तनों को यथास्थिर कर देती है तथा कीमतों और विनिमय दरों को परस्पर समायोजित कर देती है। यही बात सशोधित क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त भी कहता है।

नि सन्वेह मुद्रा-परिमाण में वृद्धि मुद्रा मूल्य की गिरावट की अपेक्षा (विप्लव) जानी है, जिससे चलन में मुद्रा-माना (स्पर्ण के रूप में) कम हो जाती है। यदि दस तथ्य की ठीक ठीक व्याख्या की जाय तो हम देखेंगे कि यह प्रतिष्ठित सिद्धान्त के विरोध में नहीं है क्योंकि इस तथ्य को चलन मति की वृद्धि एक व्यापार की मात्रा में संकुचन द्वारा पूर्णतः स्पष्ट किया जा सकता है। जगत कारण यह भी है कि मन्त्रि-काय व्यवहार अन्य विनिमय-साधनों द्वारा भी किये जाते हैं। अतः हंस्केरिच द्वारा केवल इसी तथ्य के आधार पर परिमाण सिद्धान्त को रद्द करना वह प्रमाणित करता है कि वह साम्य की दशाओं तथा सम्मन-काल की घटनाओं में भिन्नता नहीं हो सकती है।

स्वाभाविक विनिमय दर में परिवर्तन या अल्पकालीन विनिमय दर

[भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त]

टकासाली समता या विनिमय समता की युक्ति में जो विनिमय दर मासूम की जाती है वह केवल एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। लेकिन दैनिक, अल्पकालीन अवस्था बाजार दर (जिस पर कि विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय के सौदे वास्तव में किये जायेंगे) उक्त दर से कुछ भिन्न होती है। इस भिन्नता का कारण उस पर माँग और पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। चूंकि इन शक्तियों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए वास्तविक विनिमय दर भी परिवर्तित होती रहती है।

परिवर्तन का मूल कारण—भुगतान-सन्तुलन में परिवर्तन होना

दो देशों A और B की कल्पना कीजिए। इनकी मुद्रायें क्रमशः a और b हैं। a और b की पारस्परिक विनिमय दर पर प्रभाव डालने वाले चार घटक हुये—
a की माँग a की पूर्ति और b की माँग एवं b की पूर्ति। किन्तु a की माँग और b की पूर्ति पर्यायवाची है। इसी प्रकार, a की पूर्ति एवं b की माँग पर्यायवाची है। जैमे, b का क्रता इसके (b) बदले में स्वदेशी करेसी (a) देता है, अतः b की माँग के साथ a की पूर्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार, यह भी दिखाया जा सकता है कि a की माँग के साथ b की पूर्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। अतः विनिमय दर को प्रभावित करने वाले घटक वास्तव में दो ही हैं—वर्षों की माँग और

इसकी पूर्ति। इनकी समानता (equilibrium) के द्वारा विनिमय दर (विदेशी मुद्रा की कीमत) का निर्धारण होता है।

किसी विदेशी मुद्रा *b* की मांग देश (A) के निवासियों द्वारा इस कारण से की जाती है कि उन्होंने विदेश (B) से वस्तुओं, सेवाओं व प्रतिभूतियों का न्य किया है जिनका अब वे भुगतान करना चाहते हैं अथवा वे विदेश (B) में विनियोजन के लिए अपने अल्पकालीन कोषों का हस्तान्तरण करना चाहते हैं। अतः जब सभी ऐसे भुगतानों की मांग में कमी या अधिकता होती है तब ही विदेशी मुद्रा (*b*) की मांग घट बढ़ जाती है। इसी प्रकार, देश (A) में विदेशी मुद्रा (*b*) की पूर्ति किसी विशेष समय पर इस कारण से घटती बढ़ती है कि देशवासियों ने वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात अथवा अल्पकालीन कोषों का हस्तान्तरण घटा-बढ़ा दिया है।

अब हमें ये किसी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति सम्बन्धी वशाओं में परिवर्तन होने का कारण देश के निवासियों द्वारा विदेशियों को किये जाने वाले और उनसे विदेशियों को प्राप्त होने वाले भुगतानों में परिवर्तन होते रहना है।

भुगतान-सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाले कारण—

‘भुगतान सन्तुलन’ (अथवा सरल बोलचान की भाषा में, विदेशों से लेनी देनी का विवरण) के प्रमुख अंग—व्यापार, सेवाएँ, पूँजी के आवागमन आदि हैं। इन अंगों में से किसी से भी कोई परिवर्तन होने पर विनिमय बाजार में मांग-पूर्ति सम्बन्धी दशाएँ प्रभावित हो जाती हैं। भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाले कारणों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

(I) व्यापारिक कारण (Trade Conditions)—

यदि किसी देश की वस्तुओं के लिये विदेशों में अधिक मांग है तो स्वदेश की मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा बढ़ जायेगी और कमतर विनिमय दर देश के पक्ष में हो जायेगी, अर्थात्, देशी मुद्रा अपने बदले में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने सकेगी। इसके विपरीत, यदि आयात देश के निर्यात से अधिक हों तो विदेशी मुद्रा की मांग इसकी पूर्ति की अपेक्षा अधिक होगी, विनिमय दर देश के प्रतिकूल हो जाएगी और देशी मुद्रा अपने बदले में कम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेगी।

(II) स्टॉक विनिमय सम्बन्धी कारण (Stock Exchange Conditions)—

भुगतान सन्तुलन पर प्रभाव डालने वाली स्टॉक विनिमय सम्बन्धी दशाओं के अन्तर्गत ऋण सम्बन्धी व्यवहार तथा विदेशी प्रतिभूतियों का कम बिक्रय सम्मिलित किया जाता है।

(१) ऋण सम्बन्धी लेन-देन (Loan Operations)—जब देशवासी विदेशों से ऋण लेते हैं अथवा अपने दिए हुए ऋणों पर उनमें व्याज प्राप्त करते हैं, तो विदेश में स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी और ऐसा होने पर विनिमय दर हमारे पक्ष में हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि देशवासी विदेशों को ऋण दे रहे हैं अथवा उनमें प्राप्त ऋणों पर व्याज चुका रहे हैं, तो स्वदेश के विनिमय बाजार में

विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ने लगती है, जिससे विनिमय दर स्वदेश के प्रतिकूल होने लगती है । [स्मरणीय है कि यदि ऋण पर प्रयोग ऋणी द्वारा ऋणदाता देश में ही वस्तुओं प्रत्य करने में किया जाता है, तो इस प्रकार के ऋण का विनिमय दर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । हाँ, यदि ऋण का प्रयोग अन्य देशों में किया जाय, तो प्रभाव पड़ेगा ।]

(२) प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय—जब स्वदेशी विनियोक्ता विदेश में स्टॉक, बोनस और सिन्डिकेटेज आदि खरीदते हैं, तो इनके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, जिससे स्वदेश में विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और विनिमय दर बिगड़ में हो जाती है, क्योंकि अब हम अपनी मुद्रा के बदले में विदेश की मुद्रा पहले से कम मात्रा में क्रय कर पाते हैं । इसके विपरीत, जब विदेशी प्रतिभूतियाँ हमारे देश में स्टॉक आदि खरीदते हैं, तो उन्हें इनका भुगतान हमारी मुद्रा में करना पड़ता है । फलतः स्वदेश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति इसकी माँग से अधिक हो जायेगी और इससे विनिमय दर हमारे पक्ष में परिवर्तित हो जायेगी, अर्थात् अब हम अपनी मुद्रा के बदले में पहले से अधिक विदेशी मुद्रा खरीद सकेंगे ।

(III) बैंकिंग कारणा (Banking Conditions)—

बैंकिंग सम्बन्धी कारणों के अन्तर्गत हम बैंक दर के परिवर्तनों, विदेशी व्यापार में प्रयोग किये जाने वाले साख-पत्रों की घटा-बढ़ी, और मध्यस्थों की क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं —

(१) बैंक-दर—जब स्वदेश में बैंक-दर विदेशों की अपेक्षा ऊँची होती है, तो विदेशियों के लिए हमारे देश में विनियोग करना लाभदायक होता है, जिससे देश में विदेशों से पूँजी जाने लगती है । ऐसी दशा में स्वदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है और फलस्वरूप इसका मूल्य बढ़ जाता है । इसके विपरीत, जब बैंक-दर स्वदेश में अन्य देशों की अपेक्षा कम होती है, तब स्वदेशी विनियोक्तियों के लिए विदेशों में विनियोग करना अ-लाभदायक हो जाता है, अब वे पूँजी बाहर भेजने लगते हैं । विदेशों भी स्वदेश में लगी हुई पूँजी निकालने लगते हैं । फलस्वरूप देश में विदेशी मुद्रा की माँग (एवं इसका मूल्य) बढ़ जाती है ।

(२) साख पत्रों का क्रय-विक्रय—जब स्वदेश के बैंक विदेशी साख-पत्रों में रुचि लगाते हैं, तो देश की पूँजी का विदेशों को हस्तान्तरण होता है, और जब वे विदेशियों को स्वदेशी साख-पत्रों का विषय करते हैं, तब विदेशी पूँजी देश में आती है । यदि बिलों, साख-पत्रों आदि के न्य-विक्रय का सामूहिक प्रभाव यह है कि देश में विदेशों से अधिक पूँजी का हस्तान्तरण होता है, तो देशी मुद्रा की अधिक माँग होने के कारण इसका मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है, अर्थात् विनिमय दर हमारे पक्ष में परिवर्तित हो जाती है । यदि देश से विदेशों की अधिक पूँजी का हस्तान्तरण होता है, तो विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ने से विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जायेगा और फलतः विनिमय दर हमारे विपक्ष में परिवर्तित हो जायेगी ।

(३) 'अन्तर गणन' या मध्यस्थो की क्रियाएँ—'अन्तर गणन' अथवा मध्यस्थो की क्रियाओं का आशय मुद्रा के क्रय विक्रय सम्बन्धी उन कार्रवायियों से है जोकि बैंको द्वारा विभिन्न वित्त केन्द्रों में दरो की शिथिलता से लाभ उठाने की इच्छा से किए जाते हैं ।

मान लीजिए कि लन्दन में न्यूयार्क पर केविल रेट किसी समय पर ४ ६६ डालर प्रति पौंड है, लेकिन किसी कारण से न्यूयार्क में लन्दन पर केविल रेट ४ ६५ १/२ डालर प्रति पौंड है । अब मध्यस्थगण न्यूयार्क में लन्दन पर और लन्दन में न्यूयार्क पर १०० टी० (टेलीफोनिक ट्रान्सफर) बय करना प्रारम्भ कर देंगे । ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यवहारी लन्दन पर एक लाख पौंड का केविल न्यूयार्क में ४६५,५०० डालर का भुगतान करके खरीदता है तथा साथ-साथ लन्दन में एक लाख पौंड बय करके डालर खरीदे जाते हैं । प्रचलित विनिमय दर पर एक लाख पौंड द्वारा ४६६,००० डालर खरीदे जायेंगे । यह बय-विक्रय टेलीफोन पर ही जाता है । इस प्रकार कुछ ही क्षणों में उक्त व्यवहारी १०० डालर का लाभ बना लेता है ।

विभिन्न व्यवहारियों द्वारा किये जाने वाले उक्त कार्य-कलापों का सामूहिक प्रभाव यह होगा कि पौंड का मूल्य न्यूयार्क में बढ़ने लगेगा (क्योंकि वहाँ पौंड की माँग बढ़ गई है) तथा लन्दन में गिरने लगेगा (क्योंकि वहाँ पौंड की पूर्ति बढ़ गई है) । इस प्रकार दोनों वित्त-केन्द्रों की दूरी एक दूसरे के निकट होती जायेगी । अन्तर-गणन का महत्त्व वस्तुतः इसी बात में है कि वह विभिन्न केन्द्रों में दो करैसियों के मध्य दरो को समान रखता है । [उल्लेखनीय है कि आजकल विनिमय बाजार नियन्त्रित होते हैं, अतः अन्तर गणन के लिए अबसर उत्पन्न नहीं है ।]

(IV) मौद्रिक वशायें (Monetary Conditions)—

मुद्रा सम्बन्धी निम्न दशाएँ भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं —

(१) मुद्रा प्रसार (Inflation)—जब किसी देश में मुद्रा प्रसार हो गया है अथवा जब इसकी सम्भावना मान है, तब पूँजी विदेशों को जाने लगती है । यहाँ तक कि विदेशी भी अपनी पूँजी लौटाने लगते हैं । कारण, मुद्रा प्रसार से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है । परिणामतः देश की विनिमय दर इसके प्रतिकूल होने लगती है, अर्थात्, देश की मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा पढ़ने में कम माना में खरीदी जा सकती है ।

(२) मुद्रा संकुचन (Deflation)—जब मुद्रा संकुचन की स्थिति विद्यमान हो अथवा लोग यह आशा करते हैं कि करैसी की मात्रा कम होने में इसका मूल्य बढ़ जायेगा, तो वे करैसी का बय करने लगेंगे । इससे स्वदेशी मुद्रा में लिए विशाल माँग उत्पन्न हो जायेगी तथा फलस्वरूप विनिमय दर स्वदेश के पक्ष में परिवर्तित होने लगेगी ।

(V) राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियाँ—

देश की राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियाँ भी विनिमय दर पर प्रभाव डालती हैं। इनमें निम्न का समावेश है —

(१) संरक्षण नीति—आप सरकारें देशी उद्योगों को संरक्षण देकर आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि करती हैं। इससे भुगतान-संतुलन देश के अनुकूल होने लगता है और विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(२) युद्ध व वार्ता—जब देश में आन्तिपूर्व वातावरण होता है, तब विदेशियों का विश्वास कमजोर हो जाता है और वे अपनी पूर्ण स्वदेशी उद्योगों के विकास में लगते हैं। इससे विनिमय-दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।

(३) वित्त नीति—यदि सरकार धन की अर्थ-व्यवस्था अपनाती है, तो विनिमय-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(४) विनिमय नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न साधन अपनाकर विनिमय दर को प्रभावित करता रहता है।

भुगतान संतुलन सिद्धान्त के गुण-दोष—

भुगतान संतुलन सिद्धान्त के निम्न गुण हैं —(i) यह अन्य वस्तुओं को नाश होने वाले इस सामान्य तर्क का ही अनुसरण करता है कि विनिमय-दर के निर्धारण में कटौतियों की मांग-पूर्ति का बहुत भाग है, (ii) इसने विनिमय-दर के निर्धारण की समस्या को 'सामान्य साम्य विश्लेषण' (general equilibrium analysis) का ही एक अंग बना दिया है, (iii) इसने विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को विचार में लिया है, एवं (iv) यह एक रचनात्मक सुझाव भी देता है, जो यह कि मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के बिना ही, भुगतान संतुलन में, विनिमय दर का समायोजन नरके (अर्थात् अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन द्वारा), साम्य लाया जा सकता है।

किन्तु उक्त सिद्धान्त में निम्न दोष भी हैं —(i) इसने (जैसा की कीन्स ने जताया है) 'ठीसता के सिद्धम' को लागू किया जबकि 'द्रव्यो का नियम' लागू करना चाहिए था, अर्थात्, देखित और केचित्त मदों को 'दी हुई मात्राएँ' मान लिया है जबकि वास्तव में ये 'घटने बढ़ने वाली मात्राएँ' हैं, एवं (ii) अनेक कच्चे मालों के लिये मांग पूर्णतः बेतुल्य नहीं है जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। साधनो की मांग भी पूर्णतः बेतुल्य नहीं होती है, क्योंकि इन्हें भी कुछ सीमा तक आय (भले ही मँहमी) वस्तुओं (जैसे आगूर आदि) से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार नीमत-परिवर्तनों का जति आवश्यक वस्तुओं की मांग पर भी न्यूनतम असर पड़ता है। जब भुगतान-संतुलन स्वयं भी विनिमय-दरों के परिवर्तनों पर निर्भर होता है। जिस सीमा तक वह इस प्रकार निर्भर है उस सीमा तक उसे विनिमय-दरों के निर्धारण का मन्तोपजनक स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है।

विनिमय दरो मे उच्चावचनो की सीमाये

वास्तविक विनिमय दर विदेशी मुद्रा की माँग-पूर्ति सम्बन्धी दशाओ मे परिवर्तनो के कारण, स्वाभाविक विनिमय दर से जब तब ऊँची-नीची होती रहती है। यह कितनी ऊपर उठ सकती है अथवा कितनी नीचे गिर सकती है? अथवा, क्या विनिमय-दरो के उतार-चढ़ाव की कोई सीमाये है? इन प्रश्नो का उत्तर हमें विभिन्न मौद्रिक परिस्थितियों के सदर्थ म देना होगा, जोकि निम्नलिखित हैं—

(१) जब दो देशो मे स्वर्णमान हो—स्वर्णमान देशो मे विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव असीमित नहीं होते, वरन् स्वर्ण-बिन्दुओ (Specie Points) से मर्यादित होते हैं, क्योंकि स्वर्णमान के अन्तर्गत व्यापारियों को स्वर्ण का आयात अथवा निर्यात करने की स्वतन्त्रता रहती है। एक ओर, विनिमय-दर 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' (Upper Specie Points) मे अधिक नहीं जा सकती है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, तो व्यापारीगण विदेशी मुद्रा (या इसके बिल) खरीदने के बजाय सोना खरीद कर विदेशो को भेजना पसन्द करेंगे। दूसरी ओर विनिमय-दर 'स्वर्ण आयात बिन्दु' (Lower Specie Points) से नीचे नहीं गिर सकती है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो विदेशी देनदार हमें हमारी मुद्रा (अथवा इसके बिल) भेजने के बजाय सोना खरीद कर भेजने लगेगे।

(२) जब दो देशो में रजतमान हो—सम्बन्धित देशो मे रजतमान विद्यमान होने की परिस्थितियों मे स्वर्णमान की भांति ही विनिमय दरो के उतार-चढ़ाव 'रजत बिन्दुओ' से सीमित होते हैं। हाँ, असाधारण, समय मे, जबकि सोने चांदी का आयात-निर्यात नहीं होने पाता, विनिमय दरें सीमाओ का उल्लंघन कर सकती है।

(३) स्वर्णमान एवं रजतमान देशो के मध्य—जबकि एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा रजतमान पर हो, तब भी विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव उच्चतम एवं निम्नतम स्वर्ण बिन्दुओ के बीच ही सीमित रहते हैं।

(४) स्वर्णमान (अथवा रजतमान) एवं पत्र-मुद्रा मान देशो के बीच—स्वर्णमान (अथवा रजतमान) देश मे स्वर्ण की कीमत सरकार द्वारा निश्चित होती है किन्तु पत्र-मुद्रा मान देश मे वह बाजार मे समय समय पर बदलती रहती है। अतः, स्वर्णमान देश के लिए एक उच्चतम सीमा (स्वर्ण निर्यात बिन्दु) तो होती है, किन्तु निम्नतम सीमा (स्वर्ण आयात बिन्दु) नहीं होती। इसी प्रकार पत्र मुद्रा मान देश के लिए एक निम्नतम सीमा तो है लेकिन कोई उच्चतम सीमा नहीं होती है।

(५) पत्र मुद्रा मान वाले देशो के बीच—दो पत्र-मुद्रा मान देशो के मध्य विनिमय-दर उक्त परिस्थितियों की तरह स्वर्ण बिन्दुओ से मर्यादित नहीं होती है, क्योंकि इनकी मुद्राओ का सम्बन्ध किसी धातु से नहीं होता। अतः पत्र मुद्रा मान मे विनिमय-दरो के परिवर्तन की कोई सीमाएँ नहीं हैं। केवल यह कह सकते हैं कि विनिमय-दर मे त्रय शक्ति समता मे निरुद्ध रहने की प्रवृत्ति होती है। वह समता के कितनी निरुद्ध रहेगी यह सरकार की मौद्रिक नीति पर निर्भर है।

परीक्षा प्रश्न :

१. स्थैतिक विश्लेषण का क्या महत्व है ? इसकी अनुपूर्ति प्राच्यगतिक विश्लेषण द्वारा करना क्यों आवश्यक है ?

[What is the significance of static analysis ? Why is it necessary to supplement it by dynamic analysis ?]

२. 'प्रतिष्ठित सिद्धान्त की सम्पूर्ण प्रवृत्ति यह मकेव करती है कि विनिमय दरों के निर्धारण को साम्यों के सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।' इस कथन को मुद्रा प्रसार के युग में विनियमों के सम्बन्ध में स्पष्ट कीजिये।

["The whole tendency of the classical doctrine shows that it must be interpreted as a theory of equilibria" Explain this statement in context of exchanges during inflation]

३. विदेशी विनिमय दरों के भुगतान समतुल्य सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं ? यह विनिमय दरों में नित्य प्रति होने वाले परिवर्तनों को किस सीमा तक स्पष्ट करता है ?

[What do you mean by the Balance of Payments Theory of Foreign Exchanges ? How far is it an adequate explanation of day to day changes in exchange rates ?]

४. विनिमय दर में उतार चढ़ाव के क्या कारण हैं प्रबन्धित चलने के अन्तर्गत उतार चढ़ाव कैसे सीमित होते हैं ?

[What are the causes of fluctuations in the rate of exchange ? How are fluctuations limited under the managed currencies ?]

(जीवाजी एम० ए०, १९६७)

अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन

(Undervaluation and Overvaluation)

अवमूल्यन (Undervaluation)

अधमूल्यन से आशय—

‘अवमूल्यन’ का आशय किसी देश को करंसी के बाह्य मूल्य (external value) को कम करने से है। करंशियों के बाह्य मूल्य में कभी या तो सभी करंसियों के सम्बन्ध में सामान्य रूप से, या कुछ चुनी हुई करंसियों के सम्बन्ध में ही विशेष रूप में, की जा सकती है। यहाँ पर हमें ‘अवमूल्यन’ और ‘ह्रास’ में भेद समझ लेना चाहिए। परिणाम की दृष्टि से तो इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों ही दशाओं में स्थानीय करंसी का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में नीचा होता है। इनमें एकमात्र भेद यह है कि जबकि अवमूल्यन में करंसी का मूल्य सरकार द्वारा कम किया जाता है तब ह्रास की दशा में करंसी का मूल्य बाजार-शक्तियों (market forces) के प्रभाव से कम हो जाता है। उदाहरण के लिये सन् १९४६ में, भारत ने, स्टर्लिंग गुट के अन्य सदस्यों के साथ-साथ, रुपये का डालर मूल्य ३३ सेंट से घटा कर २२ सेंट कर दिया था। इस प्रकार रुपये के मूल्य में ३३% कमी हो गई और डालर का रुपया मूल्य ३३% से बढ़ गया। यह रुपये का अवमूल्यन है ह्रास नहीं।

अवमूल्यन के उद्देश्य

अवमूल्यन के लिये उचित आधार—

एक देश अपनी करंसी का अवमूल्यन निम्न उद्देश्यों से कर सकता है—(i) उन देशों के साथ, जिन्होंने अपनी करंसियों का अवमूल्यन कर दिया है, व्यापार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बनाये रखने के लिये, (ii) अन्य महत्वपूर्ण करंसियों की तुलना में, विनिमय दर को, अपनी करंसी की कम शक्ति में हुए परिवर्तन की अनुसारता में (in accordance with), यथोचित रूप से समायोजित करने के लिए, (iii) जबकि विदेशी सहायता मिलनी बन्द हो गई है तब उसने भुगतान मनुष्य को साम्प्रदायिकता में रखने के लिए, (iv) विदेशी देशों को, जिन्होंने अपनी करंसी का मूल्य नहीं घटाया है, निर्यात बढ़ाने के लिए, तथा वहाँ से आयात घटाने के लिए, जिसमें कि देश की विदेशी विनिमय कमाने की शक्ति बढ़ जाय। (v) देश के भीतर ही उपत्ति को

बढ़ावा देने तथा विदेशी बाजार में बिजली बढ़ाने की दृष्टि से देश के उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए ।

इन सब उद्देश्यों में से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भुगतान तुला की प्रतिकूल असाम्यता को, जो कि बहुत दीर्घकालिक (Chronic) हो गई है, सुधारना है । यदि भुगतान तुला की प्रतिकूल असाम्यता एक लम्बे समय तक जारी रहे, तो इससे देश के स्वयं एवं विदेशी विनिमय कोष खाली हो जाने का डर है । यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी सरकार उपेक्षा से नहीं देख सकती । सामान्य अवधियों में एक प्रति-कूल मनुष्य स्वयं के निर्यात द्वारा अपने आप मुघर जाता है । लेकिन, जब विनिमय बाजार में स्वतन्त्र विनिमय-व्यवहारों का स्थान सरकारी एजेंसियों द्वारा विनिमय व्यापार ग्रहण कर लेते हैं, अथवा जब विनिमय बाजार का नियंत्रण कठोरनायक दिया जाता है, तब यह उपचार सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी दशाओं में स्वयं का निर्यात प्रतिबन्धित होता है । अतः निम्नलिखित अन्य उपाय प्रयोग किये जाते हैं —

(१) निर्यातों को प्रोत्साहन देना—यदि भुगतान तुला में असाम्यता या प्रतिकूलता देश की निर्यात आगमनियों में गिरावट आने में है, तो निर्यातों का, इनकी उत्पादन लागत घटाने की युक्तियों द्वारा, सस्ता बनाकर, निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । किन्तु, इससे उत्पत्ति-माघन के पुरस्कारों को कम करने की समस्या उभर जाती है । यदि पुरस्कार कम किए गए तो साधनों की ओर न पार विरोध होने का भय है ।

(२) आयातों को निरस्तार्हित करना—असाम्यता की बढती हुई गडक (gap) को गटने के लिए आयातों को कम करने की नीति अपनाई जा सकती है । इस नीति के अधीन याता जायातों का पूर्ण निषेध किया जा सकता है अथवा जायात-कोटे या आयात-कर निर्धारित करके आयातों को काफी सीमा तक घटाया जा सकता है । किन्तु, इस सम्बन्ध में यह गहरी भ्रूखना चाहिए कि यदि आयातों में कोई भारी कटौती की गई, तो अन्य देशों द्वारा बदले की कार्यवाही (retaliation) की जा सकती है, जिससे देश के निर्यात कम हो जायेंगे और फलतः, आयातों में काफी कमी कर देने पर भी असाम्यता दूर न होगी । यही नहीं, विदेशी व्यापार कम होने में देश उन लाभों से भी वंचित हो जाता है जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होते हैं । अतः आयात प्रतिबंध एक सीमा तक ही अपनाये जा सकते हैं ।

(३) करन्सी का संकुचन—जबकि असाम्यता का कारण देश में मुद्रा प्रसार फैलना है, तो उसका एक उपयुक्त उपचार यह होना कि करन्सी का संकुचन किया जाय । संकुचन का मतलब है स्वदेशी करन्सी के परिमाण में कमी करना । इस कमी के फलस्वरूप स्वदेश में मागतों और कीमतें घटने लगती हैं । इसका प्रभाव देश की एक 'अच्छा' बय बाजार (market for buying) किन्तु 'बुरा' बय बाजार बना देना है । फलतः निर्यात प्रोत्साहित और आयात हतोत्साहित होते हैं । किन्तु इस नीति में भी निम्न तीन दुर्बलताएँ हैं —(१) चूँकि इस दृष्टि में मजदूरियों की कटौती

और बकारी बटने का प्रश्न जुटा हुआ है, इसलिए इनका अधिक सभो द्वारा बहुत विरोध किया जाता है। (ii) कभी-कभी आय नीमन मरचना इतनी बेतोच होती है कि मुद्रा सकुचन भुगतान तुला की विषमता के मुधार का एक उपयुक्त ढंग नहीं होता। (iii) यदि प्रचलित मुद्रा-प्रसार पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए अपनाई गई एक विस्तार नीति (Expansionary policy) का भाग है, तो मुद्रा सकुचन इस नीति के प्रभ व को ही बेनाम कर देतो है।

(४) विनिमय-नियन्त्रण—भुगतान तुला की असाम्यता के मुधार का एक अधिक कारगर (surer) उपाय विनिमय नियन्त्रण है। इस विधि के अन्तर्गत मुद्रा अधिकारी सभी निर्यातकों को यह आदेश देता है कि वे अपनी विदेशी विनिमय राशिकभी समस्त आय सरकार के हवाले कर दें, जिसका फिर बाद में लाइसेन्स प्राप्त आयातकों के मध्य आवश्यकतानुसार वितरण (rationing) कर दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति लाइसेन्स के बिना वस्तुओं का आयात नहीं कर सकता। इस प्रकार, आयातों की निर्यातों की सीमाओं के भीतर रखकर भुगतान तुला को सुधारा जाता है।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता—भुगतान तुला में असमता का शिकार बने हुए देश के लिए एक उपाय यह भी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर असाम्यता को दूर करने का प्रयत्न करे। लेकिन यह भी एक अस्थायी और सीमित उपाय है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भुगतान तुला की प्रतिकूलता के जो भी मुधार बताये गये हैं उनमें से कोई भी एक अचूक और पूर्ण इलाज नहीं है। सम्भवतः भुगतान सतुलन की असमता के मुधार का एक माध्य उपचार, जबकि सकुचन के पलस्वरूप पैकारी उत्पन्न होने का डर हो, तथा आयातों को पहले ही अधिकतम सीमा तक घटाया जा चुका हो, यह है कि देश की करें-सी का अवमूल्यन कर दिया जाय।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का प्रभाव—

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि होने लगती है। ऐसा होना विस्तृत स्वाभाविक ही है, क्योंकि अवमूल्यन के कारण स्वदेशी करेंसी विदेशी करेंसी के लिए सस्ती हो जाती है जबकि विदेशी करेंसी हमारे लिए महंगी पड़ने लगती है। इस प्रकार, अवमूल्यन एक 'अनुकूल' भुगतान सतुलन उत्पन्न कर देता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अवमूल्यन के अच्छे प्रभाव सामान्यतः तीन या चार वर्ष तक जारी रहते हैं। कारण, कुछ समय के बाद ही 'लागत-नीमन मरचनाएँ' (Cost-price structures) आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही बाजारों में अपने आपकी नई विनिमय समता (exchange parity) के अनुरूप ढाल लेती हैं, जिससे अवमूल्यन का अनुकूल प्रभाव समाप्त हो जाता है। स्पष्टतः, अवमूल्यन केवल 'सांस लेने भर की मोहलत' (brea-

thing space) देता है, जिसके भीतर ही करेंसी का अवमूल्यन करने वाले देश को चाहिये कि अपनी लागत-कीमत सरचना की शेष विषय के सन्दर्भ में इस प्रकार से सुधार ले कि उसके भुगतान सन्तुलन में न्यूनता के अवसर उत्पन्न न हों।

अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक बातें—

अवमूल्यन अस्थाई रूप में भी खब ही सफल हो सकता है जबकि निम्नलिखित बातें पूरी हो जायें —

(१) यदि अवमूल्यन किया जाय, तो लागत-कीमत सरचना पर इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया होनी चाहिये—उस देश में, जिसने करेंसी का अवमूल्यन किया है, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए अन्यथा जिस सीमा तक ये बढ़ती हैं उस सीमा तक अवमूल्यन के सुप्रभाव व्यर्थ चले जायेंगे। कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा मूल्य नियन्त्रणों की आवश्यकता होगी। पिछेवत निर्यात वस्तुओं की कीमतें सीमाबद्ध ही रखनी चाहिए।

(२) विदेशी देश को चाहिए कि अवमूल्यन करने वाले देश के साथ सहयोग करे—उसे प्रतिरोधी-उपाय (counter measures), जैसे—सुरक्षण करो म वृद्धि करना, अपना कर अवमूल्यन के प्रभावों को व्यर्थ बनाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए।

(३) आयातों और निर्यातों के लिए माँग सोचदार होनी चाहिए—यदि माँग बेवोच है, तो अवमूल्यन करने से भुगतान सन्तुलन में साम्यता की स्थापना नहीं हो सकेगी। उदाहरण के लिए, यदि विदेशी वस्तुओं के लिए भारतीय माँग बेवोच है, तो इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो भारत की न्यूनताधिक पहले जितनी मात्रा में ही वे वस्तुएँ खरीदनी पड़ेंगी, जिससे आयातों में कमी की आशा अपूर्ण रह जायेगी। साथ ही, यदि भारतीय वस्तुओं के लिए विदेशी माँग बेवोच है, तो अवमूल्यन करने पर भी भारतीय निर्यात कुछ विशेष सीमा तक न बढ़ सकेंगे, क्योंकि कीमतें चाहे कुछ भी हो, वही मात्रा, जो कि अब तक विदेशियों द्वारा खी जा रही थी, भविष्य में भी ली जायेंगी। इस प्रकार यदि आयातों और निर्यातों के लिए माँग बेवोच है, तो अवमूल्यन द्वारा साम्य की स्थापना सम्भव नहीं है बरज डर इस बात का है कि कहीं असाम्यता में अधिक वृद्धि न हो जाय। अवमूल्यन तब ही सफल हो सकता है जबकि दोनों देशों की माँगें सोचदार हों। ऐसी दशा में ही आयातों में कटौत की जा सकेगी तथा निर्यात भी बढ़ाये जा सकेंगे।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि भुगतान तुला की प्रतिकूल असाम्यता के सुधार के एक ढंग के रूप में अवमूल्यन का पर्याप्त अविवेक है। इसमें 'ह्रास' और 'स्थिर विनिमय' दोनों के ही लाभ सम्मिलित हैं। किन्तु इसकी सफलता के लिए कई अनुकूल घटकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के वातावरण में ही यह सफल हो सकता है।

पौड-स्टलिङ्ग का अवमूल्यन

मैकमिलन कमेटी, अथवा कमेटी ऑन फाइनेन्स एण्ड ट्रेड (Macmillan Committee or Committee on Finance & Trade) ने अपनी रिपोर्ट (१९३१) में महान् मन्दी के कारणों व उपचारों का विश्लेषण किया गया था। तब कमेटी ने मन्दी की समस्या के एक उपचार के रूप में अवमूल्यन के प्रस्ताव को अम्बीकृत कर दिया था। उसका यह कार्य सन् १९४६ में ब्रिटिश सरकार के कार्य में, जबकि स्टलिङ्ग का ३०% अवमूल्यन किया गया था, बिल्कुल भिन्न था। नीचे हमने यह दिखाया है कि किस प्रकार अलग-अलग समयों पर, भिन्न-भिन्न परिस्थितियाँ होने से अलग-अलग कदम उठाने आवश्यक हो जाते हैं।

सन् १९३०-३१ की परिस्थिति—

सन् १९३०-३१ में कमेटी ने अवमूल्यन का सुझाव बिना सकोच अमान्य कर दिया था और यह मत प्रगट किया था कि 'समता मूल्य पर स्थिर बनी आ रही किसी करेंसी का सरकार द्वारा अचानक ही, बिना पूर्व सूचना दिये (जिसमें कि विदेशी ऋणदाता अपनी सम्पत्ति हटा न सकें) अवमूल्यन करना एक अशुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है।'^१ अपने मत के समर्थन में कमेटी ने निम्नलिखित तर्कों दिये थे—

(१) यह उक्त विश्वास को, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और वित्त का आधार है, खोद पहुँचावेगा—अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास की एक आधार शिला यह सामान्य धारणा होती है कि सभी देश अपनी राष्ट्रीय करेंसियों का मूल्य स्थिर रखने का पल करेंगे और इसके ह्रास को तब ही मान्यता देंगे जबकि ऐसा ह्रास स्वयं से ही जाय। उन दिनों अनेक देशों की करेंसियों का मूल्य समता (Par) से इतना नीचे गिर चुका था कि उन्हें पूर्व स्तर पर लौटाना एक महान् सामाजिक अन्याय होता अथवा इसके लिए अथक राष्ट्रीय प्रयत्न और बलिदान की आवश्यकता पड़ती। सन् १९२५ में इङ्ग्लैंड की दशा भी ऐसी ही थी। ब्रिटिश करेंसी के मूल्य में सन् १९२५ में पूर्व ही ह्रास हो गया था। यदि ऐसे समय में इङ्ग्लैंड स्टलिङ्ग के सम-मूल्य को बढ़ाकर एक निश्चित स्तर पर स्थापित कर देता, तो उसका यह कदम तब उचित होता। किन्तु, कमेटी की राय में ब्रिटेन यदि सन् १९३१ में अवमूल्यन का निर्णय करता है, तो यह एक बिल्कुल ही भिन्न नीति अपनाने के सदृश्य होगा और इससे अन्तर्राष्ट्रीय वित्त-जगत को बहुत ठेस पहुँचेगी। कारण, जब विश्व के सबसे बड़े ऋणदाता देश की सरकार आन-बूझकर और एक नीति के

■ "Devaluation by any Government of a currency standing at its par value suddenly and without notice (as must be the case to prevent foreign creditors removing their property) is emphatically one of those things which are not expedient."

परिपालन के रूप में एक प्रातः यह घोषणा करती है कि उसने अपनी करंसी के मूल्य को 'समतता' से, जिस पर वह अभी तक स्थिर था, कानून द्वारा, कम कर दिया है तो यह एक ऐसी घटना है, जो अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को समाप्त कर देती है।

(२) सन् १९३०-३१ में जो समस्या प्रस्तुत थी वह व्यावसायिक संकटों और मूल्यों की विषयव्यापी गिरावट से सम्बन्धित थी—यह संकट मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों ही प्रकार के घटकों का परिणाम था। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होना तो अर्थार्थ में एक मामूली (minor) घटक था। व्यावसायिक मन्दी के अधिक महत्वपूर्ण (major) घटक निम्न थे—टेक्नोलॉजिकल परिवर्तनों (technological changes) के कारण लापर-स्थिति में परिवर्तन होना, ठेके मरक्षण कर लगाया जाना, जिनके कारण व्यापार के सहज प्रवाह में बाधा पड़ने लगी थी, पूँजी के विदेशी जावागमन, आदि। यदि ब्रिटेन ने, अन्य अनेक देशों की तुलना में, अधिक हानि उठाई, तो इसका कारण उस देश में कुछ अतिरिक्त घटकों का बिद्यमान होना था। अतः उस समय सही उपचार (remedy) ऐसे कदम उठाना था जिनसे कि आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हड़ता आवे, किन्तु अवमूल्यन करना उचित कदम नहीं था, क्योंकि इससे अन्य देश भी बदले के रूप में अपनी करंसीयों का अवमूल्यन कर सकते थे।

(३) प्रस्तावित अवमूल्यन एक पर्याप्त उपचार नहीं था—विश्व में कीमतें तेजी से गिर रही थी और बिदेय-माँग न्यूनतम बिन्दु तक घट गई थी। अतः ब्रिटिश मुद्रा का अवमूल्यन कमेटी की राय में, ब्रिटिश निर्यात उद्योगों की सहायता करने में या बेकारी को किसी उचित सीमा तक दूर करने में अधिक उपयोगी नहीं हो सकता था।

अतः कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि स्थिति का अवमूल्यन करने जैसा असाधारण उपाय कदम उठाने के तत्काल बाद ही जो स्थिति उदय होगी वह पूर्व स्थिति से भी कहीं अधिक सराब होगी।

सन् १९४६ की भिन्न परिस्थितियाँ—

सन् १९४६ की परिस्थितियाँ सन् १९३१ की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी और यही कारण है कि जो उपचार सन् १९३१ में अपनाये कर दिया गया था यही सन् १९४६ में स्वीकार किया गया। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित थीः—

(१) कीमतें ऊँचे स्तर पर थीं—अनेक देशों में कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की अपेक्षित कमी के कारण अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाई देती थी।

(२) इंग्लैंड का भुगतान-सन्तुलन इसके बहुत प्रतिफल था—अन्य अनेक देशों के साथ ही साथ इंग्लैंड का भुगतान-सन्तुलन भी उत्तरी और मध्य अमेरिका के साथ भारी प्रतिफल था और डॉलर की न्यूनता (Dollar scarcity) चरम सीमा पर पहुँच गई थी। सितम्बर १९४६ के पूर्व विनिमय दर १ पाँड=४०.३ डॉलर थी।

इस दर पर अमेरिकी वस्तुओं के लिये अंग्रेजी माँग वास्तव में बहुत अधिक थी और इसका भुगतान करना सम्भव नहीं था।

(३) नियन्त्रण के प्रयोग के विरुद्ध आपत्तियाँ—केवल नियन्त्रणों का प्रयोग करके ही चासू घाटे (current deficit) के बढ़ते हुए आकार को सीमित रखा जा सकता था। किन्तु आवश्यक नियन्त्रणों को ठीक से लागू करने में जो कठिनाइयाँ पैदा हुईं वह बहुत अधिक थीं क्योंकि बाजार शक्तियाँ विरोधी विद्या में सक्रिय थीं।

(४) अन्य देशों ने भी स्टैलिज़ का अवमूल्यन उचित बताया—मार्च १९४६ के अन्तिम दिनों में अमेरिका और कनाडा में अनेक व्यक्तियों को यह विचारित हो गया था कि स्टैलिज़ का अवमूल्यन करना आवश्यक है। उनकी राय में स्टैलिज़ का अवमूल्यन होने से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा एवं इसका स्तर और ठीका सुधर जायेगा।

(५) स्वर्ण कोषों में कमी होना—सितम्बर १९४६ में ब्रिटेन के स्वर्ण व डालर कोष घटकर १३४० मि० शतर रह गये थे, जोकि अगस्त १९४५ की तुलना में लगभग एक तिहाई थे। अब कोषों की स्थिति इतनी नाजुक थी कि ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी स्थिति को सुधारने के हेतु कुछ ठोस उपाय करने का अवसर नहीं रह गया था।

संक्षेप में सन् १९४६ की डालर कठिनाइयों ने यह अग्रगण्य मौद्रिक संकट उत्पन्न कर दिया कि सरकार को पीछे का १०% अवमूल्यन करना ही पड़ा। अन्य देशों ने भी ब्रिटिश कार्यवाही के एक सप्ताह के भीतर ही अपनी करेंसियों का अवमूल्यन कर दिया।

निष्कर्ष—अब सन् १९३१ और सन् १९४६ की परिस्थितियाँ बुनियादी रूप से (basically) एक दूसरे से भिन्न थीं। कमेटी ने सन् १९३१ की परिस्थितियों के सम्बन्ध में केवल यह मत प्रकट किया था कि उन दिनों अवमूल्यन करना कानूनी होते होते भी विवेक सङ्गत नहीं था। वास्तव में, सन् १९३१ में, इङ्ग्लैंड ने विदेशियों द्वारा अपने स्वर्ण कोषों के विनाश आह्वानों से विवश होकर स्वर्णमान का परिहारा कर दिया तथा पीड-स्टैलिज़ को अपना उचित स्तर खोजने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया। अन्य दृष्टी में, पीड-स्टैलिज़ का मूल्य हास होने दिया गया। लेकिन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अवमूल्यन और हास आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। इनमें अन्तर केवल यह है कि एक तो कानूनी कार्यवाही द्वारा लागू किया जाता है जबकि दूसरा वित्तीय बाजार की माँग एवं पूर्ति सम्बन्धी गतिकी की आन्तरिक प्रतिनिधि द्वारा लागू होता है।

अधिमूल्यन (Overvaluation)

जब किसी देश का मौद्रिक अधिकारी अपनी करेंसी इकाई (currency unit)

का मूल्य उस स्तर से, जो कि अन्यथा स्वातन्त्र्य बाजार में प्रचलित होता, ऊँचा रखा है, तो ऐसी स्थिति को 'करंसी का अधिमूल्यन' कहा जाता है।

करंसी के अधिमूल्यन की उचित ठहराने वाले कारण—

कोई देश अपनी करंसी का अधिमूल्यन क्यों करता है ? इसके कई कारण हैं। प्रायः सभी कारण एक ही मुख्य परिस्थिति से उदय होते हैं, जो यह कि देश के व्यापारिक सम्बन्ध इस भाँति अस्त-व्यस्त अथवा असन्तुष्ट हो जाते हैं कि स्वतन्त्र बाजार में राष्ट्रीय करंसी बहुत अधिक मात्रा में विप्रेषण के लिए प्रस्तुत की जावेगी जबकि इसके भय के लिए माँग इतनी नहीं होती। अब हम विभिन्न कारणों पर विस्तार से विचार करेंगे।

(१) अधिमूल्यन उस देश के लिए एक बाह्यनीय नीति है जिसे कि अबाधक ही विदेशों से भारी मात्रा में क्रय करना पड़े। जब देश युद्ध में सलान होता है, तो उसके लिए निर्यात करना सम्भव नहीं रहता। इसके विपरीत, उसे बहुत अनिवार्य आयात करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में, यदि विदेशी करंसी के क्रय का अधिकार कठोरतापूर्वक प्रतिबन्धित न किया गया, तो विनिमय-दर में गम्भीर गिरावट आ जायेगी। इसी प्रकार, जब युद्ध खत्म होता है, तब युद्ध अवधि में अर्थ-अवस्थाओं (economics) को अपने पुनर्निर्माण (reconstruction) सम्बन्धी कार्यों के लिए आयातों की बहुत आवश्यकता पड़ती है किन्तु साथ ही उनमें यह सामर्थ्य नहीं हाती है कि वे निर्यात उपपन्न करके इनका भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में, करंसी का बाह्य मूल्य निराने में दशा में कोई सुधार न होगा। व तो आयातों की आवश्यकता में कमी आ सकेगी और न निर्यात-क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। केवल इतना होगा कि आयात अधिक महंगे (costlier) हो जायेंगे तथा निर्यातों द्वारा इन्हें चुकता करना पहले से भी कठिन हो जायेगा। ऐसी दशाओं में, अधिमूल्यन की नीति अपनाना सरकार के लिये उचित है, क्योंकि इससे करंसी के बाह्य मूल्य में कोई तेज गिरावट (sharp fall) न आ सकेगी।

(२) जब किसी देश को विशाल ऋण और व्याज चुकाने हों तब भी अधिमूल्यन करना उचित है। इसके प्रमाण में भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दियों में भारत में अपनी विकास योजनाओं के अर्थ प्रबन्धन के हेतु इंग्लैंड से कई ऋण लिये थे। इन पर उम्मे व्याज तो देना ही पड़ता था, इसके अनिश्चित प्रति वर्ष भारत सचिव के कार्यालय के व्यय भी, जो कि होम चार्ज (Home charges) के नाम से प्रसिद्ध हैं, चुकाने पड़ते थे। ये भुगतान स्टैलिड्ड में चिये जाने थे। जब उन दिनों रुपये की पाँच में अधिमूल्यन रद्द कर भारत लाभान्वित हो सकता था।

(३) आन्तरिक मुद्रा प्रसार का नालनद करने के लिये भी एक देश अपनी करंसी को अधिमूल्यन कर सकता है। कारण, एक अधिमूल्यन करंसी मुद्रा प्रसार

को तोड़ती है। इसके निम्न तीन कारण हैं — (i) इसका निर्यातों पर असोत्साहक-कारी (discouraging) प्रभाव पड़ता है और इसने आन्तरिक आय स्तर भी कुप-भाषित होता है। (ii) यह आयातों को प्रोत्साहित करती है, और, इसलिये, व्ययों में भी वृद्धि हो जाती है, एवं (iii) यह उन विदेशी सामग्रियों की कीमतों को, जो कि उत्पादन-लागत में प्रवेश करती हैं, सस्ता कर देती है। फलतः आगत-कीमत चक्र के ऊपर उठने पर रोक लगती है।

किन्तु, जब उसी समय पर अन्य दृष्टि भी मुद्रा प्रसार का अनुभव कर रहे हों, तो सम्बन्धित आयातक देश के लिये अपनी करैसी का मूल्य बढ़ाना (appreciation) आवश्यक हो जाता है। अर्थात्, उसे चाहिये कि स्वदेशी करैसी को विदेशी करैसियों में और अधिक महंगा बनावे, अन्यथा, अधिमूल्यन के मुद्रा विस्फीतिक प्रभाव (disinflationary effects) आयातों की बढ़ती हुई लागतों से वेकार (offset) हो जायेंगे।

(४) जब किसी देश का व्यापार मुक्त एक विदेश से हो और वह विदेशी देश प्रथम देश के निर्यातों पर अत्यधिक निर्भर रहता हो, तो भी उस देश के लिये करैसी का अधिमूल्यन करना उचित कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में हम पाकिस्तान का उदाहरण दे सकते हैं। जिस समय सन् १९४६ में स्टर्लिङ्ग गुट के अन्य सब देशों ने अपनी करैसियों का अधिमूल्यन कर दिया था तब वह अकेला ही आड़ग रहा और उसने अपनी करैसी का अधिमूल्यन नहीं किया। उसका यह एकाकी कार्य इस परिस्थिति की कल्पना पर आधारित था कि पाकिस्तानी जूट के लिये भारतीय माँग बेलास (inelastic) है, जिससे पाकिस्तानी रुपये की अधिमूल्यन रखकर भारत को उसी माल के लिये पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य चुकाने के लिए विवश किया जा सकता है। दूसरी ओर, इसके आना मुख्यतः भारत और स्टर्लिङ्ग गुट के अन्य देशों में थे। अतः उसने यह विचार किया कि पाकिस्तानी रुपये का अधिमूल्यन होने से उनके आयात सस्ते (cheaper) हो जायेंगे। किन्तु पाकिस्तान अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसका कारण यह नहीं था कि उसकी नीति गलत थी बल्कि यह था कि जिस परिस्थिति को उसने अपनी नीति का आधार बनाया था वह यथार्थ में विद्यमान नहीं थी, अर्थात् पाकिस्तानी जूट के लिये भारतीय माँग उतनी लोचदार प्रमाणित नहीं हुई जितनी कि उसने समझ ली थी।

निष्कर्ष—भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता अधिमूल्यन के कारण कभी कभी और भी गहरी (chronic) हो जाती है, क्योंकि कीमतेँ स्वदेश में विदेशों की अपेक्षा ऊँची होने के कारण स्वदेश के निर्यात तो घट जाते हैं किन्तु आयातों में वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त युद्ध और दुर्लभता (scarcity) के समयों में करैसी का अधिमूल्यन उसी प्रकार में आवश्यक होता है जिस प्रकार से मदी और बाहुल्यता (plenty) के समयों में करैसी का अधिमूल्यन (undervaluation) आवश्यक है।

परीक्षा प्रश्न :

१. उन कारणों को बताइये जिनके आधार पर किसी देश की करेंसी का अधिमूल्यन करना उचित ठहराया जा सकता है ?
२. उन कारणों को बताइये जिनके आधार पर करेंसी के अधिमूल्यन को उचित कहा जा सकता है ।
३. बाह्य करेंसी के ह्रास द्वारा जो लाभ देश को होते हैं उनके स्वभाव की समीक्षा कीजिय ऐसे ह्रास से उसकी देनदार या लेनदार राष्ट्र के रूप में स्थिति कैसे प्रभावित होती है ?

[Examine the nature of the advantages accruing to a country by the depreciation of the external currency. How is her position as a debtor or a creditor nation effected by such depreciation ?]

४. "स्टर्लिंग का अधिमूल्यन करने के समान अति उत्तेजनापूर्ण कदम उठाने के फलस्वरूप मकट की जो परिस्थिति अनिवार्य रूप से उत्पन्न हो जायेगी उसमें हम यह देखेंगे कि समस्या पहिले की अपेक्षा अधिक उत्पन्न गई है ।" १९४६ में हुये पौंड के अधिमूल्यन के सन्दर्भ में इस कथन की आलोचना कीजिये ।

विनिमय नियन्त्रण

(Exchange Control)

परिचय—

प्रथम महायुद्ध काल में आर्थिक मामलों में अधिकाधिक राज्य-हस्तक्षेप के पक्ष में एक शक्तिशाली आन्दोलन विकसित हुआ, जिसने युद्ध की समाप्ति के बाद एक अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। समाजवादी एवं फासिस्ट नेता यह प्रचार कर रहे थे कि यह उनके राजनैतिक एवं आर्थिक हित में है कि कोषों के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर पूर्ण नियन्त्रण कर दिया जाय।^१ युद्धकाल में और १९२६ तक युद्ध मलग्न राष्ट्रा तथा छटस्य राष्ट्रों ने भी विनिमय का नियन्त्रण किया था। बाद में जब विभिन्न देशों ने अपनी करैसियों में स्वायत्तत्व प्राप्त कर लिया, विनिमय नियन्त्रणों में कुछ कमी आई। मई १९०६ से १९३१ तक विनिमय सम्बन्धी अधिकांश नियन्त्रण हटाये जा चुके थे किन्तु-युद्ध-पूर्व के समान विनिमय-स्वतन्त्रता नहीं लौट सकी। १९३१ की मदी में तो विनिमय नियन्त्रणों को पुनः लागू कर दिया गया तथा इसके बाद जो घटनाएँ हुईं और जो अन्ततः द्वितीय महायुद्ध में परिणित हो गईं उन्होंने ता विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी आन्दोलनों को बहुत ही उग्र बना दिया। द्वितीय महायुद्ध की अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की स्वतन्त्रता पूर्णतः समाप्त हो गई। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध लगभग 'तही' के तुल्य थे। सरकारी नियन्त्रण को कुछ तो राजनैतिक कारणों से एवं कुछ युद्ध विषयक कारणों से, उचित ठहराया जाता था। युद्धकाल में यह आवश्यक हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय-भुगतान-स्थिति पर कठोर नियन्त्रण रखा जाय। इन दिनों भुगतान-प्रतिबन्ध आर्थिक कल्याण के सहायक बन गये थे।

युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि टूटे हुए आर्थिक सम्बन्ध पुनः जोड़े जायें। किन्तु, उन्नीसवीं सदी के कई देशों ने

1 The movement toward exchange control was "the dream of Socialists and Fascists in various countries to secure complete control over the international movement of funds in the interest of their political and economic plans."—Paul Einzig : *Exchange Control*, p. 8.

सरकार नियन्त्रित आर्थिक-पुनर्निर्माण की नीति अपनाई। अधिकांश उद्ध-विकसित देश 'बनावू पूँजी निर्माण' की प्रक्रिया द्वारा अपनी अव्यवस्था का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने विनिमय-मुक्तानों पर नियन्त्रण लगाये। युद्ध के तत्काल बाद जो मुद्रा-प्रसारिक प्रवृत्तियाँ बनवती हुईं उन्होंने भी सरकारों को विनिमय पर नियन्त्रण लगाने हेतु विवश किया। इस प्रकार, सन् १९४५ से १९५० तक तृतीय अवधि में प्रतिबन्ध एक सामान्य बात हो गई और विनिमय की स्वतन्त्रता एक अपवाद (exception) मान रह गई।

सन् १९५० से प्रारम्भ होने वाली चौथी अवधि में जहाँ जहाँ विनिमय प्रतिबन्ध होने लगे थे। यद्यपि अनेक विकसित देशों ने विनिमय प्रतिबन्ध हटा लिए हैं तथापि जब हम भी प्रथम महायुद्ध के पूर्व के प्रतिबन्ध रहित युग में जैसा कि स्वर्णमान के समय में था नहीं पहुँच पाये हैं।¹

विनिमय नियन्त्रण का अर्थ

हेबरलर (Habermar) के अनुसार, 'विनिमय नियन्त्रण का आशय विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्र कार्यस्तर को समाप्त करके वहाँ राजकीय नियमन की स्थापना करना है।'² पूर्ण विनिमय नियन्त्रण (full-fledged system of exchange control) के द्वारा विदेशी विनिमय बाजारों पर पूर्ण पर-कारी नियन्त्रण स्थापित किया जाता है। निर्मातो एवं अन्य स्रोतों से जो विदेशी विनिमय प्राप्त हो वह सब विनिमय-नियन्त्रण-अधिकारियों के गुप्तुर्ब कर देना पड़ता है। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान देने-देने के कार्य सरकारी हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं। बाद में, विदेशी विनिमय की उपलब्ध प्रति का, राष्ट्रीय आवश्यकताओं में एक प्राथमिकता प्रथम (scheme of priority) के अनुसार, विभिन्न नाइसेंस, प्राप्त आयातकों में, विभाजन कर दिया जाता है। पूँजी के निर्यात प्रायः निषिद्ध (prohibited) होते हैं तथा केवल आवश्यक वस्तुओं के आयात को ही अनुमति दी जाती है। विलास एवं अनावश्यक वस्तुओं देश की आयात सूची में स्थान नहीं पाती हैं।

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य

सरकारों ने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई है। प्रमुख उद्देश्य नीचे समझाये गये हैं —

(१) पूँजी की 'दोड़' को रोकने के लिए—यदि पूँजी की, अचानक ही एक देश में दूसरे देशों में, विशाल मात्राओं में, जाने की छूट दी जाय, तो इससे उस देश के स्वर्ण व विदेशी-विनिमय-कोष एक बहुत ही अल्पकाल में खत्म हो जायेंगे।

¹ IMF, 1964 Report.

² Exchange control "is the state regulation excluding the free play of economic forces from the foreign exchange market"

—Habermar : *The Theory of International Trade*, p 83

अतः ऐसे आवश्यकताओं की विनिमय नियन्त्रण द्वारा रोकना आवश्यक है। सोशलिस्ट व फासिस्ट सरकारों ने भी इसी उद्देश्य से विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई थी।

(२) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना—विभिन्न देश, द्वितीय महायुद्ध की अवधि की भीति, विनिमय नियन्त्रण इस उद्देश्य में भी लागू करते हैं कि उनका विदेशी-मुद्रा कोष पर्याप्त बना रहे जिससे कि विदेशों से आवश्यक वस्तुओं की खरीदने में कभी कोई कठिनाई न हो।

(३) विभिन्न करैन्सियों के मध्य सम्बन्धों को स्थायी रखने के लिये—कुछ सरकारों ने अपनी इस इच्छा के कारण, कि उनकी और अन्य देशों की करैन्सियों के मध्य सम्बन्ध स्थायी बन रहे, विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किया है। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ में, जब इंग्लैंड ने स्वर्णमान का खण्डन कर दिया था तब, स्टर्लिंग-मुद्रा के सदस्य देशों ने पाउंड-स्टर्लिंग में अपनी करैन्सियों के मूल्य स्थायी रखने की दृष्टि से ही विनिमय नियन्त्रण लागू किये थे।

(४) शत्रु राष्ट्रों द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये—युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण इस दृष्टि से किया जाता था कि शत्रु देश को अथवा उसके एगेंडों को, जो कि सदस्य देशों में या स्वयं कन्ट्रोल सगाने वाले देशों में ही छिप कर रहते हैं, त्रय शक्ति का प्रयोग करने में रोक जाय। इस हेतु देश की बैंकों में शत्रु राष्ट्रों के निवासियों की जमा सम्पत्तियाँ जस्त कर ली जाती थीं।

(५) भुलभुल और ध्यान के भुगतान के लिये विदेशी करैन्सियाँ प्राप्त करना—इस उद्देश्य में भी अनेक ऋणी सरकारों को सन् १९२० और सन् १९३० की मध्यावधि में विनिमय नियन्त्रण लागू करने के लिये प्रेरित किया। चूंकि उन्हें पुराने ऋणों का भुगतान हेतु नये ऋण नहीं मिल पाते थे। अतः वे अपने निर्यात-आधिव्यय (export surplus) पर निर्भर थे, जोकि विनिमय नियन्त्रण द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता था।

(६) अपनी करैन्सियों का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करैन्सी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना सकता है। करैन्सी का अधिमूल्यन करने पर कुछ कार्य अथवा नागरिक उपभोग के हेतु आवश्यक वस्तुओं विदेशों से, सस्ती कीमत पर आयात की जा सकेंगी। विदेशी श्रम को अधिक सस्ते दम से चुकाने के लिए भी देश अपनी करैन्सी का अधिमूल्यन कर सकता है।

(७) स्वदेशी करैन्सी का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करैन्सी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रणों को लागू करने पर विवश हो सकता है, जिससे उसके निर्यात वृद्धि सकें तथा आयातों में कमी आ सके। उदाहरणार्थ सन् १९२०-३० के मध्य, इसी उद्देश्य की सामने रखकर जर्मनी और अन्य देशों ने अपने यहाँ विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये थे।

(८) विनिमय दरों में घट्यावों उत्पन्न-बढ़ाव रोकने के लिये—इस उद्देश्य

से विनिमय नियन्त्रण की नीति को विनिमय समीकरण कोष की स्थापना करने के साथ ही साथ, ब्रिटेन ने सन् १९३२ व सन् १९३६ की मध्यावधि में अपनाया था।

विनिमय नियन्त्रण के शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य—

युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण लागू करने का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों को मुख्यतः युद्ध सामग्री के त्रय की सुविधा के लिये सुरक्षित रखना है। जन्तु द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये भी विनिमय नियन्त्रण लगाये जाते हैं। इसके विपरीत शान्तिकाल में विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं पुनर्वास के लिये अति आवश्यक मन्त्रों व अन्य सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग मित-मयिता में करना है। निर्यात वृद्धि के लिये भी विनिमय नियन्त्रण किया जाता है। देखो पूर्ण को बाहर जाने में रोकने तथा विदेशी पूर्णों का आकर्षित करने हेतु भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये जाते हैं। हा, विनिमय नियन्त्रण का बिन्दु युद्धकाल में तो अधिक होता है, शान्तिकाल में उतना नहीं।

1919 विनिमय नियन्त्रण के ढङ्ग

विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न ढङ्गों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(I) प्रत्यक्ष एवं (II) अप्रत्यक्ष।

(I) विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग—

विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग (direct methods) यह है जोकि सरकारों के द्वारा, विनिमय दर पर सप्रभावि नियन्त्रण रखने के हेतु अपनाये जाते हैं। ये ढङ्ग निम्नलिखित हैं —

(१) हस्तक्षेप (Intervention)—हस्तक्षेप का अर्थ स्वदेश की करेंसी के त्रय और वित्रय के रूप में होता है। यह त्रय वित्रय कार्य सरकार या इससे अधिकार प्राप्त मस्या (जैसे केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी करेंसी के विकट, स्वदेशी करेंसी की विनिमय-दर को उठ बढ़ाना या गिराना है। हस्तक्षेप में प्रायः विनिमय दर को ऊँचा या नीचा टाँकने के कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। यदि किसी विदेश विन्दु पर विनिमय दर का बाधा (या टाँका) न जाय, तो विनिमय दर कुछ भिन्न होगी, वह नहीं जो कि टाँकन पर होती है। विनिमय दरों को किसी विन्दु पर टाँकने (peg) का आशय दरों को स्थायी रखने में है।

जब सरकार विनिमय दर को एक ऐसे ऊँचे (या नीचे) स्तर पर टाँकना (peg) चाहती है जो कि हस्तक्षेप के अभाव में, माँग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर, सम्भव नहीं है, तो यह आवश्यक है कि वह अपनी करेंसी के बदले में विदेशी करेंसी (या विदेशी करेंसियों के बदले में अपनी करेंसी) अनिश्चित समय तक देते रहने में समर्थ हो। सरकार की यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंसियों के कोष

अतः ऐसे आवागमनो को विनिमय-नियन्त्रण द्वारा रोकना आवश्यक है। सांशलिम्ब व फासिम्ब सरकारो ने भी इसी उद्देश्य ने विनिमय नियन्त्रण की नीति अपनाई थी।

(२) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध करना—विभिन्न देश, द्वितीय महायुद्ध की अवधि की भांति, विनिमय नियन्त्रण इस उद्देश्य से भी लागू करते हैं कि उनका विदेशी-मुद्रा कोष पर्याप्त बना रहे जिससे कि विदेशों से आवश्यक वस्तुयें खरीदने में कमी कोई कठिनाई न हो।

(३) विभिन्न करेंसियों के मध्य सम्बन्धों को स्थायी रखने के लिये—कुछ सरकारो ने अपनी इस इच्छा के कारण, कि उनकी और अन्य देशों की करेंसियों के मध्य सम्बन्ध स्थायी बने रहें, विनिमय-नियन्त्रण प्रचलित किया है। उदाहरणार्थ, सन् १९११ में, जब इङ्ग्लैंड ने स्वर्णमान का खण्डन कर दिया था तब, स्टर्लिङ्ग-गुट के सदस्य देशों ने पीड-स्टर्लिङ्ग में अपनी करेंसियों के मूल्य स्थायी रखने की दृष्टि से ही विनिमय नियन्त्रण लागू किये थे।

(४) शत्रु राष्ट्रों द्वारा ऋण शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये—युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण इस दृष्टि से किया जाता था कि शत्रु देश को अथवा उसके एजेंटों को, जो कि सदस्य देशों में या स्वयं बन्दोस सपाने वाले देशों में ही छिप कर रहते हैं, ऋण शक्ति का प्रयोग करने से रोका जाय। इस हेतु देश की बैंकों में शत्रु राष्ट्र के निवासियों की जमा सम्पत्तियाँ जप्त कर ली जाती थी।

(५) मूलधन और श्रम के मुक्तान के लिये विदेशी करेंसियाँ प्राप्त करना—इस उद्देश्य ने भी अनेक ऋणी सरकारो को सन् १९२० और सन् १९३० की मध्यावधि में विनिमय नियन्त्रण लागू करने के लिये प्रेरित किया। चूँकि उन्हें पुराने बकाया ऋण चुकाने हेतु नये ऋण नहीं मिल पाते थे। अतः वे अपने निर्यात-आविषय (export surplus) पर निर्भर थे, जोकि विनिमय नियन्त्रण द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता था।

(६) अपनी करेंसियों का अधिमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करेंसी का अधिमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रण की नीति अपना सकता है। करेंसी का अधिमूल्यन करने पर युद्ध कार्य अथवा नागरिक उपभोग के हेतु आवश्यक वस्तुयें विदेशों से, सस्ती कीमत पर आयात की जा सकेंगी। विदेशी ऋण को अधिक सस्ते ढंग से चुकाने के लिए भी देश अपनी करेंसी का अधिमूल्यन कर सकता है।

(७) विदेशी करेंसी का अवमूल्यन करने के लिये—एक देश अपनी करेंसी का अवमूल्यन करने के उद्देश्य से भी विनिमय नियन्त्रणों को लागू करने पर विवश हो सकता है, जिससे उसके निर्यात बढ़ सकें तथा आयातों में कमी आ सके। उदाहरणार्थ सन् १९२०-३० के मध्य, इसी उद्देश्य को सामने रखकर जर्मनी और अन्य देशों ने अपने यहाँ विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये थे।

(८) विनिमय दरो में अस्थायी उतार-चढ़ाव रोकने के लिये—दूसरे उद्देश्य

से विनिमय नियन्त्रण की नीति, जो, विनिमय समीकरण कोष की स्थापना करने के साथ ही माय, ब्रिटेन ने सन् १९३२ व सन् १९३६ की मध्यावधि में अपनाया था।

विनिमय नियन्त्रण के शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य—

युद्धकाल में विनिमय नियन्त्रण लागू करने का उद्देश्य देश के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी साधनों को मुख्यतः युद्ध सामग्री के त्रय की मुचिषा के लिये सुरक्षित रखना है। शत्रु द्वारा त्रय शक्ति का प्रयोग रोकने के लिये भी विनिमय नियन्त्रण लगाये जाते हैं। इसके विपरीत शान्तिकाल में विनिमय नियन्त्रणों का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं पुनर्वास के लिये अति आवश्यक मशीनों व अन्य साज-सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग मित-यथिता से करना है। निर्यात वृद्धि के लिये भी विनिमय नियन्त्रण किया जाता है। देशी पूँजी को बाहर जाने से रोकने तथा विदेशी पूँजी का आकर्षित करने हेतु भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किये जाते हैं। हाँ, विनिमय नियन्त्रण का विस्तार युद्धकाल में तो अधिक होता है, शान्तिकाल में उतना नहीं।

१९१० **विनिमय नियन्त्रण के ढङ्ग**

विनिमय नियन्त्रण के विभिन्न ढङ्गों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता

है—(I) प्रत्यक्ष एवं (II) अप्रत्यक्ष।

(I) **विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग—**

विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष ढङ्ग (direct methods) यह है जोकि सरकारों के द्वारा, विनिमय दर पर संप्रभाविक नियन्त्रण रखने के हेतु अपनाये जाते हैं। ये ढङ्ग निम्नलिखित हैं —

(१) **हस्तक्षेप (Intervention)**—हस्तक्षेप का ढङ्ग स्वदेश की करेंसी के त्रय और विक्रय के रूप में होता है। यह त्रय-विक्रय कार्य सरकार या इसकी अधिकार प्राप्त मण्डला (जैसे केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी विनिमय बाजार में, विदेशी करेंसी के विरुद्ध, स्वदेशी करेंसी की विनिमय-दर को हड़ बनाना या गिराना है। हस्तक्षेप में प्रायः विनिमय दर को ऊँचा या नीचा टाँकने के कार्यक्रमों भी सम्मिलित होते हैं। यदि किसी विशेष बिन्दु पर विनिमय दर को बाँधा (या टाँका) न जाय, तो विनिमय दर कुछ भिन्न होगी, यह नहीं जो कि टाँकने पर होती है। विनिमय दरों को किसी बिन्दु पर टाँकने (peg) का आशय दरों को स्थायी रखने में है।

जब सरकार विनिमय दर को एक ऐसी ऊँचे (या नीचे) स्तर पर टाँकना (peg) चाहती है जो कि हस्तक्षेप के अभाव में, माय और पुति की शक्तियों के आधार पर, सम्भव नहीं है, तो यह आवश्यक है कि वह अपनी करेंसी के बदले में विदेशी करेंसी (या विदेशी करेंसियों के बदले में अपनी करेंसी) अनिश्चित समय तक देने रहने में समर्थ हो। सरकार की यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंसियों के कोष

पर निर्भर है।^१ जबकि सरकार की विदेशी करेंसी देने की क्षक्ति उपलब्ध होप की मात्रा से सीमित होती है, स्वदेशी करेंसी देने की क्षक्ति इस तरह सीमित नहीं होती। यही कारण है कि सरकार स्वदेशी करेंसी का मूल्य नीचा टाँकने में, ऊँचा टाँकने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित स्थिति रखती है।

सन् १९३२ में जो विनिमय स्वायत्तकरण कोष (Exchange Stabilisation Funds) इंग्लैण्ड में स्थापित किय गए थे, उनका उद्देश्य पौण्ड स्टर्लिंग के मूल्य को, स्वदेशी और विदेशी करेंसियों के मध्य-विनय कार्यकलापों द्वारा, एक स्थिर दर पर टाँकना था। इन कोषों के बारे में विस्तृत विवरण इसी अध्याय में आगे दिया गया है।

(९) विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restriction)—‘विनिमय प्रतिबन्ध’ का अर्थ विनिमय बाजार में स्वदेशी करेंसी की आपूर्ति की अनिवार्य रूप से कम करना है। ऐसा कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे—अवरुद्ध खातों द्वारा बहुमुखी विनिमय दरों द्वारा, आदि। अणुदाता देशों के खातों को अवरुद्ध करने का ढङ्ग (blocking the accounts) कुछ देनदार देशों (जैसे जर्मनी) द्वारा सन् १९३१ के वित्तीय मजदूरी में अपनाया गया था। इनका उद्देश्य अपने दुर्बल विदेशी विनिमय कोषों की, जो कि विदेशी ऋणों का, यथापक ही विद्यान मात्रा में, भुगतान करने से क्षमतापूर्वक बचाव होने जा रहे थे, रक्षा करना था। यद्यपि उन्हें पूँजी के निकालने पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। इन देशों में देनदारों ने अपने विदेशी ऋणों का भुगतान, केन्द्रीय बैंक में विदेशी देय के नाम से खोले गये खातों में, चुका दिया। जो धन इस प्रकार में चुकाया गया वह अवरुद्ध कर दिया गया अर्थात्, उसे विदेशी लेनदार अपने देय की करेंसियों में परिणित नहीं कर सकते थे। इस प्रकार विदेशी लेनदारों को बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि वे अपने द्रव्य का इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकते थे।

बहुमुखी विनिमय दरें (Multiple exchange rates) के अन्तर्गत, विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए पृथक्-पृथक् विनिमय दरें नियत कर दी जाती हैं। इसका उद्देश्य दुर्लभ विदेशी मुद्रा की आय को अधिक से अधिक बढ़ाना है,

- १ “A government that is ‘pegging’ its currency must be in a position to pay out foreign currencies and receive its own currency; a government that is ‘pegging down’ its currency must be in a position to pay out its own currency and receive foreign currencies, and both must be prepared to go indefinitely unless they want either to resort to restriction or to fail in their purpose of controlling the rate of exchange.”

—Geoffrey Crowther : *An Outline of Money*, p 249

जो निर्यात को बड़ाकर तथा आयात घटाकर ही सम्भव है। लगभग ५० देशों ने एक या दूसरे ढंग से बहुमुखी बिनिमय दरो का प्रयोग किया है।

(३) बिनिमय निकासी सम्झौते (Exchange Clearing Agreements)— इस श्रुति का प्रयोग सन् १९२०-३० के मध्य अनेक योरोपीय देशों ने अपनी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को घटाने के हेतु किया था। बिनिमय नियन्त्रण के इस ढंग में विभिन्न देशों के व्यापारियों के पारस्परिक भुगतानों के आदान-प्रदानों का सन्तुलन करता उन देशों के केन्द्रीय बैंकों की जिम्मेदारी बन जाता है। A देश का केन्द्रीय बैंक B देश के केन्द्रीय बैंक के नाम में अपने धन खाता खोल देता है। A देश में कुछ व्यक्ति B देश के लेनदार और कुछ व्यक्ति B देश के देनदार होते हैं। A देश के देनदार 'अर्थात् आयातकर्त्ता' अपने विदेशी भुगतान अपने केन्द्रीय बैंक में जमा करा देंगे, जो फिर A देश में लेनदारों (निर्यातकर्त्ताओं) को स्वदेशी करैसी में ही भुगतान कर देगा। इसी प्रकार B देश में केन्द्रीय बैंक A देश के केन्द्रीय बैंक के नाम से अपने वहाँ एक खाता खोलता है। B देश में देनदार (आयातकर्त्ता) अपने विदेशी दायित्वों का भुगतान केन्द्रीय बैंक में जमा करा देंगे जो फिर इसमें से B देश में लेनदारों (निर्यातकर्त्ताओं) को स्वदेशी करैसी में भुगतान कर देगा। संक्षेप में आयातकर्त्ता अपने आयातों का मूल्य एक केन्द्रीय खाते में जमा कराते हैं और फिर इन रकमों का प्रयोग स्वदेश के निर्यातकर्त्ताओं को भुक्ताने हेतु किया जाता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्झौते कुलंभ विदेशी बिनिमय की चिन्ता किये बिना ही पूर्ण होते रहते हैं।

स्पष्टता, प्रस्तुत, योजना के अन्तर्गत, आयात और निर्यात व्यापार के सञ्चालन का कार्य पूर्णतः केन्द्रीय बैंकिंग अधिकारी के हाथों में दे दिया जाता है और उस पर राज्य का कठोर नियन्त्रण होता है। यही नहीं, उक्त योजना में यह मानकर चला जाता है कि सम्बद्ध देश अपने व्यापारिक कार्य-कलापों को इस ढंग से सञ्चालित करेंगे कि उनके कुल आयात मूल्य और कुल निर्यात मूल्य आपस में सन्तुलित हो जावे ताकि भुगतानों के लेने-देने की आवश्यकता ही न पड़े।

यद्यपि विमुक्त बिनिमय हस्तक्षेप की तुलना में बिनिमय निरामि की टेक्नीक श्रेष्ठ है क्योंकि यह बिदब व्यापार के प्रसार को उत्साहित करती है तथापि इसकी निम्न प्रमुख दुर्बलतायें भी हैं — (i) चूँकि इसमें एक देश को अन्य देशों से वस्तुओं खरीदने की छूट नहीं होती, वरन् वह दूसरे देश से, जोकि सम्झौते का पक्ष है, खरीदने के लिए विवश होता है इसलिए इनमें जो देश आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं वे उन देशों का जो आर्थिक दृष्टि से दुर्बल हैं, शोषण करने लगते हैं (ii) अपने द्विपक्षी स्वभाव के कारण बिनिमय निकासी सम्झौते व्यापार को असाधारण दिशाओं में मोड़ देते हैं तथा सम्झौते वाले देशों की, उन देशों के हितों को बलिदान पर, जो कि सम्झौते में सम्मिलित नहीं हैं, लाभ पहुँचाते हैं, (iii) वे विदेशी व्यापार की मात्रा को भी घटा देते हैं और विदेशी-बिनिमय में हस्तक्षेप करते हैं, (iv) निर्यातकों को

भुगतान मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके देश का केन्द्रीय बैंक उन्हें सब ही भुगतान देता है जबकि उसे विदेशी आयातकर्त्ताओं से, निर्यातकर्त्ताओं के लिए भुगतान मिल जाय, एवं (v) सभी प्रकार के विदेशी विनिमय सम्बन्धी भुगतान 'केन्द्रित' रखने पड़ते हैं अन्यथा यह योजना सफल नहीं हो सकती है।

(४) भुगतान समझौते (Payment Agreements)—विनिमय नियन्त्रण का यह ढंग विनिमय निकासी समझौते की योजना के अन्तर्गत अनुभव को गई कुछ कठिनाइयों के निवारणार्थ प्रचलित किया गया था। उदाहरणार्थ, भुगतान विषयक विलम्ब का दोष इस नवीन रीति के अन्तर्गत सहज ही खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों देश परस्पर साख-मुविधायें स्थापित कर लेते हैं। किन्तु भुगतान समझौते की निम्न दो दुर्बलतायें भी हैं—(i) साइगेन्स-प्राप्त भुगतानों के सम्बन्ध में समझौता-खाना को केवल डेबिट या क्रेडिट ही किया जा सकता है, (ii) खातों में यदि कोई गेप अदत रह जाय, तो उसका प्रयोग एक ही साकेदार द्वारा दूसरे साकेदार से वस्तुयों के रूप में ही किया जा सकता है।

(५) अन्तरण विलम्ब काल (Transfer Moratoria)—विनिमय नियन्त्रण के इस ढंग में विलम्बकाल में विदेशी लेनदारों या निर्यातकों को भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। इस उपाय का प्रयोग करके सरकार भुगतानों की समस्या का एक अस्थायी समाधान खोजने में सफल हो जाती है। आयातक औद्योगिकी अपने देश की करेंसी में भुगतान करते हैं, जो एक अधिकृत बैंक के पास डिपॉजिट रहते हैं। विलम्बकाल की समाप्ति के बाद, जिसमें सरकार विदेशी विनिमय की समस्या को हल करके अपनी स्थिति सुधार लेती है, वे डिपॉजिट्स विदेशी निर्यातकों और लेनदारों के प्रति मुक्त कर दिये जाते हैं। महान मन्दी के युग में यूरोप के अनेक देशों ने अपने राष्ट्रजनों द्वारा विदेशी लेनदारों और निर्यातकों को भुगतान भेजने पर विलम्बकाल सम्बन्धी आदेश जारी किये थे।

(६) स्वर्ण नीति (Gold Policy)—स्वर्ण के त्रय और बिक्रय की कीमतों में फल (Manipulate) करके भी विनिमय नियन्त्रण प्रचलित किया जा सकता है। ऐसे उपाय विनिमय दरो की स्वर्ण-किन्दुओं के माध्यम से प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९३६ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने स्वर्ण के त्रय बिक्रय की कीमतों को एक सहज स्तर पर नियत करते हुए विनिमय दरो के नियन्त्रण का प्रयास किया।

(II) विनिमय नियन्त्रण के अप्रत्यक्ष ढङ्ग—

विनिमय नियन्त्रण के अप्रत्यक्ष ढंग वे हैं जो कि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन को नियमनित करने हेतु अपनाये जाते हैं। ऐसे ढंग बिम्बलिसित हैं—

(१) ध्यान बरों में परिवर्तन—जिती देश में व्याज दर बढ़ने से वहाँ विदेशों से दीर्घकालीन निवेश बढ़ने लगे हैं और स्वदेशी निवेशों तक भी देश में ही अपनी पूँजी लगाते हैं। इससे स्वदेशी बरेंसी के लिए माँग बढ़ जाती है और परिणाम-

स्वरूप विनिमय दर इसके पथ में हो जाती है। सन् १९२४ और सन् १९३० के मध्य जर्मनी ने इसी तरह में विशाल कोष आकर्षित किये थे।

(२) आयात कर—सुरक्षण कर तथा कोटा-निर्धारण अप्रत्यक्ष विनिमय नियन्त्रण के प्रमुख साधन हैं। किन्तु, आयात कर विनिमय दरों का नियन्त्रण करने तथा घरेलू उद्योगों को सुरक्षण (Protection) प्रदान करने इन्हें प्रोत्साहित करने हेतु भी लगाये जा सकते हैं। केवल पहली बात में ही, जबकि इन्हे विनिमय दरों पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से लगाया जाय, विनिमय नियन्त्रण का उग मानता चाहिए।

(३) निर्यात सहायता—निर्यात सहायता भी विनिमय नियन्त्रण का एक उग है। आयात करों के सहज्य इसे भी विनिमय नियन्त्रण का उग सब ही समझा जाता चाहिए जब कि यह विदेशी विनिमय की दृष्टि से दी जाय। यदि केवल निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य में ही दी जा रही है तो इसे विनिमय नियन्त्रण का साधन नहीं मानना चाहिए।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विनिमय नियन्त्रण के प्रत्येक ढङ्ग में अपने-अपने गुण-दोष हैं। अतः किसी विशेष परिस्थिति में कौनसा या कौन से ढङ्ग अपनाने जायें इसका उत्तर उस परिस्थिति की समस्त विशेषताओं का विचार करने के बाद ही दिया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि विनिमय दरों पर प्रभावशाली नियन्त्रण करने में हेतु प्रायः एक से अधिक ढङ्गों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है।

विनिमय समानीकरण कोष

विनिमय समानीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund or Account)) सम्पत्तियों का यह संग्रह है जो कि विनिमय दरों के अवाञ्छनीय परिवर्तनों को रोकने हेतु विनिमय बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता नियन्त्रण के अधीन रखा जाता है।

कोष के उद्देश्य—

प्रथम महायुद्ध के बाद स्वर्णमान की पुनः स्थापना तो हो गई लेकिन वह पहले की भांति सहज ढङ्ग से कार्य न कर सका। कारण, प्रथम महायुद्ध के बाद की परिस्थितियों युद्ध पूर्व परिस्थितियों से बहुत भिन्न हो गई थी तथा देशों द्वारा स्वर्णमान के सेल के नियमों का पालन नहीं किया गया था। फलतः इंग्लैंड ने सितम्बर १९३१ में इसका परित्याग कर दिया। स्वर्णमानों के परित्याग के बाद स्टर्लिंग की विनिमय दरों में बहुत उतार-चढ़ाव होने लगे, जिन्हें रोकने हेतु इंग्लैंड ने ब्रिटिश ट्रेजरी के मन्त्रालय प्रबन्ध में एक विनिमय समानीकरण कोष स्थापित किया।

कोष का संचालन—

कोष के साधनों में सरकार द्वारा प्रचलित ट्रेजरी बिल्स और खुले बाजार व अन्य देशों की केन्द्रीय बैंकों से खरीदा गया सोना सम्मिलित था। प्रारम्भ में

सरकार ने कोप को १७५ करोड़ पौण्ड के बिलस दिए (जिनकी राशि सन् १९३७ तक ५७५ करोड़ पौण्ड हो गई)। इन्हें प्रति तीन माह के बाद रिन्यू कराया जाता था।

जिन दिनों व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता के कारण लन्दन में विदेशी कोपो (स्वर्ण महित) के विप्रास आगमन होते थे, उन दिनों 'कोप' स्टलिङ्ग देकर इन्हें खरीद लिया करता था, और भविष्य में, जब अदृश्य या दृश्य निर्यातों के मुग्तान में लन्दन पहुँचने वाले विदेशी कोपो (मुद्रा व स्वर्ण) की चालू पूर्ति की तुलना में इनकी माँग अधिक होने लगती थी (जिससे स्टलिङ्ग की विनिमय दर में गिरावट का खतरा पैदा हो जाता था) तो कोप संचित विदेशी मुद्रा का विनय करके स्टलिङ्ग मूल्य को गिराने में बचाता था।

आरम्भ में कोप स्टलिङ्ग के बदले में डालर खरीदता था क्योंकि सन् १९३३ तक यह स्वर्ण में परिवर्तनशील था। सन् १९३३ में अमेरिका ने भी स्वर्णमान छोड़ दिया। तब कोप फ्रांसीसी फ्रैंक खरीदने लगा। किन्तु फ्रांस भी सन् १९३६ में स्वर्णमान से हट गया। तत्पश्चात् इङ्ग्लैंड, फ्रांस एवं अमेरिका ने आपस में एक मौद्रिक समझौता किया जिसके आधीन प्रत्येक सदस्य देश को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह दूसरे देश की प्राप्त-मुद्रा को, २४ घण्टे के अन्दर, उस देश की केन्द्रीय बैंक में सौंपे म बदल ले।

कोप की सीमायें—

कोप के साधन सीमित होते थे। यत वह स्वदेशी और विदेशी करेंसियों की सापेक्षिक कीमती को केवल कुछ सीमाओं के अन्दर ही प्रभावित कर सकती थी। उदाहरण के लिए यदि विदेशी मुद्रा के लिए माँग, इसकी पूर्ति की तुलना में, लगातार अधिक डनी रहे, तो कोप बहुत दिनों तक विनिमय दर को गिरने से नहीं बचा सकता था क्योंकि धीरे-धीरे उसके स्वर्ण एवं विदेशी मुद्रा कोप खाली हो जायेंगे तथा केवल स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ ही संप्रभु में शेष रह जायेंगी। [हा, विपरीत दिशाई गिनियों का सामना करने की कोप की क्षमता अधिक थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा का प्रय करने के लिए सरकार कोप को स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ अधिकाधिक मात्रा में दे सकती थी।] दूसरे कोप की आयप्रणाली को बहुत गुप्त रखा जाता था तथा वह जटिल भी थी। तीसरे, इससे सटीरियों के कार्यकलापों को बहुत ठेरा पहुँची।

बहु विनिमय दरें (Multiple Exchange Rates)

सद्वृत्तियों विनिमय दर प्रणाली का प्रयोग सर्व-प्रथम जर्मनी में किया गया था। इसके बाद चिली, अर्जेन्टाइना, ब्राज़िल, ग्रीस इक्वेडोर आदि देश आते हैं। विनिमय प्रतिबन्ध के इस रूपान्तर के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के व्यवहारों और विभिन्न देशों में व्यवहारों के लिए पृथक्-पृथक् विनिमय दरें निर्धारित की जाती हैं।

दो प्रकार की बहु दरें -

इन प्रकार, बहु दरें दो प्रकार की होती हैं—एक तो वे बहु दरें जो कि आयात

और निर्यात व्यवहारों के विभिन्न समूहों के लिये होती है, और, दूसरी वे बहुत दूरे जो कि एक देश की अपेक्षा दूसरे देशों को लागू होती है।

(१) व्यवहारों के विभिन्न समूहों के लिये पृथक-पृथक दरें—अनेक देशों में विभिन्न समूहों के व्यवहारों के लिये पृथक-पृथक दरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ १९१६ में अर्जेन्टाइना में निम्न चार पृथक दरें मान्य थीं—सरकारी निर्यात दर १ पीड = १५ पिसोस, रेलवे प्रेषण दर १ पीड = १५ ७५ पिसोस, सरकारी आयात दर १ पीड १७ ८२ पिसोस तथा स्वतन्त्र दर १ पीड = १५ पिसोस। विभिन्न व्यवहारों के लिये विभिन्न दरें नियत करके अधिकारीगण लागतो और कीमतों को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। जैसे गेहूँ के आयात के लिये उन्हीं दर निश्चित करके स्वदेशी रोटी की कीमत को नीचा रखा जा सकता है। इस प्रकार, गेहूँ की लागत को नीचा कर डबल रोटी के उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(२) विभिन्न देशों के लिये पृथक-पृथक दरें—विभिन्न देशों की करसिद्धी के सम्बन्ध में भी बहुत विनियम दरों को व्यवस्था की जा सकती है, जिससे देश एक करसिद्धी के साथ ऐसी विनियम दर रख सकें जो दूसरी करसिद्धी के साथ विनियम दर में जो कि इन करसिद्धी के मध्य सरकारी दर द्वारा निर्धारित होती है, भिन्न हो। उदाहरणार्थ, जब डालर स्टलिङ्ग दर १ पीड = ४ डालर है, और भारत स्टलिङ्ग के साथ २० १० = १ पीड दर रखता है तो डालर और स्टलिङ्ग के मध्य निर्धारित सरकारी दर की अनुसारता में रुपये और डालर के मध्य साधारणतः ५ २० - १ डालर की दर होगी चाहिए थी। किन्तु बहुत दर प्रणाली के अन्तर्गत यह ६ रुपये = १ डालर रखी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय करसिद्धी पीड की अपेक्षा डालर में अवमूल्यित (undervalued) है। यह स्थिति इस प्रकार उदय हो सकती है कि कुछ करसिद्धियों के साथ विनियम दरें नियमित रखी जायें, जब कि अन्य करसिद्धियों में बाजार को स्वतन्त्र रहने दिया जाय। ऐसी पद्धति देश के आयात निर्यात व्यापार की दिशा को नियन्त्रित करने हेतु अपनाई जा सकती है। अतः, जब भारतीय रपया पीड की अपेक्षा डालर में अवमूल्यित होता है, तब देश के निर्यात बाजार देशों को मुक्त जाते हैं किन्तु अधिकांश आयात स्टलिङ्ग देशों से प्राप्त होते हैं।

बहु विनियम दरों के उद्देश्य —

बहु विनियम दरों के निम्न उद्देश्य होते हैं —

(१) विनियम नियन्त्रण के उद्देश्यों को पूर्णरूपेण प्राप्ति के लिये—प्रायः बहु दर, जिस पर विदेशी विनियम अधिकारियों के सुपुर्ब किया जाता है, उस दर से, जिस पर कि यह अपने उपलब्ध होता है, नीची रखी जाती है। इससे देश के विदेशी विनियम प्रभावकों का बपधाय नहीं होता।

(२) सरकार को घरेलू धन्य—बहु विनियम दर प्रणाली के अन्तर्गत, कृत्रिम

मुद्रा अधिकारी द्वारा विदेशी विनिमय की क्रय और विक्रय दरों में माजिन रखा जाना^१ इसलिए सरकार को यथेष्ट लाभ होता है। यह लाभ तब और भी महत्वपूर्ण होता है जबकि विदेशी कम्पनिया अपने मूल देश की लाभ राशियाँ प्रेषित करने के हेतु विदेशी विनिमय खरीदती हैं।

(३) सरक्षण देने के लिए—बहु दरों का एक सरक्षणायक पहलू भी है—कुछ वस्तुओं के आयात के लिए अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी विनिमय को महँगा बना कर कुछ उद्योगों को संरक्षण दिया जा सकता है। [चिन्तु याद रह कि इस उपाय से मुद्रा प्रसारक प्रभाव बढ़ सकता है क्योंकि आयातों पर प्रतिबंध लगने से कीमतों में वृद्धि हो जाती है।] इसके विपरीत आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहन देने हेतु इनके लिए दरें नाफी रखी जाती हैं। बहु दरों के सरक्षणायक प्रभाव के कारण देश में अनावश्यक और विनाश वस्तुओं के उद्योगों का विकास होने लगता है। क्योंकि सामान्यतः इन्हीं वस्तुओं के आयात के लिए विनिमय दरें समान ऊँची रखी जाती हैं।

(४) विभिन्न देशों के मध्य वेद भाव भरतने के लिये—बहु विनिमय दरों का प्रयोग विभिन्न देशों के प्रति इनके साथ देश के भुगतान सन्तुलन की स्थिति की भिन्नता के अनुसार भेदात्मक व्यवहार करने के लिए भी किया जाता है। उन देशों के आगमनों को जिनके साथ देश का भुक्तुल सन्तुलन है, उनकी करैन्सियों के लिए नाफी दरों की अनुमति देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके विपरीत, जिन देशों के साथ देश का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन है उनसे ऊँची दरें रखकर आयातों को निरुत्साहित किया जाता है।

(५) कुछ वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए—आयातों की भाँति निर्यातों के सम्बन्ध में भी बहु दरों का प्रयोग कुछ वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित और कुछ वस्तुओं के निर्यात को निरुत्साहित करने हेतु किया जा सकता है। यह युक्ति कुछ देशों को निर्यातों के प्रोत्साहन एवं अन्य देशों का निर्यातों के अग्रोत्साहन द्वारा निर्यातों को बाह्यनीय दिशा प्रदान करने के लिए भी प्रयोग की जा सकती है।

(६) स्वदेश की करैन्सी का अवमूल्यन करने के लिए—कभी-कभी देश की करैन्सी का अवमूल्यन करने के एक ढङ्ग के रूप में भी बहु विनिमय दरें प्रयोग की जा सकती हैं। जब ऊँचे विनिमय दर की शर्तियों में वस्तुओं की मूल्य बढ़ाई जाती है, तो एक प्रकार से रँगता हुआ अवमूल्यन दृष्टिगोचर होता है। इसका उद्देश्य स्पष्टतः भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति को सुधारना है।

(७) अदृश्य निर्यातों को प्रोत्साहित और अदृश्य आयातों को निरुत्साहित करने के लिये—बहुमुखी दरें प्रयोग करने वाले अनेक देशों में अदृश्य निर्यात और आयात स्वतन्त्र बाजार दरा पर जोकि सबसे ऊँची होती हैं, होने दिए जाते हैं। इसमें विदेशी पर्यटक प्रोत्साहित होने हैं क्योंकि उन्हें अपनी करैन्सिया के बदले में

देश की अधिकतम भावा में करेसी मिल सकती है, किन्तु देश से राष्ट्रजनों का जाना हतोत्साहित होता है, जिसे विदेशी विनिमय की वचत होती है।

बहु विनिमय दरों के पुन-सोच—

बहु विनिमय दरों का लाभ इन्हे अपनाने वाले देश के दृष्टिकोण से यह है कि इससे परिमाणात्मक प्रतिबन्ध और साइकेल्स वृद्धि नहीं अपनायी पड़ती है। अन्य शब्दों में, पुंति पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों द्वारा आयातों का राशनिष्ठा करने के बजाय, लागत या कीमत द्वारा मात्रा का राशनिष्ठा किया जाता है। ऐसी दर देश में आयातों को निरस्तारहित और निर्यातों का प्रोत्साहित करती है। तथा, इस प्रकार देश के लिये एक अनुकूल मुद्रागत संतुलन प्राप्त करना सुगम हो जाता है।

किन्तु बहु विनिमय दरों के सोच भी है जोकि निम्न प्रकार है—

(१) अतिविवेकता उत्पन्न करना—बहु विनिमय दरों के कारण विदेशी व्यापार में अतिरिक्त जटिलता उत्पन्न हो जाती है और यदि ये दरें स्वयं हों, या आयात और निर्यात की जान वाली वस्तुओं की सूची में परिवर्तन होता रहे तो, फिर अति-विवेकता भी उत्पन्न हो जाती है।

(२) प्रसाधनों का अनाधिक शोषण—विश्व की आर्थिक सम्पत्तियों की दृष्टि से बहु विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत देशों के और शेष विश्व के प्रसाधनों का अनाधिक (uneconomic) शोषण होता है, क्योंकि इन दरों के प्रयोग के कारण विश्व व्यापार अ-प्राकृतिक (unnatural) दिशाओं में प्रवाहित होने लगता है।

(३) नियोजित विकास में बाधा—बहु विनिमय दरें देशों के नियोजित आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं तथा अनेक वस्तुओं के लिए, जो कि देश में ही सुगमतापूर्वक उत्पन्न की जा सकती थीं, देशों की विदेशी आपूर्तियों पर निर्भर बना देती हैं। उदाहरणार्थ, ब्रिटीश १९३० में कृषि-वस्तुओं के एक शुद्ध निर्यातक से १९४० में शुद्ध आयातक में परिणत हो गया। कारण, बहु दरों की प्रणाली के अन्तर्गत वहाँ नीची दरों पर आवश्यक खाद्यान्नों के आयात को प्रोत्साहित किया गया, जिससे स्वयं देश के अन्दर कृषि के विकास पर से ध्यान हट गया और अन्ततः बहु विदेशों से आयात पर ही निर्भर रहने लगा।

यद्यपि बहु विनिमय दरें अनेक देशों की आर्थिक नीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनका हट विरोधी है। वह सदस्य देशों को दन्ते न अपनाने का परामर्श देता रहता है। उसने ऐसे सदस्य-देशों को, जो पहले से ही बहु दरें अपनाये हुए थे, केवल सन्तुलन प्राप्त के लिए ही ऐसी दरें जारी रखने की अनुमति दी है।

विनिमय नियन्त्रण के सुप्रभाव

विनिमय नियन्त्रण का समर्थन उन परिस्थितियों के आधार पर दिया जाता

है जिन्होंने इसे अपना लेने के लिए प्रेरणा दी थी। ये परिस्थितियाँ अथवा विविध नियन्त्रण के गुणभाव निम्नलिखित हैं —

(१) पूँजी की दौड़ पर नियन्त्रण—विनिमय नियन्त्रण पूँजी के निष्क्रमण (flight of capital) की समस्या के हल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने यह आपत्ति उठाई है कि विविध नियन्त्रण पूँजी के आयात को भी तो रोक देते हैं। लेकिन हमारी सम्मति में यह आपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि विचाराधीन परिस्थितियों में, जबकि पूँजी देश से भाग रही है, यदि पूँजी जाने की आशा बचापि नहीं की जा सकती है। कोई मूर्ख विदेशों ही वहाँ इन परिस्थितियों में नया निवेश करना पसन्द करेगा।

(२) मन्दी की अवधि में दीर्घकालिक निष्क्रिय भुगतान-संतुलन का उपचार—यदि किसी देश का भुगतान सन्तुलन मन्दी काल में एक दीर्घकाल से निष्क्रिय बला आ रहा है, तो विविध-नियन्त्रण ही इसका एक मात्र प्रभावशाली उपचार है। कारण, इसके अन्तर्गत देश अपने यहाँ फैली हुई बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए स्वतन्त्र नीतियाँ अपना सकता है।

(३) विद्योजित विकास में सहायक—जो देश युद्ध में सफल हैं या जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करने हेतु नियोजन विधि अपनाई है, उनके लिये विनिमय-नियन्त्रण एक ऐसा प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा वे अपने सीमित विदेशी विनिमय साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकते हैं। यही नहीं, विनिमय नियन्त्रण अनेक उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है, व्यापारिक सौदेबाजी में देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाता है और सरकार को भी विदेशी विनिमय के जय विजय से अतिरिक्त भय हो जाता है।

विनिमय नियन्त्रण के कुप्रभाव

किसी देश के हितों की प्रतिबल भुगतान सन्तुलन के प्रभावों से सुरक्षित रहने के एक उपाय के रूप में विनिमय-नियन्त्रण की पद्धति का पुनर्विचार करने से हम इस अकाष्ठ निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इसे अपनाने वाले देश की अर्थव्यवस्था के लिए और सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए भी विनिमय नियन्त्रण के परिणाम हानिकारक होने हैं और वे निम्नलिखित हैं—

(१) देश के उत्पादन और उपभोग का स्वल्प बदल जाता है। विनिमय नियन्त्रण अपनाने वाले प्रत्येक देश की आयातकों, पर्यटकों और श्रमियों से विदेशी मुद्रा का वितरण करना पड़ता है। मौनसी और कितने परिमाण में वस्तुएँ आयात की जायेंगी इस सम्बन्ध में निर्णय लेने पड़ते हैं और ऐसे निर्णय उत्पादन और उपभोग सम्बन्धी योजनाओं को बहुत प्रभावित करते हैं।

(२) घूसखोरी और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। अन्य सभी प्रकार के नियन्त्रणों की भाँति विविध नियन्त्रण भी बौकरसाही के लिए 'स्वर्ग' है। यह घूस-खोरी और पक्षपात के लिए अवसर प्रस्तुत करता है तथा जनता के नैतिक स्तर को

गिरता है। व्यापारियों के लिए यह अनेक अगुविधाओं का स्रोत है, क्योंकि लाइसेन्स प्राप्त करने की कार्यविधि प्रायः जटिल और समय व शक्ति का अप-व्यय कराने वाली होती है।

(३) व्यापार स्वाभाविक दिशा से मोड़ कर कृत्रिम दिशाओं में संचालित किया जाता है। यदि विनिमय नियन्त्रण को अनेक देश अपनाते हैं तो देश-क्रम से राशनिंग (country-wise rationing) करना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विनिमय नियन्त्रण वाले देश की करंसी स्वतन्त्रतापूर्वक उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरणार्थ, देश 'अ' एक अन्य देश 'ब' से जहाँ कि विनिमय नियंत्रण प्रचलित है, भाने व करंसी के कोष की सीमा तक ही आयात कर सकता है। मान लीजिए देश अ को एक वस्तु देश ब से आयात करनी है, किन्तु ब की करंसी अ देश के केन्द्रीय कोष में उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में अ देश ब देश पर इस बात के लिए जोर देगा कि वह अ देश की करंसी में ही उस वस्तु का भुगतान स्वीकार कर ले। सम्भव है कि बाजारों के समुच्चय के भय से ब देश उक्त अनुरोध को मान ले। चूंकि ब देश में अ देश की वस्तुओं के लिए माँग कम है (तब ही तो अ देश को ब करंसी का अभाव प्रतीत हुआ), इसलिए ब देश के केन्द्रीय कोष में एक अवरोध भेज (blocked balance) उदय हो जाता है। अब वह इस बैलेंस को प्रयोग करने के लिए अ देश में कम करने की चेष्टा करता है चाहे वस्तुएँ मँहगी ही नयी न मिलें। इस प्रकार, तुलनात्मक लागतें नहीं बरद 'अवरज भेज' ही विदेशी व्यापार की दिशा को निर्धारित करने लगते हैं जिससे कि व्यापार सर्वाधिक लाभ वाली दिशाओं में प्रवाहित होने में बाधित हो जाता है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। कभी-कभी कहा जाना है कि विनिमय नियन्त्रण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी आ जाती है। कारण, प्रायः विनिमय नियन्त्रण देश अपने आयातों को घटाता है तथा भ्रान्तरिक कीमतों का स्तर ऊँचा होने के कारण उनके निर्यात भी कम हो जाते हैं। इसके विरुद्ध यह मत प्रगट किया गया है कि समझौतों, ब्राइवेट क्षतिपूर्ति बहुमुखी विनिमय दलों, निर्यातों की आर्थिक सहायता आदि के द्वारा व्यापार को बढ़ाने का यत्न किया जाता है। स्पष्टतः हम विनिमय नियन्त्रण के विषय में कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, किन्तु यह निश्चिततापूर्वक कह सकते हैं कि व्यापार अपने स्वाभाविक मार्ग से मोड़ कर कृत्रिम मार्ग पर चलाया जाता है। सम्यक् के अतिरिक्त अन्य घटक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे 'परिमाण' में वधो आवे या नहीं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 'गुण' अक्षय हो खराब हो जाता है तथा इस सीमा तक व्यापार के लाभ में कमी आ जाती है।

(५) विनिमय नियन्त्रण सम्पर्कता से विस्तृत होता है। एक बार कुछ देशों द्वारा अपनाये जाने पर इसमें फैलने की प्रवृत्ति रहती है क्योंकि विनिमय-नियन्त्रण देश अपनी सौदा शक्ति का, जो कि उन्हें विनिमय नियन्त्रण ने प्रदान की है, अधिकतम

लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरे, विनिमय-नियन्त्रक-देश की करैसी का विनिमय भूल जाँचा हो जाता है और जब अन्य करैसियाँ ऊँची हो रही हों, तब ऊँची विनिमय दर के साथ व्यापार करना अधिक आसान होता है। तीसरे, विनिमय नियन्त्रण वाले देशों में आपस में व्यापार बढ़ जाता है, क्योंकि वे अपने व्यापार को स्वतन्त्र विनिमय वाले देशों से विनिमय नियन्त्रण वाले देशों की ओर मोड़ लेते हैं। इसीलिये स्वतन्त्र विनिमय देश भी अन्त में अपने प्रमुख बाजारों को खोने की बजाय नियन्त्रण-गुट में सम्मिलित होता पसन्द करते हैं।

(१) एक बार अपना लेने पर यह फिर छूटने का नाम नहीं लेता। उदाहरणार्थ जर्मनी ने १९३१ में पूँजी के निष्क्रमण को रोकने के लिए विनिमय नियन्त्रण अपनाया था। बाद में इसने व्यापार पर नियन्त्रण का रूप ले लिया।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय विनियोगों के सहज प्रभाव पर रोक। अन्तर्राष्ट्रीय विनियोग विदेश के आर्थिक प्रसाधनों के नियोजित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। किन्तु विनिमय नियन्त्रण इनके मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न करके इनके प्रवाह को अवरोध कर देता है।

(८) आर्थिक राष्ट्रवाद का विस्तार—विश्व के आर्थिक कार्यक्रमों पर आर्थिक राष्ट्रवाद (economic nationalism) का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे अन्ततः युद्ध तक हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक देश अपने ही राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का यत्न करता है।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का कत्ता घुटका—विनिमय नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का गम्भीर घोटता है, क्योंकि बहु पक्षी व्यापार प्रणाली और करैसियों की स्वतन्त्र परिवर्तनीयता समाप्त होकर द्विपक्षी व्यापार व्यवस्थाओं और करैसियों की अपरिवर्तनीयता का उदय होता है। इससे व्यापार का लाभ भी कम हो जाता है।

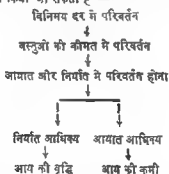
उपसंहार—

जिससे विनिमय-नियन्त्रण स्वतन्त्र व्यापार और अधिकतम विश्व सम्पन्नता के अन्तर्राष्ट्रीय आदर्श से हटने के सूचक है। किन्तु जिस प्रकार एक देश के अन्तर प्राद्वैत और सामाजिक हितों में विरोध पाया जाता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी यह विस्तृत सम्भव है कि अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए प्रयत्नशील होना राष्ट्रीय हित के विपरीत हो। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि विनिमय नियन्त्रण मौद्रिक यंत्र का एक ऐसा हिस्सा बन जाय, जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो सके। किन्तु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों के विरोध को घटाने के लिए यह आवश्यक है कि विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी उचित नियमों की एक संहिता बनाई जाय। पर्याय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसी उद्देश्य में बनाया गया था। अन्य बातों में अनिश्चित, वह प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय ह्रासों को रोकता है तथा केवल समायोजन काल में ही विनिमय-नियन्त्रण (चाहे उनका मुद्रा भी रूप हो) के लिए छूट देता

है। इसी आशय से वह आवश्यकता वाले देशों को ऋण भी देने को तत्पर रहता है, जिससे कि ये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाये बिना ही अपनी भुगतान समुलन सम्बन्धों अस्थाई कठिनाइयों पर बिजय पा सके। समय समय पर वह विभिन्न देशों के विनिमय प्रतिद्वन्द्वों की जाँच करता रहता है और उनको यह सलाह देता रहता है कि ये धन धर्म कैसे हटाये जा सकते हैं।

विनिमय दरों के परिवर्तन एवं व्यापार समुलन (Exchange Rate Changes and the Balance of Trade)

प्रो० ए० सी० एल० डे (A C L. Day) ने अपनी पुस्तक *Outlines of Monetary Economics* में विनिमय दर के परिवर्तनों और व्यापार-समुलन के मध्य सम्बन्ध पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस सम्बन्ध को वस्तुओं के लिए माँग की लोच के विचार के सन्दर्भ में स्पष्ट किया है। यदि माँग का परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से अधिक है, तो लोच 'इकाई से अधिक', और यदि कम है, तो लोच 'इकाई से कम' होगा। यदि दोनों प्रकार के परिवर्तन समानुपात में हैं, तो लोच इकाई के बराबर होगी।¹ विनिमय-दर के परिवर्तन उन वस्तुओं के कीमत-परिवर्तनों में प्रतिबिम्बित होते हैं जोकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करती हैं। कीमतों में परिवर्तनों के फलस्वरूप वस्तुओं के लिए माँग (अर्थात् आयात और निर्यात) परिवर्तित हो जाती है और इसलिये व्यापार समुलन भी बदल जाता है। इस सम्बन्ध को निम्न चार्ट के रूप में सक्षिप्त किया जा सकता है —



उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को एक सुगम उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि सरकार ने १ £ = २० सं०

¹ The formula for elasticity of demand is

$$e = \frac{\text{Proportionate Change in Demand}}{\text{Proportionate Change in Price}}$$

(अमेरिकी) अवदा, $1 \$ = ४ ६०$ विनिमय-दर निर्धारित की है। मान लीजिये कि बाजार विनिमय दर $1 \$ = २२$ गैट्स है। स्पष्ट रूप से का डालर में मूल्य ऊँचा है। रुपये का मूल्य बढ़ रहा है किन्तु डालर का मूल्य घट रहा है, क्योंकि पहले ०.० सेंट्स दर १ रुपया मिल सकता था किन्तु अब १ रुपया पाने के लिए ०.० गैट्स देने पड़ते हैं।

चूँकि रुपये का मूल्य डालर के मूल्य में बढ़ रहा है इसलिये वह अमेरिका में पहने की अपेक्षा अधिक माल खरीद सकता है। अन्य मध्य में, अमेरिकी करन्सी, पहले की अपेक्षा सस्ता है और इसलिये अमेरिकी माल भी पहने की अपेक्षा सस्ता है। पहले की रुपये के द्वारा २० सेंट्स मूल्य की अमेरिकी वस्तु खरीदी जाती थी किन्तु अब २२ सेंट्स मूल्य की अमेरिकी वस्तु खरीदी जाती है। साथ ही, अमेरिकी के लिये भारतीय करन्सी पहले की अपेक्षा महँगी हो गई है और इसलिये उनको भारतीय माल भी पहले की अपेक्षा महँगा पड़ेगा। विनिमय दरों में हुए इस परिवर्तन का व्यापार समुदाय पर क्या शुद्ध प्रभाव पड़ेगा? यह प्रभाव माँग की लोच की परस्परिकता (mutual elasticities of demand) पर निर्भर है।

भारत—यदि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग बेलाच है (अर्थात् लोच 'इन्फ़ी से कम' है), तो अमेरिकी माल के पहले की अपेक्षा सस्ता होने पर भी आयातों में अधिक वृद्धि न होगी। कुल आयात मूल्य बढ़ता तो दूर वरन् घट सकता है। दूसरी ओर, यदि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग लोचदार है तो अमेरिकी माल का सस्तापन आयातों में वृद्धि लायेगा तथा कुल आयात मूल्य बढ़ जायेगा।

अमेरिका—यदि भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग बेलाच है, तो भारतीय करन्सी का और इसलिए भारतीय माल का महँगापन अमेरिकी आयातों (अर्थात् भारत के निर्यातों) को प्रभावित नहीं करेगा। अमेरिकी आयातों का परिमाण और कुल मूल्य दोनों ही बढ़ जायेंगे। दूसरी ओर, यदि भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग लोचदार है तो भारतीय करन्सी का और इसलिए भारतीय माल का महँगापन अमेरिकी आयातों (अर्थात् भारत के निर्यातों) को प्रभावित करेगा तथा तदनुसार निर्यातों का परिमाण व कुल मूल्य दोनों ही घट जायेंगे।

अभी तक हमने दोनों देशों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप से एक दूसरे के आयातों और निर्यातों के लिये माँग की लोच पर पड़ने वाले विनिमय दरों के प्रभावों को समझाया था। अब हम इन प्रभावों को सम्मिलित रूप में समझावेंगे।

(१) मान लीजिये कि अमेरिकी माल के लिये भारतीय माँग (अर्थात् भारत के आयातों) और भारतीय माल के लिये अमेरिकी माँग (अर्थात् भारत के निर्यातों) का जोड़ 'इन्फ़ी से कम' अर्थात् 'बेलाच' है। ऐसी दशा में व्यापार समुदाय भारत के पक्ष में परिवर्तित होने लगेगा, क्योंकि इसकी वरन्सी की विनिमय दर में वृद्धि हो रही है। (जब भारतीय आयात बेलाच हैं, तो आयातों का मूल्य घट जायेगा)

लेकिन जय भारतीय निर्यात वेलोच हो, तो निर्यातों का मूल्य बढ़ेगा। अतः भारत, जिगको करेंसी का मूल्य बढ़ रहा है, व्यापार संतुलन में अनुकूलता अनुभव करेगा।) अनुकूल व्यापार-संतुलन वाले देश में आय और रोजगार में गुणक-विस्तार (multiple expansion) होता है। चूंकि अमेरिका की करेंसी का मूल्य घट रहा है इसलिये वहाँ पर उपर्युक्त का विपरीत प्रभाव देखने में आयेगा।

५) (२) यदि दोनों लोच का जोड़ 'इकाई से अधिक' है (अर्थात् लोचदार है,) तो स्थले की विनिमय दर में वृद्धि भारत के व्यापार संतुलन को प्रतिकूलता की दिशा में ले जायेगी। विदेशी माल के लिए लोचदार माप का अभिप्राय है कि विदेशी माल की कीमत में कमी होने पर (क्योंकि रुपये के मूल्य में विदेशी करेंसी सस्ती है), भारतीय आयात बढ़ने लगेंगे तथा आयातों का कुल मूल्य भी बढ़ेगा। साथ ही, भारतीय माल के लिये सोचदार विदेशी माप (अर्थात् भारतीय निर्यात) के फलस्वरूप भारतीय निर्यात में कमी होगी क्योंकि भारतीय कीमतें बढ़ गई हैं। फलतः भारतीय निर्यात का कुल मूल्य भी घट जायेगा। ये दोनों विरोधी प्रक्रियाएँ—आयातों में वृद्धि और निर्यातों में कमी—व्यापार संतुलन को प्रतिकूल भारत के लिये बना देगी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन भारत में आय और रोजगार में गुणक-संकुचन (multiple contraction) लायेगा। किन्तु अमेरिका में, जिसकी करेंसी का ह्रास हो रहा है, विपरीत प्रभाव दिखाई देगा।

(३) मान लीजिये कि दोनों लोच का जोड़ 'इकाई के बराबर' है (अर्थात्, लोच 'इकाई' है)। ऐसी वस्था में व्यापार संतुलन पूर्ववत् बना रहेगा। तबनुसार आय और रोजगार पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं होगा। किन्तु प्रो० डे ने यह दिखाया है कि क्रियाकलाप का कुल स्तर अपरिवर्तित रहते हुये भी कुछ उद्योगों में विस्तार तथा कुछ में संकुचन हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न वर्गों के मध्य आय का वितरण बदल जायेगा। यदि ऐसा हुआ, तो वचत और विनियोग में और तबनुसार आधिक्यलाप के सामान्य स्तर में भी परिवर्तित हो जायेंगे।

निष्कर्ष यह है कि विनिमय दरों के परिवर्तन आयात-और निर्यात वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तित कर देंगे। आयातों और निर्यातों के मूल्यों में कितना परिवर्तन होगा यह आयात-और निर्यात-लोच के स्वभाव पर निर्भर है। जो देश अनुकूल व्यापार संतुलन अनुभव करेगा वहाँ आय और आर्थिक क्रियाकलाप में गुणक वृद्धि होगी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन का अनुभव करने वाले देश में आय और आर्थिक क्रिया में गुणक-ह्रास होगा। विनिमय-दर सम्बन्धी परिवर्तनों के तात्कालिक एवं प्रेरित प्रभावों को निम्नलिखित चार्ट के रूप में सक्षिप्त किया जा सकता है :—

विनिमय-वृद्धि वाला देश



विदेशी माल सस्ता है (आयात सस्ते हो जाते हैं)

स्वदेशी माल विदेशियों के लिए महंगा है (निर्यात महंगे)



(अ) यदि सोच इकाई

से कम (या कम आयात) अनुकूल सतुलन → [आय व रोजगार में शुष्क वृद्धि]

(ब) यदि सोच इकाई से

अधिक (या सोच-अधिक आयात) प्रतिशूल सतुलन → [आय व रोजगार में शुष्क वृद्धि]

(घ) यदि सोच इकाई के बराबर है, तो → [व्यापार सतुलन में कोई परिवर्तन नहीं] आय व रोजगार में शुष्क वृद्धि नहीं

परीक्षा प्रश्न

१ विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्यों को समझाइये। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाने जागे वाले ढंगों की समीक्षा कीजिये।

[Explain the objectives of exchange control. Examine the method adopted to achieve these objectives.]

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

२ भारत में विनिमय नियन्त्रण की प्रणाली को समझाइये। इसकी क्या दुर्बलताएँ हैं? इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

[Explain the system of exchange control in India. What are its short comings? How can they be removed?]

(गौरव०, एम० ए०, १९६६)

३ उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिये जो विनिमय नियन्त्रण का आवश्यक बनाती हैं। साथ ही विनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंगों का विश्लेषण करिये।

[Throw light on the circumstances which necessitate exchange control. Also analyse the direct and indirect method of exchange control.]

(आमरा, एम० ए० १९६८)

४ 'एक प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन में देश की रक्षा के साधन के रूप में विनि-

मय नियन्त्रण की व्यवस्था सम्बद्ध देश के लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिये गम्भीर परिणाम रखती है।” इस कथन को समीक्षा करिये।

[“The system of exchange control as a method of safeguarding a country against an adverse balance of payments has serious consequences both for the economy of the country practising it as well as for the world's economy as a whole” Comment]

५. बहु विनिमय दरों के गुण दोषों का विवेचन करिये।

[Discuss the merits and demerits of multiple exchange rates]

अन्तरण समस्या

(The Transfer Problem)

परिचय—

विशाल एक-पक्षी अन्तरणों की समस्या इतिहास में बहुत पुरानी है। सन् १८७१ में फ्रांस द्वारा जर्मनी को युद्ध सम्बन्धी क्षतिपूर्ति का भुगतान, १९००-१४ की अवधि में कनाडा द्वारा पूँजी का आयात और जर्मनी द्वारा मित्रराष्ट्रों को क्षति-पूर्वक भुगतान ऐसे ही अन्तरणों के ज्वलन्त उदाहरण हैं। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में विशाल एकपक्षीय अन्तरण की समस्या बहुत उग्र वाद-विवाद का विषय बन गई थी। सबसे महत्त्वपूर्ण विवाद कीन्स और ओहलिन के मध्य हुआ और 'कीन्स-ओहलिन विवाद' के नाम से प्रसिद्ध है।

'एक पक्षी अन्तरण' से आशय
(Meaning of Unilateral Transfer)

'एक पक्षी अन्तरण' से आशय, एक विशेष समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए उन व्यवहारों का है जिनमें मूल्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है किन्तु बदले में कुछ प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत, द्विपक्षी अन्तरण वे हैं जिनमें मूल्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है और साथ ही, एक विशेष समयावधि के भीतर ही, उसका प्रतिफल भी प्राप्त हो जाता है। एक पक्षी और द्विपक्षी अन्तरणों का अन्तर न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बल्कि आन्तरिक व्यापार में भी लागू होता है। इसे हम न केवल द्रव्य के अन्तरण के सम्बन्ध में बल्कि वस्तुओं के सम्बन्ध में भी देख सकते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

द्रव्य के बदले वस्तुओं का अन्तरण द्विपक्षी अन्तरण (Bilateral Transfer) का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ विनिमय के दोनों पहलू प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के सामने आते हैं। किन्तु उपहार-स्वरूप वस्तुयें देना, राजनैतिक-कर (जैसे क्षतिपूर्ति) एक पक्षी अन्तरण (Unilateral Transfer) के उदाहरण हैं।

पर्यटकों द्वारा बातायात पर किये जाने वाले व्यय आदि द्विपक्षीय अन्तरण का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि इनमें द्रव्य का वास्तविक मेधाओं से विनिमय

किया जाता है। किन्तु ऋण देना या ऋण वापस करना एक मध्यम स्थिति रखता है। यदि विचाराधीन समयावधि में 'ऋण की स्वीकृति' और 'ऋण की वापसी' दोनों ही सम्मिलित हो जायें, तो 'ऋण व्यवहार' को द्विपक्षी अन्तर माना जायेगा, और, यदि विचाराधीन समयावधि में दोनों बातें (ऋण देना और ऋण लौटाना) घटित न हों, केवल एक ही बात (ऋण देना या ऋण लौटाना) घटित हो, तो इन्हें 'एक पक्षी अन्तरण' कहेंगे। यह उल्लेखनीय है कि व्याज सम्बन्धी भुगतान एक तरह से 'द्विपक्षी अन्तरण' है, क्योंकि पूँजी का प्रयोग एक वास्तविक सेवा है। किन्तु चूँकि यह नव पूँजी की सेवा प्रसार और सेवाओं के सन्तुलन में दिखाई नहीं जाती है, इसलिए इन्हें एक पक्षी अन्तरण ही समझना चाहिए।

एक पक्षी अन्तरण में निहित विशेष समस्या (Special Problem involved in Unilateral Transfer)

द्विपक्षी भुगतानों के अन्तरण की तुलना में एक पक्षी भुगतानों का अन्तरण कुछ जटिलतायें उत्पन्न करता है। अतः इन पर ध्यान से ध्यान देने की आवश्यकता है। वास्तव में द्विपक्षी भुगतानों के अन्तरण का जो विन्लेषण है वही एक पक्षी भुगतानों ■■■ लिए भी है। केवल कुछ मशोधन ही कर देन पड़ते हैं।¹

एक देश और दोष विश्व के मध्य हुए आर्थिक व्यवहारों का एक दोहरा विवरण (double balance sheet) बनाया जा सकता है जिसमें एक ओर तो वास्तविक (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के) मूल्यों का सन्तुलन हो, और दूसरी ओर, भुगतानों के साधनों (अर्थात् विदेशों की वास्तव में किये गए अथवा वहाँ से वास्तव में प्राप्त हुए आर्थिक भुगतानों) का सन्तुलन दिखाया गया है। इस बात के गर्व में, जैसा कि हमने भुगतान सन्तुलन वाले अध्याय में बताया था, भुगतान-सन्तुलन सेवा ही साम्य में रहता है जब तक कि भुगतान विदेशों मुद्रा के किसी विद्यमान स्टॉक में न किया गया हो अथवा विदेशी देश आन्तरिक मुद्रा का स्टॉक बढ़ाने के इच्छुक न हो। [उदाहरणार्थ, जर्मनी में मुद्रा प्रसार के युग में, विदेशियों ने यह लोचते हुए कि मार्क का मूल्य भविष्य में अधिक बढ़ेगा, जर्मनी को मार्क के निर्यात की अनुमति दे दी ताकि उनके पास जर्मन मार्क का राख्य बन जाय और भविष्य में इसका प्रयोग करके यह भारी लाभ उठा सकें।] किन्तु ऐसी दशाओं में सम्बन्धित रकम सेवा ही भ्रम्य होनी है। मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से तो इनका बहुत ही महत्व है, क्योंकि

¹ This (unilateral payment of large sums) is in reality only a special case of the phenomena (bilateral payments, already analysed) But it nevertheless deserves separate treatment because this case has always attracted a great deal of attention and in discussing it a number of refinements will be added to the analysis given in relation to bilateral transfer."

ये करैसी में विदेश के सूचक है, किन्तु इनका कुल अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान-सन्तुलन में परिमाणान्तरक रूप में अधिक महत्व नहीं होता ।

यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में पैसे विश्व के साथ केवल द्विपक्षीय अन्तरणों (अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के प्रत्यक्ष-विन्यासों) द्वारा सम्बन्धित हों, तो भुगतानों का सन्तुलन और वास्तविक मूल्यों के अन्तरण का सन्तुलन दोनों ही साम्यावस्था में रहेंगे । किन्तु, जब एक पक्षीय अन्तरण (जैसे शक्तिपूरक भुगतान) भी हों, तो व्यापार और सेवाओं के सन्तुलन में आधिक्य (surplus) होना चाहिए, क्योंकि भुगतान-सन्तुलन दीर्घकाल में असाम्यता की स्थिति में नहीं रह सकता । अन्य शब्दों में, एक पक्षीय अन्तरण जिसमें (in kind) किये जाने चाहिए अर्थात्, पूँजी के आवागमन अतः वस्तुओं और सेवाओं के अन्तरण का रूप में लेंगे । हाँ, यदि भुगतान की रकम अपन है और विदेशी मुद्रा के स्टॉक से मुगलनापूर्वक भुगतान किया जा सकता है, तो एक पक्षीय अन्तरण जिसमें म किये जाने आवश्यक नहीं हैं । ऐसे एक पक्षीय अन्तरण कोई समस्या भी प्रस्तुत नहीं करते हैं । किन्तु जर्मनी द्वारा शक्तिपूर्ति के भुगतान के समान विशाल रकमों के एक पक्षीय अन्तरण तब ही सम्भव है जबकि निर्बाध बाधिव्यय उत्पन्न किया जाय । यदि इनके लिये विदेशी मुद्रा के मर्चित स्टॉक का प्रयोग किया जाय, तो वह बहुत शीघ्र ही खाली हो जायेगा ।

इस सम्बन्ध में भी आन्तरिक और विदेशी व्यापार में वास्तव में कोई भेद नहीं होगा । प्रायः इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि दीर्घकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक भुगतान वस्तुओं में ही किये जाने चाहिए जबकि आन्तरिक व्यापारिक भुगतान द्रव्य में ही किये जाते हैं । निःसन्देह यह सच है कि आन्तरिक व्यापार के भुगतान प्रथमतः द्रव्य में ही किये जाते हैं किन्तु, भुगतान पाने वाला व्यक्ति भी सामान्यतः, इस द्रव्य से कुछ खरीदना ही चाहता है । ऐसे एक-पक्षीय भुगतानों के होते हुए भी व्यक्तियों के भुगतान सन्तुलन साम्य में रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति, एक देश की भाँति, दीर्घकाल में अपनी प्राप्तिवश की अपेक्षा अधिक व्यय नहीं कर सकता जब तक कि वह पिछली वस्तु का प्रयोग न करे । इस प्रकार, आन्तरिक व्यापार में भी एक पक्षीय अन्तरण अतः वस्तुओं और सेवाओं में ही सम्पन्न किये जाते हैं । किन्तु बहारा वस्तुओं के प्रवाह पर ध्यान नहीं जाने पाता, क्योंकि वे किसी राजनैतिक सीमा को पार नहीं करने और इसलिए उनका रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।¹

अन्तरण समस्या के पहलू (Aspects of the Transfer Problem)

प्रो० हैबरलर के अनुसार, एक देश से दूसरे देश को एक-पक्षीय भुगतानों

- 1 "Thus, even in domestic trade unilateral transfers are carried out finally in goods or services. But the flow of goods goes unnoticed, because it does not pass a political boundary, and is therefore not recorded"—*Ibid*, p. 64.

की समस्या के दो पहलू हैं — (I) स्वदेश में एक निदिज्ज द्रव्य राशि जुटानो पड़ती है। क्षतिपूर्ति की दशा में यह समस्या राष्ट्रीय खजाने की है किन्तु प्राइवेट पूंजी के निर्यात की दशा में व्यक्ति विशेष। (II) इस प्रकार एकत्र की गई देशी मुद्रा को राशि को भुगतान पाने वाले देश की मुद्रा में बदलना पड़ता है। अन्तरण को तब ही सफल माना जा सकता है जबकि आवश्यक निर्यात-आधिव्यय, वित्तिय के स्थाई हान (depreciation) बिना ही उत्पन्न कर लिया जाय।

निर्यात आधिव्यय का मूजन --

निर्यात-आधिव्यय के मूजन का अभिप्राय निम्नलिखित तीन बातों में या इनमें किसी एक ही बात में है — (i) आयातों के पूर्ववत् रहते हुये एक निर्यात आधिव्यय उत्पन्न हो जाय, या (ii) एक विद्यमान निर्यात-आधिव्यय पहले की अपेक्षा बड़ा हो जाय, या (iii) आयात आधिव्यय छोटा हो जाय। अन्य शब्दों में, एक निर्यात आधिव्यय का मूजन या तो भुगतान पाने वाले देश को निर्यात बन्दगार, अथवा वहाँ से आयात घटा कर किया जा सकता है, या आधिन रूप में निर्यात बढ़ाने और आधिक रूप से आयात घटाने (अर्थात् दोनों ही प्रकार से) निर्यात-आधिव्यय उत्पन्न किया जा सकता है।

अभी भी लोकप्रिय बने हुये भुगतान सन्तुलन सिद्धान्त की यह मायता है कि अन्तरण तब ही सम्भव है जबकि व्यापार या भुगतान सन्तुलन में पहले से ही सन्तुला मोड़ हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तुओं द्वारा निर्यात आधिव्यय के मूजन की प्रतीक्षा की जाय, क्योंकि जब भुगतान मिकेनिज्म कार्यशील हो जाता है तो निर्यात-आधिव्यय स्वतः उत्पन्न हो जायेगा।¹

अन्तरण मिकेनिज्म—

जब अन्तरण के लिए आवश्यक राशि देश में करारोपण द्वारा एकत्र की जाती है, तो इसका तर्क सम्मत परिणाम यह होता है कि उस देश के लोगों की आय (और इसलिए उनकी क्रय शक्ति) घट जाती है, द्रव्य का प्रचलन सङ्कुचित हो जाता है और परिणामतः कीमते गिर जाती हैं। इसी कारणों से, जो कि विपरीत दिशा में काम करने लगते हैं, भुगतान पाने वाले देशों के लोगों की राष्ट्रीय आय और क्रय शक्ति बढ़ जाती है तथा कीमते बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार, एक ओर भुगतान करने वाले देश में कीमतों के गिरने की प्रक्रिया, और दूसरी ओर भुगतान पाने वाले देश

(1 "It is therefore, not the case, as the still popular balance of payments theory supposes that the possibility of transfer depends on an already existing active balance of trade or payments. It is not necessary to wait till the goods present one with an export surplus. On the contrary, the export surplus arises automatically when the mechanism of payments is set in motion"—Ibid., p. 66

की कीमते बढ़ने की प्रक्रिया, दोनों मिनकर उन देशों के मध्य मूल्य-भिन्नता (gap in prices) उत्पन्न कर देते हैं। परिणामतः, भुगतान करने वाले देशों में निर्यात प्रोत्साहित होते हैं किन्तु वहाँ आयात घटते हैं और भुगतान पाने वाले देश में आयात बढ़ते हैं किन्तु वहाँ से निर्यात कम होती है। प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन अथवा वृद्धि एवं कमी की प्रक्रियाएँ अन्तरण को सम्भव बना देती हैं।

कीमत-परिवर्तनों की भूमिका (Role of Price Changes)

अन्तरण मिकेनिज्म में कीमत-परिवर्तनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कीमतें इस स्तर तक भुगतान करने वाले देश में बिरस्ती हैं और भुगतान पाने वाले देश में घटती हैं कि भुगतान करने वाले देश में एक निर्यात-आधिक्य उत्पन्न हो जाय किन्तु यदि कीमतों पर दबाव इतना नहीं पड़ रहा है कि जो आवश्यक आकार में निर्यात अतिरिक्त उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो, तो भुगतान करने वाले देश के विदेशी विनिमय कोषों पर दबाव अनुभव किया जायेगा। यदि यह दबाव अल्प हो, तो इसकी चिन्ता नहीं की जावेगी, किन्तु यदि यह लगातार और विशाल हो (और प्रायः ऐसा ही होता है), तो देश के केन्द्रीय बैंक को सावधानी से काम लेने की जरूरत है। ऐसी दशा में वह प्रायः बैंक दर में वृद्धि कर देता है। बैंक दर में वृद्धि होने के वंश ही प्रभाव होते हैं जो कि कीमतें गिराने से उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम, कुछ विदेशी विनिमय तो देश में विनियोजन के रूप में लौट आयेगा, और, दूसरे अर्थ-व्यवस्था में विनियोजन-क्रिया मन्द पड़ जायेगी, जिससे बेकारों फैलेंगी तथा कीमतें गिरेंगी। स्पष्टतः बैंक-दर नीति का उद्देश्य भी कीमतों में वृद्धि लाना है।

किन्तु १९३० से १९३६ के मध्य एक पक्षी अन्तरण की समस्या नियन्त्रण में बाध हो गई थी। अमेरिका को लेटिन अमेरिकी देशों और पूर्वी यूरोप के छोटे-छोटे देशों से एक पक्षी भुगतान लेने था। न तो कीमतें अमेरिका में इस स्तर तक बढ़ सकी (क्योंकि वहाँ स्वर्ण का निर्यात-आहित कर दिया था और कीमतों पर प्रभाव डालने से राय दिया गया था) और न व यूरोपीय देशों में इस स्तर तक गिर सकी (क्योंकि देनदार देशों में शक्तिशाली श्रम सघों के प्रभाव के कारण मजदूरी ढाँचा कठोर हो गया था) कि आवश्यक मात्रा में निर्यात अतिरिक्त उत्पन्न हो सके। अतः केवल यह विचार ही बचा था कि बैंक दर को बढ़ा दिया जाय। किन्तु देनदार देशों ने इस उपाय का असन्द नहीं किया जिसमें ट्रान्स्फर सम्भव नहीं हुआ।

अन्तरण-मिकेनिज्म में कीमत-परिवर्तनों के महत्त्व के सम्बन्ध में मतभेद

एक ओर तो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अन्तरण-मिकेनिज्म में कीमत परिवर्तनों की भूमिका को कोई विशेष महत्त्व नहीं देने और दूसरी ओर ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ऐसे परिवर्तनों की भूमिका को बहुत महत्त्वपूर्ण मानते हैं। प्रो० कैम्ब्रिज (Keynes) द्वितीय वर्ग के अर्थशास्त्री हैं किन्तु प्रो० ओह्लिन (Ohlin) प्रथम वर्ग में है। नीन्हा का मत है कि कीमत स्तरों में परिवर्तन अन्तरण मिकेनिज्म

की क्रियाशीलता के लिए अति-आवश्यक है। इसके विपरीत, ओहलिन ने इस बात पर बल दिया है कि अन्तरण मिकेनिज्म में कीमतों का कोई सम्बन्ध नहीं है। कीमत परिवर्तनों की भूमिका के विषय में यह विस्थात कौन्स-ओहलिन विवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा अतिपूरक भुगतानों के सम्बन्ध में उदय हुआ था। इस विवाद के कारण अन्तरण समस्या के जटिल पहलुओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है।

1) कौन्स का दृष्टिकोण—

कौन्स का कहना था कि जर्मनी को चाहिए कि अपने निर्यातों में वृद्धि करे, तब ही उसे निर्यात अतिरेक उत्पन्न हो सकेगा। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए निर्यात में सम्बन्धित वस्तुओं को कीमतों को गिराना होगा। किन्तु इन कीमतों में किम सीमा तक कमी की जा सकेगी यह जर्मन वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मांग की दशाओं पर निर्भर है। यदि विदेशी मांग की लोच (elasticity) 'एकाई' (unity) से अधिक है तो कीमतों में एक दो हुई कमी के फलस्वरूप उसके निर्यातों में अनुपात से ज्यादा विस्तार हो जायेगा और इससे निर्यात अतिरेक सहज ही उत्पन्न हो सकेगा। किन्तु, जब विदेशी मांग की लोच 'एकाई' के बराबर हो तो निर्यातों में कितनी भी वृद्धि हो जाय आवश्यक मात्रा में निर्यात अतिरेक कभी उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस तेजी से निर्यातों के परिमाण में वृद्धि होती है उसी तेजी से इनकी कीमतों में गिरावट आती है। दुर्भाग्यवश जर्मन वस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मांग की दशाएँ बहुत कठिन रह गई थीं। य इतनी अ-अनुपातिक थी कि जर्मनी की निर्यात कीमतों में बहुत अधिक कमा होने पर ही वांछनीय आकार का निर्यात अतिरेक उत्पन्न हो सकता था। इसका अर्थ था कि जर्मनी को सहायित करने के रूप में हुई प्रत्यक्ष या प्राथमिक हानि के अतिरिक्त एक अग्रत्यक्ष या द्वितीयात्मक हानि भी होगी। कारण, एक दिए हुए कुल भूतल्य के जर्मन निर्यातों में, कीमतों की कमी के कारण पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तुएँ सम्मिलित होगी। इसी बात को निम्न बयान द्वारा भी प्रबल कर सकते हैं कि वस्तुगत व्यापार शर्तें जर्मनी के लिये और भी अधिक बराबर हो जायेगी।

वस्तु पक्ष पर उपरोक्त परिणाम मौद्रिक यन्त्र द्वारा निम्न तरीके से उत्पन्न किया जाता है—**प्रथम**, जर्मनी में बरों को मजदूर किया जाता है। यह जर्मनी पर प्रत्यक्ष या प्राथमिक भार (direct or primary burden) है। यदि आवश्यक निर्यात अतिरेक उत्पन्न न हो सके, तो जर्मनी के सेंट्रल बैंक के मजदूर एवं स्वर्ण कोप घटते तथा माह का मबुचन होगा। इससे कीमतें और जाय पहले से भी अधिक घटेंगी और इस तरह से जर्मनी पर एक द्वितीयात्मक या अग्रत्यक्ष या अतिरिक्त भार (secondary, indirect or extra burden) पड़ेगा।

[यहाँ पर यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि भ्रम सम्बन्धी भ्रमों के कारण

हुई अस्थायी हानियों के अतिरिक्त मौद्रिक यन्त्र की नियन्त्रिता के कलस्वरूप कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता, क्योंकि आय और कीमते दोनों ही गिरी हैं। किन्तु यह आपत्ति वैध नहीं है, कारण केवल आन्तरिक वस्तुओं की ही कीमते तो गिरती है, आयातित वस्तुओं की कीमते नहीं। अतः वार्षिक मजदूरियाँ घट जाती हैं। इस प्रकार साख का संकुचन द्वितीयात्मक भार अवश्य ही डालता है।]

उक्त द्वितीयात्मक भार ही 'अन्तरण-हानि' (transfer loss) है। अतः जब इस अतिरिक्त भार के कारण स्वर्ण का बहिर्गमन होने लगे तो अन्तरण कठिनाइयों का उन्मूलन करना उपयुक्त ही है। यह आवश्यक नहीं है कि अन्तरण कठिनाइयाँ नष्ट इसी रूप में हो कि उस दिन को जिस पर भुगतान किया जाता है आवश्यक विदेशी विनिमय उपलब्ध नहीं हो रहा है। वे अन्य रूपों में भी अनुभव की जा सकती हैं जैसे—साख का संकुचन करने में जो समायोजन आवश्यक होते हैं उन्हें करने की असमर्थता, धर्म सम्बन्धी झगड़े, व्यापक रूप में वैकारी का कर्मनाश, आदि। इन परिस्थितियों में अन्तर्गत सरकार के लिए करो द्वारा आवश्यक द्रव्य एकत्र करना भी कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में अन्तरण कठिनाइयाँ वज्रट के घाटे के रूप में प्रगट होती हैं।

यदि आवश्यक वित्तीय कदम नहीं उठाये गये हैं या उठाये नहीं जा सकते, तो स्वर्ण बाहर जाने लगेगा और ऐसी दशा में अन्तरण कठिनाइयाँ विदेशी मुद्रा के अभाव में रूप में प्रगट होगी। ऐसा तब होता देखा गया है जबकि भुगतानों के मुद्रा-विस्फीतिक प्रभावों (deflationary influence) को एक उदार साख नीति अपनाकर ध्वस्त कर दिया जाय, जबकि बाहर जाने वाले स्वर्ण को नवीन उत्पादित बैंक मुद्रा से प्रतिस्थापित कर दिया जाय या जब साख का संकुचन करने की आवश्यकता की या तो स्वयं भुगतानों के ही कारण या अन्य कारणों से उपेक्षा कर दी जाय। किन्तु 'अन्तरण कठिनाइयाँ' मानवान का इस दशा में कोई बहुत निश्चित महत्त्व नहीं है। साख प्रसार की नीति सदा ही स्वर्ण के बहिर्गमन को बढावा देती है चाहे एक पक्षी भुगतान किये जा रहे हो या नहीं।

अतः सदा ही यह कहना सम्भव नहीं है कि एक विशेष दशा में इस तरह की कठिनाइयाँ प्राथमिक भार के कारण उत्पन्न हुई हैं या द्वितीयात्मक भार के कारण, अथवा कुछ अन्य कारणों से हुई हैं। निःसन्देह इस वाक्य का कोई आधिक नियम नहीं है कि अन्तरण होने पर विस्तार की नीति अपनाई जानी चाहिए या पर्याप्त विस्फीति पैदा नहीं की जा सकेगी। अतः कठिनाइयों का स्रोत वास्तव में वह मौद्रिक नीति है जो कि अपनाई जाती है, विदेशों को पिछाल रकमें अन्तरणित करने का दायित्व कठिनाइयों का स्रोत नहीं होती है। द्वितीयात्मक भार पड़ा है या नहीं इसका एक अच्छा चिह्न सामान्यतः व्यापार खर्तों में परिवर्तन होना है। किन्तु बाद ग्लाना चाहिए कि व्यापार करने किसी अन्य कारण से भी बदल सकती है। उदाहरणार्थ १८५८ और १९३१ के मध्य व्यापार करने जर्मनी के पक्ष में परिवर्तित हो गई थी, क्योंकि वच्चे

मालों की (जा कि जर्मनी के आयात का एक बड़ा भाग था) कीमते निर्मित वस्तुओं की, (जिनमें कि जर्मनी निर्यात करता था) अपक्षा गिर गई थी। स्पष्टतः ऐसा क्षति-पूरक भुगतानी के फलस्वरूप नहीं हुआ था।

इस प्रकार कीन्तु न यह दिखाया कि एक पक्षी भुगतान कीमता तथा व्यापार की शर्तों में परिवर्तन आवश्यक बनाने है और ऐसे परिवर्तन प्रायः भुगतान करने वाले राष्ट्र के लिए हानिकारक होन हैं।

ओहलिन का दृष्टिकोण—

ओहलिन ने कान्स की विचारधारा के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि इसने मांग वक्ष के परिवर्तन की भूमिका का दृष्टिगत नहीं रखा है। उदाहरणार्थ, जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के भुगतान की समस्या को ही लीजिए। तत्पश्चात् इसमें नया क्षति का जर्मनी में भुगतान पाने वाले देशों को अन्वरण दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि भुगतान पाने वाले देशों की मांग बढ़ गई है और जर्मनी की मांग कम हो गई है। अतः हम अपरिवर्तित मांग के आधार पर तर्क नही कर सकते।¹ प्रोफेसर ओहलिन के तर्क के अनुसार यद्यपि जर्मनी की मांग कम और विदेशों की मांग बढ़ गई है तथापि वे सामूहिक रूप से पहले के बराबर मात्रा में खर्च करते हैं। 'ले जेक्वस रूफ़े' (Jacques Rueff) ने 'क्षय-शक्ति की अविनाशिता का सिद्धान्त' (Principle of the Conservation of Purchasing Power) कहा है। इस सिद्धान्त बतलाता है कि विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में क्षय-शक्ति न तो खोती है और न पैदा हो जाती है, किन्तु वह सदा स्थिर रहती है।² एक

¹ 'We can, therefore, least of all argue on the basis of unaltered demand. The decisive point for the machinery of capital movements is, on the contrary, that demand has undergone a radical change... There is thus a market in A for more of B's goods than formerly. On the other hand the market in B for A's goods is not as big as it was before. The local distribution of demand has changed. Prior to the beginning of the movement of capital the two countries were buying so much of all kinds of goods that their value equalled that of the goods produced at home. On the other hand, after the capital movement started A buys more and B less of their combined production than before'—Ohlin : *quoted from The Theory of International Trade by Haberler*, p. 70

² 'Never in the course of the various economic transformations that occur is purchasing power lost or created, but that it always remains constant'

पक्ष की हानि दूसरे पक्ष के लाभ में सन्तुलित हो जाती है। हमारे विचारधीन उदाहरण में इसका अर्थ यह है कि भुगतान देने वाले देश को नया भक्ति घटने के रूप में ही भुगतानों की राशि की अधिक में हानि बढ़ाभि न होगी। अतः भुगतान करने वाले देश पर कोई द्वितीयान्तर भार (जिसकी कल्पना कीन्स न की थी) नहीं पड़ता।

सही दृष्टिकोण—

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कीन्स और ओहलिन के सिद्धान्त परस्पर विरोधी तथा एक पक्षी है और अन्य दोनों के मध्य है। वास्तविक जगत् में अनेक प्रकार की दृष्टियाँ देखने को मिल सकती हैं—ऐसी दृष्टियाँ, जिनमें अन्तरण के लिए सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है तथा व्यापार शर्तों में प्रतिष्ठान या अनुकूल परिवर्तन होता है, तथा, ऐसी दृष्टियाँ भी, जिनमें अन्तरण के लिए कीमत परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है तथा व्यापार शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं। इस प्रकार एक ओर अन्तरण के सम्बन्धपूर्ण हानि हो सकती है, किन्तु, दूसरी ओर, लाभ की सम्भावना भी है।

प्रो० ओहलिन का यह कहना निःसंदेह सही है कि कीन्स ने माँग पक्ष सम्बन्धी उन परिवर्तनों पर, जो कि स्वयं भुगतानों के कारण उत्पन्न होते हैं, ध्यान नहीं दिया है। हम अपरिवर्तित माँग वक्रों के आधार पर तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि भुगतानों वाले देशों के माँग-वक्र (demand curves) दाहिनी ओर खिसक (shift) जाते हैं।¹ इसका अर्थ यह है कि मौद्रिक भावों में वृद्धि के कारण पुरानी कीमतों पर ही पहलू की अपेक्षा अधिक मात्रा में खरीद की जायेगी। यहाँ तक भी सम्भव है कि जर्मन निर्यातों की कीमतों में कोई भी कमी हुए बिना ही अन्तरण सम्भव हो जाय। [ऐसा तब सम्भव है जबकि (मान लीजिए) क्षतिपूर्ति-कर लगाने से राष्ट्रीय आय में हुई घटौती उन्हें वस्तुओं के लिए विदेशी माँग में हुई वृद्धि के कारण निष्प्रभावित (offset) हो जाय। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि वे जर्मन वस्तुयें हैं जिनका निर्यात अब बढ़ जाता है, या वे विदेशी वस्तुयें हैं जो अब पहले की तुलना में कम आयात की जाती हैं।]

किन्तु, सामान्यतः, माँग में कमी और माँग में वृद्धि भिन्न-भिन्न वस्तुओं को प्रभावित करती है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों और उत्पादन में परिवर्तन होने

1 'Prof. Ohlin is undoubtedly correct in maintaining that Mr. Keynes ignores the shifts on the demand side produced by the payments themselves. One can not operate with unchanged demand curves of given elasticity, since the demand curves of the countries receiving payment will have shifted to the right.'—*Haberler The Theory of International Trade*, p. 73.

अनिवार्य है। प्रो० ओहलिन ने भी यह स्वीकार किया है कि माँग में कमी अति-प्रति का भुगतान करने वाले देश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं को ही मुख्यतः प्रभावित करेगी और माँग में वृद्धि भुगतान पाने वाले देश में उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं को ही प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किन्तु उन्होंने यह तर्क किया कि प्रथम प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन सीमित किया जायेगा और उत्पत्ति साधन निर्यात उद्योगों में प्रयोग के लिए मुक्त (release) होकर लगेंगे। यही तर्क उन वस्तुओं को भी लागू होता है जिनकी माँग बढ़ गई है। संशय उत्पादन निर्यातों के बलिदान पर भी बढ़ाया जायेगा जिससे व्यापार संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा।

यह तो सब ही स्वीकार करेंगे कि या तो भुगतान पाने वाले देश के निर्यातों में कमी होनी चाहिये अथवा भुगतान देने वाले देश के निर्यातों में वृद्धि, क्योंकि किसी तीसरे तरीके में निर्यात-आधिनय उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि उत्पत्ति के इस हेतुकेर द्वारा कीमती में क्या परिवर्तन हो जाते हैं ?

दो प्रकार के कीमत-परिवर्तन—यहाँ हमें निम्न दो प्रकार के कीमत परिवर्तनों में भेद करना चाहिये—(अ) पुराने से नये साम्य में परिणित होने के मक्रमण काल में अस्थायी कीमत भेद (temporary price discrepancies) एवं (ब) नये और पुराने साम्य के मध्य व्यापार शर्तों का स्थायी रूप से परिवर्तन (permanent shift of terms of trade)। एक बार फसल बिगड़ने या एक मुश्त रकम का भुगतान करने से कीमत भेद उदय हो सकता है जिसमें निर्यात प्रोत्साहित एवं आयात हतोत्साहित होते हैं तथा साम्य पुनः स्थापित हो जाता है। किन्तु कीमती में देशों के बीच यातायात व्यय भी राशि में अधिक अंतर होना साम्य के साथ संगति नहीं रखता, अतः वह अधिक समय तक बना नहीं रह सकता। एक सघर्ष मुक्त (frictionless) बाजार में तत्काल ही समायोजन हो जायेगा और जबकि 'कीमत परिवर्तन' (price changes) तो हो सकते हैं किन्तु 'कीमत विभ्रतायें' (price discrepancies) नहीं हो सकती हैं।

'कीमत विभ्रतायें बहुत समय तक नहीं रह सकती हैं'—इस तथ्य का यह अर्थ नहीं होता कि व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। जर्मन निर्यातों की कीमती में कमी तथा जर्मन आयातों की कीमती में वृद्धि होना सम्भव है। किन्तु इससे इस नियम की कि 'कीमतें विभिन्न देशों में समानता की प्रवृत्ति रखती हैं' सत्यता पर आँच नहीं आती है क्योंकि जर्मनों की निर्यात वस्तुओं की कीमतें जर्मनी में और अन्य देशों में भी गिर जाती हैं और वही बात आयातों के सम्बन्ध में भी है। अर्थात् आयातित वस्तुओं की कीमतें देश विदेश दोनों में बढ़ जाती हैं। कीमतों में ऐसा परिवर्तन एक ऐसी साम्याय (normal) दशा में हो सकता है, जिसमें व्यापार संतुलन पर माँग के परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण आवश्यक निर्यात अतिरेक उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विदेशी देश जमन निर्यातों के ब्यप अपनी

(क्षतिपूर्ति के कारण) बड़ी हुई आग का केवल एक अन्य भाग ही व्यय करते हैं। आखिर की निर्यात आयात किसी भी देश के कुल उत्पादन की तुलना में एक अन्य भाग ही होता है। अतः बड़ी हुई आग का एक बड़ा भाग स्वदेशी उत्पादन पर व्यय किया जा सकता है।

जर्मन निर्यातों की कीमतों में कितनी कमी आवेगी यह प्रथमतः विदेशी मांग की मोच पर निर्भर है। हैबरलर का कहना है कि मांग साधारणतः बहुत लोचदार होती है, क्योंकि विषय बाजार किसी एक अनेक देशों से निर्यातों के परिमाण की तुलना में कहीं अधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त यह बात भी, कि जर्मनी को एकाधिकार प्राप्त नहीं है वरन् अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है उसी विधा में कार्यशील होती है। कीमतों में कमी न केवल मांग को समर्थ रूप में प्रोत्साहित करेगी वरन् कुछ विदेशी प्रतियोगियों को भी बाजार में निराल देगी।¹ यह इसलिए और आसान हो जाता है कि भुगतान पाने वाले देशों में स्वदेशी वस्तुओं के लिये मांग बढ जाती है तथा परिणामस्वरूप, आवश्यक समायोजन जहाँ पहले से ही किया जाने लगता है।

द्वितीय, कीमतों में कमी की मात्रा जर्मनी में तथा, यथावधि परिवर्तन महित, वही प्रतियोगी उद्योगों में पूर्ण सम्बन्धी दसाभा पर भी निर्भर होती है।² उदाहरणार्थ, यदि जर्मन निर्यातों का उत्पादन घटती हुई लागत के बाधिन बढ़ाया जा रहा है तो जर्मनी की कठिनाइयाँ निरादरह कम हो जायेगी। यदि स्थिर लागतें निर्यातशील हैं, तो कीमतों में कोई परिवर्तन (shift) न होगा।

तैद्धान्तिक दृष्टि से यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि ये घटक किस प्रकार निर्यातशील होंगे। यही नहीं, 'परिणाम इस बात पर भी निर्भर है कि पूर्ति को समायोजन के लिये हम कितना समर्थ देन हैं। सामान्यतः जितनी सम्भी यह अवधि होगी उतनी ही कम कीमत परिवर्तन की आवश्यकता होगी। कारण, जब एक बार

¹ "By how much the price of German exports must fall depends, first on the elasticity of demand abroad demand is as a rule very elastic since the world market is, after all large compared with the volume of exports from any single country. Moreover, the fact that Germany has no monopoly but competes with other countries also works in the same direction. A fall of prices does not only stimulate demand as a whole but will also drive some foreign competitors out of the market"—*Ibid*, p 75

² "The extent of the fall in price depends, secondly, on the conditions of supply .. and also mutatis mutandis, in the competing industries abroad"—*Ibid*, p 75

निर्यात के विस्तार में जाने वाली बाधाओं को शक्तिशाली कीमत कटौतियों द्वारा दूर कर दिया जाता है, तब इस प्रकार से खोली हुई दिसाआ में निर्यात पहलू की अपेक्षा कच्ची कीमतों पर भी जारी रह सकता है।¹

यद्यपि इन सब अन्तर्सम्बन्धों की सही-सही मरिप्ति करना कठिन है तथापि सैद्धान्तिक रूप से व्यापार शर्तें जर्मनी के पक्ष में इस प्रकार से परिवर्तित हो सकती हैं जिससे कि जर्मन निर्यातों की प्रीमत खट जायें और जर्मन आयातों की कीमतें घट जायें। इसका यह विरोधाभासीय फल होता है कि स्वयं जर्मनी में प्रवाहित धन लगता है तथा अन्तरण मिकेनिज्म भुगतान करने वाले देश की स्थिति की सुगम बना देता है। निःसंदेह यह कोई बहुत सम्भाव दशा नहीं है।

स्मरण रहे कि ये सब जाने केवल सैद्धान्तिक महत्व की है। इनमें व्यावहारिक उपयोगिता कम है। वास्तविक उदाहरणों में सम्बन्धित घटक एवं इनकी सम्भावित प्रतिक्रियायें इतनी जटिल होती हैं कि अन्तरण प्रक्रिया में सज्जित कीमत परिवर्तनों की मातृम करना बहुत ही कठिन होता है। इस पर भी हैबरलर की सम्मति में, आह्वान का यह कहना ठीक है कि 'भुगतान करने वाले देश में कीमतों के गिरने और भुगतान पाने वाले देश में कीमतों के बढ़ने की धारणा अत्यधिक सरलीकरण (over simplification) है। यह विप्लेपण खण्डीय कीमत स्तरों (sectional price levels) के बारे में होना चाहिये, सामान्य कीमत स्तर (general price level) के बारे में नहीं।'²

एकपक्षीय भुगतान एवं पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन
(Unilateral payments and International Movements of Capital)

एक पक्षीय भुगतानों का वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात पर तथा कीमत-

¹ 'The result depends on how long one allows for supply to adjust itself. In general it holds true that the longer one allows, the smaller will be the necessary price changes. For once the obstacles to an expansion of exports have been swept aside by energetic under cutting exports can afterwards be maintained in the channels thus opened even at a rather higher price than before'—Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 75

But in any case as pointed out by Prof Ohlin, it is an oversimplification to say that prices fall in the country paying reparations and rise in the country receiving them. The analysis must be in terms not of general but of sectional price levels."

—*Ibid*, p. 76.

स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है वह सामान्यतः पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर इनके गहरे प्रभाव के कारण एक अल्प या दीर्घ अवधि के लिये दृष्टि में आभन हो जाना है।

एकपक्षीय भुगतानों का पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर प्रभाव—

विशाल एकपक्षीय भुगतान करने वाला देश निरी न किसी रूप में पूँजी का आयात अवश्य करने सक्षम है। यही कारण है कि व्यापार एवं सेवाओं के समतुलन पर इन भुगतानों का प्रत्यक्ष प्रभाव स्वगित हो जाता है या दुर्बल पड़ जाता है। प्रारम्भ में, भुगतान चालू उत्पादन में से नहीं बरन विदेशी लेनदारों द्वारा किये जायेंगे। अतः अन्तरण स्पर्णित हो जाता है और यदि नई सात वास्तव में लौटा दी जाय तो यह कई वर्षों की अवधि में निस्तो में किया जाता है।

उपरोक्त अन्तरण क्रेण (Transfer Credits) जिस रूप में दिये जायेंगे वह तथा इसे एक पक्षीय भुगतानों से सम्बंधित करने वाला विकेनिगम बहुत विभिन्न हो सकते हैं। जब क्रेण स्वयं कृणी को ही दिये जाते हैं तो यह सम्बन्ध प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है। टिकाऊ सम्पत्ति के अधिकार पत्रों का अन्तरण भी ऐसे ही प्रभाव रखता है।¹ उदाहरणार्थ जर्मनी के व्यापारिक जहाजों और विदेश स्थिति जर्मन सम्पत्ति के हस्तान्तरण ने व्यापार समतुलन को तत्काल ही प्रभावित नहीं किया, बरन उस अवधि के बीतने पर किया जिसमें कि इनकी आय प्राप्य होती थी।

यह धारणा कि पूँजी के आयातों बिना अन्तरण सम्भव नहीं होता प्रत्यक्ष क्रेणों से इतनी सम्बन्धित नहीं है जितनी की भुगतानों के उन प्रभावों में जो कृणी के अतिरिक्त अन्य लोगों का पूँजी के आयात की प्रेरणा देते हैं।

वास्तव में किये जा चुके भुगतान, आवश्यक प्रथम राज्दियों का एकत्रण एवं अन्तरण सम्भव बनाने के हेतु आवश्यक सात नियमन ये सब बातें मुद्रा-और पूँजी बाजारों में अभाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है, जिससे कि वहाँ व्याज दर विदेशी बाजारों की अपेक्षा बढ़ जाती है। इससे अल्पकालीन पूँजी देश में आकर्षित होने लगती है, अथवा, यदि देश अभी तक पूँजी का निर्यात करता आया था, तो वह ऐसा अब कम मात्रा में करता है। यदि भुगतान इतने विशाल हैं कि पूँजी के संचय में बाधा पड़ जाय (जैसा कि जर्मनी में हुआ था), तो न केवल अल्पकालीन बरन दीर्घकालीन पूँजी भी आयात की जाने लगती है। अर्थात् डिसेंबर,

¹ "The form in which these transfer credits are granted and the mechanism connecting them with the unilateral payments may vary considerably. A direct and obvious connection exists where the loan is made to the debtor himself. The transfer of titles to durable property has similar effects."

वेयर आदि विदेशियों को बेच जाते हैं, विदेशी बाजार में नये वस्तु निकासे जाते हैं, आदि आदि ।

किन्तु इन सब दशाओं में 'अन्तरण समस्या' सुलझती नहीं है वरन् स्पष्टित माना होती है । जब अन्तरण अन्त में किया जाय तो वह ऊपर वर्णित सिद्धांतों के अनुसार होता है । हाँ, 'स्पष्टन' बिलकुल 'समाप्ति' में भी परिणित हो सकता है । यह उस दशा में होता है जबकि देनदारों के दिवालिया होने में अन्तरण-मात्र (transfer credit) मूल्य रक्षित हो जाय । किन्तु उल्लेखनीय है कि जिन सेनदारों का रूपमा मारा जाय, जरूरी नहीं है कि वे एकपक्षीय भुगतान पाने वाले देशों के ही राष्ट्रजन हों वे किसी अन्य देशों के राष्ट्रजन भी हो सकते हैं ।

यह भी आवश्यक नहीं है कि भुगतान करने वाला देश विदेशों से जो साध प्राप्त करे वह सब एक पक्षीय भुगतान के कारण ही प्राप्त हो । अर्थात्, साध अन्य कारणों से भी प्राप्त की जा सकती है । उदाहरणार्थ जर्मनी को जो कुल साध प्राप्त हुई उसका अधिकांश भाग उसे हर हासल में प्राप्त होता, चाहे उसे एकपक्षीय भुगतान करने से या नहीं । वारण, उन दिनों विदेशी सेनदारों को जर्मन के उम्म्बस औद्योगिक नदिय में विद्वान या । विदेशियों के इसी विश्वास के कारण जर्मनी घटे पूँजी पर पूँजी का आयात कर सका था । नि सन्देह यह कहना कठिन है कि वित्तीय पूँजी एकपक्षीय भुगतान की आवश्यकता के कारण आयात की गई थी, क्योंकि यह अनेक बातों पर निर्भर थी, जैसे—क्षतिपूर्ति सम्बन्धी करो ने उपभोग घटाया या पूँजी से सचय को कम किया, अन्तरण हानि की विद्यमानता और उसका आकार, साध संकुचन की भीमा आदि ।

संभावित अन्तरण की सीमाएँ (Limits of the Possible Transfer)

यह विचार करना भी आवश्यक है कि अन्तरण किस दशा में सम्भव है और किस दशा में नहीं । जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, अन्तरण के लिए सर्वप्रथम सा आवश्यक राशि जुटानी पड़ती है तथा, दूसरे, कीमतों में परिवर्तन होने भी आवश्यक है । १ कीमत-परिवर्तन उत्पन्न विधे जा सकते हैं या नहीं, यह एक अलग बात है तथा अनेक घटकों पर निर्भर करती है, जिनका विवेचन नीचे किया जाता है । [मान लीजिये कि आवश्यक द्रव्य राशि एकत्र की जा चुकी है । यह भी मान लीजिये कि अर्थसमस्या में न्यूनतम लोच, जिसके बिना अन्तरण कदापि सम्भव नहीं होगा, मौजूद है । अन्य बातों में, उत्पत्ति सामग्री की क्षीमता (विरोधित मजदूरियाँ) पूर्णतः चेतनी नहीं हैं] —

(१) चलन में आनुपातिक वृद्धि—आवश्यक समायोजन होने के लिए यह जरूरी है कि भुगतान देने वाला देश साध को प्रतिबन्धित (control) करे । उसे इन प्रभावों के लिए नैशार रहना चाहिए जो कि स्वचालित स्वयंभोज के अन्तर्गत उत्पन्न होते हैं । जैसे, जब स्वर्ण देश में आवे, तो उसे चलन में वृद्धि करना चाहिए । यदि

वह चलन में अनुपातिक वृद्धि नहीं होने देता, तो अन्तरण विनोदनिष्पन्न का वह भाग, जोकि लेनदार देशों में अपनी और कीमतों में वृद्धि करने से सम्बन्धित है, निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात् काम करना बन्द कर देता है। तब समायोजन का सम्पूर्ण भार देनदार देश पर पड़ता है, जिससे वहाँ कीमतें और मजदूरियों में उछाल नहीं अधिक गिरावट की आवश्यकता पड़ती है जो कि अन्यथा दशा में होती।

(२) मुद्रा कोष का चलन के साथ अनुपात—यदि चलन में वृद्धि प्राप्त हुए अतिरिक्त कोष की सम्पूर्ण रकम के बराबर है, तो कोष का घटन के साथ अनुपात ज़ोचा हो जाता है। यदि बैंक अपने 'कोष-अनुपात' को बढ़ाना नहीं चाहता है तो फिर मुद्रा-मान में अन्तरण-धराराज की अपेक्षा अधिक वृद्धि करनी चाहिए। यही बात यथोचित परिवर्तन के साथ भुगतान करने वाले देश में मनुष्य के सम्बन्ध में भी लागू होती है। ध्यान रहे कि कीमत भिन्नता केवल एक बार उदय मान हो जानी चाहिए, बाद में इसे, जबकि अन्तरण प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है, घटाया भी जा सकता है। अर्थात् प्रत्येक वापिक विप्ल को चुकाने के लिए प्रयत्नशील (या अधिकाधिक) दर से समुचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(१) व्यापार चक्र की अवस्था—सम्बद्ध देश व्यापार चक्र की जिस अवस्था में से गुजर रहे हो उसका भी अन्तरण विपयक नीति की अनुसूता पर प्रभाव पड़ता है। जबकि सात का विस्तार किया जा रहा है तब आवश्यक समायोजनों के लिये केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि विस्तार की गति भुगतान पाने वाले देश में बढ़ जाय और भुगटान करने वाले देश में कम हो जाय। लेकिन मन्दीकाल में भुगतान करने वाले देश को चाहिए कि विस्फीति प्रक्रिया को, जो कि व्यापार चक्र की इस अवस्था की एक अपरिहार्य विशेषता है उग्रता प्रदान करे। किन्तु इस अवस्था में भुगतान पाने वाले देशों के मौद्रिक अधिकारियों से केवल अन्य सहाय्य की ही आशा की जा सकती है।

(४) टेरिफ स्तर और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण—अन्तरण सम्बन्ध कठिनाइयों व्यापार में रुकावटें खड़ी करने में बढ़ जाती है। यदि टेरिफों के विद्यमान स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण (volume) यथेष्ट है तो एकपक्षीय भुगतानों के अन्तरण में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। कारण टेरिफ होने हुए भी, अनेक दम्पुओं की कीमत निर्धारण किन्तु में कुछ ही ऊपर तथा एकक वस्तुओं की कीमत आयात किन्तु से कुछ ही ऊपर होगी जिससे थोटा प्रयत्न करके ही नियानों को बढ़ाया और आयातों की घटाया जा सकता है। अतः नियमान टेरिफ किसी भी वही रकम (जब तक कि वह बहुत ही असामान्य रूप से बड़ी न हो) के अन्तरण में कोई गम्भीर अडचन उत्पन्न नहीं करते। और यदि टेरिफों के कारण निर्यात में वृद्धि करना कठिन भी हो तो कम से कम आयात तो घटाया ही जा सकता है।

किन्तु, जब टेरिफ निरन्तर बढ़ाये जाते रहे, तो भुगतान करने वाले देश में कीमतें भी निरन्तर कम होती जानी चाहिये। यदि वही देश, जो भुगतान करने पर

जोर देने हैं, साथ ही आयातों का प्रत्येक सम्भव उपाय से (आपने व्यापार सन्तुलन के मुद्धार अथवा विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा के लिए) सीमित रखने की चेष्टा करते हैं तो उनकी नीति अन्तःसारपूर्ण नहीं जायेगी। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि उनकी आयात प्रतिबन्ध नीति सभी देशों के विरुद्ध है या दूसरे भुगतान करण वाले देश को प्राथमिकता प्रदान की गई है। कारण वस्तु के रूप में, भुगतानों का अन्तरण प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में, त्रिकोणीय व्यापार (triangular trade) द्वारा सम्पन्न होगा है।¹

समूहकरण में अन्तरण मिकेनिज्म की क्रियाशीलता (Operation of the Transfer Mechanism in Times of Crisis)

यह विचारणीय है कि समूहकाल में (जैसे १९३१ की महान मन्दी में) अन्तरण मिकेनिज्म, जिसका विवेचन हमने ऊपर किया है, किस सीमा तक कार्यशील रहता है। इन परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय ऋण मिलने की, और इसके साथ ही साथ डिफॉल्ट नीति द्वारा अल्पकालीन पूँजी के आवागमनों को नियंत्रित करने की सम्भावनाएँ विस्तृत हो जाती हैं। यदि किसी देश के लेनदार उसकी क्षीयता और उसकी करैंसों में विश्वास खो व, तो वे अपने हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जायेंगे। ऐसी दशा में बैंक दर में कितनी भी बड़ी वृद्धि कर वेने से पूँजी को आकर्षित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ 'बल' नहीं है। पतन की लहर अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में प्रारम्भ होकर स्वयं 'करैंसों' का भी अपनी चपेट में ले सकती है। कारण ज्वाइंट स्टॉक वैक्स अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिये उस रिक्तता को जो कि विदेशी साख वापिस लिय जाने से हुई है, केन्द्रीय बैंक की बिल वैश कर पूरा करने का यत्न करने हैं, जिनमें केन्द्रीय बैंक के बाप कम होने लगते हैं तथा विभिन्न के ह्रास का खतरा उपस्थित हो जाता है। फलतः केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों को निर्मापित करने के लिए प्रेरित होता है किन्तु इस पर भी उसे समता को कायम रखने में सफलता मिलना बहुत कठिन है।

वित्तीय संकट का कारण व्यापार चक्र हो सकता है या युद्ध अथवा अन्य। कारण कुछ भी हो, मात्र का प्रवाह अचानक मूल जाने से वित्तीय समूह और भी उग्र हो जाता है। चाहे देश में ही मात्र का विस्तार रुक गया हो या विदेशी लेनदारों द्वारा साख देना बन्द कर दिया गया हो इनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। दोनों ही दशाओं में अनिश्चित व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूँजी के प्रवाह पर निर्भर होते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। जब घत्र 'तेजों' से 'मन्दी' में परिणत हो जाता है, तब पूँजीगत वस्तुएँ बनाने वाले उद्योग, जिनमें साख के विस्तार के दिनों में सबसे भारी निर्यातों का निर्यात किया गया था, सर्वाधिक नुकसान उठाते हैं। यह दवाज क्षीय हो इन बैंकों तक जिन्होंने इन उद्योगों को वित्त दिया था, पहुँचने लगता है। ये बैंक

¹ Haberler *The Theory of International Trade*, p. 80

अपनी रक्षा के लिये केन्द्रीय बैंक से अधिव मूल्या में बित रीडिस्काउन्ट (Rediscount) कराने लगते हैं। कुछ बैंकों के दिवालिया होने से जो अल्प उत्पन्न होता है वह शीघ्र ही सम्पूर्ण चैनिंग प्रणाली पर फैल सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना द्रव्य सुरक्षित स्थान में हटाने के लिये बेचने हो जाता है। यदि आतंक विस्तृत हो जाय, तो ओम गे ठास बैंक भी अपने द्वार बन्द करने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक एक ही साथ अपने समस्त दायित्वों को निपटाने में समर्थ नहीं होता।

ऐसी परिस्थिति में प्रायः केन्द्रीय बैंक मदद के लिये आगे बढ़ता है। यदि प्रवृत्ति या अभाव कम्पाई है तो (जैसा कि मौद्रिक इतिहास बताता है) विश्वास पुनः स्थापित करने में केन्द्रीय बैंक सफल हो जायेगा। किन्तु जब साक्ष की दृष्टावट विदेशों से है स्वदेशी पूँजी भी भाग रहो है और विदेशों में केन्द्रीय बैंक की विशाल ऋण नहीं मिल रहे हैं, तो वह अपने कोषों में कमी महान करके ही हस्ताक्षर कर सकता है। किन्तु स्मरण रहें कि बोप-अनुपात में गिरावट होने से विश्वास को और भी अधिक चोट पहुँचती है और साक्ष के लोटाने (withdrawal of credit) की गति बढ़ जाती है जिस कारण दल नीति का क्षेत्र सीमित हो है।

ऐसी दशा में केन्द्रीय बैंक को यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या उसे सङ्कट-ग्रस्त बैंकों से समर्थन हटा लेना चाहिये अथवा अपनी साक्ष की क्षति गृह्णने देकर विनिमय को अस्त व्यस्त होने देना चाहिए। यदि उसने पहली नीति अपनाई, तो सम्भव है कि विदेशी लेनदार, इस भय में कि वही उनके लेनदार दिवालिया हो जायें अपनी पूँजी निष्कालना रोव दें। प्रायः कहीं भी भविष्यवासी इस कारणसे उत्पन्न होती है कि केन्द्रीय सरकार ने अत्यधिक उदार माध्य-नीति अपनाई थी या लोगों को यह आशा थी कि वह ऐसी नीति अपनायेगी।

विनिमय नियन्त्रण और अन्तरण मिश्र निगम (Exchange Control and Transfer Mechanism)

सङ्कटकाल में, स्वर्ण के बाहर जाने लगने से, मौद्रिक मिश्र निगम कार्य करता बन्द कर देता है। स्वर्णमान के अन्तिम दिनों में ऐसा ही हुआ था जिससे वह अन्ततः दृढ़ गया। आजकल, स्वतन्त्र विनिमय का स्थान विनिमय नियन्त्रण ने ले लिया है। विनिमय निगम का प्राथमिक उद्देश्य स्वर्ण खोपे धिना ही विदेशी विनिमय को दूर की उस दूर से, जो कि स्वतन्त्र बाजार में प्रचलित होती, ऊँचे स्तर पर वापस रखना है। इस हेतु ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जो कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति और इसके लिए माँग दोनों को प्रभावित करे। इसके लिए यह भी आवश्यक होता है कि विदेशी मुद्रा के लेन-देन, प्रत्येक केन्द्रीय बैंक द्वारा, चर, निगम, स्थापित किया जाय।

पूर्ति को कम करने के लिए मुद्रा अधिकारी एवं विनिमय फण्ड में से वित्तों का विपणन कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा की समस्त नानु प्राप्ति को आने अधिहार में ले सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों और व्यापक व भूतपन्न मध्यस्थी प्रयोजनाने जाने वालों को यह प्राप्त-धन विदेशों में विनियोग करने की अनुमति नहीं

की जाती है और उन्हे इसे स्वदेशी मुद्रा में ही एक निश्चित दर पर बदलने को कहा जाता है। विदेशी देशों में जो ऋण प्रतिभूतियाँ, सम्पत्तियाँ, आदि हों उन पर भी अधिकार रिया जा सकता है।

विदेशी बिलों के लिए माँग को कम करने के हेतु कुछ विशेष प्रकार के मुग-
तान विदेशों को भेजने का निषेध किया जा सकता है, आवश्यक एवं अत्यावश्यक आयातों में भेद किया जा सकता है। विशेष पर्यटन को अभ्युत्साहित किया जाता है, दैनिकीय चीजों का आयात दिया जा सकता है कि वे अपने लेनदारों को मुगतान न भेजे परास्तिथि सम्झौते (standstill agreements) किए जा सकते हैं, आदि-
आदि।

विनिमय नियन्त्रण के उपरोक्त उपायों पर एक विश्वले अन्वय म प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ पर दो ध्यान देने की बात यह है कि कुछ दशाभा में विनि-
मय नियन्त्रण अन्य दशाओं की अपेक्षा अधिक सफल हो सकता है। ऐसी वा प्रमुख दशाएँ हैं—(i) विनिमय की दुर्बलता, स्वर्ण का बहिर्गमन तथा भुगतान सन्तुलन का सकट देशों और विदेशी पूँजी के भागने (flight of capital) के कारण हो सकती है। यह पूँजी निष्क्रमण पूँजी के निर्यात से भिन्न है, क्योंकि वह 'बोझिम' घटक के कारण होता है, 'लाभ' घटक के कारण नहीं। पूँजी उन देशों में प्रवाहित होती है जिनमें जोखिम कम है अर्थात् वहाँ व्याज दर कम हो। (ii) विनिमय की दुर्बलता और स्वर्ण के बहिर्गमन का इससे भी गम्भीर कारण यह हो सकता है कि आय खाने का भुगतान सन्तुलन एक की हुई विनिमय दर पर निरन्तर निष्क्रिय बना हुआ है। यदि कीमतों और आय देख में आय देशों की तुलना में साम्य बिन्दु से ऊँची है, तो आयदाता (रोबायें, व्याज सम्बन्धी भुगतान, पूँजी की वापसी और अधिकतम लाभ की तलाश में होने वाले पूँजी के सामान्य आवागमन) निर्यात की अपेक्षा बड़े हुए होंगे। इसे स्वदेशी और विदेशी कीमतों के मध्य साम्य की पुन स्थापना द्वारा ही सुधारा जा सकता है। इस हेतु या तो विनिमय में ह्रास होने देना चाहिए या कीमतों को ब्याप्त गिराना चाहिए।

ये दोनों दशाएँ शायद ही कभी पृथक्-पृथक् उत्पन्न होती हों और एक दशा दूसरी दशा को उत्पन्न करने वाली है। उदाहरणार्थ, पूँजी का निष्क्रमण साक्ष प्रसारकों, मुद्रास्फीति से उत्पन्न हो सकता है और, दूसरी ओर, स्वर्ण का दीर्घकालिक बहिर्गमन, जो कि कीमतों की अधोमुखी समायोजित (downward adjustment) न करने का परिणाम है, विनिमय को नष्ट करके पूँजी के निष्क्रमण को प्रोत्साहित कर देता है। किन्तु संज्ञातिन विनियमन के लिए इन दशाओं पर पृथक्-पृथक् विचार किया जा सकता है।

पहली दशा में पूँजी का निष्क्रमण (flight) तो होता है किन्तु आय खाने पर भुगतान सन्तुलन साम्यावस्था में ही बना रहता है। अतः कीमतों दीर्घकालीन

साम्य स्थिति से ऊँची नहीं होती है, किन्तु फिर भी पूँजी के अस्थाई निष्क्रमण के मन्दमं में काफी ऊँची रहती है। अन्तरण के लिए या तो चलन माध्यम की संकुचित करने की तकनीक फेलनी पड़ेगी, या (यदि पूँजी की कमी बैंक साख द्वारा दूर हो जाय तो) विनिमय दर को गिरना होगा। विनिमय नियन्त्रण का उद्देश्य, पूँजी के निष्क्रमण को रोक कर, अधिकारियों को इस दुविधा (dilemma) में बचाना है।

जर्मनी के अनुभव से यह पता चलता है कि कुछ शोमाओं के भीतर, आय माने पर आधारित भुगतानों को मुक्तान पहुँचाये बिना, पूँजी का निष्क्रमण रोक जा सकता है। किन्तु ये सामान्य नया दशाएँ, जो इस नीति की सफलता में सहायक हैं, मावधानी में धार रखा जानी चाहिए। इन्हे निम्न प्रकार से सक्षिप्त किया जा सकता है — (i) वस्तु को स्थायित्व प्रदान किया जाय, (ii) यदि आम खाते पर भुगतान मन्तुलन निषिद्ध हो, तो कीमतों और आयों को, साख के मकुचन, द्वारा गिराया जाय, (iii) अपरिहार्य पूँजी निर्यातों के लिए प्राय खाते में यदेक आधारित उन्नत किया जाय, अन्यथा स्वर्ण बाहर जाने लगेगा या विनिमय दर गिरेगी। इन दोनों ही दशाओं में पूँजी के निष्क्रमण को सति बड़ जायेगी। उल्लेखनीय है कि जिन तरह से लोग बैंक में रक्का निकालने के लिए तब नहीं दौड़ेंगे जबकि वे सह अनुभव करें कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रक्का मिल जायेगा, उमी प्रकार ये देश में पूँजी का निष्क्रमण तब नहीं होगा, अर्थात्, मेनदार अपनी पूँजी तब वापस नहीं मांगेंगे जबकि इसकी बाँटसी को समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी।

एक बार जब पूँजी के निष्क्रमण का बढ़ावा देने वाले कारण दूर हो जायँ, तब नियन्त्रण को, विनिमय दर को ठेक पहुँचाये बिना भी, हटावा जा सकता है। किन्तु व्यवहार में देखा गया है कि एक प्रकार के विनिमय नियन्त्रण दूसरे प्रकार के विनिमय नियन्त्रणों को जन्म दे देते हैं।

इस प्रकार, भुगतान रोकने या स्थगित करने के लिए तथा आयातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियन्त्रित करने के लिए अन्तर्निती उपाय अपनाये जा सकते हैं किन्तु सामान्य सिद्धान्त यवका एन ही है और यह है कि यदि कीमत यन मार्ग नहीं कर सकता है तो फिर मांग की पूर्ति के साथ किसी अन्य उपाय द्वारा समायोजित किया जाय। इस हेतु या तो सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं या विशेष दशाओं के लिए विशेष नियम बनाये जा सकते हैं।

देश के ऋणी और ऋणदाता होने के चिन्ह

किसी देश का मुक्तान-मन्तुलन या तो साम्यावस्था में (in equilibrium) होता है अथवा असाम्यावस्था में (in disequilibrium)। प्राय मुक्तान मन्तुलन असाम्यावस्था में ही होते हैं, साम्यावस्था तो एक अपवादभूत (exceptional) दशा है। जब वह असाम्यावस्था में है, तो या तो देश अन्य देशों के प्रति ऋणी होता है [ऐसी दशा में उसे एक 'ऋणी देश' और उसके भुगतान मन्तुलन को 'निष्क्रिय' कहते हैं] या अन्य देश उसके प्रति ऋणी होते हैं। [ऐसी दशा में उसे एक 'मेनदार देश'

और उसके भुगतान-सन्तुलन को 'सक्रिय' करते हैं।] इसी प्रकार, जब किसी देश के भुगतान-सन्तुलन में साम्यता है (यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है), तो भी वह अन्य देशों को ऋण देकर एक लेनदार राष्ट्र बन सकता है, अथवा, अन्य देशों से ऋण लेकर एक देनदार राष्ट्र हो सकता है।

किसी राष्ट्र के ऋणी होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे—उसे मुद्रा की अतिप्राप्ति देनी पड़ती हो, अथवा एक पिछले ऋण पर व्याज सम्बन्धी भुगतान करने पड़ने हो। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दीर्घकाल में एक वस्तु विनिमय व्यापार ही तो है, मुद्रा एवं विनिमय सम्बन्धी व्यवहार तो व्यापार के मार्ग को सहज बनाते हैं। अतः एक देश अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक ले लेने के कारण भी ऋणी बन सकता है और अन्य देशों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक देकर एक लेनदार राष्ट्र बन सकता है। संक्षेप में, किसी देश को ऋण-प्रस्तुत व्यापार सम्बन्धी व्यवहारों से भी उदय हो सकती है।

जब किसी देश को अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अधिक मूल्य प्राप्त होता है, तो कहा जायेगा कि उसका व्यापार सन्तुलन 'निष्क्रिय' (passive) है। इसके विपरीत, यदि वह बिज्ज के देशों को वस्तुओं और सेवाओं के रूप में जितना प्राप्त हुआ है उससे अधिक देता है, तो उसका भुगतान-सन्तुलन 'सक्रिय' (active) कहा जाता है। एक सक्रिय (अर्थात् अनुकूल) व्यापार सन्तुलन की विद्यमानता इस तथ्य का सूचक है कि जिस देश का भुगतान-सन्तुलन इस प्रकार का है वह एक लेनदार राष्ट्र है। इसी तरह, एक निष्क्रिय (अर्थात् प्रतिकूल) व्यापार सन्तुलन देश के देनदार राष्ट्र होने का सूचक है।

किन्तु, यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यापार सन्तुलन की सक्रियता और निष्क्रियता इस बात का अन्तर्गत प्रमाण नहीं है कि देश लेनदार या देनदार राष्ट्र है। अन्य शब्दों में, पाठ्य-पुस्तकों में दिया गया यह कथन कि 'सक्रिय भुगतान-सन्तुलन रखने वाला देश एक लेनदार और निष्क्रिय भुगतान-सन्तुलन रखने वाला देश एक देनदार राष्ट्र होता है।'¹ कुछ मर्यादाओं के अन्तर्गत ही सत्य माना जा सकता है।² सच तो यह है कि एक लेनदार राष्ट्र के लिए निष्क्रिय और एक देनदार राष्ट्र के लिए सक्रिय व्यापार सन्तुलन रखना विलक्षण सम्भव है।

इस प्रकार, यदि किसी देश के व्यापार सन्तुलन में साम्यत्वस्था हो और वह एक निश्चित दर में पूँजी का आयात करना आरम्भ कर दे, तो उसका व्यापार-सन्तुलन निष्क्रिय हो जाता है। किन्तु, कुछ समय के बाद, यह आयात को हुई पूँजी व्याज सहित लौटानी पड़ती है (हाँ, यदि वह उपहार के रूप में मिली हो, तो नहीं)। दर-मदरे में व्याज और मूलधन की वापसी सम्बन्धी भुगतान आयात की जाने वाली

¹ Haberler : *The Theory of International Trade*, p. 64.

नई पूँजी की अपेक्षा बहुत बड़ जायेग जिसमे उसका व्यापार सन्तुलन सक्रिय हो । जायगा । अन्य बातें समान होने पर यही बात पूँजी का निर्यात करने वाले देश के बारे में है ।

उदाहरणार्थ, जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया (और सन् १९२६ तक), तो जर्मनी का व्यापार-सन्तुलन निष्क्रिय रहता था । क्योंकि यह विश्व के देशों को जितना चुना रहा था उसमे कहीं अधिक ऋण ले रहा था । किन्तु १९२६ में जब पूँजी का प्रवाह मूल्य गया, तब उसका व्यापार सन्तुलन लगभग रातो रात सक्रिय बन गया । क्या हम यह कह सकते हैं कि जर्मनी लेनदार राष्ट्र हो गया ? नहीं, वह तो असंदिग्ध रूप से देनदार राष्ट्र ही था और उसका व्यापार सन्तुलन इस कारण से सक्रिय हो गया था कि वह अपने पुराने ऋण चुका रहा था किन्तु नये ऋण नहीं ले रहा था । इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्व अमेरिका एक देनदार राष्ट्र था और उसका व्यापार सन्तुलन 'सक्रिय' था, क्योंकि उसके निर्यात आयातों से बढ़ रहे थे । यह आधिक्य इस कारण था कि वह यूरोपीय लेनदारों का व्याज और मूलधन चुका रहा था । किन्तु युद्धकाल में वह रातों रात एक लेनदार देश हो गया और १९१६ के बाद उसका व्यापार सन्तुलन 'सक्रिय' ही बना रहा क्योंकि व्याज और मूलधन की प्रतियों की अपेक्षा पूँजी का निर्यात अधिक होता था । इस प्रकार अमेरिका का व्यापार सन्तुलन तब भी सक्रिय था जबकि (युद्ध के पूर्व) वह एक देनदार देश था और तब भी सक्रिय रहा जबकि (युद्ध के बाद) वह एक लेनदार देश हो गया ।

अतः यह धारणा कि एक देनदार देश का व्यापार सन्तुलन सक्रिय और एक लेनदार देश का व्यापार सन्तुलन निष्क्रिय होता है केवल एक अल्पकाल में ही सम्भव है जो कि ऋणता के सन्तुलन की दशा की केवल एक लघु अवधि मान है । एक दीर्घकाल पर्यन्त विस्तृत पूँजी आवागमनों की दशा में (अवधि इतनी दीर्घ होनी चाहिए कि उसमें ऋण की स्वीकृति और इसकी व्याज सहित वापसी होता ही सम्पूर्ण हो जायें ।) व्यापार सन्तुलन की दशा ऋणता की प्रक्रिया द्वारा पहुँची हुई विशेष दशा पर निर्भर है । यही कारण है कि हम केवल देश के व्यापार सन्तुलन पर दृष्टि डाल कर ऋणता की प्रक्रिया की अवस्था को समझें बिना ही, निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि अमुक देश लेनदार है या देनदार ।

परीक्षा प्रश्न :

- विशाल एक पक्षीय मुपतानों के सम्बन्ध में जो अन्तरण-समस्या उत्पन्न होती है, वह क्या है ? ऐसे अन्तरण के मिकेनिज्म में क्रियत परिवर्तनों की भूमिका का विवरण कीजिए ।

{ What is the transfer problem involved in large unilateral payments ? Discuss the role of price changes in the mechanism of such transfers }

चतुर्थ खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति

[INTERNATIONAL COMMERCIAL POLICY]

विद्वानों के विचार—

- (१) हैबर्लर (Habesler)—“स्वतन्त्र व्यापार से आसय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का है जिसम आर्थिक शक्तिया स्वतन्त्र रूप से आचरण करती है। किन्तु इसमे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि एक ओर तो अप्रतिबन्धित स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करना और दूसरी ओर (उदाहरणार्थ) यम बाजार मे आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्र आचरण मे हस्तक्षेप का सुभाव दना एक दूसरे से असम्भव है।”

[“Free Trade is the external trade system with the free play of economic forces But it by no means follows from this that it is inconsistent to advocate, on the one hand unrestricted Free Trade and, on the other hand, certain interferences with the free play of economic forces for example on the labour market ”]

- (२) सैमुअलसन (Samuelson)—“नि सन्देह, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष मे केवल एक ही किन्तु बहुत ही शक्तिशाली तर्क है जो यह कि अप्रतिबन्धित व्यापार एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है जो कि परस्पर लाभदायक है, सभी देशों की वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति को बढ़ाता है तथा समस्त संसार मे जीवन स्तरों को ऊँचा करता है।”

[Indeed, there is essentially only one argument for free or freer trade, but it is an exceedingly powerful one—namely unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries, and makes possible higher standards of living all over the globe ”]

- (३) मिरडल (Myrdal)—“हिंदी की समरूपता केवल उन लोगों के लिए ही एक बहुत सुगम धारणा हो सकती है, जिन्होंने भाग्यवश जीवन के जूए में इनाम जीत लिया हो।”

[“Harmony of interests must be a very convenient idea for those who have drawn a lucky lot in the lottery of life ”]

विदेशी व्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या

(The Problem of an Appropriate Policy towards Foreign Trade)

परिचय—व्यापारिक नीति से आशय

प्रो० हैबरलर के शब्दों में— व्यापारिक नीति या वाणिज्य नीति से आशय उन सब उपायों का है जो कि किसी देश के बाह्य आर्थिक सम्बन्धों का नियमन करते हैं। यह उपाय एक क्षेत्रीय सरकार द्वारा जिसे कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात या आयात में बाधा डालन या सहायता पहुँचाने की शक्ति होती है, किये जाते हैं।¹ ऐसे उपायों में ड्यूटीज, आर्थिक सहायता और निषेध सम्मिलित हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जैसे—भाड़ा दरों का नियमन करना, आयातित माल के लिये एक महँगी पैकिंग विधि अपनाने पर बल देना छिपी हुई आर्थिक सहायता, आदि। इन विभिन्न उपायों में सबसे अधिक महत्व आयात करों का है। यह वास्तव में व्यापारिक नीति के सबसे विवेक-सम्मत हथियार है।

राजनैतिक विचार विमर्शों में 'लक्ष्य' एवं 'साधन' प्रायः एक अपवित्र डण्ड से मिश्रित कर दिये जाते हैं जिससे यह कहना कठिन हो जाता है कि लोग लक्ष्य के चुनाव के बारे में मतभेद रखते हैं या एक दिये हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय के चुनाव के विषय में अथवा कुछ विशेष उपायों के अपनाने से जो परिणाम उदय होंगे उनके बारे में मतभेद रखते हैं।² अतः हमें यह देखना चाहिए कि वे

1 'We understand by commercial policy or trade policy all measures regulating the external economic relations of a country, that is, measures taken by a territorial government which has the power of assisting or hindering the export or import of goods and services.'—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 212

2 'In political discussions ends and means are often mixed up in a quite unholy manner, so that it is often difficult to be sure whether people disagree in their social philosophy as to which end is desirable or whether they disagree as to the consequences which would follow from particular measures or as to the best means of achieving a given end'—*Ibid*, p 214

कोन से लक्ष्य है, जिन्हे प्राप्त करने के लिए व्यापारिक नीति को प्रयत्नशील होना चाहिए। अन्य शब्दों में, हमें मूल्यों का पैमाना' (scale of values) निर्धारित कर लेना चाहिये, जिसके सदर्थ में हम किसी व्यापारिक नीति की उपयुक्तता को परख सकें।

आर्थिक एवं अनार्थिक लक्ष्य (Economic and Non-economic Ends)

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम 'आर्थिक' एवं 'अनार्थिक' लक्ष्यों का भेद विचारणीय है। हम अनार्थिक मूल्यों या लक्ष्यों की एक सूची सरलतापूर्वक बना सकते हैं और फिर आर्थिक घटनाओं को इस सूची के सदर्थ में परख सकते हैं। अनार्थिक लक्ष्य या मूल्य निम्न है—राष्ट्रीय सुरक्षा का लक्ष्य सामाजिक न्याय का लक्ष्य अविरोधपूर्ण लक्ष्य (जैसे धार्मिक स्वभाव के लक्ष्य), गृहकृता का लक्ष्य आदि। ये लक्ष्य विद्युद्ध मूल्योक्ति सम्बन्धी हैं, किन्तु उनका 'अन्तिम' होना आवश्यक नहीं। कारण, प्रत्येक लक्ष्य किसी अन्य बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का अंग हो सकता है। उदाहरणार्थ, अनेक लोग सामरिक तैयारी को एक साधन या माध्यमिक लक्ष्य ही मानते हैं, स्वयं में एक पूर्ण लक्ष्य नहीं। स्पष्टतः आर्थिक घटनाओं के बारे में उक्त किसी भी लक्ष्य (मूल्य या इष्टिकोण) के सदर्थ में निर्णय किया जा सकता है। विभिन्न लक्ष्यों की अपनाने से विभिन्न निर्णय सम्भव होंगे तथा यह 'आर्थिक' लक्ष्यों के सदर्थ में किये गये निर्णयों के साथ संघर्ष (clash) में भी आ सकते हैं।

अनार्थिक लक्ष्यों के निश्चयेपक्ष से भी अधिक कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक लक्ष्यों (मूल्यों या इष्टिकोणों) का विश्लेषण करना। अमुक उपाय आर्थिक दृष्टि से ठीक है, ऐसा कहने में हमारा क्या आशय है? क्या कोई ऐसा विशेष आर्थिक लक्ष्य है जो कि अर्थ-विज्ञान द्वारा, अनार्थिक कल्पनाओं के बिना, या, अ-वैज्ञानिक स्वभाव के लक्ष्य दृष्टिगत रहे बिना ही स्पष्टतः परिभाषित किया जा सके तथा जिसकी प्राप्ति समस्त आर्थिक नीति का एक पुनीत कर्तव्य निश्चित हो जाय? स्पष्टतः इस प्रश्न का उत्तर है—नहीं। कोई एक सर्वोपरि आदर्श आर्थिक लक्ष्य नहीं फिर भी इस बिंदु में किये जाने वाले प्रयत्नों का अभाव नहीं है। समय-समय पर 'उत्पादक शक्ति का विकास' उत्पादकता में वृद्धि', आर्थिक प्रत्याग की वृद्धि' और अन्य लक्ष्य प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। उन्हें इस आधार पर कि ये (लक्ष्य) अर्थ-व्यवस्था के मौलिक स्वभाव में निहित हैं, आर्थिक नीति को परखने के लिए प्रयोग किया गया है। इन शब्दों की सही-सही परिभाषा करने तथा आवश्यक नियम देने के लिये यह जरूरी हो जाता है कि मौलिक लक्ष्यों को निर्धारित किया जाय। किन्तु मौलिक लक्ष्य ऐसे होते हैं कि इन्हें वैज्ञानिक रूप से 'वांछनीय' प्रमाणित नहीं किया जा सकता या आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित नहीं किया जा सकता, वरन् केवल 'दिया हुआ' ही स्वीकार करना पड़ता है।

इन प्रकार, लक्ष्यों का 'आर्थिक' एवं 'अनार्थिक' वर्णों में विभाजन केवल

पारिभाषिक सुगमता के लिये है। किन्तु साधारण बोलचाल में यह विभाजन बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है तथा दोनों के मध्य विभाजन-रेखा बदलती रहती है।

सार्वभौमिक मान्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय से सम्बन्धित है

कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना ही वांछनीय है तब हम एक विशुद्ध (pure) आर्थिक लक्ष्य को ही तो अपनाये हुए हैं। अतः कोई भी उपाय जो राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि करता है आर्थिक दृष्टिकोण से वांछनीय कहा जा सकता है। किन्तु ऐसी धारणाओं का (जैसे—राष्ट्रीय आय, अर्थात् सामाजिक उत्पत्ति) विक्षेपण करने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। यह राष्ट्रीय आय के निरपेक्ष आकार (absolute size) का ही नहीं बल्कि विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के मध्य सामाजिक उत्पत्ति के वितरण का भी प्रश्न है। यदि हम केवल कुल राष्ट्रीय आय के निरपेक्ष आकार पर ही ध्यान दें तो सामान्यतः यह कहेंगे कि हमारा मापक 'आर्थिक' है। किन्तु जब वितरण सम्बन्धी कल्पनाएँ भी विचार में ली जाती हैं (जैसे—वितरण में समानता होनी चाहिये या, अगुक्त-अगुक्त वर्ग के पक्ष में वितरण में परिवर्तन होना चाहिये), तो यह हमारी रुचि है कि उसे आर्थिक मानक माने या सामाजिक मानक। कुछ भी हो हमारे पास अब दो मापक हैं—(i) राष्ट्रीय आय के आकार में वृद्धि का और (ii) इसके वितरण के ढग का—एक इनमें से प्रत्येक के एक दूसरे से भिन्न परिणाम निकल सकते हैं।¹ उदाहरणार्थ, यह सम्भव है कि स्वतन्त्र व्यापार संरक्षण की अवस्था राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि कर दे किन्तु इसके साथ ही वह आय का एक अवांछनीय ढग से वितरण होने में योग दे सकता है।

वितरण के पाँच प्रकार—

जब हम राष्ट्रीय आय के वितरण की चर्चा करें तो हमें इसके विभिन्न प्रकारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये, क्योंकि एक आधार पर राष्ट्रीय आय का वितरण वांछनीय माना जा सकता है दूसरे आधार पर अवांछनीय। वितरण के निम्नलिखित पाँच प्रकार हैं—

“(१) प्रदेश की कुल आय का विभिन्न क्षेत्रों में वितरण—हमें इस बात का स्पष्ट निर्णय करना होगा कि किन प्रादेशिक सीमाओं की आय को अधिकतम करना है। अन्य शब्दों में, हमारे सम्मुख राष्ट्रवादी एवं विश्ववादी लक्ष्यों में चुनाव करने की समस्या उदय होती है। संरक्षणवादियों पर स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि वे जहाँ दो देशों के मध्य व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना लाभदायक समझते हैं वहाँ अपने ही देश के भीतर विभिन्न भागों के मध्य होने वाले व्यापार पर कोई प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं समझते। यह आरोप लगाने समय वास्तव में दृष्टिकोण सम्बन्धी भेद की, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की है, उपेक्षा

¹ Ibid, pp 215-216

कर दी गई और इसलिए यह ठीक नहीं है। सरक्षणवादियों की इस घोषणा में, टैरिफ (tariff) दोनों ही देशों के लिए—जो इसे लगावे और जिसके विरुद्ध लगाया जाय—उपयोगी है, असंशय हो सकती है किन्तु तब नहीं जबकि वे यह स्वीकार करते हो कि विदेशी देश हानि उठावेंगे। कारण, उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण में विदेश को हानि सम्मिलित नहीं है। दूसरी ओर, जब वे अपने देश के विभिन्न भागों के मध्य व्यापार पर विचार कर रहे होते हैं तब वे एक भाग को हानि की दूसरे भाग के लाभ से तोलते हैं और इस तुलना के फलस्वरूप यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि हानि की अपेक्षा लाभ कम है तो उनकी दृष्टि में ऐसा टैरिफ अवांछनीय होगा।

(२) वर्गों और धन्यों में 'कार्यात्मक' वितरण—इस प्रकार के वितरण का सम्बन्ध धनिकों और निर्धनों के मध्य, दहात और शहूर के मध्य, अर्जित एवं अनाजित के मध्य तथा मजदूरिया ब्याज, लगान और लाभ के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण से है।

(३) वर्ग-विशेष के भीतर पृथक्-पृथक् व्यक्तियों के मध्य वितरण—इस प्रकार के वितरण में, वर्गों और धन्यों के मध्य वितरण में कोई परिवर्तन हुए बिना हो, परिवर्तन हो सकता है। कुछ उदार विद्वानों की यह इच्छा है कि उत्पादन में कोई परिवर्तन न किया जाय, क्योंकि इससे व्यक्तियों के मध्य आय का वितरण बदल जाता है, जिसके फलस्वरूप कुछ लोगों की आय उच्च स्तर से, जिसके कि वे आदी हो चुके हैं, नीचे गिर जाती है।

(४) दो सभ्यतावधियों में सामाजिक उत्पत्ति का वितरण—आय यह तक जाता है कि एक ही हुई नीति, जैसे—स्वतन्त्र व्यापार, वर्तमान में तो अधिक सामाजिक उत्पत्ति सम्भव बनावेगी किन्तु भविष्य में इसके घटने का कारण बनेगी।
२. 'शिशु उद्योग टैरिफ' (infant industry tariffs) के समर्थन का आधार यही दृष्टिकोण है।

(५) आय का स्वायत्त एवं असकी सुरक्षा—यह भी विचारणीय है कि आय अवधि-मर्यात में नियमित रूप में प्राप्त होती है, अथवा, कभी अधिक मात्रा में तो कभी कम मात्रा में। कुछ लोगों की सम्मति में एक छोटी किन्तु नियमित आय एक बड़ी किन्तु अनियमित आय की अपेक्षा श्रेष्ठ होती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'व्यापारिक नीति' शब्द से आप क्या समझते हैं ? आप यह कैसे नियंत्रण करेंगे कि एक विशिष्ट व्यापारिक नीति वांछनीय है अथवा नहीं ?

[What do you understand by the term 'trade policy' ? How

will you decide whether a particular trade policy is desirable or not ?]

- २ 'कुछ भी हो, अब हमारे सामने दो पैमाने हैं—राष्ट्रीय आय का निरपेक्ष आकार और इसके वितरण का ढग, इनके अलग-अलग परिणाम निकलते हैं।' (हैबरलर) विवेचन कीजिये।

[“In any case there are now two yardsticks, the absolute size of the national income and its mode of distribution—and one may lead to a different conclusion from the other” (Haberler) Discuss]

- ३ वे कौन से लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिये एक व्यापारिक नीति को प्रयत्नशील होना चाहिये ? विज्ञान की सीमा में रहते हुए यह कहना कहाँ तक सम्भव है कि अमुक उपाय 'वांछनीय' अथवा 'सही' है ?

[What are the ends which a trade policy should achieve ? How far is it possible, while remaining within the realm of science, to assert that particular measures are 'desirable' or 'correct' ?]

स्वतन्त्र व्यापार

(Free Trade)

परिचय—‘स्वतन्त्र व्यापार’ से आशय

स्वतन्त्र व्यापार वह नीति है जिसके अन्तर्गत देशों के मध्य आयातों और निर्यातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। एडम स्मिथ (Adam Smith) के शब्दों में—
स्वतन्त्र व्यापार नीति वह व्यापारिक नीति है जिसके अधीन स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है तथा इनमें से किसी को भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है।¹ इस प्रकार, एक स्वतन्त्र-व्यापार-व्यवस्था (Free Trade Economy) में कोई कर नहीं लगाये जाते और यदि कभी कोई कर लगाया जाता है तो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए, स्वदेश निर्मित वस्तुओं की सुरक्षा देने के लिये नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (एडम स्मिथ, रिकार्डों और अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार के प्रबल समर्थक थे। वास्तव में, लगभग एक सौ वर्ष तक इस सिद्धांत का बोलबाला रहा। वास्तव में अनेक अर्थशास्त्री स्वतन्त्र व्यापार प्रणाली की पुनर्स्थापना का प्रबल समर्थन कर रहे हैं। प्रो० रॉबिन्सन, हैबरलर और अन्य अर्थशास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार नीति की ही सुरक्षण को अंश उल्टा बताया है।

स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क

सोमहरी सताब्दी में बहु-प्रचलित व्यापारवादी विचारधारा के अनुसार सोना चांदी प्राप्त करना ही राष्ट्र की शक्ति का आधार था। जिन देशों में सोना चांदी की कान्ठे नहीं थे उन्हें य धातुओं केवल विदेशी व्यापार में अनुकूल सत्तुलन रत्न कर ही प्राप्त हो सकती थी। अतः अनुकूल-व्यापार-सत्तुलन की प्राप्ति के लिये कठोर

1 "Free trade is that system of Commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and, therefore neither imposes additional burdens on the latter nor grants any special favours to the former"—Adam Smith : quoted by Palgrave in Dictionary of Political Economy, Vol II, p 143.

प्रतिस्पर्धात्मक नीति अपनाई गई थी। किन्तु सन् १७७६ में एडम स्मिथ की पुस्तक *Wealth of Nations* के प्रकाशन ने सरक्षणवाद या प्रतिस्पर्धात्मक नीति के विरुद्ध एक कठोर वातावरण उत्पन्न कर दिया। धन धन जनमत स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में प्रबल हो गया और इङ्ग्लैंड के नेतृत्व में, जिसे स्वतन्त्र व्यापार से विशेष लाभ था, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा हटाया जाने लगा। किन्तु 'पूर्ण' स्वतन्त्र व्यापार कभी भी स्थापित न हो सका। २० वीं सताब्दी में, विशेषतः आर्थिक मन्दी के युग में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की एक बाढ़-सी आ गई। आशा की गई कि इनसे सम्बद्ध देशों की आन्तरिक दशा सुधर जायेगी, किन्तु ऐसा नहीं हो सका। अतः इन प्रतिस्पर्धा को दूर करने के उपाय सोचे जाने लगे। इस प्रयत्न में द्वितीय महायुद्ध बाधक हुआ। युद्धोत्तर काल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गैट आदि संगठनों की सहायता से प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम करने के प्रयत्न सफलतापूर्वक जारी हैं। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में प्राप्त निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं —

(१) सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति का अधिकतम् होना — एडम स्मिथ ने स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन इस आधार पर किया था कि यह श्रम के विभाजन को प्रोत्साहित करता है तथा भाग बढ़ाने में सहायक होता है। श्रम विभाजन के विस्तार में भी स्वतन्त्र व्यापार बड़ी सहायता करता है। कारण, इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश स्वतन्त्र ही वस्तुओं का उत्पादन करने पर अपना समस्त ध्यान केन्द्रित करता है। जिनमें कि उसे विशेष सुविधायें प्राप्त होने में वह सक्ता ही उत्पन्न कर सकता है। वास्तव में, एडम स्मिथ ने बड़े ही परिश्रमपूर्वक यह दिखाया था कि स्काटलैण्ड में अगूर उत्पन्न करने में गम्भीर हानियाँ उठानी पड़ेंगी जबकि इन्हें आयात करने में तथा बिकाने में कम श्रम और पूँजी वाले उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं देने में लाभ है।

‘सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति’ (social net product) तीन तरह से अधिकतम् होती है — (अ) कटु प्रतियोगिता असावधान और अनुसृत उत्पादकों को उत्पादन क्षेत्र में से निरन्तर बाहर निकालती रहती है, जिससे कि केवल अति कुशल फर्म ही उत्पादन-क्षेत्र में रह जाती है, (ब) उपलब्ध साधनों को अधिक से अधिक विवेक सम्मत प्रयोगों में स्तेमाल किया जाता है, एवं (स) श्रम विभाजन द्वारा भी अधिक उत्पत्ति बढ़ता सम्भव हो जाता है। श्रम-विभाजन में प्रति श्रमिक-उत्पादकता में तीन तरह में वृद्धि होती है—(i) कार्य कुशलता में वृद्धि, (ii) समय की बचत, और (iii) दानों का प्रयोग।

प्रो० हैबरलर (Habeler) की सम्यति में सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम् होना ही स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष का मुख्य तर्क है। वह लिखते हैं कि—“यदि यह मान कर लें कि सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम् होना एक वांछनीय उद्देश्य है, तो हम यह देखेंगे कि स्वतन्त्र व्यापार के फलस्वरूप सामाजिक उत्पत्ति अधिकतम् सीमा तक

बढ़ जाती है। अतः यही स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक का आधार है, जो विज्ञान सम्मत है भले ही इसके समर्थन में अन्य तर्क क्यों न प्रस्तुत किये जायें।¹

(२) वास्तविक विश्व शान्ति की पूर्ण शर्त—जब तक विश्व विभिन्न पृथक्-पृथक् आर्थिक गुटों में बँटा रहेगा (जिनमें से प्रत्येक गुट विश्व के व्यापक हितों की उपेक्षा करके हृद्ये एक स्वार्थपूर्ण नीति अपनाता है), विश्व-शान्ति की आशा बेकार है। स्पष्टतः, यदि हम विश्व में स्थाई शान्ति चाहते हैं, तो राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मक नीतियों को जी-प्रातिस्पर्धी छोड़ दें और एक दूसरे के प्रति (चाहे देश छोटा हो या बड़ा, धनी हो या गरीब, विकसित हो या अविकसित, निकट हो या दूर का) समानता का व्यवहार करें।

(३) चक्र विरोधी उपाय—स्वतन्त्र व्यापार की नीति व्यापार चक्रों के विस्तार को घटाने में सहायक होती है, क्योंकि आन्तरिक विस्तार के कमस्वरूप व्यापार सन्तुलन में पतनग्रस्तता आती है, जिससे कोष घटने लगते हैं और परिणामस्वरूप करौसी का संकुचन होता है। इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था पर एक मुद्रा विस्फीतिक दबाव (deflationary pressure) पड़ने लगता है जो इससे पूर्व चले आ रहे मुद्रा प्रसारिक प्रभाव को सन्तुलित करता है। एक विपरीत दशा में अमुकूल व्यापार सन्तुलन मुद्रा प्रसारिक दबावों को प्रोत्साहित करता है। इससे यह प्रगट है कि स्वतन्त्र-व्यापार एक चक्र विरोधी हथियार का काम करता है तथा इसलिए बड़ा ही उपयोगी है।

(४) सस्ती से सस्ती कीमतों पर वस्तुओं की अधिक से अधिक पूर्ति - धन-विज्ञान के द्वारा विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करके स्वतन्त्र व्यापार सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं की कीमतें घटने में सहायक होता है। यही नहीं, लोग विश्व में वही के भी वस्तुओं सरीख समते हैं। इस प्रकार, वे वस्तुओं की निम्नतम कीमतों पर अधिकतम पूर्ति प्राप्त कर सकने हैं। इसमें उनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है एवं उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है।

(५) सभी देशों को कच्चे माल तक पहुँच के समान अवसर—चूँकि स्वतन्त्र व्यापार किसी दश के विरुद्ध या पक्ष में भेद-भाव की रीति है, इसलिए विश्व के सभी देशों को कच्चे माल तक पहुँचने के समान अवसर मिलने हैं। सन् १९३० और सन् १९३६ के मध्य स्वतन्त्र भारत अस्त-व्यस्त हो गया था और द्विपक्षीय व्यापार में सम्मिलित उत्पन्न किये जाने लगे थे। इसने सम्पूर्ण विश्व व्यापार की संरचना में बड़े

1 "Only upon this basis, and of course under the assumption that the desired end is the maximisation of the social product, can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore-ground"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 222

उलट-फेर हुए। यही कारण था कि, जर्मनी इटली और जापान ने, जिनके पास कच्चे माल का अभाव था, उपनिवेशों के पुनर्वितरण की मांग की। जापान ने तो चीन पर आक्रमण करके मंचूरिया छीन लिया था, जो कि अनेक कच्चे मालों का अग्न्याश्रय है। किन्तु स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था के अधीन कच्चे मालों के भण्डार किसी एक देश विशेष की वसीती नहीं होते। बहुपक्षीय व्यापार की प्रक्रिया द्वारा इनका प्रयोग उन सब देशों द्वारा जिनके पास कच्चे मालों की कमी है किया जा सकता है।

(६) भुगतानों के दृष्टिकोण में सुविधा—स्वतन्त्र व्यापार वस्तुओं के आवा-गमन द्वारा अर्थात् देणदार देशों से निर्यात और लेनदार देशों को आयात की व्यवस्था करके देणदार देशों में लेनदार देशों को भुगतानों का हस्तान्तरण सुविभाजनक बनाता है।

(७) करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता का आधार—करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता तब तक सम्भव नहीं हो सकती है जब तक कि स्वतन्त्र व्यापार न अपनाया जाय। अन्य शब्दों में, राष्ट्रीय करसियों की बहुमुखी परिवर्तनीयता (multilateral convertibility) स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था से अनिवार्य रूप से सम्बन्धित है। चूँकि यह व्यवस्था चतुर्थ-दशक में मज्जु हो गई, इसलिए स्वर्णमान भी दूढ़ गया था।

(८) हानिकारक एकाधिकारों की स्थापना पर रोक—स्वतन्त्र व्यापारियों (Free Traders) द्वारा यह तर्क भी दिया जाता है कि आयात-निर्यात की स्वतन्त्रता सभी भाग लेने वाले देशों को इसलिए भी लाभप्रद है कि वे हानिप्रद एकाधिकारों की स्थापना को रोकते या कमिष्ठ बनाते हैं। हैबरलर का कहना है कि इस तथ्य पर दो दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये—(अ) सामाजिक उत्पत्ति को बढ़ाने की दृष्टि में, एवं (ब) इसके वितरण पर प्रभाव की दृष्टि से।

जब कि उत्पादन घटती हुई लागतों के अन्तर्गत किया जा रहा है, तब आयात करों द्वारा पुनः बनाये गये छोटे-छोटे क्षेत्रों में यह खतरा है कि उद्योग की अनेक शाखाओं में, जिनमें बृहत् उत्पादन बहुत लाभप्रद है, बाजार के अत्यधिक छोटा होने के कारण, उत्पादन-दरकार का अनुकूलतम आकार प्राप्त न हो सके। इसी का पूरक है एनाधिपतियों का निर्माण। इससे (प्रतिबन्ध से) अर्थ-व्यवस्था को तीन हानियाँ होती हैं —

(१) चूँकि स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक देश उत्पादन की कुछ ही शाखाओं में विशिष्टीकरण करता है, इसलिये उत्पत्ति का अनुकूलतम आकार प्राप्त किया जा सकता है तथा लागतें सर्वोच्च हो कम हो सकती हैं। किन्तु व्यापार पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध न केवल देशों के अन्तराष्ट्रीय श्रम विभाजन के इन लाभों से वंचित कर देते, बल्कि नीचे की दो हानियाँ भी उठाने के लिये विवश कर देते हैं।

- (ii) प्रतिस्पर्धा की जाड़ में एकाधिकार बन जाते हैं और एकाधिकारी उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागतों की अपेक्षा, जो कि सीमित बाजार के लिये सीमित ही उत्पत्ति करने के कारण पहले से ही ऊँचे स्तर पर हैं, अधिक बढ़ जाती है, एवं,
- (iii) अनुभव से यह भी पता चलता है कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर प्रतिनियंत्रण से अधिक मामलों के संचालन में कुशलता की कमी हो जाती है।

फिन्नु, यह स्वीकार करना होगा कि स्वतन्त्र व्यापार भी एकाधिकारों के निर्माण के बिना एक 'पूर्व' बनाव नहीं है। अर्थात् स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत भी अन्तर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय एकाधिकार बन सकते हैं। विशेषतः स्थानीय एकाधिकारों की ही सीखिये। इनके उदय के लिये यातायात व्यय, जिनका प्रभाव टैरिफ के महत्व ही पड़ता है, काफी होने है।¹ उत्पत्ति की उन यातायात में, जिनके उत्पादों की केवल ऊँचा व्यय उठाकर ही यातायात किया जा सकता है, एक बृहत् उत्पादन-इकाई के फलस्वरूप सम्भव हुई नीची उत्पादन-लागतें, उत्पादों की एक विस्तृत क्षेत्र में विपणन करने की बड़ी हुई सामर्थ्य से, निम्नभावित हो जाती हैं। जब ऐसा हो, तो एक मूल्य वाले एक बाजार के बजाय एकाधिकारी जिलों की एक शृङ्खला बन जाती है, जो एक-दूसरे में कुछ सीमा तक विस्तृत होते हैं। इन जिलों के एक दूसरे पर विस्तृत भागों में तो प्रतिस्पर्धा कीमतें प्रचलित होती हैं किन्तु प्रत्येक जिले के आंतरिक भाग में एकाधिकारी कीमतों का ही बोखबासा रहता है। ये एकाधिकारी कीमतें प्रतिस्पर्धी कीमतों में केवल यातायात व्यय की राशि से ही अधिक होती हैं।

यदि ऐसे उत्पादन जिलों की शृङ्खला के बीच से एक प्रभुत्व दोवार खड़ी हो दी जाय, तो साधनों और उत्पादों की यातायात व्यय सम्बन्धी स्थिति द्वारा निर्धारित उत्पादन इकाइयों की विद्यमान एवं विवेक समस्त व्यवस्था में विपन्न पड़ जायगा, और साथ ही एकाधिकारों की शक्ति भी बढ़ जायेगी। ये दोनों प्रभाव जिलों के सामान्त पर विशेष रूप से दृष्टिगोचर होंगे। उदाहरण के लिये, दो एकाधिकारी जो किसी क्षेत्र में पहले प्रतियोगिता करते थे, अब यह देखेंगे कि उस क्षेत्र में एक प्रभुत्व दोवार बनी हुई है जो उन्हें एक दूसरे की प्रतियोगिता के प्रभाव

¹ "Nevertheless, Free Trade does not provide a complete safeguard against the formation of monopolies. Even under Free Trade there may emerge international monopolies, and local monopolies. These local monopolies owe their existence in the absence of a tariff, to transport costs which have much the same effect as tariffs"—*Ibid*, 224

स सुरक्षित रखती है। परिणामतः प्रदुल्ल दीवार की गोट में वे अपनी कीमते पहले से नहीं अधिक बढ़ा सकेंगे।^१

इस प्रकार, स्वतन्त्र-व्यापार-संग्रहालय (Free Trade School) के अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि देशों के मध्य व्यापार पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहिए, राजकीय हस्तक्षेप बिल्कुल भी न हो। प्रो० संमुअलसन (Samuelson) के शब्दों में—“अप्रतिबंधित व्यापार एक परस्पर लाभदायक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है समस्त देशों के सम्मिलित वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति में बहुत ही अधिक वृद्धि कर देता है तथा विश्व भर में ऊँच जीवन स्तर सम्भव बनाता है।”^२ प्रो० हैबरलर (Habesler) ने भी स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करते हुये इस बात पर बहुत ही जोर दिया है कि यह सामाजिक उत्पत्ति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा देता है।^३

“स्वतन्त्र व्यापार के लिये तर्कों की वृद्धता अन्य देशों द्वारा वैसी ही नीति अपनाये जाने पर निर्भर नहीं”

स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों ने एक स्वतन्त्र व्यापार नीति की अपेक्षा के अनेक लाभ, जिनका हमने ऊपर वर्णन किया है गिनाये है। किन्तु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण लाभ सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति (social net product) और सामाजिक कल्याण (social welfare) का अधिकतम हो जाना है। यदि विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो व्यापार के इन लाभों (gains of trade) में कमी आ

^१ “If a tariff wall is erected which cuts across such a network of production districts first the existing and rational arrangement of production units over space determined by the freight situation of factors and products will be disturbed and secondly, the power of the monopolies will be strengthened. Both these effects will be especially obvious in the neighbourhood of the tariff wall”—*Ibid* p. 224

^२ Unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries and makes possible higher standards of living all over the globe”—Samuelson

^३ “Only upon this basis and of course, under the assumption that the desired end is maximisation of the social product can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore ground”—Habesler *The Theory of International Trade*, p. 222

जावेगी क्योंकि प्रतिबंधों के कारण विश्व के विभिन्न देशों में प्रमाणों का वितरण और प्रयोग अनाधिक ढङ्ग में होने लगता है।

प्रतिष्ठित अर्थ-शास्त्रियों ने स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में एक और भी तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्तिगत देश की व्यापार विपक्षक मामलों में एक खुले द्वार की नीति (Open door policy) अपनानी चाहिए, क्योंकि विश्व के अन्य देश भी वंसा ही कर रहे हैं। यदि एक देश विशेष रूप विश्व के विरुद्ध प्रति-बन्धान्मक नीति (Restrictionist Policy) अपनाये, जबकि अन्य सब देश स्वतन्त्र व्यापार नीति पर चल रहे हैं, तो प्रतिबन्ध लगाने वाले देश की नीति अन्य देशों की भी प्रति-बन्धान्मक नीति ग्रहण करने के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार, धर्म-धर्म प्रभुत्व दोबारे सब देशों में खड़ी हो जायेगी, जिसमें विदेशी व्यापार की मात्रा (Volume) नगण्य रह जायेगी।

अर्द्ध विकसित अर्थ-व्यवस्थाएँ एवं स्वतन्त्र व्यापार नीति (Backward Economies and Free Trade Policy)

निमन्त्रेह, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा है, स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। किन्तु ये तर्क कुछ मान्यताओं के अधीन ही वैध हैं, जो कि निम्न हैं — (i) कि उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से रोजगार मूल्य हैं, (ii) कि स्वतन्त्र गतिशीलता पाई जाती है, तथा (iii) पूर्ण प्रतिप्रोत्तिता विद्यमान है। इन मान्यताओं को पूरा करने वाली अर्थ-व्यवस्था में प्रसाधन उत्पत्ति की विभिन्न शाखाओं में विवेकपूर्ण ढंग में सगे होने हैं। ऐसी दशा में, यदि प्रतिबन्धान्मक नीति अपनाई गई, तो प्रमाण अधिक लाभदायक उपयोगी (Uses) में हटने के लिए विवश हो जायेंगे तथा उन्हें कम लाभदायक उपयोगी में लगाना पड़ेगा। इससे उनमें वैकारी पैनेगी तथा सामाजिक शुद्ध उपज और सामाजिक कल्याण में भी कमी जायेगी।

किन्तु कीन्स ने अपनी विख्यात पुस्तक, 'सामान्य सिद्धांत' (General Theory) में स्वतन्त्र व्यापार बनाम संरक्षणवाद-विवाद पर एक नये ढंग में प्रकाश डाला है। उनके तर्कों का कुछ पर, सार यह है कि आर्थिक दृष्टि में पिछड़े हुए देश संरक्षण की नीति अपना सकते हैं।

कीन्स का कहना है कि एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के लिए, जिसमें पूर्ण और निरन्तर रोजगार भिन रहा है, स्वतन्त्र व्यापार का औचित्य संदेह रहित है। एक पूर्ण रोजगार वाली अर्थ-व्यवस्था (अर्थात् अति विकसित देश) में वास्तविक राष्ट्रीय आय को अधिकतम करने हेतु उत्पादन व्यय न्यूनतम करने पड़ते हैं। यदि वहाँ संरक्षण की नीति अपनाई जाय, तो उत्पत्ति प्रसाधन कुछ प्रयोग वाले उद्योग में लगने के बजाय कम बुजल प्रयोग वाले उद्योग में रुकने के लिए विवश हो जायेंगे, जिसमें उत्पादन लागत में वृद्धि होकर सामाजिक शुद्ध उपज (वास्तविक राष्ट्रीय आय) बढ़ने के बजाय घट जायेगी। अतः पूर्ण रोजगार वाले देशों के लिए संरक्षण की नीति उचित नहीं है।

किन्तु अर्धव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार का स्तर कोसों ऊपर होता है। वहाँ विश्वास माना में प्रसाधन (मानव एवं सामग्री) निष्क्रिय पड़े होते हैं। क्या इन परिस्थितियों में एक प्रतिवन्धक नीति अपनाने में सामाजिक शुद्ध उपज में कमी आयेगी और, इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्तों का उत्पन्न होगा ?

इसका उत्तर है— नहीं। यदि उत्पत्ति साधन (मानवीय + भौतिक) पहले से ही बेकार हैं और यदि सरक्षण के द्वारा अब तक बेकार पड़े हुए प्रसाधनों को लाभदायक काम देना सम्भव है, तो समाज की शुद्ध उत्पत्ति में, स्वतन्त्र व्यापार का उत्पन्न करने पर भी कोई कमी नहीं आयी। कारण, सरक्षण के अन्तर्गत, प्रभावपूर्ण माँग का स्तर ऊँचा हो जाता है, जिससे अधिक उत्पादन किया जाने लगता है तथा अधिक रोजगार मिलना सम्भव हो जाता है। चूँकि रोजगार में वृद्धि हो जाती है, इसलिए राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। यदि देश स्वतन्त्र व्यापार की नीति पर अड़ा रहता, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती थी।

इस प्रकार, स्वतन्त्र व्यापार का सिद्धान्त केवल पूर्ण नियोजन (full employment) सम्बन्धी दशाओं की मान्यता के अधीन मत्त है किन्तु पूर्ण से कम रोजगार वाली दशाओं में सरक्षण का सिद्धान्त सत्य होता है। इस प्रकार, इन दोनों सिद्धान्तों में परस्पर कोई असंगति नहीं है क्योंकि वे अलग-अलग परिस्थितियों के लिए बनाये गये हैं।

“अर्धव्यवस्था जो न तो साम्य में है और न साम्य को ओर बढ़ती हुई प्रतीत होती है”

मैकमिलन कमेटी रिपोर्ट (१९३०) के परिशिष्ट में लार्ड कोन्स ने यह दिलाया था कि एक ऐसी अर्धव्यवस्था में, जोकि न तो साम्य में है और न साम्य की दिशा में बढ़ती हुई प्रतीत होती है, विश्वास मानवीय एवं भौतिक प्रसाधन बेकार एवं निष्क्रिय पड़े होते हैं, जिससे वहाँ सरक्षण, न कि स्वतन्त्र व्यापार, इन प्रसाधनों को पूर्ण रोजगार दिलाने में सहायक हो सकता है। निम्नवत् अर्धव्यवस्था में स्थायी बेकारी की विद्यमानता स्वतन्त्र व्यापार को उस अर्धव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त बना देती है।

स्वतन्त्र व्यापारियों का उद्देश्य (The Aim of Free Traders)

स्वतन्त्र व्यापार के लिए समर्थन जिस लक्ष्य की पूर्ति पर आधारित है वह सामाजिक उत्पत्ति या राष्ट्रीय आय का अधिकतम होना है। यहाँ प्रश्न उदय होता है कि किस वर्ग के व्यक्तियों की आय अधिकतम होना उद्देश्य है ?

यह निरन्तर कहा जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक एवं विश्ववादी रण्टिकोण अग्रगण्य हैं, वे सम्पूर्ण विश्व की हानि की विचार में लेते हैं और मर्षर्ष की दशाओं में अपने निज के देश के हितों की बलि देने की तैयार रहते हैं। किन्तु यह धारणा सही नहीं है, स्वतन्त्र व्यापार की धारणा के लिए विश्ववादी उद्देश्य

बिन्दुल भी आवश्यक नहीं है। यद्यपि यह स्वीकार करना होना कि किसी विशेष देश के हितों का बजाय यदि समस्त विश्व को विचार में रख तो अप्रतिबंधित व्यापार के लाना जो अधिक सुगमता के साथ स्पष्ट किया जा सकता है।¹ इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीयवाद में एक मनोवैज्ञानिक सहानुभूति सम्भव है किन्तु वे एक दूसरे से अनिवार्य बने हुए नहीं हैं। स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में आर्थिक तर्क यह दिखाना है कि सभी भाग लेने वाले देश इसमें साथ उठाते हैं किन्तु वह इस बात का नहीं दिखलाता कि एक का लाभ दूसरे की हानि है। इस प्रकार एक राष्ट्रवादी एक ठो विस्वास वाला स्वतन्त्र व्यापारी हो सकता है।

एक ओर स्वतन्त्र व्यापार एवं आर्थिक उदारतावाद में और दूसरी ओर समाजवाद अथवा हस्तक्षेपवाद में क्या अन्तर है? इस विषय में याद रह कि स्वतन्त्र व्यापार उदारवादी वास्तु व्यापार प्रणाली है जो राज्य द्वारा आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्र वापसलाप में प्रत्येक हस्तक्षेप का विरोध करती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि एक प्रारंभ अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन करना और दूसरी ओर (उदारवादी) श्रम बाजार में आर्थिक शक्तियों के स्वतन्त्र वापसलाप में हस्तक्षेप का मुकाबला परस्पर अलग है।

असमर्थ हुए बिना कोई व्यक्ति एक ओर आयात करों का विरोधी और दूसरी ओर श्रमकों के हितों पर राज्य हस्तक्षेप का समर्थक कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि स्वतन्त्र व्यापार कम से कम दीव्यता में राष्ट्रीय धन के कार्यात्मक वितरण (functional distribution) को उनिक भी प्रभावित नहीं करता। अतः वह श्रम की सापेक्षिक आय (relative income) को नहीं घटाता और उसकी निरपेक्ष आय (absolute income) को तो घटा नहीं सकता। इसका निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय आय के वितरण से सम्बंधित धारणाएँ स्वतन्त्र व्यापार की लाभदायकता को ठेस नहीं पहुँचाती हैं। हाँ यह सत्य है कि धूर्ति स्वतन्त्र व्यापार सिद्धांत श्रम मूल्य सिद्धांत पर जो कि धार्मिक वगैरे राष्ट्रीय आय के परिवर्तित वितरण का सम्भावना पर स्पष्ट रूप में विचार नहीं करता है आधारित है। इसलिए इस सोना तक वह अपर्याप्त है। किन्तु उपरोक्त अपर्याप्तता के फलस्वरूप आधुनिक सिद्धांत के दृष्टिकोण में तथा राष्ट्रीय आय के वितरण में स्वतन्त्र व्यापार के फलस्वरूप कोई परिवर्तन होने की सम्भावना की दृष्टि से सिद्धांत की संधता पर कोई चोट नहीं आती है।

1 a cosmopolitan aim is in no way essential to the Free Trade postulate although it must be admitted that it is easier to explain the advantage of unrestricted exchange of goods if one takes account of the whole world rather than considers only the interests of the particular country — Haberler *The Theory of International Trade* p. 225

परीक्षा प्रश्न :

- १ स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिये जाने वाले प्रमुख तर्क क्या हैं ? आधुनिक आर्थिक विचारधारा के मद्देन में उनकी समीक्षा करिये ।

[What are the chief arguments advanced in favour of Free Trade ? Examine them critically in the light of modern economic thought]

- २ 'एक देश की स्वतन्त्र व्यापार की नीति केवल इसलिए अपनानी चाहिए क्योंकि अन्य देश भी वैसे ही नीति अपनाये हुये हैं ।' इस तर्क की वैधता पर प्रकाश डालिये ।

["The validity of the argument for a free trade policy in any country does not depend upon the adoption of the same policy in other countries " Discuss]

- ३ क्या आप कीन्स के इस मत से सहमत हैं कि देश में विशाल और स्थाई बेरोजगारी की विद्यमानता स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष को उलट देती है ? यह समझाइये कि क्या संरक्षण एक ऐसी अवस्था के लिए उचित है जो कि व तो सामान्य-वस्था में है और न साम्य की दिशा में बढ़ रही है ।

[Do you agree with Keynes in holding that a permanent mass of unemployment alters the case for free trade ? Discuss whether protection suits an economic system which is neither in equilibrium nor in the sight of equilibrium]

- ४ आप इस दृष्टिकोण में कहीं तक सहमत हैं कि जबकि स्वतन्त्र व्यापार विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए सर्वोत्तम है तब अल्प विकसित अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए वह हानिप्रद है ? उत्तर के लिए कारण दीजिये ।

[How far do you agree with the view that whereas free trade might be in the best interests of developed economies it is always harmful to under developed economies ? Give reasons for your answer]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

- ५ क्या स्वतन्त्र व्यापार विकसित देश के लिये एक पर्याप्त वृद्धि दर के माध्यम से संभव है ? आप विवेचनात्मक प्रतिपत्ति को क्या महत्त्व देंगे ?

[Is free trade compatible with an adequate rate of growth for a developing economy ? What place would you assign to discriminating restriction ?]

(जीवाजी, एम० ए०, १९६७)

- ६ स्वतन्त्र व्यापार को महत्ता स्पष्ट कीजिये । किन दशावस्थाओं में वह एक बड़ा विकसित देश के लिये एक उपयुक्त नीति हो सकती है ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये ।

[Explain the significance of free trade Under what conditions could free trade be a suitable policy for an under developed country ? Give your answer with examples]

(बिनाम, एम० ए०, १९६६)

- ७ किन परिस्थितियों में स्वतंत्र व्यापार एक अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उचित हो सकता है ? क्या ऐसी परिस्थितियाँ कुछ नीति संबंधी निर्णयों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं ?

[Under what conditions would free trade be justified from the point of view of under developed economies ? Is it possible to bring about such conditions by some policy decisions ?]

(इलाह, एम० ए०, १९६६)

संरक्षण

(Protection)

परिचय—

स्वतन्त्र व्यापार के समयन में दिये जाने वाले तर्क स्पष्ट हैं तथा इन्हें व्यापारिक नीति पर लागू करना सुगम भी है। किन्तु टैरिफ या संरक्षण के बारे में ऐसा नहीं है। इसका समयन करने वाले तर्क एक ओर तो परस्पर विरोधी हैं, और, दूसरी ओर, यदि इन्हें स्वीकार भी कर लिया जाय तो, व्यावहारिक दृष्टि से उनका कार्य और प्रभाव स्पष्ट नहीं है। स्वतन्त्र व्यापार के सम्बन्ध में जिस सुगमता से यह कह सकते हैं कि आन्तरिक और बाह्य व्यापार में कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिये उस प्रकार से संरक्षण के बारे में नहीं कहा जा सकता। यदि कहे कि टैरिफ आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, तो इसके साथ ही साथ यह भी बताना पड़ेगा कि वह किन परिस्थितियों के अन्तर्गत लाभदायक है और किन में नहीं, तथा टैरिफ को कितना ऊँचा रखा जाय। अतः प्रत्येक तर्क पर विभिन्न परिस्थितियों के सदृश में विचार करना होगा। ध्यान रहे कि कुछ ऐसे तर्क हैं जो विज्ञान सम्मत नहीं हैं तथा बाधूली तर्क द्वारा रह किये जा सकते हैं व्यवहार में, संसद, राजनैतिक दलों के विवेचनो तथा समाचार पत्रों में सबसे अधिक महत्व पाते हैं।

संरक्षण के गुण-दोष

संरक्षण की नीति के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर प्रायः कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। अब व्यापार के सामो में कमी हो जाती है। यह एक ऐसी हानि है, जिसे तब ही उचित ठहराया जा सकता है जबकि इसके लिए पर्याप्त कारण हो। नीचे उन परिस्थितियों या तर्कों का उल्लेख किया गया है, जिनमें या जिनके आधार पर संरक्षण उचित माना जा सकता है।

संरक्षण के पक्ष में तर्क (गुण)—

संरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें गैर-आर्थिक (Non-economic) एवं आर्थिक (Economic) तर्कों में विभक्त किया जा सकता है।

(I) संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तर्क—

गैर-आर्थिक दृष्टिकोण से, जिस पर कोई विशेष ध्यान न भी दिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं है, संरक्षण के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं :—

(१) सुरक्षा उद्योग तर्क (Defence Industries' Argument) यह आवश्यक है कि देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय, चाहे ऐसा करने में कुछ आर्थिक नुकसान ही उठाना पड़े। प्रायः संकट के समय में विदेशों से सहायता मिलना सदा ही सम्भव एवं भुगम नहीं होता। भय जैसा कि भारत की चीन और विशेषतः पाकिस्तान के आक्रमण से अनुभव हुआ है, किसी विदेशी देश पर अपनी रक्षा के लिए निर्भर रहना सस्तरनाक है। देश के पास अपने रक्षा उद्योग होने चाहिए चाह इसके लिए उसे भूखी मरना पड़े।

(२) राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता का तर्क (National Self Sufficiency Argument)—संरक्षण के पक्ष में एक अन्य गैर-आर्थिक तर्क यह है कि कुछ आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में देश की आत्मनिर्भरता होना चाहिए तथा अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी निर्भरता युद्धकाल में, जबकि विदेशी व्यापार सीमित हो जाता है, हानिकारक प्रमाणित होती है। यही नहीं, संकट के समय विदेशों में सहायता मिलने के साथ साथ राजनैतिक धरों भी जुड़ी होती हैं।

उपरोक्त दशाओं में लोग जानबूझ कर संरक्षण की नीति को अपनाते हैं, जिसमें उन्हें कुछ गैर-आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ आर्थिक साधनों का परिचालन करना पड़ता है। स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि गैर-आर्थिक दृष्टिकोण से संरक्षण एक सीमा तक वाछनीय हो सकता है, किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतन्त्र व्यापार ही सर्वश्रेष्ठ नीति है।

(II) संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क—

संरक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले आर्थिक तर्कों का बुनियादी भाव (basic idea) यह है कि संरक्षण के कारण सामाजिक उत्पत्ति में वृद्धि होती है, यह भाव स्वतन्त्र व्यापार के भाव में उल्टा है। अन्य शब्दों में, संरक्षण के पक्ष के तर्कों की स्वतन्त्र व्यापार के विपक्ष वाले तर्क कहना जा सकता है। संरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क निम्नलिखित हैं :—

(१) रेवेन्यू बढ़ाने का तर्क (The Revenue Argument)—संरक्षण की नीति का सरकार की आय बढ़ाने के लिए समर्थन किया जाता है। विशेषतः लविकसित देशों में पूँजी की बहुत कमी होती है, क्योंकि योगों की आय नीची होने से बचन कम होती हैं। अब, सरकार पर ही यह भार पड़ता है कि वह आर्थिक विकास के लिए सामाजिक पूँजी का निर्माण करे। इस दृष्टि से संरक्षण करो को ठीक समझा जाता है क्योंकि ये सरकार की आय में वृद्धि करते हैं। किन्तु, जैसा कि हेबरलर का कहना है, संरक्षण और आय प्राप्त करने के उद्देश्य परस्पर अलग हैं। कारण, जो कर अच्छी आय प्रदान करते हैं वे 'संरक्षण' नहीं दे सकते और जो

मरक्षण दे सकते हैं उनसे बाय बहुत कम होती है । अब सरक्षण का समर्थन करने वाले रेवेन्यू-तर्क में कोई विशेष बल नहीं है ।¹

(२) गृह बाजार के सृजन एवं विकास का तर्क (Creating and expanding a home market argument)—कहा जाता है कि सरक्षण देश में गृह बाजार का विस्तार करने में सहायक होगा । किन्तु यह भी सच है कि यदि एक ओर गृह-बाजार बढ़ता है तो दूसरी ओर निर्यात बाजार संकुचित होता है क्योंकि आयात कम होने के फलस्वरूप निर्यातों में कमी आ जाती है । प्रायः कहा जाता है कि जब देश में ही एक विस्तृत बाजार मौजूद है तो विदेशों में निर्यात बाजार ढूँढने की क्या आवश्यकता ? नि सवेह यह तर्क सब तक ठीक है जबकि देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली हो । क्योंकि कोई देश सब वस्तुओं में आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए कुछ वस्तुओं विदेशों से मँगाना अनिवार्य है और इस हेतु आयातों का भुगतान करने के लिए निर्यात करने की भी आवश्यकता है । फिर उद्योगों का सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय आधार के बजाय राष्ट्रीय आधार पर करने में कुल उत्पत्ति में कमी आ जाती है । कीन्स (Keynes) ने गृह बाजार के विकास के तर्क का उत्तर निम्न रोचक शब्दों में दिया है—'सरक्षण के अलग लोभों को अधिक परित्याग करना पड़ेगा । आयातों पर प्रतिबन्ध द्वारा हम जगने करने के लिए उपलब्ध काम की मात्रा तो बढ़ा लेते हैं किन्तु हमारी आय कम हो जाती है । आयात हमारी प्राप्तिवाँ और निर्यात हमारे भुगतान हैं । ऐसी दशा में अपनी प्राप्तिवाँ घटाकर हम अपनी दशा कैसे सुधार सकते हैं ? क्या ऐसी भी कोई चीज है जो कि एक भ्रुकम्प कर सकता है लेकिन सरक्षण नहीं कर सकता ?'²

¹ 'The duty which affords the maximum of protection is a prohibitive one which yields no revenue to the state. On the other hand the revenue yielded by a duty will be the greater the less the import of the goods falls off, that is to say the less the duty fulfils, its protective function'—Haberler. *The Theory of International Trade*, p. 239

² "If protectionists merely mean that under their system men will have to sweat and labour more, I grant their case. By cutting off imports we increase the aggregate of work, but should be diminishing the aggregate of wages. The protectionist has to prove not merely that he has made work, but that he has increased the national income. Imports are receipts and exports are payments. How, as a nation can we expect to better ourselves by diminishing our receipts? Is there anything better than a tariff could do, which an earth quake could not do better?"—Keynes *The Nation and Athenaeum* २० म्या, २४

(३) **व्यापार की शर्तों के सुधार का तर्क (The Terms of Trade Argument)**—यदि सरक्षण कर लगाये जायें, तो कुछ परिस्थितियों में विदेशी व्यापार की शर्तों में सुधार होता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई देश किसी अग्रातित वस्तु का एक प्रमुख आयातक है तो सरक्षण-कर लगाने से इसकी कीमत में कमी की जा सकती है। इससे देश के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार हो जावेगा। [किन्तु यह लाभ सामान्यतः उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि वह एक अन्य देश के हित को ठेस पहुँचा कर उपलब्ध होता है। साथ ही, यह ठर भी है कि वही अन्य देश प्रतिरोधार्थक कार्यवाही न करे।]

(४) **शोषित श्रम तर्क (Sweated Labour Argument)**—विश्व के प्रतिस्पर्धी देशों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि सरक्षण के अभाव में इन देशों में ऊँची मजदूरी पाने वाले श्रमिकों को मरते विदेशी श्रम के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः श्रम के हितों की रक्षा के लिए सरक्षण की नीति अपनाई जानी चाहिए। यह तर्क भी सही नहीं है क्योंकि इसका आधार यह भ्रान्त धारणा है कि स्वतन्त्र व्यापार में समस्त विश्व में मजदूरियों का समानीकरण हो जाना है। वास्तव में, जैसा कि प्रो० हैररजर ने बताया है, स्वतन्त्र व्यापार होते हुए भी मजदूरियों का समान होना सम्भव नहीं है, क्योंकि देशों के मध्य श्रम अ-गतिशील (Immobile) होता है। प्रो० बाइनर ने भी कहा है कि स्वतन्त्र व्यापार से श्रम के हितों पर घुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता।]

(५) **बदले की कार्यवाही का तर्क (Retaliation Argument)**—यह कहा जाता है कि चूँकि हम एक 'लेन्दे' की प्रवृत्ति वाले विश्व में रहते हैं और चूँकि एक स्वतन्त्र व्यापार वाले देश के तम सरक्षण की नीति पर चलने वाले देश को देने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं तो, इसलिए उसकी नीति करने की शक्ति बहुत दुर्बल होती है। इसके अतिरिक्त एकपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार हानिप्रद होता है। स्वतन्त्र-व्यापार देश अपने आपकी विदेशी प्रतियोगियों के समुच्चय में फँसने देता है। अतः सरक्षण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिरोधी सरक्षण अन्य देशों द्वारा सरक्षण कर लगाने के कुप्रभावों का सामना करने में सहायक होगा। [किन्तु यह तर्क भी बहुत ठोस नहीं है, क्योंकि, कुछ देशों की सरक्षण नीति के परिणाम-स्वरूप विश्व व्यापार के लाभ पहले ही कम हो गये हैं, प्रतिरोधी सरक्षण इन लाभों में और भी कमी कर देगा।]

(६) **रोजगार बढ़ाने का तर्क (The Employment Argument)**—प्रायः सरक्षण के पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस नीति को अपनाने से रोजगार बढ़ता है। 'ये देशों की समस्या को सुलझाने का सबसे प्रभावशाली साधन बताया जाता है। [यदि यह सच है तो हमें पता चलेगा कि सरक्षण में अल्पकाल में बेकारी में कुछ कमी अवश्य आवेगी किन्तु दीर्घकाल में नहीं।] बहुत विवेचन इसी अध्याय में आगे दिया गया है।]

(७) आर्थिक स्थायित्व का तर्क (Economic Stability Argument)—कभी-कभी मरक्षण वा समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि यह सरक्षित कार्य-व्यवस्था को अन्तर्गत अस्थिरता एवं विप्लव के अन्य भागों में उपस्थित होने वाले व्यापार चक्रों के कुप्रभावों से सुरक्षित रहेगा । [लेकिन अनुभव से यह तर्क ठीक प्रमाणित नहीं होता । सरक्षित देशों को भी व्यापार चक्रों का सामना करना पड़ा है । वास्तव में, नीचे ऊँचे सरक्षण करो स व्यापार चक्र के मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती है । फिर व्यापार चक्र का समाधान केवल सरक्षण नीति ही तो नहीं है । उसके अन्य उपचार भी तो उपलब्ध हैं जो कि सरक्षण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली हैं ।]

(८) व्यापार समुल्लेख तर्क (Balance of Trade Argument)—व्यापार-वादियों का कहना था कि देश में स्वर्ण के प्रवाह को आकर्षित करने के लिए अनुकूल समुल्लेख बनाये रखना चाहिए । इस हेतु आयातों की अपेक्षा निर्यातों की अधिकता होना आवश्यक है और निर्यात आधिक्य तब ही उपलब्ध हो सकता है जबकि एक उचित मरक्षण-नीति अपनाई जाय । [अन्य तर्कों की भाँति यह तर्क भी भ्रमात्मक है क्योंकि (i) यदि सभी देश हम नीति को अपना लें, तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कमी हो जायेगी, (ii) किसी देश के लिए अपना निर्यात-आधिक्य स्थायी रूप बनाये रखना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्यात आधिक्य के फलस्वरूप देश में आने वाला स्वर्ण कीमतों में वृद्धि करके आयातों को बढ़ा देता है, और (iii) यदि किसी देश के पास विशाल स्वर्ण कोष एकत्र हो भी जायें, तो अन्य देशों से माल ख़रीदने के अतिरिक्त और उसका क्या उपयोग किया जायेगा ?]

(९) ख़रीद शक्ति का तर्क (Purchasing Power Argument)—जैसा कि अन्तर्गत निम्न कहा करते थे, आयातों में कमी होसे से ख़रीद-शक्ति की वृद्धि होती है क्योंकि देश का धन बाहर कम जाता है । [लेकिन यह तर्क भी भ्रम पूर्ण है, क्योंकि लोगों को धन्युओं की, न कि द्रव्य की, आवश्यकता होती है, और, फिर आयातों का भुगतान निर्यातों द्वारा होता है, अतः यदि हम विदेशों से माल न मंगावे, तो विदेशों भी हमसे माल नहीं खरीद सकेंगे ।]

(१०) वैज्ञानिक प्रत्युत्क तर्क (The Scientific Tariffs Argument)—कुछ देशों में (जैसे कि जापान) उत्पात्ति की नीची लागतों के भय से, जोकि वहाँ भूजल की नीची दरें प्रचलित होने के कारण सम्भव है ऊँची लागत वाले देश (जैसे कि अमेरिका) यह तर्क देते हैं कि देश और विदेश में उत्पात्ति-लागतों में समानता की स्थापना के लिए प्रत्युत्क कर लगाये जाने चाहिए । ऐसा होने पर ही उचित प्रतिस्पर्धिता हो सकेगी । [किन्तु यह तर्क भी सर्वथा भ्रमात्मक है, क्योंकि यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल ही न हो, मनेगा, क्योंकि समस्त व्यापार लागत-भिरताओं के कारण उदय होता है ।]

(११) रक्षिपातन रोक्ने का तर्क (Prevention of Dumping Argument)—

ment) —कभी-कभी विदेशी उद्योगपति स्वदेश के विकासोन्मुख उद्योगों को समाप्त करने के लिए अपनी वस्तु को लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं, जिससे जब बाजार उनके अधिकार में आ जाय, तो वे मनमाना कीमत वसूल करके लाभ उठावें। इस कार्यवाही को 'राशि पतन' कहते हैं। ऐसी दशा में गृह उद्योग को संरक्षण देना उचित है।

(१२) उद्योगों की विविधता का तर्क (Diversification of Industries Argument) —प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार देशों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए, जिनमें उन्हें प्रतिभोगितात्मक लाभ हो। इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए विश्व अर्थ-व्यवस्थाओं को 'विकसित' एवं 'अविकसित' दो वर्गों में बाँटा गया है। विकसित देश औद्योगिक वस्तुओं और मध्य-विकसित देश प्राथमिक वस्तुओं (जैसे कच्चा माल, अर्द्ध-निर्मित माल, खाद्यान्न) के उत्पादन में विशिष्टता रखते हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि अपने प्रसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश को चाहिए कि यह अपने अर्थव्यवस्था को विविधीकृत बनाये। ऐसे विविधीकरण के पक्ष में निम्न कारण दिये जाते हैं —(i) विशिष्टीकरण के अन्तर्गत देश की अर्थव्यवस्था कुछ उद्योगों पर निर्भर हो जाती है। यह निर्भरता, मन्दों व युद्धकाल में हानिकारक हो सकती है, (ii) व्यापार की शर्तें प्राथमिक उद्योगों के लिए अधिकाधिक प्रतिकूल होती जा रही हैं। अतः उन्हें अन्य साधनों से अपनी माँग बढ़ानी चाहिए, (iii) रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के पक्षे होना आवश्यक है, एवं (iv) औद्योगिक देशों को हालत भी भविष्य में बिगड़ जावेगी, क्योंकि जैसे जैसे कृषक देशों में औद्योगीकरण बढ़ेगा, उन्हे वहाँ से कच्चा माल या खाद्यान्न मिलना कठिन होता जायेगा। अतः इन समस्याओं का समाधान संरक्षण की सहायता लेकर अर्थव्यवस्था को विविधमुखी बनाना है। [विविधीकृत अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में रखे गये तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए, कच्चे माल व खाद्यान्न के ग्योत रातों-रात तो सूख नहीं जायेंगे। इनके सूखने में कुछ समय लगेगा और इस बीच उपचार किये जा सकने हैं।]

(१३) राष्ट्रीय साधनों के सन्तुल्य उपयोग का तर्क (Conservation of National Resources Argument) —केरे और पेंटन ने तर्क दिया है कि स्वतन्त्र व्यापार में राष्ट्र के प्रसाधन जल्दी क्षय होने लगने हैं। अतः राष्ट्रीय साधनों की रक्षा के लिए संरक्षण की नीति अपनाना आवश्यक है। [दृढ़ सम्बन्ध में यह स्पष्टनीय है कि यदि सीमित साधनों का निर्वात 'कच्ची दशा' में दिया जायेगा, तो निर्माण सम्बन्धी लाभ देश से बाहर चला जायेगा। अतः देश को पहले माल के रूप में सामग्रियों का निर्माण करने से लाभ होगा।]

(१४) बुनियादी उद्योग तर्क (Key Industry's Argument) —जोह एण स्पान जैसे बुनियादी उद्योग स्वदेश को अर्थ-व्यवस्था को बहुत दृढ़ता प्रदान करते हैं।

अतः इनमें देश को यदि तुलनात्मक लाभ न भी हो, तो भी इनका विकास करना जरूरी है। सरक्षण की सहायता से उद्देश्य सहज ही पूरा हो सकता है।

(१५) शिशु उद्योग तर्क (Infant Industry Argument)—इस तर्क को सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है। इसके अनुसार विकसित देशों के मजबूत वयस्क उद्योगों की प्रतियोगिता के विरुद्ध एक विकासोन्मुख देश के शिशु उद्योगों को सरक्षण देना चाहिए अथवा उनकी अपाल मृत्यु का डर है। निःसन्देह, यह बात सही है। [परन्तु इस सम्बन्ध में यह नहीं सूचना चाहिए कि शिशु उद्योग 'वयस्क' होने पर भी शिशु बने रहना चाहते हैं जिससे देश पर अनावश्यक सरक्षण का बोझ पड़ने लगता है।]

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सरक्षण के पक्ष में दिये जाने वाले अनेक तर्क गहराई से परीक्षा करने पर, घोड़े निरन्तर हैं।

सरक्षण के विरोध में तर्क (दोष)—

इसके अतिरिक्त, सरक्षण की नीति के निम्नलिखित सरकारत्मक दोष (Positive Drawbacks) भी हैं—(i) निहित स्वार्थ स्थापित हो जाते हैं, जो एक बार सरक्षण मिलने पर, इसे फिर एक अधिकार के रूप में जारी रखने की माँग करते हैं। (ii) यह उद्योगपतियों में निष्कियता एवं आलस्य की वृद्धि करता है। (iii) इसमें भ्रष्टाचार के लिए बहुत अवसर हैं। (iv) एकाधिकार स्थापित होने की भी आशंका है। (v) इससे अन्तर्गत प्रतिक्री का पक्षपात किया जाता है—ये अधिनाधिक धनी बनते जाते हैं किन्तु निर्धन वर्ग उत्तरोत्तर निर्धन होने लगता है। (vi) कौमर्तें बढ़ने से उपभोक्ताओं को भी हानि होती है। (vii) सरक्षण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में सघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावनाओं की बढ़ावा मिलता है। (viii) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को ठेस पहुँचती है तथा उत्पादक साधन सर्वोत्तम प्रयोग में न लाये जाने के कारण बिना उत्पादन घटने लगता है।

उपसंहार—कुल पर सैद्धान्तिक दृष्टि में स्वतन्त्र व्यापार सर्वोत्तम है, किन्तु व्यवहार में सरक्षण की नीति अपनाता आवश्यक हो जाता है। विशेषतः जन्म-विभिन्न देशों के लिए सरक्षण की नीति बहुत ही उपयोगी है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-योग ने जन्म-विकसित देशों को अस्थाई रूप से सरक्षण बनाये रखने की अनुमति दे दी है। अधिक सही शब्दों में, विशेष परिस्थितियों में सरक्षण की नीति हो, स्वतन्त्र व्यापार की अपेक्षा, अधिक लाभदायक प्रमाणित होती है।

सरक्षण और रोजगार

प्रायः सरक्षण का सम्बन्ध इस व्यापार पर किया जाता है कि यह रोजगार बढ़ाने में सहायक है। कहते हैं कि प्रमुख-मरम्मत देश में वैकरी की सामाजिक सम्पदा का नाशना करने का सबसे प्रभावशाली अस्त्र है। इस कथन के औचित्य

की परीक्षा (वेकारी के आकार पर संरक्षण के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव इन दो शीर्षकों के अन्तर्गत) की गई है।

(I) अल्पकालीन प्रभाव—

यदि प्रशुल्क नर लगान से संरक्षित उद्योग की वस्तु बँगी ही आयातित वस्तु के साथ प्रतियोगिता कर सकती है और यदि ऐसी वस्तु के लिए मांग पूर्णतः लोच-दार नहीं है तो निःसन्देह अकेले उद्योग में वेकारी घट जायेगी, क्योंकि आयात कर लगने से देशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा बड़े हुए उद्योग में कुछ वेकारों को काम उपलब्ध हो जायेगा।

इस तरह के बिरुद्ध स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों का कहना है कि प्रशुल्क-कर कुल वेकारी को घटाने में सहायक नहीं हो सकेंगे। हम सब यह जानते हैं कि 'आयात निर्यातों का अनुमान करते हैं।' अतः आयातों के परिमाण में कमी आने का फल यह होगा कि विदेशी भी हमसे अपने आयातों को घटाने के लिए विवश हो जायेंगे। इस प्रकार, आयातों में कमी आने से जो अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होता है वह घटते हुए निर्यात-उद्योगों में उत्पन्न वेकारी से निष्प्रभावित हो जायेगा।

सरक्षणवादियों ने स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों की उक्त आलोचना को निम्न आधारों पर कुटिपूर्ण बताया है—(i) यह आवश्यक नहीं है कि आयातों में कमी निर्यातों में भी उतनी ही आनुपातिक कमी लावे, और (ii) देशी वस्तुओं के निर्यात नवीन घरेलू माँग (जो कि संरक्षित घरेलू उद्योग के विकास के कारण नये लोगों को काम मिलने में उत्पन्न होती है) हमारे निर्यात उद्योगों की वस्तुओं के लिए विदेशी माँग में आता हुई कमी को पूरा कर देगी। फलतः निर्यातों के घटने का मतलब यह नहीं है कि निर्यात उद्योगों में रोजगार कम हो जायेगा।

हमारी सम्पत्ति में उपरोक्त आलोचना व प्रस्तावोचना अथवा सत्य है। हम नहीं कह सकते कि नये रोजगार पाने वालों की माँग बिल्कुल उन्हीं वस्तुओं के लिए होगी जो कि पहले निर्यात की जाती थी अतः संरक्षण लगने के परिणाम-स्वरूप निर्यात उद्योगों में कुछ न कुछ वेकारी फैलना अनिवार्य है। लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि नई घरेलू माँग अपने आपको किसी न किसी वस्तु के लिए बढ़ी हुई माँग के रूप में व्यक्त करेगी। जिस सीमा तक ऐसा होगा उस सीमा तक निर्यात उद्योगों में होने वाली वेकारी बढ़ने वाले रोजगार से निष्प्रभावित हो जायेगी। फिर, चूँकि संरक्षित उद्योगों में रोजगार बढ़ता है, इसलिए कुल पर वेकारी में कमी अवश्य आयेगी।

(II) दीर्घकालीन प्रभाव—

चिन्तु प्रशुल्क संरक्षण के अनुकूल प्रभाव केवल अल्पकाल तक ही सीमित है। दीर्घकाल में रोजगार प्रोत्साहक के रूप में इसकी उपयोगिता बहुत कुछ समाप्त हो जाती है। अन्य बातों में, संरक्षण वेकारी की समस्या का एक अस्थायी उपचार है। अर्थ-व्यवस्था में प्रायः तीन प्रकार की वेकारी पाई जाती है, यथा—

(१) सघर्षात्मक बेकारी (Frictional Employment)—एक जॉब के छूटने पर श्रमिक को दूसरा जॉब तुरन्त ही नहीं मिलता, बरन् इसमें कुछ समय लगता है। ऐसे समयान्तर की बेकारी को 'सघर्षात्मक बेकारी' कहते हैं। जब किसी उद्योग पर विदेशी प्रतिस्पर्धिता का दबाव बढ़ रहा हो, तो उसे सरक्षण देकर सन्तुलित सघर्षात्मक बेकारी को कुछ समय के लिए घटाया जायवा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने में राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ से हाथ धोना पड़ता है। चूंकि सघर्षात्मक बेकारी जब-तब उत्पन्न होती रहती है, इसलिये हर बार जब कि इनके उत्पन्न होने का सतर्क हो, प्रत्युक्त सरक्षण द्वारा इसे रोकने का प्रयत्न करने में राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के महान् लाभ में बर्चित होना पड़ता है।¹

(२) चक्राकार बेकारी (Cyclical Unemployment)—चक्राकार बेकारी का आशय उस बेकारी से है जो व्यापार चक्र के कारण उदय होती है। प्रायः सभी पूँजीवादी देशों को ऐसी बेकारी का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक मन्दी अपने साथ बेकारी की सङ्ख्या लाती है। कहा जाता है कि सरक्षण-रर लगाकर देश को दोष विश्व से पृथक् रखते हुए मन्दी के संकट से सुरक्षित किया जा सकता है। मन्मवत इसी कारण मन् १९३१ की मन्दी के समय एक के बाद एक देश ने बेकारी को रोकने में बचने से तिर् प्रत्युक्त कर लगाए। किन्तु अनुभव यह दर्शाता है कि अनि सरक्षणवादी देश भी स्वतन्त्र व्यापार देशों की तुलना में मन्दी का ल में कम संकट-ग्रस्त नहीं रहे।

(३) स्थायी बेकारी (Permanent Unemployment)—स्थायी बेकारी प्रायः सामाजिक मजदूरियां बहुत ऊँची होने के कारण उदय होती है। ऐसी बेकारी को हल करने में सरक्षण बहुत ही कम सहायक हो सकता है वह भी तब जब कि बहुत ऊँचे आयात दर लगाये जाएँ। किन्तु, ऊँचे आयात कर लगाने से उपभोक्ताओं को बहुत त्याग करना पड़ता है जो कि न्यायोचित नहीं है। फिर, निर्यात उद्योगों में मिलती हुई बेकारी के सम्बन्ध में सरक्षण की मुक्ति बेकार है। वस्तुतः वह ऐसी बेकारी को कम करने के यत्न में सहायता देता है क्योंकि सरक्षण के फलस्वरूप आयात घटने से जिसमें निर्यात में कम आती है तथा बेकारी उत्पन्न होती है।

उपर्युक्त विवेचन से निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं —(i) यदि बेकारी स्थायी है, तो इनका उपचार यह होगा कि या तो मजदूरी-स्तरों की नीचा किया

¹ 'If one were to raise the tariff every time unemployment appeared anywhere, one would incur lasting loss for the sake of a doubtful and temporary gain. One would forgo the immense gains of international division of the labour and of technical progress for a mass of pottage'—Haberler *Theory of International Trade*, p. 226

जाय या देश अपने महा इतनी टेक्नीकल प्रगति हो जाने की प्रतीक्षा करे जिससे कि धर्म की सीमान्त उत्पादिकता बढ़कर प्रचलित गजदूरी के बराबर हो जाय, (ii) यदि बेकारी चक्र स्वभाव की है, तो वह पुन उठान (recovery) की अवस्था के आगमन पर स्वतः ठीक हो जायेगी। हाँ, यदि मजदूरियों में बटौतियों की नीति भी अपनाई जाय, तो इससे उक्त अवस्था जल्दी हो आ सकती है, एवं (iii) आंशिक (किसी एक उद्योग में) बेकारी की दशा में देश के पूर्ण रोजगार स्तर तक स्वाभाविक रूप से पहुँचने की प्रतीक्षा करनी चाहिये। हाँ, बेकार व्यक्तियों को अन्य उद्योगों के काम की ट्रेनिंग दी जा सकती है।

सुरक्षण देने की विधियाँ

देश की सरकार अनेक तरीकों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वाभाविक गति में बाधा डाल सकती है और इसके प्रभावस्वरूप देश के उद्योगों को सुरक्षण मिलता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाय जाने वाले विभिन्न व्यापार के प्रतिबंध या सुरक्षण देने की विभिन्न रीतियाँ इस प्रकार हैं—(१) वैधानिक निषेध (Legal Prohibition) जिसमें सरकार कानून बना कर किसी वस्तु के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। (२) प्रभुत्व कर (Tariffs or Duties), जिनमें आयात और निर्यात कर सम्मिलित हैं। इनमें भी आयात कर अधिक सौरभिय है। (३) आर्थिक सहायता (Bounties and Subsidies), जिसके अन्तर्गत अनुदान विशेष छूट और ऋण आदि सम्मिलित हैं, जो कि सरकार उद्योग विशेष को आर्थिक सहायता के रूप में देती है। (४) परिमाणमय प्रतिबंध (Quantitative Restrictions) जिनमें आयात की जाने वाली वस्तु के लिए कोटे निर्धारित कर दिये जाते हैं। एवं (५) विविन्न निषेध (Exchange Restrictions) जिसमें विदेशी विनिमय का राजस्व सम्मिलित है आजकल विविन्न निषेध की रीतियाँ आयातों को प्रतिबन्धित करने की विधि के रूप में भी बहुत प्रभावशाली मानी जाने लगी हैं। इनके अधीन न केवल विदेशी मुद्रा कोष ही सुरक्षित रहता है बल्कि विदेशी वस्तुओं को भी देश के बाहर राखने में सहायता मिलती है। इन रीतियों का राजनैतिक प्रभाव भी होता है। यद्यपि व्यापार को प्रतिबन्धित करने में विविन्न नियन्त्रण के साथ स्पष्टता से इष्टि-गोचर होते हैं तथापि यह अनुभव किया जाता है कि इनके कारण उत्पादन एवं व्यापार की रचना का स्वरूप बिगड़ जाता है तथा भ्रष्टाचार व भवभानी नीति को बढ़ावा मिलता है।

कोटा प्रणाली (Quota System)

संक्षिप्त इतिहास—

परिमाणमय प्रतिबंध, जिनमें से कोटा प्रणाली एक है, सर्वम पहले प्रथम विरम-युद्ध से समय में लगाय गये थे। वर्ष १९१४ और वर्ष १९१८ के बीच ऐसे नियन्त्रण युद्ध अर्थ-व्यवस्थाओं का अभिन्न अंग बन चुके थे। युद्ध सत्तम दशों में

निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाये, जिससे कि (i) फौजी महत्व का सामान शत्रुओं के हाथ न लग सके, (ii) वे स्वयं अपनी सीमाओं के भीतर दुर्लभ साधनों का निवेकपूर्ण प्रयोग कर सकें तथा (iii) तटस्थ यूरोपीय राष्ट्रों के माध्यम से उनके पुनर्निर्वात की प्रत्येक सम्भावना खरब हो जाय। उन दिनों जहाजी सुविधाओं का न मिलना भी वस्तुओं के आवागमन में बहुत बाधा बन चुका था।

युद्ध के बाद, अच्छे दिनों की आशा रखे हुये भी, नियन्त्रण पुनः एक अल्प अवधि के स्वतन्त्र व्यापार के पक्षानु, लगा दिए गये। किन्तु विश्व का जनमत इन नियन्त्रणों के बहुत ही विरुद्ध था। उस बहुपक्षी व्यापार प्रणाली (multilateral trading system) को सहज मार्ग पर पुनः लाने हेतु प्रयास किये गये। कई सम्मेलन हुए। यद्यपि इन सम्मेलनों का वास्तविक परिणाम बहुत ही मागूली निकला तथापि इनके फलस्वरूप परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों के हटाने की दिशा में कार्यवाही शुरू हो गई।

किन्तु १९२६ में कृषि में भयंकर मंदी आई, जिससे विवादों की दुनियाद को पुनः हिला दिया और जिस प्रकार मोसीकरा का बुझार एक बार उतार कर पुनः चढ़ जाता है उसी प्रकार व्यापार के प्रति उदारता की प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते पुनः एक गई तथा प्रतिबन्धों में वृद्धि होने लगी। धनें धनें प्रतिबन्धों की कठोरता बढ़ती ही चली गई। जब इङ्ग्लैंड एकमात्र देश से हट गया, तब दू-होने अधिक बुरा रूप धारण कर लिया। केवल एक वर्ष के अति-अल्प काल में ही समस्त यूरोप नियन्त्रणों और परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों के जाल में फँस गया। जैसाकि मिसेज जोन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने ठीक ही कहा है, प्रत्येक देश, 'मैं दरिद्र तो मेरा पड़ोसी भी दरिद्र' वाली नीति (Beggars my neighbour policy) का अनुसरण करने में पागल हो रहा था। वह निर्यात करने के लिए तो बहुत ही उत्सुक प्रतीत होता था किन्तु आयात करने में सबसे पीछे रहता चाहता था, जिससे बहुपक्षी व्यापार प्रणाली के मन्वानन के ठोस आधार की एक पूर्ण शर्त भंग हो गई।

कोटा प्रणाली के सैद्ध—

कोटे (quotas) जो स्वयं ही परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों का एक रूप है, स्वयं भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे—टैरिफ कोटे, एकपक्षीय आयात कोटे, आयात अनुशासन द्विपक्षीय कोटे एवं मिश्रित कोटे। नीचे इन पर सूक्ष्म में प्रकाश डाला गया है।

(१) टैरिफ कोटे (Tariff Quotas)—टैरिफ कोटे का आशय एक विशेष वस्तु की निश्चित मात्रा से है, जिसे कर की एक रियायती दर पर आयात करने की अनुमति दी गई है। इस नियत मात्रा से अधिक वस्तु का आयात करने पर दण्ड के रूप में ऊँची दर से आयात कर चुकाना पड़ता है। इस युक्ति का प्रयोग १९ वीं शताब्दी के मध्य में कई यूरोपीय देशों द्वारा, एक अल्प किन्तु निश्चित माना में सीमान्त व्यापार को प्रोत्साहन देने के हेतु, किया गया था। आजकल भी पड़ोसी

देशों से कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात प्रोत्साहित करने के लिए इस विधि का ही प्रयोग किया जा रहा है।

(२) एकपक्षीय आयात कोटे (Unilateral Import Quotas)—इस प्रकार के कोटे के अन्तर्गत एक ही हुई अवधि के भीतर वस्तु के आयात पर सरकार द्वारा विदेशी सरकारों से पूर्व वार्ता बिना ही, एक निरपेक्ष सीमा (absolute limit) बाध दी जाती है। ऐसे कोटे विश्व व्यापी (global quota) हो सकते हैं या देश भ्रम में (country wise) निर्धारित किये जा सकते हैं। विश्व व्यापी कोटे की बिनापना यह है कि नियत की हुई सीमा पर सम्बद्ध वस्तु किसी भी देश से आयात की जा सकती है बरिन् देश भ्रम वाले कोटे में कुछ माना पहले से ही कुछ देशों पर बिनागि कर दी जाती है और फिर उन्हीं से नियत सीमाओं तक वस्तु का आयात किया जा सकता है।

(३) आयात अनुज्ञापन (Import Licensing)—आयात अनुज्ञापन द्वारा पानागो से अन्त-यस्त विय बिना हो विभिन्न सप्लायरों के मध्य कोटे का सन्तान रूप में बिबरण किया जाता है। अनुज्ञापन विधि कोटे की घोषणा करने की विधि में प्रोष्ठ है। कारण चूँकि कुल कोट की मात्रा सार्वजनिक रूप से नहीं लोनी जाती है इसलिए मर्चेंटों को प्रोगाहन नहीं मिलने पाता है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन विधि के अन्तर्गत सप्लायरों की सीमा मात्राओं में बिबिध रूप से होती रहती है, एक धारणी कुल मात्रा नहीं मंगा ली जाती है।

(४) द्विपक्षीय कोटे (Bilateral Quotas)—द्विपक्षीय कोटा प्रणाली के अन्तर्गत आयातकर्ता देश निर्यातक देशों से इस आशय की वार्ता (negotiation) करना है कि उन्हीं से प्रत्येक बिबिध की कितनी मात्रा सप्लाय करेगा। अतः इस प्रकार के कोटे में विभिन्न सप्लायरों में वृत्तियों का बिबिध रूप से बिबरण हो जाता है, जिससे आयातित सप्लाय में अत्यधिक उतार-चढ़ाव नहीं हो सके और ठहराव द्वारा एकाधिकार की स्थापित नहीं हो पाते हैं।

(५) मिश्रित कोटे (Mixed Quotas)—यह नियन्त्रण का यह तरीका है जो स्वदेशी निर्मित वस्तुओं में पिलाया जाने वाला बिबिध-उत्पादित वस्तुओं का अनुपात नियत कर देता है। यह नियन्त्रण, तुलनात्मक बाजार सिद्धान्त के अनुसार, प्रयागों का अनुकूलतम बिबरण कराने में सहायक होता है।

टैरिफ (आगम-निर्गम कर) प्रणाली

पिछली हुई अव्यवस्थाओं में घरेलू उद्योगों की विकसित अव्यवस्थाओं के पैसे ही उद्योगों की प्रबल प्रतियोगिता में मरझण की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रतियोगिता 'बाजारों के लिए दौड़' का रूप लेती है तथा न केवल गुण के सम्बन्ध में बल्कि कीमत के सम्बन्ध में भी होती है। प्रतियोगी देशों की अन्तर्गत स्थिति के कारण रभोन्नी बढ बढ़त अन्यायपूर्ण हो जाती है। यह एक बर्षक और एन निम्न के मध्य प्रतियोगिता के समान है। 'निम्न' की तुलना पिछली हुई अव्यवस्थाओं में

स्थापित किये जा रहे उद्योगों से और 'वयस्क' की तुलना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सुस्थापित एवं दीर्घ अनुभव प्राप्त उद्योगों से की जा सकती है। उन्नत देश अपने स्वार्थ के लिए, विवक्षित एवं अद्विविध अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अन्तर बनाये रख पर, अपनी लाभदायक स्थिति को सदा ही म्यार्ड रखना चाहते हैं, भते ही पिछड़े हुए देशों के साथ सदा वनों में लकड़ी काटने वाले तथा खेती करने वाले ही बने रहे। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि घरेलू उद्योगों की रक्षा सब तक की जाय जब तक कि वे अपने उन्नत प्रतियोगियों में मोर्चा लेने की पर्याप्त शक्ति अर्जित न कर लें। ऐसा संरक्षण उम्ह टैरिफ और नोटा प्रणालियाँ में मिल सकता है।

टैरिफ के लाभ और हानियाँ—

टैरिफ' (Tariff) से आयाज आन्तरिक वस्तुओं में प्रतियोगिता करने वाली विदेशी की सँखी ही वस्तुओं पर लगायत कर लगाने का है। इसका भार (Burden) या तो निर्यातकों पर अथवा आयातकों पर पड़ सकता है। यह वास्तव में किन पर पड़ेगा यह वस्तु की पुति और इसके लिए माग की लोच पर निर्भर है। अन्तर्गत में, यदि विदेशी व्यापारी बेचने के लिए बहुत उत्सुक है, तो टैरिफ का भार विदेशी विक्रेताओं पर पड़ेगा। इसका अर्थ है उनके लार्मी में कमी आना तथा (इसलिए) वेग को उनके निर्यातों में घटती होना। इस प्रकार, टैरिफ के द्वारा गबाछनीय आयात को सहन ही रोक जा सकता है। अमेरिका और जापान ने अपने प्रारम्भिक विकास की अवस्था में जो नीति अपनाई थी वही भारत को भी बुद्धोतर काल में अपनानी पड़ी है। यदि उगने टैरिफ संरक्षण न दिया होता तो उसके अनेक उद्योग आज जीवित दिखाई न देते। किन्तु टैरिफ के निम्नलिखित दोष भी विचारणीय हैं —

(१) प्रतिकार का भय — यदि एक संघोचित अवधि के बाद भी कोई देश भारी टैरिफ संरक्षण जारी रखे, तो उसके निर्यातों के विदेशी कंठा भी उसकी वस्तुओं के विरुद्ध टैरिफ बढ़ाने के रूप में प्रतिकाररत्मक उपाय (retaliatory means) अपना सकते हैं। हाँ, किन्तु वस्तुओं में उसका एकाधिकार है उनमें स्थिति कुछ भिन्न है। किन्तु मायद ही कभी कोई एकाधिकार बिन्कुल पूर्ण हो जिसमें प्रतिकार की वृद्ध न कुछ सम्भावना अवश्य ही विद्यमान रहती है। अतः किसी भी देश को अपनी स्वार्थपूर्ण नीति इस सीमा तक नहीं उपनानी चाहिये कि स्थल उसके निर्यातों को भी हानि पहुँचे।

(२) घरेलू उपभोक्ताओं का शोषण — संरक्षण-भर उपभोक्ताओं को (सम्भवतः) अच्छी किम्मी की आयातित वस्तुओं के प्रयोग में वंचित कर देते हैं। उन्हें स्वदेशी की घटिया वस्तुएँ ही खरीदनी पड़ती हैं तथा इनके लिये ऊँचे दाम देन पड़ने हैं। इस प्रकार, जबकि उपभोक्ताओं का शोषण होता है, तब स्वदेशी निर्यातकों को प्रभुत्वों की आड़ में भारी लाभ होते हैं। यदि अधिक समय तक संरक्षण चाल रह, तो श्रेष्ठताओं को बहुत अमृषिष्ठा उठानी पड़ सकती है। यह तो केवल तब ही है जबकि देश पूर्णतः औद्योगिक हो जाय कि वे अपनी स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को पटो

हई कीमतों का लाभ उठा सकने है। किन्तु स्पष्टतः, उनके त्याग की कोई न कोई सीमा होना अवश्य है। यह सीमा इस बात पर निर्भर है कि देशी उत्पादक खुले बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कब और किस सीमा तक प्राप्त कर लेते हैं।

(३) सरक्षण के जारी रखने पर जोर देना—जब स्वदेशी उत्पादक पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तब भी वे एक न एक आधार पर सरक्षण के जारी रखने पर जोर देने रहते हैं। इस प्रकार तथा कवित्त 'क्रिस्टु' इस समय 'बमस्क' होने में इन्कार कर देता है कि कहीं उसे सरक्षण से वंचित न कर दिया जाय। अर्थात्, वे उपभोक्ताओं पर एक स्थायी भार' बने रहते हैं।

(४) सुधार के लिए प्रेरणा का अभाव—"आपत्तियाँ हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं।" जब किसी स्वदेशी निर्माता को प्रतियोगियों के इस चैलेंज का सामना करता पड़ता है कि वे बाजार को छीन लेंगे तब तब ही उसमें बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरणा सन्निभ हो जाती है। किन्तु सरक्षण की दृष्टि में प्रतियोगिता का भय न होने में उसमें अकुशलता प्रोत्साहित होती है। अतः यह अवश्यक है कि केवल एक शरणाई अवधि के लिए ही, जिसमें नि स्थानीय निर्माताओं को पर्याप्त शक्ति सग्रह कर लेने का अवसर मिल सके सरक्षण दिया जाय।

आयात कोटे के गुण-दोष

आयात कोटे के लाभ—

आयात-कोटा किसी वस्तु की यह निर्धारित मात्रा है जिसे एक निर्यात अवधि में आयात करने की अनुमति होती है। यह भी स्वदेश के उद्योगों को सरक्षण देने का एक उपाय है और मरक्षक-बरो की तुलना में इसके निम्नलिखित लाभ हैं —

(१) सरक्षित उद्योगों के लिए अधिक सुरक्षा—आयात-कर खाने पर भी आयात में वृद्धि हो सकती है क्योंकि सम्भव है कि (i) विदेशी वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाय, (ii) स्वदेश की माग बढ़ जाय, (iii) विदेशी देश द्वारा राशिपतन किया जाय, और (iv) विदेशी सरकार अपने यहाँ के उद्योगों को आर्थिक सहायता दे, जिससे कि इनकी वस्तुयें सस्ती हो सकती हैं। इस प्रकार, आयात कोटा प्रणाली उद्योगों को आयात करों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

(२) ठोस नियोजन सम्भव होना—चूँकि आयात करों के अधीन स्वदेशी उत्पादनों की अधिक सुरक्षा प्राप्ता होती है, इसलिए वे अपने उद्योग के भावी विकास के लिए ठोस योजनाएँ बना सकते हैं।

(३) युद्धकालीन नियन्त्रण सहनीय होना—यान्त्रिकाल में विदेशी वस्तुओं की मात्रा पर, जोकि देश में आयात की जा सकती है प्रतिबन्ध लगे होने से जनता को उनकी जादत पड़ जाती है जिससे कि वह इन्ते युद्धकाल में, जब कि वे कठोरता-पूर्वक लागू किये जायें गुणमतापूर्वक सहन कर लेती हैं। इस बात का एक मकद-कालीन परिस्थिति में, जैसी कि इस समय भारत के सम्मुख चीन और पाकिस्तान

की नापाक साजिश और आक्रामक कार्यवाहियों के कारण उपस्थिति है, महत्त्व और भी अधिक हो जाता है।

(४) पिछड़े हुए देशों के लिए उपयोगी—आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश आर्थिक दृष्टि में प्रगतिशील देशों से, स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के अन्तर्गत, बराबरी के आधार पर प्रतियोगिता नहीं कर सकते हैं। किन्तु विभाजित कोटा-प्रणाली के अन्तर्गत पिछड़े हुए देशों के हित सुरक्षित रहते हैं क्योंकि आयात कोटे पिछड़े हुए देशों के पक्ष में निर्धारित किये जा सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोटा प्रणाली अपनाये की हानियाँ—

द्वैत प्रणाली के समान ही कोटा प्रणाली की भी अपनी विदेश हानियाँ हैं। सबसे प्रमुख हानियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) एकाधिकारों का निर्माण—आयात कोटे की आठ में सुरक्षित अनुभव करते हुए उद्योगपति एकाधिकारक कुचाले दिखाने में तनिक भी भय अनुभव नहीं करते। उदाहरण के लिए वे उत्पादन की मात्रा में कटौती कर देते हैं और इस प्रकार कीमतें जान-बूझकर बढ़ा देते हैं। जिस सीमा तक कोटा प्रणाली के अन्तर्गत यह सम्भव होता है उस सीमा तक उपभोक्ताओं के हितों को असुरक्षित ही समझना चाहिए।

(२) कृत्रिम ऊँची कीमत भिन्नताएँ—कोटे निर्धारित कर देने से आयातक और निर्यातक देशों के मध्य इनके कीमत स्तरों में झूठी और यातायात व्ययों की सीमा से भी अधिक कृत्रिम भिन्नता उत्पन्न हो जाती है।

(३) अत्यधिक बैलौबता—कोटा प्रणाली के अन्तर्गत न केवल अधिकतम मात्रा, बल्कि न्यूनतम मात्रा भी कठोरतापूर्वक निर्दिष्ट कर दी जाती है। जहाँ आयात की मात्राओं को सम्बन्धित वस्तु के लिए माँग में होने वाले परिवर्तनों के प्रभुत्व में घटाना या बढ़ाना सम्भव नहीं होता।

(४) भ्रष्टाचार के लिए अवसर—आयात-लाइसेन्सों के वितरण में भ्रष्टाचार फैलने का भी बहुत कुयोग रहता है।

(५) प्रशासनिक कठिनाइयाँ—कोटा प्रणाली के कार्यान्वयन में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ भी उदय होती हैं। उदाहरणार्थ, स्वदेशी आयातकों में या विदेशी स्थलायुक्तों में कोटा विभाजित करने के आशय के लिए कौनसा आधार बर्ण चुना जाय इस सम्बन्ध में बड़ी ही कठिनाई अनुभव होती है।

(६) विदेशी व्यापार के सहज या स्वतन्त्र प्रवाह में बाधा—कोटा प्रणाली उन शक्तियों के स्वतन्त्र कार्य मंचालन में अस्त-व्यस्तता उत्पन्न कर देती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने वाली हैं। उदाहरणार्थ, यह विसिष्टीकरण के संघ को संकुचित कर देती है और सभाव्य प्रचुरता के मध्य वास्तविक निर्धनता के विरोधाभास को जन्म देती है।

(७) अकुशलता को प्रोत्साहन—आयात-व्यवसाय में कोटा प्रणाली के अन्तर्गत ऊँची कीमत भिन्नतायें विद्यमान होती हैं तथा इसे अधिक लाभ-पद बना देती हैं। असाधारण लाभ कमाने के प्रलोभन से अव्यक्त फर्मों भी व्यापार में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार, आयात व्यापार बेईमान सटोरिया के हाथ की कठपुतली बन जाता है।

(८) छुपा हुआ भेदात्मक व्यवहार—निर्यातक देशों के विरुद्ध कुछ भेद-भाव करने बिना ही कोटा प्रणाली को लागू करना सम्भव नहीं है। नि-सन्देह कठोर टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत भी निर्यातक देशों के विरुद्ध भेदभाव किया जाता है किन्तु वह सब पर प्रयत्न होता है, जबकि आयात-कोट के अधीन गुप्त रहता है। अतः, टैरिफ प्रणाली के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत करने है कि फिर क्यों न केवल टैरिफ ही अप-नाये जो एकाधिकारिक शोषण भी सम्भव नहीं बनाये।

(९) भुगतान-सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति से समायोजन की कठिनाई—एक पक्ष कोटा प्रणाली के अन्तर्गत जो अपिपत्तम् धाना आयात कर सकता है, वह कठोरतापूर्वक निर्धारित होती है। यदि इस देश का भुगतान-सन्तुलन अनुकूल है और वह चाहता है कि ऋणों देश अपने बनाया कण चुका दे, तो उसे ऋणी देश से अधिक मात्रा में वस्तुयें आयात करने को तैयार होना चाहिए। किन्तु कोटा प्रति-बन्धा के कारण वह अधिक माल नहीं मँगवा सकता। फलतः विदेशी ऋणों का पुन-भुगतान बहुत ही कठिन होगा।

(१०) कौर्षी के अन्तरण में कठिनाई—कोटा प्रणाली के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक गन्त की सहजता भी कम हो जाती है, और अन्तरण-क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार, कोटा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टावहे ढाल देती है।

दुनियाबी बोप को कुछ सीमा तक दूर करना सम्भव है—

उपरोक्त विवेचन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कोटा प्रणाली के प्रयोग के पक्ष में कोई सबल तर्क नहीं है। फिर भी कोटा-प्रणाली के दुनियाबी बोपों को सर-कार कुछ सामयिक कदम उठाकर दूर कर सकती है। ये उपाय निम्न-लिखित हैं —

- (१) आयात व्यापार के ऊँचे स्तरों के कुछ भाग को, आयात लाइसेन्सों पर करारोपण द्वारा, सरकारी खजाने में सौदा जा सकता है।
- (२) आयात लाइसेन्स सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के पक्ष में खोला दिया जाय। इसके भी सम्भावित लाभ का एक अच्छा खासा भाग सरकार को मिल सकता है। किन्तु मैदानितः दृष्टि में आकर्षक होने हुए भी ये उपाय व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसी दशा में छोटी-छोटी फर्मों लाइसेन्स प्राप्त न कर सकेंगी तथा इनमें सटोरियों लाभ उठा जायेंगे।

- (iii) अतः एक अधिक स्पष्ट उपाय तो यह होगा कि सरकार स्वयं ही विदेशी व्यापार करने लगे। चूँकि कोटा प्रणाली में भी एक तरह से व्यापार पर सरकार का ही एकाधिकार स्थापित हो जाता है इसलिए कहा जाता है कि सरकार व्यापार में प्रविष्ट करके सब लाभ स्वयं हाँ नहीं न उठाये ?
- (iv) एकाधिकारित बापण में बचने के लिए निम्न युक्तियाँ दी जा सकती हैं — (अ) कोटा प्रणाली लचीली रखी जाय अर्थात् कोटे का आकार कीमतों के स्तर पर निर्भर बनाया जाय, जैसा किमने ऊँची हो जाये तो कोट में छील दी जा सकती है, (ब) कोटा प्रणाली में सम्बन्धित वस्तुओं के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रण लागू किया जाय, (ग) टैरिफ आयोग भी मर्यादित उद्योगों की वस्तुओं की किस्म तथा कीमतों पर निर्णय लेवे, एवं (द) देशी फर्मों के लागू नियमित रूप में जँसवाये जायें, जिससे वे यथोचित से अधिक लाभ न ले सकें।

✓ टैरिफ और कोटा प्रणालियों की तुलना

कोटे और टैरिफ में कई बातें एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इन दोनों में अन्तर की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

- (i) कोटे की अवस्था टैरिफ कम उच्च और स्वभाव में कम भेदात्मक (less-discriminatory) है।
- (ii) कोटा प्रणाली के अन्तर्गत वस्तुओं की अधिकतम मात्रा, जिसका देश में आयात किया जा सकता है, कठोरतापूर्वक नियत होती है, किन्तु टैरिफ की दशा में सदा ऐसा नहीं है। यदि किसी कारणवशा नियतकाल में कीमतें घट जायें, तो उस सीमा तक व्यापार पर टैरिफ का प्रतिवन्धात्मक प्रभाव टीला हो जायेगा।
- (iii) कोटे देश में एकाधिकारों के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, किन्तु टैरिफ के अन्तर्गत यह बात सम्भव नहीं है।
- (iv) कोटा प्रणाली के कारण भुगतान समुत्तन सम्बन्धी स्थिति में समायोजन होने कठिन है किन्तु टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान समुत्तन सम्बन्धी स्थिति इतनी कठोर नहीं बनती है।
- (v) अज्ञान सम्बन्धी कोटे अज्ञात और स्थिर देश के मूल्य कीमतों में भारी अन्तर पैदा कर देते हैं; किन्तु टैरिफ के अन्तर्गत लागत-कीमत संरचनाओं (cost-price structures) के मध्य सम्पर्क बड़ी मात्रा में रहता है।
- (vi) कोटा प्रणाली में प्रधाननिर्मात्रा उद्योग होती हैं, जो टैरिफ-यामन में पूर्णतः अनुपस्थित हैं।

- (vi) यह सम्मानना है कि कोटा प्रणाली के अधीन देशों के मध्य भेद-भाव रखा जायेगा, किन्तु टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा भेद-भाव नहीं होता ।
- (viii) आयात कोटे के अन्तर्गत न्यूनतम् एवं अधिकतम् मात्राये निर्धारित होती है जिससे आयातों की मात्रा में लोच का अभाव रहता है लेकिन ऐसी यथोपेक्षा टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत नहीं है ।
- (ix) आयात कोटे के अन्तर्गत, ऊँचे नामों का आकर्षण उत्पत्ति-साधनों को जब उद्योगों से आयात उद्योगों में स्थानान्तरित कराता है किन्तु यह अन्यायिक आचरण टैरिफ के अन्तर्गत नहीं होता ।
- (x) आयात कोटे के अधीन असाधारण घातों की मात्रा बहुत ही ऊँची होती है किन्तु टैरिफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि नामों का एक भाग टैरिफ प्रणाली के द्वारा सरकारी खजाने में पहुँच जाता है ।
- (xi) उपभोक्ताओं को टैरिफ की अपेक्षा आयात कोटे के अन्तर्गत अधिक हानि सहनी पड़ती है ।

इस प्रकार यह देखेंगे कि आयात कोटे और टैरिफ एक दूसरे से बहुत ही कम मिलने-जुलते हैं । दोनों में समानता केवल इतनी है कि उन दोनों का ही प्रभाव विश्व व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक होता है । किन्तु दोनों 'असमान' अधिक हैं- 'समान' कम ।

व्यापार की शर्तों और आर्थिक कल्याण पर संरक्षण का प्रभाव

(Effect of Tariff upon a Country's Terms
of Trade and Economic Welfare)

व्यापार की शर्तों पर प्रभाव—

आयात करों द्वारा व्यापार-शर्तों को कुछ परिस्थितियों में देश के अनुकूल बनाया जा सकता है । उदाहरण के लिए यदि कोई देश किसी आयातित वस्तु का महत्वपूर्ण कोटा है तो इसकी कीमत को टैरिफ लगा कर घटाया जा सकता है क्योंकि ऐसी दशा में टैरिफ का भुगतान विदेशी विक्रेता स्वयं अपनी जेब से करने के लिए विवश हो सकते हैं । इसमें देश के लिए व्यापार शर्तों पर सुधार हो जावेगा । किन्तु यह लाभ सामान्यतः उच्च या न्यायपूर्ण नहीं समझा जाता, क्योंकि इसकी प्राप्ति अन्य देश के नुकसान पर होती है । इसके अतिरिक्त, दूसरे देशों द्वारा प्रतिकारात्मक कार्रवाहियाँ किये जाने का भी डर है ।

आर्थिक कल्याण पर प्रभाव—

संरक्षण-कर देश के आर्थिक कल्याण को एक से अधिक तरीकों में करते हैं —

(१) टैरिफ कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं—जब आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाया जाता है, तो साधारणतः विदेशी वस्तुओं की कीमतें गृह-बाजार में बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में ऊँची लागत वाली स्वदेशी वस्तुएँ भी, उद्योग को कुछ हानि पहुँचाये बिना ही ऊँची कीमतों पर बिकने लगती हैं। यह परिस्थिति उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ बनाती हैं। साथ ही यह भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि उपभोक्ताओं को ऊँची कीमतों से हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनकी वास्तविक आय में कीमत वृद्धि की सीमा तक कमी हो जाती है।

(२) कुशलता में सुधार के लिए प्रेरणा कम होना—टैरिफ सरक्षण पाग बाला गृह उद्योग संरक्षण को छोड़ने के लिए कभी भी तत्पर नहीं होता और संरक्षण की आड़ में रहते हुए उसे अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। परिणामतः सामाजिक शुद्ध उत्पत्ति में कमी आ सकती है तथा कीमतों का स्तर काफी लम्बे समय तक ऊँचा बना रह सकता है।

(३) आर्थिक प्रसाधनों का अनाधिक बिनाश—जब कुछ वस्तुओं पर ऊँचे टैरिफ लगाये जाते हैं तब वह देश में इन वस्तुओं के उत्पादन की इच्छा प्रोत्साहन देते हैं। वास्तव में वे ही प्रसाधन अन्य उद्योगों में अधिक उत्पादक (productive) हो सकते थे। इस प्रकार, उत्पादक साधन ऊँची कीमतों के कारण अपनी अत्यधिक लाभदायकता के फलस्वरूप, अनाधिक प्रयोगों में ही बने रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय उत्पत्ति कम होती है।

(४) टैरिफ हमारी राष्ट्रीय आय को अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं—टैरिफ लगाने में आयात कम हो जाते हैं। हमारे आयात अन्य देशों के निर्यात होते हैं। अतः हमारे आयात घटने का अर्थ है उनके निर्यात घटना। चूँकि विदेशियों की निर्यात आय घट गई है, इसलिए स्वभावतः वस्तुएँ खरीदने की उनकी क्षमता भी, गुणक (multiplier) की कार्यशीलता के फलस्वरूप अनुपात से कहीं अधिक, कम हो जाती है। फलतः वे हमारे देश की वस्तुएँ कम माना में खरीदते हैं। इस प्रकार, हमारे निर्यात हमारे आयात घटाने की प्रारम्भिक कार्यवाही के फल-स्वरूप, कम हो जाते हैं। चूँकि एक ओर स्वदेश निर्यात वस्तुओं का उपभोग विदेशी वस्तुओं की कम खरीद के कारण बढ़ता है, और, दूसरी ओर, हमारे आयातों में वमी के फलस्वरूप निर्यात आय में घटौती के कारण आय घट जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय आय पर टैरिफ का प्रभाव (effect) इन विपरीत प्रभावों के शुद्ध परिणाम (net result) पर निर्भर करेगा।

यदि हम अपने निर्यातों में हुई वमी की अपेक्षा आयातों में अधिक घटौती करने में समर्थ हो जायें, तो निश्चय ही हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। किन्तु हमारी राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि एक विदेशी देश की हानि पर प्राप्त होती है, जहाँ कि

निर्यातों में आयातों की अपेक्षा अधिक कमी के फलस्वरूप धन कम हो जाती है। वत विदेशी देश इसके बदले के लिए अपने यहां टैरिफ बढ़ा सकता है। यदि उसने ऐसा किया तो हमारे लाभ केवल अस्थाई प्रमाणित होंगे। इस प्रकार अन्तिम विवर्णन में, टैरिफ निर्यात-आय में वृद्धि नहीं कर सकते, किन्तु उसी आय में एक देश विशेष के हिस्से को यह भी केवल अस्थाई रूप से, बढ़ा देते हैं और यह भी किसी अन्य देश की हानि पर ही सम्भव होता है।

(१) टैरिफ देश में रोजगार पर प्रभाव डालते हैं—एक देश अन्य देश के हित का बलिदान करते हुए टैरिफ बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने में सफल हो सकता है। इसी प्रकार, एक देश में रोजगार भर, दूसरे देश की हानि पर, बढ़ाया जा सकता है। यह बात निम्नलिखित दो बातों के बारे में विशेष सही है, क्योंकि वहाँ एक ओर विशाल मात्रा में प्रसाधन निष्क्रिय या अर्द्ध-उपेयित पड़े होने हैं जबकि दूसरी ओर व्यापारी बकारी फैली होती है।

(२) टैरिफ मजदूरियों को प्रभावित कर सकते हैं—यदि टैरिफ के परिणामस्वरूप, एक देश के आयात उसके निर्यातों की अपेक्षा अधिक घट जायें, तो धन के लिए माग बढ़ जायेगी। यदि यह वृद्धि एक ऐसे समय पर होती है जबकि देश में श्रम का महत्त्व से ही पूर्ण नियोजन (fully employed) है, तो मजदूरियाँ बढ़ सकती हैं। मजदूरियों में एक भी वृद्धि हो सकती है जबकि देश में मजदुरी पूर्ण रोजगार तो नहीं है तथापि विकासीमुख उद्योगों में जिस तरह का धन निर्यातित है उस प्रकार के धन के लिए ही माग बढ़ जाय। किन्तु धन के लिए माग में वृद्धि अस्थाई होती है। यह तब लुप्त हो जाती है जबकि अन्य देश प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ लगा देते हैं और हमारे साथ ही साथ मजदूरियों में प्रारम्भ में हुई वृद्धि भी लुप्त हो जाती है। इस प्रकार मजदूरियों में हुई वृद्धि, जो कि उत्पादनता में वृद्धि पर आधारित नहीं है, जीवनयापन की सामग्री में अनिवार्य रूप से वृद्धि कर देती है।

(३) टैरिफ सदा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा डालते हैं—यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ भी घट जाता है।

(४) लाभ जो टैरिफ-संरक्षण से कभी-कभी प्राप्त होते हैं—आजकल विकासीमुख देशों द्वारा संरक्षण अधिकारिक अपनाया जा चुका है। कारण वे अर्थ-समस्या के सभी क्षेत्रों में एक पूर्ण निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार उन्नति करने के लिए उत्सुक होते हैं। नये-नये हुए आर्थिक विकास को यदि विदेशों से बहुत प्रतिप्रेमिता के दबाव में बांटे जाने दिया तो वह काम नहीं रह सकता है। 'गिभु बा पोपेज करो, बालक की रक्षा करो तथा बयस्क को स्वतन्त्र छोड़ दो' (Nurse the baby, protect the child and free the adult) एक ऐसा उपदेश है जो उनके लिए वांछनीय है। जब तक नये उद्योगों को संरक्षण न दिया जायेगा तब तक विनियोजन उनके विनियोजन करने और जोत्तिम्ब उठाने के लिए आगे

न बढेगे। परिणामस्वरूप, विकास योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। हाँ, यदि सरक्षण दिया जाय, तो नव उद्योग स्थापित हो सकेंगे, उत्पादन, रोजगार और आय में वृद्धि हो सकेगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी बढ जायेगा। किन्तु उचित समय पर सरक्षण हटा लेने का ध्यान रखना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

- १ टैरिफ और कोटे के प्रभावों की तुलना कीजिये। इनमें से कौन व्यापार का नियमन करने की दृष्टि से बेहतर है ?

[Compare the effects of tariffs and quotas Which one of them is better as a means of controlling trade ?]

(बिज्जस एव गोरलपुर, एम० ए०, १९६६)

- २ किस सीमा तक कोई देश टैरिफ के द्वारा बेकारी को घटा सकता है ?

[To what extent can a country diminish unemployment by means of tariffs ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

- ३ एक उद्योग को गरक्षण प्रदान करने के साधन के रूप में, राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों से, टैरिफ और कोटे के तुलनात्मक गुणों की समीक्षा कीजिए।

[Examine the comparative merits from national and international point of view of tariffs and quotas as means of affording protection to an industry]

(इलाहाबाद, एम० कॉम०, १९६७)

- ४ इस दृष्टिकोण की विवेचना करिये कि अपने सरक्षात्मक और पुनर्वितरणात्मक प्रभावों में कोटे बहुत सीमा तक टैरिफ के समान हैं।

[Consider the view that quotas are much like tariffs in their protective and redistributive effects.] (आगरा, एम० ए०, १९६७)

- ५ "शिशु के जन्म को शिशु-सरक्षण पर प्राथमिकता देनी चाहिये।" आलोचना करिये।

["Infant creation" should be given precedence over infant protection" Comment.] (इलाहाबाद, एम० ए० १९६६)

- ६ सरक्षात्मक आयतकरों के 'पूँजी की सीमान्त मुद्रातता' और 'राष्ट्रीय आय के वितरण' पर प्रभावों का विश्लेषण कीजिये।

[Analyse the effects of protective import duties on (a) marginal efficiency of capital and (b) distribution of national income]

— (इलाहाबाद, एम० कॉम०, १९६६)

- ७ यदि स्वतन्त्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को अधिकतम करता है, तो फिर आप किन आधारों पर सरक्षण का समर्थन करते हैं ?

[If free trade leads to maximisation of gain from international trade, on what grounds would you justify protection ?] (इलाहाबाद, एम० कॉम, '१९६६)

- ८ स्वतन्त्र व्यापार और सरक्षण के बीच जो विवाद है उसकी मुख्य बातों पर प्रकाश डालिये ? दोनों में से किसे आप भारत के लिये पसन्द करेंगे ?

[Explain clearly the salient features of the controversy between Free Trade and protection Which of the two would you recommend for India ?] (आगरा, एम० ए०, '१९६८)

- ९ (अ) "स्वतन्त्र व्यापार सारे विश्व के लिये लाभदायक है ऐसा दिखाया जा सकता है किन्तु एक अकेले देश के लिये वह कभी सर्वोत्तम नीति प्रमाणित नहीं हुआ है।"

(ब) "टैरिफ़ करो के द्वारा सरक्षण धरोहर उद्योगों को प्रोत्साहित करने का एक समयातीत ढंग है।" उपरोक्त दोनों कथनों पर अपने विचार उदाहरण सहित दीजिये।

[(a) "Free trade can be shown to be beneficial to the universe as a whole, but has never been proved to be the best policy also for a single country " (b) "Protection by tariff duties is an outmoded form of encouraging domestic-industries" Give your views with examples on the above two statements] (आगरा, एम० ए०, '१९६८)

१०. किन परिस्थितियों में एक विकसित देश के लिये टैरिफ़ सरक्षण उचित होगा ?

[Under what conditions is tariff protection justified in the case of an economically developed country ?]

(आगरा, एम० ए०, '१९६६)

- ११ विवेचन कीजिए कि टैरिफ़ किम सीमा तक (अ) सरक्षित देश में अधिक स्थायित्व ला सकता है, (ब) अन्य देशों में टैरिफ़ के प्रभाव को निष्प्रभावित कर सकता है, तथा (स) पूर्ण रोजगार उत्पन्न कर सकता है।

[Discuss how far tariffs can (a) ensure greater stability within a protected country, (b) neutralise the effect of tariffs in other countries, and (c) create full employment.]

द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रणालियाँ

(Bilateral and Multilateral Trading Systems)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने जिस मार्ग को व्यक्तिगत उत्पादकों और उपभोक्ताओं की स्वतन्त्र इच्छा के अन्तर्गत खुला होता उसमें सरकार अनेक तरीकों से बाधा डाल सकती है। इन तरीकों में पुराने सरक्षण प्रमुख के तरीके से लेकर नये और दक्ष तरीके जैसे अवमूल्यन और अधिमूल्यन, बहु विनिमय दर, प्रत्यक्ष परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, विनिमय नियन्त्रण, कोटा निर्धारण निश्चासी और क्षतिपूर्ति ठहराव, काउंटेस और अन्त में राजकीय व्यापार तक सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक तरीके की परीक्षा करने से यह पता चलेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के परिमाण (volume) पर सबसे अधिक प्रतिबन्धनात्मक प्रभाव डालने वाला तरीका द्विपक्षवाद (Bilateralism) है। हावर्ड एस० एलिस (Howard S. Ellis) के शब्दों में—“युद्धोत्तरकाल में स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार को सबसे बड़ा खतरा द्विपक्षवाद से है तथा इस प्रवृत्ति पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखना ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक और आर्थिक सौजन्य की प्रमुख समस्या है।”¹

द्विपक्षवाद (Bilateralism)

द्विपक्षवाद से आशय—

एलिस ने द्विपक्षी ठहराव की परिभाषा निम्न शब्दों में की है —‘एक व्यापारिक व्यवस्था उस समय द्विपक्षी’ कही जाती है जबकि इसमें इस बात का प्रयत्न किया जाय कि ‘B देश की A देश के निर्यातों’ का ‘A देश को B देश के

¹ ‘The chief peril to a large volume of free multilateral trade in the postwar world may be bilateralism and the chief problem of international commercial and economic comity may be the effective curbing of this tendency’—Howard S. Ellis : *Essays in International Finance*, No 5, Summer 1955

निर्यातों' से एक पूर्व निर्धारित परिमाणान्तरक अनुपात बना रहे। "1 अनेक व्यवस्थाओं में सामान्यतः १:१ का अनुपात ही प्रचलित है, किन्तु जब व्याज सम्बन्धी भुगतान, बकाया दायित्वों के भुगतान या नये ऋणों की स्वीकृतियाँ भी ठहराव में सम्मिलित हों, तब इस समानुपात से भिन्न कोई भी अनुपात भी निश्चित किया जा सकता है। व्यापार में द्विपक्षी सन्तुलन (Bilateral Balance) की प्राप्ति के लिये अगनाई गई सबसे प्रचलित विधियाँ अतिपूर्ति एवं निकासियाँ हैं। इन विधियों की संक्षेप में नीचे समझाया गया है।

(१) अतिपूर्ति-ठहराव (Compensation Agreements)—इस विधि के अन्तर्गत A से B को भेजे गये प्रत्येक निर्यात पार्सल के बदले में B से A की उतनी ही मूल्य का निर्यात पार्सल जाना आवश्यक है। इस प्रकार की समानता 'कुल व्यवहारों पर' नहीं बरत प्रत्येक सौदे के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप से बनाये रखने का पलन किया जाता है, जिससे कि एकपक्षी शेष कभी एकत्र (accumulate) न हो सके और न पूँजी की ऋण या विलयमान बावों के भुगतान के रूप में भेजना पड़े।

(२) निकासी-ठहराव (Clearing Agreements)—जब लेन-देनों की 'समानता' (equality) पर इतना अधिक धन दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि निर्यातकर्त्ताओं की आनुपातिक आयात अथवा आयात-कर्त्ताओं की आनुपातिक निर्यात उपलब्ध न होने से कठिनाइयाँ अनुभव हों। ऐसी कठिनाइयों का व्यापार पर बहुत ही प्रतिबन्धात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इनके निवारण के लिए प्रायः निकासी ठहराव किये जाते हैं। ऐसे ठहरावों की कार्य विधि कुछ इस प्रकार है—A से आयात करने वाले B देश के आयातक अथवा भुगतान स्थानीय करन्सी में एक सम्मिलित खाते में जमा करा दते हैं। इस खाते का सञ्चालन एक सरकारी संस्था (जैसे कि केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। A को निर्यात करने वाले B देश के निर्यातकर्त्ता उक्त खाते में ही, जैसे ही आयातों के द्वारा यथेष्ट शेष उपलब्ध हो सकें, भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। यदि B की A के निर्यात A को B के निर्यातों से अधिक हो, तो A देश के निर्यातकर्त्ताओं को अपना भुगतान पाने के लिए उस समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि B में पिछड़े हुए आयातों से पर्याप्त धन एकत्र न हो जाय। यदि वे प्रतीक्षा न कर सकें, तो फिर उन्हें अपने माल के लिये कोई दूसरा बाजार खोजना पड़ेगा। निकासी-ठहराव से सम्बन्धित देशों के मध्य साम्य की प्राप्ति निम्नलिखित उपायों द्वारा हो सकती है —

1 "A trading arrangement is bilateral when it involves an effort to achieve a predetermined quantitative ratio of the exports of country A to country B to the exports of country B to country A"—Howard M. Ellis : *International Finance* Section Princeton University

(१) इकट्ठे हुए क्रेडिट बैलेन्स के सम्बन्ध में इस आशय का कोई समझौता सरकारी स्तर पर हो जाय कि इसे बकाया चले आ रहे दायित्वों के भुगतान में प्रयोग किया जावेगा।

(२) A से B की अधिक होने वाले निर्यात में सरकारी स्तर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा कमी कराई जाये या B से A की निर्यात बढ़ाये जाये।

(३) A से निर्यातों को तब तक के लिये बन्द कर दिया जाय जब तक कि B का बैलेन्स चुकता न हो जाय।

(४) B की करेंसी में A की करेंसी का मूल्य अधोमुखी (bownwards) समायोजित किया जाय।

इन उपायों के द्वारा ११ का सरल अनुपात अथवा कोई भी ऐसा अनुपात कायम हो जायेगा, जो कि B की A में पूँजी का, सरकारों के मध्य ठहरी हुई दर में, ट्रान्सफर करादे। एष अनिपूर्ति ठहराव और एक निवासी ठहराव का भेद पूँजी के ट्रान्सफरों को बन्द करने में निहित है, अधिक वस्तुओं के बारे में प्रतिबन्ध लगाने में नहीं।

द्विपक्षवाद का विचित्र प्रतिबन्धात्मक स्वभाव—

वाहे कोई भी अनुपात निर्धारित किया जाय और इसे प्राप्त करने का ठग कुछ भी हो, निवासी ठहराव (जहाँ तक व्यक्तिगत व्यापारी सम्बन्धित हैं) विदेशी व्यापार की मात्रा और लाभदायकता को उन रात और लाभ की अपेक्षा जो कि उन्हें स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार के अन्तर्गत सामूहिक रूप से होता था, कम कर देते हैं। देश के निर्यातकर्त्ता सर्वोत्तम बाजार में विक्रय करने के लिये स्वतन्त्र नहीं होंगे, वरन् उन्हें उन देशों में बेचना पड़ता है जो कि स्वदेश से इतना सखी दे कि वहाँ के निर्यातकर्त्ताओं को भुगतान प्राप्त करने का बखस मिल जाय। इसी प्रकार आयात भी अब सबसे सस्ते बाजार से नहीं किये जाते, वरन् उस देश से किये जाते हैं जिसके लिये आयातक देश को एक निवासी वैष (clearing balance) उपलब्ध है। किन्तु यदि निकामी ठहराव के साथ भेदात्मक विनिमय दरें भी प्रचलित हैं, तो एग भेद बरतने वाला देश अन्य देशों के नुकसान पर अपने विदेशी व्यापार की लाभदायकता को बढ़ा सकता है, जिससे कुल में विश्व व्यापार पर बुरा प्रभाव ही पड़ता है। अब प्रश्न यह है कि विदेशी व्यापार में अन्य हस्तक्षेपों की अपेक्षा द्विपक्षवाद इतना प्रतिबन्धात्मक क्यों है। इसका उत्तर इसरी कुछ विशेषताओं में निहित है, जो कि निम्नलिखित हैं —

(१) निवासी ठहराव ग्लोबल रूप से सङ्कुचनशील (contractive) होते हैं, यद्यपि व्यावहारिकता के दृष्टिकोण में कुछ वस्तुओं को निवासी ठहराव से पूर्णतः मताग कर ली जाती है। जब एक बार ऐसा हो जाय, तो फिर निवासिधारा (clearing) ही व्यापार मचानन का एक मात्र गानून सम्मत टग होगी है।

(२) द्विपक्षवाद धन धन बढ़ता ही चलता जाता है। जब कोई देश विशेष

यह देखे कि उसके व्यापारिक साथी देशों ने निवासी व्यवस्था कायम करती है, जिसमें वह अपने लिये आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने हेतु यथेष्ट स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर सनता, तो वह स्वयं भी कच्चे माल के विक्रेता देशों पर निवासी व्यवस्था लागू करने के हेतु विवश हो सकता है। इस प्रकार, निवासी प्रक्रिया एक 'बुचक' (vicious circle) में परिणित हो जाती है।

(३) निवासी के फलस्वरूप प्राप्त द्विपक्षी शेष तथा विविध विनिमय दरो (प्रत्येक नाभेदार देश के सम्बन्ध में) परस्पर फिट मगति (consistency) नहीं है। उदाहरणार्थ निवासी वाले देश की विनिमय दरे आवश्यक रूप में अधिमूल्यित या अवमूल्यित होती है और विभिन्न व्यापारिक सम्बन्धों में भेद-भाव भी बरती है।

(४) निवासी या भुगतान समझौते के अन्तर्गत अपनाया जाने वाला पारस्परिक निर्दोषी का अनुपात न्यूनाधिक मनमौजी (arbitrary) होता है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल वास्तु व्यापार वस्तु प्रयोजित व्यवहारों की मात्रा और दिशा भी 'आधुनिक अधिपतय' के साधारण मार्ग' से भिन्न हो जाती है। प्रारम्भ में तो आपात-निर्यात सम्बन्धी अनुपात व्यापार को अस्त-व्यस्त नहीं करते, लेकिन कुछ समय भीतने के बाद (यदि इन अनुपातों को सशोधित न किया जाय तो) द्विपक्षी-व्यवस्था का प्रत्येक सम्बन्धित देश में वहा की सापेक्षिक साधन-कीमत सरचना में सम्बन्ध टूट जाता है। यहाँ तक कि निवासी वाली विनिमय दरे से भी उसका सम्बन्ध नहीं रहता।

द्विपक्षवाद के उद्देश्य—

अब हम उन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे जिनके कारण देश निवासी ठहरावों में प्रविष्ट होते हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

(१) विनिमय दरो का स्थायीकरण—कहा जाता है कि एक देश अपनी विनिमय दरे की स्थायित्व प्रदान करने तथा भुगतान संतुलन की गम्भीर असाम्यता का निवारण करने के उद्देश्य से द्विपक्षवाद का आशय लेता है। [किन्तु हमारी सम्मति में यह द्विपक्षी व्यापार समझौते के लिये एक सही और पर्याप्त बचाव (defence) नहीं है। यदि एक देश अपने भुगतान संतुलन में गम्भीर असाम्यता का सामना कर रहा है, तो इसे विनिमय नियन्त्रणों के द्वारा, जो कि द्विपक्षवाद की अपेक्षा बड़ी हल्के हथियार हैं, सुधारा जा सकता है।]

(२) अवांछनीय पूँजी-आवागमनों को रोकना—कभी कभी कहा जाता है कि द्विपक्षी व्यापार समझौते किसी देश द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं कि वह पूँजी के अवांछक और अवांछनीय आवागमनों का, जो कि देश के भुगतान संतुलन पर भारी बोझ डाल देते हैं, रोक सकें। [यह तर्क भी व्यर्थ है, क्योंकि इस उद्देश्य का भी कुछ कम हल्के उपायों (जैसे—आयात कोटे और विनिमय नियन्त्रण) द्वारा पूरा किया जा सकता है।]

(३) **राष्ट्रीय सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण**—बना जाता है कि द्विपक्ष-वाद का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को हल बनाना अथवा उपभोक्तृओं के कल्याण में वृद्धि करना है। [किन्तु द्विपक्षवाद का यह आवात चयन उद्देश्य भी, एक दूसरे के साथ द्विपक्षी सन्तुलन के बिना ही, आपात नियन्त्रण के द्वारा, पूरा किया जा सकता है।]

(४) **एकाधिकारिक शक्ति**—द्विपक्षवाद का वास्तविक उद्देश्य यह है कि देश इसकी सहायता में अपनी एकाधिकारिक शक्ति का अपन लिये लाभप्रद ढंग में प्रयोग करना चाहता है। बात यह है कि द्विपक्षी व्यापार समझौते देश के बाह्य बाजार (external market) को पृथक् पृथक् टुकड़ों में बाँट देते हैं। कोई देश अपने बाजार को इस प्रकार नये विभाजित करना चाहता है? इसका कारण विस्तृत स्पष्ट है। जब कोई देश अपने बाह्य बाजार का टुकड़ा में बाँटने में सफल हो जाता है तो वह बड़ा निर्मित वस्तुओं में अपना कच्चा माल खरीदने में अपनी एकाधिकारिक शक्ति कुशल देशों के विपक्ष लाभदायकता के साथ प्रयोग करने में समर्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ जर्मनी ने जो कि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व ही यूरोप की औद्योगिक शक्ति का अंश बना हुआ था, अपनी अकाधिकार एवं विपक्षी शक्तियों का प्रयोग १९३०-३५ की मध्यावधि में मध्य यूरोपीय राज्यों और लैटिन अमेरिकी देशों के विरुद्ध केवल अपने लाभार्थ किया था।

एकाधिकार (एक शब्द-एकाधिकार) व्यापार में होने वाले लाभों में अनिवार्य रूप में कमी ला देता है। विशेषतः जो देश इन शक्तियों के दबाव में होते हैं उनका बहुत पोषण होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि द्विपक्षवाद एक देश द्वारा दूसरे देश पर 'घोषा' जाता है। अन्य देशों पर उनकी इच्छा या हित के विरुद्ध द्विपक्षवाद को पोषण की शक्ति कई क्षेत्रों से उदय होती है जो कि निम्न है—(i) देशों की बाह्य खाता सम्बन्धी कण प्रस्तुता, (ii) नये ऋणों के लिए एक देश की दूसरे देश पर निर्भरता, (iii) एक देश की कुछ वस्तुओं के उत्पादन में, जोकि पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुलतारमक लाभ होना, (iv) एक देश का दूसरे देश के नियंत्रण में भारी हिस्सा होना, एवं (v) अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति-राजनीति (power-politics) का सीधा प्रयोग।

द्विपक्षवाद को रोकने के उपाय—

चूँकि द्विपक्षवाद विदेशी व्यापार में ऐसे हस्तक्षेप करता है जो न केवल विदेशी रूप से प्रतिबन्धात्मक (particularly restrictive) है बल्कि जहाँ तक मर-कारो नियमन के बंध संध्या का प्रश्न है, विमुक्त अहेतुक (gratuitous) भी होते हैं। इसलिये व्यापार की द्विपक्षी-प्रवाह में बहने से रोकने के उपायों पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है। ये उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) **द्विपक्षी व्यापार समझौते का बहिष्कार**—सैनिक गुटबन्धियों की हो

भांति द्विपक्षी समझते भी कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें राष्ट्र एक के बाद एक नहीं छोड़ सकते बरन् सब सामूहिक रूप से तथा एक ही साथ छोड़ सकने हैं। जन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने अनिवार्य नियमों में यह ठीक ही प्रावधान (provision) निषा है कि नमस्त निकासी समझौते एक निर्धारित तिथि तक खत्म कर देने चाहिये। विन्तु कोष ने सदस्य देशों पर बालू अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के सम्बन्ध में भुगतान एवं अनुरण करने पर प्रतिबन्ध न लगाने जवया भेदपूर्ण करेंसी-व्यवस्थाओं (जिनमें द्विपक्षी निकासियाँ भी सम्मिलित हैं) में मजबूत न होने की शर्तें नहीं लगाई हैं और इन प्रथाओं को एक अन्तरिम अवधि के लिये जिनकी सम्झाई अभी अनिश्चित ही रखी गई है जारी रखने की छूट दी है।

(२) दुर्बल भुगतान-सन्तुलन वाले देशों को सुदृढ़ बनाना—केवल एक ऋणात्मक कार्यवाही (negative action) करके ही शान्त वैतना पर्याप्त न होगा, क्योंकि निकासियों किंगो राष्ट्र की एकाधिकार में अबाधनीय लाभ प्राप्त करने की भावना में ही नहीं, बरन् गहरी जड़ वाली आर्थिक कठिनाइयों पर आधारित निराशा-भावना से भी उत्पन्न होती और बनी रहती हैं। एक अनुपयुक्त विनिमय दर, जो कि भुगतान सन्तुलन में साम्यता की दृष्टि से बड़ी अधिक ऊँची है, ऐसी ही कठिनाइयों में से एक है। कम से कम तीन परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण अनुपयुक्त दरों के सुधार के लिए देशों के व्यक्तिगत प्रयत्नों पर निर्भर रहना असम्भव है यथा—(i) देश को यह प्रलोभन रहता है कि वे अपनी करेंसी के बाह्य मूल्य को इसके दाम्न-विश्व या साम्य स्तर की अपेक्षा घटाकर 'बेकारी का निपट' कर दें, (ii) विनिमय दर की कठौती से हाथ उठाने वाले अन्य देशों को भी ऐसा ही करने का प्रलोभन होता है, एवं (iii) जहाँ आयात और निर्यात सम्बन्धी माँग लोच (elasticities) से यह प्रकट हो कि विनिमय दर में छोटे मीठे परिवर्तन करने से भुगतान सन्तुलन में कोई सुधार नहीं हो सकता है, वहाँ भारी अवमूल्यन (drastic devaluation) ही एक मात्र उपाय है।

उक्त तीनों दशाओं में एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था द्वारा ही, जिसे कि अनुपयुक्त अवमूल्यन के विरुद्ध बीटो के प्रयोग का अधिकार हो, उद्देश्य-रहित अवमूल्यन-वृत्त के विरुद्ध साम्यविष गाएली दी जा सकती है। उक्त संस्था देशों पर यह दबाव डालने में भी समर्थ होनी चाहिये कि वे अपने यहाँ आवश्यक आन्तरिक समायोजन (adjustments) कर लें जबकि दुर्बल करेंसी वाले देश अपने यहाँ मुद्रा प्रसारित प्रवृत्तियों को दबायें और हट नरेंसी वाले देश अपने यहाँ मुद्रा विस्फीतिक प्रवृत्तियों को रोकें। कारण, जब ऐसे समायोजन कर लिए जायेंगे, तब ही भुगतान में सुधार सम्भव हो सकेगा। जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विधान में भी कहा गया है, दोषी देशों पर दबाव डालने के लिए यह प्रावन्ती लगाई जा सकती है कि वे संस्था के प्रस्तावों का प्रयोग करने में वचित कर दिये जायेंगे, अथवा, उन्हें वस्तुमूली मौद्रिक सङ्कटन में जिम्मापित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही साथ उम्मे चाहिए

कि भुगतान सतुलन सम्बन्धी अस्थाई अथवा मौसमी कठिनाइयों पर एक सुरक्षित विदेशी विनिमय कोषों में कमी आने पर, जितने समय में मुपारारत्मक कार्यवाही की जाये उतने समय तक के लिये, देशों को अल्पकालीन ऋण भी दे ।

किन्तु, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मौलिक दोष जब तक विद्यमान रहेंगे, ऋणों सम्बन्धी कठिनाइयों को बुनियादी रूप में ठीक नहीं किया जा सकेगा । अतः यदि भविष्य में द्विपक्षवाद में बचना है, तो देश की अर्थव्यवस्था को जो कि अभी तक एक या दो निर्यात वस्तुओं पर ही मुख्यतः आधारित रही है, विविधीकृत (diversified) बनाना होगा । विश्व के घनिक एवं उन्नत देशों को भी चाहिए कि वे पिछड़े हुए देशों के औद्योगीकरण में पर्याप्त धन आदि से सहायता करें ।

(३) एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समस्या की स्थापना—एक अन्य महत्वपूर्ण उपाय यह है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सङ्गठन की स्थापना की जाय, कारण एक शक्तिशाली सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के घनिष्ठ सहयोग से, भेद रहित बहुमुखी व्यापार प्रणाली के स्वस्थ विकास में, योग दे सकेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में से द्विपक्षवाद को समाप्त करने की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बहुत कार्य किया है, जैसे—द्विपक्षवाद का अतिमत्त बाह्य-प्यार कराना, अनुपयुक्त अवमूल्यन के विरुद्ध दबाव डालना, भुगतान सतुलन सम्बन्धी अस्थाई कठिनाई को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण देना, उन्नत देशों को पिछड़े हुए देशों में विनियोग करने की प्रेरणा देना । ये सब प्रवृत्तियाँ इस विश्वव्यापी भावना का प्रतीक है कि द्विपक्षवाद को जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए । इतने पर भी—“अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में द्विपक्षवाद के विरुद्ध संघर्ष अब ही सफल हो सकता है जबकि इसका संचालन प्रतिस्पर्धायुक्त एवं भेद-भाव के विरुद्ध सामान्य आक्रमण के एक अङ्ग के रूप में किया जाय । एक ऐसे विश्व में, जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ऊँचे टैरिफ की जमीन में जकड़ा रहता है, कोटे नीचे निर्धारित किये जाते हैं, विदेशी विनिमय का मनगाने उल्लू से बितरण किया जा सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स एवाधिकारिक घोषण कर रहे हैं, द्विपक्षवाद के विरुद्ध सफलता के आगार कम ही होंगे ।”¹

¹ ‘The struggle against bilateralism in international trade will only be successful if it is conducted as a part of a general attack upon restriction and discrimination. In a world where international trade remains in the fetters of high tariffs, low quotas, arbitrary exchange allocations and monopolistic exploitation by international cartels, the eventual success of the struggle against bilateralism would be unlikely’—Howard S. Ellis *Bilateralism and The Future of International Trade*.

बहुपक्षवाद (Multilateralism)

बहुपक्षी व्यापार प्रणाली से आशय उन व्यापारिक संधियों का है जो कि अन्तराष्ट्रीय समझौते के बलस्वरूप एक ही साथ दो से अधिक देशों के मध्य सम्पन्न होती हैं। द्विपक्षी व्यापार समझौतों की प्रणाली बहुपक्षी व्यापार प्रणालियों की तुलना में नई है, किन्तु दो महायुद्धों की अवस्थापति में तथा वर्तमान युद्धोत्तर काल में विश्व के देशों द्वारा ऐसे समझौते इसनी अधिक नख्या में किये गये कि इन्होंने पुरानी बहुमुखी व्यापार प्रणाली को दृष्टि-ओम्भत कर दिया है।

द्विपक्षी व्यापार प्रणाली पर बहुमुखी व्यापार प्रणाली की श्रेष्ठता—

द्विपक्षी व्यापार समझौतों का स्वभाव विश्व व्यापार के लिये प्रतिवन्धनात्मक होने के साथ ही साथ इनकी निम्नलिखित हानियाँ भी हैं —

(१) आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहारों का विस्थापन—जबकि बहुपक्षी व्यापार एक ऐसी विश्व-बाजार-व्यवस्था को जन्म देता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाएँ एक दूसरे के निकट सम्पर्क में आती हैं, तब द्विपक्षवाद के अन्तर्गत कोई एक विश्व-बाजार नहीं होता और जिस सीमा तक व्यापार 'द्विपक्षी' होता है उस सीमा तक आर्थिक एवं वित्तीय व्यवहार विस्थापित (dislocate) हो जाते हैं।

(२) अनसमझौते विनिमय दरें—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत सभी विषय-वस्तुओं का मूल्यमान समान रूप से होता है, किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसा नहीं है। यही नहीं, जबकि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत, जोकि अन्तराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का 'सार' (essence) है, समस्त राष्ट्रीय करेंसियों का मूल्यमान समान रूप से होता है तब द्विपक्षवाद के अन्तर्गत विनिमय दरें अनसमझौते और उन दरों से भिन्न होती हैं जो कि एक स्वतन्त्र विश्व विनिमय बाजार में विद्यमान होती चाहिए।

(३) जब अथवा विपक्ष पर प्रतिबन्ध—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत देश को सबसे सही बाजार में बेचने और सबसे सस्ते बाजार में खरीदने की स्वतन्त्रता होती है किन्तु यह स्वतन्त्रता द्विपक्षवाद के अन्तर्गत सम्भव नहीं है। एक देश सर्वोत्तम बाजार में न तो खरीद सकता है और न बेच ही सकता है।

(४) शोषण के लिये सौंदा—द्विपक्षवाद के अन्तर्गत एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अपनी चब एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग अपने से दुर्बल राष्ट्र के विरुद्ध अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये कर सकता है। उदाहरणार्थ, जर्मनी ने महायुद्धों की अवस्थापति में अपनी चब शक्ति का प्रयोग दुर्बल सेंटिन अमेरिकी देशों का शोषण और इस प्रकार अपनी युद्ध-अव्यवस्था का निर्माण करने में किया। किन्तु बहुपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसे शोषण के लिये कोई सौंदा नहीं है।

(५) वस्तुओं एवं साधनों का प्रतिबन्धित पहुँच—पुरानी अच्छी बहुपक्षी

व्यापार प्रणाली के अधीन प्रत्येक देश के लिए, जब तक कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कीमत चुका सकता है, प्रत्येक वस्तु और साधन मुक्त पहुँच होती थी किन्तु ऐसी स्वतन्त्र और समान पहुँच (Free and equal access) द्विपक्षवाद के अधीन सम्भव नहीं है क्योंकि इससे स्वतन्त्र विश्व बाजार का ही अभाव होता है। 'सम्पन्न' एवं 'विपन्न' वर्गों में विभाजन, जो कि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत अनुपरिचित है, द्विपक्षवाद के अधीन प्रवसता में पाया जाता है।

(६) भेदात्मक व्यवहार—जिसी की देश के पक्ष या विपक्ष में वस्तु की कीमत, पुण या मात्रा की दृष्टि से भेदात्मक वर्धन करने के लिये बहुपक्षी व्यापार समझौते के अंतर्गत कोई अवसर नहीं होता, किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत पर्याप्त रहता है।

(७) अहम्य मद्य की उपेक्षा—जबकि बहुपक्षवाद के अन्तर्गत हृदय एवं अहम्य दोनों ही प्रकार की मद्य समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, द्विपक्षी समझौते से सम्बन्धित देशों का अहम्य एक विशेष अवधि के भीतर केवल चाकू व्यावहारिक के सम्बन्ध में भुगतान सतुलन को सतुलित करना होता है जिससे अहम्य मद्य की उपेक्षा हो जाती है तथा ऐसे ठहरावों में 'स्थानान्तरण व्यापार' (transit trade) को सम्मिलित करने का भी कोई प्रावधान (provision) नहीं होता है।

(८) व्यापार-वर्षों में समायोजन सम्भव नहीं—बहुपक्षवाद के अन्तर्गत व्यापार की मात्रा दोनों देशों की लागत-कीमत परिस्थिति द्वारा निर्धारित होती है तथा व्यापार में इस परिस्थिति के परिवर्तन के अनुसार ही समायोजन होता रहता है किन्तु द्विपक्षवाद के अन्तर्गत ऐसे समायोजन सम्भव नहीं है।

(९) एकाधिकारों और कार्टेलों की स्थापना—द्विपक्षवाद के अन्तर्गत एकाधिकारों और कार्टेलों की स्थापना होना बहुत ही शुभ है। ये संस्थाएँ ऊँची कीमतें निर्धारित कर सकती हैं और इस प्रकार सहाय्य विरोधी कार्यकलापों में सलग्न रह सकती हैं। लेकिन बहुपक्षवाद के अन्तर्गत कीमतें विश्व बाजार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता की उपस्थिति के कारण लागतों से बहुत निकट समानता रखती हैं, जिससे उत्पादकों के लिये उपभोक्तकों का शोषण करना सम्भव नहीं होता। इस प्रकार, द्विपक्षवाद के विपरीत, बहुपक्षवाद विषय भरे उपभोक्तकों के हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है।

द्विपक्षवाद के लिये औचित्य —

द्विपक्षवाद के लिए सहानुभूति रखन वालों की कमी नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग उन देशों द्वारा किया जाता है जो कि अपने उद्योगों का विकास या पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। किन्तु इस परिस्थिति का समर्थन करना सम्भव नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) यदि आर्थिक रूप से निर्बल देशों को इस हथियार के प्रयोग की अनुमति देना ठीक ही हो, तो राष्ट्रों में शक्ति सम्पत्ति या शक्ति के व्यापार पर कोई ऐसी

विभाजक रेखा खींचना कठिन होगा जो यह बता सके कि अमुक-अमुक राष्ट्र दुर्बल और अमुक-अमुक राष्ट्र सबल है। सच तो यह है कि यदि यह प्रथा एक बार स्वीकार कर ली गई, तो युद्ध पूर्व अवधि की भांति यह अन्य देशों पर भी फैलने का डर है जिस से सीधे ही शक्तिशाली देश भी भेदान्तर एकधिकार अपना लेंगे। यदि ऐसा हुआ, तो दुर्बल देश अपने को पहले से भी अधिक दुर्बल पायेंगे, क्योंकि उनकी सापेक्षिक स्थिति तो पहले की अपेक्षा कुछ थोड़ा न होगी किन्तु विश्व व्यापार में उनका हिस्सा पहले से भी कम हो जायेगा।

(२) एक देश के लिए प्रायः यह कठिन या लगभग असम्भव ही होता है। कि वह निकासियों की व्यवस्था में अलग हो जाय, क्योंकि किसी भी समय पर उसको यह विरवास होगा कठिन है कि स्वतन्त्र बहुपक्षी व्यापार के लिए द्वार खोल कर बहु इतना पर्याप्त विदेशी विनिमय अर्जित कर सकता है कि अपनी आयात सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करले। आस्ट्रिया भी, जिसने १९३३-३५ में अन्य सब विनिमय नियंत्रण हटा लिए थे, निकासी समझौते रद्द न कर सका था।

उपसंहार—भारत के लिए लाभ

इस प्रकार, विश्व शान्ति और आर्थिक सम्पन्नता के हित में बहुपक्षी व्यापार व्यवस्थाओं को द्विपक्षी व्यापार पर प्राथमिकता देना आवश्यक है। युद्धोत्तर काल में, विशेषतः स्वतन्त्र होठों के बाद, भारत ने विश्व के अनेक देशों (जैसे चैकोस्लाविकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, स्विटजरलैंड, फिनलैंड, मिश्र, लार्जेन्टाइना, सोवियत रूस और पाकिस्तान आदि) से द्विपक्षी व्यापार समझौते किये हैं। यद्यपि बहुपक्षवाद विश्व व्यापार का सर्वरक्षी कार्य सर्वाधिक वांछनीय स्वरूप है तथापि द्विपक्षवाद को भारत की दिशिष्ट आर्थिक दशाओं के स्वयं में बिल्कुल अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। कारण, इससे उसे निम्नलिखित लाभों की आशा है—

- (१) ये समझौते हमें आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न और यन्त्रों में पर्याप्त मात्रा में दिला सकेंगे।
- (२) ये भारत के आयात व्यापार की विधा को बाहर देशों से नॉन-बालर देशों को मोड़ने में सहायक होंगे।
- (३) ये निर्यातों में वृद्धि कर सकेंगे जिससे कि हमारे भुगतान सतुलन की प्रतिकूलता कम होने में सहायता मिलेगी।
- (४) कुछ दशाओं में द्विपक्षी व्यापार समझौते अनिवार्य हैं। उदाहरणार्थ, ईस्ट जर्मनी, रूस, फिनलैंड आदि से (जहाँ कि विदेशी व्यापार पर सरलार का प्राथमिक्य है) व्यापार केवल द्विपक्षी व्यापार समझौते के आधार पर ही बढ़ाया जा सकता है, एवं
- (५) इनने द्वारा भारत समझौतों से सम्बद्ध अन्य देशों से राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक निकट हो जायेगा। यहाँ,

सङ्घा और समुक्त अरब गणराज्य से हमारा व्यापार इसी श्रेणी का है।

किन्तु यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि द्विपक्षी व्यापार समझौते केवल अल्पकाल के लिए ही उचित ठहराया जा सकते हैं। दीर्घकाल में, जबकि राज-नैतिक शान्ति और स्थायित्व प्राप्त हो जाय, सब भारत को बहुमुखी व्यापार प्रणाली से ही लाभ की विशाल सम्भावनाएँ हैं।

परीक्षा प्रश्न :

- १ द्विपक्षी व्यापार समझौते क्या हैं और इन्हें क्यों अपनाया गया है ? क्या भाग इन्हें विश्व व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला मानते हैं ? यदि हाँ, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है ?

[What are bilateral trade agreements and why have they been resorted to ? Do you think them to be restrictive to world trade ? If so, how can they be prevented ?]

- २ बहुपक्षी एवं द्विपक्षी व्यापार-समझौतों के सापेक्षिक गुण दोषों का विश्लेषण कीजिये। आप भारत के लिए इनमें से किये बेहतर समझते हैं और क्यों ?

[Discuss the relative merits and demerits of multilateral and bilateral trade agreements Which system would you advise for India and why ?]

(आगरा, एम० कॉम०, १९६६)

- ३ द्विपक्षी व्यापार समझौते कहीं तक स्वतन्त्र व्यापार की दिशा में ले जाने हैं ? इनकी सीमाएँ बनाइये।

[How far are bilateral trade agreements a move towards free trade ? Examine their limitations]

(गोरख०, एम०ए०, १९६८)

- ४ क्या द्विपक्षी व्यापार समझौते परमानुबहित राष्ट्र व्यवहार से संगति रखते हैं ? उदाहरण सहित उत्तर दीजिये।

[Are bilateral trade agreements consistent with the most favoured nation's treatment ? Illustrate your answer with examples]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

साम्राज्यीय अधिमान

(Imperial Preference)

परिचय—

आर्थिक सहयोग (economic co operation) का एक अन्य रूप जो कि विश्व के व्यापारिक राष्ट्रों के मध्य उदय हुआ है 'साम्राज्यीय अधिमान' है, जिसे जागतिक राष्ट्रमण्डलीय अधिमान' (Commonwealth Preference) कहते हैं।

साम्राज्यीय अधिमान का अर्थ

साम्राज्यीय अधिमान' (Imperial Preference) वह प्राथमिकता या विशेष रियायत है जो कि एक अधीन देश (या उपनिवेश) अपने साम्राज्य (या मातृ) देश के प्रति विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में देता है चाहे साम्राज्य देश (Empire country) उसे वंसी प्राथमिकता रियायत दे या नहीं। यह प्राथमिकता या रियायत आयातों या निर्यातों से अथवा एक ही समय पर दोनों से सम्बन्धित हो सकती है। इस प्रकार साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत एक अधीन देश साम्राज्य देश में, किसी अन्य देश में मस्ती या श्रेष्ठ वस्तुओं आयात करने के बजाय, महँगी अथवा घटिया वस्तुएँ लेने को भी तैयार हो जाता है। इसी तरह, वह साम्राज्य देश में अपने निर्यातों का कम मूल्य चार्ज कर सकता है। साम्राज्यीय-अधिमान साम्राज्य देश के आयातों पर कम दर से इम्पूटी लेने के रूप में भी हो सकता है जबकि अन्य देशों से वंसी ही वस्तुओं पर ऊँची दर में इम्पूटी ली जाती है। यह भी हो सकता है कि अधीन देश अपने आन्तरिक बाजार को अथवा या पूर्णतः साम्राज्य देश की कुछ वस्तुओं के लिए मुरलित कर दे अथवा साम्राज्य देश को 'ड्रा बैक' (Draw-backs) की स्वीकृति दे।

साम्राज्यीय अधिमान की सफलता के लिए आवश्यक बातें

साम्राज्यीय अधिमान की योजना सफल हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि (i) साम्राज्य एवं अधीन देशों के मध्य व्यापार की संश्लेष सम्भावनाएँ विद्यमान होती चाहिए, (ii) अधीन देश साम्राज्य देश के अधिमान सम्बन्धी दावे को स्वीकार करने के लिए तत्पर होना चाहिए, एवं (iii) साम्राज्य देश की सहमति के बिना

अन्य देशों को कोई अधिमान या रियायत नहीं दी जाये। स्पष्टतः साम्राज्यीय-अधिमान-योजना का आर्थिक महत्त्व इस बात से उदय होता है कि इसमें साम्राज्य में बाहर के देशों के साथ रियायती व्यवहार का अभाव है।

साम्राज्यीय अधिमान योजना की दुर्बलतायें

विश्व-व्यापार पर प्रभाव—

साम्राज्यीय अधिमान योजना बढ़ते हुए विश्व व्यापार के हितों के विरुद्ध है।

यह बात निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगी —

(१) यह अर्थ के विभाजन एवं विशेषीकरण में आधार डाल कर विश्व व्यापार की मात्रा को घटाने हैं—विश्व व्यापार विषयक एक स्वस्थ नीति की बुनियादी विशेषता किसी देश की इस स्वतन्त्रता में निहित है कि वह सस्ते से सस्ते बाजार में खरीद सकता है और मंहेंगे से मंहेंगे बाजार में बेच सकता है। किन्तु यह विशेषता साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत उपस्थित नहीं है, क्योंकि अधीन देशों की साम्राज्य देशों के प्रति न केवल राजनैतिक बरत आर्थिक रूप से भी एक दास जैसा व्यवहार करना पड़ता है। वह न तो मंहेंगे से मंहेंगे बाजार में बेचने के लिए स्वतन्त्र होता है और न सस्ते से सस्ते बाजार में खरीदने के लिए। अतः अधीन देश स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाले लाभ से वंचित हो जाते हैं।

(२) योजना से बाहर के देशों द्वारा प्रतिकारात्मक (retaliatory) उपाय किये जाने की भी सम्भावना है। वास्तव में आजकल विश्व कई गुटों में विभाजित हो गया है तथा व्यापारिक दल घट्टी का असाइन बन चुका है।

(३) यह अधीन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था का डोल और सन्तुलित आधार पर विकास करने से रोकती है। विशेषतः जब कि एक साम्राज्य देश एक औद्योगिक उन्नत राष्ट्र हो, तो अधीन देश को कृषक देश बना रहने पर ही विवश किया जा सकता है जिसमें कि साम्राज्य देश की आवश्यक कच्चा भात नियमित रूप से मिलता रहे तथा उनकी निर्मित वस्तुओं के लिए वहाँ विक्रय-बाजार सदा उपलब्ध रहे। स्पष्टतः ऐसी दशा में पिछड़े हुए भागों की समस्या (problem of backward areas) उत्पन्न हो जाती है, जहाँ लोगों की क्रयशक्ति बहुत ही नीची होती है।

(४) उपनिवेशों और साम्राज्य देश के मध्य आय सम्बन्धी विस्तृत अन्तर (wide income disparities) उदय हो जाते हैं। एक ओर तो साम्राज्य देश में लोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु दूसरी ओर, अधीन देशों में लोग अपना न्यूनतम भरण पोषण करने में भी कठिनाई अनुभव करने हैं।

(५) पिछड़े हुए अधीन देशों में सम्भाव्य प्रचुरता के मध्य दरिद्रता विद्यमान होती है। साम्राज्य अधिमान की नीति का अनुमान करने से जो आय-सम्बन्धी भिन्नतायें उदय होती हैं वे उपभोग-वृत्ति (propensity to consume) को निरस्त करती हैं। एक ओर पृथ्वी के गर्भ में विद्याल प्रमाणन ध्रुव पड़े रहते हैं और यह

प्रतीक्षा करते रहते हैं कि एक दिन उनके शोषण का भी क्षवमर आयेगा, तब दुमरी ओर, लोग भरपेट भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा जीवन की अन्य धुनपाटी आवश्यकतायें भी पूरी करने में असमर्थ होते हैं।

ये सब बातें विश्व-व्यापार के विस्तार और स्थायित्व के लिए हानिप्रद हैं। वास्तव में, साम्राज्यीय अधिमान योजना 'सर्वानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार योजना' (Scheme of Most Favoured Nations Clause) से ठीक विपरीत है। अतः यह कहना बिल्कुल सच है कि साम्राज्यीय अधिमान न केवल व्यापार के परिणाम को घटाता है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को भी कम करता है।

साम्राज्यान्तर्गत व्यापार पर प्रभाव—

साम्राज्यीय अधिमान योजना ने एक नये प्रकार के व्यापार को जन्म दिया है। इस नये प्रकार के व्यापार को 'साम्राज्यान्तर्गत व्यापार' (Inter Empire Trade) कहते हैं। इस प्रकार का व्यापार, जो साम्राज्यीय अधिमान नीति के अभाव में कदापि विद्यमान नहीं हो सकता था, विश्व व्यापार में एक अलग श्रेणी का होता है क्योंकि यदि दोनों तरह के व्यापार संचालन में एक ही श्रेणी के होने, तो एक के विस्तार द्वारा ही आवश्यकता का तनिक भी अनुभव नहीं होता।

साम्राज्य अधिमान की नीति का विकास कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का फल है। यह सभी अधीन देशों को इस बात के लिए विवश करती है कि वे मात्र देश की वृद्ध व्यापारिक सुविधायें बेचारे मातृ देश उन्हें बंदी सुविधायें दे या नहीं। हाँ, मातृ देश अधीन देशों द्वारा प्रदान की गई व्यापारिक सुविधाओं के बचले में उनकी सुरक्षा का भार प्रायः अपने ऊपर ले लेता है। कुछ भी हो, अधीन देशों की अर्थ-व्यवस्थायें मातृ देश की अर्थ-व्यवस्था का एक आवश्यक अंग बन जाती हैं तथा उन्हें इसका एक विस्तार मान समझा जा सकता है। साम्राज्यीय अधिमान की विचारधारा ने साम्राज्यान्तर्गत व्यापार पर बहुत ही प्रभाव डाला है, जो कि इस प्रकार है—

(१) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के हित पर प्रभाव—साम्राज्यीय अधिमान योजना के अन्तर्गत साम्राज्य के देशों के हित बलान् मात्र ही देश के हित से बाँध दिये जाते हैं। अधीन देशों के प्रसाधनों का शोषण इस तरीके से किया जाता है कि मातृ देश की मुनिपादी आवश्यकतायें सन्तुष्ट होती रहें। इस प्रकार, व्यापार एक पूरक स्वभाव ग्रहण कर लेता है तथा वह लाभ-न्यूनतम घटकों (cost price factors) से निर्धारित नहीं होने पाता है।

(२) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की दिशा पर प्रभाव—अनुभव ने यह दिखाया है कि साम्राज्यीय अधिमान की नीति के अधीन देशों के अर्थव्यवस्था का विकास प्रमुख एवं निष्कर्षण उद्योग-प्रमुख बना दिया है, जबकि मातृ देश ने औद्योगिक विरासत में एक श्रेष्ठ स्थान पा लिया। इस प्रकार, साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की दिशा यह रही कि अधीन देशों में कृषि उपजें, खनिज-पदार्थ और अन्य कच्चा माल साम्राज्य देश को जाता है, तथा वहाँ से निर्मित वस्तुयें आधीन देशों को जाती हैं।

(३) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—नि मदेह साम्राज्यीय अधिमान नीति ने साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की मात्रा (volume) को बढ़ा दिया है किन्तु यह वृद्धि अल्पकालीन है, अन्ततः, वह इसे घटाने में ही योग देगी ।

१

परीक्षा प्रश्न

१ साम्राज्य अधिमान की प्रथा के परिपालन के फलस्वरूप न केवल व्यापार के परिमाण में कमी होती है वरन् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाला लाभ भी घट जाता है ।” क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? सकारण उत्तर दीजिये ।

['Imperial Preference results not only in a reduction in the volume of trade but also diminishes the gain from international trade' Do you agree ? Give reasons for your answer]

२ साम्राज्य अधिमान क्या है ? इसका विश्व व्यापार के तथा साम्राज्यान्तर्गत व्यापार के परिमाण, इनकी रचना और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

[What is Imperial Preference ? What effect does it have on volume, composition and direction of world trade and of inter empire trade ?]

राशिपतन, कार्टेल्स एवं एकाधिकार

(Dumping, Cartels and Monopolies)

परिचय—

अब तक हमने यह मान कर विवेचन किया था कि स्वदेश में और विदेश में स्वतन्त्र प्रतियोगिता ही प्रचलित है। अब हम यह देखेंगे कि यदि स्वतन्त्र प्रतियोगिता अनुपस्थित है अथवा इसके कमी हो गई है, तो छबूटोज (duties) घटाने या बढ़ाने के क्या प्रभाव होंगे? एकाधिकारिक शोषण के विरुद्ध क्या टैरिफ एक पर्याप्त बचाव है? यदि किसी छबूटी की आड़ में एक कार्टेल (cartel) बन जाय या किसी विनोप सस्या को एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो जाय, तो क्या करना चाहिए? इस सम्बन्ध में सब में विचारणीय प्रमेय (phenomenon), जो अपना प्रभाव स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अन्तर्गत विस्तृत करता है किन्तु जो एकाधिकार और सरक्षण का 'शिष्ट' है, 'राशिपतन' के नाम से विख्यात है।

राशिपतन (Dumping)

राशिपतन का अर्थ—

विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार में राशिपतन की परिभाषायें दी हैं। किन्तु समस्त परिभाषाओं में से निम्नलिखित दो परिभाषायें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं—

(१) विदेशों में गृह कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर विक्रय करना—प्रायः सर्वत्र ही 'राशिपतन' शब्द का आशय किसी वस्तु को विदेशों में ऐसी कीमत पर बेचने से लगाया जाता है जोकि उसी वस्तु की उसी समय पर तथा उन्ही परिस्थितियों के अधीन (अर्थात् भुगतान सम्बन्धी समान दशाओं के अन्तर्गत) स्वदेश में चार्ज की जाने वाली कीमत में भी (यातायात व्यय को विचार में लेते हुए) कम है।¹

1 "The term dumping is now almost universally taken to mean the sale of a good abroad at a price which is lower than the selling price of the same good at the same time and in the same circumstances (that is, under same conditions of payment etc.) at home, taking account of differences in transport costs"

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 296.

प्रोफेसर वाइनर के अनुसार—“दो बाजारों में कीमत सम्बन्धी विभेद निया जाना ही राशिपतन है।”^१ वाइनर की परिभाषा निम्नलिखित तीन कारणों से अधिक श्रेष्ठ मानी गई है —

(१) राशिपतन के आधारभूत कीमत नियम वही (same) होते हैं चाहे यह दो स्वतन्त्र देशों के मध्य हो या एक ही देश के दो भागों में हो ।

(२) इस परिभाषा में विपरीत राशिपतन (Reverse Dumping) भी सम्मिलित है, जिसमें कि विदेशी कीमतें गृह कीमतों से ऊँची रखी जाती हैं ।

(३) कीमत विभेद देश और विदेश के मध्य ही नहीं होता, बरन् दो विदेशी बाजारों के मध्य भी हो सकता है ।

किन्तु हम इस अध्याय में स्थानाभाव के कारण सबसे महत्त्वपूर्ण दशा पर ही ध्यान देंगे जो कि गृह कीमत से कम कीमत पर विदेशों में वस्तु के निर्यात से सम्बन्धित है और फिर इसके निरूपण यथोचित परिवर्तनों के साथ अन्य दशाओं पर भी लागू किया जा सकते हैं ।

प्रो० वाइनर की परिभाषा के अनुसार राशिपतन के दो प्रमुख स्वरूप हैं (१) स्वदेशी कीमत (home price) और (२) विदेशी कीमत (foreign price) । स्वदेशी कीमत व विदेशी कीमत की तुलना करते समय हमें निम्नलिखित बातों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए —

(अ) वह समय-बिन्दु (point of time), जिससे कि तुलना का सम्बन्ध है । यह समय बिन्दु वह होना चाहिए जबकि विक्रय अनुबन्ध किया गया है । यदि इससे आसन्न उस समय का लिया जाय, जबकि वस्तुओं वास्तव में निर्यातक देश की सीमा को छोड़ रही हो तो राशिपतन विरोधी उपाय ठीक-ठीक लागू न किये जा सकेंगे क्योंकि सम्भव है कि मध्यान्तर में स्वदेशी कीमतें बढ़ जायें ।

(ब) वातायात व्यय को भी विचार में लेना चाहिए । जब निर्यात के लिये उद्भूत की गई c o f price स्वदेशी कीमत की तुलना में वातायात व्यय की सम्पूर्ण राशि से ज्यादा होती है, तब ही राशिपतन विद्यमान होता है । स्वदेशी और विदेशी कीमतों में वास्तविक तुलना तब ही सम्भव है जबकि दोनों ही कारखाना मूल्य पर (वातायात व्यय जोड़े बिना ही) ली जायें ।

(स) हमें अन्य अनेक बातों पर भी ध्यान देना चाहिए । जैसे—निर्यात के लिए विरोध पैकिंग का व्यय, भुगतान सम्बन्धी दशाएँ, किस्म सम्बन्धी रिबेट आदि । यदि इन्हें विचार में न लिया गया, तो वास्तविक कीमत-तुलना सम्भव न हो सकेगी ।

^१ “Dumping is the price-discrimination between two markets.”
—Viner : *Dumping*, p. 5.

सन् १९१६ में अमेरिका के टेरिफ कमिशन ने विदेशी राशिपतन के बारे में १४६ शिकायतें प्राप्त की थी, जिनमें से २३ का सम्बन्ध विदेशी में वस्तुयें स्वदेशी कीमत से कम पर विनय करने से था और ६७ दशायें केवल विदेशी उत्पादकों से बहुत प्रतियोगिता मान होने से सम्बन्धित थी। अन्य शिकायतें घोंसे में डालने वाले व्यापार चिन्ह, वस्तुओं के झूठा वर्णन तथा कस्टम अधिकारियों के सामने मूल्य सम्बन्धी झूठी घोषणायें करने के सम्बन्ध में थी। वैज्ञानिक विवेचना में 'राशिपतन' शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी कीमत पर वेचने से लिया जाता है जो कि विदेशी देश में प्रचलित कीमत से कम हो, या उस कीमत में, जिस पर कि विदेशी उत्पादक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कम हो।

(२) विदेशों में उत्पादन लागत से कम कीमत पर विनय करना—यह राशिपतन की दूसरी प्रमुख परिभाषा है। इसके अनुसार राशिपतन का आशय, वस्तुयें विदेशों में उत्पादन-लागत से कम कीमत पर बेचने में है। निर्यातों पर जो हानि होती है उसकी पूर्ति उस लाभ में से करनी जाती है जो कि देश में ही वस्तु को बिक्री करने में होता है। कभी-कभी यह भी होता है कि 'बूवि' स्वदेश में उत्पादक अल्पधिक ऊँची कीमत चार्ज कर रहे थे, इसलिए उनके लिए यह सम्भव हो गया कि वे विदेशों में कम कीमत पर निर्यात कर सकें। ध्यावहारिक दृष्टि में उपरोक्त परिभाषा में कई दोष हैं —

(अ) उत्पादन लागत का पता बहुत ही कठिनाई से लग सकता है जबकि स्वदेशी कीमत के विषय में ऐसी बात नहीं है।

(ब) उत्पादन लागत की धारणा स्वयं में ही भ्रामक भी है। यदि हमका आशय प्रति इकाई औसत लागत (average costs) से हो और प्रबन्ध व्यय एवं स्थाई पूँजी पर व्याज आदि कुल लागत (total cost) में सम्मिलित हों, तो निम्नोक्त हानि निर्यात प्रायः उत्पादन लागत से कम पर किया जाता है। किन्तु, इस अर्थ में, औसत लागत से कम पर वस्तुयें बेचने में कोई हानि उदय नहीं होती है। हानि तो तब ही हो सकती है जबकि कुल उत्पात्ति औसत लागत से कम पर बेची जाय। लेकिन जब राशिपतन लिया जाता है, तो, नियम के रूप में, स्थायी लागतें (सामान्य उपरिव्यय (general overhead costs) अथवा अधिकतर स्थाई लागतें आन्तरिक दिनी से चुक जाती हैं जिससे निर्यात कीमत के लाभदायक होने के लिए इतना ही आवश्यक है कि वह निर्यात की गई मात्रा की परिवर्तनशील लागतें पूरी कर दे। इस प्रकार निर्यात कीमत का मूलतः स्तर सीमान्त लागत (marginal costs) के द्वारा, अर्थात्, निर्यात के लिए उत्पात्ति का विस्तार करने की अतिरिक्त लागत के द्वारा, निर्धारित होती है। उन सब बड़े प्रचलित दशायों में, जिनमें कि उत्पात्ति का विस्तार विद्यमान उत्पादक इकाई के भीतर ही किया जा सकता है (अर्थात् मकान, प्लांट या साज सामान बढ़ाये बिना ही कथथा कम से कम उन्हें जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ा है उससे अधिक

बढाये बिना ही उत्पादन का विस्तार किया जा सकता है), सीमान्त लागत 'औसत लागत' से नीचे ही रहती है।

(४) यही नहीं, हानि पर विक्रय करना (selling at a loss) वादयास भी भ्रम उत्पन्न करने वाला है। मान लीजिए कि कीमत रास्ता की बाधू लागतों (स्टाई एय परिवर्तनशील) का तो चुकता कर लेती है किन्तु स्थिर पूँजी विषयक मुगतान (जैसे व्याज) नहीं। यदि ऐसी कीमत पर बेचने को ही हम हानि पर बेचना कहते हैं, तो 'हानि पर बेचना' मन्दी युग की एक साधारण घटना है। किन्तु, यदि इस वादयास का प्रयोग तब ही किया जाता है जबकि किसी सम्प्रा के बाधू व्यय इसकी बाधू प्राप्तिसे अधिक बैठें, तो 'हानि पर विक्रय करना' एक अल्पकालीन प्रमेय (short run phenomenon) है जो कि केवल इसलिए घटित होता है कि सम्बन्धित उपक्रमी यह आशा करते हैं कि दशाये शीघ्र ही सुधर जायेंगी।

राशिपतन की दोनो प्रतियोगी परिभाषायें—(i) आन्तरिक कीमत से कम पर विदेशों में विक्रय करना, और (ii) आन्तरिक कीमत तथा उत्पादन लागत (पूर्णत औसत लागत के अर्थ में) में कम पर विदेशों में विक्रय करना, अनेक दशाओं में एक से ही परिणाम प्रस्तुत करती हैं। जब निर्यात कीमत आन्तरिक कीमत से नीचे है, तो यह प्रायः पूर्णत औसत लागत से भी नीची होती है। अतः केवल उन दशाओं में ही दोनो परिभाषाओं के मध्य भिन्नता पाई जायेगी, जिनसे कि निर्यात कीमत आन्तरिक कीमत से तो नीचे है किन्तु औसत लागत से ऊपर। ऐसी दशाओं में, आन्तरिक कीमत, जो कि एकाधिकार के कारण अत्यधिक ऊँची है, औसत लागत से अधिक होती है और यह अधिकता उस राशि की अपेक्षा अधिक होगी, जिससे कि निर्यात-औसत आन्तरिक-कीमत की अपेक्षा अधिक है।

यदि इस व्यावहारिक नदिनाई को, निःसाध ही औसत लागतों का सही-सही निर्धारण किया जा सके, छोड़ दें, तो भी निम्न बातों के सदर्भ में यह तय किया जा सकता है कि कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ है—(i) राशिपतन की जिन दशाओं की दूसरी परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है वे ठीक उन्ही आधिक निर्यातों और परिस्थितियों में उदय होती हैं जिनसे कि अन्य दशाओं का उदय होता है। इस प्रकार, यह दूसरी परिभाषा एक ही वर्ग की आधिक घटनाओं को ही हिस्से में अनावश्यक ही विभाजित कर देती है। (ii) यही नहीं, उसे व्यापारिक नीति के विषय में निर्णय देने के लिए, 'यहाँ एक उचित आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि' आयातक और निर्यातक दोनो ही देशों के लिए इस विषय का कोई सहस्य नहीं होता कि राशिपतन-कीमत (Dumping price) औसत लागत से अधिक है या नहीं। इस प्रकार, हेराल्ड ने सम्मति दी है कि राशिपतन को 'विदेशों में बस्तुओं आन्तरिक कीमत से कम पर बेचने के रूप में' परिभाषित करना अधिक श्रेष्ठ है।

राशिपतन के विभिन्न स्वरूपों का वर्गीकरण—

राशिपतन के विभिन्न स्वरूपों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता

है —(१) आवधिक राशिपतन, (२) अल्पकालीन राशिपतन एवं (३) दीर्घकालीन राशिपतन ।

(१) आवधिक राशिपतन (Sporadic or Occasional Dumping)—इस प्रकार का राशिपतन प्रायः एक बिक्री-मौसम के अन्त में किया जाता है, जिसमें कि स्वदेशी बाजार में सगम्य न बिकने योग्य बचा हुआ भाल जल्दी से बेचकर रकम सही की जा सके । यद्यपि इसमें विदेशी प्रतियोगियों को बहुत कठिनाई हो सकती है तथापि यह कोई विशेष ध्यान देने योग्य घटना नहीं है ।

(२) अल्पकालीन राशिपतन (Intermittent or Short-period Dumping)—इस प्रकार का राशिपतन वह है जिसके अन्तर्गत विदेशों में वस्तु समय-समय पर स्वदेश की कीमत से कम कीमत पर, निर्यात की जाती है । इसमें 'हानि पर बेचा जाना' (selling at a loss) सम्भव है । यह राशिपतन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है —

- (i) विदेशी प्रतियोगियों की अपेक्षा कम कीमत पर बड़े समय के लिए विजय द्वारा विदेशी बाजार में पंर जमाना या इनके छिन्ने से रोकना,
- (ii) विदेशी प्रतियोगियों को नष्ट करना या उन्हीं राशिपतन करने वाले उत्पादन की इच्छानुसार चलने हेतु विवश करना ।
- (iii) प्रतियोगी स्थायी रूप से स्थापित होने से रोकना । राशिपतन के हिसात्मक रूप का प्रयोग जनमत को डराने के लिए किया जाता है जिससे कि वह टैरिफ लगाने के पक्ष में अपनी आवाज उठावे । चूँकि यह उपाय बहुत व्यवपूर्ण है तथा इस बात का भी खतरा है कि विदेशी देश कड़ी रक्षात्मक कदम (defensive measures) (जैसे कि राशिपतन विरोधी कर लगाना) उठाने के लिए विवश न हो जावे इसलिये इस प्रकार का राशिपतन कम ही किया जाता है ।

- (iv) निम्नरीत विद्या में राशिपतन' के विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप राशिपतन अर्थात् रक्षात्मक राशिपतन करना ।

(३) दीर्घकालीन राशिपतन (Long-period or Continuous Dumping)—दीर्घकालीन राशिपतन हानि उठाकर नहीं किया जा सकता, अर्थात् वस्तु को विदेशों में सीमान्त लागत में नीची कीमत पर ही लगाकर बेचने रहना सम्भव नहीं है । विदेशों में वस्तु का लाभ सहित विनय तब ही किया जा सकेगा जब कि —

{ १ } निर्यात की मात्रा इतनी हो कि विश्वमान स्थिर पूँजी पूर्णरूपेण प्रयोग में आ सके, अथवा स्थिर पूँजी में समुचित परिवर्तन करके स्वदेश की कीमत को घटाने योग्य हो, उत्पादन बढ़ाना सम्भव हो सके । स्वदेश की कीमत जो एक विशुद्ध प्रतिस्पर्धिता मूल्य नहीं हो सकती है, सीमान्त लागत के ऊपर ही रहती है । निर्यात कीमत इतनी होनी चाहिए कि कम से कम सीमान्त लागत पुनर्ता हो जाय, अथवा वस्तु हानि पर ही निर्यात की जावेगी । इस प्रकार का राशिपतन प्रायः तब किया जाता है

जबकि उत्पत्ति की घटती हुई लागतों पर बढ़ाया जा सकता हो। इन दोनों में विशाल ट्रस्टों और कार्टलों द्वारा किया जाने वाला राशिपतन सम्मिलित है।

(ii) राज्य या कोई अन्य सरथा निर्यात-सहायता (export bounty) दे रही हो। यदि ऐसा है तो, दीर्घकालीन राशिपतन किया जा सकता है और वस्तुमें विदेशों में हानि सह कर भी बेची जा सकती है।

राशिपतन के लिए आवश्यक दशाएँ—

प्रोफेसर हैबरलर ने राशिपतन की सफलता के लिए दो दाने आवश्यक बताई हैं —

(१) वस्तुमें पुन बापस आने से रोकी जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो स्वदेशी उपभोक्ता उन्हें सस्ते विदेशी बाजार में से खरीद लेंगे। दम्पनों के स्वदेश लौटने को रोकना एक बहुत प्रचलित उपाय उन पर द्यूदी लगाना है। विश्व व्यापार व्यवस्था विदेशी कर्ताओं ने इस आशय के ठहराव भी, कि वे इन्हे स्वदेश के कर्ताओं को पुन विजय नहीं करेंगे रोक लगाने का काम करते हैं। मौसमी या आकस्मिक राशिपतन की दशा में स्वदेश के बाजार में कर्ताओं के मिलन की अनिश्चितता भी पर्याप्त रोक होती है। किन्तु बड़े पैमाने पर दीर्घकालीन राशिपतन की दशा में द्यूदी ही स्वदेशी बाजार की रक्षा के लिए निताम्न आवश्यक होती है।

(२) स्वदेशी बाजार पर एकाधिकार होना चाहिए। यदि प्रतियोगिता स्वतन्त्र है, अर्थात्, यदि कोई एक उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता है, जिससे कि अत्येक उत्पादक के लिए लगभग एक समतल माँग वक्र (horizontal demand curve) है, तो स्वदेश की कीमत को बलपूर्वक नीचे रखना पड़ेगा।

एकाधिकार कई रूप में हो सकता है—(i) सरथा का आकार बाजार को खलते हुए घटता बढ़ा है कि कोई अन्य सरथा उसमें प्रवेश करके लाभ नहीं उठा सकती है, अथवा (ii) सरथा को कोई पेटेंट प्राप्त है या (iii) कई उत्पादक ध्वनित या स्पष्ट ठहराव द्वारा एक कार्टेल के रूप में, उत्पादन की मात्रा को सीमित करने हेतु, संयुक्त हो गए हैं।

राशिपतन का आर्थिक मूल्यांकन—

राशिपतन के आर्थिक महत्त्व को समझने के लिए हमें निम्नलिखित दो समस्याओं में भेद करना चाहिए —

(१) संकुचित समस्या (Narrower Problem)—हम यह कल्पना कर सकते हैं कि राशिपतन के लिए आवश्यक दशाएँ—एकाधिकार एवं मरक्षण—दो हों और अपरिवर्तित हैं। ऐसी दशा में हम राशिपतन के प्रभावों का त्रिवेचन परन्तु भाग्यतः देश के दृष्टिकोण से और फिर निर्यातक देश के दृष्टिकोण से कर सकते हैं।

आयातकर्ता के दृष्टिकोण से—राशिपतन का सबसे अधिक विरोध उन देशों द्वारा किया जाता है जिनमें कि वस्तुयें राशिपतित (dump) की जाती हैं। उदारवादी व्यापार नीति अपनाने वाले देश भी प्रायः शिकायतें करते रहते हैं। कारण, इन देशों में निहित स्वायों की खपने निज की वस्तुओं के लिए मरझण पाने के सुयोग कम है तथा वह ऐसा अनुभव करने हैं कि लघुटीज के अभाव में वे स्वयं विदेशों में एक बृहत् पैमाने पर राशिपतन नहीं कर सकते हैं।

(अ) सामान्यतः राशिपतित आयातों (dumped imports) की आवश्यकता न अधिक आवश्यकता की जाती है। यदि आयात एक ऐसी कीमत पर जो कि निर्यातक देश में आन्तरिक उतमोत्तमों से चार्ज की जाने वाली कीमत में या उत्पादन लागत में भी कम है, प्राप्त बिचे जाते हैं, तो आयातक देश को किसी भी रूप में, बगलें कि सन्म आयात भविष्य में जारी रहे, कोई भी हानि नहीं होगी है। आयातक देश की दृष्टि में इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि वस्तुयें सस्ती इत्यादि मिल रही हैं कि निर्यातक देश को एक प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ मिला हुआ है या वह राशिपतन कर रहा है या राशिपतन एकाधिकार के कारण है अथवा विदेशी सरकार द्वारा दी जाने वाली निर्यात भाषिष उहाय (export bounties) के कारण। इनमें से भी कोई भी परिस्थिति स्वतन्त्र व्यापार के मौलिक तर्क (सामाजिक उत्पत्ति का अधिकतम होने) को नहीं काटती है। उक्त परिस्थितियों का केवल इतना महत्त्व है कि इनमें यह पता चलता है कि सस्ते आयात भविष्य में जारी रह सकेंगे या नहीं। यदि विदेशी निर्यातकर्ता देश को जतयापु या अन्य प्राकृतिक सुविधा मिलने होने के कारण सस्ते आयात सम्भव हुए हैं तो वे अनिश्चित काल तक रह सकते हैं और यदि विदेशी एकाधिकारी की राशिपतन सम्बन्धी नीति के कारण सम्भव हुए हैं तो किसी भी क्षण बन्द हो सकते हैं।

(ब) राशिपतन केवल तब ही हानिकारक है जबकि वह मकोचन (spasms) के रूप में हो और प्रत्येक मकोचन इतनी अवधि तक जारी रहे कि आयातक देश में उत्पत्ति का हेर-फेर हो सकता है। कारण, जब एक मकोचन के बाद दूसरा मकोचन आता है, तो पहले मकोचन के अन्तर्गत जो उत्पत्ति सम्बन्धी हेर-फेर हुआ था उसे उलटना पड़ता है। ऐसा एक एक कर होने वाला राशिपतन (intermittent dumping) तो उस दशा में भी हानिप्रद हो सकता है जबकि देश में कोई प्रतिस्पर्धी उद्योग नहीं है। कारण, इसमें एक ऐसे उद्योग की, जो कि सस्ती आयातित वस्तुओं का प्रयोग करता है, स्थापना हो जाती है किन्तु जब सन्म आयात बन्द हो जायेंगे तो यह उद्योग भी कायम न रह सकेगा।

(ग) जबकि राशिपतन से सम्बन्धित वस्तुयें उद्योगी वस्तुयें हैं तब भी राशिपतन भाँग के हेर-फेर का कारण बन सकता है और इस हेर-फेर को भी बाद में पुनः पकटना पड़ता है, जिनमें हानि हो सकती है।

(द) 'कटा काट राशिपतन' (cut throat competition) भी, जिसे प्रति-

योगियों की बाजार से निकालने के लिए और इनके निकालने के बाद ऊँची एकाधिकारी कीमत चार्ज करने के लिए अपनाया जाता है, हानिप्रद है। किन्तु व्यवहार में इस प्रकार का राशिपतन कम ही किया जाता है क्योंकि कीमत-युद्ध बहुत महंगा पड़ता है तथा इस बात का भी खतरा रहता है कि कानून का हस्तक्षेप एकाधिकारी को अपने महँगी विजय के मुपरिणाम भोगने से वंचित कर सकता है।

निर्मातकों के दृष्टिकोण से—ऊपर हमने आयातक देश के दृष्टिकोण में राशिपतन पर विचार किया था, अब निर्यातक देश के दृष्टिकोण में विचार करेंगे।

(अ) यदि स्वदेशी बाजार पर एकाधिकार एक अपरिवर्तनीय स्थिति है, तो राशिपतन उस दशा में ही लाभदायक कहा जायेगा जबकि यह स्वदेशी उपभोक्ताओं का वस्तुओं की कीमत पर विलास है। किन्तु ऐसा तब ही सम्भव है जबकि सीमान्त लागतें घटती जा रही हों।

(ब) जब राशिपतन के फलस्वरूप स्वदेशी कीमत में वृद्धि हो जाती है तो कोई राय प्रकट करना कठिन है। कारण, कीमत बढ़ना स्वयं में ही निम्न का पर्याप्त आधार नहीं है। वास्तव में, प्रत्येक प्रकार के निर्यात के फलस्वरूप निर्मातक वस्तु की स्वदेशी कीमत बढ़ती ही है। अब सही निर्णय करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बड़ी हुई कीमतों में उपभोक्ताओं की हानि को, बड़ी हुई कीमतों से होने वाले उत्पादकों के लाभ के साथ मिलाएँ। वाइनर (Viner) ने यह मत प्रकट किया है कि उपभोक्ताओं की जितनी हानि होती है उत्पादकों को लाभ उससे कहीं कम होता है। अतः राशिपतन पर स्वदेशी कीमत में वृद्धि होने की दशा में, हानिकारक ही समझना चाहिए।

(स) उत्पादक वस्तुओं के राशिपतन (dumping of producers' goods) पर तथा अधिक ध्यान गया है। स्वतन्त्र व्यापार के सगर्बक सब ही ऐसे राशिपतन का उदाहरण देकर यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि आयातक देशों के लिए राशिपतन कितना हितकारी है। और, नि मन्वेह यह बात ठीक है भी। किन्तु हमें देखना तो यह चाहिए कि निर्यातक देश की दृष्टि में ऐसा राशिपतन किन सीमा तक लाभदायक है। जब निर्यातक देश के पूँजीपति सामान बनाने वाले उद्योग आयातक देशों में सस्ती कीमत पर उत्पादक वस्तुओं बेचते हैं, तो वहाँ इनकी सहायता से अनेक उद्योग विकसित हो जाते हैं जो निर्यातक देश के वंश ही उद्योगों से प्रतियोगिता करने लगते हैं। इस दृष्टि में राशिपतन निर्यातक देश के लिये हानिप्रद ही कहलायेगा। इस हानि से बचने के लिए प्रायः दो उपाय किये जाते हैं—(१) स्वदेश में एकाधिकारी कीमत उन मामलों पर जिन्हें निर्माण-क्रिया द्वारा तैयार भाल में बदल कर निर्यात किया जाना है, घटा दी जाती है, तथा (२) मगान्य निमित्त आयातों की प्रतियोगिता में टकरार करने हेतु स्वदेश (जो कि राशिपतन करने वाला देश है) के निर्माताओं के पक्ष में एन समानीकरण शुल्क (equalising duty) लगा दी जाती है, जिससे उनका स्वदेशी बाजार छिपने नहीं पाता है।

(२) व्यापक समस्या (Broader Problem)—हम यह कल्पना कर सकते हैं कि एकाधिकार एवं सरलण सम्बन्धी दशायें बदली जा सकती हैं। ऐसी दशा में हमें यह देखना होगा कि इनके अन्तर्गत परिस्थिति स्वतन्त्र प्रतिमोहिता वाली परिस्थिति की अपेक्षा अधिक वाछनीय है या कम और यदि हम इसे कम वाछनीय समझें तो फिर यह प्रश्न उत्पन्न सकते हैं कि राशिपतन की सम्भव बनाने वाली दशायें किम प्रकार से समाप्त की जा सकती हैं।

अब हम राशिपतन पर विस्तृत समस्या के रूप में विचार करेंगे। इस दृष्टि में राशिपतन असहिष्णु रूप से हानिकारक है, क्योंकि उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में एकाधिकारिक वृद्धि का आशय यह है कि उत्पादन को अधिक अनुकूलतम् के स्तर से वंचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राशिपतन एक और तीव्रदेशी निर्माणी उद्योगों के लिये मर्यादीकरण इष्टोत्तम माना आवश्यक बनाता है, और, दूसरी ओर, अन्य देशों की प्रतिकारात्मक कदम उठाने के लिये उकसाता है।

निष्कर्ष के रूप में, हम मेयर (Mayer) का यह कथन बूझ सकते हैं कि राशिपतन (अर्थात् सस्ती विदेशी वस्तु) इतना हानिप्रद नहीं है जितना कि स्वदेश के बाजार पर एकाधिकार कायम होना है। जब स्वदेश के बाजार में एकाधिकार पहले से ही विद्यमान है, तो फिर राशिपतन के आगमन का महत्त्व अपेक्षित कम ही है और वह लाभप्रद हो सकता है और हानिकारक भी।

विनिमय राशिपतन—

विदेश में वस्तुओं के राशिपतन का एक अप्रत्यक्ष तरीका विनिमय राशिपतन (exchange dumping) है। इसे 'छुपा हुआ राशिपतन' (disguised dumping) भी कह सकते हैं जो 'खुले राशिपतन' (open dumping) का ठीक विपरीत है। इसका सम्बन्ध वस्तुओं के सामान्य राशिपतन से नहीं है, बरन् विदेशों में एक देश द्वारा अपनी करौसी का राशिपतन करने से होता है। इसके फलस्वरूप स्वदेश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में बहुत सस्ती हो जाती है, जिससे राशिपतन करने वाले देश के आयात सीमित हो जाते हैं किन्तु निर्यात बढ़ने लगते हैं।

इस प्रकार का राशिपतन सर्वप्रथम जर्मनी, आस्ट्रिया, और अन्य मध्य यूरोपीय राज्यों द्वारा, अपने भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी घाटों का उपचार करने हेतु, बिना गया था। बाद में, अन्य देशों ने भी यह टीकनीक अपनाई। अनेक दशाओं में विनिमय राशिपतन के निरुद्ध प्रविक्षात्मक कार्यवाहियाँ की गईं। सब तो यह है कि एक बार प्रारम्भ कर दिये जाने पर विनिमय राशिपतन एवं इसके प्रतिकार का चक्र चली रहता नहीं है। यह दो महामुद्रों के बीच की सम्पूर्ण अवधि में जारी रहा और प्रत्येक देश 'beggar my neighbour policy' का अनुसरण करने में पगल के समान व्यस्त कर रहा था। किन्तु द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने पर विनिमय

राशिपतन की जिम्मा को 'ब्रेक' लगा, क्योंकि प्रत्येक देश अपने सुरक्षा साधनों को मजबूत और गतिशील बनाने में लग गया।

सन् १९४४ में युद्ध समाप्त हुआ और तत्पश्चात् देशों के दो वर्ग नामने आए—एक ओर जर्मनी, इटली और नازی कैम्प के अन्य हारे हुए राष्ट्र, तथा, दूसरी ओर अमेरिका तथा अन्य मित्र राष्ट्र। इनके मध्य खाई इतनी गहरी थी कि इन पाटना एक असम्भव-सा कार्य प्रतीत हुआ। यह जर था कि भयानक मन्दी युग की समाज विरोधी एवं सकुचित आर्थिक नीतियां वही पुन न अपनाई जायें। अतः राजनैतिक शान्ति और आर्थिक समृद्धि की विधा में बढ़ने के एक प्रथम कदम के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार को पुनः सगठित करने का विचार किया गया। दसवां अर्थ यह था कि समस्त प्रतिबन्धात्मक नीतियों को (जिनमें कि विनिमय राशिपतन भी सम्मिलित था) समाप्त कराया जाय। परिणामतः विश्व-भर के विप्लवार्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने स्वतन्त्र ध्यापार को पुनर्जीवित करने तथा इस आशय के लिए कोई ठोस योजना बनाने हेतु अपील की। अन्तिमत् सन् १९४५ में ब्रिटनवल्स में ४४ देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसने एफ. एम. टी. (I. M. F.) की योजना बनाई।

विनिमय राशिपतन पर नियन्त्रण हेतु कोष द्वारा किये गये उपाय—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विनिमय राशिपतन को रोकने के लिए उचित एवं विस्तृत नियम बनाये हैं। इनके अनुसार (१) सदस्य राष्ट्रों को अपनी करेंसियों का स्वर्ण के साथ सम-मूल्य (par value) घोषित करना पड़ता है। किन्तु वह समता सदा के लिए कठोरतापूर्वक निर्धारित नहीं है, वरन् इसमें परिवर्तन भी किये जा सकते हैं जैसे—(अ) सभी देशों की समता दरों में एक ही साथ परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु इसके लिये कुल कोष में पूंजी-न्यूनक १०% से अधिक भाग रखने वाले सदस्य देशों की सहमति होना जरूरी है। (ब) कोई भी सदस्य देश अपनी करेंसी के स्वर्ण मूल्य में १०% कमी कर सकता है। इसके लिए उसे केवल इतना ही आवश्यक है कि वह कोष को अपने इरादों की सूचना दे दे। (स) दसवां ऊपर १०% के परिवर्तन के लिए सम्बद्ध देश को कोष की पूर्ण अनुमति लेनी होगी। (द) यदि इससे भी अधिक परिवर्तन करना आवश्यक समझा जाय तो यह बोप की सहमति से ही सम्भव है और ऐसी सहमति कोष केवल भुगतान सन्तुलन में उत्पन्न हुई किसी भीतिक असाम्यता के उपचार हेतु ही दे सकता है।

इस प्रकार कोष ने विनिमय दरों में व्यवस्थित ढङ्ग से समायोजन (orderly adjustments) करने की योजना बनाई है। अब कोई भी सदस्य देश गैर-जिम्मेदार ढङ्ग में तथा प्रतियोगिता मूलक विनिमय ह्रास में भाग नहीं ले सकता है। इस प्रकार, भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों पर जङ्गल का कानून (The Law of Jungle) नहीं चल सकेगा। अब कभी कोई देश यह अनुभव करे कि इसकी विनिमय

दर उसकी अव्यवस्था के साम्य के अनुसार नहीं है, तो वह इसमें परिवर्तन कर सकता है, किन्तु इससे पूर्व कोप और देश के मध्य विचार विमर्श आवश्यक है। इस प्रकार, पहले तो विनिमय दर स्वयं ही सावधानी से निर्धारित की जाती है और बाद में यदि आवश्यकता पड़े तो उसे संशोधित भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत एक ओर आन्तरिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार तथा दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्तता एवं विश्व व्यापार के ऊँचे स्तर की समुचित महत्त्व दिया गया है। अब प्रत्येक देश विश्व बाजारों में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिये अपनी उत्पादक कुशलता पर निर्भर रहने लगा है। विविध ह्रास के कृत्रिम प्राप्ति-हान पर नहीं।¹

अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार

‘ग्रन्पास टैरिफ के ही शिशु हैं’—

किसी भी यथेष्ट मात्रा में राक्षिपतन के लिये संरक्षण मिलना एक आवश्यक शर्त है। किन्तु इसके अतिरिक्त एकाधिकारिक सङ्गठनों का, जो कि राक्षिपतन करते हैं, अस्तित्व भी मुख्यतः संरक्षण करों के ही कारण है। एक अमेरिकन चीनी उत्पादक ने १९०० के औद्योगिक आयोग के समक्ष गवाही देते समय कहा था कि टैरिफ ही ट्रस्टों के जनक हैं। सम्भवतः यह कहना तो अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि प्रत्येक कार्टेल और प्रत्येक ट्रस्ट टैरिफ का ही शिशु (the child of a tariff) है, किन्तु यह असंदिग्ध है कि अधिकांश कार्टेलों का संरक्षणात्मक टैरिफ के कारण ही अस्तित्व बना हुआ है। एक विशाल आर्थिक क्षेत्र के अनगिनती उत्पादकों की अपेक्षा करों की आवश्यकता द्वारा सुरक्षित एक छोटे क्षेत्र के बोझ से ही उत्पादकों के लिये सङ्गठित होकर कार्य करना सुगम है। यदि सब ही टैरिफ कल हटा लिये जायें तो अनेक उपक्रमियों की एकाधिकारिक स्थिति, जो उन्हें अपने उत्पादन तथा देश में प्राप्त है, जाती रहे, अधिकांश विद्यमान कार्टेल्स तोप हो जायें या उनकी शक्ति खत्म हो जायगी। कारण, टैरिफ के अभाव में प्रत्येक उत्पादक को केवल यातायात व्ययों का प्राकृतिक संरक्षण मात्र ही प्राप्त होता है, जैसे ही उसकी कीमत इस स्तर से जिस पर कि

1 'Thus exchange depreciation which may be necessary for a country whose money is over-valued can be accomplished without inviting retaliation. In this way, the Fund not only provides temporary assistance over a period when the country cannot acquire an adequate supply of foreign exchange it also sponsors measures to remedy more fundamental difficulties. And, by holding member countries to their agreement not to engage in competitive exchange depreciation, it introduces a measure of disarmament into the field of international economic relations'—Tarshus : *The Elements of Economics*, p 619.

विदेशी उत्पादक अपने देश में सांभदायकता के साथ बेच सकते हैं, बढ़ती है, वैसे ही वह ऐसा करना प्रारम्भ कर देगा।¹ अनुभव द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है। यूरोपीय महाद्वीप की अस्था इङ्ग्लैंड में कार्टेल् कम विकसित हुए जिसका कारण कुछ तो अंग्रेज व्यवसायियों की व्यक्तिवादी मनोवृत्ति है और कुछ वहाँ सरक्षण करो का अभाव होता है। जर्मनी में भी हम देखते हैं कि १८७६ में सरक्षण अपना लेने के बाद वहाँ कार्टेल् तेजी से स्थापित हो गये।

यह एक सामान्य नियम (general rule) है कि एकाधिकारों का अस्तित्व टारिफ के ही कारण है। किन्तु इसके दो अपवाद हैं—(१) स्थानीय एकाधिकार (local monopolies) जिन्हें यातायात व्ययों का सरक्षण प्राप्त होता है और (२) अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार (international monopolies), जिन्हें विश्व भर में किसी वस्तु की पूर्ति के पूरे नियन्त्रण में लेकर दो या अधिक कस्टम क्षेत्रों में जो कि टारिफ द्वारा या यातायात व्यय द्वारा अथवा दोनों ही के द्वारा बाहरी प्रतिस्पर्धिता से सुरक्षित है पूर्ति के अधिनाश या कम से कम इतने भाग का नियन्त्रण प्राप्त होता है कि वे बाजार कीमत पर अपना प्रभाव डाल सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्ग—

यहाँ हमें अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्गों में भेद करना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की अपनी विशेष समस्याएँ हैं। ये वर्ग निम्नलिखित हैं—

(१) एक या कई देशों के किसी समूह को विश्व बाजार में एकाधिकारिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। यह समूह संयम विश्व से अच्छी कीमतें वसूल करने में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

(२) समस्त देशों के या अधिकांश देशों के उत्पादक अपने राष्ट्रीय कार्टेल् (यदि कोई हो) के द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय संघ या कार्टेल् बना लेते हैं। और समुक्त रूप से उत्पादन को प्रतिबन्धित (restrict) तथा मूल्यों को नियन्त्रित (control) करते हैं।

कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार—

प्रथम वर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार प्रायः सदा ही कच्चे मालों के निर्यात

¹ 'If all tariffs were removed tomorrow, very many entrepreneurs would lose the monopolistic position which each today possesses in his own line and country, while most of the existing cartels would vanish or would cease to exercise any power. For, without a tariff each producer has only the natural protection of transport costs as soon as his price exceeds the level at which foreign producers can profitably sell in his country they will commence to do so'—Haberler *The Theory of International Trade* p 325

पर आधारित होते हैं। किसी एक देश में ही एक महत्वपूर्ण कच्चे माल की पूर्ति के अधिकांश या सब स्रोत केन्द्रित हो सकते हैं, किन्तु इन पर निर्माण सम्बन्धी क्रियाएँ अनेक विभिन्न देशों में सम्पन्न की जा सकती हैं चाहे ऐसा करने की लागत कुछ दशों में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक बँटे।

किन्तु यह तथ्य मान ही कि एक दिए हुए कच्चे माल की पूर्ति के लिये एक देश विशेष की सीमाओं के भीतर सम्पूर्णतः या अधिकांशतः विद्यमान हैं, शेष विश्व का, अथवा, अन्य देशों में यहाँ तक कि स्वदेश में भी उपभोक्ताओं का, एकाधिकारिक शोषण सम्भव बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ-साथ आवश्यक एक बात यह भी है कि उत्पादन एवं पूर्ति का नियन्त्रण करने के आग्रह के लिए उत्पादकों को संगठित भी किया जाय। लगभग सब ही कच्चे माल, जिनके सम्बन्ध में पहली शर्त पूरी होती है, कृषि या खनिज पैदावार है, जिन्हें कुछ बृहत् सस्थानों द्वारा नहीं वरन् अनगिनती छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार, एक संगठित एकाधिकार के सृजन (creation) और पूर्ति के प्रतिबन्धन (restriction) के लिये लगभग सदा ही सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है।¹ जिन २० वस्तुओं को अभी तक एकाधिकारिक नियन्त्रण में लाने का प्रयास किया गया है उनमें केवल एक बौ की दशा में राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हुई थी किन्तु अन्य सब दशाओं में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार का हस्तक्षेप निम्नलिखित उद्देश्यों से हो सकता है—

- (१) अपनी आय बढ़ाने के लिये, चाहे यह स्वदेशी उत्पादकों के व्यय पर हो या विदेशी उपभोक्ताओं के व्यय पर।
- (२) कीमत को स्वाभिव्यक्त प्रदान करने तथा, यदि सम्भव हो तो, उत्पादकों को एक ऊँची कीमत दिलाने के लिए।
- (३) देश में सम्बद्ध कच्चे मालों का प्रयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना और इनकी रक्षा हेतु संरक्षण देने के लिए।
- (४) विदेशी उपभोक्ताओं पर स्वदेशी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिये।
- (५) तेज स्तर से खत्म होने वाले कच्चे मालों को सुरक्षित रखने के लिये।

एकाधिकृत वस्तु की निर्यात कीमत बढ़ाने के लिए सरकार निम्नलिखित

¹ 'Nearly all the raw materials which fulfil the first condition are agricultural or mineral products produced not by a few large undertakings but by numerous small ones. Thus, the intervention of the state is nearly always necessary in order to create an organised monopoly to restrict supply'—*Ibid*, p. 326

निसी भी ढंग का प्रयास कर सकती है — (i) सरकारी एकाधिकार (state monopoly) कायम करना, (ii) प्राइवेट एकाधिकारी संगठन (private monopoly) का निर्माण करना, जिसमें सम्मिलित होने के लिए सरकार उत्पादकों को विवश करे, (iii) उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाना, (iv) एक न्यूनतम कीमत निर्धारित करना (v) निर्यात कर लगाना या कोटे निर्धारित करना, एवं (vi) सरकार द्वारा वस्तु का त्रय विक्रय (state trading), जिससे कि इसकी बाजार कीमत बढ़ जाय ।

सामान्य रूप में, कच्चे मालों के एकाधिकार सम्बन्धी प्रयत्न अधिक सफल नहीं हुए हैं । इन्होंने उत्पादकों का केवल जब तक ही खोर बंध भी अस्थाई रूप से लाभ पहुँचाया है । अधिकांश दशाओं में (विशेषतः दीयकाल में) उन्हें इनके कारण खुदसाज ही अधिक हुआ । ये सब प्रयास विश्व-अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अपेक्षित कम महत्त्व के हैं तथा थोड़े ही दिनों चले हैं । कारण, या तो कुल पूर्ति की स्थायी रूप में प्रतिबंधित करना, योजना से बाहर के देशों में उत्पादन के विकास के कारण, असम्भव प्रमाणित हुआ अथवा टैक्निकल प्रगति के फलस्वरूप स्थानापन्न बिकसित हो गये, जो फिर एकाधिकृत वस्तु में प्रतियोगिता करने लगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स (International Cartels)

उद्योग की एक दो हुई शाखा में अधिक से अधिक देशों के उत्पादकों के एक रेदे संगठन को जो कि उत्पादन और कीमत पर अकेले ही नियोजित रूप से नियन्त्रण रख सके तथा विभिन्न उत्पादक देशों में बाजार का विभाजन कर सके, 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स' कहते हैं । प्रथम महायुद्ध के बाद इनकी स्थापना के प्रति लोगों में बड़ी रुचि पैदा हुई थी तथा ये अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में चर्चा का विषय रहे । इनसे यह भय है कि ये उपभोक्ताओं का एकाधिकारिक घोषण करेंगे । उनसे यह आशा कम ही है कि वे टैरिफ दीवारों को समाप्त करने में सहायक होंगे । सब तो यह है कि १९१६ और १९२८ की मध्यावधि में इनसे जो कटु अनुभव हुए हैं उनके कारण 'कार्टेल्स' शब्द लोगों के लिए एक 'बुराई का प्रतीक' (Symbol of evil) बन गया है ।

कार्टेल्स शब्द की प्रमुख परिभाषायें—

नीचे कार्टेल्स की कुछ प्रमुख परिभाषायें प्रस्तुत की जाती हैं —

(१) विलियम एस० फेरिश (William S. Ferish)—'प्रतियोगिता का नियन्त्रण, उत्पादन एवं निश्चित कीमतेँ इन सबका समूह ही कार्टेल्स कहलाता है ।'¹

¹ "Cartel is a combination of competitor's control, production and fixed prices"

(२) सी० डी० एडवार्ड्स (C. D. Edwards)—“एक कार्टेल व्यावसायिक उपक्रमों का समूह है जो आपस में कुछ प्रकार की प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसके सदस्य अपने निजी लाभ के लिये पृथक्-पृथक् व्यापार करते रहते हैं किन्तु कुछ विषयों में (जैसे कि कीमत-निर्धारण के विषय में) वह सामूहिक निर्णय लेते हैं।”¹

(३) न्यूयार्क ट्रस्ट कम्पनी (The New York Trust Company)—“सभी परिभाषाओं में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कार्टेल-कार्पोरेशन एक ही प्रकार के उद्योग में सलग्न विभिन्न व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा नियत वह व्यवस्थाएँ हैं जो कि प्रतिस्पर्धिता को पूर्णतः या अंशतः समाप्त करने हेतु बनाई गई हैं।”²

(४) मैसन (Mason)—“शब्द से संकुचन एक उचित अर्थ में कार्टेल से आशय व्यापार की एक ही शाखा में सलग्न विभिन्न फर्मों के मध्य उन व्यवस्थाओं का है, जोकि उत्पादन और विपणन के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करे। कार्टेल ठहरावों का विशेष उद्देश्य सदस्य-फर्मों द्वारा उत्पत्ति या विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाना, बाजारों का विभाजन करना तथा वस्तुओं की कीमत नियत करना है।”³

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से एक ‘कार्टेल’ के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का पता चलता है —(i) कार्टेल एक सामूहिक विपणन की व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को इसकी नीतियाँ निर्धारित करने में उचित भाग मिलता है। इसे प्रकार यह एक जनतन्त्रीय व्यवस्था है। (ii) यह वैधानिक रूप से पृथक्-पृथक् सदस्यों

1 “A cartel is a group of business enterprises formed for the purpose of avoiding some kinds of competition among themselves. Its members continue to do business separately for their own profit but they act together in deciding such matters as the prices they are to charge, the amounts they are to produce or sell and share of the market which is regarded as the exclusive right of each of them.”

2 “At the core of all definitions is the fact that cartel activities are arrangements among business enterprises engaged in the same type of industry to avoid or regulate some or all forms competition.”

3 “Cartels, in the narrow and proper sense of the term, are agreements between firms of the same branch of trade limiting the freedom of these firms in the production and marketing of their products. Cartel agreements aim typically at the restriction of output or sales by the member firms, at an allocation of territories and a fixing of the prices of products.”

का संगठन है। अन्य शब्दों में एक ही कम्पनी के कई विभाग आपस में कार्टेल जैसा ही ठहराये नहीं कर सकते हैं। (iii) चूँकि कार्टेल प्राइवेट उपक्रमियों के मध्य की जाने वाली व्यवस्था है, इसलिए इसे प्राइवेट क्षेत्र को विशेषता माना जा सकता है। (iv) कार्टेल सम्बन्ध स्वभाव में ऐच्छिक होते हैं। इसे कानूनी दबाव द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता। (v) एक कार्टेल का क्षेत्र एक ही उद्योग होता है अथवा परस्पर मिलते-जुलते कई उद्योग भी हो सकते हैं। (vi) कार्टेलों के निर्माण का केन्द्रीय उद्देश्य उत्पादकों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाया है। (vii) भाग लेने वाली फर्मों के मध्य कोई औपचारिक या निहित ठहराव होना आवश्यक नहीं है, बरन् वह आपसी व्यवहार से ध्वनित (implied) भी हो सकता है। (viii) कार्टेल-सम्बन्ध सदस्यों के लिए लाभदायक होते हैं, अन्यथा वह इनमें क्यों प्रवेश करने लगे ? (ix) यद्यपि कार्टेल सम्बन्धी ठहराव नवकरण (renewal) द्वारा एक दोष अवधि तक जारी रखा जा सकता है तथापि व्यवहार में वह 'अस्थायी' ही प्रमाणित हुआ है, क्योंकि सदस्यगण ठहराव का नवकरण करने में सकीन करते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल वैधानिक रूप से स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रमियों का, जो कि एक से अधिक देश में एक ही या मिलते-जुलते उद्योगों में सलग हैं, एक ऐच्छिक, अस्थायी और औपचारिक सन्ध है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को सीमित करना है ताकि सदस्य-इकाइयों को साधारण की अपेक्षा अधिक लाभ हो।

कार्टेल-संचालन के उद्देश्य एवं ढंग—

सभी कार्टेलों का उद्देश्य लाभों को अधिकृत करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति निम्नलिखित चार ढंगों में की जा सकती है —

(१) प्रत्यक्ष कीमत निर्धारण ठहराव—कार्टेल के सदस्य उस स्तर से ऊँची ही कीमत नियत करने का यत्न करते हैं जोकि प्रतियोगिता की परिस्थिति में प्रचलित होती है। इस सन्ध की पूर्ति का एक तरीका यह है कि वे आपस में कीमत-निर्धारण का ठहराव करें। किन्तु इसके पूर्व कार्टेल-सदस्य कीमत-युद्ध के द्वारा अ-सदस्यों (non-members) को ठराने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ही यह बात पूरी हुई कि कीमतें फिर एक ऊँचे स्तर पर निर्धारित कर दी जाती हैं और सदस्यों से यह आप्रह्न किया जाता है कि वे इनका कठोरतापूर्वक अनुसरण करें।

(२) क्लिफ का हास—प्रायः कार्टेल यह अधिक पसन्द करते हैं कि किसी में कमी कर दी जाय और इस प्रकार लाभ बनाये रखा जाय। असन्तुष्ट श्रेणियों के सामने अन्यत्र खरीदने का विवल्प नहीं होता, जिससे वे घटिया वस्तु पहली श्रितनी कीमत पर या इससे अधिक कीमत पर खरीदने के लिए विवश रहते हैं।

(३) प्रतिवन्धित पूर्ति—कुछ कार्टेल पूर्ति पर इसलिए विवन्धन करते हैं जिससे कि इनके कारण सम्भव हुई ऊँची कीमतें उन्हें अधिक लाभ अर्जित करा सकें।

(४) व्यापार क्षेत्र का विभाजन—उपरोक्त तीनों कार्टेल-उपाय (cartel measures) तब तब सफल नहीं होंगे जब तक कि सदस्यों में व्यापार-क्षेत्रों का विभाजन पहले में ही निश्चित नहीं कर लिया जाता । प्रायः सदस्य यह वायदा करते हैं कि वे एक-दूसरे के क्षेत्र में अपनी उत्पत्ति नहीं बेचेंगे । इस उपाय के द्वारा कार्टेल एक मार्ब-भौमिक शक्ति प्राप्त कर लेता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते—

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स में निष्कट रूप में सम्बन्धित 'अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते', भी जाने हैं जो कि प्रायः निर्वाण के लिए उत्पन्न की जाने वाली छुपि वस्तुओं के सम्बन्ध में सम्पन्न किए जाने हैं । चूंकि कृषि पर जनवायु की विपरीतताओं का गहरा प्रभाव पड़ता है इसलिए कृषि वस्तुओं के उत्पादन में समय-समय पर घटा-बढ़ी के चक्र उत्पन्न होने रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों (International Commodity Agreements) का उद्देश्य इन प्रवृत्तियों पर घटा सम्बन्ध अनुसंधान करना है । इनमें प्रायः बहुतों देश सदस्य बनते हैं जो कि छुपि वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक या प्रमुख उपभोक्ता होते हैं ।

कार्टेल और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—

वनेश अर्थशास्त्रियों का, जो कि कार्टेलों का विरोध करते हैं, यह तर्क है कि चूंकि कार्टेल्स एक एकाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं इसलिये वे एकाधिकार के सम्बन्धी अपराधों (जैसे ऊँची कीमत, कम उत्पादन, पटिया क्लिप्, एवं असाधारण लाभ) को जन्म देते हैं । यही नहीं, वे स्वतन्त्र व्यापार को भी सीमित करते हैं तथा अधीन क्षेत्रों में वहाँ के उत्पादकों का घाव करते हैं । वे नये गेटेवुडों की दवा देते हैं तथा प्रतियोगिता की प्रक्रिया में बाधा डाल कर अकुशलता को बढ़ावा देते हैं । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों पर कोई ऐसा निष्पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण नहीं रखा जाता है जिससे कि उपभोक्ताओं के व्यापक हितों की रक्षा हो सके । इस प्रकार, उक्त अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि दशा को सब हानि सहकर भी कार्टेलों में बचना चाहिए ।

किन्तु ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो इसमें भिन्न मत रखते हैं । उदाहरण के लिये, प्रो० शुम्पीटर (Scumpeter) ने कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स, जहाँ व्यक्तिगत दशा में तथा व्यक्तिगत इष्टिबोध से इतने अधिक प्रतिबन्धान्मक प्रतीत होते हैं, वास्तव में प्रगति के मार्ग पर चलने वाले इन्जिन हैं तथा दीर्घकाल में कुल उत्पत्ति का विस्तार करते हैं । - मदी के दिनों में कार्टेल्स जैसे प्रतिबन्ध बहुत ही प्रभावशाली उपहार का कार्य करते हैं । अन्त में वे उत्पादन को न केवल नियमित बनाते हैं, बल्कि कुल उत्पादन में वृद्धि भी करते हैं ।"

प्रो० शुम्पीटर के उक्त समर्थन पर भी यह स्वीकार करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का विश्व का जनमत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हितों के विरुद्ध समझता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जो कार्टेल दो महायुद्धों के बीच की स्वयंसेवा में

स्थापित हो गये थे। उन्होंने स्वतन्त्र विश्व व्यापार के घुलित विकास में बाधा डाली, धकड़ान और ऊँची लागत वाले उत्पादकों की रक्षा की (जबकि इस रक्षा का भार कुशल उत्पादकों तथा उपभोक्तों को उठाना पड़ा), औसत दीर्घकालीन उत्पादन लागत को ऊँच स्तर पर बनाये रखा, संभाव्य उपभोग (potential consumption) को वास्तविक उपभोग (actual consumption) में परिणत होने से रोका गया तथा मनुष्य विश्व व्यापार के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की उपेक्षा की गई। अतः एक विकासमूलक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों की सरकार इन कार्टेलों के कार्यकलापों पर कड़ा निगरानी रखें।

टैरिफ हटवाने में कार्टेल्स का योगदान—

फ्रांसिसी लेखकों का यह मत था कि उद्योग की अधिक से अधिक शक्तियों में एक प्रभावशाली कार्टेल की स्थापना करनी चाहिये, जिससे उत्पत्ति पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण प्राप्त हो अर्थात् जो स्वतन्त्र प्रतियोगिता को खत्म कर सके। ऐसी कार्टेलों की स्थापना टैरिफ में सामान्य कमी लाने की दृष्टि में अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने समूहवाद की दृष्टि में सबसे कम प्रगति की है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह कार्टेलों की स्थापना का सबसे कट्टर समर्थक रहा। इसके विपरीत, जर्मनी ने, जो कि कार्टेल्स का मातृ-देश है तथा जिसने सभी अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों में महत्वपूर्ण भाग लिया है, उक्त फ्रांसिसी विचारधारा¹ का समर्थन नहीं किया। अथ दरदो में, जर्मनी को यह विश्वास नहीं था कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों की स्थापना टैरिफ हटवाने या कम कराने में सहायक होगी। सच तो यह है कि फ्रांसिसी विचारधारा का, इङ्ग्लैंड, हॉलैंड, स्केन्डिनेवियाई देशों तथा जर्मनी के प्रतिनिधियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कड़ा विरोध किया जाता रहा है और इसके लिए निम्नवेह उचित आधार भी थे।

(१) विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का क्षेत्र, महत्व एवं विश्व व्यापार में इनका हिस्सा—लीफमैन (Liefmann) के अनुसार २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कार्टेलों की संख्या ४० थी। Wagenführ के अनुसार महायुद्ध के बाद की अवधि

¹ 'The only way to solve the European economic problem seemed to be to organise the European industries upon the horizontal method that is, by branches of industry. Only in this way can be begun to make the important adaptation which are necessary and the international cartels will also in part solve the question of reducing tariffs'—Loucheur, the French Industrialist and politician in a speech before the World Economic Conference at Geneva in 1927, quoted by prof. Haberler in his book *The Theory of International Trade*, p 328

मे इनकी सख्या ३२० थी, जिसमे से २३० औद्योगिक कार्टेल थे। विश्व मन्दी ने इनकी सख्या को घटा दिया किन्तु सख्या मे भी अधिक इनके महत्त्व को कम किया। वास्तविकता यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों का महत्त्व इनकी सख्या मे नहीं, परन्तु इनके कार्य एत गुण से ही जाना जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि उद्योग की विभिन्न शाखाओं के कार्टेलीकरण की उप-युक्तता के सम्बन्ध मे आर्थिक नेतृत्वों ने जो विचार प्रकट किये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स को भी लागू होते हैं किन्तु इनमे भाग लेने वाले देशों की सख्या जितनी अधिक होती है उत्पत्ति-शाखाओं के कार्टेलीकरण मे बाधाएँ उसमे भी बड़ी अधिक अनुपात मे प्रस्तुत होती हैं। एक देश के उत्पादकों की अपेक्षा विभिन्न देशों के उत्पादकों को संयोजित करना बड़ी कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त, यह कठिनाई भी है कि राष्ट्रीय कार्टेल्स, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के अपरिहार्य अवघो हैं, विभिन्न देशों में समान रूप से विनियमित नहीं होते और न सब देश ही अन्तर्राष्ट्रीय द्वारा के समान दृष्टि के साथ भाग लेने को तत्पर होते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल बनने की सम्भावना एक बड़ा अवधि, जिसमे इसका अस्तित्व रह सकेगा, इस बात पर निर्भर है कि इनकी शृंखला (chain) मे कौन-सा देश सबसे कमजोर है। उदाहरणार्थ, उद्योग का कार्टेलीकरण अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड में कम विकसित हुआ जिसमे वह अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों में सदस्य नहीं बना और यह तथ्य भी उनकी शक्ति के बहुत सीमित होने का कारण है। साथ ही, कई अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स केवल इस सम्भावना के कारण नहीं बन सके कि इंग्लैंड उनमे सम्मिलित नहीं होगा।

कार्टेल अपने कीमत बढ़ाने के उद्देश्य मे [ध्यान रहे कि यहाँ 'कीमत' शब्द एक विस्तृत अर्थ रखता है और इसके अन्तर्गत मुद्रता की शक्त भी सम्मिलित है] तब ही सफल हो सकता है जबकि वह उत्पादन पर कुछ सीमा तक नियन्त्रण रखे और उत्पादन पर नियन्त्रण रखना तब ही सम्भव है जबकि उत्पाद की मात्रा विभिन्न उत्पादकों मे बहुत व्यापक रूप से बिखरी हुई न हो। अतः इस दृष्टि मे कृषि का कार्टेलीकरण असम्भव है। यही नहीं, वह उद्योग भी, जिनमे अधिराज्य उत्पत्ति छोटी-छोटी या मध्यम कर्मों द्वारा की जाती है कार्टेलीकरण के लिए अनुपयुक्त है। ऐसे उद्योग प्रायः वे हैं जिनमे कि व्यक्तिगत कारीगरी, दृष्टि, डिजायन या पेशन का बहुत महत्त्व होता है। उद्योगों के निम्नलिखित वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कार्टेलीकरण की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त हैं—

- (१) कच्चे मालों पर घनिष्ठ निर्भरता वाले उद्योग, जिनमे कच्चे माल की पूर्तियों पर बड़े नियन्त्रण द्वारा बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका जा सकता है। इस वर्ष मे कच्चे मालों के (ट्रिपल एक्सपोर्ट) एकाधिकार आने हैं। जस्ते का अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल ही ऐसा है जो कि एक ऐसे कच्चे माल से सम्बन्धित है जिस पर कि अधिकांश देशों ने टैरिफ

लगाया हुआ था। अतः इसके अतिरिक्त अन्य सब कार्टेलों का टैरिफ नीति की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। जो बोझ महत्त्व है वह इस लिये है कि वे उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं।

(ii) किन्तु ग्रेडेन्टों का शोषण करने वाले कार्टेल बहुत महत्त्व रखते हैं। ये कार्टेल्स इलेक्ट्रिकल एव कंसीकन उद्योगों में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं जैसे—Lamp Cartel and Ball bearings Cartel आदि।

(iii) सबसे अधिक महत्त्व के कार्टेल उन उद्योगों में पाये जाते हैं, जिनमें पृष्ठ उपकरण के लाभ बहुत महान् हैं और इसलिये जिनमें केन्द्रीय करण की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। अनुकूलतम् वाकार की मन्त्रा स्थापित करने के लिये जितनी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता है उसकी पूँजी लगान में नये प्रवेशक संकोष या असमयता अनुभव करते हैं। लौह एव स्पात उद्योग की गणना ऐसे ही उद्योगों में की जा सकती है। जो लोग अन्तराष्ट्रीय कार्टेलों के माध्यम से टैरिफ हटाने की चर्चा करते हैं वे इसी उद्योग के अन्तराष्ट्रीय कार्टेलों को नष्ट करने के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

अतः स्पष्ट है कि चूँकि अन्तराष्ट्रीय कार्टेलों का विश्व व्यापार में एक अल्प हिस्सा होता है तथा उनका गमाव एकता (cohesion) में नहीं है इसलिये टैरिफ को हटाने या कम कराने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है।¹ यदि हम विभिन्न फर्मों को अन्तराष्ट्रीय कार्टेलों में सम्मिलित होने के लिये विवश करने हेतु सरकार के शक्तिशाली हस्तक्षेप का प्रयोग नहीं करना चाहते² तो यह स्वीकार करना होगा

¹ Those who hope to reduce tariffs through international cartels produce the international cartels of this (iron and steel) industry as their show piece. Nevertheless, cartels cover too small a sector of world trade and have nothing like sufficient cohesion to do much in this direction"—Haberler: *The Theory of International Trade*, p. 310-33

² The experts expressly point out that the establishment of international industrial cartels should not be brought about artificially by measures of compulsion. It is much better to let them arise from the free initiative of the participating groups as a result of the prevailing economic circumstances. Both the foundation and the actions of the cartels should be quite free from the influence of Governments which may use them to promote their own aims in the sphere of trade policy"—*Report of the Economic Experts of the Europe-Commission of the League of Nations*

नि परिभाषात्मक कारणों से विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स टैरिफ दोवारों को गिराने के उपयुक्त साधन नहीं है।

(२) अधिकांश विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स का अस्तित्व टैरिफ के कारण ही है। अतः वे कठिनाई में ही टैरिफों को नष्ट करने के 'साधन' बताये जा सकते हैं। जब तक कि सम्बन्धित उद्योग प्रत्येक भाग लेने वाले देश में समान रूप से बाधित नहीं है तब तक दुर्बल राष्ट्रीय समूह अपने टैरिफ संरक्षण को न तो छोड़ेंगे और न छोड़ ही सकते हैं। यही नहीं तबान्धित अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के सदस्य आरम्भ में कीले जाने ठहरावों द्वारा बचे होते हैं तथा बड़ा और विनय सेनो का विभाजन भी केवल एक अल्प समयावधि के लिए होता है। इस सम्बन्ध में 'लण्डन-मण्डन' सम्बन्धी वार्तालाप निरन्तर चलते रहते हैं और कभी पूर्णता को नहीं पहुँच पाते हैं। इन वार्ताओं में जिनमें प्रत्येक सदस्य देश दूसरों से अपने सहयोग के मूल्य के रूप में अधिक से अधिक लाभदायक शर्तें प्राप्त करना चाहता है, दबाव डालने का सबसे वास्तविक उपाय विद्यमान टैरिफ ही (विशेषतः इन्हें बढ़ाने की सम्भावना) हैं। जब ऐसा है तो अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के दुर्बल सदस्य कभी भी अपने वास्तविक या सम्भाव्य टैरिफ संरक्षण को छोड़ने के लिए इच्छापूर्वक तैयार न होंगे।¹

(३) अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक कार्टेल्स टैरिफ के कम कराने में तब ही सहायक हो सकते हैं जबकि वे स्वयं टैरिफ के स्थानापन्न का काम करें, जिससे कि 'टैरिफ के संरक्षण' का स्थान 'कार्टेल्स का संरक्षण' ले सके। परन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स किस प्रकार वे टैरिफ संरक्षण पर उद्योगों की निर्भरता का दूर कर सकते हैं। यह तरीका स्पष्ट है और इस प्रकार है—उन्हें अपने दुर्बल सदस्यों को यह आश्वासन देना होगा कि वे विद्यमान टैरिफ के अधीन जिस आपेक्षिक स्थिति में थे वही स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी। यह प्रवृत्ति बाजारों को घाटन के अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स के सम्बन्ध में स्पष्टता से दृष्टिगोचर होती है और सब तो यह है कि अधिकांश कार्टेल्स होने भी इसी प्रकार के हैं। यदि कार्टेल्स-ठहराव द्वारा सदस्य देशों के मध्य बाजारों का विभाजन स्वतन्त्र व्यापार वाली दशा के विभाजन के ही समान है तो टैरिफ और ठहराव दोनों ही अनावश्यक (superfluous) हैं तथा टैरिफ के हटाने या न हटाने कोई अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु, यदि विभाजन एक भिन्न प्रकार का है तो इसका पक्ष टैरिफ के ही समान है। अर्थात् वह एक

1 "It cannot be too strongly emphasised that in these struggles, in which each member country tries to get better terms from the others as the price of its adherence the strongest means of exerting pressure is the existing tariffs and in particular, the possibility of raising them"—*Ibid*, p 331

विद्यकरहित परिस्थिति को बनाए रखता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अधिन कठिन बनाता है या रोकता है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल अन्य दिशाओं में भी लाभदायक हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, वे ज्ञान के संचय में अपव्यय को रोकने में (जैसे कि प्रतिपोगी विज्ञापन व्ययों को घटाने में) सहायता कर सकते हैं। वे एक अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मठित की गई अर्थव्यवस्था के अग्रणी कहलाने का ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। वे आर्थिक संकुटा की उथला को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं। किन्तु वे टैरिफ को कम कराने तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभ हानि रहित ढंग में उपलब्ध कराने के एक साधन के रूप में कदापि उपयुक्त नहीं हैं। किन्तु स्मरण रह कि यदि हम समायोजन की कठिनाइयों से घबराते हैं तो फिर हम अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभों का आनन्द उठाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। हितों का मध्यम वास्तव में इतना प्रबल है कि इस बात की प्राप्ति नहीं की जा सकती कि विभिन्न पक्ष स्वेच्छापूर्वक एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल में, टैरिफ सरक्षण के परित्याग हेतु तथा अपने ही भण्डे के नीचे ऐसे सब समायोजन करने के लिए जा कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के लाभ पूर्णरूपेण प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, सम्मिलित हो जायें।

कुछ विद्वानों का विचार है कि यदि सरकारी आर्थिक सहायता आदि के रूप में नियोजित रूप से हस्तक्षेप (planned intervention) करे तो टैरिफ को कम करने पर जो समायोजन आवश्यक होंगे उन्हें करने में सुविधा हो सकती है। किन्तु हैबरलर के मतानुसार इसका सबसे सरल उपाय यह है कि सभी टैरिफों में मामान्य रूप से कटौती कराने की दिशा में कदम उठाए जायें।

परीक्षा प्रश्न

१. राशिपतन क्या है? इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? राशिपतन

1. "If they agree upon the same division despite the tariffs, as that which would prevail under Free Trade, both the tariffs and the agreements are superfluous and the removal of tariffs makes no difference in this respect. But if the division is different from this, then its effect is similar to that of tariffs. It maintains an irrational situation and makes more difficult or prevents an international division of labour"—*Ibid* p 332

विरोधी सन्निधम बनाने में जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उनका उल्लेख कीजिये।

[What is dumping? What are its various forms? Mention the difficulties inherent in the framing of anti-dumping legislation]

२. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राशिपतन के उद्देश्यो एवं दणों को समझाईये और इसका सामना करने हेतु अपनाये गये उपायों का विवेचन कीजिये। वे उपाय कहाँ तक सफल हुए हैं?

[Explain the objects and methods of dumping in the international trade and state the measures, which have been adopted to combat it. To what extent have these measures been successful?]

(विनम०, एम० ए०, १९६६)

३. राशिपतन के स्वभाव एवं इसके विभिन्न श्रेणों का विवेचन कीजिये और दोनों आयातकर्ता एवं निर्यातकर्ता देशों की दृष्टि से राशिपतन का प्रभाव स्पष्ट करिये।

[Discuss the nature and forms of dumping and explain the effect of dumping both on exporting and importing countries]

४. "विनिमय राशिपतन" को समझाईये। इसके नियन्त्रण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था है और यह कैसे कार्य करती है?

[Explain "exchange dumping" What is the international machinery for its control and how does it function?]

५. "टैरिफ ट्रस्टों के जनक हैं"। इस कथन का विवेचन करिये। कच्चे मालों के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार किस सीमा तक सफल हो सकते हैं?

['The tariff is the Mother of Trusts;'] Discuss. How far can the International Monopolies of Raw Materials be a success?]

६. अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेलों के उद्देश्यो एवं ढङ्गों का विवेचन कीजिये। किस सीमा तक वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह में बाधा डालने हैं?

[Describe the aims and methods of international cartels. To what extent, if at all, do they hamper the free flow of international trade?]

१ व्यापारिक संधियाँ

(Commercial Treaties)

परिचय—‘व्यापारिक सन्धियों’ से आशय

प्रायः व्यापारिक सन्धियाँ अनेक विषयों पर विस्तृत होती हैं, जैसे—वाणिज्य दूतों के अधिकार एवं उनकी योग्यतायें, विदेशी फर्मों की स्थापना और विदेशी व्यापारिक एजेंटों का पद, विदेशियों और उनकी सम्पत्तियों के लिये कानूनी एवं पुलिस संरक्षण, कानूनी निर्णयों का कार्यान्वयन, पेटेन्ट्स, ट्रेडमार्क्स, वापौराइट आदि की रक्षा, कस्टम सम्बन्धी औपचारिकतायें, आयात कर एवं अन्य कर, स्वदेश के बन्दरगाहों में विदेशी जहाजों का आगमन तथा उनके अधिकार, रेलों की माडा दर सम्बन्धी नीति, आदि। इन सब विषयों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है —(i) वाणिज्य दूत सम्बन्धी विषय, (ii) विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी विषय, (iii) याता-यात सम्बन्धी विषय, एवं (iv) प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी विषय। आर्थिक विकास के साथ ही साथ देशों के पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों में भी जटिलता बढ़ती जा रही है और अब अनेक उक्त विषयों को विशेष ठहरावों के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाने लगा है। वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, ‘व्यापारिक सन्धियाँ’ वाक्यांश केवल प्रशुल्क सम्बन्धी प्रश्नों पर हुये देशों के पारस्परिक ठहरावों के लिये प्रयोग किया जाता है।¹

¹ "Commercial treaties may cover a very wide range of subjects we may group all these subjects under the four heads of (a) consular matters, (b) rights of foreigners, (c) transport questions; and (d) tariff and trade questions. In the course of development, the economic relations between states have become more and more complex, and it has, therefore, become usual to regulate certain matters by special agreements. A tendency has also come about to reserve the expression 'Commercial treaties' for agreement on tariff questions".

—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 36.

व्यापारिक संधियों के रूप (Forms of Commercial Treaties)

व्यापारिक संधियों के दो रूप मुख्य हैं—द्विपक्षी संधियाँ (दो देशों के मध्य) एवं बहुपक्षी संधियाँ (दो से अधिक देशों के मध्य)। बहुपक्षी संधियाँ (multilateral treaties) को 'सामूहिक ठहराव' या 'अन्तर्राष्ट्रीय समझौते' (International Conventions) भी कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का एक मफन और स्पष्ट उदाहरण १९०२ का ब्रुसेल्स-चीनी-समझौता (Brussels Sugar Convention) है। आधुनिक काल में ग्रेट समझौता भी इसी श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि संधियों की एक सम्पूर्णा शृङ्खला जिनमें में प्रत्येक औपचारिक रूप में द्विपक्षी है, सामूहिक विचार विनिमय एवं निणयों का भी परिणाम हो सकती है। यदि ऐसा है, तो उनकी विषय-सामग्री भी लगभग समान होगी।

व्यापारिक संधियाँ लागू करने के ढङ्ग

व्यापारिक संधियों के अन्तर्गत जिस प्रकार के विदेश सम्बन्ध को बनाये रखने की बात है उसकी पूर्ति देशों द्वारा दो प्रकार के तरीकों से की जा सकती है—

अ एव अग्रगण्य। 'अग्रगण्य विधि' इस प्रकार है—कोई देश इस बात पर राजी हो

न है कि एक विदेशी देश के वाणिज्य दूत के अमुक-अमुक अधिकार और कर्तव्य होंगे जयदा एक विदेशी कम का स्थापित होने के लिए अमुक-अमुक कर्तव्य पूरी करती पड़ेगी अथवा, विदेशी देश न आने वाले अमुक-अमुक माल पर अमुक-अमुक राशि का आयान-कर लगाया जायेगा। 'अग्रगण्य विधि' के अन्तर्गत एक ऐसा मापक (measure or yardstick) निर्धारित कर दिया जाता है जिसके अनुसार दूसरे देश के साथ किसे जान वाले व्यवहार को नियमित रखा जा सके। ऐसे तीन उपाय सम्भव हैं और इनमें से प्रत्येक के लिये एक उपयुक्त संधि-वाक्य होता है जैसे—'समता वाक्य' (The Parity Clause), 'आदान प्रदान वाक्य' (The Reciprocity Clause), एवं परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (The Most Favoured Nation Clause)। (१) समता वाक्य' के अन्तर्गत एक देश दूसरे देश के नागरिकों और वस्तुओं के साथ वैसा ही व्यवहार (इसमें खराब नहीं) करता है जैसा कि वह अपने ही नागरिकों के साथ करे। (२) 'आदान प्रदान वाक्य' के अधीन, एक देश दूसरे देश के राष्ट्रजनों और वस्तुओं के साथ वैसा ही (कम से कम इसमें खराब नहीं) व्यवहार करता है जैसा कि दूसरे देश द्वारा पहले देश के राष्ट्रजनों के प्रति किया जाय। (३) 'परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' के अधीन एक देश का दूसरे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार जयदा खराब नहीं होना चाहिए जोकि वह किसी अन्य देश के नागरिकों के साथ कर रहा है।

संकुचित अर्थ में व्यापारिक संधियों के भेद

[विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियाँ एवं टैरिफ संधियाँ]

व्यापारिक संधियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं—(I) 'विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियाँ' (Pure M F N Treaties) एवं (II) 'टैरिफ संधियाँ' (Tariff Treaties)। विशुद्ध परमानुग्रहित राष्ट्र संधियों के अन्तर्गत एक देश अपने आपको इस बंधन में जकड़ता है कि वह दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर उमसे ऊँची हूट्टियाँ नहीं लगायेगा, जोकि वह किसी तीसरी देश से आने वाली वस्तुओं पर लगा रहा है। इस प्रकार, आयात-करों की राशि देश के प्रभुसत्तामय (autonomous) नियम पर निर्भर होती है। इसके विपरीत, टैरिफ संधियों के अन्तर्गत विशेष टैरिफों में सम्बन्धित पूर्ण विवरण (प्रत्येक कर की राशि सहित) स्पष्ट कर दिया जाता है। [किन्तु स्मरण रहे कि टैरिफ संधियों में भी प्रायः एक परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सम्मिलित हो सकता है।]

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार

(Most Favoured Nation's Treatment)

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का अर्थ—

अधिकांश व्यापारिक संधियों में एक महत्वपूर्ण वाक्य अवश्य रहता है जोकि 'परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Most Favoured Nation Clause) के नाम से विख्यात हो गया है। इसका उद्देश्य किसी राष्ट्र को एक परमानुग्रहित स्थिति प्रदान करना नहीं है, परन्तु अनुबन्ध के प्रत्येक पक्ष को विन्हीं अन्य पक्षों के समान अनुग्रह-पूर्ण व्यवहार करने का आश्वासन देना है। जब अनुबन्ध करने वाले पक्षों की संख्या विस्तार होती है तो M F N Clause एक 'समान रूप से अनुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Equally Favoured Nation Clause) का रूप धारण कर लेता है। यदि यह वाक्य X और Y दो देशों के मध्य हुई किसी संधि में सम्मिलित है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि X देश Y देश के राष्ट्रजनों और उनकी वस्तुओं के साथ एक ऐसा व्यवहार करने का वचन देता है जो कि विन्हीं अन्य देशों के राष्ट्रजनों और वस्तुओं के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से खराब नहीं होगा। ऐसा ही वचन Y देश भी X देश को देता है। इस प्रकार, परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सब प्रकार के व्यापारिक भेद-भाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार को खत्म कराने का प्रयत्न करता है और इसनिचे, अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को अधिक उदार ढङ्गा में संचालित कराता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का वर्गीकरण—

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। किन्तु इन्हें तीन विभिन्न ढङ्गों से वर्गीकृत किया जा सकता है—(I) अर्तयुक्त एवं अर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य; (II) एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य, एवं (III) सीमित एवं असीमित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य।

(I) शर्तयुक्त एवं शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य (Conditional M F N Clause) के आधीन अनुबन्ध का कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति वह अनुग्रहित या रियायती व्यवहार करने का वचन देता है जो कि उसने किसी तीसरे पक्ष के साथ पहले ही कर दिया हो, किन्तु इसके साथ ही वह शर्त भी होती है कि दूसरा पक्ष भी पहले पक्ष को वह रियायत दे जोकि उसने अपनी ज़ोर से, बिना तीसरे पक्ष को दे रखी हो। इसके विपरीत, 'शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य' (Unconditional M F N Clause) के अन्तर्गत यदि अनुबन्ध के एक पक्ष ने किसी तीसरे पक्ष को कोई सुविधा दे रखी हो, तो वह अनुबन्ध के दूसरे पक्ष को तत्काल ही, स्वयं और बिना शर्तपूर्ति के, प्राप्त हो जाती है।¹ उदाहरणार्थ, यदि X और Y के बीच हुई संधि में एक शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य सम्मिलित है, तो इयूरोप में कोई भी घटोती जो कि, X द्वारा Z के पक्ष में की गई हो, Y को भी तत्काल ही लागू होने लगती है, चाहे Y वे सुविधायें X को न दे जो कि Z ने X को दी हैं। इस प्रकार के ठहराव परिचयी देशों में बहुत लोक प्रिय रहे हैं।

शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के दोष—शर्त रहित M F N Clause को आलोचना विन्म आधारों पर की गई है—(१) यह नई संधियों की संभावनाओं को संभाव्य अथवा कम करता है। अन्य बातों में, नई संधियाँ या तो की नहीं जाती हैं अथवा कुछ सीमित रियायतों का ही विनिमय किया जाता है। (२) इसके अतिरिक्त संधि के नियमों या प्रावधानों (provisions) की रचना देना चतुराई से की जा सकती है, कि M F N Clause लागू न हो सके। (३) यही नहीं, देश अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने से हिष्कृच्छाते हैं, क्योंकि भाग न लेने वाले देश भी, कोई रियायत बढ़ाने में दिये बिना ही, अपन अधिकार के रूप में रियायतें पाने का दावा प्रस्तुत कर देते हैं। शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के आलोचकों का कहना है कि 'शर्त युक्त' परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य टैरिफ की समानता का तो नहीं किन्तु 'सबसे अधिक समानता' (equality of opportunity) का वचन अवश्य देता है।

शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के दोष—शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के समर्थकों का यह कहना है कि शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य तो परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के उद्देश्य पर ही पानी फेरने वाला है। कारण—प्रथमतः,

1 "Under the Most Favoured Nation Clause, therefore, every reduction in duties which one State grants to another is immediately extended to all those States which stand in a Most Favoured Nation position towards the first one. The M F N Clause thereby establishes a nexus between all the commercial treaties of a country"—Haberler : *The Theory of International Trade*, p 364.

ममान रियायत' (equal concession) क्या है इसकी परिभाषा करना कठिन है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि X और Y के मध्य एक परमानुग्रहित राष्ट्र ठहराव है। X एक अन्य देश Z से आने वाले गेहूँ पर आपात कर घटा देता है जबकि Z कपड़े पर, जिसे वह X से मंगाता है, आपात कर में कमी कर देता है। अब Y भी X को गेहूँ भेज रहा है किन्तु वह X से खिलौने (न कि कपड़ा) मंगाता है। ऐसी परिस्थिति में, खिलौनों पर छूटी में कितनी कमी करने को कपड़े पर छूटी में की गई कमी के बराबर समझा जाय ? इस विषय में निर्णय पक्षों की स्वतन्त्र इच्छा से ग हाकर राजनैतिक एवं आर्थिक उक्ति द्वारा होता है। अब शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य को न्याय-दृष्टि से, एक जबैध सधि या अन्य पक्षों के साथ वार्ता में प्रवेश के लिए बल का प्रयोग समझना चाहिए। व्यवहार में शर्त रहित परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का अर्थ परमानुग्रहित राष्ट्र जैसा व्यवहार करने से इन्कार करने के ही बराबर है।¹ दूसरे, शर्तयुक्त परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य भेदात्मक व्यवहार की सम्भावना को बिल्कुल ही खत्म नहीं करता है। तीसरे, यह उन देशों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है जिन्होंने बोडी ही छूटी लगा रखी है या इली-गिनी छूटियाँ लगा रखी हैं। चूँकि वे अल्प रियायत ही दे सकते हैं, इसलिए परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य से वे अधिक लाभान्वित नहीं हो सकते।² चौथे परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य व्यापार को सुगम नहीं बनाता, अर्थात्, आर्थिक संधियों को खत्म नहीं करता है।

(II) एक पक्षीय एवं बहु पक्षीय परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—सामान्यतः परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य का सचालन द्विपक्षीय होता है। अन्य पक्षों से, यह अनुबन्ध करने वाले दोनों ही पक्षों को लागू होता है। कभी-कभी, जैसे कि युद्धकाल में, द्वी इतरपक्ष सचालित किया जाता है। उदाहरणार्थ, बार्सा सन्धि एक पक्षीय या एक-तरफा ((unilateral) थी, क्योंकि इसके द्वारा जर्मनी ने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी

¹ "Hence the conditional most Favoured Nation Clause is to be regarded, from a justicic stand point, only as a 'pactum de contrahendo', as an obligation to enter into negotiations with the other contracting party. In practice the conditional Most Favoured Nation Clause means a little more than a refusal to grant Most Favoured Nation treatment at all"—Habercer : *The Theory of Inte national Trade*, p. 365

² "The Free Trade countries especially must have found it unfair to be treated worse, because they had nothing to offer as a reciprocal concession by the United States than the Protectionist countries which continued to place great obstacles in the way of American exports even after they had some relatively small reductions in their duties upon American goods

—*Ibid.*, p. 366.

नी थी कि वह मित्र राष्ट्रों के साथ ५ वर्ष की अवधि तक परमानुग्रहित राष्ट्र जैसा व्यवहार करता रहेगा किन्तु इसके बदले में मित्र राष्ट्रों ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी।

(III) प्रतिबन्धित एवं स्वतन्त्र परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य—परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य उस दशा में 'प्रतिबन्धित' (restrictive) कहलाता है जबकि यह कुछ विषयों को कुछ वस्तुओं अथवा देशों को ही लागू होता है। किन्तु जब यह सब विषयों को, सब वस्तुओं अथवा सब देशों को लागू होता है, तब वह अप्रतिबन्धित या स्वतन्त्र (unrestricted) कहलाता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार तब ही प्रभावपूर्ण हो सकता है जबकि यह अप्रतिबन्धित और सतत रहित हो। एक सतत रहित और प्रतिबन्धहीन परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार में स्वतन्त्र व्यवहार को पुनर्जीवित करने और टैरिफ व्यवस्थाओं को सुगम बनाने में बड़ी सहायता मिलती है।

परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के अपवाद—

किन्तु परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के कुछ अपवाद भी रहे जा सकते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के अपवाद ऐसे किसी भी ठहराव में ध्वनित माने जाते हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं —

(१) नितागत स्थानीय स्वभाष का सीमान्त व्यवहार—यह अपवाद सीमान्त जिलों के मध्य होने वाले व्यापार में, जो कि प्रायः अल्प-मात्रा में हुआ करता है, सम्बन्धित है। इन जिलों के निवासी अल्प-मात्राओं में वस्तुओं खपूटी सिये बिना या घटी हुई दर में खपूटी देकर सीमान्त के आर-पार से जा सकते हैं। किन्तु कोई भी देश, परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार के आधार पर, इस रियायत को देने का दावा नहीं कर सकता।

(२) कस्टम यूनियन का निर्माण—जब दो देश, जिन्होंने ऊँचे प्रमुख जगह रखे हैं, एक कस्टम यूनियन बना लें, तो कोई भी उससे यह आशा नहीं कर सकता कि वे एक ही बार में एक दूसरे की वस्तुओं में अपनी खपूटियाँ हटा लेंगे। वे उन्हें धीरे धीरे ही हटावेंगे। इस मध्यान्तर में, जो कि पर्याप्त दीर्घ हो सकता है, कानूनी स्थिति की दो व्याख्याएँ सम्भव हैं — (i) दोनों देशों के मध्य घटी हुई खपूटियों को एक अपूर्ण कस्टम यूनियन का प्रतीक माना जा सकता है, जोकि निकट भविष्य में पूर्ण कस्टम यूनियन बन जायेगी, अथवा (ii) घटी हुई खपूटियों को 'रियायती खपूटियाँ' (preferential duties) समझा जा सकता है। पहिली व्याख्या के अन्तर्गत सीमान्त देश, परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के आधार पर ऐसा ही व्यवहार करने का दावा नहीं कर सकता, किन्तु द्वितीय व्याख्या के अन्तर्गत कर सकता है।

परमानुग्रहित राष्ट्र वाक्य के कई क्षेत्रीय अपवाद भी दीर्घकाल में घटे जा रहे हैं तथा स्वीकार किये जाते हैं। कई देशों ने उन देशों को, जो कि उनके साथ विशिष्ट भौगोलिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक सम्बन्ध रखते हैं, विशेष

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को मुपुर्दगी देने के लिये है, तथा (ii) वस्तुवत्न आयात, जो विदेशी सप्लायरों के भारतीय एजेंटों द्वारा, 'स्टाक और विक्रय आधार पर', बाद में निदिष्ट अधिकारियों के आदेशानुसार वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को बेचे जाने के लिये है। प्रथम वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में निगम केवल नाममात्र का ही कमीशन लेता है किन्तु दूसरे वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय एजेंट को अपने उपरिव्यय (overhead expenses) पूरे करने तथा अल्प लाभ कमाने का अवसर दिया जाता है और निगम अपने लिए नाममात्र का सेवा व्यय लेता है। कुछ वर्ष पूर्व ट्रांक एंड विजय आधार पर आयात बन्द कर दिए गए थे लेकिन अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में, इसकी उपयोगिता का अनुभव करके, इन्हें पुनः आंशिक या पूर्ण ढर से आरम्भ कर दिया गया है।

(१०) सहायक समूह—निगम के दो सहायक सङ्गठन हस्तक्रीशल और हाथकरघा निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Exports Corporation) हैं जो क्रमशः हाथ करघा और वस्त्रकारी की वस्तुयें तथा भारतीय फ़िल्मों का निर्यात करने हैं। निगम ने CAPEXIL द्वारा सञ्चालित 'आस्ट्रेलिया की रक्षाओं का निर्यात बढ़ाने की योजना' में भी भाग लिया है।

(११) विदेशों में कार्यालय—विभिन्न देशों में बढ़ते हुये व्यापारिक वातावरण ने निरन्तर संपर्क बनाये रखने तथा विदेशी देशों में भारतीय निर्यातों को प्रोत्साहन देने के प्रयास में निगम की सहायता के लिये निगम ने विदेशों में शाखा कार्यालय खोलने की नीति अपनाई है। उसने रीडिंग, प्रास, मास्को, बुडापेस्ट, पूर्वी बर्लिन, मीडियल और नैरोबी में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और बेंगलूर, चेन्नै, काहिरा, सागोन, तेहरान और नाबुल में शीघ्र ही खोलने का रहा है। निगम का कार्य सञ्चालन मितव्ययितापूर्वक तथा जनहित की दृष्टि से किया जाता है। सालफीताछाही पचासाध्य दूर रखी जाती है। इसके उपरिव्यय उचित सीमाओं के भीतर रहते हैं।

(१२) निगम की आय में वृद्धि—१९६८-६९ के लिये निगम को १२.०९ करोड़ ४० का कर-पूर्व लाभ हुआ था। १९६८-७० में पहली तीन तिमाहियों के लिये उसे १९.०९ करोड़ ४० का कर-पूर्व लाभ है। इस प्रकार निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है किन्तु उसके व्यय पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी बढ़ गये हैं, जो स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि उसके व्यापारिक कार्यक्षेत्रों में भी वृद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का मूल्यांकन—

राजकीय व्यापार निगम के कार्यक्षेत्रों के उपरोक्त सक्षिप्त विवेचन से यह विस्तृत स्पष्ट है कि वह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने एवं विविध मुन्नी बनाने में सफल रहा है। इसने आवश्यक वच्चे माख प्राप्त करने और फिर उद्योगपतियों में इसका समुचित वितरण करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। निर्यात करने वालों को

आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को सुदृढ़ किया है। राजकीय व्यापार वाले देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के साथ-साथ उसने जापान और अमेरिका जैसे देशों से वहाँ की व्यापारिक सस्थाओं में भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए आयात व्यवस्था को सुधारन की योजनायें भी बनाई हैं और इनके लिए धन की व्यवस्था निगम द्वारा स्थापित एक विशेष कोष से की जाती है। अगर देशों से हमारा व्यापार जहाँ प्रतिकूल था, वहाँ अब अनुकूल हो गया है।

देश की विदेशी मुद्रा की आप में निगम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वस्तु पूँजी १९१६-१७ में १० मि० से बढ़कर अब १० मि० हो गई है। ईश्वर के रूप में भी इसने बड़ी राजिया सरकारी खजाना का दो है। निगम न उत्पादन क क्षेत्र में भी कदम बढ़ा दिया है। उसने मद्रास में एक बिन फैंट्री खोली है। उसने प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर कुछ वस्तुओं के उतारन षटाने के लिये मित यथितापूर्ण किन्तु कुशल व्यवस्था की है। उसने बम्बई में एक विशाल टैंक बनाया है जिससे आयातित वस्तुएँ तैलों की सप्लाई करके रक्षा जा सकेगी।

उक्त सफलताओं के साथ ही साथ निगम की निम्न दुर्बलतायें भी सामने आई हैं — (१) निगम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर, व्यापारिक मूल्यों पर और बाह्य निम्न का मान आयात करने में असफल रहा है। (२) उसने कई वस्तुओं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बिक्रय मूल्यों से कम दरों पर करके विदेशी मुद्रा अर्जन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की है। (३) उसने निजी निर्यातकों के कोटों में मद्रा कटौती की प्रणाली प्रपना कर देश के निर्यात व्यापार की उपेक्षा की है। (४) निगम ने अनावश्यक वस्तुओं का कम करके अपनी पूँजी जटकाई है और देश की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार समय पर आवश्यक वस्तुओं का सभरण नहीं किया है। (५) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लाभतें बढ़ गईं। जैसे—सोयाबीन का तेल खरीदने समय ५० आनर प्रति टन अधिक चुकाया गया है। (६) निगम की ओर से सुपरिगो देने में विलम्ब हुये हैं। इससे आईर रह ही गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हे कार्यान्वित करने में सुस्ती करता है। (८) वस्तुओं के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियमन का अभाव है। (९) इसका स्टाफ बार बार बढ़ता रहता है। (१०) इस बारे में बहुत ही अनिश्चितता प्रतीत होती है कि निगम किन वस्तुओं का आयात निर्यात करेगा। यथवा यह भविष्य में किन दिशाओं में अपना कार्य बढ़ावेगा।

निगम के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वस्तुओं के आयात के लिए ऊँची कीमतें ले रहा है और इस प्रकार ऊँचे लाभ कमा रहा है। किन्तु निगम द्वारा प्रकाशित सत्रे अंतिम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वह वस्तुओं के थोक न्य के फलस्वरूप नीची कीमतें प्राप्त होने का सम्पूर्ण लाभ कर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है और कुछ वस्तुओं के लिए कीमतें इस प्रकार निर्धारित की

जानी है कि मध्यजन् मुनाफाखोरी न कर सकें। किन्तु यह बात विश्वास उत्पन्न करने वाली नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि निगम को ऐसे उपाय करने चाहिये जिनसे कि उपाभोक्ता वास्तव में लाभ उठावे। यह भी कहा गया है कि निगम अपने अनुबन्धों को गुप्त रखता है किन्तु यह स्वाभाविक ही है। व्यापारिक शक्तों के प्रकाशन में शक्ति का भय है। निगम के कार्यरूपापो की उचित आलोचना सदा वाञ्छनीय है किन्तु व्यापार की गोपनीयता के बोधिव को भी स्वीकार करना होगा। कुछ देशों का कहना है कि पूर्वी यूरोप की नियमित व्यवस्थाओं बाग्य देश अब अब देशों के ब्राइवेट व्यापारियों में अनुबन्ध करने को इच्छा प्रदर्शित करने लगे हैं, जिस कारण निगम की उपादेयता कम हो गई है। किन्तु जैसा कि हम पहले भी मकेत कर चुके हैं, निगम की उपादेयता यह है कि वह विशाल मगडन होने के माने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने की स्थिति में है जबकि व्यक्तिगत व्यापारी विदेशी उपक्रमियों की तुलना में ऐसी लाभप्रद स्थिति नहीं रखते।

निगम का भविष्य—

राजकीय व्यापार एक निबबध्यापी घटना है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विक्रमोन्मुख देशों की व्यापारिक व्यवस्था में ब्राइवेट नियति-गृह दुर्बल स्थिति में होते हैं जिस कारण वे अनुकूल व्यापार प्रति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही नहीं, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग और उद्ये द्विषा लेने की भी सम्भावना में रहती है। विश्व बाजार में विपणन को जाने वाली ऐसी अनेक वस्तुओं (जैसे—सम्फर मकरी इन्डियन मून आदि) है जिनके आधिक्य और अभाव एक चक्र के रूप में उदय होते रहते हैं। एक कठिन जमाव की अवधि में कीमत अस्तर प्रायः बहुत अधिक हावे है तथा भारत में आयातकर्ताओं को यह सोभ हो सकता है कि वे एक न एक बहाने की भीड़ में कीमतों में जाह-तोह करें। ऐसी स्थिति में, जबकि एक ओर हमारे निर्यात-गृहों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति विश्व बाजार में दुर्बल हो और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की कीरी का भय हो, एक सरकार-संचालित मस्या ही विदेशी व्यापार को बढाने में सहाय्य हो सकती है। विशाल मगडन के कारण वह प्रतिस्पर्धा द्वारा अनुकूल व्यापार शक्त प्राप्त कर सकती है तथा विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई कर सकती है।

यह भी सम्भव है कि अपने मुक्तान सम्झौतों (freedom agreements) के जपान पूर्वी यूरोप के देशों को जूते, ऊनी कपटो आदि के जो निर्यात करिये गये उनका सुफल यह हुआ कि देश में प्रगतिशील और कुशल उद्योग स्थापित हो गये हैं और अब इनके बाजार पर पश्चिमी यूरोप के बाजारों में भी प्रवेश का यत्न कर सकते हैं। यह भी उक्त सम्भव है कि नास्तान्तर में निगम अपने निर्यात-वायं-यम की पूर्ति के स्थि, देशों उत्पादकों व सहायक के रूप में, निगम कार्य आरम्भ

करे। मद्रास में विंग फॅक्टरी का खुलना इस दिशा में पहला कदम है। वह जूते बनाने का यन्त्रीकृत कारखाना भी खोल सकता है, जिससे आर्डर के अनुसार उत्तम क्रांति के जूते बनाय जा सकें।

परीक्षा प्रश्न :

१. यह उद्योगों को संरक्षण देने के साधन के रूप में राजकीय व्यापार के गुण-दोषों की परीक्षा कीजिये।

[Examine the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]

२. विदेशी व्यापार में सरकारों के भाग लेने से जो समस्याएँ एक पूँजीवादी देश में उत्पन्न हो सकती हैं उसका विवेचन कीजिये।

[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade.]

३. राजकीय व्यापार निगम क्या है? इसके गुण-दोषों का विवेचन कीजिये।

[What is a State Trading Corporation? Discuss its advantages and disadvantages.] (जागरा, एम० ए०, १९६८)

४. राजकीय व्यापार निगम का कार्यचालन समझाइये। इसके क्या गुण-दोष हैं एवं इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है?

[Explain the working of State Trading Corporation. What are its main weaknesses and how can they be overcome?]

(गोरख, एम० ए०, १९६६)

५. भारत के राजकीय व्यापार निगम के कार्यचालन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का एक सफल ढंग है?

[Critically examine the working of S T C of India. Is State Trading a successful method of protecting domestic industries?]

(जागरा, एम० कॉम०, १९६८)

भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

परिचय—

व्यापार नीति का सम्बन्ध मुख्यतः विदेशी व्यापार से है तथा वह 'सामान्य आर्थिक नीति' का एक हिस्सा होती है। जब-जब सामान्य आर्थिक नीति में परिवर्तन होते हैं, देश की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो जाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत का व्यापारिक नीति और इसके अन्तर्गत हुए विभिन्न व्यापार समझौते का अध्ययन करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति वतन्त्र व्यापार की नीति—

सन् १८२३ तक भारत की व्यापारिक नीति 'निर्बाध व्यापार नीति' (Laissez-faire) पर आधारित थी। निर्बाध व्यापार नीति के अन्तर्गत सरकारों हस्तक्षेप का प्रभाव होता है। भारत के विदेशी शासकों के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति उनके देश के हितों को बढ़ाने वाली थी। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि एक व्यापारिक सरथा 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' की स्थापना के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन के चरण भारत में जमे थे और गत दो शताब्दियों का इतिहास उस वणिज प्रवृत्ति की पराकाष्ठा का ज्वलन्त उदाहरण है जिसने हमें गुलाम बनाया (और स्व० रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में) "गंगा के जल को टेम्स नदी में उड़ेलने" का कुकर्म किया। ब्रिटेन की शोषण नीति के फलस्वरूप एक ओर जब ब्रिटेन स्वयं दिन दूना रात चीगुना बढ़ता गया, तब भारत दिन प्रतिदिन दरिद्रता-ग्रस्त एवं अभावयुक्त देश बनता गया। भारत जैसे विशाल उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन को न केवल ब्रिटिश वस्तुओं (कपड़ा लोहा आदि) का सरोदार बल्कि ब्रिटेन के चमड़ा, सूती वस्त्र आदि उद्योगों के लिये मनचिन्ते भावों पर कच्चा माल बेचने वाला भी देश उपलब्ध हुआ।

शोषण की इसी अवधि में भारतीय अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए राज-नीतिक दायता से मुक्त होने के लिए क्रियात्मक रूप से कटिबद्ध हुए। ब्रिटेन के लिए

भारत की स्वतन्त्रता का जयं त्रितेन के पतन के गूनापत के रूप में था। गिडाल विचारक पट्टाभि सीतारामैया ने उन दिनों कटाक्ष रूप में कहा था कि 'यदि भारत स्वतन्त्र होता है तो इंग्लैंड वाले अपनी खुदाई का मोखला पावडर करके लायेंगे और लोहा पिघला कर पियेंगे।'

कुछ भी हो, विदेशी सरकार ने अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए स्वयं में स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया ही, साथ ही भारत को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हमारा देश विदेशों निर्मात वस्तुओं से पट गया। यहां के उद्योग क्षेत्रों ने नष्ट प्रायः जो गये तथा वह सु-व्यवस्था में निर्मात करने वाला देश बन गया।

विश्वेदारमक संरक्षण—

इस अस्तुतिविक्रम की हानियां प्रथम महायुद्ध में सभी पर प्रगट हो गईं। अतः परिस्थितियों से विवश होकर सरकार ने १९२३ में विश्वेदारमक संरक्षण की नीति अपनाई, जिसमें स्वभावतः स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अन्त हो गया। विश्वेदारमक संरक्षण की नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को संरक्षण मिला और इन्होंने इसके फलस्वरूप बहुत प्रगति भी की। किन्तु व्यवहार में विश्वेदारमक संरक्षण की नीति इस कठोरता से कार्यान्वित की गई कि अनेक योग्य एवं महत्वपूर्ण उद्योग, इससे वंचित हो रहे।

साम्राज्यीय अधिमान (ओटावा सम्झौता)—

१९३०-१९३२ के महान् मंदी युग में समस्त विश्व के विभिन्न भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं। भारत के विदेशी व्यापार का कुल मूल्य एवं परिमाण भी बहुत घट गया, क्योंकि कृषि वस्तुओं के लिये, जो कि हमारी निर्यात मूर्तियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, विश्व-मंदी तथा इनकी नीमके बांणों द्वारा बहुत कम हो गई थी। पुनर्जीवन (recovery) के एर उपाय के रूप में ब्रिटेन ने एर विशेष प्रकार की व्यापार नीति अपनाई तथा इसके अन्तर्गत साम्राज्यीय अधिमान योजना के द्वारा अपने साम्राज्य के देशों में व्यापार बढ़ाने का गतन किया। इस योजना की रूप रेखा ओटावा (कनाडा) के दाहिने आर्थिक सम्मेलन (Imperial Economic Conference) में तैयार की गई।

अन्य साम्राज्य—देशों सहित भारत ने इस सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो ओटावा पैक्ट (Ottawa Pact) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत भारत ने कुछ प्रकार की ओटोमोबाइल्स पर ७३% तथा जैर्निफ़्टिक सामान, ऊनी सामान, मुर्गा-चनें, फ़िस्ट आदि पर ५०% अधिमान दिया। ये वस्तुएँ वह ब्रिटेन में आयात करता था। दूसरी ओर, ब्रिटेन ने भारत को कई वस्तुओं पर १०% अधिमान स्वीकृत किया तथा कई वस्तुओं को श्रुटी बिंदु बिना ही अपने बाजारों में जाने की अनुमति दी।

ओटावा सम्झौते की रचना इस तरीके से की गई थी कि वह भारत की

अपेक्षा ब्रिटेन के लिए अधिक लाभदायक रहा है। भारत से ब्रिटिश निर्यात वस्तुओं पर ऐसे अधिमान (preferences) दिलाये गये, जो कि ब्रिटिश निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन फूँक सकें। वहाँ निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन की सहूलियत देने से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार की वृद्धि हुई तथा ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के अन्य उद्योगों में भी गति आई। इस प्रकार, ब्रिटेन मन्दी के गहरे गड्ढे में से निकलने में समर्थ हुआ। किन्तु, दूसरी ओर, जो अधिमान भारतीय वस्तुओं पर स्वीकृत किये गये वे भारतीय निर्यातों में कोई विशेष वृद्धि न कर सकें क्योंकि टर्नि वस्तुओं की कीमतें एक जम्मे समद्विगुण के बाढ़ ही मुझार नहीं। यही नहीं, अधिमान सूची में सम्मिलित सभी वस्तुएँ भारत के लिए लाभदायक नहीं। इस प्रकार, ओटावा समझौते की आग न ब्रिटेन, भारत बर्मा और तथा जैसे आधीन देशों के साथ अपनी शोषक और स्वार्थपूर्ण नीति का जारी रख गया। ओटावा समझौते में अफिरकास साथ ब्रिटेन को ही प्राप्त हुआ, जबकि भारत या अधिकतम घोर तक शोषण किया गया। [भारत में चाय बागानों के ब्रिटिश मालिकों और जूट मिलों के ब्रिटिश उद्योगियों को जहाँ लाभ हुआ, क्योंकि ओटावा पैक्ट के अन्तर्गत चाय और निर्यात जूट यह दो चीजें ही एसी थी जिनका निर्यात बहुत बढ़ गया।]

ओटावा पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के समय तथा इसके बाद भी भारतीय जन-मत और विद्वानों ने बहुत आलोचना की थी। अब यह पैक्ट भारतीय विधान सभा द्वारा १९३६ में मंजूर होकर पारित किया गया, किन्तु कांग्रेस ने अपने विशेष अधिकार के द्वारा इसे १९३६ तक जारी रखा।

इण्डो-ब्रिटिश ट्रेड एग्रीमेन्ट—

सन् १९३६ में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक नये व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर हुए, जार्कि 'भारत-ब्रिटेन व्यापारिक करार' (Indo-British Trade Agreement) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ठहराव या ओटावा पैक्ट के बुनियादी शर्तों को दूर न कर सका। इस नये ठहराव के अधीन भारत ने ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले २० परशत पर १०% अधिमान स्वीकृत किया और ब्रिटेन ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर अधिमान दिया और अन्य वस्तुओं को हट्टी-दी आगे भी अनुमति दी।

यह नया समझौता भी अन्तर्गत की बहुत आलोचना का विषय बना। इसे बनाने लिये कुछ ही महीने हुए थे कि द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। द्वितीय महायुद्ध के आगमन और निर्यात दोनों पर ही कड़ा नियन्त्रण किया गया तथा भारत की व्यापारिक नीति युद्धकाल की सङ्कटवाली अवस्थाओं के अनुसार ढाली गई। नतीजतन देशों में व्यापार की कठोर मनाही कर दी गई तथा फिर एक तटस्थ राष्ट्रीय से जो व्यापार कठोर प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जा सकता था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की व्यापारिक नीति—

द्वितीय विश्व-युद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन को तृतीय पक्ष का राष्ट्र बना, दिया था,

भारत की स्वतन्त्रता ने “कफन में दूसरी कील ठोकने” का कार्य किया। किन्तु भारतीय नेताओं, गाँधीजी एवं नेहरूजी के “भुन जाओ और क्षमा करो” के उपदेश ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपानास में ब्रिटेन को बड़ी भारी राहत दी। हमारी सद्-इच्छा की परिचायक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध नये विरे से चालू हुए और राष्ट्रमण्डल का जन दृष्टा व्यापार के क्षेत्र में साम्राज्य अधिमान की नीति पूर्ववत् जारी है किन्तु अब यह राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान (Commonwealth Preferences) के नाम से प्रसिद्ध है।

स्वतन्त्रता के बाद, नये बाजार प्राप्त करने तथा निर्यात व्यापार में नई मंदा प्रचलित करने हेतु भारत ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के देशों में कई व्यापारिक समझौते सम्पन्न किये हैं। विभिन्न समझौते दो प्रकार के हैं—द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय। द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में भारत ब्रिटिश व्यापारिक करार (१९३६) पहला कदम था। अब निम्न देशों के साथ भी द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न हो गये हैं—रूस, पोलैंड, बंको-स्लावेकिया, हंगरी, इटली, नावों और यूरोप के अन्य देश। साल चीन से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध आजकाल टूट चुके हैं। भारत पर जापान के बाद भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध भी टूट गया इसमें पूरा भी ३ सम्बन्ध बचे ही सकोचपूर्ण तथा प्रति-
 षा मय थे सौहार्दपूर्ण नहीं। तादात्म्य समझौते की भावना का पालन करते हुए राजनैतिक सम्बन्धों के साथ भी नाव वाकिस्तान में व्यापारिक सम्बन्ध भी सुधरने की आशा थी किन्तु यह दुराशामान रह गई है।

जहाँ भारत ने विशेष देशों में विशेष व्यापारिक समझौते किये हैं, वहाँ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कारारों में भी सम्मिलित हुआ है। भारत सहित २३ राष्ट्रों ने जनवरी में १९४७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो कि ‘व्यापार एवं प्रशुनक विषयक सामान्य करार’ (General Agreement on Tariffs and Trade) के नाम से विख्यात है। इस समझौते का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना था टैरिफ़्स बरों में पारस्परिक रिवापत्ते दिनामा है। राष्ट्रमण्डल अधिमान के जारी रहने के लिए इस समझौते में छूट दी गई है।

वर्तमान स्थिति—

इस समय राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान प्रणाली का प्रयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि वह हमारे विकास कार्यक्रमों में सहायक हो। अब तो भारतीय निर्मातों का स्वरूप ही बदल गया है। जहाँ ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र-मण्डलीय देशों को कच्चा मात्र अधिनास में आया करता था वहाँ अब निर्मित माल की प्रमुखता होने लगी है। हमारे आयातों में पूर्ण जीवित वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई है तथा निर्मित उपभोग्य वस्तुओं का आयात कम हो गया है। अब अब भारत ब्रिटिश बाजार में हटतापूर्वक प्रति-योग्यता करने लगा है। जबकि ब्रिटेन में लगभग सभी भारतीय आयातों पर भारत को रिवापत्ते प्राप्ति है तब वह स्वयं ब्रिटेन को इनी गिनी रिवापत्ते ही दे रहा है। योरो-

पियत साम्रा बाजार के बनने से राष्ट्र-मण्डलीय अधिमानों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है । यदि ब्रिटेन भी उक्त साम्रा बाजार में सम्मिलित हुआ, तो भारत को कुछ हानि उठानी पड़ सकती है । १९६६ में भारत ने बहुत से नये व्यापार-व्यवहार किए और कुछ पुराने करारों को बढ़ाया ।

विदेशों में भारतीयों की ओर से समुक्त उद्योग-धन्धे स्थापित करने के प्रयास में इस वर्ष और अधिक सफलता मिली । एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में विकास-कार्यक्रमों में भारतीय उद्योगपति अधिकाधिक सहयोग दे रहे हैं । इस तरह की लगभग ५० योजनाएँ आजकल मसार के भिन्न-भिन्न भागों में भारत की सहायता में अमल में लाई जा रही हैं ।

परीक्षा प्रश्न :

१. साम्राज्य अधिमान के प्रचलन का उद्देश्य क्या था और वहाँ भारत के लिये कहीं तक हितकर रहा ?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial ?]

२. भारत सरकार की व्यापारिक नीति की आलोचना कीजिये ।

[Examine critically the commercial policy of the Government of India]

३. भारत ने अनेक विदेशी देशों के साथ अधिकाधिक संख्या में व्यापारिक समझौते किये हैं । इसके कारण बताइये और हाल के किसी एक व्यापारिक समझौते के स्वभाव एवं उद्देश्य का विवेचन कीजिये ।

[Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries. Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India]

(इलाहूँ, एम० कॉप०, १९६७)

१९६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

प्रारम्भिक—

पॉन्क व छ जून १९६६ की मध्य रात्रि के दो बजते भारतीय रुपय का २९ ५/८ के र्शिताव में अवमूल्यन किया गया। अब भारत द्वारा नियत जाने वाले आयात पर एक अमरीकी डालर के लिए ७ रुपए ५० पैसे और एक पौड स्टर्लिंग (ब्रिटिश) के लिए २१ रुपये (१९६७ में पौड के अवमूल्यन के बाद में १८ ८०) तथा उसी मुद्रा खर्च के लिए ८ रुपए ३३ पैसे देने पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा भेजे गये वेल मिलन ने रुपय के अवमूल्यन का सुझाव दिया था। लेकिन, भारत सरकार इसका बराबर विरोध करती रही। मसंद में अनेक बार यह घोषणा की गई कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। पिछले महापुत्र के बाद भारतीय रुपए के मूल्य में दूसरी बार घटाया गया है। इसमें पूर्व सत्र १९६६ में उस समय भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, जब ब्रिटिश पौड की कीमत घटाई गई थी।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने कई अन्य कदमों की घोषणा की। इनके अनुसार वारह वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया, अनेक वस्तुओं के दुनियादी निर्यात शुल्क में परिवर्तन किया गया, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू सभी विशेष राजनामों को खत्म कर दिया गया। इनके बदले में कुछ अन्य निर्यात योजनाएँ बनाई गईं ताकि निर्यातकों का कच्चे माल, मशीनों के औजार और स्पेयर पार्ट्स आदि भंडारों के लिए सुविधाएँ दी जा सकें।

अवमूल्यन के लिये विवश करने वाली परिस्थितियाँ

सहायक वित्त मंत्री श्री अश्वमेध चौधरी ने रुपए के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय से सही बताते हुए कहा कि, "यदि यह कदम अब नहीं उठाया जाता, तो आयात के पूरी तरह से बन्द हो जाने की सम्भावना पैदा हो जाती। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कदम पिछले कई सालों में उठाये जा रहे थे, वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए।

देश की वित्तीय स्थिति काफी दिनों से चिन्ताजनक हो रही थी। पिछले दस वर्षों में निर्यात घटता जा रहा था। हमारा सामान अन्य देशों के सामान की कीमतों के सामने टिक नहीं रहा था, इसलिए १९६५ में निर्यात को प्रोत्साहन देने के एक कदम उठाया गया। इनमें वित्तीय साधनों पर दबाव पड़ा। सूखे की स्थिति और पाकिस्तानी आक्रमण ने हालात को और अधिक बिगाड़ दिया। विदेशी मतागतता पर भी प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में रूप के अवमूल्यन पर विचार किया गया। बाद में योजना आयोग वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के परामर्शदाताओं के साथ प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया। सरकार ने भी इस बात का अनुभव किया कि घटसन, चाय, सूती कपड़ा, कच्चा सोया, मैंगनीज आदि जिन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता है उनके परिमाण में बहुत ज्यादा वृद्धि सम्भव नहीं है। इस पृष्ठभूमि में अन्य मन्त्रियों ने भी अवमूल्यन के प्रश्न पर विचार किया और मन्त्रिमण्डल में इसके पक्ष में निर्णय किया गया।

अवमूल्यन से की गई आशाएँ—

(१) इससे निर्यात को भारी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा मान न केवल बढ़ता हो जायेगा, बल्कि लोग निर्यात उद्योगों में रूपा भी लगायेंगे।

(२) यह भी आशा की गई कि आयातित चीजों का रूप में मूल्य बढ़ जाने से ऐसी चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी जो अब हम बाहर से मँगाई जा रही हैं। नेता के द्वारे से भी यही बात है। इस प्रकार इसका स्वावलम्बन में सहायता मिलेगी।

(३) नई विनिमय दर से आयात निर्यात पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वरन् देश में बाहर जाने वाले और बाहर से देश की आने वाले भुगतान पर भी असर पड़ेगा। इससे भारत में धन भेजने की प्रोत्साहन मिलेगा और भारत से बाहर धन भेजने पर कुछ रोक लगेगी। अब बाहर से धन लगाने वालों के मुनाफे के रूप में होने वाले विदेशी मुद्रा का क्षीयन कम हो जायेगा।

(४) रूप की नया शक्ति में कमी होने के कारण बहुत-सी वस्तुएँ भी पैदा हो गई हैं। रूप के पुराने विनिमय मूल्य के कारण निर्यातकर्ता अपने सामान का दाम कम लगाते थे और आयात करने वाले बड़ा बड़ाकर दाम सवाले थे। भागियों की हथियाई देशों से न भुनाकर अब देश रूप में भुनाई जाती थी जिससे ज्यादा दाम मिलते थे। बाहर से भुगतान अब धन उरीकों में होता था और सोना, घड़ियाँ, कमरे, ट्रांस्फ़र आदि चीजें बढ़ती हुई माना में देश में चोरी में लाई जा रही थी। बंधन उरीकों से जो आयात होता था उसमें भी नया महंगा मुनाफा कमा रहे थे और यह कमाई दिखाकर रखी जा रही है। नए विनिमय दर के कारण से सब कार्यवाहियाँ अब अपनी सामर्थ्य में रहनी हैं। अब अवधि दरियों में हमारी जो विदेशी मुद्रा जा रही थी, वह कम जायेगी, और हमारा विदेशी मुद्रा कोष बढ़ेगा।

(५) अवमूल्यन के कारण विदेशी मुद्रा के रूप में न तो श्रम की कुल

रकम में और न इसकी वार्षिक अदायगी की राशि में कोई वृद्धि होगी। परन्तु स्पष्ट के रूप में अदृश्य ऋण की अदायगी का बोझ बढ़ जायेगा। यही नहीं सरकारी आपात का दौर दूसरे विदेशी सचं का भी परिणाम स्पष्ट के रूप में बढ़ जायेगा।

(६) अवमूल्यन में हमारे वज्रट को भी कई प्रकार से ताम होगा। उदाहरण के रूप में निर्यात शुल्कों में हमें काफी आमदनी होगी। इसी तरह से विदेशी सहायता के रूप का मूल्य बढ़ जायेगा।

(७) कुछ आवश्यक चीजों के दामों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए इसलिए प्रथम प्रबन्ध किया गया कि अनाज, उर्वरक, किरोसीन (मिट्टी के तेल) और डीजल तेल का दाम बढ़ने न गए। जो निवासियों विदेशों में पढ़ रहे हैं उनको ही कम व्याज पर ही ऋण दिमाने का आश्वासन दिया गया।

पैदावार को बढ़ाकर ही दामों में स्थिरता लाई जा सकती है। हमारी सीनो योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले हैं उनमें से अधिकांश बाहर से आने वाले कच्चे माल और कल-पुर्जों की कमी के कारण पूरी क्षमता के उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण उत्पादन बढ़ने में बाधा पड़ती थी। अब बाहर से ज्यादा कच्चा माल और पुर्जे मँगाने की वांछित की गई। इसके लिए आपात का तरीका सरल किया गया। किरोसीन (मिट्टी के तेल) पारिषद की गिरी और कपास का आपात बढ़ाया गया।

रूपों के अवमूल्यन पर प्रतिक्रियाएँ

वित्त मंत्री और योजना मंत्री के बार-बार इस आश्वसन के बावजूद कि रूप का अवमूल्यन नहीं किया जायगा, सरकार ने रूप का ३६ ५ प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जो व्यवहार में लगभग ५० प्रतिशत है। आमतौर से यह ख्याल था कि भारत सरकार आम चुनाव में पूर्व यह कदम नहीं उठायेगी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में निर्णय पर भारी आघात पड़ा। अधिकांश उद्योगपतियों ने सरकार के इस कदम की औद्योगिक विफल में बाधक बताया। प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार थीं—(१) यह कदम सरकार के उन आश्वासनों के विरोध था जो उनमें लोक सभा में दिये थे। अवमूल्यन के नाम पर जो लाभ प्राप्त होने के दावे किए जा रहे हैं वे सलन मात्रित होंगे। (२) देश के अन्दर और बाहर प्रतिभूल प्रभावी के बनाया रूपों के अवमूल्यन में जनता का विश्वास सरकार में कम हो जायगा क्योंकि सरकार कमरा खा-खा कर यह कह रही थी कि वह रूप का अवमूल्यन नहीं करेगी। इसमें विदेशों में हमारा दायित्व बढ़ जायगा। इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा—धर्मकर जनता का मनोबल गिरिया। (३) इस कार्यवाही से औद्योगिक में विलम्ब होगा। अग्रान्त दिये गये सामान की कीमत करती बढ़ जायगी। आन्तरिक मूल्य स्तर भी इसमें बढ़ सकता है। (४) यह कार्यवाही “अनाउरयक” है। वित्त, तथा योजना मंत्रियों ने हाल में मदद में सलन दिया गया था कि रूप का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। इसमें रूप की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

(५) अवमूल्यन से अधिकांश जनता बुरी तरह प्रभावित होगी—मुद्रा स्फीति और बंदों और रुपए का मूल्य ज्यादा घट जायगा । (६) सरकार एक ओर विदेशी दवाओं और दूसरी ओर निहित स्वार्थों के आगे झुकी है । यह सदिग्ध है, अवमूल्यन से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी । आयात को नागत बढ़ जायगी और मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी । विदेशी श्रृंखला का बोझ भी बढ़ जायगा ।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का प्रभाव
[मूल्य स्तर के संदर्भ में]

अवमूल्यन के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इसका महाराष्ट्र मुगलान मनुजन की स्थिति में सुधार लाने के निम्ने निर्यात व्यापार को बढ़ाया देने और आयात-वस्तुओं की माँग कम करने हेतु लिया जाता है । इस तर्क का औचित्य अन्य बातों के अतिरिक्त आयात और निर्यात वस्तुओं की माँग की मूल्य-स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात् इन वस्तुओं के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप माँग किस प्रतिशत में घटती-बढ़ती है । १९५०-५१ से १९६४-६६ तक १६ वर्षों की अवधि में भारत का व्यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में १० और १७ के बीच रहा । १९५१-५२ में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा था । १९५८-५९ से १९६३-६४ तक यह प्रतिशत लगातार १२ रहा । १६ वर्षों में इन प्रतिशतों का औसत १३ था ।

आयात-वस्तुओं के मूल्य की स्तर—

१९५५-५६ में आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक निम्नतम अर्थात् ८४ था, लेकिन इस वर्ष के आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक उच्चतम नहीं था । आयात-व्यापार के परिमाण का सूचकांक १९६३-६४ में उच्चतम था जबकि इस वर्ष आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक ९८ था । आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक १९५७-५८ में सबसे ज्यादा अर्थात् १०४ था । इस प्रकार उच्चतम और निम्नतम सूचकांक के बीच अंतर २० था । आयात-व्यापार के परिमाण के उच्चतम सूचकांक और निम्नतम सूचकांक में अंतर ११६ का था अर्थात् यह सूचकांक २१२ और ९६ के बीच रहा । इसमें स्पष्ट होता है कि आयात के परिमाण में तेजी से घटा बढ़ी हो रही थी लेकिन आयात की प्रति इकाई के मूल्य के सूचकांक में घटा बढ़ी सीमित रूप में हुई । सम्पूर्ण स्थिति को जांच के निम्ने प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक और आयात निर्यात वस्तुओं के परिमाण के सूचकांक का महत्त्व सम्बन्ध निकाला गया । महत्त्व सम्बन्ध का गुणक $+ ०.२$ आया । सह-सम्बन्ध का गुणक धन $(+)$ में होना इन बातों का संकेत है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि होने पर आयात के परिमाण या मात्रा में भी वृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होने पर आयात की मात्रा भी कम हुई । लेकिन सह-सम्बन्ध का गुणक ०.२ ज्यादा नहीं । इसलिये ऊँची कीमत पर भी आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं है । अर्थशास्त्रियों की भाषा में यह कहा जा सकता है कि आयात-वस्तुओं की माँग यहाँ लोचनीय है । अतः अवमूल्यन के फलस्वरूप आयात वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने में भारतीय आयात में ज्यादा कमी नहीं हो सकती ।

निर्घात-वस्तुओं की मूल्य-सूच —

१९५५-५६ में निर्घात की प्रति इकाई का मुचकात ६० था जो न्यूनतम है। उस वर्ष में निर्यात के परिमाण का मुचकात ११२ था। १९६४-६५ में निर्घात के परिमाण का अधिकतम मुचकात १२० था जब कि उस वर्ष निर्घात की प्रति इकाई का मुचकात १०० था। प्रति इकाई मूल्य का निम्नतम मुचकात १९५५-५६ में ६० और १९५१-५२ में अधिकतम अर्थात् १८२ था। इन दोनों के बीच अन्तर ८२ था। इसमें यह विचार निकाला जा सकता है कि निर्घात का परिमाण प्रति इकाई मूल्य की तुलना में बड़ा परिवर्तनशील रहा। निर्घात के परिमाण के मुचकात और प्रति इकाई मूल्य के मुचकात के बीच सह सम्बन्ध का गुणक — निकाला गया। महत्सम्बन्ध का गुणक (—) ऋण में होने का संभव है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप भारत में निर्घात का परिमाण कम हो जाता है और प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर निर्यात का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। सर्वसाधनों की भाषा में कहा जा सकता है कि भारत का निर्घात पर्याप्त रूप में मूल्यबोधशील नहीं है।

निर्घात बढ़ाने की आशा पूरी नहीं हुई

सरकारी अंश में यह जाना ही गई थी कि इस अवमूल्यन के पश्चात् निर्घात-वातार में वृद्धि होगी यद्यपि बंसी आया निर्घातों की और निर्यातों ने नहीं की थी।

यह के अवमूल्यन के हमारे नियामों की मात्रा (volume) रचना (Composition) तथा उनके व्यापार की दिशा (Direction) पर भी प्रभाव हुए हैं उनकी समीक्षा नीचे की गई है।

निर्घात व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—

अवमूल्यन ने भारत के निर्घात व्यापार को बड़ा उछाल पहुँचाई। यह जून १९६६ में मई १९६७ तक के आँकड़ों में स्पष्ट है। निर्यात आय वृद्धि योजना के तीसरे वर्ष में बढ़ती प्रारम्भ हुई थी और १९६३-६४ में १,९६६ मि० डॉलर से बढ़कर १९५४-६१ में १,७०५ मि० डॉलर हो गई। १९६१-६६ में विगत वर्ष की राशि के बराबर (लगभग १६६३ मि० डॉलर) रही। किन्तु १९६६-६७ के पहले दो महीनों की छोटकर निर्घात आय घटती गई। यह १९६१-६६ में १,५६३ मि० डॉलर से घटकर १९६६-६७ में १,५५३ मि० डॉलर रह गई अर्थात् उसमें ७३% कमी हुई। मार्च १९६७ के बाद भी निर्घात आय की कमी होने की प्रवृत्ति जारी रही।

अब प्रश्न यह है कि हमारे नियामों में गिरावट क्या आई? सैद्धान्तिक दृष्टि में तो अवमूल्यन के फलस्वरूप इनमें वृद्धि होनी चाहिए थी। सम्भोदतापूर्वक विचारणा करने पर निर्यातों की गिरावट के लिए निम्न कारण उत्तरदायी प्रतीत होते हैं — (१) मूल्य बढ़ा करण सम्भव यह रहा कि सत्ता निर्यात को साहजिक मानने में समर्थ हो गई तथा परम्परागत निर्यात वस्तुओं पर गिरावट निर्धारण करना दिया गया। इसमें निर्यात व्यापार को घटता गया तथा कुछ महीनों तक

तो वह यथावत् रह गया । जहाँ तक हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई की सुरक्षित रखने के उद्देश्य का सम्बन्ध है निर्यात कर लगाना ठीक हो था । यह भी सच है कि बाद की सरकार ने कुछ नगद सहायता भी धारित की लेकिन वह अपर्याप्त थी । (२) साथ ही विभिन्न उद्योगों में जो निर्यातित वस्तुओं का उपयोग करती है (जैसे—मूँतों वस्त्र जूट के कारखाने कैमीकल्स इन्वीनिशियल गुड्स आदि), उत्पादन-लाभों में बड़ गई, क्योंकि इनके आयात वस्तुओं का मूल्य रुपये में ५७.५% बढ़ गया । (३) सरासरी दृष्टि फलते (जिनहोम) कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग को कुप्रभावित किया) मुद्रा स्फीति का जारी रहना स्वदेशी माल का बर्तन रहना, रुपया भुगतान समझौते वाले देशों में व्यापार अस्त-व्यस्त हो जाना व कुछ अन्य कारणों से जो निर्यात-वस्तुओं के बाद की अवधि में निर्यातों में कमी के लिए दायी रहे ।

रचना (Composition) की दृष्टि से प्रभाव—

सन् १९६६-६७ में हमारी अधिकांश निर्यात आय (लगभग ४१.६%) तीन प्रमुख परम्परागत वस्तुओं जूट (२१.५%), चाय (१३.८%) और सूती माल (६.९%) से हुई । किन्तु इन तीनों पर अवमूल्यन का बुरा प्रभाव पड़ा । इनसे निर्यात आय १९६६-६७ में १९५५-६६ की तुलना में क्रमशः १५.५% १३.६% और ३६.१% कम हो गई । अन्य वस्तुओं जिनका निर्यात कुप्रभावित हुआ निम्न है — तम्बाकू, कहवा, नारियल जटा उत्पाद धातु निर्मित माल, मीनीज खनिज और अन्नक । इस निराशापूर्ण चित्र का एक उदाहरण यह है कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में घुट्टि हुई जैसे—कमठा व खाले, कोह खनिज, खली, पशु पदार्थ एवं वनस्पति कहवा, जूते आदि, जूट के देशों फल व सब्जियाँ । अवमूल्यन से सुप्रभावित होने वाली इन वस्तुओं का हमारी कुल निर्यात आय में भाग २२% है । स्पष्टतः कुल पर निर्यात आय में कमी हुई ।

क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से—

(१) विश्व के अनेक देशों की भारतीय वस्तुओं निर्यात होती है, किन्तु १९६६-६७ में केवल चार देशों का भाग ही हमारे कुल निर्यात में ५०% से भी अधिक था । ये देश निम्न हैं —अमेरिका जिसने यू० के० को हमारे सबसे बड़े साहब के पद से हटा दिया है १८.८%, यू० के० १७.४%, रूस १०.७% और जापान ६.२% । (२) हाल के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों से भारत के व्यापार में वृद्धि होना एक उल्लेखनीय घटना है । रूस को छोड़ने हुए पूर्वी यूरोप के देशों का भाग ८.८% और रूस सहित पूर्व यूरोपियन गुट का भाग १६.५% है । (३) जर्मनी तथा फ्रांस के छोड़ने हुए यूरोपियन साम्राज्य के देशों का भाग ७.६% है । जर्मनी तथा फ्रांस की हमारा निर्यात सम्बन्ध है । (४) इकोपी क्षेत्र में जापान भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक भागीदार है । उसका भाग हमारे कुल निर्यात में ६.२% है । अन्य इकोपी देशों में आस्ट्रेलिया नैपल और लक्सा प्रमुख है । (५) अन्य एशियाई देशों

(वर्षात् इक्कीस देशों के वितरित) जो हमारे निर्यात सामुग्री हैं। इनमें प्रमुख भाग कुर्न (= ७%) और ईराक (= १%) का है। (६) अफ्रीका ग्रुप में ४० अंगण-राज्य हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। उसका भाग हमारे कुल निर्यातों में २०% है। (७) लेटिन अमेरिका के विकासोन्मुख देशों को हमारे निर्यात बाजार में अभी कोई महत्व नहीं मिला। १९६८ में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की लेटिन अमेरिका के देशों की यात्रा से इनके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने की आशा है।

अबमूल्यन के बाद हमारे निर्यात अधिकांश बाजारों में (जिनमें हमारे बड़े बाजार देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन ५० जर्मनी, आस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हैं) घट गये हैं। वह ५० जर्मनी पोलैंड और संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों के साथ भी, जिनमें हमारे रुपये-मुगलान-सम्बन्धित थे, हमारे निर्यात कम हो गये। लेटिन अमेरिकी देशों को नगण्य निर्यातों में भी २०% कमी हो गई। हाँ, जापान, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस इटली, बल्जियम, ईराक, तुर्कान और केन्या को निर्यात बढ़े। किन्तु इन अपवाद मूलक देशों का भाग हमारे कुल निर्यात में केवल २०% ही है, जिस कारण निर्यात कुल पर घटे ही है।

आयात व्यापार पर अबमूल्यन के प्रभाव

रुप के अबमूल्यन से आयात-वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना स्वाभाविक है। भारत में आयात-वस्तुओं की आवश्यकताएँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फलतः हम अपनी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष में काफी घनराशि निकासनी पड़ी है और बहुत स्तर पर इन आयातों के लिए विदेशी सहायता भी लेनी पड़ी है। हमारे आयात की एक विशेषता यह है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात-व्यापार पर १९५७ के वर्ष से जो नियन्त्रण लगाए गये हैं उनमें हम केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही आयात करने की स्थिति में हैं जो योजनाओं के अन्तर्गत रहे गये कारवर्क्यों को पूरा करने के लिये अति आवश्यक हैं। इस प्रकार अबमूल्यन से आयात का मूल्य कम होने की सम्भावना नहीं है। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों को पूरी उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने के लिए काम करने दें, नये उद्योगों का, जिन्हें हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो हम अधिक मात्रा में कच्चा मान और पूर्ण आयात करने की व्यवस्था करनी होगी। आयात की लागत में वृद्धि हो जाने से कुछ अनिवार्य वस्तुओं के सागत-मूल्य-दाले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयात वस्तुओं की लोचहीन मग की स्थिति में अबमूल्यन से आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुएँ तैयार करने की प्रक्रिया को भी रण नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने छोटे समय में रुप का अबमूल्यन मुगलान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय नहीं हो सका।

दूसरी बार अबमूल्यन करने की सुझाव

इन बातों को दृष्टि में रखकर यह आशानी में कहा जा सकता है कि रुप

भारत का विदेशी व्यापार

(The Foreign Trade of India)

प्रारम्भिक—

वर्तमान ससार में किसी देश के आर्थिक विकास और उसकी सम्पन्नता के लिये विदेशी व्यापार की उत्पत्ति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वावलम्बिता युग पहले से ही समाप्त हो चुका है। बितनी ही वस्तुएँ तो ऐसी हैं जिन्हें एक देश उत्पन्न ही नहीं कर सकता और बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से देश में बहुत ही अधिक लागत पर उत्पन्न किया जा सकता है। दोनों ही दशाओं में विदेशी व्यापार लाभदायक होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएँ कम मूल्य पर मिल जाती हैं। विशिष्टीकरण तथा विनिमय (दोनों) के अधिक लाभों को प्राप्त करने के लिये विदेशी व्यापार का विकास अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, देशों की पारस्परिक मित्रता और सहयोग के लिये भी विदेशी व्यापार आवश्यक है। इसके अन्तर्गत सभी देशों को पारस्परिक सहायता के द्वारा अपनी-अपनी अर्थ-व्यवस्था के विकास और उपभोग-स्तर को ऊँचा उठाने का अवसर प्राप्त होता है।

भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास

(I) प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक—

ऐतिहासिक खोज में पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्यापार पर्याप्त विस्तृत एवं महत्वपूर्ण था। अस्मरणीय काल में जल और यल दोनों ही मार्गों से भारत के विदेशियों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। अब से ५ ००० वर्ष पूर्व भी भारत का देविनोन से व्यापार होता था। ऐसा पता चलता है कि भारतीय व्यापारियों के पास बड़े-बड़े जहाजी वेड़े थे और वे सुदूर-पूर्व तथा मध्य पूर्व के देशों के साथ नियमित रूप में व्यापार करते थे। पश्चिम में मिस्र, यूनान, अरब और ईरान से, लेकर पूर्व में चीन, मलय प्रायद्वीप, जावा, फिलिपीन्स, इण्डोनेशिया, ब्रह्म और बालीकट के मूठी कपड़े को संसार भर में ख्याति प्राप्त थी। निर्यात की वस्तुओं में सूती कपड़े, धातु के सामान, हाथी दाँत, रंग, मसाले, हथियार और बनेक कलात्मक सामान सम्मिलित थे और धातुओं पीतल, टीन, सराब, घोड़े आदि का आयात होता था।

मुसलमानों के निरन्तर आक्रमणों ने देश की राजनीतिक दशाओं में अनिश्चितता उत्पन्न करके व्यापार में भारी कमी कर दी। परिणाम यह हुआ कि समुद्री व्यापार घट गया, परन्तु मुस्लिम काल में चल मार्गीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई। साथ ही, आन्तरिक व्यापार की भी उन्नति हुई, जिसका प्रमुख कारण चल मार्गों का विकास था। मोरलैंड (Moreland) के अनुसार लाहौर और काबुल तथा मुल्तान और कंधार के बीच व्यापार नियमित रूप से होता रहता था। यही चल मार्ग काबुल और कंधार से चीन और ईरान को जाने प और इनके द्वारा भारत का माल यूरोप तक पहुँचता था। इस काल में भी आयात और निर्यात की वस्तुयें पहले जैसी ही थी।

यूरोपीय व्यापारियों ने आते ही देश के विविध व्यापार से लाभ उठाना आरम्भ किया। डच, फ्रांसीसी तथा इण्डिया कम्पनी ने देश के उद्योगों की प्रोत्साहन देकर व्यापार में वृद्धि की, परन्तु यह स्थिति अधिक समय तक चली न रह सकी। पश्चिम में 'औद्योगिक क्रांति' के पश्चात् दृष्टाएँ बदल गई और १८वीं शताब्दी में जैसे-जैसे इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपियन देशों के उद्योगों का विकास हुआ, उन्होंने भारतीय माल के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने आरम्भ कर दिये। इंग्लैंड ने ऐसा अनुभव किया कि उसके लिये भारत से कच्चा माल लेना और अपने उद्योगों की उपज को भारत में बेचना अधिक लाभदायक था। अतः वहाँ कच्चे मालों के आयातों को प्रोत्साहन दिया गया और भारत का इंग्लैंड की औद्योगिक उपज का बाजार बनाने का प्रयत्न किया गया। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना रयेल नहर का निर्माण थी। इसके फलस्वरूप समुद्र के रास्ते से भारत और इंग्लैंड का अन्तर ५५०० मील में घट गया और यूरोप के बाजार भारत के लिये खुल गये। मुक्त-व्यापार नीति के फलस्वरूप भी व्यापार के विस्तार में सुविधा हुई। सन् १८६४-६६ तथा सन् १८६६-१९०४ के बीच विदेशी व्यापार का वार्षिक मूल्य ६६ करोड़ रूपय से बढ़कर २१० करोड़ रूपय हो गया और सन् १९०६-१४ में यह ३७६ करोड़ रूपय तक पहुँच गया।

(II) प्रथम महायुद्ध-काल—

सन् १९१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ। युद्ध के कारण वातायात सबको अतिशय बड़ गई। साथ ही यूरोप के देश युद्ध-कार्य में इतने तल्लीन हो गये कि वे अपने विदेशी व्यापार को बनाये न रख सके। युद्ध काल में भारत में निर्यात और आयात दोनों में ही कमी हुई। सन् १९१३-१४ और १९१८-१९ के बीच निर्यात ३२४ करोड़ रुपये में घटकर केवल १६० करोड़ रुपये और आयात १६३ करोड़ रुपये से स्थान पर केवल ६३ करोड़ रुपये रह गये। अनुमानतः भारत के विदेशी व्यापार में कुल मिलाकर लगभग ५०% की कमी हो गई। अन्य देशों के साथ तो व्यापार पूर्णतया बन्द हो गया, परन्तु मिन देश भी माल ले जाने और भेजने में कठिनाई अनुभव

कर रहे थे। आयातों के घटने का परिणाम यह हुआ कि मुद्र-काल में देश के उद्योगों को प्राकृतिक संरक्षण मिला गया।

(III) दो महायुद्धों के मध्य काल—

युद्धोत्तर-काल में भारत के विदेशी व्यापार में एकदम तेजी आई। यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाएँ युद्ध के कारण चौपट हो गई थी, इसलिये उन्हें आयातों की भारी आवश्यकता थी। भारत के लिये निर्यातों का बढ़ाने और ऊँची कीमत प्राप्त करने का अच्छा अवसर था, परन्तु यातायात की कठिनाइयों तथा ऊँची विनिमय दर के कारण भारत इस तेजी का पूरा-पूरा लाभ न उठा सका।

सन् १९२०-२१ में तेजी का यह नम दूट गया और विदेशी व्यापार में फिर मन्दो आ गई। परन्तु २ वर्षों के पश्चात् सन् १९२२-२३ में फिर उद्धार काल आरम्भ हुआ। सन् १९२४-२५ तक दसायें काफी सुधर गईं। अभिवृद्धि का यह क्रम निरन्तर आगे ही बढ़ता रहा, कवन सन् १९२६-२७ के बीच महान् अवसाद के काल में यह दूट गया था। सन् १९१६-२० तथा सन् १९२६-३० के बीच व्यापार की स्थिति निम्न थी—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापारसौर
१९१६-२०	३३६	२२२	+ ११४
१९२०-२१	२६७	३४७	- ८०
१९२१-२२	२४५	२५२	- ७
१९२२-२३	३१६	२४	+ ७०
१९२६-३०	३१५	२४६	+ ६९

युद्धोत्तर-काल में उद्धार का तत्काल कारण यह था कि धीरे-धीरे सभी योरोपीय देशों की मुद्राओं की कीमतों में स्थिरता आ गई, उनकी साल में वृद्धि हो गई और मुद्र के हर्जाने (Repatriation) का प्रश्न भी सुलझ गया था।

सन् १९२६ में महान् अवसाद आरम्भ हुआ। इसके प्रथम चिह्न संयुक्त राज्य अमरीका में दृष्टिगोचर हुये थे। परन्तु धीरे-धीरे ससार के लगभग सभी देश इसकी जकड़ में आ गये। अवसाद के प्रमुख कारण निम्न थे— कच्चे मालों और निमित्त वस्तुओं का अति-उत्पादन होना, ससार का अधिकांश स्वर्ण अमरीका में एकत्रित हो जाना, विभिन्न देशों में मुद्रा-संकुचन की नीति अपनाया जाना, कुछ देशों में राजनैतिक अस्थिरता होना आदि।

युद्धोत्तर काल में आर्थिक राष्ट्रीयवाद की भावना भी तीव्र हो गई थी, जिसके अन्तर्गत सभी देशों ने विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिये थे और विदेशी व्यापार को अतिक्रमण कर दिया था। विभिन्न देशों द्वारा स्वयंमान का परि-त्याग, मुद्रा-अवमूल्यन, आयात अभ्यस्त नीति आदि ने भी विदेशी व्यापार के मार्ग में

वनक बाधाओं उपस्थित थी। अबसाद का सबसे बुरा प्रभाव वृषि प्रधान देशों पर पड़ा, क्योंकि ऐसे जाल में वृषि उपज और अच्छे माल के मूल्यों में ही सबसे अधिक पतन होता है। इससे भारत के निर्यात व्यापार को भारी धक्का लगा। साथ ही, जनता के पास श्रवण-शक्ति की कमी, राजनैतिक अस्थिरता तथा देशी उद्योगों के विकास में, जिने मरदान नोति ने प्रोत्साहित किया था, बाधाओं को भी पर्याप्त मात्रा में पड़ा दिया था।

भारत में आयातों की तुलना में निर्यातों का पतन अधिक हुआ, जिसका मुख्य कारण यही था कि दस का निर्यात व्यापार अच्छे मालों से जिसकी कीमतें बहुत नीचे गिर गई थी, सम्बन्धित था। इस जाल में भारत में पर्याप्त मात्रा में रत्नों का निर्यात किया और इसी कारण निर्यातों में कमी आने पर भी व्यापारालेख अनुकूल ही बना रहा। सन् १९३० तथा सन् १९३८ के बीच भारत ने २१० करोड़ रुपये की वीमत के खर्च का निर्यात किया। अबसाद के सबसे बुरे वर्ष अर्थात् सन् १९३२-३३ में भी हमारा व्यापारालेख अनुकूल ही था, जिसकी मात्रा ३ करोड़ रुपये थी। यह इसी कारण सम्भव हुआ था कि हम निर्यातों की कमी में उत्पन्न हुई स्थिरता को विदेशों में सोना भेज कर पूरा कर रहे थे।

मवसाद सन् १९३३ में समाप्त हुआ और सन् १९३३-३४ में उद्धार की प्रवृत्ति फिर आरम्भ हो गई। फलतः विदेशों में भारत के माल की माँग बढ़न लगी। उद्य उद्धार के अनेक कारण थे — सत्यप्रथम, अमेरिका और फ्रांस ने वृत्तिम उपयोग द्वारा उद्धार का क्रम आरम्भ किया था। दूसरे, इसी साल में मसार के देशों ने दूसरे महायुद्ध की तैयारी आरम्भ कर दी थी। तीसरे, ओटावा सम्मेलन के कारण भारत और राष्ट्र-सम्बल देशों के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। चौथे, दसों साल में सन् १९३४ में भारत-जापान सम्मेलन भी हुआ, जिसने भारतीय व्यापार के विस्तार में सहायता दी।

सन् १९३३-३६ तक व्यापार का विस्तार होना गया, परन्तु सन् १९३६-३७ में फिर मन्दी आई, जो सन् १९३६ तक चलती रही और अन्त में दूसरे महायुद्ध के आरम्भ होने पर फिर तेजी आरम्भ हुई। परन्तु महान् अबसाद के परभाव भारतीय व्यापार का कोई विशेष विस्तार नहीं हो सका। कारण, युद्ध द्विजने के भय में व्यावसायिक वर्ग विनिमित था। इसके अतिरिक्त, चीन-जापान युद्ध के कारण पूर्व की मण्डियों में बहुत व्यापार सम्भव न था। सन् १९३६-४० में प्रथम बार तेजी प्रवृत्ति रूप में आई, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिये विभिन्न देशों ने अस्त्र उद्योगों के विकास और स्टाकों के जमा करने पर अधिक व्यय करना आरम्भ कर दिया था, जिसने भारतीय निर्यातों के लिए माँग एवं उनके मूल्य दोनों में वृद्धि हुई थी।

(IV) दूसरा महायुद्ध-काल —

सन् १९३६ में दूसरे महायुद्ध का आरम्भ होने ही विदेशों व्यापार में तेजी के साथ वृद्धि हुई। अच्छे माल और निर्मित वस्तुएँ दोनों ही की विदेशी माँग पर्याप्त

बली और यद्यपि बहुत से देशों को शत्रु घोषित करके उनके साथ व्यापार बर्जित कर दिया गया था तथापि भारतीय व्यापार निरन्तर विस्तृत ही होता गया। निम्न भावने इस वृद्धि का कुछ अनुमान प्रदान करते हैं [यद्यपि ये पूर्वतया सन्तोषजनक नहीं हैं, क्योंकि उनमें ब्रिटिश सरकार द्वारा खरीदे हुए माल तथा उधार-पट्टा (Land-lease) प्रणाली द्वारा प्राप्त माल की कीमत नहीं दिखाई गई है] —

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
१९४०-४१	७१७	१५७	३४४
१९४१-४२	२३७	१७३	४१०
१९४२-४३	१८७	११०	२८७
१९४३-४४	१२२	११८	३१७
१९४४-४५	२१०	२०४	४१४

युद्ध-काल के केवल सन् १९४२-४३ के वर्ष को छोड़ कर निरन्तर विदेशी व्यापार का विस्तार ही हुआ है। किन्तु वर्ष विशेष में व्यापार की मात्रा घटने के कई कारण थे, जैसे — (i) जापान के युद्ध में सम्मिलित हो जाने के कारण सुदूर-पूर्व (Far-east) का व्यापार समाप्त हो गया था। (ii) विनियम निबन्धन प्रणाली को कड़ा कर दिया गया था, जिससे व्यापारियों को भारी असुविधा रहती थी। (iii) आयात तथा निर्यात व्यापारियों को अनुज्ञापित कर दिया गया था। (iv) युद्ध की प्रगति के साथ जलयानों के मिलने में कठिनाई होती गई और इसका विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। (v) कुछ देशों को तो शत्रु घोषित कर दिया गया था और उनके साथ व्यापार बर्जित था, परन्तु विश्व देश भी युद्ध कामों में इतने व्यस्त थे कि वे नैतिक सामानों के अतिरिक्त अन्य माल भेजने में असमर्थ थे। (vi) साम्राज्य डालर बोप के वार्यवाहन ने अमरीका से माल भेजना कठिन बना दिया। (vii) शत्रु की वार्यवाहियों के कारण यातायात में अधिक कठिनाई हुई। बाद को इन सब बाधाओं ने नियमितता धारण कर ली और इनके रहते हुए भी व्यापार का विस्तार होता रहा। युद्ध-काल की प्रमुख विशेषता यह थी कि निर्यातों की अपेक्षा आयातों में अधिक कमी हुई थी।

(V) युद्धोत्तर-काल में विदेशी व्यापार—

युद्ध का अन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुधार हुआ। युद्धकाल में आयातों के रुक जाने तथा मूल्यों के ऊपर उठने पर देशों उद्योगों का समुचित विकास न हो सका था, जिससे देश में पूर्वागत और आवश्यक कच्चे मालों का निरन्तर अभाव अनुभव किया जा रहा था। अब युद्ध-कालीन तनाव कम होते ही आयातों में वृद्धि हुई। जलयानों की कमी के कारण कठिनाई बनी रही। आरम्भ में सबसे अधिक वृद्धि उन वस्तुओं के आयातों में हुई, जिनकी सैनिक कार्यों के लिए आवश्यकता

थी, परन्तु तत्पश्चात् खाद्यान्न तथा पूँजीगत माल के भी आयात बढ़े। आयातों में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई कि मुद्रोत्तर काल में व्यापार में भारत के लिए प्रति-बल हो गया। यह स्थिति आगे के आंकड़ों द्वारा स्पष्ट हो जाती है —

(मरीच १९५० में)

वर्ष	निर्यात तथा पुनर्निर्यात	आयात	व्यापारानुपात
१९४५	२६६	२३२	— ३
१९४६	२६६	२६२	— २६
१९४७	३२०	२३४	— १४
१९४८	४२८	४५१	— ४३
१९४९	४२३	५४३	— १२०

मुद्रोत्तर-काल में आयातों की अत्यधिक वृद्धि के प्रमुख कारण थे, जैसे —

- (i) धीरे-धीरे भारत सरकार ने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को ढीला कर दिया था,
- (ii) जलयान यातायात की पूर्ति बढ़ गई थी (iii) देश में मुद्रा-प्रसार के दूर करने का प्रयास किया गया, (iv) खाद्यान्नों के आयातों में अधिक वृद्धि हुई और (v) भारत सरकार ने खुले सामान्य अनुज्ञापन (Open General Licences) नीति में अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में उदारता को अपनाया था।

देश का विभाजन—सन् १९४७ से भारत के दो भाग कर दिये गये—पाकिस्तान और भारत। इस विभाजन के कई दुष्परिणाम हुए —(i) खाद्यान्न की दृष्टि बनी हुई गई और (ii) बन्धा माल बचाने वाले क्षेत्र भारत में निकल गये। फलतः एक ओर तो खाद्यान्न का अधिक आयात करना पड़ा और दूसरी ओर रस्द और पटसन के निर्यात में कमी आ गई। इन दोनों के सम्बन्ध में पाकिस्तान में अनेक समस्याएँ किये गये, जिनका उसने पालन नहीं किया। फलतः हमारा निर्यात व्यापार बहुत घट गया और बन्धी सामग्री के लिए हमें विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। इस प्रकार देश के विभाजन ने हमारे विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल दिया और व्यापार का सन्तुलन हमारे देश के अधिकाधिक प्रतिरूत होता चला गया। अन्त में इसे ठीक करने के लिए भारत सरकार को दृष्टिगोप्य उपाय करने पड़े।

१९४९ का खपत का अवमूल्यन—मुद्रोत्तर-काल में इंग्लैंड तथा स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के अन्य देशों का व्यापारानुपात डालर क्षेत्र के साथ प्रतिरूत हो बना रहा। कुछ काल तक इंग्लैंड ने मुद्रा-कोष तथा अमेरिका से ऋण लेकर डालर की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया, परन्तु जब किसी भी प्रकार घाटा पूरा न हो सका तो सितम्बर १९४९ में स्टर्लिङ्ग का अवमूल्यन पूरा कर दिया गया। उसने डालर में स्टर्लिङ्ग की कीमत ४.०३ से घटकर २.८० रह गई। इंग्लैंड का अनुकरण करते हुये पाकिस्तान को छोड़कर स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के देशों ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अव-

मूल्यन कर दिया। डालर में रुपये की कीमत ३० २२३ सेन्ट से घटकर केवल २१ सेन्ट रह गई। अवमूल्यन एक आर्थिक आवश्यकता थी। सन् १९४५ तक डालर क्षेत्र से भारत का व्यापार अनुकूल था, परन्तु सन् १९४६ में स्थिति बदलने लगी थी। सन् १९४८-४९ में तो उदार जायत नीति के फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रोंय व्यापार में १२० करोड़ रुपये का घाटा था। भारत में भी 'डालर समस्या' उत्पन्न हो गई थी किन्तु अवमूल्यन ने इस स्थिति को कुछ अज तक सुधार दिया था।

जबकि सन् १९४८-४९ में घाटा १२० करोड़ ८० था, तब यह सन् १९४९-५० में १०९ करोड़ ८० और सन् १९५०-५१ में केवल २२ करोड़ ही रह गया। व्यापार-सन्तुलन की स्थिति में इस सुधार के लिए अवमूल्यन के अतिरिक्त अन्य कारण भी बायीं थे — जैसे (i) सरकार ने डालर आयातों पर प्रतिबन्ध लगाकर देश की आयात माँग को स्थगित क्षेत्र से ही पूरा करने का प्रयत्न किया था। (ii) कोरिया युद्ध के आरम्भ होने पर सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा स्टॉकों का जमा करना आरम्भ कर दिया था, जिससे देश के पर्याप्त व्यापार का प्रोत्साहन मिला था। इस प्रकार, व्यापार की दृष्टि से भारत के अनुकूल होती गई।

उपरोक्त प्रवृत्ति सन् १९५०-५१ तक बनी रही। किन्तु अनेक अनुकूल घटक सन् १९५१ के प्रारम्भ में लुप्त हो गये। सरकार ने भी अपनी निर्यात नीति में परिवर्तन किया और देशी उपजों की देशी उद्योगों में अधिक मात्रा में उपयोग करना आरम्भ कर दिया। इससे सन् १९५२ के प्रारम्भ में व्यापाराधेय की प्रतिकूलता सन् १९४८-४९ की अपेक्षा भी अधिक हो गई।

पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विदेशी व्यापार

देश में १ अप्रैल सन् १९५१ में नियोजित विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। योजनावद्ध विकास कार्यक्रमों के हमारे विदेशी व्यापार पर बहुत प्रभाव डाला है। नियोजन की अवधि में विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) विदेशी व्यापार का कुल परिमाण—विदेशी व्यापार का कुल परिमाण जो सन् १९५०-५१ में १,२५१ करोड़ ८० था, सन् १९५५-५६ में १,३८३ करोड़ ८०, सन् १९६०-६१ में १,७६५ करोड़ ८०, सन् १९६५-६६ में २,२१५ करोड़ ८० और १९६६-६७ में २,५७५ करोड़ ८० था। अवमूल्यन के बाद की दर पर यह राशि १९६५-६६ के लिये १,४८८ करोड़ ८० और १९६६-६७ के लिये ३,२३४ करोड़ ८० होती है। १९६७-६८ और १९६८-६९ के लिए व्यापार की कुल राशि क्रमशः ३,१८५ करोड़ ८० और ३,१३९ करोड़ ८० बनती है।

(२) प्रतिकूल व्यापारिक सन्तुलन—व्यापार सन्तुलन सन् १९४७ से देश के प्रतिकूल रहता है। यह प्रतिकूलता द्वितीय योजना के प्रारम्भ होने पर बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि साधानों, पूँजीगत वस्तुओं और कच्ची मग़ास का आयात बहुत बढ़ गया था। सन् १९५७-५८ में घाटा ६४० करोड़ ८० तक जा पहुँचा। बाद में कुछ सुधार हुआ, जिसमें यह सन् १९६०-६१ में ४८० करोड़ ८० और सन् १९६१-६२ में ४३२

करोड़ २० रह गया। तृतीय योजना के दूसरे वर्ष से व्यापारिक घाटा पुनः बढ़ने लगा। सन् १९६२-६३ में यह ४४६ करोड़ २० हो गया। सन् १९६३-६४ में कुछ कमी आई और यह ४३० करोड़ २० रहा। किन्तु इसके बाद इसमें निरन्तर वृद्धि होती गई। यह सन् १९६४-६५, १९६५-६६ और १९६६-६७ में क्रमशः ५३३ करोड़ २०, ६०३ करोड़ २० और ६४१ करोड़ २० हो गया। अवमूल्यन के बाद की दर पर घाटा १९६४-६५ में ८४० करोड़ २०, १९६५-६६ में ९५० करोड़ २० था। १९६६-६७ में ९२२ करोड़ २०, १९६७-६८ में ७८७ करोड़ २० और १९६८-६९ में ४३३ करोड़ २० रहा।

(३) निर्यात सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ—नियोजन के प्रथम दश वर्षों (सन् १९५१-१९६१) भारतीय निर्यात लगभग स्थिर रहे। पहली योजना में कुल निर्यात ३,०४४ करोड़ २० अथवा वार्षिक औसत ६०९ करोड़ २० था जबकि दूसरी योजना में कुल निर्यात १,११० करोड़ २० अथवा वार्षिक औसत ६२२ करोड़ २० था। इस प्रकार, दूसरी योजना के दौरान निर्यात व्यापार पहली योजनावधि की अपेक्षा थोड़ा ही अधिक था। यद्यपि दुसरी योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान निर्यात में स्पष्ट वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। इस दशक में विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का भाग ७.१२% था, वहीं १९६० में घटकर केवल १.२% रह गया। तीसरी योजना की अवधि में हमारे निर्यात निरन्तर बढ़ते गये, केवल अन्तिम वर्ष तक आक्रमण के कारण उभरे कमी हुई। सन् १९६०-६१ में ६८२ करोड़ २० से बढ़कर निर्यात १९६१-६२ में ६६१ करोड़ २०, १९६२-६३ में ६८५ करोड़ २०, १९६३-६४ में ७९३ करोड़ २० एवं १९६४-६५ में ८१६ करोड़ २० हो गये। किन्तु १९६५-६६ में निर्यात लगभग ८०७ करोड़ २० ही थे। इस प्रकार तीसरी योजनावधि में वार्षिक निर्यात औसत ७५२ करोड़ २० हुआ। यह दूसरी योजना की अपेक्षा २१% ऊँचा था।

१९६५-६६ में हमारे निर्यात अवमूल्यन के बाद की दर पर १,७६९ करोड़ २० थे। १९६६-६७ में १,१५६ करोड़ २० रहे। इस प्रकार अवमूल्यन के कारणात् बाद निर्यात नहीं बढ़े जिसकी हमें आशा थी। बाद की स्थिति में सुधार हुआ और निर्यात धीरे-धीरे बढ़ने लगे। यह १९६७-६८ में १,१९९ करोड़ २० और १९६८-६९ में १,३५१ करोड़ २० हो गये। विगत वर्षों में हुई तेज वृद्धि के बावजूद विश्व के निर्यात व्यापार में भारत का योगदान केवल ०.९३% रहा।

निर्यात के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के अतिरिक्त निर्यात सम्बन्धी एक नवीन प्रवृत्ति यह है कि इसकी रचना में भी परिवर्तन हो गये हैं। सन् १९६०-६१ में हमारी तीन प्रमुख निर्यात वस्तुओं—जूट, सूती वस्त्र और चाय—का भाग कुल निर्यात में ६७% था, जो सन् १९६०-६१ में ४८% और १९६५-६६ में केवल ४३% रह गया। लाख एवं तिलहन का भाग भी घटा है। तीसरी योजनावधि में चाँदी, सोना और इस्पात, हाथ करवे के कपड़े, इन्जीनीयरी के सामान आदि अनेक

वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछ नई वस्तुओं का पहले पहल निर्यात किया गया, जो प्रधानतः इन्जीनियरी और रसायन क्षेत्र की है। १९४७-४८ में हमारे निर्यात में केवल १० मदे शामिल थे किन्तु अब इन मदों की भरमा बढ़कर २,९९० में भी अधिक हो गई है। १९६८-६९ में तंबाकू माल के निर्यात में २०% वृद्धि हुई और कच्चे माल विरोधित खनिज पदार्थों के निर्यात में केवल ३% वृद्धि हुई। इस वर्ष (१९६८-६९) में लोह और इस्पात से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई गई।

विगत वर्षों में प्रमुख वस्तुओं के निर्यात की स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है —

(करोड़ रुपये)

वस्तु	१९४०-४१	१९४४-४५	१९६०-६१	१९६४-६५	१९६७-६८
पटसन का सामान	१४४	११८	१३५	१८३	२३४
चाय	६०	१०९	१२३	१०१	१७९
मृत्ती वस्त्र	१३८	६४	५८	६३	७९
जुत्तों	—	५	१४	३५	४५
कच्चे धातु	१०	२३	३९	२५	८६
काजू	९	१	१९	७	४३
तम्बाकू	१९	११	१६	२२	३५
कहूआ	१	२	७	१३	१८
चीनी	—	१	३	१२	१६
मसाले	१६	११	१७	२३	४५
अन्नक	१०	८	१०	११	१५
वनस्पति तेल	२५	३४	९	४	४
गोद लाल	१४	१३	९	३	५
रई	१७	३९	१३	१३	१९

तीसरी योजना की अवधि में भारत के निर्यात-व्यापार के भौगोलिक वितरण में भी ध्यान देने योग्य परिवर्तन आये। इस अवधि में भारत से पश्चिम यूरोप को होने वाले निर्यात में थोड़ी-सी कमी आई। दूसरी ओर अमरीका को होने वाले निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतया अमरीका को होने वाले निर्यात वृद्धि के कारण हुई। १९६०-६१ में अमरीका को होने वाला भारत का निर्यात जहाँ १६ प्रतिशत था वहाँ १९६५-६६ में बढ़कर १८.३ प्रतिशत हो गया। पर भारत के निर्यात व्यापार में सबसे अधिक वृद्धि पूर्व यूरोप के देशों को (जिनमें रूस भी शामिल है) होने वाले निर्यात के क्षेत्र में हुई, जहाँ १९६०-६१ में भारत के निर्यात में केवल

■ ७ प्रतिशत जग इन देशों का था वहाँ १९६५-६६ में यह वंश बढ़कर १६.३ प्रतिशत हो गया। इस निर्यात में मुख्य भाग रुस की होने वाले निर्यात का रहा। अफ्रीका और एशिया तथा सुदूर-पूर्व के देशों को होने वाले निर्यात में मूल्य की दृष्टि से साधारण सी ही वृद्धि हुई।

अब मगार के लगभग सभी राष्ट्रों को हम निर्यात करते हैं जिनमें से प्रमुख देशों का थोड़ा निम्न तालिका में दिया गया है —

(करोड़ रुपया)

देश	१९५०-५१	१९५१-५६	१९६०-६१	१९६१-६६	१९६७-६८
अमेरिका	११५	८७	१०३	१४८	१०७
ब्रिटेन	१४०	१६६	१७३	१४६	२२६
रुस	१	३	२६	६३	११२
जापान	१०	३०	३५	५७	१३६
म. अरब	६	६	१३	२७	२२
गणराज्य					
बंगाल	१४	१४	१८	२०	३०
९० जर्मनी	११	१५	२०	१८	२१
आस्ट्रेलिया	३०	२५	१२	१८	८८

तामरी योजना की अवधि में निर्यात को बढ़ाने के लिये कई संस्थागत वित्तीय तथा अन्य प्रकार के उपाय किये गये थे। निर्यात को बढ़ाने के लिए संस्थाओं के ढाँचे में तीसरी योजना की अवधि में सुदृढता लाई गई। वाणिज्य मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया विभाग १९६२ के प्रारम्भ में ही खोल दिया गया था। व्यापार तथा वाणिज्य के सभी सक्ष्मों की समीक्षा करने के लिए तथा सरकार की परामर्श देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मण्डल (Board of Trade) गठित किया गया था। (इसका १९६६ में पुनर्गठन हुआ है।) इन्स्टीट्यूट इन्टर्नैटियनल ऑफ फारेन ट्रेड (Indian Institute of Foreign Trade) नामक एक नई संस्था एक स्वायत्त संगठन के रूप में खोली गई, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण अनुसन्धान और बाजार अध्ययनों से सम्बंधित कामकाजों का विकास करना था। तीसरी योजना की अवधि में बहुत सी निर्यात वर्षक परिपक्व गठित की गई, जिससे इनकी संख्या अब १६ हो गई है। परिपक्व के कार्यों में सम्बन्ध स्थापित करने तथा विकास कार्यों में उन्हें सहायता पहुँचाने के लिये एक शोध संस्था 'भारतीय निर्यात संगठन संघ' (Federation of Indian Export Organisations) स्थापित किया गया है। सरकारी व्यापार निगम के सहायक कर्मियों और धानुओं के निर्यात की वृद्धि करने के लिए कर्निज तथा धातु व्यापार निगम स्थापित किया गया।

तीसरी योजना की अवधि में निर्यात में होने वाली वाय की वृद्धि का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसमें बहुत-सी निर्यात वस्तुओं और तैयार किये गये माल के निर्यात की बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चालू किये गये। इनमें में कई कार्यक्रम तीसरी योजना के शुरू होने के पहले ही प्रारम्भ विद्ये जा चुके थे पर तीसरी योजना की अवधि में इन्हे परिष्कृत और सशोषित किया गया।

निर्यात का बढ़ाने में वित्तीय उपाय भी सहायक हुये। तीसरी योजना की अवधि में कई वस्तुओं पर आयात कर तथा उत्पादन की वापसी के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। वाय पर लगने वाला निर्यात कर क्रमशः घटाया गया और अन्त में समाप्त कर दिया गया। जुलाई १९६३ में एक बाजार विकास निधि स्थापित की गई तथा निर्यात प्रबंधक परिषदों को अनुदान देने के लिये और भारतीय निर्यात वस्तुओं की विदेशों में बिक्री बढ़ाने में कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को चलाने के लिए केन्द्रीय बजट में १९६३-६४ में लगातार विशिष्ट राशियाँ की व्यवस्था की जाती रही है। निर्यात करने वालों को कुछ प्रत्यक्ष करों की छूट १९६२-६३ के केन्द्रीय बजट से ही शुरू कर दी गई थी। १९६४-६६ के केन्द्रीय बजट में भारत सरकार ने निर्यातकों को निर्यात के २ प्रतिशत से लेकर १५ प्रतिशत तक कर उधार प्रमाण-पत्र देने की घोषणा की थी। प्रारम्भ में बाईस वस्तुओं की सूची दी गई थी जिन्हें कर उधार के लिए उपयुक्त माना गया था।

देश से निर्यात होने वाली वस्तुएँ टीक प्रकार की हों इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संसद ने १९६३ में (किस्म नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम पार किया था। इसके बाद कई अन्य वस्तुएँ इस अधिनियम के श्रेण में लाई गई और एक निर्यात निरीक्षण सलाहकार परिषद (Export-Inspection Advisory Council) भी गठित की गई, जो किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम बनाती है। तीसरी योजना के अन्त तक देश से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में दो सगभग ८० प्रतिशत किस्म नियन्त्रण और अज्ञान में तद्वान से पूर्व निरीक्षण की योजना के अन्तर्गत आ चुकी है।

तीसरी योजना की अवधि में विश्व निर्यात की अपेक्षा भारत के निर्यात में वृद्धि की गति धीमी रही। परिणामस्वरूप विश्व-निर्यात में भारत का भाग जहाँ १९६० में १२ प्रतिशत था, १९६५ में घटकर १० प्रतिशत से भी कम रह गया।

(४) आयात सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ—पञ्च-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास में सबसे अधिक प्रभाव आयातों पर डाला है। पहली योजनावधि के कुल आयात ३,६१५ करोड़ रु० (वार्षिक औसत स्तर ७२३ करोड़ रु०) थे, द्वितीय योजना के कुल आयात १,९२६ करोड़ रु० (वार्षिक औसत स्तर ८८५ करोड़ रु०) थे। इस प्रकार पहली योजना की अपेक्षा द्वितीय योजना में आयात स्तर २६% बढ़ गया। तीसरी योजना के लिए आयात बिल ६,१८१ करोड़ रु० था। वार्षिक आयात स्तर १,२३६ करोड़ रु० था। इस प्रकार, तीसरी योजना के औसत आयात स्तर में

दूसरी योजना की अपेक्षा ३६% के लगभग ही वृद्धि हुई। तीसरी योजना में चीनी हमारे के बाद आयात घुन बढ़ गये, यद्यपि योजना के प्रथम वर्ष में ये काफी घट गये थे। सन् १९६०-६१ में आयात १,१७० करोड़ रु० से घटकर सन् १९६१-६२ में १,०६१ करोड़ रु० रह गये थे किन्तु सन् १९६२-६३ में बढ़कर १,१३१ करोड़ रु०, १९६३-६४ में १,२६० करोड़ रु० और १९६४-६५ में १,३१४ करोड़ रु० हो गये। पान आक्रमण और देश में २ वर्ष के निरन्तर सूखे की स्थिति के कारण जायानो व रक्षा सामग्री का आयात बढ़ गया यह १९६५-६६ में १,३५० करोड़ रु० था। १९६६-६७ में कुल आयात १४०६ करोड़ रु० हुये। अव्यवस्था के बाद की दर पर आयात १९६४-६५ में २,१२६ करोड़ रु० १९६५-६६ में २,२१६ करोड़ रु० और १९६६-६७ में २,०७८ करोड़ रु० हुये। १९६६-६७ में आयात विम में जो नयी आई वह अव्यवस्था का सुपरिणाम था तथा देश में अव्यवस्था सुधारने लगी थी। १९६७-६८ और १९६८-६९ में आयात क्रमशः १,९८६ करोड़ रु० और १,७८६ करोड़ रु० हुए। इस प्रकार आयात नियमि में काफी सुधार हुआ है।

आयातों के सम्बन्ध में दूसरी उल्लेखनीय प्रवृत्ति यह है कि कुल आयात में सरकारी धन का भाग निरन्तर बढ़ रहा है। यह १९५५-५६ में १८% था और आज-कल कुल आयात में सरकारी भाग ४० प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। इन आयातों में खाद्यान्न सरकारी उपक्रमों के लिए पूँजीगत सामान, लौह व स्पात रेलवे स्टोर्स, कम्प्यूरीकेशन स्टोर्स आदि सम्मिलित है।

ग्राहबेट आयातों में आवश्यक कच्चे मानो, अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं और पूँजीगत वस्तुओं का भाग बड़ा जबकि अविकसामा-मक मशीन, विद्युत उपभोक्ता सामान का भाग बहुत कम हो गया। सोडा एवं स्पात का उत्पादन स्वदेश में ही बढ़ने से इसका आयात भी काफी कम हुआ। तीसरी योजना के अन्तिम वर्षों में खाद्यान्नों का आयात एकाएक बढ़ गया। अमेरिका जापान बर्मा मंगुल अरब गणराज्य और प० जर्मनी ने आयात जॉब रहे किन्तु सऊदी अरब और यू० के० से घटे। सोवियत रूस में भी हमारे आयात बढ़ रहे हैं।

(५) व्यापार की विज्ञा—जहाँ तक भारत के व्यापार में विभिन्न देशों के महत्व का प्रश्न है, २०वीं सताब्दी में ब्रिटेन और साम्राज्य देशों के साथ व्यापार में निरन्तर वृद्धि हुई। सन् १९०४-१५ में इन देशों का भाग केवल ४१% था, जो १९४४-४५ में ६३% तक पहुँच गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद देश का व्यापार साम्राज्य और अन्य देशों के साथ लगभग समान रहा है। प्रथम योजना के अन्त में गैर-साम्राज्य देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा था। आजकल हमारे सर्वाधिक आयात ग० यूरोप में है, जिसमें यू० के० और ई० ई० भी० देश मुख्य हैं। प० मोलाभ का आयात सूची में दूसरा स्थान है। इन क्षेत्र में हमारा सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है। पूर्वी-यूरोप में हमारा सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। हमारे आयात अमेरिका और रूस में बढ़ रहे हैं जबकि यू० के० और ई० ई० भी० देशों से घटे हैं।

हमारे सर्वाधिक निर्यात के क्षेत्र क्रम में प० यूरोप (जिसमें प्रमुख यू० के० में ई० ई० सी देश)। प० गोल्फ स्ट्रेट (जिसमें प्रमुख अमेरिका), अन्य एशियाई देश, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व एवं अन्य अफ्रीकी देश हैं।

भारत के विदेशी व्यापार की विसा
(अप्रैल-मार्च)

(करोड़ रु०)

देश/क्षेत्र	आयात		निर्यात	
	१९६८-६९	१९६७-६८	१९६८-६९	१९६७-६८
१ यूरोपीय सामान बाजार	२३३ ६५	२५६ १०	११० ८४	८८ ४१
२ यूरोपीय स्वतंत्र बाजार क्षेत्र	१७० ४६	२०८ ७०	२१६-२८	२६२ ३४
जिसमें यू० के०	१०२-८७	१६२-६५	२००-८३	२०८ ४७
३ पूर्वी यूरोपीय देश	३०१-०४	२२२ २०	२६६-१९	२२४ ५८
जिसमें रूस	१८५ ५१	१११ २२	१४८-१७	११० ५१
४ नार्थ अमेरिका	६७३-७८	८७४ ६२	२६३ ०७	२३५ ६६
जिसमें अमेरिका,	५०१-०६	७७६ ६४	२३३ ४०	२०६ २०
कनाडा	१८७ ०	९८ ०८	२९ ६७	२९ ७४
५ लैटिन अमेरिका	१६ ८३	११ ८६	३-६५	५-४५
६ अफ्रीका	१४८ २२	६४ १२	७२ ७६	६९-६९
जिसमें मध्य	४१ ४१	२६ ६०	२१ ८२	२१ ५०
७ दक्षिणी	२७८ २७	२८८ ८८	३४३ ६४	२७०-०८
जिसमें जापान	११५ ३०	१०८ ४३	१५८-१६	११५-६९

भारत का भुगतान संतुलन

प्राचीन और मध्ययुग में भारत का व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन शान्ति ही अनुकूल रहते थे, क्योंकि वह जितना आयात करता उससे ज़्यादा निर्यात भी करता था। ब्रिटिशकाल में यद्यपि व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल रहता था तथापि उमका भुगतान संतुलन प्रतिकूल था। भारत को प्रतिवर्ष होम चार्ज (Home Charges) के रूप में भारी राशि इंग्लैंड को देनी पड़ती थी, जिसके लिए उसे वस्तुओं का अधिक निर्यात करना पड़ता था। इस अधिक निर्यात के बदले में हमें सोना या चांदी प्राप्त नहीं होता था। द्वितीय महायुद्ध काल में भारत के निर्यात-दत्तने बढ़ गये और उसके आयात इतने कम हो गये कि न केवल हमने इंग्लैंड का पिछला कृण चुका दिया बल्कि उसके सेनदार के रूप में भी सामने आये। अब वह अपने निर्यात आधिक्य के बदले में सोना चांदी प्राप्त कर सकता

था। किन्तु युद्धोत्तरकाल में व्यापार सन्तुलन और इसके फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन प्रतिफल हो जाने से यह सम्भव न हो सका। युद्धोत्तरकाल में भारत की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन निम्न शीपको के अन्तर्गत किया जा सकता है—(I) अवयून्यन के पूर्व की व्यवस्था (II) अवयून्यन से लेकर पहली योजना के अन्त तक की अवस्था (III) द्वितीय योजनावधि एवं (IV) तृतीय योजनावधि की अवस्था।

(I) १९४६ के अवयून्यन से पूर्व भुगतान सन्तुलन की स्थिति—

युद्ध की समाप्ति के बाद भुगतान सन्तुलन में युद्धराश्वीन आधिक्य साध्रता में घाटे में परिणत हो गया। सन् १९४८-४९ में चामू भुगतान सन्तुलन का घाटा २५२१ करोड़ रु० तक पहुँच गया था। इसके लिये मुख्य व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता बायीं ओर व्यापार सन्तुलन की प्रतिकूलता के लिये निम्न कारण दायीं ओर थे—(i) युद्धकाल में स्टलिंग की कमाई के आधार पर भारत में नोट छापे गये जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ गई। परिणामतः देश बिक्री के लिये अच्छा और खरीद के लिये बुरा बाजार बन गया। (ii) युद्ध समाप्त होने ही सरकार ने आयात निषेध हटाने का फैसला किया जिससे कि युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के लिये स्थगित रखी गई विशाल मात्रा की सन्तुष्टि हो सके। इससे आयातों में भारी वृद्धि हुई। (iii) औद्योगिक मशीनरी के प्रतिस्थापन तथा नविकरण के लिये पूँजीगत सामान का भारी मात्रा में आयात हुआ क्योंकि युद्धकाल में यह कार्य स्थगित रखना पड़ा था। (iv) देश विभाजन के फलस्वरूप कच्चे तेल और कपास की बड़ी कमी हो गई और इनका हमें विदेशों से आयात करना पड़ा। (v) गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पाकिस्तान में रह गये जिससे खाद्य समस्या ने विकरान रूप धारण कर लिया। फलतः भारत को विशाल मात्रा में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। (vi) देश में बहु उद्देश्य नदी घाटी योजनाएँ आरम्भ की गईं। इन विकास कार्यक्रमों के लिए पूँजीगत साज-सामान भारी मात्रा में मँगाना पड़ा। (vii) अन्ध सघर्षों और प्राकृतिक सङ्कटों के कारण युद्ध पूर्व के वर्षों की तुलना में युद्ध के बाद हमारे कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में कमी हो गयी जिससे निर्यात के लिए आधिक्य कम रह गया। (viii) अदृश्य बर्तों (जैसे विदेशी ऋणदायकों) पर व्यय बढ़ गया।

इन सब कारणों से भारत की युद्धोत्तर अवधि में भुगतान में घाटे का सामना करना पड़ा। भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति के सुधार के लिए सरकार ने निम्न लिखित कदम उठाये—

(१) कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के यत्न किये गये जैसे—अधिक खाद्यान्न उपजाने आदीलेन अधिक कपास उपजाने एवं अधिक जूट उपजाने आदि। उत्पादन सम्बन्धी कदम स हूट दी गई तथा अन्य भी माहम भी दिये गये।

(२) मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण रखने हेतु तत्पु बचत आन्दोलन आरम्भ किया गया मूल्य नियन्त्रण व कोटा निर्धारण की पद्धति अपनाई गई ।

(३) विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत अधिवार रिजर्व बैंक को सौंपे गये, जिससे व्यर्थ वस्तुओं पर विदेशी मुद्रा का व्यय न हो ।

- - (४) 'गोरवाला निर्यात प्रोत्साहन समिति' को सिकारिशो पर निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये, जैसे—अधिक निर्यात करने पर भ्राय कर में छूट देना, डाक पामल दरें कम करना, कुछ निर्यात वस्तुओं पर उपादन शुल्क की आपसी रेल भाड़ों में कमी निर्यात सलाहकार परिषद् तथा अलग-अलग वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन समितियों की स्थापना आदि ।

(५) आयातों को भी कम से कम करने के लिए निम्न उपाय किये गये—आयात सलाहकार परिषद् की स्थापना, आयात लाइसेंस की प्रथा आरम्भ करना, कई वस्तुयों 'स्वतन्त्र आयात सूची' (Open General Licence) में से निकाल देना, आयात वस्तुओं की प्राथमिकता सूची बनना, हर छठे माह आयात नीति पर पुनर्विचार करना, स्थगित भुगतान पद्धति पर आयात की व्यवस्था करना, उपभोग वस्तुओं का आयात लगभग रोक देना, आदि ।

अन्त में जब उपरोक्त उपाय विशेष सफल होते दिखाई न पड़े, तो सितम्बर १९४६ में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया तथा डॉलर की अल्पता के कारण व्यापार को डॉलर क्षेत्रों से मोड़कर सुलभ मुद्रा क्षेत्रों में बढ़ाने के यत्न किये गये ।

(II) अवमूल्यन के बाद प्रथम योजना की समाप्ति तक भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति—

प्रथम योजनावधि में केवल एक वर्ष १९४१-४२ को छोड़कर शेष अवधि के लिए भारत का भुगतान सन्तुलन (बालू खाता) अधिस्थित रहा । इस अधिधि में व्यापार सन्तुलन निरन्तर प्रतिकूल रहा और यह प्रतिकूलता बढ़ती गई । चूंकि महत्त्व मंदो के सम्बन्ध में अनुकूल देय था इसलिए व्यापार सन्तुलन के प्रतिकूल होने पर भी भुगतान सन्तुलन में अधिस्थिति हुआ ।

भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में गुबार का तत्कालिक कारण रुपये का अवमूल्यन था, जिसने आयातों को निरुत्साहित तथा निर्यातों को प्रोत्साहित किया । आयात प्रतिबन्ध भी कड़े कर दिये गये थे । कोरियाई युद्ध के कारण भारतीय निर्यात की मात्रा और कीमतें दोनों बढ़ गईं । किन्तु ये सब अस्थायी फटक थे, जो १९४१ के प्रारम्भ में ही सुप्त हो गये । तत्पश्चात् व्यापारिक उपलब्धता में अपनी आजाद हुआ (= २३२५ करोड़ ६०) । इस प्रतिकूलता का कारण प्राकृतिक विपदाओं के फल-स्वरूप देश में कृषि उत्पादन कम होना था । इससे विदेशों से भारी मात्रा में खाद्यान्न और नक्की कपास का आयात करना पड़ा । पाकिस्तान द्वारा अवमूल्यन न करने से पाकिस्तानी बूट के लिए भी अधिक दाय देने पड़े ।

किन्तु १९४१-४२ एक अपवाद वर्ष था । तत्पश्चात् जलवायु सम्बन्धी अनुकूल

दशाओं के कारण कृषि उत्पादन काफी बढ़ गया। इससे वषात, साधान और जूट के आयात क्षिप्त में बहुत कमी हुई। चूंकि प्रथम योजना में औद्योगिक विनियोग के कार्यक्रम माधारण ही थे, इसलिए पूँजीगत सामान का आयात भी कम रहा।

(III) द्वितीय योजनावधि में भुगतान सन्तुलन—

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष में भुगतान सन्तुलन का १९५५-५६ का आधिरस्य 'घाटे' में परिणित हो गया। यों तो सम्पूर्ण योजनावधि में गम्भीर घाटे रहे किन्तु १९५७-५८ सबसे अधिक और भयंकर घाटे का वर्ष था। इस वर्ष १०५ करोड़ रु० का घाटा हुआ। ये घाटे क्या हुए और १९५७-५८ में सबसे अधिक घाटा क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण निम्न थे —

(१) विशाल विनियोग कार्यक्रम—द्वितीय योजना एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। इसके अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में विनियोग से विशाल कार्यक्रम बनाये गये थे। पन्चम योजना के पहले वर्ष से ही आयातों में वृद्धि हो गई। १९५७-५८ में मशीनों और धातुओं का आयात ५९४ करोड़ रु० हुआ जब कि १९५६-५७ में ४४२ करोड़ रु० और १९५५-५६ में केवल २९६ करोड़ रु० था।

(२) साधन स्थिति में बिधाट—प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण खाद्य-निर्मात भी बिधाट गई, जिनसे खाद्यान्नों के आयात में भारी वृद्धि हुई। जबकि १९५४-५५ में २६ करोड़ रु० का साधनाभ रंगया गया था तब सितम्बर ५९५८ को समाप्त होने वाले २२ वर्षों में २९६ करोड़ रुपये का मगाया गया।

(३) निर्यात वस्तुओं की खपत देश में ही बढ़ना—निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुओं (जैसे तिलहन, लोहा और कपास आदि) की खपत देश में ही बढ़ गई, क्योंकि इनका प्रयोग करने वाले कारखाने देश में खुलते जा रहे थे।

(४) मुद्रा प्रसार—मुद्रा प्रसार के पक्षस्वरूप उत्पादन व्यय बढ़ गये और निर्यात वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। इससे इंग्लैंड और जापान की सहती व टिकाऊ वस्तुओं से विदेश बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन हो गया।

फलतः एक ओर निर्यातों में कमी आई जबकि दूसरी ओर आयातों में भारी वृद्धि हो गई। आयात सन् १९५५-५६ में ७६१-१४ करोड़ रुपये में बढ़कर १९५६-५७ में १०-६६५ करोड़ रु० और १९५७-५८ में सबसे अधिक अर्थात् १,२३९ करोड़ रु० हो गये। अतः द्वितीय योजना में भुगतान सन्तुलन घाटे का ही गया।

यह उल्लेखनीय है कि द्वितीय महायुद्ध के पूर्व व्यापार-सन्तुलन की अनुकूलता भारत के लिए आवश्यक समझी जाती थी, जिससे कि वह "होम चार्जेज" का भुगतान करता रहे। लेकिन अब व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता उतनी आवश्यक नहीं रह गई है और आयाती १० वर्ष तक सम्भव भी नहीं है, क्योंकि पञ्चवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो विशाल-विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए हमें भारी मात्रा में मशीनों, कच्चे मालों तथा अन्य साज-सामान का अनिवार्य रूप से आयात करना पड़ेगा। अतः, यदि व्यापार सन्तुलन और इसके पक्षस्वरूप भुगतान सन्तुलन

में घाटे रहते हैं, तो हममें हमें घटाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं हम अपने मचित विदेशी मुद्रा कोष पर आहरण करके, और, विदेशी मुद्रा कोष एवं मिन देशों से बाह्यिक सहायता लेकर पूरा कर सकते हैं।

किन्तु यह भी सच है कि एक दीर्घकाल तक व्यापार-सन्तुलन का प्रतिबल रहना अवश्य ही चिन्ता की बात होगी। द्वितीय योजनावधि में जो भीषण घाटे हुए उनमें तो हमारी योजना के सटार्ई में पड़ने तक का मय उत्पन्न हो गया था। फिर मिन देशों के ऋणों पर अधिक निर्भर रहना उचित नहीं है, क्योंकि इसके साथ राज-नैतिक शर्तें जोड़ी जा सकती हैं। फिर अविष्य में ऋणों की अदायगी भी तो करनी होगी। अतः यह जरूरी है कि देशों उपभोग में मयासम्भ्रम मयम से काम लेकर और समुचित निर्यात-वृद्धि उपायों द्वारा व्यापार सन्तुलन की प्रतिबलता को स्थानम् सीमा तक घटाया जाय। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने यही नीति अपनाई थी। उसने आयात प्रतिबंधों को कड़ा किया, आयात-प्रतिस्थापन (Import substitution) एवं आयात-जमा (Import Deposit) योजनाएँ शरम्भ की तथा निर्यात सम्बर्धन के लिए निम्न कार्य किये —

(१) निर्यात सम्बर्धन परिपदों व निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना।

(२) निर्यात नियन्त्रण व कोटा पद्धति की समर्पित अधिकांश निर्यात शुल्क, रूढ़ता, वारंश-शुल्क की जापसी, निर्यात उद्योगों के कच्चे मालों के आयात के लिए विशेष लाइसेन्स देना। परिवहन सुविधाओं में प्रावधिकता देना।

(३) राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) के द्वारा कम्प्यूनिस्ट देशों से व्यापार बढ़ाना।

(४) बाजारों का अध्ययन करना विदेश प्रदर्शनियों में भाग लेना, द्वि-पक्षीय व्यापार समझौते करना विज्ञान एवं प्रचार के लिए विशेष आयोजन करना।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी होकर व्यापारिक सन्तुलन की प्रतिबलता कम हुई तथा भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हुआ। सन् १९५६-६० में हमें विदेशी मुद्रा कोष से केवल १६ करोड़ २० निकालने पड़े जबकि सन् १९५७-५८ में २५६.८ करोड़ २० निकालने पड़े थे। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष में स्थिति में पुनः बिगाड़ हुआ जबकि भुगतान सन्तुलन का घाटा सन् १९५६-६० में १८५ करोड़ २० से बढ़कर सन् १९६०-६१ में ३६९.४ करोड़ २० हो गया। इस वर्ष हम विदेशी मुद्रा कोष से ५६ करोड़ २० निकालने पड़े।

(IV) तृतीय योजनावधि में भुगतान सन्तुलन—

तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में भुगतान सन्तुलन का घाटा सन् १९६०-६१ की अपेक्षा कम रहा। किन्तु सन् १९६२-६३ में यह बढ़ने लगा। इस कारण भारतीय भूमि पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई संकटपूर्ण स्थिति थी। सन् १९६३-६४ में भुगतान सन्तुलन का घाटा ३३५ करोड़ २० था जबकि सन् १९६२-६३ में २००, ३०

मे ३४५ करोड़ २० था। सन् १९६४-६५ के लिए घाटा ४३७ करोड़ २० था। १९६५-६६ और इसके बाद घाटा भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण और देश में उत्पन्न हुए व्यापक खाद्य सङ्कट के फलस्वरूप इसमें भी अधिक वृद्धि मगा, जिस कारण रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। इससे स्थिति में सुधार हुआ, परन्तु कुछ विशेष नहीं। निर्यातों में सुधार की प्रवृत्ति अवमूल्यन के बाद प्रथम दो तीन महीने रही किन्तु इसके बाद गिरावट आनी आरम्भ हुई। अनुमान है कि निर्यात ५% कम हो गये। अब अप्रैल १९६८ में कुछ सुधार दृष्टिगोचर हुआ है।

हमारे भुगतान संतुलन पर दबाव पड़ना अनिवार्य है, क्योंकि देश की विकासात्मक आवश्यकताएँ भी विशाल हैं। जब हम इन दबावों से घबड़ाना नहीं चाहिये। हा, ऐसे सब सम्भव उपाय करने चाहिए जिनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने और घाटा न्यूनतम सीमा तक कम हो जाय। इस हेतु निम्न उपाय आवश्यक हैं—
(१) निर्यातों को अधिक से अधिक बढ़ाना, (२) आयातों को न्यूनतम रखना, (३) मित्र देशों व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना, (४) प्राइवेट विदेशी पूँजी की प्रोत्साहन देना, (५) कृषि के भुगतान की अवस्थाएँ पुन निर्धारित हो जायें (६) अतिरिक्त उत्पादन का एक भाग निर्यात के लिए सुरक्षित रखा जाय, (७) औद्योगीकरण की गति का कुछ जमियल किया जाय, (८) आयात-करो में वृद्धि के साथ आयात नीति को उदार बनाया जाय, (९) कृषि एवं सुरक्षा के बाद मशीन-मत्त आयातों को प्राथमिकता दी जाय, (१०) ड्यूटी वॉक ऑन इन्पुटीज की प्रथा में सुधार किये जायें, (११) उद्योगों की लुप्त (idle) क्षमता का उपयोग किया जाय, (१२) चौथी योजनाबद्धि के लिए मशीन-मत्त आयातों की आवश्यकता का मही-सही अनुमान लगाया जाय, (१३) प्रत्येक उद्योग अपनी आवश्यकता को अपनी निर्यात आय के द्वारा पूरा करने के लिए प्रयत्नशील बने।

विदेशी पार का भविष्य

निर्यात—

चीनी योजना के अधीन १९६७-६८ के १.१६६ करोड़ २० के निर्यात लक्ष्य को बढ़ाकर १९७३-७४ में १,६०० करोड़ २० करना है। अनुमान है चीनी योजना में निर्यात से ८,३०० करोड़ २० की कुल आय होगी। चतुर्थ योजनाकाल में निर्यात-व्यवस्था के मुख्य तत्त्व इस प्रकार होंगे—(१) देश में निर्यातित वस्तुओं के उत्पादन आधार का विस्तार। (२) जब तक पर्याप्त उत्पादन नहीं होता, तब तक व्यय पर अस्थायी नियन्त्रण लगाना। (३) समुद्रपार की माँग को पूरा करने के लिए माल की उत्पादन प्रणाली में सुधार करना। (४) किम्ब नियन्त्रण को मरुती में लागू करना तथा माल भेजने आने में पहले उसकी जाँच पड़ताल व निरीक्षण की व्यवस्था करना। (५) उत्पादन लागत में कमी करने के उपाय करना।

चीनी योजना के निर्माण में प्रमुखतया वृद्धि चाय, लौह धातुक, इन्जीनियरी सामग्री, जूट का सामान, फल व सब्जिया (जिसमें बाजू की गिर्य भी शामिल है)

वनस्पति घों (अगन्ध तेल), मक्खी, मछली, तम्बाकू (अनिमित्त), सूती कपड़े, लोहा व इस्पात, रसायन तथा तत्सम्बन्धी उत्पादनों में होगी। चीनी, काफी, मसाले, नारियल की जटाओं के मूल और उससे बनी वस्तुओं और दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में अपेक्षाकृत कम वृद्धि की सम्भावना है।

व्यापार मण्डल की एक उपसमिति द्वारा तैयार किये गये निर्यात नीति प्रस्ताव से प्राप्त (१९६८) में गतिशील निर्यात नीति की ओर देश की अर्ध-व्यवस्था में जाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं—(१) निर्यात के लिए अधिक ऊँचा विनिमय दरिद्रेक प्राप्त करने के उद्देश्य से विशेषतः कृषि, तान और औद्योगिक उत्पादनों के अंश में उत्पादन वृद्धि बढ़ाते रहना। (२) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए साधन जुटाने और विनियोग में प्राथमिकता। (३) बड़े हुए उत्पादन का उचित भाग निर्यात करने का निश्चय रहे इसके लिये प्रयत्न करना। (४) निर्यात के लिये सुविधाओं का विकास करना। (५) दीर्घकालीन आधार पर निर्यात की गति निर्बाध रखने के लिए कुछ वित्तीय राहते। (६) स्तर में लगानार सुधार और मूल्यों में कमी के द्वारा हमारी निर्यात वस्तुओं की प्रतियोगिता-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार व व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों प्रयत्न करें। (७) निर्यात सम्बन्धी विपणन सेवाएँ और संस्थाओं को सशक्ति करना और उनमें सुधार करना। (८) निर्यात के लिये अन्धरी शर्तों पर पर्याप्त धोर समय पर निम्नने वाले ऋणों की व्यवस्था। (९) निर्यात के लिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा सशक्ति प्रयत्न करना। (१०) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेशी मुद्रा साधनों के वितरण में सहायता देना। (११) विश्व के बाजारों में हमारे माल की बिक्री में होने वाली बाधाएँ हटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयत्नों का समर्थन करना।

आभाव—

चीनी योजना के अंशों आगत लक्ष्य १९६७-६८ के २,०११ करोड़ रु० से घटकर १९७३-७४ में २,०३० करोड़ रु० रह जायेगा। यह कमी साधारणों में आत्म-निर्भरता बढ़ाकर प्राप्त की जायेगी। अनुमान लगाते समय निम्नलिखित मान्यताएँ की गई थी—(१) कि निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। यदि लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी रहेगी तो आभाव की आवश्यकताएँ दृढ़ जायेंगी। (२) आगत पर लगाये गये वर्तमान प्रतिबन्ध योजना अवधि के दौरान लागू रहेंगे। (३) उपभोक्ता वस्तु-उद्योगों के लिए कच्चे माल का केवल उतना ही आयात किया जायेगा जितना कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से आवश्यक हो। (४) मिट्टी के तेल और अरबारी बायज जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में भाग की वृद्धि का रास्ता के लिए उपयुक्त उपाय लिए जायेंगे। (५) चीनी योजना के पिछले वर्षों में संयंत्रों के उत्पादन की क्षमता के लिए तत्काल कार्यवाही की जायेगी। (६) भारत में असीढ़ धातुओं के उद्योगों

म पितृययिता करन के लिए सभी सम्भव उपाय किए जायेंगे । (७) पूँजी पदांशों में सम्बन्धित उद्योगों को आयातित कच्चे माल और कल पृजों की माग पूरा रूप से पूरी की जायगी दश में उत्पादित मशीनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नीति सम्बन्धी कारगर उपाय अपनाये जायेंगे और कल पृजों के आयात को उदारनीति से दक्ष में निमित्त मशीनरी व उपकरणों के सभरण को बढ़ाने में सहायता मिलेगी और उनका उपयोग आयातित पूरा मशीनों या उपकरणों के स्थान पर किया जा सकेगा ।

परीक्षा प्रश्न

१. सन् १९४६ से भारत के विदेशी व्यापार की दिशा और रचना में जो परिवर्तन हुये हैं उनका विवेचन कीजिये ।
[Discuss the changes which have taken place in the direction and composition of India's Foreign Trade since 1939]
२. भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में युद्धोत्तर काल में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये ।
[Critically examine the postwar changes in the direction of India's foreign trade] (गौरव० एम० ए०, १९६८)
३. १९४७ के बाद भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य प्रवृत्तियों की आलोचना करिये । इनमें सविषय के लिये क्या सिद्धांत प्राप्त होती हैं ?
[Comment on the main trends in India's foreign trade since 1947. What lessons do they have for the future ?]
(इसाह० एम० ए० १९६८)
४. योजनावधि में भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों का विवेचन करिये । हाल में रुपय और स्टर्लिंग के अवमूल्यन ने भारत के विदेशी व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया है ?
[Discuss the trends in India's foreign trade during the Plan Period. How has recent devaluation of Rupee and Sterling affected India's foreign trade ?] (आगरा, एम० कॉम० १९६८)
५. भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति जो स्वतन्त्रता के बाद रही है उसकी संक्षेप में परीक्षा कीजिये । समय समय पर इसके सुधार हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं और वे कहां तक सफल हुये हैं ?
६. भारत की भुगतान संतुलन सम्बन्धी हाल की कठिनाइयों के क्या कारण हैं ? इन्हें हल करने हेतु अवमूल्यन और अन्य उपायों का विवेचन कीजिये

भारत की विदेशी व्यापार-नीति

(Foreign Trade Policy of India)

परिचय—

जिसो देश की विदेशी व्यापार नीति मुख्यतः 'व्यापार नियन्त्रण (trade control)' की धारणा से सम्बन्धित होती है। इसे भारत में सर्वप्रथम मई १९४० में एक युद्ध-उपाय (war measure) के रूप में प्रचलित किया गया था। इसके दो उद्देश्य थे—(i) निर्यात पक्ष पर, सरकार ने भारत से निर्यातों का नियमन इस प्रकार न किया कि युद्ध-कार्यों के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की पूर्ति सुरक्षित बनी रहे एवं साथ ही वस्तुओं शत्रु तक न पहुंचने पायें, और (ii) आयात पक्ष पर, सर्वोच्च प्राथमिकता उन वस्तुओं को दी गई जो युद्ध प्रयासों में सहायक हों, तथा अ-आवश्यक नागरिक उपभोग पर अकुश लगाया गया। महायुद्ध अगस्त १९४५ में समाप्त हुआ, किन्तु युद्धोत्तर काल में भी व्यापार का नियन्त्रण कुछ संशोधनों सहित जारी रखा गया, जिसमें कि आयातों का विवेकीकरण हो सके।

(I) आयात नीति

निर्दोजन के पूर्व आयात नीति—

आयात पक्ष पर सरकारी नियमन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है—

(१) विभाजन के पूर्व—युद्ध की समाप्ति के तत्काल बाद सरकार ने 'उन्मुक्त व्यापक लाइसेन्स' (Open General License) की नीति अपनाई, जिसके अनुसार विश्व के विभिन्न भागों से अनेक प्रकार की वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई। इस नीति के निम्न उद्देश्य थे—(i) ऐसी कई चीजों की पूर्ति बढ़ाना, जिनके विवे मांग अत्यधिक बढ़ी हुई थी, (ii) देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, (iii) मुद्रा प्रसारक दबाव को घटाना, एवं (iv) कोमलता में अधिक वृद्धि को रोकना। आयात नीति को उदार बनाने में स्टर्लिंग पावनों के सम्य से बढ़ी सहायता मिली जो कि उस समय १,७६६ करोड़ ६० के लगभग थे। उन आवश्यक वस्तुओं के आयात पर, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिये उस समय अपरिहार्य समझी गई विशेष बस दिया गया। अथवा विकासवात्मक किस्म (non development nature) की वस्तुओं के आयात के लिय भी छूट दी गई।

(२) देश विभाजन के फलस्वरूप आयात नीति में कठोरता—आयात व्यापार की सम्पूर्ण रचना अगस्त १९४७ में देश के विभाजन के बाद विदार रूप में बदल गई। विभाजन के कारण देश में बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जबकि मुँता वस्त्र और जूट के निर्माण उद्योग भारत में रह गए तब कच्चा जूट और कच्ची कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान को प्राप्त हुए। गेहूँ उपजाने वाले सरस क्षेत्र भी पाकिस्तान के भाग में आया। इस प्रकार भारत इस बात के लिये विवश हो गया कि वह विदेशी भाषाओं में कच्ची जूट, कच्ची कपास और खाद्यान्न का आयात करे। इस परिस्थिति का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि हमारे भुगतान सन्तुलन में विदेशी घाटे (Big deficits) रहने लगे।

आयातों में सहस्र वृद्धि होने की सरकार की आयात नीति पर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उन्मुक्त व्यापक लाइसेन्सिंग की नीति का, जोकि कुछ सीमा तक उद्धार थी, अब कठोर बनाया गया। कुछ कम आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाये गये। इस प्रकार, आयातों की उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति (upward trend) कुछ सीमा तक रक गई। किन्तु इस सम्पूर्ण अवधि में कच्ची कपास और कच्ची जूट के आयातों की अनुमति जारी रही जिससे कि दोनों महत्वपूर्ण उद्योगों के हित सुरक्षित रहे। साथ ही, सरकार ने सब प्रकार की मशीनों के आयात को प्रोत्साहित किया, जिससे कि देश के औद्योगीकरण को गति को बढ़ावा मिले।

(३) रुपये के अवमूल्यन के प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन के साथ, जोकि सितम्बर १९४६ में हुआ था, एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस अवमूल्यन ने भारत को अपने कुछ निर्यात उद्योगों, विशेषतः जूट और चाय उद्योगों की स्थिति को सुधारने में सहायता दी और अगले वर्ष (१९४७-४८) में व्यापार सन्तुलन की प्रतिफलता ४६ करोड़ ८० के स्तर तक घट गई। भारत को इससे भी अधिक लाभ होता किन्तु भारत-पाकिस्तान सम्बन्धी में तनाव आने से ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान सरकार ने अपनी मुद्रा का स्वर्ण में अवमूल्यन नहीं किया, जिससे भारत तक व्यापार में बहुत जटिलताएँ उत्पन्न हो गईं। कोरियाई युद्ध के आरम्भ पर (जून १९५१) निर्मित वस्तुओं और कच्चे मालों के लिये स्टॉक-मरहू सम्बन्धी माँग बहुत बढ़ गई, जिससे भारत में निर्यात तो बहुत बढ़े किन्तु आयात कम हो गये। किन्तु अचानक ही जलवायु सम्बन्धी यद्वाओं के बिगड़ने से भारत को कच्ची कपास और खाद्यान्न का अधिकाधिक आयात करना पड़ा। अतः वह कोरियाई युद्ध में उत्पन्न परिस्थिति का पूर्ण लाभ न उठ सका। उसके व्यापार सन्तुलन की प्रतिफलता १९५१-५२ में २३७ करोड़ ८० तक पहुँच गई।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयात नीति—

भारत में १ अप्रैल १९५१ में प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के शुभारम्भ के साथ ही साथ एक व्यापक आधार पर नियोजित विकास के प्रथम प्रथम चरण आरम्भ हुये। सरकार ने अपनी व्यापार नीति को इस प्रकार में समायोजित करने का यत्न किया कि

राजता के कार्यान्वयन में सुविधा हो जाय । 'नीति का निर्माण करने में सरकार को विभिन्न घटक विचार में लेने पड़े, जैसे—देश के औद्योगिक विकास की अवस्था, उसकी आवश्यकताएँ एवं आकांक्षाएँ, विदेशी विनिमय प्रसाधन अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व, निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता आदि ।'¹ देश के प्रगतिशील विकास के लिए सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों को एक प्राथमिकता आधार (priority basis) पर वितरित किया गया तथा आयात-यापार के नियमन में बड़ी ही सावधानी रखी गई ।

इस अवधि से आयात नीति इस तरह से समायोजित की गई कि देश के औद्योगिक विकास को अधिक प्रोत्साहन मिले । अतः उन वस्तुओं के आयात पर जिनके सम्बन्ध में देशी उत्पादन में यथेष्ट प्रगति कर ली थी प्रतिवध लगाय गये । कई महीने पर ड्यूटी में वृद्धि करके 'चुनीदा आयात नियन्त्रण' (selective import control) को तैयार अपनाई गई । इसके अनुसार पूँजीगत वस्तुओं तथा कच्चे मालों के आयात-को प्राथमिकता दी जाती रही तथा कम आवश्यक वस्तुओं के आयात को सीमित रखा गया ।

विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति में मुद्धार के कारण जो कि प्रथम योजना-वधि के मध्य भाग में समय हुआ आयात नियन्त्रण में पुनः कुछ ढील दी गई । चूंकि कृषि उत्पादन में यथेष्ट मुद्धार हो गया था इसलिए भाँडे रैमारे पर आयातों और कच्ची रुपयों के आयात की आवश्यकता न रही । १९५२-५३ से १९५४-५५ की तीन वर्षों अवधि में आयात-स्तर में कुछ स्थायित्व आ गया तथा वह यथेष्ट सीमा हो गया ।

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति—

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । चूंकि द्वितीय योजना के विकास कार्यक्रम कहीं अधिक बड़े थे, इसलिये पूँजीगत वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे मालों का बड़े रैमारे पर आयात करने की आवश्यकता हुई । योजनाकाल में विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति में बड़ा असंतुलन हो गया । यह वास्तव में उन दबावों एवं कठिनाइयों का सूचक था जो कि एक विकास प्रक्रिया की अपेक्षाएँ विनियमाएँ हैं । द्वितीय योजना के आरम्भ होने के एक वर्ष के भीतर ही विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति सराबोर हो गई जिससे सरकार को औद्योगिक राज-सामान के आयातों पर भी बड़ी निगरानी रखनी पड़ी । 'उत्पन्न व्यापक लाइसेंसिंग नीति' का स्थान वास्तविक प्रयोग कर्ताओं के प्रति प्राथमिकता वाली नई प्रणाली (system of preference to actual users) में ग्रहण कर लिया । यहाँ तक कि घट-हुए आयात नीते भी पुनः नवीकरणात्मक छूट गये । स्टील मशीनरी, स्टील-कच्ची रुपय, कर्मिक-आर इलेक्ट्रीकल गुड्स जोकि देश के उद्योगों के लिए बहुत ही

¹ "P. G. Sales New Directions in India's Foreign Trade, p. 17

आवश्यक थे उनको भी ख़येष्ट सीमित किया गया। अ-आवश्यक वस्तुओं का निर्यात कर दिया गया और अनेक आयातित निर्मित वस्तुओं के कोटे पर्याप्त घटा दिये गये। इस अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं का आयात तो ह्रृद्विह्वल का डींचा मात्र रह गया। इनमें रेशम कपड़ा कागज, फ़ोटोग्राफ़ी का सामान, घड़ियाँ आदि का समावेश था।

प्राथमिकता-क्रम—सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि सरकार ने महत्त्वपूर्ण और आवश्यक वस्तुओं के आयातों के लिए एक प्राथमिकता-क्रम त्रिचरित किया, जो इस प्रकार था—(i) बुनियादी उद्योग (जैसे कि स्थात एवं भारी इंजीनियरिंग) के लिए पूर्णतः नशीनरी और अत्यावश्यक पूर्ण संचालन के लिए सर्व अधिक मुविषय वेना तय हुआ, (ii) व्यापक रोज़गार प्रदान करने वाले तथा अविन्यक्त उपभोक्ता वस्तुओं बनाने वाले प्रमुख उद्योगों की भी बुनियादी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया, (iii) उन उद्योगों को भी प्राथमिकता दी गई, जिनहोंने अब तक दमोष्ठ प्रगति कर ली थी और इसलिये उन्हें निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये केवल अल्प आधातो की ही आवश्यकता थी, एवं (iv) ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, जोकि अपने आयातित पुता में काफी घटोती कर सकने में समर्थ थे।

द्वितीय योजनावधि में आयात नीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आयात की देशी उत्पादन के साथ सम्बन्धित (linking of imports with indigenous production) किया गया, अर्थात्, सरकार ने आयातों की मात्रा को देशी संसाधन तक घटाने का ध्यान किया जिससे कि गृह-उद्योग देश की आवश्यकतायें पूरा करने की स्थिति में बना रहे।

समय समय पर साधनों का भारी आशत करने की आवश्यकता का भी सरकार की आयात नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता रहा। प्रतिकूल जलवायु सम्बन्धी दशाओं के समय में सरकार को साधनों का ही नही बरत कच्ची कपास के पर्याप्त आयात की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे कि भारतीय वस्त्र उद्योग की आवश्यकता दूरी होती रह। ऐसी व्यवस्थाओं में P L 480 Loans उल्लेखनीय हैं।

एक विशाल उधार आयात नीति का लाभ उठाते हुए देश में अनेक नये उद्योग स्थापित हो गये तथा आयातों में वृद्धि हो गई थी। किंतु बिदेसी विनिमय सम्बन्धी जो कठिन स्थिति उत्पन्न हुई उसके सुधार के लिए सरकार का धन उपाय करने पड़े, जैसे— आयातों पर कड़ी देखरेख, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं भिन्न देशों में सहमता, स्थगित भुगतान प्रणाली (Deferred Payments System) के आधार पर आयातों को प्रोत्साहन देना एवं भारतीय उद्योगों में विदेशी पूँजी को भाग लेने के लिए निर्मोचक करना आदि।

तीसरी योजना की अवधि में आयात नीति—

तीसरी योजनावधि के लिये यह अनुमान था कि आयातों का वार्षिक मूल्य अंशतः १,२७० करोड़ रु० रहेगा। किन्तु चीन (और फिर पाकिस्तान) के आक्रमण के पक्ष-बहुप उत्पन्न हुई सुरक्षा आवश्यकताओं के सन्दर्भ में इस स्तर से भी अधिक

वृद्धि की आवश्यकता हुई। अतः सरकार को एक पूर्ण निर्धारित योजना के अनुसार आयातों का प्रवाह नियमित बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पड़े।

सब से यह है कि तीसरी योजना के आरम्भ से ही सरकार की आयात नीति ने अधिक प्रतिबन्धनात्मक रूप धारण कर लिया। उपभोक्ता-वस्तुओं का आयात लगभग रुक गया। मशीनों और महत्वपूर्ण पुर्जों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक (selective) हो गई। सरकार ने विदेशों विनिमय की शक्ति के अनुसार धरती प्राथमिकताओं निर्धारित करने का यत्न किया। चूंकि देश के विदेशी मुद्रा को एक स्थूलतः स्तर तक घटाने थे, इसलिए आयात नीति विदेशों से मिलती एक अन्य महत्वपूर्ण मितने की सम्भावनाओं पर आधारित की गई। केवल वही मशीनरी या पुर्जों वस्तुओं, जो कि देश में उपलब्ध नहीं की जाती थी आयात होने दो गई। तीसरी योजना के समय मकदमालीन परिस्थिति की घोषणा होने के साथ ही साथ सरकार की आयात नीति युद्ध प्रयासों की वृद्धि की दृष्टि से ढाली जाने लगी। इस प्रकार अब सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुकूल उत्पादन की सुधारण की दृष्टि से मशीनों के आयात की अनुमति दी गई। सितम्बर १९६२ में एक 'आयात प्रतिस्थापन समिति' (Imports Substitution Committee) का गठन किया गया। इसके जन्म से यह सर्वे करने का काम था कि किस उद्योगों में अब तक श्रमान बिदे जाने वाले पुर्जों आदि का उत्पादन करने को कहा जा सकता है।

एक समुचित आयात-नीति का विकास करने में टैरिफ समीक्षण न एक महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। टैरिफ-संरक्षण का प्रमाण देश के उद्योगों की रक्षा, सबंधन एवं स्थापना हेतु किया गया है। चूंकि टैरिफ समीक्षण के मुद्दों की स्वीकार करना या न करना सरकार की इच्छा है, इसलिए टैरिफ नीति भी समय-समय की आवश्यकतानुसार आर्थिक विकास के हवाला द्वारा निर्धारित की जा रही है।

आयात-अधिकार प्रदान करने वाली स्कीम

(Import Entitlement-Schemes,

निर्यातों को बढ़ाने हेतु अनेक विकल्पित एक विकासोन्मुख दशा न निर्यात-प्रोत्साहन स्कीम पिछले २०-२५ वर्षों में एक न एक रूप में प्रचलित की है। ऐसी प्रोत्साहन-स्कीमों में से एक स्कीम निर्यातकों को यह अनुमति देती है कि वे अपनी निर्यात-आमदनी या कुछ भाग या तो कतिपय निर्दिष्ट वस्तुओं का अथवा धरती स्वेच्छा को वस्तुओं का आयात करने में प्रयोग करें। उन्हें कभी-कभी यह भी, अनुमति होती है कि वे अपना आयात-अधिकारी साधनेवाले को खुले बाजार में अथवा इन लोगों को वेच दें जोकि निर्यात-वस्तुओं बनाने में आयातित-सामग्री का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी स्कीम सभी निर्यातों को लागू होती है चाहे वे किसी भी देश से आये, और कभी विशेष देशों से अथवा विशेष वस्तुओं के निर्यात मान को। सामान्यतः पिछले आयातों के आधार पर 'इम्पोर्ट एन्टाइटलमेंट साधने' दिए जाते हैं लेकिन ये अधिक भी दिये जा सकते हैं।

भारत न भी उक्त प्रकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना (I E S) को अपनाया है। यह स्कीम १९५० में प्रचलित की गई थी तथा ६ जून १९६६ को समाप्त कर दी गई थी। किंतु कुछ दिनों बाद ही पुनः प्रचलित कर दी गई। १९५०

यह केवल २ वस्तुओं को ही लागू होती थी किन्तु १९६५ में भारत के लगभग २०% निर्यात इसकी परिधि में थे। १९६६ में स्कीम को पुनः केवल हीरे जवाहरात और गहनों के लिए शुरू किया गया तथा अन्य वस्तुओं पर विस्तृत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। स्कीम का प्रमुख और आवश्यक विशेषता यह है कि निर्यातकर्ता C O B Value का एक निर्दिष्ट प्रतिशत निर्यात उत्पादन में प्रयोग होने वाले कच्चे मालों आदि का आयात करने में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के आय न ला देने में का नियन्त्रण स्वयं ही इच्छा करता कर सकता है अथवा बिना अन्य निर्यातों को बच सकता है। इस निर्माता का यह वायिब्य होगा कि वह स्वयं में निर्देशित उत्पादों का निर्माण और इसके एक भाग का निर्यात करे।

स्कीम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं — (अ) भारतीय उद्योग और व्यापार का विकास तथा देश के निर्यातों को विविधमुखी बनाने में सहायक होना (आ) निर्यात उद्योगों का अनुनिकतम् बनाना और उनकी अद्यतित कच्चे माल, पुर्ण आदि से सहायता करना (इ) देशी बाजार के लिए उत्पादन करने वाले निर्माताओं को अपना निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले निर्माताओं को ऐसे कच्चे मालों व पुर्णों की उदात्ति का एक निम्न योग्य साधन प्रदान करना एवं (ई) निर्माताओं को न केवल निर्यात हेतु बल्कि आन्तरिक बाजार हेतु भी उत्पादन करने की प्रेरणा देना। हम भी तब उद्देश्य की पूर्ति इस विश्वास पर आधारित है कि निर्माता/निर्यातकों को निर्यात करने में उठावें उसकी क्षतिपूर्ति आन्तरिक बाजार के लिए निर्माताओं की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ने से हो जायगी।

आयातों के सम्बन्ध में पूर्व जमा का आदेश—

रिजर्व बैंक ने यह आदेश जारी किया कि आयातकों को अपने आनेवाले विपश्य आयत के मूल्य का २५% जमा करना होगा। इस आदेश का उद्देश्य आयातों के लिए दौड़ (rush for imports) को रोकना है। जमा की आवश्यकता आयातकों को अपने आयात कार्यक्रम शर्तें खर्च करने के लिए प्रेरित करेगी और इस प्रकार राष्ट्र के अति अल्प विदेशी विनिमय कोष के शीघ्रतापूर्वक उपयोग पर रोक लगायगी। चूंकि आयातकों के रकबा प्रसाधन देश में डिवायिट के फलस्वरूप समुचित हो जायेंगे द्रायिन्ग आयातों की तावत भी बढ जायेगी। इससे भी आयातों के लिए दौड़ पर रोक लग्यी तथा 'सूट्टा जनित सम्बन्ध' में कमी होगी।

वित्तीय और आर्थिक क्षेत्रों में इस आदेश का अनावश्यक एवं कठोर बताया गया है। कहा गया है कि चूंकि सभी आयात योजना निर्देशित प्राथमिकताओं के अनुसार किए जाते हैं इसलिए उक्त आदेश अनावश्यक है। इस आदेश के फलस्वरूप आयातकों के बैंक से उठने वाले धन पर उपार लिये हुये प्रसाधन अनावश्यक ही 'बन्द'

हो जायेंगे । यदि सरकार आयातों को नियमित ही करना चाहती है तो इसके लिए वह अन्य उपयुक्त कदम उठा सकती थी ।

[प्रारम्भ में रिजर्व बैंक ने छ ध्रेणियों के आयातों को २५% मूल्य जमा कराने के आदेश से मुक्त किया तथा बाद को और भी झूटें दी हैं ।]

आयात नीति के विषय में सुझाव—

(१) आयात नीति ऐसी होनी चाहिये कि जो स्वस्थ आयात प्रतिस्थापन को मुहूर्त क्षण में सहायक हो और जो व्यापारियों व उद्योगपतियों को अपनी अत्यावश्यक सामग्रियां अपेक्षित सरभत्तापूर्वक प्राप्त करने में समर्थ बनावे । (२) औद्योगिक कच्चे मालों एवं पुर्जों पर आयात-कर घटाने चाहिये तथा आयात नियंत्रित नीतियां ओझल सम्बन्धी अपघि के लिये बनानी चाहिये । (३) विदेशी सहायता में कटौती की सम्भावना को हृदयगत रखते हुए राज्यों को चाहिए कि अपने आयात-कार्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण करे । कार्यक्रमों के चयन में खाद्यान्नों और सुरक्षा-आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिये । (४) आयातों को निर्यातों के साथ सम्बन्ध करना चाहिए अन्यथा आयातों वपों के स्विच रने गये मामूली विकास त्थय भी पूरे न हो सकेंगे ।

निर्यात-नीति

द्वितीय महायुद्ध की अवधि (१९३९-४५) में, विश्व के अधिकांश देशों की सरकारों के समक्ष भारत सरकार ने भी अपने निर्यात व्यापार पर कठोर नियन्त्रण लगा दिये थे । इतने पर भी निर्यात पर्याप्त बढ़ गये जबकि आयात बहुत ही कम हो गये । इस प्रकार, युद्धकाल में भारत ने विज्ञात राशि में स्टर्लिंग पावने सक्त्र कर लिये ।

युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों में निर्यात नीति—

युद्धोत्तरकाल में नियन्त्रणों को कुछ ढीला किया गया । किन्तु विभाजन के कारण देश के निर्यात व्यापार का स्वरूप एक बम ही बदल गया । वास्तव में भारत की स्थिति वही ही सङ्कटपूर्ण हो गई, क्योंकि उसकी तीन प्रमुख निर्यात वस्तुयें, जिन पर पिछले पचास दशान्दी में भारत का निर्यात व्यापार आधारित रहा था, विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुई । कच्ची कपास एवं कच्चे जूट का निर्यात सबसे अधिक कुप्रभावित हुआ । पाकिस्तान में कच्ची कपास मिलने में बहुत कठिनाई हुई जबकि भारत में कच्ची कपास के लिए माँग बढ़ती जा रही थी । फलतः भारत की कच्ची कपास के निर्यात की क्षमता बहुत घट गई । कच्चे जूट के सम्बन्ध में भी भारत पाकिस्तान पर निर्भर रहने लगा । चूँकि पाकिस्तान की हठधर्मी के कारण कच्चा जूट प्राप्त करने में कठिनाई हुई, इसलिए जूट के कारखाने, कच्चे माल के अभाव में, पूरी क्षमता में उत्पादन न कर सके । फलतः देश से जूट का निर्यात भी बहुत घट गया । अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी भारत की निर्यात स्थिति खराब हो गई ।

इन सम्मिलित समस्याओं के कारण निर्यात नीति का एक क्रान्तिपूर्ण मोड़ देना आवश्यक हो गया—निर्यात की मात्रा, मूल्य, रचना एवं वित्त सभी में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई। इन दिनों अमेरिकी बाजार का महत्त्व बढ़ गया था। उत्तर की रूमाई बढ़ाने के लिए भारत को अपने निर्यात ढाल-धौं में मोड़न पड़े।

यद्यपि भारत के निर्यात व्यापार का, मुख्य धीरे-धीरे बढ़ रहा था, तथापि उसका आयात व्यापार इसमें भी अक्षिप्त तैरती से बढ़ता जाता था। इसमें व्यापार संतुलन की प्रतिफलता अधिक बढ़ गई तथा भारत को कई सुधारात्मक उपाय करने पड़े। इन समय तक भारत को अपनी अधिकांश वस्तुओं का प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर निर्यात करने में कठिनाई अनुभव होने लगी थी। अतः सितम्बर १९४६ में स्टालिन के अवसूचन के साथ ही साथ भारत ने भी स्वर्ण में रुपये का अवमूल्यन किया ताकि भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ जाय। यह भी अनुभव किया गया कि कृषि उपाय में आयातों को घटा कर भारत अपने व्यापार संतुलन में नहीं सुधार सकता। अतः स्वदेशी उत्पादन के बढ़ाने पर अधिकारिण बल दिया गया, जिसमें कि एक ओर भारत के आयात घट सकें तथा, दूसरी ओर, देश की निर्यात सम्भावनाएँ बढ़ जायें।

निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जुलाई १९४८ में 'निर्यात प्रवर्धन समिति' (Export Promotion Committee) नियुक्त की। इसकी शिफारिशों के अनुसार सरकार ने कई वस्तुओं के निर्यात की शर्तों की उदार बनाया, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्यात के लिये अधिक सुविधायें प्रदान की गईं, कुछ औद्योगिक कच्चे सामान पर निर्यात ह्यूटिया समाप्त कर दी गईं, कुछ दत्तात्रय में कोटा प्रणाली को खत्म कर दिया गया, लाइसेंस देने की कार्यविधि को सुगम बनाया गया तथा प्रथम आगम प्रथम सेवा (First come, First served) का विहाय (कुछ उत्पादों की दशा में उच्चतम सीमा सहित) प्रचलित किया गया। अल्पसंख्यक और सरकार की उदार निर्यात नीति के फलस्वरूप भारतीय वस्तुओं के निर्यातों का मूल्य १९४८-४९ में ४५४ करोड़ रु० से बढ़कर १९४९-५० में ५१३ करोड़ रु० हो गया।

१९५० के मध्य भाग कोरियाई युद्ध छिड़ने से विश्व व्यापार के स्वरूप में अचानक ही परिवर्तन हुआ। चूंकि भारत के औद्योगिक कच्चे मालों के लिए माँग अचानक ही बढ़ गई, इसलिये इन वस्तुओं की कीमतें तीव्र गति से बढ़ने लगी। आन्तरिक और बाह्य माँगता में बहुत अन्तर हो गया। इस विषमता के कारण अनेक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो गई। अतः संभावित सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसने निर्यात व्यापार का पुनः नियमन किया।

पहली योजनावधि में निर्यात नीति—

जून १९५१ में कोरियाई युद्ध अचानक ही समाप्त हो गया, जिससे सरकार

की व्यापार एवं प्रमुख नीतियाँ म भी कुछ परिवर्तन करने आवश्यक हो गयीं। विदेश म क्रताओं के बाजार (buyer's markets) उदय होने पर सरकार ने निर्यात नीति को उदार बनाने का प्रयास किया। इस समय तक देश कई नए उद्योग स्थापित करने में समर्थ हो गया था और इनका निर्मित माल भी समुद्र पार के देशों को अतिरिक्त मात्रा में जाने लगा था। १९५०-५३ में निर्यातों में गिरावट आई। स्पष्टतः, यदि निर्यात को उदार करने के उपाय न अपनाये गये होते तो देश गिरावट और भी अधिक हो सकती थी।

१९५५ के मध्य में वृष्टि दबावे अनुकुल रहने से व्यापार मनुष्य की अनाम्यता को सुधारने में बड़ी सुविधा हो गई। उस समय सरकार ने यह अनुभव किया कि 'निर्यात प्रवर्धन' (export promotion) उसी व्यापार नीतियों का एक महत्वपूर्ण सहारा है। उस तक यूरोपीय देश अपनी मुद्रास्तरित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन कर चुके थे तथा विभिन्न प्रेरणाओं के अन्तर्गत निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। अतः इस अवधि में अनेक भारतीय वस्तुओं के निर्यात मात्रा में घटने की प्रवृत्ति दिलाई। मही नहीं, उसकी प्रतियोगिता क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। फलतः सम्पूर्ण निर्यात नीति का पुनर्निरीक्षण (review) करना जरूरी हो गया। निर्यातों का उदार बनाने के अतिरिक्त, सरकार ने आयातों का भी अल्प मात्राओं में निर्यात कर का प्रयत्न किया जो कि पिछले वर्षों से निषिद्ध थे। कई मद्रा के सम्बन्ध में निर्यात 'लाइसेन्स' निवृत्त करने की अवधि बढ़ा दी गई। निर्यात वस्तुओं में निर्माण में प्रयोग किए गए आयातित कच्चे माल पर चुकाई गई चुट्टी के लौगने (drawback of import duty) को सुधारा पड़ने का स्वीकृत की गई।

निर्यात प्रवर्धन का विभाग में सर्वत्र महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया था अक्टूबर १९५६ में 'निर्यात प्रवर्धन परिषद' (Export Promotion Council) की स्थापना करना था। उसी समय पर, भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने जूट व्यापार की सम्पूर्ण रचना का रिव्यू करने तथा उपयुक्त सफाई देने हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों को भेजा। १९५५-५६ में सरकार ने लम्बाई, चौड़ाई, अक्षर और प्लास्टिक के लिए निर्यात प्रवर्धन परिषदें स्थापित कीं। विद्यमान व्यापार के प्रवाह की बढ़ाने के लिए तथा निर्यात अर्थव्यवस्था वाले देशों से व्यापार की सुविधा के लिए 'राजकीय व्यापार निगम' (State Trading Corporation) स्थापित किया गया।

द्वितीय योजना में निर्यात नीति —

द्वितीय योजना में निर्यातों को अधिकतम करने (और इसके साथ ही आयातों में मितव्ययिता करने) की आवश्यकता पर बहुत बल दिया गया। निर्यातों को प्रोत्साहित देने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए। इसने १९५७ में एक निर्यात प्रवर्धन समिति (Export Promotion Committee) नियुक्त की, जिसके जिम्मे समस्या के सभी पहलुओं के अध्ययन का काम सौंपा गया था। इसने अन्य बातों के

साथ ही साथ निम्न बातों की भी विचारिश की थी—चाय पर निर्यात कर घटाना, कुछ वस्तुओं के आन्तरिक उपभोग में कमी करना, भारत-मित्र समझौते की भाँति अन्य देशों से भी व्यापार संधियाँ करना, निर्यात वस्तुओं पर बिक्री कर और उत्पादन कर लोड़ाना, कुछ दशाओं में निर्यात की जिम्मेदारी एक ही संगठन को सौंपना, शिपिंग सुविधाओं में सुधार करना। इसने निर्यात का लक्ष्य ७०० करोड़ रु० वार्षिक में अपर निर्धारित किया।

अन्य अनेक वस्तुओं (जैसे—मसाले, कैंचीबत्ता, सेन का सामान आदि) के लिये निर्यात परिपक्व स्थापित की गई। इनमें यह अनुरोध किया गया कि वे विभिन्न देशों में बाजारों का गहन सर्वेक्षण (intensive survey) करावें, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल भेजें, व्यापार सम्बन्धों प्रचार करें, आकांक्षे एकत्र करे, क्रिस्म और पैकिंग सम्बन्धी प्रमाण निर्धारित करें तथा निर्यात व्यापार पर लगे हुए प्रतिबन्धों के कारण जो झगड़े उदय हो उनमें पक्ष का कार्य करे, इन परिपक्वों के अतिरिक्त, सरकार ने कई वस्तु बोर्ड (Commodity Boards) भी कायम किये, जिनका उद्देश्य निर्यात वस्तुओं के सम्बन्ध में सूचना और सहायता प्रदान करना था। इसने अनेक वस्तुओं के निर्यातों पर से कस्ट्रोम हटाने का भी प्रयत्न किया।

सन् १९५७ के अर्ध भाग से अधिकाधिक निर्यातों की आवश्यकता ने विशेष महत्त्व धारण कर लिया। व्यापार संतुलन की बढ़ती हुई न्यूनता (gap) को कवर करने के लिए विशेष उपाय किये गये। सरकार ने लगभग २०० वस्तुओं के निर्यात पर से कस्ट्रोम हटा लिये, कई मंदों के सम्बन्ध में बड़े निर्यात कोटे स्वीकृत किये गये, देश के आन्तरिक भागों से बदरगाहों को निर्यात के लिए रेलों द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में उच्च प्राथमिकता दी गई, विदेशी बाजारों के भारतीय वस्तुओं को अधिक प्रतियोगात्मक बनाने के लिए प्रशुल्क रिमायटे दी गई, निर्यातकों को कच्चे माल और पुर्जों के आयात की सुविधा उनकी निर्यात क्षमता के अनुसार ही दी जाने लगी, एवं कुछ विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन भी किया गया। यही नहीं, चीनी उद्योग के लिए एक अनिवार्य निर्यात योजना बनाई गई, विदेश जाने वाले व्यापार प्रतिनिधियों की विनिमय गुविधायें उदारतापूर्वक दी गई, निर्यात-जोखिम, जिसे व्यापारिक बीमा कंपनियों द्वारा सामान्य स्वीकार नहीं किया जाता है, के लिए बीमे की सुविधायें देने हेतु एक राश्व-अधिकृत निर्यात जोखिम बीमा निगम (Export Risk Insurance Corporation) भी स्थापित किया गया।

निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण कदम 'क्रिस्म नियन्त्रण' (Quality Control) के रूप में उठाया। इस विषय में भारतीय मानक समीक्षा एवं विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन परिपक्व अच्छा कार्य कर रही है। विदग्धता से व्यापारिक मध्या व गुलझाने में भारतीय निर्यातिका को विभिन्न दशा निगुन भारत सरकार के वाणिज्य दूत सहायता करते हैं।

तीसरी योजनावधि में निर्यात नीति—

चूँकि तीसरी योजना में देश के औद्योगीकरण का उद्देश्य रखा गया था, इसलिए देश के आयातों में भारी वृद्धि होने की आशा थी। अतः एक 'संबन्धित निर्यात वृद्धि अन्दोलन' चलाया गया जिससे कि देश के बाह्य खाते में कोई गम्भीर बाधा-पड़ना न उत्पन्न हो सके। १९६२ में भारत सरकार ने एक 'बोर्ड ऑफ ट्रेड' (Board of Trade) स्थापित किया, जो कि कार्याविधियों को सरल बनाने के उपाय कर रहा है, प्रेरणाओं की अधिक उद्धार बना रहा है, और अधिक सार्व सुविधाएँ देने का प्रयत्न करता है। आशा है कि वह विदेशों में भारतीय हस्ताक्षरों में सम्बद्ध व्यापारिक विभागों के कार्य में सुधार एवं निर्यात वस्तुओं की लागतों में कमी कर सकेगा।

भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ाने के उपायों का मुकाबल देने हेतु मार्च १९६१ में एक आयात-निर्यात नीति समिति (Export-Import Policy Committee) नियुक्त की गई जिसके अध्यक्ष श्री रामानुजामी मुदातिवर थे। इसकी एक प्रमुख सिफारिश यह थी कि एक वार्षिक निर्यात योजना बनाई जाय, जिसमें कि उद्योग धर्म और वस्तु का धर्म से उचित लक्ष्य रखे जायें। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत 'निर्यात सम्बर्धन के निर्देशालय' (Directorate of Export Promotion) को पुनः संगठित किया गया है, जिसमें कि निर्यात-प्रोत्साहन की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा सके। निर्यात व्यापार के लिए एक आयात निर्यात स्थायीकरण कोष (Import Export Stabilization Fund) भी स्थापित किया गया है।

भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ अन्य कदम भी उठाये, जैसे— अधिक निर्यात सम्भावना वाली कुछ वस्तुओं की लागत सरचनाओं का बहुत अध्ययन करने हेतु एक 'लागत घटती समिति' (Cost Reduction Committee) बनाई, निर्यात क्षेत्र समिति (Export Sector Committee) ने पाँच अध्ययन दल स्थापित किये जो कि अपने-अपने वर्ग की वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन के समस्त पहलुओं का गहनता से अध्ययन करते हैं, इन्जीनियरिंग और प्लास्टिक के सामानों, बुनियादी कौमीकल्स, फार्मसी-वस्तुओं, चमड़े के सामान के निर्यात की प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात संवर्धन समितियाँ नियुक्त की गईं, इन्स्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (Institute of International Trade) की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन के समस्त पहलुओं में अनुसन्धान और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। एक 'निर्यात निरीक्षण औरामसंरक्षा परिषद' (Export Inspection Advisory Council) भी स्थापित की गई। कुछ वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में जहाजों में लदान के पूर्व किस्म निरीक्षण और नियन्त्रण की योजना भी चलाई गई। पञ्चीक निर्यात गृह (Export Houses) खोल गये। एक विपणन विकास कोष (Marketing Developing Fund) भी स्थापित किया गया। अन्तिम किस्म नियन्त्रण और जहाजों में लदान के पूर्व निरीक्षण के विवेक कानून बनाया

गया। 'क्षनित्र धातु व्यापार निगम' (Minerals and Metals Trading Corporation) की स्थापना भी की गई जो सनित्रों में राजकीय व्यापार के बट्टे दूने परियाण का नजानता है। बिभिन्न देशों से द्विपक्षीय टट्टराख करने की नीति की जारी रगा गया। इनन निर्यात के द्विविधीकरण पर तथा बिदेशी बिनिमय सम्बन्धी मिति को बिगाडे बिना ही अयात प्राप्ति करने को बल दिया जाता है।

निर्यात-साख सम्बन्धी सुविधायें—

स्मरण रहे कि निर्यात प्रोत्साहन केवल निर्यातकों को सस्ती और उदार साख सुविधायें देने की ही समस्या नहीं है। निगदेह इनकी अनुपस्थिति निर्यातकों को कठिनाई में डाल सकती है चाहे अन्य निर्यात-प्रोत्साहन दिये जाते रहे। आधुनिक वर्षों में अलग्गनीय अधिकार-पत्रों के बिरुद्ध निर्यात-साख स्वीकृत करने की परम्परा का स्थान, केतालों के बाजार के उदय और निर्यात बाजारों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के कारण, 'उदार शर्तों पर साख देने की नीति' ने ले लिया। मक्ष समस्या यह है कि निर्यात सम्बन्धी साख सस्ती एव प्रतियोगितात्मक शर्तों पर दी जाये। साथ ही व्यापारिक, राजनैतिक एव बिस्तीय जोखिमों के बिरुद्ध बीमे की, अथवा, अन्य प्रकार की गारण्टी भी दी जाय। इस बिधा में जो प्रगति हुई है उसका चर्चित बिबरण एव अगले अध्याय में दिया गया है।

निर्यात के रूप यह कहा जा सकता है कि देश की बिदेशी व्यापार सम्बन्धी नीति भली प्रकार मचायित है और बहुत ही सतोपजनक प्रभावित हुई है। किन्तु इनन पर भी व्यापार में साम्य की स्थापना नहीं हो सकी है। इसका कारण यह नहीं कि नीति दोषपूर्ण है बरन् यह है कि लेनी से बिश्वास करने के उद्देश्य वालों प्रद-ध्यक्षन्या में भुगतान मतुलन में अयाम्यता रहना स्वाभाविक है। बीबी पोन्न-काल में निर्यात बढ़ाने हेतु बिरोध प्रबल निचे जायेंगे। इन पर एक अथले अध्याय में प्रकाश डाला गया है।

आयात-निर्यात वापार मज्जूठन सम्बन्धी अध्ययन दल की शिफारिशें

(१) हर वर्ष सरकार की निर्वाण नीति के बारे में एक रिपोर्ट पुस्तक-रूप में प्रकाशित की जाय, जो ६ माह के निर्यात व्यापार के बारे में हो। (इस मुद्राव को सरकार ने स्वीकार कर लिया है)।

(२) भारतीय व्यापार सेवा नियुक्त की जाय। (इसे भी सरकार ने मिश्रान्तर्ग मान लिया है)।

(३) निर्यात नीति में उन सम्भावित मिश्रान्तों का उल्लेख होना चाहिए जिनका निर्यात बढ़ाने में उपयोग होता हो। उसम मिश्र-मिश्र बीजों के बारे में भी मकेत होना चाहिए जिनके लिए प्रार्थनापत्रों पर तननीरी अधिकारियों एवं प्रशासन-मन्त्रालया में बिचार-विमर्श किया जाना हो। सामान्य सिहाबनोरन के लिए आक-मिक परिवर्तनों की आवश्यकता हो, तो सार्वजनिक सूचना से नीति में सगोधन किया जा सकता है।

(४) सामान्य रूप से जिन वस्तुओं का निर्यात नहीं होता है उनके निर्यात की अनुमति देने का निर्णय सावधानीपूर्वक विचार-विनिमय के बाद किया जाना चाहिए । ऐसी अवस्था में निर्यातित वस्तुओं के व्यक्तिगत शिपिंग-बिलों की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में कस्टम अधिकारियों को जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर निर्यात की अनुमति देने की छूट होगी चाहिए । यदि जरूरी समझ आए, तो इस प्रकार के लाइसेंसों की संख्या-अवधि सीमित हो सकती है ।

(५) यदि व्यक्तिगत शिपिंग बिलों को पृष्ठांकन की जरूरत पड़े, तो कस्टम्स में इन मामलों को अपने साथ लेने की प्रार्थना की जा सकती है ताकि इस अवस्था में निर्यातकों को कस्टम्स व लाइसेंस-अधिकारियों दोनों से निबटारा न पड़े ।

(६) किसी वस्तु को निर्यात-वृद्धि को प्रोत्साहन देने की योजना में समिलित करने के लिए अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि अमुक वस्तु के निर्यात पर नियन्त्रण है या नहीं । यदि नियन्त्रण है तो उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि इस प्रकार के नियन्त्रण को जारी रखना आवश्यक है या नहीं । इस प्रकार की वस्तुओं पर नियन्त्रण तभी रहना चाहिए जबकि उसका औषध हो ।

(७) अधिक व कम रकम की जांच करने के लिए एक पृथक समिति नियुक्त की जाय । निर्यात-प्रोत्साहन लाइसेंस की विधि को और भी सरल बनाने के लिए सरकारी की गई है ।

(८) सधु-स्तरीय क्षेत्र के उद्योगों के ऐसे मामलों में जिनमें मशीनरी आगने या इसके विस्तार के लिए आयातित कच्चे माल की जरूरत नहीं है, उद्योगों के राज्य निर्देशक की पूर्ण की सिफारिश की जरूरत नहीं है । ऐसी अवस्था में डी० सी० (एग० रस० पी०) द्वारा आवश्यकता प्रमाणित की जानी चाहिए ।

(९) वाणिज्य लाइसेंसों की मुविधा सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं की भी मिलनी चाहिए, ताकि वे कच्चा माल आसानी से आयात कर सकें ।

(१०) अध्ययन दल ने अफगानिस्तान से माल आयात करने के लिए कस्टम्स-क्लिपरेस परमिट जारी करने के निमित्त 'पास बुक' प्रणाली का सुझाव दिया । प्रत्येक पार्टी को एक 'पास-बुक' देने से कार्य में सुविधा होगी । इसमें पार्टी द्वारा आयातित न निर्यातित माल का उल्लेख होना चाहिए तथा अन्य पार्टियों से सौदे दिए गए निर्यात का मूल्य भी इसी में अंकित होना चाहिए । यह पास बुक लाइसेंसिंग कार्यालय में पार्टी द्वारा हर तीसरे महीने पेश की जानी चाहिए । रिजर्व बैंक को सिर्फ स्वीकृति प्राप्त आयातकों के निर्यात व आयात का ही हिसाब-किताब रखना चाहिए ।

(११) आयात (नियन्त्रण) आदेश के 'बचत' अनुच्छेद में दिए गए प्रति-बन्धित सामान की सूची विस्तृत की जाए ताकि ट्रान्जिस्टर, टैप-रिकॉर्डर व अन्य ऐसा सामान जो बहुत बड़ी मात्रा में पहने आयातित किया जाता था, इसमें शामिल किया जाए ।

(१२) यह भी सुभाष दिया गया है कि आयात नीति द्विबीजन का तीन इकाइयों में विभाजन होना चाहिए ।

वर्तमान आयात-निर्यात नीति

केन्द्रीय सरकार ने १९७०-७१ के लिए अपनी आयात निर्यात नीति घोषित कर दी है, जिसके अनुसार ३८ और वस्तुओं का आयात सरकारी एजेंसियों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है । कुछ मिलाकर आयात और निर्यात में सरकारी राज्य व्यापार निगम सनित्र व धातु व्यापार निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील की भूमिका को बड़ा दिया गया है ।

निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने तथा निर्यात की मर्यादनाओं के लिए अधिक सुविधायें दी गई हैं और लघु उद्योगों का अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है । लघु उद्योगों के लिए उन की जरूरतों के लिए आयात के हेतु तिहाई विदेशी मुद्रा स्वीकार की जाती थी अब उसे बढ़ा कर पचास प्रतिशत कर दिया गया है । १५९ ऐसी वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया गया है जो अब देश में ही और अच्छी किंमत की तैयार होने लगी है ।

राज्य व्यापार निगम और सनित्र तथा धातु निगम अनेक वस्तुओं के लिए कच्चा माल आयात करेंगे जो वास्तविक निर्यातियों को दिया जायेगा । प पीकले निर्यातक अपना आयात लाइसेंस उक्त निर्यातों को स्थानांतरित कर सकेंगे । दोनों निगमों द्वारा आयातित वस्तुओं का बिक्री मूल्य विदेश व्यापार मंत्रालय के आम नियमों में बड़ी निगम तम करेंगे । जिन ३८ अतिरिक्त वस्तुओं का आयात सरकारी निगम करके उनका १९६८-६९ में मूल्य ३६ करोड़ १० लाख । इन पाउडर-बद्ध कुछ दवाइयों तथा रेशम विशेष स्टेनलेस इस्पात की पी शीट और टीन की हैं ।

आयात निर्यात में सरकार क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका दम्बई कॉर्पोरेशन से प्रस्तावों के प्रकाश में है ।

दोनों सरकारी निगम निर्यात प्रयत्नों को बितरित, बिक्री सबंधी और अन्य सामान्य सहायता देने का अपना क्षेत्र और भी बढ़ायेंगे । निर्यात के लिए उत्पादन करने वाले संस्थाओं की मशीनें आयात कराने के लिए कुछ उदार नीति अपनाई जायगी और वर्तमान क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी पूँजी लाने के आवेदनों पर भी उदारता से विचार दिया जायेगा । निर्यात में अच्छा कीर्तिमान स्थापित करने वाले संस्थानों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा । उत्पादन का १० से २५ प्रतिशत तक निर्यात करने वाले संस्थानों को मशीनें के स्रोतों और क्षमता विस्तार की विशेष सुविधायें मिलेंगी ।

सन्तु उद्योग में नए संस्थानों के लिए आरंभिक आयात लाइसेंस की सीमा ५० हजार १०० म बढ़ाकर ७५ हजार १०० कर दी गई है । वर्तमान संस्थान भी इसका लाभ उठा सकेंगे ।

उन्मुक्त वाइमेंत नीति के अन्तर्गत काजू, खालें आवि का आयात, जो पहले हो अनुमित है, जारी रहेगा ।

जिन वस्तुओं को अनुमित सूची से हटा दिया गया है और जिनका आयात बन्द कर दिया गया है उनमें अनेक किस्म की मशीनें, इस्पाती रस्से वास्तवधारिण, विजली के जनेत्र उपकरण, हाथीदांत, जायफल दातनीनी, इत्यादि कायर्दृष्ट्य वास्त्व, कारतूस आदि १५६ वस्तुएँ हैं ।

विदेशी व्यापार सचिव श्री कृष्ण बिहारीलाल ने नई नीति की व्याख्या करते हुए बताया कि विदेशी मुद्रा की अच्छी स्थिति के कारण (कुल सुरक्षित मुद्रा ६१८ करोड़ ₹० मूल्य की है) कुछ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की जरूरत पूरी की जा सकती है । उन्होंने बताया कि गत वर्ष सन्तु उद्योगों का निर्यात क्षेत्र में अधिक अच्छा प्रदर्शन रहा । कुल ६५८ संस्थानों में ५ जिन्हें पुरस्कार के लिए मुद्रा की गई योजना में शामिल किया गया था ४६५ सन्तु उद्योग के संस्थान थे । इसमें आने से भी कम बड़े उद्योगों में थे ।

परीक्षा प्रश्न :

- १ भारत की १९४८ से आज तक जो विदेशी व्यापार नीति रही है उसका संक्षिप्त विश्लेषण कीजिये । इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं ?

[Discuss briefly the Foreign Trade Policy of India from 1948 to the present day. What improvements would you suggest in it ?]

- २ माननावधि में सरकार की आयात-निर्यात नीति की प्रमुख विशेषताये बताइये ।

[Bring out the salient features of Import-Export policy of the Government of India during the Plan Period]

(आगप, एम० कॉम०, १९६६)

- ३ देश के नियोजित आर्थिक विकास के सदर्भ में भारत की विदेशी व्यापार संबंधी नीति की प्रमुख विशेषताये बताइये ।

[Give the main features of India's foreign trade policy in the context of the planned economic development of the country]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

भारत की प्रशुल्क नीति

(India's Tariff Policy)

परिचय—१९२३ के पूर्व स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण

समझ किसी भी देश में उद्योग वहाँ की सरकार की सक्रिय सहायता के बिना प्रगति नहीं कर सके हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा जाता है कि जपान में राज्य आधुनिक उद्योगों का 'धर्म-पिता' है। इसी प्रकार, जर्मनी में भी औद्योगिक विकास राज्य के पालन-पोषण के अन्तर्गत ही सम्भव हुआ था। दुर्भाग्यवश भारत की स्थिति इससे भिन्न रही है। यहाँ राज्य देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के दारे में ग़ुनाहिक तटस्थ रहा। नि सन्देह ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने देशी उद्योगों का प्रोत्साहन तो दिया किन्तु उसने ऐसा अपने ही स्वार्थ के लिए किया था और यह नीति भी अल्पकाल की गई जबकि ब्रिटिश राज ने भारत का शासनसूत्र कम्पनी के हाथों से अपने हाथ में ले लिया। तब से विदेशी सरकार ने एक 'स्वतन्त्र व्यापार की नीति' (policy of laissez-faire) अपनाई जो भारत के हित में न होकर मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन के उद्योगों के ही हित में थी। उन दिनों आयात-कर लगाये तो जाते थे किन्तु इनका उद्देश्य देशी उद्योगों का संरक्षण प्रदान करना नहीं था बल्कि सरकार की रकबू में बृद्धि करना था।

प्रथम महायुद्ध के समय में पहली बार इस बात का अनुभव हुआ कि विकासोन्मुख ब्रिटिश साम्राज्य के लिए औद्योगिक दृष्टि में निर्धन भारत सहायता का स्रोत होने के बजाय सतरे का स्रोत हो सकता है। अतः यहाँ कुछ उद्योगों की स्थापना करना बाध्यता समझा गया। तदनुसार सन् १९१६ में एक 'औद्योगिक आयोग' (Industrial Commission) नियुक्त किया गया, जिसने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। किन्तु, ब्रिटिश सरकार भारत को प्राथमिक स्वशासन देने को तत्पर नहीं थी। अतः एक 'ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी' (Joint Select Committee) समझौता का कोई उचित समाधान ढूँढ़ने के लिए नियुक्त की गई।

प्राशुल्क स्वशासन का प्रस्ताव

(The Fiscal Autonomy Convention)

सक्त कमेटी ने एक समझौता परस समाधान खोजा, जो यह था — "भारत

के लिए सही प्राथुलिक नीति कुछ भी हो किन्तु इतना तो निश्चित ही स्पष्ट है कि उस अपने हितों पर विचार करने की यही स्वतन्त्रता होनी चाहिये, जो कि ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, न्यूजीलैण्ड कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका को है। अब समिति को राय है कि भारत सचिव की इस विषय पर उस दशा में जबकि भारत सरकार और उसकी विधान सभा में मतभेद हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, और जब उसे कोई हस्तक्षेप करना ही पड़े तो यह साम्राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने तक ही सीमित होना चाहिए।”

यह सुझाव ‘प्राथुलिक स्वशासन के प्रस्ताव’ के नाम से विख्यात है। इससे पूर्व तक ब्रिटिश संसद ही देश के लिए प्रचलित नीति निर्धारित किया करती थी। किन्तु १९०१ से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर, भारत एक स्वतन्त्र प्रचलित नीति अपनाने के लिए मुक्त हो गया। किन्तु प्रस्ताव की व्यावहारिक उपयोगिता नहीं के बराबर थी। भारत सचिव को यह आदेश दिया गया था कि वह तब ही हस्तक्षेप करे जबकि भारत सरकार और विधान सभा में मतभेद हो। चूँकि व्यवहार में मन्त्रिमण्डल ही कभी हुआ (क्योंकि भारत सरकार एक अनुसूचीय विदेशी नौकरशाही थी जबकि विधान सभा भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करती थी,) इसलिए भारत सचिव को हस्तक्षेप करने का अवसर बार-बार मिला।

भारतीय प्रचलित आयोग, १९२१

भारतीय जनता ने प्रस्ताव की बहुत आलोचना की। अब, फरवरी १९२० में विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सरकार से भारत के लिए प्रचलित नीति के प्रश्न पर विचार करने [] एक प्रचलित आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। तदनुसार १९२१ में एक भारतीय प्रचलित आयोग (Indian Fiscal Commission) नियुक्त हुआ। इसमें जिम्मे यह काम था कि वह सभी (भारतीय + ब्रिटिश) हितों के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रचलित नीति की जाँच करे और साम्राज्य अधिमान अपनाने की वांछनीयता पर भी सम्मति दे। इस आयोग ने, बहुत से, भारत के लिए ‘विभेदात्मक संरक्षण की नीति’ का सुझाव दिया।

विभेदात्मक संरक्षण (Discriminating Protection)

विभेदात्मक संरक्षण का अर्थ एवं स्वभाव—

भारतीय प्रचलित आयोग ने पूर्ण संरक्षण की नीति का, जो कि बिना भेद-भाव प्रत्येक उद्योग को लागू की जा सके, सुझाव नहीं दिया था। संरक्षण में जो खतरे निहित होते हैं उनसे बचने तथा उपनात्काओं पर संरक्षण का न्यूनतम योग्य होने के लिये आयोग ने यह सुझाव दिया कि केवल ‘योग्य’ (deserving) उद्योगों को ही संरक्षण दिया जाय। कोई उद्योग संरक्षण पाने का अधिकारी है या नहीं इसकी परख के लिए आयोग ने कुछ शर्तें निर्धारित कर दी थी, जिनका पूरा होना आवश्यक था। वे शर्तें मुख्यतः तीन थी और सामूहिक रूप से ‘त्रिसूत्रीय फार्मूला’ (Triple

Formula) के नाम से विख्यात है। (१) उद्योग ऐसा होना चाहिये जिसे कि प्राकृतिक सुविधाएँ (natural advantages) प्राप्त हों, जैसा कच्चे माल की सस्ते की पूर्ति होना, सस्ती शक्ति की सुविधा होना, श्रम की पर्याप्त पूर्ति मिलना और विशाल गृह बाजार की विद्यमानता। (२) उद्योग ऐसा होना चाहिए जो कि संरक्षण की सहायता के बिना देश के हित में बाधनीय ढङ्ग से विकसित नहीं हो सकता हो। (३) उद्योग ऐसा होना चाहिये जो कि अन्तिमत्त, संरक्षण के बिना भी, विदेशी प्रतियोगिता का सामना कर सकता हो।

उपरोक्त तीन मुख्य शर्तों के अतिरिक्त आयोग ने कुछ सहायक शर्तें भी निश्चित की थीं। इन्हें भी संरक्षण की स्वीकृति के पूर्व पूरा किया जाना आवश्यक था। उदाहरणार्थ, जिस उद्योग में 'बढ़ती हुई उपज का नियम' क्रियाशील है उसे उस उद्योग पर प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें कि 'घटती हुई उपज का नियम' क्रियाशील हो। इसी प्रकार, सुरक्षा एवं बुनियादी उद्योग को संरक्षण के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निश्चय हुआ। उन उद्योगों को भी प्राथमिकता देने का सुझाव था जो कि कालान्तर में समस्त स्वदेशी माँग को पूरा कर सकें।

त्रिसूत्रीय फार्मूला देश के हितों के विरुद्ध—

यह त्रिसूत्रीय फार्मूला देश में बहुत ही बड़ो आलोचना का विषय बना और इसमें निम्नलिखित दोष बताये गये —

(१) भारतीय हितों की अपेक्षा ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान—कमीशन के सदस्यों ने ब्रिटिश हितों का अधिक ध्यान रखा। यत वे भारतीय हितों के अनुकूल एक उचित प्रत्युक्त नीति निर्धारित नहीं कर सके।

(२) कठोर शर्तें लगाना—त्रिसूत्रीय फार्मूले के रूप में जो शर्तें आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी वे बहुत कठोर और भ्रमपूर्ण थीं। केवल कुछ ही उद्योग इन्हें सम्पूर्ण रूप से सम्पुष्ट कर सकते थे। भारत में, अनेक सुविधाएँ निम्न केवल उदाहरण के रूप में गिनायी गयी थी, संरक्षण स्वीकार करने के लिए कठोर शर्तें लगा दी गईं :

(३) दूसरी शर्तें एक स्वतः सिद्ध बात थी—वास्तव में इसे एक शर्त नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि यदि विदेशी प्रतियोगिता न हो, तो उद्योग संरक्षण क्यों मंगेगा। यही नहीं, पहली और तीसरी शर्तें व्यवहार में एक समान थी और इनका सामूहिक आशय यह था कि ऐसे किसी उद्योग को संरक्षण नहीं दिया जावेगा जो कि समाज पर हानि न कर सके। वास्तव में पहली शर्तें तीसरी शर्त का एक स्पष्टीकरण मात्र थी किन्तु इन्हें अलग-अलग रूप दिया गया था।

(४) संरक्षणवाद के इतिहास में एक अमृतपूर्व कठोरता—जैसा कि आयोग के अन्वय में की रिपोर्ट में बताया गया था, किसी भी अन्य देश में इतनी कठोर शर्तें लागू नहीं की गईं जितनी कि भारत में आयोग ने संरक्षण के लिये उद्योग का चयन

करने के सम्बन्ध में रखी थी। उन्हें किसी भी भाँति इस देश के औद्योगिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता था।

(५) सामान्य आर्थिक विकास के साधन के रूप में प्रयोग न होना—विभेदात्मक संरक्षण की नीति में एक मौलिक दोष यह था कि इसे सामान्य आर्थिक विकास का एक साधन (an instrument of general economic development) नहीं बनाया गया। वरन् कुछ उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धिता का सामना करने की सामर्थ्य प्रदान करने को एक उपाय मात्र ही समझा गया। किन्तु इस रूप में भी संरक्षण तब ही दिया जा सकता था जबकि उद्योग स्वयं इसके लिए प्रार्थना करे। यह इष्टिजनों वृत्तिवादी उद्योगों के विकास में कदापि सहायक नहीं हो सकता था।

अतः यह स्पष्ट है कि विभेदात्मक संरक्षण की नीति बहुत ही मनोवर्ण (hostilating) थी।

विभेदात्मक संरक्षण व्यवहार में—

सरकार ने विभेदात्मक संरक्षण की नीति को स्वीकार कर लिया और इसे कार्यान्वित करने का भी यत्न किया। इस नीति की सफलताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) उद्योगों का अभूतपूर्व विस्तार—अनेक उद्योग (जैसे—सीह एव स्पात, सूती वस्त्र, चीनी, चाय और चाय की नुदो, दिग्बलाई एव मँगनीशियम फ्लोराइड) संरक्षण के फलस्वरूप बहुत विस्तृत हो गये। इनमें से चीनी उद्योग का ही संरक्षण के पूर्व लगभग नहीं के बराबर अस्तित्व था, किन्तु १९३२ में इसे संरक्षण मिलने के पाँच वर्षों के भीतर ही यह उद्योग इतना तेजी से बढ़ा कि वह समस्त देश की माँग को पूरा करने लगा।

(२) सहायक एव सम्बद्ध उद्योगों का विकास—कई सहायक एव सम्बद्ध उद्योग (विशेषतः सीह एव स्पात तथा सूती वस्त्र से सम्बद्ध उद्योग) भी विकसित हो गये।

(३) मन्दी का सामना करने में सहायता—यह संरक्षण के ही कारण था कि संरक्षित उद्योग ने केवल विस्वव्यापी भयंकर मन्दी के श्रृंखले सह सके, वरन् इस बटिगाई पूर्ण अवधि में उन्होंने कुछ विस्तार भी कर लिया। जबकि अन्य उद्योगों ने भारी हानि उठाई।¹

(४) कृषि पर अनुकूल प्रभाव—विभेदात्मक संरक्षण की नीति कृषि के लिए भी लाभदायक प्रमाणित हुई। कारण संरक्षण की प्रेरणा से सूती वस्त्र उद्योग का अत्युत्पन्न विकास हुआ जिसने ऊँची कीमत वाले मध्यम एवं लम्बे रेशे, कपास, क जपादन या बहुत प्रोत्साहित किया। प्रति एकड़ उपज भी काफी सुधर गई।

विभेदात्मक संरक्षण की नीति की कुछ बलपन्नताएँ एवं दुर्बलताएँ भी सामने आईं, जो कि इस प्रकार हैं —

¹ L. C. Jain *The Working of the Protective Tariffs in India*, p. 14.

(१) **असंतुलित विकास**—केवल तौह एवं स्यात उद्योग को छाड़ कर अन्य सब उद्योग जिन्होने विभेदात्मक संरक्षण से लाभ उठाया उपभोक्ता वस्तुयें बनाने वान उद्योग ही थे । पूर्णोद्यत वस्तुयें बनाने वाने उद्योगो के विकास पर कोई ध्यान नही दिया गया । इस उपेक्षा के ह्रा कारण एक व्यापक आधार वाना संतुलित औद्योगिक विकास सम्भव नही हो सका ।

(२) **भोद्य उद्योगो के दावो को अस्वीकृत करना**—इन नीति ने एक व्यापक दृष्टिकोण के बजाय संकुचित दृष्टिकोण ही अपनाया । अर्थात्—इसने केवल कुछ उद्योगो को विद्वाना प्रतियोगिता में बचाना वा समस्या पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया । त्रिमूर्तोय फासू ने की कठोर दनों के कारण अनेक योग्य उद्योगो को संरक्षण के लिए उचित माग को भा अस्वाइड टरिफ बोर्डों द्वारा ठुकरा दिया गया । जिन उद्योगो को संरक्षण नही दिया गया था उनमें स्फूत रसायन तेल कोयला, सामिट और काच प्रमुख थे । भारतमें ॥ विभिन्नात्मक संरक्षण का नीति को महत्कार ने इस प्रकार से लागू किया गया था कि संरक्षण दना मन्तान दग से अस्वीकृत कर दिया गया । उदाहरणार्थ भारत में तेन उद्योग को बर्मी गैल शुप और स्टड्ड जामल कम्पनी में कीमत युद्ध के कारण भार्ये हानि उठानी पड रही थी जिससे विवग होकर इस उद्योग ने मर् १९२८ में संरक्षण के लिये प्रायना पत्र दिया किन्तु वह अस्वीकृत हो गया क्योंकि कामत युद्ध सरकार और टैरिफ बोर्ड की सम्मति में भारतमें उपभोक्ताओ के अहित में नही था ।

ऐसा ही व्यवहार सीमट उद्योग क साथ हुआ । प्रथम महायुद्ध काल में बि गो में आयात बंद हो जाने से उस प्राकृतिक संरक्षण मिल गया जिससे उद्योग में विशेष उत्तति कर नी थी । किन्तु युद्ध के बाद उसे पुन नष्ट प्रतियोगिता का सामना करना पडा तथा वह १९०४ में विनष्ट होने की स्थिति पर पहुच गया । विदेशी प्रतियोगिता के अनिरिक्त रैमवे आदि की नीति थी सीमे ट के निषणन में साधक हो रही थी । दश में सीमे ट के उपादव के लिए समस्त प्राकृतिक सुविधाए (उदाहरण क निचे कृता पत्थर मिट्टी जित्तम पयाप्त सत्ता भ्रम आदि) प्राप्ता थी । इन सुविधाओ के उपलब्ध होते हुए भी उद्योग को सरकार द्वारा इस आधार पर संरक्षण नही दिया गया कि वह उद्योग राष्ट्रीय हितों के साथ गति नही रखता था ।

(३) **नीति के कार्याचयन का दोषपूर्ण दग**—प्रयुक्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि एक स्पाई (Permanent) टरिफ बोर्ड गठित किया जाय किन्तु वास्तव में केवल अस्थाई (ad hoc) टरिफ बोर्ड ही गठित किए गए । अतः टरिफ बोर्ड ने सदस्यो में बार बार परिवर्तित होना पडा था जिससे कि वे साधनामान र्क श्रेणों केकर वाय बली कर सकते थे । न तो सदस्यो को कुछ अनुभव मच्य हो पाता था और न वे टैक्नीक और वायविधि में ही कुशलता ला सकते थे ।

(४) **संरक्षण देने में विलम्ब**—नीति के वास्तविक वायकरण में दूसरा ग गोर दोष यह था कि संरक्षण के लिए प्रायना पत्रों पर विषय देने में बहुत विलम्ब

हो जाता था जिससे कि मध्यान्तर काल में उद्योगों को भारी हानियाँ उठानी पड़ती थी।

(५) विदेशी हितों का प्रभाव—भारत के प्राबुल्क इतिहास में मेनचर्वेस्टर के पूर्वोपस्थितियों का प्रभाव 'व्यापक' रूप से दिखाई देता था। 'वि भारतीय बाजार को ब्रिटिश निर्माताओं व्यापारियों, बैंकरों और जहाजी कंपनियों के लिये उसी प्रकार सुरक्षित रखना चाहते थे जिस प्रकार कि अमेरिकन पूर्वोपस्थित अमेरिकन बाजार को अपने लिये रखते हैं।'¹

उपरोक्त दोषों के सम्बन्ध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने विभेदात्मक संरक्षण की 'विभेद युक्त किन्तु संरक्षण रहित' (Discrimination and no protection) की विन्नेयन दिया है। परिणामों की दृष्टि से इसकी सफलताएँ उन सफलताओं के सम्मुख, जो कि जापान में संरक्षण की नीति ने दिखाई है अति 'गुच्छ' है। श्री० बी० पी० अदारकर के शब्दों में—'हमने उद्योगों को बहुत ही अधश्चरे दम में, सकोच-पुष्क तथा अपूर्ण सहायता दी है और उन्हें प्रायः अपने पैरों पर ही खड़ा रहना पड़ा है।' प्रशुल्क आयोग (१९४०) ने भी अपनी रिपोर्ट में विभेदात्मक व्यवहार के विषय में लिखा था कि, 'पिछले आयोग ने संरक्षण को समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया उसमें एक मौनिक दोष था। उसने संरक्षण की एक सामान्य आर्थिक क्रिया का साधन नहीं माना बल्कि एक ऐसा साधन मान ही सम्मता जो कि कुछ विशिष्ट उद्योगों को ही विदेशी प्रतिस्पर्धिता का सामना करने में सहायक बनाय। इसी नृति के कारण देश का अ-सन्तुलित विकास हुआ और यहाँ बुनियादी और प्रमुख उद्योग विपश्चित न हो सके। सब तो यह है कि सहायक एवं सम्बद्ध उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधायें दी ही नहीं गई, जिससे कि समाज पर संरक्षण का आवश्यकता में अधिक भार पड़ा।'²

**युद्धोत्तर काल में भारत की प्रशुल्क नीति
अन्तर्गम टेरिफ बोर्ड एवं पुनर्गठित टेरिफ बोर्ड—**

द्वितीय महायुद्ध में भारत के औद्योगिक विकास की दुर्बलताएँ सरकार के समक्ष आईं। कारण, यहाँ अत्यावश्यक उद्योगों के अभाव के कारण युद्ध प्रयासों में बड़ी बाधा पड़ी थी। यही नहीं, युद्ध ने उद्योगों की एक प्राकृतिक संरक्षण प्रदान

¹ Dr. Buchanan *Development of Capitalistic Enterprise in India*, p. 465

² It has vouchsafed nothing better than a perfunctory assistance, indifferently and grudgingly rendered to industries whose subsequent development has been left to take its own course "

—B P Adarkar.

³ *Fiscal Commission Report (1950)*, p. 49

कर दिया या क्योंकि विदेशी आयात स्वतः घट गये थे। अतः अब भारतीय उद्योग-पति यह चाहते थे कि इस लाभप्रद स्थिति को बनाये रखा जाय। वे नय उद्योग स्थापित करना चाहते थे किन्तु उनको यह भय था कि युद्ध की समाप्ति पर उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धिता का पुनः सामना करना पड़ेगा। अतः सरकार ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह लड़ाई खत्म हो जाने के बाद भी “युद्ध जनित उद्योगों” को समुचित संरक्षण दनी रहेगी। इस वचन को पूरा करने के लिये ही सरकार ने १९४५ में एक अन्तरिम टैरिफ बोर्ड (Interim Tariff Board) नियुक्त किया और इसे युद्धकाल में प्रारम्भ किए गए उद्योगों की समस्या पर विचार करने तथा तीन वर्ष की अवधि के लिए संरक्षण दर की सिफारिश करने का कार्य सौंपा। इस टैरिफ बोर्ड ने ४२ उद्योगों का संरक्षण दर का सुझाव दिया जबकि प्रार्थना ४९ उद्योगों द्वारा की गई थी। यह अस्थाई टैरिफ बोर्ड १९४७ में तोड़ दिया गया तथा इसके स्थान पर एक नया पुनर्गठित टैरिफ बोर्ड गठित किया गया जिसे कुछ अतिरिक्त कार्य (additional functions) भी सौंपे गए।

द्वितीय प्रभुत्व आयोग (Second Fiscal Commission)

स्वतः अतः के पश्चात् यह अनुभव किया जाने लगा था कि देश के औद्योगिक विभाग को एक नियोजित ढङ्ग से सञ्चालित करने हेतु देश की प्रभुत्व नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने १९४८ के अपने औद्योगिक नीति प्रस्ताव (Industrial Policy Resolution of 1948) में कहा कि ‘टैरिफ नीति अनुचित प्रतियोगिता को रोकने तथा उद्योगों पर अत्यायुक्त भार डाले बिना ही भारतीय प्रमाधनों का प्रयोग करने की दृष्टि से बनाई जायगी।’ साथ ही सरकार ने यह भी घोषित किया कि वह देश की दीर्घकालीन टैरिफ नीति के विषय में परास्परिक देव हेतु एक प्रभुत्व आयोग नियुक्त करेगी।

तदनुसार सन् १९४९ में श्री टी० टी० कृष्णामाचारी की अध्यक्षता में द्वितीय प्रभुत्व आयोग, नियुक्त किया गया। इसने सन् १९४२ से लेकर सन् १९४८ तक विधेदात्मक संरक्षण के कार्यवाहन की परीक्षा की तथा सभी नीति के विषय में भी विचार किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सन् १९५० में दी। कृष्णामाचारी प्रभुत्व आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुमुखी विकास की सुविधा के लिए भारत की प्रभुत्व नीति में ज्ञान्तिकारी परिवर्तनों के सुझाव दिये।

नई प्रभुत्व नीति की विशेषताएँ—

इस नई प्रभुत्व नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थी—

(१) एक व्यापक दृष्टिकोण—कमीशन ने संरक्षण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। अब टैरिफ संरक्षण को मुख्यतः एक ‘सहाय’ की प्राप्ति का ‘गापन’ माना जाता है अर्थात् इसे देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने वाले साधनों में

से एक साधन माना गया है। फलतः उद्योगों को, आखिर विकास की एक व्यापक योजना की पृष्ठभूमि में, संरक्षण दिया जाता है।

(२) बुनियादी मार्ग-दर्शक सिद्धान्त—कृष्णामाचारी आयोग ने कुछ बुनियादी सिद्धान्त भी निर्धारित किये, जो संरक्षण स्वीकृत करने या न करने के विषय में मार्ग-दर्शन करते हैं। ये सिद्धान्त निम्न हैं—संवारी का उन्मूलन उत्पादकता में प्रगतिशील वृद्धि, प्राकृतिक प्रसाधनों का पूर्णतम उपयोग, कृषि एवं उद्योग का तेजी से विकास एवं एक विविधीकृत अर्थ-व्यवस्था (diversified economy) का निर्माण।

(३) उद्योगों का वर्गीकरण—यद्यपि विकासात्मक नियोजन द्वितीय प्रमुख आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही आरम्भ हुआ तथापि आयोग ने अपनी सिफारिशों इस तरह से दी थी कि वे एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकें। उसने संरक्षण देने की दृष्टि से उद्योगों को तीन वर्गों में बाँटा—(अ) सुरक्षा एवं अन्य सामरिक उद्योग (Defence and other strategic industries,—इनके विषय में कमीशन ने यह सुझाव दिया कि इनको संरक्षण देने की क्षात्रता चाहिए जो भी आवे इसके प्रत्येक दशक में संरक्षण देना चाहिए क्योंकि वे हमारी नव-प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। (ब) आधारभूत एवं प्रमुख उद्योग (Basic and key industries)—इस श्रेणी के उद्योगों के लिए टैरिफ कमीशन को चाहिए कि संरक्षण की गतों और सीमा नियत करदे तथा समय-समय पर इनकी प्रगति की जाँचता रहे। इसके संरक्षण देने में किसी भी उद्योग को बाधक नहीं बनने देना चाहिये। (स) अन्य उद्योग (Other Industries)—तीसरी श्रेणी में अन्य सब उद्योग सम्मिलित किए गये। इनके लिये टैरिफ कमीशन यह निर्णय करे कि उन्हें संरक्षण दिया जाय या नहीं। संरक्षण सम्बन्धी निर्णय आर्थिक सुविधाओं पर, जोकि उद्योग को प्राप्त हों, इसकी संभावित लागत पर एवं राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से उद्योग के महत्त्व पर निर्भर होगा। इस प्रकार, किसी भी उद्योग को संरक्षण देने या न देने का निर्णय अब राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में ही लिया जाता है।

(४) सामान्य सिद्धान्त स्पष्ट रूप से निर्धारित करना—कमीशन ने कुछ सामान्य सिद्धान्त भी निश्चित किए हैं जिनका टैरिफ कमीशन को मर्यादाशक्ति पालन करना चाहिए—(i) यदि किसी उद्योग की आर्थिक सुविधायें (जैसे आन्तरिक बाजार, श्रम पूँति आदि) प्राप्य हैं, तो केवल इस आधार पर ही संरक्षण अन्वीकृत नहीं कर देना चाहिए कि उसके लिए अच्छा मान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। (ii) न केवल विद्यमान (existing) यह बाजार को बरत एक संभाव्य (potential) निर्यात बाजार को भी विचार में लेना चाहिए। (iii) संरक्षण मागने वाले उद्योग से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह समस्त यह बाजार की मांग को पूरा करे। (iv) जिस नये उद्योगों में भारी पूँजीगत विनियोग की आवश्यकता पड़ती है, उनके मामलों पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए तथा उन्हें यथा-

सम्भव संरक्षण देना चाहिए । (v) संरक्षित उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगों को 'अतिपूरक संरक्षण' (Compensatory protection) दिया जा सकता है । (vi) यदि आवश्यक प्रतीत हो तो कृषि उद्योग को भी एक बार में अधिकतम समय ५ वर्ष तक, संरक्षण दिया जा सकता है । (vii) सामान्यतः, संरक्षण वाला से सम्बद्ध उद्योगों पर उत्पादन करों का भार नहीं डालना चाहिए ।

उपरोक्त सामान्य सिद्धान्तों ने उन दुर्बलताओं को दूर कर दिया है जो कि ब्रिटिश युग में अपनाई गई विभेदात्मक संरक्षण की नीति में मौजूद थे । ये टैरिफ बोर्ड को व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं जिससे कि वह उद्योगों को, राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से तथा नियोजित अव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार समुचित संरक्षण दे सके ।

(५) विकास कोष (Development Fund)—आयोग का यह भी सुझाव था कि संरक्षण कर लगाने में जो रैवेन्यू प्राप्त हो उसमें से एक विकास-कोष स्थापित किया जाय और फिर इसमें से योग्य (Deserving) उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाय । स्मरण रहे कि कुछ परिस्थितियों में आर्थिक सहायता देना टैरिफ संरक्षण की तुलना में अधिक लाभप्रद है ।

(६) टैरिफ कमीशन—अब तक यह होता था कि जब-जब किसी विशेष उद्योग में संरक्षण के लिए प्रार्थना की, तब तब एक विशेष या अस्थायी टैरिफ बोर्ड नियुक्त कर दिया जाता था और जब वह अपना निर्णय दे देवे तो तब उन्हें भग कर दिया जाता था । ऐसी दशा में संरक्षण की स्वीकृति के उपरान्त जो निरोधन सम्बन्धी उपाय अपनाने आवश्यक थे वे नहीं अपनाय जा सकते थे । इस कोष को एक स्थायी संस्था की नियुक्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता था । प्रस्तुत आयोग ने यह सुझाव दिया कि ऐसी संस्था को 'टैरिफ कमीशन' कहना चाहिये और अन्य कार्यों के साथ ही साथ इसके निम्न प्राग भी होने चाहिये—संरक्षण करों में परिवर्तनों का सुझाव देना कानूनी रूप से कराना, संरक्षित उद्योगों के कारखानों की जांच करना तथा यह चेक करना कि उन्होंने समाज के प्रति अपना कर्तव्य किस सीमा तक पूरा किया है । कमायन की प्रति बीसरे वर्ष एक रिपोर्ट भी देनी चाहिये । कमीशन में एक स्थायी स्टाफ रखा जाय जिसमें आर्थिक अनुसन्धान के लिए टेक्नीकल स्टाफ भी होना चाहिए ।

(७) सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय की आवश्यकता—कृष्णामाचारी अयोग ने इन बातों पर बल दिया कि सरकार को टैरिफ कमीशन की सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्यवाही करनी चाहिए । निर्णय लेने में उसे साधारणतः दो महीने से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए । भूतकाल में असाधारण विलम्बों के कारण ही नव स्थापित उपरान्त की बहुत क्षति हुई एवं हानि सहनी पड़ती थी ।

(८) अ-प्रभुत्विक उपाय (Non-fiscal measures)—शीघ्र औद्योगिक विकास के दिन में यह आवश्यक था कि प्रभुत्व नीति के प्रभाव को घटाने के लिए

उद्योगों में सहाय्यार्थ अन्य अ-प्राथुलिक कदम भी उठाये जायें। ऐसे कदमों के बारे में टैरिफ कमिशन का सूचित रखा जाना चाहिए, जिससे कि इनकी प्रगति के सम्बन्ध में ही वह उचित अ-प्राथुलिक उपाय अपना सके। इस प्रकार, प्राथुलिक एवं अ-प्राथुलिक उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम—

- ५ सरकार ने सुरक्षण के उक्त नये दृष्टिकोण और नवीन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और लगभग सब ही सिफारिशें मान ली। वास्तव में, भारत सरकार को प्रभुत्व नीति कृष्णामाचारी आयोग के मुझावों के अनुसार ही निर्मित हुई है। इसी के अन्तर्गत सन् १९५२ में एक स्थाई टैरिफ कमिशन स्थापित हुआ। इसने सदस्यों की संख्या ३ से ५ तक बढ़ी गई है जिनमें से एक सदस्य बेगमर्बन होता है। विशेष आशयों के लिए अधिक में अधिक दो अतिरिक्त सदस्य भी रखे जा सकते हैं। विशिष्ट जांच पड़ताल में कमिशन की सहायता करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न अमेसरो (assessors) की भी नियुक्ति की जा सकती है। आयोग एक अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) संस्था है तथा इस भावे यह लोगो को गवाहों देने के लिये बुला सकती है, उन्हें दाय्य दिवाकर जांच सकती है तथा कामगारों को प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकती है। कमिशन का कर्तव्य, क्षेत्र बहुत ही व्यापक रखा है। प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं—(i) उद्योगों के, जिन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है, सुरक्षण सम्बन्धी दावों (claims) पर विचार करना। (ii) कृषि एवं अन्य उद्योगों के लिये सुरक्षण देने के प्रश्न पर विचार करना। (iii) टैरिफ दरों में वृद्धि करने के अतिरिक्त अन्य उपायों (जैसे कच्चे मालों के सम्बन्ध में रियायती कर और आर्थिक सहायता) द्वारा सुरक्षण देने की प्रायोजनाओं पर विचार करना। (iv) कीमतों और जीवन-मापन के व्ययों पर सुरक्षण के प्रभावों के विषय में तथा सरक्षण-भारमन या रेवेन्यू-करो के फलस्वरूप उदय हुई कठिनाइयों के विषय में जांच करना तथा रिपोर्ट देना। (v) कुछ प्रकार की जाचें अपनी इच्छा से करना। (vi) सुरक्षण की अवधि का निर्णय करना। (vii) कुछ विशेष वस्तुओं की कीमत के बारे में जांच करना, चाहे यह वस्तु सुरक्षित हो या नहीं। (viii) निम्नलिखित विषयों के बारे में जांच-पड़ताल करना—बस्टम या अन्य सुरक्षण करो में घटत या बढ़त करने के आशय से जांच करना, राखितपतन या सुरक्षित उद्योगों द्वारा सुरक्षण से अनुचित लाभ उठाने के मामलों की भी जांच करना। (ix) सामान्य कीमत स्तर, जीवन-मापन के व्ययों तथा देश की अर्थ-व्यवस्था पर सुरक्षण के सामान्य रूप से पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करना। (x) सुरक्षणात्मक करो के कार्यवाहन से उदय होने वाली कठिनाइयों पर विचार करना। (xi) सुरक्षण पाने वाले उद्योग की उत्पादन लागत, उत्पादन का पैमाना, किस्म भावी विस्तार की सम्भावना तथा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के सम्बन्ध में उसे दिये गये सुरक्षण के प्रभावों की समय-समय पर जांच करते रहना।

टैरिफ कमिशन के कार्यकलापों का विवरण—

विद्युत बर्षों में टैरिफ कमिशन के कार्यकलापों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि इसने अपने उद्देश्य के अनुसार वाचरण किया है। १९५६-६० के अन्त तक इसने कुल १६६ जाच पड़तालें की थी जिनमें से १६ उन उद्योगों के सम्बन्ध में भा थी जिनहीं नये मरक्षण के लिए प्रार्थना की थी २४ कीमत सम्बन्धी जाचें (price enquiries) थी १ जाच सरकार द्वारा TISCO और HSCO को दिये जाने वाले श्रृंखला पर व्याज दर के सम्बन्ध में और १२५ जाच वर्तमान मरक्षण को जारी रखने के सम्बन्ध में थी। १९६०-६१ में कुल १४ टैरिफ जाच पड़तालों (tariff enquiries) और २ कीमत जाच (price enquiries) हुई थी। १९६१-६२ में ६ टैरिफ जाच पड़ताले और ४ कीमत जाचें हुई और १९६२-६३ में भी इतनी ही टैरिफ एवं कीमत जाच की गई। १९६३-६४ में टैरिफ कमिशन द्वारा १७ टैरिफ जाचें तथा २ कीमत जाच की गई थी। १९६४-६० में टैरिफ कमिशन ने ६ टैरिफ जाच और १ कीमत जाच पूर्ण की थी। १९६१-६७ में पांच टैरिफ जाच पड़ताले और तीन कीमत जाच-पड़तालों की गई। १९६७-६८ में ३ कीमत जाचें और १ टैरिफ जाच की गई। इन जाच पड़तालों के आधार पर ही कमिशन सम्बद्ध उद्योगों को मरक्षण देता सरक्षण की अवधि को बढ़ाता और समाप्त करता रहता है।

मूल्यांकन—

कमिशन की सिफारिशों पर जिन उद्योगों को पहली बार सरक्षण मिला है उनमें निम्न महत्वपूर्ण उद्योग सम्मिलित हैं—औटोमोबाइल्स एवं तत्सम्बन्धी गुर्जे वाल बिजनेस औटोमोबाइल हैंड टायर इन्फ्लेटर्स पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्स फोर्मर ट्रिट्मिंग हाइड्रोवोलाइजिंग कास्टिक सोडा क्लोरीन वाउडर हाजीनिंग स्टोन फाइनस और कंस्ट्रक्शन-कार्बाइड। कमिशन द्वारा की गई विभिन्न जाच पड़तालों के विश्लेषण में यह पता चला है कि सरक्षण को जारी रखने के हेतु प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों की संख्या बहुत अधिक है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि टैरिफ कमिशन प्रारम्भ में प्रायः एक अल्प अवधि के लिए ही सरक्षण देना स्वीकार करता है। अब उससे सरक्षण बढ़ाने के लिए बार-बार अनुरोध किया जाता है। निःसन्देह सरक्षण की अल्प अवधि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है किन्तु साथ ही हमें यह याद रखना चाहिए कि यह उद्योगपतियों को अपने कोषों का नये उपक्रमों में निविनियोजन करने से रोकती है।

अर्थव्यवस्था के सुरक्षित भाग (protected sector) में देश के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण योग देना आरम्भ कर दिया है। इन उद्योगों के उत्पादन में जोमत औद्योगिक उत्पादन की अपेक्षा कक्षा अधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त मरक्षण उद्योगों में कीमतें अधिक नहीं बढ़ सका है जबकि अन्य उद्योगों में कच्चा माल हो गई है। इनके उत्पादकों का निष्पन्न भी गिरावर सुधार हो रहा है।

वास्तव में वर्तमान टैरिफ कमिशन के कार्यकलाप श्रृंखलाओं अस्थाई टैरिफ

घोटों के कार्यक्षमता की अपेक्षा अधिक सराहनीय है। आशा की जाती है कि पिछले वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है वह कमीशन को प्रशुल्क नीति का संचालन इस ढङ्ग से करने में सफल बनावेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था के तेज और सन्तुलित विनाम में सहायता मिले। डॉ० बी० के० आर० चौ० राव की अध्यक्षता में तटकर आयोग (Tariff Commission) के काम के बारे में समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट पर सरकार ने निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं — (क) जिन उद्योगों से सरक्षण हटा लिया गया है उसके दो सीमा श्रृंखला बाढ़ उनकी स्थिति की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिये। (ख) अनुविहित मूल्य नियमन लागू करने के लिये (कृषि जिन-या के अतिरिक्त) मूल्य की जांच का काम आमतौर पर तटकर आयोग को सौंपा जाना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में जब तदर्थ समितियाँ नियुक्त की जायें तो उन्हें भी तटकर आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का सहयोग देना चाहिये। (ग) यद्यपि कीमतें कम करने पर विचार रखना आयोग का काम नहीं होना चाहिये, पर जांच करने समय उस यह पता लगाना चाहिये कि उद्योग की लागत अधिक क्यों है और उसे कम करने के लिये क्या उपाय अपनाये जा सकते हैं।

यहाँ सरक्षण विषयक एक नई प्रवृत्ति का उल्लेख करना आवश्यक न होगा। सरक्षित उद्योगों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष घटती जा रही है। इसका कारण यह है कि द्वितीय और तृतीय योजनावधियों में औद्योगिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य द्वारा उद्योगों को विभिन्न प्रकार से आर्थिक सहायता आवि दी गई और फिर उत्तरोत्तर गिरती हुई भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी दशा के सुधार के लिए सन् १९५७ में आयात के सम्बन्ध में कठोर नीति अपनाई जा रही हैं, जिससे उद्योग अब सरक्षण के आश्रित नहीं रह गये। अन्य शब्दों में, सरक्षण हमारी राष्ट्रीय नीति का एक स्वाभाविक एवं स्थायी कार्यक्रम बन गया है।

श्री एस० मुबहाण्णम की अध्यक्षता में नियुक्त तटकर पुनर्विचार समिति (Tariff Revision Committee) ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि (i) भारत के व्यापार और इसके विकास की आवश्यकताओं के अनुसार आयात सीमा-शुल्क के निर्धारण के ढङ्ग की आवश्यक फेर बदल करके ब्रूसेल्स तटकर नियमों के अनुरूप बनाया जाय। (ii) नये उपशोर्षक सोलते समय परिसोषित भारतीय व्यापार वर्गीकरण को ध्यान में रखा जाय। (iii) सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अनुसूचियाँ यथासम्भव एक ही होनी चाहिये ताकि उनके प्रशासन और व्याख्या में एकरूपता आ जाय। समिति ने सशोषित सीमा शुल्क तटकर अनुसूची के आधार पर सशोषित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तटकर अनुसूची का प्रारूप भी तैयार किया है। समिति ने अब आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के संशोधन का काम हाथ में लिया है।

परीक्षा प्रश्न :

- १ विभेदात्मक संरक्षण का अर्थ एवं इसकी क्रियाविधि को समझाये । यह भारत के औद्योगिक विकास को गतिमान बनाने में वहाँ तक सहायक है ?

[Explain the meaning and working of discriminating protection. How does it help in accelerating the industrial development of India ?]

- २ टैरिफ संरक्षण मौलिक रूप से एक सफल की प्राप्ति का साधन और नीति को लागू करने का एक उपकरण है जिसे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रयोग करना चाहिए ।" इस कथन की परीक्षा करिये और भारतीय प्रभुत्व आयोग १९५० की सिफारिशों पर प्रकाश डालिये ।

[Tariff protection is primarily a means to an end—one of the instruments of policy which the state must employ to further economic development of a country." Examine this statement and discuss the recommendations of the Indian Fiscal Commission 1950 ?]

- ३ भारत सरकार की वर्तमान प्रभुत्व नीति किन सिद्धान्तों पर आधारित है ? इस नीति ने १९४९ से किस तरह कार्य किया है ?

[What are the principles on which the present protection policy of the Indian Government is based ? How has this policy worked since 1949 ?]

- ४ भारत की वर्तमान प्रभुत्व नीति की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये और यदि आवश्यक हो, तो सुधार के लिये सुझाव दीजिये ।

[Give a critical review of India's present fiscal policy and offer suggestions for modification if necessary.]

निर्यात संवर्धन

(Export Promotion)

प्रारम्भिक—

भारत को विदेशी मुद्रा अर्जित करने की विशेष आवश्यकता है, विशेषतः ऐसी स्थिति में जबकि विश्व का कुल निर्यात तेजी में बढ़ रहा है और उसमें भारत का योग निरन्तर कम हो रहा है। विश्व के कुल निर्यात में भारत का निर्यात प्रतिशत १९५५-५६ में १.३८% था जो १९६५-६६ में कम होकर ०.९१% रह गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि इसका अर्थ यह है कि भारत के निर्यात व्यापार में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी कि दुनिया के कुल निर्यात व्यापार में। भारत का निर्यात व्यापार कुल आयात व्यापार के प्रतिशत के रूप में १९५५-५६ में ७.८% था जो १९६५-६६ में ५.७२% रह गया। यही स्थिति भारत के निर्यात-व्यापार की राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में है। भारत का निर्यात व्यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में १९५५-५६ में ६.१ था जो १९६५-६६ में कम होकर ४.० रह गया। स्पष्ट है कि भारत का निर्यात व्यापार तेजी में बढ़ाने की आवश्यकता है अन्यथा हम अपने आयात व्यापार के लिये पर्याप्त धन नहीं जुटा सकेंगे।

आगामी कुछ वर्षों तक निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता सर्वसुखी बनी रहेगी। सावधानी से विश्लेषण करने पर यह पता चलेगा कि निर्यात व्यापार राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर एक कठोर अनुशासन लागू करता है और यदि हम राष्ट्र की प्रगति करना चाहते हैं, तो यह अनुशासन हमें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना होगा। वास्तव में, परम्परागत एवं अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को वदेष्ट माना में बढ़ावा हमारा एक पुनीत राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह हमारे निर्माताओं और व्यापारियों की योग्यता की कसौटी है। वर्तमान में हानि सहकर भी हमें निर्यात बढ़ाने चाहिये, क्योंकि इससे देश की भावी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होना है तथा हम सभी को अब सन्तोष करने के मोठे फल दीर्घकाल में मिलेंगे।

पुर्नान्वेषण इस देश में उद्योगपतियों में अभी पर्याप्त निर्यात-चेतना (export

consciousness) उत्पन्न नहीं हो सती है। आन्तरिक बाजार का प्रबोधन उन्हे नियमित बढ़ाने पर (जिससे कि बिनी बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ते हैं तथा प्रतियोगी भीमर्तें रखती पड़ती हैं) ध्यान नहीं देने देता। निर्यातों के प्रति इस अपेक्षाभाव को दूर करने हेतु उद्योग और सभाज दोनों पर बड़े अनुशासन की आवश्यकता है।

निर्यात का लक्ष्य ऊँचा होना स्वाभाविक है, क्योंकि (i) जनसंख्या की तेजी, से वृद्धि तथा अभी भी जीवन-यापन के नीचे बन हुए स्तर के कारण चौथी योजना का आकार तीसरी योजना की अपेक्षा अधिक बड़ा रखा गया है, (ii) इसके अन्तर्गत उद्योगों की भ्रमता में संघट्ट वृद्धि की जानगी, जिसके लिये पहले से भी अधिक माका में पूँजीगत परनुये आयात करनी पड़ेगी; (iii) विद्यमान स्थापित क्षमता के पूर्ण शोषण के लिए भी कच्चे माल, उत्पादन उपकरण स्पेयर्स और प्रतिस्थापनों का अधिक मात्रा में आयात करना पड़ेगा, एवं (iv) भारत को जल्दो पर व्याज तथा मूलधन सम्बन्धी भुगतान भी करने पड़ेंगे। इन सब भुगतानों के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अतः निर्यात लक्ष्य काफी ऊँचा रखना पड़ेगा।

निर्यात बढ़ाने हेतु उठाये गये या प्रस्तावित नये कदम

(१) द० पू० एशिया और सुदूर पूर्व में भारतीय व्यापार गृह खोलना—सरकार ने दक्षिणी पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व के देशों में भारतीय व्यापार गृह (Indian Trading Houses) खोलने की योजना बनाई। इन उपायों का उद्देश्य इन क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना है। व्यापार गृहों का गठन कुछ विदेशी संगठनों की रूप-रेखा के अनुसार किया जाएगा तथा वहाँ अच्छी निर्यात-मभावनाओं वाली भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन और विक्रय किया जायेगा। इन व्यापार गृहों की स्थापना भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों के सह द्वारा की जायेगी, जो इनका वार्षिक व्यय वहन करेंगे। ये व्यापार-गृह विद्युत् व्यापारिक आधार पर संगठित किये जायेंगे तथा इनको निर्यात संबंधन परिपदों से भी सहायता मिलेगी।

(२) अधिक लक्ष्य में राजकीय व्यापार निगम—निर्यात व्यापार में सार्वजनिक क्षेत्र को पहले की अपेक्षा अधिक बड़ा हिस्सा दिया जायेगा और इस हेतु चौथी योजना के अन्तर्गत विदेशी बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विपणन के लिए कई राजकीय व्यापार निगम स्थापित किये जायेंगे।

(३) निर्यात नियन्त्रण—बोर्ड ऑफ ट्रेड (Board of Trade) के एक मतिरि ने इस बात पर बल दिया है कि किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी कानून पर कड़ाई में ध्यान दिया जाय। अन्यथा निर्यात व्यापार में चुनौती नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय (selective control measures) निर्यात की कई वस्तुओं की उचित विदम के अभाव में, बेकार हो जायेंगे।

(४) निर्यात संवर्धन परामर्शदाता बोर्ड—राज्यों में एक-एक निर्यात संवर्धन परामर्शदाता बोर्ड (Export Promotion Advisory Board) स्थापित किया जाएगा, जो चौथी योजना की पृष्ठ-भूमि में जायातो और गयातो के मध्य खाई को पाटने के लिए आवश्यक परामर्श देगे ।

(५) लागतों में कमी करने के उपाय—ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन लागतें कम हो जाये । यदि यह सम्भव हुआ, तो विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुएँ अधिक हड़ता से प्रतियोगिता कर सकेंगी । विदेशों में भारतीय माल की खपत बढ़ाने में लागत-घटौती की दिशा में कुछ अधिक नहीं किया जा सका है । यह सदा ही सत्य नहीं है कि प्रतियोगिता में सफलता के लिए जो लागत-घटौती आवश्यक है वह मजदूरियों में कमी करके ही सम्भव है । कारण, प्रायः उ-पादक-साज-सामान और उत्पादन-टेकनीक में भी बहुत कमियाँ देखी गई हैं । अतः, यदि हमें सुधार लिया जाय, तो मजदूरियों में घटौती किये बिना ही लागतों में कमी हो जा सकती है ।

(६) निर्यातों का चुनाव—निर्यात सहायता केवल चुने हुए निर्यातकों को जिन्हें कि निर्यात व्यापार में वास्तविक रुचि हो तथा जो निर्यात व्यापार में भाग लेने की क्षमता भी रखते हों, दी जानी चाहिए । निर्यात क्षेत्र में नये प्रवेशकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । विदेशी सुविधाओं की स्वीकृति विशेष दायित्वों पर आधारित होनी चाहिए ।

(७) स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र—बाधना में एक स्वतन्त्र व्यापार वाला क्षेत्र (Free Trade Zone) स्थापित किया गया है । 'स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र' का उद्देश्य वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, उपरिगम्य घटाना तथा निर्यात के लिए पुनः विभाजन उद्योगों (reprocessing industries) की स्थापना को प्रोत्साहन देना है । इस क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए आयात साइसेन्स अधिक उदारतापूर्वक दिये जाते हैं । यद्यपि ये उद्योग अर्धकायत निर्यात के लिए ही उत्पादन करेंगे तथापि कुछ सीमा तक उन्हें आन्तरिक बाजार में बिक्री की भी छूट होगी ।

(८) निर्यात कार्यक्रम में लघु पैमाने के उद्योगों की भूमिका—चौथी योजना के निर्यात कार्यक्रम में लघु उद्योगों को एक महत्वपूर्ण भूमिका लेनी है । पृथक-पृथक वस्तुओं के लिए अभी से लक्ष्य निर्धारित किये जायें, जो कि वार्षिक आधार पर होने चाहिए । निःसन्देह लघु उद्योगों के क्षेत्र में निर्यात वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर है । उदाहरणार्थ, छाते के विक्रेताओं ने जब गरमक प्रकाश किये तो इनका निर्यात कई गुना बढ़ गया था । इसी प्रकार, साइक्लो, चून्ियो आदि के निर्यात भी बहुत बढ़ाया जा सकता है । सरकार ने कई निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ चालू की हैं । लघु उद्योगों को इनमें ताम उठाना चाहिए । यह सुभाव भी है कि लघु-उद्योगों की उत्पत्ति का विपणन करने के लिए राजकीय व्यापार निगम की शक्ति का एक सञ्जठन बनाना

चाहिए। निर्यात गृह (export houses) भी स्थापित निय जा सकते हैं। बर्त राग्यो न निर्यात नियम स्थापित निय गय हैं।

(१) आन्तरिक उपभोग को घटाने के उपाय—जिन वस्तुओं की अधिक निर्यात सम्भावनायें हैं उनके उपभोग का दम म घटाना चाहिए जिससे कि इनका अधिकधिक मात्राओ म निर्यात किया जा सके। याचना आयात न चौकी योग्यता की अवधि न एसी वस्तुओं क अतिरिक्त उत्पादन का निर्माण के लिए सुरक्षित रखने का फनला दिया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री दासजी न यह सुभाव दिया था कि पब्लिक रैक्टर का उपभोग वस्तु उद्योगो म भी माग सेना चाहिए जिसन कि इनका निर्मात माकी बताया जा सके।

(१०) विदेशी विनिमय—निर्यात-वृद्धि के लिए विदेशी विनिमय अधिक म मा म मूल्य होना चाहिए, जिससे कि निर्माताओ को विदेशों से आधुनिकतम मशीनों का आयात करन म सुविधा हा जाय और व ऐसी वस्तुएँ निर्मित कर सके, जिनके लिए विदेशा बाजारो म माग बहुत बढ़ सकती है।

(११) पब्लिक सेक्टर में जूट मिलों की स्थापना—जूट के मशीन बादि बनान के निय आधुनिक मायातित मशीन और साज-सामान से युक्त जूट मिल पब्लिक सेक्टर म स्थापित निय जायें। इससे लागतें कम हो जायेंगी तथा प्रतियोगी नीमते पर निर्यात किया जा सकेगा।

(१२) चाय की खेती का विस्तार—विरोपन्ना ने यह सुभाव भा दिया है कि राज्य सरकारें चाय की खेती को बढ़ावा दें और इस हेतु सिंचाई सुविधायें तथा बागोचा के विस्तार के लिए पर्याप्त भूमि की व्यवस्था करें।

डा० राय के सुभाव—

डा० राय ने चौकी योजनावधि म निर्यातों को बढेछ माना म बाले के लिए सात उपायों का सुभाव दिया है। य सुभाव निम्न हैं—(i) आन्तरिक उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसका अर्थ यह नहीं है कि आन्तरिक उपभोग का बर्त मान स्तर से भी कम कर दिया जाय, बरन् यह है कि अतिरिक्त उत्पादन का कुछ भाग आन् उत्पादन म म अभी निर्यात निय जाने वाले भाग के असावा निर्यात के निचे सुरक्षित रखा जाय। (ii) आरक्षण नियमों का अधिकार अनुपात हृषि पर आधारित है जबकि हृषि उत्पादन म जनवागु के अनुसार विशाल परिवर्तन होते रहन हैं। अत निर्यात का नियमित प्रवाह बनाय रखन के निय निर्यात सम्बन्धी स्टॉक बनाये जायें। (iii) हृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों म विनिमोन्न द्य प्रचार से होना चाहिय कि निर्यात म वृद्धि हो। इस हेतु आवश्यक कच्चे मालों तथा मशीनों पुर्जों का प्राप्ति मे बिलम्ब नहीं होना चाहिये। (iv) बेचन निर्यात के लिए ही उत्पादन करने वाले कारखाने विशेष रूप से छोले जायें। य कारखाने पब्लिक रैक्टर म स्थापित निये जाने चाहिये तथा इनम आधुनिकतम मशीनें होनी चाहिये। (v) निर्यात प्रोत्साहन के लिए जा भी आधुनिक एवं अय उपाय निय जाय व चौकी

योजना की सम्पूर्ण अवधि में बने रहने चाहिये, जिससे कि निर्यातको और निर्याताओं के निर्यात सम्बन्धी प्रयासों में विघ्न न पड़े। (vi) निर्यात प्रोत्साहन के लिए विदेशी विनिमय उदारतापूर्वक स्वीकृत किया जाय, चाहे इसमें कुछ अपव्यय ही हो। जिन आयातों के लिये विदेशी विनिमय की सुविधाएँ दी जानी चाहिये वे निम्न हैं — निर्यातकों के प्रतिनिधियों की विदेश यात्रा, बित्री बढ़ाने हेतु प्रचार, बाजार और वस्तु सम्बन्धी अनुसन्धान, कार्यालयों दिपो, एम्पोरियम आदि खोलना। (vii) निर्यात प्रोत्साहन के लिये कुल बितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जावगी इसका निश्चय पहले में ही करना आवश्यक है तथा आवश्यक विदेशी मुद्रा किरातों में देने की व्यवस्था करनी चाहिये।

निर्यात बढ़ाने हेतु प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण आवश्यक

निर्यात व्यापार बढ़ाने हेतु वस्तुओं के उत्पादन की प्राथमिकताएँ निश्चित करना आवश्यक है किन्तु हमारे निर्यात व्यापार घटने के प्रयासों की एक कमी यह है कि निर्यात वस्तुओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण सही ढङ्ग से नहीं हुआ है। निर्यात व्यापार की सूची में अभी तक लगभग ३०० वस्तुएँ सम्मिलित की गई हैं। लेकिन इनमें से १० से अधिक वस्तुएँ ऐसी नहीं हैं जिनमें राजकोष को निर्यात व्यापार के द्वारा विशेष लाभ होता हो। हमारे निर्यात व्यापार की वस्तुओं को लेकर लागत और लाभ के आधार पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। इस प्रकार के विश्लेषण का एक लाभ तो यह होता कि अभी तक जो वस्तुएँ निर्यात-वस्तुओं की सूची में सम्मिलित हैं, वह निकाल दी गई होती और ऐसी वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया होता जिनसे अधिक निर्यात-आय प्राप्त होने की सम्भावना है। नीचे कुछ प्रमुख माप दण्डों पर विचार किया गया है, जिनको इस प्रकार की सूची तैयार करने में दृष्टिगत रखना आवश्यक है।

(१) भारत के निर्यात व्यापार के गठन में कुछ वृत्तिवादी कमी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित कुछ थोड़ी-सी वस्तुओं के निर्यात द्वारा प्राप्त होता है। अतः दीर्घकालीन नीति अर्थात् समय-त्रिविध प्रकार की वस्तुओं के निर्यात पर बल देने की आवश्यकता है और अल्पकाल में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मुनहरी अण्डे देने वाली भुर्मा अर्थात् ऐसी वस्तुओं के निर्यात की जिनमें अधिक लाभ प्राप्त होता है, प्रोत्साहन दिया जाय। पटसन और चाय के निर्यात व्यापार के महत्व को देखते हुये वह जरूरी है कि इन वस्तुओं के व्यापार पर पटने की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाय।

(२) भारत द्वारा निर्यात होने वाली अधिकतर वस्तुओं का कुल निर्यात उत्पादन में गौण योग है। ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है जिनमें अधिक आय प्राप्त होती है और इन वस्तुओं के उद्योगों का भविष्य भी इन वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर करता हो। ऐसी परिस्थिति में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राष्ट्रीय नीति में उन्हें उच्च प्राथमिकता

देने की आवश्यकता है। निर्यात वस्तुओं के इन उद्योगों में अधिक पूँजी लगाने और ठीक समय पर इन्हें सृष्ट बनाने की दिया में यदि कोई कदम नहीं उठाये गये तो इन उद्योगों के संकटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(३) निर्यात वस्तुओं की प्राथमिकता देने समय उत्तरी मार्ग को ध्यान में रखना आवश्यक है। निर्यात वस्तुओं की मार्ग मान्यता करने के तीन साधन हैं। प्रथम, निर्यातक विभिन्न देशों में की गयी पूछताछ के द्वारा मार्ग का अनुमान लगाता है। दूसरे विभिन्न देशों को भेजे गये डेलीवरीनों की रिपोर्टों में भी कुछ वस्तुओं की मार्ग का अनुमान लगाया जाता है। तीसरे सरकार या राजकीय व्यापार निगम तथा सैनिक और धातु व्यापार निगम द्वारा स्थित गये व्यापार समझौतों से भी विभिन्न वस्तुओं की मार्ग का अनुमान लगाया जा सकता है। निर्यात वस्तुओं की मार्ग का ज्ञान हो जाने पर इन वस्तुओं के सम्बन्ध में नीति अपनाई जाती चाहिए।

(४) ऐसी निर्यात वस्तुओं की प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिनके उद्योगों में आयात-वस्तुएँ कम लगती हैं।

भारतीय लघु उद्योगों के महासंघ के सुझाव

भारतीय लघु उद्योगों के महासंघ (The Federation of Associations of Small Industries of India) ने निर्यात प्रोत्साहन विषयक प्रस्ताव में निम्न विहित सुझाव दिये हैं — (१) निर्यात प्रोत्साहन की स्कीमें दो शीर्षकों के अन्तर्गत बनाई जायें—प्रत्यक्ष प्रोत्साहन एवं वित्तीय प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त, निम्न सुविधायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं—बाजार सूचना का सप्रहरण एवं प्रसारण, समुद्र पार धातुओं का संवर्धन, उत्पाद-सर्वेक्षण निर्यात विपणन सम्म भी इन्हें निर्माता स-निर्यातकों के लिये समुचित आयात सुविधायें, अच्छी निर्यात उपसंधियों के लिये पुष्टिकार-वितरण। (२) एक निर्यात-निर्देशालय स्थापित किया जाये जो लघु उद्योगों की निर्यात समस्याओं की सुलझाये। (३) एक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत सूचना-संघ (International pricing Intelligence) स्थापित किया जाय। इसमें लघु उद्योग के लाभार्थ एक विशेष विभाग होना चाहिये। (४) व्यापारिक बैंक (विद्योपत सरकारी बैंक) लघु उद्योगों की 'सिन्डिकेटिड प्रदाता' रूप में देकर विकास प्रमुख ऋण' (Development oriented loans) दें। (५) लघु उद्योग निगमों की चाहिये कि पूँजीगत सामान बेचने में (किराया खरीद आदि पर) लघु उद्योगों की सहायता करे। (६) एक राष्ट्रीय विनियोग शुल्क की स्थापना की जाय। (७) लघु उद्योगों का दुर्लभ देशी कच्चे माल उचित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाय।

निर्यात सम्बर्द्धन के लिए अन्य उपयोगी सुझाव

(१) सभी प्रकार के अपत्यस करों को (जैसे—निर्यात व्यूट्रीज, विक्री कर, नगरपालिका कर, स्थानीय कर) उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कि निर्यात किये जायें, सीटा बना चाहिये। वास्तविक ऐसा केवल निर्यात व्यूट्रीज के लिये किया जा रहा है, अन्य अपत्यस करों के बारे में नहीं, जो कि अभी भी विज्ञान राशि के हैं।

पुन निर्यात इस्सूटीज की बागिसी में भी बहुत विलम्ब होता है तथा विद्याल कोष १२ (या इससे भी अधिक) महीनो तक अटके रहते हैं।

(२) निर्यात-वस्तुओं की कीमतों को प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर लाने हेतु यह आवश्यक है कि निर्यातक उद्योगों को आयातित कच्चे माल आदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर उपलब्ध कराये जायें। अभी कुछ थोड़े कच्चे माल ही STC के द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। उनको निम्न भी आवश्यक कोटि की नहीं होती तथा वे महंग होते हैं। दुर्भाग्य से निर्यातकों को Replenishment licences देने में विलम्ब किया जाता है।

मधुक्त राष्ट्र सभ के जिन निर्यात प्रोत्साहन विशेषज्ञों ने हाल में ही भारत के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात व्यापार की जांच की थी, उनके नेता श्री सी० एफ० कोलन ने एक प्रश्न कार्यक्रम में अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रकट करत हुए यह विचार-मन्त्र किया था कि यदि निर्यात को जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन मूल्य बढ़ाया जाये और अच्छी विम्ब एवं अच्छे आकर्षक पैकिंग पर ध्यान दिया जाये तो भारत के निर्यात में वृद्धि हो सकती है। इन विशेषज्ञों की अन्तिम रिपोर्ट अभी तभी मिली है। परन्तु यह समझा जाता है कि यदि निर्यात प्रोत्साहन को गम्भीरता से लिया जाय तो कुछ वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छा स्थान बनाया जा सकता है।

(३) अन्तरम्परागत वस्तुओं के लिये निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों स्वीकार करने में जल्दी की जाय, जिसमें कि निर्यातकों के हाथ से वे नये बाजार में निर्यात करके जो कि उन्होंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किये हैं। सरकार ने १९७२-७४ तक अनु-वर्तमान २४० करोड़ रु० के स्तर में बढ़ाकर ५०० करोड़ रु० करने का लक्ष्य बनाया है।

(४) जो लोग निर्यात क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाते हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए। (व्यापार बोर्ड ने उल्लेखनीय निर्यात करने वालों को प्रति वर्ष १० पुरस्कार देने का निर्णय भी किया है। उल्लेखनीय निर्यातकों का चुनाव करने लिये अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों की एक समिति बरेगी। बोर्ड की आशा है कि इन पुरस्कारों से भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा तथा उनकी रनि में वृद्धि होगी। इससे निजी उत्पादक तथा निर्यातक विदेशी बाजारों में अपना सामान बेचने को अधिक इच्छुक होंगे। १९६३ में पहली बार सफल निर्यातकों को पुरस्कार दिये गये।)

(५) सरकार को चाहिए कि निर्यात के लिये नीतियाँ, क्रिया विधियाँ एवं प्रोत्साहन-स्कीम बनाये समय व्यापारिक संगठनों से विचार विमर्श करे।

(६) निर्यात के लिये विनियम में व्यक्तिगत प्रयत्नों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु विदेशी ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क रखना और व्यापारिक सम्बन्धों का निर्माण करना चाहिये। पूर्वीय वस्तुओं के निर्यात की दशा में 'विनयात्तर सेवा'

(After sales Service) परम आवश्यक है। इस हेतु ट्रेड र्जमचारियों को निरन्तर विदेशों में भेजना चाहिये जो यह देखें कि उनका बेना मया माल कंसा कार्य कर रहा है। सरकार ने विदेशी यात्राओं पर जो अत्यधिक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं वह इस दिशा में बाधक हैं जिस कारण निर्यात व्यापार को बहुत डेम पहुँच रही है। हमें वा दय है कि इस वर्ष से विदेशी यात्रा सम्बन्धी नियम ढीले कर दिये गये हैं।

(७) U. S AID के निर्देशन जॉन० पी० लेविज (John. P. Lewis) ने भारतीय व्यवसायियों की प्रशंसा करते हुये कहा था कि "I know of no business leadership group better equipped with the essential resources, not only of mind but of character, dedication, personal grace and good humour for bringing about this kind of assignment." किन्तु स्वयं भारत की सरकार को अपने व्यवसायियों में विश्वास नहीं है। तब ही तो भारतीय व्यवसायियों के विकास हेतु मोनिया बनाने में उनको असमर्थता जाता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह अपने दृष्टिकोण में सुधार करे।

(८) हमारे विदेशी दूतावासों के वाणिज्य विभाग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि उनमें नर्मचारियों की संख्या जल्दतर से कम है, दूसरे, जो लोग नियुक्त किए जाते हैं उनमें अपने काम को अच्छी तरह करने की योग्यता नहीं होती। अगर इन विभागों को दोषरहित बनाया जाय तो हमारा विदेशी व्यापार काफी उत्थित कर सकता है।

(९) विदेशी व्यापार के उपलब्ध आकड़े निस्तृत तो होते हैं फिर भी नवीनतम नहीं होते। विदेशी व्यापार का हमारा टीचा अक्सर बदलता रहता है। समय प्रतिपोषिता तभी सम्भव है जब आंकड़े नवीनतम हों।

(१०) विदेशों में जो मेले और प्रदर्शनियाँ होती हैं उनमें न तो हमारे सामान की मजाबूट आधुनिक ढंग से की जाती है और न ही मुद्रित मामूरी स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। कई बार तो स्थानीय के प्रभारी व्यक्ति उस स्थान की भाषा नहीं जानते होते जहाँ मेले और प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। विदेशों में जो 'सो एम' बनाए गए हैं उनकी भी कड़ी दया है। इन सब कमियों को दूर करना होगा। आकाशवाणी पर व्यापार विभाग आरम्भ करने के बारे में भी सरकार विचार कर चुकी है, परन्तु इस सुभाव को स्वीकार नहीं किया गया जिसके कारण वस्तुओं के विज्ञापन हमारे रेडियो पर नहीं दिये जा सकते। अतः पश्चिमी एशिया तथा पूर्व में बहुत से लोग जो हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनते हैं, भारत द्वारा उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम बीन-मो चीजें तैयार करते हैं। कुछ समय पहले रेडियो सोलोन पर इनके विज्ञापन सुने जा सकते थे, परन्तु विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण इसे भी भीमित कर दिया गया है। सरकार को चाहिए कि वह व्यापार को बढ़ाने की यातिर आकाशवाणी पर व्यापार विभाग आरम्भ करने के बारे में पुनः विचार करे।

(११) सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि रूस और पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाकर हम उस विदेशी मुद्रा की आय को न खो दें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी नीतिज्ञ यह होनी चाहिए कि रूस, पूर्वी यूरोप तथा स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा वाले देशों को हमारा निर्यात एक साथ बढ़े। यह बहुत अच्छी बात है कि रूस और पूर्वी यूरोप के देशों की निर्यात में हमारे तैयार माल और परिष्कृत वस्तुओं की प्रतिशतता बढ रही है। इसी प्रकार स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा वाले उन देशों को हम निर्यात बढ़ाना चाहिए जहाँ से हम मशीनें और पूँजीगत सामान का आयात कर रहे हैं और जिनके साथ हमारा व्यापार अमलुसित है।

(१२) कृषि और उद्योग के उत्पादन में विरासत को देखते हुए ऐसा लगता है कि जब तक कोई सुधार के उपाय न किए जायेंगे यह सध्य पूरा करना कठिन होगा। सबसे पहले तो सरकार को प्रत्येक आर्थिक विषय पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना पड़ता है। इसके बाद सरकार को अपनी नीति को अमल में लाने के लिए अपने प्रशासन को दोपराहत बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कृषि के बारे में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके और किसान को खाद आदि आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। कृषि उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर लिया जाना चाहिए और इसे एक उद्योग ही मानना चाहिए। सरकार को अपनी भूमि सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि जड़े जड़े कामों पर खेती की जा सके क्योंकि तभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग में लाया जा सकता है। उद्योगों को जब तक प्रोत्साहन नहीं दिया जाता उपयुक्त उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार का वर्तमान रईसा लाभप्रद सिद्ध नहीं होगा कि उद्योग ठीक चल रहे हैं और इन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है।

(१३) हमारी निर्यात नीति की चाहिए कि कच्चे मालों की तुलना में निम्नित वस्तुओं के निर्यात पर कन दे, जिससे विदेशी मुद्रा की कपाई बढ़ सके। इन सम्बन्ध में स्कैप (scrap) के निर्यात की अनुमति देने और इस पर तकद सहायता देने की नीति का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्यातों ने इलेक्ट्रिक फर्नेस इन्डस्ट्री के लिये कठिनाइयाँ पैदा कर दी हैं। स्कैप के बजाय 'तैयार इस्पात' का निर्यात करना बेहतर होगा।

(१४) विकसित और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों में परिवर्तन किए बिना अन्य विकसित देशों का निर्यात नहीं बढ़ सकता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गड़बड़ों और अव्यवस्था को दूर करने की दिशा में 'ग्रेट' संगठन ने काफी काम किया है, लेकिन फिर भी वह अर्द्धविकसित देशों के निर्यात वृद्धि को बढ़ावा नहीं दे सका है। अब स० रा० के सत्वावधान में एक संगठन बना है, जिसमें काफी अच्छा काम किया है।

(१५) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री वी० टी० दत्तेत्रिया ने सुभाष

दिया है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह बैंकों को कम व्याज पर ऋण दे। बैंक होने पर बैंक निर्यातकों को ऋण-सम्बन्धी सुविधाएँ दें जैसे। ज्ञानन म इस तरह की व्यवस्था है, और भारत में इसे जासानी से अप-बाधित या मजबूत है।

(१६) नवीन एवं निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर वस देते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्रों में निर्यात कार्यक्रम में वस्तुओं की प्रमुख भूमिका है और इनकी ओर से आँखें हटाना हानिप्रद होगा।

(१७) निर्यात में अनिवार्यता रखने की स्कीम का विरोध करते हुए ACC व प्रमुख आ आदिम म तब किया कि हम सख्त विदेशी आह्वन को अपनी उपज खरीदने के लिए दिवंगत नहीं कर सकते, चाहे सरकार कुछ भी क्यों न करे। यदि अनिवार्यता प्रचलित की गई तो यह खतरा है कि भारतीय निर्यातों में अन्वेषण के लिए ठो कुल कृषि ही आपसों किन्तु दीर्घकाल में हानि होगी, क्योंकि भारत व बाह्य न विदेशों में जन पैदा हो सकता है—अनिवार्यता की पूर्ति वस्तु निर्माता एवं निर्यातक विदेशी बाजारों में किसी भी कीमत पर वस्तुओं बेचने का प्रयत्न करेंगे तब ही व पंखड़ी दते में बनें। यह तो विदेशी आह्वन के हाथ में बेचने के समान है क्योंकि वह भारतीय निर्यातकों की दुर्बल स्थिति की जानकारी देवते हुए इसका लाभ उठाने की कानिष करता। यही नहीं, अनेक उत्पादकों की यह प्रतीति भी होगी कि वे जिस, विदेशी माँगों और प्रवृत्तियों के समान मानकों पर परियाय करके सस्ती चीजों की पर धटिया वस्तुओं निर्यात करें, जिससे कि सरकारी आदेशों की पूर्ति हो सके। यह तो ठीक उनके विपरीत है क्योंकि हम चाहते हैं। निर्यात नीति की सफलता एक दीर्घ अवधि में भारतीय वस्तुओं और भारतीय व्यापारिक पद्धतियों के प्रति विदेशी तरी प्रकार की भावना उत्पन्न करने में निहित है।

(१८) शिपिंग कम्पनियों से अनुरोध किया जाय कि वे निर्यातों पर अपने निर्यात-भाड़े की दरें कम करें, क्योंकि वे निर्यात वस्तुओं की कीमत पर बहुत बोझ डाल रही हैं।

(१९) केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही कीमतें कम हो सकती हैं।

(२०) व्यापारी वर्ग को चाहिए कि बाह्य के स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र की सुविधाओं का अधिक लाभ उठाएँ। [व्यापारियों की ओर से कहा गया है कि इस क्षेत्र में बाधक सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए।]

निर्यात उद्योगों को कच्चे मान में प्राथमिकता

जो उद्योग निर्यात करते हैं अथवा जो निर्यात के लिए मान बनाते हैं उन्हें स्वदेशी कच्चा मान प्राथमिकता में दिवंगत के बारे में वाणिज्य मन्त्रालय ने अपनी सत्रवीस विस्तार में घोषित की है। जिन उद्योगों को इन क्षेत्रों में रखा गया है उनमें इ-ऑनियम, रासायनिक, प्लास्टिक, धोआक आदि के उद्योग शामिल हैं। इनकी जो कच्चा मान उपलब्ध कराया जाएगा उनमें गिन आयरन, सब प्रकार

का ऐल्यूमीनियम, साइकिल के टायर, ट्यूब व रिंग, गंधक का माल, प्राकृतिक व रासायनिक, रबड़, कार्बन ब्लैंक, चीनी व मृत्ती कपड़े शामिल हैं। इनमें से अधिकांश कच्चे माल को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है। जेप चीजे भी शीघ्र ही आवश्यक वस्तु घोषित कर दी जायेंगी। निर्यात-उत्पादन-निर्देशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे कच्चे माल के किसी भी निर्यात को वह माल किसी भी निर्यात-उद्योग को मुहैया किये जाने का आदेश दे सकते हैं। इस प्रकार के कच्चे माल का मूल्य लेने और देने वाले के बीच बातचीत में तय होगा। निर्यात उत्पादक निर्देशक भी हस्तक्षेप करेंगे जब कोई पार्टी उनमें बहेगी। स्वदेशी कच्चा माल माधुरण तैयार माल का निर्यात किये जाने के बाद मुहैया किया जाएगा। किन्तु निर्यात के लिए कच्चा माल यदि पेशगी देना जरूरी समझा गया तो उसकी भी व्यवस्था की जायगी। निर्यात किये जाने वाले हाथकरघा वस्त्रों के लिये सूत बाय, फाफी व पटसन के बगोचा के लिये ड्रॉरक तथा स्टेपलाशक द्रव्यों को भी इसी प्रकार व्यवस्था की जायगी।

U. S. AID द्वारा भारत के निर्यात-प्रोत्साहन आन्दोलन में सहायता

अमेरिका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भारत को निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन में सहायता देने के लिए एक विशेष विभाग भारत में खोल रही है। यह विभाग भारत के वाणिज्य मन्त्रालय एवं अन्य सम्बद्ध सरकारी मण्डलों के साथ सहयोग से कार्य करेगा। सबसे पहले वह भारत की मुख्य निर्यात-वस्तुओं के लिये विदेशी बाजारों की खोज करेगा। वह यह देखेगा कि क्या निर्यात के लिये कुछ नई चीजें भारत की मौजूदा निर्यात सामग्रियों की स्थानांतरित कर तैयार की जा सकती है जिनमें वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बना सकें। विभाग का एक काम भीरनी होगा कि वह विदेशी आयातकर्ताओं के साथ भारतीय निर्यात-कर्ताओं का सम्पर्क स्थापित करने के लिये एक बड़ी का काम करेगा। निर्यात को बढ़ाने के लिये जहाँ उत्पादन की विस्म का स्तर उन्नत करना और उत्पादन का मूल्य घटाना आवश्यक है, वहाँ विदेशी आयातकों के साथ सम्पर्क होना भी बहुत जरूरी है। उत्पादन व्यय को कम करने के लिए तो बहुत समय से जोर दिया ही जाता रहा है, फिर भी भारतीय उद्योगों को कोई खास सफलता नहीं मिली है। उदाहरण के लिए विदेशी विशेषज्ञ यह समझ नहीं पाते कि भारत में निर्मित इस्पात का मूल्य इतना ऊँचा क्यों है। यदि उसका उत्पादन व्यय कम किया जा सके तो उसके निर्यात की सम्भावनाएं बहुत हैं।

अन्तरमन्त्रालय विभाग की स्थापना

एक उच्च अधिकार प्राप्त अन्तरमन्त्रालय विभाग स्थापित किया जा रहा है जो कि त्रिधाविधि सम्बन्धी एवं अन्य विषयों को कम में कम करेगा। देखा गया है कि निर्यात-कायज-पनों के एक मन्त्रालय से दूसरे मन्त्रालय में जाने जाने में बहुत अमूल्य समय नष्ट हो जाता है।

निर्यातक संगठनों की मान्यता

केन्द्रीय सरकार ने निर्यात व्यापार सम्बन्धी अपनी नीति में संशोधन करके कम्पनियों व फर्मों को निर्यात संगठन की मान्यता सम्बन्धी शर्तों और कड़ी बनाने का निर्णय किया है ताकि ऐसे संगठनों को अधिक सुविधाएँ दी जा सकें। निर्यात व्यापार संगठनों की मान्यता पाने के लिए कम से कम २५ लाख रु० मूल्य का गैर परम्परागत और २ करोड़ रुपये मूल्य का परम्परागत भाल का निर्यात आवश्यक है। निर्यात संगठनों को मान्यता देने की योजना ८ वर्ष पूर्व शुरू हो गई थी।

परीक्षा प्रश्न :

1. चौकी योजना के निर्यात रुध्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ? अपने सुझाव भी दीजिये ।
[Discuss the steps taken or proposed for achieving the export target of the Fourth Plan Give your suggestions.]
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिय निर्यात संवर्धन की महत्ता स्पष्ट कीजिये और नीचरी पञ्चवर्षीय योजनावधि में की गई प्रगति का मूल्यांकन करिये ।
[Explain the significance of export promotion to Indian economy and evaluate the progress achieved during the period of the Third Five Year Plan]
(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)
3. निर्यात संवर्धन की तकनीक को समझाइये और उन कठिनाइयों को इंगित कीजिये, जोकि इस सम्बन्ध में एक अर्थिक रूप से कम विकसित देश को उठानी पड़ती है ।
[Explain the technique of export promotion and indicate the difficulties which are experienced in this connection by an economically underdeveloped country]
(आगरा, एम० ए०, १९६६)
4. 'आर्थिक आत्म निर्भरता का आशय है कि भारत को अपने निर्यात इस सीमा तक बढ़ा लेने चाहिये कि वह आवश्यक आयातों का भुगतान कर सके ।'
विवेचन कीजिये ।
['Economic self reliance really means that India should increase her exports to such an extent that she may be able to import ' Discuss]
(बोरख० एम० कॉम०, १९६६)

निर्यात साख

(Export Credit)

प्रारम्भिक—

निर्यात सबूद'न मे समुत्ती और उदार निर्यात-साख मुनिधाओं की भूमिका बड़ी (यद्यपि अकेली नहीं) महत्वपूर्ण है। चाहे अन्य घटक अनुकूल हो किन्तु नरती निर्यात साख के अभाव मे निर्यातको को प्रतिस्पर्धा करने मे कठिनाई होगी। हाल के वर्षों मे 'विक्रेता बाजार' के बजाय 'क्रंता बाजार' उदय होने लग हैं तथा निर्यात-बाजारों की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अत निर्यात साख की समस्या को हल करना आवश्यक हो गया है।

निर्यात वित्त से आशय

निर्यात वित्त' (Export Finance) शब्द की परिधि मे दोनो 'सदान-पूर्व' एक सदानोत्तर साख' आ जाती है। वित्त की आवश्यकता वस्तुओं के प्रोमेसिंग, उत्पादन और पैकिंग से लेकर वस्तुओं के जहाज पर सदान होने तक की अवस्था मे अथवा सदान के समय से विदेशी आयातकर्ता से मूल्य के वसूल होने की तिथि तक पड सकती है। सदान पूर्व वित्त (pre-shipment credit) आन्तरिक वित्त (domestic finance) मे इस बात मे भिन्न है कि उत्पादक सदा यह नहीं जानते (और यदि जानते हैं, तो सदा पहले से ही भेद नहीं कर सकते) कि वे गृह बाजार के लिये वश उत्पन्न कर रहे हैं और विदेशी बाजार मे क्या बेच सकेंगे।

निर्यात साख की लागत को घटाने मे कठिनाइयाँ

उक्त भेद सम्बन्धित कठिनाई ने निर्यात साख की लागत मे कमी करने के प्रयत्न को जटिल बना दिया है। इस दिशा मे निम्नलिखित कठिनाइयाँ होनी हैं —

(१) यह विश्वास दिनाता पडता है कि निर्यात साख के लिये जो प्राथमिकतापूर्ण व्यवहार (preferential treatment) दिया जायेगा, उनका दुर्प्रयोग न होगा तथा वह आन्तरिक उद्देश्यों के लिये स्तम्भान नहीं किया जायेगा। स्मरणीय है कि दोनो 'सदान पूर्व निर्यात साख' एवं 'आन्तरिक साख' एक ही ढग मे (कंश क्रेडिट्स या ओवरड्राफ्ट्स के द्वारा) प्राप्त की जाती है। पुन सदान-पूर्व वित्त का एक भाग पूँजीगत या अर्द्ध-पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन मे प्रयोग किया जाना है और

नवकरण-योग्य अल्पकालीन ऋण (rolled over short term credits) के रूप में होता है। मियादा ऋण (term loans) के रूप में नहीं।

() भेद करने का असमयता तथा लदान पूर्व वित्तीय आवश्यकताओं का दृष्टि निर्यात आकार मोट्रिक अधिकारियाँ व लिये साख्त नियम व नियमों को वृद्धि बना जाता है। यदि क्रेडिट मिनिस्ट्रि के तहत वृद्धि भाग को मुक्त रूप में प्रवाहित हान दिया जाय तो साख्त नियमों सम्बन्धी समस्त उपाय असफल हान का डर है।

लदानांतर मात्र अधिकारिता अल्पकाल के लिये होगी है (जब—परम्परागत वस्तुओं की दशा में मात्र और इन्फ्लेक्शनरी गुड्स का दशा में ६ माँ)। अधिकारिता मात्र में नियामक द्वारा बिना आक एक्मपोजेज के रूप में प्राप्त का जाना है जिसे हस्तान्तरण के लिए बना द्वारा स्थापित कर दिया जाता है।

नयात्रि मात्र की लागत का कम करने का सुप्रभाव

निर्यात साख्त की लागत का कम करने का गुड परिणाम यह होगा कि विश्व बाजार में भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति बढ़ जायगी। सस्ती लागत-पूर्व साख्त सस्ती हो जाने पर उत्पादक अपनी प्रतिस्पर्धा उत्पादन लागत को नाचा रख सकेंगे जिससे उनके उत्पादों का एक प्रतिस्पर्धात्मक कामत लाभ प्राप्त हो सकेगा। किन्तु लदानांतर साख्त का लागत घटाने का परिणाम यह होगा कि निर्यातक या तो अपने समुद्र पार-ग्राहकों को सस्ती सम्बन्धी साख्त द सकेंगे अथवा अपने उत्पादों के किन्हीं मूल्य को घटा सकेंगे।

छबलानी कमेटी के सुझाव

छबलानी कमेटी (Chabiani Committee) ने इस समस्या के प्रति जो इन्फ्लेक्शन अपनया था उसकी विवक्षताय निम्नलिखित है —

(१) वैका द्वारा निर्यातकों से जो व्याज दरें ली जाती हैं उन पर उत्कृष्टतम सामाग्य (ceiling) निधारित करना आवश्यक है क्योंकि भारत में निर्यात वित्त की लागत विदेशों की अपेक्षा नहीं अधिक होती है।

(२) उपरोक्त सीमाया की प्रभावपूर्ण बनाने हेतु गद्यात्त पुनर्निष्ठ सुविधायें बना की समुचित लागत पर दी जाना चाहिये और वस्तु स्वयं वित्त लागत पर कोय उधार लेते हैं तथा निर्धारित उत्कृष्टतम लागत सीमा के मध्य सम्पत्ति मार्जिन हाना चाहिये।

(३) निर्यात साख्त की दशा में जो सामाग्य वर्गों की जाय वह सम्पूर्ण निर्यात मेक्टर की (अर्थात् लदान पूर्व और पैकिंग क्रेडिट सह नवकर लदानांतर साख्त सह अन्तराष्ट्रीय मध्यकालीन एवं दाघकालीन साख्त और परम्परागत व अपरम्परागत दोनों प्रकार का वस्तुओं के लिये सब) लागू हानी चाहिये। किन्तु आन्तरिक बाजार में निर्यात साख्त का दुर्प्रयोग न हो सक इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियाँ रखना चाहिये। साख्त नियमों का व्यवस्था भी ठीक से लागू की जाना चाहिये।

निर्यात साख के सुधार के लिये उठाये गये १६म

(१) १९५७ में निर्यात जोखिम बीमा निगम (ERIC) की स्थापना की गई ।

(२) अक्टूबर १९५८ में रिजर्व बैंक ने बिल बाजार याचना को निर्यात बिलों पर भी विस्तृत कर दिया ताकि बैंक्स अधिक उदार शर्तों पर निर्यात-साख सुविधायें दे सकें । यह स्वीम १९६२ तक प्रचलित रही और कुछ समय तक स्थगित रहने के बाद पुनः प्रचलित हुई ।

(३) १९६२ के मसौदन द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को १८० दिन तक निर्यात बिल खरीद अथवा भुनाने तथा निर्यात व्यापार के १८० दिन के मियादी प्रोमोटों पर ऋण देने का अधिकार मिला । तदनुसार वह किसी भी शिटयून्ड बैंक को १८० दिन के मियादी प्रोमोट के आधार पर ऋण दे सकता था, बशर्तें ऋण लेने वाला बैंक यह विश्वास दिलावे कि वह स्वयं भी उतने मूल्य के निर्यात-बिलों पर साख देगा । मार्च १९६३ में निर्यात बिल साख स्कीम (Export Bill Credit Scheme) प्रचलित की गई, जिसने (i) स्वीकृत सहायक प्रतिभूतियों के रेंज (range) को बढ़ा दिया, (ii) साख देने की अवधि भी बढ़ा दी (जब यह श्रृंखला हीन हो गई), (iii) पुनर्वित्त की लागत बैंक-दर पर ही देने रहने दी क्योंकि डिप्लोमैट बैंकों के माग-प्रोमोटों पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाती थी, एवं (iv) बैंक्स बैंक दर पर ही सामान्य कोर्ड के अतिरिक्त उधार ले सकते थे ।

द्वितीय अध्ययन दल (मधराजी कमेटी) ने यह सुझाव दिया कि निर्यात साख की लागत को कम करने हेतु रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधायें बैंकों को बैंक दर से १.५% में कम पर मिलनी चाहिए । इस मुझाव की श्रवनायी कमेटी ने अस्वीकार कर दिया ।

(४) १ जनवरी १९६३ से बैंकों को पुनर्वित्त नियम से मध्यमकालीन ऋण प्राप्त होने लगे हैं, जोकि छ माह से ५ वर्ष की अवधि के लिये होते हैं ।

(५) निर्यात बिल के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि FRIC को एक अधिक व्यापक संगठन ECGC में परिणित कर दिया गया, जो निर्यात जोखिम का बीमा करने के साथ-साथ निर्यात गारन्टी की व्यवस्था पर भी कार्य करता है । इस नियम के 'पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी' के सिद्धान्त (Principle of Packing Credit Policy) को 'उपानोत्तर साख गारन्टी' (Post Shipment Credit Guarantee) पर लागू कर दिया है ।

निर्यात साख एवं गारन्टी निगम (ECGC)

(Export Credit Guarantee Corporation)

मार्च १९६४ में निर्यात साख एवं गारन्टी निगम की स्थापना हुई थी और निर्यात जोखिम बीमा निगम (ERIC) को, जो कई वर्षों पूर्व में कार्य कर रहा था, इसी में सम्मिलित कर दिया गया था । नये निगम के अध्यक्ष अधिक व्यापक हैं ।

आवश्यकता एवं उपयोगिता—

ERIC से छः वर्ष के कायकाल में विश्व व्यापार की रचना आदि में दूर-दामी परिवर्तन हो गये थे। विश्व के सप्ताहवार में प्रतिबोधिता धीरे-धीरे बहुत कटु-होनी जा रही थी, जिससे विदेशी कौताओं की सोदा शक्ति बहुत बढ़ गई तथा वे उदार और मुगम गर्ने प्राप्त करने में सफल हो रहे थे। ERIC को अपने निर्मात जोखिम के बीना सन्दर्भी कार्य के अनुग्रह तथा निर्यात-साख विपयक कमेटियों की सिफारिशों के द्वारा यह विश्वास हो गया कि निर्यात जोखिम बीमा (चाहे इसे कितना ही विस्तृत कर दिया जाय) एक पूण समाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, भारतीय निर्यातकों को प्रत्येक स्तर पर (उत्पादन के प्रारम्भ में लेकर विदेशी कौता से भुगतान मिलने तक) सस्ती और उदार साख-मुविधाये देने की निरन्तर आवश्यकता है। अतः राज-नैतिक व्यापारिक एवं मौद्रिक जोखिमों के विरुद्ध निर्यात बीमा करने के साथ ही साथ निर्मातकों को सस्ती, उदार एवं मुगम साख बिलाने के लिए निर्यात साख एवं गारन्टी निगम की स्थापना की गई।

कार्य-विस्तार—

निर्यात साख की व्यवस्था का कार्य निगम के लिये पूर्ण रूपेण नया नहीं था। कारण ERIC द्वारा जो पैगिय क्रेडिट पालिसियाँ बैंकों को जारी की जाती थी और अन्य स्टेण्डर्ड पालिसियाँ जो उन्हें अभिहस्ताकित (assign) की जाती थी उन पर भी निर्यातक (exporters) बैंकों से फाइनेन्स प्राप्त किया करते थे। १९६३ के अन्त में इस प्रकार से प्राप्त साख की मात्रा केवल ८ करोड़ रु० थी। किन्तु ECGC द्वारा व्यापक वस्तु-समूह ग्रहण करने के बाद बहुत परिवर्तन हो गया है। निर्यातकों द्वारा ECGC की पालिसियाँ बैंकों के पक्ष में अभिहस्ताकित करके तथा ECGC द्वारा बैंकों की प्रि-शिपमेन्ट क्रेडिट एवं पोस्ट शिपमेन्ट क्रेडिट गारन्टियाँ जारी करके प्राप्त हुई कुल बैंक फायनेन्स १७३% बढ़ गई।

इतनी प्रगति कैसे सम्भव हुई? जब ECGC निर्यात जोखिम अपने कंधों पर ले लेता है, तो निर्यातकों के वैनिंग सम्बन्धी कागज पत्रों का महत्त्व बैंकरो की दृष्टि में बढ़ जाता है और वे उनके बिलों को सहज ही भुना देते हैं। किन्तु, ECGC निर्यातकों की अधिक प्रत्यक्ष एवं ठोस उपायों द्वारा बैंक से फाइनेन्स प्राप्त करने में सहायता करता है। जैसे—वह प्रि शिपमेन्ट पैगिय क्रेडिट पालिसियों (Pre shipment Credit Policies) अर्थात् बैंकों की इनके द्वारा निर्यातकों की निर्यात-बाजारों से लिये कच्चा माल खरीदने, विषायाण (processing) तथा पैकिंग करने हेतु दो जाने वाली फाइनेन्स के लिए गारन्टी देता है। अब ECGC ने दो नई गारन्टियाँ प्रचलित की हैं — (i) पोस्ट शिपमेन्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी, जिसका उद्देश्य किसी निर्यात बिल को भुजाने, खरीदने, अथवा विनिमय करने से उद्बध हुई हानि के विरुद्ध बैंक की रक्षा करना है, और (ii) एक्सपोर्ट फायनेन्स गारन्टी, जिसका उद्देश्य उन निर्यातकों को सहायता करना है, जो ऐसी वस्तुयें निर्यात कर रहे हैं, जिनकी

अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों आन्तरिक कीमतों से नीची है। यह गारन्टी बैंक-एडवांस के उस भाग को सुरक्षित करती है जो कि जहाजी प्रलेखों के मूल्य से अधिक है। दोनों ही गारन्टियाँ शर्त रहित हैं तथा उधार लेने वालों को नुटियों से बैंक की पूर्ण रक्षा करनी है चाहे हानि का कारण कुछ भी हो। हानि ही न दो नई गारन्टियाँ और चालू की गई हैं—एक्सपोर्ट कर्पोरेशन गारन्टी और एक्सपोर्ट प्रोडक्शन गारन्टी।

ECGC ने निर्यातकों के लाभाय एक अच्छाकार विदेशी क्रेडिट स्कीम लागू की (scheme of revolving foreign exchange credit) भी प्रचलित की है, जिसके द्वारा भारतीय निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही निर्यात उद्योगों के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा इस प्रकार स्थापित क्षमताओं के पूर्णतम प्रयोग के पक्षधर बनने की मित्र दयिताओं का लाभ उठा सकेंगे।

ECGC निर्यातकों के जोखिम में भाग लेने वाला प्रमुख साकेदार है, क्योंकि वह राजनैतिक जोखिमों का ८५% और व्यापारिक जोखिम का ८०% उठाता है। १ अप्रैल १९६६ से बीजों प्रसार के जोखिमों के लिये प्रतिशत १० कर दिया गया है। जोखिमों का 'साल जाच गड़ताल' की प्रणाली के आधार पर अभिगोचन किया जाता है। वह स्वतन्त्र खेतों के द्वारा जोकि निर्यातकों को सहज ही उपलब्ध नहीं होते हैं, प्रत्येक विदेशी क्रेडिट को, जोकि उधार लेना चाहता है, निम्नोप दशा और गुणवत्ता के बारे में व्यापक समीक्षा करता है, जिससे कि भारतीय निर्यातक गलत हाथों में न पड़ जायें।

जैसे ही निगम को सूचना मिलती है कि निर्यात किये गये सामान का मूल्य नहीं दिया जा रहा है, निगम पैसा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता लेता है और इस सम्बन्ध में स्वयं भा प्रयत्न करता है।

निर्यातकों को इसकी गई चिपमेंट पालिसियों के अधीन १९६८-६९ में निगम ने ७५ ६४ करोड़ २० की जोखिम उठाई। फायनेन्सियल गारन्टियों के अधीन उठाई गई जोखिम १२०.०७ करोड़ २० थी। प्रीमियम आय ५१ ५१ लाख २० हुई। निगम ने १६० लाख ८० के दावों (claims) का भुगतान किया। निगम की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले निर्यातकों की सराया बर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। १९६७-६८ में निगम ने १६८० पालिसियाँ जारी की थी जबकि १९६८-६९ में २४२० पालिसियाँ जारी की गईं।

परीक्षा प्रश्न :

१. निर्यात माल एवं गारन्टी निगम के कार्यकलापों की समीक्षा कीजिये।
[Examine the working of the Export Credit and Guarantee Corporation]
२. निर्यात वित्त से क्या आशय है? इसे सस्ता बनाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं? इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिये।

आयात-प्रतिस्थापन

(Import Substitution)

प्रारम्भिक—

यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि हमारे जैसे विकासोन्मुख देश का विशाल माना न आयात करना पड़े। जैसे—हम अपने उद्योगों को खड़ा करने के लिए पूँजीगत वस्तुओं, विदेशी टेक्नीकल ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का आयात करना पड़ता है। औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में ऐसे आयात अनिवार्य ही हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि आयात की कुल मात्रा को नियन्त्रण की सामान रखने के लिए प्रत्येक प्रयास करना चाहिए, जिसमें कि अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक भार न पड़े। यह उस दशा में और भी अधिक आवश्यक हो जाता है जबकि भुगतान संतुलन अनुकूल नहीं है। जब विदेशी मुद्रा दुर्लभ हो, तो यह आवश्यक है कि हम अपने आयातों को न्यूनतम सीमा तक घटा दें और जहाँ तक सम्भव हो वहाँ तक आयातों के बिना ही काम चलायें। पाकिस्तान से युद्ध छिड़ने पर भारत सरकार को आयातों पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े, जिन्होंने कई उद्योगों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया तथा इस प्रकार सब पर आयात-प्रतिस्थापन की महत्ता स्पष्ट कर दी।

आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता

जहाँ तक उद्योगों का सम्बंध है, हमारे देश की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को निम्न चार वर्गों में बांटा जा सकता है—(१) अनुरक्षण (Maintenance), (२) विकास (Development), (३) उपभोक्ता वस्तुएँ (Consumer goods) एवं (४) रक्षा सामग्री (Defence requirements)। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि इन सभी शीर्षकों के अधीन आयातों पर अपनी निर्भरता को न्यूनतम सीमा तक घटावें। साथ ही, निर्यात की मात्रा को बढ़ावें, जिससे कि हम अपनी आयात-आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें। खोपी योजना के लिये हम विदेशों से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिले है। इस मन्दर्थ में भी इन प्रयासों का महत्त्व बढ़ जाता है।

“आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।” विकास की रीति को बनाने

रक्षणे के लिए हमारी आगामी सम्बन्धी विद्यालय आवश्यकताओं ने, जबकि विदेशी मुद्रा प्रसाधनों की बहुत ही कमी है तथा विदेशी सहायता में कटौती होने की आशंका है, 'प्रतिस्थापन' के विचार को जन्म दिया है। 'विदेशी हथियारों का प्रतिस्थापन करिये', 'पी० एल० ४८० का प्रतिस्थापन करिये' और अब 'आयातों का प्रतिस्थापन करिये' य नारे भारत में जोर-शोर से लगाय जा रहे हैं।

आयात प्रतिस्थापन का अर्थ एवं स्वभाव

विदेशों से मंगाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का उत्पादन और प्रयोग करना ही 'आयात-प्रतिस्थापन' कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन भारत के लिये कोई नवीन चीज तो नहीं है लेकिन हाल के वर्षों में इस बात पर जो बल दिया गया है वह अवश्य ही नवीन है। सभी देशों में औद्योगीकरण की प्रारम्भिक अवस्था की यह विशेषता होती है कि आयातित वस्तुओं का स्थान खाने खाने नव-प्रचलित स्वदेशी वस्तुओं द्वारा लिया जाता है। अनेक देशों में तो सकल 'आयात-प्रतिस्थापन' न निर्यात-सम्भावनाओं में वृद्धि कर दी है। वास्तव में, भारत की विकास योजना के पीछे दुनियादी तत्त्व आयात प्रतिस्थापन ही है।

आयात प्रतिस्थापन मुख्यतः व्यक्तिगत पहल, कल्पना, साहस और निर्णय का परिणाम है। हार्मिंग इस बात का एक ज्वलन्त प्रमाण है। बड़ा सरकार में कोई मार्ग दर्शन न मिलने लुपे भी, उपनयनियों ने, लाभ अवसरों से, प्रेरणा प्राप्त करके, ऐसे उद्योग स्थापित किये जिनमें आयात-प्रतिस्थापन और निर्यात-विवर्धन दोनों ही सम्भव हो गये। एक विशाल स्वदेशी बाजार (जैसा कि भारत में है) की विद्यमानता ने भी आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन प्रदान किया है। आधुनिक युग में विविध-नियन्त्रणों और आयात प्रतिबन्धों के कारण कई विकासोन्मुख देशों में एक 'बन्द बाजार' (closed market) उत्पन्न हो गया है। इसने भी एक बड़े पैमाने पर आयात-प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित किया है। अनेक देशों में यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये अपनाई गई सरकारी नीति का परिणाम है। दुनियादी और सामरिक उद्योगों के सम्बन्ध में आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता 'आयात-प्रतिस्थापन' के लिये मुख्य प्रेरक शक्तियाँ रही हैं।

आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में उपाय

आयात-प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित उपाय करना आवश्यक है — (१) न्यून प्राथमिकता वाली, अ आवश्यक एवं विलास वस्तुओं के प्रयोग को विलकुल ही बन्द करना या बहुत घटा देना तथा इनके लिये स्वदेशी स्थानापन्न (substitutes) खोजना। (२) आधुनिक मशीनों और साज-सामानों के प्रयोग तथा कुशल प्रबन्ध के द्वारा दुर्लभ सामग्रियों के अपव्यय को रोचना या कम करना। (३) महंगे आयातों को वैकल्पिक आयातों से, जो कि कम सस्ते हों, प्रतिस्थापित करना। (४) ऊच्च मानों, लोचन निर्मित वस्तुओं आदि का अधिकतम प्रमाणीकरण करना, जिससे इन परस्पर परिवर्तन (interchangeability) सम्भव हो जाय।

(१) नए क्षमताये उत्पन्न करने के लिये विद्यमान क्षमताओं का पूरकतन प्रसार करना जोर जहा जहा सम्भव हो, विद्यमान प्लांटों का विस्तार करना । (२) निमित्त मान के लिये अत्याय को प्रोत्साहन देना । (३) देश में दुर्लभ सामग्रियों का उत्पादन करना । (४) विदेशी तकनीकी ज्ञान (Foreign technical know-how) के स्थान में पर्याप्त ज्ञान तकनीकी ज्ञान का उपयोग करना ।

आयात प्रतिस्थापन की समस्याएँ

आयात प्रतिस्थापन की कुछ अपनी समस्याएँ भी हैं —

(१) स्वदेशी आयात स्थानापन्न की उत्पादन लागतें प्रारम्भिक तद्व्यापारों में ऊँची हुयी होती हैं। अतः आयात-स्थानापन्न उद्योगों की सहायताएँ आयात नियन्त्रण और मरम्माणमक टैरिफ की आवश्यकता पड़ सकती हैं। आयात स्थानापन्न की ऊँची लागत अन्य वस्तुओं पर, अन्तर-उद्योग सम्बन्धों के द्वारा, प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उच्च गुणवत्तामय लाभ तथा उनकी गुणवत्तामय क्षमता को घटा देता है। यह बात उद्देश्य वस्तुओं और उपयोग वस्तुओं दोनों के सम्बन्ध में लागू होती है।

(२) प्रारम्भ में स्वदेशी स्थानापन्न की किम्ब भी घटिया होने की सम्भावना है। वस्तुओं की किम्ब घटिया होने में निर्माण में कमी हो सकती है तथा विदेशी आयातकों के विश्वास को ठेस लग सकती है जिस कारण अन्य वस्तुओं का आयात भी कम होना पड़ सकता है।

(३) आयात प्रतिस्थापन के लिए अविवेकपूर्ण दौड़ दौड़े उद्योगों का जन्म दे सकती है जो कि देश की प्रगति पर स्वार्थ बोक बन जायें। परिमाणान्तर प्रतिस्पर्धा और विविध नियंत्रणों की ओर में स्थापित हुए उद्योगों की कृपानता प्रायः बहुत ही नीची होती है। अतः निम्न गुणवत्ता ज्ञान पर इन्हें गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

(४) विभिन्न देश विद्योपत विक्रमों मुक्त देश, पारस्परिकता के आधार पर व्यापार करना पसन्द करते हैं। यदि हम किसी देश की वस्तुओं में खरीदने का निर्णय करें, तो हम उस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह देश भी हमारी वस्तुओं में खरीदने का निर्णय कर सकता है। एशिया और अफ्रीकी देशों की भारत से निर्यात रुकी है कि भारत उनमें पर्याप्त आयात नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि गुरुत्वाकर्षण व्यापार में अभाव में वे भारत में निर्यात बहुत सीमा तक बढ़ावेंगे।

भारत में हुई प्रगति

आयात पर बड़े प्रतिबन्ध लगाए रखने के साथ साथ, नये मात और मध्य-पूर्वी वस्तुओं आदि अनेक आवश्यक वस्तुओं के देश में ही उत्पादन का बढ़ावा देने के प्रयत्न किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में भेजा जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं का किम्ब सीमा तक उत्पादन हुआ, देशी मनेत्र उन वस्तुओं

में स अधिकांश की कुल सप्लाय के मुकाबिले आयात के अनुपात में हुई भारी कमी से मिलता है।

आयात प्रतिस्थापन—आयातित वस्तुओं के प्रतिपात

मिलार्ड की मशीनें	कुछ नहीं
टर्कों और वसे	४%
फिफ्ट मोटर कार	१%
वीप	३%
ए ब्रेकेडर कार		१ ४%
वेल्स स्क्रूटर	.	४%
लैब्रेटो स्क्रूटर		६%
रेलवे के डिब्बे		१%
मिजली के खम्भे	.	४%
मिजली आयातित पंप		१%
डीजन इंजन		५%
बीनी मिल मशीनें		८%
सीमेंट मिल मशीनें		८%
भ्रमण निर्माण मशीनें		२%
शीत ताप नियंत्रण यंत्र		१%
रेफ्रिजो		२%
साइकिल	कुछ नहीं

यद्यपि अधिकतर वस्तुओं की कुल उपरति ध (अर्थात् सप्लाय) बड़ी है परन्तु विदेशों से आयात की गर वस्तुओं का अनुपात घटा है। यह कमी १९२५-२६ से विशेष रूप से अधिक हुई। विदेशी वस्तुओं का कम से कम उपयोग करने में फिफ्ट मोटरकार रेलवे के डिब्बे साइकिल, मिलार्ड की मशीन, मिजली आयातित पंप तथा माल उठाने के यंत्र आदि उद्योग सबसे आगे रहे हैं। इंजीनियरी उद्योग की बहुत सी वस्तुयें अब विदेशी मानो का कम से कम उपयोग कर रही हैं। उद्योग कि उक्त सूची में दिखाया गया है। साइकिल और मिलार्ड की मशीनें और बिजली के पंखे तो पूर्णरूप से स्वदेशी हो गए हैं।

भारतीय मानक संस्था (Indian Standards Institute) महत्त्वपूर्ण मशीनों के साथ ध म अनुसृत देशी स्थानापन्न का सुझाव देती है। उदाहरण के लिये, साइकिल के धारे में, उसमें निचल या रोमिप्रम प्लेटिंग के स्थान में अब उपयुक्त पेंटस स्प्रिंगल करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय अनुसन्धानसालाये विभिन्न प्राइवेट, पब्लिक एंव डिफेंस संस्थानों, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, केन्द्रीय सड़क उद्योग संस्थान, केन्द्रीय

एव राज्य सरकार, विश्व विद्यालयों और अन्य अनेक मस्याओं ने भी आयात-प्रतिस्थापन की समस्या पर गम्भीरता से ध्यान देना आरम्भ कर लिया है। निर्यात-सम्बन्धन परिणदों ने एव निर्यात प्रोत्साहन आन्दोलन चलाया है। आयातों के विवेकीकरण और प्रतिस्थापन के लिये एक दम वर्षीय योजना पर विचार किया जा रहा है। किन्तु आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में हम वास्तविक प्रगति तक ही कर सकते हैं जबकि विभिन्न मण्डलों के अनिश्चित प्रत्येक उपरमी स्वयं भी इन दिशा में कार्य करना आरम्भ कर दें।¹

आयात प्रतिस्थापन के कार्य को सहज बनाने के मुभाव

पूर्ण आत्म-निर्भरता न तो सम्भव है और न वाछनीय। अम और अमेरिका देने साधन-सम्पन्न एव विकसित देश भी कुछ सामानों के लिये विदेशों पर निर्भर रहते हैं। सच तो यह है कि औद्योगीकरण और आयात प्रतिस्थापन दोनों के लिये पूँजीगत सामान और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यह बात कम से कम प्रारम्भिक अवस्थाओं के लिये सत्य है। उदाहरणार्थ, यद्यपि भारतीय रेलवे की कुल आवश्यकताओं का १०% भाग ही आयात हो रहा है तथापि पिछले दशक में उनका आयात-जल कठिनार्थ में हो कुछ घटा है। यही कारण है कि विगत वर्षों में आयात प्रतिस्थापन सब-सभी विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भारतीय आयात बढ़ते गये हैं। यद्यपि स उद्देश्य कुल आयातों में कमी करने का नहीं बरन् विदेशी मुद्रा की बचत का होना चाहिये, जिसमें कि हम पूँजीगत मान और बुनियादी उपभोग वस्तुओं को, जिनसे हम निकट भविष्य में देश में ही पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकेंगे, आयात कर सकें। आयात प्रतिस्थापन के कार्य को सहज बनाने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो० भार० एल० बार्णोय ने निम्नलिखित उपयोगी सुझाव दिये हैं — (१) आयात प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में प्रयत्न सुनियोजित एव विवेक सम्मत होने चाहिये, जिसमें असफल प्रयोगों से निराशा का सामना न करना पड़े। (२) आयात स्थानापन जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में ही उत्पन्न किये जायें। प्राइवेट सेक्टर को भी पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हाँ, सरकार को यह देखना चाहिये कि इन्फ्रान्स्ट्रक्चर्स पर्याप्त हों, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अपर्याप्त इन्फ्रान्स्ट्रक्चर्स ने आयात प्रतिस्थापन और सामान्य आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा डाली है। (३) लाइसेन्सिंग और नियन्त्रण कम से कम उन क्षेत्रों से हटा देने चाहिये जहाँ विदेशी निर्यात का प्रश्न नहीं उठता। इससे उपकरणों की पहल-भावना और निर्णय बुद्धि को स्वतन्त्र

¹ "But it is obvious that we would only be able to make real progress towards import substitution only, if in addition to these various organisation, every entrepreneur himself starts working in this direction."—S V Bhare, Industries Commissioner & Additional Secretary, Industries & Labour Dept Maharashtra.

भूमिका निभाने का सुयोग मिलेगा। ऐसी ही अनुकूल परिस्थितियों ने विदेशों में आयात प्रतिस्थापन को सफल बनाया है। (४) यदि सरकार देश में आयात प्रतिस्थापना वाले उद्योग कायम करना चाहती है तो उसे प्रायवेट विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन देना चाहिये। (५) आयात प्रतिस्थापना के लिये देश-विदेश के व्यापारिक एवं औद्योगिक सङ्गठन जो परामर्श दें उन पर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिये। (६) भारतीय उद्योग को भी चाहिये कि आयात प्रतिस्थापन या निर्यात सम्बंधन सम्बन्धी अनुसन्धान एवं विकास कार्य पर अधिक ध्यान दे।

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने सुझाव दिया था कि एक केन्द्रीय मस्था स्थापित करनी चाहिये जो आयात स्थानापन्नों की खोज करने वालों और इनका प्रयोग करने वालों के मध्य एक मंचना प्रसार सङ्घटन (Clearing House) का कार्य करे।

गडर राव का सुझाव है कि आयात प्रतिस्थापन की दिशा में विशाल परिपदों द्वारा किया गया कार्य सन्तोषजनक नहीं है। इनके बजाय ऐसी परिपदें स्थापित करनी चाहिये, जिनमें दोनों उत्पादक-वस्तु एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों।

उपसंहार—

इसकी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि वह भविष्य में ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना — लिये ही अनुमति देगी जो कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में ७५ से ८५% देशी मशीन प्रयोग करें। इससे हमारी आयात-निभरता कम होगी।

परीक्षा प्रश्न :

- १ आयात प्रतिस्थापन क्या है ? इसकी समस्याओं पर प्रकाश डालिये।
- २ भारत में आयात प्रतिस्थापन की दिशा में जो कदम उठाये गये हैं उनकी ममीक्षा कीजिये।

राजकीय व्यापार

(State Trading)

परिचय —

महान मन्दी (१९२९-३०) के पूर्व विदेशी व्यापार प्रायः पूर्णतः प्राइवेट उपक्रम (पब्लिक एव सक्करी) के हाथों में था तथा सभी विश्व-देशों में (एत और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को छोड़ते हुए) स्वतन्त्र व्यापार का ही बोलबाला था। किन्तु मन्दी ने प्रत्येक देश को बहुत हानि पहुँचाई, जिस कारण विवश होकर सरकारी ने विदेशी व्यापार में भाग लेना आरम्भ कर दिया। यह प्रवृत्ति आज भी प्रचलित है और पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है।

राजकीय व्यापार का अन्वय

राजकीय व्यापार का अर्थ यह नहीं है कि देश में आयात और निर्यात में भाग लेने वाले प्राइवेट व्यापारिक संगठन नहीं होंगे। वास्तव में, राजकीय व्यापार और प्राइवेट व्यापार एक दूसरे में पूर्ण मगलित रहते हैं। प्राइवेट व्यापार का मंचालन प्राइवेट व्यक्तियों और सङ्गठनों द्वारा होता है किन्तु सरकार का उन पर नियमन रहता है। इस प्रकार, राजकीय व्यापार का आशय व्यापार पर राज्य के स्वामित्व तथा नियमन से है जबकि वास्तविक व्यापारिक लेनदेन प्राइवेट उपक्रमियों द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकते हैं। किन्तु हम 'राजकीय व्यापार' (State Trading) और 'स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रम व्यापार' (Free Private Enterprise Trade) में भेद करना चाहिए। इन दोनों प्रकार की व्यापारिक तन्त्रोंको में मौलिक भेद यह है कि राजकीय व्यापार मुख्यतः देश के आर्थिक हित में मंचालित होता है, किन्तु स्वतन्त्र प्राइवेट उपक्रम व्यापार का व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से।

राजकीय व्यापार का महत्त्व

कुछ अर्थशास्त्रियों ने राजकीय व्यापार की बहुत सराहना की है किन्तु ऐसे भी अर्थशास्त्रज्ञ हैं, जिन्होंने इसे एकदम बुरा बताया है। इन दो 'अनियो' (extremes) के मध्य कुछ अर्थशास्त्रियों ने मध्यम मार्ग अपनाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार एक निष्पक्ष व्यक्ति को, जो एक ही व्यक्ति के दो अन्तर्गत व्यापार के भी दो पक्ष हैं—मकर (लाभ) और दुर्बल पक्ष (हानि)। अब इन्होंने यह मत प्रकट किया है

कि यदि राजकीय व्यापार की टेक्नीक का सन्चार के साथे सहो-सहो प्रयोग करे, तो देश इससे लाभान्वित हो सकते हैं।

राजकीय व्यापार के लाभ—

राजकीय व्यापार के निम्नलिखित लाभ बताये गये हैं—

(१) नियोजन के सदर्भ में आवश्यक—नियोजित अर्थव्यवस्था का राजकीय व्यापार के बिना चलना कठिन है। आर्थिक नियोजन में परिमाणात्मक नियोजन का प्रदत्त निहित है और परिमाणात्मक नियोजन (quantitative planning) राजकीय व्यापार के अभाव में सम्भव नहीं है। यदि विदेशी व्यापार प्राइवेट उप-श्रमियों के हाथों में स्थान-न छोड़ दिया जाय तो परिमाणात्मक सभ्यो की पूर्ति सिद्ध हो जाती है। यही कारण है कि विश्व की लगभग सभी नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में राजकीय व्यापार प्रचलित हो गया है।

(२) नियोजित अर्थव्यवस्थाओं से व्यापार में सुविधा—कुछ विश्व अर्थ-व्यवस्थाएँ (जैसे रूस और नैकोस्तालिया) नियोजित अर्थव्यवस्थाएँ हैं। इनकी नीति 'सरकार से सरकार स्तर पर' लेन देन करना है। अतः ऐसे देशों में प्राइवेट व्यक्ति एवं संगठन सामान्य तम से वस्तुएँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि इन देशों में व्यापार करता हो, तो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाओं को भी राजकीय व्यापार का सहारा लेना पड़ेगा। [हाल में कुछ नियोजित अर्थव्यवस्थाओं की सरकारी एजेंसियों ने प्राइवेट व्यापारियों से लेन देन करने की इच्छा प्रकट की है।]

(३) वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता के रूप में पूर्णतम् लाभ होना—एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश (जैसे कि अमेरिका) राजकीय व्यापार के माध्यम से, वस्तुओं के क्रेता और विक्रेता के रूप में अपनी आर्थिक शक्ति का, आर्थिक रूप से दुर्बल देशों (जैसे सेंटिन अमेरिकी देश, से व्यापार का पूर्णतम् सम्भव लाभ उठाने में, प्रयोग कर सकता है।

(४) देनदार राष्ट्र के लिए लाभ—राजकीय व्यापार के द्वारा देनदार राष्ट्र अपनी ऋणशक्तता को भी अपन लाभार्थ स्थापन कर सकता है। उदाहरणार्थ, जर्मनी को लीजिए, इसने १९३०-१९३६ के मध्य, अपनी देनदार-स्थिति का लाभ उठाने हुए ही अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करली थी।

(५) स्वदेशी उत्पादकों को उत्तमोत्तम लाभ—स्वदेशी उत्पादन में तो व्यक्तिगत रूप से इतने शक्तिशाली होते हैं और न इतनी शक्तिशाली उदाहरणों में ही अपना नमूना कर पाते हैं कि विदेशों से शलाका प्रतिपादित का सामना कर सकें। राजकीय व्यापार के बारे में यह कहा जाता है कि वह स्वदेशी उत्पादकों को सुरक्षा देने का सर्वोत्तम साधन है। उदाहरणार्थ, भयंकर मन्दी युग में अनेक रुपक देशों ने कोम्पनी के उतार-चढ़ाव में स्वदेशी उत्पादकों की सहायता के लिए राजकीय व्यापार की टेक्नीक अपनाई थी।

(६) मन्दी से मुक्ति—राजकीय व्यापार देश की मन्दी के प्रभावों से रक्षा करना है। उदाहरणार्थ, अर्जेन्टायना में सरकार ने एक 'थेन रेग्युलेटिंग बोर्ड' स्थापित किया था जिसका उद्देश्य एक नियत सोमा में अधिक कीमतें गिरने पर अनाज की खरीद करना था और जब कीमता में असाधारण वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती थी, तब वह नुरक्षण कोषों में अनाज बचा करता था।

(७) विदेशी विनिमय कोषों पर अनुचित दबाव हटाने बिना ही आयात सम्भव होतः—राजकीय व्यापार देश को आवश्यक वस्तुओं विदेशी मुद्रा के द्वारे में कार्द विन्य बिना किया बिना ही बॉक बय ठहरावों या द्विपक्षीय समझौतों (bulk purchase agreements or bilateral trade agreements) के द्वारा, आयात करने में समर्थ बनाना है।

(८) सङ्गण अवधि के लिए उपयुक्त नीति—प्रती राजकीय व्यापार को एक पारित्वेन न स्वाधिक होतः न समर्थ सपना। तब तब, मध्यान्तर तबि न द्वि-पक्षवाद का अपनाता होगा आ राजकीय व्यापार के बिना सम्भव नहीं है।

राजकीय व्यापार के दोष—

राजकीय व्यापार के विरोधी न केवल इसके मध्यान्को द्वारा इस प्रणाली के नियम न बनाने गत गुणों में त्रुटि देखने हैं बरन् इसके कुछ स्पष्ट दोष भी बताने हैं य उर एत बाल निम्नलिखित हैं

(१) निहित स्वाधो की स्थापना—गिरती हुई कीमतों के पुनः मन्दी उन्नादकों का संरक्षण देने के लिए जितनी योजनाएँ बनाई गईं वे सब अन्ततः लाभ रमा के उपाय के रूप में प्रयोग की गईं। उदाहरणार्थ, न्यूजीलैण्ड में एक ऐसी योजना बनाई गई थी कि मन्दी के दिनों में कीमतें इतनी ऊँची निर्धारित की जायें जिसमें उन्नादकों का सामान्य लाभ हो सके। किन्तु मन्दी समाप्त होने के बाद भी कुछ काल और कुछोत्तर काल में, जो कि कुलभता और अभाव की अवधिमा थी, यह नीति लागू रही गई और इस नीति की चाल रखने के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि यह देश में कीमत स्तरों में स्वाधिक प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार, अर्जेन्टायना में थेन रेग्युलेटिंग बोर्ड ने द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के बाद भी कार्य करना बन्द नहीं किया यद्यपि वहाँ अनाज की कीमतें बहुत ऊँची हो गई थी। इन सम्बन्ध में तर्क यह दिया गया कि बोर्ड की अब कुछ लाभ बना लेना चाहिए ताकि दुर्दोतरवाद में जब कीमतें घटनी शुरू हो जायेंगी, तो उसका प्रयोग किया जा सके। इन प्रकार, एक बार अपनाते पर राजकीय व्यापार का विस्तार होता नहीं है।^१

^१ 'Once state trading is established it will become a voracious creature and be not satisfied with its existing functions. It will like Oves Twist always, hanker for more.'—Kestri D Doodha : *Economic Relations in International Trade* p 109

(२) विश्व समाज की आर्थिक हानि—राजकीय व्यापार, सरकार के द्वितीय कानूनलापों द्वारा, कीमती को ऊँचे स्तरों पर रखने की युक्ति बन गया है। ऊँचो कीमते उपभोग को घटाती है। घटी हुई माँग उत्पादन के पैमाने को सीमित (restrict) करती है। चूँकि बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिताओं को सत्रिय होने में रोक दिया जाता है, इसलिए विश्व समाज को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।

(३) स्वतन्त्र और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से इसका सामंजस्य नहीं—राजकीय व्यापार की नीति एक ऐसा व्यापारिक पैटर्न स्थापित करती है जो कि स्वतन्त्र और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से असङ्गत (inconsistent) है।

(४) अकुशलता को बढ़ावा—स्वतन्त्र व्यापार के अन्तर्गत एक बड़ा सर्वोत्तम विश्व बाजार में खरीदने और बेचने के लिए स्वतन्त्र होता है। किन्तु राजकीय व्यापार की प्रणाली के अन्तर्गत उसे ऐसी स्वतन्त्रता नहीं होती है। प्रतिमोहिना समस्त आर्थिक प्रगति का मूल है, किन्तु यह राजकीय व्यापार की दशा में अनुत्पन्न होती है। परिणामतः अकुशलता पनपती है।

(५) विभाजित विश्व-अर्थव्यवस्था—राजकीय व्यापार द्वि-पक्षवाद को बढ़ावा है और द्वि-पक्षवाद विश्व-अर्थव्यवस्था के टुकड़ों में बँटने का। जब विश्व-अर्थव्यवस्था विभाजित होती है, तब आर्थिक रूप में शक्तिशाली देश आर्थिक रूप में पिछड़े हुए देशों का शोषण करने का अवसर पा जाते हैं। यह शोषण कुछ समय तक जारी रहता है और अन्तिम में दुर्बल राष्ट्रों में इसके प्रति विरोध उमड़ने लगता है, जो फिर विश्व-ध्वान्ति के लिए खतरा बन जाता है।

(६) समुचित समूहन संरचना का अभाव—व्यापार के लिए विशिष्ट ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। बाजार दशाओं का ज्ञान तथा निर्णय क्षमता होना भी आवश्यक है। किन्तु ये गुण एक सरकारी एजेंसी में नहीं होते, क्योंकि उनमें नीतिरक्षाही का बोलबाला होता है।

(७) केन्द्रीयकरण सम्बन्धी दुर्बलताएँ—कहा जाता है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वह कितनी ही जानकारी रखती हो अनेक कर्तव्यों और सप्ताहों में जीवित और सफलतापूर्वक कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसकी यह असमर्थता 'व्यापार की शक्तों' पर बुरा प्रभाव डालती है।

(८) बाजार सम्बन्धी दशाओं में असमर्थता—अनुभव से पता चला है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा थोक खय (bulk buying) के कारण बाजार दशाओं में अनाम्यता उत्पन्न हो जाती है। विरोध एक ऐसे बाजार में, जिसमें कीमते बढ़ रही हैं इस प्रथा ने कीमत वृद्धि की ओर भी बलित उत्साह दिया, जिसमें खरीदें माना और मूल्य की दृष्टि से अनाधिक हो गई।

स्पष्टतः, राजकीय व्यापार एक मिश्रित वरदान है। जब तक उसे नहीं रूप से और सच्चाई के साथ प्रकाशित नहीं किया जावेगा, राजकीय व्यापार की नीति

से सम्भर आर्थिक समस्याये उत्पन्न होने का भय रहेगा। समाज के व्यापक हितों में वृद्धि करना जो दूर यह आर्थिक अतिरमण (aggression) का साधन भी बन सकती है।

विश्व में राजकीय व्यापार की लोकप्रियता

राजकीय व्यापार युद्धोत्तर काल की एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। प्रत्येक देश ने चाहे उसकी राजनैतिक विचारधारा कुछ भी हो, अपनी कुछ आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए ग्लोबलिक सीमा तक राजकीय व्यापार को अपनाया है। अधिकांश स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्थाओं में राजकीय व्यापार कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। पश्चिम यूरोप के देशों में, अमेरिका आस्ट्रेलिया ग्युजीनैण्ड और अनेक एको-एशियाई देशों में (जो कि विकसित होने की अवस्था में हैं), राजकीय व्यापार अपनाया गया है। 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग-संगठन' (Organisation for European Economic Co-operation) के अध्ययन के अनुसार इन देशों में अमेरिका और कनाडा से कुल आयातों का ११% भाग राजकीय व्यापार के अधीन है। एफ़ इकोपी (ECAF) अध्ययन के अनुसार, राजकीय व्यापार युद्धोत्तर काल में इस क्षेत्र के विशालीनित देशों में अधिकाधिक महत्त्व प्राप्त करता जा रहा है। जर्मा, लक्सा और इन्डोनेशिया जैसे देशों में राजकीय व्यापार कुल व्यापार का एक बड़ा अनुपात है। जापान, मलेशिया, फिलिपीन्स और आस्ट्रेलिया में भी व्यापारियों में राजकीय व्यापार का आशय लिया है जिससे कि आवश्यक वस्तुओं की सच्चाई पर्याप्त और नियमित रूप में मिलती रहे तथा इनके उत्पादन विपणन एवं वितरण पर नियन्त्रण द्वारा इनकी आन्तरिक कीमतों में स्थायित्व आ सके। इकोपी रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भी इन देशों में राजकीय व्यापार बढ़ेगा तथा उनके सम्पूर्ण व्यापार और विकास यात्रनाओं का अभिन्न अङ्ग बन जायगा। इसी प्रकार, अफ्रीका व निर्यातमुख्य देशों (जैसे माइनीरिया घाना सूडान, तन्जानिया और माली), तथा दक्षिणी अमेरिका के के विशालीनित देशों (जैसे ब्राज़िल पेरू एंड मारीसस) में भी राजकीय व्यापार पर्याप्त लोकप्रिय है।

पूर्वी यूरोप की केन्द्र नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में तथा चीन में तो सम्पूर्ण बिजनी व्यापार तथा समस्त आन्तरिक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। इनका संचालन प्रायः पूर्णरूपेण सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

भारत में राजकीय व्यापार

भारत में राजकीय व्यापार का सुभारम्भ —

राजकीय व्यापार की टेक्नीक का सबसे प्रारम्भिक रूप ईस्ट इण्डिया कम्पनी है। इसका आधुनिक रूप स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में दिखाई देता है। राज्य द्वारा स्थापित व्यापारिक संस्था की धारणा सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध काल में विकसित हुई। तब से इस पर सामयिक विचार विमर्श होते रहे हैं। सन् १९४६ में, डाक्टर देशमुख की अध्यक्षता में एक स्टेट ट्रेडिंग कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी का यह मत

था कि सरकारी खाते में व्यापारिक कार्यकलापों का संचालन करने के लिए प्रचलित विभागीय व्यवस्थाएँ ठीक नहीं थी और इनके स्थान में एक विशिष्ट संगठन बनाने की आवश्यकता थी। अतः इसने यह सुझाव दिया कि खाद्यान्न और उर्वरकों के सम्बन्ध में सरकारी विभागों के तय विषय कार्यकलाप एक विधान निर्मित संगठन को सौंप दिये जायें जिसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के नाम से पुकारा जाय। इस निगम को पूर्वी अफ्रीका से कपास का आयात करने तथा छोटे रेगे वाली कपास एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात का काम भी सौंपा जाय।

सरकार ने इन सिफारिशों का स्वीकार नहीं किया। अम्योक्ति का कारण यह बताया गया कि विश्व बाजारों में परिस्थितियाँ बदल गई हैं और इस बीच आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त बढ़ गया है। सन् १९४२ में एक अन्य कमेटी भी कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में नियुक्त की गई जिसने राजकीय व्यापार के प्रश्न पर पुनः विचार किया। पहली कमेटी के समान डरान भी यह सिद्धान्त स्वीकार माना कि एक राजकीय व्यापार मन्त्रालय की स्थापना श्रेयस्वी चाहिए। इनकी मत भिन्नता केवल सीने जाने वाले मायों के सम्बन्ध में थी।

सन् १९५१-५२ के करारोपण जॉब कमीशन ने यह मत प्रगट किया कि अभी व्यापार के क्षेत्र में सरकार के विस्तृत एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का उपायुक्त समय नहीं आया है। जबकि यह विचार विमर्श चल रहा था, देश समरजबादी तमूने के समाज की विघ्ना में तेजी से बढ़ रहा था। इसके असिद्धि द्वितीय योजना के बड़े हुए आकार के कारण सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। ऑल इण्डिया कांफ्रेंस कमेटी की एक सब कमेटी ने सन् १९५४ में द्वितीय योजना के प्रारूप पर विचार करते समय यह सुझाव दिया था कि एक राजकीय व्यापार मन्त्रालय की स्थापना के लिए जो कि विदेशी एवं आन्तरिक दोनों ही प्रकार के व्यापार में भाग ले सक्रिय एवं त्रोटक कदम उठाने चाहिए। पहली बार सन् १९५५ में वित्त मन्त्री ने इस प्रकार की स्थापना के सिद्धान्त का स्वीकृत किया और कहा कि जब ऐसे संगठन की स्थापना होगी, तो उसका उद्देश्य वस्तुओं के व्यापार का नियमन करना होगा। मर्चेंट्स ट्रेडिंग के एक बिल (१९५६) में भी राजकीय व्यापार संगठन के पक्ष में मत दिया।

अन्ततः मई मन्त्र १९५६ में ५ करोड़ रु० की अधिकृत पूँजी से राजकीय व्यापार निगम (STC) स्थापित हुआ। यह एच पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाला संगठन है। इसकी सम्पूर्ण पूँजी सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

राजकीय व्यापार निगम के कार्य—

राजकीय व्यापार निगम प्राइवेट क्षेत्र में प्रतियोगिता नहीं करता। इसके प्रमुख कार्य निम्न हैं—(i) राज्य नियन्त्रित अव्यवस्थाओं से व्यापार के निम्न माग प्रवाह करना। (ii) कुछ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए उचित कीमतों पर व्यवस्था करना। (iii) व्यापारिक विवादों को निपटाने में सहायता करना।

(iv) ऐसी वस्तुओं के आयात-निर्यात का भार लेना, जिन्हें थोक में ही प्राप्त किया जा सकता है। (v) दुर्लभ वस्तुओं में व्यवहार करना और इनके विनियमित वितरण में सहमति करना। (vi) आयातों के साथ निर्यात (linking imports with exports) की शर्तें जोड़कर निर्यातों को बढ़ावा देना। (vii) निर्यात माँग की समुचित पूर्ति के लिए उत्पादन को संतुष्टि करना एवं निर्यात आदेश पूरा करने में सक्षम हुए उपक्रमों को सहायता देना। (viii) राजकीय व्यापार नति देशों के साथ विनियम ठहरावों के समुचित सम्पादन पर ध्यान देना।

निगम द्वारा किया गया कार्य—

मार्च १९७० तक राजकीय व्यापार निगम द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं —

(१) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार—निगम को पूर्वी यूरोप के आठ देशों (इस्तोनिया, लैतोनिया, लिथुनिया, जर्मन जनतन्त्रशासक राज्य (GDR), हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, रूस और यूगोस्लाविया) के साथ व्यापारिक सम्बन्धों में, समय-समय पर किये गये द्विपक्षीय ठहरावों के आधार पर, एक उज्ज्वल स्थिति प्राप्त है। निगम ने इन राज्यों में न केवल परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात बढ़ाया है बल्कि कई नई मर्चे भी प्रचलित की हैं।

(२) निगम के कुल व्यापार में वृद्धि—निगम के व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। १९५६-५७ में यह ६.१८ करोड़ रु० में बढ़कर १९६२-६३ में १४१.२६ करोड़ रु० हो गया। १९६३-६४ में MMTC की पुष्कल स्थापना के फलस्वरूप व्यापार में कमी आई और केवल ६७.७७ करोड़ रु० रहा। १९६५-६६ में ६६.४६ करोड़ १९६६-६७ में १५६.४ करोड़ रु०, १९६७-६८ में १४१.२० करोड़ रु० तथा १९६८-६९ में १६७.२० करोड़ रु० था।

(३) दो विभाग—निगम का कार्य अधिकाधिक बढ़ रहा था, इसलिए सरकार ने कॉर्पोरेशन के कार्यों को दो मस्थाओं में विभक्त कर दिया। अक्टूबर १९६१ में एजिन्ट और पब्लीक वेंचर्स के व्यापार के लिए एक अलग विभाग बना दिया गया। दोनों विभाग अब अपने-अपने व्यापार की बटाली के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं। १९६४ में धातु पत्ती व्यापार निगम की भी स्थापना हुई।

(४) निर्यात व्यापार—निगम के निर्यात १९६६-६७ में ३०.६६ करोड़ रु० और १९६८-६९ में ४८ करोड़ रु० हुए और १९६९-७० में ५२ करोड़ रु० तक पहुँचने की आशा है। इस प्रकार वह दिन दूर नहीं जबकि निगम अपने १२५ करोड़ रु० वार्षिक निर्मात के लक्ष्य को पूरा कर लेगा। STC के विभाजन के फलस्वरूप धातुओं और यन्त्रों की १३ मर्चों में व्यापार का कार्य MMTC को चला गया। अब भी STC के साथ मजिन मर्चा का व्यापार चलता है और उनकी गिनती करना जारी है। नई पुरानी मर्चों को मिलाकर इनकी कुल संख्या लगभग ११० है जिनमें उसका व्यापार ९० देशों में हुआ। लगभग ४१ देशों में इसने १०८ मर्चें पच्चीस बार प्रचलित की

हैं। इनमें से कुछ मदी ने तो इन देशों की आयात सूची में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है।

निगम के निर्यात को चार श्रेणियों में वर्गित किया जा सकता है—(अ) इजिप्टियन मुद्स (मसीतां औजार, रेशमे रॉलिंग स्टॉक और सधु उद्योगों के उत्पाद सम्मिलित करते हुए), (ब) कंभोक्लस, दवाये वादि, (स) उपभोक्ता सामान (जैसे—जूते, बान, ऊनी चरत्र, सूती बस्त्र), एवं (द) आम व फलों के रस। निगम के सुप्र-
 २ यन्नों का ही यह परिणाम है कि कई देशों में रेलवे रॉलिंगस्टॉक के निर्यात के लिये अनुबन्ध हुये हैं तथा इनकी पूर्ति के लिये समुचित व्यवस्थाये भी जा सकी है। नि तदेह रेलवे भारत से रॉलिंग स्टॉक के निर्यात का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। निगम ने स्पेन, अफ्रीका और मध्यपूर्व में भी टैंडर दिये और वे स्वीकार हुये हैं। निगम ने विदेशी व्यक्तिगत फर्मों की सुविधा के लिये अमेम्बनी केन्द्र खोले हैं। ऐसा एक केन्द्र म्गोस्लाविया में खुला है। जूते के निर्यात का रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के बाद अब प० यूरोप, अमरीका और कनाडा में भी बढ़ाने के यत्न किये जा रहे हैं तथा इनके फलस्वरूप निगम को कनाडा और अमरीका से कुछ बाँधर भी मिले हैं। मन्त्रास की बिग पैक्ट्री ने काम चालू कर दिया है तथा भविष्य में निगम वालों का कच्ची हालत में निर्यात करने के बजाय बनी बनाई सामग्री के रूप में निर्यात किया करेगा। धातु के निर्यात को बढ़ाने के लिये निगम इनकी पैकिंग टेक्नीक में सुधार कर रहा है। निगम विदेशों में (सब प्रथम योरोप में) गोदाम सुविधाये स्थापित करने का विचार कर रहा है। इन गोदामों का लाभ सभी निर्यातकर्त्ता उठा सकेंगे। इस प्रकार, उन्हें निर्यात आदेशों को पूरा करने में सुविधा हो जायेगी।

(५) सम्पर्क, बदल-बदल एवं समानान्तर व्यवहार—निर्यात बढ़ाने और कुछ निविष्ट देशों को कुछ वस्तुओं के निर्यात में कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निगम ने जो महत्त्वपूर्ण ढंग अपनाये हैं उनमें से एक ढंग विदेशों में अच्छी क्पाति बानी फर्मों के साथ 'सम्पर्क, बदल-बदल और सामानान्तर व्यवहार' (link, barter and paralleled deals) करना है। इस तरीके से एक ओर सीमित विदेशी मुद्रा प्रसाधनों पर भ्रर डाले बिना ही देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात की व्यवस्था हो गई है, और, दूसरी ओर, भारतीयों के बेची न जाने वाली वस्तुओं के तथा उन वस्तुओं के, जिनमें निर्यात आवश्यक तो उपलब्ध है किन्तु कीमत-विषमता के कारण वे पर्याप्त मात्रा में निर्यात नहीं की जा रही थी, निर्यात में भी बहुत वृद्धि हो गई। अन्य शब्दों में, विदेशी मुद्रा की बचत करते हुए अत्यावश्यक आयात प्राप्त किए गये हैं।

उपरोक्त व्यवहारों के फलस्वरूप भी कई नई वस्तुयें पश्चिमी यूरोप को जानें लगी हैं, जैसे—टाट के थैले स्विटजरलैंड की, सिलार्ड की मदीने फ्रांस और प० जर्मन की तथा ऊनी बस्त्र, तम्बाकू और लनी बलीचे स्वीडन की। यही नहीं, इन व्यवहारों के कारण जूट के सामान और बोक्साइट (इटली), चाय और सूती वस्त्र

(निव्वरलरलरल) जूट का सामान चाय, सूती वस्त्र, हाथ वरखे के वषडे आदि (स्कोटन) का नियाम पहले की अपेक्षा बढ गया है। नियम को इस दिशा में जो मरुतता मिली है उनकी ससद की आगषन समिति (Estimates Committee) ने बढी मरुतता की है।

(६) कीमतों में स्थायित्व लाने के प्रयत्न—सरकार की इस नीति के मरुर्म में कि इस के उत्पादन को उच्चतम सम्भव स्तर पर बनाये रखा जाय, कुछ वस्तुओं के उत्पादन को उच्चतम सीमा दिनाई जायें तथा एक बढती हुई दर में बिदना माग को पूरा किया जाय नियम में समय-समय पर कीमत स्थायित्व एवं 'वन्डर-स्ट्रोक' सम्बन्धी कार्यबलाप हाथ में लिये हैं। ये कार्यबलाप कच्चा जूट, जाम, मन्दाकू, टाट रंगे बाली कपास आदि के सम्बन्ध में ये और इनके नियम की यथेष्ट मरुतता मिली है।

(७) लघु एवं मध्यम उद्योगों की वस्तुओं के निर्यात को बढावा—प्रगति-शील औद्योगिक देशों में लघु एवं मध्यम पैमाने के उद्योग यथेष्ट मात्रा में निर्यात करने हैं। पिछले १०-१५ वर्षों में भारत में भी अनेक छोट और मध्यम उद्योग बिस्मित हो गये हैं किन्तु इस निर्यात में उनका भाग बरिध नहीं रहा है। अतः नियम ने 'लघु उद्योगों के लिये निर्यात सहायता की योजना' (Export Aid for Small Industries) बनाई, निम्न अन्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्योगों में सम्बन्ध निर्माताओं का व्यापक 'बिपन्न-सेवा' प्रदान की जाती है। जैसे—निर्यात के लिये उत्पाद का चुनाव करना, पैकिंग, डिजायन, कंटेनरों तैयार करना एवं अन्य बिस्व व्यापिक सहायता मन्त्रै, कीमत निर्धारण आदि। नियम के प्रराली में लघु उत्पादकों को बिबेधों में एवं बढी राशि में आउर मिले। व निर्यात स्वभाव में अमरुतरागन है, क्योंकि अब तक इनका भारत में बरगी निर्यात नहीं हुआ था।

(८) नियम द्वारा आयात—नियम में अनेक प्रकार के औद्योगिक करने मालों और उर्वरकों के आयात का कार्य भी हाथ में लिया हुआ है। कास्टिक सोडा, सोडा एस, कच्ची रेशम आदि के आयात में तो उसका एकाधिकार है। म्यूज प्रिन्ट, प्रिडिय मशीनों, कच्ची किचन, एक्मरे किचन, फोटोग्राफिक सामान, ट्रेक्टर, मशीन हुस्म, टायर-स्प्रूब, बिभिन्न प्रकार के रसायन आदि राजकीय व्यापार वाले देशों एवं अन्य देशों में आयात लिये जाते हैं और मान्य एजेन्सियों द्वारा इनका बितरण कराया जाता है। सीमेन्ट के बितरण का तथा आयातित करो के क्रय बिस्व का कार्य जो नियम के क्रिमे रता है। यह बहुत ही मरुतनीय बात है कि अन्तराष्ट्रीय सूचना पर ही नियम राज बिस्व-बान्तर परिस्थिति के बावजूद पूर्णोणत सायान, करने मालों एवं दुर्लभ सामग्रियों की अन्तराष्ट्रीय कीमतों पर ब्यवस्था करने में समर्थ हुआ है। उसने आयात क्रियाबलाप बढी ही कुशलता में मरुचालित किन हैं।

(९) कीमत नीतियाँ—नियम द्वारा किन वस्तुओं के आयात की ब्यवस्था की जाती है उनको दो वर्गों में बाँटा जा सकता है —(१) प्रमुख आयात, जो कि

वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को सुपुर्दगी देने के लिये हैं, तथा (ii) अप्रत्यक्ष आयात, जो विदेशी मन्थालयों के भारतीय एजेंटों द्वारा 'स्टाक और विक्रय आधार पर', बाद में निश्चित अधिकारियों के आदेशानुसार वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को बेचे जाने के लिये हैं। प्रथम वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में निगम केवल नाममात्र का ही कमीशन नेता है किन्तु दूसरे वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय एजेंट को अपने उपरिव्यय (overhead expenses) पूरे करने तथा अल्प लाभ कमाने का अवसर दिया जाता है और नितम अपने लिए नाममात्र का सेवा व्यय लेता है। कुछ वर्ष पूर्व स्टॉक एवं विक्रय आधार पर आयात बन्द कर दिए गए थे लेकिन अधिकांश वस्तुओं के सम्बन्ध में, इसकी उपयोगिता का अनुभव करके, इन्हें पुनः आंशिक या पूर्ण रूप में आरम्भ कर दिया गया है।

(१०) सहायक संगठन—निगम के दो सहायक मज्जून हस्तकौशल और हाथकरवा निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Exports Corporation) हैं जो नमूना हाथ करवा और वस्तुकारों की वस्तुयें तथा भारतीय फिल्मों का निर्यात करने हैं। निगम ने CAPEXIL द्वारा गठानित 'आस्ट्रेलिया को रूपायनों का निर्यात बढ़ाने की योजना' में भी भाग लिया है।

(११) विदेशों में कार्यालय—विभिन्न देशों में बढते हुये व्यापारिक आता-वरण से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने तथा विदेशी देशों में भारतीय निर्यातों को प्रीत्याहृत देने के प्रवास में निगम की सहायता के लिये निगम ने विदेशों में शाखा कार्यालय खोलने की नीति अपनाई है। उसने रोडहंम, प्राग, मास्को, बुडापेस्ट, पूर्वी बर्लिन, मीडियल और नरोवी में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और वेगनाम, बेरग, बार्हिरा, लागोस, तेहरान और काबुल में भी खोलने जा रहा है। निगम का कार्य संचालन मितव्ययितापूर्वक तथा जनहित की दृष्टि से किया जाता है। लाभकीताशाही यथासाध्य दूर रखी जाती है। इसके उपरिव्यय उचित सीमाओं के भीतर रहते हैं।

(१२) निगम की आय में वृद्धि—१९६५-६६ के लिये निगम को १२.०६ करोड़ २० का कर-पूर्व लाभ हुआ था। १९६६-७० में पहली तीन तिमाहियों के लिये उसे १२.०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाभ है। इस प्रकार निगम की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है किन्तु उसके व्यय विद्यमान वर्षों की अपेक्षा काफी बढ गये हैं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसके व्यापारिक कार्यकलापों में भी वृद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का भूत्यांकन—

राजकीय व्यापार नियम के कार्यकलापों के उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से यह निश्चित स्पष्ट है कि वह देश के विदेशी व्यापार को बढ़ाने एवं विविध मुद्दों बनाने में सफल रहा है। इसने आवश्यक कच्चे माल प्राप्त करने और फिर उत्पादितियों में इनका समुचित वितरण करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। निर्यात करने वालों को

आयात करने में प्राथमिकता देकर व्यापारिक आधार को सुदृढ़ किया है। राजनीय व्यापार वाले देशों में व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने में साथ-साथ उसने जापान और अमेरिका जैसे देशों में वहाँ की व्यापारिक संस्थाओं में भी सम्बन्ध स्थापित किये हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए आयात व्यवस्था को सुधारने की योजनाएँ भी बनाई हैं और इनके लिए धन की व्यवस्था निगम द्वारा स्थापित एक विशेष कोष से की जाती है। अनेक देशों से हमारा व्यापार जहाँ प्रतिकूल था, वहाँ अब अनुकूल हो गया है।

देश की विविध मुद्रा की जाय म निगम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी दत्त पूँजी १९५६-५७ में १० मि० से बढ़कर अब २० मि० हो गई है। ईन्क ने एच में भी इसने बड़ी राशि का सरकारी खजाना को दी है। निगम में उत्पादन के क्षेत्र में भी बढम बढ़ा दिया है। उसने मद्रास में एक विंग फैक्ट्री खोली है। उसने प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर कुछ वस्तुओं के उतारने बढ़ाने के लिये मित्यप्रीतापूर्ण नित्य कृपा व्यवस्था की है। उसने बम्बई में एक विशाल टैंक बनाया है जिससे आयातित वनस्पति तेलों की सहेज करके रखा जा सकेगा।

उक्त सफलताओं के साथ ही माघ निगम की निम्न दुर्बलताएँ भी सामने आई हैं — (१) निगम उद्योगीताओं की आवश्यकताओं के अनुसार गम्य पर, व्यापारिक न्युनो पर और वांछित विरम का माल आयात करने में असफल रहा है। (२) उसने कई वस्तुओं का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय मूल्यों से कम दरो पर करके विदेशी-मुद्रा अर्जन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की है। (३) उसने निजी निर्यातकों के कौटो म मदा कटौती की प्रणाली अपना कर देश के निर्यात व्यापार की उपेक्षा की है। (४) नियम में अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करके अपनी पूँजी अदकाई है और देश की औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार समय पर आवश्यक वस्तुओं का सभरण नहीं किया है। (५) उसने विश्व बाजार की पूर्ण जानकारी के अभाव में ऊँचे मूल्यों पर वस्तुओं का आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लागतें बढ गईं। जैसे—लोहाशीन का तेल खरीदने समय ५० डालर प्रति टन अधिक चुकाया गया है। (६) निगम की ओर में सुपदगी देने में विलम्ब हुये हैं। इसके आर्धर एह हो गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हें कार्यान्वित करने में सुस्ती करता है। (८) वस्तुओं के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियमन का अभाव है। (९) इसका स्टाफ बार बार बदलता रहता है। (१०) इस बारे में बहुत ही अतिरिचितता प्रतीत होती है कि निगम किन वस्तुओं का आयात-निर्यात करेगा। अथवा वह अवस्थ में किन दिशाओं में अपना कार्य बढ़ावेगा।

निगम के विरुद्ध यह भी आरोप लगाया गया है कि वह वस्तुओं के आयात के लिए ऊँची कीमतें ने रहा है और इस प्रकार ऊँचे लाभ कमा रहा है। किन्तु निगम द्वारा प्रकाशित सन्ने अन्तिम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई वस्तुओं के बाक प्रथम फनस्वरूप नीची कीमतें प्राप्त होने का सम्पूर्ण लाभ कर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया जाता है और कुछ वस्तुओं के लिए नीयतें दान प्रकार निर्धारित की

जाती है कि मध्यम मुनाफाखोरी न कर सकें। किन्तु यह बात विस्वास उत्पन्न करने वाली नहीं है। हम इतना ही कह सकते हैं कि निगम को ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे कि उपभोक्ता वास्तव में लाभ उठावे। यह भी कहा गया है कि निगम अपने अनुबन्धों को मुक्त रखता है, किन्तु यह स्वाभाविक ही है। व्यापारिक घटनों के प्रकाशन से हानि का भय है। निगम के कार्यसूचियों की उचित जांचोचना सदा वांछनीय है किन्तु व्यापार की गामनीयता के अतिरिक्त को भी स्वीकार करना होगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि पूर्वी यूरोप की नियमित व्यवस्थाओं वाले देश अब अन्य देशों के प्राइवेट व्यापारियों से अनुबन्ध करने की इच्छा प्रदर्शित करने लगे हैं, जिस कारण निगम की उपादेयता कम हो गई है। किन्तु जैसा कि हम पहले भी सकते कर चुके हैं, निगम की उपादेयता यह है कि वह विशाल समूहों के नाम पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने की स्थिति में है जबकि व्यक्तिगत व्यापारी विदेशी उपक्रमियों की तुलना में ऐसी लाभप्रद स्थिति नहीं रखते।

निगम का भविष्य—

राजकीय व्यापार एक विश्वव्यापी घटना है और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। विशालोन्मुख देशों की व्यापारिक व्यवस्था में प्राइवेट निर्यात-गृह दुर्वल स्थिति में होते हैं जिस कारण वे अनुकूल व्यापार-स्थिति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही नहीं, विदेशी मुद्रा के दुर्गुणों और उन्मत्त होने की भी सम्भावनाएँ रहती हैं। विश्व-बाजार में विपणन की जगह वाली ऐसी अनेक वस्तुएँ (जैसे—सल्फर, मर्करी, कृत्रिम सूर्य आदि) हैं जिनके आभियन और अभाव एक चक्र के रूप में उदय होते रहते हैं। एक कठिन अवस्था की अवधि में कीमत-अन्तर प्रायः बहुत अधिक होते हैं तथा भारत में आयातकर्तियों को यह लाभ हो सकता है कि वे एक न एक बहाने की ओर में कीमतों में जोड़-तोड़ करें। ऐसी स्थिति में, जबकि एक ओर हमारे निर्यात-गृहों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षति विश्व बाजार में दुर्वल हो और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा की खोरी का भय ही, एक सरकार-सहायित-संस्था ही विदेशी व्यापार को दक्षिण में सहायक हो सकती है। विशाल समूहों के कारण वह प्रतिस्पर्धा द्वारा अनुकूल व्यापार स्थिति प्राप्त कर सकती है तथा विदेशी मुद्रा की अधिक कमाई कर सकती है।

यह भी स्मरणीय है कि रुपये मुद्रातन समझौते (rupee payment agreements) के अन्तर्गत पूर्वी यूरोप के देशों को जूते, ऊनी वस्त्र आदि के जो निर्यात किये गये उनका मुफल यह हुआ कि देश में प्रगतिशील और कुशल उद्योग स्थापित हो गये हैं और अब इनके व्यापार पर पश्चिमी यूरोप के बाजारों में भी प्रवेश का यत्न कर सकते हैं। यह भी तर्क सम्भव है कि कालान्तर में निगम अपने निर्यात-कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, देशी उत्पादकों के सहयोग के रूप में, निर्माण कार्य आरम्भ

करे। मद्रास में विद्युत फैक्टरी का खुलना इस दिशा में पहला कदम है। यह जूत बनाने का यंत्रोक्त कारखाना भी खोल सकता है जिससे आह्वर के अनुसार उत्तम ब्राई क जूते बनाये जा सकें।

परीक्षा प्रश्न

१. गृह उद्योगों को संरक्षण देने के साधन के रूप में राजकीय व्यापार के गुण दोषों की परीक्षा कीजिये।

[Examine the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]

२. विदेशी व्यापार में सरकारों के भाग लेने से जो समस्याएँ एक पूँजावादी देश में उदय हो सकती हैं उसका विवेचन कीजिये।

[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade]

३. राजकीय व्यापार निगम क्या है? इसके गुण दोषों का विवेचन कीजिये।

[What is a State Trading Corporation? Discuss its advantages and disadvantages] (आगरा, एम० ए० १९६६)

४. राजकीय व्यापार निगम का कार्यचालन समझाइय। इसके क्या गुण दोष हैं एवं इन पर कसे विजय पाई जा सकती है?

[Explain the working of State Trading Corporation. What are its main weaknesses and how can they be overcome?]

(गोरख, एम० ए० १९६६)

५. भारत के राजकीय व्यापार निगम के कार्यचालन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने का एक सफल ढंग है?

[Critically examine the working of S T C of India. Is State Trading a successful method of protecting domestic industries?]

(आगरा, एम० एम० १९६८)

भारत की व्यापारिक नीति एवं व्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

परिचय—

व्यापार नीति का सम्बन्ध मुख्यतः विदेशी व्यापार से है तथा वह 'सामान्य आर्थिक नीति' का एक हिस्सा होती है। जब-जब सामान्य आर्थिक नीति में परिवर्तन होते हैं, देश की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो जाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत का व्यापारिक नीति और इसके अन्तर्गत हुए विभिन्न व्यापार समझौते का अध्ययन करेंगे।

द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति स्वतन्त्र व्यापार की नीति—

सन् १६२३ तक भारत की व्यापारिक नीति 'निर्बाध व्यापार नीति' (Laissez-faire) पर आधारित थी। निर्बाध व्यापार नीति के अन्तर्गत सरकारों हस्तक्षेप का अभाव होता है। भारत के विदेशी शासकों के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति उनके देश की हितों को बढ़ाने वाली थी। यह दोहराने की आवश्यकता नहीं कि एक व्यापारिक संस्था 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की स्थापना के परिणामस्वरूप ही ब्रिटेन के ध्वज भारत में जमे थे और गत दो शताब्दियों का इतिहास उस वणिज्य प्रवृत्ति की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है जिसने हमें गुलाम बनाया (और स्व० रमेशचन्द्र दत्त ने शब्दों में) "गंगा के जल को टेम्स नदी में उड़ेलने" का कुकर्म किया। ब्रिटेन की शोषक नीति के फलस्वरूप एक और जब ब्रिटेन स्वयं दिन डूना रात चौगुना पड़ता गया, तब भारत दिन प्रतिदिन दरिद्रता-ग्रस्त एवं अभावयुक्त देश बनता गया। भारत जैसे विशाल उपनिवेश के रूप में ब्रिटेन को न केवल ब्रिटिश वस्तुओं (कपड़ा, सोहा आदि) का खरीदार बल्कि ब्रिटेन के चमड़ा, गूँठी वस्त्र आदि उद्योगों के लिये मनचोते भावों पर वज्र्या माल बेचने वाला भी देश उपलब्ध हुआ।

शोषण की इसी अवधि में भारतीय अपनी सर्वांगीण प्रगति के लिए राजनीतिक दायित्व से मुक्त होने के लिए त्रियात्मक रूप से कटिबद्ध हुए। ब्रिटेन के लिए

भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ ब्रिटेन के पतन के मूल्पात के रूप में था। विद्वान् विचारक पट्टाभि सौतारामैया ने उन दिनों कटाक्ष रूप में कहा था कि 'यदि भारत स्वतन्त्र होता है तो इंग्लैंड वाले अपनी खदानों का शोयला पाउडर करके मारेंगे और लोहा पिघला कर पिघेंगे।'

कुछ भी हो, विदेशी सरकार ने अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए स्वयं तो स्वतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण किया ही, साथ ही भारत की भी इमर्का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें हमारा देश विदेशों निमित्त वस्तुओं से परे था वहाँ के उद्योग घटते गल्ट प्राय हो गये तथा वह मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया।

विभेदात्मक संरक्षण—

इस असन्तुलित विकास की हानियाँ प्रथम महायुद्ध के वर्षों पर प्रगट हो गईं। अतः परिस्थितियों से विवक्ष्य होकर सरकार ने १९२३ में विभेदात्मक संरक्षण की नीति अपनाई, जिसने स्वभावतः स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अन्त हो गया। विभेदात्मक संरक्षण की नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों को संरक्षण मिला और इन्होंने इसके फलस्वरूप बहुत प्रगति भी की। किन्तु व्यवहार में विभेदात्मक संरक्षण की नीति इस कठोरता से कार्यान्वित की गई कि अनेक योग्य एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग इससे वंचित हो रहे।

साम्राज्यीय अधिमान (ओटावा समझौता)—

१९३०-१९३२ के महान् मन्दी गुण में समस्त विदेश के विप्रे भारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। भारत के विदेशी व्यापार का कुल मूल्य एक परिमाण भी बहुत घट गया, क्योंकि कृषि वस्तुओं के लिये, जो कि हमारी निर्यात मूल्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती थी, विश्व-मांग तथा इनकी कीमतें दोनों ही बहुत कम हो गईं थी। पुनर्जीवन (recovery) के एक उपाय के रूप में ब्रिटेन ने एक विशेष प्रकार की व्यापार नीति अपनाई तथा इसके अन्तर्गत साम्राज्यीय अधिमान योजना के द्वारा अपने साम्राज्य के देशों में व्यापार बढ़ाने का यत्न किया। इस योजना की रूप रेखा ओटावा (कनाडा) के छाही आर्थिक सम्मेलन (Imperial Economic Conference) में तैयार की गई।

मध्य साम्राज्य—देशा सहित भारत ने इस सम्मेलन में ब्रिटेन के साथ एक व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो ओटावा पैक्ट (Ottawa Pact) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ठहराव के अन्तर्गत भारत ने कुछ प्रकार की आटोमाकाइन्स पर ७३% तथा इलेक्ट्रिक सामान, ऊनी सामान, गुण-पिचों, स्प्रिट आदि पर १०% अधिमान दिया। ये वस्तुएँ वह ब्रिटेन से आयात करणा था। दूसरी ओर ब्रिटेन ने भारत को कई वस्तुओं पर १०% अधिमान स्वीकृत किया तथा कई वस्तुओं को ड्यूटी दिये बिना ही अपने बाजारों में आने की अनुमति दी।

ओटावा समझौते की रचना इस तरीके से की गई थी कि वह भारत की

अपेक्षा ब्रिटेन के निम्ने अधिक लाभदायक रहा है। भारत से ब्रिटिश निर्यात वस्तुओं पर ऐसे अधिमान (preference) दिलाये गये, जो कि ब्रिटिश निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन फूँक सके। वहाँ निर्यात उद्योगों में पुनर्जीवन की तहर दी देने से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार की वृद्धि हुई तथा ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के अन्य अंगों में भी गति आई। इस प्रकार, ब्रिटेन मन्दी के गहरे गड्ढे में से निकलने में समर्थ हुआ। किन्तु, दूसरी ओर जो अधिमान भारतीय वस्तुओं पर स्वीकृत किये गये वे भारतीय निर्यातों में कोई बिराह वृद्धि न कर सके क्योंकि वृष्टि वस्तुओं की कीमतें एक लम्बे समय विलम्ब के बाद ही मुफार सकी। यही नहाना, अधिमान सूची में सम्मिलित सभी वस्तुओं भारत के लिए लाभदायक न थी। इस प्रकार, ओटावा समझौते की शान्त न पिटने, भारत, जर्मा और जर्मन जैसे माघीन देशों के साथ अपनी शोषक और स्वार्थपूर्ण नीति का जारी रख सका। ओटावा समझौते से अधिकांश लाभ ब्रिटेन को ही प्राप्त हुआ, जबकि भारत का अधिकतम घोसा तक छापन रिया गया। [भारत में चाय आगालों के ब्रिटिश मालिक और जूट मिलों के ब्रिटिश उद्योगियों को ऊँचे तान हुए, क्योंकि ओटावा पैक्ट के अन्तर्गत चाय और निमित्त जूट यह दो चीजें ही गयी थी जिनका निर्यात बहुत गया।]

ओटावा पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के समय तथा इसके बाद भी भारतीय जन-मत और विद्वानों ने बहुत आलोचना की थी। अतः यह पैक्ट भारतीय मित्रान सभा द्वारा १९३६ में गमाप्त कर दिया गया, किन्तु बाइसराय ने अपने विशेष अधिकार के द्वारा इसे १९३६ तक जारी रखा।

इंडो-ब्रिटिश ट्रेड एग्रीमेन्ट—

सन् १९३१ में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक नये व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर हुए, जाकि 'भारत-ब्रिटेन व्यापारिक करार' (Indo-British Trade Agreement) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ठहराव भी ओटावा पैक्ट के सुनिश्चिती शर्तों की दूर न कर सका। इस नये ठहराव के अधीन भारत ने ब्रिटेन से आयात किये जाने वाले २० पदार्थों पर १०% अधिमान स्वीकृत किया और ब्रिटेन ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर अधिमान दिया और अन्य वस्तुओं को इक्वटी-बी आने की अनुमति दी।

यह गया समझौता भी जनता की बहुत आलोचना का विषय बना। इसे कहने लगे कुछ ही महीने हुए, वे कि द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। द्वितीय महायुद्ध का मे आयात और निर्यात दोनों पर ही बड़ा नियन्त्रण किया गया तथा भारत की व्यापारिक नीति पुनर्जागर की सङ्कुटनीलीन आवश्यकताओं के अनुसार ढाली गई। न देशों से व्यापार में कठोर मनाही कर दी गई तथा मित्र एवं तटस्थ राष्ट्रों में भी व्यापार कठोर प्रतिबन्धों के अधीन हो गया जो सक्ता था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत की व्यापारिक नीति—

द्वितीय विश्व-युद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन की वृत्तीय पक्ति का राष्ट्र बना, दिया था,

भारत की स्वतन्त्रता ने “बफन में दूसरी चीन ठोक्ने” का काम किया। किन्तु भारतीय नेताओं, गांधीजी एवं नेहरूजी ने “भूत जाओ और श्मा करो” के उपदेश ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त म ब्रिटेन को बड़ी भारी राहत दी। हमारी सद्-इच्छा की परिचायन प्रवृत्ति के फलस्वरूप हमारे सम्बन्ध नये सिरे से बानू हुए और राष्ट्रमण्डल का जन्म हुआ। व्यापार के क्षेत्र में साम्राज्य अधिमान की नीति पूर्ववत् जारी है किन्तु अब यह राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान (Commonwealth Preferences) के नाम से प्रसिद्ध है।

स्वतन्त्रता के बाद, नए बानार प्राप्त करने तथा निर्यात व्यापार में नई नई प्रवर्धित करने हेतु भारत ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के देशों से कई व्यापारिक समझौते सम्पन्न किये हैं। विभिन्न समझौते दो प्रकार के हैं—द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय। द्विपक्षीय समझौतों की विधा में भारत ब्रिटेन व्यापारिक करार (१९३६) पहला कदम था। अब निम्न देशों के साथ भी द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न हो गये हैं—रूस, पोलैंड, पॅरो-ग्वायेनिया, हंगरी, इटली, नाबे और यूरोप के अन्य देश। लाल चीन से हमारे व्यापारिक सम्बन्ध आश्चर्यजनक ढंगे हुये हैं। भारत पर आक्रमण के बाद भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध भी टूट गये इससे पूर्व भी ये सम्बन्ध बड़े ही गंभीरपूर्ण तथा प्रति-द्वन्द्वीय थे, सीहानपूर्वक नहीं। तात्कालिक समझौते की भावना का पालन करते हुए राजनैतिक सम्बन्धों के साथ ही नाब पाकिस्तान से व्यापारिक सम्बन्ध भी सुधरने की आशा थी, किन्तु यह दुःखसामान रङ्ग गई है।

जहाँ भारत ने विशेष देशों में विशेष व्यापारिक समझौते किये हैं, वहाँ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक कारारों में भी सम्मिलित हुआ है। भारत सहित २३ राष्ट्रों ने जनवरी में १९४७ में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक करार पर हस्ताक्षर किये जो कि “व्यापार एवं प्रचुलक विषयक सामान्य करार” (General Agreement on Tariffs and Trade) के नाम से विख्यात है। इस समझौते का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार एवं भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना या टैरिफ दरी में पारस्परिक रियायतें दिखाना है। राष्ट्रमण्डल अधिमान के जारी रहने के लिए इस समझौते में छूट दी गई है।

वर्तमान स्थिति—

इस समय राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान प्रणाली का प्रयोग इस तरीके से किया जा रहा है कि वह हमारे विकास कार्यक्रमों में सहायक हो। अब तो भारतीय निर्यातों का स्वरूप ही बदल गया है। जहाँ ब्रिटेन और अन्य राष्ट्र मण्डलीय देशों को बच्चा मान अधिकता से जाया करना था वहाँ अब निमित्त माल की प्रमुखता होने लगी है। हमारे आयातों में पूँजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई है तथा निमित्त उपभोग्य वस्तुओं का आयात कम हो गया है। अब अब भारत ब्रिटिश बाजार में इतना पूर्वं प्रति-योगता करने लगा है। जबकि ब्रिटेन से तयभव सभी भारतीय आयातों पर भारत की रियायतें प्राप्त हैं अब वह स्वयं ब्रिटेन को इन्हीं गिनी रियायतें ही दे रहा है। योरो-

पियन साम्राज्य बाजार के बनने से राष्ट्र-मण्डलीय अधिमानों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। यदि ब्रिटेन भी उक्त साम्राज्य बाजार में सम्मिलित हुआ, तो भारत की कुछ हानि उठानी पड़ सकती है। १९६६ में भारत ने बहुत से नये व्यापार-करार किए और कुछ पुराने करारों को बढ़ाया।

विदेशों में भारतियों की ओर से मयुक्त उद्योग-धंधों स्थापित करने के प्रयास में इस वर्ष और अधिक सफलता मिली। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में विकास-कार्यक्रमों में भारतीय उद्योगपति अधिकाधिक सहयोग दे रहे हैं। इस तरह की लगभग ५० योजनाएँ आजकल समार के भिन्न-भिन्न भागों में भारत की सहायता से अमल में लाई जा रही हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. साम्राज्य अधिमान के प्रचलन का उद्देश्य क्या था और यहाँ भारत के लिये कहीं तक हितकर रहा ?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial ?]

२. भारत सरकार की व्यापारिक नीति की आलोचना कीजिये।

[Examine critically the commercial policy of the Government of India]

३. भारत ने अनेक विदेशी देशों के साथ अधिकाधिक संधियों में व्यापारिक समझौते किये हैं। इसके कारण बताइये और हान के किसी एक व्यापारिक समझौते के स्वभाव एवं उद्देश्य का विवेचन कीजिये।

[Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries. Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India.]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६७)

१९६६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

प्रारम्भिक—

पांच व छ जून १९६६ की मध्य रात्रि के दो बजे ने भारतीय रुपया का १६ ५% के डिस्काउंट में अवमूल्यन दिया गया। अब भारत द्वारा किया जान वाले आयात पर एक अमरीकी डॉलर के लिए ७ रुपए ५० पैसे और एक पौंड स्टर्लिंग (ब्रिटिश) के लिए २१ रुपये (१९६७ में पौंड के अवमूल्यन के बाद में १८ ६०) तथा रूसी मुद्रा रूबल के लिए ८ रुपए ३३ पैसे देने पड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक द्वारा भेजे गये बेल मिशन ने रुपए के अवमूल्यन का मुभाव दिया था। लेकिन भारत सरकार इसका बराबर विरोध करती रही। मसदा में अनेक बार यह घोषणा की गई कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायगा। पिछले महायुद्ध के बाद भारतीय रुपए के मूल्य को दूसरी बार घटाया गया है। इससे पूर्व सन् १९४६ में उस समय भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था, जब ब्रिटिश पौंड की कीमत घटाई गई थी।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने कई अन्य कदमों की घोषणा की। इनके अनुसार बारह वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया, अनेक वस्तुओं के कुनिमावी निर्यात शुल्क में परिवर्तन किया गया, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लागू सभी विशेष राजमाफी को खत्म कर दिया गया। इनके बदले में कुछ अन्य निर्यात योजनाएँ बनाई गईं ताकि निर्यातकों को कच्चे माल, मशीनों के औजार और स्पेयर पार्ट्स आदि मँगाने के लिए सुविधाएँ दी जा सकें।

अवमूल्यन के लिये विवश करने वाली परिस्थितियाँ
तत्कालीन वित्त मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने रुपए के अवमूल्यन सम्बन्धी निर्णय को सही बताते हुए कहा कि, “यदि यह कदम अब नहीं उठाया जाता, तो आयात के दूरी तरह में रुक हो जाने की सम्भावना पैदा हो जाती। इससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो कदम पिछले कई सालों से उठाये जा रहे थे, वे उपयोगी सिद्ध नहीं हुए।

देश की वित्तीय स्थिति काफी दिनों से चिन्ताजनक हो रही थी। पिछले दस वर्षों में निर्यात घटता जा रहा था। हमारा सामान अन्य देशों के सामान की कीमतों के सामने टिक नहीं रहा था, इसलिए १९६५ से निर्यात को प्रोत्साहन देने के अनेक कदम उठाये गए। इनमें वित्तीय राशियों पर दबाव पड़ा। मूँखे की स्थिति और पाकिस्तानी जात्रमण ने हालत को और अधिक बिगाड़ दिया। विदेशी सहायता पर भी प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों में रुपए के अवमूल्यन पर विचार किया गया। बाद में योजना-आयोग, वित्त मन्त्रालय और अन्य विभागों के परामर्शदाताओं के साथ प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया। सरकार ने भी इन बात का अनुभव किया कि घटसम, चाय, मूँखे कपड़ा, कच्चा सोहा, मैगनीज आदि जिन वस्तुओं का भारत से निर्यात किया जाता है, उनके परिमाण में बहुत ज्यादा वृद्धि सम्भव नहीं है। उस पृष्ठभूमि में अन्य मन्त्रियों ने भी अवमूल्यन के प्रश्न पर विचार किया और गन्विमण्डल में इसके पक्ष में निर्णय किया गया।”

अवमूल्यन से की गई आशाएँ—

(१) इससे निर्यात को भारी प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा मान्य न केवल सस्ता हो जायगा, बल्कि लोग निर्यात उद्योगों में तथा भी समायेंगे।

(२) यह भी आशा की गई कि आयातित चीजों का रुपए में दृढ़ वृद्धि जाने से ऐसी चीजों को देश में बनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी जो अब तक बाहर से मंगाई जा रही हैं। खेती के बारे में भी यही बात है। इस प्रकार इससे स्वावलम्बन में सहायता मिलेगी।

(३) नई विनिमय दर से आयात-निर्यात पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, व क देश में बाहर जाने वाले और बाहर से देश को आने वाले भुगतान पर भी असर पड़ेगा। इससे भारत में धन भेजने को प्रोत्साहन मिलेगा और भारत से बाहर धन भेजने पर कुछ रोक लगेगी। अब बाहर से धन लगाने वालों के मुनाफे के रूप में होने वाले बिदेसी मुद्रा का छिजन कम हो जायगा।

(४) रुपए की कम शक्ति में नमी होने के कारण बहुत-सी वुराइयों भी पैदा हो गई हैं। रुपए के पुराने विनिमय मूल्य के कारण निर्यातकर्ता अपने मान का दाम कम लगाते थे और आयात करने वाले बढ़ा बढ़कर दाम लगाते थे। यानियों की हुशियाँ बँकों से न भुनाकर अबैध रूप से भुनाई जाती थी, जिससे ज्यादा दाम मिलते थे। बाहर से भुगतान अवैध तरीकों से होना था और खोना, घड़ियाँ बँभरे ट्राजिस्टर आदि चीजें बल्लूई हुई मात्रा में देश में चोरी में लाई जा रही थी। वैध तरीके से जो आयात होना था उसमें भी लोग गहरा मुनाफा कमा रहे थे और यह कमाई छिपाकर रखी जा रही है। नए विनिमय दर के कारण से सब कारंवाजियाँ अब उतनी लाभप्रद न रहेंगी। अब अवैध जरियों से हमारी जो बिदेसी मुद्रा जा रही थी, वह सब जायेगी, और हमारा बिदेसी मुद्रा कोष बढ़ेगा।

(५) अवमूल्यन के कारण बिदेसी मुद्रा के रुज में न तो ऋण की कुल

रख में जोर न इसकी वार्षिक लक्ष्यकी की राशि में कोई वृद्धि होगी। परन्तु रुपए के रूप में अवश्य ऋण की अदायगी का बोझ बढ जायेगा। यही नहीं सरकारों आगमन का जोर दूसरे विदेशी खर्च का भी परिणाम रुपए के रूप में बढ जायेगा।

(६) अवमूल्यन से हमारे वज्रट को भी कई प्रकार से लाभ होगा। उदाहरण के रूप में निम्नान्त मुक्तों में हम काफी आमदनी होगी। इसी तरह से विदेशी सहायता के रूप का मूल्य बढ आयेगा।

(७) कुछ आवश्यक चीजों के दामों में वृद्धि नहीं होगी वरिष्ठ इतनी, यह प्रबन्ध किया गया कि अनाज, उर्वरक, निरोसीन (मिट्टी के तेल) और डीजल तेल का दाम बढने न पाए। जो विद्यार्थी विदेशों में पढ रहे हैं, उनको ही कम व्यय पर ही ऋण दिलाने का आश्वासन दिया गया।

पैदावार की बढाकर ही दामों में स्थिरता लाई जा सकती है। हमारी चीनी योजनाओं के अन्तर्गत जो कारखाने खुले हैं उनमें में अधिकांश बाहर में आने वाले कच्चे माल और बल-बुर्जों की कमी के कारण पूरी क्षमता के उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, जिन कारण उत्पादन थकने में आया पड़ती थी। अब बाहर से ज्यादा कच्चा माल और बुर्ज भंडारों की आवश्यकता की गई। इसके लिए आयात का तरीका सरल किया गया। निरोसीन (मिट्टी के तेल) निर्यात की बिक्री और कपास का आयात बढ़ाया गया।

रुपये के अवमूल्यन पर प्रतिक्रियाएँ

वित्त मंत्री और योजना मंत्री के बार-बार इस आश्वासन के बावजूद कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायेगा, सरकार ने रुपए का ३६% प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जो व्यवहार में लगभग ५७ प्रतिशत है। आमतौर से यह ख्याल था कि भारत सरकार आम चुनाव में पूर्व यह कदम नहीं उठायेगी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण पर भारी बाधक्य आया। अधिकांश उद्योगपतियों ने सरकार के इस कदम की औद्योगिक विकास में बाधक बताया। प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार थीं—(१) यह कदम सरकार के उन आश्वासनों के विपरीत था जो उनमें लोक सभा में दिये थे। अवमूल्यन के नाम पर जो लाभ प्राप्त होने के दावे किए जा रहे हैं वे गलत शक्ति होते हैं। (२) देश के अन्दर और बाहर प्रतिभूत प्रभावों के अलावा रुपये के अवमूल्यन में अलग का विचारसरण सरकार में कम हो जायेगा क्योंकि सरकार कम खर्च कर यह कह रही थी कि वह रुपए का अवमूल्यन नहीं करेगी। इससे विदेशों में हमारा दायित्व बढ जायेगा। इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा—सातकर अन्तर्गत का मनोबल गिरेगा। (३) इस कार्यवाही से औद्योगिकरण में विलम्ब होगा। आयात किए गये सामान की कीमत काफी बढ जायेगी। आन्तरिक मूल्य स्तर भी इसमें बढ सकता है। (४) यह कार्यवाही “अनावश्यक” है। वित्त, तथा योजना मंत्रियों ने हाल में मजदूरी में वृद्धि दिया गया था कि रुपए का अवमूल्यन नहीं किया जायेगा। इससे रुपए की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

(५) अवमूल्यन से अधिकांश जनता बुरी तरह प्रभावित होगी—मुद्रा स्फाति और बढ़ेगी और रुपए का मूल्य ज्यादा घट जायगा । (६) सरकार एक ओर विदेशी व्यापारियों और दूसरी ओर निहित स्वाम्या के आग भुकी है । यह सदिग्ध है अवमूल्यन से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी । आयात को रागत बढ़ जायगी और मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी । विदेशी ऋणों का बोझ भी बढ़ जायगा ।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन का प्रभाव

! मूल्य लोच के तदनुसार ।

अवमूल्यन के पथ में एक प्रमुख तर्क यह है कि इसका सहारा भुगतान कमजोर की स्थिति में सधार लाने के लिये निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने और गमात वस्तुओं की माग कम करने हेतु लिया जाता है । इस तर्क का औचित्य अन्य बातों के अतिरिक्त आयात और निर्यात वस्तुओं की माग की मूल्य लोच पर निर्भर करता है अर्थात् इन वस्तुओं के मूल्य में प्रतिगत परिवर्तन के फलस्वरूप माग कम प्रतिशत में घटती बढ़ती है । १९५०-५१ से १९९१ तक १६ वर्ष की अवधि में भारत का व्यापार राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में १० और १७ के बीच रहा । १९५१/५२ में यह प्रतिशत सबसे ज्यादा था । १९५५-५६ से १९६९-७४ तक यह प्रतिशत लगातार १२ रहा । १६ वर्षों में इन प्रतिशतों का औसत १३ था ।

आयात-वस्तुओं के मूल्य की लोच —

१९५५-५६ में आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक निम्नतम अर्थात् ८४ था लेकिन इस वर्ष के आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक उच्चतम नहीं था । आयात व्यापार के परिमाण का सूचकांक १९६३-६८ में उच्चतम था जबकि इस वर्ष आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक ९८ था । आयात का प्रति इकाई के मूल्य का सूचकांक १९५८-५९ में सबसे ज्यादा अर्थात् १०४ था । इस प्रकार उच्चतम और निम्नतम सूचकांक के बीच अंतर २० था । आयात व्यापार के परिमाण के उच्चतम सूचकांक और निम्नतम सूचकांक में अंतर ११६ का था अर्थात् यह सूचकांक २१२ और ९८ के बीच रहा । इससे स्पष्ट होता है कि आयात के परिमाण में तेजी से घटा बढ़ी हो रही थी लेकिन आयात की प्रति इकाई के मूल्य के सूचकांक में घटा बढ़ा सामित रूप में हुई । सम्पूर्ण स्थिति की जांच के लिये प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक और आयात निर्यात वस्तुओं के परिमाण के सूचकांक का सह सम्बन्ध निकाला गया । सह सम्बन्ध का गुणक +०.२ आया । सह सम्बन्ध का गुणक धन (+) में होना हमें बताने का संकेत है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि होने पर आयात के परिमाण का मात्रा में भी वृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होने पर आयात की मात्रा भी कम हुई । लेकिन सह सम्बन्ध का गुणक ०.२ ज्यादा नहीं । इसलिये ऊँची नीमत पर भी आयात पर निर्भरता बहुत ज्यादा नहीं है । अवधारणियों की जांच में यह कहा जा सकता है कि आयात वस्तुओं की माग यहाँ लोचहीन है । अतः अवमूल्यन के फलस्वरूप आयात-वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से भारतीय आयात में ज्यादा कमी नहीं हो सकती ।

निर्यात-वस्तुओं की मूल्य-सीध —

१९५५-५६ में निर्यात की प्रति इकाई का सूचकांक ६० था जो न्यूनतम है। इसी वर्ष में निर्यात के परिमाण का सूचकांक १६५ था। १९६५-६६ में निर्यात के परिमाण का अधिकतम सूचकांक १३० था जब कि इस वर्ष निर्यात की प्रति इकाई मूल्य का सूचकांक १०७ था। प्रति इकाई मूल्य का निम्नतम सूचकांक १९५५-५६ में ६० और १९५१-५० में अधिकतम अर्थात् १६२ था। इन दोनों के बीच अन्तर ४२ था। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्यात का परिमाण प्रति इकाई मूल्य की तुलना में ज्यादा परिवर्तनशील रहा। निर्यात के परिमाण के सूचकांक और प्रति इकाई मूल्य के सूचकांक के बीच सह-सम्बन्ध का गुणक -0.2 निकाला गया। सहसम्बन्ध का गुणक $(-)$ शून्य में होने का मतलब है कि प्रति इकाई मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप भारत के निर्यात का परिमाण कम हो जाता है और प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर निर्यात का परिमाण बढ़ जाने की सम्भावना रहती है। अर्थशास्त्रियों की साधा म कहा जा सकता है कि भारत का निर्यात पर्याप्त रूप में मूल्यनोबन्धीन नहीं है।

निर्यात बढ़ाने की आशा पूरी नहीं हुई

सरकारी ओकों में यह आशा की गई थी कि इस अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात व्यापार में वृद्धि होगी यद्यपि वंसी आका निर्याताओं और निर्यातकों ने नहीं की थी। हमारे अवमूल्यन के हमारे निर्यातों की मात्रा (volume), रचना (Composition) एवं इसके व्यापार की दिशा (Direction) पर जो प्रभाव हुए हैं उनकी समीक्षा नीचे की गई है।

निर्यात व्यापार के परिमाण पर प्रभाव—

अवमूल्यन ने भारत के निर्यात व्यापार को बहुत ठेस पहुँचाई। यह जून १९६६ में मई १९६७ तक के आँकड़ों से स्पष्ट है। निर्यात-आय तृतीय योजना के तीसरे वर्ष में ख़रीबी प्रारम्भ हुई थी और १९६३-६४ में १,६६६ मि० डालर में बढ़कर १९६४-६५ में १,७२१ मि० डालर हो गई। १९६२-६६ में विगत वर्ष की राशि के बराबर (लगभग १,६६३ मि० डालर) रही। किन्तु १९६६-६७ के पहले दो महीनों की छोड़कर निर्यात आय घटती गई। यह १९६४-६६ में १,६६३ मि० डालर में घटकर १९६६-६७ १,३५३ मि० डालर रह गई अर्थात् उसमें ८३% कमी हुई। मार्च १९६७ के बाद भी निर्यात आय की कम होने की प्रवृत्ति जारी रही।

अब प्रश्न यह है कि हमारे निर्यातों में गिरावट क्यों आई? भौतिक दृष्टि से तो अवमूल्यन के फलस्वरूप इनमें वृद्धि होनी चाहिए थी। सम्भोदनापूर्वक विश्लेषण करने पर निर्यातों की गिरावट के लिए निम्न कारण उत्तरदायी प्रतीत होते हैं — (१) सबसे बड़ा कारण सम्भवतः यह रहा कि सभी निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ समाप्त कर दी गईं तथा परम्परागत निर्यात वस्तुओं पर पर्याप्त निर्यात कर लगा दिये गये। इससे निर्यात व्यापार को बचका लगा तथा कुछ महीनों तक

तो वह यथावत् रह गया। जहाँ तक हमारी विदेशी मुद्रा की बमार्द को सुरक्षित रखने के उद्देश्य का सम्बन्ध है निर्यात कर खपाना ठीक हो था। यह भी सच है कि बाद की सरकार ने कुछ नगद सहायता भी घोषित की लेकिन वह अपर्याप्त थी।

(२) साथ ही विभिन्न उद्योगों में जो कि आयातिन कच्चे मालों का उपयोग करती है (जैसे—मूती बरतन जूट के कारखाने कैमीकन्स, इन्जीनियरिंग गुड्स आदि), उत्पादन-लाभ में बढ़ गई, क्योंकि इनके आयात खिला का मूल्य रुपये में १७.५% बढ़ गया। (३) खराब कृषि फसलें (जिन्होंने कृषि-उत्पादन पर आधारित उद्योग को कुप्रभावित किया) मुद्रा, स्फोटक का जारी रहना स्वदेशी माँग का दबते रहना, कृषि भुगतान समझौते वाले देशों में व्यापार अस्त-वस्त हो जाना व कुछ अन्य कारण थे जो कि अवमूल्यन के बाद की अवधि में निर्यातों में कमी के लिए दायी रहे।

रचना (Composition) की दृष्टि से प्रभाव—

सन् १९६६-६७ में हमारी अधिकांश निर्यात आय (लगभग ४१.६%) तीन प्रमुख सुरम्भरागत वस्तुओं जूट (२१.५%), चाय (१३.८%) और सूती माल (६.६%) से हुई। किन्तु इन तीनों पर अवमूल्यन का बुरा प्रभाव पड़ा। इनसे निर्यात आय १९६६-६७ में १९५५-६६ की तुलना में क्रमशः १५.५%, १६.६% और ३६.१% कम हो गई। अन्य वस्तुओं जिनका निर्यात कुप्रभावित हुआ निम्न हैं — तम्बाकू, कहवा, मारियल जटा उत्पाद धातु निर्मित माल, मैकनीज एलुमि और अन्नक। इस निराशापूर्ण चित्र का एक उल्लेख यह था कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई, जैसे—चमड़ा व खालें, मोह एलुमि, लोह, पशु पदार्थ एवं वनस्पति, कहवा, जूट आदि, जूट के रेशे, फल व सब्जियाँ। अवमूल्यन से कुप्रभावित होने वाली इन वस्तुओं का हमारी कुल निर्यात आय में भाग २२% है। स्पष्टतः कुल पर निर्यात-आय में कमी हुई।

क्षेत्रीय वितरण की दृष्टि से—

(१) विश्व के अनेक देशों को भारतीय वस्तुओं निर्यात होती हैं, किन्तु १९६६-६७ में केवल चार देशों का भाग ही हमारे कुल निर्यात में ५०% से भी अधिक था। ये देश निम्न हैं—अमेरिका जिसने यू० के० को हमारे सबसे बड़े ग्राहक के पद से हटा दिया है १८.८%, यू० के० १७.४%, रूस १०.७% और जापान ६.२%। (२) हाल के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों से भारत के व्यापार में वृद्धि होना एक उत्तेजनपूर्ण घटना है। रूस को छोड़ते हुए पूर्वी यूरोप के देशों का भाग ८.८% और रूस सहित पूर्वी यूरोपियन गुट का भाग १६.५% है। (३) लक्ष्मनचर्ग को छोड़ते हुए यूरोपियन साम्राज्य के देशों का भाग ७.६% है। लक्ष्मनचर्ग को हमारा निर्यात नगण्य है। (४) इक्वैडोर क्षेत्र में जापान भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। उसका भाग हमारे कुल निर्यात में ६.२% है। अन्य इक्वैडोर देशों में आस्ट्रेलिया, नेपाल और तवा प्रमुख हैं। (५) अन्य एशियाई देशों

(अर्थात् इन्केफी देशों के अतिरिक्त) १० हमारे निर्यात भाग्यशाली हैं। इनमें प्रमुख भाग कुवेन (०.७%) और ईराक (०.५%) का है। (६) अनीका गुप्त में ६० ल० गण-राज्य हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। उसका बाण हमारे कुल निर्यातों में २.३% है। (७) नेटिन अमेरिका के विकासोन्मुख देशों को हमारे निर्यात बाजार में अभी कोई महत्व नहीं मिला। १९६८ में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नेटिन अमेरिका के देशों की यात्रा से इनके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ने की आशा है।

अवमूल्यन के बाद हमारे निर्यात अधिकांश बाजारों में (जिनमें हमारे बड़े बाजार-देश जैसे अमेरिका ब्रिटेन १० जर्मनी, आस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हैं) घट गये हैं। कम १० जर्मनी वोलेंड और मयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों के साथ भी, जिनसे हमारे रपड़े-भुगतान समझौते थे, हमारे निर्यात कम हो गये। नेटिन अमेरिकी देशों की नगभ्य निर्यातों में भी २०% कमी हो गई। हाँ, जापान ब्रिक्सीलाब्राकिया, यूगोस्लाविया, फ्रांस इटली, वल्जियम, ईराक सुदान और केन्या को निर्यात बढ़े। किन्तु इन अपवाद मूलक देशों का भाग हमारे कुल निर्यात में केवल २०% ही है, जिस कारण निर्यात कुल पर घटे हो रहे हैं।

आयात व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव

राष्ट्र के अवमूल्यन से आयात वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाया स्वाभाविक है। भारत में आयात-वस्तुओं की आवश्यकताएँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फलतः हमें अपनी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कोष से काफी धनराशि निकालनी पड़ी है और वृद्धत स्तर पर इन आयातों के लिए विदेशी सहायता भी लेनी पड़ी है। हमारे आयात की एक विशेषता यह है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात व्यापार पर १९५७ के वर्ष में जो नियन्त्रण लगाए गये हैं उनसे हम केवल अनिवार्य वस्तुओं का ही आयात करने की स्थिति में हैं जो योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये अति आवश्यक हैं। इस प्रकार अवमूल्यन से आयात का मूल्य कम होने की सम्भावना नहीं है। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों की पूरी उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने के लिए काम करने दें, नए उद्योगों का, जिन्हें हम वहाँ स्थापित करना चाहते हैं तो इन अधिक मात्रा में कच्चा माल और पुर्जें आयात करने की व्यवस्था करना होगी। आयात की लागत में वृद्धि ही जाने में कुछ अनिवार्य वस्तुओं के लागत-मूल्य बढ़ने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आयात वस्तुओं की नीचहीन मात्रा में स्थिति में अवमूल्यन में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देखेंगे वस्तुएँ तैयार करने की प्रक्रिया को भी बल नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने छोड़े समय में रूपए का अवमूल्यन भुगतान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय नहीं हो सका।

दूसरी बार अवमूल्यन करने की भूमिका

इन बातों की दृष्टि में रखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि रूपए

के अवमूल्यन से भुगतान सन्तुलन की स्थिति में समता लाना सम्भव नहीं है। हमारे सामने ऐसे तथ्य भी अनेक हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि निर्यात-व्यापार बढ़ाने की दिशा में भी उत्साहजनक प्रगति नहीं हुई है। यदि सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् अन्य निर्णय लिये होते तो अनिश्चितता की जो स्थिति पैदा हुई उससे बचा जा सकता था। रुपये के अवमूल्यन के बाद घोषित निर्यात में जो अवमूल्यन के दस सप्ताह पश्चात् लागू की गई, निर्यात-व्यापारियों को निर्यात सहायता देना, विशेषतया इ जीर्णवरी वस्तुओं के निर्माताओं को सहायता देना शामिल था, जिससे कि वे निर्माण करने की अमत्ता बटा सकें और दूसरे देशों की होद का मुकाबला कर सकें। कुल मिलाकर बहुत कुछ सफलता रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् सरकार निर्माता और व्यापारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर निर्भर थी। यदि आर्थिक नीतियाँ बिना सोचे-समझे अपनाई जाती रहें तो यह अवमूल्यन दूसरी बार अवमूल्यन करने की प्रेरिका मिद्ध होगी। इसलिये सध्यों की प्राप्ति के लिए रुपये के अवमूल्यन के बाद आवश्यक उपायों की योजना बनायी जानी चाहिए।

उपयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता—

(१) अत्याप्त प्रतिस्थापन के स्थान पर निर्यात-व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पिछले दस वर्षों में हम केवल ४ प्रतिशत वार्षिक दर से निर्यात व्यापार में वृद्धि लाने में सफल हुए। निर्यात-व्यापार में वृद्धि आगामी पांच वर्षों में वार्षिक प्रतिशत दर से लानी होगी। रुपये के अवमूल्यन से व्यापार के वर्तमान पैटर्न में विविधता लाने के लिए देश को एक अक्षर मिना है।

(२) अल्पकाल में निर्यात-वस्तुएँ अपने देश में कम उपयोग होने देने के लिए कुछ समय बरतने की आवश्यकता है। किन्तु दीर्घकाल में इस बात का ध्यान रजना होगा कि निर्यात-वस्तुओं का उत्पादन समुचित मात्रा में बढ़ सके। सरकार को प्रमुख उत्पादन की सप्ताई निर्यात-वस्तुओं के उद्योगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करनी होगी।

(३) यदि नयी निर्मित वस्तुओं के निर्यात की प्रोत्साहन दिया जाना है तो निर्यात व्यापार को सहायता देने के कार्यक्रम ज्यादा उद्योगों के लिये लागू किये जाने चाहिए। निर्यात-व्यापार बढ़ाने के उपाय, जैसे कि पाकिस्तान में काम में लाये जा रहे हैं, यहाँ भी काम में लाये जाने चाहिए। इन उपायों में निर्यात-व्यापार पर बोनस देने की स्कीम, आर के अनुसार भुगतान करने की स्कीम शामिल है। कुछ निर्यात-वस्तुओं के उद्योगों में यहाँ भी ये लागू की जा सकती हैं।

(४) इसके अनिश्चित राज्य व्यापार नियम का बारोबार, जिसका उद्देश्य व्यापार के नये मार्ग खोलना है, बढ़ाना होगा।

(५) रुपये के अवमूल्यन को अन्ततोगत्वा सफल बनाने के लिए मुद्रा-विस्फीतिकारी नीति अपनाने की आवश्यकता है ।

उपसंहार—

भारतीय रुपया मुद्रा के अवमूल्यन के बाद भारत के निर्यात में गिरावट की जो प्रवृत्ति जल्दी आ रही थी वह १९६८ का वर्ष मार्च में मई की तिमाही में खत्म हो गई और अप्रैल मई में गत वर्ष इसी काल का तुलना में निर्यात में प्रतिशत अधिक हुआ । अधिकारियों का कहना है कि इस वर्ष वर्षा सामान्य हान में निर्यात-वृद्धि की इस प्रवृत्ति के और जोर पकड़ने की आशा है । आयात की आवश्यकताओं और भुगतान की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्यात का काफी बड़ान का प्रयत्न करना चाहिए ।

परीक्षा प्रश्न .

- १ भारतीय रुपये का अवमूल्यन (१९६६) क्यों किया गया ? इससे क्या आशाएँ लगाई गई थी ?

[Discuss the effects of the recent devaluation of the Indian Rupee on India's Economy] (आबरा एम० ए०, १९६६)

- २ भारतीय रुपये के अवमूल्यन का हमारे विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

[Examine the effect of evaluation on India's foreign trade] (गोरख०, एम० ए०, १९६८)

- ३ जून १९६६ में हुये भारत रुपये के अवमूल्यन के निम्न पर प्रभाव की आलोचनात्मक विवेचना का जरा

(अ) देश का निर्यात-व्यापार,

(आ) अयात प्रतिस्थापन, एवं

(इ) भारतीय जनता की आर्थिक समृद्धि ।

[Critically discuss the effect of devaluation of the Indian rupee in June 1966 on (a) the country's exports, (b) the progress of import substitution in India and (c) the economic prosperity of the Indian people in general]

(बलाहा० एम० ए० १९६८)

पौंड का अवमूल्यन और भारत

(Devaluation of Sterling and India)

प्रारम्भिक—

ब्रिटन में पौण्ड स्टर्लिंग (अर्थात्) १९६७ में पौण्ड मुद्रा का एक बार और अवमूल्यन करके विश्व-मुद्रा बाजार में एक विचित्र-सी स्थिति पैदा कर दो। बीसवीं शताब्दी में ब्रिटेन द्वारा अपनी मुद्रा का यह तीसरा अवमूल्यन है—प्रथम बार १९३० में (जबकि उसने स्वयंमान को रखा था) दूसरी बार १९४६ में और अब तीसरी बार १९६७ में। इस नये १४ ३% अवमूल्यन से एक पौण्ड का मूल्य केवल २४० डांलर के बराबर निश्चित किया गया है, जबकि अब अमरीकी डांलर की तुलना में एक पौण्ड स्टर्लिंग की कीमत २ ८० डांलर के स्थान पर २४० डांलर के बराबर हो गई है। भारतीय मुद्रा के सम्बंध में भी एक पौण्ड की कीमत, जो भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन से २१ रुपये के बराबर हो गई थी, अब घट कर १८ रुपये के बराबर रह गई है, अर्थात् हमारे रुपए का मूल्य एक पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में तीन रुपये बढ़ गया है।

पौंड के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि^१

दूसरे महायुद्ध के बाद से पौण्ड पर दबाव तीव्र गति से बढ़ने लगा, जिसे १९४६ में थोड़ा ठीक किया गया था। इंग्लैंड अपनी देनदारियों और दायित्वों की पूर्ति करने में तभी से असमर्थ होता जा रहा था। उसके डांलर कोष में कमी आती जा रही थी। दूसरी तरफ, उसका निर्यात घटता जा रहा था और आयात बढ़ता जा रहा था। इस कारण उसकी भुगतान तुला विपरीत होती जा रही थी और भादा बढ़ता जा रहा था। इस बीच दूसरे महायुद्ध में यूरोप के व्यवस्थापित देशों की अर्थ-व्यवस्था का विकास तीव्रता के साथ होने लगा था। फलतः उनका खोया हुआ व्यापार उनको पुनः प्राप्त होने लगा था। इसका दबाव इंग्लैंड पर पड़ा और उसके विनिमय समता कोष पर बोझ बढ़ता चला गया। इंग्लैंड को पौण्ड की विनिमय दर बनाये रखने में कठिनाई होने लगी। किन्तु इंग्लैंड की महत्ता को बनाए

१ पौंड और रुपया योजना १० मार्च १९६८।

रखने के लिए अमेरिका उसकी सहायता करता रहा, जिससे वह इतने समय तक पौड की विनिमय दर को बनाए रखन में सफल हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कुछ यूरोपीय देशों और मस्याओं ने भी उसकी सहायता की। अमेरिका यह जानता था कि यदि इङ्गलैंड की मुद्रा का अवमूल्यन होया, तो डालर की भी भारी आ जयिती।

१९८६ में पूर्व इङ्गलैंड की मुद्रा का मूल्य अधिक था। उस समय तब पौड ४०३ डालर के बराबर था। यह कृत्रिम दर थी, जिसको इङ्गलैंड जबरदस्ती बनाये हुए था। इससे उसको हानि हो रही थी क्योंकि निर्यात की अपेक्षा आयात बृद्धि होने लगी थी। अतः १९४६ में इङ्गलैंड ने अवमूल्यन करके एक पौड को २५० डालर के बराबर कर दिया था। इस प्रकार, डालर के सम्बन्ध में पौड की कीमत ३० ५ प्रतिशत कम हो गई थी। इतना ही भारतीय मुद्रा का भी अवमूल्यन किया गया था परन्तु उस समय भारत की अपेक्षा इङ्गलैंड को अधिक लाभ हुआ था। भारत को लाभ अवमूल्यन से नहीं, बल्कि कोरिया के युद्ध के कारण अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अभूतपूर्व विकास होने से हुआ था। फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्था इङ्गलैंड की अर्थव्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर रह गई। अन्य देशों की वस्तुओं की अपेक्षा इङ्गलैंड की वस्तुओं को प्राथमिकता मिल रही थी, पर भारत को अपनी योजना की सफलता के लिए भिन्न प्रकार का आयात करना था। अमेरिकी आयात में ह्रास हो गया। भारत के निर्यात में बृद्धि तो हुई नहीं, आयात में ही बृद्धि होने लग गई। फलतः भुगतान तुला नष्टात्मक होने लग गई और निर्यात के कम होने के कारण विदेशी बाजार में रुपये की माँग गिरने लग गई। परन्तु रुपये की पूति बढ़ती जा रही थी जिस पर आर्थिक शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा था और रुपये के मूल्य का प्राथिक शक्तियों के कारण ह्रास होता जा रहा था। रुपये के विनिमय मूल्य में कमी हो रही थी। इन परिस्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दबावों के कारण ५ जून, १९६९ को भारत ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया।

जिस समय भारत ने रुपये का अवमूल्यन किया, तब इंग्लैंड में भी अवमूल्यन के लिए शोर मचा था, परन्तु राजनीतिक कारणों से वह टाला जाता रहा। इङ्गलैंड ने भुगतान अनुदान विषय में होता जा रहा था और उसे बनाए रखने के लिए इङ्गलैंड को अपने स्वर्ण कोष का भारी भाग में संप्रयोग करना पड़ रहा था। विदेशी विनिमय कोष की माँग गिरती जा रही थी, किन्तु व्यापारिक घाटा और स्टालिम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। नष्ट-प्राप्ति के लिए वहाँ सट्टे की प्रवृत्ति मजदूर थी, जिस कारण आंक का वातावरण उत्पन्न हो गया था। अपनी अवस्था को ठीक करने के लिये इंग्लैंड ने अवमूल्यन के पहले 'मुद्रा मनुचन' की नीति का उप योग किया और आय और मजदूरी को यथावत रखने का प्रयत्न भी किया। उसने बैंक की दर भी बढ़ानी आरम्भ की। मजदूरी और आय तथा लागत और कीमतों के सम्बन्ध में भी अपेक्षित नीति अपनाई गई। इन सब कार्यों के पदार्थ भी अर्थ

व्यवस्था के साथ को बनाये रखने में कठिनाई हो रही थी। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्टॉलिन की माँग गिर गई थी परन्तु उसकी पूर्ति बढ़ती जा रही थी, जिसको 'विनिमय-समता कोय' भी ठीक नहीं कर पा रहा था। इससे यह ज्ञात होता था कि इंग्लैंड की मुद्रा का मुख्य दानर की अपेक्षा अधिक था। जब इंग्लैंड की अपनी अवस्था ठीक करने के लिए अधिक सहायता नहीं मिली, तो उसने १६ दिसम्बर १९६७ को पौड का अवमूल्यन कर दिया। जिस प्रकार जून १९६६ में रुपये के अवमूल्यन से भारत में कठोर और राजनैतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई थी और कांग्रेस में मतभेद हो गया था, उसी प्रकार पौड के अवमूल्यन से इंग्लैंड की मजदूर सरकार में मतभेद पैदा हो गये। सिंगापुर में तो अवमूल्यन के कारण उपद्रव हुआ और डेन्मार्क की सरकार अवमूल्यन के प्रश्न पर भग हो गई। परन्तु इंग्लैंड की सरकार बिरने गिरते बची।

पौड का अवमूल्यन क्यों ?

(१) जब किसी देश का भुगतान असन्तुलन अन्य देशों के साथ सिलसिले प्रतिकूल दिशा की ओर बना रहता है, तो उसे समुद्रत करने के लिए 'मॉड्रिन अव-मूल्यन' अन्तिम उपाय के रूप में ही अपनाया जाता है। हाल ही के पौड के अव-मूल्यन से स्पष्ट है कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में काफी समय से असन्तुलन चला आ रहा है। वयपि इस भुगतान-असन्तुलन में इंग्लैंड बन्दरगाह की हड़ताल, जिनमें इंग्लैंड में १,०७० साल डालर की दाँति उठानी पड़ी, पौड के अवमूल्यन के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। परन्तु इसमें राबेह नहीं कि गत १६ महीनों में यथासम्भव प्रयत्न करने के बावजूद भुगतान-असन्तुलन बना रहा।

(२) विश्व में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ विन्य मण्डियों में ब्रिटेन द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता काफी हद तक घट गई है जबकि दूसरी ओर साम्रा बाजार के सदस्य देशों में अपने क्षेत्र में ही व्यापार-वृद्धि का निश्चय करके इंग्लैंड के निर्यात को काफी घटका पहुँचाया है। कुछ वर्ष पूर्व तक भारत जैसे विकासशील देश औद्योगिक मशीनों और रासायनिक पदार्थों के लिए मुख्यतः इंग्लैंड के आयात पर निर्भर करते थे। लेकिन आज बृहत्-से विनासशील देश इस स्थिति में पहुँच गये हैं कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ उन्होंने विदेशी मण्डियों में भी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इंग्लैंड द्वारा अधिकाधिक विदेशी आण प्राप्त करने और घरेलू कार्यों में यथासक्ति मौद्रिक समुच्चन करने के बावजूद वह विश्व के बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाए रखने में असमर्थ रहा है।

(३) पौड का अवमूल्यन साम्रा बाजार की सदस्यता सुलभ बनाने के लिए भी ब्रिटेन द्वारा किया गया है। इसकी आवश्यकता वह निम्न कारणों से अधिकाधिक महसूस करता रहा है — (१) इंग्लैंड के आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन पर अमरीका का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फलस्वरूप इंग्लैंड के उद्योगों का गला घुटन लगा है। इस समस्या के समाधान के लिए इंग्लैंड के पास एक ही विचार है

कि वह यूरोपीय साम्राज्यवादी की सदस्यता ग्रहण करे। इसके फलस्वरूप कच्चा माल एवं सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव होगा जिसमें अर्थशास्त्र सस्ती वस्तुएं निर्मित होंगी और इंग्लैंड अमेरिका के शोषण से मुक्ति पा सकेगा। (ii) इंग्लैंड के आर्थिकदार्ढ्य एवं तकनीकी के लिए भी अमेरिका जोर एवं आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति निर्माणक देश के लिए हानिकारक है। यूरोपीय साम्राज्यवादी की सदस्यता से इंग्लैंड के तकनीकीयों के केन्द्र-विन्दु यूरोपीय साम्राज्यवादी के राष्ट्र ही होने निश्चय इंग्लैंड का विकास ही न करेगा। (iii) साम्राज्यवादी की सदस्यता स्वीकार न करने में इंग्लैंड का विदेशी व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस प्रकार साम्राज्यवादी की सदस्यता इंग्लैंड के लिए आत्म-रक्षा का प्रश्न बन गया है। (iv) साम्राज्यवादी राष्ट्रों के औद्योगिक विकास और अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों पर उनके बढ़ते हुए प्रभाव से इंग्लैंड में यह भय व्याप्त हो गया है कि निर्यात भविष्य में वहाँ के कारखानों को कच्चा माल मिलना कठिन हो जायेगा। इस उद्देश्य की भी पूर्ति के लिए वह सदस्यता ग्रहण करना चाहता था। (v) आज ब्रिटेन अपने ही अकेला महामुस करके गया है। इसलिए वह बाध्य होकर अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए मित्र राष्ट्रों का बोध भाजन बनने के बावजूद भी साम्राज्यवादी की सदस्यता के लिए कटिबद्ध है। (vi) इंग्लैंड की सदस्यता के कई राजनैतिक कारण भी कहे जा सकते हैं जो बार्थिक कारणों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। आज इंग्लैंड यह जानता है कि राष्ट्रकुल का त्रमश घटना हुआ राजनैतिक प्रभाव इसके चमकते हुए मित्तारे पर बादल बंधकर छा रहा है। इस प्रकार, यदि सदस्यता मिल जाती है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह एशिया में अपना राजनैतिक प्रभाव बनाये रखने में सफल हो सकेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं पर प्रभाव

अधिकतर राष्ट्रों का सम्बाध पीड स्टलिङ्ग से है, अब पीड के नये अवमूल्यन से अन्तर्राष्ट्रीय अवयवबस्था प्रभावित हुये बिना नहीं रह सके। इस समय स्टलिङ्ग क्षेत्र में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका, रोडेसिया, भारत, पाकिस्तान, श्री लंका, अफ्रीका और कैरेबियन सागर के भूतपूर्व उपनिवेश अदन, जुर्दान, कुवैत, ब्रूनो, हांगकांग, मलेसिया, सिंगापुर, आइसलैंड, माट्टा, ब्रिटिश गुआना, ब्रिगान्ती होट्टा और आयरलैंड गणतन्त्र है, जो न केवल अपने मुराति क्षेत्र में दक्ष और पीड का प्रपह ही करते हैं, अपितु उसे लन्दन के वित्तीय संस्थानों में भी जमा रखते हैं, तथा लेनदेन का हिसाब भी पीड में ही करते हैं। इस प्रकार मुद्रा के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन में पीड का बहुत महत्व है।

(१) स्टलिङ्ग का अवमूल्यन पहले भी १९४६ में १० १% किया गया था, उस समय स्टलिङ्ग क्षेत्र के २२ सदस्यों में से १७ ने इसी अनुपात में अवमूल्यन किया था, परन्तु अब ब्रिटेन के अलावा अन्य अनेक देशों ने भी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, जो इस प्रकार स्पष्ट है :—

आयरलैण्ड	१४ ३	प्रतिशत	श्री लंका	५०	प्रतिशत
फिजी	"	"	हांगकांग	१४ ३	"
डेन्मार्क	"	"	साइप्रस	"	"
उजराइयन	"	"	माल्टा	"	"
गायना	"	"	मालवी	"	"
बरमूदा	"	"	जेम्बिया	"	"
सीरिया	२०	प्रतिशत	टिनीडाड	"	"
रूत	२६ ६	"	टोबागो	"	"
न्यूजीलैंड	१६ ४	"			

अमरीका, कनाडा, यूरोपियन साम्राज्य बाजार के देश, रबीडन, नार्वे, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, ग्रीस, जापान, आस्ट्रेलिया, यु० ए० आर०, पानामा, यूगोस्लाविया, कुवेत, बरीनी, मनेसिया, सिंगापुर आदि देशों ने अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के लिये इन्कार कर दिया। फिर भी अमरीकी डॉलर पर पौण्ड के अवमूल्यन की सबसे अधिक प्रतिशतियां हुईं, क्योंकि पौण्ड मुद्रा के अवमूल्यन के साथ ही अमरीका ने बैंक डिस्काउन्ट की दर बढ़ा कर साठे अंश प्रतिशत कर दी। इसके साथ ही सरकारी व्यय में ७०० करोड़ डॉलर की कटौती करने और १० प्रतिशत सरचार्ज वृद्धि पर भी जोर दिया गया। यद्यपि अमरीका ने सोने का मूल्य ३५ सेट प्रति औंस रखने की घोषणा की, फिर भी पौण्ड के अवमूल्यन के कारण डॉलर पर पड़ने वाले दबाव से अमरीकी सरकार तनक हो उठी।

(२) स्टर्लिंग क्षेत्र के देश जो इंग्लैंड में सुरक्षित कोष के रूप में निविद्योग करने के उसका सूर्य भी कम हो गया है। उस समय लगभग एक अरब डॉलर घन पौंड के रूप में लन्दन में जमा था, जिसकी कीमत एक ही रात में घटकर १४.३% कम हो गई। इस प्रकार, पौंड के अवमूल्यन से अनेक देशों को आर्थिक हानि हुई है।

पौंड के अवमूल्यन से ब्रिटेन पर प्रभाव

पौंड के अवमूल्यन का अर्थ है — (i) ब्रिटेन से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं अन्य राष्ट्रों के लिए अधिक सस्ती हो जायेंगी और नारो, मशीनी औजारों व अन्य बहुत-सी वस्तुओं की बिक्री को तत्काल बहाबा मिलेगा। (ii) आयातित माल की कीमत बढ़ जायेगी। इससे राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर में गिरावट आ सकती है क्योंकि ब्रिटेन का करीब आधा भोजन और इनके कच्चे मान विदेशों से प्राप्त होते हैं। (iii) लेविन औद्योगिक ब्रिटेन के लिए निर्यात में बढ़िया व आयात में कटौती का लाभ तभी बना रह सकेगा जब बेतन-वृद्धि पर पड़ा अकुल रखा जाय। अगर ऐसा हो सका तो व्यापार की खाई कम हो जायेगी और औद्योगिक उत्पादकता बढ़ जायेगी। (iv) लेकिन अगर दूसरे राष्ट्र भी प्रति-योगिता बनाए रखने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर देते हैं और अगर घर

पर मूल्य-वृद्धि के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि की माँग जोर पकट आती है तो ये लाभ अंग्रेजों के हाथ ही समय तक रहेंगे।

सरकार ने राजकीय व्यय में (मुख्यतः सैनिक व्यय में) कमी करने की घोषणा की। किन्तु यह मोटर गाड़ियाँ खरीदने पर प्रविष्यक्त लगाने, वॉर दर को ८०% कर दिया जिससे विदेशी पूँजी और अल्पकालीन लाभ दूढ़ने वाला विनियोजन स्थानान्तरित न हो सके, क्योंकि इससे स्टॉक पर भार की मात्रा बढ़ जाती। मिल् मजिनको तथा थमिको और अन्य आवश्यक वस्तुओं से अलग-अलग वारंट-बोन की गई, जिनसे अवमूल्यन में उत्पन्न ख़तरों से बचा जा सके। इसी के साथ उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में १४ अरब डॉलर के ऋण की माँग की। वहाँ की आदेश दिया गया कि यह निर्यात व्यापार के उद्योगों को ही ऋण देने से प्राप्यमिता है। वहाँ नहीं ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों पर निगम कर ४०% से बढ़ाकर ४०% कर दिया। पौंड के अवमूल्यन के साथ काम में लाये गये इन उपायों सहित अवमूल्यन का उद्देश्य दूसरे देशों की वस्तुओं के आयात को ब्रिटेन में पहुँचा देना देना है जिससे कि ब्रिटेन के आयातक कम भाल आयात कर सकें।

अवमूल्यन के कारण विभिन्न वस्तुओं के मजदूरों की क़यसत कम हुई और आयात की सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़। इङ्ग्लैंड कच्चे माल के साथ-साथ अनाज और अन्य वस्तुओं का आयात करता है। इन सबका प्रभाव तत्पक्ष और कीमत पर पड़ना स्वाभाविक है। अतः लाभ और कीमतों पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य हो गया। यदि कीमत तथा माँग को नियमित किया जा सके, तो व्यापार में स्थिर वृद्धि होगी। परन्तु वास्तविकता यह है कि 'यदि' बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि देखा जाय, तो इङ्ग्लैंड को १४३% में अधिक अवमूल्यन करना चाहिए। अब भी पौंड का मूल्य कम है, जिसके लिए इङ्ग्लैंड को देर सवेर फिर अवमूल्यन करना होगा। अवमूल्यन बीमारी की दवा नहीं है बल्कि तात्कालिक रीक ही है। इङ्ग्लैंड पर ऋण का भार बढ़ गया है जिससे भुगतान की समस्या अधिक बढ़ती जायेगी।

पौंड के अवमूल्यन में भारत के विदेशी

व्यापार पर प्रभाव

यद्यपि भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार निरन्तर कम होता जा रहा है, तो भी भारत अभी तक ब्रिटेन को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। १९६१-६२ में १९६५-६६ के बीच की पंचवर्षीय अवधि में भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन का योग १६७ प्रतिशत था। पट्टी और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में भारत ने कुल व्यापार में ब्रिटेन का योग क्रमशः २४ प्रतिशत और २२४ प्रतिशत था। १९६६-६७ में भारत के कुल व्यापार में ब्रिटेन का योगदान केवल ११.५ प्रतिशत था और अगस्त-अक्टूबर १९६७ में ब्रिटेन का योग केवल ११.२ प्रतिशत रह गया।

पौंड के अवमूल्यन में ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार पर प्रतिफल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। पौंड के अवमूल्यन के कारण भारत ब्रिटेन को कम वस्तुओं

निर्यात कर सकेगा और साथ ही ब्रिटेन की बनी वस्तुयें कम मूल्य पर उपलब्ध होने के कारण अधिक आयात करने लगेगा। क्योंकि दोनों में निर्यात का प्रतिशत अधिक है इसलिए निर्यात के परिमाण में थोड़ी भी कमी होने से कुल व्यापार पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बाय भी कम होगी।

आयात पर प्रभाव—

ब्रिटेन से भारत निरन्तर कम आयात करता रहा है और १९६६-६७ के वर्ष में भारत लगभग १,००० पौण्ड का आयात पहले से कम करने लगा। १९६४-६६ में भारत ने ३,१५० लाख पौण्ड की वस्तुयें आयात की थी लेकिन १९६६-६७ में २,१३० लाख पौण्ड के मूल्य की वस्तुयें आयात की गईं। इन आयातों में से ४० प्रतिशत के लगभग का मूल्य ब्रिटेन से ही ऋण लेकर भुगतान किया गया। पौण्ड के अवमूल्यन के बाद ब्रिटेन ने जो कदम उठाये हैं उनमें राष्ट्र मण्डलीय देशों को बिये जाने वाले ऋण पर भी प्रभाव पड़ेगा और महँगी मुद्रा की नीति ब्रिटेन द्वारा अपनाई जाने के कारण भारत में ब्रिटेन की कम पूर्जा लगाई जायेगी। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटेन में भारत कम वस्तुयें आयात करेगा, बावजूब इससे कि उनका मूल्य अब भारत के लिए कम हो गया है।

कुछ जवाहरातों का आयात बढ़ाया जा सकता था, लेकिन ब्रिटेन के निर्यातकों के मुकाबले में हमारी स्थिति कमजोर हो जाने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका है। दि लन्दन डायमण्ड कम्पनी का जवाहरातों के व्यापार में एकाधिकार है। इस कम्पनी ने अपने जवाहरातों का मूल्य १६ ६६ प्रतिशत के लगभग बढ़ा दिया है। उसका असर यह हुआ है कि पौण्ड के अवमूल्यन से पूर्व के बराबर ही इन जवाहरातों का मूल्य रुपये में है। इस प्रकार भारत के आयातकों को पौण्ड के अवमूल्यन का जवाहरातों के व्यापार में लाभ नहीं हो पाया है। इसलिये हमारी यह चारणा पक्की होती जा रही है कि ब्रिटेन से भारत का आयात बढ़ नहीं पाया है।

निर्यात-व्यापार की सम्भावनायें—

पौण्ड के अवमूल्यन का ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार पर असर निर्यात-व्यापार के क्षेत्र में आयात-वापार के मुकाबले अधिक पड़ेगा। पौण्ड के अवमूल्यन का भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापार पर तीन तरह से असर पड़ सकता है। प्रथम, ब्रिटेन भी मण्डो में भारत की बनी वस्तुओं को दूसरे देशों की बनी वस्तुओं की ज्यादा होड़ ना मुकाबला करना पड़ेगा, खासतौर से उन देशों की बनी वस्तुओं को होड़ का, जिन्होंने अपनी-अपनी मुद्राओं का पौण्ड के अवमूल्यन के साथ-साथ अवमूल्यन किया है। इससे ब्रिटेन के साथ हमारे ७० प्रतिशत निर्यात पर प्रतिफल प्रभाव पड़ेगा। परम्परागत निर्यात-वस्तुओं में चाय, सूती वस्त्र, पटसन की बनी वस्तुयें, तम्बाकू और अन्य तरह के मान सम्मिलित हैं। दूसरे, ब्रिटेन के आयातक भारत से भारतीय वस्तुयें कम आयात करना अधिक पसन्द करेंगे, क्योंकि भारत की बनी वस्तुयें पौण्ड के अवमूल्यन के पश्चात् १६ ६ प्रतिशत अधिक मूल्य पर उन्हें प्राप्त हो सकेंगे। पौण्ड के

मुकाबले में लक्ष्य का मूल्य १५६ प्रतिशत बढ़ चुका है। पीण्ड का मूल्य रुपये के मुकाबले में अवमूल्यन के कारण १४३ प्रतिशत कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, भारत की वनी हुई वस्तुओं माल होने की दरों में १२२ प्रतिशत वृद्धि की घोषणा महाभारती उद्योग द्वारा की जाने के बाद महुयी हो जायेगी। इससे अतिरिक्त ब्रिटेन की सरकार द्वारा महुये पीण्ड की नीति की घोषणा करने के पश्चात् विदेशी वस्तुएँ ब्रिटेन की मण्डियों में महुयी हो जायेंगी। जिसका अवतंगत्वा प्रभाव भारत के निर्यात पर पड़े बिना नज़र रह सकता। तीसरे, भारत के निर्यातक अपने यहाँ की वनी वस्तुएँ स्वयं की मण्डियों में बचने के लिये उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि पीण्ड का दाय्य रुपये में २१ से १५ रह गया है।

पीण्ड के अवमूल्यन के अन्य प्रभाव

(१) १९६६ में भारत ने जिन समय अवमूल्यन दिया था उसके मन्तिष्य में यह बात थी कि विदेशी पूँजी द्वारा भारत में बसाया गया मुनाफ़ा व बचने में भारत की कम विदेशी मुद्रा दनी पड़े परन्तु ब्रिटेन द्वारा पीण्ड के अवमूल्यन में यह स्थिति फिर न बसावत हो गई।

(२) इस अवमूल्यन का भारतीय वित्तीय अवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार इस प्रभाव को अपने व्यय में कटौती करके दूर कर लेती है तब तो भारत के बरदान पर इसका कोई भार नहीं पड़ेगा, परन्तु यदि सरकार अपने बजट में किसी प्रकार का कटौती नहीं करती तो निरवय ही भारतीय सरकार की अधिक कर देने के लिए विवश किया जा सकता है।

(३) ब्रिटेन ने अपनी बैंक दर बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दी जिससे भारत के निजी कारोबार के धन के भावा पर शीघ्र प्रतिप्रिया शुरू हो गई। भारत में इस समय बैंक दर ६ प्रतिशत है और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसमें कोई वृद्धि की जायेगी। इसका प्रतिकूल प्रभाव यह होगा कि भारतीय एकतर्जन बैंकों की कुछ पूँजी खन की ओर जाने लगेगी। इस प्रकार भारतीय द्रव्य बाजार की पूर्ति स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी तथा वर्तमान आर्थिक मंदी की स्थिति सुधरने के बजाय और भी अधिक खराब हो सकती है।

(४) ब्रिटेन स्वतन्त्रता के समय भारत का देनदार था, परन्तु धीरे धीरे हमने उनमें अपना धन तो ले ही लिया विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिये और भी बहुत सा धन ऋण के रूप में लिया है। इस कारण भारत ब्रिटेन का देनदार बना रहता है। इस अवमूल्यन ने पीण्ड का दाय्य तीन रुपये कम करके भारत की इस देनदारी को कम कर दिया है। परन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भारत की ब्रिटेन से मिलने वाली वार्षिक सहायता में १४३ प्रतिशत की वनी हो जायेगी।

(५) अब भारतीयों के लिये स्टनिज़्ड छात्रों में प्रवेश करवा जाता है। ज़ायदा इसी प्रकार भारतीय छात्र और छात्राओं को ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त करने के

लिये कम घन की आवश्यकता होगी, तथा भारत सरकार के कन्धों पर विदेशी पूँजी की माँग का भार कम हो जायेगा ।

उपसंहार—

अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देश व्यापारिक नीति को मकुचित राष्ट्रवादी नीति पर आधित करते जा रहे हैं, जिस कारण विश्व व्यापार कम होता जा रहा है और विश्व व्यापार में से भी पिछड़े हुये देशों का भाग घटता जा रहा है । भारतीय मुद्रा हमर की अपेक्षा सस्ती है । किन्तु अमरीका भारत से आयात बहुत ही कम करता है, जिसके अविव्य में बढ़ने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार, भारत का व्यापार अब दो पाटों में कस गया है । एक ओर अमरीका की अनुदार नीति तो दूसरी ओर इंग्लैण्ड की मुद्रा अवमूल्यन से उत्पन्न हुई समस्या है । पौण्ड के अवमूल्यन में भारत पर जो प्रभाव पड़ेये उनका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को हानि की सम्भावना अधिक है । पौण्ड के अवमूल्यन कृप्रभावों का सामना करने हेतु निम्न मुकाब दिए जा सकते हैं — (१) आयात प्राप्ति लाइसेन्सों को उन्मुक्त हस्तांतरणीयता प्रदान की जाय । (२) वगदी सहायता देते समय इसकी गणना, चासू अनुबन्धों की बजा में, पुरानी विनियम दर पर की जाय । (३) उन चालू अनुबन्धों के लिये जिनका भुगतान अवमूल्यन के बाद की विनियम दरों पर मिलेगा । व्यापारिया की हानि-पूर्ति हेतु सरकार को चाहिये कि विक्रय की निर्यात कर में पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर दें । विशेषतः सूती वस्त्रों के चालू अनुबन्धों के सम्बन्ध में समुचित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । (४) निर्यात करों को घटाने में रेवेन्यू सम्बन्धी लाभों के विचार को आड़े नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि यदि हमने अपने निर्यातों की कीमतों को विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर नहीं रखा, तो हमारे निर्यात घट जायेंगे तथा दुर्लभ विदेशी मुद्रा की हानि उठायेंगे । (५) सरकार को चाहिये कि एक ऐसी उपयुक्त सत्ता स्थापित करे जो कि विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में तत्कालिक निर्णय में और समुचित उत्पादन व निर्यात प्रमुख नीतियों का अनुसरण करे ।

परीक्षा प्रश्न

१. १९६७ में पौण्ड का अवमूल्यन क्यों किया गया ? इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

[Why was the Sterling devalued in 1967 and how has it affected India's foreign trade ?] (आगरा, एम० कॉम०, १९६८)

भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या

(Problem of Foreign Exchange in India)

प्रारम्भिक—विदेशी मुद्रा के अभाव की समस्या

प्रथम योजना की अवधि में विदेशी विनिमय ने कोई समस्या प्रस्तुत नहीं की थी। हम विदेशी सहायता का पूर्ण प्रयोग भी न कर सके। यहाँ तक कि इङ्ग्लैंड ने रोके गए स्टर्निङ्ग पावने से जो एकम प्रयोग के लिये मुक्त की गई थी उसका भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया। पहली योजना का आरम्भ होने पर विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताएँ २६० करोड़ रु० के बराबर अनुमानित थीं। किन्तु कृषि उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि होने, कोरियाई युद्ध के प्रभावस्वरूप निर्यात आय साधारण रूप में अधिक होने, विकास ध्येय की धीमी प्रगति और गैर आवश्यक आयात पर नियन्त्रण होने के कारण थालू खाते में वास्तविक घाटा आधा से कहीं कम हुआ। इस प्रकार केवल १२७ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा ही प्रयोग में आई और विदेशी विनिमय कोष में ६०२ ३५ करोड़ रु० की एक बड़ी राशि बच रही।

द्वितीय योजनावधि में विदेशी विनिमय सहायता का प्रारम्भ

द्वितीय योजना में भारी उद्योगों पर बस दिया गया था। अतः यह स्पष्ट था कि योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिये पूँजीगत सामान के लिये भारी आयात की आवश्यकता पड़ेगी। अनुमान था कि पाँच वर्ष की अवधि में आयात आधिक्य (Import Surplus) १,३७५ करोड़ रु० का होगा। इसमें से २२५ करोड़ की पूर्ति अल्पकाल से होंगे २०० करोड़ रुपये पीछे पावना कोष में मिल जायेंगे और १०० करोड़ रुपये ग्राइडेट रूप से नियोजित किये जायेंगे तथा ६०० करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कमी पड़ेगी।

तालिका १
भारत की विदेशी मुद्रा सुरक्षित कोष (करोड़ रु०)

वर्ष की समाप्ति	निधि	वृद्धि (+) या कमी (-)
१९५०-५१	१,०२८ १५	२८ ५५
१९५१-५२	६०२ ३५	१०४७
१९५२-५३	६८१ १	२२१ २
१९५३-५४	४२१ २	२५६ ६

सन् १९५६-५७ में पूँजीगत वस्तुओं का आयात बहुत बढ़ गया, किन्तु निर्यातों में उतनी वृद्धि न हो सकी । हमारे भुगतान सन्तुलन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा । चावल खाते के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी विनिमय कोष से आहरण करना आवश्यक हो गया । स्थिति बिगड़ती ही रही । फल यह हुआ कि अर्प्रैल ५६ में सितम्बर ५७ तक १८ महीने की अवधि में रिजर्व बैंक को विदेशी सम्पत्तियों में ३६६ करोड़ रुपये की कमी आ गई । यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ६५ करोड़ रुपये की सहायता न मिली होती, तो यह कमी ४६१ करोड़ रुपये तक जा पहुँचती ।

सकट के लिए उत्तरदायी कारण

विदेशी विनिमय संकट के लिए जो कारण हाथी बने उनको समझ लेना आवश्यक है । ये कारण निम्नलिखित हैं —

(१) योजना का बहुत महत्वाकांक्षी होना—विदेशी विनिमय कोष में तेजी से गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण हमारी द्वितीय योजना का स्वभाव बहुत महत्वाकांक्षी होना था । योजना में जिस दर से विनियोग किया गया वह अमाधारण रूप से ऊँची थी । योजना के प्रथम वर्ष में पूँजीगत सामान का आयात बहुत मात्रा में हुआ । आयात की दर पहली योजना की तुलना में दूनी हो गई ।

(२) आयातित विनियोग वस्तुओं की ऊँची लागतें (Higher costs of imported investment goods)—विदेशों में आयात की गई विनियोग वस्तुओं की विदेशी लागतें स्वेज नहर के संकट और विदेशों में मुद्रा प्रचार की प्रवृत्तियों के कारण, पहली योजना की तुलना में १० से १९ प्रतिशत बढ़ गई थी ।

(३) निश्चित समय से पहले आयात (Imports ahead of the Schedule)—प्राइवेट साहसियों को यह आज्ञा थी कि द्वितीय योजना के अन्तिम वर्षों में विदेशी विनिमय का सकट उत्पन्न हो जायगा । अतः उन्होंने अपने समस्त आयात समय से पहले ही योजना के प्रारम्भिक वर्षों में प्राप्त करने के गत्न किये ।

(४) खाद्यान्नों के आयात में अचानक वृद्धि (Sudden increase in imports of foodgrains)—सन् १९५१-५२ में खाद्यान्नों के आयात का व्यय २२८ करोड़ रुपये था । सन् १९५५-५६ में केवल २६ करोड़ रह गया किन्तु १९५७-५८ में पुनः बढ़कर १५२ करोड़ रुपये हो गया । यद्यपि खाद्यान्नों के आयात का स्तर हमारी भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी गठनाइयों का एकमात्र कारण नहीं था तथापि विदेशी विनिमय संकट उत्पन्न करने में इसका महत्त्वपूर्ण योग्य रहा ।

(५) गैर योजना व्यय में वृद्धि (Rise in non-plan expenditure)—बामुसेना और नौसेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा सम्बन्धी व्यय बहुत बढ़ गये थे । इसने भी विदेशी विनिमय संकट में योग दिया । पहली योजना के कुछ अपूर्ण कार्यक्रम भी दूसरी योजना के प्रारम्भ में ही पूरे किये गये । इससे भी द्वितीय योजना का विदेशी विनिमय सम्बन्धी व्यय बढ़ गया ।

(६) अर्थव्यवस्था में उपभोग सम्बन्धी माँग बढ़ना (Rising consump-

tion demand within the economy)—विदेशी विनिमय सङ्कट का एक कम महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि अर्थ-व्यवस्था में उपभोग सम्बन्धी माँग बढ़ गई थी जिसे घरेलू उत्पादन द्वारा जो कि गुरुवत कुटीर और ग्राम उद्योगों पर आघातित था, पूरा नहीं किया जा सका।

(७) आयात नियन्त्रण नीति की दुर्गन्तायें (Loopholes in the Import Control Policy)—सन् १९५६-५७ के पहले छ महीनों में गैर आवश्यक वस्तुओं का आयात विशाल मात्रा में किया गया। यद्यपि लाइसेंस और निषेधन की कठोर व्यवस्था विद्यमान थी।

सरकार द्वारा सङ्कट निवारण के उपाय

द्वितीय योजना के प्रथम वर्ष के बाद भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर कठोर बचाव पड़ने लगे। जुलाई ५७ में विदेशी विनिमय कोष बहुत घट गये, अगस्त ५७ में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के इन्फू विभाग की विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ३७५ करोड़ रुपये तक गिर गई। विदेशी विनिमय सङ्कट का निवारण के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये —

तालिका २ भारत का विदेशी मुद्रा कोष

(करोड़ रु०)

३१ मार्च की समाप्त वर्ष	कोष	वृद्धि (+) या कमी (-)
१९३८-५६	३७५ रु	— ४२ रु
१९५६-५७	३६२-६	— १६०
१९६०-६१	३०३-६१	— ५६-२५
१९६१-६२	२६७-३१	— ६३०
१९६२-६३	२६५-१०	— २२१
१९६३-६४	३०५-५१	+ १०७१
१९६४-६५	३४६-६८	— २६-१३
१९६५-६६	२६७-६८	+ ४८-३०
१९६६-६७	४७५-४४	+ १८०-४६
१९६७-६८	५३८-५५	+ ६०-११
१९६८-६९	५७६-७०	+ ३८-१५
जन० ७०	६७१-०	+ ९४-३

(१) विदेशी कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था में संशोधन—रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था को अक्टूबर सन् १९५७ में संशोधित किया गया। इस संशोधन के अनुसार वार्षिक न्यूनतम विदेशी प्रतिभूति कोष (४०० करोड़ रु०) और स्वर्ण कोष (११५ करोड़ रु०) को पटानर केवल २०० करोड़ रु०

(जिसमें ११५ करोड़ ४० का स्वर्ण भी सम्मिलित है) रहने दिया गया, ताकि घाटे की पूर्ति के लिए कोष से अधिक राशि का आहरण किया जा सके ।

(२) आयात-नियन्त्रण में कठोरता—आयात-प्रतिबन्ध कड़े किए गए । पूंजीगत सामान के आयातकों को लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु यह नियम बनाया गया कि वे विदेशी सप्लायरों से स्थगित मुग्तान के समझौते करें ।

(३) निर्यात सवर्धन के लिए विशेष उपाय—निर्यात बढ़ाने के लिए कई तरह की कार्यवाहियों की गईं जिनका विवेचन हमने भुगतान सन्तुलन की प्रतिकूलता को घटाने के उपायों के अन्तर्गत किया है ।

(४) विदेशी मुद्रा के ऋण—यही नहीं, मित्र देशों और मुद्रा कोष से अधिक ऋण लेने के यत्न किए गए । यदि विदेशी धन से सामयिक ऋण न मिले होते तो, भारत अपने विकास कार्यक्रमों को बड़ापि पूरे नहीं कर सकता था ।

उपरोक्त उपायों के फलस्वरूप भुगतान सन्तुलन में बाटा कम हुआ और इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा काय सम्बन्धी स्थिति में भी स्पष्ट सुधार हुआ । सन् ५६६०-६१ को छोड़कर काय में उत्तरोत्तर कम र शिर्षा निकासी गई है ।

सन् १९६२ में चीन के घातपूर्ण आक्रमण के कारण भारत के भुगतान सन्तुलन पर दबाव पड़ने लगे । स्वर्ण की निरव्ययिता के लिये नवम्बर सन् १९६२ व जेनवरी १९६३ के बीच में एक नई स्वर्ण नीति की घोषणा की गई । इसकी प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं —(i) सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड जारी करने का फैसला किया, जो कि १५ वर्ष की अवधि के और ६५ प्रतिशत व्याज के होंगे । लोग अपना सोना देकर इन बॉन्डों का क्रय करते हैं । क्रय की दर ६२½ रुपये प्रति तोला होगी । (ii) सरकार ने देख भर में सोने के बायदा व्यापार पर रोक लगायी । इसका उद्देश्य सोने पर आधारित छट्टा सम्बन्धी त्रय-विक्रय को रोकना था । (iii) सरकार ने स्वर्ण निर्यात नियन्त्रण तिवन जारी किये । इनके अनुसार आभूषणों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्वर्ण की, जो कि पास में हों, घोषणा करना आवश्यक हो गया । यदि किसी के पास अधोषिप्त स्वर्ण है, तो सरकार उसे जब्त कर सकती है । (iv) देख में भविष्य में सोने से या दिशमान आभूषणों से बनाये जाने वाले सब आभूषण १४ कैरट से अधिक शुद्धता के नहीं होने चाहिए ।

आधा थी कि ४,००० करोड़ रुपये के सोने का पता लगेगा लेकिन वास्तव में ४ करोड़ रुपये के और आभूषण स्वर्ण की घोषणा की गई । स्वर्ण नीति का उद्देश्य सोने के तत्कर व्यापार को रोकना और आभूषण इत्यादि के लिए सोने की आन्तरिक माग को कम करना था जिससे कि स्वर्ण की कीमतें अन्त में नीचे आ सकें । लेकिन अभी तक यह एक स्वप्न रह चुका है और स्वर्ण की आन्तरिक कीमत अभी भी काफी ऊँची बनी हुई है ।

वर्तमान स्थिति

जैसा कि वियत पृष्ठ में दी गई तालिका २ को देखिये से पता चलता है,

१९६३-६४ को छोड़कर प्रस्तुत दशक (१९६०-६६) के प्रथमाप में हमारे बोधों में लगातार वृद्धि होती गई है। १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति २४ करोड़ रुपये का पुराना ऋण वापस करने के बाद, ११ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् वृद्धि ३५ करोड़ रुपये की थी, जबकि पिछले वर्ष में १२ करोड़ रुपये मुद्रा कोष में उधार लेने के बाव भी दो करोड़ रुपये की कमी हुई अर्थात् १४ करोड़ रुपये की वृद्धि थी। इस प्रकार १९६३-६४ में विदेशी विनिमय सफट में वृद्धि कमी हुई। १९६४-६५ में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण एवं और आयातों में भारी वृद्धि हुई और दूसरी ओर निर्यात म्यूनाधिन स्थिर रहे जिससे कि वर्ष पर्यन्त विदेशी मुद्रा-कोष पर दबाव जारी रहा और १९६४-६५ में निवल ५६.१३ करोड़ रुपये की कमी हुई। इस असुधारण कमी का कुछ हद तक यह भी कारण है कि सरकार को अनाज, उर्वरक आदि के आयात पर अधिक खर्च करना पड़ा और जहाज भाड़े पर भी अधिक खर्च हुआ। नवम्बर १९६४ में ब्रिटिश बैंक दर को बढ़ाकर ७ प्रतिशत कर देने का भी हमारे भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विदेशों से पर्याप्त विद्यालय महायत्ना मिलने पर भी विदेशी मुद्रा-कोष से जो भारी निकासी हुई उसने देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष में ऋण सम्बंधी सचनो (stand-by-arrangements) का लाभ उठाने तथा सरकारी स्टॉक से १६ करोड़ रुपये के मूल्य का अमौद्रिक स्वर्ण विदेशी मुद्रा कोष में हस्तांतरित करने के लिये विवश बना दिया। जून १९६६ में रुपये का अवमूल्यन करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। १९६६-७० में हमारे विदेशी विनिमय कोष की स्थिति में काफी सुधार रहा है, क्योंकि (i) कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई विशेषतः खाद्य-स्थिति में सुधार हुआ, (ii) आयात प्रतिस्थापन में प्रगति हुई, (iii) औद्योगिक निर्यातों की गति बढ़ गई, जिससे आयातों में कमी आई किन्तु हमारे निर्यातों विशेषतः अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यातों में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार, भुगतान मतुलन की प्रतिकूलता में सुधार हुआ।

विदेशी विनिमय सम्बंधी कठिनाइयों के कारण कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया था कि हमें अपने ऋणों की अदायगी रोक देनी चाहिए। किन्तु यह सुझाव ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि अपनी ऋण-अदायगी की जिम्मेदारियों को अन्य जिम्मेदारियों की भाँति पूरा करें। अवश्य ही अपने भिन्न देशों से और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लगनी भिदाद की सहायता माँगते समय हम उनसे इस बात को भी ज्ञान में रखने को कहें कि हम अपने ऋणों की अदायगी करनी हैं। हमने पहले भी ऐसा ही किया है। परन्तु ऋणों की अदायगी रोकने का वित्तकुल कोई प्रयत्न नहीं है।

चौथी योजना के लिये विदेशी विनिमय

चौथी योजना के लिए विदेशी विनिमय प्राप्त करने की नीति बुनियादी रूप में भिन्न रहनी पड़ेगी। जब योजना आयोग चौथी योजना पर विचार कर रहा था, तब इसकी एक प्रमुख चिन्ता यह थी कि बाणिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए जिस विद्यालय आकार की योजना को कार्यान्वित करने जा रहे हैं उसके लिए आवश्यक

विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त की जाय। उसे नवीन राजनैतिक एवं आर्थिक घटनाओं के मद्दम में इसकी सम्भावनायें घुँघली हो प्रतीत हो रही थी। जबकि हमारी रक्षा और अधिक आवश्यकताओं के कारण विदेशी सहायता की आवश्यकता बढ़ रही है तब इसकी पूर्ति की दृष्टिसे विपन्न रहते हैं क्योंकि (i) सभी अर्ध-विकसित राष्ट्रों की सहायता सम्बन्धी आवश्यकता बढ़ गई है तथा (ii) विकसित राष्ट्रों पर राजनैतिक एवं अन्य कारणों से सहायता राशि को सीमित करने के लिये दबाव पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में, व्यापार एवं वाणिज्य हों विभिन्न राष्ट्रों की नीति का आधार बनने जा रहा है। वास्तव में, विकसित एवं कम विकसित राष्ट्रों के हित एक दूसरे के विरुद्ध होते जा रहे हैं। यह बात अभी हाल में हुए विदेश व्यापार एवं वाणिज्य सम्मेलन में प्रगट हुई थी।

उपरोक्त घटक यह आवश्यक करने हैं कि विदेशी मुद्रा की समस्या का जोई स्थायी और पगोपन्नक हल ढूँढा जाय। इस हेतु सरकार को योजना के विदेशी मुद्रा वाले भाग में विनियोग की बचत करने का उपाय ढूँढना होगा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के स्मार्ट साधन तलाश करने होंगे, आयात पर नियंत्रण किये जाने वाले विदेशी विनिमय में भारी कटौती करनी पड़ेगी एवं विदेशी ऋणों पर व्याज सम्बन्धी व्यय में घटौती के उपाय विचारने होंगे। यदि सरकार उपयुक्त आर्थिक नीतियाँ अपनाये, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति कठिन नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं —

(१) विदेशियों को सनिज प्रसाधनों के शोधन की अनुमति देना—ऐसी अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाय —(i) विदेशी फर्मों सरकार को रॉयल्टी विदेशी मुद्रा में चुकावे, (ii) निर्यात से पहले सनिजों का भारत में ही विधायन (Processing) किया जाय, जिससे कि इनकी कीमत मृद्धि का कुछ लाभ भारत को भी मिल सके, (iii) उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत ही निर्यात किया जाय, एवं (iv) आन्तरिक उपभोग के लिए कीमतों की अधिकतम सीमाएँ निर्धारित कर दी जायें।

(२) विदेशी संस्थाओं को उद्योग स्थापित करने की अनुमति देना—ऐसी अनुमति देते समय सरकार यह शर्त रखे कि इनके उत्पादन का एक अंश अल्पतया ही निर्यात किया जायेगा। यह प्रतिपादित इतना पर्याप्त होना चाहिए कि फर्मों द्वारा साक्षात् और व्याज का भ्रमण करने के उपरान्त भी थोड़ा-थोड़ा विदेशी मुद्रा बचे। कारखानों की स्थापना के स्थानीय व्यय पूरे करने के लिये अमेरिकी उपकरणों की आवश्यकता कि अमेरिकी सरकार ने वार्ता करके P. L. 480 ऋणों के रूप में कोषों के प्रयोग की अनुमति प्राप्त कर ली। जो उद्योग इस योजना के अधीन प्रारम्भ किये जायें वे मुख्यतः निम्न दो श्रेणियों के हो सकते हैं —(i) ऐसी मशीनें वा, जो कि अभी तक पूर्णतः आयात की जा रही हैं, निर्माण करने के लिये उद्योग, एवं (ii) औद्योगिक एवं उद्योगोत्पाद दोनों प्रकार की उद्घाटन वस्तुओं बनाने के लिये उद्योग, जिससे कि एशियाई

बाजारों के लिये इनकी कीमतें कम की अपेक्षा कम हो सकें। तृतीय वर्ग के उत्पादन का एक अंश आन्तरिक बाजारों के लिये भी सुरक्षित रखना चाहिये, जिससे कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में स्वस्थ प्रतियोगिता प्रचलित हो सके।

(३) भारतीय उद्योगपत्नियों को एशियाई और अफ्रीकी देशों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देना—अन्य शब्दों में, निम्नित वस्तुओं के निर्यात पर से जोर हटाकर कारखानों का निर्माण करने पर जोर दें। चूंकि सभी अर्थ-विकास देश अपना विश्वास करने के लिए उत्सुक हैं इसलिए वे इस नीति का अधिक प्रेम से स्वागत करेंगे, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का एक स्थायी स्रोत खुल जावेगा।

(४) स्थिति भुगतान पद्धति पर निर्यात सुविधायें देना—सरकार को चाहिये कि एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को स्थिति भुगतान पद्धति पर पूर्ण प्लान्ट और मशीनें निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन दे और आवश्यक बिा की व्यवस्था भी करे।

(५) तकनीकी ज्ञान का निर्यात—एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों को इनकी आवश्यकताओं का विकास करने में सहायता देने के लिये तकनीकियों को भेजकर टेक्निकल ज्ञान का निर्यात करे।

(६) व्याज ब्याज घटाना—विदेशी ऋणों पर व्याज सम्बन्धी व्यय कम करने हेतु सरकार को निम्नलिखित कार्यविधि अपनानी चाहिये जब विदेशों से विशेष परियोजनाओं में प्रयोग के लिये ऋण प्राप्त होते हैं, इन परियोजनाओं का कार्य प्राइवेट फर्मों को सौंपा जाता है एवं ये फर्म अपने विदेशी सहयोगियों से मशीनें आदि स्थिति भुगतान की शर्तों में मंगाती है, तो दोहरा व्याज दिया जाता है—एक बार सरकार द्वारा और दूसरी बार फर्मों द्वारा। अब यदि सरकार विदेशों से मिले ऋण में से ही उक्त फर्मों को मुद्रा का आयात के लिए धन दे दिया करे, तो लाखों रुपयों के व्याज की बचत हो सकेगी।

(७) विदेशी वित्त केन्द्रों में ऋण लेना—सरकार को चाहिये कि जापान की भांति विदेशी वित्त केन्द्रों में, खुले बाजारों में ऋण लेना शुरू करे। ये ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं—(i) सामान्य वार्षिक विकास हेतु लिये गये ऋण एवं (ii) प्राइवेट एवं पब्लिक उपक्रमों द्वारा विदेशों में खेयों और डिबेन्चरों के रूप में प्राप्त की जाने वाली पूंजी की गारन्टी।

(८) विश्व बाजारों का लगातार अध्ययन—यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय हमारे परम्परागत निर्यात जैसे कि चाय और पटसन की वस्तुओं के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हो रही है और अन्य देशों के साथ प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती जा रही है। हमने अभी अपना माल बेचने की कला भी नहीं सीखी है। व्यापारी वर्ग और सरकार दोनों को ही गसरार की मार्केट का लगातार अध्ययन करने के लिए और उत्पाद पैदा करने के लिए एक संस्था की स्थापना करने में सहयोग देना चाहिए।

श्री मनुभाई शाह ने ये तीन शर्तें बताई हैं —(i) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को ठीक प्रकार से डिब्बो या पैकेटो में बन्द किया जाना चाहिए ताकि विदेश में जो लोग उन्हें खरीदें उन्हें वे जीवें आकर्षण दिखाई दें, (ii) निर्यात सम्पूर्ण परिपक्व और चम्पु बोर्ड अपने लक्ष्यों को बढ़ाये, और (iii) कुछ हद तक निर्यात व्यापार की दिशा को बदलें ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन की जा सके। निर्यात व्यापार में निर्यातकों को समाप्त करने के लिये एक व्यापार मंच बनाने हेतु सरकार वित्तीय तथा अन्य रिमायने देने के लिये विचार कर रही है ताकि अवस्थित दम में वस्तुओं के कम-विक्रय का प्रबन्ध हो सके। अब समय आ गया? अब हमें नई-नई वस्तुओं के निर्यात के लिये नये बाजार ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिये।

(६) आर्य निर्भर अर्थव्यवस्था—एक राजनीतिक ने हाल में योजना का लक्ष्य इस प्रकार बताया है कि देश की अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाया जाये ताकि विदेशी सहायता पर हम कम से कम निर्भर रहे और अन्त में हमारी अर्थ-व्यवस्था 'स्वयं विकसित होने वाली' बन जाये। इसका मतलब यह है कि हमें विकास की ऐसी अवस्था तक पहुँचना होगा जहाँ पूँजी संचयन की दर और बचत की दर इतनी हो जाये कि उसमें आगे कोई वृद्धि किये बिना ही हम अर्थव्यवस्था में ६ या ७ प्रतिशत की वृद्धि करने रहे।

(१०) इंडीनिफरी वस्तुओं के निर्यात पर विशेष ध्यान देना—जबकि इंडीनिफरी गृह के निर्यात १९६५-६६ में २६ करोड़ ४० से बढ़कर १९६६-६७ में ४५ करोड़ ४० हो गए हैं तथा मेन्टीनेन्स आयात इन वर्षों में ४३ करोड़ ८० से बढ़कर २८० करोड़ ४० हो गये। अभूतपूर्व वृद्धि आयात नीति को उद्धार बनाने से सम्भव हुई। इस प्रकार, इंडीनिफरी उद्योग ने विदेशी धितिमय कौप पर सर्वाधिक बचाने डाला। अब हमें चाहिये कि सचेत और निरन्तर प्रयासों द्वारा वह उद्योग सहायता की अधिकाधिक दे।

(११) कृषि उत्पादन में वृद्धि—दो-तिहाई निर्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिये निर्यात-लक्ष्यों की पूर्ति में कृषि उत्पादन में वृद्धि का बहुत महत्व है। चौथी योजना के दौरान आम फसलों तथा व्यावसायिक फसलों को एक जैसी प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

(१२) अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन न देना—सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई है जिसकी स्थापना में तथा जिसके चलाये के लिये अत्यधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। श्री राम ने सुझाव दिया कि कम से कम अब से ऐसे उद्योगों की स्थापना की गजब नही देनी चाहिये जो चालू होने के तीन वर्ष के अन्दर विदेशी मुद्रा अर्जन नहीं कर सकें या विदेशी मुद्रा की वचत नहीं कर सकें।

(१३) मेन्टीनेन्स आयातों पर विदेशी मुद्रा के व्यय में बचत करना—४० उद्योगों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद मेन्टीनेन्स काउन्सिल ऑफ एम्पाईड इन्वॉन्-

मिक रिमर्च' ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चीची योजनावधि में मेन्टीनेस आयातों पर होने वाले विदेशी मुद्रा के व्यय में कम से कम १०% बचत की जा सकती है। इसकी सिद्धि हेतु नार्वे-सिड ने निम्न दो सुझाव दिये हैं—प्रथम, प्रत्येक उद्योग के लिए उद्योगपतियों का एक कन्सोर्टियम (संगठन) स्थापित किया जाय जो कि दत्त में स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन के लिए व्यवस्था करे। दूसरे, प्रत्येक उद्योग में अधशास्त्रियों और विद्यार्थियों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाय, जो वर्तमान समय में आयात किया जा रहा विभिन्न इन्पुट्स (inputs) की सूची तैयार करे और उन साधनों को बनाये जिससे द्वारा इनका देश में ही उत्पादन किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेन्टीनेस आयात की समस्या इसलिये गम्भीर हो गई है कि सम्बद्ध उद्योग पति इन सबों की विदेशी विनिमय लागत को अज्ञित करने में असफल रहें हैं जब तक कि उद्योग (प्राइवेट या सार्वजनिक) सरकारी विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त विदेशी विनिमय के अजन का दायित्व स्वयं पर नहीं लेगा। सब इन समस्या सुलभता कठिन है।

उपसंहार—

उद्योग क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक पंच सूची कार्यक्रम पर अमल किया है जिसमें देश में खनी सामग्रियों के अधिक व्यवहार पर बल दिया गया है। इस कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें देश में मशीनों के अधिजाधिक निर्माण की व्यवस्था है। चीनी, सीमेन्ट निर्माण सामग्री बायलर कोयलाई यन्त्र गैस सिलिंडर, रासायनिक सामग्री, कागज गोदाम आदि को ठण्डा रखने के तथा डेपरी से सम्बन्धित उपकरण बनाने की मशीनरियों का निर्माण देश में इतना बढ़ा दिया गया है कि इनके आयात पर व्यय होने वाले लगभग तीन करोड़ रुपय की प्रति वर्ष बचत होने लगी है। ट्रक तथा अन्य व्यावहारिक वाहनों के कलपुर्जों विधायित सीमा ६० प्रतिशत से भी अधिक मात्रा में सारे देश में निर्यात होने लगे हैं। कारों की भी—माहल के अनुसार—८० से ६० प्रतिशत सामग्री देश में बनने लगी है। वैज्ञानिक कृषि माल के व्यवहार में वृद्धि कर दिये जाने से भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में काफी कमी हो गई है। बिजली के तार बनाने में अल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाना लगा है जिससे प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी है। इंजीनियरिंग सम्बन्धी उद्योगों को गंधक व लौह के स्थान पर तमक का तेजाब जस्ता-बादल करण के लिये कहा गया है। मक्का और जिक अन्तर्माइक के बदले में टिटोनियम हायड्राइड का प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। इससे प्रति वर्ष लगभग एक करोड़ रुपय की विदेशी मुद्रा की बचत होने लगी है। ओपचियों में तथा ओपचि उपकरणों में जह्म आयातित विस्मय मेटल का प्रयोग हस्ता या उनके स्थान पर अब मैनीसियम तथा अन्य मिश्रित मिश्रित पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। रासायनिक पदार्थों तथा औद्योगिक मश्रूम होने वाले आयोडिन मा यम, क स्थान पर देश में उप-य

आयातित कच्चे भाव का व्यवहार किया जाने लगा है। देशी सामग्रियों के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिए बहुत से उद्योगों में विशिष्ट आदेश जारी किये गये हैं। भवन निर्माण तथा पाइप बिछाने के सम्बन्ध में आदेश दे दिया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो आयातित सीमेंट की चादरो के बजाय देश में बनी सीमेंट की चादरो का व्यवहार किया जाए। इससे लगभग ४६ लाख रुपये वार्षिक की बचत होने लगी है। प्राकृतिक रबर का उत्पादन बढ़ जाने में एक करोड़ ८० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत होने लगी है।

परीक्षा प्रश्न :

1. हमारे देश में विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न होने के मुख्य-मुख्य कारणों का विवेचन कीजिये। विदेशी विनिमय प्रसाधनों की बचत के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और ऐसे कदम हमारे देश में विकासार्थक नियोजन सम्बन्धी योजनाओं में कहाँ तक सहायक हो सके हैं ?

[Discuss the main causes of foreign exchange crisis in our country. What steps have been taken for the conservation of foreign exchange resources and to what extent do you consider such actions can help the developmental programmes of planning in our country ?]

2. भारत में वर्तमान विदेशी मुद्रा संकट को पैदा करने वाले कौन-कौन से घटक हैं ? क्या इनकी राय में सरकार की नीति इस संकट को पार करने के लिये पर्याप्त है ?

[What important factors have led to the present foreign exchange crisis in India ? Do you consider the Government policy adequate to meet the crisis ?]

(इलाहूँ एम० बी०, १९६६)

3. क्या एक अर्द्ध-विकसित देश में, जो कि अपने आर्थिक विकास की दर की तेजी से बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, विदेशी विनिमय का संकट उत्पन्न होता अनिवार्य है ? इस संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डालिये।

[Is a foreign exchange crisis inevitable in the case of an under-developed country trying to accelerate its rate of economic growth ? Examine India's case in this context.]

(आगरा, एम० ए०, १९६८)

विदेशी पूँजी एवं विदेशी विनिमय

(Foreign Capital and Foreign Exchange)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी पूँजी और विदेशी विनिमय की समस्याओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन समस्याओं से भारत के विदेशी व्यापार का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रस्तुत अध्याय में हम यह देखेंगे कि भारत में विदेशी पूँजी और विदेशी विनिमय की स्थिति क्या है तथा इसे कैसे सुधारा जा सकता है।

भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी का महत्व

विदेशी सहायता की आवश्यकता—

यह कहना गलत न होगा कि एक अर्ध-विकसित देश में आन्तरिक साधनों की बाढ़े कितनी ही बुझता। पूर्वक गतिशील बिना बाध, वे नियोजित विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपर्याप्त प्रमाणित होगे। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि पूँजी आधिक्य वाले देशों ने पूँजी-आयातों द्वारा आन्तरिक साधनों की मूल्यता को पूर्ण किया जाय। इनमें अर्ध-विकसित देशों को सम्मत्ता होने की कोई बात नहीं है। आज के अनेक उन्नत देशों ने भी अपनी प्रारम्भिक अवस्थाओं में विदेशों से व्यापक ऋण लिए थे। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड ने १६वीं एवं १७वीं शताब्दी में हालैंड से ऋण लिये और अमेरिका व कनाडा ने १९वीं शताब्दी में यूरोप से ऋण लिये। इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद विदेशी पूँजी के प्रति पहले जैसी विरोध भावना भी नहीं रही है, क्योंकि अब तब स्वतन्त्र देश अपने हितों की रक्षा करने में स्वयं को पर्याप्त समर्थ समझते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं (जैसे विश्व बैंक आदि) की स्थापना ने भी विदेशी पूँजी को एक अतिरिक्त-राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब आनुकूल अर्ध-विकसित देश अपने आर्थिक विकास के लिये विदेशी वित्त-साधनों का अधिकधिक प्रयोग कर रहे हैं।

भारत को विदेशी पूँजी से लाभ—

भारत में विदेशी पूँजी के पक्ष-विपक्ष में इतना कुछ कहा सुना गया है कि साधारण जनता भ्रम में पड़ जाती है। नीचे भारतीय परिस्थितियों में विदेशी पूँजी के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

विदेशी पूँजी से भारत को लाभ—

(१) देश में अपार प्राकृतिक साधन हैं, जिनका पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा सका है। इससे भारतवर्षी दखि बने हुए हैं। प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए पूँजी सर्वथा आवश्यक है।

(२) विदेशी पूँजी के आयात के साथ साथ हमें विदेशी टेक्निकल ज्ञान एवं प्रबंध कौशल भी प्राप्त होना है। आर्थिक विकास के लिए प्राथमिक ज्ञान का बहुत महत्व है जो दुर्भाग्य से हमारे देश में अलभ्य है। अतः विदेशी तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति से हम आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिलेगी।

(३) औद्योगिक विकास के लिए एक अविकसित देश को विदेशों से पूँजी एवं साधन संग्रहण पड़ता है जिसके निम्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा जुटाना उभ कठिन होता है। भारत के सम्बन्ध में भी यही बात है। विदेशी पूँजी की प्राप्ति में यह कठिनाई या हम होती है।

(४) औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में व्यवसायों की जाति में बहुत होती है व स्थापना व्यय भी अधिक होता है। अतः देशी साहसी नव व्यवसायों में पूँजी लगाने में सकोच करते हैं। किन्तु विदेशी पूँजी के वित्तियोग की दशा में व्यवसायों की जोखिम प्रायः विदेशियों द्वारा उठाई जाती है और बाद में ये व्यवसाय उनसे दशमसियों द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं।

(५) आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए भी विदेशी पूँजी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि निर्धारित मन्थों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन देश में ही जुटाने में कठिनाई हो रही है।

(६) उपयोगी सम्पत्ति का निर्माण—विदेशी पूँजी के प्रयोग में दान में ऐसी सम्पत्ति का सृजन किया जा सकता है जिससे मूलधन और व्याज देने के बाद भी लगानार लाभ प्राप्त होता रहे। रेलें, बहरेँ, विद्युत केन्द्र ऐसी ही सम्पत्तियाँ हैं।

(७) स्फीति के असरों को रोकने के लिए—जब देश में भारी वित्तियोग किये जा रहे हों तो मुद्रा की पूँति के मुकाबिले में इतनी ही तेज गति में वस्तुओं की पूँति में वृद्धि नहीं होती है। फलतः कई बार अथ तन्त्र में मुद्रा स्फीति का असर दिखाई पड़ता है। ऐसे समय पर स्फीति के असरों को कम करने के लिए विदेशी सहायता का उपयोग किया जा सकता है। निस्सन्देह कई बार विदेशी सहायता स्फीति का कारण बनती है। किन्तु जब यह सहायता उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में प्राप्त हो तो इसका असर मुद्रा स्फीति निरोधक के रूप में ही होता है। उदाहरणार्थ अमेरिका में हन P L 480 के अन्तर्गत जो सहायता मिलती है, उससे हम यहाँ और बाहर बड़ा पैसा आयात करते हैं। इससे हम एक 'बैफर स्टॉक' खड़ा कर सकते हैं, जो हम कमी के वर्षों में अनाज के भावों को बहुत ऊपर जाने से रोकने में मदद करता है।

(८) घातक पूँजी के पूरक के रूप में कार्य के लिए—भिन्न भिन्न देशों

को विदेशों से अब तक जो आर्थिक और फौजी सहायता मिली है वह सब शर्तों से मुक्त है।

(४) विदेशी पूँजी वस्तुओं के रूप में भी प्राप्त हुआ करती है जैसे मशीनें आदि, जो प्रायः विनियोगकर्ता देश की औद्योगिक व्यवस्था के अनुसार निर्मित होती है। ऐसी दशा में भारतीय परिस्थितियों में उनका अधिक उपयोग सम्भव नहीं होता तथा इसके अतिरिक्त विदेशों पर निर्भरता की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(५) आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण होने-भिने लोगों के हाथों में होता विदेशी पूँजी की ही वजह है। भूतकाल में विदेशी पूँजी के कारण ही भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली निरस्त हुई थी।

(६) जिन व्यवसायों में विदेशी पूँजी लगती है उनमें म्यूनाधिक सीमा तक विदेशियों का नियन्त्रण स्थापित हो जाता है। वे ऐक्यीकृत परामर्शदाता मंचालक, प्रबन्धन आदि के रूप में व्यवसाय में बने रहते हैं और यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए कभी भी चिन्ताजनक बन सकती है।

(७) विदेशी पूँजीपतिवर्ग न अपनी भारतीय गिना-गिनीयों से पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया है। उन्हीं उच्च पदों पर नौकर नहीं रखा गया जिससे वे अनुभव एवं प्रशिक्षण से वंचित हो गये। मर्यादा विदेशी पूँजी प्राप्त संस्थाओं का तो प्रगति से भारतीयकरण हो रहा है तथापि उच्च पदों के सम्बन्ध में स्थिति अभी भी असन्तोषजनक बनी हुई है।

विदेशी पूँजी के लाभ-दायों के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इसके अधिकांश दोष विदेशी नियन्त्रण से सम्बन्धित हैं विदेशी पूँजी से नहीं। विदेशी पूँजी का सदुपयोग करने के लिये निम्न साधनानिष्टा की आवश्यकता है —

(१) किसी भी प्रकार के साधन के विनियोग के लिए कई विकल्प हो सकते हैं, परन्तु 'विदेशी सहायता' जैसे अति उपयोगी और तात्त्विक साधन का उपयोग इन्ततम होना चाहिए। इसका विनियोग इतना होना चाहिए कि जिससे अधिक से अधिक बढ़ता मिल सके। यदि इसका विनियोग इस प्रकार से नहीं किया जाता, तो उसकी सहायता का बौद्धिक अर्थतन्त्र की कगार की निश्चय ही तोड़ डालेगा।

(२) यदि किसी देश की ऋण की सब रकम एक राष्ट्र भरनी पड़े, तो सम्भव है कि उसके अर्थतन्त्र पर प्रतिकूल दबाव पड़े। इससे बचने के लिए कई बार इस प्रकार के ऋण की अवधि और भविष्य में भरने की रकम के हिसाब से हर साल 'अग्र फण्ड' में निश्चित रकम जमा की जाती है। ऐसा करने से कारोबार में अपव्ययों पर भी प्रकुश आवेगा और ऋण की रकम के धीरे धीरे इकट्ठा होने में अर्थतन्त्र पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।

(३) अन्त में तो ये ऋण आयात के मुकाबले में अधिक निर्यात करके ही चुकाने पड़ते हैं। परन्तु कई बार आज की महाकाट होठ के कारण अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार में अर्धविकसित देशों का माल चलता ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में विदेशी ऋण पूरा करना अर्धविकसित देशों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ममय का गया है कि विकसित देश दत्त प्रश्न पर बहुत ही महानुभूतिपूर्वक और समझदारी से सोचें।

विदेशी पूँजी के प्रति सरकार की नीति—

१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, आन्तरिक पूँजी की कमी के कारण, विदेशी पूँजी की माँगना में, सरकार ने रेलों और नहरों का निर्माण कराया। चाय और काँची के बगीचा, कोयला व जूट उद्योगों के विभाग में भी विदेशी पूँजी काम आई। किन्तु विदेशी पूँजीपतियों ने अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि रखा तथा देश का नाशिक और राजनैतिक लोभण किया। अब भारत में विदेशी पूँजी की घुमा की दृष्टि में देखा जाने लगा। फिर भी, विभिन्न समितियों और जायानों ने विदेशी पूँजी के महत्त्व को स्वीकार किया। सन् १९२५ की विदेशी पूँजी समिति (External Capital Committee) ने दृढ़ बात पर बल दिया कि विदेशी पूँजी का विनियोजन भारतीय हितों के अनुसार होना चाहिए। सन् १९३५ के भारतीय सचिवालय में भी विदेशी पूँजी पर कोई बन्धन नहीं था। राष्ट्रीय योजना समिति (NPC) ने भी यह सुझाव दिया था कि विदेशी पूँजी का उपयोग सरकार की अनुमति से और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। सन् १९४६ की प्रथम मौखिक नीति में सरकार ने विदेशी पूँजी के महत्त्व को स्वीकार किया। किन्तु वह भी स्पष्ट कर दिया कि विदेशी पूँजी पर आवश्यक नियन्त्रण रखा जाना। सन् १९४६-५० के प्रद्युक्त अधोक्ष में यह मत प्रगट किया कि विदेशी पूँजी का उपयोग सरकारी क्षेत्र में किया जाना चाहिए, विशेषतः उन योजनाओं के लिये, जिनमें अधिक आयान करना पड़ता है। चूँकि उन दिनों राष्ट्रीयकरण आदि विवादों के कारण विदेशी पूँजी की स्थिति अस्पष्ट थी, इसलिए उस देश में विदेशी पूँजी के विनियोजन के लिए उचित मातावरण बनाने पर बल दिया।¹

फलतः ९ अप्रैल १९४६ को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में सरकारी नीति की घोषणा की थी, जिसकी प्रमुख बातें निम्न हैं—(i) विदेशी पूँजी के नियमन का उद्देश्य यह होगा कि विदेशी पूँजी इस प्रकार से उपयोग की जाये, जिससे कि वह देश के लिए अधिक लाभप्रद हो सके। (ii) विदेशी पूँजी अतिरिक्त पूँजी के अनुप्राप्त का कार्य करेगी तथा कई क्षेत्रों में अत्यावश्यक वंशानिक, प्राविधिक और औद्योगिक ज्ञान व पूँजीगत यस्तुयें उपलब्ध कराने में सहायक होगी। (iii) देखी एवं विदेशी पूँजी में कोई भेदभाव नहीं किया

¹ "It should be the duty of the State Policy to create and maintain conditions favourable for the inflow of all such foreign capital as desired to come to India."

जायेगा तथा सरकार विदेशी हितों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगावेगी । (iv) देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार विदेशी विनियोजकों को लाभ व पूँजी को स्वदेश भेजने के लिए उचित सुविधायें देगी । (v) भविष्य में उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने पर विदेशी विनियोजकों को न्यायोचित हर्जाना दिया जायेगा । (vi) कुछ दशाओं को छोड़ कर अन्य सब दशाओं में स्वामित्व और प्रभावपूर्ण नियन्त्रण भारतीयों के हाथ में रहे । इस प्रकार से विदेशी पूँजी व हस्तम्बन्धी व्यवसाय सरकार द्वारा नियन्त्रित किया जायेगा । (vii) यदि विदेशी कम्पनियाँ भारतीय हितों के अनुकूल तथा सहयोगी व रचनात्मक ढङ्ग से कार्य करती रहे, तो सरकार उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचावेगी ।

वर्तमान समय में भी इस नीति का पालन किया जा रहा है । अभी हाल में यह नियम भी बनाया गया है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा संचालित सभी उद्योगों के प्रबन्ध और स्वामित्व के आधे से अधिक भाग देश की सरकार या प्राइवट कम्पनियों का रहना चाहिए । अन्य दृष्टियों में, विदेशी पूँजी के लिए स्वीकृति सहनशीलता या सहभागिता के आधार पर ही दी जायेगी । वर्तमान विदेशी कम्पनियाँ अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं बशर्ते वे भारतीय हित में बाधक न बनें और भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करें ।

लोकतन्त्रात्मक जीवन शैली की रक्षा करने एवं उद्योग मुहूर्त बनाने के लिए समाज में स्थिरता रखना जरूरी है । अब नव स्वतन्त्रता-प्राप्त देशों में जहाँ व्यक्तिगत आय और सम्पत्ति की विषमतायें बहुत हैं, इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वही अधिक सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रीभूत न हो जाए, क्योंकि इससे देश की सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता की, जिसे सभी लोकतन्त्रात्मक सामन्य पद्धति के देश चाहते हैं, गहरा भंगका लगेगा । राजनैतिक स्थिरता से देश में विदेशी पूँजी के प्रभाव को बल मिलता है क्योंकि इससे लोगों में इन देशों के आर्थिक विकास के प्रति आस्था और विश्वास दृढ़ होता है ।

वर्तमान उद्योगों में विदेशी उद्योगपतियों द्वारा उत्तरीतर अधिक पूँजी लगाने और नये लोगों द्वारा पूँजी लगाने में मन्दोच की प्रवृत्ति से यह नतीजा निश्चयात् सचता है कि जो लोग भारत की अच्छी तरह जानते हैं वे भारत में ज्यादा से ज्यादा पूँजी लगाने के लिए तैयार हैं । इन बात का समर्थन ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने भारत के उद्योगों में आजादी मिलने के बाद जो भूमिका अदा की है उससे भी होता है, क्योंकि ब्रिटेन के व्यापारी भारत को ज्यादा नजदीक से जानते हैं ।

भारत में निजी विदेशी पूँजी विनिमय को बढ़ाना देने के लिए यह जरूरी है कि सभी सम्भावी पूँजी विनियोगकर्ताओं को भारत के विषय में अधिक जानकारी दी जाए । यह एक ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए केवल सरकारी कार्यावाही जरूरी हो इस कार्य के लिए अब एक गैर सरकारी मस्था स्थापित की गई है जिसको पूँजी विनियोग केन्द्र (इन्वेस्टमेंट सेंटर) कहते हैं । इस संस्था के कार्य निम्न हैं —

(i) पूँजी निर्यात करने वाले देशों में भारत की विनियोजन नीति एवं कार्यविधि का प्रचार करना, (ii) भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूँजी आकर्षित करने में सहायता देना, (iii) विदेशी व्यापारियों को भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में सलाह देना, (iv) विशिष्ट उद्योगों में विदेशी पूँजी प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाना, (v) सूचनाएँ प्रसारित करना ।

पूँजी विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre) को अपने प्रयत्नों में पर्याप्त सफलता मिली है । कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, प० जर्मनी, स्विटजरलैंड, बेल्जियम और जापान के बहुत से उद्योगपतियों ने केन्द्र के माध्यम से भारतीय उद्योगों में पूँजी-सहयोग के समझौते किये हैं ।

पिछले वर्षों में कई प्रतिनिधिमण्डल भी विदेशों में गये हैं और उन्होंने विदेशियों को भारत में पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है । अस्मिता हो, यदि भारतीय बैंकों की बिजली साम्राज्य में 'सूचना केन्द्र' स्थापित कर दिये जायें, जिनमें विदेशी विनिर्माजकों को भारत में विनियोजन सम्बन्धी सूचनाएँ सत्काम मिल सकें ।

देश में विनियोग के आतावरण को सुधारने के लिए सामान्य उपाय करने के अतिरिक्त सरकार ने अन्य कदम भी उठाये हैं जो इस प्रकार हैं — (i) विदेशी विनियोग या सहयोग वाले मामलों पर जल्दी ही निर्णय दिये जा सकें, इस हेतु जॉब पत्रदान सम्बन्धी निष्पक्ष कार्यविधियों में सुधार करना, (ii) प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेशी पूँजी और तकनीकी ज्ञान के नियमित प्रवाह को उत्साहित करने के लिए कर्म में रियायत देना, जैसे — भाषाओं को सुपरट्रेन्स में छूट देना इन्जीनियरिंग सेवाओं पर कर की दर घटाना, विदेशियों को स्वीकृत प्रतिभूतिपत्रों से प्राप्त होने वाली आय को मुक्त करना, सरकार की अनुमति से भारतीय कंपनियों को जो अनु छिप गये हो उन पर कर से विदेशी विनियोजकों को मुक्त करना, विदेशों से दोहरे करारोपण के बचाव के उद्देश्य करना, विदेशी टेक्नोसियनों की सतस्वाही के सम्बन्ध में मुक्त समयावधि वधाहर ५ से ७ वर्ष करना, विदेशियों द्वारा भारतीयों को मेमबरी से हटाना-तरण से जो पूँजीगत लाभ हो उस पर कर न लेना । प० जर्मनी ने भारत में विनियोग करने वाले जर्मनी नागरिकों को सीमा-मुविषाये दी है जिसके बचने में भारत ने प० जर्मनी को कुछ विशिष्ट रियायतें दी हैं ।

अधिक विशाल माथा में विदेशी प्राइवेट पूँजी प्राप्त करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने कैंपेटन प्रोजेक्ट आरम्भ करने के लिए विदेशी कम्पनी को ही लैटर्स ऑफ इन्टेंट (Letters of Intent) देने का निर्णय किया है । अब तक यह होना था कि सरकार विदेशी कम्पनी से कोई भारतीय समेतार दूँडने को कहती थी और फिर देने माकेदार को ही लैटर ऑफ इन्टेंट प्रदान करती थी । इन उपक्रमों के लिए भारतीय मुद्रा की व्यवस्था करने हेतु औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की मेवाये उपलब्ध कर दी गई है । यह भी भोविन किया गया है कि विदेशियों द्वारा

निजी भारतीय बैंक में जमा कराई गई रकम पर जो व्याज प्राप्ति होगा उस पर कर नहीं लिया जावेगा।

जातावरण विनियोग के अनुकूल—

भारत में विदेशी उद्योगपतियों को पूँजी लगाने हेतु जातावरण पड़ने की अपेक्षा बहुत ही अनुकूल है। भारत का निजी क्षेत्र उसके सम्पूर्ण विनियोग का एक बड़ा हिस्सा है और उसका योगदान राष्ट्रीय उत्पादन के ८६ प्रतिशत के बराबर है। यह क्षेत्र पर्याप्त कुशल और उत्तरदायी है। इसका अगला मुख्यवर्षित संगठन है और जब सभी सरकार या अन्य कोई शक्ति इसका बाट पट्टेयने का खन करती है तो यह उसका मुकाबला भी करता है। हमारी सरकार यह समझने लगी है कि कम्पनियों में उद्देश्य पूरा नहीं होता, इसलिए मूल्य उत्पादन और वितरण पर से कन्ट्रोल जगह-जगह हटाए जा रहे हैं। हमारी मुद्रा और राजकोषीय नीतियाँ भी अर्थतन्त्र के विकास के अनुकूल ढाँची जा रही हैं। कृषि के मोर्चे पर भी स्थिति में सुधार हुआ है। दो वर्ष का सूखा अब अमीन की चीज बन गई है। लेकिन पिछले दो वर्षों में उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं रही है। महंगाई के कारण खहरों में माल की माँग कम हो गई। किन्तु कृषि उत्पादन बढ़ने में माँग थब फिर बढ़ने लगी है। बैंक दर भी कम कर दी गई है और रिजर्व बैंक ने श्रृंखला की शर्तें उदार कर दी हैं। उत्तरीतर बढ़ते हुए विकास ध्येय में सरकार ने बिधाम लिया है। लेकिन अन्य सब सरकारों की भाँति भारत सरकार भी अपना प्रशासनिक व्यय नहीं घटा सकी है।

दूसरी ओर निजी क्षेत्र ने भी यह समझ लिया है कि कहा-कही सरकारी प्रयत्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार के उत्पादक व्यय में कटौती में कल-कारवाने बन्द होने लगे हैं। नींव के निर्माण में हम सरकार या नेतृत्न चाहते हैं क्योंकि यह भावश्यक और उत्पादक है। हमारे देश में सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ सबक सीने हैं। अब नीची योजना का उद्धार करने में सगे हैं।

उस प्रकार भारत के अन्दर परिस्थितियाँ अर्थतन्त्र के तेज विकास के अनुकूल हैं। यह विकास हम कहाँ तक कर पावेंगे यह हम बात पर निर्भर करता है कि हमारे वैदेशिक व्यापार को गुला हमारे पास में झुकी हुई हो। भारत जैसे विकासशील देश में विनाम विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर करता है यह मुद्रा व्यापार और विदेशी विनियोग से ही प्राप्त हो सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि विकसित देशों के लिए एक-दूसरे के जहाँ पूँजी लगाना ज्यादा आकर्षक है लेकिन विकासशील देशों में पूँजी नगाना उताने में ज्यादा फायदेमन्द है। यहाँ तक भारत का सम्प्रन्ध है यहाँ निम्नतर विकास के लिए प्रति संघार है। भारत उन थोड़े से देशों में है जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का विनियोग हो सकता है। यहाँ उन्हें अपने विनियोग पर ज़रूरी मुताफा मिलेगा।

कर लगाए जाने में पूर्ण विनियोजित पूँजी पर ताग वाजिव चौर पर काफी ज्यादा होता है, इसलिए विमुक्त साध की राशि विनियमित देशों में सामान्य तोर पर

वर्जित की जाने वाली धन राशि में अधिक होती है। विकासशील देशों द्वारा करो म विभिन्न रियायत दिव जान और विनियोग में भाग लेने वाले देशों की सरकारों के बीच दौड़ते कर न लगाय जान के लिए समझौते के बायजूद यदि पूँजी विनियोजक का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह यह है कि विदेशी पूँजी विनियोजक को अपने देश में वर्जा केवल ही आधार पर दिया जाता है कि वह अपने सरकार को वित्तना कर देता है, जो स्वभावतः समझौते के अनुसार बहुत कम होता है।

श्री विरमा न पूँजी विनियोजकों को मदद के लिए एच डियमन क्लब का सुझाव दिया है जो यह कि पूँजी जमान बाज दक्ष का सरकार को चाहिए कि वह अधिकारित देशों में लगाई जाने वाली पूँजी के एच प्रश को कर-मुक्त रखे। इस तरह की रियायत से अधिक जरूरतमंद देशों में अधिक निजी पूँजी आयेगी। उन्होंने कहा कि कुछ विकासशील देशों ने जिनमें एच भाग्य भी है, उत्पादन और वितरण पर कई नियमनों में ढील दे रखी है। स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए पूँजी विनियोजकों को अपने देश में तैयार मान के निर्णय के लिए अपने साधनों का उपयोग करना चाहिए और उनके देश की सरकार को ऐसे मामलों पर कोई आपात प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। इससे विकासशील देशों का अपने वर्जों की अदायगी और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिकायत की कि कुछ विदेशी टेक्नीशियन में उत्पादन की स्वामीय समस्याओं को हल करने में यह उत्साह नहीं पाया जाता है जो वे अपने देश में दिसाते हैं। यह मनुक्त रूप से बताया जाने वाले उद्योग में हानिकारक प्रमाणित हुआ है।

विदेशी पूँजी सम्बन्धी वर्तमान स्थिति

(I) विदेशी सहायता (External Assistance)—

विदेशी सहायता से अभिप्राय उस सहायता का है जो सरकारी स्तर पर प्राप्त होती है। इसका प्रयोग पब्लिक एवं प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में हुआ है। विभिन्न देशों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता मिली है। इसमें अनुदान (जो कि भेद स्वरूप हैं, जल लौटाये नहीं पड़ते), P. L. 480 और P. L. 665 के अन्तर्गत अमेरिकी सहायता एवं ऋण (स्वयं में लौटाये जाने वाले एवं विशेषी मुद्रा में लौटाये जाने वाले) सम्मिलित हैं।

सितम्बर १९६७ तक भारत को विदेशी सहायता के रूप में कुल १४९४.९१ करोड़ रु० प्राप्त हुये। १९६७-६८ में ८६१ करोड़ रु०, १९६८-६९ में १२१ करोड़ रु० और १९६९-७० (अप्रैल-सितम्बर) में २८० करोड़ रु० की शुद्ध विदेशी सहायता मिली। सर्वाधिक विदेशी सहायता अमेरिका ने प्रदान की। सहायता देने वाले देशों में दूसरा स्थान सोवियत संघ का है। तीसरा स्थान जर्मनी का है।

विदेशों में प्राप्त होने वाली सहायता के सम्बन्ध में निम्न प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती हैं—(१) विगत वर्षों में भारत को प्राप्त विदेशी सहायता में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिसका कारण यह है कि योजना व्यवस्था बराबर बढ़

रहा है। (ii) विदेशी मुद्रा में नुकसाने योग्य ऋणों की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है किन्तु अनुदान और P. L. 480 के अन्तर्गत प्राप्त राशियाँ घट गई हैं, जिनका स्वाभाविक परिणाम यह है कि सामान्य कर भार में वृद्धि होती जाती है। (iii) विदेशी ऋणों की मात्रा में बहुत उदारता आई है—व्याज दर कम हुई है तथा ऋण लौटाने की अवधि अपेक्षित समी की गई है। (iv) यद्यपि व्याज दर घटी है तथापि ऋण की बढ़ती हुई मात्रा के कारण कुल देय व्याज बढ़ा है। यदि विदेशी कम्पनियों द्वारा अर्जित एज प्रेषित नामांक की गयी सम्मिलित कर लिया जाय, तो वार्षिक व्याज की रकम कुल विदेशी मुद्रा कमाई (चासु) का २०% है। (v) विदेशी ऋणों को लौटाने में कठिनाई होन लगी है, क्योंकि विदेशी ऋणों में स्थापित फारजाँ मिलभ्य में फल देने वाले हैं। इसी कारण भारत ने ऋणदाता देशों से ऋण लौटाने की तिथियाँ स्थगित करने का अनुरोध कई बार किया। (vi) भारत-पाक युद्ध के कारण कुछ समय तक दोनों देशों को विदेशी ऋण मिलने बन्द हो गये थे किन्तु अब फिर आरम्भ हो गये हैं।

(II) भारत में विदेशी व्यावसायिक विनियोग—

प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोग या विदेशी व्यावसायिक विनियोग (Foreign Business Investment) में दीर्घकालीन स्वभाव के विनियोग हैं जो भारत में व्यावसायिक उपक्रमों में गैर-निवासीयों (non-residents) द्वारा किये गये हैं। इनमें (अ) विदेश स्थापित कम्पनियों की भारत में कार्य करने वाली शाखाओं के कुछ विदेशी दायित्वों और (इ) भारतीय कम्पनियों में विदेशियों द्वारा खरीदे गये अंश (आधुनिक स्वतन्त्र कंपो समेत) एवं ऋण-पत्र सम्मिलित होते हैं। अभी तक भारत में प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोग प्रायः विदेशी प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किये गये हैं। लेकिन आधुनिक वर्षों में ऐसे विनियोगों का एक पर्याप्त भाग वह है जो प्राइवेट कम्पनियों ने विश्व सस्याओं से ऋण लिया है। मार्च १९६७ के अन्त में प्राइवेट सेक्टर में विदेशी विनियोगों का मूल्य १,१११ करोड़ रुपये था।

संयुक्त उपक्रम (विदेशी सहयोग)—

आधुनिक वर्षों में विदेशियों ने भारतीय व्यवसायियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने आरम्भ किये हैं। इनमें विदेशी व्यवसायी अल्प पूँजी सौदागते हैं, तकनीकी सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं, औद्योगिक उपक्रमों की प्रारम्भिक योजनाएँ तैयार करते हैं और साथ ही भारतीय विनियोगकर्ता भी उनके सहयोग के कारण ऐसे उपक्रमों में अधिक पूँजी लगाने हेतु उत्साहित होते हैं। ३० सितम्बर १९६६ तक सरकार ने २,६६० विदेशी सहयोग के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये थे, जिनका देश वय से वितरण इस प्रकार था :—यू० के ८०६, अमेरिका ५३६, ५० जर्मनी ४६१, जापान २६२, स्विट्जरलैंड १३७, फ्रांस ११२, इटली ८१, यू० जर्मनी ६०, हॉलैंड ४५, स्वीडन ५१, डेन्मार्क ३२, चेकोस्लावाकिया ३३, आस्ट्रिया २४, बेल्जियम २५, पोलैंड १८, कनाडा २०, हंगरी १६, यूगोस्लाविया १४, फिनलैंड ५, पनामा ४, पाकिस्तान २,

अन्य २२२। इन प्रकार यू० के०, अमेरिका और ५० जर्मनी इन तीन देशों का भाग ६०% में भी अधिक था। सरकारी अर्थ-व्यवस्था वाले देशों (यू० जर्मनी, चेकोस्लावाकिया, पोलेण्ड, हंगरी और यूगोस्लाविया) में हुए सम्झौतों की संख्या १४१ है जबकि शेष देशों में २७४६ सम्झौते हुए।

३० जून १९१७ तक जो २,७३० सहयोग-सम्झौते सरकार द्वारा स्वीकार किये गए थे उनका उद्देश्य रम में वितरण यह था —मशीनरी ७८६, इन्जिन ४४२, लैंबीयन पोटकटन १२६, यातायात इक्विपमेंट ६० (इन चारों का मेयर कुल के १०% में भी अधिक है), लोहा व इस्पात ७३, दवाइयाँ ५६, बुनियादी औद्योगिक स्थापन ५२, वाहन ४०, मोमेंट ३४, रबर ३४, मृत्ती कटन २७, मिर्क, एक व्यक्ति २०, व्यापारिक ४४, वागान १३, चीनी ११, अन्यूमिनियम ६, विद्युत उत्पादन १२, फूट ३, सिपिंग ८, बैकिंग व बीमा १०, अन्य ४८४।

उन्नेसनीय है कि सहयोग-सम्झौतों की वाणिज्यिक संध्या घटने लगी है। इसका कारण यह है कि अब अधिकांश सामग्री दिशामें प्रयोग में आ चुकी है तथा विदेशी तकनीक के उपयोग की सम्भावनामें भी सतम होने लगी हैं।

विदेशी ऋण की समस्याएं

विदेशी ऋणों का कमर तोड़ बोझ—

विनाश के पथ पर अग्रसर देशों को अन्य देशों से सहायता लेनी पड़े, इनमें कीड़े बुराई नहीं है। किन्तु भारत की पर-निर्भरता जिस हद तक बढ़ गई है वह बिना का विषय है। विदेशों द्वारा दी गई सहायता का बोझ जब कमर तोड़ने की मात्रा तक पहुँच जाए, तो मनक ही जाना चाहिये। सर्व प्रतिनिध भारत पर विदेशी ऋण का बोझ बढा ही जाता है। हम सहायताओं योजनायें बनाते हैं, उन योजनाओं की पूर्ण के लिये हम विदेशों से ऋण लेना होता है। फिर धीरे-धीरे ऋणों की उस राशि का व्याज ही इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाने में भी परेशानी होती है। मूलराशि तब चुकाने का जब नम्बर आयेगा तब आयेगा, व्याज चुकाने के लिए भी हमें फिर विदेशियाँ ने ही और ऋण माँगना पड़ता है। इस प्रकार भारत मर्दा हाथ में मिश्रा-पात्र लिए ही रहता है। बीसवीं शताब्दी में योजना की समाप्ति तक भारत की ऋणों के व्याज की ही देनदारी २१ अरब ५६ करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी।

व्याज और बर्जा की जवाबगी की देनदारी का यह बोझ तभी कम हो सकता है, जबकि व्याज की दर कम हो और साथ ही उनकी जवाबगी अधिक लम्बी अवधि में हो। इमीलिए भारत को पेरिस में हुई भारत सहायता एवं की वेंचर में यह प्रार्थना करना पडे कि उन्हे विदेशी ऋणों की जवाबगी के कार्यक्रम में परिवर्तन किया जाय या उसे उनकी जवाबगी के लिए अतिरिक्त विशाद हो जाए।

ऋणों के प्रयोग में अपव्यय—

किन्तु विदेशी ऋणों का एक और पट्टा भी है। भारत ने पिछले बीस वर्षों

मे ८,००० करोड़ रु० का सामान मगाया। यह ८,००० करोड़ रु० का सामान इस प्रकार था १ ३०० करोड़ रु० के पुर्वे १,००० करोड़ रु० का लोहा और इस्पात, १,४०० करोड़ रु० के पट्टीलिमम उत्पादन, २,३०० करोड़ रु० का अनाज, २०० करोड़ रु० के उर्वरक ५०० करोड़ रु० के रासायनिक पदार्थ और १,२०० करोड़ रु० की रुई। इसके अलावा और भी कितना ही सामान विदेशों से आयात किया गया, जिसमें उपभोग्य वस्तुएँ और बहुत सी मशीनरी भी शामिल हैं। लेकिन अगर हमने समझदारी से काम लिया होवा और अपनी योजनाओं का ठीक ढंग से बनाया होता तो हम हमसे भी ६०० करोड़ रु० की बचत कर सकते थे। उस दशा में हमारा विदेशी एजों का बोझ उतना नहीं होता जितना आज है। इस बात को भी स्पष्ट किया जा सकता है कि एक रुपये की वस्तु का उत्पादन करने के लिए तीन रुपये का बिनियोग करना पड़ता है। यदि हम ८०० करोड़ रु० का सामान इस देश में प्रति वर्ष तैयार करते थे तो हम उसके लिए आज भी १५ या २० वर्ष पूर्व नवीं २४०० करोड़ रु० बिनियोग करना पड़ता जिसमें मे उस समय के हिस्से से आधा अंश यानी १,२०० करोड़ रु० यही मुद्रा के रूप में और १,२०० करोड़ रु० विदेशी मुद्रा के रूप में होता। यदि इन बीस वर्षों में १० वर्ष भी हम रा उत्पादन ८०० करोड़ रु० वार्षिक के हिसाब से होता रहता तो हम ८,००० करोड़ रु० की बचत कर लेते और यदि अधिक नहीं, पाँच वर्ष ही हमारी उत्पादन की यह रफ्तार रहती तो भी कम से कम ४,००० करोड़ रु० की बचत हो जाती।

लेकिन हमारी सरकार के सामने समाजवाद का आदर्श था, और औद्योगिक विकास को उसमें कमो धी, इसलिए परिणाम यह हुआ कि उसने औद्योगिक विकास एवं योजना को फ्रिगान्वित करने के लिए औद्योगिक नीति अपनाई। उसने देश को ८,००० करोड़ रु० के औद्योगिक उत्पादन से वंचित कर दिया। उदाहरण के लिए भारत प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में लोहा खनिज निर्यात करता है और विदेशों से तैयार इस्पात आयात करता है। यदि भारतीय उद्योगपतियों को भारत में ही इस्पात कारखाने की अनुमति दे दी जाती तो विदेशों से तैयार इस्पात का आयात करने की आवश्यकता न पड़ती। किन्तु इस तरह के सभी मामलों में समाजवाद का आदर्श आटे जा गया और परिणाम यह हुआ कि या तो सरकार ने इस्पात कारखाने हथकौनी और उन्होंने प्रबन्ध कौशल और अनुभव की कमी के कारण लाभ के बजाय घाटा दिया, या विदेशों से इस्पात का आयात करने में हम अपनी कीमती विदेशी मुद्रा को व्यय करना पड़ा।

यदि हमने आदर्शवाद को आटे न जाने दिया होता और अपने देश के भीतर ही निरसरकारी खन के अनुभव का लाभ उठाकर उत्पादन किया होता तो आज हम विदेशी मर्जों में गले तक डूबे न होते और हमें गिरापात्र लेकर अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाता न पड़ता। यदि सरकार अब भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और

गैरसरकारी क्षेत्र को देश के विकास में योगदान का अवसर दे तथा विदेशों से प्राप्त ऋण का पूरा सदुपयोग वरे एवं नियंत्रण बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा वरे तो स्थिति सुधर सकती है।

यह ठीक है विदेशी ऋण लिए बिना किसी भी अल्पविकसित देश का तीन-तीनवें दशक से आर्थिक विकास करना आसान नहीं है। अल्पविकसित देश इस स्थिति में नहीं होने कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनरी एवं अन्य परिष्कृत उपकरण स्वयं बना सकें। उन्हें उनका बाहर से आयात करना ही पड़ता है। इसके अलावा उनके पास तकनीकी ज्ञान भी पयाप्त नहीं होता वह भी उन्हें बाहर से ही प्राप्त करना पड़ता है। यही कारण कि भारत को भी विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में वज लेना पड़ा है।

परन्तु यदि सरकार आयात निर्यातकर्ताओं को आयात के बीजक कम मात्रा के और निर्यात के बीजक कम मात्रा के बनाने की प्रवृत्ति से रोशन के लिए बड़े बड़म उठाती और विदेशी कंपनियों को भारत में प्राप्त मुनाफा का अधिक भाग इसा देश में पुनर्निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती तो विदेशी मुद्रा की कुछ बचत होती और इस प्रकार हमारा विदेशी ऋणों का बोझ कुछ हल्का हो जाता।

सहायकों का कर्तव्य —

इसके अलावा जो विकसित देश अल्पविकसित देशों को विकास के लिए सहायता देते हैं उनका भा यह कर्तव्य होता है कि वे अल्पविकसित देशों द्वारा अपने यहाँ विकास के फलस्वरूप तैयार किए गए सामान को खरीदें। यदि अल्पविकसित देश हमेशा प्राथमिक उत्पादों के ही निर्यातकर्ता बन रहें तो उनके औद्योगिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। तत् राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने १९५० और १९६० के बीच एक अध्ययन में यह अनुभव किया कि विश्वित देशों से निर्यात देशों से निर्यात किए गए सामान के मूल्य १५ प्रतिशत गिर गये। इस प्रकार विकासोन्मुख देशों को अपने निर्यात व्यापार से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन देशों में भारत भी है। विकासोन्मुख देशों में इस समस्या के हल के लिए जो भी प्रयत्न किए उन्हें विकसित देशों ने व्यर्थ करने का प्रयत्न किया। इसका कारण शायद यह नहीं है कि विकसित देश अल्पविकसित देशों की सहायता नहीं करना चाहते। कठिनाई यह है कि वे अपने निजी स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं। इस सम्बन्ध में विकसित देशों को अपना रुख में परिवर्तन करना चाहिए। जब तक अल्पविकसित देशों का निर्यात नहीं बढ़ेगा और निर्यात से उन्हें बचत नहीं होगी तब तक उनके लिए अपने निर्यातों का उत्तारना कठिन सम्भव होगा।

चौथी योजना की पूर्ण सम्बन्धी आवश्यकताएँ

इसमें भारत के सामने यह समस्या पैदा हो गई है कि यदि विदेशों से सहायता न मिले तो उस अपन पिछड़े ऋणों और व्याज की बदायणी स्थिति करने के

लिए भी ऋणदाता देशों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए भारत को विकास योजनाओं को जारी रखने, उसके कारखानों की बेकार क्षमता को चालू करने, अन्न के आयात की आवश्यकता पूरी करने एवं पुराने ऋणों को व्याज सहित अदायगी करने के लिए विदेशों से सहायता मिलना जरूरी है। राजनीतिक दलों के बिना यदि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऋणदाता देशों या विश्व बैंक से कोई उपयोजी सुझाव प्राप्त हो तो उन्हें स्वीकार करने का अर्थ देश की प्रगुष्टता का बेचना नहीं समझा जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने ही भीतर से अपनी आवश्यकतायें पूरी करने योग्य होने में अभी १५ वर्ष और लगव। तब तक विदेशी सहायता से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। चौथी योजना में २५१४ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की आवश्यकता आती गई है और उसे प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत विदेशों सह यता पर कितना अधिक निर्भर है, यह इस बात से प्रकट हो जाता है कि विदेशी मुद्रा के अभाव में कच्चा माल और पुर्जों का आयात न होने के कारण बहुत से कारखाने अपनी पूरी उपादन क्षमता का उपयोग नहीं कर पाये। विदेशों से जो सहायता हमें मिलती है, उसका अधिकतर भ्रष्ट परिपोजनाओं में बँटा होता है। लेकिन हमारे सामने ऐसी सहायता की भी समस्या है, जो किसी परिपालना में बँटी न हो और जिससे हम अपने उद्योगों को चालू रखने के लिए विदेशों से कच्चा माल और पुर्जें मंगा सकें। सन्देह नहीं, कि तीसरी योजना में भारत की आर्थिक वृद्धि की गति कृषि और औद्योगिक, दोनों क्षेत्रों में मन्द हुई है। इसलिए विश्व बैंक और भारत को सहायता देने वाले पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि वे भारत को जो सहायता देते हैं उसका उचित उपयोग हो और उससे देश की आर्थिक वृद्धि अधिक तेजी से हो सके।

वास्तव में जो देश सहायता देता है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसे सिर्फ अपने ऋण की वापसी और व्याज पर ही नजर रखनी चाहिए, उसकी ही हुई सहायता का उपयोग कैसा होता है, इससे उसका कोई वास्ता नहीं। कारण, ये देश भी अपनी जनता से इकट्ठा किया हुआ धन ही सहायता में देते हैं।

उपसंहार—

पिछले कुछ समय से सहायता देने वाले देशों की प्रवृत्ति सहायता देने के विरुद्ध हो रही है। स्वयं अमरीका की विदेशी सहायता जहाँ १५ वर्ष पूर्व अपने राष्ट्रीय उत्पादन का २ प्रतिशत थी, वहाँ अब यह आधा प्रतिशत रह गई है जिसको और एक सेनेटर ने ध्यान भी सोचा था। यह स्थिति तब है, जबकि अमरीका को समूचे इन १५ वर्षों में बहुत अधिक बड गट है।

ब्रिटेन की इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्तामिब अफैयर्स ने दू. व्यूज आन ऐंड दू डेवर्पिंग प्रम्टीज नाम से एक पुस्तक हान में ही प्रकाशित की है जिसमें ब्रिटिश अर्थशास्त्री पी० टी० बावर ने दस मत का प्रतिपादन किया है कि अल्पविकसित देशों

को विकास के लिए विदेशी सहायता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इन देशों में उस सहायता का उपयोग करके अपना विकास करने के लिए आधारभूत परिस्थितियों का अभाव होता है। लेसक ने लिखा है—“विदेशी सहायता अविकसित देशों के भौतिक दृष्टि से पिछड़ेपन के मुख्य कारणों पर प्रभाव नहीं डालती। इसीलिए विदेशी सहायता पाने वाले देशों की गरीबी का निरन्तर जारी रहना जरा भी आश्चर्यजनक नहीं है।”

श्री बाबर ने भारत का उदाहरण भी दिया है और कहा है कि—“सहायता पाने वाले देश, जैसे भारत, आम तौर पर अपनी सुरक्षित निधि नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि ऐसा करने में उनकी सफलता उनकी विदेशी सहायता की माँग के विरुद्ध तर्क बन जाएगी।” लेसक ने जापान, मलयेशिया और हांगकांग का उदाहरण देकर कहा है कि जब वे विदेशी सहायता के बिना उन्नति कर सके हैं तब अन्य देश क्यों नहीं कर सकते।

यद्यपि लेसक के ये सब कथन सही और तर्क संगत नहीं हैं तो भी वे ग्रन्थ समाप्ति के परिचायक जल्द ही जो पवित्र देशों में विदेशी सहायता के विरुद्ध बनती जा रही है।

इसलिए यह जरूरी है कि यदि सहायता देने वाले देश भारत के राष्ट्रीय आत्म सम्मान को चोट पहुँचाए बिना देश के विकास की गति को तेज करने और सहायता में प्राप्त धन के सदुपयोग के लिए कुछ सुझाव देने हैं तो उन्हें सद्भावना से ग्रहण करना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए और किसी भी प्रकार की राजनीतिक शर्तों को स्वीकार किए बिना विद्युत् आर्थिक दृष्टि से परेश कर स्वीकरणीय सुझावों को स्वीकार कर लेना गलत नहीं होगा।

परीक्षा प्रश्न :

१. भारत के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी की भूमिका पर प्रकाश डालिये।
२. भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति का विश्लेषण करिये।
३. चौथी योजना की आवश्यकताओं को ध्वनित करने अधिक मात्रा में विदेशी पूँजी की प्राप्ति कहीं तक और कैसे सम्भव है ?

छठा खण्ड

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग

[INTERNATIONAL ECONOMIC AND
MONETARY COOPERATION]

अल्प-विकसित देशों की समस्याएँ

(Problems of Economic Development in Under developed Countries)

प्रारम्भिक—

मानव के इतिहास में दूसरा महायुद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस अवधि में कई साम्राज्य धराशायी हुए। उपनिवेशवाद का आत्मा और नव-स्वतन्त्र राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। यदि हम सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि एशिया और यूरोप के लोगों के जीवन-स्तर में विशेष अंतर नहीं था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद स्थिति पिछले डेढ़-सौ वर्षों में पूर्णतया बदल गई है। उपनिवेशवाद के युग में अपनाए गये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के सिद्धान्त ने अनेक उपनिवेशों को कृषि पदार्थों के उत्पादक मात्र का स्थिति में लाकर छोड़ दिया है। किन्तु साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने महा माना प्रकार के बहुत उद्योग स्थापित कर लिये। १९५० से आरम्भ होने वाले दशक तक एक ओर तो उपनिवेशवाद को बल मिलता रहा और दूसरी ओर साम्राज्यवादी देशों में उद्योग बढ़ते गए।

विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग

विभिन्न उपनिवेशों में हो रही औद्योगिक क्रांति को साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा निरस्ताहित किया गया लेकिन दासता के वधने में जकड़े हुए देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्रगति को ज्यादा नहीं रोका जा सका। कुछ क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को मन्त्रिय रूप में प्रोत्साहन मिलता रहा। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में इन देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग महामारी और झूत से फँसने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए किया गया और उच्चतम स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध की गईं। इस चीज से मृत्यु दर कम होने और जन्म दर बढ़ने रहने के कारण जनसंख्या की वृद्धि में योगदान मिला। इससे पहले इन देशों की जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ जन्म-दर के मुकाबले में मृत्यु-दर ज्यादा थी। लेकिन स्वतन्त्र हो जाने पर इन देशों की लोकप्रिय राष्ट्रीय सरकारों ने चिकित्सा सुविधाएँ और स्वास्थ्य-सेवाएँ ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करने का भर-मक प्रयत्न किया और इसके फलस्वरूप इन देशों में मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन-

जन्म-दर में कोई कमी नहीं हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि इन देशों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई।

जनसंख्या और आर्थिक साधनों के बीच परस्पर विरोध

इस प्रकार उन्नत देशों में तो वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति हुई किन्तु कम उन्नत देशों में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और अतः विस्फोट। हानि में लगाय गये अनुदान के अनुसार जबकि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय का औसत १२६ डॉलर है। समूचे विश्व के ६६% लोग गरीब देशों में बसे हुए हैं। उनकी कुल आय विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पादन की १६% है। विश्व के लगभग ४० देशों में, जिनमें विश्व की कुल अबासी के ३१% लोग रहते हैं, कुल विद्युत आय के ४०% का जमाव है तथा इनका विश्व के कुल इस्पात-उत्पादन में योग ६३%, कच्चे सोह्य में ८४% और विद्युत-शक्ति में ७४% योग है। एक और भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि इन चालीस देशों में वैज्ञानिक अनुसंधान की क्षमता ८५% है।

यदि राष्ट्रीय आय में लगाने के लिए वर्ष ५ से ६% तक वृद्धि-होती रहे तो कम उन्नत देशों की यूरोपीय देशों के वर्तमान जीवन-स्तर तक पहुँचने में ८० वर्ष और अमेरिका के वर्तमान-जीवन स्तर तक पहुँचने में १२० वर्ष लगेंगे। इस अर्थ में उन्नत-देशों का विकास अवरोध नहीं रहेगा। सामग्री में अनुसंधान की क्षमता ८५% होने के कारण उन्नत देश इस अवधि में और भी ज्यादा तरक्की कर लेंगे और इस प्रकार गरीब और अमीर देशों के बीच खाई चौड़ी होती जायेगी। राष्ट्रीय आय और प्रति-व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि की बात करते समय अक्सर एक बात हम भूल जाते हैं कि कम उन्नत देशों में प्रति व्यक्ति आय केवल १०० डॉलर है जब कि उन्नत देशों में प्रति व्यक्ति आय १,५०० डॉलर। अतः उन्नत देशों में इस वृद्धि का प्रतिफल यदि कम रहे तो भी कुल वृद्धि का आधार बहुत ज्यादा होता है। यहाँ आर्थिक साधनों के वितरण और जनसंख्या के वितरण में आधार-भूत विरोधाभास है, जिसका अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव गंभीर विना नहीं रह सकता। इस प्रकार विकासशील देशों के आर्थिक विकास की कोई अलग समस्या नहीं है, बल्कि दो महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं—मानव संसाधन का विकास और समाज में समानता का विकास। समाज के विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, “मानव जाति की गरीबी और अमीरी के आधार पर बढ़ना इतना ही सरल और खतरनाक है जितना कि किसी एक देश में ही इस प्रकार का असन्तुलन होना।”

भूख और भूखमरी की समस्या

विश्व के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती कम उन्नत देशों में व्याप्त भूखमरी और भूख की समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में सम्पन्न और निम्न देशों के साधन-उत्पादन का अन्तर बढ़ता रहा है। आज से तीस वर्ष पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्षेत्र अन्न निर्मात बरते थे। किन्तु १९५० से आरम्भ होने वाले

दशक में कम उन्नत देशों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे इन देशों में खानापान का अभाव होने लगा। १९६० में २ करोड़ टन अन्न वहाँ आयात होता था जो १९६६ में ३ करोड़ १० लाख टन होने लगा।

अल्प-विकसित देशों के अधिकांश व्यक्ति पोषक तत्वों से रहित भोजन पाने हैं। हाल के अध्ययन में कम उन्नत देशों में पोषक तत्वों की कमी के दुष्परिणामों का और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का विवेचन किया गया है तथा निम्न निष्कर्ष निकाले गये हैं — (i) पोषक तत्वों की कमी के कारण मनुष्य की औसत आयु सीमित रह जाती है और फलस्वरूप उसके जीवन में उत्पादन में योग देने के वर्षों की संख्या भी सीमित रह जाती है। (ii) पोषक तत्वों की कमी से काम करने वालों की उत्पादकता कम होती है। (iii) रोग का मुकाबला करने में मजदूर की शक्ति कम रह जाती है और वह अपने काम से ज्यादा गैर-हाजिर रहता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं का शिकार भी ऐसे लोग ज्यादा होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं। (iv) पोषक तत्व (जैसे-विटामिन ए, बी) की कमी के कारण खोम अंधे हो जाते हैं जिसका उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। कम पोषक तत्व प्राप्त-बच्चों का शालाकाल सं हो पूर्णतया बौद्धिक विनाश नहीं हो पाता।

अतः राष्ट्रीय विनाश के सिद्धान्तों में एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, जो यह कि इन देशों में पोषक तत्वों की कमी के कारण शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से कम उन्नत व्यक्तियों की वृद्धि हो रही है। डाक्टर सी० गोपासन (निर्देशक पोषक-सत्त्व अनुसंधान संस्था) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के देशांतरों में स्कूल जाने की उम्र से कम के बालक, पोषक तत्व में मिलने के कारण बीने रह जाते हैं। प्रोफेसर रैलबोथ ने भूल की समस्या का उत्तम निम्न वाक्यों में किया है "बैसांतिक स्वच्छता की रक्षा और आध्यात्मिक मुक्ति के लक्ष्य की प्राप्ति भी भरे पेट ही हो सकती है।"

लगभग दो या ज्यादा दशकों से माध्यम वा सिद्धान्त यहाँ लागू होता बिताई दे रहा है। एशिया के अधिकांश देशों में जन्म-दर ज्यादा और मृत्यु-दर कम होती जा रही है। प्राथमिक विकास के इस परिणाम का मुकाबला करने के लिए निम्न राष्ट्रों ने जनसंख्या-वृद्धि पर नियन्त्रण रखने हेतु अनेक उपाय किये हैं। भारत विज्ञान के नये तकनीकों को अपनाने में भी पीछे नहीं रहा। दरअसल विकासशील राष्ट्रों ने इस संघ में विकसित उन्नत उपायों को अपनाने में अद्भुत सांस्कृतिक क्षमता का परिचय दिया है। यह ठीक है कि जन्म-दर पर नियन्त्रण रखने के नए तकनीकों का प्रचार करने में अनेक समस्याएँ हैं जिनके मूल में वैज्ञानिक और तकनीकी कारण भी हैं। गंभीरता का निम्न स्तर भी एक भारी आवंट है जिन पर संचार के समुचित माध्यमों द्वारा काबू पाना है। परिवार नियोजन के नये तकनीकों का प्रचार करने के लिए टेलीविजन के उपयोग की बात कही गई है और सम्मोद है कि इन नये तकनीकों को जल्द जन-सम्पर्क के वृत्त कार्य-क्रम द्वारा जनता तक पहुँचाया जा सकेगा। फिर

भी इस क्षेत्र की समस्या का कोई सौघ्र समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमें निवृत्त भविष्य में जनसंख्या-वृद्धि को बिलकुल रोक देने की कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए।

जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रहेगी इस तथ्य ने जीवित रहने की समस्या पर विशेष रूप से विचार करने का महत्व बढ़ा दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों को ने इस प्रश्न को लेकर घोर निराशा व्यक्त की है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि की धीमी गति को देखकर चिन्ता होने लगी है। लेकिन सम्पूर्ण चित्र यह नहीं है। आज हमारे सभी विज्ञान वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और विधायक इस बारे में एक मत हैं कि कृषि को राष्ट्रीय या राष्ट्रीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि हम, कृषि को उन्नत बनाने की दिशा में जो रुकावटें आ रही हैं, उन पर सौघ्र कार्रवाई करेंगे।

बेरोजगारी का बढ़ता हुआ भार

विकास की विधि पर जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। कई विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक अध्ययनशी ने कहा है कि एक घनी आबादी वाले देश में, जो कि प्राचीन पद्धति के अनुसार संहति है, विकास अपने आप में बेरोजगारी का कारण बन जाता है। विकास का एक परिणाम यह है कि आज अनेक व्यक्ति, जो प्राचीन समाज में किसी न किसी प्रकार काम पर लगे हुए थे, बेरोजगार के सिक्के बन चुके हैं। हम इतिहास की घटनाओं की उल्टी नहीं कर सकते। बेरोजगार व्यक्ति देश के भारी अमनीय का कारण बन जाता है। अब विकास की चार्ज भी विधि उसके लिए गणित सम्बन्धी सन्तुलन तक सीमित नहीं रह सकती। आयोजकी की तकनीकों की समस्या को हल करना होगा, ताकि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि न हो। बुद्धिमत्ता का तर्काज है कि अब भविष्य में रोजगार दिलाने के मुकामले में गुरुत्व रोजगार दिलाने के प्रश्न को प्राथमिकता दी जाय। यदि इस प्रकार का सन्ध रखा जाय तो पूँजी-विनिर्माण और मुद्रा-बाह्य की समस्या सामन आती है। यह समस्या तब और भी उग्र रूप धारण कर लेती है जब हम मशीनों के स्थान पर अनुष्णों की काम में लगे हैं। इस सन्दर्भ में कृषि और खाद्य उत्पादन तथा वितरण का महत्त्व और भी स्पष्ट हो जाता है। किन्तु यह निष्कर्ष निकालना गतत हाया कि अल्प-निकसित देशों को पहले अपने यहाँ कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाना चाहिए और उसके बाद औद्योगीकरण करना चाहिए। आधुनिक कृषि के लिए आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता होती है और हम उद्योगों को उन्नत बनाने बिना कृषि को भी उन्नत नहीं बना सकते। हम आज आधुनिक विध में रह रहे हैं और हम कई देशों के काम को कुछ दिनों में ही पूरा करना होगा।

कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन पिछड़े हुए देश कई टेक्नोलीजी कभी भी नहीं अपना सकते और वहाँ लक्ष्य प्राप्त करने की भावना काम नहीं करती। अतः कम उन्नत देश जहाँ हैं, वहाँ ही बन रहेंगे। लेकिन इस निराशावादी धारणा के

स्वायत्त पूर्व में दो क्षत्तिशाली क्षत्तियों का विकास हुआ है—जापान और चीन। प्राचीन देशों में आधुनिकीकरण का जो अनुभव प्राप्त है, उससे हम यह कह सकते हैं कि सत्रास्रि साल शायद सबसे मुक्तिल समय होता है। अतः वर्ष और दृढ निश्चय के साथ कार्य करना होना। चाहे उद्योग हो या कृषि, औद्योगिकीकरण का आशय केवल टेक्नोलॉजी या कार्य-कुशलता का कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफर मात्र नहीं है। टेक्नोलॉजी को व्यापक रूप में फैलाने की आवश्यकता कला होती है।

विकासशील देश और सिद्धान्त

नये विकासशील देश जो प्राचीन परम्पराओं और रीति-रिवाजों के अन्तर्गत विकसित हुए हो ऐसा नहीं है, बल्कि उन्नत देशों को भी प्राचीन धार्मिक भावनाएँ विरासत में मिली थीं। अतः इस आधार पर विश्व को पुराने और नये विश्व में बांटना कहीं तक उचित है, जबकि उन्नत देश भी हमने दरअसल मुक्त नहीं हैं। कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में अयोग्यता ज्यादा पाई जाती है जिस कारण निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निश्चय ही, तर्क यह नहीं है कि निजी क्षेत्र में क्षमता का अभाव है और सरकारी क्षेत्र को सर्वत्र प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, वरन् सपर्यं केवल उन दो तरह के संगठनों के बीच है एक वे जो मूल्य हैं और दूसरे वे जो सक्षम नहीं हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हों या निजी क्षेत्र के। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की प्रबन्ध-व्यवस्था में अक्षमता का कारण उनका वर्तमान ढांचा है। दूसरी ओर, ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ निजी क्षेत्र के उद्योगी नहीं हैं, अतः इनमें सरकारी हस्तक्षेप के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय काम में नहीं लाया जा सकता। हमारा लक्ष्य सही ढंग के प्रबन्ध को आगे बढ़ाना और सुप्रबन्ध उपलब्ध करना होना चाहिए। दरअसल, इटली, जर्मनी और हालैंड आदि देशों के औद्योगिक प्रबन्ध में जो उपाय काम में लाये गये उनकी सीख की जानी चाहिए और इन उन्नत देशों में भी ठीक-उपयोग होना चाहिए। कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्त्व ऊँचे स्तर की टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, बल्कि ऊँचे स्तर के संगठन के कारण है। अतः सरकारी क्षेत्र के उद्योग में ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी वही संगठन पद्धति काम में लानी चाहिए। कम उन्नत देश प्रायः उत्पादन के नये तकनीक उपकरण सेने को तत्पर रहते हैं, प्रबन्ध के तकनीक नहीं।

आर्थिक प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण

अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध में भी अनेक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। अन्य विकसित देशों में उन्नत देशों की अपेक्षा सरकार के अधिक हस्तक्षेप और नियन्त्रण की आवश्यकता है। प्रायः विवाद किया जाता है कि अर्थ विकास की स्थिति में सरकार को कम हस्तक्षेप करना चाहिए या ज्यादा। हमारा मत है कि सरकार द्वारा पूरी तरह नियन्त्रण रखना और अपने आदेश के अनुसार साधनों को बांटना उचित नहीं है। लेकिन यह भी ठीक है कि केवल कीमत नियन्त्रण या बाजार शक्तियों के द्वारा साधनों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटना भी सम्भव नहीं है। जब अर्थव्यवस्था

पूर्णतया स्वतन्त्र हो और विदेशी मुद्रा की कोई रक्षावट न हो, तब बाजार-व्यवस्था के द्वारा साधनों का समुचित वटन हो सक्ता है। लेकिन यह यतं वठिन है। अतः बुद्धिमत्ता इसी से है कि हम कन्द्रीय-व्यवस्था को पूर्णतया सम्म न करें बल्कि उसका उपयोग बाजार की नीमतें स्पष्ट करने ॥ करें।

आर्थिक प्रचलन में कन्द्रीय के कुछ ऐसे तत्त्वों का उपयोग आवश्यक है जो अभी बड़े-बड़े नियमों और उन्नत देशों की सरकारों द्वारा काम में लाये जाते हैं। ये तरीके अल्प विकसित देशों की सरकारों द्वारा कन्द्रीय आदि की समस्याओं के समाधान में काम में लाये जा सकते हैं।

यह अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के विदेशी व्यापार विदेशी सहायता और विकास को सुसम्बद्ध बनाने की आवश्यकता पर खर दिया है। विश्व का कोई भी देश अकेला समृद्ध नहीं रह सकता। औद्योगिक ज्ञानि में भी विश्व को यही पाठ मिला। इसमें आश्चर्य्य यूरोप के देशों के लिए पहली बार बाजार खुला और जन-सत्ता की शक्त-शक्ति भी बढ़ी। विश्व के निर्जन देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विदेशी सहायता का सहारा लिया जाता है। विदेशी-सहायता साधनों का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करने का एक अस्थायी उपाय है और अन्तर्गत-व्यवस्था में वृद्धि होती है और विश्व के आर्थिक विकास को भी बल मिलता है। सरक्षित व्यापार का अर्थशास्त्र अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे अन्तर्गत-व्यवस्था अभीर और गरीब दोनों देशों को नुकसान होता है।

उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों की चरित्र है कि ऐसा वातावरण तैयार करने के लिये-तरीके निकालें, जिससे विकासशील देशों की व्यापार सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र हल हो सके। ग्रेट ब्रिटन २० वर्षों की अवधि में विश्व व्यापार को उदार बनाने के लिये उचित वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण योग दिया है। १९५३ में ७८ अरब डॉलर का विश्व व्यापार हुआ था। जो १९७० में बढ़कर ३०० अरब डॉलर के लगभग हो गया है। इस प्रगति के बावजूद विकासशील देशों के हित को अनेक व्यापारिक समन्वयों का अब तक हल नहीं हो पाया है। इस अवधि में तैयार माल का विश्व व्यापार २४० प्रतिशत बढ़ा है जबकि विकासशील देशों को लाभ पहुँचाने वाले प्रारम्भिक उपायों का व्यापार केवल ८६ प्रतिशत बढ़ा है।

विकासशील देशों के औद्योगिक विकास में दो कठिनाइयाँ मुख्य हैं प्रथमतः, पूँजी की कमी और दूसरे, शक्ति की कमी। इन कठिनाइयों को हल करने के लिए विकासशील देशों के मध्य एकता बहुत जरूरी है। केन्द्रीय मन्त्री श्री दिनेशसिंह ने कहा था कि अब तक विकासशील देशों में केवल व्यापार के आधार पर सहयोग होता था। किन्तु व्यापार का क्षेत्र सीमित है और उसमें प्रतियोगिता की भी गुंजाइश है। सोभाव्यतः औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग की सम्भावना से अब इन देशों के बीच सहयोग का क्षेत्र काफी बड़ा गया है। समुक्त उद्योगों की स्थापना से सभी देशों को लाभ होगा। इन ८९ में यह काम विशेष महत्वपूर्ण है। भारत, समुक्त अरब गणराज्य और

यूगोस्लाविया को इसमें जितनी सफलता मिलेगी विश्व के अन्य विकासशील देश उससे ज़रूर ही प्रेरणा लेंगे। यदि विकासशील देशों के साधन इकट्ठे किये जाएँ तो विकास की सम्भावनाएँ काफी बढ़ जायेंगी। आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग से माँग और उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों का विकास होगा और अतिरिक्त क्षमता का उपयोग होगा। चापसी सहयोग से बड़े उद्योगों और रसायन उद्योग समूहों की स्थापना हो सकेगी और कम लागत पर भारी मशीनों का उत्पादन हो सकेगा।

श्री दिनेशसिंह ने विकासशील देशों की मदद के लिये विकसित देशों के सामने एक चार-सूत्री योजना रखी थी, जो निम्न प्रकार है — (i) विकसित देशों को प्रति वर्ष अपने राष्ट्रीय उत्पादन के १ प्रतिशत के बराबर पूँजीगत साधन विकासमान देशों को स्थानान्तरित करना चाहिये। (ii) इनके प्राकृतिक साधनों के विकास में मदद देनी चाहिए। (iii) विकासमान देशों को विकसित देशों के कच्चे मालों की बिक्री के लिए सुविधाएँ मिलनी चाहिए। (iv) विकासमान देशों से जो तैयार अथवा अर्द्ध-तैयार माल विकसित देशों में जाये उन पर कोई शुल्क नहीं लगाना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

१. विकासोन्मुख देशों की प्रमुख समस्याएँ क्या हैं? इनके समाधान के लिये सुझाव दीजिये।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

(International Economic Cooperation)

परिचय —

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का आशय राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों के परस्पर निर्भर होने में है। ऐसा सत्योग आन्तरिक नीति (domestic policy) का विकल्प (alternative) न होकर वास्तव में कई प्रकार से इसका पूरक (complementary) है। अन्तर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक दूसरे में सहयोग करने का आग्रह यह नहीं है कि राष्ट्र अपने घरेलू मोर्चे पर उपयुक्त आर्थिक नीति नहीं अपना सकेंगे। तब तो यह है कि आन्तरिक एवं बाह्य स्थायित्व के लिए दोनों मोर्चों पर एक समन्वित नीति अपनानी चाहिए। आजकल भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग निम्न कारणों से बहुत आवश्यक हो गया है —

- (i) अनेक अर्ध-विकसित देशों ने अपने विकास के निम्ने विशाल आर्थिक कार्यक्रम बनाये हैं जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें विशाल पूँजी विनियोगों की आवश्यकता है। इतने बड़े पैमाने पर पूँजी केवल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि स्वयं अर्ध-विकसित देशों में आय व जीवन-स्तर नीचा होने के फलस्वरूप वहाँ दक्ष और पूँजी के निर्माण की दर बहुत नीची है। (ii) जहाँ एक ओर अविकसित देशों को भारी मात्रा में पूँजीगत वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, वहाँ दूसरी ओर उनकी उत्पादन-शक्ति कम है, जिससे कि वे अधिक मात्रा में निर्यात नहीं कर पाते हैं। फलतः उनके भुगतान सन्तुलन में निरन्तर घाटा रहता है तथा वे विदेशी विनियम का अभाव अनुभव करते हैं। यह अभाव अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही स्थानाधिक सीमा तक दूर हो सकता है। (iii) विकास कार्यक्रमों के सुमचालन के लिये टेक्निकल कर्सेचरियों की आवश्यकता पड़ती है, जोकि अविकसित देशों में नगण्य है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अविकसित देशों को भी उन्नत देशों के वैज्ञानिक एवं टेक्निकल ज्ञान का लाभ भोग सकता है। (iv) विश्व युद्ध ने लड़ाकू देशों की जन-व्यवस्थाएँ ध्वस्त कर दी थीं। उनके पुनर्निर्माण व पुनर्वसन के लिए भी अन्तर्रा-

प्रांतीय सहयोग आवश्यक हो गया था, (v) स्थायी विश्व शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य आर्थिक अन्तरों को कम किया जाय। इसके लिए भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रयत्न

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व स्वर्णमान के दिनों में, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य कुछ न कुछ सोमा तक सहयोग एवम् समन्वय रहता था। फिर भी, उन दिनों विश्व में लोगों के विचारों पर 'राष्ट्रीयता' की ही छाया थी। सन् १९३१ में स्वर्णमान टूट गया और उसके साथ ही राष्ट्रीयता का युग भी समाप्त हो गया। तत्पश्चात् यू० के., मयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जास में एक त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement) हुआ, जिसका उद्देश्य हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की करंसियों में स्थायित्व लाना था। कॉमनवेल्थ प्रिफरेंस क्षेत्र के विषय में ओटावा समझौता (Ottawa Agreement) क्षेत्रिक सहकारिता (regional cooperation) की दिशा में एक अन्य कदम भी मिला जो कि १९४०-४० के मध्य उठाया गया। यद्यपि ये प्रारम्भिक कदम उपयोगी थे तथापि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोगों की वास्तविक धारणा पिछले कुछ वर्षों में ही विकसित हुई है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीचड़, विश्व बैंक समुक्त राष्ट्र और अन्य आर्थिक एजेंसियाँ, मार्शल सहायता कार्यक्रम, ओ० ई० ई० सी० और यूरोपियन साक्षात् बाजार पेरिस क्लब आदि स्थापित हुये।

अमेरिकन ऋण कार्यक्रम एवं यूरोपियन पुनर्जीवन योजना

(The American Loan Programme & European Recovery Plan)

ब्रिटेन एवम् यूरोपियन देशों की युद्ध-जर्जरित अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए इन्हें भारी मात्रा में पूँजीगत सामानों, कच्चे मालों एवं खाद्यान्न की आवश्यकता थी, जो उन्हें अमेरिका ही दे सकता था। किन्तु इतनी की जल्दता के कारण ये देश अमेरिका से क़य करने में असमर्थ थे। फलतः अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों के मध्य ऋण समझौते हुए। इन समझौतों के अन्तर्गत विपन्न देश अमेरिका में निर्धारित की गई सीमा तक उपहार ले सकते थे।

किन्तु ये समझौते भी विपन्न देशों की आवश्यकता को पूरा न कर सके। उन्हें और अधिक सहायता की आवश्यकता थी। अतः १९४७ में अमेरिका के स्टेट सिक्रेटरी जार्ज मार्शल ने यूरोपीय देशों को आर्थिक पुनर्गठन के लिए अधिक सहायता का वचन दिया। किन्तु इसके लिए यह शर्त रखी गई कि वे आपस में भी सहयोग करें। अप्रैल १९४८ में यूरोपियन पुनर्वासि सम्न्वयी कार्यक्रम का कानून बनाया गया, जिसमें यूरोपीय देशों की बहुत राहत मिली।

यूरोपियन आर्थिक सहयोग सङ्गठन

(The Organisation for European Economic Cooperation)

इसी समय पश्चिमी यूरोपीय सरकारों ने भी परस्पर आर्थिक सहयोग की दिशा में कदम उठाये। अठारह यूरोपीय देशों ने एक 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग

सङ्गठन' (O E E C) स्थापित किया, जिसका मुख्य कार्यालय पेरिस बनाया गया। इस सङ्गठन का मुख्य कार्य वाणिज्यिक नियत आर्थिक सहयोग प्रदान करना (Economic Cooperation Administration or E.C. A) को अमेरिकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत में सहायता देना था। यह सहायता पाने वाले देशों का होने वाले नामों की सूची बन-रिपोर्ट भी प्रकाशित करता था। आधा भी यह कि उपरोक्त सङ्गठन (O E E C) यूरोपियन सहयोग का एक स्थाई केन्द्र बन जाएगा। निम्नलिखित सङ्गठन राश्र्य वृद्ध हो जानदार रहा। इसके ही प्रयासों द्वारा ५० यूरोप की युद्ध जर्मन अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यकजनक उत्पत्ति करली, सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग बढ़ा एवं इनमें वित्तीय एवं आर्थिक स्थिरता आई। व्यापार एवं बुगतान सम्बन्धी व्यवस्थाओं को उदार बनाने और करों-सिद्धों को बहुपक्षीय परिवर्तनशीलता स्थापित करने में भी OEEC, ने महत्वपूर्ण योग दिया।

आर्थिक सहयोग एवं विकास सङ्गठन

(The Organisation for Economic Coop. & Development)

यूरोपीय आर्थिक सहयोग सङ्गठन, जो कि एक क्षेत्रीय सङ्गठन था, अब एक अधिक व्यापक सङ्गठन में, जिसे 'आर्थिक सहयोग एवं विकास सङ्गठन' (OECD) कहते हैं, परिणत हो गया है। इनमें यूरोपीय देशों के अतिरिक्त अमेरिका और कनाडा भी पूर्ण सदस्य बन गये हैं। OECD की 'विकास सहायता समिती' (Development Assistance Committee, DAC) अर्थ विकसित देशों के लिए सहायता देने की सम्भावनाओं खोजती है। इस समिती में पूँजी देने वाले निम्न दस राष्ट्र सम्मिलित हैं—अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इटली, जपान नीदरलैंड और पुर्तगाल। यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) का सम्मेलन भी इसमें सम्मिलित है।

विकासोन्मुख देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इनके सभी निमित्त एवं अर्द्ध-निमित्त वस्तुओं के आयातों पर २१ मुख्य परिचयी औद्योगिक राष्ट्रों (OECD) ने रियायतें देने की एक योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार सभी औद्योगिक देशों में विकासोन्मुख देशों के निर्यातों को समान अवसर दिये जायेंगे। कृषि उत्पादों और फौज फौज वृद्ध तथा EEC और इसके अकीकी साभेदारों के मध्य कस्टम-रियायतें पहले से ही प्रभावशील हैं, इसलिये OECD के सामने एक मुख्य कार्य इन रियायतों में समानता लाना है। ये रियायतें १० वर्ष के लिए होगी। कुछ वस्तुओं पर कस्टम क्यूटीन बिल्कुल हटाई जा सकती है।¹

यूरोपियन भुगतान सङ्घ

(European Payments Union)

स्वतंत्रता के खण्डन के बाद (विशेषतः द्वितीय महायुद्ध काल में) अन्तर्राष्ट्रीय

¹ *Economic Times* 7. 12. 1967.

भौतिक प्रणाली एवं भुगतानों की सङ्गठित व्यवस्था टूट गई, जिससे देशों को विदेशी श्रोतों से अत्यावश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। अतः यूरोपीय देशों को द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने पड़े, जिनके अनुसार व्यापार सन्तुलित स्तर पर रिया जाने लगा। किन्तु इनसे भी कठिनाई हल न हुई, क्योंकि कुछ देशों के पास अधिक माँग वाली निर्यात वस्तुओं का अभाव था, जिससे वे विदेशों से अपनी ग्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए यूरोपीय देश बहुपक्षीय भुगतान व्यवस्था पर सौटने के लिए बहुत उत्सुक थे, ताकि वह अपनी आवश्यक वस्तुएँ कहीं न भी प्राप्त कर सकें।

इस दिशा में यूरोपीय आर्थिक सङ्गठन ने पहले कदम के रूप में एक उदार नीति अपनाई जिसके अन्तर्गत यूरोपीय देशों के पारस्परिक व्यापार पर लग हुए प्रतिबन्ध हटाने हटाने समाप्त किये जाने थे। दूसरा कदम यह था कि भुगतानों की पूरापूर्यापी व्यवस्था करने के लिए एक यूरोपीय भुगतान सङ्घ (E P U) की स्थापना की गई।

यूरोपीय भुगतान सङ्घ की कार्यप्रणाली इस प्रकार थी — (i) सभी सदस्य देश उसे हर महीने यह सूचना दिया करते थे कि किस किस देश के साथ उनका क्या मुद्रा बाँट साता लेप है। इन सूचनाओं के आधार पर EPU के अधिपारी प्रत्येक देश के सामूहिक लेन (या देन) बात पर लेते थे। (ii) किन्तु इनके निबटारे की जिम्मेदारी EPU पर होती थी। उदाहरण के लिये, यदि A को किसी महीने में B, C और D के साथ क्रमशः १०, २० और ३० मि० डालर का बाधियम लेप है, और लेप देशों के साथ १० मि० का बाँटा, तो उसे यूनिफन से ५० मि० डालर लेते रहे। इस प्रकार, द्विपक्षीय सन्तुलन के बजाय यूनिफन के प्रति देश के सन्तुलन का महत्त्व हो गया और, ऋणता की सामूहिक यणना के कान्स्वरूप, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था प्रचलित हो गई। (iii) निबटारे की सुविधा के लिए यूनिफन ने एक माप प्रणाली बनाई, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य ने, जिसका यूनिफन पर लपटा निकले, यूनिफन को अपने मोटे के २०% तक साँझ देने का बचन दिया। यदि लेनदार सदस्य का बाधियम इस प्रतिष्ठत में अधिक है, तो लेन आधिनय के ५०% भाग का भुगतान स्वर्ण या डालर में किया जायेगा और ५०% भाग यूनिफन पर साँझ के रूप में छोड़ दिया जायेगा। इसके विपरीत, यदि वाले देश को EPU इसके कौंट के २०% तक साँझ दिया करती थी। २०% से अधिक किन्तु १००% से कम पाटे के लिए कुछ तो स्वर्ण या डालरों में भुगतान किया जाता था और लेप के लिए अनिश्चित राश्व स्वीकृत की जाती थी। १००% से अधिक के पाटे पूर्णतः रखें या डालर में ही चुकाने पड़ते थे।

इस व्यवस्था के कारण वह सदस्य-देश भी, जिनके स्वर्ण एवं डालर कोष खपताते थे, आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने में समर्थ हो गए। वस्तुयें यूनिफन के किसी

भी सदस्य देश से खरीदी जा सकती थी। कारण, अब द्विपक्षीय भुगतान के बजाय बहु-मुखी व्यवस्था चालू हो गई थी, यूनिवन-क्षेत्र में व्यापार अधिक स्वतन्त्रतापूर्ण हो गया था, करंटियों एवं दूसरे म पूंजी परिवहनकोल हाँ गई एवं विनिमय नियन्त्रण समाप्त हो गया थे। चूँकि लेनदार देश EPU को साक्ष देने के लिये बाध्य थे, इसलिये उन्हें यह प्रेरणा रहती थी कि वे अपना आधिक्य देश अन्य सदस्य देशों से अधिक आयात करने की चुकटा कर लें। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो गई।

यूरोपियन मॉनेटरी समझौता (European Monetary Agreement)

बीरे-बीरे यूरोपीय करंटियों की परिवर्तनशीलता पुनः स्थापित हो गई और व्यापारिक सौद विदेशी विनिमय बाजारों के जरिये चिज जाने लगे। चूँकि EPU का उद्देश्य पूरा हो चुका था, इसलिये सन् १९५६ में इसे समाप्त कर दिया गया और एक नया समझौता लागू किया गया जोकि यूरोपियन मॉनेटरी समझौता (E M A) के नाम से विख्यात है।

EMA का उद्देश्य कठिनाइयाँ उत्पन्न होने पर सदस्य देशों की सहायता करना है। इस समझौते के अनुसार एक 'यूरोपियन फण्ड' ६०० मिलियन डॉलर की पूँजी में स्थापित किया गया है, जिसमें से भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयों के निवारण के लिए मददगारों को २ वर्षीय साक्ष दी जाती है। EPU की भाँति EMA भी बहुमुखी भुगतान प्रणाली स्थापित करता है, जिसको निम्न दो निम्नतमक विशेषतायें हैं—(अ) इसमें सभी लेन-देन पूर्णतः स्वस्थ व डालर में चुकाये जाते हैं, और (ब) निबधारे अधिकृत (नम एवं विकस्य) दसों पर किये जाते हैं, अमेरिकी डॉलर से समता दर पर नहीं। यह उल्लेखनीय है कि EMA को विधा का प्रयोग तब ही किया जा सकता है जबकि विदेशी विनिमय बाजारों के द्वारा इन की व्यवस्था टूट जाय।

स्टर्लिंग क्षेत्र प्रणाली (Sterling Area System)

बहुमुखी व्यवस्थाओं का एक रूप तो वह था, जिसके अन्तर्गत यूरोपीय भुगतान मप जैसे सघन स्थापित हुये जिन्होंने बहुमुखी लेनदेन सम्भव बनाये, और, दूसरा क्षेत्र वह था, जिसके अन्तर्गत स्टर्लिंग एरिया जैसे करेन्सी क्षेत्र बने, जिनमें कि विभिन्न देशों के पारस्परिक लेनदेन एक 'मुख्य' करेन्सी के सम्बन्ध में निपटायें जाते हैं।

स्टर्लिंग क्षेत्र प्रणाली से आशय एवं इसकी विशेषतायें—

सन् १९३१ में स्वयंमान टूट गया। ब्रिटेन व पश्चिम व्यापारिक सम्बन्ध वाले देशों ने सामान्य हितों से प्रेरित होकर अपनी करेन्सियों का सम्बन्ध स्टर्लिंग से स्थापित कर लिया, जिसमें कि करेन्सी का एक मुख्य क्षेत्र बन गया। चूँकि इस क्षेत्र में युनिवर्सल करेन्सी 'स्टर्लिंग' थी, इसलिए यह क्षेत्र स्टर्लिंग एरिया के नाम से

प्रयत्न हुआ। १९३१ और १९३६ के मध्य लन्दन एक अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु था, जिसकी निम्न विशेषताएँ थी — (i) अपने देशों का समूह, (ii) त्रिदल से यनिष्ठ-वापारिक एवं वित्तीय सम्बन्ध, (iii) स्टलिग में अन्य करेंमिया का मूल्यांकन, (iv) स्टलिग की डालरो में स्वतन्त्र परिवर्तनशीलता, (v) लन्दन में विभिन्न देशों के विदेशी मुद्रा कोष रखे जाना एवं (vi) लन्दन के माध्यम से अधिकांश लेनदेन निपटाया जाना।

मार्च १९४६ में कनाडा की छोड़कर स्टलिङ्ग क्षेत्र में अन्य सब साम्राज्यीय देश आयरिश रिपब्लिक, पुर्नवाल स्केन्डिनेवियन राष्ट्र, बाल्टिक देश, मध्यपूर्व के दस आइसलैण्ड और अर्जेन्टाइना सम्मिलित थे। द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर स्टलिग क्षेत्र बहुत सङ्कुचित हो गया तथा इसकी बहुमुखी व्यवस्थाओं का स्थान विविध नियन्त्रणों से ले लिया। आजकल स्टलिग एरिया की निम्न प्रमुख विशेषताएँ हैं — (१) सभी सम्बद्ध राष्ट्र अपने विदेशी मुद्रा सम्बन्धी व्यवहारों की प्रायः कठिनायि विविध नियन्त्रणों की कसौटी के अनुसार ही संचालित करते हैं। (२) डालर देशों से जापानी को सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता है जिससे कि इन साध भुगतान सम्बन्ध अधिक प्रतिकूल न होने पाय (३) क्षेत्र के बाहर पूर्वी के शक्ति पर बड़े निरभ्रण लग हुए हैं किन्तु क्षेत्र के अन्दर वे अपेक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक बिये जा सकते हैं। (४) डालर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की कमी देशों को एक कठोर लोच में रक्खी पड़ती है। किन्तु एरिया के बाहर के देशों को भुगतान के लिए इसमें से उचित सीमा तक आहरण किया जा सकता है।

स्टलिङ्ग एरिया का महत्त्व—

स्टलिङ्ग एरिया एक व्यापक करेंमी क्षेत्र है जिसके भीतर भुगतान बहुमुखी (multilateral) होते हैं, अर्थात्, एक सदस्य देश इस क्षेत्र के अन्य देशों से वस्तुओं का स्वतन्त्रतापूर्वक कम विक्रय कर सकता है। सम्बद्ध देशों में पूर्वी का स्थानान्तरण भी स्वतन्त्र होता है। वे देश भी, जिन्होंने स्टलिङ्ग एरिया के साधनों का अंजन करने में कोई योग नहीं दिया या जल्प योग दिया है इन साधनों का लाभ उठा सकते हैं। इस क्षेत्र की सदस्यता के कारण ही विभिन्न देशों के जो संचित स्टलिङ्ग बैलेन्स थे उनका भुगतान उन्हें सुगमतापूर्वक मिल गया।

स्टलिङ्ग एरिया में विविध प्रकार के देश (विकसित एवं अल्पविकसित, औद्योगिक एवं कृषक, स्वतन्त्र एवं आधीन, सखु एवं विशाल) सम्मिलित होने से इसके प्रशासन में कई कठिनाइयाँ प्रस्तुत हुई हैं, यथा— (i) दुर्लभ करेंमियों का वितरण सभी सदस्यों के अनुकूल नहीं हो सकता है। वास्तव में, दुर्लभ मुद्राओं की अधिक कमी करने वाले देशों का यह आरोप है कि उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हिस्सा नहीं मिला, (ii) सभी इमानेंद्र के कारण तो कभी अन्य देशों के कारण डालर-भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती रही हैं जिनसे विचित्र हाँकर डालर प्रत्यागा पर बहोर्य वेदात्मक प्रतिबन्ध लगाने पड़े हैं, (iii) प्रत्येक देश की

केन्द्रीय बैंक अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार चलना चाहती है, जिसमें एव समन्वित नीति का पालन नहीं हो पाता है तथा मौद्रिक मामलें बनाये रखना कठिन हो गया है (iv) सदस्यों की डालर सम्बन्धी आवश्यकताओं का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि पर्याप्त जानकारी का अभाव है, (v) मुद्रास्वामी अवरुद्ध कोषों को मुक्त करने में बड़ी देर लगाई गई, एवं (vi) संयुक्त से नीति विषयक निर्णयों के बारे में भी सदस्य-देशों को सतोष नहीं है।

सन् १९४७ में एक 'स्टैलिज़ एरिया मास्यकीय समिति' गठित की गई थी, जो प्रशासन की मुविधा के लिए आवश्यक सांख्यिकी सूचना एकत्र करती है। 'वॉमन-वैल्यू सम्पर्क समिति' का कार्य उपलब्ध प्रसाधनों के सदस्यों में सदस्यों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है। वॉमनवैल्यू के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में स्टैलिज़ एरिया के कामकाजों की समीक्षा की जाती है तथा सुझावों का आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार, स्टैलिज़ एरिया अन्तर्देशीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग का एक सफल उदाहरण है।

भारत को लाभ—

स्टैलिज़ अभ की सदस्यता से भारत कई प्रकार लाभान्वित हुआ है जैसे—

- (i) वह अन्य सबस्य देशों से स्वतन्त्रतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने में समर्थ हुआ जबकि इनके भुगतान की जिम्मेदारी बैंक ऑफ़ द्रॉलैंड पर थी। (ii) यूजी का आयात सुगम हो गया जिसमें उसके विकास कार्यों में बहुत मदद मिली। (iii) स्टैलिज़ बैलेंसिंग का सहज हो भुगतान हो गया, क्योंकि वह एरिया के किसी भी देश में इनके बदले वस्तुओं सरीय सनता था। हमने उसका आर्थिक विकास तेजी से सम्भव हो गया। यह अवश्य है कि भारत को जो लाभ हुआ वह उसकी डालर-कमाई की तुलना में कम था। कारण, उसका डालर क्षेत्र में काफी व्यापार था, जिसमें उसने पर्याप्त डालर आय अर्जित की और कन्व्हेन कोष में जमा कराई।

व्यापार एवं प्रमुख विषयक सामान्य समझौता या गैट (The General Agreement on Trade and Tariffs or GATT)

जिन दिनों (१९४७ में) जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सङ्गठन का चार्टर बनाया जा रहा था उन्हीं दिनों चार्टर बनाने वाली समिति के सदस्यों ने परस्पर टैरिफ़ विषयों के बारे में विचार करना जारी रखा और व्यापार एवं प्रमुख विषय-यह एक सामान्य समझौते की रूपरेखा बनाई। इसे १ जनवरी १९४८ से व्यवहार में लाया गया और इसके सचालन का भार जिस सङ्गठन पर है उसे 'गैट' के नाम से पूछा जाता है। यह विभिन्न देशों का एक दोसा दावा सङ्गठन है, जो व्यापार की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करता रहता है। इसके प्रमुख नियम निम्न हैं—(i) परमानुबद्धित राष्ट्र वाक्य (M. F. N. Clause), जिसका आशय यह है कि एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को दी गई रियायतें अन्य सब राष्ट्रों को भी, जो कि गैट के सदस्य हैं 'दरन (automaticaly) प्राप्त हो जायगी, (ii) परिमाणायक नियन्त्रणों के प्रयोग

पर प्रतिबन्ध, (iii) आयातित एवं स्वदेशी वस्तुओं पर आन्तरिक करों की समानता, (iv) वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध न होना, (v) अत्यधिक आयात-निर्घात कर व मानकीकृतताही पर रोक एवं (vi) निर्यातों के लिए आर्थिक महायताओं की आवश्यक गमीक्षा ।

गैट की लोचपूर्णा व्यवस्थायें—

गैट के नियम पर्याप्त लोचदार रूढ़े गये हैं जिसने कि व्यापक सदस्यों के विविध हितों और दृष्टिकोणों की संतुष्टि हो सके । इस प्रकार, गैट के स्वतन्त्र व्यापार एवं भेदभाव रहित व्यवहार सम्बन्धी उद्देश्य अविवर्धित दशा द्वारा पराजय-शीति के प्रयाग से पूर्ण गति रखने हैं । गैट के नियमों में यह छूट दी हुई है कि एक सदस्य देश अपने कीमत-स्वायत्त-कार्यक्रम (price support programme) को नष्टना हेतु विदेशों से कृषि-वस्तुओं के स्वतन्त्र आयात पर प्रतिबन्ध लगा सकता है । किन्तु शाय ही, यह शर्त रखी हुई है कि वह स्वदेश की कृषि वस्तुओं के उत्पादन या निर्यात के विषय में भी उतने ही प्रतिबन्ध-आगत नियन्त्रण लागू करेगा । कारण, जब तक आयातित एवं स्वदेशी वस्तुओं पर समान रूप में प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे, तब तब बाजार में विदेशों विरोधता का अपना सामान्य विस्तार न छोड़ना पड़ेगा ।

गैट की सफलतायें—

इस समय गैट से विश्व की बड़ी व्यापारिक शक्तियाँ सम्बद्ध हैं और विकासोन्मुख देश भी इतने सदस्य हैं । सबका व्यापार मिलाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का $\frac{1}{3}$ है । गैट ने अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य किया है, निम्ना अनुमान इसके निम्नलिखित कार्यक्रमों से लगाया जा सकता है —

(१) झगड़ों का निपटारा—गैट की झगड़ों का निपटारा कराने में सबसे अधिक सफलता मिली है । इसके वार्षिक सम्मेलनों में नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषी राष्ट्र के विषय में शिकायतें प्रस्तुत की जाती हैं । प्रारम्भ में तो पक्षों में यह प्राप्ति की जाती है कि वे पारस्परिक बातों द्वारा अपने विवाद को सुलझा लें । किन्तु, यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहें तो सङ्घटन की एक वक्तिग कमेटी समस्या का सावधानी से अध्ययन करती है और अपना सुझाव या निर्णय देती है । दोषी सदस्य से इस सुझाव या निर्णय का पालन करने के लिए कहा जाता है । यदि वह ऐसा न करे, तो हानि उठाने वाले पक्ष को यह अनुमति दे दी जाती है कि वह दोषी देश के विरुद्ध, उमन कुछ या सब रियायतें तोटाकर, प्रतिकायस्थक कार्यवाही करे । प्रायः व्यवहार में दोषी सदस्यों ने वक्तिग कमेटी के सुझावों का आदर किया है । केवल अमेरिका ने ही नोडरनेट के डेरा लताओं पर अपने आयात प्रतिबन्धों में सन्तोष न करना स्वीकार नहीं किया था । सन् १९५३ में सदस्यों ने एक पैनल बना दिया है जो झगड़ों के निपटारे के लिए एक अनौपचारिक न्यायालय के सदस्य कार्य करता है ।

(२) परिमाणात्मक प्रतिबन्धों में कमी—विभिन्न देशों ने अपने स्वयं एवं विदेशी मुद्रा कोषों की सुरक्षा के लिए जो परिमाणान्तरक प्रतिबन्ध लगाये हुए थे उनमें कमी कराने में भी गैट की सफलता मिली है। गैट का हथियार समझना-बुझाना (persuasion) और परामर्श देना है। किन्तु ये हथियार बहुत दुर्लभ हैं तथा इन ऐसे देशों पर जो कि परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों को जारी रखने पर अड़ा हों, इसका प्रभाव पड़ना कठिन है। फिर भी, परिमाणान्तरक प्रतिबन्धों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा उन्हे हटाने या कम करने पर जोर दिया जाता रहता है।

(३) टैरिफ वार्ताएँ—गैट ने अपनी टैरिफ वार्ताओं द्वारा बंटवों में सर्वोच्च लाभ प्राप्त की है। विश्व व्यापार के २/३ भाग के सम्बन्ध में लगभग ९,००० टैरिफ दरों पर वार्ताएँ हुई हैं। इन वार्ताओं के फलस्वरूप प्रभावशाली टैरिफ दरों में ५०% कमी हो गई है और स्थिरता एवं निश्चितता आ गई है, जिससे सदन्य-वेग बहुत लाभान्वित हुए हैं तथा विश्व के स्वतन्त्र व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

गैट का भविष्य—

गैट का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वह सदस्य-देशों की विरोधी नीतियों को अपने मौलिक उद्देश्यों के अनुसार किस सीमा तक नवोन्मेष कर सकता है। १९५४-५५ में यह प्रस्ताव रखा गया था कि गैट के सङ्गठन की सुधारने के लिए एक 'व्यापार सहयोग सङ्गठन' (Organisation for Trade Cooperation, OTC) की स्थापना की जाय। इसका मतलब यह था कि गैट के अनौपचारिक मंगल को एक औपचारिक सङ्गठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय, जिसका अपना ग्यारह सदस्य हों और वार्ताओं के सम्पादन के लिये एक एक्जीक्यूटिव बनेगी हो।

जब तक देशों की मौद्रिक एवं व्यापारिक नीतियाँ स्वतन्त्र व्यापार के आदर्श को प्राप्त नहीं कर लेती हैं, गैट और इसके कार्यक्षेत्रों के लिये आवश्यकता बनी रहेगी। अब अविश्वसित देश अपने विकास में तेजी में लगे हुए हैं। परिणामतः आयातों और निर्यातों के स्वभाव में, इनकी मात्रा और रचना में बहुत परिवर्तन हो जायेंगे। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ भुगतान संतुलनों में भी परिवर्तन होंगे। इस प्रकार, गैट का भविष्य में कम विचलित देशों के निर्यात-व्यापार के विकास के लिए एक ठोस कार्यक्रम अपनाए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु अविश्वसित देशों के दावा का स्वीकार करना तथा इस विषय में उनकी नीति के लिए विश्वसित देशों का समर्थन प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है।

गैट समझौते के अन्तर्गत भारत ने विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण टैरिफ रियायतें प्राप्त की हैं और बदले में उन्हें महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। गैट देशों को भारत के निर्यातों का ५०% भाग टैरिफ रियायतों में सामान्वित हो रहा है, जो कि उनमें गैट समझौते के अन्तर्गत प्राप्त की है। एक अविश्वसित देश के लिये जो कि केन्द्रीय आर्थिक नियोजन के द्वारा तेजी से आर्थिक विकास करने पर धुना हुआ है, भारत को भविष्य में गैट में बहुत लाभ होने की सम्भावना है।

गैट के नवें सम्मेलन में, जो कि जनेवा में १९५५ में हुआ था। अर्ध-विकसित देशों के इस अधिकार को स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास सम्बन्धी अपने वायव्यो की पूर्ति के उद्देश्य से पर्याप्त विदेशी विनियम कोष निर्मित करने हेतु परिभाषात्मक प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। गैट के १२वें सम्मेलन में जो कि जनेवा में १९५८ में हुआ था, यह सामान्य अनुमति हुई कि यूरोपियन साझा बाजार योजना के आधीन औद्योगिक देशों की नई प्रमुख नीति अर्ध-विकसित एवं कृषक देशों के निर्यात व्यापार को बहुत ही शक्ति पहुँचायेगी। अतः यह गुमान दिया कि चाय, शक्करा, शक्करा और चीनी का निर्यात करने वाले अर्ध-विकसित देश मिलकर टैरिफ में कमी की कला के लिए आयातक देशों में अनुरोध कर। इस मुकाम के तत्काल बाद ही इन निर्पातक देशों ने आयातक देशों में यह समुक्त अनुरोध किया कि टैरिफ में कमी की जाती चाहिए। १९५६ के टोक्यो में हुए गैट सम्मेलन के बाद यह समाचार मिल कि भारत एवं अन्य अर्धविकसित देशों से विकसित देशों को बेची जाने वाली वस्तुओं पर आयात प्रतिबन्ध हटाने वाले हटाने जायेंगे। उदाहरणार्थ दिसम्बर १९५६ में ५० जर्मनी ने भारत के जूट निर्यात पर में पाच बप के लिये गायत प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की। १९६२ और १९६३ के सम्मेलनों में भी गैट के उन्नत सदस्य देशों से चाय, कढ़वा, चीनी और अन्य वस्तुओं पर जो कि अल्प विकसित देशों द्वारा निर्यात की जाती थी टैक्स घटाने का अनुरोध किया गया।

८ फरवरी १९६५ को गैट के नवें अधिवेशन पर लगभग सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए। यह अधिवेशन अल्प विकसित देशों के दृष्टिकोण में बहुत प्रेरणा प्रदान करता है। इस अधिवेशन के पत्रस्वरूप इस आवश्यकता को अधिकृत रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि विकासोन्मुख देशों को अपनी नई निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार खोलने चाहिए। यही नहीं, विकसित देशों से यह कहा गया है कि वे विकासोन्मुख देशों के वर्तमान या सम्भाव्य निर्यातों पर कोई नये टैरिफ या प्रतिबन्ध न लगायें। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण परिणतन तो यह व्यवस्था होना है कि विकासोन्मुख देशों को रियायतों विकसित देशों में मिले उनके लिये वे बदले की रियायतें दें ऐसा आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार भारत को दोहरा लाभ हो रहा है—एक ओर उसके निर्यातों में कुछ परिपक्व गैट सदस्य देशों द्वारा की गई टैरिफ रियायतों के फलस्वरूप वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर उसे अपने विदेशी विनियम कोष सुरक्षित रखने के लिए परिभाषात्मक आयात प्रतिबन्धों की नीति अपनाने की अनुमति भी प्राप्त है।

भारत सहित ४६ देशों ने ३० जून, १९६७ को एक करार पर हस्ताक्षर किया जिसका उद्देश्य टैरिफ में ५०% तक कमी करना है। स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट केनेडी ने अंतराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो वार्ता शुरू की थी यह करार उसका जन्म अन्वय था। भारत ने इस बात का प्रयत्न किया कि भारत और अन्य विकासशील देशों को अपनी विनाश सम्बन्धी आवश्यकताओं पूरी करने हेतु केवल टैरिफ की आधी

कटोनों का ही पूरा-पूरा नाम न पहुँचे वरन् उन्नत देश विकासशील देशों का उनसे भी अधिक रियायतें दें।

नवम्बर १९६८ में जबका म व्यापार तथा तटवर सम्बन्धी सामान्य करार व्यवस्था में वध मध्यमों का एक्कीसवा अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों का भाग निरन्तर कम होने पर विश्व प्रवृत्ति की गति। अधिवेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि इन देशों की व्यापार की समस्याओं का समाधान के लिए विशेष करार किए जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिवेशन में अनुरोध किया गया कि बीबीनके अधिवेशन की सिफारिशों को दीर्घ कार्यन्विष्ट किया जाय। अधिवेशन ने यह भी मत प्रकट किया कि व्यापार तथा तटवर सम्बन्धी के बीच भाग के कार्यन्विष्ट होने में आन बागी कठिनाइयों की एक विशेष समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए जिसमें इसकी अधिक प्रभावशाली तथा सुप-बन्धित रूप में कार्यन्विष्ट किया जा सके।

१९६४-६७ के दौरान तटवर को कम करने की स्थितिद्वयों पर काननी के केंनेडी-रौंड (Kennedy Round) में किए गए करारों को जनवरी १९६८ में कार्यान्विष्ट किया जा रहा है। भारत तथा अन्य विकासशील देशों के आग्रह पर विकसित देशों ने तटवर में प्रतिक्रिया करने का जगह एक साथ कमी करने की बात मान ली थी।

यूरोपियन साभा बाजार (European Common Market)

यूरोपियन साभा बाजार या यूरोपियन आर्थिक समुदाय का जन्म यूरोपियन एकता के लिए देशों की संघट्ट इच्छा के फलस्वरूप हुआ था। EEC एक नई संस्था है किन्तु जिस भावना में इसका संघट्ट हुआ वह बहुत पुरानी है। यूरोप का इतिहास का अध्ययन करने में यह पता चलेगा कि एक संयुक्त यूरोप का निर्माण करने हेतु जिसने अनेक प्रयत्न किए गए। जिस प्रकार भारतीय उप-महादीप में एकता के लिए भावना समय-समय पर करवटें लेती रहती थी उसी प्रकार यूरोप में भी एकता की भावना दार्शनिका एवं कवियों की रचनाओं तथा स्पेन के राजा तथा नेपोलियन और हिटलर के कार्यों में झलकती है। बहुत समय तक गुरुत्वात्मीय एकता के स्वप्न मात्र रहा। किन्तु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना और फिर इसकी सफलता ने यूरोप-वासियों को यह दशा दिया कि यदि वे मिलकर काम करें तो यूरोपियों का सङ्घ क्या नहीं कर सकता है। किन्तु यह सब राष्ट्रीय द्वेष भावों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

प्रथम महायुद्ध के बाद, जब लीग ऑफ नेशन्स (जोर्ज मुश्केन यूरोपीय देशों की संस्था थी) की स्थापना हुई तब यूरोपियन एकता के विचार ने आगे स्वरूप धारण किया। द्वितीय महायुद्ध ने तो यूरोपियन एकता को जनित्राज देना दिया क्योंकि उन दिनों पश्चिमी यूरोप के अस्तित्व का ही खतरा उत्पन्न हो गया था। युद्ध

के बाद यूरोप के बड़े राष्ट्रों ने अपने आपकी दो महान धनियाँ (रूस और अमेरिका) के चक्कर में फँसा पाया। अमेरिका की शक्ति का स्रोत उसकी टेक्नीकल प्रगति में निहित था किन्तु यूरोप में राजनैतिक सीमाओं के कारण लम्बे हुए आर्थिक प्रतिवधों ने इस प्रगति में बाधा डाल रखी थी। अतः यूरोपियन राष्ट्रों की एकता के लिये प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। सम्भव था कि यह भावना कुछ समय तक अपूर्ण रहती किन्तु अमेरिका के सहायता तम में अन्तर्जाल में ही इस फलीभूत होने का अवसर दे दिया। मई १९४७ में पश्चिमी यूरोप की युद्ध-वर्जित अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध **मार्शल योजना** (Marshall Plan) आरम्भ की गई। इस योजना में जो कि यूरोपियन पुनर्जीवन कार्यक्रम (ERP) के नाम से प्रसिद्ध हुई, सहायता देने के लिए OEEC की स्थापना हुई, जो एक अन्तर्सरकारी संस्था थी। इससे दशों में राजनैतिक एकता तो उत्पन्न न हुई किन्तु एकता की भावना बहुत मजबूत हो गई जिसके फलस्वरूप एक व्यापक संस्था में स्थापना हुई जो कि आगे चलकर यूरोपियन आर्थिक समुदाय की जननी बनी।

यूरोपियन कोयला एवं स्पात समुदाय—

२ मई १९५० का फ्रांसीसी प्रस्ताव में राष्ट्र-गुणन यह उद्देश्य रखा कि कोयला और स्पात सम्बन्धी कामों में और जमीनी प्रसाधनों को एक सामान्य संगठन के अन्तर्गत मिलाया जाय और इस संगठन की सदस्यता अन्य यूरोपियन देशों के लिए भी खुली होनी चाहिये। उनका प्रस्ताव एक लक्ष्य की प्राप्ति का माधन रास्ता था और लक्ष्य था एक यूरोपियन सङ्घ की स्थापना जो कि शांति बनाय रखने के लिए अपरिहार्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक था कि फ्रांस और जर्मनी के सदस्यों पुराने बिगड़े हुए सम्बन्धों को ठीक किया जाय। ब्रिटेन ने इस भावना की अपेक्षा की किन्तु फ्रांस जर्मनी, इटली नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग इन छ देशों ने एक यूरोपियन कोयला एवं स्पात समुदाय (European Coal and Steel Community) की स्थापना के संसन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। प्रस्ताव के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई जिसमें छ सरकारों के प्रतिनिधि लिये गए इसके निर्णय छ देशों के सम्बन्ध उनको पर लागू होते थे जिनके विरुद्ध केवल न्यायालय में ही अपील करने की अनुमति थी।

बढ़ती हुई यूरोपियन एकता—

कोयला एवं स्पात प्रसाधनों के एकीकरण के फलस्वरूप इन उद्योगों की अमूल्यवर्धन उत्पन्न हुई। उपरान्त 'छ देशों' ने अपनी सामरिक शक्ति का एकीकरण करने हेतु एक यूरोपीय रक्षा समुदाय (European Defence Community) स्थापित करने का यत्न किया। किन्तु इसे फ्रांस की राष्ट्रीय गंगा ने स्वीकार नहीं किया। उपरान्त इनका ध्यान पुनः आर्थिक एकीकरण पर गया। उन्होंने आपस में सभी आर्थिक प्रतिवधों को दूर करने के उद्देश्य से एक आर्थिक समुदाय (Economic community) स्थापित करने की योजना बनाई। साथ ही, उन्होंने यूरोपियन

अणु शक्ति समुदाय (European Atomic Energy Community) की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया। उनके प्रयत्नों की सफलता मिली। २५ मार्च १९५७ को रोम सन्धि पर हस्ताक्षर हुये तथा १९५८ के प्रारम्भ में यूरोपियन आर्थिक समुदाय (European Economic Community, EEC) की स्थापना हुई। अणु शक्ति समुदाय भी स्थापित हो गया।

यूरोपियन आर्थिक समुदाय (EEC) के उद्देश्य एवं इसकी प्रगति—

यूरोपियन आर्थिक समुदाय का कार्य क्षेत्र ४४६,००० वर्ग मील तक फैला हुआ है तथा इसमें १७ करोड़ से अधिक जनसंख्या है। इसमें १८ सम्बद्ध सदस्यी देश (उपनिवेश एवं अधीन क्षेत्र) भी हैं। इसकी जनसंख्या ४३ करोड़ है। यदि सदस्यों के लिए आपस में सभी प्रायः आपन स्वीकृत कर निवाराये तो समुदाय के अन्तर्गत फिनलैंड को छोड़कर समस्त गैर कम्युनिस्ट यूरोप आ जाता है इसकी जनसंख्या पने रिकॉर्ड से १३ गुनी हो जायेगी।

रोम सन्धि के अन्तर्गत समुदाय के भीतर सभी आर्थिक सीमान्त १९७० तक या अधिक से अधिक १९७३ तक खत्म कर दिये जायेंगे, जिससे कि वस्तुएँ, मनुष्य, सेवाएँ और पूँजी स्वतन्त्रता पूर्वक आने जाने लगे। 'छ देश' समुदाय विदेशी व्यापार कृषि, मात्तमात और अन्य अनेक क्षेत्रों में सामाज्य एवं एकीकृत नीतियाँ अपनायेगा। अन्तिम लक्ष्य एक मयुक्त राष्ट्र यूरोप का निर्माण करना है। समुदाय के कार्य क्षेत्र में एक जनतन्त्रीय शासन की पूर्ण मशीनरी सक्रिय है। इस मशीनरी के विभिन्न अङ्ग (एग्ज़क्यूटिव, कैबिनेट, पार्लियामेण्ट और सुप्रीम कोर्ट) विस्तारित हैं —

(१) कोयला एवं स्टील उच्च सत्ता (The Coal and Steel High Authority, 1952), जिसका काम छ देशों के मध्य समस्त व्यापारिक प्रतिस्पर्धी का सम्मूलन करके कोयला, स्टील, लौह खनिज एवं स्क्रैप के लिए एक सामाज्य बाजार (Common Market) स्थापित करना तथा बनाये रखना है।

(२) सामाज्य बाजार आयोग (The Common Market Commission 1958), जिसका कार्य १२ से १५ वर्ष की अवधि में एक पूर्ण सामाज्य बाजार स्थापित करना है, जिसमें सभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों समाप्त कर दिये जायेंगे और जो कृषि, मात्तमात एवं विदेशी व्यापार के विषय में मिली-जुली नीतियाँ अपनायेगा तथा आर्थिक मौद्रिक एवं श्रम नीतियों को भी एकीकृत करेगा।

(३) यूरोपीय अणु शक्ति समुदाय (Euratom, 1958), जिसका कार्य अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग के लिए एक शक्तिशाली उद्योग कायम करना तथा एक अणु सामाज्य बाजार का निरीक्षण करना है।

इन सब में सामाज्य बाजार आयोग सबसे महत्वपूर्ण है, प्रो० वाल्टर हेलेस्टीन (Walter Hallstein) के शब्दों में, 'यह एक प्रेरक शक्ति, एक निरीक्षक एवं एक ईमानदार मध्यस्थ है जो कि समुदाय को रोम सन्धि की अनुसूचिता में ढालने में लगा हुआ है।'

१९६७ में प्रगति लेखा-जोखा—

दिस० १९२७ में तीनों यूरोपियन समुदायों की एन्जीन्यूटिन मशीनरी कंपनी एन स्प'त यूरोपीय अगुवर्क्ति एवं सामग्र बाजार एक ही १४ सदस्यीय आयोग में मविनीन हो गई है। एक सामान्य कृषि नीति की पूर्णता प्रदान करने की दिशा में भी यथेष्ट प्रगति हुई है। जबकि रोम सन्धि के अनुसार पर गोचा गया था कि कृषि नीति को समुदाय द्वारा सबसे अन्त में स्वीकार किया जायेगा। कमारोपण के क्षेत्र में भी 'छह देशों' में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये, जिनमें से एक है वर्तमान 'टर्न ओवर टैक्स सिस्टम' (Turn Over Tax System) के स्थान में 'एडेड वैल्यू टैक्स सिस्टम' (Added Value Tax System) को अपनाना।

छह देशों के दृष्टिकोण से एक प्रमुख सफलता व्यापारिक वार्ताओं के 'कनेडी राउंड' (Kennedy Round) को संपूर्ति होना था। इस वार्ता में आयोग ने अपनी सदस्य-सरकारों का प्रतिनिधित्व किया जिससे यह जाहिर हो गया कि EEC एक 'क्वाई' के रूप में सफलता सहित वार्ता चला सकता है। कमीशन ने विभिन्न टैक्स्टाईल पार्ताओं में भी भाग लिया।

रोम सन्धि में एक ऐसी सामान्य कृषि नीति की कल्पना की गई थी जो उत्पादकता को बढ़ाये, कृषि-जनसंख्या को उचित स्तर पर जीवन निर्वाह का अवसर दे और बाजारों के समुक्त प्रबन्ध के द्वारा उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर गारन्टीड पूर्ति की व्यवस्था करे। ऐसी एकीकृत नीति को स्वीकार करने के मार्ग में अनेक बाधाएँ आईं क्योंकि कृषि सम्बन्धी दबाये छह देशों में अलग-अलग हैं। यही नहीं, इन देशों में कृषक जनता का राजनीति पर काफी प्रभाव है। कृषि बिना ही सम्म्या को लेकर ही फ्रांस ने प्रोसेस वार्ताओं का ७ महीने तक बायबाट किया था। फ्रांस ने यह दख लिया कि जल्दी से सन्धि पर हस्ताक्षर करने की बजाय देर में किसी सतोष-जनक सन्धि पर हस्ताक्षर करना अच्छा है। वार्ताओं में चीनी और फल सन्धियों से सम्बन्धित निमन्त्रों के सम्बन्ध में कठिनाई हुई। फ्रांस एक प्रमुख चीनी उत्पादक देश है। वह इटली और जर्मनी की EEC के एन्जीन्यूटिन कमीशन द्वारा प्रस्तावित मात्रा में अधिक बड़े कोटे स्वीकार नहीं करना चाहता था क्योंकि ये देश सीमांत उत्पादक थे। दूसरी ओर बेल्जियम कोटे की व्यवस्था द्वारा चीनी उत्पादन को सीमित कर देने के विरुद्ध था, क्योंकि ऐसा होने में उनकी निर्यात क्षमता कम हो जाती तथा समुदाय के कृषि बोध से मिलने वाली कीमत सहायता (price subsidy) में कमी जाती। इन कठिनाइयों के मद्देन में मन्त्रियों की वार्ता बार बार अवलट हो जाती थी जिनुं जुलाई १९६६ में कृषि नीति विषयक ठहराव हो ही गया।

पंचवर्षीय योजना (प्रथम मध्यमकालीन आर्थिक कार्यक्रम)

वॉशिंग्टन डॉक मिनिस्टर्स आफ दि यूरोपियन इक्वोनोमिस्त कन्फ्रेंस ने फरवरी १९६७ में १९६६ से १९७० को मध्यावधि के लिये एक आर्थिक योजना का मसविदा स्वीकार करके छह सदस्य देशों के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक

व्यापार में बराबर बराबर विस्तारित कर सकेगी। (४) अन्तर-समुदाय व्यापार के लिए व्यापारियों को भविष्य में छह विभिन्न कर व्यवस्थाओं के बजाय एक ही सामान्य व्यवस्था में निपटना पड़ेगा।

दूसरा निर्देश सामान्य कर व्यवस्था को लागू करने के दमों से सम्बन्धित था। EEC की व्यापारिक नीति और विकासोन्मुख देश—

सन् १९६६ में EEC ने विकासोन्मुख देशों के २५% निर्यात लिए। इस प्रकार यह विकासोन्मुख देशों का सबसे बड़ा—अमेरिका EFTA देश समूह समाजवादी देशों और जापान में भी बड़ा—अकेला ग्राहक है। कारण पश्चिमी यूरोप की साधन-स्थिति (resource position) कुछ ऐसी है कि वह साक्षात् कल्प मान, दी धन और सुनिश्चिती धातुओं के लिए विकासोन्मुख देशों पर अधिक निर्भर है। १९६६ से समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में विकासोन्मुख देशों में जबकि EFTA और EEC में प्रतिवर्ष ४५ डॉलर प्रति व्यक्ति का आयात किया, तब अमेरिका ने (जहाँ प्रति व्यक्ति आय दूनी है) केवल ३० डॉलर का आयात किया।

विकासोन्मुख देशों से निर्यात अन्य देशों की अपेक्षा EEC की अधिक उम्माह दिया रहे हैं। १९५८ और १९६६ के मध्य विकासोन्मुख देशों से विश्व की कुल निर्यात ५०% बढ़ गए। जापान और समाजवादी देशों की निर्यातों में सबसे तीव्र वृद्धि हुई (निर्यात लगभग तिगुने हो गए हैं) किन्तु स्मरण रहे कि इन देशों के साथ विकासोन्मुख देशों का व्यापार मामूली ही है अधिकतर व्यापार तो अमान्यवादी पश्चिमी देशों में होता है। इस वक्त में भी EEC देशों की निर्यात ७२% EFTA को २८% और अमेरिका को ३०% बढ़े।

उक्त विपत्तियों का अधिक विकास की गति के अन्तरो के आधार पर द्रुत स्पर्ध नहीं किया जा सकता। GNP की वृद्धि इन तीन पक्षों में EEC में सर्वोच्च और EFTA में निम्नतम थी किन्तु ये अन्तर उनमें नहीं छोटे हैं जो कि विकासोन्मुख देशों से आयातों की वृद्धि-दर में है। यथार्थ में, दोनों EFTA एवं USA में विकासोन्मुख देशों से आयात GNP कुल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) की अपेक्षा घीमी गति में बढ़े हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम आयात वृद्धि के लिए श्रेय आय-वृद्धि का देना चाहते हैं तो EEC की माय वृद्धि का, लाभ गुणांक बहुत होने के कारण, अधिक सार्थक स्वीकार करना होगा। अन्य शब्दों में अमेरिका का ऊँचा विकास ढांचा (high development pattern) यूरोपियन ढाँचे की अपेक्षा कम साधन-प्रधान (less resource oriented) होगा, जिस कारण U S A और (Europe) के मध्य अन्तर का तो समाधान हो जाता है लेकिन EFTA और EEC के बीच के अन्तरों का नहीं।

यदि हम बन्धु वक्त के आधार पर तुलना करें, तो उक्त अन्तरों का समाधान हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि आधारभूत कारण चाहे कुछ भी हो, विकासोन्मुख देशों से आयातों के प्रति EEC में आकर्षण अधिक पाया जाता है।

अतः यदि साधन और आवश्यकताओं के मध्य सम्बन्धों में परिवर्तन धीरे-धीरे हो, तो यह सम्भव है कि विकासोन्मुख देशों के निर्यात के बाजार के रूप में EEC का नागरिक महत्व और भी अपेक्षा भी अधिक हो जायगा। इस सम्बन्ध में तीन बातें उत्पन्न होती हैं—

(१) विकासोन्मुख देशों से १९५८ से आयातों में वृद्धि के लिये एमोसिस्टेड देशों के साथ रियायत व्यवस्थाओं को थोड़ा नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि एमोसिस्टेड देशों से आयात नॉन-एमोसिस्टेड देशों में आयातों की अपेक्षा वही घटती गति में रहेंगे।

(२) निर्मित वस्तुओं के आयातों के सम्बन्ध में अगवाई जाने वाली उदार नीति को भी आयात वृद्धि के लिये थोड़ा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बुनियादी धानुओं को छोड़कर निर्मित वस्तुओं का विकासोन्मुख देशों से EEC को आयात सामूली है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऐसे आयात अमेरिका में EFTA देशों की अपेक्षा तीन गुने हैं।

EEC में अगवाई जाने वाली व्यापारिक और सामान्य आर्थिक नीति की विकासोन्मुख देशों से अधिक आपात आकर्षित करने वाली नहीं है। ट्रोपिकल प्रोडक्ट्स (Tropical Products) पर आन्तरिक कर बहुत ऊँचे हैं। कृषि नीति आत्म निर्भरता पर आधारित है (विशेषतः चीनी, अनाज और फलों के सम्बन्ध में) स्पष्टतः ऐसी नीति विकासोन्मुख देशों के हितों के विरुद्ध है। विकासोन्मुख देशों से निर्यातों के लिए अमेरिका में सोयाबीन के विरुद्ध कोई रियायत नहीं दी जाती है। इन नीतियों के बावजूद विकासोन्मुख देशों से यदि आयात बढ़ें तो इससे यह पता चलता है कि यूरोपीय देशों की आवश्यकता बढ़ रही है, न कि उन्होंने विकासोन्मुख देशों के हितों को प्रधानता दी है।

१९५८ की रोम संधि ने EEC और सम्बद्ध क्षेत्रों के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की कल्पना की थी। अधिक विस्तृत नियम एक विशेष सम्मेलन (convention) में सम्मिलित किये गये थे जो कि ५ वर्षों के लिये था। इस सम्मेलन की सम्पत्ति तक अनेक एसोसियेटेड देश स्वतन्त्र हो गये थे, जिस कारण दूसरा पाँच वर्षीय सम्मेलन (the Convention of Yaounde) हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्न-लिखित हैं—(१) EEC और एसोसियेटेड देशों व क्षेत्रों के मध्य मुक्त व्यापार होगा, किन्तु एसोसियेटेड देश चाहें तो फिस्कल अथवा सुरक्षात्मक (Fiscal or Protective) कारणों से EEC से आयातों पर टैरिफ जारी रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। (२) तीसरे देशों के साथ व्यवहार में एसोसियेटेड देश EEC के सामान्य वैदेशिक सटकरों (common external tariffs) से बचे हुए न होंगे। (३) EEC एमोसिस्टेड देशों के विकास के लिए एक विकास कोष में से मदद देगा। (४) अन्य बातों पर भी EEC के संगठन में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। (५) फ्रेंच कोलोनियों को फ्रान्स के बाजारों में जो विशेष स्थिति प्राप्त है (उन्हें निरन्तर

बाजार के स्तरों से ऊँची कीमतें देनी पड़ती है और बदले में वे स्वयं भी फ्रांस के निर्यातों के लिये ऊँची कीमत देते हैं) वह शर्तें शर्तें समाप्त की जाएंगी। इन कोलोनियों को विशेष सहायता दी जायेगी जिससे कि वे अपनी उत्पादकता को इस सीमा तक बढ़ा लें कि नई स्थिति का सामना कर सकें।

१९६४ में कन्वेंशन के आरम्भ के अवसर पर तृतीय देशों के विरुद्ध सामान्य स्तर पर कई ट्रांजीट प्रोडक्ट्स पर नीचे कर दिए गये या स्थगित कर दिये गए। इस प्रकार भेदभाव का समायोजन धीरे-धीरे होने के बजाय भेदभाव 'साम्यात्मिक' हो गया।

समुदाय की रियायती व्यवस्थाएं प्रारम्भ में ही नॉन-एसोसियेटेड विकासोन्मुख देशों (विशेषतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में) के लिये चिन्ता का विषय रही हैं। यह डर था कि उनका व्यापार वही अस्त व्यस्त न हो जाय अर्थात् एसोसियेटेड देशों के निर्यात बाहरी देशों के निर्यातों का जो किन्हीं दशाओं में उनके लिये परमावश्यक हैं (जैसे—कहवा, कोकोआ और भाग) स्थान न लें। किन्तु अभी तक ये आशंकाएँ निर्मूल हुई हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था EEC की विकासोन्मुख देशों के कुल निर्यातों में १९६०-१९६६ की मध्यावधि में ७२% वृद्धि हो गई है। इसी अवधि में EEC की एसोसियेटेड देशों और क्षेत्रों के निर्यात केवल ३३% ही बढ़े। इससे यह निष्कर्ष मिलता है कि रियायती व्यवस्थाओं को अभी अपना प्रभाव दिखाने का अवसर नहीं मिला है। जहाँ तक भविष्य की स्थिति का प्रश्न है वह इस बात पर निर्भर होगी कि विकास के लिये दी जाने वाली सहायता का उपयोग करके एसोसियेटेड देश अन्य सप्लायरों की तुलना में प्रतिस्पर्धा कर पायेंगे या नहीं।

अंकटाड द्वितीय (UNCTAD II) के सामने यह प्रश्न है कि क्या EEC समुदाय जैनी प्रीकरेन्शियल स्कीमों को समाप्त कर देना चाहिये। प्रेसीडेन्ट जोम्सन् ने तो सामान्यीकृत रियायतों (generalised preferences) के पक्ष में अमेरिका का समर्थन व्यक्त किया है। अल्जीयर्स चार्टर (Algiers Charter) में भी यह कहा गया है कि विशेष रियायतों को समाप्त कर दिया जाय और जो देश इसे अब तक रियायतें पाने रहे हैं उन्हें तात्कालिक हानि से बचाने के लिये क्षतिपूर्ति लाभ दिये जायें। किन्तु EEC का दृष्टिकोण Yaounde Convention के अनुसार विद्यमान रियायतों की ही बनाये रखने का है—ऐसा EEC स्वयं के हित में चाहती है या अफ्रीकी देशों के हित में, इस बारे में निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्पष्टतः विवेकपूर्ण कदम तो यह होगा कि UNCTAD-I और अल्जीयर्स चार्टर की सिफारिशों का अनुसरण किया जाय।

उल्लेखनीय है कि एसोसियेटेड देशों की निर्मित वस्तुओं को EEC में मुक्त-पहुँच (free access) प्राप्त है, जिस कारण औपचारिक रूप से यह प्रतीत होता है कि उनका स्थिति अनेक विकासोन्मुख देशों की अपेक्षा बहुत अनुकूल है। किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है। कारण, इन देशों में औद्योगीकरण विलम्ब से आरम्भ हुआ है। श्रु-

बाजार पर आधारित उद्योग सामान्यतः एमोस्तिनटेड देशों में छोटे और अमहत्वपूर्ण होते हैं जिससे इनके नियम अविष्य उम्भवत नहीं हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि औद्योगिक देशों में व्यापारिक बाधाओं की समाप्ति मान से विकासोन्मुख देशों का लाभ नहीं हो जायगा। इन देशों में एक औद्योगीकरण स-निर्यात प्रयास की सफलता के लिये यह भी जरूरी होगा कि उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान का कोशल का हमनाकरण हो। अतः निम्न वस्तुओं के प्रति EEC की व्यापारिक रियायतें अधिबाध में निष्प्रभावी (unefective) हैं।

मोटे रूप में EEC की व्यापारिक नीति अन्य औद्योगिक देशों के ही समान है—ऊँचे भावों पर (औ कि स्थानीय पूर्ति कोनों में प्रतिस्पर्धा न करने वाले हो) नाकी या शुल्क इत्यादीज सवामा, प्रोमेसिंग के साथ के साथ बढ़ती हुई टैरिफ दरें निर्धारित करना और जिन दवाओं में ऊँचे टैरिफ भी सकल न होंगे वहाँ कोश प्रतिपाद्य लगाना। साथ ही, EEC में टेम्परेट क्षेत्र के कृषि उत्पादों के विषय में आमनिर्भरता के लिये प्रयास किया जा रहा है तथा ट्रोपीकल फ्रूट्स (जैसे—महंगा और चाय) पर ऊँचे कर लगाये गये हैं।

EEC की रचित विकासोन्मुख देशों के लिये अन्य औद्योगिक देशों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अतः विकासोन्मुख देश उससे निम्न जायायें लगा सकते हैं — (१) विकासोन्मुख देशों की व्यापार दलों की प्रतिबन्धन न होने देने बल्कि अनुकूल बनाने की योजनाओं के प्रति पूर्ण सहयोग देना। (२) ट्रोपीकल फ्रूट्स पर आन्तरिक-नरों को हटाना या घटाना। (३) आन्तरिक कृषि नीतियों में ऐसे समाधान करना जिससे विकासोन्मुख देशों में प्रतिस्पर्धात्मक निर्यातों (जैसे—चीनी) की वृद्धि को ठेस न पहुँचे। (४) सभी विकासोन्मुख देशों को सामान्य रियायतें (generalised preferences) देने के प्रस्तावों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना। (५) विकासोन्मुख देशों में निर्यात-उद्योग कायम करने और इनके उत्पादकों का विस्तार करने में उनको प्रत्यक्ष और संवेष्ट सहायता देना।

विकासोन्मुख देशों को रियायतें देने के प्रश्न पर का दृष्टिकोण—

यूरोपियन समुदाय के आयोग के अध्यक्ष जीन रे (Jean Ray) ने कोसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स को भेजे गये अपने दो टिप्पणी-पत्रों में भारत और अन्य विकासोन्मुख देशों को हित की बातों की चर्चा की है। ये दो टिप्पणी-पत्र निम्न प्रकार हैं —

(१) OECD की चार सदस्यीय समिति की रियायतों प्रयुक्तों से सम्बन्धित रिपोर्ट पर विचार—विकासोन्मुख देशों के लिये रियायती टैरिफों के विषय में OECD की चार सदस्यीय समिति ने निम्न जाठ बातें रखी थी —(i) विकासोन्मुख देशों के लिये सुरक्षा प्रावधान रखा जाय, (ii) रियायतों की व्यवस्था सभी विकसित देशों द्वारा समान स्तर पर की जाय, (iii) विकासोन्मुख देशों की एक ऐसी सूची तैयार की जाय जिसमें सामान्य होने वाले देशों के नाम हो, (iv)

अपवाद सूची बनाई जाय, (v) मूल स्थान (Origin) सम्बन्धी नियम अलग अलग हो सकते हैं किन्तु उनका एकीकरण (Coordination) होना चाहिए, (vi) केन्द्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं (अर्थात् पूर्वी यूरोप के देशों) को भी विकासोन्मुख देशों की सहायता करनी चाहिये, (vii) पारस्परिकता (reciprocity) की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विकासोन्मुख देश क्षत्रीय व्यवस्थाओं में प्रविष्टि होकर स्वयं ही अपने विकास को बढ़ावेंगे एवं (viii) रियायतें घटती हुई और अन्धार्ई होनी चाहिए प्रारम्भ में ये केवल १० वर्ष के लिए हो सकती हैं।

(२) साक्षात् सम्बन्धी सहायता—कौनेडी दौर की रागाण्टि की अवस्थाओं में विकासोन्मुख देशों ने एक अमेरिकन प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसके अनुसार एक 'बहुमुखी कार्यक्रम' (multilateral programme) गठित किया जाना था। इसके अनुसार विकासोन्मुख देशों को ४५ मि० टन खाद्यान्न सप्लाई किया जायगा। इसमें ECM का भाग २३% रखा गया जो नगदी ऋण या जिनस भ दिया जा सकेगा। कमीशन ने जिस के रूप में सहायता देने की इच्छा दिखाई है जो विकासोन्मुख देशों की आवश्यकता पर आधारित होगी राजनीति पर नहीं।

ब्रिटेन और साम्राज्य बाजार—

ब्रिटेन ने १९५६ में साम्राज्य बाजार में प्रवेश करने में इन्कार कर दिया था और यहाँ तक कि इसके विरोध में यूरोपियन अबाध व्यापार समुदाय' की रचना तक कर डाली थी। बाद को १९६३ में EEC की प्रगति को देख कर उसने इनमें सदस्यता ग्रहण करने की प्रेरणा की। किन्तु फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल के प्रबल विरोध ने उसे साम्राज्य बाजार का सदस्य नहीं बनने दिया। अब १९६७ में ब्रिटेन ने सदस्यता के लिए प्रस्ताव पुन रखा। इस बार वह राष्ट्रमंडल के हिस्से को छोड़ने और अपनी ऊँची नीति सम्बन्धी सर्तों से भी हटने के लिए तैयार हो गया। किन्तु इतने पर भी फ्रांस ने उसकी सदस्यता का विरोध नहीं छोड़ा। कहा गया कि ब्रिटेन को पहले अपनी भुगतान संतुलन सम्बन्धी प्रतिकूलता को सुधार लेना चाहिए। तब तक के लिए वह एसोसिएट सदस्य बन सकता है, किन्तु ऐसी सीमित सदस्यता ब्रिटेन को स्वीकार नहीं हुई।

फ्रान्स के विरोध के कारण—

१९५८ में सनाहट होने के समय से डिगाल का उद्देश्य यूरोप को एक समुक्त राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का रहा—ऐसा समुक्त राष्ट्र, जिसमें फ्रान्स की स्थिति मुख्य हो। किन्तु फ्रांस EEC का एक वरिष्ठ साभेदार तब ही तक बना रह सकता है जब तक कि ब्रिटेन उससे बाहर है। यदि ब्रिटेन EEC में सम्मिलित हो जाय, तो फ्रान्स की प्रभावशाली स्थिति समाप्त हो जायेगी, क्योंकि फ्रान्स की भाँति ब्रिटेन भी एक 'ड्वार्ड' है, अल्प सम्पन्न राष्ट्र है, और अंग्रेजी EEC की प्रमुख भाषा

बन जायेगी, क्योंकि जर्मन और इन भाषाओं में बोलने की योग्यता अंग्रेजों के अधिक निश्चित है।

ब्रिगाद का ब्रिटेन विरोधी दृष्टिकोण इसलिए भी था कि वह स्वयं अमेरिका विरोधी थे जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिटेन अमेरिका का निश्चित सहयोगी है।

इससे भी बड़ा कारण यह है कि ब्रिटेन साम्राज्यवाद में प्रवेश के साथ राष्ट्र-मण्डल के देशों के व्यापारिक हितों की भी रक्षा करना चाहता था। सासफर कनाडा एवं यूजीलैंड के हितों की रक्षा के लिए वह अपनी जीए राष्ट्रमण्डल के कृषिजन्य वस्तुओं के व्यापार को विशेष स्थिति दिखाना चाहता था।

इन सब प्रश्नों पर आकर फ्रान्स में ब्रिटेन की गारों की यूरोपीय आर्थिक पत्र में प्रवेश से पहले ही अटका कर रख दिया। १४ जनवरी, १९६१ को जनरल डिगाल ने कहा — “ब्रिटेन एक असम द्दीप है, समुद्री व्यापार करने वाला राष्ट्र है और अपने व्यापार, अपने बाजारों और अपने मान मुहैया करने वालों के द्वारा बनेक प्रकार के देशों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें से कुछ बहुत दूर है ... प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटेन अपने आपको यूरोपीय महाद्वीप के साथ रख सकता है, और महाद्वीप की भांति सही अर्थों में एक सामान्य टैरिफ में रह सकता है, राष्ट्रमण्डल के मामले में सब तरफों से जोड़ सकता है, इस दावे का परित्याग कर सकता है कि उसकी कृषि को एक विशेष स्थिति प्रदान की जाये, और सबसे बढ़कर क्या यूरोपीय महाद्वीप व्यापार क्षेत्र (यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया) के साथ हुए अपने सब समझौतों को रद्द कर सकता है ? सारा प्रश्न यही है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रश्न फिलहाल हल हो गया है। क्या यह किसी दिन हल होगा ? स्पष्टतः इसका उत्तर केवल ब्रिटेन ही दे सकता है।” जनरल डिगाल ने इस उद्धरण से वे सब आर्थिक कारण स्पष्ट हो जाने हैं जिनके ब्रिटेन के साम्राज्यवाद में प्रवेश को उन्होंने अटकाया।

राष्ट्रमंडल से बदलते हुये सम्बन्ध—

ब्रिटेन के ‘डि इकनामिस्ट’ पत्र के अनुसार “पाच वर्ष पूर्व थी इकित्तिबेकर कनाडा की हैरोल्ड मैकमिलन के यूरोपीय साम्राज्यवाद में प्रवेश के इरादे पर चौक लगा था। परन्तु अभी हाल में आल्ब-कनाडियन आर्थिक समिति के आन्वयगतक गान्ति के साथ सम्पन्न हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिए सम्मेलन में आये छ कनाडी मंत्रियों ने ब्रिटेन के इस वाक्य में पुनः प्रवेश के नए प्रयत्न पर बुनियादी तौर पर अनुकूल रस ही प्रकट किया।”

वास्तव में राष्ट्रमण्डल का रूप बहुत बदलता रहा है। किसी समय उत्तम ११ देश थे, अब २६ हैं। देशों की संख्या इतनी अधिक हो जाने के कारण उसमें वह सुगठित एकता नहीं रही, जो पहले थी। ४१ वर्ष पूर्व १९२६ में लार्ड-बाल्फोर की अध्यक्षता में गये समिति ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल के जिस स्वरूप की कल्पना की थी, उसमें मूल सिद्धान्त यह था कि उसके सदस्य सभी देश

स्वतन्त्र है, उनका स्तर यमान है और 'धरेलू या बंदेस्तिक नीति के किसी पहलू के बारे में कोई किसी के लक्ष्य नहीं है।' समानता के इस सिद्धान्त का पालन किया गया। परन्तु फिर भी ब्रिटेन ने नवोक्ति राष्ट्रमण्डल का गठन किया था इसलिए संप्रदाय सदस्य राष्ट्रों के प्रति उसका भाव सरलता का था और सदस्य राष्ट्र भी उसमें कुछ आयात रखते थे। लेकिन राष्ट्रमण्डल को वैश्वीय राष्ट्रमण्डलीय देशों में दक्षिणी रोडेशिया और बियनाम के सवानो को लेकर अपने समान स्तर का लाभ उठाना और ब्रिटेन को उसमें कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः ब्रिटेन का स्थान है कि जब राष्ट्रमण्डल के हमारे देश संपन्न होंगे तो लाभ अपनी दृष्टि में उठाने हैं और ब्रिटेन को कठिनाई में डाल सकते हैं तो वे ब्रिटेन से सरलता की भाषा बोल कर सकते हैं? ब्रिटेन यह तर्क भी देता है कि जब राष्ट्रमण्डल के सदस्य राष्ट्र राष्ट्रमण्डल से बाहेर जब अलग हो सकते हैं तो ब्रिटेन से ही उनका हर हालत में, अपने हितों की उपेक्षा करके भी, राष्ट्रमण्डल का साथ देने की आशा करना वहाँ तक न्याय-संगत है? इसलिए ब्रिटेन ने अपना हित देखकर अपना यह पुराना हथकण दिया है कि यह यूरोपीय साम्राज्यवादी में तबो जायेगा जबकि राष्ट्रमण्डल के हितों की यह रक्षा कर सकेगा। अब वह कहता है, पहले मुझे यूरोपीय शक्ति बाजार में प्रविष्ट हो जाने दो उसके बाद राष्ट्रमण्डल के हित-समर्पण का प्रयत्न करने की बात सोची जायगी। उसके इस हथकण का परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रमण्डल का विघटन स्वरित हो जाये।

साम्राज्यवादी में प्रवेश के लिए ब्रिटेन उत्सुक क्यों ?

ब्रिटेन का यूरोपीय साम्राज्यवादी में प्रविष्टि होने में क्या हित है? असल में अमेरिका को यू.जी. और टेक्नोलॉजी से ब्रिटेन सहित यूरोप पर बहुत जबरदस्त आक्रमण किया हुआ है। अमेरिका की विदेशी में लगी ४५ अरब डॉलर की यू.जी. में से एक तिहाई यू.जी. यूरोप में लगी हुई है। अकेले ब्रिटेन में ही ६२ अरब डॉलर का उसका यू.जी.-विनियोग है। इसके अलावा अमेरिका से यूरोप को बहुत बड़ी मात्रा में नई टेक्नोलॉजी का आयात करना पड़ता है। अनुमानतः यूरोप प्रतिवर्ष अमेरिका से पेटेंट प्राप्त करने के लिए १ अरब डॉलर व्यय करता है।

दूसरी ओर यूरोप के आला दिभाग अमेरिका में अच्छा वेतन और अनुसंधान की अच्छी सुविधाएँ मिलने के कारण चुम्बक से लकड़ने जाने लोहे की तरह अटलांटिक के उस पार लिये चले जा रहे हैं। इससे यूरोप के सामने (जिसमें ब्रिटेन भी सम्मिलित है) यह समस्या पैदा हो गई है कि यदि वह अपने को सम्भालने के लिए समर्थ नहीं हुआ तो क्या वह आशियन और टेक्नोलॉजीकल मामलों में अमेरिका का दास होने से बच सकेगा ?

अमेरिका और साम्राज्यवादी का आयातियाँ करोड़ करोड़ बराबर है परन्तु साम्राज्यवादी ने देशों की प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय अमेरिका की औसत प्रति व्यक्ति आय से आधी है। इसका कारण यह पाया गया है कि अमेरिका के भीतर

बनाना आन्तरिक बाजार ही इतना बड़ा है कि वह नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर बड़े हुए उत्पादन को खपा सकता है। इसलिए पश्चिमी यूरोप के सभी देश अब यह अनुभव करने लगे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय सीमाओं को मिटाकर बड़े-से-बड़ा बाजार बनाना चाहिए। इसी में ब्रिटेन का लाभ है, इसी में यूरोपीय साम्राज्य बाजार का और इसी में यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र का भी लाभ है।

ECM में ब्रिटेन के प्रवेश से भारत की हानि—

लेकिन ब्रिटेन को यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रवेश से भले ही लाभ हो, राष्ट्र-मण्डल के देशों, खासकर भारत को इससे व्यापार में भारी हानि उठानी पड़ेगी। ब्रिटेन भारत के माल का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक रहा है और राष्ट्रमण्डल के देशों को दी जाने वाली टैरिफ सम्बन्धी तरजीहों के कारण उसका माल ब्रिटेन में सन्ना पहुँचता रहा है। इस तरजीह की वजह से ब्रिटेन में उसके माल की अधिक बिक्री रही है, जबकि यूरोपीय साम्राज्य बाजार के देशों से जहाँ उसे यह रियायत नहीं मिली हुई है, उसका व्यापार उसना नहीं रहा।

यदि ब्रिटेन यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रविष्ट हो जाता है तो साम्राज्य बाजार के देशों में परस्पर टैरिफ न होने या बहुत कम होने के कारण ब्रिटेन को यूरोपीय देशों का माल राष्ट्रमण्डलीय देशों या भारत में सस्ता पड़ेगा। दूसरी ओर भारत के माल पर वही टैरिफ लग जायेगा जो यूरोपीय साम्राज्य बाजार के देशों में लगता है। इससे ब्रिटेन में उसका माल महँगा पड़ेगा और भारत के व्यापार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है।

ब्रिटेन जब यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र में (अर्थात् EFTA, जिसके सदस्य हैं, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन) प्रविष्ट हुआ, तब में टैरिफ की इन छूटों के कारण ही भारत का व्यापार न केवल यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र के देशों के साथ घटा, बल्कि ब्रिटेन के साथ भी घट गया। यही बात ब्रिटेन के साथ भी भारत के व्यापार में हुई। १९६० में जहाँ ब्रिटेन को भारत का निर्यात ३५ करोड़ डॉलर था, वहाँ वह १९६४ में घटकर ३९२ करोड़ डॉलर रह गया। इस प्रकार उसके निर्यात में ११ प्रतिशत की कमी हुई। दूसरी ओर उसी अवधि में ब्रिटेन को यूरोपीय अबाध-व्यापार क्षेत्र का निर्यात ४९ प्रतिशत बढ़ा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि ब्रिटेन का यूरोपीय अबाध व्यापार क्षेत्र में प्रवेश भारत के लिए इतना हानिकर हो सकता था, तो उसका यूरोपीय साम्राज्य बाजार में प्रवेश तो और भी अधिक नुकसानदेह होगा।

राष्ट्रमण्डल का प्रभावकारी सदस्य होने से ब्रिटेन में तथा राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत देशों में भी चीनी के कारण भारत कच्ची वस्तुओं का निर्यात करने में समर्थ नहीं रहेगा। यह दो-राने की आवश्यकता नहीं कि जबकि पहली ओर दूसरी पक्षधरों की मजदूरी हमारे निर्यात-वृद्धि की दिशा में प्रयत्न किये थे, तब यूरोपीय पक्षधरों की योजना

में निर्यात-वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की गई। कारण, अधिक निर्यात के बिना हमारी विदेशी मुद्रा बर्जित करने की सामर्थ्य कम होने का डर था। निर्यात-वृद्धि की आधारभूत आवश्यकता के इस गम्भीर अवसर पर अचानक ही ब्रिटेन वर एण्ट-मण्डन के देशों की उपेक्षा करते हुए यूरोपीय संयुक्त बाजार को सदस्यता स्वीकार करना गम्भीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सहायता देना जिस प्रकार भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है उसी प्रकार ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संयुक्त-बाजार का सदस्य बनना भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रहार करेगा। निश्चय ही यदि ब्रिटेन सदस्य बन जाता है तो वहाँ के बाजार में भारत की वस्तुओं की काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और काफी कठिनाई का घौघन करना पड़ेगा जिनकी राष्ट्रमण्डल का सदस्य होने के कारण उसे छूट थी। यही कारण है कि भारत में अब भी ब्रिटेन से, राष्ट्रमण्डल के लिए सुविधायें प्राप्त किये बिना और उसके हितों की रक्षा किये बिना, यूरोपीय साम्राज्य बाजार में सम्मिलित न होने का अनुरोध किया है।

भारत की माँगें—

भारत की ओर से यूरोपीय आर्थिक सच को पहले एक ज्ञापन भारत की कठिनाइयों के समाधान के लिए दिया गया था जिसमें रोम सन्धि का हवाला देकर उसके ढाँचे के भीतर ही भारत के निर्यात व्यापार को सुविधायें देने के सुझाव दिये गये थे। इन सुझावों पर भारत अब भी बस बै सकता है। ये सुझाव थे—(१) यूरोपीय आर्थिक सच भारत के प्राथमिक, अर्ध-संस्कार और कुछ तैयार (प्रोसेस्ड) उत्पादों पर जो अब तक ब्रिटेन में कोट्रे और इपुटी के बन्धन से मुक्त होकर प्रविष्ट होने रहे हैं सर्वसामान्य बर्देनिक टैरिफ के बजाय शून्य टैरिफ लगा दे, (२) अन्य उत्पादकों को रोम सन्धि के अनुच्छेद २३६ के अनुसार ब्रिटेन में उसी तरह विशेष रियायतें दे दे जैसा फ्रांस में मोरक्को और अल्जीरिया के सामान को दी जाती है, (३) भारत के विशेष हित के सामान पर जनरल एक्सेम्प्ट और ट्रेड एण्ड टैरिफ के अनुच्छेद २४ के अनुसार सर्वसामान्य बाहरी टैरिफ में काफी कटौती कर दे, (४) और इन परिवर्तनों एवं सुविधाओं के सन्तुलन काल को काफी लम्बा कर दे।

यदि भारत दृढ़ता से ये सुझाव पुनः यूरोपीय साम्राज्य बाजार के सामने रखे और वह भी इन पर सहानुभूति से विचार करे तो भारत के हितों की कुछ रक्षा हो सकती है।

महा जाता है कि परिवर्तन नहीं खने होंगे तथा कॉमनवेल्थ व्यापार के बिना विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ रखी जायेंगी। किन्तु यह स्पष्ट है कि ऐसी व्यवस्थाएँ सीमित हो होंगी तथा मध्यान्तर अवधि भी छ-सान वर्षों की होगी। इसके अतिरिक्त, भारत की स्थिति अन्य कॉमनवेल्थ के देशों से भिन्न है। जबकि कॉमन वेल्थ के अन्य देश ब्रिटेन से वर्तमान व्यापार बना रहने पर ही सन्तुष्ट हो जायेंगे (और इसे ही साम्य स्वीकार करने की तत्पर हैं अधिक नहीं) जब भारत एवं एक दो अन्य विकसित-

न्यून देशों को वर्तमान व्यापार मर्यादों बना रहने से ही सन्तोष न होगा, वरन् वे यह चाहेंगे कि उनके निर्यात बढ़ें।

अफ्रीकी साम्प्रदायिक बाजार (African Common Market)

अफ्रीकी साम्प्रदायिक बाजार की स्थापना हाल ही में कासाब्लांका शक्तियों (Casablanca Powers) द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य और स्वरूप बहुत कुछ यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समान है। इसके छह संस्थापक सदस्य निम्न हैं — मरुस्त अरब गणराज्य (मिश्र, सीरिया और ईरान), बाना, अल्जीरिया, मॉरिशस, निजी और माली। भारत की गई थी कि यह देश पहले वर्ष में अपनी कच्चे तेल की ५% कमी कर देंगे और तत्पश्चात् दोष कच्चे तेल को भी अपने ४ वर्षों में समाप्त कर देंगे। उन्होंने एक स्थायी संगठन 'अफ्रीकी साम्प्रदायिक बाजार परिषद' (African Common Market Council) स्थापित करने का निर्णय किया, जिसमें प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा। इसी सहायता के लिए परामर्शदाता भी होंगे। कोयिन का प्रधान कार्यालय कासाब्लांका में होगा और इसकी बैठक प्रति छह माह हुआ करेगी। निर्णय सर्वसम्मति से किये जायेंगे। प्रत्येक राज्य का एक वोट होगा। कोई भी सदस्य देश अपने अन्य सदस्यों से परामर्श किये बिना, अ-सदस्य देशों से, किसी ठहराव में प्रविष्ट न हो सकेगा।

इस समय यह कहना कठिन है कि कासाब्लांका आर्थिक समुदाय (Casablanca Economic Community, CEC) का अन्य देशों पर विशेषतः भारत के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत ही अल्प है। १९६२-६३ में हमारे निर्यातों का केवल ३.२% भाग ही उनकी रक्षा का और हमारे आयातों का केवल १.८% भाग ही उनसे आया था। इतने पर भी इन देशों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना तथा इनके साथ अपना व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार करना आवश्यक है। इन आवश्यकताओं के बारे में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनके विकास का स्तर समान नहीं है। किन्तु सब ही अपनी जनता का जीवनमान एक नियोजित ढंग से ऊँचा करने के लिये अनुकूल है। इनमें से अधिकांश प्राथमिक मनुष्यजन प्रतिकूल रहता है। प्राथमिक वस्तुओं (primary products) का उत्पादक होने के कारण वे अपने विवादास्पद विदेशी मुद्रा के अंश के लिए इनी-विनी वस्तुओं के निर्यात पर ही निर्भर रहते हैं।

भारत को चाहिए कि परम्परागत बाजारों को स्थिर रखते हुए नये बाजारों को अपेक्षित करे। अफ्रीकी बाजार, जर्मनी और इटली के अफ्रीकी बाजारों के समान ही है। इन सम्पन्न देशों से टक्कर लेने के लिए हमें अपनी विक्रयकला और वितरण-नीति को सरल बनाना होगा। मुख्य निर्यात, पवित्र-मुद्रा, निर्यात-मुद्रा और तद्वर्तता की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इसके अलावा अफ्रीका से आने वाले माल के लिये भारत में बाजार अनुसन्धान भी करना अभीष्ट है क्योंकि जब तक अफ्रीका से आयात

नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे निर्यात में भी वृद्धि नहीं हो सकती। प्रसन्नता की बात है कि अफ्रीका के देशों में अधिकांश वस्तुएँ खुले लाइसेंस में शामिल हैं। भारत को भी अफ्रीकी वस्तुओं सम्बन्धी आयात-नीति में दिखाई देनी होगी क्योंकि आगिर व्यापार दोनों पक्षों का आपसी मधुर सम्बन्ध ही तो है।

यूरोपियन स्वतन्त्र व्यापार परिषद् (European Free Trade Association)

यूरोपियन स्वतन्त्र व्यापार परिषद् (EFTA) की स्थापना मई १९६० में (U. C. M. की स्थापना के दो वर्ष बाद) ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और आस्ट्रेलिया (जिन्हें 'Outer Seven' कहा जाता है) द्वारा स्टार होम प्रस्ताव की पुष्टि के कमन्सकरण हुई थी। जून १९६१ में फिनलैंड भी इस परिषद् का एक 'एसोसियेटेड सदस्य' बना था।

EFTA आठ देशों के मध्य एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके द्वारा, सदस्यों के मध्य व्यापार पर से सगुप्त टैरिफ एवं अन्य प्रतिबन्ध समाप्त करके, एक 'एनाकी बाजार' (single market) स्थापित किया जायेगा। किन्तु सदस्य देश अन्य देशों के प्रति स्वेच्छानुसार टैरिफ एवं व्यापारिक नीतियाँ अपना सकते हैं। EFTA का उद्देश्य अन्तिमतः ECM में मिश्रित हो जाना है। इसीलिए इसके सदस्य-देश अपनी टैरिफ नीतियों को ECM की टैरिफ नीति के अनुसार ही चलाने का प्रयत्न करते हैं।

रोम समिधि (जिसके आधार पर ECN की स्थापना हुई) एवं स्टारहोम समिधि (जिसके आधार पर EFTA बना) में टैरिफ नीति विषयक दो अन्तर अल्लेखनीय हैं, एक तो स्टारहोम प्रस्ताव कृषि टैरिफों पर नामु नहीं होता वह इन्हें अछूता छोड़ देता है किन्तु रोम समिधि एवं सामग्री कृषि नीति एवं एकीकृत कृषि कीमतों पर बल देती है और दूसरे, स्टारहोम प्रस्ताव एक सामान्य बाह्य टैरिफ (common external tariff) की व्यवस्था नहीं करता। EFTA का प्रत्येक सदस्य इस बात के लिए स्वतन्त्र है कि वह एरिया के बाहर के देशों के साथ अपने व्यापार में जो चाहे टैरिफ लगाये। इसके विपरीत, ECM में एक सामान्य टैरिफ (Common Tariff) स्थापित किया है, जो उस समय, जबकि अन्तर समुदाय (inter community) टैरिफ समाप्त हो जायें, लागू होगी।

१९६७ का वर्ष प्रारम्भ होने के साथ ही सप्त देशीय यूरोपियन-व्यापार-मध्य (EFTA) एक पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बन गया। EFTA के मध्य व्यापार की निमित्त वस्तुओं पर लगे हुए औष २०% टैरिफ भी १ जनवरी १९७३ की अर्ध राति से हटा दिया गया है। टैरिफ कम करने का काम १९६० में आरम्भ हुआ था। उक्त समय ब्रिटेन, पुर्तगाल, आस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन और स्विटजरलैंड ने टैरिफ कम किये थे। फिनलैंड १ वर्ष बाद एसोसिएट सदस्य बना था। अब उसने अपने टैरिफ १९६७ में १०% तक घटा दिये और औष १०% १९६८ में हटा दिये। किन्तु, स्मरण रहे आधिराज्य कृषि एवं सामुद्रिक उपज पर अभी टैरिफ

लगे हुये है और EFTA देश अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले माल पर स्वैच्छानुसार टैरिफ लगाते है। इस प्रकार EFTA देशों की १०० मि० जनसंख्या को अभी तक केवल निमित्त वस्तुओं में अबाध व्यापार का लाभ मिला है। निर्मित वस्तुओं पर टैरिफ रिहाय्या में तीन वर्ष पूर्व ही हटा लिये गये हैं, जो इस मुद्दे के देशों के लिए एक सराट-नीय सफलता है।

ज्ञान क्षर्ण की जाने वाली टैरिफ घटीतियों के फलस्वरूप EFTA के सदस्यों के मध्य व्यापार गतिमें ही दूना हो चुका था। पूर्ण अबाध व्यापार के प्रचलन के साथ अब यह आशा है कि छोटे EFTA राष्ट्रों का गृह बाजार कई गुना बड़ा हो जायेगा। यदि ऐसा विकास न होता तो EFTA देशों को छ देशीय यूरोपीय आपिक समुदाय में कुछ भेदभाव का सामना करना पड़ता और इसका उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा असर होता। अब EFTA के उत्पादकों और व्यापारियों के लिए यह अवसर है कि वे १०० मि० जनसंख्या वाले बाजार के लिए अधिक बड़ी उत्पादक और विवरक इकाइयाँ स्थापित करें।

ECA और EFTA के मध्य इनकी स्थापना के समय से ही प्रतिद्वन्दितता बनी आ रही है, जिस कारण समुक्त राष्ट्र के रूप में यूरोप का एकीकरण नहीं हो सका है। पिछले छ वर्षों में EFTA सरकारों ने EEC के साथ अपने सम्बन्धों की जाई की पाटने के लिए कई बार प्रयत्न किये किन्तु EEC का इस कुछ उत्साहजनक नहीं रहा। इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक तो यह है कि स्वयं EEC को अन्तराष्ट्रिक विरोधों का सामना करना पड़ रहा है और दूसरे EFTA को EEC जितना आकर्षक लगता है उतना EEC को EFTA नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, EFTA देशों में उन शर्तों पर मतभेद नहीं हैं जिन पर कि उन्हें EEC में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे—डेन्मार्क EEC में पूर्ण सदस्यता चाहता है किन्तु स्विट्जरलैंड एवं आस्ट्रिया एसोसिएट सदस्यता पर ही राजी है। इन राष्ट्रों ने ब्रिटेन को EEC में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी थी किन्तु डेन्मार्क का ब्रिटेन के प्रवेश के प्रति पुराना विरोध अभी भी जारी है। इस प्रकार, यूरोप की अधिक एकता का स्वप्न साकार होने में अभी विग्रह है।

कोलम्बो योजना और भारत का योगदान

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के मद्देन में सभी देशों की, जिनमें नवोदित जनसन्नाहमक गणराज्य विशेष उल्लेखनीय हैं, कुछेक प्रतिज्ञास्पर्षी दृष्टिों जटिल बन गई है कि भाग के इंजानिफ युग में अपने ही मसाधनों द्वारा उनको अल्पावधि में मुलभाना इन देशों के बूने की बात नहीं है। यह बात बत कुछ दशकों में दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मन्द आर्थिक गति से पुष्ट होती है। गत वर्ष प्रकाशित समुक्त राष्ट्र सच की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील राष्ट्रों के विनाश की गति या तो स्थिर रही है अथवा जो भी प्रगति हुई है, वह निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नगण्य है। इसके दो मुख्य कारण रहे हैं—पहला, सीमित और साधन और दूसरा व्या-

व्यवहारिक तकनीकी ज्ञान की कमी। शायद इसीलिए भारत जैसे प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण देश के लिए कहा गया है कि 'साधन होते हुए भी भारत एक निर्धन देश है'। हमारे पास प्राकृतिक सम्पदा है, बिजली पैदा करने के लिए पानी है उद्योग स्थापित करने के लिए खनिज पदार्थ हैं, परन्तु इन सबका उपयोग करने के लिए वह ज्ञान नहीं है जो अमरीका रूस के पास है। अतः इस अभाव की पूर्ति हेतु अपने ससाधनों पर अतिरिक्तिक निभर करने के साथ साथ ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का सदस्य बनना, जिनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयत्नों द्वारा आर्थिक सामाजिक विकास की गति प्रदान करना है भारत की दूरदर्शिता और सद्भावना का ही सीतक है।

कोलम्बो योजना के उद्देश्य —

अन्य सस्याओं की भाँति 'कोलम्बो योजना' भी जिसका पूरा नाम 'दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए कोलम्बो योजना' है, उन अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों में से एक है जिसका भारत आरम्भ में समर्थन करता आया है। १९६० में जब इस योजना के कार्यन्वयन पर बातचीत चल रही थी, उस समय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उपयोगिता के बारे में कहा था—“मु. विश्वास है कि कोलम्बो योजना जैसे सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम दक्षिण और दक्षिण-पूर्व स्थित देशों के आर्थिक विकास में बरदान साबित होंगे। भारत इस योजना की सदस्यता का हार्थिक स्वागत करता है।”

योजना का शुभारम्भ—

दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने और वहाँ के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाने में मदद देने के प्रश्न पर मण्डल के विदेश मन्त्रियों की पहली बैठक जनवरी १९६० में कोलम्बो में हुई थी। इस बैठक के निर्णय के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न समस्याओं पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसकी पहली बैठक १९६० में सिडनी में हुई जिसमें इन देशों की आर्थिक उन्नति के लिए एक छह वर्षीय विकास योजना मुझाई गई और इन देशों में तकनीकी शिक्षा के अभाव की पूर्ति के लिए तुरन्त तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बैठक में सलाहकार समिति ने अलग से एक स्थायी समिति की स्थापना भी की। इस समिति की रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए १,००,४०,००,००० पौन्ड की विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी विदेशी सहायता के समस्त पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह अनुमति किया गया कि इसकी उपलब्धि राष्ट्र सङ्घ के देशों के बूने की धातु नहीं है और इसके लिए ससार के अन्य देशों का सहयोग भी आवश्यक होगा। परिणामतः इन देशों की तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक सामूहिक तकनीकी परियोजना लागू की गई।

तकनीकी परियोजना की विशेषताएँ—

(१) इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी सदस्य देश कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों में कैर-बदल के लिए मुभाय रत सकता है, जिन पर विचार करना प्रत्येक सदस्य देश अपना कर्तव्य समझता है। इस बृहत दृष्टिकोण से न केवल सदस्य राष्ट्रों को अपने हितों की सुनिश्चितता के प्रति आस्था बढ़ती रहती है, बल्कि इन देशों में पारस्परिक भाईचारे और सद्भावना को भी बढ़ावा मिलता है।

(२) इसके अन्तर्गत उपलब्ध सहायता राजनैतिक स्तरों से सर्वथा मुक्त होती है। अतः सहायता प्राप्त करने वाले और सहायता देने वाले राष्ट्रों के सम्बन्धों में किसी प्रकार की कड़वाहट का प्रश्न ही नहीं उठता और सहायता देने वाला देश और सहायता लेने वाला देश, सीधे बातचीत करके स्थिति का सुलझान कराने हैं। यही कारण है कि आरम्भ में यह योजना यद्यपि केवल छ वर्षों के लिए अर्थात् १९५१ से १९५७ तक के लिए बनाई गई थी, तथापि इसकी उपलब्धियों और महत्त्व को देखते हुए १९५५ में कोलम्बा योजना को सनाहकार समिति ने इसकी अवधि १९६१ तक, १९५६ से १९६६ तक और फिर १९७१ तक बढ़ा दी।

(३) इसके अन्तर्गत आर्थिक-तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित सदस्य राष्ट्रों द्वारा कम विकसित देशों को पचासप्रतिशत सहायता दी जाती है। उदाहरण के लिए, अन्य सदस्य देशों की तुलना में यार्डलैंड काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। अतः इसके विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत काफी सहायता उपलब्ध की गई है। पार्सिन्द को सबसे अधिक सहायता अमरीका आस्ट्रेलिया और जापान से मिली है।

सदस्य देश—

आरम्भ में इस योजना की सदस्यता केवल राष्ट्रमंडलीय सदस्यों अर्थात् आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, मलेशिया, उत्तर योर्किया, सिंगापुर, तैवान, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड आदि तक ही सीमित थी। परन्तु दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को माघन जुटाने की समस्या की व्यापकता को देखते हुए इसकी सदस्यता अन्य राष्ट्रों के लिए भी खोल दी गई है। इस समय २४ राष्ट्र इस योजना के सदस्य हैं, जो इस प्रकार हैं —आस्ट्रेलिया, भुटान, बर्मा, कम्बोडिया, कनाडा, ताका, भारत, इण्डो-नेशिया, कोरिया गणराज्य, लाओस, मलेशिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फ़िलीपीन, सिंगापुर यार्डलैंड, ब्रिटेन, वियतनाम, अमरीका, अफ़ग़ानिस्तान ईरान, नेपाल और मालदीव द्वीप-समूह।

कोलम्बो योजना की प्रगति—

अनेक कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सदस्य देशों की निम्नी प्रगति हुई है, वह वास्तव में सन्तोहनीय है। इसमें मन्देह नहीं कि सत्ताधरों के अभाव में इन देशों में विकास की गति सदस्यानुसार बनाये रखना सम्भव नहीं हो सका, फिर भी इन २० वर्षों में हुई प्रगति को देखते हुए यह

निम्नतः रूप से कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र के सभी देश अपने लोगों के रहन-सहन का स्तर सुधारने और आय बढ़ाने के लिए कुतसकल्प हैं। इस सकल्प को मार्ग रूप देने के लिए इन देशों की सरकारें राष्ट्रीय विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में लगी हुई हैं।

जैसाकि कोलम्बो योजना की सलाहकार समिति (१९६६) की १७ वीं बैठक की रिपोर्ट में कहा गया था, कोरिया, फिलीपीन, थाईलैंड और मलेशिया में गत वर्षों की अपेक्षा आर्थिक विकास की गति काफी सन्तोषजनक रही, जबकि भारत, पाकिस्तान, फिलीपीन, थाईलैंड और वियतनाम गणराज्य द्वारा किये जाने वाले ब्यापार की दर में सबसे अधिक वृद्धि हुई। चूँकि इस योजना के अन्तर्गत अधिकतर सदस्य देशों की लक्ष्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब इन देशों की आर्थिक विकास की योजनाओं में कृषि की पैदावार बढ़ाने पर अधिक बल दिया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इन देशों में काफी प्रगति हुई है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता से भारत, पाकिस्तान, लक्का, इंडोनेशिया और बर्मा में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य शिक्षा, संचार और परिवहन आदि के अनेक कार्यक्रमों को भी शीघ्रगतिशीलता से पूरा किया जा रहा है जिनसे इन देशों की आर्थिक और जनव्यवस्था सम्बन्धी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी।

वैसे तो सामूहिक योजना के कार्यक्रमों में सभी देश गवर्नरशिप आदि सहायता उपलब्ध करा रहे हैं किन्तु सबसे अधिक सहायता अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा और यूजीलैंड के बाद भारत में प्राप्त हो रही है। इनके अतिरिक्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों (जैसे—IBRD, समुत्तराष्ट्रीय विशेष कोष) के माध्यम से भी इस योजना के सदस्य विकासशील देशों को मायिक सहायता मिल रही है।

कोलम्बो योजना परिषद् की एक पड़ताल के अनुसार कोलम्बो योजना के सदस्य देशों में तकनीकियन की कमी है, शिल्पिक शिक्षा के सरकारी विभागों और उद्योग तथा सरकारी शिल्पिक विभागों में पालमेन का अभाव है, कृषि विस्तार, पशुपालन, मछलीपालन, अन्य सम्पदा से सम्बन्धित ज्ञान और मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की अत्यन्त आवश्यकता है। सदस्य देशों में तकनीकी ज्ञान के इस अभाव को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपने सीमित साधनों के बावजूद जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है। ११ दिसम्बर १९६८ तक भारत ने विभिन्न देशों के ४०१० व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें दीं। ये प्रशिक्षणार्थी अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कम्बोडिया, केनिया, पाना, जापान, तंजानिया, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, यूजीलैंड, माइजीरिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, बर्मा, मलेशिया, मलावी, मारीशस, मालदीव द्वीप समूह, मूगाण्डा, नाजोस, वियतनाम, श्री लंका और सियरा लियोन से आए। जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण कोट विज्ञान, कराधान, चर्म प्रयोगिकी, काजू उत्पादन

सांख्यिकीय निम्न नियंत्रण, सिवार्ड, परिवहन, लघु उद्योग, इस्पात उत्पादन में प्रशिक्षण कृषि योजना प्रचार और मैकान नदी परियोजना के टोनले सीप क्षेत्र के लिए भी भारतीय विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध की गईं। इसमें सन्देह नहीं कि कोलम्बो योजना के प्रारम्भ में जो सदस्य देश तकनीकी प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, वनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और अमरीका पर निर्भर करते थे, वही देश आज अन्य सदस्य देशों को तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग दे रहे हैं। ऐसे देशों में भारत का मुख्य स्थान है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत दिसम्बर १९६८ के अग्त तक भारत को १८ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त हुईं और कोलम्बो योजना के देशों में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, लाघ तथा कृषि उद्योग तथा व्यापार, विजली तथा ईंधन इ.जी.नियरी, परिवहन तथा संचार साधन बैकिंग थम प्रशासन, ट्रेड सुविधा के कार्य, मुद्रण आदि के क्षेत्रों में ५१०० भारतीयों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्राप्त हुईं।

योजना के प्रारम्भ से ३१ अक्टूबर १९६८ तक भारत को इन देशों में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई—आस्ट्रेलिया ५४ ६५ करोड़ रु०, न्यूजीलैंड ४६१ करोड़ रु०, कनाडा ३२८.६७ करोड़ रु० तथा ब्रिटेन २००० करोड़ रुपये।

निष्कर्ष—उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कोलम्बो योजना जैसे सांख्यिक प्रयास का वर्तमान शीतयुद्ध की खाई को पाटने और विश्व शांति तथा सहभावना के नाक-साम आर्थिक पुनर्निर्माण के वातावरण के निर्माण में अद्वितीय योग्य है। उप-प्रधानमंत्री श्री मोरारजी के शब्दों में इस योजना की आधारशिला रखते शाने सदस्य देशों के मन्त्रों की मूर्त रूप देने की दिशा में कोलम्बो योजना एक व्यावहारिक कदम है। इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान में न केवल सदस्य देशों में निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में सहायता मिली है, बल्कि प्रारंभिक सहकारी क्षेत्र में नये-नये कार्यक्रमों की विस्तार करने और सदस्य देशों में पारस्परिक सहायता की भावना में भी अभिवृद्धि हुई है। विस्तार और अभिकमित देशों के बीच यह योजना एक मूल्यवान् परीक्षण है। मुझे विश्वास है कि कोलम्बो योजना के सदस्य देश उसी भावना से जोत-प्रोत और अन्तर्राष्ट्रीय सहकार की भावना के साथ राष्ट्रीय निर्माण की गतिविधियों में पहले से भी अधिक रुचि लेते रहेंगे।”

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

(United Nations's Conference of Trade and Development)

कोलम्बो योजना के पाँचवें दशक के अन्तिम वर्षों में जारी की गई हुबला योजना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सहकर सम्मेलने (गाट) की स्वीकृति से न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अक्षेपित वृद्धि नहीं हुई अपितु इनसे विकासशील देशों की अर्थ-व्यवस्था और व्यापार को भी पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला। एशिया और

समृद्ध देशों के बीच की खाई बढती गई और १९६० में समुक्त राष्ट्र सभ की इस घोषणा के बावजूद कि बीसवीं शताब्दी का सातवाँ दशक विकास दशक होगा दशक के आरम्भिक वर्षों में विकासशील देशों की समस्या में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। इस स्थिति के निराकरण के लिए नये गिने में अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्न किए गये और ऐसी व्यवस्था करने पर जोर दिया गया जिसमें विरासतशील देशों के आर्थिक विकास और व्यापार को बढाने पर अधिक जोर दिया जाय। इन प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप जून, १९६० में समुक्त राष्ट्र सभ के व्यापार और विकास सम्मेलन का जन्म हुआ।

पहले सम्मेलन की उपलब्धियाँ—

अतः समुक्त राष्ट्र का पहला व्यापार और विश्व सम्मेलन जेनेवा में हुआ। इस सम्मेलन में विकासशील देशों की समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों पर विस्तार से विचार किया गया। विचार-विमर्श के बाद अनेक महत्वपूर्ण विषयों (जैसे—रुग्ने मान और बनी हुई चीजों का व्यापार, ऋण और पूँजी लगाना जहाजरानी और भाड़े आदि) के सम्बन्ध में सिफारिशें की गईं और मसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष तिथान्त निश्चित किये। सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने और सम्मेलनों की मध्या-धधि में काम करने के लिए एक संगठन बनाया गया। साथ ही, आशा प्रकट की गई कि दूसरे अधिवेशन होने तक सम्मेलन के सक्षम की प्राप्ति के लिए काफी काम होगा।

किन्तु पहले सम्मेलन के बाद के वर्षों में यह आशा पूरी नहीं हुई। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी वृद्धि हुई है किन्तु विकासशील देशों के आर्थिक विकास की गति में कमी हुई है और गरीब और समृद्ध राष्ट्रों के बीच की खाई बड़ी है। जहाँ विकसित देशों में राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ६० डालर की दर से बढ़ रही है वहाँ अविासित देशों में राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति २ डालर में भी कम दर से बढ़ रही है। १९५३ में मसार के कुल व्यापार में विकासशील देशों का हिस्सा २७% था किन्तु १९६६ में यह घटकर १६.३% रह गया। विकासशील देशों के निर्यात की क्रय शक्ति निरन्तर गिर रही है। १९६५ में इन देशों को अपनी सम्पुर्णों के लिए इस दशक के अनुशास की अपेक्षा १०% कम दाम मिले। सम्मेलन की सिफारिश के बावजूद विकासशील देशों को फायदा पहुँचाने वाले कच्चे या बुनियादी माल के लिए कोई करार नहीं किया गया। विकासशील देशों के तैयार और मर्प-नैयार माल के निर्यात पर लगे तटकरों में कोई कमी नहीं की गई है। पहले सम्मेलन में सर्वसम्पति से सिफारिश की थी कि विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत भाग विकासशील देशों को दें किन्तु वास्तव में इस अवधि में विर-सित देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जा रही सहायता में लगातार कमी हुई है। जहाजरानी के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण वीर-तरीके और व्यवस्थाएँ और उनके भाड़े में

द्वे के कारण विकासशील देशों का भुगतान-संतुलन बिगड़ गया है। इससे विकास-शील देशों के निर्यात में वृद्धि नहीं हो सकी है और उनको विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

निस्सन्देह पहले संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विनाम सम्मेलन के बाद विश्व जनमत में परिवर्तन आया है। इस सम्मेलन में पूर्व कुछ ही देशों को ही तटकर आदि की सुविधाएँ मिल रही थी और विकासशील देशों को इन सुविधाओं में कश्चिन् रखा जाता था। पहले सम्मेलन में इस सिद्धान्त को बदल दिया गया। परन्तु -मान्यारिन् रूप में विकासशील देशों को तरजीह देने का अभी भी कोई समझौता नहीं है, यद्यपि पिछले तीन वर्षों में कुछ देशों ने अरबी नीति में परिवर्तन किया है। जास्टिसिया, अमरीका और समाजवादी देशों ने विकासशील देशों ने हक में कुछ फैसले किये हैं।

पहले इस नियम का कड़ाई में पालन होता था कि विकासशील देशों को व्यापार सम्बन्धी जो छूट दी जाएगी, वैसी ही रियायतों की अपेक्षा उनमें भी की जायेगी। अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के सिद्धान्त और अन्तर्राष्ट्रीय तटकर और व्यापार समझौते (GATT) के अव्याय ४ में यह व्यवस्था है कि विकासशील देशों को व्यापार में जो रियायतें दी जायेंगी, उसके बदले में उनमें कोई अपेक्षा नहीं की जायेगी। कंवेन्टी पार्टी से भी विकासशील देशों को कुछ व्यापार सम्बन्धी रियायतें प्राप्त हुई हैं।

समस्या और समाधान (दूसरे १९६७ के सम्मेलन की पृष्ठ भूमि) —

यदि विकासशील देशों के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति होनी है तो पहले सम्मेलन के दौरान सामने आई सभी समस्याओं का आपसी बातचीत और विचार-विमर्श द्वारा निराकरण होना चाहिए। दूसरे सम्मेलन १९६७ के दौरान, छोटे समय में विकासशील देशों की इन सभी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता। अब इस विषय में कोई प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि आपसी बातचीत और विचार-विमर्श से प्रमुख कठिनाइयों दूर की जा सकें। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव डा० राबुल प्रिथिवी ने व्यापार और विकास मण्डल के पाँचवें अधिवेशन में ऐसी कुछ समस्याओं की चर्चा की जो उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—जिनसे के सम्बन्ध में नीति, तटकर आदि से उत्पन्न समस्याएँ, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं की तरजीह देना, सहायक पुँजों का प्रदन, समाजवादी देशों और अन्य देशों के बीच व्यापार की समस्याएँ और विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न। इस बार में सर्भा देवेंद्र में सहमति थी कि दूसरे सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श द्वारा इन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। वास्तव में कि विकासशील देशों की कुछ समस्याएँ सम्मेलन के दौरान हल हो जायेंगी और सम्मेलन के अन्य समय भी कालान्तर में पूरे होंगे।

एशिया, अफ्रीका और अमरीका के विकासशील देश कुछ गहानो पूर्व से सम्मेलन को सफल बनाने के उपायों पर विचार कर रहे थे। इकाफे क्षेत्र के देशों सितम्बर १९६७ म बँकाक मे बैठक करके एक घोषणा पत्र स्वीकार किया। अमरीका के देशों ने बगोटा (बोलम्बिया) म और अफ्रीका तथा एशियाई देशों ने अल्जीयर्स म उन पर विचार किया। और फिर अल्जीयर्स घोषणा' जारी की गई थी। इस घोषणा पत्र मे कहा गया है कि सभी विकासशील देशों के आधारभूत हित एक हैं। अल्जीयर्स सम्मेलन में यह बात भलीभाँति अनुभव की गई कि सम्मेलन की सफलता के लिए विकासशील देशों की एकरता आवश्यक है। अल्जीयर्स सम्मेलन म यह बात भी अनुभव की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की उन नीतियों का जो विकासशील देशों के कृषि भी वर्ग को लाभ पहुँचायें सभी विकासशील देशों को समर्थन करना चाहिए। इन समस्याओं के निदान के लिए भी जिनका सामना छोटे से देशों को करना पड़ता है सभी '७७' देशों का समर्थन जरूरी समझा गया है।

अल्जीयर्स सम्मेलन मे यह स्वीकारा गया है कि जहाँ विकसित देशों को अपनी सम्पत्तता और तकनीकी प्रगति के कारण विकासशील देशों की भरसक सहायता करनी चाहिए, वहाँ विकासशील देश केवल स्वावलम्बन द्वारा ही प्रगति और सम्पत्तता हासिल कर सकते हैं। अतः सम्मेलन म विकासशील देशों ने स्वावलम्बन द्वारा विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग रूप से और मिलकर पारस्परिक व्यापार को बढ़ाने, अधिक प्रगट आर्थिक सम्बन्ध कायम करने और घनिष्ठ सहयोग करने का संकल्प दुहराया। इस दिशा मे व्यापार और तटकर समझौते और भारत, युगोस्लाविया और समुक्त गणराज्य के विपक्षी विचार विमर्श द्वारा दुस्सात की जा चुकी है।

क्या संकटाढ (UNCTAD) असफल रहा ?

विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन २६ मार्च १९६८ को समाप्त हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही १८ दिन तक चली। इस सम्मेलन की कार्यवाही इतने अधिक समय तक चलना इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देशों के समक्ष अनेक गम्भीर समस्याएँ हैं। अन्त मे विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उसे लेकर सर्वत्र निराशा व्यक्त की गई। विकासशील देशों मे निराशा ज्यादा दिखाई देती थी। कहा गया कि समुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन जैसे उन्नत देशों मे आर्थिक संकट पैदा नहीं हुआ तो विश्व व्यापार व विनाम सम्मेलन के ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हुये होते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट पैदा हो जाने के कारण विकासशील देशों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देने की स्थिति मे न देश बचने आसना नहीं पा रहे हैं। इस संकट से पूर्व भी उन्नत देश विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति साक्ष्य ध्यान नहीं दे रहे थे—अपना राष्ट्रीय हित को संकुचित मनावृत्ति अपनाकर कही कही उम्होन इस ओर ध्यान दिया।

विश्व व्यापार व विकास सम्मेलन की कार्यवाही में स्पष्ट हो गया कि विश्व के राष्ट्रों में आर्थिक क्षेत्र के प्रति जागरूकता अभी पैदा नहीं हुई है। यदि हम सब मान्ति स्वतन्त्रता और एकता की बात करते हैं तो यह भी जरूरी है कि इसकी अभिव्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी हो। इसके माने हैं कि यह हम सबका सामूहिक दायित्व है कि विज्ञान और टेक्नोलोजी के इस युग में हर पुरुष या महिला या बालक के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। विश्व का अर्थ तन्त्र ऐसा होना चाहिये कि इस काम को पूरा करना सम्भव हो सके। विरागशील देशों द्वारा सहायता व्यापार अधिमानों इत्यादि के बारे में जो इस सम्मेलन में प्रश्न उठाए गये थे उन सब का व्यापक दृष्टिकोण से महत्व है। उन्नत देशों द्वारा इन प्रश्नों का दिया गया उत्तर यदि निराशाजनक है तो इसका प्रमुख कारण यह है कि विश्व के राष्ट्रों में विकासशील देशों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में आवश्यक जागरूकता अभी नहीं है।

इन सब बातों के होते हुए इस सम्मेलन की कुछ उपलब्धियाँ भी थी। अकटाइ के प्रमुख प्रस्ताव से कुछ प्रश्नों को हल करने में मदद मिली, क्योंकि उसमें सभी अहम सबानों की झूची दी गई है जिन पर गम्भीरतापूर्वक निरन्तर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इन प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट है कि उन्नत देश विकासशील देशों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अब किस हद तक तैयार है। इस प्रस्ताव में ऐसे प्रश्नों पर भी रोशनी डाली गई है जिन पर बाद में आवश्यकतापूर्वक अध्ययन करने और कुछ ठोस कदम उठाने के बारे में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। व्यापार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व कम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, शुरू में कुछ सकोच दिखाने के बाद, अन्तर्गत-गवा अपने राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत विकासशील देशों को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन उसने इस पर प्रमत्त करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। द्वितीय अधिमानों के बारे में फ्रांस के राज में दिव्यार्ई आई है। पाकिस्तान देश अकटाइ की एक कार्यकारी समिति के रूप में काम कर देने के प्रश्न पर झुक गये हैं। अकटाइ के तत्वावधान में अधिमानों के प्रमुख प्रश्न पर बात-चीत करने के लिए उन्नत देश अब तैयार हो गये हैं।

जीओनिक वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों को अपना निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाएँ अब बढ़ गई हैं। यह ठीक है कि यदि इन वस्तुओं की सूची में तैयार और अर्द्ध-तैयार माल शामिल नहीं किया जाता तो कम विकसित और अन्य विकसित देशों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी तैयार और अर्द्ध-तैयार वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों के पक्ष में उदार नीति अपनाई गई है।

इस सम्मेलन की दूसरी विशेषता यह है कि इस बार ७७ राष्ट्रों का समूह एकता के सूत्र में बंध कर जाग बठा है। उनकी इस एकता का परिणाम असीरी

देशों के निर्णय से मिला है जिन्होंने विकासशील देशों के हित को अपने हित से अधिक महत्व देते हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा स्वीकृत अधिमानों को ठुकरा दिया है। ये माधारण लाभ हैं लेकिन इनके आधार पर ही हम उन्नत और अल्प-विकसित देशों में सहयोग की भावना पैदा करने में सफल हो सकते हैं।

विश्व व्यापार नीति (World Trade Policy)

अक्टूबर के सेक्रेटरी जनरल राउल प्रीविश ने यह मत प्रगट किया है कि UNCTAD को विकासोन्मुख देशों के सहयोग से एक विश्व व्यापार नीति का विकास करना चाहिए। यदि विश्व व्यापार भूतकालीन प्रवृत्ति के अनुसार ही चलता रहा, तो विकासोन्मुख देशों के बिदेजी मुद्रा वर्जन में सन् १९७० तक २० बिलियन डॉलर की ग्यूनता हो जाएगी। यदि ये देश १% की मामूली दर से भी अपना विकास करना चाहे, जिसका सुझाव यू० एन० की जनरल असेम्बली ने दिया था तो भी इस ग्यूनता को पाटना आवश्यक है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अभी तक विकासोन्मुख देशों की दृष्टि से कोई विश्व व्यापार नीति नहीं है। विकसित देश वस्तुओं के विश्व उपभोग में विकासोन्मुख देशों की निरिप्त वस्तुओं की मामूली गति से वृद्धि भी सहन करने को तैयार नहीं है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि विकासोन्मुख देशों से निर्यातों को व्यवस्थित रूप में बढ़ाया जाय तथा औद्योगिक राष्ट्र अपनी आयात आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम निश्चित करें। यह बड़े खेद की बात है कि जबकि विकसित देश आपस में ही व्यापार बढ़ाने के लिये एकीकृत नीतियाँ एवं उपाय अपना रहे हैं तब विकासोन्मुख देशों ने ऐसा नहीं किया है।

परीक्षा प्रश्न :

१. दो महायुद्धों के बीच की अवधि में जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विघटन हुआ उसकी मुख्य विशेषताएँ बताइये।

[Bring out the main features of the International economic disintegration in the inter-war period]

(आगरा, एम० ए०, १९६७)

२. गैट क्या है ? यह विश्व व्यापार में उदार बनाने में कहाँ तक सफल हुआ है ?
[What is GATT ? How far has it succeeded in liberalising world trade ?]

(गोरखपुर, एम० ए०, १९६८)

३. अक्टूबर द्वितीय के मामले प्रमुख प्रश्न क्या थे ? इसकी सफलताओं और विफलताओं का संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिये।

स० दया०, ४०

[What were the main issues before UNCTAD II ? Briefly evaluate its achievements and failures]

(इलाह०, एम० ए०, १९६६)

४. कामनवेल्थ देशों को अक्टोड और गैट के माध्यम से एक बहुमुखी व्यवस्था उपलब्ध है।" विवेचन कीजिये।

['Commonwealth countries are best handled multilaterally through the UNCTAD and GATT' Discuss]

(इलाह०, एम० कॉम०, १९६६)

५. 'केनेडी राउण्ड एग्रीमेन्ट' क्या है ? यह गैट के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक करता है ? सावधानी से स्पष्ट कीजिये।

[What is Kennedy Round Agreement ? How far does it subserve the purpose of GATT ? Explain this carefully]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

६. गैट के बुनियादी सिद्धान्त क्या हैं ? क्या इन पर अर्थव्यवस्था के नियोजित आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

[What are the basic principles of GATT ? Have they been affected by the planned economic development of under-developed countries ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

७. गैट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? इनकी पूर्ति किस सीमा तक हुई ? अधिक सकलता के लिये व्यावहारिक सुझाव दीजिये।

[What are the main objectives of the GATT ? To what extent have they been realised ? What practical suggestions could you make for improving conditions ?]

(आगरा, एम० ए०, १९६६)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(International Monetary Fund)

परिचय—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में एक महान् घटना है। यद्यपि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का पक्ष्म उदाहरण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पूर्व भी इस दशा में कई प्रयत्न हो चुके हैं, तथापि वह अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्बन्धों के संगठित संचालन (Organised conduct) का सत्रमे मिलन और सचेत प्रयास है।

कोष के जन्म की पृष्ठभूमि

यद्यपि मुद्रा कोष, वास्तविक रूप से, सन् १९४४ में, स्थापित हुआ था, तथापि इसका उद्भव (Origin) प्रथम महायुद्ध के समय में पता लगाया जा सकता है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण स्थापित हुआ —

(१) स्वर्णमान का परिष्कार—प्रथम महायुद्ध से पूर्व विश्व के अपनी राष्ट्र स्वर्णमान पर थे किन्तु युद्धकाल में यह मान स्थगित हो गया। युद्धोत्तर काल में इसकी पुनः स्थापना हेतु प्रयत्न किये गये और पुनः स्थापना भी हो गई। किन्तु विभिन्न राष्ट्रों की परिस्थितियाँ मौलिक रूप से इतनी बदल गई थी कि स्वर्णमान जल्दी ही पुनः टूट गया। एक अन्तर्राष्ट्रीय मान का अभाव हो जाने से विनिमय-दरों में बड़ी अस्थिरता (instability) आ गई और अधिकांश देशों ने विनिमय नियन्त्रण (exchange control) की नीति ग्रहण कर ली।

(२) युद्धकालीन मुद्रा प्रसार—सगण्य सभी देशों की आर्थिक दशाएँ युद्धकालीन मुद्रा प्रसार के कारण बहुत बिगड़ गईं। अनेक देशों ने बहुत अधिक (excessive) मात्रा में नोटों का निर्गमन किया, जो कि अपरिवर्तनशील थे। इससे कीमतों में अपेक्षित वृद्धि हो गई। विभिन्न देशों में कीमत-स्तर बहुत असमान (unequal) हो गये तथा इसका विदेशी व्यापार पर बहुत कुप्रभाव हुआ। यहाँ तक कि आन्तरिक व्यापार भी अस्त-व्यस्त हो गया।

(३) देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा—प्रत्येक देश अन्य देशों के हितों की चिन्ता

न करते हूये एक स्वार्थपूर्ण आर्थिक नीति अपना रहा था। यदि कुछ देशों ने अपनी करंसी का अवमूल्यन करके अपने निर्यातों में वृद्धि करने का प्रयास किया, तो अन्य देश इसे अपने यहाँ आयात नियन्त्रण लगाकर असफल बनाने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार, मौद्रिक सहयोग के स्थान में बहु-प्रतियोगिता प्रचलित थी।

(४) द्वितीय महायुद्ध की शरारत में घन सम्पत्ति की अत्यधिक बर्बादी—द्वितीय महायुद्ध के समय में दशायें और भी बिगड़ गईं। युद्ध के अर्थ-प्रदमन के लिये विशाल मात्राओं में अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा निर्गमित (issue) की गई। इसके अतिरिक्त मानवीय घन व जायदाद की इतनी अधिक बर्बादी हुई थी कि सभी राष्ट्र यथ्यायोग पुनर्निर्माण और पुनर्वास के कार्यक्रम शुरू कर देने के लिये बहु-उत्सुक थे।

स्पष्टतः उक्त समस्याएँ किसी एक (single) देश के प्रयत्नों से ही सुलभता सम्भव न थी। समय की यह माँग थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक क्षेत्र में सब देश आपस में सहयोग करें। चूँकि स्वयंमान की पुनः स्थापना सम्भव नहीं थी, इसलिए इसके स्थान में किसी नई व्यवस्था का प्रचलन आवश्यक था। यह नई प्रणाली ऐसी होनी चाहिये थी जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के द्वारा पर्याप्त लोच प्रदान करे तथा साथ ही मौद्रिक अनुशासन के उन सिद्धान्तों का भी पालन करे, जिनके बिना कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य नहीं कर सकती है। इस हेतु विभिन्न राष्ट्रों ने विभिन्न योजनाएँ प्रस्तुत कीं। सन् १९४४ में ब्रैंटनवुड्स नामक स्थान पर एक सम्मेलन इन योजनाओं पर विचार करने हेतु बुलाया गया। इसमें ४४ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनके विचार विमर्श के परिणामस्वरूप दो अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्राग्रे स्थापित हुई—मुद्रा काप एवं विश्व बैंक।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I. M. F.) के उद्देश्य

जैसा कि मुद्रा कोष के नार्डर में बताया गया है, इसकी स्थापना निम्न उद्देश्यों से हुई है—(i) एक स्थायी मंस्था के माध्यम से, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं पर परामर्श व सहयोग के लिये उचित व्यवस्था करेगी, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार एवं सम्बन्धित विकास में सुविधा देना और इसके द्वारा रोजगार व वास्तविक आय के ऊँचे स्तर कायम रखना। (iii) विनिमय स्थायित्व तथा मुख्यस्थित विनिमय समझौते की बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धात्मक ह्रास (competitive depreciation) की रोकथाम करना। (iv) भुगतानों की एक बहुपक्षीय प्रणाली (multi-lateral system of payments) स्थापित करने में तथा इसके द्वारा विन्मयस्थ स्थिरता-विनिमय-प्रतिस्पर्धा की हटवाने में सहायता देना। (v) अन्तर्राष्ट्रीय कोषों में वृद्धि करके तथा विनिमय दरों के परिवर्तनों को मुख्यस्थित रूप में सम्भव बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय समायोजन के लिये मुद्रा मनुचन की अपेक्षा, एक अधिक श्रेष्ठ साधन प्रदान करना (vi) इन उद्देश्यों की पूर्ति करते हूये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में

सुविधा पहुँचाना तथा भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी असाम्यता (dis-equilibrium) की श्रद्धि में उग्रता को कम करना ।

मुद्रा कोष का सङ्गठन (Organisation of the Fund)

३० जून १९६६ को कोष के सदस्यों की संख्या १७४ थी । मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य के लिए इसकी राष्ट्रीय आय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति (Position) के आधार पर एक चन्दो-सम्यक् (subscription quota) नियत कर दिया जाता है । सदस्य देश अपने कोटे का २५% भाग स्वर्ण या डॉलर में और दोष भाग राष्ट्रीय करेंसी में, जो कि सम्यक् देश में ही कोष के नाम से रखी जाती है, देता है । सन् १९५६-६० में ५ बिलियन डॉलर की वृद्धि के बाद फण्ड के कुल प्रसाधन १६ बिलियन डॉलर हो गये । २५ सितम्बर सन् १९६५ से मुद्रा कोष की टोकियो बैठक के प्रस्तावानुसार कोष के अग्यक्षों में पुन २५% वृद्धि की गई है । और इसके फलस्वरूप कोष के वर्तमान प्रसाधन २१ बिलियन डॉलर हो गये हैं । १ जनवरी १९७० से चन्दो में फिर परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है । यह परिवर्तन अक्टूबर १९७० में लागू होगा । अब कोष की कुल पूँजी २५.६० बिलियन डॉलर हो जायेगी । भारत का बाँदा वर्तमान ७५ करोड़ से बढ़कर ८४ करोड़ डॉलर हो जायेगा । उसका स्थान चन्दो की दृष्टि से अभी तक पाँचवाँ था किन्तु अब छठवाँ रह जायेगा और इस प्रकार उसे संचालक-मण्डल में एक सदस्य नामजब करने का अधिकार नहीं रहेगा । फण्ड की सर्वोच्च सत्ता बोर्ड आफ गवर्नर्स है । इसमें अपने अनेक अधिकार बोर्ड आफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दिये हैं । मैनेजिंग डायरेक्टर कोष के स्टाफ का मुखिया और बोर्ड आफ एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का चैयरमैन भी होता है ।

कार्य प्रणाली (Mode of operation)

फण्ड के पास विभिन्न सदस्य देशों की करेंसियों और स्वर्ण के रूप में विशाल पूँजीगत प्रसाधन है । यह एक ऐसे ढङ्ग से कार्य करता है, जिसमें कि विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव न्यूनतम सीमा तक घट जायें तथा बहुपक्षीय व्यापार पद्धति की फरस स्थापना हो जाय । इसके कार्यवृत्तियों की प्रमुख विशेषतायें निम्न-लिखित हैं —

(१) स्वर्ण या डॉलर में करेंसियों के सम-मूल्य का निर्धारण—प्रत्येक सदस्य देश अपनी करेंसी का सम-मूल्य अमेरिकी डॉलर (इसकी तैल व शुद्धता वह होनी चाहिये जो कि जुलाई १९४४ को की थी अर्थात् ०.८८, ५८, ६७१ ग्राम स्वर्ण प्रति डॉलर) में या स्वर्ण में घोषित कर देता है । कोई देश चाहे तो अपनी करेंसी का सम-मूल्य पारित न भी करे (जैसे साइप्रस व अफगानिस्तान) । किन्तु अब एक बार विभिन्न

करैसिया के सम मूल्य निश्चित हो जाना है तब किसी दा दगा के मध्य विनिमय-दर मान्य करना सुगम हो जाता है ।

(२) सम मूल्य में परिवर्तन की अनुमति सुपरिभाषित सीमाओं तक—फण्ड क अन्तर्गत विनिमय-दर दलों कठोर (rigid) नहीं है जितना कि वे स्वयंमान के अधीन हुआ करती थी । किसी भी देश को नवनुसूचित सुपरिभाषित सीमाओं के भीतर ही अपनी वनियादी (basic) समता दर को बदलने की अनुमति दी जा सकता है । राश्वर्य देण १०% की सीमा तक तो स्वयं ही केवल अपना ऐसा इरादा मुद्रा कोष की सूचित करके परिवर्तन कर सकता है । यह परिवर्तन (१०% का सीमा तक) शीघ्र सम्पूर्ण या छोटा या बड़ा करके भी सम्भव है । परिवर्तन क प्रति मुद्रा कोष सामान्यतः विरोध नहीं करता । किन्तु प्रथम १०% से अधिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण देश को मुद्रा कोष की अनुमति नहीं पड़ती है अर्थात् यदि अनुमति प्राप्त न हो तो वह ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता । प्रथम १०% से अधिक परिवर्तन की अनुमति फण्ड द्वारा तब ही प्रदान की जाती है जबकि उस देश का सन्तोष हो जाय कि उपरान्त परिवर्तन प्रस्ताव करन देश के भुगतान संतुलन में उत्पन्न हुई किसी मौलिक असाम्यता के सुधार के लिए आवश्यक है । किन्तु मौलिक असाम्यता (Fundamental disequilibrium) क्या है फण्ड के चारों ओर इसकी परिभाषा तो नहीं की गई है । लेकिन इसका तो कहा ही जा सकता है कि प्रथम १०% से अधिक किसी परिवर्तन क प्रस्ताव को उचित ठहराने के लिए प्रस्तावक देश के भुगतान संतुलन की असाम्यता निरन्तर और गम्भीर घाट (continuing and serious deficit) के रूप में प्रकट होना चाहिए ।

यदि फण्ड की असाम्यता की गम्भीरता के बारे में सन्तोष हो जाय तो वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को प्रस्ताव करन जाने देश की आन्तरिक सामाजिक अथवा राजनैतिक नीतियों के आधार पर उत्सीकृत न कर सकेगा । यदि कोई देश फण्ड की सहमति के बिना अपनी करैसी के सम मूल्य में परिवर्तन करता है तो उसे कोष की सदस्यता सम्बन्धी लाभों से वंचित किया जा सकता है और अन्तिमन कोष की सदस्यता से निकाला भी जा सकता है । फण्ड चाहे तो अपनी ओर से भी मनी उद्यम देशों की वरसियों के सम मूल्यों में अनुपातिक परिवर्तन (proportionate changes) कर सकता है ।

(३) भुगतान संतुलन में अस्थायी असाम्यता के सुधार के लिए विदेशी मुद्रा के ऋण देना—फण्ड यह अनुभव करता है कि स्वतंत्र विश्व व्यापार के लिए विनिमय स्थायित्व की बड़ी आवश्यकता है । अनन्तकाल उद्देश्य देण के सम-मूल्य में उतार चढ़ावों को रोकना और इसके लिए भुगतान संतुलन की असाम्यता का सुधार करने में सहायता देना है । यदि किसी देश को घाट का सामना करना पड़ा है तो वह आवश्यक विदेशी मुद्रा उस देश को एक निश्चित विनिमय दर पर अर्पण । विदेशी मुद्रा वाले इस ऋण की सहायता से वह देश अपने विदेशी दायित्व चुकाने में

समय हो जाता है। इस प्रकार कोप कठिनाई के समय देशों को एक 'साँस लेने भर की मोहलत' (breathing space) प्रदान करता है, जिसमें वे अपनी असाम्यता का सुधार कर सकते हैं। किन्तु, यदि असाम्यता किसी ऐसे मौलिक कारण (जैसे—बरेखी के अधि मूल्यन या अत्यधिक उत्पादन लागत) से, जो कि देश की अर्थ-व्यवस्था में मरचनात्मक परिवर्तन (structural changes) करने आवश्यक बनादे, उत्पन्न हुई है, तो वह उस देश से यह प्रार्थना करेगा कि ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय। जब किसी साम्य की आन्तरिक वित्त नीति और विनिमय स्थानित्व को ठीक-ठाक रखने की नीति (जो कि कोप का एक प्रमुख सद्य है) के साथ मेल होता है, तो फण्ड मुख्यतः सम्भालने-बुझाने के टेक्नीक अपनाता है। हाँ जब कोई खदखद निरन्तर ही बिरोधी नीतियाँ अपनावे, तब फण्ड सम्बद्ध खदखद को अपने कोषों की सुविधाएँ देने में मना कर सकता है।

(४) विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष या आह्वरण करने का अधिकार—जबकि फण्ड एक देश को कर-सौ घेयता है तो वह इसे उसके मूल-देश (Country of origin) से अपना उस देश से जिसने अपने व्यापार द्वारा इसका आधिपत्य प्राप्त कर लिया है खरीदता है। कोई देश कितनी मात्रा में आवश्यक करेखी खरीद सकता है, इसकी न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों ही सीमाएँ निश्चित कर दी गई हैं। सद्यस्य देश मुद्रा कोप से किसी एक वर्ष में अपने कोटे के २५% तक कोई भी करेखी खरीद सकता है। कोप इस विषय में कोई बाँध जिये बिना ही तत्काल अपनी अनुमति दे देगा है। किन्तु सदस्य देश 'महमति छह्राव' (Waiver agreement) पर हस्ताक्षर करके किसी एक वर्ष में उक्त प्रतिशत से अधिक मात्रा में भी करेखी खरीद सकता है। लेकिन इसकी अनुमति तब ही मिलती है जबकि वह कोप को यह सम्योप दिला दे कि ऐसा बय आवश्यक है तथा उचित उद्देश्यों के लिए है। किसी भी बरा में कुल आह्वरण (कम) फण्ड में किसी देश के करेखी कोटे के २००% से अधिक नहीं हो सकता। व्यवहार में देश १५०% से अधिक आह्वरण नहीं करते हैं। क्योंकि अधिक उधार लेना या बय करने पर, श्रंता-बेध की आन्तरिक प्रयुक्त व मौद्रिक नीति में, कोप का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। यह स्मरणीय है कि क्रयाधिकार को सीमित करने का उद्देश्य देशों की वृहत मात्राओं में विदेशी मुद्रायें खरीदने से अप्रोत्साहित करना है। अब कोप विदेशी मुद्रा का कृण स्वीकृत कर देता है अथवा यो कहे कि प्रार्थी देश की एक निश्चित मात्रा में विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे देता है, तो यह सब आह्वरण एवं साथ (in one lump sum) किया जा सकता है अथवा छोटा छोटा (in instalments) भी कई बार में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

(५) अण के बचन (Stand by arrangements)—कभी-कभी एक सदस्य को ठीक से यह पता नहीं होता कि उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता कब पड़ेगी। ऐसी दशा में, दूरदर्शिता के विचार से वह फण्ड के पास अपना एक 'लेनी-पाता' बोल सकता है। यह 'लेनी साता' अवधि में, आवश्यकता के समय कोप

द्वारा ऋण देने के बचन के रूप में होता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बद्ध देश एवं निश्चित रकम एक वियत अवधि के भीतर ज़मी भी कोष से ऋण स्वरूप माँग सकता है। ऋण का बचन देने के पूर्व मुद्रा कोष सामान्यतः ऐसे सम्भावित ऋण के शोचित्र के बारे में सन्तोष प्राप्त करता है, जिससे वास्तविक ऋण देते समय जाँच पड़ताल करने में वृथा विलम्ब न हो।

(६) फण्ड के कोषों की तरसता—यदि देनदार देश अपनी निज की करौसी के बदले में मुद्रा कोष विदेशी मुद्रा खरीदते ही चले जायें, तो यह सम्भव है कि काप के पास ऐसी करैसियाँ, जिनकी विश्व-बाजार में कम माँग है, अधिक इकट्ठी हो जायें, तथा, ऐसी करैसियाँ जिनकी विश्व-बाजार में अधिक माँग है, घट जायें, यदि ऐसा हुआ, तो मुद्रा-कोष एवं सुरक्षित कोष (Reserve fund), अबदा यो कहे कि विनिन देशों की केन्द्रीय बैंकों के अन्तिम ऋणदाता के रूप में, कार्य न कर सकेगा। अतः यह बहुत आवश्यक है कि मुद्रा-कोष अपने प्रसाधनों की तरस दशा में बर्बाद रहे।

इस आशय के लिए—यह नियम रखा गया है कि ऋणी या क्रेता देशों की कोष में ली गई समस्त सास ३ वर्ष की अवधि के भीतर ही लौटानी पड़ेगी। ऋण की इन वापसियों (repayments) को टेक्निकल भाषा में 'पुनर्कय' (Re-purchases) कहा जाता है। ऋण की वापसियाँ के सम्बन्ध में एक 'स्वचालित पुनः कय वाक्य' (automatic repayments' clause) होता है, अर्थात्, किसी देश के मौद्रिक (स्वर्ण या विदेशी मुद्रा) कोष में जो वृद्धि हुई हो उसका आधा भाग अनिवार्यतः मुद्रा-कोष में अपनी आन्तरिक करैसी, जो कि विदेशी मुद्रा लेते सन्नय कोष की भी गई थी, वापस खरीदने में प्रयोग किया जायेगा।

लेकिन, जब मौद्रिक कोष में कोई वृद्धि न हो, या वृद्धि तो हुई है किन्तु वृद्धि होने पर भी मौद्रिक काप देश के कोटे (Quota) से कम हो, तो ऐसा पुनः कय न करना पड़ेगा। किन्तु यदि ऋण चुकाने की सम्पूर्ण अवधि में यह अपयोज्यता बनी रहे, तो सम्बद्ध देश के लिए वह अनिवार्य होगा कि ऋण की अवधि के अन्त में स्वर्ण लेकर अपनी वरैसी का पुनः कय करें। किन्तु ऐसे अनिवार्य कय का अक्सर कठिनाता न ही आता है, क्योंकि ऋणी देश प्रायः अन्य देशों या सदस्यों से ऋण लेकर, कोष में अपनी आन्तरिक करैसी का पुनः कय कर लिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जब नभी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी-स्थिति बहुत विषम हो जाती है, तो मुद्रा कोष स्वयं भी ऋण की अवधि बढ़ा देता है।

(७) अव्यवस्थित वास्ते करैसी—यह सम्भव है कि किसी देश की करैसी की पूर्ति कम (short supply) हो। विदेशी विनिमय बाजार में किसी देश की करैसी की अन्य पूर्ति भरोसे यह पता चलता है कि उसका भुगतान मनुष्य उसके अनुकूल चल रहा है अर्थात् उसके निर्यात आयातों की अपेक्षा अधिक है। जिन देश का भुगतान संतुलन अनुकूल रहता है वह विनिमय स्थायित्व में विधि उत्पन्न करते का इतना ही दोषी है जितना कि वह देश जिसके भुगतान संतुलन में घाटा रहा करता

है। अतः मुद्रा कोष अनुकूल स्थिति वाले देश से यह आशा करता है कि वह अपनी करेंसी का पुनर्पूर्वतन करके स्थिति को गंभीर देगा। वास्तव में, जैसे ही कोष किसी विदेश करेंसी को 'दुर्लभ' (scarce) घोषित करे, वैसे ही सम्बद्ध देश को चाहिए कि अपनी करेंसी का इस प्रकार से पुनर्पूर्वतन करे कि देश में लागते व कीमतें बढ़ जायें जिससे आयात बढ़ें और निर्यात घटे।

(६) फण्ड योजना में स्वर्ण का स्थान—फण्ड की योजना के अधीन प्रत्येक सदस्य देश को कोष में अपने कोटे के २५% तक या अपने स्वर्ण धारण (gold holdings) के १०% तक स्वर्ण में जमा करना पड़ता है। सदस्य देशों की करेंसियों के सम-मूल्य भी स्वर्ण में नियत किये जाते हैं। सम-मूल्य में परिवर्तन सुगमभाषित सीमाओं के अन्तर् में किये जा सकते हैं। यदि कोई विशेष करेंसी कम मात्रा में है, तो फण्ड इसे स्वर्ण लेकर खरीद सकता है।

(७) केन्द्रीय बैंकों का बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की विभिन्न देशों की केन्द्रीय बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के प्रसाधनों का समग्र समूह के रूप में करता है जिन प्रकार से कि एक देश का केन्द्रीय बैंक स्वदेश के समस्त व्यापारिक बैंकों के मदद काय एकत्र करता है।

(१०) सम्प्राप्ति काल में सुविधायें—फण्ड का उद्देश्य सभी विनिमय नियंत्रणों को हटाना है जिससे कि विश्व व्यापार का विकास हो सके। किन्तु कोष यह अनुभव करता है कि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तिकालीन अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तित करने में कुछ कठिनाई होगी। इस बीच सबसे बड़ा कोष द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति गई सीमा तक नियंत्रणों को जारी रख सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष योजना एवं स्वर्णमान

फण्ड की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देश को फण्ड के पास अपने कोटे (Quota) का २५% तक या अपने स्वर्ण-कोष का १०% तक स्वर्ण में जमा करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, सदस्य-देशों की करेंसियों के सममूल्य (Par-values) भी स्वर्णमान में व्यक्त किये जाते हैं। इनमें सुनिश्चित सीमाओं के भीतर ही कोई परिवर्तन करने की अनुमति दी जा सकती है। स्वर्ण का मूल्य फण्ड द्वारा ३५ डॉलर प्रति (विशुद्ध) औंस नियत किया गया है। यदि फण्ड के पास किसी विशेष करेंसी का अभाव हो, तो वह स्वर्ण के बदले में उस करेंसी का त्रय कर सकता है। इस प्रकार, फण्ड की योजना में स्वर्ण का एक पहलुपूर्ण स्थान है। इसी आधार पर प्रो० विलियम्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने फण्ड की योजना को एक अनिवार्य स्वर्णमान योजना (essentially a gold standard plan) घोषित किया है। दूसरी ओर, वीन्स जैसे अर्थशास्त्रियों ने फण्ड की योजना को 'स्वर्णमान का ठीक विपरीत' (the exact opposite of gold standard) बताया है। ये दोनों परस्पर विरोधी दृष्टि-कोण हैं। नीचे इन पर गंभीरता से विचार किया गया है।

“फण्ड-योजना अनिवार्य रूप से एक स्वर्णमान योजना है”—

कोप के साथ इनके मदस्य-देश जिम तरह में अपने सोदे करते हैं उसमें यह प्रतीत होता है कि स्वर्णमान और फण्ड-योजना एक दूसरे में बहुत सादृश्य रखती हैं। फण्ड की योजना के अन्तर्गत, भुगतान सन्तुलन में घाटा रखने वाले देश की स्थिति स्थण खोल वाले देश के समान तथा भुगतान सन्तुलन में आधिक्य रखने वाले देश की स्थिति 'स्वर्ण पाने वाले देश' के समान होती है। यह उत्संखतीय है कि सदस्य-देश कोप के साथ केवल अपने केन्द्रीय बैंक या खजाने के द्वारा ही व्यवहार कर सकते हैं। फण्ड को सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए समायोजन गृह का कार्य करना वाना नहीं माना जा सकता। अधिराज अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान, फण्ड के हस्तक्षेप बिना विदेशी विनिमय बाजार के द्वारा निबटा दिये जाते हैं। फण्ड के माध्यम में सदस्य-देश जो सोदे करते हैं वे एक असाधारण स्वभाव के होते हैं और इनकी तुलना में स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण या अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के आवागमन में भी जा सकती है। य सोदे भी बैंक कोपो को ठीक उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं जिस प्रकार में कि स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण के आवागमन करते हैं।

मान लीजिए कि भारत में डालरों का अम्पाई अभाव है। अतः रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया मुद्रा कोप से डालरों का भ्रय करना चाहता है। यदि फण्ड आवश्यक शक्ति में डालर बचने को तैयार हो जाय, तो रिजर्व बैंक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क में खुले हुए फण्ड के डालर खाते के विरुद्ध आहरण कर लेगा। इस मौके के फनस्वरूप फेडरल रिजर्व बैंक के पास फण्ड के डालर खाने में कमी आ जायेगी तथा भ्रय बिना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया में खुले हुए फण्ड खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया इस प्रकार से प्राप्त की गई डालर बैंकों को व्यापारिक बैंकों को बेचेगा, जो फिर इसे अपने ग्राहकों को बेचेंगे। इसमें व्यापारिक बैंकों के माग-दिपाजिट (demand deposits) घट जायेंगे। अतः केन्द्रीय बैंक के पास रखे हुए उनके कोपो में भी कमी आ जायेगी। इस प्रकार, उक्त सोदे का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विस्फीतिक प्रभाव (contractionist effect) पड़ता है। विलु अमेरिका में विपरीत प्रवृत्ति (trend) दिखाई देगी। भारत द्वारा खरीदे गये डालरों का प्रयोग अमेरिका से आयातों का भुगतान करने में किया जायेगा। इससे उस देश के व्यापारिक बैंकों के डिपॉजिट्स में कोप दोनों में वृद्धि हो जायेगी और इसलिए वे साख का विस्तार करने की नीति (expansionist policy) अपना रहेंगे।

“फण्ड योजना स्वर्णमान का ठीक विपरीत है”—

यद्यपि फण्ड की योजना में स्वर्ण एक ऐसे माध्यम के रूप में सामने आता है, जिसके द्वारा विभिन्न करारों परस्पर सम्बन्धित हो गई हैं तथापि वह कई महत्त्वपूर्ण बातों में पुराने स्वर्णमान से भिन्न है। प्रमुख निम्नलिखित हैं —

(१) फण्ड योजना में 'स्वर्ण' देशों की करौसी का उस प्रकार से आधार नहीं है जिस रूप से वह स्वर्णमान के अन्तर्गत होता था—करौसियों का स्वर्ण-मूल्य में कठोरतापूर्वक नियत (rigidly fixed) नहीं होता वरन् उसमें कुछ मुनिश्चित सीमाओं के भीतर परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्ण उत्पादन सम्बन्धी उत्तार-वृद्धावर्धन योजना के अन्तर्गत अपहृत्वपूर्ण हो गये हैं किन्तु जहाँ राष्ट्रीय करौसियों की स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा के साथ कठोरतापूर्वक सम्बद्ध रखा जाता था तब ऐसे उत्तार-वृद्धावर्धन बहुत महत्वपूर्ण होते थे। इस प्रकार फण्ड की योजना में स्वर्ण एक 'वुधमन्त्रित सेवक' (faithful servant) के रूप में कार्य करता है, 'तात्ताशाह स्वामी' (wayward master) के रूप में नहीं, जैसा कि वह स्वर्णमान के अधीन था।

(२) सचेत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रवन्ध—नई योजना के अन्तर्गत बाधक्य एव घाटे वाले दोनों ही प्रकार के देशों से फण्ड द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान मतुलन में साम्यता बनाये रखें। जब कोई देश ऐसी साम्यता बनाए रखने में असमर्थ हो जाय, तब कांप उसे अपनी विनिमय दरों में नियोजित (orderly) ढङ्ग से समायोजन करने का निर्देश करता है। किन्तु स्वर्णमान इन समस्याओं से मुक्त था। उसके अन्तर्गत सचेत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रवन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस प्रकार, फण्ड की योजना स्वर्णमान के निर्वाणवादी पहलू (laissez faire aspect) के विस्तृत विपरीत है।

(३) मुद्रा सङ्कुचन एक तर्क सत्य परिणाम नहीं है—स्वर्णमान के अन्तर्गत स्वर्ण खोने वाले देश के लिए यह एक तर्क सङ्गत परिणाम था कि वहाँ मुद्रा सङ्कुचन की स्थिति पैदा हो जाय, किन्तु कोष-खाजगी के अधीन 'धाटा रखने वाले' (deficit) सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें फण्ड के साथ सौदा करने के फल-स्वरूप, मुद्रा-सङ्कुचन सम्बन्धी फल भोगन हा पडें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रेसीडेंट का दृष्टिकोण—

यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रेसीडेंट जैकबसन (Jacobsson) के दृष्टिकोण का उल्लेख करना आवश्यक न होगा। उनके अनुसार, वर्तमान करौसी प्रणाली जिसका अनुगमन विद्वद के अनेक राष्ट्रो द्वारा किया जा रहा है, सन् १९२० और १९३० के स्वर्ण-विनिमय मान से सादृश्य रखती है। सन् १९६० के अन्त में मोन्ट्रियल गृह के देशों ने छोड़कर दोष देशों की केन्द्रीय बैंकों व सरकारों के कोष ६० बिलियन डालर थे, जिसमें से ३५ मि० डालर स्वर्ण में १०३ बिलियन डालर डालरों में और ७ बिलियन डालर स्टर्लिंग तथा ४ बिलियन डालर अन्य विभिन्न करौसियों में थे... जिस प्रणाली के अधीन अधिकतर देश अपने कोष अथवा स्वर्ण में और अथवा

रिजर्व करैसियों के रूप में रखते हैं, उसे स्वर्ण विनिमय मान का आधुनिक स्वरूप कहा जा सकता है।¹

मुद्रा कोप योजना की तुलनात्मक श्रेष्ठता—

मुद्रा कोप योजना निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से श्रेष्ठ है। स्वर्णमान को बुनियादी (basic) ठुबलना यह भी कि इसके कारण देश की आन्तरिक एवम् बाह्य मौद्रिक नीतियों में संघर्ष होने लगता था। विनिमय दरें स्वर्ण की अपरिवर्तनीय मानाओं से कठोरतापूर्वक सम्बद्ध होती थी। स्वर्ण के आगमन की समस्या का सामना करने वाले देश को मुद्रा प्रसार के प्रति और स्वर्ण के बहिर्गमन की समस्या का सामना करते वाले देश को मुद्रा संकुचन के प्रति घुटने टेकने पड़ते थे, तब ही साम्य पुन स्थापित हो पाता था। इस प्रकार आन्तरिक मौद्रिक नीति को बाह्य मौद्रिक नीति के अनुशासन में चलना पड़ता था।

किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की योजना के आधीन देश को अपनी करैसी का प्रसार या संकुचन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलतः उसकी अव्यवस्था समायोजन की कष्टजनक प्रक्रिया (painful process of adjustment) में बच जाती है। कोप योजना के अनुसार, विनिमय दरें कठोरतापूर्वक नियत नहीं होती हैं। उसमें समय और परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है। किन्तु यह अवश्य है कि कोई भी देश मनमाने ढंग से विनिमय दरों को परिवर्तित नहीं कर सकता। वह असीमित विनिमय नियन्त्रण भी नहीं लगा सकता। स्वर्णमान के टूटने के बाद विश्व के देशों ने पुनः पन मान अपना लिया। पनमान के अन्तर्गत करैसियों की परिवर्तनीयता सम्भव नहीं रह गई है। यही नहीं, विनिमय दरें बार-बार परिवर्तन करने तथा विनिमय नियन्त्रण अपनाने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अज्ञान-यत्नता उत्पन्न हो गई। किन्तु मुद्रा कोप ने विनिमय दरों में परिवर्तन करने के अधिकार को सुधारिभाषित सोमाओं तक सीमित करके, विनिमय नियन्त्रणों का निषेध करके तथा स्वर्ण के माध्यम से करैसियों की परिवर्तनीयता सम्भव बनाने पर स्वर्णमान के समस्त लाभ प्राप्त कर लिए हैं तथा पनमान की हानियों में बच गया।

वहूपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करने एवं विनिमय नियन्त्रण

हटवाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप की सफलता

मुद्रा कोप ने अपने कार्यकाल में सन् १९४५ से आरम्भ होने और १९६७ में

¹ 'The system under which most countries hold their reserves partly in gold and partly in reserve currencies is the present-day version of the gold exchange standard'—Jacobson President of the I M F.

इसने अपने सक्रिय जीवन के २२ वर्ष पूर्ण कर लिये। इस अवधि में इन्होंने जा कार्य किए हैं उनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है।

(१) उत्तरोत्तर उदार नीति अपनाता—कोष बहुत सावधानी से कार्य को चला रहा है। उसने ऋण सम्बन्धी कार्यकलापों में जोखिम को न्यूनतम रखने की नीति अपनाई। यह सावधानी का रस अप्रैल सन् १९५२ तक रहा। परिणामस्वरूप सन् १९५६ और सन् १९५७ के वर्ष उसने कार्य बहुत मन्द रहे। सन् १९५३ में उसने 'नग्न की शर्तें उदार बनाई और 'ऋण बचन व्यवस्थाओं' (Stand-by Arrangements) के आघोष विदेशी मुद्रा के ऋण अधिक उदारतापूर्वक दिए जाने लगे।¹ सन् १९५५ तक छ वर्षों अवधि कोष के लिए अन्य कार्य वाला समय था। इसने उसने केवल ५४२ मि० डॉलर के ऋण लिये।

(२) कार्यों का विस्तार और पूँजी में वृद्धि—सन् १९५६-५७ में मुद्रा-कोष के कार्यकलापों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अक्टूबर सन् १९५० में कोटा-वृद्धि द्वारा फण्ड के प्रसाधनों का विस्तार किया गया। कारण, जबकि पिछले दशक (सन् १९४०-१९५०) में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ठूला हो गया था, तब कोष के कोटे वही बने हुए थे, जिसने "सहमति वाक्य" (Waiver Clause) का प्रयोग बार-बार करना पड़ रहा था। अतः १५ मितम्बर सन् १९५६ के मध्य देशों के कोटे में ५०% स माध्य वृद्धि की गई। जापान, वनाडा और १० जर्मनी के लिए, शिनची विकास-मति लेज होने के कारण जापान अवस्था अच्छी हो गई थी, ५०% से भी अधिक वृद्धि की माग स्वीकृत हुई। सन् १९६५ फण्ड के कोटे २५% में गुन, बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अन्तर्गत फण्ड के अभ्यर्श (quotas) में जो सामान्य वृद्धि उस वर्ष लागू की गई उसके अनुसार सभी देशों के अभ्यर्श २५% बढ़ाये गये और १६ सदस्यों के अभ्यर्श अधिक अनुपात में बढ़ाने की अनुमति दी गई। ६० देशों ने ऐसी वृद्धियाँ स्वीकार कर ली हैं। अतः कोष की पूँजी १६ बि० डॉलर में बढ़ कर २१ बि० डॉलर हो गई। १९७० में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप कोष की कोटा पूँजी २० बि० डॉलर हो जायेगी। SDR की ३०० करोड़ डॉलर व्यवस्था अलग में है।

(३) परिवर्तनीयता के क्षेत्र का विस्तार होना—कोष के व्यवहारों में स्वीकृत कर नियमों के प्रयोग का क्षेत्र बराबर बड़ रहा है। फरवरी सन् १९६१ को १० सदस्यों (नेलरियम फ्रान्स जर्मनी, आयरलैण्ड, इटली लक्जमबर्ग, नीदरलैंड पाँच स्वीडन और ज़िटेन) ने अपनी कर संधि के लिए परिवर्तनीयता का दाखिल स्वीकार किया। औपचारिक परिवर्तनीयता का क्षेत्र बढ़ जाने में ऋणी-सदस्य अब

¹ मुद्रा-कोष सदस्यों को विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष रूप में बेचता है और माग की आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा देने के बचन भी करता है। मुद्रा बेचने के दखत भी अवधि प्रायः एक वर्ष की होती है किन्तु इसे समझौते द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।

अपने विदेशी मुद्रा वाले ऋण को पहले से अधिक देशों की करेंसियों में चुका सकते हैं। सन् १९६१ के पूर्व पुनः ऋण (Repayment or Repurchases) अधिकांशतः स्वयं या अमरीकी डॉलर में किये जाते थे, किन्तु सन् १९६२ में पुनः ऋण प्रथम बार कितनी ही करेंसियों में सम्मिलित हुए। ३० अप्रैल सन् १९६८ तक कोष के विदेशी मुद्रा ऋणों में डॉलर का भाग ६१.७% था, किन्तु सन् १९६४-६५ में यह १५% हो रह गया। १९६७ से फण्ड ने अपने लेन-देनों में पहले की अपेक्षा अधिक देशों की मुद्राओं का प्रयोग किया। यूरोपियन मुद्राओं, स्टर्लिंग और अमरीकी व स्नाइपन डॉलरों के विक्रय के अतिरिक्त उसने आस्ट्रेलिया, ब्राजील, आयरलैंड, मलेशिया, मक्सिमो, इ० अफ्रीका और बंनारुएला की मुद्राओं में भी रुचि ली। इसके फलस्वरूप कुछ करेंसियों के क्षेत्रों में ख़ासा स्तर में भी नीचे गिर गये। अब प्रायः सब करेंसियाँ जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतानों के अर्थ प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता था, परिवर्तनशील बन गई हैं। यह भुगतानों की दृष्टिसे व्यवस्था करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है।

(४) विदेशी मुद्राओं का ऋण-विक्रय—जब से कोष ने कार्य आरम्भ किया तब से ३० अप्रैल सन् १९६५ तक ५८ सदस्यों ने विदेशी मुद्राओं खरीदी, जिनमें से अनेक ने तो कई बार मुद्राएँ लीं। तीन अन्य सदस्यों ने कोष से ऋण-वचन-अनुबन्ध प्राप्त किये किन्तु कोष से वास्तविक ऋण नहीं किया। इस प्रकार लाभ उठाने वाले ६१ देशों में से २० देश लेटिन अमरीका, १४ यूरोप, ७ म० पू०, ८ सुदूरपूर्व, ६ अफ्रीका और ६ उत्तरी अमेरिका में थे। कोष द्वारा कुल ६३६.६ करोड़ डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा बेची गई। ४७ सदस्य देशों ने लगभग ५६०.३ करोड़ डॉलर मूल्य की अपनी मुद्राएँ चापस लीं। यह पुनः ऋण स्वयं और परिवर्तनशील मुद्राओं में किया गया। ३० अप्रैल सन् १९६५ को कुल बकाया राशि २७८.६ करोड़ रुपये थी। इसका अधिकांश भाग ३ वर्ष से अधिक पुराना नहीं था। केवल ३ ऋण ही ४६ मा ५ वर्ष पुराने थे।

१९६७ में प्रगति—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बकाया बाहरण (Drawing Outstanding) (बकाया बाहरण से आशय फण्ड के उन प्रसाधनों का है जो कि सदस्यों के खान्ने प्रयोग में हैं) १९६७ के अन्त में ४,४७८ मि० डॉलर, १९६६ के अन्त में ५,१११ मि० डॉलर, १९६५ के अन्त में ४,३५४ मि० और १९६४ के अन्त में २,६२१ मि० डॉलर थे। १९६७ में नवीन बाहरण ८३५ मि० डॉलर हुए किन्तु पुनः ऋण या पुनः भुगतान ६१८ मि० डॉलर थे। ऋण-वचन-व्यवस्थाओं (stand-by arrangements) के अधीन सदस्यों की उपलब्ध राशियों में तेजी से वृद्धि हुई और वे ३६५ मि० डॉलर से बढ़कर १७६४ मि० डॉलर तक पहुँच गईं। १.८ बि० की वृद्धि उस समय हुई जबकि ब्रिटेन ने ब्रिटिश पौंड का १४.३% जनमुत्खन कर दिया। उमने इतना ऋण हम हेतु माँगा जिससे कि उसकी मुद्रा में विश्वास पुनः जम सके। ब्रिटेन के बाद आयरलैंड, इसरायल, गायना, स्पेन, साइप्रस, मलायो, जम्बिया,

जमैका, ट्रिनिडाद, टोबागो, सियरा लियोनी, न्यूजीलैंड, लका, आइसलैंड, टेन्सांक, फिनलैंड और नैपान ने भी अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। इस बार के अवमूल्यन १९४६ के अवमूल्यन की अपेक्षा सीमित थे।

१९६७ में फण्ड के लेनदेन मुख्यतः विकासोन्मुख देशों के साथ हुए (अमेरिका या ब्रिटेन ने कोई अग्रहण नहीं किया और उनके बकाया आह्वरणों में भी कमी आई)। इस वर्ष के फण्ड से निम्न देशों ने ऋण लिए। अफ़ग़ानिस्तान, बर्मा, बुरुण्डी, नमिका, किली कोलम्बिया, कोस्टारिका, एत सल्वाडोर, फिनलैंड, घाना, ग्वाटेमाला, हैटी, आइसलैंड भारत, ईराक, लिबेरिया, माली, न्यूजीलैंड पोल, क्लिपीस, सियरा लियोनी, सोमाली, स्पेन, सूडान, सीरिया, थानिधिया, टर्की और यूगोस्लाविया। इनमें से अनेक देशों ने पहले भी फण्ड से ऋण लिये थे।

१९६७ के वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय द्रव्यता की कमी की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में कोप ने कुछ नई व्यवस्थाएँ की थी। यह व्यवस्था विशेष आह्वरण अधिकारी (Special Drawing Rights S. D. R.) के नाम से प्रसिद्ध हुई है। जल्दी ही इस व्यवस्था पर अमल होने लगा। फण्ड के प्रशासनिक व्यय १९६६-६७ में १८ मि० डालर हुए, जबकि आय ८६ मि० डालर हुई।

सन् १९६२ में कोप ने अपने कोप की अनुपूर्ति हेतु 'उधार सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था' (General Agreements to Borrow GAB) की थी जिसका प्रयोग १९६४ में ४०५ मि० और १९६२ में ५०५ मि० डालर तक किया गया। सन् १९६६ में १० औद्योगिक देशों की समूह में GAB का विधायन डालर थी, जो २४ अक्टूबर १९६९ से आगे चार वर्ष तक के लिये है।

कोप में अपनी अतिपूरक वित्त व्यवस्था नीति (Compensatory Finance Policy) को उद्धार बनाया है। यह नीति उन देशों द्वारा इसके प्रभावों के प्रयोग पर लागू होती है, जो कि अपनी विदेशी विनिमय सम्बन्धी कमाई के लिए प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों पर निर्भर है।

(५) विकासोन्मुख देशों की सहायता—विगत ५ वर्षों में विकासोन्मुख देशों के लिये, वर्ष के रूप में, कोप से आह्वरण की सम्भावनाओं में बहुत वृद्धि हो गई है। इसका कारण यह है कि अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में स्थिति देशों के कोटे (quotas) फण्ड में ऊँचे हो गये हैं और कोप से भी उद्धार नीति अपनायी है। विकासोन्मुख देशों के कुल कोटे १९६२ में २६ बि० डालर से बढ़कर १९६७ के अन्त में ४८ बि० डालर हो गये हैं। इसी अवधि में उनके बकाया आह्वरणों (outstanding drawings) में ४७६ मि० डालर की वृद्धि हो गई है। स्मरण रहे कि सदस्य-देश मुद्रा कोप में अपने कोटे के १२५% तक उधार ले सकते हैं। इस उधार लेन की क्षमता की (सभी देशों के लिये सम्मिलित रूप से) 'Gross Fund Positions' कहते हैं। ३१ दिसम्बर १९६७ की यह क्षमता ४,७१२ मि० डालर

तक पहुँच गई थी अर्थात् १९६२ की अपेक्षा दूनी हो गई थी। यह समता अब लगभग 'शून्य' (exhaust) गई है।

सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विकासोन्मुख देशों के वर्षों ने पिछले ५ वर्षों में अपनी Drawing Positions बढ़ा ली है जैसा कि निम्नांकित तालिका में स्पष्ट है —

(मि० डॉलर)

	१९६२	१९६८
वेटिन अमेरिकी देश	१०५५	१८८२
मध्यपूर्व के देश	२४४	६८६
एशियाई देश	८८५	१२८४
अफ्रीकी देश	१४१	८५७

मुद्रा-क्षेत्र के कार्यों की आलोचना

क्षेत्र के अब तक के कार्यक्षेत्रों से इसकी निम्न धूर्तताएँ प्रकाश में आई हैं —

(१) सब मुद्राओं का चुनाव उपयुक्त नहीं—विभिन्न दरें एक ऐसे समय में नियत की गई थी जबकि कैंसिया प्रायः अधिभूलित था। फलतः बाद का कई दशकों में इनके अवमूल्यन की आवश्यकता हुई।

(२) सख्त बौद्धान्तिक आधार पर निर्दिष्ट नहीं—बढ़ाया तो विभिन्न देशों का विदेशी व्यापार की मात्रा के आधार पर हो सकता था या व्यापारानेय की स्थिति के आधार पर और या विदेशी विनिमय की आवश्यकता के आधार पर परन्तु इनमें से किसी को भी आधार नहीं बनाया गया। ऐसा मान्य होना है कि अफ्रीकी और अमेरिकी के आर्थिक और राजनैतिक स्वाध्याय को ध्यान में रखकर बड़ा निर्धारित किया गया और इसी का परिणाम इस के व्यापार क्षेत्र के रूप में सामने आया।

(३) प्रगति से तोषजनक नहीं—कहा गया है कि क्षेत्र ने जो सहायता प्रदान की है वह बहुत ही अल्प है। अब संस्था को भंग कर देना चाहिए। [यह आलोचना क्षेत्र के प्रारम्भिक वर्षों के कार्यक्षेत्रों की प्रगति पर आधारित प्रतीत होती है। सन् १९५६, १९६५, १९७० और १९७१ में सावकों की बढ़ती लेन के बाद क्षेत्र द्वारा दी गई सहायता निरन्तर बढ़ती जा रही है।]

(४) सुविधाओं के देने में भेदभाव—कहा गया है कि मुद्रा क्षेत्र ने श्रद्धा प्रायः अमेरिका ब्रिटन और अन्य धनी राष्ट्रों के ही समर्थकों को दिये। [किन्तु अब इस आलोचना में अधिक सार नहीं है क्योंकि क्षेत्र में अविकसित देशों का बहुमत हो गया है जिससे उनकी अवहेलना करना सुगम नहीं।]

(५) **कार्यकारिणी की दोषपूर्ण सदस्यता**—मुद्रा-बोप की कार्यकारिणी की सदस्यता इस प्रकार रखी गई कि अमरीकन हितों की रक्षा होती रहे, इसीलिए लेटिन अमरीका के देशों के लिये दो स्थान सुरक्षित रखे गये ।

(६) **डालर की अल्पता**—स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को डालर की बहुत कल्पता अनुभव हो रही थी । किन्तु फिर भी फण्ड उसे "अल्प-मुद्रा" (Scarce currency) घोषित न कर सका । फलतः अनेक देशों को अमेरिका से डालर की प्राप्ति के लिए सीधे समझौते करने पड़े । [अब रिजर्व करैसियों की स्थिति सुधारने हेतु एक नया मुद्रा-बोप स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है ।]

(७) **साल्म घोषणा की अवहेलना**—बोप पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इसने देशों का इनको साल्म-अमता का विचार किये बिना ही त्रय-अधिकार (purchasing rights) स्वीकार किये । [यह आलोचना भी अनुचित है क्योंकि इसमें फण्ड के उद्देश्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है ।]

(८) **प्रसाधनों का अभाव**—इन देशों के लिए एक उचित समाधान यह है कि इन्हे दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रीय ऋण देकर रोजगार एवं अन्य में वृद्धि की गम । परन्तु बोप के पात्र ग्राहकों का अभाव रहा है । [अब दो बार कोटा वृद्धि द्वारा इस अभाव को दूर कर लिया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि देश विशेषतः अविकसित देश बोप से किसी वर्ष में अपने कोटों की सम्पूर्ण राशि तक (न कि केवल २५% तक) ऋण ले सकता है ।]

(९) **बानी समस्या**—मुद्रा बोप की आलोचना इसे एक बानी मस्या कह कर भी की गई है जिसमें अधिनाश घन विकसित राष्ट्रों ने लपाया है और जिससे कुछ देश अपनी आर्थिक उन्नति हेतु पर्याप्त यत्न किये बिना लगातार उधार लेकर कार्य करता रहे है । इस प्रकार बोप मुस्ती को उत्साहित करता है । [अन्य आलोचनाओं की भांति यह आलोचना भी अनुचित है, क्योंकि न केवल अल्प विकसित राष्ट्र वरन् अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों ने भी विगत कुछ वर्षों में भारी ऋण लिये । राय तो यह है कि बोप उन सभी देशों को ऋण देता है, जिनकी युगतानुता सकटग्रस्त हैं ।]

मुद्रा-बोप की सफलताएं

मुद्रा-बोप की स्थापना का उद्देश्य विश्व के देशों को सांघिक और अस्थायी आर्थिक कठिनाइयों से मुक्त करना, उनके आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना एवं पूर्ण रोजगार उत्पन्न करना था । निम्न-देत में लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए है किन्तु उचित दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई है, जिसका अनुमान निम्नलिखित विवरण से लगाया जा सकता है .—

(१) **विनिमय दरों का स्थायित्व**—बोप की एक प्रमुख समस्या विश्व राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धी मुद्रा-अवमूल्यनों की रोकने की थी । इस हेतु यह आवश्यक समझा जा सकता है .—

गया कि सभी देशों की मुद्राओं की समता दर निर्धारित की जाये। उनमें अधिकांश अच्छी आर्थिक स्थिति के देशों की समता दरें, तो वृद्धि निर्धारित कर दी और देश के सम्बन्ध में निम्न किया कि इन्हें 'घोरे-घोरे स्थिति' सुधारने पर निर्धारित किया जाय। सन् १९४६ में ३२ देशों की समता-दरें निर्धारित हुईं और ३० जून सन् १९६६ तक १०० सदस्य देशों में से १०४ की समता-दरें निर्धारित हो गयी थी। जिन १६ देशों की समता-दरें निर्धारित नहीं हुईं उनमें कुछ तो नये सदस्य देश थे और कुछ आर्थिक दृष्टि में बहुत गरीब थे।

आवश्यकता पड़ने पर कोष ने समता-दर में परिवर्तन करने की अनुमति दी है। उदाहरणार्थ, सन् १९४७ के अन्त में फ्रांस ने अपनी मुद्रा का समतल १०० अन्तर्गत न करने की अनुमति मांगी। साथ में यह भी बताया कि वह कुछ देशों के साथ उच्छानुसार अलग-अलग दर व्यवस्थाएँ। बहुत सोच-विचार के बाद मुद्रा-कोष ने फ्रांस के अवसूचन की अनुमति तो दी किन्तु बहुमुखी विनिमय दर के सिधे बना दिया। फ्रांस ने कोष की अवहेलना करते हुए फ्राँक का अवसूचन किया और बहुमुखी विनिमय दर अपनाई। यह कोष के लिए प्रथम परीक्षा-पत्र था। श्रीआर्य से फ्रांस ने सन् १९४८ में ही केवल एक ही समता दर की व्यापारिक कार्या का आभार दर्शाने की घोषणा कर दी, जिससे बहुत उत्तर्कित हुई। कोष ने फ्रांस की नई स्थिति को स्वीकार कर लिया।

नवम्बर सन् १९४६ में इंग्लैंड समेत २८ देशों ने मुद्राओं का अवसूचन कर दिया, जिसे कोष की स्वीकृति प्राप्त थी। यह सामूहिक अवसूचन इन देशों के आर्थिक हितों के अनुकूल थे। इसके बाद समता-दरों में यथेष्ट स्थिरता आ गई। बेरिया, इजिप्त, अरब देशों के बाद में भी समता दरें अक्षिप्त नहीं रही यही नहीं इन देशों ने भी (जैसे—कनाडा आदि), जो बहुत समय से अपनी मुद्राओं के सम-सूच्य घोषित नहीं कर रहे थे, अपनी स्थिति निश्चित कर दी। १९६६ में भारत ने अपने रुपये का और १९६७ में इंग्लैंड ने पाउण्ड का पुनः अवसूचन किया, जिसका उद्देश्य मुद्रातान्तरण सम्बन्धी विघटनता हुई स्थिति पर काबू करना था। इस प्रकार कुल पर, कोष के मार्ग दर्शन में विश्व से सभी देश अनुशासन बंध बनने की प्रेरित हुये हैं। सन् १९४६ से १९६६ तक के बहुमुखी दरें अपनाई हुई हैं। क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से विपन्न हैं, इसलिये अस्थाई रूप से ऐसा करने की छूट देना उचित ही है।

(२) भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था—मुद्रा-कोष की स्थापना के समय प्रायः सभी देशों के विदेशी विनिमय कोष घट गये थे और इस कारण उन्होंने विनिमय-नियन्त्रण लगाने हुए थे तथा विदेशी व्यापार कम हो गया था। इस स्थिति से निबटने के सिधे मुद्रा-कोष ने विदेशी मुद्रा के ऋण देने की नीति अपनाई। १९४६ से १९५८ तक कोष ने पश्चिमी यूरोपीय देशों की लगभग ११६ करोड़ डॉलर की विदेशी मुद्रा की सहायता दी। सन् १९५८ में वोटें बंटते जान से कोष के प्रभावों में वृद्धि हो गई तथा वह अधिक उदारवादी ऋण देने में समर्थ हुआ। इसका एक लाभ तो यह

हुआ कि कुछ पाने वाले देशों की विदेशी विनिमय सम्बन्धी दशा मजबूत हुई और दूसरे उन्हें अधिक सहायता मिलने का आरोप हा गया। इसी से सन् १९५८ में १४ प० यूरोपीय देशों ने अपनी मुद्रा के समस्त विदेशी कोषों को परिवर्तनशील घोषित कर दिया। अन्य शब्दों में, अन्य देशों के पास इन देशों की मुद्राओं के जो भण्डार थे या होंगे, उनके बदले में मुद्रा-कोष द्वारा निश्चित दर पर कोई भी मुद्रा खरीदी जा सकती है। यह घोषणा भुगतान की बहुमुखी व्यवस्था स्थापित करने की राह में एक महत्वपूर्ण मोड़ान थी। शीघ्र ही स्टर्लिंग क्षेत्र के १५ देशों ने अपने विनिमय नियन्त्रण छोले किए। इस प्रकार, बहुमुखी भुगतान व्यवस्था स्थापित करने में पर्याप्त सफलता मिली है और फलस्वरूप विदेशी पूँजी के विनिमय में बहुत वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार भी बढ़ने की अपेक्षा लगभग दुना हो गया है।

(१) स्वर्ण नीति—मुद्रा-कोष का स्थापना से विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मान स्थापित हो गया है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य देश की मुद्रा का मूल्य डालर में और डालर का मूल्य स्वर्ण में निश्चित है। अमेरिका की सरकार ने १ औंस स्वर्ण = ३५ डालर के तुल्य माना है। सदस्य-देश इस दर से अधिक पर स्वर्ण न तो खरीद सकते और न बेच ही सकते हैं। किन्तु उत्तर अमेरिकियों ने विषम स्थिति पैदा कर दी है। इनके कारण देश की सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि होती है। मुद्रा कोष ने बार-बार देशों से आग्रह किया है कि वे अनाधिकृत रूप से ऊँची दर पर होने वाले स्वर्ण के क्रय-विक्रय को रोकें तथा स्वर्ण को निजी हाथों में न जाने दें, वरन् अप्रिभूत शोषों में रखें जिसमें वह विविध दर के निजी हाथों में काम ला सकें। कंप ने सन् १९५२ से एक स्वर्ण क्रय-विक्रय सेवा (Gold Transactions Service) भी आरम्भ की। इसका उद्देश्य यह है कि देश कोष के माध्यम से सोने का क्रय-विक्रय कर सकते हैं, जिसके लिये कोष केवल १/३२% शुल्क लेता है। इस सुविधा के फलस्वरूप देशों को माल खरीदना बेचना सुगम हो गया है।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय द्रवना—सन् १९६३ से एथीवर्गटिव कापरेन्टरी ने अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता के प्रश्न पर बहुत ध्यान देना आरम्भ कर दिया है। GAB में भाग लेने वाले १० औद्योगिक देश समूह ने भी इस विषय में खामान्तर अध्ययन कराये हैं। सितम्बर १९६७ में मुद्रा कोष के गवर्नरों के वार्षिक सम्मेलन में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स (Special Drawing Rights या SDR) रखा गया है। ये एक बैंक के चेकों की भाँति होंगे। अन्तर केवल यह होगा कि इनके पीछे किसी धरोहर के रखने की आवश्यकता न होगी। १ जनवरी १९७० से सदस्यों को ३५० करोड़ डालर का अधिकार दिया गया है। १९७१ व १९७० में ६५० करोड़ डालर की दो किश्तें और भी आवीगी।

१९६८ में विकासोन्मुख देशों को मदद—

सन् १९६८ में मुद्रा कोष के लिये कार्यकर्ताओं की दृष्टि से एक रिकार्ड वर्ष

था। इस वर्ष विकासोन्मुख देशों ने कोष के प्रभावों का पहने की अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में कोष के साधनों का लाभ उठाया। विगत १० वर्षों में इन देशों के छोटे जिन अनुपात में बढ़े, उस अनुपात में इनके (सामूहिक स्तर में) कुल आहारण नहीं बढ़े। अफ्रीका, एशिया, लेटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में ८७ सदस्य देशों के शुद्ध आहारण १९६७ में १६७० मि० डालर में बढ़कर १९६८ में १७४६ मि० डालर हो गये जबकि आहारण में ७६ मि० डालर की वृद्धि हुई जबकि समस्त १११ सदस्यों के शुद्ध आहारण ६०० मि० डालर से बढ़े अर्थात् ८,४८४ मि० डालर से बढ़कर ५,१८६ मि० डालर हो गए।

मुद्रा कोषों द्वारा प्रकाशित सूचना से पता चलता है कि १९५८ से विकासोन्मुख देशों के शुद्ध आहारण धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। यह १९५८ में ६५० मि०, १९६० में ७४० मि०, १९६२ में १२०० मि०, १९६४ में १२६२ मि० और १९६६ में १४२६ मि० डालर थे। इस प्रकार १९५८-६८ की मध्यावधि में विकासोन्मुख देशों के शुद्ध आहारण ११ मि० डालर से बढ़े अर्थात् १७०% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, इसी अवधि में उनके लक्ष्य २४०% बढ़े। इनके छोटे से शुद्ध आहारणों का अनुपात १९५८ में ४४% था, जो १९६६ में ३४२, १९६४ में ३४५ और १९६८ में ३४८% था।

कोष की 'निर्यात-सूचना के प्रभावों की दूर करने हेतु क्षतिपूर्क वित्त व्यवस्था' के अधीन विकासोन्मुख देशों ने १९६८ में ६०.३५ मि० डालर लिये। जबकि १९६७ में १९५८ मि० डालर लिये थे।

कोष कम से कुछ ऋणता १९६८ में एशियाई और लेटिन अमेरिका के देशों के लिये कुछ घटी किन्तु अफ्रीकी देशों के लिये बढ़ी —

(मि० डालर)

	१९६८ के अन्त में	१९६७ के अन्त में
लेटिन अमेरिका के देश	५१७ ८	५२० ३
एशियाई देश	८६६ ४	६८४ ७
अफ्रीकी देश	३७० १	३१७ २

कोष के साथ विकासोन्मुख देशों के ऋण बंधन अनुवन्ध १९६८ के अन्त में ७४०.१ मि० डालर के हुये (जिसमें से ३३६ ३ मि० डालर उपयुक्त रहे) जबकि १९६७ के अन्त में ५४२ ८ डालर के थे, जिसमें से ३७६ ६ मि० डालर उपलब्ध थे।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

सदस्य बनने का निर्णय ऐतिहासिक—

भारत उन देशों में से है जिन्होंने सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। सन् १९४४ में हुए ब्रिटेन वुट्टन सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था। अक्टूबर १९४६ में भारत इस कोष का सदस्य बना। उसके सदस्य बनने

से पूर्व यह प्रश्न अत्यन्त विवाद-ग्रस्त रहा कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना भारत के हित में होगा ? अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बनने के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिये गये —

(१) भारत की भविष्य में व्यापार मन्तुलन की किमी स्थिति परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, अतः उसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनना आवश्यक नहीं है । (विरोधियों का यह तर्क इस बात पर आधारित था कि उस समय देश ने लगातार कई वर्षों तक अनुकूल व्यापार की स्थिति का ही सामना किया था, जिसके फलस्वरूप हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टर्लिंग बावने एकत्र हो गए ।)

(२) इसके प्रमुख सदस्य मुख्यतः कुछ सैनिक गुटों के सदस्य थे । अतः इन कोष से सहायता केवल उन्हीं देशों को मिलेगी जो इन सैनिक गुटों के सदस्य होंगे ।

(३) कि अब तक ब्रिटेन अपना स्टर्लिंग पायना नहीं चुका देता, भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनना चाहिए । (यह तर्क ठीक नहीं था, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल ब्रिटेन के द्वारा बनाई गई सस्था नहीं थी ।)

(४) मुद्रा कोष केवल सम्पन्न देशों का ही महापना देश । तत्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कथन अनुचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि तब विश्व के अधिकतर अविश्वसित देश परतन्त्र थे और यूरोप के तथा अन्य कुछ सम्पन्न देश ही इस कोष का सदस्य बनने की क्षमता थे । (परन्तु आज स्थिति सर्वथा विपरीत है । अब तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकतर सदस्य अविश्वसित और हाल में स्वतन्त्रता प्राप्त देश हैं ।)

विरोधियों के बावजूद भी अपने दीर्घकालीन हितों की रक्षा करते हुए भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने का निर्णय किया ।

स्टर्लिंग की बासता से मुक्ति—

सदस्य बनने के कुछ समय ही पश्चात् १८ दिसम्बर १९४६ को भारत ने अपने रुपये की विनिमय दर निश्चित की और १८ दिसम्बर १९४६ से १ रुपया = ०.२६८-६०१ ग्रैन सेना माना जाने लगा । स्वर्ण मरुपये का यह मूल्य तब किये जाने के बाद ॥ १ रुपया = १ लिब्र ६ पैस हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने १ पाउण्ड = २५.५१३४ ग्रैन स्वर्ण घोषित किया था । भारत का मुद्रामान अब स्टर्लिंग विविध मान नहीं रह गया अपितु स्वर्ण समता मान हो गया । कोष का सदस्य बन जाने के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धाराओं ४० और ४१ समाप्त कर दी गई । इनके अनुसार बैंक के नियम अनिवार्य था कि वह रुपये को स्टर्लिंग की रूप में बदलेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने का तात्पर्य यह होता है कि देश समस्त अन्तिम विदेशी विनिमय अपने ही पास रखे और आवश्यकतानुसार व्यय करे । इस तरह भारत के निचे स्टर्लिंग क्षेत्र की सदस्यता त्यागना आवश्यक था । परन्तु भारत में विदेशी मुद्रा बाजार न तो उस समय ही इतना विकसित था और न आज है कि

हम अपने देश में ही आवश्यकतानुसार हर देश की मुद्रा प्राप्त कर सकें। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद स्टलिन क्षेत्र जैसे मुद्रा क्षेत्र का बना रहना और मुद्रा कोष के सदस्यों का इस क्षेत्र का भी सदस्य होना परस्पर विरोधी बातें हैं, तथापि विश्व की आर्थिक परिस्थितियों की देखने हुए इस क्षेत्र का क्षेत्र द्वारा विरोध नहीं किया गया है। केवल स्टलिन क्षेत्र ही नहीं अपितु पिछले कुछ वर्षों में बनेर मुद्रा सभों का उदय हुआ है। इन मुद्रा बाजारों एवं सभों की विश्व मुद्रा कोष में यदि प्रत्यक्ष नहीं तो विरोध न कर ही विश्व के आर्थिक विकास का स्वाभाविक अंग मान लिया है।

बिनिमय नियन्त्रण के लिए समुचित छूट—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होने के नाते भारत के लिये यह भी आवश्यक था कि वह विदेशी विनिमय का नियन्त्रण पर से नियन्त्रण हटा ले। इसका तात्पर्य यह है कि देश के तथा विदेश के लोगों को यह अधिकार प्राप्त हो जाए कि वे बिना किसी बाधा अथवा निषेध के विदेशी तथा भारतीय मुद्रा का त्रय विनिमय कर सकें। परन्तु इस प्रकार का नियन्त्रण तुरन्त हटाना तो उस समय सम्भव था और न ही अनिवार्य। अन्य मुद्रा कोष ने इस बात को मान लिया था कि जिन देशों में विदेशी विनिमय नियन्त्रण है वे धीरे-धीरे अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार बिनिमय नियन्त्रण को मिथिल करेंगे और अन्त में बिल्कुल समाप्त कर देंगे।

विश्व बैंक की सदस्यता का लाभ—

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने के कारण ही भारत विश्व बैंक का सदस्य बन सका है। इस देश की आर्थिक उन्नति के लिये विश्व बैंक प्रूप में जो सहायता की है उसमें सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। विश्व बैंक ने भारत को न केवल स्वयं दीर्घकालीन आर्थिक सहायता प्रदान की है अपितु अन्य देशों की इसके लिये उत्साहित किया है।

सोवियत राष्ट्र तथा अन्य पूर्वी यूरोप के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने से इनकार कर दिया जिसके फलस्वरूप भारत सबसे अधिक नन्दा देने वाले ५ देशों में गिना गया और इस प्रकार कोष की संचालक मण्डली का स्थायी सदस्य बन गया। भारत की मुद्रा कोष में प्राप्त सहायता का विवरण इस प्रकार है—

(१) १९४७-४८ में अर्थात् मुद्रा कोष के कार्य आरम्भ करने के दूसरे वर्ष से ही भारत ने इस कोष में २८० लाख डॉलर के बराबर विदेशी विनिमय ऋण स्वरूप प्राप्त किया। इतना अधिक ऋण लेने का यह तात्पर्य हुआ कि मुद्रा कोष ने भारतीय मुद्रा की पूति अपने कोटा के २५ प्रतिशत में भी अधिक होगई, जिस कारण भारत की अधिक व्याज दर कोष को बेनी पड़ी।

(२) १९४९ में भारत ने भी अन्य अनेक देशों की भाँति स्टॉकिंग के साथ अपने सिकके का अवमूल्यन किया। इस अवमूल्यन के लिए भारत को मुद्रा कोष में अनुमति भी मिल गई क्योंकि ' भारत तथा अन्य देशों के मौद्रिक तथा व्यापारिक

सम्बन्ध ब्रिटेन से इतने अधिक घनिष्ठ है कि इनकी मुद्राओं का स्टर्लिंग के साथ अवमूल्यन करना आवश्यक था।”

(३) १९४८-४९ तक भारत ने कोप से ७१९ लाख डॉलर की सहायता प्राप्त की और १९४९-५० में यह राशि १० करोड़ डॉलर हो गई। १९५३ में भारत के व्यापार सन्तुलन में सुधार हुआ और इस सुधार से भारत ने मुद्रा कोप से ३६० लाख डॉलर के बराबर अपनी मुद्रा का पुनः नया कर लिया।

(४) प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं छाटो-सी योजना भी और इसके अतिरिक्त योजना के आरम्भ में स्टर्लिंग पावने के रूप में देश के पास विदेशी विनिमय का पर्याप्त पश्चित कोप था। इन दो कारणों से भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुद्रा कोप में विशेष सहायता नहीं लेनी पड़ी। किन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना साल के १९५७ में जब भारत कई वर्षों तक लगातार विदेशी व्यापार में भारी असन्तुलन की स्थिति का सामना कर चुका था, मुद्रा कोप से भारत को १२० करोड़ डॉलर के बराबर विदेशी सहायता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कोप ने भारत को ७२ करोड़ डॉलर के काप में से कभी भी मुद्रा विकास के लिए अनुमति दी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ही भारत ने मुद्रा कोप से १२६ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त की। १९६२ में पुनः भारत ने २९ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त की। १९६३ में इस ऋण में से, भारत ने अपने विदेशी भुगतान की स्थिति में सुधार के कारण मुद्रा कोप को २०० करोड़ डॉलर बढ़ा कर दिये। १९६४ में देश की भुगतान स्थिति अधिक बिगड़ी, जिसका कारण यह था कि दस वर्षों भारतवर्ष को पहले के लिए विदेशी ऋणों की बढ़ा करना पड़ा। इस तरह देश के समस्त विदेशी-विनिमय सङ्कट पुनः आ पड़ा। देश को बार-बार विदेशी-विनिमय के संकट का सामना करने का एक कारण, जिसे मुद्रा कोप ने भी स्वीकार किया है, यह है कि भारत को दूसरे विकासशील देशों के अनुपात में बहुत कम विदेशी सहायता प्राप्त होती है। योजना के अन्तिम वर्ष में पाकिस्तान से युद्ध, सूखा तथा विदेशी सहायता एकाएक बन्द हो जाने के कारण भारत को मुद्रा कोप से पुनः १८७ करोड़ डॉलर के बराबर सहायता प्राप्त हुई।

(५) भारत ने अपनी व्यापार तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति में पूर्णतः पुनर्स्थापना करने के लिए जून १९६६ में अपने सिक्के का अवमूल्यन किया। इस अवमूल्यन की मुद्रा कोप ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था में दीर्घकालीन परिवर्तन की सजा दी।

(६) मुद्रा कोप के दिक्कतों को औपचारिक ढंग से आज तक सहायता प्राप्त की है, भारत ने उनमें से सबसे अधिक राशि (३१ मार्च १९६९ तक ८१७.५० करोड़ ₹०) सहायता के रूप में प्राप्त की है। (इसमें से ५३८.५० करोड़ ₹० लौटा भी दिया गया है। जब-जब भारत ने विदेशी विनिमय के सङ्कट का सामना किया है, इन मुद्रा-कोप में पर्याप्त सहायता मिली है।

(७) आर्थिक नीति निर्धारण में भी मुद्रा कोष ने हमारा-मिश्र प्रदर्शन किया है। मन् १९४२ में मुद्रा कोष ने भारत के आग्रह पर एक आर्थिक मिशन भारत भेजा था जिसने देश की आर्थिक उन्नति के मूल मन्त्र के रूप में यह सुझाव दिया कि देश की आर्थिक उन्नति आन्तरिक मूल्य की स्थिरता के माध्यम से होनी चाहिए। प्रथम पंच-वर्षीय योजना की मुद्रा कोष ने अच्छा प्रमाण पत्र दिया था और स्वीकार किया था कि देश की आर्थिक उन्नति मूल्य स्थिरता के माध्यम से होनी चाहिए। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मुद्रा कोष ने खुले आम कोई मत व्यक्त नहीं किया, परन्तु काप के विभिन्न प्रकाशनों तथा कोष के मैनेजिंग डायरेक्टर (श्री स्वाइनर) द्वारा अक्टूबर १९६४ में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिए गए भाषण से यह प्रतीत होता है कि मुद्राकोष भारत की आर्थिक प्रगति में सन्तुष्ट होने हुए भी देश की मूल्य-स्थिरता से पूर्णरूप से सन्तुष्ट नहीं है।

मनुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा फ्रांस को उनके जाड़े के अनुसार सामूहिक रूप में इतने मत देने का अधिकार है कि वे कोष के हर महत्वपूर्ण कार्य के निर्णय में अपना बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भारत प्रथम ५ सर्वेस एग्रीज कीटा वाले देशों में होने हुए भी मुद्रा कोष की नीति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाल सकता क्योंकि भारत न तो किसी गुट का सदस्य है और न ही किसी ग्रेड में शामिल होकर ही बहुमत प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा कोष का मुख्य कार्यालय मनुक्त राज्य अमेरिका में होने के कारण मुद्रा कोष के अधीनस्थ हमकारी अधिकतर अमेरिकन हैं। कोष के उच्च पदस्थ कर्मचारियों में से केवल एक भारतीय है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सदस्यों में नियमित वित्तिय ढहरावों और विविध स्थायित्व को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या व्यवस्था की है ? क्या इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाने हेतु कोई सुधार अपेक्षित हैं ?

[Discuss the mechanism adopted by the International Monetary Fund for promoting exchange stability and orderly exchange agreements among members. Are any changes envisaged to make it more effective ?]

(इनाहा० एम० कॉम० १९६९)

२. कैसे और किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्यों का स्वर्गमान के लाभ उपलब्ध कराता है ?

[How and to what extent does the I M F function to secure for its members the advantages of the Gold Standard ?]

- ३ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सफलताओं का मूल्यांकन करिये और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भूमिका को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव दीजिये ।

[Assess the achievements of the International Monetary Fund and suggest measures to make it more contributive to international trade] (इलाहा० एम० कॉम० १९६७)

- ४ अ० मु० कोष के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं ? यह सदस्य देशों की क्या सहायता करता है ?

[What are the main objectives of the I M F ? How does the Fund assist the member countries ?]

(विक्रम एम० ए०, १९६६)

- ५ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों को बताइये । इनमें दुर्लभ करेंसियों की और विनिमय-स्थायित्व की समस्या का निवारण किस तरह किया है ?

[State the purposes of the International Monetary Fund How has it dealt with the problem of scarce currencies and with that of exchange stability ?]

- ६ चालू व्यवहारों के सम्बन्ध में भुगतानों की एक बहुमुखी व्यवस्था के स्थापित करने तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटवाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सीमा तक सहायक हुआ है ?

[How far has the IMF helped the establishment of a multi-lateral system of payments in respect of current transactions and the elimination of foreign exchange restrictions ?]

- ७ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग के क्षेत्र में जो भूमिका निभाई है उसका विवेचन कीजिये ।

[Discuss the role of I M F in the field of International Monetary Cooperation] (विक्रम, एम० ए० १९६६)

- ८ अ० मु० कोष की सदस्यता से भारत को क्या लाभ हुये हैं ?

[Assess the beneficial effects enjoyed by India in her membership of the I. M. F. in her foreign trade and economic development] (इलाहा० ए० कॉम०, १९६६)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

(The International Bank for Reconstruction & Development)

पश्चिम —

द्वितीय महायुद्ध ने न केवल बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को विस्थापित कर दिया बल्कि जन-धन दोनों को बहुत क्षति पहुँचाई। इस प्रकार, युद्ध जर्जरित एवं व्यवस्थाओं के तात्त्विक पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। यह भी अनुभव किया गया कि पश्चिम और पूर्व के बीच व जीवन-यापन स्तरों में बहुत अधिक अन्तर है, जो कि कभी भी महान् अघाति का जम दे सकता है। यदि इस अन्तर को दूर (या कम) नहा दिया गया, तो सम्पूर्ण बिस्व पुनः एक नये युद्ध की लपेट में आ जायगा तथा विश्व शांति की बुनियादें हिल जायेंगी। इस प्रकार, युद्ध की समाप्ति के बाद अल्प विकसित देशों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की गम्भीर समस्या सामने थी। फलतः ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर ही, अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के अनुरिक्त, एक 'अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक' भी स्थापित हुआ।

विश्व-बैंक के कर्तव्य या उद्देश्य (Functions or Objectives)

जैसा कि विश्व बैंक के पाषण्ड अर्न्तनियमों (Articles of Association) में बताया गया है, बैंक के कर्तव्य या उद्देश्य निम्नलिखित हैं — (i) सदस्य देशों की अर्थ व्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण एवं विकास में सहायता करना। इस हेतु विश्व बैंक उत्पादक उद्देश्यों के लिए पूँजी के विनियोग को सुविधाजनक बनावेगा। (ii) विदेशी प्राइवेट विनियोगों को प्रोत्साहित करना। इस हेतु बैंक प्राइवेट विनियोगों को द्वारा दिये गये ऋण व विनियोगों की गारन्टी देगा या इनसे जाल वेगा। (iii) जब उचित सर्तों पर प्राइवेट पूँजी उपलब्ध नहीं है, तो अपने स्वयं कोष से या उधार लिभे गये कोष से उत्पादक कार्यों के लिये ऋण देना। (iv) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घ सूत्रीय विकास में और भुगतान संतुलन की साम्यता बनाये रखने में सहायता करना। इस हेतु वह सदस्यों के उत्पादक प्रसाधनों का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विनि-

योजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। (v) अपने कार्यकलापों द्वारा युद्धकालीन अव्यवस्था को शान्तिकालीन अव्यवस्था में बदलना।

विश्व बैंक का संगठन

(I) विश्व बैंक की सदस्यता—

विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पहले मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। २१ अक्टूबर सन् १९४५ तक मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त कर लेने वाले देश विश्व बैंक के भी आरम्भिक सदस्य माने गये हैं। जिन भी देश लिखित आवेदन द्वारा सदस्यता त्याग सकता है परन्तु यह आवश्यक है कि सदस्यता त्यागने से पहले वह देश बैंक से लिए हुए समस्त ऋण का भुगतान कर दे। यदि कोई देश मुद्रा कोष की सदस्यता त्याग देता है, तो विश्व बैंक में भी उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। २१ मार्च १९५६ को बैंक के सदस्यों की संख्या ११० थी।

(II) विश्व बैंक की पूँजी तथा सदस्य के चन्दे—

स्थापना के समय कोष को अधिकृत पूँजी १००० करोड़ डालर निर्दिष्ट की गई थी जिसे १-१ जून डालर के १ लाख अंशों में विभाजित किया गया था। २२ दिसम्बर सन् १९५८ में बैंक की अधिकृत पूँजी को पूरा करना संपूर्ण हुआ। फलतः १५ सितम्बर सन् १९५९ से सब देशों की पूँजी बढ़ गई। लगभग सभी देशों के चन्दे चुकाने पर दिये गये किन्तु कुछ देशों के चन्दे चुकाने में भी अधिक हुए। राष्ट्रवादी चीन (तेवान) ही एक ऐसा देश था जिसने अपने चन्दे केवल २५% बुद्धि ही स्वीकार की। निम्नलिखित तालिका से कुछ प्रमुख देशों के, १५ सितम्बर सन् १९५९ से पूर्व तथा बाद के, चन्दे दिखाये गये हैं—

विश्व बैंक के चन्दे

(करोड़ डालर में)

देश	१५ सितम्बर सन् १९५८ से पूर्व का चन्दे	पूँजी वृद्धि के बाद चन्दे
संयुक्त राज्य अमेरिका	३१७.५	६०५.०
ब्रिटेन	१३०.०	२००.०
चीन (तेवान)	६०.१	७५.०
फ्रांस	५२.५	१०५.०
भारत	४०.०	८०.०
यू. जर्जनी	३३.०	१०५.०
मनाडा	३२.५	७५.५
जापान	२५.०	६६.६

बैंक की पूँजी में वृद्धि का कारण यह था कि ऋणों की माँग तेजी से बढ़ती

जा रही थी जिसे पूरा करने हेतु बैंक को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण लेने पड़ रहे थे। बैंक की कुल अधिदत्त पूँजी में से केवल २०% पूँजी ही दत्त थी और शेष को सदस्यों ने अनाधारण परिस्थितियों में ही माँगा जा सकता था। इसमें ग भी २२% स्वण-भाग निकाल दें तो ऋण देने योग्य प्रमाणन २२० करोड़ डालर थे जबकि बैंक मन १९५६ तक ४५० करोड़ डालर के ऋण दे चुका था। ऐसी स्थिति में पूँजी बढ़ाना कम से कम मुद्रा-बाजार में ऋणदानाओं में बिबिधता बढ़ाने हेतु आवश्यक था। ३० जून सन् १९६६ को बैंक की प्राणित पूँजी (Subscribed Capital) २०६६ करोड़ डालर थी, जिसमें से केवल २२४०३ करोड़ डालर दत्त पूँजी थी और शेष को सुरक्षित रखा गया था। बैंक की प्राणित पूँजी १९६७ वर्ष में बढ़ कर २७८५ करोड़ डालर और १९६८ में २७६४०२ करोड़ डालर हो गई। १९६६ में यह २३०३७ करोड़ डालर है।

प्रत्येक देश के चन्दे की निम्न की भाषों में बंटा गया है — (अ) १०% चन्दा मागने पर तुरन्त ही दत्ता पड़ता है और (ब) शेष ८०% उस समय देना पड़ता है जबकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक मंजूर। अन्वेषण का २% स्वर्ण अथवा अमरीकन डालर में लिया जाता है और शेष १८% सदस्य देश अपनी मुद्रा में दे सकता है। जब और अधिक चन्दे की माग की जाती है, तो सदस्य देश की यह अधिकार होता है कि वह उन स्वर्ण, डालर अथवा बैंक द्वारा आदर्शित किसी अन्य मुद्रा में चुका दे। समय समय पर बैंक ऐसी मुद्रा की घोषणा करती रहती है।

(III) बैंक का कार्यक्षेत्र—

(१) बैंक को व्यक्तियों और व्यक्तिगत संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवसाय का अधिकार नहीं है। वह केवल सदस्य-देश की सरकार द्वारा ही व्यवसाय कर सकता है।

(२) मुद्रा-कोष की भाँति बिबिध बैंक में सदस्यों की प्राप्ति होने वाले ऋणों की मात्रा उनके चन्दे पर निर्भर नहीं होती है चन्दे तो केवल उत्तरदायित्वों तथा मामल शक्तियों की सीमायें निर्दिष्ट करते हैं।

(३) बैंक का उद्देश्य यह भी नहीं है कि व्यक्तिगत विदेशी ऋण के स्थान पर अपनी ओर से ऋण दे। इसके विपरीत, वह व्यक्तिगत ऋणों का प्रोत्साहन देती है। वह अपने पास से तो केवल उतरी रक्का में ऋण देती है जबकि व्यक्तिगत विदेशी ऋण उपलब्ध नहीं होते हैं।

(४) बैंक अपने ऋण पर व्याज तो लेती ही है परन्तु जिन व्यक्तिगत ऋणों की गारंटी भी जाती है उन पर भी जोषिम उठाने का कमीशन लिया जाता है। बैंक द्वारा अपने ऋण लिए हुए कोषों में से उधार देने पर व्याज दर उस दर से जो कि वह स्वयं चुका रहा है, १% अधिक होती है। अब तक व्याज दर ४५ से ६% के मध्य रही है और गारंटी ऋणों पर बैंक १ से १५% तक कमीशन लेता है। १९६८ से बिबिध बैंक में व्याज दर में ३% की वृद्धि कर दी है।

(५) गारन्टी लेने से पहले बैंक यह देख लेता है कि ऋण लन वाले की माँग नहीं तक वास्तविक है और देने वाले को खर्च कहीं सत्र उचित अथवा न्यायपूर्ण है। ऋणों की गारन्टी अथवा उसके प्रदान करने के सम्बन्ध में बैंक की शर्तें निम्न प्रकार होती हैं — (i) प्राचीन देश को अन्य आतों से उचित शर्तों पर ऋण मिलन का सम्भावना नहीं है। (ii) यदि वह देश जिसकी सीमा में ऋण का उपयोग होना है, स्वयं ऋण नहीं लेता तो सदस्य देश अथवा उसकी केन्द्रीय बैंक को ऋण के भूतलन, धातु तथा अन्य खर्चों के चुकाने की गारन्टी देनी पड़ती है। (iii) बैंक द्वारा नियुक्त को हर्ष ऋण समिति ऋण देने के प्रस्ताव का समर्थन करे। (iv) भूतलन एवं धातु चुकाने की शक्ति भी उपयुक्त होनी आवश्यक है। (v) गारन्टी देने समय बैंक ऋण लेने वाले ऋण देने वाले तथा सम्स्त सदस्यों के हित को देखती है। (vi) बैंक द्वारा दिये गये अथवा गारन्टी किये गये ऋण कुछ विशेष दशओं को छोड़कर केवल पुन निर्माण अथवा विकास योजना पर ही व्यय किये जा सकते हैं।

(६) विश्व बैंक बहुदेशीय निवासी तथा व्यापार के आधार पर कार्य करती है। प्राप्त ऋणों के द्वारा किसी भी देश से माल खरीदा जा सकता है। अतः प्रत्येक सदस्य को अनुकूलतम बाजार से माल खरीदने का अवसर मिलता है। जब तक ऋण का उपयोग बैंक के उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जाता है, जब तक सदस्य द्वारा ऋण के व्यय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है।

(७) विश्व बैंक ऋण के प्रयोग से सम्बन्धित योजना के कार्य पर ध्यान रखती है और समय-समय पर ऋणी देश को प्रगति का विवरण बैंक को प्रस्तुत करना पड़ता है। बैंक भी समय-समय पर-विशेषज्ञों द्वारा जांच कराती रहती है।

(८) बैंक प्रायः सदस्य देश की राजता के सम्पूर्ण व्यय का उतना ही भाग ऋण देता है जो कि विदेशों में माल खरीदने में खर्च है। किन्तु यह भाग भी कुछ अथवा १०% से अधिक नहीं होना चाहिए। ज्यादा-ज्यादा कार्य पूर्ण होता जाना है बैंक किये में ऋण देता जाता है।

(IV) विधान और प्रबंध —

बैंक के प्रबंध के लिए एक गवर्नर मण्डल, एक कार्यकारिणी समिति, एक प्रबंध तथा अन्य नर्मकारी होते हैं।

बैंक का मण्डल अधिकार गवर्नर मण्डल (Board of Governors) के हाथ में होता है। प्रत्येक सदस्य देश का एक गवर्नर (जो परम्परागत्तर उनका वित्त मंत्री हुआ करता है) और एक स्थानागत गवर्नर होता है। गवर्नरों की कार्यक्षमि ५ वर्षों के किन्तु दोष में सदस्य देश किसी अन्य व्यक्ति को भी अपनी ओर से गवर्नर नियुक्त कर सकता है। स्थानागत गवर्नर को गवर्नर की अनुपस्थिति में ही वाट दन का अधिकार होता है। गवर्नर मण्डल अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेता है। यह मण्डल बैंक की माघारण मण्डल (General Council) का कार्य करता है। इसकी बैठक में नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। गवर्नरों को वेतन नहीं मिलता। हाँ, मात्र

भस्ते मिलते हैं। प्रत्येक गवर्नर को २५० मत और १ लाल डालर चन्दे के पीछे एक और मत देने का अधिकार होता है।

दिन प्रतिदिन का कार्य प्रशासनिक सचालक समिति या कार्यकारिणी परिषद् (Board of Executive Directors) करती है, जिसमें १० सदस्य होते हैं (आठ जन बैंक के २० प्रशासनिक महासचिव हैं)। ५ सदस्य पाँच बड़े-बड़े आग्नेय बलि देशों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और शेष ७, मुद्राकोष की भाँति प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। यह समिति गवर्नर मण्डल से प्राप्त समस्त अधिकारों का प्रयोग करती है। वायव्यारिणी समिति एक प्रत्यक्ष की नियुक्ति करती है, जो कि न तो कार्यकारिणी का सदस्य है। सक्षता दे और न गवर्नर मण्डल से। यह बैंक का वैनिक कार्य चलाय के लिए उत्तरदायी होता है।

गवर्नर समिति क्रम से कम मात सदस्यों की एक सलाहकार समिति का भी निर्वाचन करती है। इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ रहें जाते हैं। समिति की बैठक प्रायः वर्ष में एक बार होती है। आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी बुलाई जाती हैं। बैठक बुलाने का श्रेय बैंक चहल करता है।

जब किसी ऋण का प्रारम्भ पत्र प्राप्त होता है तो समुचित जाँच के लिये बैंक एक ऋण समिति (Loan Committee) नियुक्त करता है। इसमें विश्व बैंक के एक या सदस्य, जो सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञ हों रहते हैं तथा एक ऋण प्राप्ति देश के गवर्नर द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ होता है। समिति की रिपोर्ट पर ही ऋण देने या न देने का निर्णय किया जाता है।

(V) आय का बितरण—

कोष का प्रबंधक मण्डल यह निर्दिष्ट करता है कि बैंक की कुल आय में से कौन-सा भाग सुरक्षित कोष में डाला जाये और कौन से भाग का सदस्यों के बीच बितरण किया जाय। कुल लाभ का २% उल सदस्यों में बाँट दिया जाता है जिनकी मुद्राओं का ऋण देने के लिए उपयोग किया गया है। शेष सभी देशों में उनके धनो के अनुपात में बाँट दिया जाता है। लाभ का अनुपात सदस्य देश की मुद्रा में किया जाता है, परन्तु जिस देश की मुद्रा बैंक के पास नहीं होती उसे सोने अथवा किसी अन्य मुद्रा में भुगतान किया जाता है।

विश्व बैंक के कार्यकलापों की प्रगति—

३० जून, १९६१ को विश्व बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के २३ वर्ष पूरे कर लिए हैं। १९६५-६६ में इसने अन्य सहयोगी मस्याओं (IDA और IFC) के साथ मिलकर ११६० मि० डालर नये ऋण दिये। इसने जकेले १९६४, १९६६, १९६७, १९६८ और १९६९ के वर्षों में क्रमशः १०२३, ८३९, ८७७, ८४७ और १०६९ मि० डालर के ऋण स्वीकार किये। किन्तु जैसा कि बाग के चार्ट से स्पष्ट है, पूरी राशि अभी वितरित नहीं की गई है।

१९४७ तक विश्व बैंक का कार्य पुनर्निर्माण से सम्बन्धित रहा। उसने ४ पुन-

निर्माण ऋण दिये, जिसकी कुल राशि ४६७ मि० डालर थी और ये फ्रान्स, नीदरलैंड, डेनमार्क और लक्जमबर्ग को दिये गये थे। १९४७ के बाद सभी ऋण विवास कार्यों के लिए ही दिये गये हैं। इनका अधिकांश भाग अल्प विकसित एवं अविकसित देशों को मिला और यह उचित भी था, क्योंकि इन देशों में केवल निमित्त मात्र आयात करने हेतु धनोपयोग की समस्या नहीं थी वरन् उन्हें सामाजिक पूँजी का भी निर्माण करना था, जिसके लिए न तो उनके पास धन था, न अनुभव और न तकनीकी ज्ञान। अतः बैंक ने बिजली, यातायात, कृषि उद्योग तथा अन्य उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों के निधे ऋण दिये। अधिकांश ऋण बिजली, यातायात और उद्योग के विकास हेतु दिये गये हैं। इनसे स्पष्ट है कि विश्व बैंक सर्वव्यवस्थाओं के निछेरेपन को दूर करके आधुनिक स्तर पर लाने का यत्न कर रहा है।

विश्व बैंक द्वारा दिये गये लगभग ७२% ऋण एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी व केंद्रीय अमेरिका के पिछड़े हुए क्षेत्रों में दिया गया। एशिया में जापान के अतिरिक्त अन्य सब देश प्रत्येक क्षेत्र में अविकसित दशा में थे। राजनैतिक आग्रहण के बाद पिछड़े हुए देशों की अधिक विकास सम्मन्धी माँग बढ़ गई है।

१९५६ से पूर्व डालर की माँग ८२% से भी अधिक थी लेकिन अब मार्क, पौंड, स्टलिंग, स्विस फ्रैंक, फ्रैंच फ्रैंक कैनेडियन डालर और नीदरलैंड में ग्लिडर का महत्त्व काफी बढ़ गया है। भारतीय मुद्रा में भी ऋण दिये गये। वर्ष के दौरान २४६ मि० डालर के पुनः मुगतान (repayments) हुये। ३० जून, १९६६ तक ऋणियों से कुल २,५६० मि० डालर लौटे। इस प्रकार बकाया ऋणों की रकम ६,२६६ मि० डालर थी।

१९९७ में ऋणियों ने १८८ मि० डालर की अदायगी दी और १९६८ और १९६९ में क्रमशः २३७ और २६८ मि० डालर की वापसी हुई। बैंक की प्राप्त और शुद्ध आय १९६६ में क्रमशः शिखर स्तर पर पहुँच गई, जो क्रमशः ४१० मि० डालर और १७१ मि० डालर थी।

बैंक के कार्यकलापों का सूक्ष्म विवरण

(मि० डालर में)

	१९६५	१९६६	१९६७	१९६८	१९६९
ऋण-नवपाये	३८	३७	४७	४४	८४
ऋण-स्वीकृति	१०३३	८३६	८७७	८४७	१३६६
ऋण-वितरित	६०६	६६८	७६०	७७२	७६२
ऋण-अदायगी					
(बैंक) १३७		१६६	१८८	२३७	२६८
कुल आय	२६७	२६०	३३१	३५६	४१०
मुद्रा आय	१३७	१४४	१७०	१६६	१७१
कुल व्यय	८६१	६१४	६०२३	११६०	१२४४

अल्प-विकसित देशों की समस्याओं के प्रति अधिक झुकाव—

बैक यह समय गया है कि विकासोन्मुख देशों के साथ व्यवहार करते समय इनकी तीन विचित्र समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये—(i) चूंकि प्राथमिक उत्पादन (Primary products) में उनकी आय कम और अस्थिर है, इसलिये इनकी अर्थ-व्यवस्था को विविधतामय (Diversified) बनाने की आवश्यकता है। (ii) उनके ऋण दायित्व पहले से ही अत्यधिक हैं तथा निर्यात-आय इनके भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है। (iii) इनकी करामतों के मूल्य में निरन्तर ह्रास हो रहा है, जिनमें भयंकर मुद्रा प्रसार की आशंकाएँ उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर बिन्दु बैंक के प्रेसीडेंट ने गार्डरक्षक के विमलजित तीन नये तारों के बजाये हैं—

(१) कृषि उत्पादन में सहायता करना—कृषि उत्पादन में सहायता करना पहला नया तरीका है। कृषि, वन और मछली पालन इन व्यापक क्षेत्रों के अर्धन सिखाई व बाढ़ नियन्त्रण, पशु पालन, जनारोपण, फार्म यन्त्रीकरण, मछली व्यवसाय सम्मिलित है। जब बिन्दु बैंक एक अधिक व्यापक मोर्चे पर कार्यवाही करना चाहता है जिसमें भण्डार व विपणन, कृषि वित्त संस्थाओं और टेक्नीकल सहायता भी आ जायेगी। यह एक महान परिवर्तन (big change) है, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष कृषि सहायता (direct farm finance) के युग का भी थी विशेष होता है। इन विद्याओं में उधार देना जर्जीवा तो न होगा किन्तु बठिन होणा और साथ ही परिणाम भी देर से दृष्टिगोचर होंगे। उनमें अनिश्चितता भी होगी। अतः कोई बड़ी आशामें न रखना ही ठीक होगा। किन्तु विशेष क्षेत्रों में प्रयोगात्मक प्रयास तो किये ही जा सकते हैं। इन हेतु मयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agricultural Organisation of the U. N. or F. A. O.) समुचित योजनाये बना चुका है।

(२) नये उद्योगों तथा मेकैनिक्स आयातों के लिए ऋण की व्यवस्था—यदि महंगी मशीनों व सामग्रियों में भारी प्रारम्भिक निवेश करने के लिए विदेशी विनिमय या सहायता उपलब्ध हो जाय किन्तु कच्चे मालों तथा स्पेयर पुर्जों की निर्यात आपूर्ति (supply) उपलब्ध न हो, तो यह विनिमय अवरोध (blocked) हो जाता है तथा कोई विशेष लाभ नहीं दे पाता। अतः यह आवश्यक है कि कच्चे माल आदि के आयातों के द्रव्य प्रवचन की व्यवस्था भी की जाय, जिससे कि बुनियादी व आवश्यक उद्योग निरन्तर प्रगति करने रहे। हर्ष का विषय है कि इस तरह के ऋण I. D. A. द्वारा दिए जा सकते हैं।

(३) स्कूलों के निर्माण के लिए साख देना—टेक्नीकल शिक्षा की सुविधाओं के लिए उधार देना बहुत प्रचलित है और इस हेतु कई संयुक्त राष्ट्रीय संस्थाएँ विद्यमान हैं। किन्तु स्कूलों के निर्माण के लिए उधार देना मुक्त नया है। शिक्षा क्षेत्र

मे IDA ने कई देशों को साक्ष दी है। यूनेस्को भी बैंक को महत्वपूर्ण स्कीमे बनाने में व उनके लिए साक्ष की व्यवस्था करने में सहायता दे रहा है।

विश्व बैंक के कार्यों का मूल्यांकन—

विश्व बैंक पर कई आरोप लगाये जाते हैं, जैसे—

(१) यह कहा जाता है कि उसका कार्य विलम्बपूर्ण होता है। यह विलम्ब ऋण लेने वाले देश के लिए बड़ा असुविधानजनक होता है।

(२) इसका कार्य (जैसे—अधिकारियों की नियुक्ति करना, ऋण देना) भी मेढ-भाब से पूर्णतया विमुक्त नहीं है। किन्तु सच्चाई तो यह है कि अल्प विकसित देशों में प्रतिशत और अनुभवों अधिकारियों का अभाव है, जिससे विकसित देशों में न ही अधिकारियों की नियुक्ति करना बैंक के लिए अनिवार्य सा है। जहाँ तक ऋणों का प्रश्न है अधिकांश ऋण एशिया, अफ्रीका और केन्द्रीय व दक्षिणी अमेरिका के देशों को ही दिये गये हैं जिसमें पश्चात का आरोप ठीक नहीं जैचता।

(३) बैंक ऋण देने से पूर्व पुन भुगतान की क्षमता पर अधिक बल देता है। यह आलोचना भी सही प्रतीत नहीं होती है। बैंक एक वित्तीय संस्था है। यदि वह पुन भुगतान क्षमता पर ध्यान न दे, तो पूँजी फँस सकती है और यदि ऐसा हुआ, तो भविष्य में बैंक को ऋण देने की क्षमता कम हो जायगी। हाँ, यह अवश्य है कि यदि सम्बद्ध देश की सरकार गारंटी कर दे, तो फिर बैंक को ऋण देने में मनोबल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बैंक द्वारा निरीक्षण का प्रश्न है, वह तो संस्था के लिए लाभदायक है ही। इसके अतिरिक्त अभी तक बैंक ने किसी देश में, अनावश्यक या अनुचित रूप से, ऋण देने से दन्कार नहीं किया है।

(४) विश्व बैंक की व्याज की दर के सम्बन्ध में भी आपेक्ष किया गया है। निस्तन्देह ६½% व्याज की दर संसार भर में साधारण दर है, परन्तु कहा जाता है कि विश्व बैंक को अधिक उधार होना चाहिए था। क्योंकि अल्प विकसित देशों को ऊँची व्याज-दर देने में कठिनाई होती है। यदि बैंक व्याज दर कम न भी कर सके, तो यह कमोमाल लेना तो बन्द ही कर सकता है। अब ऋणों के सम्बन्ध में कठोरता तथा ऊँची व्याज की दरें ये दोनों ही विकासोत्त अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना के कारण दूर हो गई हैं।

जहाँ तक भविष्य का सम्बन्ध है, इन दोनों संस्थाओं की उपयोगिता बड़े प्रसन्न राजनैतिक तथा आर्थिक शांति और स्थिरता पर निर्भर होगी। भारत को दोनों संस्थाओं से लाभ और सहायता प्राप्त हुई है। फिर भी विश्व बैंक का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें मिस्टर ब्लेक के इस कथन को नहीं गूलना चाहिए कि—“संसार के कम विकसित देशों के लिए विश्व बैंक एक अपूर्व सहाय है और इसका मूल्यांकन केवल कुछ पत्र-पत्र के खबरी तथा सोमेट की चिल्लिहू के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दगना सत्य अधिक महत्त्व है। इसका कार्य संसार की धन राशि में वृद्धि

करके मानवता को प्रकाश और उष्णता प्रदान करना है और उन्हें यशान और उदासी से मुक्त करना है। बैंक का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था और विचारधारा का निर्माण करना है जिससे प्रचुरता केवल स्वप्न अथवा कल्पना न रह कर एक ठोस सत्यता बन जाये।”

अभी हाल में विश्व बैंक के वित्तीय मामलों में जो विस्तार किया गया है इसके फलस्वरूप बैंक अल्प-विकसित देशों को अधिक सहायता दे सकेगा।

भारत और विश्व बैंक

भारत ने विश्व बैंक की प्रारम्भिक सदस्यता प्राप्त कर ली थी। उसे बैंक की सदस्यता से पर्याप्त सहायता मिली है। बैंक में भारत की प्रारम्भिक पूँजी ४० करोड़ डालर निर्धारित हुई थी और अधिकतम पूँजी देने प्रथम ५ देशों में होने के कारण उसे विश्व बैंक में एक स्थाई प्रशासनिक महासहक नियुक्त करने का अधिकार मिला। बैंक से प्राप्त हुई सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।

विश्व बैंक से श्रृंखला—

३० जून, १९६६ तक विश्व बैंक ने भारत की सरकारी एवं गैर सरकारी मशीनों की विभिन्न परियोजनाओं के लिये ७५५.४७ करोड़ रु० ऋण दिये। इस राशि में से ३१ मार्च १९६६ तक ६४१.७५ करोड़ रु० प्राप्त कर लिये गये हैं, से मिली ऋण राशि ६७२ मि० डालर थी। १९६७ में भारत को विश्व बैंक से सबसे अधिक मात्रा में ऋण मिला। सध्या और एकम की दृष्टि से विश्व में सबसे अधिक ऋण भारत को ही मिले है। इसके बाद जापान, मैक्सिका, इटली और कोलम्बिया का स्थान है। बैंक ने भारत को जिन परियोजनाओं के लिये ऋण दिया है उनमें से भी हैं — (१) रेलों के लिये आवश्यक सामग्री तथा पुर्जों का आयात, (२) जलपनवार वाली तथा जंगल भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाने के लिये आवश्यक कृषि मशीनों की खरीद, (३) दामोदर घाटी निगम को बिजली परियोजनाएँ, (४) एयर इण्डिया द्वारा विमानों की खरीद, (५) कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों का विकास, (६) कोयला (महाराष्ट्र) की नए बिजली परियोजना, (७) टाटा आयरन एण्ड स्टील क० तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क० के लिये कायकम, (८) कम्बई के निकट ट्राम्प में तापीय बिजलीघर की स्थापना (९) राज्य बिजली मण्डलों तथा कुछ बिजली कम्पनियों द्वारा बिजली लाइनों के निर्माण के लिये सामग्री तथा उपकरणों का आयात, (१०) आन्ध्र प्रदेश में कोरापुट में स्थित तापीय बिजलीघर का विस्तार (द्वितीय चरण) (११) गैर सरकारी क्षेत्र में कोयला उद्योग का विकास और (१२) भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनिर्माण निगम को सहायता, जिसमें वह गैर सरकारी कम्पनियों को ऋण द सके।

भारत को जो ऋण प्राप्त हुये हैं उनके सम्बन्ध में निम्न आलोचनाएँ की गई हैं — (१) सामान्य उद्देश्यों के लिए श्रृंखला नहीं—ये ऋण केवल निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिलते हैं, जबकि भारत सामान्य ऋण भी चाहता है, जिनका प्रयोग निर्यात भी वार्ध के लिए किया जा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने

बैंक से निश्चित उद्देश्य ऋणों के स्थान में सामान्य ऋण देने की प्रार्थना की थी ।
 (ii) ऊँची ग्याज—ग्याज की दर ऊँची है । भारत जैसे अ विकसित और निरत
 राष्ट्र के लिए २१% से ४७% तक ग्याज-दर बहुत भारस्वरूप है, जिससे विवश
 होकर उन्हें सस्ती साख के अन्य स्रोत तलाशने पड़ने हैं । (iii) नवगण्य ऋण—औद्यो-
 गिक एवं विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए भारत की जो ऋण मिता
 है वह बहुत नवगण्य है ।

इस एक-दो वर्षों में बैंक ने वित्तीय सहायता देने की सत्तों का कुछ उद्धार
 बना दिया है । वह यह अवितरित ऋण पर वार्षिक ग्याज ६% के बजाय ६%
 लेता है । इससे ऋणी देशों पर प्रयोग में आये ऋण का व्यय-भार कम हो गया
 है । क्योंकि कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था का आधार है, इसलिए आर्थिक विकास की एक
 बुनियादी आवश्यकता यह है कि कृषि क्षेत्र में तेजी से उन्नति की जाय । किन्तु कृषि
 का विकास शिक्षित प्रबन्धकों और टेक्नीशस कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर
 है । तदनुसार, विश्व बैंक ने हमें कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मार्गदर्शन और
 प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है । यही नहीं, अभी हाल में, विश्व बैंक ने कुछ
 निश्चित उद्देश्य ऋणों (Specific loans) को सामान्य ऋणों (Block loans) में
 बदल कर हमारे लिए बड़ी सुविधा कर दी है ।

प्राथमिक सहायता, सलाह एवं प्रशिक्षण—

ऋण के अतिरिक्त कुछ अन्य रीतियों से भी विश्व बैंक भारत की सहायता
 करता रहता है जैसे—समय समय पर बैंक के तकनीकी विशेषज्ञ भारत में आते रहते
 हैं । समान हमारी विकास योजनाओं के अध्ययन और उनकी लाभदायकता का
 अनुमान लगाने हेतु कई मिशन भेजे हैं । अब तक १५ से भी अधिक मिशन भारत आ
 चुके हैं । विशेष जांच-पड़ताल के लिए बैंक के अधिकारीगण भी भारत आते रहते
 हैं । यहाँ तक कि १९५७-५८ से बैंक का एक स्थाई प्रतिनिधि भारत में रहता बना
 आ रहा है, जो कि योजनाओं, आर्थिक नीतियों में सलाह देता है । उसने १९५८-
 ५९ में औद्योगिक सात एवं विनियोग निगम को सलाह देने हेतु एक विशेषज्ञ को एक
 वर्ष तक के लिये भारत भेजा । बैंक ने पाकिस्तान से हमारे गहरी पानी विवाद को
 सुलझाने में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है । वह अपने 'आर्थिक विकास विद्यालय' में
 भारतीयों की प्रशिक्षण भी देता है । उसने भारत सहायता क्लब (Aid India Club)
 के द्वारा भारत की अतिरिक्त सहायता विनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया है ।

बैंक से हमारे देश को सहायता निरन्तर एक प्रवाह के रूप में मिलती रहती
 है । वास्तविकता यह है कि विश्व बैंक हमारे लिए एक बड़ी उपयोगी सस्था सिद्ध हुई
 है । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को सकलता एक बड़े अंश तक विश्व बैंक की यथा
 समय पर्याप्त सहायता द्वारा ही सम्भव हो सकी है ।

भारत सहायता क्लब (Aid India Club)—

योजनागत में भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताएँ बहुत

अधिक बढ़ जाने के कारण विशेष प्रयत्न आवश्यक हो गये हैं। वास्तव में योबनाओं में विकास पति बढ़ाने के लिए अधिक ध्यान आवश्यक हो गये हैं। सन् १९५८ में विश्व बैंक ने कनाडा, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का वासिण्डन में एक सम्मेलन बुलाया था, ताकि भारत को अधिक विदेशी सहायता उपलब्ध करने के लिए विचार किया जाय। मार्च सन् १९५६ में इन देशों के सम्मेलन ने भारत को निम्नलिखित पर फिर विचार किया। अन्त में मई १९६१ में इन देशों का एक और सम्मेलन हुआ, जिसमें फ्रान्स ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन ने भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त ऋण देने के करार किये। १० मिलियन पाउण्ड और विश्व बैंक ने जिन्हें 'भारत सहायता क्लब' का नाम दिया जाता है, अक्टूबर-दिसम्बर १९६६ में ४३६ ३४ करोड़ की सहायता मिली। ऐसी सहायता के कारण भारत की विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाई कुछ सीमा तक हल हो सकी।

भारत की विश्व बैंक परिवार की सहायता के चार पहलू (Aspects) —

भारत की विश्व बैंक और इसने सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा जो सहायता दी जा रही है। उसके निम्नलिखित चार पहलू हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है —

(१) अधिक सहायता की आवश्यकता—इस समय भारत को जो सहायता उपलब्ध है उमय नहीं अधिक मात्रा में सहायता की आवश्यकता है। निस्सन्देह १ मन्थर्वे भारत की सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं किन्तु इनके प्रसाधन हमारी आवश्यकताओं से कम पड़ गये हैं। यदि अधिक मात्रा में बाह्य सहायता (External assistance) उपलब्ध हो जाय, तो हम अपनी योजनाओं का आकार बड़ा रख सकते हैं। किन्तु, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि इन संस्थाओं के प्रसाधन अंश भी दिए जाएँ, तो इन संस्थाओं में मिलने वाली सहायता भारत की आवश्यकताओं के लिये अपर्याप्त रहेगी। कारण, जो अन्य देश अभी इन संस्थाओं से ऋण ले रहे हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में भविष्य में बढ़ने वाली है, जिससे वे भी अधिक सहायता की माँग करेंगे। इसके अतिरिक्त, अपनी ही देश भी आग्रह हो रहे हैं तथा उनके आर्थिक विकास के लिए साधनों की माँग भी इन्हीं संस्थाओं को पूरी करनी होगी।

(२) विकास कार्यक्रम में कृषि का महत्व—कृषि कृषि हमारी सर्व-व्यवस्था का आधार है इसलिए आर्थिक विकास की एक बुनियादी आवश्यकता यह है कि कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से प्रगति की जाय। हमें का विषय है कि विश्व बैंक ने भी इस बात को समझ लिया है पिछले बरसात के अनुभव से यह मान्य हुआ है जब तक कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक उन्नति निरंतर बढ़ती हुई जन-संख्या के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त न हो सकेगी। किन्तु कृषि का विकास निम्नलिखित प्रवृत्तियों व टेक्नॉलॉजिकल कर्मचारियों की उपलब्धता पर निर्भर है। नदरुवार विश्व बैंक ने कृषि और जल के क्षेत्र में अधिक माहिरता व प्रोत्साहन देने का निगम किया है। इस दिशा में विश्व बैंक (IBRD), अंतरराष्ट्रीय विकास

परिपद् (I. D. A.) और विश्व कृषि सङ्गठन (F. A. O.) साथ मिलकर कार्य करेंगे।

(३) 'मुक्त' सहायता की आवश्यकता—भारतीय योजनाओं को अधिक माना में 'मुक्त सहायता' (Free assistance) की आवश्यकता है। 'बन्धे ऋणों' या 'समर्प ऋणों' (Tied loans) की अपनी कुछ कठिनाइयाँ हैं। प्राइवेट विदेशी पूँजी का प्रवाह थोड़ा है और समाप्त होता जा रहा है तथा द्विपक्षीय सहायता (Bilateral assistance) पर राजनैतिक रंग पड़ा होता है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् व अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा स्वीकृत साख व विनियोग का अधिकतम भाग अवितरित रहता है, क्योंकि वह कुछ विशिष्ट योजनाओं से बँधा होता है। अतः यह आवश्यक है कि न केवल भारत अधिक विदेशी सहायता प्राप्त करे वरन् मुक्त रूप से प्राप्त करे। इसी उद्देश्य के आर्थिक विकास की सामान्य आभ्य मिलेंगी। इस दृष्टिकोण से यह प्रशंसनीय है कि पिछले वर्ष I. D. A. ने भारत को एक नये ढंग से औद्योगिक साख प्रदान की थी, जो किसी विशिष्ट परियोजना से बंध न थी वरन् खुले हुए भारतीय पूँजीगत सामग्री उद्योगों में निर्माताओं की सहायता के लिए थे, जिससे कि पहले से ही विद्यमान क्षमता का प्रयोग कर सकें, क्योंकि अब वे आवश्यक पुर्जों व सामग्रियों का बड़ी तादाद में जो हम साख में पूर्व विदेशी विनियम की दुर्गन्धता के कारण सम्भव नहीं हुआ था, आयात कर सकें।

(४) वित्तीय सहायता की शर्तें—अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् (IDA) के ऋण हमारी आवश्यकताओं व आर्थिक स्थिति के बिल्कुल अनुकूल हैं। अब तो विश्व बैंक परिवार से प्राप्त होने वाली सहायता की शर्तें और भी उदार बना दी गई हैं। विश्व बैंक एवं IDA न केवल महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विदेशी विनियम सम्बन्धी लागत वरन् स्थायी करंसी वाला लागत के सम्बन्ध में सहायता देने को तैयार हैं। अवितरित ऋणों (Undisbursed loans) पर वार्षिक व्यय (Annual commitment charge) ३½% से घटा कर ३% कर दिया है। इससे ऋणी देशों पर प्रयोग में न आने ऋण का व्यय भार कम हो गया है। किन्तु न केवल व्याज कम होना आवश्यक है वरन् ऋण की वापसी के लिए दी गई अर्वाध भी अधिक लम्बी होनी चाहिए। हमें है कि विश्व बैंक ने इस दिशा में भी ध्यान दिया है। फिलीपाइन्स को अभी हाल में जो ऋण दिया गया है वह ३० वर्ष के लिए है। बताया है कि भारत के सम्पर्क में भी विश्व बैंक यही नीति अपनावेगा।

बैल कमीशन की रिपोर्ट—

१९६७ में बैल मिशन ने भारत के लिये उपलब्ध सहायता का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए आयोग ने जो धनक सुझाव दिए हैं, उनमें कुछ दृष्ट प्रकार है —(१) विदेशी निजी उद्योगों के सहयोग में कृषि कार्यक्रम पर बल और खाद-उत्पादन कार्यक्रम का विस्तार। (२) औद्योगिक विनियोग और उत्पादन पर और अधिक रियायत तथा अनावश्यक नियन्त्रणों का उन्मूलन। (३) परिवार नियोजन के कार्यक्रमों पर

हड़ता से अमल । (४) निर्यात हटाने और आयात में उदारता बरतने की नीति जारी रहे । (५) निर्यात बढ़ाने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएँ । (६) वर्तमान उत्पादन सुविधाओं के अधिक प्रभावी उपयोग के कदम उठाए जाएँ । (७) वर्तमान सुविधाओं की वास्तविक क्षमता को देखते हुए नई क्षमता कायम करने की योजनाओं और ऐसी क्षमता के विस्तार की सम्भावनाओं का स्थान । (८) आवश्यक छंटों में विदेशी निजी पूँजी आकर्षित करने के लिए और प्रयास किये जाएँ । (९) अनुत्पादक सरकारी खर्च घटाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ ।

वैल मिशन ने सुझाव दिया है कि चानू वित्तीय वर्ष के लिए सुभाषी गई ७० मे ८० करोड़ डालर की मदद खाद महायाना के रूप में दी जानी चाहिए, जिससे भारत १९६७ में लगभग १ करोड़ टन अनाज विदेशों में भगा सके । मिशन ने भारत सहायता क्लब से १० करोड़ डालर की रंर-परियोजना मदद का समर्थन किया । मिशन के अनुसार १९६७-६८ में निर्यात के लिए धन जुटाने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा के अजित साधनों के पूरक रूप में ऐसी सहायता की जरूरत होगी । मिशन ने कम से कम ६० करोड़ डालर की परियोजना सहायता का सुझाव दिया । मिशन के अनुसार उत्पादन की गति तेज करने और उसे ५ से ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर बनाये रखने के लिए ऐसी मदद जरूरी होगी ।

परीक्षा प्रश्न :

- १ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं ? वह सदस्य देशों की जो सहायता देता है उसके स्वभाव और उसकी सीमा का मूल्यांकन कीजिये ।
- २ विश्व बैंक अर्द्ध विकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायता करने के लिये क्या कार्य कर रहा है ?—[विवेचन कीजिये ।

[Examine the role played by the I B R. D in assasting the economic growth of underdeveloped countries]

(बागरा, एम० ए० १९६७)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

(International Finance Corporation)

परिचय—

विश्व बैंक ने पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है, किन्तु इसके कार्यवाहन में निम्न हो कमियाँ अनुभव की गई —(१) वह सरकारी गारन्टी पर ही प्राइवेट उद्योगों को ऋण देता है, जो इनके लिए कोई उसाहजनक बात न थी, क्योंकि प्रथमतः सरकारें प्राइवेट उपक्रमों की गारन्टी देना पसन्द नहीं करती हैं और, दूसरे गारन्टी के वहाने कहीं उद्योगों में सरकार का हस्तक्षेप न बढ़ जाय इस डर में प्राइवेट उपक्रमी स्वयं भी सरकार की गारन्टी पर ऋण लेने में असह्य करने हैं। एवं (२) चूंकि विश्व बैंक उद्योगों को अशुभ पूर्ण में हिस्सा नहीं ले सकता, केवल निश्चित व्याज वाले ऋण ही दे सकता है इसलिये वह ऋणी उद्योग में इतनी रुचि नहीं लेता जितनी को अशुभारी लेते हैं। यही नहीं, ऋण के कारण सस्या पर व्याज का भार भी बढ़ जाता है। इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् स्थापित किय गये हैं।

वित्त निगम ने जुलाई १९५५ से कार्य आरम्भ किया। वह विश्व बैंक की एक सम्बन्ध सस्था के रूप में कार्य करता है तथा उसकी प्रबन्ध व्यवस्था विश्व बैंक के ही सहस्र है। विश्व बैंक का प्रेसीडेंट निगम का चैयरमैन होता है।

निगम के उद्देश्य

निगम का प्रधान उद्देश्य अर्ध-विकसित देशों में उत्पादक प्राइवेट उपक्रमों को प्रोत्साहन देकर उनके आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह उत्पादक प्राइवेट उपक्रमों में प्राइवेट विनियोजकों के साथ मिलकर विनियोग करता है और पुनर्भुगतान के लिये सरकार की गारन्टी नहीं माँगता। वह वास्तव में 'देशी और विदेशी प्राइवेट पूँजी', 'अनुभवों प्रबन्ध' तथा 'विनियोग मुञ्चन-मर' इन तीनों में समन्वय स्थापित करता है।

निगम का संगठन एवं प्रबन्ध

एक स्वतन्त्र सस्था होते हुये भी निगम विश्व बैंक के सरभण में कार्य करता है। इसका सदस्य होने के लिए विश्व बैंक की सदस्यता आवश्यक है। निगम की अधिकृत पूँजी ११ करोड़ डालर है, जो एक-एक हजार डालर के १,१०,००० अंशों में विभाजित की गई है। ३० जून १९६७ को निगम की रजिस्ट्रार पूँजी १० करोड़ डालर के लगभग थी, जिसमें प्रमुख देशों का भाग (लगभग ५) इस प्रकार था —

अमेरिका	३५१ ६८	जर्मनी	१६*५५
ब्रिटन	१८४	कनाडा	३६
फ्रांस	५८ १५	नीदरलैंड्स	३०*४६
भारत	४४ ३१		

रपयटत ७ २७ करोड़ डालर की पूँजी (अर्थात् मुक्त की लगभग ६%) इन सात देशों के पास थी।

निगम का कोष विश्व बैंक के कोषों से अलग-थलग रखा जाता है। यह बैंक से उधार लेन-देन नहीं कर सकता किन्तु शुल्क देकर विश्व बैंक के अधिकारियों की सेवा का प्रयोग कर सकता है। यह विश्व बैंक के द्वारा ही अन्य विश्व सस्थाओं में सम्पर्क स्थापित कर सकता है। उसका प्रधान कार्यालय विश्व बैंक के सामे ही होता है। किन्तु वह अन्य कार्यालय कहीं भी रख-रखाव देखा में स्थापित कर सकता है। इस समय इसके कार्यालय ग्युआक, लन्दन और पेरिस में भी हैं।

वित्त निगम की सर्वोच्च प्रबन्ध-सत्ता गवर्नर मण्डल है। विश्व बैंक ने सदस्य देशों द्वारा मनोनीत गवर्नर ही निगम में भी गवर्नर मण्डल के सदस्य होते हैं। यह मण्डल नीतियाँ निर्धारित करता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष वित्त निगम का पदेन प्रधान होता है। कार्य संचालन की जिम्मेदारी संचालक मण्डल पर है जिसमें विश्व बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य ही, जो वित्त निगम के सदस्य हैं, सम्मिलित होते हैं। संचालक मण्डल विश्व बैंक की सहमति से एक अध्यक्ष नियुक्त करता है जो वित्त कार्य संचालन के लिये दायी होता है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। प्रत्येक सदस्य को २५०+ प्रति अंश एक मत देने का अधिकार होता है। प्रायः समस्याएँ बहुमत द्वारा होती हैं।

३० जून १९६८ को निगम के सदस्यों की संख्या ८६ तक पहुँच गई।

निगम के कार्यक्षेत्रों का क्षेत्र—

(१) ऋण देना और अंश पूँजी का काम करना—निगम की स्थापना के पूर्व विश्व बैंक की यह राय थी कि वित्त निगम का मुख्य कार्य औद्योगिक ऋणों में अंश-पूँजी सौदीकरण होना चाहिए, ऋण देना नहीं। बाद में, इसका चार्टर संशोधित होने समय, कुछ लोगों ने यह मत प्रकट किया कि पूँजी विनियोजन में बहुत कठिनाइयाँ हैं, जिससे आरम्भ में वित्त निगम का कार्य ऋण देना ही रखा जाय। फलतः

निगम को अथ विनियोजन का अधिकार नहीं मिला। किन्तु निगम ने दूरदर्शिता के विचार से, जिन उद्योगों को कृषि दिये समये किसी भी समय अथ पूँजी खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखा। यही नहीं बँट जाने वाले लाभ में निगम का हिस्सा भी नियत किया गया।

कुछ वर्षों से कार्यवाहन से ही निगम को अनुभव हो गया कि उसकी श्रण देने की विशेष प्रणाली जिसमें ऋणों को पूँजी में परिणित करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता था, श्रणी देशों के नियमों और विधानों के अनुकूल नहीं थी, जिससे बार-बार स्पष्टीकरण देने पड़ते थे और ऋण देने में विलम्ब हो जाता था। निगम को यह परेशानी भी होती थी कि उसे पहले से ही ऐसी समस्याएँ और व्यक्ति तथा करने पड़ते थे, जो ऋण को पूँजी में बदलने की अवधि की समाप्ति पर उन अर्थों को खरीद ले, क्योंकि निगम स्वयं ही अर्थों को खरीदने का अधिकार नहीं रखता था।

इत कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सन् १९६१ में निगम के नियमों में मदीयन किया गया जिससे उसके अर्थों में विनियोजन करने पर उसे बाध नहीं होता ही गई। ज्ञाता है कि अब निगम के अथ पूँजी विनियोजन से अधिकसित देश विशेष लाभ उठा सकेंगे।

(२) प्राइवेट उद्योगों में ही विनियोजन करना—निगम सरकारी उपक्रमों में या सरकार की प्रमुखता वाले उपक्रमों में विनियोजन नहीं कर सकता। वह प्राइवेट उपक्रमों में विनियोजन करता है और इस हेतु सरकार की मारफती नहीं माँगता। यदि किसी उपक्रम का प्रबन्ध प्राइवेट हाथों में है और सरकार की मामूली पूँजी लगी है, तो निगम की विनियोजन करने में बाधा न होगी। वह नये उपक्रमों में कुल पूँजी का आधा भाग लगा सकता है बस शेष आधा भाग प्राइवेट विनियोजकों ने लगा दिया हो। वह पुरानी समस्याओं के विकास हेतु लगाई जाने वाली पूँजी में ५०% से भी अधिक विनियोजन कर सकता है किन्तु कुल नयी पूँजी (नई + पुरानी) निगम के विनियोजन से अधिक हो जानी चाहिए। यह केवल विदेशी पूँजी द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों में भी सहयोग दे सकता है किन्तु देशी और विदेशी पूँजी के सहयोग वाली इकाइयों को प्राथमिकता देता है। वह अपने साथ-साथ प्राइवेट विनियोजकों का भी उपक्रम में पूँजी लगाने को उत्साहित करता है जिसमें उद्योग को पर्याप्त पूँजी मिल जाय।

(३) केवल निर्माणी उपक्रमों को ही सहायता देना—वित्त निगम निर्माणी उद्योगों में, जिनमें खनन, विधायन एवं सभी तरह के उत्पादन काय शामिल हैं, धन लगाना है। वह लोकोपयोगी सेवाओं (जैसे—बिजली, सिंचाई, गृह निर्माण, होटल आदि) और विदेशी व्यापार के लिये धन नहीं देता।

(४) अन्य शर्तें—(अ) निगम छोटे, गृह एव मध्यम सभी प्रकार के उपक्रमों को धन देता है किन्तु इनकी कुल पूँजी (निगम के सहयोग की मिलावर) ५ लाख डॉलर से कम नहीं होनी चाहिये। (आ) वह १ लाख डॉलर से कम और

३० लाख डालर से अधिक पूँजी नहीं लगाता । यदि निजी पूँजी अधिक बाने को तैयार हो तो वह ३० लाख डालर से भी अधिक विनियोग कर सकता है । (६) विनियोजन का स्वरूप ऋण (Loans) अर्थात् पूँजी का त्रय अथवा ऋणों को पूँजी में परिवर्तन करने की दान वाला ऋण हो सकता है, प्रायः वह जोसिम पूँजी लगाना अधिक पसन्द करता है ताकि उसका मस्या में प्रत्यक्ष स्वार्थ रहे । (७) व्याज दर उद्योग की अजन शक्ति के अनुसार निश्चित की जाती है और प्रायः ६ से १०% तक ली गई है । (८) वह लाग में हिस्सा देने की शर्त लगा सकता है । (९) अप्रयुक्त ऋण राशि पर १% वार्षिक दर में ध्याज लगाया जाता है । (१०) ऋण सुविधाजनक बिन्दु में चुकाया जा सकता है । य बिन्दु ५ से १५ वर्ष तक के सिधे निश्चित की गई । वार्षिक बिन्दु की म-या नियत करने में उत्पादन आरम्भ होते तथा लाभ अजन की शक्ति का ध्यान रखा जाना है । (११) निगम डालर में या आवश्यकता पड़ने पर अथ मुद्राओं में विनियोग करता है । (१२) वित्त निगम केरन उद्योग की जमानत पर हो ऋण दे देता है उसकी सम्पत्ति बंधक नहीं रखता सरकार या अन्य तस्याओं से गारन्टी दिलाने की माग नहीं करता । हा, सस्था पर ऐसी शर्तें लगा सकता है जिसके अनुसार वह एक निश्चित रकम में अधिक ऋण में ले और अपनी बाखू पूँजी का विनियोग ठीक में करे । (१३) ऋण की राशि एक मुश्त या बिन्दु में ली जा सकती है । इसका प्रयोग करी में भी सामान खरीदने में अधया कितो भी विकास कार्य में किया जा सकता है ।

प्रार्थी उद्योग पूरी योजना बनाकर निगम को भेजते हैं । इसका विश्लेषण करने में निगम की योजना की उपयुक्तता तथा प्रबन्ध व्यवस्था की कुशलता का अनुमान लग जाता है । सब बातों में समुप्य होकर ही वह विनियोग करने का निगम करता है । ऋण देने के पश्चात् भी वह ऋणों उपक्रम से सम्बन्ध बनाय रखता है । इस हेतु अपने विशेषज्ञ भेजकर जागकारी प्राप्त करता है, रिपोर्ट आदि भगवाता है । पूँजी का विनियोजन करने की दक्षा में उपयुक्त नियमों का अनुसरण किया जाता है । आजकल प्रायः सभी देशों में विदेशी विनियम सम्बन्धी बड़े प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सस्याओं के विनियोजन पर प्रायः कोई रोक नहीं है । यदि किसी देश में ऐसा हो, तो निगम वहाँ की सरकार से स्वीकृति मागता है । यदि स्वीकृति न मिले, तो वह प्रार्थी उपक्रम को ऋण देने से इन्कार कर देता है ।

निगम के कार्यक्षलापो की प्रगति—

३० जून १९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कार्यकारी जीवन के ११ वर्ष पूरे हो गये । इन ११ वर्षों में इसके कार्यक्षलापो की प्रगति का बखण मक्षेप में नीचे किया गया है —

(१) स्वीकृत किये गये ऋण—३० जून १९६६ तक निगम ने ३६ दशो में २२२१ मि० डालर की सहायता दी । १९६६-६७ में ४६१ मि० डालर की सहायता दी गई है जबकि १९६५-६६ में ३५६ मि० डालर दिय गये थे । इस प्रकार,

अपने कार्यचालन के द्वितीय दशवर्ष के प्रथम वर्ष में IFC ने पिछले दशवर्ष की कुल सहायता का एक चौथाई भाग स्वीकृत किया। अधिकतर ऋण ५ से १०% पर दिए गए हैं। अधिकांश ऋणों को अज पूँजी में परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

(२) प्रायोजना-लागत अंश—१९६६-६७ में निगम ने ३३० मि० डालर की लागत वाली प्रायोजनाओं के लिये ४६ मि० डालर दिए। इस प्रकार २० शून्य १६= तक नियम ने जिन प्रायोजनाओं के लिये वित्त प्रदान किया उनका कुल लागत १०१० मि० डालर थी, जिसमें निगम का अंश १=६ मि० डालर था। इस प्रकार निगम के प्रत्येक १ डालर के विनियोग के लिये अन्य विनियोजकों में ९ डालर प्रदान किये। (विकास वित्त कंपनियों की दशा में यह अनुपात १ और १२ का है) स्पष्टतः वित्त निगम से अन्य स्रोतों द्वारा विनियोजन को यथेष्ट प्रोत्साहन मिल रहा है। यथार्थ में ऐसा प्रोत्साहन देने के लिये ही निगम की अपनी भूमिका १९६२ में केवल सहायता होने के बजाय 'सहायता-से-विनियोजक' की बनानी पड़ी।

(३) विनियोग पोर्टफोलियो—२० जून १९६८ तक IFC का कुल विनियोग-पोर्टफोलियो अल्प आय वाले देशों में १६६५-६६ में ८४ मि० डालर में बढ़कर १९६६-६७ में १०७६ मि० और १९६७-६८ में २१५ मि० डालर हो गया। इन पर निगम की औसत वार्षिक आय ७.४१% हुई है। विनियोग पोर्टफोलियो में दिनबंदी घटा वित्त वर्ष के ३०% से बढ़ कर अब ४०% हो गया है। इसके अतिरिक्त वह जनता की समस्याओं के निर्वाहों का अभिगोपन भी करता रहा है। इससे स्वामीय पूँजी बाजारों के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। IFC की इनिवर्टी फार्नेसिंग की एक उत्प्रेरणात्मक विशेषता यह है कि वह अपने पोर्टफोलियो से सदा धिपका नहीं रहता बल्कि उसे बदलता रहता है तथा इस हेतु प्राइवेट विनियोजकों को अपने निजी विनियोगों में भाग लेने का अवसर देता है। कोपी का इस प्रकार से पुनः प्राप्त करने रहने का ही यह सुपरिणाम था कि निगम अपनी दत्त अंश पूँजी (=१० करोड़ डालर) के समभोग देने के बराबर (अर्थात् २२.१ करोड़ डालर) विनियोग-दायित्व उठाने में समर्थ हुआ।

(४) विश्व बैंक की सहयोग—विश्व बैंक ने कई देशों के विकास बैंकों और वित्त संस्थाओं की उद्योगों की ऋण देन हेतु सहायता की योजना बनाई है। वित्त निगम भी इसमें हिस्सा ले रहा है ताकि दोनों संस्थाओं की सम्मिलित पूँजी अतिरिक्त देशों की आवश्यकताएँ पूरी कर सके। इस योजना का लाभ यह है कि एक ओर तो अल्प विकसित देशों को सहम्यता मिलने में सुविधा हुई जायेगी और दूसरे वित्त निगम और विश्व बैंक को एक अच्छा मध्यस्थ मिलने में उनका दायित्व हल्का हो जायेगा। ३० जून १९६८ तक निगम ने १० विकास वित्त कंपनियों में १९.२ मि० डालर के अंश खरीदे।

(१) वित्त निगम के प्रसाधनों में वृद्धि—स्मरण रहे कि १९६१ में निगम

के नियमों में एक मशोधन के अनुसार निगम द्वारा पूँजी स्टॉक में विनियोग करने पर से पाबन्दी हटा ली गई थी और १९६५ के दूसरे मशोधन ने निगम को अपनी प्रभार रहित प्राप्त पूँजी और आधिक्य के चार गुने की सीमा तक विश्व बैंक से उधार लेने की शक्ति दी। इसमें I F C के पास द्वितीय दशान्द के कार्यचालन के लिये ५०० मि० डालर जुड़ गये हैं। अतः अब वह पहले की अपेक्षा बड़े ऋण ले उठा सकता है। १९६६-६७ में निगम को कार्यचालन के लिए उपलब्ध प्रसाधनों की संख्या राशि ३१०४ मि० डालर तक पहुँच गई। जिसमें विश्व बैंक से प्राप्त १०० मि० डालरों का ऋण भी सम्मिलित है।

(६) सहायता वाले वाले देश, उद्देश्य एवं ऋण आकार—१९६६-६७ में निगम ने अपने विनियोगों का आकार बढ़ा दिया है। इस वर्ष कुल तीन विनियोग (बांग्ला, भारत और फिलिपाइन्स) १० से १२ मि० डालर के हुये। अतः औसत आकार ८५ मि० डालर का रहा जबकि पिछले दशान्द में वह केवल १४ मि० डालर की ही थी। निगम अपने व्यवसाय को विविधमूर्ती बनाता जा रहा है। इस वर्ष तो इसने पर्यटन के लिए भी आर्थिक सहायता दी है। वह भौगोलिक दृष्टि से भी अपने व्यवसाय को फैला रहा है। इस वर्ष ऐशिया और अफ्रीका में विनियोजन पर अधिक ध्यान दिया गया है। यदि विभिन्न देशों को I F C से अनुसूचित सहायता मिली है तो इसका कारण उनका विभेदात्मक व्यवहार नहीं है बल्कि कुछ देशों की उपयुक्त स्थानीय दशाएँ विकसित करने की असमर्थता है।

भारत और ४० मि० निगम—

भारत ने निगम के समझौता-पत्र पर १९५५ में हस्ताक्षर कर दिये थे और इस त्वा पर वह निगम का प्रारम्भिक अवस्था में ही सदस्य बन गया था। वह पहले पांच अधिकतम पूँजी वाले देशों में से है और इस नाते उसे निगम के प्रशासनिक मंचालक मण्डल में एक स्थायी स्थान मिला हुआ है। निगम में पहला ऋण जनवरी १९५६ में रिपब्लिकन फोर्ज कंपनी को मिला जो १५ लाख डालर का था। दूसरा ५८ लाख डालर का ऋण किर्लोस्कर ऑयल इजन्स लि० को अप्रैल १९५६ में मिला। चूँकि इनकी आवश्यक पूँजी अन्य साधनों से मिल गई थी, इसलिए उन्होंने इन स्वीकृत ऋणों का लाभ नहीं उठाया। तीसरा १३६५ लाख डालर का ऋण आसाम निमिगेनशिट लि० को जून १९६० में एक चौथा २१० लाख डालर का ऋण K S B Pump Ltd को जनवरी १९६१ में मिला। अन्य ऋण निम्न थे—प्रिंसोयन बीमारम इण्डिया लि० ८६६ लाख डालर, फोर्ट मोस्टर इन्डस्ट्रीज लि० १२११ लाख डालर, महिन्द्रा सूजीन रटील कम्पनी लि० ३४१० लाख डालर, सश्री मशीन वर्क लि० १०८० लाख डालर। नई उर्वरक प्रयोजनाओं के लिये सहायता देने के सम्बन्ध में वित्त निगम में चर्चा चल रही है। १९६६ के अन्त तक निगम ने आठ भारतीय कम्पनियों में १५४२ करोड़ रुपये का विनियोग कर रखा है।

प्रारम्भिक वर्षों में भारत ने निगम से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया, क्योंकि

उमे विश्व बैंक से अधिक धम्बी अवधि के और कम व्याज के ऋण मिल जाने है। फिर युद्धोत्तर काल में अधिकतम निजी उद्योग सरकारी प्रोत्साहन से स्थापित हुये है और उन्हें अन्य देशों से भी पूँजी उधारतापूर्वक मिलती रही है, जिससे निजी उद्योग पतियों का ध्यान निगम की ओर अधिक नहीं गया। किन्तु पिछले ३-४ वर्षों में भारतीय उद्योगपतियों ने निगम की सुविधाओं का लाभ उठाने पर अधिक ध्यान दिया है।

वित्त निगम के कार्यों का मूल्यांकन—

निगम के कार्यवाहन की प्रमुख आलोचनाये निम्नलिखित है —

(१) अधिकसिक्त देशों को अल्प सहायता—अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का काम अधिकसिक्त देशों की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये समूली रहा। विगत १५ वर्षों में उसने ३६ देशों में २२२ मि० डालर की सहायता दी है जबकि अधिकसिक्त देशों की संख्या १०० के लगभग है। हमारी सम्मति में यह आलोचना सही नहीं है। कारण, प्रत्येक नई सस्था प्रारम्भिक वर्षों में धीमी गति से ही प्रगति करती है। जिस प्रकार विश्व बैंक और मुद्रा कोष की प्रगति, प्रारम्भिक अवस्था पार करने के बाद अब सराहनीय बन गई है, उसी प्रकार वित्त निगम भी भविष्य में तेजी से प्रगति कर सकेगा ऐसा हमें विश्वास है। इसके अतिरिक्त निगम की सफलता का ठीक ज्ञान इसके द्वारा दिये गये ऋणों से नहीं, बरन् इस बात से होता है कि इसने निजी व्यवसायों को देसी और विदेशी पूँजी किस सीमा तक उपलब्ध कराई है। इस दृष्टि से तो निगम कायं बहुत सन्तोषजनक कहा जावेगा, क्योंकि ऋणी उद्योगों में निगम के प्रत्येक डालर के निवेश के कारण ४ अतिरिक्त डालरों का निवेश हुआ है।

(२) महँगे ऋण—निगम अपने ऋणों पर औसतन ७% व्याज लेता है। आलोचकों का कहना है कि यह दर बहुत ऊँची है। बिशेषतः जबकि निगम का व्यवसाय के लाभ में भी हिस्सा होता है। निःसन्देह विकासोन्मुख देशों की उपयुक्त दर ऊँची प्रतीत हो सकती है किन्तु यदि यह ध्यान में रखें कि निगम बिना जमानत ऋण देता है, ऋण-प्राप्ति की आवश्यकता की यथासाध्य पूरी करने के लिये प्रयत्नशील रहता है, और निजी उद्योग सम्बी अवधि के और वह भी अनुरक्षित ऋण अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आलोचना की सराहनीयता प्रत्यक्ष हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि निगम के पिछले अध्यक्ष गार्नर ने कहा था, यदि निजी उद्योग का आधार मुहब्द है, तो उसे सस्ती मुद्रा की सहायता नहीं चाहिए। पुनः महँगी पूँजी वा महत्व समझकर उसका उपयोग नहीं होता। मर्त्य में निगम को व्याज-दर ऊँची नहीं है, और यदि मान भी नी जाय कि ऊँची है, तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता।

(३) ऋण-प्रकार उपयुक्त नहीं—निगम छोटे-बड़े सभी उद्योगों को ऋण देता है। किन्तु कुछ आलोचकों का कहना है कि निगम केवल छोटे उद्योगों को ही ऋण दे। अन्य आलोचकों की सम्मति में इसे केवल बड़े उद्योगों को ही ऋण देना

चाहिए। हमारी सम्मति है कि दोनों ही विचार ठीक नहीं हैं। एक बहुत छोटी मस्या को प्रायः बोझी पूँजी चाहिये जिसमें जो विदेशी मुद्रा का जवाब बहुत ही मामूली होता है। अतः इसकी आवश्यकताएँ देशी स्रोतों से ही पूरी की जा सकती हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़े उद्योग को ऋण देना भी नियम के उद्देश्य से असंगत है। कारण नियम का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों में प्राइवेट पूँजी को प्रोत्साहित करना है और बड़ा बहुत बड़े उद्योगों का अभाव है। अतः अल्प विकसित देशों को बहुत बड़े ऋणों की आवश्यकता नहीं। यथायथ प्रत्येक मांग की विधायक दस्तावेजों के सम्बन्ध में सहायता देने की उपयुक्तता या विचार किया जाना चाहिए। नियम का सबसे छोटा ऋण मल्टेडोर के एक हाजियरा कंपनी को मिला था, जिसमें ७० अधिक कार्य करते थे। छोटी होते हुए भी इसका वित्तीय राशि १२ करोड़ डॉलर वार्षिक थी। अतः इसे उहाँ दिया जाता अशुद्धि नहीं कहा जा सकता। नियम के २५% ऋण २० लाख डॉलर या इससे अधिक राशि के हैं। इससे बड़ी राशि के ऋणों की अल्प विकसित देशों को ज़रूरत नहीं है और यदि हाँ भी तो नियम पर कोई बचनबद्धता नहीं है।

कार्पर के संशोधन के परामर्श नियम ने विनास बैंकों की जोखिम पूँजी में विनियोग किया है और ऋण लेने की क्षमता में वृद्धि होने से वह कम विकसित सदस्य देशों के आर्थिक विकास में एक व्यापक पैमाने पर हाथ बँटाने में समर्थ हो गया। इन देशों में इन्क्यूबेटी पूँजी के उत्पादक विनियोग के लिए प्रचुर अवसर हैं। नियम का विनियोग अंतर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करके अविकसित देशों में वित्तीय देशों द्वारा विनियोग को सम्भव बना सकता है। नियम ने इस विधा में सन्तोषजनक प्रगति की है।

परीक्षा प्रश्न .

1. किन बातों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम विश्व बैंक से भिन्न है। विवेचन करिये।

[In what respects does the International Finance Corporation differ from International Bank of Development and Reconstruction ?]

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियमों के कार्यक्षेत्रों की आलोचना कीजिये। अप्रवृत्त देशों के विकास में नियम कहाँ तक सहायक हुआ है ?

[Give a critical estimate of the working of the International Finance Corporation. How far has the Corporation been helpful in the development of under developed countries ?]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद्

(International Development Association)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ अपेक्षाकृत एक नई संस्था है, जो अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर कम विकसित देशों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का अर्थ-प्रबन्ध करती है। यह नस्था २६ सितम्बर सन् १९६० में स्थापित की गई थी। यह अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (विश्व बैंक) के सहायक के रूप में कार्य करती है।

परिषद् की स्थापना क्यों ?

विकासोन्मुख देशों के समक्ष गम्भीर पूँजी सम्बन्धी समस्याएँ हैं। सर्वप्रथम, उन्हें दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है—विकास पूँजी (गृह उद्योगों के विकास हेतु) एवं सामाजिक पूँजी (सार्वजनिक लाभ के सामान्य कार्यों के सम्पादन हेतु)। दोनों वर्गों की पूँजी की आवश्यकता दीर्घकालीन होती है। कारण, उपक्रमों के लाभप्रद बनने में १८ वर्ष तक लग जाते हैं और इसके बाद भी ऋण धन सहज-सहज ही चुकाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक पूँजी तो स्पष्ट अनु-त्पादक है ही। दूसरे, व्याज का भुगतान भी एक गम्भीर समस्या है। यदि दीर्घ-कालीन ऋणों पर ५-६% की दर से व्याज लयावें, तो २० वर्ष में मूलधन के बराबर ही व्याज देनी पड़ती है, जो अल्प-विकसित देशों के लिये बहुत भारस्वरूप है। तीसरे यदि मूलधन और व्याज का भुगतान विदेशी मुद्रा में ही करना पड़ा, तो स्थिति और भी गम्भीर बन जाती है। चौथे, निजी उपक्रमों प्रायः शीघ्र एवं पर्याप्त लाभ देने वाले उद्योगों में ही निमोग्न करते हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सदा ऋण देने को प्रस्तुत रहता है किन्तु सामाजिक उद्योगों में प्रायः सरकार को ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये वित्तम्ब से लाभ देते हैं और वह भी साधारण, और, साथ ही सरकार पर अन्य कार्यों का भार होने से उसकी पूँजी लगाने की क्षमता भी सीमित होती है, जिससे यह आवश्यक है कि कोई बाह्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था उसे ऋण दे। इसी आवश्यकताओं के सदर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है कि कम विकसित देशों को ऐसे ऋण प्रदान कर सके जिनके उपयोग में उन्हें अधिक स्वतन्त्रता रहे और जिनके भुगतान की रीति ऐसी हो कि ऐसे देशों के

व्यापाराग्रेय पर अधिक भार न पड़े। अतः यह सत्या विश्व बैंक के उद्देश्यों को और भी अधिक बल तक पूरा कर सकेगी और साथ ही कुछ ऐसे उद्देश्यों के लिए भी ऋण दे सकेगी जिनके लिए विश्व बैंक ऋण देने में असमर्थ है।

परिपद् का संगठन—

कोई भी देश जो विश्व बैंक का सदस्य है, विकास परिपद् का भी सदस्य बन सकता है। १० जून १९६६ को इसके सदस्यों की संख्या ६८ थी। परिपद् में सदस्य-देशों को विभक्तित और अविकसित वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग में १६ और द्वितीय वर्ग में ५० देश हैं।

सभ की प्रारम्भिक पूँजी १०० करोड़ डालर रखी गई है और इसे उपरांत वर्गों में निम्न प्रकार बांटा गया है—७४.१ करोड़ डालर विकसित देशों के लिए और २५.९ करोड़ डालर अविकसित देशों के लिये। सभ की प्राप्तियें पूँजी ६६६ १५ मि० डालर हो गई हैं। दूसरे वर्ग के सदस्यों को अपने चन्दे का १०% स्वर्ण और परिवर्तनीय मुद्राओं में और शेष ६०% राष्ट्रीय मुद्राओं में, पाँच किस्मों में, चुकाता पड़ता है और प्रथम वर्ग के सदस्यों को सम्पूर्ण चन्दा स्वर्ण या परिवर्तनीय मुद्राओं में देना पड़ता है। अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी व कनाडा सबसे बड़े चन्दाधारी देश हैं। इनकी चन्दा राशिवाँ क्रमशः ३२० २६ मि०, १३१ १५ मि०, ५२०६६ मि० व कनाडा ३० ८३ मि० डालर हैं। भारत का चन्दा ४००३१ मि० डालर है जो उसने १०% स्वर्ण व परिवर्तनीय मुद्राओं में तथा ९०% रुपयों में दिया है।

विकास परिपद् में सभी अविकसित देश बड़ी आस लगाये हुये हैं। किन्तु इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए परिपद् के साधन अपर्याप्त हैं। अतः कार्यकारी सचालको के सुझाव पर परिपद् के साधनों में कृत्रिम प्रस्ताव रबीकार लिया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम वर्ग के सदस्यों से पूरक ऋणदात लेकर अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी पहली व्यवस्था ७१० मि० डालर के लिए सन् १९६५ में की गई थी।

विकास परिपद् के लिये प्रबन्ध व्यवस्था विश्व बैंक की ही भाँति है। गवर्नर मण्डल, प्रशासनिक सचालक मण्डल और अन्य उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त विश्व बैंक के नियमित कर्मचारी ही इसके कार्य सम्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हाँ, यदि भविष्य में आवश्यक समझा जाय, तो अलग कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य की ३००-प्रति पाँच हजार डालर एक मत देने का अधिकार है।

विकास परिपद् के कार्य—

जैसा कि हमने पहले भी सकेत किया है अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद् विश्व बैंक की पूरक संस्था है और अल्प-विकसित देशों को विकास हेतु सन्तु और दीर्घ-कालीन ऋण देता है। इनकी छत्ती अधिा सरल और सुविधाजनक है। विकास मध्य के ऋण का सुलभ ऋण (Soft Loans) कहा जाता है, जिनकी सीमा विशेषताये होती हैं—(i) व्याज की दरें नीची होती हैं, (ii) ऋण सम्झौ अवधि के लिए दिए

जाते हैं, और (iii) ऋण का भुगतान ऋणी देश की मुद्रा में स्वीकार कर लिया जाता है।

बहुत से ऐसे देशों को भी, जिन्हें विश्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो सकते, मध्य से प्राप्त हो सकते हैं। मध्य द्वारा दिये गये ऋणों पर कोई व्याज नहीं है। इससे कमविकसित देशों को बहुत ही लाभ है, क्योंकि उन पर ऋण का भार बहुत कम पड़ता है। परिपक्व ऋण देने हेतु व्यवसाय की उत्पादकता या लाभ प्राप्त करने की शक्ति पर विशेष ध्यान नहीं देता। फलतः परिपक्व से सभी प्रकार के व्यवसाय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऋण प्राप्त करने की शर्त केवल यह है कि योजना विशेष की दश के जायिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए। चूँकि ऋण का भुगतान देशी मुद्रा में किया जा सकता है इसलिए ऋणी देश को विदेशी मुद्रा के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती। उसे भुगतानक्षेप की प्रतिकूलता की भी चिन्ता नहीं रहती। ऋण देने के बाद परिपक्व समय समय पर ऋणी देश में योजना की प्रगति का भीरा देती रहती है एवं प्राविधिक और अन्य सहायता देती है। परिपक्व राजनीति के प्रभाव से निवृत्त होकर केवल जायिक आधार पर ही ऋण देती है। ऋण देने के पूर्व वह परियोजना की जांच एक विशेषज्ञ समिति से कराती है। वह इस बात का ध्यान रखती है कि ऋण का निर्धारित योजना के लिए ही सहायता किया जाय। इसके द्वारा कही में भी वस्तुमें खरीदी जा सकती है।

विकास परिपक्व के कार्यक्रमलाभों की प्रगति—

परिपक्व ने ८ नवम्बर १९६१ को कार्यक्रम शुरू किया और ३० जून १९६७ को परिपक्व के ऋण देने योग्य कुल प्रस्तावन १,७८१ मि० डालर थे, जिसमें से इस तिथि तक वह १,६८४२ मि० डालर के ऋण स्वीकृत कर चुकी है। इस प्रकार ३० जून १९६७ को परिपक्व के अबद्ध ऋण (uncommitted funds) १६८ मि० डालर रह गये। ३० जून १९६८ को स्वीकृत ऋण राशि १७७६ मि० डालर हो गई और अबद्ध ऋण केवल १५ मि० डालर रह गये। किन्तु यह राशि उन परियोजनाओं के जिसे सुरक्षित कर दी गई है जोकि अभी अंतिम निर्णय की अवस्था में हैं। यह सहायता निम्न कार्यों के सम्बन्ध में दी गई है—विद्युत शक्ति, परिवहन, तार परिवहन, कृषि और वन विकास, उद्योग, जल पुति योजना, शिक्षा योजना। ये ऋण भ्यान्वुक्त हैं। इन पर उधार लेने वालों से केवल ३% सेवा व्यय लिया जाता है। सबसे अधिक सहायता एशिया और मध्य पूर्व के देशों को प्राप्त हुई है तथा उन्हें भ्यान्वुधार परिवहन के लिये सबसे अधिक ऋण मिला है।

भारत और अं० वि० परिपक्व—

भारत परिपक्व का प्रारम्भिक सदस्य और अपने चन्दे के आधार पर इसमें एक प्रस्तावित सभासद नियुक्त करने का अधिकारी है। यद्यपि उसका चन्दा अधिकतम पाँच में से एक है तथापि उसे भाग २ के सदस्य देशों में सम्मिलित किया गया है,

जिससे वह परिपद से गयेष्ठ ऋण मुविघाये प्राप्त कर सकता है। विगत ८ वर्षों में परिपद ने भारत को सड़कों, रेलों, टेली-कम्यूनिकेशन, सिंचाई, विद्युत शक्ति के विकास और बम्बई-बन्दरगाह के सुधार-हेतु ऋण दिये। १९ अगस्त सन् १९६६ को विश्व बैंक ने परिपद द्वारा भारत को १२० मि० डालर का गैर-प्रयोजना (non-project) ऋण स्वीकृत किया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना है ताकि वह विद्यमान निर्माणों खर्चा के द्वारा उत्पत्ति बढ़ाने हेतु पुर्जें, सामग्रियाँ, फुटकर हिस्से एवं अन्य सामान का आयात कर सके। इस ऋण से निम्न उद्योगों को लाभ पहुँचने की आशा है — व्यापारिक व्हीकल्स, मशीनों और कार, इलेक्ट्रिकल इन्विपमेन्ट, कृषि ट्रैक्टर, बॉय एवं रोलर विपरिम्प, औद्योगिक एवं खनन यन्त्र, उर्वरक एवं नौटनारिक इवाइयाँ, बुनियादी असीह धातुय। यह ऋण कुल ६०० मि० डालर की पहली निश्चित थी। इस ऋण का प्रयोग लाइसेंस पाने वाली फर्मों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम ढङ्ग से किया जानगा। यह ऋण व्याज-मुक्त है। इसकी मदावली १० वर्ष बाद शुरू होगी तथा इसे ५० वर्षों में लौटाना होगा। इस नये ऋण में यह प्रगट होता है कि परिपद भूत विनित्त देशों के लिए कृषि-विकास के महत्त्व को अनुभव करने लगी है। ११ मार्च १९६६ तक परिपद ने भारत को ७५७ ५६ करोड रुपये के ऋण दिये, जिसमें से ५७० ३० करोड रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

विश्व बैंक एक सम्बद्ध संस्थाओं के ऋणों की सहस्यता में पिछले दशान्न में भारत में निर्माणी संस्थाओं में गयेष्ठ वृद्धि हुई है, जो अब पर्यन्त पूँजीगत सामान (जैसे—औद्योगिक एवं विद्युत मशीनरी, कन्स्ट्रक्शन इन्विपमेन्ट और व्यापारिक व्हीकल्स) बनाने में समर्थ है। उद्योगों की क्षमता बढ़ाने की प्राथमिकता दी गई थी। इसका कारण यह था कि देश में विद्युत विकास, सड़क विकास एवं कन्स्ट्रक्शन इन्विपमेन्ट की भारी माँग होने लगी थी जिसे पूरा करना जरूरी था। किन्तु विदेशी विनिमय की कमी के कारण विनाश गण वह खर्च आयात नहीं कर पा रहे हैं जोकि वर्तमान स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए आवश्यक है। आयात नियन्त्रण में ढील देने हेतु ही IDA ने भारत को नये Credits दिये हैं।

भारत को परिपद द्वारा दी गई कुल सहायता का ५०% भाग मिला है। स्पष्ट है कि IDA ने भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है और उसके आर्थिक विकास में सारी योग दिया है।

परिपद के कार्यों का मूल्यांकन—

परिपद के समस्त एक विस्तृत कार्यक्षेत्र है। आजकल अनेक अविकसित देश आर्थिक विकास के लिए योजनायें बना रहे हैं किन्तु उनके लिये धनाभाव बहुत खटकने वाला है। परिपद इस अभाव को दूर करने के विकास कार्य में सच्ची सेवा करती है। परिपद के अधिकारियों को चाहिए कि परिपद के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान

करे। जैसा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा था, परिपद् के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जिन तक विश्व बैंक नहीं पहुँच सकता। आशा है कि परिपद् अपने इस पुनोत्त उद्देश्य में सफल होगी।

मार्च १९६८ में परिपद् के अबद्ध साधन केवल ५२ मि० डालर रह गये थे। अतः परिपद् के सचालको ने १२०० मि० डालर के पूरक अंशदान का प्रस्ताव रखा है। यह राशि १८ सदस्य देशों और म्विटरलैण्ड (जोकि परिपद् का सदस्य नहीं है) से तीन वार्षिक किस्तों में प्राप्त की जायगी।

परीक्षा प्रश्न :

- १ "अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में जिस नई मौद्रिक संस्था का उदय हुआ है वह विकसित राष्ट्रों की इस शुभेच्छा का सूचक है कि वे अपने अल्पविकसित भाइयों को तेज गति में अपने बराबर के स्तर पर लाना चाहते हैं।" इस कथन को IDA के कार्यक्रमलापों के संदर्भ में जाँचिये और यह बताइये कि परिपद् अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुई है ?

एशियाई विकास बैंक

(Asian Development Bank)

प्रारम्भिक—

२६ नवम्बर सन् १९६६ को बहुचर्चित प्रथम एशियाई विकास बैंक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। यह एशिया और सुदूर पूर्व के विकास हेतु स्थापित किया गया पहला क्षेत्रीय बैंक है। जापान के प्रधानमंत्री ने बैंक के उद्घाटन भाषण में कहा है कि— 'बैंक एशियाई राष्ट्रों की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं का पूर्ति बिन्दु है। यह एशियाई राष्ट्रों की स्व सहायता भावना और समेक्यता का प्रतीक है।'^१

एशियाई विकास बैंक की स्थापना के कारण—

सर्वप्रथम मार्च सन् १९६३ में मनोला में एशियाई विकास बैंक की स्थापना का विचार किया गया था। किन्तु बैंक की स्थापना के लिए वास्तविक ठोस कदम ईकैफी (ECAFE) की बॅलिंगटन बैठक में ही उठाये जा सकते थे। वास्तव में एशिया ही एकमात्र ऐसा प्रमुख क्षेत्र बचा हुआ था जिसमें अभी तक इसकी अपनी कोई क्षेत्रीय विकास संस्था नहीं थी। अतः इण्टर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के नमूने पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना का मुभाव सम्बद्ध पक्षों को बहुत उत्साहप्रद प्रतीत हुआ। अमेरिका ने भी उक्त बैठक में इस प्रस्ताव के पक्ष में राय दी यद्यपि वह पहले इसके विरुद्ध था। इस रूख-परिवर्तन का कारण यह था कि अमेरिकी कांग्रेस प्रत्यक्ष सहायता देने के बजाय विद्व नस्थाओं के माध्यम से सहायता देने के पक्ष में थी।

बैंक की संरचना—

अफ्रीकी विकास बैंक में क्षेत्र से बाहर के सदस्य सम्मिलित नहीं हैं किन्तु

^१ The Bank represents the realisation of a long cherished aspiration of the nations living in the region. It could be described as the crystallisation of Asia's spirit of self help and solidarity among peoples of this region"—Osaku Sato, Japan's Prime Minister 24 11 1966

ADB में है। जिस समय बैंक का उद्घाटन हुआ उस समय ३० (१८ क्षेत्रीय एवं १२ गैर-क्षेत्रीय) देश सदस्य थे। अब इसकी सदस्य-संख्या ३३ है।

बैंक का प्रबंध-संगठन एवं पूँजी—

जापान के टाकेशी वाटानाबी (Takeshi Watanabe) को ५ वर्ष के लिये बैंक का प्रेसिडेंट चुना गया है। १९६८ में आस्ट्रेलिया के वी विलियम मैकमहॉन (William McMahon) को बैंक का चेयरमैन चुना गया है। तैवान और हेग्मार्क के प्रतिनिधियों को वायस चेयरमैन चुना गया है। अन्तिम तीन व्यक्ति द्वितीय वार्षिक सभा तक पद पर रहेंगे।

प्रबंध बोर्ड में ७ क्षेत्रीय और ३ गैर-क्षेत्रीय संवालयक हैं। क्षेत्रीय संचालक १०% अंश पूँजी के आधार पर चुन गये हैं। भारत, जापान एवं आस्ट्रेलिया तो अपने-अपने क्षेत्र के आधार पर ही चुन लिए गए, किन्तु अन्य देशों को आपस में मिलना पड़ा। इस ढङ्ग से चुने गये क्षेत्रीय संचालक फिलिपाइन, थाईलैंड और द० कोरिया हैं। गैर-क्षेत्रीय संचालक अमेरिका, इंग्लैंड और प० जर्मनी हैं।

बैंक के बटॉक की नियुक्ति करने में भौतिक वितरण की आवश्यकता का ध्यान में रखा जाता है। यथाशक्ति सुयोग्य कर्मचारी ही रखे जाते हैं।

विकासोन्मुख राष्ट्रों को ३५.८०% मतधिकारों पर नियंत्रण है। भारत को विकासोन्मुख राष्ट्रों की मतशक्ति का २५% प्राप्त है। अन्य देशों के मतधिकार इस प्रकार हैं — जापान १७.२३%, आस्ट्रेलिया ७.६९%, न्यूजीलैंड २.५२%। इस प्रकार क्षेत्रीय सदस्यों की ६३.२४% मतशक्ति प्राप्त है। शेष गैर-क्षेत्रीय १३ सदस्यों के पास है जिनमें अमेरिका कनाडा, ब्रिटेन और प० जर्मनी सम्मिलित हैं।

बैंक की अधिकृत पूँजी १,००० मि० डॉलर है। ADB के चार्टर के अनुसार, सदस्यों द्वारा आवी पूँजी पहले पाँच वर्षों में समान वार्षिक किस्तों द्वारा दी जायेगी। श्रुति की जाने वाली पूँजी में से ६०.७०% परिवर्तनशील कर्तव्यों में होगी। इस प्रकार बैंक के कार्यक्षेत्र की २००० मि० जनता की माँग को पूरा करने हेतु प्रतिवर्ष १०० मि० डॉलर के (खर्च सम्मिलित करते हुए) ही उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें से १०% ही उदार शर्तों पर दिया जावेगा। शेष कठोर शर्तों पर उपलब्ध किया जायेगा। अतः पूँजी बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। जापान और भारत ने नरम शर्तों पर उधार देने में प्रयोग हेतु स्थापित विशेष कोष (Special Fund) में विशिष्ट राष्ट्रों में उदारतापूर्वक सन्दा देने की अपील की। एक अन्य उपाय बाँह्स की विपरी (Issue of bonds) बताया गया, किन्तु यह उपाय सोन-चार वर्ष बाद ही प्रयोग किया जा सकेगा जबकि बैंक पश्चिम के पूँजी बाजार का विश्वास अजित करे।

【 हर्ष की बात है कि बैंक को तीसरी माधारण स्तर में तीन धनिक राष्ट्रों ने विकासोन्मुख एशियाई देशों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिये कोष उपलब्ध

करने का वचन दिया है—जापान ३० मि० डालर, ब्रिटेन १४४ मि० डालर और आस्ट्रेलिया १० मि० डालर। ये राशियाँ विशेष नीप म रखी जायेंगी।]

विकासोन्मुख राष्ट्रों में भारत का चन्दा (= ६३ मि० डालर) सबसे बड़ा है। भारत के दत्ते बड़े चन्दे के कारण ही विकासोन्मुख राष्ट्रों को सम्मानित स्थान मिल गया है। इसके बिना ADB एक स्वकीय सहायता की क्षेत्रीय मस्या प्रतीत होने के बजाय बाहरी स्रोतों से प्राप्त होने वाली सहायता का वितरण करने वाली एजेंसी जैसी। जापान और अमेरिका ■ चन्दा (प्रत्येक) २०० मि० डालर है।

बैंक ने १६ दिस० से मनीला (जहाँ इसका प्रधान कार्यालय रना गया है) में व्यवसाय आरम्भ कर दिया है।

बैंक के कार्य—

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एशियाई बैंक की स्थापना बीतनाम सम्बन्धी अमेरिकी नीति से विमुख भी प्रभावित नहीं है। इसका प्रबन्ध एवं गन्तव्य एशिया-वासियों के लानार्थ एशिया बासी द्वारा दिया जाता है। यह अन्य अन्तर्राष्ट्रीय नस्थाओं के प्रयत्नों में, जो कि एशियाई क्षेत्र के विकासार्थ किय जा रहे हैं, वृद्धि करेगा। पूँजी की उपयोगिता के कारण आज अनेक एशियाई देश चालू विकास-दशावधि में से ५% विकास दर के लक्ष्य को करने में भी त्रुटि आई अनुभव कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण बदल है। यह एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास की गति बहुत बढ़ाने में सहायक होगा।

बैंक के कार्यकलापों का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत रखा गया है, जिसमें कृषि, निर्माण एवं शक्ति का विकास सम्मिलित है। विद्व की अन्य वित्त मददाओं की भाँति ADB भी लगभग ६% भ्याज दर पर धन देगा तथा २० से २५ वर्ष तक की अवधि में उसकी अदायगी की जा सकेगी।

बैंक के कार्यकलापों की प्रगति—

१६ दिस० १९९६ को बैंक के कार्यचालन के ३ वर्ष पूरे हो गये हैं। यह समयावधि एशियाई विकास बैंक जैसी बहु-राष्ट्रीय वित्त नस्था के कार्यचालन के मूल्यांकन के लिए बहुत ही पोटी है। फिर भी बैंक की उपलब्धियों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है —

(१) बैंक ने अपने संगठन का कार्य पूरा कर लिया है। इसकी प्राथित पूँजी ६७८ मि० डालर है। इसमें से ६०% पूँजी क्षेत्र के १६ देशों ने प्रदान की है।

(२) बैंक के साधारण पूँजी प्रसाधन (विशेष कार्यकलापों के लिये अलग रखी गई पूँजी के अतिरिक्त) ४०१४ मि० डालर से जिसमें से ३३६४ मि० डालर परिवर्तनीय करेण्डियों में था।

(३) १९९६ में बैंक की ग्राँस वामदनी १२६ मि० डालर और ग्राँस व्यय

७४ मि० डालर थे। इस प्रकार उसे ३३ मि० डालर की बुद्ध वामदनी हुई जबकि १९६८ में ३५ मि० और १९६७ में २१ मि० डालर हुई थी।

(४) इस वर्ष में बैंक ने पहली बार बौट वेचे। बौण्ड जर्मनी सघीय गण-राज्य में नेचे गये। इनकी कुल राशि ६० मि० डालर थी। इन पर व्याज ७% है तथा इनकी अवधि १५ वर्ष रखी गई है।

27

(५) ३१ दिस० १९६९ तक बैंक ने कुल २७ ऋण ११ विकासोन्मुख सदस्य देशों में २६ प्रोजेक्टों के लिये स्वीकार किये। ऐसे ऋणों की कुल राशि १३६७० मि० डालर है। १९६९ में जो ऋण स्वीकार किये गये वह नवा, नेवान (चीन), इथोपिया, द० कोरिया, ग्लेशिया, नेपाल, फिलिपाइन्स, सिंगापुर थाईलैण्ड और पकिनी साम्राज्य में १९ प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में है।

(६) इथि एम मछली-पालन, वातायात और विवात बैकिंग के क्षान में १० देशों को २२३ मि० डालर की तकनीकी सहायता १३ प्रस्तावों के सम्बन्ध में दी गई। १९६८ में ११ प्रस्तावों पर ११४ मि० डालर की सहायता दी गई थी।

(७) साधारण पूँजी में से दिये गये प्रोजेक्ट ऋणों के लिये व्याज दर ६.३% बाजों की गई किन्तु विशेष कोष में से दिये गये ऋणों पर व्याज की दर २.१% से लेकर ३% तक रखी गई है।

(८) बैंक के विनियोग १९६९ के अंत में २२५७ मि० डालर के बराबर थे, जो बैंक के परिवर्तनशील करैन्सियों के कोष का जिसकी चालू कार्यक्षमताओं के लिये आवश्यकता नहीं थी, प्रतिनिधित्व करते हैं।

(९) चूँकि अधिकांश विकासोन्मुख सदस्य देशों ने कृषि को बहुत महत्त्व दिया था, इसलिये बैंक ने एशिया में इथि सम्बन्धी एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण आरम्भ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि भविष्य में बैंक कृषि के विकास में क्या योग दे सकता है।

(१०) मलेशिया सरकार की प्रार्थना पर बैंक ने एक क्षेत्रीय वातायात सर्वेक्षण भी आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य द० पू० एशिया में वातायात के विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करना और बैंक को विनियोग सम्बन्धी सुझाव देना है।

बैंक की कठिनाइयाँ—

(१) अपायार्थ पूँजी के सम्बन्ध में बैंक का कार्यचालन कठिनाईपूर्ण होगा। उगे सहायता के लिए प्रायोजनार्थों की परीक्षा में विवाद का सामना करना पड़ेगा। भाषा है कि भारत व इण्डोनेशिया जैसे राष्ट्रों के सहयोग से ये विवाद सहज ही सुल-भार्य जा सकेंगे। साथ ही ADB में एशियाई आवाज को बुलन्द करने हेतु भारत और जापान को भी मिलकर कार्य करना होगा। हर्ष वा विषय है कि इस विषय में प्रयत्न चालू हो गये हैं।

(२) यह दर प्रगट किया गया कि विकसित देशों से एशिया को द्विपक्षी सहायता (bilateral aid) में कमी हो जायगी।

(३) स्थानीय करेंसियो में चन्दा एक गम्भीर समस्या है। क्योंकि इनका प्रयोग सीमित होगा।

(४) बैंक को क्षेत्रीय प्रतियोगिता तथा आर्थिक दशाओ में विशाल अन्तरों के कारण परिचासन में कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती है, किन्तु जिस तरह से इसकी स्थापना हुई है उसमें यह आशा बँधती है कि ABD एशियाई क्षेत्र के विनाश में उप-पाणी सेवा करेगा। अठ दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों ने यह माग की है कि कृषि प्रियम बहुत स्थापित किया जाने वाला विशेष कोष केवल दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के नाभार्य अन्तरूप में प्रयोग किया जाय।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता श्री भगत ने ADB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उद्घाटन बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'प्रारम्भिक वर्षों में ADB को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कठिन निर्णय लेने होंगे और राष्ट्रों में विन्यास की भावना उत्पन्न करना होगी। उस अवस्था बुझाना से कार्य करना होगा, सभी राष्ट्रों में सहयोग प्राप्त करना होगा, यत यह रातोरात में चमत्कार नहीं कर सकेगा।' उन्होंने गैर-क्षेत्रीय देशों के सहयोग के लिए साजुवाद दिया तथा इस बात पर और डाला कि ADB अन्य विश्व वित्त संस्थाओं से भावी सम्बन्धों की सहकारी व्यवस्था की रूप रेखा बनावे। श्री भगत ने सभी ईशेकी देशों से ADB में सामिल होने का अनुरोध किया।

भारत और एशियाई विकास बैंक —

एशियाई विकास बैंक के घोषणापत्र की धारा २ में निम्नलिखित ऋण के प्रार्थना पत्रों की प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने की व्यवस्था है। लेकिन किस प्रकार के प्रोजेक्ट को सहायता दी जानी चाहिए, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हर देश की अपनी समस्याएँ हैं। उसकी अपनी विकास-योजनाएँ हैं जिसमें वह अपने ढङ्ग से प्राथमिकताएँ देता है। निम्नलिखित भारत अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए बैंक के प्रस्तावनों का उपयोग करना चाहेगा। लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे उपयोग बहुत सीमित और चुनौदा (selective) ही रहेंगे। एशियाई विकास बैंक किस प्रकार भारत के लिए सहायक हो सकता है। इस पर नीचे प्रकाश डाला गया है —

(१) स्थगित भुगतान पद्धति पर निर्यात—बड़े सम्भवतः अन्य एशियाई विकासोन्मुख देशों के विनाश कार्यक्रमों पर इन देशों को अपने निर्यात की वृद्धि द्वारा अधिक ध्यान केन्द्रित करेगा। ग देश भारतीय पूँजीगत वस्तुओं और मशीनें खरीदने में समर्थ हो सकें इस हेतु हमें स्थगित भुगतान पद्धति (system of deferred payments) का स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें हमें कठिनाई पड़ सकती है क्योंकि हम अभी स्वयं ही विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों में फँस हुए हैं। किन्तु इस दिशा में एशियाई बैंक सहायक बन सकता है।

(२) साधन उत्पादन बढ़ाने में सहायता—भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन्नति

मुख्य सिंचाई, बिजली, उर्वरक और अन्य उत्पादन साधनों पर निर्भर करती है। ऐसा स्थिति में एशिया विकास बैंक के लिए क्या यह उचित नहीं कि वह सिंचाई-सुविधाओं में वृद्धि, बिजली और उर्वरक के रूप में उत्पादन साधन उपलब्ध करने, आदि की ओर विशेष ध्यान दे ? भारत जैसे देश में एशियाई विकास बैंक जिसके विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य है, साधन एकत्र कर सकता है और भारत के कृषि-विकास में आ रही रुकावटों को दूर करने में साधन और ज्ञान द्वारा सहायता पहुँचा सकता है। एशियाई विकास बैंक अपने पोषणा पत्र की धारा-१४ (१) के आधीन विकास योजनाओं तैयार करने में भारत की मदद कर सकता है, जिसमें यह इस प्रकार की योजना बता सके कि उसमें उर्वरकों की प्रधानता रहे और विद्युत शक्ति कृषि विकास के काम में लायी जा सके। एशियाई विकास बैंक विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को इस काम में लगाकर सहायता कर सकता है।

(३) अन्य पूँजीगत वस्तुओं में उत्पादन-वृद्धि—भारत की मुद्रा बाहुल्यकारी स्थिति में पूँजीगत वस्तुओं में वृद्धि करने के प्रोजेक्टों में पूँजी विनियोग करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि इन प्रोजेक्टों में पूँजी विनियोग का प्रतिफल प्राप्त करने में काफी अन्तर रहता है। पूँजीगत वस्तुओं का उद्योग में यह समयबन्धि और भी ज्यादा होती है, क्योंकि इनके प्लांटों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और इनके लिए किया गया अनुसन्धान आदि पर भी ज्यादा लागत आती है। इन कारणों से घरेलू साधनों से अर्ध-व्यवस्था में इतनी बड़ा पूँजी-विनियोग करना सम्भव नहीं हो पाता। इन क्षेत्रों में इस्पात, अल्युमिनियम और रासायनिक उद्योग शामिल हैं, जिनकी दिन-पर-दिन जरूरत बढ़ती जा रही है। एशियाई विकास बैंक इस दिशा में भी भारत की मदद कर सकता है।

(४) भुगतान समुत्पन्न की प्रतिकूल स्थिति में सुधार लाना—कई वर्षों से भारत विनियोग प्राप्त के साथ प्रतिकूल भुगतान समुत्पन्न की स्थिति में है और सामान्यतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ भारत का व्यापार-समुत्पन्न प्रतिकूल है। मबपि, ब्रिटेन और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के लिए भारत का निर्यात तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में काफी बढ़ा, लेकिन उन देशों को भारत के कुल निर्यात व्यापार का प्रतिशत ८१ से कम होकर ७१ प्रतिशत रह गया है जबकि ब्रिटेन को किया जाने वाले निर्यात का प्रतिशत २६८ से कम होकर २१०१ प्रतिशत रह गया है। भारत अमेरिका से वन्य ची आयात करता ही है, लेकिन साथ ही वह बड़े पैमाने पर महँगे कच्चे तेल, लोहा और इस्पात सस्ते तेल इत्यादि भी आयात करता है। आयात के प्रतिकूल प्रतिरूप को खत्म करने के लिए एशियाई विकास बैंक को भारत के ऐसे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिनके उत्पादन से आयात कम हो सके। इसी प्रकार कृषि के विकास के लिए आवश्यक उद्योग (जैसे रासायनिक खाद) और बिजली की योजनाओं को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। भारत, पाय, कच्चा, जूट और सूती कपड़े के निर्यात द्वारा अविश्व

विदेशी मुद्रा कमा सकता है। एशिया के देशों में जहाँ तक भुगतान सन्तुलन की स्थिति का प्रश्न है, भारत की स्थिति सबसे ज्यादा गिरी हुई है। एशिया के देशों में जो एशियाई विकास बैंक के सदस्य देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जो भुगतान-सन्तुलन की कमी से बुरी तरह पीड़ित है। इसलिए, विदेशी मुद्रा के संकट पर काबू पाने में एशियाई विकास बैंक को भारत को पूरी मदद करनी चाहिए। स्टालिन् क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की सम्भावनायें भी बहुत उज्ज्वल नहीं हैं।

निष्कर्ष—एशियाई विकास बैंक की ये समस्याएँ हैं, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन समस्याओं को देखते हुए उसके पास साधन बहुत कम हैं। इसलिए सदस्य देशों द्वारा एशियाई विकास बैंक को कुल पूँजी में अतिरिक्त योगदान देने की आवश्यकता प्रतीत होती है और फ्रांस तथा सोवियत गण जैसे देशों को भी सदस्य बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है जैसा कि बैंक के प्रेसीडेंट ने सुझाव दिया है।

एशियाई विकास बैंक को दूसरे क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और एशिया के आर्थिक विकास के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी समझा जाना चाहिए। डा० पी० एस० सोकनायन ने ठीक कहा है “एशिया को एक आर्थिक इकाई के रूप में अपना अस्तित्व अभी सिद्ध करना है।” और, एशियाई विकास बैंक ही एक ऐसी एजेंसी है जो कि एशिया के क्षेत्रीय विकास के लिए वित्त अथवा धन उपलब्ध कर सकता है। एशिया के राष्ट्रों में आर्थिक स्वतन्त्रता की भावना पैदा करने का प्रयत्न है। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं परस्पर आर्थिक निर्भरता आधिक उपनिवेशवाद का एक नया रूप न ले ले।

परीक्षा प्रश्न :

1. एशियाई बैंक के उद्देश्य एवं इसके कार्यकलापों का विवेचन कीजिये।
[Discuss the objects and the working of Asian Development Bank]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता

(International Monetary System and International Liquidity)

वर्तमान विश्व-मुद्रा-प्रणाली (The Present World Monetary System)

विश्वी भी कानून अथवा नियम म विश्व-मुद्रा-प्रणाली की परिभाषा नहीं की गई है। वास्तव म यह एक अनौपचारिक (Informal) व्यवस्था है, जिसम विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाये अन्तर्राष्ट्रीय सस्थायें तथा प्रचार्य और सुविधायें सम्मिलित होती हैं।¹ यह विभिन्न राष्ट्रो के मौद्रिक सहयोग और अनुशासन का प्रतीक है।

प्रत्येक देश की एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली होती है जिसम मुद्रा इकाई बनाई व्यवस्था, करंसी व्यापारिक बैंक और केन्द्रीय बैंक सम्मिलित हैं। केन्द्रीय बैंक अपने पास स्वर्ण और विदेशी विनिमय कोष रखता है। विश्व मौद्रिक प्रणाली विभिन्न राष्ट्रीय मुद्रा प्रणालियों का मिश्रण है। विभिन्न देशों के बैंक, जो आयात-निर्यात में साख की व्यवस्था तथा अन्य एजेन्सी कार्य करते हैं विश्व-मौद्रिक प्रणाली का प्रमुख अंग बने हुये हैं। एक देश की करंसी का दूसरे देशों की करंसीया में सम्बन्ध जोड़ने के लिए अनेक विनिमय दरें होती हैं, जो एक या अधिक प्रमुख करंसीयों के या स्वर्ण के सम्बन्ध में निर्धारित की जाती हैं। विनिमय दरों को स्थायी रखने के लिये विदेशी मुद्रा के कोषों की आवश्यकता रहती है।

आजकल विश्व के देशों की करंसीयों के मूल्य स्वर्ण (या डालर) में घोषित किय जाते हैं जिससे स्वर्ण समताओं के आधार पर पारस्परिक विनिमय दरें निश्चित हो जाती हैं। इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि विश्व की वर्तमान मुद्रा प्रणाली

¹ The International Monetary System is not to be found described in legislations or regulations. It is a highly informal system some of it represented by national institutions based on national laws, some of it consisting in a complex of role of practices and facilities"—K K Sharma *Monetary Policy in Planned Economy*, p 46

'स्वर्ण विनिमय मान' (Gold Exchange Standard) है। (कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, इनके विचार हम एक पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं) इसके अधीन बाहर और कुछ नीमा तक स्टॉक कोप करेंसियो' (Reserve Currencies) का कार्य करते हैं। इस कोप का मरका है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नीम, जो विनिमय दरों में स्थायित्व बनाने रखने के लिए देशों को विदेशी मुद्रा के ऋण देता है।

आलोचकों का कहना है कि विश्व मुद्रा प्रणाली (स्वर्ण विनिमय मान) के वास्तविक रूप में — (१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन, और (२) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का अत्यधिक सृजन।

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन—कुछ समय से अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में गम्भीर घाट रहने लगे हैं। वहाँ मुद्रा-माना कसती (tighten) जा रही है जिससे बेकारी फैलने लगी है। दूसरी ओर, यूरोप के आधिकारिक वाले देश मुद्रा प्रसार से खुशी हैं। इन कठिनाइयों के लिए आलोचकों ने भुगतान सन्तुलन और सत्याम्यधी नीतियों को दोषी ठहराया है। कुछ सीमा तक यह ठीक भी है। किन्तु उक्त दोषों के लिए अन्य घटक भी दायी हैं, जिन पर आलोचकों का ध्यान नहीं गया है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में असाधारण बेकारी उत्पन्न होने के लिए १९४६-४७ की अत्यधिक विनियोग तेजी (investment boom), कार्य अवसरों के ढाँचों में परिवर्तन, श्रम शक्ति में परिवर्तन आदि भी दायी थे। अतः, यदि भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी प्रभावों से मुक्त कोई नीति या प्रत्यक्ष अपनाई जाती, तो भी ये घटक सुधार नहीं कर सकते तथा कुछ बेकारी फैलना अनिवार्य था। इसी प्रकार, यूरोपीय देशों की अमेरिकन घाटे के कारण ही मुद्रा प्रसार नहीं भोगना पड़ा, बल्कि इसके लिए अन्य कारण भी दायी थे। उदाहरणार्थ, कॉमन मार्केट वाले देश बाहर से क्रय न करके अपने मार्केट के भीतर ही क्रय करते हैं, जिससे उनके व्यापार सन्तुलन में आधिकारिक (और इसलिए मुद्रा प्रसार) उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार, केवल भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी असाम्यतओं को ही विभिन्न देशों की कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। "दस देश समूह" (Group of Ten) की रिपोर्ट में भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी असाम्यताओं और इनके सुधारों को दूर करने के लिए जिन उपायों का सकेत किया गया है उनमें आय नीति (Income Policy) मुख्य है। 'आय नीति' के अनुसार भाड़े वाले देश (अमेरिका) में मजदूरियों और अन्य श्रमियों का इस प्रकार से नियमन होना चाहिए कि वे स्थिर बनी रहें। ऐसी दशा में उत्पादकता की वृद्धि के साथ-साथ मुद्रा में वस्तुओं की कीमतें घटने लगेंगी तथा वे, आधिकारिक वाले देशों द्वारा अपने यहाँ कीमतें ऊँची न रखने पर भी, प्रतिस्पर्धा कर सकेंगी, अर्थात् उनका निर्यात बढ़ जायेगा, जिससे घाट की स्थिति सुधार होने लगेगी।

इस पर भी विद्वानों में कुछ न कुछ सीमा तक मुद्रा-प्रसार होना अवश्यमावी है। कारण, शायद ही किसी देश ने कोई उचित आय नीति अपनाई हो। अमेरिका

को ही नीजिए। वहां मजदूरियों और कीमतों के सम्बन्ध में जो नियम (Guide posts for Wages and Prices) बने हुए हैं, वे अधिक से अधिक, कीमतों को बढ़ने से रोक सकते हैं। कारण, राष्ट्र-व्यापी उत्पादकता में वृद्धि होने के साथ ही साथ मजदूरियों में भी आनुपातिक वृद्धि प्रोत्साहित होती है।

भुगतान सन्तुलन को असाम्यता के सुधार का भार (burden) घाटे वाले और आधिपत्य वाले देशों में परस्पर जिस प्रकार से वितरित होगा वह अन्तर्राष्ट्रीय शोषों की मात्रा पर, अर्थात्, साल की उस मात्रा पर जो कि देश परस्पर देने को तैयार हो, निर्भर करता है। यदि कोप लक्ष्य है, अथवा अन्य देश पर्याप्त साल सुविधायें देने को तैयार नहीं है, तो घाटे वाला देश अपने भुगतान सन्तुलन को सुधारने के लिए मुद्रा-पूति पर कठोर नियन्त्रण रखने एवं सार्वजनिक व्यय में कटौती करने के लिए विवश हो जायेगा, जिससे बेकारी बढ़ेगी और उसी की असाम्यता के सुधार का प्रमुख भार होना पड़ेगा। इसके विपरीत, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कोप विशाल है, अथवा घाटे वाले देश को अन्य देशों में साल सुविधायें सुगमता से मिल जायें, तो वह सुधार प्रक्रिया सुगमता से पूरी कर लेता है, जिसमें कम बेकारी उत्पन्न होती है। ऐसी दशा में आधिपत्य देश एक दीर्घ अवधि तक 'आधिपत्य शोष वाले' ही बने रहते हैं, जिसमें नहीं मुद्रा पूति का यथेष्ट इस्तेमाल हो जाता है। अतः उनको ही मुद्रा प्रसार के रूप में समायोग का प्रमुख भार होना पड़ता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का अव्यवस्थित मुजब—आलोचकों का दूसरा आरोप यह है कि विश्व मुद्रा प्रणाली की आड़ का काम करने वाला मोडिफ़ाए जिस प्रकार से एकत्र होता है वह दोषपूर्ण है। अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में घाटा रहने से अन्य देशों का डालर प्राप्त होते हैं। यह घाटा कभी अधिक तो कभी कम रहता है। कण्ठ विश्व बाजार में डालर की पूर्ति बटती घटती रहती है। किन्तु अमेरिकन घाटे का विश्व की कोप सम्बन्धी आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। कण्ठ विश्व कोष नहीं परिमाण में एकत्र नहीं हो सकता है। यदि अमेरिकन घाटा दीर्घ समय तक बना रहे, तो बाजार का सम्मान कम हो जायेगा और हमने विश्व-द्रवता को ठेस पहुँचाने का डर है। किन्तु, यदि भुगतान सन्तुलन में घाटा न हो, तो डालर रखने वाले देश कभी भी अमेरिका से स्वर्ण मांग सकते हैं। इसी प्रकार, यदि भुगतान सन्तुलन में आधिपत्य बना रहे तो विश्व के अन्य देश अपने डालर कोषों को कम करके अमेरिका की बाजार खुराने लगते हैं। इससे अमेरिका के रिजर्व बढ़ने बन्द हो जाते हैं। [ध्यान रहे कि अमेरिका अपने रिजर्व में डालर नहीं रखता परन्तु स्वर्ण और अन्य करैसिया रखता है।] इस प्रकार, अमेरिकन आधिपत्य और घाटा ही विश्व-द्रवता को ठेस पहुँचाते हैं।

हमारी सम्मति में यदि अमेरिकन भुगतान सन्तुलन का नियन्त्रण अच्छे ढंग से किया जाय, तो वर्तमान विश्व-मुद्रा प्रणाली (स्वर्ण विनियम मान) खनेक वर्षों तक सफलतापूर्वक चल सकती है। यदि विश्व का सबसे बड़ी राष्ट्र ही ऐसा न कर सके,

ना फिर स्वयं विनिमय मान ही क्या, कोई भी मौद्रिक प्रणाली भंग हो सकती है। निम्नोद्देश ऐसे तरीके खोजे जाने चाहिए, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय नोपी के सृजन का नियंत्रण हो सक। यही कारण है कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का प्रबन्ध विश्व की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

स्वर्ण व डालर का आर्थिक संकट^१

आजकल विदेशी व्यापार में लेन-देन का हिसाब करने एवं भुगतान करने के लिए स्वर्ण के अलावा मुख्य रूप में डालर एवं पौंड का उपयोग किया जाता है। पौंड से अवन्यून्यन के परचम्प जनता का ध्यान डालर की तरफ द्रिच गया। परामु आज डालर के प्रति भी लोगो की धारणाएँ निम्न धारणों से विपरित हो देखी जा रही हैं जिसमे लोगो का आकषण स्वर्ण के प्रति अधिक होता जा रहा है।

अमेरिका का प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन—

पिछले २० वर्षों में १९५७ को छोड़ कर एक भी वर्ष ऐसा नहीं बीता है जिसमें अमेरिका की विदेशी देनदारी लेनदारी से अधिक न रहती हो। इन अवधि में भुगतान सन्तुलन का घाटा ३५ अरब डालर रहा। भुगतान सन्तुलन के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण निम्न रहे हैं—आयात का व्यय, समुद्र पार के सैनिक व्यय, विदेशी सहायता और पूँजी के निर्यात के रूप में अमेरिका जितना दूसरों को देता रहा है उतना निर्यात से, विदेशों में लगी पूँजी पर लाभ में और अन्य प्राप्तियों की राशि से नहीं कमाता रहा। अमेरिका ने १९६६ में माल और सेवाओं के निर्यात से ५३ अरब डालर कमाये थे जिसमें से माल और सेवाओं के आयात को घटाने पर ५ अरब १० करोड़ डालर का शुद्ध लाभ रहा। लेकिन पेंशन, सरकारी, सहायता और अनुदान पूँजी आदि के रूप में इतनी घन राशि बाहर गई कि हिसाब साफ होने पर १ अरब ३६ करोड़ डालर का शुद्ध घाटा रहा। इस घाटे की पूर्ति कुछ तो खोने की बिक्री से की गई और शेष की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उधार लेकर। विदेशी भुगतान के घाटे के निम्न प्रमुख कारण बताये जा सकते हैं—

(१) सैनिक व्यय में बढ़ोतरी—अमेरिका चाहता है कि वह वैश्व-साम्यवादी विद्रोह का नेता बसा रहे। नेतृत्व कायम रखने के लिए पूँजी का निर्यात, आर्थिक सहायता या सैनिक गठबंधन या कार्यवाही तीनों का सहारा लिया जाता रहा है। इन क्षेत्रों में भी सैनिक व्यय का हिस्सा सबसे ज्यादा है। पचास वित्त वर्ष का प्रशासनिक बजट १३५ अरब डालर का है जिसमें से ७५ अरब डालर प्रतिरक्षा के लिए रते गए हैं। इस राशि का १/३ भाग दक्षिणी पूर्वी एशिया में नियतनाम युद्ध के लिए निर्धारित किया गया है।

(२) विदेशी सहायता और पूँजी निर्यात—विदेशी सहायता के मायने में

^१ श्री कलशचन्द्र शर्मा, आर्थिक समीक्षा, १ मई, १९६८।

भी अमेरिका कम उदार नहीं रहा है। १९६६ में ही ४ अरब १३ करोड़ डॉलर की नई पूँजी दूसरे देशों में लगाई गई। इस प्रकार भी विदेशी भुगतान का घाटा बढ़ा है।

(३) फ्रांस की नीति—सरकार की सुरक्षित मुद्राओं को डॉलर और डॉलर को सोने में बदलने की सुविधा के लिये दस देशों (अमेरिका ब्रिटेन फ्रान्स जर्मनी, स्विटजरलैंड हॉलैंड इटली बेल्जियम, कनाडा और जापान) ने समुक्त स्वर्ण कोष बना रखा है जिससे कि लोगों का डॉलर में विश्वास बना रहे। यह गुट समुक्त रूप से अमेरिकी डॉलर को सोने में बदलने के लिये तैयार रहता है परन्तु जून १९६७ में फ्रांस के इस कोष से अलग हो जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है जिसके फलस्वरूप भी सोने की मांग और बढ़क उठी है। बहुत से दस डॉलरों का सोना देने के इच्छुक हो गए हैं। फ्रांस ने अपने भण्डार में अब ७५ करोड़ डॉलर (१९५८) की जगह ३२३ करोड़ डॉलर (जुलाई १९६७) का स्वर्ण जमा कर लिया है। अब फ्रांस के पास संसार में दूसरे नम्बर का स्वर्ण भण्डार है। इसलिये फ्रांस यह चाहता है कि अगर संसार में सोना ही अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान का एकमात्र साधन बना रहे और डॉलर का अवमूल्यन हो जाये तो विश्व में फ्रांस की प्रभुसत्ता बढ़ जायेगी और अमेरिका की आर्थिक सत्ता घट जायेगी। इसी आशा में फ्रांस और कुछ अन्य देश जैसे—जर्मनी, इटली स्विटजरलैंड आदि भी डॉलरों को स्वर्ण में बदलने लगे हैं। इसका अन्वयाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लंदन में ही ३५ करोड़ पौंड का लगभग ७५० टन सोना हस्तांतरित हुआ। पेरिस में सोने के दाम बढ़कर प्रति किलो ७००० फ्रैंक तक पहुँच गये और ४५ डॉलर प्रति औंस स्वर्ण तक के सौदे हो गये—२६ मार्च १९६८ के समाचार के अनुसार पेरिस के स्वतन्त्र बाजार में सोना ४० ३८ डॉलर प्रति औंस के भाव में बिक रहा था जबकि स्वर्ण दर ३५ डॉलर प्रति औंस है।

(४) सोने की सीमित उपलब्धि—व्यक्तिगत जमाखोरी, बढ़ती औद्योगिक खपत, और डॉलर व पाउण्ड में विश्वास घटने से सोना खरीदने की होड़ प्रारम्भ हो गई, डॉलरों को स्वर्ण में बदल जाने लगा। साथ ही सोने का उत्पादन स्थिर-सा हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के कारण और डॉलर का मूल्य स्थिर रखने के लिये अमेरिका को अपना सोने का भण्डार अन्तर्राष्ट्रीय सोना बाजारों (विशेषतः लंदन) में बेचना पड़ा। इससे अमेरिका का स्वर्ण भण्डार घटता गया। १९५८ में यह भण्डार २०५८ करोड़ डॉलर का था। जुलाई १९६७ में घटकर १,३१७ करोड़ डॉलर का रह गया। आगामी तालिका से विश्व के स्वर्ण भण्डार का अनुमान लगाया जा सकता है —

विश्व के सरकारी स्वर्ण भण्डार

(मूल्य करोड़ अमेरिकी डालर)

देश	१९५८	१९६१	१९६८	१९६३	१९६४	१९६५	१९६६	मुनाई १९६७
अमेरिका	२०३८	१६८५	१६०६	१२६०	१५४७	१४०७	१३२४	१३१७
फ्रांस	७५	१२६	७५६	३२८	३७३	४७१	५२४	५०३
जर्मनी	५६३	३६६	३६८	३८४	४२५	४४१	४२६	४२६
स्विट्जरलैंड	१६८	२२६	२६७	२८२	२७३	३०४	२८४	२८४
इटली	१०६	२२३	२२४	२३४	२११	२४०	२४१	२४१
ब्रिटेन	२८१	२२७	२५८	२४८	२१४	२२७	१६४	अनुपलब्ध
हालैंड	१०३	१५८	१५८	१६०	१६६	१७३	१७३	१७३
बेल्जियम	१२७	१२५	१३७	१३७	१४५	१४६	१४६	१४६
कनाडा	१०८	८४	७१	८२	१०३	११५	१०४	१०७
जापान	३	६८	२६	३०	३३	३३	३३	अनुपलब्ध
अन्य सरकारें	४८८	४०१	५५१	५८७	५६२	६०४	६३१	अनुपलब्ध
सकल सरकारी स्वर्ण	३८०३	३८८७	३६२०	४०२२	४०८५	४१६३	४०६१	
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ	१४१	२२५	२२०	२०८	२१७	१३८	२२१	
अधिकृत स्वर्ण भण्डार	३९४४	४११२	३८४०	४०३०	४३०२	४३०१	४२८२	

नोट—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित आँकड़ों पर आधारित

प्रतिफलता के सुपाद हेतु उठाये गये कदम—

(१) बैंक दर में १/२ प्रतिशत की वृद्धि कर ५ प्रतिशत कर दी गई है, जिससे पूँजी निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा ।

(२) डालर की सिनियारिटी के लिये २५ प्रतिशत सोना अनिवार्य रखने की व्यवस्था का भी त्याग कर दिया गया है जिससे स्वर्ण बाजार में पूर्ति में वृद्धि होगी जनस्वहय भाव गिरेगा ।

(३) इंग्लैंड में अनुरोध कर पुनवार एवं अनिवार को वहाँ के सोना बाँकी एससेंजो को बंद करा दिया और बैंकी में नक्की के सिवाय सब काम बन्द करवा दिये ।

(४) ४५ करोड़ डालर का सोना बाजार में निरुत्ता ।

(५) गोल्टपुल के सदस्य देशों के बैंकरो को १० मार्च को वासिगटन मुला कर परामर्श किया जिसमे यह तय किया कि स्वर्ण के दो मूल्य निर्धारित किये जाएँ प्रथम सरकारें व केन्द्रीय बैंक परम्पर ३५ डालर प्रति ओम सोने की बिक्री करें और स्वयंज बाजार म मोने की कीमत बाजार भाव म तय हो ।

(६) १० प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जा रहा है इससे वहाँ ४ अरब डॉलर की सालाना आय बढ़ जायेगी ।

(७) ३०० से ४०० करोड़ डॉलर का प्रशासनिक व्यय घटाने का निर्णय किया गया है ।

(८) आयात में कटौती करने और निर्यात बढ़ाने का निर्णय किया है ।

इस प्रकार अमेरिका द्वारा उपर्युक्त कदम डॉलर संकट को दूर करने के लिए उठाये गए हैं । मुख्य रूप से अमेरिका के सामने अपने भुगतान-सन्तुलन को पक्ष में करने के लिये दो ही रास्ते हैं—या तो वह वियतनाम तरीके तर्बसि मुद्रा से जल्द से जल्द मुक्ति पा ले या फिर आयात कम करके निर्यात व्यापार इतना बढ़ा ले कि सारे लवें आमदनी से पूरे हो जायें ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा या स्वर्ण की मूल्य-वृद्धि—

भुगतान की निम्नलिखित स्थिति को सुधारने के लिये विश्व के अधिकतर देश सुझाव दे रहे कि जिस प्रकार राष्ट्रीय मुद्रा में सोने और नोटे का सम्बन्ध समाप्त कर देना चाहिए । उनका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की जानी चाहिये जिसका अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों में उपयोग हो लेकिन उसके बदले में राष्ट्रीय वा सौना माँगने का अधिकार न हो । हाँ, इस मुद्रा की कुल रकम सोने के अनुपात में प्रचलित की जाये और सब देशों का सोने का भण्डार इसकी पीठ पर हो । उनका मत है कि आपसी सहयोग से ही इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव है ।

परन्तु, फ्रांस के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान स्वर्ण में ही होना चाहिए । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा प्रचलित करने के अधिकार देने से उसकी शक्ति बहुत बढ़ जायेगी, क्योंकि यह अधिकार राज्य की प्रभुसत्ता से जुड़ा होने के कारण राष्ट्रीय सरकारों की ही होना चाहिए । इस संकट का निवारण स्वर्ण की दर बढ़ा कर किया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि एक औंस सोना ३५ डॉलर के बजाय ७० डॉलर का हो जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान की तरलता दुगुनी हो सकती है । दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि डॉलर का अवमूल्यन होना चाहिए । अमेरिका इस सुझाव से बिल्कुल सहमत नहीं है । उसका विचार है कि यदि १९३४ में निर्धारित दर बढ़ी गई तो डॉलर में विश्वास जाता रहेगा ।

इस प्रकार मौजूदा परिस्थितियों में डॉलर का अवमूल्यन वाछनीय होते हुए भी अव्याजनीय है, क्योंकि भुगतान सन्तुलन में घाटे के बावजूद भी डॉलर हर जगह छाया हुआ है । यदि उसकी विनिमय दर गिरी तो लगभग हर देश को अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना पड़ेगा । ब्रिटेन की हालत खराब होने के कारण स्टर्लिंग धन प्रथमरा सा हो रहा है । फिर भी तत्तानिदेशों समेत २२ देशों ने अपनी मुद्राओं

की विनिमय दर गिरा दी—डालर का अवमूल्यन होने पर मुद्रा का अन्तर्राष्ट्रीय ढांचा एक बार तो अवश्य ही चरमरा जायगा।

भारत पर स्वर्ण संकट का प्रभाव—

स्वर्ण के लिए मुभाई गई दिमागी पद्धति का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर शीघ्र कोई प्रभाव नहीं पड़न वाला है और स्वतन्त्र बाजार में सोने का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण भारत में सोना चारों छिने जाना कम हो जान की सम्भावना है। परन्तु भुगतान संतुलन को सुधारन के लिए अमरीका तथा अन्य राष्ट्र जैने ही अगली कार्यवाही करेंगे, भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर निश्चय ही तबका प्रभाव पड़गा। अमरीका को भारत द्वारा निर्यात २०१ करोड़ रुपये से भी अधिक का है जबकि स्वर्ण पूल के बचस्व देगो को भारतीय निधान ४८० करोड़ रुपये मूल्य का है। भारत सहायता-सङ्घ भी अपना हाथ पीछे खींच लेना और विदेशी सहायता में और अधिक कटौती हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप हमारे आयात के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा में बहुत अधिक कमी हो जायगी जिसका 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति' पर दुष्प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। यह भी सच है कि इसके कारण आयोजना के स्तर में भी कटौती करनी होगी। इसी प्रकार भारत पर विदेशों जूणो-सम्बन्धी सन्धों के मामले में भी, जो इस समय लगभग ५००० करोड़ रुपये हैं, समस्याएँ पैदा होगी। योजनाबद्ध विज्ञान के लिए यह अत्यावश्यक है कि ऐसी सभी सम्भावित समस्याओं का समय में पहले ही ठीक-ठीक मूल्यांकन कर लिया जाए ताकि किसी अन्य और घोर आपत्ति से बचने के लिए शीघ्र ही उपाय किए जा सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता (International Liquidity)

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता से आशय—

'अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता' का अर्थ स्वर्ण एवं विश्व-बाजारों में स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार की जाने वाली करेंसिया (विशेषतः डालर एवं स्टर्लिंग और आजकल गिबस प्राक एवं १० जर्मन मार्क्स भी) के कोषों की कुल विश्व वृत्ति तथा इन करेंसियों के उपलब्ध श्रेणियों की वृत्तियों के कुल योग से है। सन् १९६१ के अन्त में कम्प्यूनिस्ट युग के देशों के अतिरिक्त अन्य सब देशों के सरकारी कोष कुल ६६,२०० मि० डालर के बराबर थे, जिनमें स्वर्ण की मात्रा ४०,२०० मि० डालर थी। स्पष्टतः कुल द्रवता में स्वर्ण का भाग बाधे से अधिक है, किन्तु राष्ट्रीय करेंसियों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की दृष्टि में किसी राष्ट्रीय करेंसी का महत्त्व तब उदय होता है जबकि वह अन्य देशों के कोषों में स्थान पाये। उदाहरण के लिए कानन विश्व के अन्य देशों के कोषों में रखा जाता है किन्तु रबय अमेरिका में वह सरकारी कोष में नहीं रखा जाता। अमेरिका अपने कोष में मुख्यतः स्वर्ण और कुछ विविध करेंसियाँ ही रखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की आवश्यकता—

अन्तर्राष्ट्रीय मुक्ताने ऋणी या ऋणदाना दोनों में से किसी भी दसा की करेसी म या परस्पर स्वीकार्य किमी तीसरे दस की करेसी में किये जा सकते हैं। प्रत्येक दसा में एक करेसी को दूसरी करेसी में परिणत कराना पड़ता है। यह कार्य विनिमय बैंको द्वारा अपने प्रमाणनों की सहायता से, अथवा, विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा के बिलों के क्रय विनय द्वारा, अथवा देश के केन्द्रीय बैंक से विदेशी मुद्रा का ऋण लेकर सम्पन्न किया जा सकता है। यदि केन्द्रीय बैंक के माघन अन्यान्त हो, तो वह अन्य देशों की केन्द्रीय बैंकों से या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले सकता है। इतने पर भी यदि विदेशी मुगनाम की व्यवस्था न हो सके, तो फिर सम्बन्धित देश आयात न करने पायेगा जिससे विश्व व्यापार में कमी हो जायेगी। अतः विश्व व्यापार के विस्तार के लिए स्वर्ण एवं परिवर्तनशील करेंसियों की उपलब्धि (सर्वात् अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता) को पर्याप्तता आवश्यक है।

द्रवता के अभाव का उदय—

सन् १९६० में डालर पतन के चक्कर में आ गया और उस पर बीज आरम्भ हो गई। तब से ही मुद्रा कोष द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की पर्याप्तता (adequacy) के बारे में मदेह प्रकट किये जाने लगे हैं।

प्रो० ट्रिफिन (Triffin) का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक कोष (स्वर्ण + करेसिया) बढ़ तो रहे है, किन्तु जबकि करेसियों की वृद्धि अनुपातातीत हुई है तब स्वर्ण अनुपात में कम बढ़ा है। स्वर्ण-कोष १५% तक वृद्धि प्रति से बढ़ रहा है। चूँकि १०-१५ वर्ष के पूर्व विश्व की विकास दर (एव इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की माँग) १% थी, इसलिये कोष सम्बन्धी आवश्यकता ५०% स्वर्ण में और ५०% करेसिया में पूर्ण होती थी। किन्तु आजकल विश्व-अर्थ व्यवस्थाओं की विकास दर घट जाने से कोष में स्वर्ण और करेसियों का समुलन बिगड़ गया है। अन्य शब्दों में, कोष में करेसियों का अनुपात बढ़ रहा है जबकि स्वर्ण का अनुपात घट रहा है। अतः द्रवता के अभाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि इसे हल न किया गया, तथा अथक प्रयासों के कलस्वरूप जिस बहुपक्षी परिवर्तनशीलता को स्थापना हुई है, वह पुनः टूट जायेगी।

चूँकि स्वर्ण-पूर्ति में वृद्धि करना कठिन है इसलिये यह कहा जा सकता है कि द्रवता-अभाव को घटाने के लिए करेसी-धारणों में वृद्धि की जाय। किन्तु करेसी धारणा को बढ़ाने में कई खतरे हैं — (i) यदि करेसी धारणा बढ़ाया गया, तो कोष करेसियों (reserve currencies) पर दबाव पड़ जायेगा क्योंकि अधिक माना में रने जान से इनमें लोगों का विश्वास कम हो जाता है और (ii) कोष-करेसियों वाले देशों में भी जानो-जान्तरिक आवश्यकता के अनुसार एक ठोम आर्थिक नीति का पालन करना कठिन हो जायगा।

अधिक द्रवता के प्रवण के लिए विभिन्न योजनाएँ—

अन्त अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की वृद्धि के लिये कुछ अन्य वैकल्पिक योजनाएँ रखी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं —

(१) ट्रिफिन योजना (Triffin Plan)—इसके अनुसार राष्ट्रीय करेंसिया के बावजूद अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक (Supernational central bank or XIMF) बनाया जाय, जो विश्व-अवस्थास्थाओं की विकास बरों के अनुरूप एक उपयुक्त दर में साख उत्पन्न करे तथा XIMF currency (जिसे कीन्स ने Bancor Currency कहा है) ही भविष्य में एक रिजर्व करेंसी के रूप में चले। इन योजना को निम्न देशों के कारण पसन्द नहीं किया गया — (i) यह मुद्रा प्रसारिक प्रभाव उत्पन्न करेगी, (ii) इसमें राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का हनन होता है, एवं (iii) इसने इतनी अधिक आशा करना असामयिक (too much too soon) है।

(२) हैरोड योजना (Harrod's Plan)—डाक्टर ने स्वर्ण का वही मूल्य चला आ रहा है जो कि सन् १९३४ में प्रचलित था। विल्टन तब से कीमतों के निर पेश रहकर लगभग दूने हो गये हैं। डाक्टर हैरोड ने यह मुझा दिया कि स्वर्ण-कीमत को ३५ डॉलर में बढ़ा कर ७० डॉलर प्रति औंस कर देना चाहिए। इससे द्रवता में वृद्धि हो जायेगी। अन्य शब्दों में उन्होंने डाक्टर के अवमूल्यन का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव में निम्न दोषों की ओर इन्हीं दोषों के कारण वह लोकप्रिय न हो सकी— (i) अमेरिका के भुगतान संतुलन में कोई मौलिक अयोग्यता नहीं है, फिर डाक्टर का अवमूल्यन क्यों किया जाय ? (ii) यदि डाक्टर का अवमूल्यन किया गया, तो उसके साथ साथ में आधिक्य पहले की अपेक्षा बढ़ जायगा। फलतः प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन होने लगेगा। (iii) स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से स्वर्ण उत्पादक देश (जैसे—रूस) ही अधिक लाभान्वित होंगे। यदि ऐसा हुआ, तो एक विरोधी विचार बारा वाले राष्ट्र की आर्थिक दशा मजबूत बनेगी। (iv) यदि स्वर्ण कीमतों में एक बारकी वृद्धि की गई, तो अत्यधिक द्रवता (और इसके फलस्वरूप मुद्रा प्रसार) की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। (v) यदि वृद्धि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में की जाय, तो इससे स्वर्ण कीमतों की प्रवृत्ति के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होकर सद्दा प्रारम्भ हो जायेगा।

(३) जैकोबसन योजना (Jacobsen Plan)—मुद्रा कोष के स्थापन प्रबन्ध सचालक ने एक समन्वयात्मक प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार आधिक्य भुगतान वाले देशों (surplus payment countries) के साथ ऋण वचन अनुबन्ध (Stand by Arrangements) किए जायें। जब द्रवता की माँग बढ़े, तो कोष इन अनुबन्धों के अधीन प्रमुख करेंसिया उधार ले फिर अरुणत वाले देशों को ऋण में दे। इस प्रकार ये ऋण माघन द्वितीय रक्षा पत्ति का कार्य करेंगे। कोष ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है।

ऋण-वचन-अनुबन्ध के अतिरिक्त अन्य युक्तियों द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता

को बढ़ाने का यत्न किया गया है। इन उपायों में करेंसी (currency swaps) और सिटा-वृद्धि की योजनाएँ मुख्य हैं।

(४) पत्र-स्वर्ण योजना (Special Drawing Rights, SDR)—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं 'दस देश समूह' द्वारा कराये गये अध्ययनों से यह पता चलता है कि स्वर्ण और रिवरब करेंसियों की विद्यमान विश्व सप्लाई द्रवता सम्बन्धी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है किन्तु भविष्य की दृष्टि से चिन्ता प्रगट की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान द्रवता का वितरण विभिन्न देशों के मध्य न्यायोचित नहीं है। विशेषतः विकासोन्मुख देशों को, जिन्हें भारी मात्रा में आयात करने पड़ रहे हैं, द्रवता की आवश्यकता अनुभव हो रही है। यदि इसकी पूर्ति न हुई तो इनकी योजनाएँ भङ्ग होने का डर है। इसी हेतु अभी हाल में सितम्बर १९६७ में रायोकित्ज़नेरियो की बैठक में नयार की गई योजना के अनुसार मुद्रा कोष ने 'पत्र स्वर्ण' (Paper Gold) प्रचलित किये हैं। इस योजना की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं —

(अ) अतिरिक्त कोषों का मुन्नब—एक नियत राशि तक अतिरिक्त कोष, SDR के रूप में वार्षिक आधार पर पहिले ५ वर्षों की अवधि के लिये, बनाये जावेंगे। इसमें सदस्यों का योगदान उनके विद्यमान सम्पत्तियों में अनुपातिक होगा और वह इसका प्रयोग अपने भुगतान मन्तुलन सम्बन्धी घाटों की पूर्ति के लिए ही कर सकेंगे। स्कीम के संचालन का भार मैनेजिंग डाइरेक्टर पर होगा। आशा है कि प्रारम्भिक ५ वर्ष की अवधि में अतिरिक्त कोष की मात्रा १५ वि० प्रतिवर्ष होगी।

(आ) करेंसियों का कय—घाटे वाला देश प्रारम्भिक पाँच वर्षों की अवधि में अपने कुल SDR हिस्से के ७०% तक अन्य करेंसियों खरीद सकेगा (ऐसा करने पर उसका SDR जोटा कम हो जायेगा और लेनदार राष्ट्रों का बट जायेगा)।

(इ) SDR के आधार पर आहरण शतर्हित होयें—अधिकतम निर्धारित सीमा तक आहरण करने के लिए देनदार दत्त स्वतन्त्र होंगे, अर्थात् उनसे यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि अपनी घरेलू आर्थिक नीतियों में कोई परिवर्तन करें। उन्हें यह राशि पाँच वर्षों की अवधि के भीतर नहीं लौटानी पड़ेगी, लौटाने पर प्रत्येक वर्ष इस अवधि के बाद उठेगा।

(ई) SDR का स्वर्ण मूल्य—SDR का स्वर्ण-मूल्य प्रचलित दर के हिसाब से ही नियत किया गया है और इसके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य में व्याज की दर गामूली रखी गई है।

(उ) अवमूल्यन—यदि मौलिक असाम्यता करेंसी का अवमूल्यन करना आवश्यक बनाए, तो सम्बन्धित देश को मुद्रा कोष के प्रति कुछ अतिरिक्त भुगतान करना होगा, ताकि SDR के रूप में उसका जोटा बना रहे।

स्पष्ट है कि SDR ने हिसाब की एक नई अन्तर्राष्ट्रीय इकाई का मूजन किया है, किन्तु यह स्वर्ण या रिवरब करेंसियों की प्रतिस्थापित नहीं करती बरन् इनका

गूरक मात्र है। अतिरिक्त आहरणों से अर्द्धविकसित देशों को विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सदस्य देश को स्वर्ण या परिवर्तनशील वर-सों में कोई प्रारम्भिक भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्व व्यापार में विनिमय माध्यम का कार्य करने के लिए पत्र चलन के मुद्दन की दिशा में SDR स्कीम एक महत्वपूर्ण नदम है। इसे एच विस्व केन्द्रीय बैंक की स्थापना की दिशा में उठाया गया कदम भी कह सकते हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता का परिमाण निकट भविष्य में अपर्याप्त ही रहेगा तथापि SDR स्कीम उसका एक प्रगतिशील समाधान है और मानव जाति को स्वर्ण के दौर्घकालिक मोह जाल से मुक्त कराने वाली है।

किन्तु स्कीम की विभिन्न सीमाएँ भी हैं—(i) SDR के कोटे IMF की वर्तमान सशक्तता के अनुसार ही निर्धारित कर दिये गये हैं, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया। उचित तो यह था कि SDR कोटा घाटे वाले देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता, क्योंकि स्कीम का बुनियादी उद्देश्य यही तो है कि देशों को अपने भुगतान सन्तुलन में समायोजन करने के लिये जल्दबाजी न करनी पड़े। (ii) ब्रूकै फण्ड को मध्यमता विश्व व्यापी नहीं है इसलिये विश्व-व्यापार एवं भुगतानों का एक महत्वपूर्ण भाग SDR स्कीम में बाहर ही छूट गया है।

जभी तक फण्ड के विशेष आहरण खाते (Special Drawing Account) में भाग लेने वाले देशों को कुल ३,४१४ मि० डालर के हिस्से (SDR Holdings) प्रदान किये गये हैं। कुछ देशों ने SDR का प्रयोग किया है जिसमें उनके SDR हिस्से कम होकर मुद्रा कोष में अन्य देशों के SDR हिस्से (SDR Holdings) बढ़ गये हैं। मुद्रा कोष के SDR हिस्से १ जनवरी १९७० को शून्य से बढ़कर ३१ जनवरी १९७० को १२३ मि० डालर हो गये, क्योंकि कुछ सदस्यों ने SDR का प्रयोग फण्ड में लिये हुये ऋणों को चुकाने में किया। कुछ देशों ने SDR का उपयोग करैन्सिया प्राप्त करने के हेतु किया, जिस कारण U. S. का SDR कोटा ३२४ मि० डालर से बढ़कर ८६६३ मि० डालर हो गया। जास्ट्रिया, बेल्जियम, इटली, नीदरलैण्ड्स, कनाडा, जापान, आस्ट्रेलिया, ८० अफ्रीका, मेक्सिको और वनेजुएला के SDR कोटा भी बढ़ गये हैं।

SDR का प्रयोग करने वाले देश निम्न हैं—संयुक्त अरब गणराज्य, फिली-पाइन और इजराइल। इन्होंने अपने प्रारम्भिक कोटे की लगभग सम्पूर्ण राशि स्तंगल कर डाली है। अन्य देश हैं—चीन, लका, पाकिस्तान, सुदान, कोम्बोडिया।

कोष की रिपोर्ट से पता चला है कि विकासोन्मुख देशों—विशेषतः मिश्र, इजराइल और चीन—ने SDR का उपयोग दुर्लभ करेंसिया प्राप्त करने में किया है। इस प्रकार का उपयोग स्कीम के उद्देश्यों से विपरीत है। अतः कोष प्रविण्य में SDR के उपयोग के विशेष में कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहा है।

परीक्षा प्रश्न :

१. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली है। इसमें क्या दोष है ?
२. अभी हाल में जो डॉलर मकट उदय हुआ उसके क्या कारण थे ? भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ?
३. अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता से आप क्या समझते हैं ? इसे बढ़ाने के उपायों पर प्रकाश डालिये।
४. अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की धारणा का समझाइये और सितम्बर १९६७ में रायो-डिजेनेरियो में अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता के विकास हेतु जो योजना बनाई गई थी उसकी आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये।

[Explain the concept of international liquidity and critically assess the plan which was evolved at Riode Janeiro in September 1967 for ensuring international liquidity]

मन्दी—एक विश्व समस्या

(Depression—A World wide Problem)

प्रारम्भिक—

पिछले दो चार वर्षों से दश के कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में मन्दी के लक्षण प्रगट हुए हैं। इस सम्बन्ध में याद रह कि मन्दी की समस्या भारत की ही समस्या नहीं है बल्कि यह एक विश्व-समस्या है। श्रम विभाजन की नीति जब तक मसार में लागू नहीं होती, मन्दी की समस्या हल नहीं होगी। एशिया अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के पिछड़े देश विकसित हो रहे हैं अब वे अच्छे माल के निर्यातक ही नहीं, बल्कि उत्पादन मात्र के विक्रता भी बन गये हैं। इस हावत से सब देशों को अपना औद्योगिक विकास समन्वित करना होगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन इस काम में महायक सिद्ध हो सकता है। पश्चिमी दश कब तक चलेंगे इसकी प्रतीक्षा करनी होगी।

पश्चिमी देश और मन्दी

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद पश्चिम जर्मनी का 'मार्शल योजना' के अधीन अमरीका ने अपार धनराशि मिली। अपने तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाकर उसने सारे दश में सभा उद्योग नये आधार तथा नई मशीनों से सजे किये। इससे वह ब्रिटेन तथा फ्रांस से भी आगे बढ़ गया। किन्तु अब उसे भी औद्योगिक मन्दी तथा बढ़ती हुई बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी और जापानी माल उसके बाजारों में भर गया है। इससे उसे अपने उद्योगों की सुरक्षा देने की जरूरत महसूस हुई। वहाँ भी मांग घट गई है। अधिक मामलों के विरोध कहते हैं कि वहाँ लोग अपनी आमदनी का अधिक से अधिक भाग बैंकों में जमा कर रहे हैं। खर्च करना नहीं चाहते और इसका कारण है बेकारी का भय। कोयला खाने बन्द हो रही है। उद्योगों में लोगों की अधिक संख्या में काम नहीं मिलता और अब कम्प्यूटर लग जाने के बाद कार्यालयों तथा उद्योगों में जनशक्ति की जरूरत और भी घट जायेगी।

इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही पश्चिम जर्मन सरकार ने चार वर्ष की योजना कार्यान्वित करने का फैसला किया। वे इस योजना का प्रोजेक्शन

कहते हैं। वहाँ सरकार मकानों तथा सड़कों का निर्माण बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या हल करना चाहती है। सारे पश्चिमी यूरोप में उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार हो रहा है जिससे अधिवाधिक लोगों को काम मिले और क्रय शक्ति बढ़े। यह होने पर ही देश में उत्पादित माल खप सकेगा।

ब्रिटेन अपनी आर्थिक समस्या हल करने का जी तोड़ प्रयास कर रहा है। मजदूर दलीय सरकार ने इसके लिए साहसपूर्ण कदम उठाये हैं। पिछड़े इलाकों के विकास के लिए श्री विल्सन की सरकार उद्योगपतियों को भूमि, ऋण तथा कारखानों के लिए बने बनाये मकान दे रही है। यह कार्यक्रम उनकी योजना का आवश्यक अंग है। इसे ही वहाँ 'प्रोत्साहन भवद' कहा जाता है। इसी तरह बेल्ज के औद्योगीकरण तथा वहाँ की बेरोजगारी को दूर करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

इतना ही नहीं, ब्रिटेन की सरकार सरकारी खन में उपभोक्ता उद्योग खड़ा कर रही है इसका कारण है—निजी विनियोजन का अभाव। वहाँ भी पूँजी-पति अपनी पूँजी उद्योगों में लगान में हिंक्ष रह रहे हैं। इस हालत में सरकार और क्या करे। आयोजन और सरकारी क्षेत्र की अनिवार्यता का यही कारण है।

इन प्रकार पश्चिमी देशों में योजनावद्ध विकास में अन्यायता अब मानी जाने लगी है। किन्तु उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक है सिद्धान्तवादी नहीं। ब्रिटेन और जर्मनी में भी सरकारी व्यय में कटौती की जा रही है। कारखानों की क्षमता का कुल ७५ प्रतिशत काम में आ रहा है। सरकार अपनी ओर से पूँजी लगा रही है। बैंक दर घटाकर ऋण का निस्तार किया जा रहा है। कारखानों का मुनाफा तेजी से घटा है और श्रम संगठन वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस हालत में मर्हगार्ड बढ़ी है। करोड़ों में वृद्धि की जा रही है। इन देशों में अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिदिन बढ़ रहा है।

भारत और मन्दी

जब विकसित देशों की यह हालत है तो भारत जैसे विकासशील देश की समस्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर है। आजादी से प्राप्त अधिकार तथा आम लोग की आकांक्षों एवं आकांक्षाओं में वृद्धि के कारण निजी स्वार्थों को नियन्त्रित करना अनिवार्य हो गया है अन्यथा जन आन्दोलन देश और समाज को रौंद ही तोड़ डालेंगे।

मन्दी से उबरने के लिये भारत के सम्बन्ध में सुझाव—

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योगमंडल सचिव देश में आई मन्दी से निपटने के लिए जोह पिट, स्पान और केमिकल् जैसे औद्योगिक माल और पत्थर, मिलाई की मशीनों, कपड़ा और प्लास्टिक के सामान जैसे तैयार माल पर उत्पादन शुल्क घटाने, बम्पनी कर तथा बैंक दर कम करने तथा रिजर्व बैंक की ऋण नीति और दीर्घी करने की मांग की।

मन्दी के मुकाबले के लिये सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वह अर्थ-व्यवस्था को मन्दी में से तेजी से निकालने के लिए काफी नहीं है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल मंत्र ने सरकार और उद्योग दोनों के द्वारा 'अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील' कार्यक्रम पर अमल किए जाने का सुझाव दिया। उसने चेतावनी दी कि उद्योगों में तर्जमान मन्दी को सिर्फ अस्थायी दौर नहीं माना जाना चाहिए। इसके सम्भार परिणाम निकलने और उसे समय रहते रोकना नहीं गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। नव और भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सच की एक समिति ने औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी के कारणों का अध्ययन किया था और उसने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में उन दूर करने के कुछ उपाय सुझाए हैं जो कि निम्न प्रकार हैं —

(१) सरकारी कृषि उपज के मूल्य स्थिर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये और अनुत्पादक खर्च कम कर दे जैसे सहायता राशि (सब्सिडी), सामुदायिक विद्यालय और ग्रामाण निर्माण कार्य आदि का खर्च। उसे ऐसी औद्योगिक योजनाओं पर भी धन नहीं लगाना चाहिए जो खम्बे समय के बाद उत्पादन शुरू करनी हैं। इसके साथ ही सरकार को ऐसी योजनाओं पर धन लगाना चाहिए, जिन पर काम चल रहा है या जिनमें अर्थ-व्यवस्था का ठोपा मजबूत होता हो।

(२) कुछ क्षत्रों में रेल परिवहन तथा बिजली की कमी अनुभव की जाने लगी है। उदाहरण के लिए कोयला उद्योग की रेल परिवहन की भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः रेल विभाग के निर्माण में कठौती बहाल की जाये और रेल परिवहन की दिक्कत खत्म किया जाय। बिजली की उत्पादन-क्षमता का बढ़ाया जाय।

(३) सरकार भारी एवं दरम्यानी इस्पात-बाँचा निर्माण उद्योग की क्षमता का अधिक उपयोग करे। इस क्षेत्र में पहले ही ज़रूरत में अधिक क्षमता को देखते हुए ढाँचे बनाने के नए कारखानों के लिए लाइसेन्स नहीं दिए जाने चाहिए।

(४) अब वित्तीय-प्रोत्साहन कम्पनी-करी में कमी कर दिए जाने चाहिए। यदि कम्पनी कर घटा दिया जाता है तो निर्माता मन्दी का मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बैंक दर भी घटा दी जानी चाहिए जिससे ध्यान और लाभांश की दरें बराबर की जा सकें।

(५) रिजर्व बैंक की ऋण नीति को और उदार बनाया जाए जिससे धन कम व्याज पर ही नहीं, अधिक मात्रा में भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही बैंकों को देहाती क्षेत्रों में धन-संग्रह की गुंतिपाएँ दी जानी चाहिए।

(६) निर्माताओं को बाजार की माँग के मुताबिक चीजें बनाने देना चाहिए केवल वे ही चीजें नहीं जिनके लिए उन्हें लाइसेन्स दिया गया था।

(७) देश में इन्फ्लेशनरिय मात की माँग में कमी का निर्वात बढ़ाने के

लिए लाभ उठाया जाए। इसके लिए सरकार को कुछ विशेष प्रोत्साहन देने चाहिए।

चूंकि देशी बांग में कमी का एक सम्भावित कारण आयात की नई उदार नीति के अन्तर्गत कुछ अधिक आयात भी है, इसलिए ऐसे उपाय करना जरूरी है कि जो चीजें देश में बनने लगी हैं, उनका आयात न हो।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'मन्दी—एक विश्व समस्या है'—इस कथन की समीक्षा कीजिए। भारत पर मन्दी का क्या प्रभाव पड़ रहा है ? इसके उपचार बताइये।

परिशिष्ट (अ) विदेशी व्यापार गुणक (Foreign Trade Multiplier)

प्रारम्भिक—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 'विदेशी व्यापार गुणक' की धारणा 'वेग' velocity की धारणा से उदय होती है। जब लोग व्यय करते हैं, तो त्रय-शक्ति विकसिताओं को प्राप्त हो जाती है, जो फिर स्वयं भी व्यय करते हैं, जिसके फलस्वरूप और भी अधिक व्यक्ति अतिरिक्त त्रय शक्ति पाते तथा खर्च करते हैं। प्राप्त होने वाले अतिरिक्त कोष बाद में कितनी तेजी से व्यय किये जायेंगे, यह 'मुद्रा के वेग' पर निर्भर है। किन्तु, जो व्यक्ति अधिक कोष प्राप्त करता है आवश्यक नहीं कि वह सब की सब अतिरिक्त त्रय शक्ति को व्यय कर दे। कारण, वह इसके एक भाग को निष्क्रिय (Idle) रख सकता है अथवा पिछले श्रेणियों के चुकाने में इस्तेमाल कर सकता है। कुछ भी कारण हो, किन्तु यह निश्चित है कि समस्त कोष व्यय नहीं किये जायेंगे। यदि ये बाद में कभी व्यय किये गये, तो उनके प्रभाव घटे हुये व्यय के सदृश होंगे। वर्ष में व्यय की अपेक्षाकृत धीमी दर कुल व्यय-राशि को घटा सकती है। इस प्रकार, यदि प्राप्ति और व्यय की मध्यान्तर औसत अवधि दूनी हो जाय, तो व्यय राशि ५०% घट जायेगी। यह धारणा क्षरण' (leapage) कहलाती है और व्यय धारा में से हुये रिसाव को सूचित करती है।

आयात और निर्यात क्षरण —

रिसाव या क्षरण वह त्रय-शक्ति है जिसे व्यय-धारा में से अलग कर लिया गया है। जैसे-जैसे रिसाव अधिक होता जाता है, त्रय-शक्ति की प्रथम वृद्धि से उत्पन्न हुआ विस्तारकारी उद्बेग भी धीरे-धीरे घटने लगता है और अन्ततः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार व्यय धारा में से हुआ कोई भी रिसाव अतिरिक्त व्यय की राशि को घटा देता है। आयातों की दशा में, जबकि व्यय का अधिकार किसी विदेशी को चला जाता है, त्रय-शक्ति देश से बाहर हस्तांतरित हो जाती है और तब विदेशी अर्थव्यवस्था के पास अनिरिक्त त्रय शक्ति (बड़े हुये निर्यात) हो जाती है किन्तु आयातक देश के पास यह कम रह जाती है (घटे हुये आयात)।

जैसे-जैसे त्रय शक्ति विस्तृत होती है इस अतिरिक्त व्यय का एक भाग आयातों पर काम करता है, जिससे इस रिसाव में वृद्धि होती है। इस प्रकार, रिसाव दो प्रकार का होता है—(अ) वह जो वस्तु, सचय आदि से उदय होता है और (ब)

वह जो आयातों के कारण उदय होता है। ये दोनों ही विस्तारमूलक शक्तियाँ (गुणक) को, एक-एककी अपेक्षा की अपेक्षा, जो कि आयात नहीं करती हैं और जिस आयातों के द्वारा क्रय शक्ति का अतिरिक्त रिसाव प्राप्य नहीं है अधिक सौप्रता से काट देते हैं।

विदेशी व्यापार गुणक—

‘गुणक’ व्यय के इस प्रकार से खोये हुए भाग का प्रतिपूरक (reciprocal) होता है। इसमें दोनों प्रकार के रिसाव सम्मिलित होते हैं, तकनीकी भाषा में, वह दोनों प्रकार के अनुपातों के योगफल का प्रतिपूरक होता है।¹

विदेशी व्यापार गुणक भी अतिरिक्त निर्यातों से प्राप्त अतिरिक्त क्रय शक्ति को दिखलाता है। निर्यात से क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, आयात से कमी। अतः, यदि आयातों की अपेक्षा निर्यात अधिक बढ़ते हैं, तो हमारी क्रय शक्ति में ‘शुद्ध वृद्धि’ होती है और यदि निर्यातों की अपेक्षा आयात अधिक बढ़ते हैं, तो क्रय शक्ति में शुद्ध कमी होगी। यदि आयात और निर्यात समान रूप से बढ़ें, तो क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूर्ववत् रहेगी। यदि क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन (शुद्ध वृद्धि या शुद्ध कमी) हुआ है तो वह अर्थ व्यवस्था में गुणक (विन्तु घटते हुए) प्रभाव के साथ, फैल जाता है और बाढ़ की विभिन्न प्रकार के खरपों के रूप में दिखाई देता है।

उदाहरणार्थ, एक स्फीतिक चक्र (expansionary cycle) को लीजिये। मान लीजिये कि हमारे निर्यातों में विदेशियों की आय बढ़ने के फलस्वरूप, कुछ प्रारम्भिक वृद्धि हो जाती है। ऐसा होने पर देश की भूगर्भिक में अधिक क्रय शक्ति प्राप्त होगी और फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय की एक श्रृङ्खला चल पड़ेगी। जैसे-जैसे विदेशियों की आय और बढ़ेगी निर्यातों में वृद्धि घटती हुई दर से होगी, क्योंकि एक तो विदेशियों की बचतें बढ़ जानी हैं और दूसरे हमारे अपने आयात भी बढ़ने हैं। आय में वृद्धि होता उस समय बन्द हो जाना है जबकि ये दोनों प्रकार के क्षरण क्रय शक्ति में हुई समस्त प्रारम्भिक वृद्धि को सोच लेते हैं—एक प्रकार का क्षरण बचनों को बढ़ाता है और दूसरा आयातों को। बचत में वृद्धि होने का मतलब है कि उपभोग पर और व्यय नहीं किया जायेगा तथा जब तक उपभोग-बचतों के लिए माँग वर्तमान स्तर की तुलना में बढ़ नहीं जानी उसका कोई उपभोग खोप नहीं रहता। अन्य शब्दों में, ये कोप रद्द-धारा में जलग हो गये हैं। इस तथ्य का (कि बड़े हुए आयातों के लिये मुद्रा द्वारा मुतलान बिना जा रहा है) अर्थ यह है कि क्रय शक्ति विदेशी सत्ताधरों को टासफर की जा रही है। यहाँ भी कुछ कोप व्यय-धारा से निवृत्त जाने हैं। जब

¹ “The multiplier is the reciprocal of the proportion of spending so lost. It includes the two leakages, technically the reciprocal of the sum of the two proportions”

अतिरिक्त निर्यातों के बढ़ने प्राप्त हुआ समस्त प्रारम्भिक कोप काम में आ जाता है अर्थात् वह तो निष्क्रिय वस्तुओं के रूप में निष्क्रिय (inactive) बन जाता है अथवा बढ़े हुये आयातों के भुगतान में विदेशों को जला जाता है, तब कुछ कोप सक्रिय कोप पुनः उत्पन्न हो रह जाते हैं जितने कि यह निर्यात वृद्धि के पूर्व थे। आयातों पर यह द्वितीयक प्रभाव सप्तायर देशों की रूप शक्ति को बढ़ाता है, जो अब (क्रेता देश का) अधिक निर्यात करने है, क्योंकि उस देश के बड़े हुए निर्यातों ने उसकी आय और इसलिये उसके आयातों को बढ़ा दिया है। अब वे स्वयं भी वृद्धि दिलाने हैं—उनकी आयें बढ़ती हैं और उनके आयात घटते हैं, जिनमें से कुछ पुनः प्रथम देश में आने हैं। चूंकि प्रथम स्तर पर आयात आय-वृद्धि का एक अनुपात मानें, इसलिये विभिन्न प्रभाव घटती हुई दर से होने हैं। निर्यातों में हुई प्रारम्भिक वृद्धि ने जिन स्फोटिक शक्तियों को गतिशील बनाया था वह हमारे देश में, जो कि प्रथम देश के बड़े हुये निर्यातों का श्रोत था, आयातों में हुई वृद्धि से उदय होने वाली विस्फोटिक शक्तियों से समुत्पन्न हो सकती है।

गुणक-विश्लेषण का महत्त्व—

गुणक-विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि एक देश की तेजी कैसे अपने आपकी अन्य देशों में सर्वाहित कर देती है और एक देश को विस्फोटित कैसे अन्य देशों को फँस जायेंगे। तेजी के फलस्वरूप आय व आयात में वृद्धि होती है, जिस कारण सप्तायर देशों में विस्तार की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और, फिर आयात अधिक बढ़ते हैं तथा तेजी और भी जोर पकड़ती है। हम इसी प्रकार चलता रहता है। इसी प्रकार, तेजी की दशा में आयात और निर्यात घटते हैं, जिसके फलस्वरूप व्यापार में भाग लेने वाले पक्षों को नुकसान पहुँचता है तथा मंदी फैलने लगती है।

आयातों की अपेक्षा निर्यातों में अधिक वृद्धि होना रफ़ोतिक (expansionary) होता है। किन्तु जब निर्यात में विराट् आयातों की अपेक्षा धीमी गति से हो, तब भी ऐसा ही होता है। यदि निर्यात में १ करोड़ रु० और आयात में १.५ करोड़ रु० में कमी होती है, तो चिदेजियों के प्रति स्वदेश के शुद्ध भुगतानों में ०.५ करोड़ रु० की कमी होती है अर्थात् इतने कोप उसकी व्यय-धारा में बने रहते हैं और इस प्रकार उनका ही प्रेरणाह्वन देते हैं जितना कि निर्यात में १.५ करोड़ रु० और आयात में १ करोड़ रु० की वृद्धि होने पर देते। इसी प्रकार, निर्यातों की अपेक्षा आयातों में अधिक वृद्धि उत्पन्न ही विस्फोटिक (deflationary) होती है जितनी कि निर्यातों की अपेक्षा आयातों में हुई घोड़ी कमी।

निर्यात-आयात समुत्पन्न पर पड़ने वाले इस प्रभाव में तब भिन्नता होगी जबकि यह बढ़ने लगे या घटने लगे व्यापार के साथ हो। हम यह मान सकते हैं कि आयात और निर्यात जब समान राशियों में बढ़ने हैं तो ऐसी वृद्धियों का प्रभाव तटस्थ होगा, क्योंकि समस्त देश जितनी न्यून शक्ति अधिक पाता है उतनी ही खो भी देता है। इन पर भी वृद्धि प्रेरणादायक है—निर्यात उद्योगों का विस्तार होता है और क्षमता को

१ के लिये नये विनियोग किये जाते हैं। अधिक विस्तार की आवश्यकताओं की मनो-
 र्नामित कर देती है। दूसरी ओर, आयात और निर्यात में समान रूप से हुई
 ती मंदा की मनोवृत्ति बनाती है। तेजी की दशा में धारण-घटक में श्रिष्ट होता है जो
 यह कि पहिले की अपेक्षा कम राशि निष्क्रिय रहती है किन्तु पहिले की अपेक्षा कम
 अधिक किया जाता है और कवस्वरूप गुणक के मूल्य या आकार (value or size)
 में घटि हा जाती है।

आयात-धारण का आकार देश में आर्थिक क्रिया के स्तर के साथ साथ परिवर्तित
 होता है। यदि निष्क्रिय श्रमता या बेकारी एक बड़ी मात्रा में विद्यमान हो, तो व्यय
 में हुई वृद्धि पुरखत घरेलू उत्पादकों को मिलेगी, आयातकों को नम। किन्तु जैसा
 जैसा पूर्ण श्रमता का स्तर निम्न पहुँचिगा, विदेशों से अधिकाधिक प्राप्त होगी और
 विज्ञानोन्मुख मांग उपलब्ध घरेलू पूर्ति की तुलना में बढ़ जायेगी। इसके अतिरिक्त,
 दीर्घकाल में धारण का मूल्य या आकार आम-निर्भरता के अन्त के साथ परिवर्तित हो
 सकता है।

उधार लेने के निम्नो स्तरों पर आय और व्यय की वृद्धि विद्यमान मयनों के
 प्रयोग की दृष्टि को ऊँचा कर देती है। किन्तु जैसा-जैसा वास्तविक उत्पादन क्षमता-
 स्तरों के निकट होने लगता है और अधिक आय विस्तार, अतिरिक्त विनियोजन की
 आवश्यकता बना देता है। ताकि बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये नये प्लांट लगाये जा
 सकें। अतिरिक्त विनियोजन को आवश्यक कार्यक्षमता के ऊँचे स्तरों पर आन्तरिक
 धारण ममदत कहीं कम होता है क्योंकि छोटे ही कोष निष्क्रिय रह जाते हैं किन्तु
 अधिकांश कोष विनियोग कर दिये जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह सम्भव है कि ये
 दोनों प्रकार के धारण एक चक्र में विपरीत दिशाओं में चलें—आर्थिक क्रिया के साथ
 आयात-धारण तो बढ़े किन्तु आन्तरिक धारण घटे। आर्थिक क्रिया के संकुचन की दशा
 में विपरीत क्रम देखा जाता है। परिणामस्वरूप गुणक का मूल्य प्रायः अस्थिर होता है
 क्योंकि दूसका वास्तव में आकार इन दो बुनियादी परिवर्तनशील सप-ग्रहों का ही
 प्रतिबिम्ब होता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी-अपनी शक्तियों के अनुसार चल रहा
 होता है।

यदि सभी देश सम्पन्न होने लगे, तो निर्यात एवं आयात भी ऊँचे रहते हैं।
 किन्तु सभी देश यदि मंदी में चले रहें हैं, तो निर्यात और आयात भी अपेक्षित नीचे
 होने हैं। राष्ट्रीय आय, निर्यात-आयात और विनियोग सभी साप-साय बढने-घटने हैं
 तथा इनमें से प्रत्येक व्यय-धारा पर अन्ती क्रिया-प्रतिक्रिया दिसनाता है। दोनों ही (तेजी
 या मंदी की) दशाओं में प्रत्येक देश के लिये मुक्तता एवं प्राप्तिर्था स्तुलित होने हैं।
 किन्तु आन्तरिक वन्व्याण पर उनका क्या प्रभाव होगा? गुणक तर्क के अनुसार घूँकि
 आय में और निर्यात समक्ष बिंदव की दृष्टि में बराबर होने चाहिये, इनलिय, सामान
 रूप से मूल्यवृद्धि किये जाने पर, जो देश अधिक प्राप्त करते हैं उनमें लिये कमशक्ति

७०४]

वे 'शुद्ध अन्तर्प्रवाह' (Net in flow) की प्रेरणा उन देशों को, जिनहे प्राप्तियों की अपेक्षा भुगतान अधिक करना पड़ रहा है, क्रय शक्ति के शुद्ध बहिर्गमन (Net out-flow) की कुप्रेरणा के ठीक बराबर होगी। इस प्रकार, सम्पूर्ण विश्व के लिये, 'विदेशी व्यापार गुणक' सदा 'शून्य' होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विश्व व्यापार के स्तर का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। क्योंकि यह सेक्टर विश्व की क्रय शक्ति में त तो वृद्धि कर सकता है न कमी। ऐसी दशा में गुणक निरर्थक रह जाता है। अब इसकी उपयोगिता मुख्यतः एक छोटे क्षेत्र में या कुछ देशों तक सीमित है। बड़े क्षेत्रों पर लागू करने की दशा में गणना सम्बन्धी त्रुटियाँ हो सकती हैं।

प्रश्न :

1. विदेशी व्यापार गुणक क्या होता है? क्या यह व्यापारिक नीति के लिये एक संतोषजनक आधार प्रदान करता है?

[What is a foreign trade multiplier? Does it provide a satisfactory basis for commercial policy?]

(इलाहाबाद, एम० ए०, १९६६)

2. राष्ट्रीय आय के संदर्भ में विदेशी व्यापार गुणक की धारणा का विवेचन कीजिये।

[Discuss the concept of foreign trade multiplier in relation to national income]

(आगरा, एम०, ए०, १९६७)